

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj.)

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER'S No	DUE DATE	SIGNATURE

प्रमुख देशों का आर्थिक विकास

डा० इण्गमलाल साहूवाल

एम० ए० पी० एच० डी०

अर्थशास्त्र विभाग राजकीय महाविद्यालय

भोलेवाडा (राजस्थान) ।

मीनाक्षी प्रकाशन

मेरठ

नयी दिल्ली

प्रमुख देशों का आर्थिक विकास



ब्रिटेन का आर्थिक विकास

पहला अध्याय

कृषि व्यवस्था व कृषि क्रान्ति

(AGRICULTURE SYSTEM AND AGRICULTURAL REVOLUTION)

आधुनिक युग के आरम्भ होने तक इंग्लैण्ड एवं कृषि प्रधान आर्थिक व्यवस्था का ही देश था। ब्रिटिश कृषि विकास का इतिहास तीन महान् अवस्थाओं¹ से गुजरता है। पहली, दासता की अवस्था जो रोमन साम्राज्य के काल से सम्बद्ध है तथा जिसकी मुख्य विशेषताएँ—ग्रामीण अर्थव्यवस्था का होना, भूमि पर कुछ बड़े व सम्पन्न भू स्वामियों का स्वामित्व होना व खेती का सारा काम दासों द्वारा किया जाना—रही थी। दूसरी, मेनोरियल (जमींदारी) अवस्था जिसमें मध्य युग का अधिकांश समय शामिल किया जाता है तथा जिसकी मुख्य विशेषता खेतीहर ढाँचे में अर्द्ध सामन्तीपन पाया जाना था। इस अवस्था में भू-स्वामित्व तो कुछ बड़े जागीरदारों या जमींदारों (लॉर्ड्स) के हाथ में था किन्तु भूमि जोतने का काम जो लोग करते थे वे न तो पूरी तरह दास थे और न ही पूरी तरह से स्वतन्त्र। उनकी स्थिति दासता व स्वतन्त्रता के बीच की थी। तीसरी, अनुबन्ध अवस्था जो कृषि में आधुनिक युग का सूत्रपात करती है तथा जिसके अन्तर्गत न केवल भू-स्वामियों की सख्या अत्यधिक देखने को मिलती है बल्कि सम्पूर्ण कृषिगत ढाँचा ऐच्छिक अनुबन्ध प्रणाली पर टिका हुआ दिखाई पड़ता है। इंग्लैण्ड की कृषि में आज जो भी आधुनिक तरीके देखने में आते हैं तथा वहाँ व यूरोप के अन्य देशों में खेतीहर जनसंख्या की जो भी स्थिति है वह सब कृषि विकास के इतिहास में हमारे काल से तीसरे काल तक पहुँचने के बीच हुए प्रयत्नों का ही परिणाम है। अर्थात् ब्रिटिश कृषि के इतिहास में मेनोरियल पद्धति का विशुद्धीकरण होना, उसका टूट जाना, सर्वाधिक महत्त्व की घटना रही है तथा उसी में आधुनिक कृषि के विकास का चरण प्रारम्भ हुआ है।

मेनोरियल पद्धति

इतिहासकार इस बारे में त्रिकुल भी एकमत नहीं हैं कि मेनर (Manor) या जमींदारी प्रथा का उद्गम म्रोत कहाँ है। एक विचारधारा के अनुसार मेनोरियल पद्धति रोमन साम्राज्य की वह विरासत थी जिसे उमने मध्य युग को मँपा था। दूसरी विचारधारा के अनुसार मेनर प्रथा का जन्म ट्यूटॉनिक काल में हुआ था। इस प्रथा के उद्गम के बारे में आधुनिक मत यह है कि मेनोरियल प्रणाली का विकास

¹ Ogg and Sharp, *Economic Development of Modern Europe*, 1959, 17-39

इंग्लैंड में स्वतन्त्र रूप से हुआ। साथ ही आधुनिक मत के अनुसार, मेनोरियल पद्धति का उद्गम चाहे किसी भी तरह या किसी भी देश में हुआ हो, इतना निश्चित है कि यह प्रणाली अलग-अलग नामों के अन्तर्गत न केवल इंग्लैंड में पनपी बल्कि इसका विकास फ्रांस, रूस, जापान व भारत जैसे एक दूसरे से असम्बद्ध देशों में भी हुआ। इस तरह एक बात स्पष्ट है कि जमींदारी प्रथा का उद्भव समार के सभी प्रमुख देशों की आर्थिक प्रगति के इतिहास में एक अनिवार्य चरण के रूप में मौजूद रहा है।

मेनर या जमींदार, एक ऐसी सस्था जो मध्य युग में खूब फली-फूली, ऐसी भू-सम्पत्ति थी जिसका स्वामित्व लॉर्ड का होता था तथा जिस पर आश्रित किसानों का एक समुदाय रहता था। उस भूमि पर लॉर्ड अपना स्वामित्व या तो उस भूमि को सामन्ती नैट के रूप में प्राप्त करने से स्थापित करता था या वह उस खरीदता था। कई बार लॉर्ड उस भूमि पर अपना स्वामित्व उसे जबरदस्ती हथ्या कर या फिर किसी और तरीके से कब्जा जमा कर भी स्थापित कर लेता था। लॉर्ड की जमीन पर जो आसामी (tenants) होते थे वे या तो अपने पूर्वजों की जमीन पर रह रहे लोग हों थे या फिर उस जमीन पर आबाद होने वाले व्यक्ति होते थे जिस पर लॉर्ड का आधिपत्य होता था। लॉर्ड के स्वामित्व के अन्तर्गत आने वाली इस भूमि पर आबाद होने वाले आसामियों में वे लोग भी शामिल हों थे जो स्थायी रूप से लॉर्ड के कर्जदार बन चुके थे या जो लोग बसने के लिए लॉर्ड की कृपा व सुरक्षा की आकांक्षा रखते थे। इंग्लैंड में सारे मध्य युग में लगभग सम्पूर्ण भूमि किसी न किसी मेनर अर्थात् जागीर के अन्तर्गत आती थी। बारहवीं व तेरहवीं शताब्दी में इंग्लैंड में आधुनिक व्यापार व शहरी जीवन के विकास के पहले देश को लगभग सारी आबादी मेनोरियल थी।

जार्ज डब्ल्यू० साउथगेट¹ के अनुसार, एक मेनर एक बड़ी भू सम्पत्ति से बनता था जिसमें आमतौर पर एक पूरा का पूरा गाँव व उसके आस पास की जमीन शामिल होती थी। इस भू सम्पत्ति के चोतरफा एक कामचलाऊ बाड़ा लगा दिया जाता था जिससे मेनर की हद्द का भी पता चलता था और उसके भीतर की जमीन की सुरक्षा भी होती थी। प्रत्येक मेनर में एक लॉर्ड हुआ करता था यद्यपि यह वहना सही नहीं होगा कि लॉर्ड ही पूरे के पूरे मेनर का मालिक होना था। निरपेक्ष स्वामित्व तो केवल संघाट का था और मेनर का लॉर्ड अर्थात् जागीर का स्वामी संघाट का प्रतिनिधि या 'आसामी' माना जाता था। लेकिन एक लॉर्ड, जो मेनर का सर्वोच्च होता था, उसके मेनर (जागीर) से कानूनन तब तक नहीं हटाया जा सकता था जब तक उमने देश द्रोह का ही कोई काम न किया हो। इस तरह अपने अपने मेनर पर लॉर्ड का अधिकार काफी सुरक्षित था।

मेनोरियल पद्धति की विशेषताएँ

देश के एक बहुत बड़े भाग में मेनोरियल संगठन से काफी समानता पायी

जाती थी। मेनर या जागीर की मुख्य विशेषताएँ निम्न थी—

(1) सुसम्बद्ध मकान—जागीर के अन्तर्गत आने वाले मकानों से एक सुसम्बद्ध गाँव का आभास होता था। गाँव की सबसे महत्वपूर्ण व विशाल इमारत मेनर भवन ही होता था जिसमें लॉर्ड रहा करता था। आम लोगों के मकान कच्चे व फूस की छतों के बने होते थे जिनमें साधारणतः एक कमरा होता था। गाँव के पास ही झरने पर कोई पानी का मिल या पहाड़ी पर पवन चक्की होती थी।

(2) खुले खेत की व्यवस्था—मध्य युगीन कृषि की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, जो इंग्लैण्ड में 19वीं शताब्दी तक चलती रही, खुले खेत की व्यवस्था (open field system) थी। एक ही मेनर अर्थात् जागीर के अन्तर्गत रहने वाले विभिन्न व्यक्तियों की जमीनों को अलग-अलग करने के लिहाज से न केवल कोई बाड़ा नहीं होता था बल्कि पूरे मेनर में, भीतर की तरफ, कोई मजबूत दीवार, जिससे जमीनें बँटी हुई दिखायी दे, नहीं होती थी। फसलों की रक्षा के लिए कुछ भीड़ी बाधाएँ इधर-उधर लगा दी जाती थी। फसलों के हेर-फेर (crop rotation) के लिए कोई भी वैज्ञानिक पद्धति नहीं थी। इसके स्थान पर एक तिहरी-खेत-प्रणाली (three field system) होती थी जिसमें कृषि योग्य भूमि को तीन भागों में बाँट दिया जाता था। इनमें से दो भागों पर तो खेती की जाती थी और शेष एक भाग को हर साल परतो भूमि के रूप में छोड़ दिया जाता था। खुली खेती प्रणाली की एक अन्य विशेषता यह भी थी कि जमीन के टुकड़ों को कई पट्टियों में विभाजित कर दिया जाता था ताकि उन पट्टियों को आसामियों को सौंपा जा सके।

(3) जोते और आसामी—भूमि रखने वाले मेनर के प्रत्येक आसामी को भूमि को अनेक पट्टियाँ (strips) सौंप दी जाती थी। ये पट्टियाँ अक्सर अलग-अलग खेतों में होती थी और कई बार तो ये एक ही खेत के भिन्न-भिन्न हिस्सों में होती थी। कुल मिलाकर एक आसामी के पास औसतन 30 एकड़ के लगभग भूमि होती थी। प्रत्येक मेनर में चरागाह होते थे जो सर्दियों के मौसम में पशुओं के लिए घास पेंदा करने के लिए पर्याप्त होते थे। जमीन के ऐसे टुकड़ों को, जो न तो खेती योग्य होते थे और न ही चरागाह के रूप में काम आ सकते थे, 'वेकार भूमि' माना जाता था। इस वेकार भूमि को, कुछ प्रतिबन्धों के अन्तर्गत, मेनर के ही निवासी काम में लेते थे।

(4) स्वामित्व—मेनर का स्वामी अक्सर कोई बहादुर (knight) सरदार, काउण्ट, ड्यूक या बिशप या फिर स्वयं सम्राट ही हुआ करता था। कुछ अधिक प्रभावशाली तथा सम्पन्न स्वामियों के पास कई जागीरें (manors) होती थी जो कई क्षेत्रों में बिखरी हुई होती थी। मेनर या जागीर फीफ (Fief) का एक भाग होते थे। भू-स्वामी से ऊपर की आठ सम्बन्धों में सामन्तीपन था जब कि भू-स्वामी से नीचे के लोगों में सम्बन्धों का ढाँचा मेनोरियल रीति-रिवाजों पर आधारित था। ये मेनोरियल रीति-रिवाज बम तो सामन्ती व्यवस्थाओं से काफी मिलते-जुलते थे किन्तु फिर भी कुछ मानों में भिन्न थे। मध्य युग से पहले की मेनोरियल आवादी मुख्य रूप से कृषि-दासों (serfs) की थी। लेकिन ये कृषि-दास गुलाम नहीं थे। इनको खरीदा या बेचा

नहीं जा सकता था। ये कृषि-दास बोई चल-सम्पत्ति (chattel) या बिक्री योग्य वस्तु नहीं बल्कि व्यक्ति माने जाते थे। फिर भी कृषि-दासों को पूर्ण रूप से स्वतन्त्र व्यक्ति का दर्जा भी प्राप्त नहीं था। जब भूमि का स्वामित्व बदलता था तो जमीन के साथ कृषि-दास भी नये मालिक को मिला जाते थे। कृषि दास सम्पत्ति रखने के लिए, 'यहाँ तक कि शादी करने के लिए भी स्वतन्त्र नहीं थे। इसके अलावा इन कृषि-दासों को अपने स्वामी (lord) के प्रति अनेक कर्तव्यों का निर्वाह करना होता था।

(5) बड़ा भाग स्वामी का—मेनर या जागीर का बहुत बड़ा भाग—कई बार आधा या उससे भी अधिक—लॉर्ड के लिए आरक्षित होता था। लॉर्ड के अधीन मेनर की भूमि डिमेन (demesne) या 'कार्य-क्षेत्र' कहलाती थी। इस क्षेत्र में सिंचित भूमि के अलावा, चरागाह व जंगल भी सम्मिलित होते थे। आसामियों के लिए यह एक प्रकार से अनिवार्य था कि वे डिमेन पर कृषि का काम देखें। लॉर्ड व उसका परिवार डिमेन से प्राप्त उत्पाद पर ही ऐश-आराम की जिन्दगी बसर करते थे।

(6) वस्तु-विनिमय प्रथा—मध्ययुगीन मेनर पर प्राकृतिक अर्थव्यवस्था प्रचलित थी। वस्तुओं के बदले वस्तुएँ विनिमय की जाती थी तथा मिल वाले, लुहार व गाँव के अन्य कारीगरों की सेवाओं के बदले उन्हें अनाज, ऊन, अण्डे व ऐसी ही अन्य वस्तुएँ दी जाती थी।

(7) कृषि-दास प्रथा—मेनर की भूमि को दो भागों में विभाजित किया जाता था डिमेन या आन्तरिक भूमि जिस पर लॉर्ड का अधिकार रहता था तथा कृषि-दास भूमि या बाह्य भूमि जो कृषि दासों को बाँटी हुई होती थी। इन कृषि-दासों के पास अपनी भूमि के लिए कोई बंधपट्टा नहीं होता था। उस भूमि पर उनका अधिकार केवल परम्परा से था जबकि कानूनन वह भूमि लॉर्ड की मानी जाती थी। लॉर्ड उन्हें बेदखल कर सकता था। कृषि दासों की प्रत्येक चीज डिमेन का ही भाग मानी जाती थी।

(8) आत्म-निर्भरता—मेनर का काम-काज आत्म-निर्भरता के आधार पर चलता था। यह धारणा प्रचलित थी कि एक मेनर में उन सब चीजों का उत्पादन किया जाना चाहिए जिनकी कि जरूरत पड़ती है और यह भी कि जो कुछ पैदा किया जाये उसका वही के निवासियों द्वारा उपभोग कर लिया जाना चाहिए। बाह्य व्यापार को अवाञ्छनीय माना जाता था तथा उसे कम से कम रखने पर बल दिया जाता था। पूर्ण आत्म-निर्भरता तो खैर कभी प्राप्त नहीं हो पाती थी किन्तु हाँ एक मेनर द्वारा बहुत बड़े असर तक आत्म-निर्भरता प्राप्त कर ली जाती थी। मेनर के लोग अपने गेहूँ स्वयं पीमते थे, वे अपना मूत खुद कातते थे, अपना कपड़ा खुद बुनते थे तथा पशुओं की खासों को नम चमड़े में बंद कर अपने जूते भी खुद बनाते थे। किन्तु रेशम, मुँद्री, कीलिया तथा नमक आदि जैसी चीजों के लिए उन्हें अन्य लोगों पर आश्रित रहना पड़ता था। इस तरह पूर्ण आत्म-निर्भरता तो मेनर या एक जागीर के लिए अप्राप्य लक्ष्य ही बनी रहता था किन्तु बाहरी जगत् के साथ कम से कम व्यापार को अच्छे प्रबन्ध की निशानी माना जाता था।

(9) आजाद और गुलाम—एक मेनर की आबादी को स्वतन्त्र और बन्धन

युक्त लोगों की दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। मुक्त लोगों में मेनर का स्वामी अर्थात् लॉर्ड, उसका कारिन्दा (bailiff), गाँव का पादरी तथा कुछ अन्य लोग आते थे। बन्धन युक्त (unfree) लोगों में आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण वर्ग आता था क्योंकि मेनर के लिए श्रम की पूर्ति का स्रोत वही था। यही लोग लॉर्ड के अधिकार वाली भूमि डिमेन को जोतते थे। इन बन्धन युक्त लोगों को विलेन (villeins) या कृपिदास भी कहा जाता था। इनमें दूसरी श्रेणी के लोग को बोरदार (bordars) कहा जाता था जिनकी हालत विलेन से कुछ खराब होती थी।

एक पूर्ण-विलेन (कृपिदास) के पास एक विरगेट (virgate) भूमि अर्थात् लगभग 30 एकड़ जमीन होती थी जबकि अर्द्ध-विलेन के पास 15 एकड़ जमीन ही होती थी। बोरदार के पास तो और भी कम जमीन होती थी—एक एकड़ से लेकर पाँच एकड़ तक। प्रत्येक विलेन को लॉर्ड की भूमि पर सप्ताह में दो-तीन दिन तक काम करना पड़ता था तथा वह अपने मेनर को लॉर्ड की अनुमति के बिना नहीं छोड़ सकता था। लॉर्ड को विलेनस (कृपिदासों) पर कर लगाने का अधिकार तो था मगर उसे उन्हें प्राणदंड देने का अधिकार नहीं था। बोरदार (Bordars) के पास न केवल कम भूमि होती थी बल्कि विलेन की भाँति उन्हें तो अपने हल-बैल रखने का भी अधिकार नहीं प्राप्त था। बोरदार लोगों को हर सोमवार लॉर्ड के लिए काम करना पड़ता था। इसीलिये उन्हें कभी-कभी 'सोमवारी आदमी' भी कहा जाता था। विलेनो पर लगे हुए सारे प्रतिबन्ध बोरदारों पर भी लागू होते थे। किन्तु इन कृपिदासों के लिए स्वतन्त्रता प्राप्त कर पाना सम्भव था। बहुत कम मौकों पर ही लॉर्ड किसी कृपिदास को स्वतन्त्रता प्रदान करता था। अक्सर दास लोग अपनी स्वतन्त्रता का क्रय करते थे।

इंग्लैण्ड के आर्थिक इतिहास पर लिखने वालों, जैसे साउथगेट ने निष्ठा है कि कृपि-दासों की स्थिति अत्यधिक पद दलित नहीं थी यद्यपि वह बहुत सन्तोषजनक होने से काफी दूर थी। उनका जीवन स्तर आज के श्रमिक वर्ग के जीवन स्तर से काफी नीचा था। लेकिन उन्हें बेकारी का कोई भय नहीं था। न ही बीमारी या बुढ़ापा उनके लिये अनर्थकारी होता था। अपने कृपि-दासों का दमन करना स्वयं लॉर्ड के हित में नहीं होता था क्योंकि मेनर की समृद्धि सन्तुष्ट कृपि-दासों द्वारा की जाने वाली आवश्यक श्रम की पूर्ति पर ही निर्भर करती थी।

(10) सार्वभौमिक प्रचलन—अपने प्रचलन काल में मेनोरियल प्रथा सार्वभौमिक थी तथा वह सारे देश में पायी जाती थी। यहाँ तक कि मध्ययुगीन कस्बे भी विकसित मेनर ही थे। अपने सगठन व वार्यों की दृष्टि से इंग्लैण्ड भर के मेनर काफी समानता लिये हुए थे। कृपि करने का मुख्य उद्देश्य बाजारों में पूर्ति बढ़ाना नहीं बल्कि जीवन-निर्वाह करना माना था। मेनोरियल प्रथा की सबसे प्रमुख विशेषता लॉर्ड की भूमि डिमेन (demesne) पर कृपि-दासों के श्रम द्वारा खेती किया जाना था। जब कृपि की यह व्यवस्था समाप्त हो गई तब मेनोरियल पद्धति का भी अन्त हो गया।

मेनोरियल पद्धति के हानि-नाम

मेनोरियल पद्धति का सर्वप्रमुख लाभ तो यह था कि उसने एक बड़ी सराया में

लोगों में भूमि के प्रति रुचि जागृत की तथा उम रुचि को स्थायित्व प्रदान किया। इस प्रथा ने हिंसा के उस युग में लोगों को सुरक्षा भी प्रदान की। इसने कृषि के विकास में योगदान मिला तथा हम प्रथा में सहकार व निगम का वह सिद्धान्त निहित था जिस पर मध्ययुगीन समाज आधारित था।¹

लेकिन मेनोरियल प्रथा के कई दोष थे और वे बड़े ही स्पष्ट थे—

(1) छोटे मातृको को भूमि अर्जित करने में भारी कठिनाई होती थी तथा लॉर्ड व उसके कारिन्दे का आसामियों के साथ एकदम मनमाना व्यवहार हुआ करता था।

(2) सामूहिक तौर पर खेती करने की जो परम्परा मेनर में प्रचलित थी उससे बुद्धिमान व उद्यमी व्यक्तियों द्वारा खेती में नये प्रयोग करने में बाधा पड़ती थी। भूमि में किसी भी तरह का सुधार असम्भव-सा था।

(3) सीमा सम्बन्धी झगड़े सामान्य थे तथा एक पट्टी से दूसरी पट्टी तक जाने में बहुत अधिक समय की बर्बादी होती थी।

(4) कृषि के तरीके एकदम आदिम थे तथा उसकी उत्पादकता भी बहुत कम थी। प्रति एकड़ गेहूँ का उत्पादन 1930 के उत्पादन की तुलना में एक-चौथाई से भी कम था। फसलें बहुत कम थीं। बीजों की किस्म बहुत घटिया होती थी तथा कृषि-पद्धतियाँ एकदम पुरातनपन्थी थीं।

(5) जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग अभावग्रस्त था, यहाँ तक कि बहुत से लोग भूखे रहते थे।

(6) ग्रामीण जीवन में एकरसता और उत्पीड़न था। मकान तग और गन्दे थे, खाना बेस्वाद होता था तथा मजदूरी बहुत कड़ी व थकाने वाली होती थी।

कृषिदास प्रथा का पतन

तेरहवीं शताब्दी के बाद कृषिदास प्रथा का पतन होना आरम्भ हो गया। कुछ कृषिदासों को मानवीय या धार्मिक आधारों पर स्वतन्त्र कर दिया गया। अनेक कृषि-दासों को मेनर छोड़कर जाने की अनुमति इस शर्त पर दे दी गई कि वे मामूली-सा व्यक्ति कर (poll-tax) चुकाते रहेंगे। अधिक हिम्मत वाले कृषिदास भागकर दूर के कस्बों या जागीरों में जा बसे। काला बुखार, श्रमिकों के बारे में इस अवधि में बनाये गये अनेक विधेयक तथा चौदहवीं शताब्दी में हुए किसान बिप्लव (peasant's rebellion) जैसे कारणों ने मिलकर कृषिदासों के स्वतन्त्र होने की गति को और भी तेज कर दिया। सोलहवीं शताब्दी तक तो कृषिदास प्रथा (serfdom) का कोई व्यावहारिक अर्थ रह ही नहीं गया था। कृषिदास प्रथा के इंग्लैण्ड में पराभव के सम्बन्ध में लाजबाब बात यह रही कि देश में इस प्रथा को कभी भी कानून पास करके औपचारिक रूप से समाप्त नहीं किया गया और न ही इसे समाप्त करने के लिए स्थानीय इकाइयों ने कोई विधेयक पारित किये। कृषक समुदाय को मेनोरियल या जागीरदारी करो व भुगतानों से केवल इसलिए ही छूट

¹ W J Ashley, *Introduction to English Economic History and Theory*,

मिलती चली गयी कि वे पुराने पड चुके थे या किसी काम के नहो रह गये थे। स्वयं जमींदारो (Jords) ने ही उन करो या भुगतानो की अनुपालना पर जोर देना बन्द कर दिया था। जब कृषि श्रमिको को उनकी मजदूरी के बदले नकद मिलने लगा तथा जब कृषिदासो पर भगी ढेर-सारी पाबन्दियो की अनुपालना असम्भव-सी हो गयी तो कृषिदास कृषि श्रमिको के ही एक विशाल भाग का श्रमिन्न अंग बन गये।¹

मेनोरियल प्रथा का अन्त

चौदहवीं शताब्दी के अन्त तक यह स्पष्ट हो चुका था कि मेनोरियल पद्धति की कोई उपयोगिता नही रह गयी थी तथा यह प्रथा कटक लगने लगी थी। ब्रिटिश आर्थिक इतिहास के प्रमुख लेखको साउथगेट तथा ऑग व सार्प ने तीन मुख्य तत्त्वो का उल्लेख किया है जो मेनोरियल पद्धति के अन्त के लिए उत्तरदायी कहे जा सकते है।

(1) श्रमिको को नकद-भुगतान—श्रमिको की सेवाओ के बदले नकद देने की प्रथा जिसे रूपान्तरण (commutation) या परिवर्तन प्रणाली के नाम से जाना जाता था तथा जो 13वीं शताब्दी के बाद सामान्य बन गयी, मेनोरियल व्यवस्था के अन्त मे एक सहयोगी कारण बनी। रूपान्तरण प्रथा का आरम्भ तो भू-स्वामी तथा आसामियो के बीच लेन-देन की सुविधा के लिए हुआ था। आसामियो ने उनके हिस्से मे आने वाले वस्तु-भुगतान के दायित्वो तथा अन्य सेवा सम्बन्धी दायित्वो का निपटारा नकद राशि भू स्वामी को देकर करना शुरू कर दिया तो इस पद्धति को रूपान्तरण (commutation) का नाम दिया गया। भू-स्वामी को अपने आसामियो से जो नकद राशि इस प्रकार मिलती थी उससे वह मजदूरी देकर श्रमिको को काम पर रखने लगा जिनसे अधिक कुशल काम लेना भी सम्भव था तथा जिससे भू-स्वामी की कृषि क्रियाओ मे अधिक लोचशीलता भी आ जाती थी। दूसरी तरफ आसामियो को नकद दे देने से जब भू-स्वामी की बेगार मे छुटकारा मिल जाता था तो वे अपना ध्यान उनकी अपनी जमीन, पशुओ या मुर्गीपालन पर केन्द्रित कर सकत थे।

इस तरह रूपान्तरण की प्रथा 13वीं सदी के बाद धीरे-धीरे किन्तु निश्चित रूप से प्रगति करती गयी। इस प्रथा को एक स्वतन्त्र श्रमिक वर्ग के उदय तथा नकद मुद्रा के प्रचलन मे तीव्रता से और भी प्रोत्साहन मिला। किसान की स्थिति लगभग बाज लगान देने वाले व्यक्ति जैसी हो गयी। ये रूपान्तरित भुगतान (commuted payments), जो एक बार निश्चित कर दिये जाते थे, एक पवित्र अनुबन्ध का रूप ले लेते थे तथा उन्हें लगभग नही के बराबर बदला जाता था। धीरे-धीरे मुद्रा की क्रय शक्ति घटने के साथ ये अनुबन्ध किसानो के लिए लाभ का सौदा बन गये। अन्त मे, यद्यपि इसके पीछे कोई मुनिश्चित योजना नही थी, मेनोरियल सम्बन्धो मे ह्रास आता चला गया तथा वे मृतप्राय हो गये व कृषिदास (serfs) मुक्त आसामी (free tenants) बन गये।

(2) डिमेन (Demesne) खेती का परित्याग—लॉर्ड की व्यक्तिगत भूमि

¹ Cheyney, *Industrial and Social History*, 1920, 113

डिमेन से विमुख होते चले जाने, बड़ी ज़मीनों का विकास होने तथा सहवर्ती ज़मीनों की बाड़ाबन्दी (enclosure) जैसी प्रवृत्तियों ने भी मिलकर उन दूसरे तत्त्व को जन्म दिया जो इंग्लैंड में मेनोरियल पद्धति के विपरीत का कारण बना। जब मेनोरियल प्रणाली अपने चरमोत्कर्ष पर थी तब लॉर्ड्स को अपनी भूमि डिमेन (demesne) पर कृषि का काम प्रत्यक्ष रूप से लॉर्ड्स द्वारा अपने कारिन्दे (bailiff) की देख-रेख में कृषिदासों के लिए निर्धारित थम के सहारे करवाया जाता था। भू-स्वामी या लॉर्ड्स का मुनाफा उस भूमि से उत्पन्न होने वाली वस्तुएं होती थी जिनका वह उपभोग करता था या जिनको बेचता था। तेरहवीं शताब्दी के बाद, जब सेवाओं को नकद रकम में रूपान्तरित करने की प्रथा चल निकली, तो लॉर्ड्स की अपनी भूमि पर मजदूरों का अधिकांश काम भाड़े के मजदूरों द्वारा किया जाने लगा।

1348-50 के वर्षों में आये काले बुखार की महामारी में इंग्लैंड की जनसंख्या 40 लाख से घटकर सिर्फ 25 लाख रह गयी। इसके परिणामस्वरूप थमिकों का अभाव हो गया तथा उनकी मजदूरी में 50% की वृद्धि कर दी गयी। रूपान्तरण (commutation) की वजह से लॉर्ड्स को कृषिदासों के अनिवार्य थम या बेगार से पहले ही हाथ धोना पड़ गया था। अब मजदूरी में वृद्धि से उसके लिए भाड़े के मजदूरों को काम पर लगाना और भी अव्यावहारिक हो गया। एक शब्द में कहा जाए तो मध्ययुगीन मेनर या जागीर का थम सगठन टूट चुका था।¹ इस स्थिति ने भू-स्वामियों को अपनी जमीन आसामियों को लीज (lease) पर देने के लिए मजबूर कर दिया। यहाँ तक कि आसामियों को आकर्षित करने के लिए भू-स्वामी वीज व अन्य चीजें देने लग गये। जहाँ तक सम्भव होता एक भू-स्वामी या लॉर्ड अपनी सारी की सारी जमीन एक ही आसामी को लीज पर देता था। कभी-कभी जमीन को कई आसामियों के बीच बाँटना जरूरी हो जाता था।

पूर्ण स्वामित्व वाले आसामियों (freeholders) जो अपनी जमीन सम्राट से प्रत्यक्ष प्राप्त करते थे तथा आंशिक स्वामित्व वाले आसामियों (copyholders), जिन्हें अपनी जमीन पर तब तक बने रहने का अधिकार था जब तक वे लगान (quitrent) देते रहें, की तुलना में डिमेन पर काम करने वाले आसामी, जो लीज-धारी (leaseholders) कहलाते थे, जमीन को लॉर्ड्स से कुछ निश्चित शर्तों पर पूर्व निर्धारित अवधि के लिए प्राप्त करते थे। आरम्भ में ये लीजधारी आसामी (अर्थात् सत्रहवीं शताब्दी तक) अपने लगान वस्तुओं के रूप में अदा किया करते थे किन्तु बहुत जल्द ही उन्होंने भी अपने लगान को मुद्रा में रूपान्तरित करवा लिया। इस तरह भू-स्वामी पूरी तरह से आधुनिक किस्म वाला लॉर्ड बन गया जो अपने लीज-धारियों द्वारा अदा किये जाने वाले मौद्रिक लगान से अपना काम चलाता था। यही लीजधारी आसामी, जो अपना लगान मुद्रा के रूप में अदा करते थे, बाद में स्वतंत्र लगान देने वाले किसानों के रूप (free renting farmers) में सामने आये।

मेनोरियल पद्धति के कमजोर पड़ते जाने तथा डिमेन से तो लॉर्ड्स की भूमि

¹ R. H. Tawney, *The Agrarian Problem in the Sixteenth Century*, 1912, Part I, (full description of the process)

पर दासों द्वारा कृषि) की प्रथा के परित्याग का एक प्रभाव यह भी हुआ कि कृषि जोतों के आकार में असमानता अत्यधिक बढ़ गई। महनती और अपनी कमाई बचाकर चलने वाले आसामियों को भू-स्वामी लोग अपनी अधिक से अधिक जमीन लीज पर देते चले गये जिससे उनकी जोतों का आकार अत्यधिक बढ़ा बन गया। भू-स्वामियों को तो सिर्फ अपने लगान से मतलब था। भूमि का इस रूप में कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में केन्द्रीकरण हो जाने से उस पूँजीवादी कृषि की नींव पड़ी जो इंग्लैंड में सत्रहवीं व अठारहवीं शताब्दी में उभरी।

(3) भेड-फार्मिंग के लिए बाड़ाबन्दी—भेड प्रजनन के लिए बाड़ाबन्दी की जो प्रथा चल निकली थी तथा जिसमें खेती योग्य जमीन को चरागाहों में बदलने की आवश्यकता पड़ती थी, ने भी मेनोरियल प्रणाली के टूटने में अपना योगदान दिया। यह प्रक्रिया भी तेरहवीं शताब्दी में ही आरम्भ हुई। पतोंडस के औद्योगिक केन्द्रों में ऊन की बढ़ती हुई मांग ने भेड प्रजनन को एक बहुत मुनाफे वाला व्यवसाय बना दिया था। एक डिमेन के अन्तर्गत जितनी भूमि आती थी वह भेड प्रजनन (sheep farming) के लिए पर्याप्त नहीं होती थी। भेड प्रजनन फार्मों के आकार को बढ़ाने के लिए कुछ भू-स्वामियों (lords) ने अपनी भूमि डिमेन के साथ सामान्य चरागाह तथा बेकार पड़ी भूमि व जगलात वाली भूमि की भी बाड़ाबन्दी कर दी। ग्राम-वासियों के अधिकारों पर यह एक गम्भीर अतिक्रमण था क्योंकि इसके कारण उनको चरागाहों के उपयोग से वंचित होना पड़ा। सिंचित भूमि की छोटी-छोटी व बिखरी हुई पट्टियों (जिन पर पहले कई आसामी खेती करते थे) का पुनर्गठन हो जाने से बनेक आसामियों को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से बेदखल करना पड़ा। इस तरह भूमि से बेदखल किये गये आसामियों की संख्या भी काफी थी। एक बार भूमि से बेदखल कर दिये जाने के बाद ये आसामी भूमिहीन कृषि मजदूर बन गये या आवारागर्दी करने लगे।

तेरहवीं शताब्दी के कानूनों ने भू-स्वामियों द्वारा चरागाह, बेकार पड़ी भूमि तथा यहाँ तक कि कृषि-योग्य भूमि की भेड प्रजनन के लिए बाड़ाबन्दी को बंध माना। आसामियों का निर्वाचन या उनकी बेदखली इतनी सामान्य व अन्यायपूर्ण हो गयी थी कि अपने एक प्रार्थना प्रवचन में 1549 में बिशप लेटिमेर ने उनकी इस व्यथा-कथा को अभिव्यक्त करते हुए कहा कि 'जहाँ पहले हमें कई मकान और लोग-बाग खड़े दिखाई देते थे वहाँ अब एक गडरिया और उसका कुत्ता खड़े मिलते हैं।' इस तरह मेनर या जागीरे भेड प्रजनन फार्म बन गये जिन पर केवल भू-स्वामियों का कब्जा था तथा जिनकी देखभाल के लिए कुछ गडरिये रख लिये गये थे।

(4) अन्य तत्त्व—इन उपर्युक्त तीन तत्त्वों के अलावा, जो कि मेनोरियल प्रथा के पतन के लिए उत्तरदायी थे, इंग्लैंड की बढ़ती हुई जनसंख्या ने भी इस पद्धति को दिनातीत अर्थात् पुराना बना दिया क्योंकि मेनोरियल प्रणाली कम जनसंख्या के लिए अधिक उपयुक्त थी। कृषि में विविधता तथा कानून और व्यवस्था की स्थिति में निरन्तर सुधारों ने भी मेनोरियल प्रणाली की उपयोगिता समाप्त कर दी। कृषिदासों की स्वतन्त्रता की तरफ प्रगति से मेनोरियल अदालतों (Manorial

courts) का भी पतन हो गया जो पहले जुमानो आदि से लॉर्ड के लिए काफी मुद्रा जुटाती थी।

इस तरह पन्द्रहवीं शताब्दी के अन्त तक मध्ययुगीन मेनोरियल प्रणाली की पूर्ण रूप से समाप्ति हो चुकी थी।

सोलहवीं व सत्रहवीं शताब्दी की कृषि क्रान्ति

अपने मध्ययुगीन स्वरूप से आधुनिक स्वरूप में आने तक ब्रिटिश कृषि का रूपान्तरण होने में जितने बड़े पैमाने पर परिवर्तन हुए हैं उन्हें देखते हुए इसे 'कृषि क्रान्ति' का नाम एकदम सही दिया गया है। सोलहवीं तथा सत्रहवीं शताब्दी में इंग्लैंड में घटित होने वाली इस कृषि क्रान्ति की मुख्य विशेषताएँ निम्न थी—

(1) बाड़ाबन्दी आन्दोलन (enclosure movement) जिससे विनाश भेड़ विकास फार्मों (sheep raising farms) की स्थापना हुई तथा जिनसे मेनोरियल प्रणाली का अन्तिम रूप से विघटन हुआ।

(2) समुदाय भावना का ह्रास तथा उसके स्थान पर व्यक्तिवाद की भावना का विकास भी वह तत्त्व था जिसने श्रेणियों (gilds) तथा जागीरों (manors) के पतन को और भी तेज कर दिया। स्वहित के दावे अधिक महत्वपूर्ण बन गये तथा मध्य युग में प्रचलित मिल जुलकर काम करने की भावना के स्थान पर प्रतिस्पर्धा की भावना अधिक जोर पकड़ती चली गई। परम्पराओं का स्थान शुद्ध व कोरी व्यावसायिकता ने ले लिया।

(3) 'मुनाफे के लिए खेती' कृषि का मूलमन्त्र बन गया। ऐसा सोलहवीं शताब्दी से हुआ। इस शताब्दी से पहले कृषि का मुख्य उद्देश्य जीवन निर्वाह (subsistence) करना मात्र था।

(4) इस अवधि में भूमि के पुनर्गठन (consolidation of land) के कारण रोजगार में कुछ कमी आयी होगी तथा कुछ छोटे किसानों की बेदखली भी हुई होगी किन्तु कुल मिलाकर इस प्रवृत्ति से कृषि अधिक लाभकारी व्यवसाय बन गयी।

(5) चरागाह खेती (pasture farming) न केवल बड़े भू-स्वामियों के बीच अधिक लोकप्रिय हुई बल्कि वह उन लीजधारियों (leaseholders) में भी लोकप्रिय हो गयी जिन्होंने लीज पर बड़ी मात्रा में भूमि ले रखी थी। बड़े लीजधारियों ने यह महसूस कर लिया कि भेड़ों के फार्म स्थापित करना फसलों उगाने से कहीं अधिक लाभप्रद है।

(6) उन ग्रामीण प्रदेशों से जनसंख्या का ह्रास अधिक तीव्र हो गया जहाँ भेड़ पालन तेजी से किया जाने लगा था। अधिकांश लोगों को अपने-अपने मेनर छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा क्योंकि अब उन्हें भेड़ पालन के उद्देश्य से चरागाहों में रूपान्तरित कर दिया गया था।

(7) भू-स्वामियों द्वारा सोलहवीं शताब्दी में बहुत ऊँचे लगानों की माँग की जाने लगी तथा इस अवधि में उनका यह तालच बढ़ता ही गया। इन वर्षों में मूल्यों के बढ़ने के कारण भी लगानों में और वृद्धि हुई।

(8) आबारागर्दी काफी आम बात हो गयी क्योंकि जो लोग मेनर छोड़-छोड़कर जाने के लिए बाध्य हो गये थे उन्हें तुरन्त काम नहीं मिला और वे रोटी तक माँगकर खाने के लिए मजबूर हो गये। कगाली (pauperism) एक गम्भीर समस्या बन गयी तथा राज्य को बाध्य होकर इस समस्या का मुकाबला करने के लिए एक मुनिश्चित नीति तैयार करनी पड़ी।

(9) गरीबों में बढ़ते हुए असन्तोष की अभिव्यक्ति विप्लवों (revolts) के रूप में हुई। कृषि-असन्तोष ने इंग्लैंड में 1549 में हुए विद्रोह में देशद्रोहियों की संख्या बढ़ाने में काफी सहायता की।

(10) 1487 में इस प्रकार के विद्रोह जाये गये जिनमें सिंचित भूमि का चरागाहों में रूपान्तरण करने पर रोक लगा दी गई। इस तरह नये-नये रूपान्तरित किये गये चरागाहों को पुनः सिंचित खेतों में बदल दिया गया।

(11) धार्मिक मठों के समापन पर देने से देश की एक-तिहाई कृषि-भूमि आम लोगों के हाथों में पहुँच गई। ये भूमि के नये स्वामित्व वाले लोग अपनी भूमि को श्रद्धा बेचते रहते थे। ये लोग नये विचारों वाले लोग थे तथा इनका एकमात्र उद्देश्य कृषि से प्राप्त होने वाले लाभ को लगान की दरे चढ़ाकर बढ़ाते रहना था। पुरानी परम्पराओं को अस्वीकार करते हुए इन लोगों ने भेड़ पालन पर अधिक बल दिया व उसकी शुरुआत की।

ये सारे परिवर्तन जो ब्रिटिश कृषि में ट्यूडर (Tudor) काल में हुए, तत्कालीन लेखकों द्वारा बढ़ा-चढ़ाकर बताये गये। किन्तु, इन अतिशयोक्तियों के उपरान्त, ब्रिटिश कृषि के तीव्र तरीकों, उद्देश्यों तथा संगठन के क्षेत्र में इस अवधि में हुए ये परिवर्तन इतने महत्वपूर्ण अवश्य थे कि उनसे आधुनिक युग का आरम्भ होने की बात स्वीकार की जा सकती है।

ब्रिटिश कृषि की कायापलट : 1700-1850

आमतौर पर सत्रहवीं शताब्दी को ब्रिटिश कृषि के इतिहास में जड़ता का युग माना जाता है। तबकि चाहे इस युग में कृषि के रूपान्तरण या कायाकल्प की गति चाहे धीमी अवश्य पड़ गई हो, वह एकदम रुकी नहीं थी। बाढ़ाबन्दी आन्दोलन (enclosure movement) के विपरीत उठाये गये आपत्तियों—कि इससे जनसंख्या उजड़ती है, कगाली तथा अकाल का खतरा पैदा होता है—का कोई विशेष महत्व नहीं रह गया था। यहाँ तक कि सत्रहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में एक निश्चित मात्रा में कृषि भूमि का पुनर्गठन तथा बाढ़ाबन्दी भी की गई थी। बहुत सारी बेकार पड़ी भूमि (waste land), जिन पर अब तक कोई मैती नहीं की गई थी, का भी पुनर्ग्रहण किया गया तथा कृषि में सुधार करने के उद्देश्य से वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाने के बारे में भी प्रयास किये गये।

कृषि-क्रान्ति से तुरन्त पहले अर्थात् 1750 के आस-पास खुली-खेत प्रणाली (open-field system) लगभग आधे इंग्लैंड में मौजूद थी। इस प्रणाली में भूमि का बहुत दुरुपयोग होता था क्योंकि प्रति वर्ष तीन खेतों में से एक खेत को

बेकार छोड़ दिया जाता था, अर्थात् उस पर खेती नहीं की जाती थी। अठारहवीं शताब्दी में जनसंख्या भी तेजी से बढ़ रही थी जिससे खाद्यान्नों की माँग बढ़ने लगी तथा उनकी कमी पैदा होने लगी। इसका परिणाम यह हुआ कि खाद्यान्नों के मूल्य बढ़ने लगे और यह अनिवार्य हो गया कि उनके उत्पादन में वृद्धि की जाये। यह उत्पादन की वृद्धि पुराने तरीकों से सम्भव नहीं थी।

ब्रिटेन में जनसंख्या वृद्धि

(जनसंख्या सारो में)

वर्ष	जनसंख्या	वर्ष	जनसंख्या
1760	108	1870	316
1780	126	1880	350
1800	157	1890	382
1810	179	1900	415
1820	210	1910	452
1830	241	1920	428
1840	269	1930	448
1850	275	1950	506
1860	291		

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि इंग्लैण्ड की जनसंख्या 1760 से 1820 की 60 वर्षों की अवधि में दुगुनी तथा 1860 में 1760 की तुलना में तिगुनी हो चुकी थी। जनसंख्या के इस बढ़ते हुए दबाव की स्थिति में एक एकड़ भूमि भी बेकार करना सम्भव नहीं रह गया था। भूमि का पुनर्गठन (consolidation) तथा बाड़ों-बन्दी (enclosure) अनिवार्य बन चुके थे। 1801 में एक सामान्य बाड़ाबन्दी अधिनियम (Enclosure Act) पारित किया गया। खुले खेत समाप्त हो गये तथा ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों के चारों ओर बाड़ें लगा दी गयीं।

इंग्लैण्ड में कृषि-क्रान्ति होने से पहले वहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में समाज तीन श्रेणियों में बँटा हुआ था—

- (i) मेनोरियल लॉर्ड्स या जागीरदार,
- (ii) पूर्ण स्वामित्व वाले किसान (Small Freeholders), तथा
- (iii) श्रमिक।

उन्नीसवीं शताब्दी में इन श्रेणियों के सदृश अनुरक्षक (squire), आत्मायी कृषक (tenant farmers) व श्रमिक हुआ करते थे।

भूमि के पुनर्गठन तथा बाड़ों (enclosures) की स्थापना से कृषि में नये प्रयोगों को प्रोत्साहन मिला। अठारहवीं शताब्दी में खेती के काम में लिए जाने वाले पशुओं की नस्ल में सुधार पर भी काफी ध्यान दिया गया। गौ मास का उत्पादन करने के लिए बैलों की नस्ल तैयार की गई। अठारहवीं शताब्दी में इन बैलों की नस्ल में सुधार से उनका वजन दुगुना हो गया। इसी तरह भेड़-मास तथा ऊन के लिए भेड़ों का प्रजनन किया गया। भेड़ों की नस्ल-सुधार के प्रयासों से इसी अठारहवीं शताब्दी में

उनका वजन तिगुना हो गया तथा उनसे प्राप्त होने वाली ऊन के भार में तो और भी अधिक वृद्धि हुई।

कृषि करने के तरीकों में सुधार के प्रयासों को राजकीय आश्रय दिया गया। सम्राट जॉर्ज तृतीय ने कृषि-सुधारों में इतनी अधिक रुचि ली कि लोग उसे स्नेहवश कृपक जॉर्ज (Farmer George) कहकर पुकारने लगे थे। जेथ्रो टूल द्वारा ड्रिल का आविष्कार किये जाने से दुआई के तरीके में महत्वपूर्ण सुधार हुआ। आर्थर यंग तथा टॉमस कोक जैसे आधुनिकतावादी लोगों ने किसानों को नये एवं आधुनिक कृषि तरीके अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया।

लेकिन ब्रिटिश कृषि में हुए इन परिवर्तनों से बढ़ती हुई जनसंख्या को अधिकाधिक खाद्यान्न उपलब्ध कराने की समस्या का समाधान करने में आंशिक सफलता ही मिल पाई। 1750 के बाद ब्रिटिश जनसंख्या में होने वाली वृद्धि इतनी तीव्र थी कि उन्नीसवीं शताब्दी के लगते ही अनाज का आयात शुरू करना पड़ा। इस तथ्य के बावजूद कि बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए अनाज का आयात अनिवार्य बन गया था, अठारहवीं शताब्दी में इंग्लैंड में हुई कृषि-क्रान्ति ने ब्रिटिश कृषि को यूरोप के अन्य देशों की तुलना में सबसे आगे की कतार में ला खड़ा किया। इंग्लैंड की कृषि तत्कालीन यूरोप में सबसे अच्छी कृषि थी तथा आने वाले कई वर्षों तक वह एक आदर्शस्वरूप बनी रही।

अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में तथा उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में इंग्लैंड में महत्वपूर्ण आर्थिक व सामाजिक उतार-चढ़ाव लाने वाली घटनाएँ घटीं। इन परिवर्तनों को दो मोटी श्रेणियों के अन्तर्गत रखा जा सकता है—(1) कृषि की कार्यापद्धति, तथा (2) उद्योग में क्रान्ति। ऐतिहासिक दृष्टि से देखने पर यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि इन दोनों ही प्रकार के परिवर्तनों में घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। यूरोप के अलग-अलग प्रदेशों में कृषि-क्रान्ति के भिन्न-भिन्न अर्थ लगाये गये। इंग्लैंड में कृषि-क्रान्ति का जो अर्थ लगाया गया उसे ऑग व शार्प¹ ने निचोड़ के रूप में इस तरह अभिव्यक्त किया है 'भूमि पर स्वामित्व तथा नियन्त्रण का घटते हुए भूस्वामियों के हाथों में केन्द्रीकरण, सामान्य भूमि की बाढाबन्दी (enclosure) के आन्दोलन का नवीनीकरण (जिन भूमि का उपयोग आसामी लोग अपने जीवन-निर्वाह के लिए खेती करने के आदी हो चुके थे), बड़ी संख्या में आसामियों तथा छोटे भू-पतियों का धर्मिक वर्ग में प्रवेश तथा अनेक लोगों का कृषि-व्यवसाय से पूरी तरह निष्कासन—यही इंग्लैंड की कृषि-क्रान्ति का आशय था।

ब्रिटिश कृषि की यह कार्यापद्धति, जिसे अनेक लेखकों ने कृषि-क्रान्ति का नाम दिया है, अठारहवीं शताब्दी के अन्तिम वर्षों में प्रारम्भ हुई थी तथा उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में तो बहुत कुछ महत्वपूर्ण घटित हो चुका था।

ब्रिटेन में हुई क्रान्ति की व्याख्या करते समय केवल इसी तथ्य का ध्यान रखा जाना पर्याप्त नहीं है कि अठारहवीं शताब्दी में इंग्लैंड में आर्थिक दशाएँ अनुकूल थीं बल्कि इन तथ्यों को भी ध्यान में रखना होगा कि यह क्रान्ति भू-स्वामियों के

विशेषाधिकारों के उन्मूलन के लिए नहीं की गयी थी तथा न ही इसका उद्देश्य लोगों को आर्थिक अथवा सामाजिक मुक्ति दिलाना या उन्हें अधिक राजनीतिक शक्ति प्रदान करना ही रहा था। ब्रिटेन की कृषि-क्रान्ति किसी अचानक फट जाने वाले विप्लव का परिणाम नहीं थी जैसा कि प्रायः 'क्रान्ति' शब्द के साथ आभास होता है। वास्तव में वर्ग आन्दोलन नहीं था। यह तो केवल उन स्वाभाविक धीरे धीरे परिपक्व होने वाली दशाओं का प्रतिनिधित्व करती है जिनसे ब्रिटिश कृषि की वायापलट हुई थी।

ब्रिटिश आर्थिक परिवर्तनों पर लिखते हुए आर्थर बिर्नी¹ ने कहा है कि इस अवधि में कृषि करने के तरीकों में तीन मुख्य परिवर्तन हुए (1) जल-निकास (drainage) की पद्धति में सुधार, (2) कृत्रिम रासायनिक खादों की खोज, (3) कृषि मशीनों का आविष्कार। ब्रिटिश कृषि-क्रान्ति ने अपने आपको त्रिविध रूपों में प्रस्तुत किया है किन्तु उसके मूल तत्त्व निम्न रहे हैं—

(1) कृषि में पूँजी का प्रयोग—अठारहवीं शताब्दी में इंग्लैण्ड में पूँजीवाद का विकास एक आधारभूत आर्थिक तथ्य रहा है। पूँजीवाद के अभ्युदय ने न केवल वहाँ के उद्योग और व्यापार को प्रभावित किया अपितु उसने कृषि पर भी अत्यधिक प्रभाव डाला। ब्रिटेन के भू स्वामियों ने मिट्टी की किस्म सुधारने, नई फसलें उगाने के प्रयोग करने तथा कृषि करने के तरीकों में सुधार लाने के उद्देश्य से पूँजी का व्यापक उपयोग आरम्भ कर दिया। अधिक सम्पन्न भू स्वामियों ने अपनी पूँजी का एक बड़ा भाग अतिरिक्त भूमि खरीदने, मशीनें तथा खाद का क्रय करने व कृषि करने के नये व महंगे तरीकों को अपनाने के लिए अलग रख दिया। कृषि में इस पूँजी-निवेश का मुख्य मन्तव्य यह था कि कृषि से प्रतिफल की एक निश्चित दर प्राप्त की जा सके—एक ऐसा विचार जिसने उस पुरानी धारणा को एकदम उतार दिया जिसके अनुसार कृषि केवल जीवन-निर्वाह के लिए थी। यहाँ तक कि छोटे किसानों ने भी अपने आप ही कृषि में पूँजी लगाना आरम्भ कर दिया। इससे कृषि में विज्ञान तथा अनुभव से तैयार की गई प्रक्रियाओं का उपयोग काफी बढ गया। साथ ही इसके कारण मनुष्य के स्थान पर मशीनों का प्रयोग आरम्भ हुआ। यह प्रवृत्ति निम्न तालिका से पूरी तरह स्पष्ट होती है—

कृषि जनसंख्या में कमी

वर्ष	कृषि में कुल जनसंख्या का प्रतिशत
1811	34
1821	32
1831	28
1841	22
1851	16
1861	10

¹ A Birnie *An Economic History of Europe 1760-1930*, 1953, 13

कृषि पर आश्रित जनसंख्या के प्रतिशत में आयी इस गिरावट से यह स्पष्ट हो जाता है कि उन्नीसवीं शताब्दी में मशीनों का उपयोग बढ़ने से कृषि मजदूरों की माँग में निरन्तर कमी आती चली गई। पूँजी-प्रधान कृषि की शुरुआत हो जाने से बड़े पैमाने की प्रतिस्पर्धा भी आरम्भ हो गई जिसने छोटे भू-स्वामियों को निवाल बाहर किया तथा भूमि की बड़ी जोनों में केन्द्रीकरण होने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया।

(2) यन्त्रीकरण तथा उन्नत तकनीक का उपयोग—अठारहवीं तथा उन्नीसवीं शताब्दी में घटित ज्ञान ब्रिटिश कृषि-ज्ञान का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू मशीनों के बढ़ते हुए उपयोग के कारण कृषि-तकनीक में होने वाले सुधार थे। कृषि करने की तकनीक में इन सुधारों का उद्देश्य कृषि-उत्पादन को अधिकतम करना तथा उसकी लागत को न्यूनतम करना था। ब्रिटिश किसानों तथा सुधारकों ने नई तकनीकों का प्रयोग तथा जाँच करने में अगुवाई की। टाउनशैंड¹ ने इंग्लैंड में शीतकालीन भूमि के नीचे उगने वाली फसलों को लोकप्रिय बनाया तथा उसने एक नई चार-चक्रीय (Four course Rotation) पद्धति का विकास किया जिसमें परती (fallow) भूमि पर चुकन्दर तथा तिपतियाँ फसलें उगायी जाने लगीं। रॉबर्ट बेकवेल ने पशु-नस्ल सुधार का वैज्ञानिक तरीका खोज निकाला जिससे उसने थोड़े ही समय में भेड़ों व अन्य जानवरों का वजन दुगुना करने में सफलता प्राप्त कर ली। स्काटलैंड के एक किसान डीवस्टन ने पकाई हुई मिट्टी की सिलिण्डर के आकार की ईंटों द्वारा जल-निर्वास की एक नई पद्धति का आविष्कार किया।

कृषि में मशीनों के प्रयोग में एक यन्त्रीकृत फसल बाँधने वाली मशीन (Mechanical String Binder) के आविष्कार से एक नया अध्याय जुड़ा। यह मशीन न केवल अनाज की खड़ी फसल को काटने का काम करती थी बल्कि स्वचालित रूप में उसकी पोलियाँ बाँध देती थी। प्राकृतिक व रासायनिक खाद के उपयोग में भी वृद्धि हुई तथा मिट्टी की किस्म को बदल कर उसे गेहूँ की खेती के लायक बनाने की प्रथा भी सामान्य बन गई। मशीन निर्माण के कारण थम के बचत की नई विधियाँ खोजी गयीं इनमें घोड़े से चलने वाली गाहने की मशीन (Threshing Machine) सबसे प्रमुख थी। अनेक किसान गोप्टियाँ तथा पशु-मेले आयोजित किये जाने लगे। लेवेग तथा अन्य शोधकर्ताओं की रासायनिक खोजों से, जो 1840-49 के वर्षों में हुई, वैज्ञानिक सिद्धान्तों के व्यावहारिक उपयोग को बढ़ावा मिला।

(3) बाड़ाबन्दी (Enclosures) का पुनर्जीवन—कृषि के क्षेत्र में पूँजी तथा मशीनों के बढ़ते हुए उपयोग ने उन अनेक छोटे भू-स्वामियों पर विपरीत प्रभाव डाला जो बड़े भू-स्वामियों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में समर्थ नहीं थे। उधर निर्माण-उद्योग (manufacturing) के विकसित होते चले जाने के कारण छोटे किसानों को कुटीर उद्योगों आदि से प्राप्त होने वाली सहायक आय भी मिलनी बन्द हो गई। बाड़ाबन्दी-प्रथा का फिर से पुनर्जीवित किया जाना तो उनके लिए अन्तिम चोट थी। सामान्य भूमि की बाड़ाबन्दी को फिर से अस्मिन्व में लाने का कारण यह था कि खाद्य वस्तुओं के बढ़ते हुए मूल्यों के कारण कृषि-योग्य भूमि में मित्रों वाला

साभ बढ़ता जा रहा था। इस बार बाढ़ाबन्दी कृषि-भूमि की हुई और उसे अनाज के उत्पादन में प्रयुक्त किया गया। एडम स्मिथ जैसे जाने-माने अर्थशास्त्रियों ने भी बाढ़ाबन्दी प्रणाली (enclosure system) का समर्थन किया और इस तथ्य की तरफ ध्यान आकर्षित किया कि उप-विभाजित तथा खुले खेत वाली प्रणाली से भूमि का दुरुपयोग होता था। एडम स्मिथ ने यह स्पष्ट कर दिया कि ब्रिटिश कृषि का भविष्य बड़े आकार के खेतों में ही निहित है तथा उसमें भारी पूंजी विनियोग की आवश्यकता है। 1836 में पारित किये गये एक विधेयक से इस बात को सम्भव बना दिया गया कि यदि दो-तिहाई लोगों की सहमति हो तो कुछ विशेष प्रकार की सामूहिक भूमि (common lands) की, बिना समद की पूर्वागुमति के, बाढ़ाबन्दी की जा सकती थी। बाढ़ाबन्दी आन्दोलन 1800-1819 की अवधि में चरमोत्कर्ष पर पहुँच गया था जब इंग्लैंड में 30 लाख एकर से भी अधिक भूमि की बाढ़ाबन्दी की गई थी।

इंग्लैंड में भूमि की बाढ़ाबन्दी (Enclosure)

वर्ष	बाढ़ाबन्दी (लाख एकरों में)
1700-1759	34
1760-1769	70
1770-1779	120
1780-1789	45
1790-1799	86
1800-1809	155
1810-1819	156
1820-1829	38
1830-1839	25
1840-1849	35

औसत लघु कृषक पर बाढ़ाबन्दी के विपरीत प्रभाव पड़े। 1801 में आर्थर यंग ने लिखा था कि 'इन बाढ़ाबन्दीयों से गरीब लोगों को चोट लगी थी और कुछ को तो सम्भीर चोट लगी थी।' नकद के रूप में जो मुआवजा दिया गया था वह अपर्याप्त था तथा बाढ़ाबन्दी के विरुद्ध लोगों का विरोध काफी हिंसक रूप लेने लगा। किन्तु इस विरोध का कोई परिणाम नहीं निकला क्योंकि पूंजीगत एवं वैज्ञानिक तरीकों के बढत हुए प्रयोग तथा जनसंख्या में हो रही निरन्तर वृद्धि ने बड़े खेतों को एक प्रकार में अनिवार्य बना दिया था। ऐसी स्थिति में छोटे किसान शहरों की तरफ चल पड़े जहाँ वे समय के साथ फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर बन गये। उनमें से कई समुक्त राज्य अमेरिका चले गये। इस प्रकार छोटे किसानों के वर्ग का पतन हुआ तथा कृषि-क्रान्ति के फलस्वरूप वे पूरी तरह समाप्त हो गये।

(4) भूमि का बड़ी खेतों के रूप में पुनर्गठन—कृषि-क्रान्ति के फलस्वरूप उत्पन्न हुई नई परिस्थितियों में भू-स्वामियों में अधिकाधिक केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति स्पष्ट होती चली गई। औद्योगिक पूंजीपतियों ने भी भूमि के बड़े-बड़े टुकड़े खरीद

लिये जिनसे भूमि के पुनर्गठन की प्रक्रिया में और भी तेजी आ गई। छोटे भू-स्वामी (small freeholders) अपनी जमीनों से पिंड छुड़ाकर खुश ही होते थे। कृषि विपत्ति के युग में तथा उसके बाद 1815 के शान्ति युग में छोटे किसानों द्वारा बेची जाने वाली जमीनों की सख्या अपनी चरम सीमा पर पहुँच गई। 1845 तक केन्द्रीकरण की यह प्रक्रिया अपनी सर्वाधिक गहत्वपूर्ण अवस्थाओं से गुजर चुकी नहीं जा सकती है।¹

एक प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक कनिंघम ने लिखा है कि 'कृषि सुधारों में होने वाली प्रगति ने ग्रामीण समाज में गहरी दरारें पैदा कर अपना निशान छोड़ा। छोटा किसान, जिसे इस संघर्ष में घुटने टेक देने पड़े और भी दया का पात्र था क्योंकि औद्योगिक श्रमिकों की जिस श्रेणी में वह आ जाता था वह तो स्वयं ही घोर कष्ट अधोगति के युग में प्रवेश कर रही थी।'²

इंग्लैंड में हुई कृषि-क्रान्ति के फलस्वरूप तीन स्पष्ट वर्गों का उदय हुआ : (1) भू-स्वामी वर्ग; (2) कृषक लोग जो पूँजीपति के लिए खेत की देखभाल करने मात्र का काम करते थे जिससे कि उसे लाभ देने वाली इकाई बनाया जा सके; तथा (3) खेतीहार मजदूर जो न भूमि के मालिक थे, न उसका प्रबन्ध उनके हाथ में था और जो केवल मजदूरी के बदले में काम करते थे।

1850 के बाद ब्रिटिश कृषि

उन्नीसवीं शताब्दी का तीसरा-चतुर्थांश ब्रिटिश इतिहास का स्वर्ण-युग माना जाता है। यह समृद्धि 1874 तक चली जो अच्छी फसल का अन्तिम वर्ष था। 1875 में 1884 तक फसलें खराब रही तथा मन्दी की छाया पड़नी प्रारम्भ हो गयी। इस तरह ब्रिटिश कृषि पर जो मन्दी छा गई वह प्रथम महायुद्ध तक चलती रही।

इस सम्बन्ध में सबसे पहला मामला 1875 के बाद कृषि के अन्तर्गमन आने वाली भूमि के क्षेत्र में निरन्तर कमी तथा चरागाह के अन्तर्गमन उपयोग में आने वाली भूमि की वृद्धि के रूप में सामने आया।

ब्रिटेन में भूमि का वर्गीकरण

वर्ष	कृषि भूमि	(मिलियन एकड़ में)
		रक्षाधीन चरागाह भूमि
1871	18.4	12.4
1881	17.4	14.6
1891	16.4	16.4
1901	15.6	16.7
1911	14.6	17.4

नेहों की खेती के अन्तर्गमन आने वाले क्षेत्र में भी गिरावट आयी तथा वह 1870 में 3.7 मिलियन एकड़ से घटकर 1903 में मात्र 1.6 मिलियन एकड़ रह गयी।

¹ Porter, *Progress of the Nation*, 1847, 159-60

² Cunningham, *The Industrial Revolution*, 1908, 562

इस कमी से यह स्पष्ट ही है कि कृषि-उत्पादन में भी गिरावट आयी। गेहूँ का उत्पादन, जो 1841-45 के वर्षों में इतना था कि वह देश की 90 प्रतिशत जनता के लिए पर्याप्त था, 1906 में इतना गिर चुका था कि अब वह केवल 11 प्रतिशत जनसंख्या के लिए पर्याप्त था।

ब्रिटिश कृषि में आने वाली इस गिरावट के लिए मुख्य रूप से तीन कारण उत्तरदायी थे—(1) कृषि भूमि के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में एक-चौथाई गिरावट आ जाना, (2) अनाजों के उत्पादन में आयी कमी की पूर्ति मास आदि के उत्पादन में वृद्धि से आंशिक रूप में ही हो पाना, तथा (3) आयातित खाद्यान्नों पर आश्रित जनसंख्या के अनुपात में वृद्धि होना। समुद्री यातायात की सस्ती लागत ने ब्रिटिश कृषि के लिए विदेशी प्रतिस्पर्धा का दरवाजा खोल दिया। उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त में तो ब्रिटिश बाजारों में अमरीकी गेहूँ के अम्बार लग गये। 1875 में 1885 तक की अवधि में कृषि-पदार्थों के मूल्यों में निरन्तर गिरावट भी आयी।

1882 में नियुक्त किये गये शाही आयोग ने स्पष्ट किया कि ब्रिटिश कृषि में मन्दी आने के मुख्य कारण विदेशी प्रतिस्पर्धा, ऊँचे लगान, पशुओं की बीमारियाँ तथा फसलों का खराब हो जाना थे। लॉर्ड एवरस्ते की अध्यक्षता में एक अन्य शाही आयोग 1893-97 में बिठाया गया। अपने प्रतिवेदन में इस आयोग ने बताया कि चांदी के मूल्यों में गिरावट से भू-स्वामियों तथा किसानों को पूँजी का भारी नुस्खाना हुआ है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि श्रैष्ठिक शहरो को प्रस्थान कर रहे थे तथा फलों की खेती, डेयरी फार्मिंग तथा मुर्गीपालन अधिक लाभ वाली कृषि गतिविधियाँ बनते जा रहे थे। ब्रिटिश कृषि का न्यूनतम बिन्दु उन्नीसवीं शताब्दी के समाप्त होने के पहले आ चुका था।

ब्रिटिश कृषि का पुनरुत्थान बीसवीं शताब्दी के शुरू के वर्षों से आरम्भ हुआ जब वहाँ के कृषकों ने यह महसूस किया कि उन्हें अपने आपको नई परिस्थितियों के अनुरूप ढालना होगा। उन्हें यह आशा नहीं रही कि वे खाद्यान्नों का आयात रोकने में सफल हो पायेंगे, इसलिए उन्होंने अपना ध्यान पशुपालन, दुग्ध उत्पादन तथा अण्डे व मक्खन के उत्पादन पर लगाया। इस प्रकार की उत्पादक गतिविधियाँ मूलतः श्रम-प्रधान थीं तथा छोटी-छोटी जाते किसान जो अधिक व्यक्तिगत देखभाल करने की स्थिति में थे, इसमें अधिक सफल हो सकते थे। इसमें देहाती किसानों के एक वर्ग का अभ्युदय हुआ। वैसे बड़े भू-स्वामी छोटी-छोटी जाते वाले आसामियों की सत्ता बढ़ने के खिलाफ थे क्योंकि इससे उनकी परेशानी बढ़ने का भय था किन्तु संसद ने 1908 में छोटी जातें तथा आवंटन सम्बन्धी विधेयक (Small Holdings and Allotments Act, 1908) (तथा 1926 में पुनः इसी विधेयक को संशोधित कर) व 1931 में कृषि भूमि उपयोग सम्बन्धी विधेयक (Agricultural Land Utilisation Act, 1931) पारित कर पाँच एकड़ की छोटी जातें स्थापित करने का रास्ता साफ कर दिया।

प्रथम विश्व-युद्ध (1914-19) के दौरान ब्रिटिश कृषि में अस्थायी तौर पर समृद्धि आयी। यथासम्भव अनाज का देश ही में उत्पादन करने के प्रयासों को बढ़ावा देने से चरागाह के रूप में प्रयुक्त की जा रही भूमि की कृषि भूमि के रूप में

पुनर्स्थापना हुई। देश में पैदा किये गये गेहूँ के ऊँचे मूल्य मिले। 1917 का अनाज उत्पादन अधिनियम (Corn Production Act, 1917) न्यूनतम मूल्य की गारण्टी देने, लगान निश्चित करने तथा कृषि मजदूरी को न्यूनतम मजदूरी दिलाने के उद्देश्य से लाया गया। 1924 के कृषि मजदूरी अधिनियम (Agricultural Wages Act, 1924) ने न्यूनतम मजदूरी के भुगतान को अनिवार्य बना दिया।

द्वितीय विश्व-युद्ध का आरम्भ ब्रिटिश कृषि के लिए नई आशा लेकर आया क्योंकि इंग्लैण्ड अपनी ही भूमि पर अधिक से अधिक अनाज उगाने के लिए बाध्य हो गया। कृषि क्षेत्र लगभग दुगुना हो गया तथा गेहूँ के मूल्यों में भी अत्यधिक वृद्धि हुई। 1942 व 1943 के युद्ध-वर्षों में रिकॉर्ड फसलों का उत्पादन हुआ दूसरे विश्व-युद्ध की समाप्ति पर ब्रिटेन में गेहूँ का उत्पादन व आलू का उत्पादन 1938 की तुलना में दुगुना हो रहा था और भारी मात्रा में चुकन्दर की भी खेती हो रही थी।

सरकार ने भी कृषि में भारी रुचि लेना आरम्भ कर दिया। प्रत्येक काउण्टी में स्थापित युद्ध-कृषि समितियों के अलावा 1941 में एक कृषि सुधार परिषद् स्थापित की गयी जिसका उद्देश्य कृषि में आधुनिक अनुसन्धानों के प्रयोग को बढ़ावा देना था। श्रमिकों का अभाव होने के कारण कृषि श्रमिकों की मानद मजदूरी में निरन्तर वृद्धि की जाती रही यद्यपि वे औद्योगिक श्रमिकों की तुलना में नीचे बने रहे।

दूसरे महायुद्ध के बाद का समय ब्रिटिश कृषि के बारे में लेखे-जोखे से गुरु हुआ। यह अनुमान था कि देश के कुल 60 मिलियन एकड़ क्षेत्रफल में से 48 मिलियन एकड़ का उपयोग कृषि के लिए हो रहा था। ब्रिटिश कृषि में करीब साढ़े बारह लाख लोगो को रोजगार मिल रहा था। कृषि उत्पादन का मूल्य दुगुना हो चुका था और दूसरे महायुद्ध के आरम्भ होने से पहले के 290 मिलियन पौंड मूल्य के मुकाबले वह 580 मिलियन पौंड वार्षिक के स्तर तक पहुँच गया। 1947 में पारित कृषि अधिनियम का उद्देश्य स्थिर एवं कुशल कृषि बनाये रखना था।

द्वितीय युद्ध के बाद की ब्रिटिश कृषि की मुख्य विशेषताएँ

(1) कृषि मूल्यों की गारण्टी तथा नियन्त्रण की नीति का कड़ाई से पालन किया गया। ये मूल्य कृषि मन्त्री द्वारा एक निश्चित अवधि तक के लिए तय किये जाने की व्यवस्था की गयी।

(2) अकुशल खेती के लिए अब कोई स्थान नहीं रह गया था। अकुशल किसानों को उनकी भूमि से वेदखस किया जा सकता था।

(3) भू स्वामी द्वारा अपने आसामी को जमीन से हटा देने के उसके अधिकार को सीमित कर दिया गया। कृषक को इस निर्णय के विरुद्ध मन्त्री को अपील करने का अधिकार दिया गया।

(4) छोटी जोतों का सवाल कृषिगत आधारों पर तय किया जाने लगा न कि सामाजिक मुद्दों पर। इसी को दृष्टिगत रखते हुए 1947 के कृषि अधिनियम में यह व्यवस्था रखी गयी कि उचित लगान पर छोटी जोतें बनी रह सकें ताकि अनुभवी कृषि मजदूर 'नीचे के स्तर से उठकर' कुशल कृषक बन सकें।

(5) 1946 व 1956 में पहाड़ी खेती अधिनियम (Hill Farming Acts) ब्रिटिश संसद द्वारा पहाड़ी खेती की अवनति को रोकने तथा चरागाहों की स्थिति सुधारने (उन्नत रासायनिक खादों का उपयोग बढ़ाकर तथा घटिया चरागाहों में पुनर्बोध डालकर) के उद्देश्य से पारित किये गये। यह करना इसलिए जरूरी था कि ग्रेट, ब्रिटेन में अधिकांश गौ-मांस तथा भेड़-मांस इन्हीं बेल्ज, स्कॉटलैंड तथा उत्तरी इंग्लैंड के पहाड़ी इलाकों से प्राप्त होता है।

(6) ऐच्छिक व सरकारी विपणन व्यवस्थाओं का विकास भी आधुनिक ब्रिटिश कृषि की महत्वपूर्ण विशेषता रही है। 1955 में एक आलू विपणन बोर्ड तथा 1957 में एक अण्डा विपणन बोर्ड स्थापित किया गया। कुछ अन्य कृषि उत्पादों के भी नियन्त्रित रूप में विपणन की व्यवस्था की गई। सूअर उद्योग विकास बोर्ड 1957 में स्थापित किया गया।

(7) बीसवीं सदी के दूसरे चतुर्थांश में कृषि सहकार का भी काफी विकास हुआ। यह सहकार सरकारी विपणन सुविधाओं के साथ-साथ पनपा। किसानों ने अपने क्षेत्रीय या बाउण्टी संगठन बनाये जिनका उद्देश्य कृषिगत वस्तुओं की सहकारी खरीद व बिक्री को बढ़ावा देना था।

पिछले सौ सालों में कृषि के क्षेत्र में आये उतार-चढ़ावों ने व्यक्ति को यह सोचने के लिए बाध्य कर दिया है कि क्या भूमि का निजी स्वामित्व उपयुक्त व्यवस्था है? किन्तु अपने 1947 के कृषि विधेयक में श्रम दल की सरकार ने भूमि का राष्ट्रीयकरण नहीं किया तथा वह निजी स्वामित्व में बनी रही। अकुशल किसानों को उनकी जमीन से निकास देने के अधिकार की भी काफी आलोचना की गई तथा 1958 के कृषि विधेयक ने राज्य से वह अधिकार वापस ले लिया। यह इसलिये किया गया कि आम धारणा यह बनी थी कि अकुशल किसान को राज्य द्वारा बेदखल करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जब वह अपने खेत से पर्याप्त प्रतिफल प्राप्त करने में असफल हो जायेगा तो उसे बाध्य होकर अपना खेत छोड़ना पड़ेगा।

ब्रिटिश कृषि के बारे में नवीनतम स्थिति यह है कि वहाँ की समग्र राष्ट्रीय धारणा में कृषि का प्रतिशत योगदान घटता जा रहा है। 1965 में यह प्रतिशत योगदान 3.3% था जो 1970 में घटकर 2.8% रह गया। 1975 में यह घटकर 2.7% हो चुका था। ऐसा इसलिये हुआ है कि इस दौरान निर्मित माल वाले क्षेत्र में अत्यधिक तेजी से प्रगति हुई है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि कृषि का निरपेक्ष भाग भी राष्ट्रीय उत्पाद में घटा है। राष्ट्रीय उत्पाद में कृषि का निरपेक्ष अंशदान 1965 से 1975 के दस वर्षों में दुगुने से भी अधिक हो चुका है। वह मूल्य की दृष्टि से 1965 के 1027 मिलियन पाउंड के मुकाबले 1975 में 2,527 मिलियन पाउंड का हो चुका था। 1980 तक उसके और भी द्यौड़े हो जाने के अनुमान हैं।

औद्योगिक क्रान्ति

(THE INDUSTRIAL REVOLUTION)

प्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकार अर्नाल्ड टॉयनबी ने 1884 में 'औद्योगिक क्रान्ति' की अभिव्यक्ति का उपयोग उन महान् परिवर्तनों का उल्लेख करने की दृष्टि से सबसे पहली बार किया था जिनसे ब्रिटिश अर्थव्यवस्था का अठारहवीं तथा उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में कायापलट हुआ था। लेकिन 'औद्योगिक क्रान्ति' की अभिव्यक्ति पर यह आपत्ति उठायी जाती रही है कि आर्थिक इतिहास में क्रान्तियाँ अज्ञात रही हैं क्योंकि आर्थिक विकास (economic evolution) की प्रक्रिया सदैव धीमी होती है। दूसरी ओर 'क्रान्ति'¹ का अर्थ होता है—आधारभूत परिवर्तन, एक राजनीतिक क्रान्ति का अर्थ होता है—सरकार का पूरी तरह से बदला जाना (उदाहरण के लिए फ्रांस की 1789 व रूस की 1917 की हिंसक क्रान्तियाँ), एक कूटनीतिक क्रान्ति का आशय होता है—अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में समग्र पुनर्व्यवस्था, एक कृषि क्रान्ति का अर्थ होता है—कृषि की तकनीक व संगठन में परिवर्तन, और एक सामाजिक क्रान्ति का अर्थ होता है—विभिन्न सामाजिक वर्गों की सापेक्षिक स्थिति में परिवर्तन।

इन आधारों को लिया जाय तो यही प्रतीत होता है कि औद्योगिक क्रान्ति न तो आकस्मिक थी और न ही ध्वसात्मक। यह तो एक ऐसा आन्दोलन था जो 150 वर्षों तक चलता रहा। यह उक्ति सही ही है कि जो लोग औद्योगिक क्रान्ति की अवधि में जी रहे थे वे उन महान् परिवर्तनों के प्रति शायद ही चेतन या जागरूक रहे होंगे जो उस समय हो रहे थे। लेकिन, जैसा कि आर्थर बिर्नी ने अपनी पुस्तक 'यूरोप का इतिहास' में लिखा है, यह अभिव्यक्ति एकदम अनुपयुक्त भी नहीं थी। जिन परिवर्तनों का वर्णन औद्योगिक क्रान्ति की अवधि से सम्बन्धित है वे परिवर्तन इतने 'दूरगामी और गूढ़' अपनी अच्छाइयों व बुराइयों के अनूठे मिश्रण में इतने कार्शिक तथा सामाजिक उत्पीड़न व भौतिक प्रगति के मिले-जुले रूप में इतने नाटकीय रहे कि उन्हें बिना किसी अतिशयोक्ति के 'क्रान्तिकारी' कहा जा सकता है। उन्हें क्रान्तिकारी परिवर्तनों का नाम देने से हमें यह बात स्मरण हो आती है कि अठारहवीं तथा उन्नीसवीं शताब्दी के दौरान हुए आर्थिक परिवर्तनों में उससे पहले के युग में हुए आर्थिक परिवर्तनों की तुलना में अत्यधिक तेजी थी तथा सामाजिक उत्पीड़न के रूप में इन दोनों शताब्दियों में हुई आर्थिक प्रगति के लिए जो कीमत

चुकानी पड़ी वह भी पहले की तुलना में बहुत अधिक थी।¹

साउथगेट ने भी यही विचार व्यक्त किया है कि 'किसी क्रान्ति के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह अचानक या हिंसक हो, वह धीरे-धीरे और यहाँ तक कि न दिखायी पड़ने वाली अर्थात् अगोचर भी हो सकती है' औद्योगिक क्रान्ति औद्योगिक प्रणाली में आये हुए परिवर्तनों से सम्बद्ध थी, हाथ से काम करने के स्थान पर मशीनों (जिन्हें शक्ति से चलाया जाने लगा था) द्वारा काम तथा औद्योगिक सगठन की दृष्टि से घरों में काम करने के पुराने तरीके की जगह फैक्ट्रियों में काम औद्योगिक क्रान्ति का परिचायक थे। इन नयी परिस्थितियों में उद्योग का उद्देश्य बड़े पैमाने पर उत्पादन करना बन गया था, एक सीमित व स्थायी बाजार के लिए ही उत्पादन करने के पुराने आदर्श के स्थान पर अब सस्ता व भारी मात्रा में उत्पादन करने का निश्चय प्रतिस्थापित हो चुका था। इसका उद्देश्य उन बाजारों तक चीजें पहुँचाना था जो राष्ट्रीय सीमाओं से बाहर भी पहुँचते थे और यहाँ तक कि विश्व-व्यापी बन चुके थे।¹ श्रीमती नॉर्वेल्ले ने सारी वस्तु-स्थिति का निचोड़ अपने इस कथन में बड़े ही सुन्दर तरीके से प्रस्तुत किया है कि 'औद्योगिक क्रान्ति जैमी अभिव्यक्ति का प्रयोग इसलिए नहीं किया जाता कि परिवर्तन की प्रक्रिया बहुत तीव्र थी बल्कि उसका प्रयोग इसलिए किया जाता है कि जब वे पूर्ण हो गये तब वे परिवर्तन आधारभूत थे।' श्रीमती नॉर्वेल्ले ने आगे लिखा है कि 'बैसा देखा जाय तो औद्योगिक दशाओं में क्रान्तिकारी परिवर्तन आ गया था किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि वे अचानक बदल गयी थी।'²

लेकिन जैसा कि आर्थर बिर्नी ने लिखा है कि 'औद्योगिक क्रान्ति' की अभिव्यक्ति एकदम अनुपयुक्त नहीं है, उस दृष्टि से यह कहना ठीक होगा कि इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रान्ति की सबसे महत्वपूर्ण बात यही रही कि उससे देश में आर्थिक विकास की गति तीव्र होने में बहुत सहायता मिली। 1781 से 1913 तक के बीच इंग्लैंड में जो आर्थिक विकास की दर रही वह 1700 से 1780 तक की आर्थिक विकास की दर की तुलना में तीन गुना थी। अमरीकी अर्थशास्त्री प्रो० डब्लू० डब्लू० रोस्टोव ने अनुमान लगाया है कि ब्रिटिश अर्थव्यवस्था ने स्वयं स्फूर्त विकास की अवस्था (take-off stage) 1780 के बाद के दो ही दशकों में प्राप्त कर ली थी।

क्रान्ति का युग

'औद्योगिक क्रान्ति' कहलाने वाले जो महत्वपूर्ण परिवर्तन इंग्लैंड में हुए उन्हें कोई निश्चित तिथि दे पाना बहुत कठिन काम है। ब्रिटिश आर्थिक इतिहासकार माउथगोट ने लिखा है कि 1765 से 1785 की बीस वर्षों की अवधि में अनेक महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उद्योग से सम्बन्धित आविष्कार हुए लेकिन फिर भी यह नहीं माना जा सकता कि औद्योगिक क्रान्ति इस अवधि तक ही सीमित रही। इतिहासकार अर्नाल्ड टॉयनबी ने उन सभी महत्वपूर्ण परिवर्तनों को औद्योगिक क्रान्ति के विषय-क्षेत्र में सम्मिलित किया है जो इंग्लैंड में 1760 से लेकर 1850 तक की

नब्बे वर्ष की अवधि में हुए। प्रोफेसर नेफ ने स्थिति का अधिक व्यापक रूप स्वीकार करते हुए उन सभी परिवर्तनों को औद्योगिक क्रान्ति की सीमा में शामिल किया है जो 1550 से लेकर 1890 तक की 340 वर्षों की अवधि में हुए। श्रीमती नॉर्वेल्ल ने औद्योगिक क्रान्ति के अन्तर्गत हुई महान् घटनाओं को दो स्पष्ट अवधियों में विभाजित किया है—पहली अवधि 1770 से 1840 तक तथा दूसरी अवधि 1840 से 1914 तक की है। अपने आपको बिना किसी विवाद में उलझाये हुए, जो औद्योगिक क्रान्ति की अवधि निर्धारित करते समय अक्सर उत्पन्न होता है, हम यह कह सकते हैं कि वे समस्त तकनीकी परिवर्तन और बड़े आविष्कार जो इंग्लैंड में 1750 में लेकर 1914 तक की अवधि में हुए ब्रिटेन की औद्योगिक क्रान्ति के मर्म या केन्द्र-बिन्दु कहे जा सकते हैं। इस तरह ग्रेट ब्रिटेन की औद्योगिक क्रान्ति की सक्रिय अवधि लगभग 164 वर्ष की रही जा सकती है।

औद्योगिक क्रान्ति के कारण

उन कारकों की एक बहुत लम्बी सूची है जिन्होंने सबसे पहले इंग्लैंड में तथा उसके बाद यूरोप के अन्य देशों में उस औद्योगिक क्रान्ति को जन्म दिया जिसने मानव के आर्थिक विकास को नये आयाम प्रदान किये। अठारहवीं शताब्दी के मध्य तक ब्रिटिश अर्थव्यवस्था मूलतः कृषि प्रधान थी। आधुनिक मानदण्ड को यदि आधार माना जाय तो उस समय इंग्लैंड में बहुत कम नगर थे तथा 80% जनसंख्या गाँवों में रहती थी। गाँवों में बसने वाली जनसंख्या के लिए जीविकोपार्जन का मुख्य साधन कृषि ही था। अधिकांश उद्योग, जिनमें सूती वस्त्र, ऊन, इस्पात, लोहे का छोटा सामान, काच तथा चीनी के बर्तन बनाना सम्मिलित हैं, अपने आधुनिक स्वरूप में सारे ब्रिटेन में कहीं पर भी नहीं थे और यदि वे कहीं पर थे भी तो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ही छोटे पैमाने पर चलाये जा रहे थे।

उपनिवेशों के बढ़ते चले जाने के साथ अठारहवीं शताब्दी में ब्रिटिश व्यापार भी फैलने लगा था। ब्रिटिश व्यापारियों को इंग्लैंड में बने हुए सूती वस्त्र के लिए निरन्तर बढ़ती हुई माँग का सामना करना पड़ रहा था और तत्कालीन उत्पादन के ढाँचे के अन्तर्गत उत्पादन में अधिक वृद्धि कर पाना असम्भव सा था। एक ओर बुनकरों की धागे के अभाव में काफी समय तक बेकार बैठे रहना पड़ता था तो दूसरी ओर सूत कलके वाले हमेशा ही व्यस्त रहते थे। पूरे समय काम करने वाला एक बुनकर 6 सूत कानने वाले लोगों द्वारा तैयार किये गये धागे का उपयोग कर सकता था। ऐसी स्थिति में इस प्रकार का परिवर्तन होना आवश्यक था कि जिससे सूत का उत्पादन काफी बढ़ सके। सूती धागे का उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता ने ही सबसे पहले औद्योगिक क्रान्ति को आरम्भिक गति प्रदान की। यही वह सबसे प्रमुख कारण था जिसके फलस्वरूप इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रान्ति के आरम्भिक वर्षों में आविष्कारों की जो एक शृंखला बनी वह सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र से ही सम्बन्धित थी।

इंग्लैंड में घटित औद्योगिक क्रान्ति के अभ्युदय व उसकी परिपक्वता के लिए

निम्न तत्वों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है—

(1) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रसार—इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रान्ति का सर्वाधिक प्रमुख कारण अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में होने वाला वह महत्त्वपूर्ण प्रसार था जो वहाँ की अर्थव्यवस्था में सत्रहवीं तथा अठारहवीं शताब्दी में हुआ था। इसके अतिरिक्त 1776 में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक 'राष्ट्रों की सम्पदा' (Wealth of Nations), जो अर्थशास्त्र की सबसे पहली प्रामाणिक पुस्तक बनी, में इस बात का उल्लेख किया था कि श्रम-विभाजन या व्यवसायों का विशिष्टीकरण बाजारों के प्रसार पर निर्भर करता है। एडम स्मिथ की यह अवधारणा एक स्वयंसिद्ध तथ्य है। यह तो इसी से स्पष्ट हो जाता है कि आर्थिक विकास की प्रक्रिया के आरम्भ से ही विशिष्टीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता रहा है। सोलहवीं व सत्रहवीं शताब्दी में नये समुद्री मार्गों की खोज ने इंग्लैंड के उद्यमियों व व्यावसायिकों के लिए एशिया, अफ्रीका तथा अमरीका के नये बाजार खोल दिये थे। इसका प्रभाव यही हुआ था कि यूरोप के देशों तथा इन तीनों महाद्वीपों के देशों के बीच व्यापार का परिमाण काफी बढ़ गया।

सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह थी कि इन महाद्वीपों में सूती वस्त्र, अन्य उपभोक्ता वस्तुओं तथा टिकाऊ पदार्थों की आवश्यकता थी और इन सभी वस्तुओं के उत्पादन में मशीनों का उपयोग बड़ी आसानी से किया जा सकता था। इन वस्तुओं की माँग में होने वाली वृद्धि ने यन्त्रीकृत उत्पादन (mechanised production) को अत्यधिक गति प्रदान की और यही गति अठारहवीं शताब्दी के दौरान हुए अनेक महान् आविष्कारों के लिए उत्तरदायी थी। हारग्रीव्स द्वारा आविष्कृत कताई की मशीन (spinning jenny), आर्क राइट का वाटरफ्रेम (waterframe), मॉल्टोन की चट्टी (mule) तथा कार्टराइट द्वारा आविष्कृत शक्ति चालित करघा (powerloom), ये सब वे यन्त्रीकृत तरीके थे जिनका उद्देश्य कताई व बुनाई के तरीकों को अधिक द्रुतगामी बनाकर सूती वस्त्र का उत्पादन बढ़ाना था। जिस चीज ने इन आविष्कारों को अनिवार्य बना दिया था वह सस्ती चीजों के लिए निरन्तर चढ़ती रहने वाली माँग थी। सस्ती वस्तुओं का उत्पादन करने वाली मशीनें मात्र तैयार करना तब तक निरर्थक है जब तक कि वृद्धिगत उत्पादन की खपत के लिए व्यापक बाजार न हो। यही कारण है कि ब्रिटिश आर्थिक इतिहास का विवेचन करने वाले लगभग सभी प्रमुख लेखकों ने बाजार के प्रसार को औद्योगिक क्रान्ति का एक प्रमुख कारण माना है। जिनोंने तो यहाँ तक लिखा है कि 'बाजार पहले होना चाहिए, उसके अनुसार आविष्कार का तो अनुकरण कर सकते हैं।'

(2) ब्रिटिश उपनिवेशों का प्रसार—विदेशी व्यापार में हुए विकास के इस आर्थिक कारण के अतिरिक्त उस समय ऐसे कई राजनीतिक तत्त्व भी थे जिन्होंने ब्रिटेन के लिए रास्ता आसान बना दिया तथा उसे औद्योगिक क्रान्ति के क्षेत्र में अगुआ बनाया। यूरोप के प्रमुख राष्ट्रों में उस समय एंगिया तथा अफ्रीका में अधिक से अधिक उपनिवेश बनाने की होड़-सी लगी थी तथा झगड़े हो रहे थे। इन सघर्षों में ब्रिटेन एक विजयी राष्ट्र के रूप में उभरा। नौसैनिक शक्ति की श्रेष्ठता ने ब्रिटेन

को स्पेन, फ्रांस तथा हालैण्ड जैसे देशों की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर सकने की शक्ति प्रदान की। विशेष रूप से भारत तथा अमरीका में ब्रिटिश उपनिवेशों की स्थापना हो जाने से नये बाजार प्राप्त करने का लाभ जैसे ब्रिटेन के लिए ही सीमित हो गया। फ्रांस, जो कि एक अपेक्षाकृत धनी और अधिक साधन सम्पन्न देश था, के पास अपनी वस्तुओं को बाहर भेजने के लिए कोई रास्ता नहीं था। राजनीतिक दृष्टि में विभाजित जर्मनी की स्थिति तो और भी खराब थी। हर यूरोपीय युद्ध में जर्मनी की ही सबसे अधिक बरबादी हुई थी। इन परिस्थितियों में ब्रिटिश राजनीतिज्ञों की चतुराई और दूरदर्शिता ने ब्रिटेन को सारे यूरोप में सर्वोच्च राष्ट्र के रूप में स्थापित कर दिया। राजनीतिक सर्वोच्चता के इस अफेले तत्त्व ने ब्रिटिश साहसकर्ताओं और व्यापारियों को निरन्तर बढ़ती जा रही औपनिवेशिक इकाइयों का अधिकाधिक शापण करने के लिए प्रवृत्त किया जो उस ब्रिटिश साम्राज्य का भाग थी जहाँ भूयं कभी अस्त नहीं होता था।

(3) पूँजी की प्रचुरता—बहुत बड़े पैमाने पर विश्व बाजारों पर एकाधिपत्य होने के अतिरिक्त ब्रिटेन के पास आवश्यक पूँजी भी उपलब्ध थी जो औद्योगिक प्रयोगों व अनुसंधानों के लिए अनिवार्य थी। ब्रिटिश व्यावसायिकों ने, जो विदेश व्यापार की कला में प्रवीण थे, इस कार्य के लिए पर्याप्त ससाधन जुटा लिये थे। वहाँ की वैकल्पिक व्यवस्था भी काफी विकसित हो चुकी थी जिससे पूँजी का श्रेष्ठतम उपयोग कर सकने में बड़ी आसानी हो गयी थी। देश की राजनीतिक एवं सामाजिक दशाएँ भी नीत्र गति से पूँजी निर्माण कर सकने के पक्ष में थी जिससे औद्योगिक विकास का गतिमान होना स्वाभाविक ही था।

(4) व्यापार की स्वतन्त्रता—अपनी सीमाओं के भीतर ब्रिटेन में पूर्ण व्यापारिक स्वतन्त्रता थी। द्वितीय राष्ट्र होने के कारण इंग्लैण्ड युद्धों के उन विनाशकारी प्रभावों से बचकर रह सका था जिन्होंने यूरोप के अन्य देशों को बरबाद कर दिया था। मुक्त व्यापार की यह नीति (*laissez faire*) ब्रिटेन के लिए दोहरी लाभकारी थी क्योंकि इसके कारण ब्रिटिश व्यापारों अपने उपनिवेशों से कच्चे माल का स्वतन्त्र रूप में आयात कर सकने के अलावा उन्हें निर्मित माल भी बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप के भेज सकते थे। इस सिद्धान्त का प्रतिपादन तथा समर्थन प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों द्वारा किया गया था। अन्य प्रतिस्पर्द्धियों से अधिक थ्रेष्ठ स्थिति में होने के कारण तथा एक शासक देश होने के कारण भी मुक्त व्यापार ब्रिटेन के लिए काफी लाभकारी नीति थी। सबसे मुख्य बात यह थी कि तकनीक में होने वाले प्रत्येक सुधार से विभिन्न औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन में काफी वृद्धि हो रही थी। उस वृद्धिगत उत्पादन को बेचने के लिए ब्रिटेन के पास बाजार तैयार थे। इसके अनिरीक्त ब्रिटेन का इन बाजारों में कोई प्रतिद्वन्द्वी नहीं था।

(5) व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के लिए सम्मान—ब्रिटेन में औद्योगिक क्रान्ति होने का एक अन्य कारण एक औसत ब्रिटिश नागरिक को प्राप्त धार्मिक तथा राजनीतिक स्वतन्त्रता थी। यह कहना सही है कि एक बहुत लम्बे समय तक ब्रिटेन में भी राजनीतिक अधिकार एक बहुत ही छोटे समुदाय का एकाधिकार बने रहें थे

तथा देश की सरकार सम्पन्न एवं प्रभावशाली कहे जाने वाले भू-स्वामी वर्ग की मुट्ठी में बँध थी। लेकिन, अन्य देशों की तुलना में, इस ब्रिटिश मध्यवर्ग या सम्पन्न भू-स्वामियों के वर्ग की विशेषता यह थी कि इस वर्ग के लोगों में उद्योग तथा व्यवसाय के प्रति बड़ा सम्मान था। इतना ही नहीं, वे उन्में प्रोत्साहन भी देते थे। ब्रिटेन में वर्ग-भेद था तो अवश्य लेकिन उसमें उनकी तीव्रता या पैनापन नहीं था जितना कि यूरोप के अन्य देशों में था। यहाँ तक कि भू-स्वामी वर्ग तथा सामान्य व्यक्तियों, आसामियों आदि के बीच वैवाहिक सम्बन्ध भी होते रहते थे और उसका परिणाम यह होता था कि भू-स्वामियों के वर्ग में नया खून प्रवेश पाना रहता था। इसके अनिरीक्त सामान्य-जन के साथ बहुत निवट-सम्बन्धों के कारण वहाँ का भू-स्वामी वर्ग देश के जेप लोगों से बड़ा हुआ या अलग नहीं रहता था। जिन दिनों ब्रिटेन के मुख्य प्रतिस्पर्द्धी माने जाने वाले देश फ्रांस, हालैंड तथा जर्मनी में समायोजित हो चुकी सामन्ती व्यवस्था की जकड़न ज्यों की त्यों कायम थी उन दिनों ब्रिटेन में एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था कायम हो चुकी थी जो आर्थिक परिवर्तनों को न केवल सहज रूप से स्वीकार करती थी बल्कि जो उनके प्रति जागरूक भी थी। उस समय प्रचलित सामान्य धारणा कि 'प्रत्येक व्यक्ति का घर ही उसका अभेद्य दुर्ग है' ने ब्रिटेन में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को पूरी तरह स्थापित कर दिया था। आविष्कारकों तथा नव-प्रवर्तकों के लिए यह एक ऐसा अनुकूल वातावरण था जिसमें वे अपने नये आविष्कारों या नव प्रवर्तनों के लिए प्रयत्न कर सकते थे।

मॉरिस डॉन ने सारी स्थिति पर विचार करने के बाद बड़े ही सटीक रूप में लिखा है कि 'औद्योगिक आविष्कार मूलतः सामाजिक उत्पाद होते हैं आविष्कारकों के सम्मुख जो प्रश्न उठाए जाते हैं तथा आविष्कारकों को जिन चीजों की आवश्यकता अपने आविष्कार के लिए पड़ती है उन सभी का निरूपण तत्कालीन सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों तथा आवश्यकताओं से ही होता है।' प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत विज्ञापनाओं व योग्यताओं के प्रति प्रशंसा के भाव ने ब्रिटेन में उन अनुकूल परिस्थितियों को जन्म दिया जिनमें उद्यमियों के वर्ग का अभ्युदय आसान बन गया।

(6) प्रगतिशील विचारों का फैलाव—क्रान्तियाँ हमेशा सबसे पहले मनुष्यों के मस्तिष्कों में जन्म लेती हैं। नॉर्वेल्ल¹ ने लिखा है कि विचारों के फैलाव ने भी औद्योगिक क्रान्ति को लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। नॉर्वेल्ल के अनुसार, उत्तीसवीं सदी फ्रांसीसी क्रान्ति का ही प्रतिफल था जिसमें 'स्वतन्त्रता, समानता तथा भ्रातृत्व' के नारा का गुञ्जाया गया था। इस नयी भावना के साथ इंग्लैंड में यन्त्रीकृत उत्पादन के लिए होने वाले आविष्कारों की श्रृंखला भी जुड़ गयी और इसका परिणाम यह हुआ कि इनके रास्त में आने वाली सारी भौतिक तथा कानूनी बाधाएँ साथ ही साथ हटती चली गयीं।

अनेक ब्रिटिश आर्थिक इतिहासकारों ने इंग्लैंड में घटित औद्योगिक क्रान्ति को बदलते हुए दृष्टिकोणों के सन्दर्भ में समझाने का प्रयास किया है। उदाहरण के

¹ L. C. A. Knowels, *The Industrial and Commercial Revolution in Great Britain during the 19th Century*, 5-7

लिए, लोहे के परिद्ववण (smelting) के लिए कोयले के उपयोग का सिद्धान्त 1620 ही में खोज लिया गया था किन्तु तत्कालीन औद्योगिक परिस्थितियों में उनका उपयोग इस कार्य के लिए पसन्द नहीं किया गया। उस समय लकड़ी का उपयोग लोहे को गलाने के काम में अधिक आर्थिक समझा जाता था। कोई सौ वर्षों के बाद ही डर्बी ने लोहे गलाने वाले कारखानों के मालिकों को यह समझाने में सफलता पायी कि लोहे को गलाने में कोयले का उपयोग अधिक मितव्ययितापूर्ण है और उसकी सलाह भी शायद इसलिए प्रभावकारी रही होगी क्योंकि तब तक इंग्लैण्ड में लकड़ी का इतना अभाव हो गया था कि खनिज कोयला (coke) ही अधिक सस्ते ईंधन के रूप में दिखाई पड़ने लगा था।

(7) नव-प्रवर्तक साहसकर्ता—प्रसिद्ध अर्थशास्त्री शुम्पीटर ने औद्योगिक क्रान्ति को इस रूप में समझाने का प्रयास किया है कि वह नव-प्रवर्तक साहसी (innovating entrepreneur) के कारण हुई थी जिनमें क्रान्ति के मध्य महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की। यह सही भी है कि ब्रिटिश साहसियों ने सामुद्रिक यात्राओं तथा दूर-दूर तक के देशों के साथ व्यापारिक सम्बन्धों की कड़ियाँ जोड़ने में विश्व के अनेक आश्चर्यजनक रिकॉर्ड कायम किये थे। किन्तु अनेक अन्य आर्थिक इतिहासकारों का मत है कि साहस भरा उद्यम ब्रिटेन में औद्योगिक क्रान्ति को जन्म देने में एक प्रमुख कारण रहा है किन्तु शुम्पीटर की इस राय का मानना सम्भव नहीं है कि सारी की सारी औद्योगिक क्रान्ति साहसकर्ताओं का ही परिणाम थी। अन्य अनेक तत्त्वों जैसे—सस्ता श्रम, विशाल क्षेत्रों में फैले हुए व्यापक बाजार तथा तकनीकी सुधारों के कारण उत्पादकता में होने वाली अभूतपूर्व वृद्धियाँ भी औद्योगिक क्रान्ति के जनक के रूप में उतने ही उत्तरदायी माने जा सकते हैं। इन सभी तत्त्वों ने मिलकर जिस औद्योगिक क्रान्ति को जन्म दिया उसी से ब्रिटिश उद्योगों का कायापलट सम्भव बना।

औद्योगिक क्रान्ति सबसे पहले इंग्लैण्ड ही में क्यों ?

ब्रिटिश कृषि जिसका कि कायापलट अठारहवीं सदी के उत्तरार्द्ध तथा उन्नीसवीं सदी के पूर्वार्द्ध में हुआ था के बदले हुए स्वरूप का अनुकरण उद्योगों द्वारा इस रूप में किया गया कि उनकी तकनीक तथा संगठन के क्षेत्रों में अनेक दूरगामी परिवर्तन हुए। ये सक्रमणकालीन स्थितियाँ अनेक रूपों में मुखरित हुईं जिनमें उद्योगों का कुछ ही स्थानों पर केन्द्रीकरण, इन औद्योगिक केन्द्रों पर जनसंख्या का जमाव तथा उनके फलस्वरूप होने वाला नगरों का विकास व निर्मित वस्तुओं के ब्रिटिश उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि को विशेष रूप से लिया जा सकता है।

इन सब बातों को देखते हुए कई बार यह प्रश्न उठाया जाता रहा है कि उद्योगों में हुए ये समस्त क्रान्तिकारी परिवर्तन सर्वप्रथम इंग्लैण्ड ही में क्या हुए? क्या कारण था कि इंग्लैण्ड ही के समकक्ष माने जाने वाले अन्य यूरोपीय देशों के उद्योगों को अपनी ही क्रान्तिकारी अवस्था में प्रवेश करने के लिए और भी काफी समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ी? कम से कम छः ऐसे प्रमुख कारण रहे जिनकी वजह से

औद्योगिक श्रान्ति के क्षेत्र में ब्रिटेन अग्रणी रहा¹—

(1) अतिरिक्त पूंजी की तुलनात्मक बहुतायत—हमारे पास अठारहवीं सदी में ब्रिटेन या यूरोप के अन्य देशों, किसी के भी बारे में इस सम्बन्ध में आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं कि उस सदी में पूंजी की मात्रा कितनी थी या उसे कहाँ और किस तरह लगाया गया था। इस कठिनाई के उपरान्त इतना कहना सम्भव है कि जो कुछ भी हमारी जानकारी है उसके हिसाब से यही प्रतीत होता है कि औद्योगिक क्रांति के जमाने में ब्रिटेन में उपलब्ध पूंजी निर्माण के अवसर तथा उस पूंजी निर्माण पर प्रतिफल स्वरूप प्राप्त होने वाले पुरस्कार तत्कालीन यूरोपीय देशों की तुलना में काफी अधिक थे। इसके अनिरिक्त इंग्लैंड में उस समय विद्यमान राजनीतिक एवं धार्मिक स्थितियाँ भी अधिक अनुकूल थीं। इंग्लैंड की आर्थिक प्रणाली भी कम रुकावटें डालने वाली थी। 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना तथा उसके तुरन्त बाद अन्य अनेक बैंकों की स्थापना ने भी एक निश्चित गतिशीलता प्रदान की। अठारहवीं सदी के उत्तरार्द्ध में ब्रिटेन में धन व पूंजी के विकास की प्रक्रिया को तत्कालीन युद्धों से कुछ आघात अवश्य लगा किन्तु ब्रिटेन को होने वाला यह नुकसान उसके सबसे निम्न के प्रतिस्पर्द्धी प्राप्त की जाने वाली हानि से काफी कम था। इंग्लैंड में तो 1800 से काफी पहले ही धन का उपयोग बड़े परिसम्पत्त (estates) का निर्माण करने, नई फसलों को पहली बार उगाने के प्रयोग करने तथा पूंजी प्रधान कृषि-व्यवस्था का विकास करने में किया जा रहा था। यह बात तत्कालीन यूरोप के और किसी भी अन्य देश में नहीं हो रही थी। लगभग इसी समय इंग्लैंड में बड़े पैमाने पर निर्मित माल तैयार करने वाले उद्योगों के लिए भी विशाल मात्रा में चल कोष (mobile funds) सामान्य रूप से उपलब्ध थे।

(2) कुशल व अकुशल श्रम की बहुतायत—एक अन्य तत्त्व जिसने इंग्लैंड को औद्योगिक क्रांति के क्षेत्र में अग्रणी बनाया वह यह था कि वह कुशल व अकुशल श्रमिकों की पूर्ति की दृष्टि से अधिक लब्ध्वी व लाभदायक स्थिति में था। सत्रहवीं व अठारहवीं सदी में ब्रिटेन ने फ्रांस तथा नीदरलैंड्स के अनेक कुशल शिल्पियों को अपने यहाँ बसने के लिए आकर्षित किया। इस अकेले तत्त्व ने ब्रिटिश श्रमिक वर्ग की औद्योगिक क्षमता व वृद्धि के स्तर को काफी ऊँचा उठा दिया। मुख्य रूप से आप्रवासी शिल्पियों का लाभ देश के रेशम, कागज तथा चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने वाले उद्योगों को मिला किन्तु इंग्लैंड में निर्मित माल तैयार करने वाले उद्योगों की एक भी शाखा ऐसी नहीं बची थी कि जिसे आप्रवासी शिल्पियों की दक्षता तथा उनके ज्ञान का लाभ न पहुँचा हो।²

(3) बाजारों का प्रसार—विशेष रूप से 1760 के बाद ब्रिटिश वस्तुओं के लिए दुनिया के अनेक भागों में होने वाली माँग निरन्तर बढ़ती चली गयी। उत्पादन की नई पद्धतियों ने न केवल वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ा दिया था बल्कि उन्होंने

¹ Ogg and Sharp *op cit*, 129

² J E T Rogers *Industrial and Commercial History of England*, New York 1892, Lectures I and II

उत्पादन लागत को भी इस तरह कम कर दिया था कि ब्रिटिश वस्तुओं के लिए और भी अधिक माँग पैदा होती चली गयी। शुरू शुरू में तो श्रमिकों को, जो अनभिज्ञ थे, ऐसा लगा कि मशीनें उन्हें नौकरी से निकलवा देगी। किन्तु निरन्तर बढ़ती हुई माँग तथा वस्तुओं की सस्ती लागत के कारण अन्त में कम नहीं बल्कि पहले से भी ज्यादा लोगों को काम मिला।

निर्मित वस्तुओं के बड़े पैमाने पर उत्पादन ने उन वस्तुओं के दुनिया-भर में निर्यात को बढ़ावा दिया। अपने प्रमुख औद्योगिक प्रतिद्वन्द्वियों, विशेष रूप से फ्रांस पर इंग्लैंड ने शुरू में ही जो बढ़त हासिल कर ली थी उसके आधार पर वह दूर-दूर के देशों से व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करने में सफल हो गया। नये-नये बाजारों की खोज की गयी व उनका विवास किया गया तथा ब्रिटिश वस्तुओं ने विदेशों में अपनी प्रतिष्ठा जमा ली।

(4) श्रेणी व्यवस्था (guild system) का विघटन—उद्योग का बड़े पैमाने पर केन्द्रीकृत हो जाने का मिलसिला ब्रिटेन में फैक्ट्री प्रणाली से सीधे-सीधे आरम्भ नहीं हो गया जैसा कि अन्य देशों में हुआ था। सत्रहवीं तथा अठारहवीं शताब्दी में इंग्लैंड का ऊन-उद्योग व्यापारी-निर्माताओं (merchant manufacturers) के नियन्त्रण में आ गया जिनके पास बच्चा माल होता था तथा जो औजारों के भी मानिक हुआ करते थे। ये लोग अकसर चुनफरो, रगई करने वालों तथा अन्य कामगारों को काम पर रख लेते थे। ये कामगार अलग-अलग जगहों पर रहते थे तथा अपना काम भी अपने-अपने घरों या दुकानों पर ही करते थे। यह व्यवस्था फैक्ट्री प्रणाली से सिर्फ एक कदम ही पीछे थी जिसमें वस्तुओं का निर्माण एक ही छत के नीचे किया जाता था।

(5) यांत्रिक आविष्कारों की जल्दी व तीव्र प्रगति—इस बारे में अनेक प्रकार की कल्पनाएँ भी जा चुकी हैं कि आगिर इंग्लैंड में ही क्यों महान् वैज्ञानिकों जैसे के (Kay), हार्ग्रीव्स (Hargreaves), आर्क्राइट (Arkrigh), क्रॉम्पटन (Crompton), रेडक्लिफ (Radcliff), होरोक्स (Horrocks), न्यूकॉमिन (Newcomen), वॉट (Watt), बोल्टन (Bolton), टेलफोर्ड (Telford), मर्डॉक (Murdock), ट्रेवेथिक (Trevethick), कोर्ट (Cort) आदि व अन्य अनेक प्रबुद्ध वैज्ञानिकों का एक पूरा का पूरा नक्षत्र मण्डल उदित हुआ। यही वे लोग थे जिनके द्वारा अठारहवीं तथा उन्नीसवीं सदी में ब्रिटेन का औद्योगिक नेतृत्व मजबूती के साथ स्थापित हो सका था। ऐसा इसलिए नहीं हुआ था कि परिष्कृत मशीनों व यन्त्रों की आवश्यकता इंग्लैंड में फ्रांस, जर्मनी या अन्य यूरोपीय राष्ट्रों की अपेक्षा अधिक तीव्रता से अनुभव की गयी थी और न ही ऐसा इसलिए हुआ कि ब्रिटेन शुद्ध-विज्ञानों (pure sciences) में किसी प्रकार का नेता था यद्यपि वहाँ भी डेवी (Davy), फेरेडे (Faraday), केवेंडिश (Cavendish) जैसे महान् वैज्ञानिकों ने सैद्धान्तिक विज्ञान के क्षेत्र में अपने-अपने महत्वपूर्ण योगदान दिये थे।

दो प्रमुख तत्त्व ऐसे रहे जिन्होंने आविष्कारों के क्षेत्र में भी इंग्लैंड को अग्रुव बनाया। पहला तत्त्व तो यह था कि ब्रिटेन में आविष्कारों की जरूरत कम

से कम उतनी तो थी ही जितनी अन्य देशों में थी। दूसरा, औद्योगिक क्रान्ति की इस अवधि में ब्रिटिश वैज्ञानिकों का झुकाव व्यावहारिक पहलू की ओर अधिक रहा। जिन दिनों सकुचित दृष्टिकोण रखने वाले अन्य यूरोपीय देश बिजली, विद्युत् शक्ति व रासायनिक प्रतिक्रियाओं आदि के क्षेत्र में सैद्धान्तिक अनुसन्धानों में लगे हुए थे उन दिनों ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने अपने आपको उपतन्त्र ज्ञान के ही व्यावहारिक उपयोग में लगा दिया। इन अभिलाषा ब्रिटिश आविष्कारकों की शिक्षा दीक्षा नाममात्र की ही हुई थी किन्तु धैर्य के साथ प्रयोगों के माध्यम से इन लोगों ने ऐसे यन्त्र बनाये जिनका बहुत व्यावहारिक महत्त्व था। वाॅट ने वाष्प को शक्ति के एक महान् स्रोत के रूप में विकसित किया। इन महान् ब्रिटिश आविष्कारकों ने इसी मिद्धान्त को चित्रित किया कि आवश्यकता आविष्कार का नेतृत्व करती है। यद्यपि यूरोप के अनुभव ने यही प्रदर्शित किया था कि आवश्यकता हमेशा आविष्कारों को पैदा नहीं करती।

(6) बड़े पैमाने पर उत्पादन योग्य वस्तुएँ—ऑग व शार्प के अनुसार अन्तिम तत्त्व जो ब्रिटेन को औद्योगिक क्रान्ति का नेता बनाने के लिए उत्तरदायी था वह यह रहा कि इंग्लैंड द्वारा उत्पादित निर्मित वस्तुएँ (manufactured goods), फ्रांस द्वारा उत्पादित वस्तुओं के विपरीत, कुछ इस प्रकार की थी कि उनके उत्पादन में अत्यधिक व्यक्तियुक्त कुशलता या कारीगरी की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। इस प्रकार की वस्तुएँ निश्चय ही फँकनी प्रणाली के अन्तर्गत बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त थी। इस तरह फँकनी प्रणाली के अन्तर्गत उत्पादित ब्रिटिश वस्तुओं की प्रगति के अवसर अच्छे थे जबकि यूरोप के अन्य देशों में बनने वाली कलात्मक वस्तुओं को निरन्तर धक्का लग रहा था।

ब्रिटिश आर्थिक इतिहासकार जार्ज साउथगेट ने लिखा है कि एक और तत्त्व भी ऐसा था जिसके कारण इंग्लैंड ऐसा देश बना जहाँ उद्योगों में सबसे पहले क्रान्ति हुई। साउथगेट के अनुसार ब्रिटेन को अनेक प्राकृतिक लाभ प्राप्त थे। इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति विश्व व्यापार के लिए सर्वाधिक उपयुक्त थी दुनिया का कोई भी भाग उसके जहाजों की पहुँच के परे नहीं था। उसके बट पट तट पर अनेक अच्छे घटराह थे तथा नौ परिवहन के लिए उपयोगी उमकी नदियाँ आन्तरिक जल यातायात के लिए काफी उपयोगी थी। एक द्वीप होने के कारण यूरोप से 14 मील चौड़ी इंग्लिश चैनल के कारण अलग होने से, उसे वह सुरक्षा प्राप्त थी जो यूरोप के किसी भी अन्य देश को प्राप्त नहीं थी। यही वह सबसे महत्त्वपूर्ण तत्त्व था जिसने इंग्लैंड को बार बार होने वाले युद्धों से उत्पन्न होने वाली बाधाओं से दूर ही रखा।

ब्रिटेन की जलवायु भी स्वास्थ्य के अधिक अनुकूल थी तथा उमम काम करने की प्रवृत्ति का प्रोत्साहन मिलता था। तकनीकी कारणों से यह जलवायु वहाँ के वस्त्र उद्योग के लिए विशेष रूप से उपयुक्त था। प्राकृतिक ममाधन विजेपत्तल कोयला व लोहा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि यदि इंग्लैंड में इजिप्ती तथा मसीनो के निर्माण के लिए लोहा उपलब्ध न होता तथा उसे मत्ताने के लिए व इजिप्ती को चत्ताने के लिए कोयले का अभाव होता तो वहाँ शायद

औद्योगिक क्रान्ति कभी नहीं होती।

औद्योगिक क्षेत्र में इंग्लैंड में प्रथम रहने का एक प्रमुख कारण वहाँ की राजनीतिक एवं वित्तीय स्थायित्व की स्थिति भी थी। 1688 के बाद इंग्लैंड का संविधान बहुत ही सुदृढ़ आधार पर खड़ा कर दिया गया था। यूरोप के अधिकांश देशों ने इन सिद्धान्तों को उन्नीसवीं शताब्दी के आरम्भ होने तक भी नहीं अपनाया था। जहाँ तक वित्तीय स्थायित्व का प्रश्न है, इंग्लैंड की महान् व्यापारिक कम्पनियाँ देश में प्रचुर मात्रा में धन-सम्पदा ला रही थी। इस प्रवृत्ति ने, धार्मिक मान्यताओं से उत्पन्न भित्तव्ययिता की आदत के साथ मिलकर जो स्थिति पैदा की उससे पूँजी का संचय होना स्वाभाविक ही था और वही पूँजी उद्योगों के लिए उपलब्ध होने लगी।

औद्योगिक क्रान्ति के परिणाम मुख्य परिवर्तन और उनका स्वरूप

(1) औजारों के स्थान पर मशीनों का प्रयोग—औद्योगिक क्रान्ति का प्रथम परिणाम, बिर्नी के अनुसार, औद्योगिक तकनीक में होने वाला वह महत्वपूर्ण परिवर्तन था जिसे संक्षेप में औजारों की जगह मशीनों के प्रयोग का नाम दिया जा सकता है। मशीनें और औजार दोनों ही भौतिक उपकरण होते हैं लेकिन औजारों को जहाँ हाथ से काम लेना होता है वहाँ मशीनों को चलाने के लिए भाप जैसी शक्ति का उपयोग किया जा सकता है। हवा और पानी के स्थान पर भाप की ताकत का उपयोग शुरू हुआ तथा भाप ने मशीनी तरीकों से उत्पादन की तकनीक को स्वीकारने की व्यावहारिकता का निर्माण किया। यही कारण है कि भाप के इंजिन को सम्पूर्ण औद्योगिक क्रान्ति का केन्द्रीय तत्त्व माना गया है और जो सही भी है।

भाप द्वारा किसी भी चीज को चला सकने की शक्ति के विषय में तो कई शताब्दियों से पता था किन्तु इस जानकारी को व्यावहारिक स्वरूप सत्रहवीं शताब्दी में ही मिल पाया। न्यूकॉमिन ने एक इंजिन बनाया था जिसका उपयोग इंग्लैंड में अठारहवीं सदी में व्यापक रूप से किया गया। न्यूकॉमिन के इंजिन की कमियों को जेम्स वॉट ने ठीक किया। किन्तु आरम्भिक वर्षों के इन आविष्कारों के प्रयत्नों में इसलिए अधिक कठिनाई उपस्थित हुई क्योंकि दक्ष कारीगरों व अभियन्ताओं का काफी अभाव था। अठारहवीं शताब्दी के अन्त में जाकर, वह भी वॉट व उसके सहयोगियों के प्रयासों से, देश में प्रशिक्षित इंजीनियरों का एक वर्ग तैयार हो पाया। यह कठिनाई 1794 में और भी कम हो गयी जब मॉडस्ले (Maudsley) ने एक मशीनी औजार स्लाइड रेस्ट (slide rest) का आविष्कार किया। यह अकेला आविष्कार ही इतना महत्वपूर्ण था कि उसने इंजीनियरिंग उद्योग में क्रान्ति का द्वार खोल दिया।

(2) कोयले व लोहे का व्यापक उपयोग—पहले-पहले जो मशीनें बनीं वे लकड़ी की थीं इसलिए ज्यादा टिकाऊ नहीं थीं। भाप का उपयोग शुरू होने पर मशीनों के निर्माण में लोहे का उपयोग वाछनीय बन गया। लोहे को गलाने के लिए पहले जिम लकडी के बोगियों का प्रयोग होता था उसके स्थान पर डबियों के आविष्कार के बाद खनिज कोयले (coke) का उपयोग होने लगा। 1829 में नेलसन (Neilson)

ने लोहा गलाने का एक नया तरीका रोज निवाला जिसे गर्म-भट्टी पद्धति (Hot Blast Method) का नाम दिया गया। इस पद्धति में कच्चे कोयले का उपयोग सम्भव बना और इसी ने भावी औद्योगिक समृद्धि की एक प्रकार से नींव डाली।

लोहा उद्योग विकास के साथ-साथ मशीनों को चलाने के लिए वाष्प शक्ति के बढ़ते हुए प्रयोग ने मिलकर औद्योगिक कार्यों के लिए कोयले की माग में निरन्तर वृद्धि की। फ्रांस जैसे देश औद्योगिक सर्वोच्चता के लिए हो रहे संघर्ष में गम्भीर रूप से पिछड़ गये क्योंकि वे कोयले के अभाव से ग्रस्त थे। इस बात का अन्दाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 1913 में फ्रांस का कोयले का उत्पादन मात्र 41 मिलियन टन था जबकि उसी वर्ष में ब्रिटेन में कोयले का उत्पादन 292 मिलियन टन (7 गुने से भी अधिक) था। कोयले का अभाव फ्रांस के अधूरे और लड़खड़ाते हुए औद्योगीकरण के लिए प्रमुख उत्तरदायी कारण रहा।

(3) फैक्ट्री प्रणाली का विकास—अठारहवीं तथा उन्नीसवीं शताब्दी के दौरान ब्रिटिश उद्योगों द्वारा प्राप्त की गयी तकनीकी प्रगति ने वहाँ के औद्योगिक संगठन का स्वरूप ही बदल दिया। औद्योगिक क्रान्ति से पहले उद्योगों को छोटे पैमाने पर संगठित किया जाता था तथा औद्योगिक इकाई एक छोटा कारखाना (workshop) हुआ करता था। कुछ उद्योगों में छोटी-छोटी श्रेणियाँ (guilds) भी थी तथा श्रमिक घरेलू प्रणाली के अन्तर्गत (domestic system) संगठित थे। अपने छोटे से कारखाने में श्रमिक अपना मालिक स्वयं ही था।

औद्योगिक क्रान्ति ने छोटे कारखानों में उत्पादन की इस मध्ययुगीन प्रथा का अन्त कर दिया। मशीनों के प्रयोग ने एक ही भवन की छत के नीचे भारी सख्या में श्रमिकों के केन्द्रीकरण को बढ़ावा दिया। इन श्रमिकों पर नियोक्ता की ओर से कोई निरीक्षक या अभिकर्ता नियुक्त किया जाता था। कार्य-कुशलता की दृष्टि से फैक्ट्री प्रणाली की श्रेष्ठता के बारे में किसी प्रकार का सन्देह नहीं रह गया था। मशीन से बनी चीजों की प्रतिस्पर्धा में हाथ से सामान तैयार करने वाले श्रमिकों ने कुछ समय तक तो व्यर्थ संघर्ष किया और बाद में वे भी उसी 'घुणित' फैक्ट्री प्रणाली में सम्मिलित हो गये।

फैक्ट्री प्रणाली का अभ्युदय विशाल पैमाने पर उत्पादन करने की इस सामान्य प्रवृत्ति का केवल एक उदाहरण है जो आधुनिक औद्योगीकरण की मुख्य विशेषता बनी है। औद्योगिक इकाई के आकार में इस वृद्धि से व्यावसायिक इकाई के आकार में भी काफी वृद्धि हुई। व्यवसाय की एकल स्वामित्व प्रणाली का स्थान भागीदारी प्रथा ने लिया तथा भागीदारी प्रथा से सीमित दायित्व वाली कम्पनियों का निर्माण आरम्भ हुआ।

फैक्ट्री प्रणाली (factory system) की मुख्य विशेषता यह थी कि पूँजी-पतियों के स्वामित्व वाले कारखानों में बड़ी सरया में मजदूरों को भर्ती किया गया। इस बारे में बहुत ही सीधा-सादा तर्क दिया जा सकता है कि कताई-बुनाई की प्रक्रियाओं को लेकर हुए आविष्कारों या सुधारों ने आखिर क्यों-कर वस्त्र-मिलों को जन्म दिया। सबसे पहले तो यही कारण लिया जा सकता है कि नई मशीनें काफी

मँहगी थी। दूसरे, नई मशीनों को घर में ही रखकर कार्य कर सकना असम्भव हो चुका था। इन्हीं कारणों से फैक्ट्री प्रणाली का विकास हुआ। फैक्ट्री प्रणाली सबसे पहले सूती वस्त्र के उत्पादन में फैली, उसके बाद चमड़ा उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, धातु उद्योग तथा अन्य कई उद्योगों में भी इस प्रणाली का विकास हुआ।

‘उत्पादन की एक विशिष्ट इकाई’, जैसा एक ब्रिटिश लेखक ने लिखा था, ‘अब एक परिवार या कुछ लोगों का एक समूह कतई नहीं रह गयी थी जो सस्ते व सीधे सादे औजारों से थोड़े से कच्चे माल को लेकर वस्तुएँ बनाती थी बल्कि वह मुगठित व मुसगठित श्रमिकों का एक विशाल समूह बन चुकी थी जो हजारों-लाखों व्यक्तियों से मिलकर बनी थी तथा जो भारी मात्रा में व पेचीदा मशीनों पर बड़े पैमाने पर उत्पादन करने में सहयोग करती थी और जिसके हाथों से निरन्तर और विशाल परिमाण में कच्चा माल तैयार चीजें बनकर उपभोक्ताओं तक पहुँचता था।’

यही नई इकाई उन्नीसवीं शताब्दी की फैक्ट्री थी।

(4) जनसंख्या में वृद्धि—औद्योगिक क्रांति के वर्षों में ब्रिटिश जनसंख्या में बड़ी तेजी से वृद्धि हुई। 1801 में की गई जनगणना में ब्रिटेन की जनसंख्या केवल 9 मिलियन थी। यही जनसंख्या 1851 तक दुगुनी हो गयी तथा 1901 तक फिर दुगुनी हो गयी। फ्राम में इसी अवधि में जनसंख्या 50 प्रतिशत से भी कम बढ़ी।

औद्योगिक क्रांति से पहले इंग्लैण्ड की अधिकांश जनसंख्या गाँवों में रहती थी। लेकिन औद्योगिक परिवर्तनों के परिणामस्वरूप लोग लोहा व कोयला क्षेत्रों में केन्द्रित होते चले गये और धीरे-धीरे स्थिति यह बनी कि 80 प्रतिशत के लगभग लोग वस्त्रों व शहरों में रहने लग गये।

(5) विदेश व्यापार का विकास—विदेश व्यापार का विकास औद्योगिक क्रांति का कारण और परिणाम दोनों ही रहा। उन्नीसवीं शताब्दी के आरम्भ में सम्पूर्ण यूरोप में ब्रिटेन ही एकमात्र औद्योगिक राष्ट्र था और इसलिए वह स्वाभाविक रूप से विश्व का कारखाना (workshop of the world) बन गया। इंग्लैण्ड के उद्योग कम विकसित राष्ट्रों को निर्मित माल भेजते थे तथा उसके बदले में वे कच्चा माल तथा खाद्य पदार्थों का आयात करते थे। इस प्रकार का विनिमय ब्रिटेन के लिए बहुत ही लाभ का सौदा था क्योंकि ब्रिटेन निर्मित माल बहुत ही सस्ती लागत पर तैयार करता था और उसे काफी ऊँचे मूल्य पर बेचता था। इस प्रकार एक निर्मित माल वाला देश (manufacturing country) होने से ब्रिटेन को लाभ ही लाभ था। 1913 में ब्रिटेन के 80% निर्यात निर्मित वस्तुओं के थे जबकि उसके तीन-चौथाई आयात कृषि पदार्थों के थे।

(6) पूँजी की सर्वोच्च स्थान—औद्योगिक क्रांति का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू यह था कि उद्योग में पूँजी का स्थान सर्वोच्च हो गया। मध्य युग में पूँजी को उद्योगों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं था अर्थात् मध्ययुगीन उद्योग पूँजी-प्रधान नहीं थे। श्रेणियों (guilds) में काम करने वाले कारीगर को अपना धन्धा जमाने के लिए थोड़े से और बहुत सस्ते किस्म के औजारों की आवश्यकता होती थी। यह कहना सही है कि वस्त्र उद्योग तो सोलहवीं शताब्दी के बाद से ही किसी से किसी रूप में

पूँजी-प्रधान रहा किन्तु तत्कालीन इकाइयो में लगी हुई पूँजी की तुलना में औद्योगिक क्रान्ति के दौरान स्थापित हुई विशाल औद्योगिक इकाइयों में लगी हुई पूँजी का परिमाण अत्यधिक विशाल था।

(7)। कताई व बुनाई के लिए मशीनों का आविष्कार—1733 में जॉन के (John Kay) ने एक नई तकनीक फ्लाइंग शटल (flying shuttle) के लिए स्वतन्त्राधिकार प्राप्त किया जिससे बुनकरों की उत्पादकता इतनी सीमा तक बढ़ गयी कि कताई करने वालों के लिए उनकी सूत की मांग को पूरा कर पाना असम्भव-सा हो गया। जिस करघे को चलाने के लिए पहले दो आदमियों की आवश्यकता पड़ती थी वहाँ के (Kay) के आविष्कार के बाद केवल एक ही बुनकर काफी था तथा करघे की उत्पादकता भी पहले से दुगुनी हो चुकी थी। सूती धागे के लिए मांग उसकी पूर्ति की तुलना में इतनी अधिक बढ़ चुकी थी कि 1761 में दो इनामों को देने की घोषणा इस बात के लिए की गयी कि कोई ऐसे चरखे (spinning wheel) का आविष्कार करे जो एक ही समय में एक से अधिक धागा बुन सके।

बिना किसी विलम्ब के 1764 में जेम्स हारग्रोव ने अपनी कताई-चरखी (spinning jenny) पूरी कर डाली जो एक सीधी सादी हाथ से चलने वाली मशीन थी। शुरू में तो इस चरखी पर एक साथ 8 धागे बुन सकते थे जो बाद में 16, उसके बाद 20 तथा आविष्कर्ता हारग्रोव के अपने जीवन-काल में ही 80 तक पहुँच गये। इसके अतिरिक्त हारग्रोव की यह मशीन इतनी आसान थी कि कोई बच्चा भी उसे चला सकता था। किन्तु इस मशीन से बुना जाने वाला धागा इतना पतला होता था कि उसे मिर्च बाने (weft) में ही प्रयुक्त किया जा सकता था। इस कमी को रिचर्ड आर्कराइट ने 1771 में दूर किया। उसने अपने नाम पर रजिस्टर्ड करवायी गयी नई मशीन वाटरफ्रेम (waterframe) बनाई जिसने न सिर्फ धागे को मजबूती प्रदान की बल्कि जिससे पहली बार सिर्फ कपास पर आधारित धागा बुनना सम्भव हुआ।

आर्कराइट द्वारा आविष्कृत वाटरफ्रेम (waterframe) वस्त्र निर्माण के इतिहास में केन्द्रीय महत्त्व की घटना न केवल इसलिए मानी जाती है कि इसके बनने से पूर्णरूप से कपास पर आधारित कपड़ा बुनना सम्भव हो गया बल्कि इस आविष्कार का महत्त्व इसलिए भी है कि इसके दो जोड़े रॉलर पानी या भाप की शक्ति से ही चल सकते थे जिन्हें घर पर या छोटे से कारखाने में नहीं लगाया जा सकता था और जो बड़े कारखाने में ही लाभप्रद हो सकते थे। 1779 में सेम्युअल क्रॉम्पटन ने चट्टी (mule) या म्यूल जेनी (mule jenny) का आविष्कार किया जिसमें उसने हारग्रोव तथा आर्कराइट के आविष्कारों की अच्छाइयों का सम्मिश्रण कर लिया। इस म्यूल जेनी पर दो हजार तक एक साथ लगाये जा सकते थे तथा इसे एक अकेला आदमी चला सकता था। यह क्रॉम्पटन के आविष्कार का ही परिणाम था कि अच्छे किस्म का धागा देश में पहली बार तैयार होने लगा जिससे इंग्लैंड में मलमल के उत्पादन की शुरुआत हुई।

कताई के क्षेत्र में 1764 से 1779 के बीच जो महान् सुधार हुए उन्होंने कताई करने वालों तथा बुनकरों के बीच चले आ रहे परम्परागत सम्बन्धों को एवढम

उलट दिया। बुनाई के क्षेत्र में के (Kay) द्वारा आविष्कृत पलाइंग शटल के बाद कोई नया आविष्कार नहीं हुआ इसलिए अब पिछड़ने की चारी बुनकरों की थी। 1784 के बाद डा० एडवर्ड कार्टराइट (Edward Cartwright) ने पहले शक्ति-चालित करघे के सिद्धान्तों का विकास किया जिसे पानी से चलाया जाना था। लेकिन उसके आविष्कार को मान्यता उन्नीसवीं शताब्दी के प्रथम दशक में ही मिल पायी 1809 में ब्रिटिश संसद ने कार्टराइट को 10,000 पौण्ड का अनुदान स्वीकृत कर उद्योग के प्रति उसकी सेवाओं का सम्मान किया।

रेडक्लिफ, होरोक्स आदि ने मिलकर कार्टराइट द्वारा निर्मित करघे में इतने अधिक सुधार किये कि 1815 तक बुनकर भी कताई उद्योग की बराबरी में आ गये। आरम्भ के वर्षों में बुनाई घरेलू प्रणाली (domestic system) के अन्तर्गत की जाती थी किन्तु भाप की शक्ति का प्रयोग आरम्भ होने के बाद सन्तुलन कारखानों (factories) के पक्ष में हो गया। इस तरह वस्त्र उद्योग को धीरे-धीरे औद्योगिक क्रान्ति के पर्यायवाची के रूप में जाना जाने लगा।

औद्योगिक क्रान्ति के प्रभाव

(अ) आर्थिक एवं सामाजिक प्रभाव—ब्रिटेन में फैक्ट्री प्रणाली के विकास पर टिप्पणी करते हुए एक लेखक ने लिखा था कि 'महान् आविष्कारों ने फैक्ट्री में जो किया वह यही था कि उन्होंने हाथ से काम के स्थान पर यान्त्रिक सहायता की स्थापना कर दी।' कहने को तो बॉट, क्रॉम्पटन व कॉर्ट के आविष्कारों से पहले भी ब्रिटेन में कारखाने थे किन्तु उन्नीसवीं शताब्दी में जो फैक्ट्री प्रणाली विकसित हुई उसमें धूम्रिक की मशीन के अधीन काम करने की बात सन्निहित थी। श्रम तथा पूँजी के बीच नये समीकरणों का निर्माण हुआ। मध्ययुगीन श्रेणी-सदस्य (guildsman) स्वयं ही मजदूर और स्वयं ही मालिक भी था। किन्तु फैक्ट्री प्रणाली के अन्तर्गत मालिक और मजदूर के बीच एक स्पष्ट रेखा खिंच गयी। अब तो न केवल कच्चे माल की पूर्ति करता था बल्कि कारखानों के भवनो तथा मशीनों का भी मालिक होता था जबकि दूसरा केवल मजदूरी के बदले काम करता था।

इस तरह औद्योगिक क्रान्ति ने एक ऐसा मजदूरों का विशाल वर्ग तैयार कर दिया जिनके पास बेचने के लिए अपने हाथों के श्रम के अतिरिक्त कुछ भी न था। वर्ग-संघर्ष के बीज बो दिये गये थे। इसके अतिरिक्त श्रमिकों की सरया अधिक होने का अर्थ यह था कि उनकी मिलने वाली मजदूरी कम तथा काम के घण्टे अधिक रहते। श्रमिकों को एक अमानवीय जीवन बिताने की स्थिति में छोड़ दिया गया था।

फैक्ट्री प्रणाली का एक और प्रभाव यह हुआ कि औरतों और बच्चों से काम लेने की प्रथा आरम्भ हुई। मशीनों से काम लेने में अधिक शक्ति का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं थी और स्त्रियाँ तथा बच्चे काम के लिए सस्ते रहते थे। यह प्रथा विशेष रूप से वस्त्र उद्योग में खूब फैली। इसका अर्थ पुष्टियों के लिए बेकारी था। कई बार तो ऐसा हुआ कि वयस्क व्यक्ति काम की तलाश ही करते रहते जबकि उनके बीबी-बच्चे परिवार की रोजी-रोटी की व्यवस्था करने वाले (breadwinner) बन जाते।

यद्यपि प्रत्येक आविष्कार का अन्तिम परिणाम यह हुआ था कि रोजगार में वृद्धि हुई किन्तु प्रारम्भ में उसके कारण कुछ लोगों को बेकार होना पड़ा। इसमें उत्पीड़न की स्थिति पैदा हुई तथा श्रमिक लोग ऐसे आविष्कारों के विरुद्ध हिंसक हो उठे। आविष्कारक हारग्रीवज को एक बार ऐसी ही हिंसक भीड़ का सामना करना पड़ा। लेकिन हाथ से काम करने के स्थान पर मशीनों के प्रतिस्थापन की प्रवृत्ति इतनी दृढ़ थी कि उसे मुट्ठी भर लोगों के हिंसक विरोधी से रोका नहीं जा सकता था। श्रमिक वर्ग को इस अपरिहार्यता को स्वीकार करना ही पड़ा।

औद्योगिक क्रान्ति के उद्भव ने व्यापार चक्रों की प्रक्रिया को भी जन्म दिया। इससे इंग्लैंड में तेजी और मन्दी की एक शृंखला-भी बन गयी। विनियोग के स्तर में हानि वाले गम्भीर उतार-चढ़ावों ने मूल्यों तथा रोजगार के स्तर में भी भारी उच्चावचन पैदा किये। औद्योगिक क्रान्ति से पहले लोगों ने इस प्रकार की आर्थिक घटनाओं को घटित होने हुए कभी नहीं देखा था। इस तरह आर्थिक जड़ता की पिछली अनेक गताब्दियों की स्थिति यकायक पूरी तरह नष्ट हो गयी और उसके स्थान पर पूँजी-प्रधान तकनीक पर आधारित विशाल पैमाने के उत्पादन का एक नया युग आरम्भ हुआ।

आधुनिक ब्रिटिश औद्योगीकरण के जीवन के प्रारम्भिक वर्ष 1850 तक समाप्त प्रायः हो चुके थे और उसी के साथ औद्योगिक क्रान्ति की भी विदाई हो गयी। बावजूद इसके कि औद्योगिक क्रान्ति ने अपने समय में कुछ पोढ़ियों को बच्यो और पोड़ा पहुँचाई थी, यह इंग्लैंड के आर्थिक इतिहास में घटने वाली सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी। इंग्लैंड के आर्थिक जीवन में 1850 के बाद जो क्रान्तिकारी परिवर्तन आये तथा औद्योगिक क्रान्ति के दौरान हुए रूपान्तरण के कारण औद्योगिक उत्पादन में जो ज्यामितिक वृद्धियों का दौर शुरू हुआ वह उस औद्योगिक क्रान्ति का ही परिणाम था जो वहाँ अठारहवीं तथा उन्नामवीं शताब्दी में बड़े ही शान्त तरीके से होती चली गयी थी। औद्योगिक क्रान्ति ने ही विशिष्टीकरण (specialisation) की प्रवृत्ति को गति प्रदान की तथा उसके दौरान ही रेलमार्ग यातायात एवं जल-परिवहन के क्षेत्र में अनेकों क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए।

(ब) राजनीतिक प्रभाव—औद्योगिक क्रान्ति ने इंग्लैंड के राजनीतिक पटल पर भी अपना न मिटने वाला प्रभाव छोड़ा। औद्योगिक क्रान्ति से पहले ब्रिटिश संसद में भू-स्वामियों व सामन्त वर्ग के प्रतिनिधियों का ही बोलबाला था तथा सामान्य जनता की वहाँ अनदेखी की जानी थी। औद्योगिक क्रान्ति प्रारम्भ हो चुकने के बाद के कई वर्षों तक भी यह स्थिति बनी रही कि धरवाद हो रहे बस्वों या नाममात्र के गाँवों से कॉमन सभा (House of Commons) में प्रतिनिधि भेजे जान रहे जबकि इस दौरान विकसित हुए नये औद्योगिक केन्द्रों में रहने वाली धनी आबादी को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। यह विमर्शित तब और भी गहरी होनी चली गयी जब एक ओर तो औद्योगिक केन्द्रों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हुई तथा दूसरी ओर उनका प्रतिनिधित्व संसद में नहीं बढ़ाया गया। भू-स्वामियों ने इस बात के भरमक प्रयास किये कि जैसे भी हो औद्योगिक समुदाय के लोगों को राजनीति से अलग ही रखा

जाए किन्तु ससदीय मुधारो के लिए की जाने वाली माँग इतनी प्रभावी थी कि ऐसा बहुत अधिक समय तक कर पाना सम्भव नहीं रहा ।

फिर भी यहाँ यह कहना गलत नहीं होगा कि श्रमिक-वर्ग को एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक शक्ति बनने में काफी लम्बा समय लगा तथा उन्हें सफलता भी काफी लम्बे संघर्ष के बाद ही मिल पायी । जो भी हो, आज की ब्रिटेन की लेबर पार्टी का जन्म औद्योगिक क्रान्ति के उन संघर्षमय वर्षों में ही हुआ था । इंग्लैण्ड के औद्योगिक क्षेत्र 'सर्वहारा वर्ग' के गढ़, श्रम संघवाद के किले तथा समाजवाद के बाल-निकेतन बन गये ।'

औद्योगिक क्रान्ति के दौरान विश्व के अन्य देशों की अपेक्षा ब्रिटेन द्वारा की गयी प्रगति का ही यह परिणाम था कि इंग्लैण्ड एक राजनीतिक महाशक्ति बन गया तथा उसकी यह राजनीतिक सर्वोच्चता द्वितीय महायुद्ध होने तक कायम रह सकी । फ्रांस को नीचा दिखाने में इंग्लैण्ड को मिली सफलता भी वहाँ की औद्योगिक क्रान्ति का ही परिणाम थी । यह सही ही है कि 'खून और खज़र के बूते पर नहीं बल्कि लोहे और कोयले की नींव पर ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित किया गया था ।'

तीसरा अध्याय

प्रमुख उद्योगों का विकास

(THE DEVELOPMENT OF MAJOR INDUSTRIES)

यन्त्रीकरण के क्षेत्र में हुए अनेक आविष्कारों तथा औद्योगिक क्रान्ति के वर्षों में सगठन सम्बन्धी हुए अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तनों के परिणामस्वरूप सूती वस्त्र उद्योग, कोयला, लोहा व इस्पात तथा इजीनियरिंग जैसे अनेक प्रमुख उद्योगों में पूरी तरह से उत्पादन का तौर-तरीका ही बदल गया। इन उद्योगों में होने वाले उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई तथा लागतों में भी भारी गिरावट आयी। फैक्ट्री-प्रणाली के अभ्युदय के बाद तो इन उद्योगों का पूरी तरह से कायापलट ही हो गया। औद्योगिक क्रान्ति के उन सघर्ष भरे वर्षों में इन प्रमुख उद्योगों का जो इस तरह रूपान्तरण हुआ वह ब्रिटिश आर्थिक इतिहास की निःसन्देह महानतम घटना कही जा सकती है।

1 सूती वस्त्र उद्योग

जिन चार महान् आविष्कारों ने ब्रिटेन के सूती वस्त्र उद्योग की तकदीर ही पलट दी उनको शुरूआत 1733 में जॉन के (John Kay) द्वारा आविष्कृत फ्लाईंग शटल (flying shuttle) से हुई थी। इस आविष्कार का अनुकरण 1767 में हार्ग्रीव्स (Hargreaves) को स्पिनिंग जेनी (spinning jenny), 1769 में आर्क राइट द्वारा आविष्कृत वाटर फ्रेम (water frame) तथा 1776 में सेम्युल क्रॉम्पटन द्वारा तैयार की गयी म्यूल जेनी (mule jenny) द्वारा किया गया। इसके बाद जब 1785 में एडमण्ड कार्टराइट (Edmund Cartwright) ने शक्ति चालित करघे का निर्माण कर लिया तब ब्रिटेन के सूती वस्त्र उद्योग में एक तरह से सम्पूर्ण क्रान्ति आ गयी।

अठारहवीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों में सूती चीजों का उत्पादन काफी नगण्य व अमहत्वपूर्ण ही था। इसकी जगह ऊनी चीजों का उत्पादन काफी लोकप्रिय था तथा सूत की बनी चीजों का भारत से आयात किया जाता था। 1720 के बाद भी लगभग 50 वर्षों तक ब्रिटेन ऐसे घागे का उत्पादन करता था जो सूत और सन (linen) का मिश्रण होता था।

1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत में लगभग अराजकता की स्थिति फैल गयी तथा भारत पर अपना-अपना आधिपत्य जमाने में फ्रान्स तथा इंग्लैंड के बीच सघर्ष छिड़ गया। अराजकता की इस स्थिति में भारत से सूत की बनी चीजों के ब्रिटेन में आयात में बाधा उत्पन्न हुई तथा अंग्रेज व्यापारियों ने इस अवसर का

उपयोग भारत में कपास का आयात करने में किया।

ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ग्रेट ब्रिटन में सूती वस्त्र मिलों का तो निर्माण औद्योगिक क्रान्ति के विभिन्न आविष्कारों के कारण हो चुका था किन्तु वहाँ पर कपास का उत्पादन बिलकुल भी नहीं होता था। अब तक 1769 में आकराइट द्वारा आविष्कृत वाटर फ्रेम की वजह से इंग्लैंड में ऐसा मजबूत सूती धागा भी बनाया जाने लगा था जिसका उपयोग ताने (warp) के रूप में किया जा सकता था। इसका परिणाम यह हुआ कि अब इंग्लैंड में पूरी तरह से सूती वस्त्र का उत्पादन कर सकना सम्भव हो गया। तीसरा तत्त्व, जिसने इंग्लैंड के सूती वस्त्र उद्योग के विकास को बढ़ावा दिया वह यह था कि वहाँ की सरकार ने 1774 में छपे हुए सूती कपड़ों पर लगे हुए प्रतिबन्ध को हटा लिया था। चौथा तत्त्व ज़िम्न अन्तिम रूप से सूती वस्त्र उद्योग के विकास को प्रोत्साहन दिया वह संयुक्त राज्य अमरीका के दक्षिणी राज्यों में कपास की बड़े पैमाने पर खेती आरम्भ कर दिया जाना था। इसका परिणाम यह रहा कि अठारहवीं शताब्दी के अन्त तक इंग्लैंड के सूती वस्त्र उद्योग के लिए कपास अपरिमित माना में आयात कर सकने का यह एक प्रमुख स्रोत बन गया।

उद्योग का स्थानीयकरण (Localisation of Industry)

अनेक कारणों से सूती वस्त्र उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त स्थान इंग्लैंड में लक्जानायर बना। सूती धागे के उत्पादन के लिए गीले जलवायु की आवश्यकता होती है तथा लक्जानायर में वर्षा की अधिकता के कारण वहाँ की जलवायु में सदैव नमी बनी रहती है। लक्जानायर में सरने भी थे जो तब उपयोगी थे जब जल-शक्ति का उपयोग किया जाता था। जब कोयले का उपयोग भाप बनाने के लिए किया जाना लगा तब भी यही स्थान सूती वस्त्र उद्योग के लिए उपयुक्त रहा क्योंकि इंग्लैंड में कोयले के भण्डार भी इसी क्षेत्र में पड़ते थे। लीवरपूल में म्थिन लक्जानायर काउंटी (जिल्ला) में एक अच्छा बन्दरगाह भी था जो कपास का आयात करने तथा निर्मित सूती वस्त्र का निर्यात करने के लिए उपयुक्त था। इन सभी कारणों से लक्जानायर ही सूती वस्तुओं के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त जगह थी। सूती वस्त्र उद्योग काफी सुगमजित भी हो गया तथा उसके बाजार व व्यापार मार्ग भी लगभग निर्धारित हो गए। सूती वस्त्र उद्योग की विभिन्न क्रियाओं ने लक्जानायर में इनकी त्रिशिष्टता और कुशलता प्राप्त कर ली थी कि पूरे देश में उसका बड़ी मुकाबला नहीं था। इनके अनिरिक्त वहाँ अनेक सहायक उद्योग घन भी खुल गये थे।

सर्वोच्च शिखर पर

इंग्लैंड में सूती वस्त्र उद्योग का आरम्भ अठारहवीं शताब्दी में हुआ था जबकि ऊनी वस्त्रों का उत्पादन वहाँ सैंकड़ों वर्षों में होता आया था। कच्ची ऊन की पूर्ति वहाँ सीमित थी। दूसरी तरफ आयातित कपास ऊन के मुकाबले सस्ता भी था और बाहर में आयात किया जाने के उपरान्त उसकी पूर्ति लगभग असिमित थी।

कातने व बुनने के तरीके भी बहुत समय तक अपरिवर्तित रहे तथा उनमें मानवीय हाथों के श्रम का ही उपयोग होता रहा। 1790 में कार्टराइट द्वारा ऊन साफ करने की एक मशीन का आविष्कार किये जाने से पहले ऊन साफ करने का काम हाथों द्वारा ही किया जाता था। चट्टियों (mules) का ऊन साफ करने के लिए आम उपयोग काफी बाद में शुरू हुआ। ऊनी वस्त्र बनाने के लिए शक्ति चांति करघे का उपयोग 1824 के बाद ही शुरू हुआ हालांकि 1850 तक भी हाथ से ही ऊनी कपड़े बुनने की प्रथा समाप्त नहीं हुई थी।

ऊन के उत्पादन में न्यू साउथ वेल्स (new south wales) में 1805 के बाद बड़े बड़े मेड फार्मों की स्थापना के बाद काफी वृद्धि हो गयी। 1830 के बाद ऊन का आयात भी शुरू हो गया था। लेकिन इन सब परिवर्तनों के बावजूद इंग्लैंड के ऊनी वस्त्र उद्योग को उसका पुराना स्थान वापस नहीं मिल पाया। 1830 के बाद तो लगभग प्रति वर्ष सूती वस्त्र उद्योग ने ऊन उद्योग को विस्थापित करना आरम्भ कर दिया तथा उसकी सर्वोच्च स्थिति को छीन लिया। ऊन उद्योग को दूसरे स्थान पर ढकेल दिया गया था।

सन उद्योग (linen industry) इंग्लैंड में कभी महत्वपूर्ण नहीं रहा। कम से कम सूती वस्त्र या ऊनी वस्त्र उद्योग के मुकाबले में तो कभी नहीं। इस उद्योग में भी मशीनों का उपयोग 1840 के बाद ही सामान्य बना यद्यपि बुनाई के क्षेत्र में इस उद्योग में मशीनों को 1860 से पहले स्वीकार नहीं किया गया था। रेशम उद्योग भी इंग्लैंड में शताब्दियों से विद्यमान था किन्तु वह भी सत्रहवीं सदी के अन्त में ही महत्वपूर्ण बना। अठारहवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में रेशम उद्योग ने भी ऊनी उद्योग के साथ मिलकर कुछ ऐसे कानून बनवाये जिनसे सूती वस्त्र उद्योग के विकास में बाधा पड़ी। मशीनों के उपयोग के अठारहवीं व उन्नीसवीं शताब्दी में प्रारम्भ हो जाने तथा कुछ संरक्षण प्राप्त होने से रेशम उद्योग उन्नीसवीं सदी के मध्य तक फलता-फूलता रहा। किन्तु इंग्लैंड के रेशम उद्योग को फ्रांस की प्रतिस्पर्धा तथा 1860 के बाद उस पर लगे संरक्षणवादी तटकरों को हटाने की क्रिया ने समाप्त प्राय कर दिया।

वस्त्र सफेद करने की कला (bleaching) तथा रंगाई के क्षेत्र में आयी क्रान्ति ने भी, जो सूती वस्त्र उत्पादन के लिए अनुकूल थी, उद्योग को चरमबिन्दु पर ले जाकर स्थापित कर दिया। पुराने समय में सूती वस्त्र को सफेद करने में कई महीनों का समय लग जाता था और काफी स्थान की भी आवश्यकता होती थी क्योंकि हर गज टुकड़े को धूप में फैला-फैलाकर सुखाना पड़ता था। क्लोरीन की सहायता से धोबीय कर सकने की खोज उद्योग के लिए भाग्यशाली रही। अब सूती कपड़े को सफेद करने में कुछ ही दिन लगने लगे। औद्योगिक क्रान्ति के आरम्भ से ही नई रंगाई तकनीकों (new dyes) का आविष्कार हो रहा था। किन्तु थॉमस बेल (Thomas Bell) के बेलनाकार छपाई (cylindrical printing) के आविष्कार ने सूती वस्त्रों की रंगाई में नई क्रान्ति ला दी। इस अकेले आविष्कार ने सूती वस्त्र उद्योग को सर्वोच्च स्थिति प्रदान कर दी।

सूती वस्त्र उद्योग के बारे में आँकड़ों से यही इंगित होता है कि उन्नीसवीं शताब्दी के पहले 60 वर्षों में उसमें निरन्तर प्रगति हुई। इस अवधि में सूती वस्त्र तैयार करने के लिए जितने यन्त्रीकृत तरीके अपनाये गये उन सभी का इतने कम स्थान में तो उल्लेख करना भी सम्भव नहीं है। 1830 में आविष्कृत गोलाकार कताई मशीन (ring spinning frame), हेल्मेन (Heilmann) द्वारा 1847 में बनायी गयी कपास साफ करने की मशीनें तथा दाताब्दी के अन्त में बने नॉर्थ्रॉप करण (Northrop Loom) जैसे आविष्कारों का विशेष उल्लेख किया जा सकता है। इन आविष्कारों के बाद सूती वस्त्र निर्माण की प्रत्येक क्रिया में मशीनों का उपयोग बढ़ता गया तथा उद्योग के भीतर ही विशिष्टीकरण को भी और बढ़ावा मिला। कताई तथा बुनाई अब दो अलग अलग विभाग बन गये तथा ऊन व सूत दोनों ही में ब्लीचिंग का काम व रंगाई का काम अलग अलग उद्योगों के रूप में किया जाने लगा।

इस्लैण्ड के सूती वस्त्र उद्योग को सबसे पहला गम्भीर झटका अमरीकी गृह युद्ध के समय लगा। अमरीकी सधीय नौसेना द्वारा दक्षिणी राज्यों के सभी बन्दरगाहों की नाकेबन्दी कर दिये जाने से लकाशायर को पहुँचने वाला कच्चा माल बन्द हो गया। अन्य स्रोतों से कच्चा माल प्राप्त करने की चेष्टाएँ अपर्याप्त रही। रूई कपड़ा मिलों को बन्द कर देना पड़ा। इससे मिल मालिकों को भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा तथा एक बहुत बड़ी सख्या में श्रमिक भी बेकार हो गये। लेकिन वस्त्र उद्योग ने इस विपत्ति का साहस व धैर्य के साथ मुकाबला किया। पुनः पूर्व स्थिति में पहुँचने में काफी समय लग गया।

अमरीकी गृह-युद्ध के कड़वे अनुभव ने लकाशायर के वस्त्र निर्माताओं को भारत, दक्षिणी अफ्रीका तथा आस्ट्रेलिया जैसे देशों से कपास की पूर्ति प्राप्त करने की सम्भावना को प्रोत्साहित करने के लिए बाध्य कर दिया। भारत में रलों के निर्माण से यह प्रक्रिया और भी आसान हो गई तथा उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में ब्रिटेन ने भारत तथा मिस्र से भारी मात्रा में कपास का आयात किया। मिस्र से प्राप्त रूई अच्छी किस्म की मानी जाती थी और वह अमरीकी रूई के समकक्ष ही थी।

रूई की पूर्ति के अभाव के भय से बीसवीं शताब्दी के आरम्भ होते ही 1902 में ब्रिटिश कपास उत्पादक सघ का गठन किया गया। इस सस्था ने ब्रिटिश उष्ण जलवायु वाले उपनिवेशों में कपास की खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारी मात्रा में रकम लगाई। इसका परिणाम यह रहा कि भारत तथा वेस्टइण्डीज में कपास की किस्म में भी सुधार हुआ तथा उनका उत्पादन भी बढ़ा।

प्रथम महायुद्ध छिड़ जाने से भी ब्रिटिश सूती वस्त्र उद्योग को भारी धक्का लगा। दूर-दराज के देशों से समुद्री मार्ग द्वारा कपास का आयात करना बहुत कठिन बन गया। कच्ची रूई की कमी आ जाने के कारण युद्ध की अवधि के दौरान सूती वस्त्र उद्योग को कपास नियन्त्रण समिति (Cotton Control Committee) के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत ले जाया गया। कपास का गश्तबन्ध करना पड़ा। युद्ध के कारण जहाजों को अन्य स्थानों पर भेजना पड़ा जिससे कई बाजार हाथ से निकल गये।

प्रथम विश्व-युद्ध के बाद सूती वस्त्र उद्योग

प्रथम विश्व-युद्ध के समाप्त होने के तुरन्त बाद ब्रिटिश सूती वस्त्र उद्योग के लिए उपनिवेशों से वस्त्र की माँग में एक अस्थायी उफान आया। किन्तु उसके बाद पुनः अवनति आरम्भ हो गई। 1924 तक तो सूत व कपड़े के उत्पादन में एक-तिहाई गिरावट आ चुकी थी। 1911 से 1924 के बीच लगभग 50,000 श्रमिक बेकार हो गये। सूती वस्त्र उद्योग की अवनति का प्रमुख कारण यह था कि उद्योग के हाथ से भारत तथा चीन जैसे बड़े बाजार हाथ से निकल गये थे। ये दो देश ब्रिटिश सूती वस्त्र उद्योग के कुल उत्पादन का लगभग दो-तिहाई माल खरीदते थे। 1913 से 1929 के बीच ब्रिटिश सूती वस्त्र उद्योग ने इन दोनों देशों में क्रमशः 58 तथा 71 प्रतिशत बाजार खो दिये थे। ऐसा इसलिए हुआ कि युद्ध के बाद जापान एक शक्तिशाली प्रतिस्पर्द्धी के रूप में अवतरित हुआ तथा चीन व भारत में स्थानीय स्तर पर भी सूती वस्त्र उद्योग काफी पनप गया। 1930 तक इन देशों में स्थानीय सूती वस्त्र उद्योग वहाँ की आधी जरूरतें पूरी करने लग गया था तथा ब्रिटेन का भाग (वहाँ की कुल माँग में) जो प्रथम युद्ध से पूर्व 71 प्रतिशत तक था, वह गिरकर 29 प्रतिशत पर आ गया।

पहले महायुद्ध के बाद ब्रिटिश सूती वस्त्र उद्योग की अवनति काफी अंश तक इन वर्षों में जापानी वस्त्र उद्योग की तीव्र प्रगति का भी परिणाम मानी जा सकती है। प्रथम विश्व-युद्ध के बाद जापान को न केवल भारतीय बाजार पर अधिकार करने में सफलता मिल गयी बल्कि चीन के बाजार में भी उसका प्रतिशत भाग 1913 के 22 से बढ़कर 1929 में 67 हो गया। ब्रिटिश सूती वस्त्र उद्योग की अवनति को अधिक तीव्र बना देने के लिए कुछ ऐसे तत्त्व भी उत्तरदायी थे जो उसके वस के बाहर थे। कच्चे माल के स्रोत से बहुत दूर लकाशायर में सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण का एक प्रमुख कारण यही था कि प्रथम महायुद्ध से पहले तब ग्रेट ब्रिटेन में उद्योगों तथा यातायात के क्षेत्र में एक व्यापक क्रान्ति हो चुकी थी। इसके अतिरिक्त सुदूर पूर्व के देश औद्योगीकरण में बहुत धीमे थे। लेकिन प्रथम महायुद्ध के बाद पूर्वी देशों में भी उद्योगों का विकास आरम्भ हो गया था। इसके अतिरिक्त पूर्वी देशों को एक स्वाभाविक लाभ तो यह था कि उनके पास कच्चे माल का भण्डार था तथा दूसरी ओर उनके यहाँ विशाल स्थानीय बाजार भी उपलब्ध थे। इन बदली हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कई लेखकों ने तो यहाँ तक मान लिया कि लकाशायर के वस्त्र उद्योग की समाप्ति सिर्फ थोड़े से समय का प्रश्न रह गया है।

1930 की महान् मन्दी

1930 में महान् मन्दी की स्थिति ने आग में घी डीकने का ही काम किया और ब्रिटिश सूती वस्त्र उद्योग की हालत और भी गम्भीर हो गयी। सूत की बनी चीजों का निर्यात 1932-33 में 1910-11 के मुकाबले एक-तिहाई रह गया। पूर्वी देशों के कृषकों के पास विद्यमान त्रय-शक्ति का अभाव होने (कृषि पदार्थों के

मूल्यों में मन्दी के कारण भारी गिरावट आ चुकी थी) तथा जापान द्वारा गलाकाट प्रतियोगिता करने से भी ब्रिटिश सूती वस्त्र उद्योग में 1930 के बाद भारी गिरावट आती चली गयी। इसके अतिरिक्त भारत की स्थानीय कपड़ा मिलों ने भी अपना उत्पादन अत्यधिक बढ़ा लिया था। इन सब तत्त्वों ने मिलकर लकागायर की सूत की बनी चीजों की मांग में अस्थायी नहीं बल्कि स्थायी कमी कर दी।

ब्रिटिश सूती वस्त्र उद्योग की हालत निरन्तर गम्भीर होती जा रही थी और महान् मन्दी के वर्षों में उसे सुधारने के लिए कोई सन्तोषप्रद हल नहीं ढूँढा जा सका था। इस बीच ब्रिटिश सूती वस्त्र उद्योग को एक धक्का तब और लगा जब भारतीय तथा जापानी सूती वस्त्र मिलों ने उत्पादन के ऐसे तरीके अपनाने आरम्भ कर दिये कि त्रिनसेसून की बनी वस्तुओं की उत्पादन लागत एकदम नीचे आ गयी। इस तरह 1930 के बाद ब्रिटिश सूती वस्त्र उद्योग के सामने फिर एक बार अपने यहाँ बनाने वाली सूती वस्तुओं की उत्पादन लागत घटाने का प्रश्न उठ खड़ा हुआ। इस काम को प्रारम्भ करने का अर्थ था सम्पूर्ण उद्योग का पुनर्गठन तथा बीमार व पुरानी पढ़ चुकी औद्योगिक इकाइयों को सूती वस्त्र उत्पादन के क्षेत्र से निकाल बाहर करना। 1928 में मम्बई बनाने की नीति (policy of combination) प्रारम्भ की गयी जिसके अन्तर्गत रुई व्यापार सम्म्यान की एक संयुक्त समिति (joint committee of cotton trade organisation) गठित की गयी। इस समिति के गठन का उद्देश्य अन्तिम रूप में देश के एक करोड़ तकुओं तथा 30,000 करघों पर नियन्त्रण स्थापित करना था। किन्तु सूती वस्त्र उद्योग में बहुत बड़ी मात्रा में बेकार पड़ी क्षमता विद्यमान थी और जब तक उसमें लगी पूँजी को यट्टा खाते नहीं लिप्य दिया जाता (write-off) तब तक सम्पूर्ण उद्योग की वित्तीय स्थिति नहीं सुधर सकती थी। किन्तु यह सारी व्यवस्था चूँकि एग्नित्त थी इसलिए इसे अधिक समर्थन नहीं मिल पाया। वह सफल नहीं हो पायी।

अन्त में, सरकार ने स्थिति को सुधारने तथा उद्योग को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से एक तकुआ बोर्ड (spindle board) 1936 में गठित किया। पुराने तकुओं को निकाल बाहर फँकने व उद्योग की क्षमता में सुधार करने का निश्चय किया गया। 1939 तक बोर्ड ने लगभग 40 लाख तकुओं को निकाल बाहर किया था। मितम्बर 1939 में सरकार ने एक और व्यापक उपाय किया जिसके अन्तर्गत सूती वस्त्र उद्योग पुनर्गठन विधेयक पारित किया गया। सरकार द्वारा किये गये इन प्रयासों का परिणाम भी अच्छा निकला तथा सूती वस्त्र उद्योग में कुछ सीमा तक अपनी खोई हुई शक्ति पुनः प्राप्त की। किन्तु इसके बावजूद 1939 में स्थिति यह थी कि लगभग एक लाख से अधिक मजदूर बेकार थे तथा सूती वस्त्र उद्योग में लगी हुई एक-तिहाई मशीनरी बेकार पड़ी हुई थी।

द्वितीय विश्व-युद्ध और सूती वस्त्र उद्योग

द्वितीय विश्व-युद्ध के छिड़ने के साथ ही सेना के लिए कपड़े बनाने के भारी माना में ऑर्डर्स (orders) मिले जिससे सूती वस्त्र उद्योग को काफी प्रोत्साहन

मिला। लेकिन युद्ध छिड़ जाने का एक परिणाम यह भी हुआ कि उद्योग पर लगे सरकारी नियन्त्रण और भी कड़े हो गये। इसके अतिरिक्त समुद्री मार्ग असुरक्षित हो गये तथा अनेक व्यापारिक जहाजों को सैनिक कार्यों में लगा दिया गया। 1940 तक तो सूती वस्त्र उद्योग के सामने श्रमिकों तथा कच्चे माल की बेहद कमी आ खड़ी हुई। सरकार ने दो नई केन्द्रीय संस्थाएँ कपास बोर्ड (cotton board) तथा कपास नियन्त्रण संस्था (cotton control body) स्थापित की। 1941 में कपास की सीमित पूर्ति की व्यवस्था (limitation of supplies orders) के अन्तर्गत मिलों को रुई की पूर्ति तीन महीनों में एक बार की जाने लगी तथा नागरिकों को दिये जाने वाले कपड़ों पर भी कुछ प्रतिबन्ध लगा दिये गये। ब्रिटेन के व्यापार बोर्ड (board of trade) ने यह सलाह दी कि रुई के अभाव को देखते हुए सूती वस्त्र के उत्पादन को केन्द्रीकृत कर दिया जाना चाहिए। इस नवीन व्यवस्था के अन्तर्गत दो-तिहाई चुनी हुई मिलों को तो सूती कपड़े का उत्पादन करते रहने की अनुमति प्रदान की गयी लेकिन शेष एक-तिहाई मिलों को बन्द कर दिया गया।

सूती वस्त्र के उत्पादन में इस केन्द्रीकरण ने एक नई समस्या उत्पन्न कर दी। कई सारी मिलें बन्द कर दिये जाने में मजदूर वर्ग सूती वस्त्र उद्योग से असन्तुष्ट हो गया। सूती वस्त्र उद्योग में लगे हुए अनेक श्रमिकों ने युद्ध के दौरान उपलब्ध अनेक वैकल्पिक काम ढूँढ़ लिये तथा सूती वस्त्र उद्योग को एकदम छोड़ दिया। परिणाम यह रहा कि सूती वस्त्र उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या दिसम्बर 1939 के 3 87 लाख के स्तर से गिरकर दिसम्बर 1943 तक 2 29 लाख के स्तर पर आ गयी।

सूती वस्त्र उद्योग में द्वितीय विश्व-युद्ध के दौरान रोजगार

वर्ष	कुल रोजगार (हजारों में)
1939	387
1940	377
1941	266
1942	247
1943	229
1944	237
1945	256

जब 1945 में दूसरा महायुद्ध समाप्त हुआ तो सूती वस्त्र उद्योग को पुनः घातिकालीन परिस्थितियों के अनुरूप ढालना आवश्यक हो गया। सम्पूर्ण सूती वस्त्र उद्योग के पुनर्गठन का एक तीव्र कार्यक्रम आरम्भ किया गया। इन प्रयत्नों का परिणाम यह रहा कि 1951 तक तो सूती वस्त्र उद्योग के उत्पादन में वृद्धि होती रही लेकिन उसके बाद फिर एक बार उसे धक्का लगा जब विदेशों में ब्रिटेन में बने

कपड़े की माँग में भारी गिरावट आ गयी। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद उत्पादन, रोजगार तथा निर्यात के क्षेत्र में भयंकर उतार-चढ़ावों का युग प्रारम्भ हो चुका था।

सूती वस्त्र उद्योग में रोजगार उत्पादन तथा निर्यात

वर्ष	रोजगार (‘000 में)	सूत उत्पादन (मि० पाँड)	वस्त्र उत्पादन (मि० गज)	सूत निर्यात (मि० पाँड)
1937	359	1,376	4,124	159
1946	240	781	1,974	19
1951	319	1,077	2,961	65
1958	239	774	2,030	27

उपर्युक्त आँकड़ों को देखने से यह बात तो काफी स्पष्ट हो जाती है कि द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद से ब्रिटिश सूती वस्त्र उद्योग सकट की अवस्थाओं से गुजरता रहा है। ऐसी कई कारण रहे हैं जिन्होंने मिलकर ब्रिटिश सूती वस्त्रों की अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में स्थिति को काफी कमजोर बना दिया है। इन कारणों में से कुछ मुख्य कारण निम्न हैं।

(1) ब्रिटिश सूती वस्त्र उद्योग जो कि औद्योगिक क्रान्ति के पूर्ण एकाधिकार वाले स्वर्णिम दिनों में पनपा था (जब सभी औपनिवेशिक बाजारों पर ब्रिटेन का पूर्ण नियन्त्रण था) अब ऐसी स्थिति में पहुँच गया है जहाँ उसे जापान, भारत तथा कुछ यूरोप के देशों में घोर प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना पड़ रहा है। विश्व बाजार में उसका पूर्ण एकाधिकार समाप्त हो गया है। इतना ही नहीं, अब इंग्लैंड का घरेलू बाजार भी गट्टर कुल के देशों से आने वाले सूती सामान से भर गया है।

(2) पिछले कुछ वर्षों में विश्व में कई अन्य धागे जैसे कृत्रिम रेशम, नाइलॉन, टेरेलिन, कृत्रिम धागा (acrylic fibre) आदि भारी मात्रा में तैयार किये जा रहे हैं। इन्हें रासायनिक प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। ये धागे अधिक टिकाऊ होते हैं, देखने में ज्यादा खूबसूरत और बनाने में कम खर्चाली होते हैं। इनके अत्यधिक उत्पादन ने सूती वस्त्र की माँग को विपरीत रूप से प्रभावित किया है तथा सूती कपड़ों के स्थान पर अब इनका प्रयोग किया जाने लगा है।

(3) अपने प्रतिस्पर्द्धी जापान द्वारा काम में ली जा रही आधुनिक मशीनों व उपकरणों की तुलना में ब्रिटिश सूती वस्त्र उद्योग द्वारा प्रयुक्त मशीनें पुरानी और दिनातीत (outdated) हैं तथा उनको बदलने की प्रक्रिया भी काफी धीमी है। यहाँ तक कि ब्रिटिश सूती वस्त्र उद्योग द्वारा प्रयुक्त उत्पादन की तकनीकों के मुकाबले जापान की तकनीक में अत्यधिक सुधार हो चुका है। इन बातों का परिणाम यह हुआ है कि ब्रिटिश सूती वस्त्र उद्योग अपने प्रतिस्पर्द्धियों से प्रभावशाली ढंग से मुकाबला करने की स्थिति में नहीं रह गया है। यही वजह है कि अब जापानियों ने

सूती वस्त्र के उत्पादन में विश्व में प्रधानता की स्थिति बना ली है।

(4) नये विनियोगकर्ता सूती वस्त्र उद्योग में अपनी पूंजी लगाने में अधिक हिचकिचाहट प्रदर्शित करते रहे हैं क्योंकि अब यह स्पष्ट हो चला है कि इस उद्योग का भविष्य उज्ज्वल नहीं है। इस स्थिति ने भी सूती वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण को अत्यधिक बढिन बना दिया है।

(5) एक ओर प्रतिस्पर्धी देश जापान और भारत को यह लाभ प्राप्त है कि वहाँ सस्ता श्रम उपलब्ध है जिसे काम में लेकर वे अपनी उत्पादन लागत कम रख सकते हैं तो दूसरी ओर ब्रिटिश सूती वस्त्र उद्योग में अभी भी अत्यधिक कुशल श्रमिकों को लिया जा रहा है जिन्हें बहुत ऊँची तनखाहें देने की जरूरत पड़ती है। इसका परिणाम यह है कि ब्रिटिश सूती माल की उत्पादन लागत अपेक्षाकृत ऊँची रहती है।

इस बारे में तो अब रचमात्र भी सन्देह नहीं रह गया है कि ब्रिटिश सूती वस्त्र उद्योग के लाभ कमाने के दिन समाप्त हो गये हैं। उपनिवेशों के समाप्त हो जाने तथा चारों तरफ शक्तिशाली प्रतिस्पर्द्धियों से घिर जाने के साथ ही ब्रिटिश सूती वस्त्र उद्योग एक दूसरे ही युग में प्रवेश कर चुका है। लेकिन इन निराशाजनक प्रवृत्तियों के उभरने का यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि ब्रिटिश सूती वस्त्र उद्योग का भविष्य एकदम अन्धकारपूर्ण हो चुका है। सच्चाई यह है कि आज तक भी सूती वस्त्र उद्योग ब्रिटेन में तैयार माल वाले उद्योगों (manufacturing industry) में सबसे महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है तथा देश से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में भी सूती वस्त्र का निर्यात काफी प्रमुख बना हुआ है। 1960 तथा 1970 वाले दशकों में इस दिशा में अनेक प्रयास किये गये हैं कि ब्रिटिश सूती वस्त्र उद्योग मजबूत और स्वस्थ बन सके और उनका अच्छा परिणाम भी निकला है। 1979 में ब्रिटेन का सूती वस्त्र उद्योग पुनः सन्तोषजनक स्थिति में पहुँच गया है।

2 लौह और इस्पात उद्योग

इंग्लैण्ड में लोहे का उत्पादन बहुत प्राचीन काल से होता रहा है। लोहे को गलाने का काम रोमन काल तथा एंग्लो-साक्सन (anglo-saxon) काल में बराबर किया जाता रहा तथा मध्य युग में यह उद्योग काफी फला-फूला। लोहे तथा इस्पात का उपयोग पहले तो तलवारें बनाने के लिए किया जाता था तथा बाद में, विशेष रूप से चौदहवीं सदी के बाद, उसका उपयोग तोपें बनाने के काम में किया गया। लोहे के लिए उस समय भी माँग इतनी अधिक थी कि उसका आयात किया जाता था।

लोहे का उत्पादन तथा उसका इस्पात की शक्ल में रूपान्तरण अनेक अवस्थाओं से गुजरा है। प्रत्येक अवस्था को पूरा होने में कई वर्ष लगे हैं। 1750 तक लोहे को गलाने के लिए लकड़ी के कोयले काम में लिये जाते थे जिसका परिणाम यह हुआ कि देश में वनों का नाश होता चला गया। जैसे जैसे जंगलों का विनाश बढ़ा वैसे-वैसे लकड़ी काटने पर सरकारी नियन्त्रणों को भी बढ़ाया गया। इस स्थिति का परिणाम यह निकला कि लोहे का उत्पादन गिरता चला गया तथा 1740 में उसका वार्षिक

उत्पादन मात्र 18,000 टन रह गया था और इंग्लैंड स्वीडन तथा रूस से लोहे का आयात करने के लिए बाध्य हो गया।

इस स्थिति से निवटने के लिए खनिज कोयले का उपयोग (लकड़ी के कोयले के स्थान पर) लोहा गलाने के लिए करने की दिशा में ध्यान केन्द्रित किया गया। अठारहवीं शताब्दी के शुरू में अब्राहम डर्वी नाम के व्यक्ति ने कोयले को कोक (coke) में रूपान्तरित करने की विधि खोज निकाली तथा कोक का उपयोग लोहा गलाने के लिए किया जाने लगा। इस खोज ने लोहा गलाने के काम को जगलो की कटाई से असम्बद्ध कर दिया। हेनरी कोर्ट द्वारा 1784 में की गयी खोजों से लोहे का सस्ता तथा अत्यधिक मात्रा में उत्पादन सम्भव बना। लोहा गलाने की भट्टियों में सुधार के प्रयासों को तब भारी सफलता मिली जब 1828 में नेलसन ने गर्म भट्टी (hot blast) का आविष्कार किया जिससे न केवल लोहा गलाने में कम समय लगने लगा बल्कि उससे लिए ईंधन की आवश्यकता भी कम हो गयी। अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में विल्किंसन ने लोहे का उपयोग पुल, जहाज तथा मकान बनाने के काम में किया। लोहे के उपयोग के प्रति विल्किंसन का प्रेम कितना गहरा था यह तो इसी से स्पष्ट है कि अपनी मृत्यु के समय उसने यह निर्देश दिया था कि उसे लाहे के बक्से (coffin) में रखकर गाड़ा जाए।¹

अठारहवीं शताब्दी के अन्त में रूस तथा स्वीडन द्वारा लोहे पर लगाये गये भारी तटकरी ने इंग्लैंड के लिए लोहे के आयात को रोक दिया बनाकर भी लौह उद्योग के विकास में मदद दी। रेलों के निर्माण, जहाजों के निर्माण में लकड़ी के स्थान पर लोहे का उपयोग किये जाने तथा मशीनों के निर्माण में लोहे के निरन्तर बढ़ते हुए उपयोग ने भी लोहे की माँग को अत्यधिक बढ़ा दिया था। इन सब कारणों ने मिलकर इंग्लैंड के लौह उद्योग का इतना अधिक विकास किया कि 1890 तक इंग्लैंड लोहा व इस्पात का उत्पादन करने वाले विश्व के देशों में प्रथम स्थान पर रहा।

उन्नीसवीं शताब्दी के दौरान लोहे में कार्बन की मात्रा नियन्त्रित करके इस्पात की किस्म में भारी सुधार किये गये। इस कार्य के लिए हेनरी बेसेमर (Henry Bessemer) ने एक बहुत शक्तिशाली भट्टी विकसित करके 1855 में एक नई प्रक्रिया की शुरुआत की। पुराने नरम लोहे (malleable iron) के स्थान पर बेसेमर इस्पात (Bessemer steel) अत्यधिक श्रेष्ठ था। इस्पात के उत्पादन में एक और सुधार की शुरुआत 1878 में गिलक्राइस्ट तथा यॉन्सन द्वारा की गयी जिससे फॉलफोरस युक्त कच्चे लोहे का इस्पात तैयार करने की दिशा में उपयोग सम्भव बन गया। 1867 में साइमस तथा मार्टिन ने मिलकर एक खुली भट्टी पद्धति (open hearth system) विकसित की। साइमस ने तो 1878 में ही एक विद्युत भट्टी भी तैयार कर डाली थी लेकिन उसका बड़े पैमाने पर उपयोग नहीं किया गया। फिर भी यह भट्टी अच्छी किस्म का इस्पात तैयार करने के लिए काफी उपयोगी है।

इंग्लैण्ड में लौह-पिंड उत्पादन

वर्ष	उत्पादन (टनो में)
1720	17,000
1740	18 000
1788	68 000
1839	13 47 000
1859	38 00 000
1871	65 00 000
1913	76 63 000

1870 के बाद जर्मन तथा अमरीकी लौह व इस्पात उद्योग की तीव्र प्रगति ने ब्रिटिश उद्योग की समृद्धि के लिए खतरा उपस्थित कर दिया। इन दोनों देशों में लौह व इस्पात उद्योग की प्रगति इतनी तीव्र थी कि 1890 तक अमरीका ने ब्रिटिश लौह व इस्पात उद्योग को पीछे छोड़ दिया तथा 1903 तक जर्मनी भी इंग्लैण्ड से आगे निकल गया। 1913 तक तो स्थिति यह हो गयी थी कि अमरीकी लौह व इस्पात का उत्पादन ब्रिटिश उत्पादन का चौगुना तथा जर्मन उत्पादन ब्रिटिश उत्पादन का तिगुना हो चुका था। इन देशों में लोहे के उत्खनन में आसानी ने भी प्रतिस्पर्द्धियों के रूप में उनकी क्षमता काफी बढ़ा दी थी। इससे ब्रिटिश लौह व इस्पात के निर्यातों में गिरावट आयी। किन्तु 1900 के बाद निर्यात में वृद्धि का एक नया दौर आया तथा ब्रिटेन के निर्यात भी 29 मिलियन पौण्ड से बढ़कर प्रथम महायुद्ध से पहले तक 48 मिलियन पौण्ड हो गये।

✓ प्रथम महायुद्ध और लौह एवं इस्पात उद्योग

प्रथम महायुद्ध से पहले तक ब्रिटिश लौह और इस्पात उद्योग की दो प्रमुख विशेषताएँ थी (1) प्रथमतः सम्पूर्ण उद्योग देश के कोयला उत्पादक क्षेत्र के हृदय गिरे केन्द्रित था जिसमें कि उद्योग के लिए लौह व इस्पात का उत्पादन भारी मात्रा में तथा सस्ती लागत पर कर सकना सम्भव था। (2) दूसरी विशेषता यह थी कि उद्योग इस रूप में संगठित था कि उसका कच्चे लोहे कोयले तथा इस्पात मिलों पर पूरा नियन्त्रण था। इस प्रकार का केन्द्रीकरण बड़े पैमाने की मिनव्ययिताएँ प्राप्त करने में सहायक होता है। 1928 में देश के कुल लौह व इस्पात उत्पादन का 70 प्रतिशत भाग 20 फर्मों द्वारा उत्पादित होता था। किन्तु अफसोस की बात यह रही कि ब्रिटिश लौह व इस्पात उद्योग में इस सीमा तक केन्द्रीकरण होने के उपरान्त भी वह बहुत मजबूत नहीं बन पाया क्योंकि इसी अवधि में अमरीका तथा जर्मनी में लौह व इस्पात उद्योग में और भी अधिक केन्द्रीकरण हो चुका था। जर्मनी में तो सम्पूर्ण लौह व इस्पात उत्पादन का 70 प्रतिशत केवल 5 फर्मों के हाथ में केन्द्रित था जबकि अमरीका में सिर्फ 2 फर्मों देश के कुल उत्पादन का 55 प्रतिशत भाग उत्पादित कर रही थी।

प्रथम महायुद्ध की अवधि की एक अन्य विशेषता यह भी रही कि इस अवधि

मे विश्व के कई और देशों में भी लौह व इस्पात के उत्पादन में वृद्धि हो गयी। प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने तक विश्व स्तर पर लौह व इस्पात उद्योग की कुल उत्पादन क्षमता में काफी वृद्धि हो चुकी थी। युद्ध के तुरन्त बाद इंग्लैंड के लौह व इस्पात उद्योग पर उसकी माँग में कमी होने का भी विपरीत प्रभाव पड़ा। ऐसा विशेष रूप से इसलिए हुआ कि इंग्लैंड में बने लोहे की उत्पादन लागत अपेक्षाकृत ऊँची थी तथा इस बीच विश्व माँग का झुकाव लोहे की जगह इस्पात की ओर हो गया था। 1929-33 की अवधि में आयी विश्व मंदी ने उद्योग की हालत और भी खराब कर दी। इस बात का अनुमान केवल इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि 1928-33 के बीच लौह पिंड व इस्पात का उत्पादन क्रमशः 7.29 व 9.6 मिलियन टन से घटकर 4.12 व 7.0 मिलियन टन रह गया था।

1927 में जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस तथा लासमबर्ग द्वारा बनाये गये अन्तर्राष्ट्रीय इस्पात सघ (International Steel Cartel) से ब्रिटिश लौह व इस्पात उद्योग को एक ओर धक्का लगा। घरेलू स्तर पर तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उठ खड़ी हुई इन चुनौतियों का मुकाबला करने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार ने दो संस्थाओं का गठन किया। पहली संस्था ब्रिटिश इस्पात निर्यात सघ (British Steel Export Association) तथा दूसरी संस्था लौह व इस्पात शोध संस्थान (Iron and Steel Research Council) के नाम से जानी गई। इन संस्थाओं के गठन का उद्देश्य देश के लौह व इस्पात उद्योग का विवेकीकरण (rationalisation) करना था तथा बैंक ऑफ इंग्लैंड ने, अपनी सहायक बैंकिंग संस्थाओं के माध्यम से, इस प्रकार के विवेकीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की स्वीकृति दे दी थी।

किन्तु आश्चर्य की बात यह रही कि जिन दिनों ब्रिटिश लौह व इस्पात उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए ये सब प्रयास किये जा रहे थे उन्हीं दिनों लौह व इस्पात उद्योग 1929 की महान् मंदी के कुचक्र में फँस गया। सरकार को अपनी स्वतन्त्र व्यापार की नीति का परित्याग करने के लिए बाध्य होना पड़ा तथा उसने लौह व इस्पात उद्योग को संरक्षण देने की नीति भी अपनायी। एक नई संस्था गठित की गयी जिसका नाम लौह व इस्पात उद्योग की राष्ट्रीय परिषद् (National Council of Iron and Steel Industry) रखा गया। इसका उद्देश्य उद्योग को पुनः सक्रिय करना था। लेकिन यह संस्था भी उद्योग को मंदी के पंजों से छुड़ा पाने में सफल नहीं हो पायी। लौह व इस्पात उत्पादकों को सरकार द्वारा आयातित लोहे व इस्पात पर भारी मात्रा में तटकर लगा देने से घरेलू बाजार तो प्राप्त हो गया लेकिन ये उत्पादक तो अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भी अपना हिस्सा प्राप्त करना चाहते थे। इस कार्य के लिए ब्रिटिश लौह व इस्पात सघ (British Iron and Steel Federation) ने अन्तर्राष्ट्रीय इस्पात सघ (International Steel Cartel) के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किये जिसके अनुसार उद्योग को विदेशी बाजारों में उसके 1934 के निर्यातों के बराबर अंश (Quota) प्रदान किया गया। इन उपायों से ब्रिटिश लौह व इस्पात उद्योग को आंशिक रूप से स्थिति सुधारने में सफलता मिली।

द्वितीय विश्व-युद्ध में लौह व इस्पात उद्योग

युद्ध के दौरान लौह व इस्पात की सैनिक आवश्यकताओं के कारण बढ़ी हुई माँग के दबाव ने उद्योग को काफी सहारा दिया। 1936 में स्थिति में सुधार के बाद से ही लौह व इस्पात की माँग में निरन्तर वृद्धि होती जा रही थी और उसे पूरा करने के लिए देश की खानों से निकाला जाने वाला कच्चा लोहा अपर्याप्त था। इसके परिणामस्वरूप युद्ध-पूर्व के वर्षों की बढ़ती हुई माँग को पूरा करने के लिए भारी मात्रा में कच्चे लोहे (iron-ore) का आयात करना पड़ा। किन्तु द्वितीय विश्व-युद्ध के वर्षों में जगह-जगह हुई नौसैनिक नाकेबन्दियों (Naval Blockades) तथा जहाजों से कच्चा लोहा पूर्ति में भारी कमी आ गयी। इस तरह आयातित लोहा सादकर लाने ले जाने में बढ़ते हुए खतरो की वजह से युद्ध-पूर्व के 5 मिलियन टन के स्तर से गिरकर 1941 में 1.5 मिलियन टन वार्षिक पर आ गया। कच्चे लोहे की पूर्ति में इतनी अधिक गिरावट आ जाने से नई व्यवस्था करने की आवश्यकता पड़ी तथा इस्पात मिलों को पुराना लोहा (iron-scrap) कच्चे माल के रूप में उपलब्ध कराया गया।

द्वितीय विश्व-युद्ध के दौरान लौह व इस्पात का उत्पादन

(हजार टनों में)

वर्ष	कच्चे लोहे का उत्पादन	लौह पिंडों का उत्पादन	इस्पात का उत्पादन
1939	14,486	7,980	—
1940	17,702	8,205	—
1941	18,974	7,395	10,127
1942	19,906	7,726	10,647
1943	18,494	7,187	10,282
1944	15,472	6,737	10,010
1945	14,175	7,107	8,865

यदि सम्पूर्णता से देखा जाए तो यही स्पष्ट होता है कि द्वितीय विश्व-युद्ध के कारण लौह व इस्पात की उत्पादन पद्धतियों में अनेक दूरगामी परिवर्तन हुए। युद्ध के कारण उत्पन्न हुई अनेक बाधाओं और कठिनाइयों के उपरान्त न केवल इस्पात और लौह का उत्पादन बनाये रखा गया अपितु उसमें वृद्धि भी की गयी। किन्तु दूसरा विश्व-युद्ध जैसे ही समाप्त हुआ उसके विनाशकारी प्रभाव दिखाई देने लगे और यह पाया गया कि लौह व इस्पात उद्योग तो सबसे अधिक खराब हालत में है। मारा का मारा यूरोप लोहे के अकाल (iron famine) से ग्रस्त था और बुरी तरह ध्वस्त हो चुका था। प्रो० जी० डी० एच० कोल ने लौह व इस्पात उद्योग की युद्ध के बाद की स्थिति का चित्रण करते हुए बड़ा ही सटीक सारांश निकाला है कि 'जर्मनी के उत्पादन के 15 मिलियन टन के 1938 के प्राप्त उत्पादन स्तर से गिरकर ढाई मिलियन टन पर आ जाने, फ्रांस तथा अन्य प्रमुख यूरोपीय देशों में 1937 के 15 मिलियन टन के समुक्त उत्पादन से घटकर 9 मिलियन टन पर

केन्द्रीय सस्या के द्वारा ही होता है।

1946 से लेकर 1955 तक विश्व के लौह व इस्पात उत्पादक देशों में ब्रिटेन तीसरे स्थान पर रहा। किन्तु जर्मनी व जापान के अभ्युदय के बाद ब्रिटिश लौह व इस्पात उद्योग ने अपनी सर्वोच्चता खो दी है तथा विश्व उत्पादन में इसका प्रतिशत भाग निरन्तर गिरता जा रहा है। 1946 में विश्व लौह व इस्पात उत्पादन में ब्रिटेन का भाग 10 प्रतिशत था जो 1956 तक गिरकर 8 प्रतिशत पर आ चुका था। स्वीडन व अन्य देशों पर कच्चे लोहे की आपूर्ति के लिए ब्रिटिश लौह व इस्पात उद्योग की भारी निर्भरता भी उसकी धीमी प्रगति के लिए उत्तरदायी रही है।

इन सब विपरीत परिस्थितियों के उपरान्त यह बात ब्रिटिश लौह व इस्पात उद्योग की प्रशंसा में अवश्य कहा जा सकती है कि वह आज तक भी इंग्लैंड का एक प्रमुख आधारभूत उद्योग बनी हुई है। यह उद्योग द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रारम्भ हुई विकट प्रतिस्पर्द्धा की स्थिति में भी न केवल अपना अस्तित्व बनाये रख सका है बल्कि इमने यह भी सिद्ध कर दिया है कि कच्चे माल का अभाव उद्योग के लिए कोई स्थायी कठिनाई नहीं है। आज दिन तक ब्रिटिश लौह व इस्पात उद्योग द्वारा प्रयुक्त आधे से भी अधिक कच्चा लोहा आयात किया जा रहा है किन्तु इमने उपरान्त उद्योग अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अपना पांव जमाये हुए है। ब्रिटिश लौह व इस्पात उद्योग की प्रशंसा में यह भी कहा जाना चाहिए कि उसी के कारण हमने इस्पात युग में प्रवेश किया है। यह नहीं कहा जा सकता कि इस्पात युग हमेशा-हमेशा के लिए चलता रहेगा। ऐसे अनेक मिश्रण (alloys) तैयार हो चुके हैं जो इस्पात से अधिक श्रेष्ठ हैं। धातु निर्माण के विज्ञान को तो अभी अन्तिम शब्द कह देने से पहले कई मजिलें तय करनी हैं।

3 कोयला उद्योग

औद्योगिक क्रान्ति ने हाथ से काम करने की जगह मशीनों द्वारा उत्पादन को प्रतिस्थापित कर एक आधारभूत परिवर्तन ला दिया था। मशीनें केवल शक्ति से ही चलाई जा सकती थीं और सबसे पहले उसकी पूर्ति जल द्वारा की गयी। समय के साथ भाप की शक्ति को पहचाना गया और भाप की शक्ति के उपयोग ने लोहे की माँग पैदा की क्योंकि वह मशीनों तथा इजिनो के निर्माण के लिए जरूरी था और कोयला उन्हें चलाने के लिए आवश्यक था। ग्रेट ब्रिटेन के पास लोहा व कोयला दोनों ही प्रचुर मात्रा में थे, यदि यह बात नहीं होती तो वह शायद ही इतनी प्रमुखता प्राप्त कर पाता।¹

उत्पादन के नये तरीके

खनिज कोयले का प्रयोग घरेलू काम-काज के लिए तो ब्रिटेन में शताब्दियों से होता आ रहा था किन्तु इसे तोड़ा गलाने (smelting) के काम के लिए अनुपयुक्त समझा जाता था क्योंकि इसमें गन्धक (sulphur) होता था। लेकिन सत्रहवीं शताब्दी

के अन्त तक जंगलो के नष्ट हो जाने के कारण लकड़ी के कोयलो का अभाव हो गया। जैसे-जैसे शहरो का विकास हुआ तथा रेलो का प्रसार हुआ वैसे-वैसे ईंधन की माँग बढ़ी। यह समस्या तब सुलझी जब डर्बी (Darby) ने एक ऐसा तरीका खोज निकाला जिससे खनिज कोयले को नरम कोयले यानि कि कोक (coke) में बदला जा सकता था (गन्धक अलग करके) तथा उसे लोहा गलाने के काम में लिया जा सकता था।

उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य तक कोयले के उपयोग के क्षेत्र में अनेक नई खोजें हुईं। 1856 में विलियम हेनरी परकिंस ने एक ऐसी विधि खोज निकाली जिससे कोलतार द्वारा रंग की डाई (dyes) तैयार की जा सकती थी जो वस्त्रों के रंगने के काम आती थी। अब तो हमें कोयले से अनेको दवाएँ, रंग, सुगन्धित पदार्थ व सत प्राप्त होने लग गये हैं।

उत्खनन सम्बन्धी कठिनाइयाँ

प्रमुखता प्राप्त करने से पहले कोयला उद्योग को अनेक कठिनाइयों से गुजरना पड़ा और उन्हें दूर करना पड़ा। जैसे-जैसे कोयला निकाले जाने वाले गड्ढे गहरे होते उनमें पानी भरता चला जाता। अठारहवीं सदी से पहले इस पानी को हाथों से खाली किया जाता था। यह प्रक्रिया न्यूकमिन तथा जेम्स वॉट द्वारा भाप के इंजिन के आविष्कार के बाद काफी आसान हो गयी।

कोयले का खनन करने वालों के सामने दूसरी कठिनाई छतों का ढह जाना थी। अठारहवीं शताब्दी में यह एक आम प्रथा थी कि कोयला निकालते समय यहाँ-वहाँ कुछ खम्भे छोड़ दिये जाते थे और जब उस भाग पर काम पूरा हो जाता तो वे खम्भे हटा लिये जाते थे। 1810 के बाद यह आम रिवाज बन गया कि खान की छतों के नीचे मजबूत लकड़ी के बने खम्भे लगाये जाते। दूषित हवा निकालने के लिए पखो (exhaust fan) के 1837 में हुए आविष्कार से पहले खानों में रोशनदानों की भी भारी कठिनाई आती थी।

खिडकियों रोशनदानों की समस्या के साथ ही जुड़ी हुई एक अन्य समस्या रोशनी का प्रबन्ध करने की थी। खानों में खुले लैंप काम में लेना खतरा भरा काम था क्योंकि कोयले की परतों से विस्फोटक गैस निकलती रहती है। सर हम्फ्री डेवी द्वारा 1815 में आविष्कृत एक लैंप, जिसे डेवी लैंप का ही नाम दिया गया, ने इस समस्या को 'भी हल कर दिया'। अब तो अधिक सहत्वपूर्ण गलियारों में रोशनी करने के लिए विजली का उपयोग किया जाता है। 1839 में सोहे के तारों के सहारे चलने वाली ट्रांसी का आविष्कार होने से पहले खान के भीतर से कोयले को ऊपर तक लाना भी एक भारी समस्या थी। कोयला खान की एक और समस्या यह होती है कि खान की गहराई बढ़ने के साथ-साथ उसका तापमान भी बढ़ता जाता है। इस कठिनाई के कारण पहले बहुत गहराई तक खान खोदना असम्भव-सा था किन्तु कृत्रिम रूप से खानों को भीतर से ठण्डा रखने के तरीके खोज लिये जाने से यह कठिनाई भी दूर हो गयी।

एक अन्य कठिनाई जिसने इंग्लैंड में खनिज कोयले के उत्पादन को शताब्दियों तक काफी कम बनाये रखा, यह थी कि कोयले को देश के विभिन्न भागों तक पहुँचाना असम्भव था। भारी चीज होने के कारण यह खच्चरो या घोड़ों के बस की बात नहीं थी। नहरों से परिवहन की व्यवस्था के विकास तथा बाद में रेलों के जाल से कोयले का आवागमन न केवल आसान बन गया बल्कि उसकी लागत भी काफी कम हो गयी। कोयले को खानों के भीतर सीधेता से काटने की मशीनों के आविष्कार के बाद तो मानवीय श्रम की आवश्यकता में काफी कटौती सम्भव हो गयी।

काम की दशाएँ

आम जनता और यहाँ तक कि सरकार को भी अठारहवीं तथा उन्नीसवीं शताब्दी के पहले कुछ वर्षों तक कोयला खानों में काम की दशाओं से कोई सरोकार ही नहीं था। इन खानों में काम की दशाएँ इतनी अमानवीय थी कि बहुत गहराई तक उनमें कोयला काटने तथा उसे बाहर तक ढोकर लाने के काम में आदमियों, औरतों और बच्चों को लगाया जाता था जिन्हें दिन में चौदह-चौदह घण्टे काम करना पड़ता था। गम्भीर दुर्घटनाएँ होना आम बात थी। मजदूरी और व्यवसायों की अपेक्षा कुछ अधिक थी। स्कॉटलैंड के कोयला मजदूर तो इंग्लैंड के मजदूरों से भी बुरी हालत में काम करने के लिए मजबूर थे। उनकी हालत तो गुलामों की सी थी। अगर वह खान बेच दी जाती जिसमें वे काम कर रहे होते तो साथ में वे भी बिक जाते। उनकी हालत में सुधार अठारहवीं शताब्दी के अन्त में ही हुआ।

ब्रिटिश संसद ने उन्नीसवीं शताब्दी में कोयला खानों में काम करने वाले मजदूरों की काम की दशाएँ सुधारने के लिए अनेक कानून बनाये। 1842 में दस वर्ष से कम उम्र के बच्चों तथा किसी भी उम्र की लड़कियों या औरतों के खानों के अन्दर काम करने पर रोक लगा दी गयी। 1850 में खानों के निरीक्षण के लिए एक व्यवस्था स्थापित की गयी। 1860 तथा 1872 में कोयला खान नियमन कानून (Coal Mines Regulation Act) पारित किये गये। 1881 में गृह सचिव को कोयला खानों में होने वाली दुर्घटनाओं की जाँच करने का अधिकार दिया गया। 1911 के कोयला खान नियमन कानून में कोयला खानों से सम्बन्धित सम्पूर्ण कानून को संहिताबद्ध (codified) किया गया। इस कानून में खानों में खम्भों की व्यवस्था (roof support), मशीनों तथा विस्फोटकों (explosives) का उपयोग, रोशनदानों की व्यवस्था, सुरक्षा उपाय करने, दुर्घटना के समय कार्यवाही की प्रक्रिया तथा खानों के निरीक्षण में सम्बन्धित विषय शामिल किये गये। 1920 में एक शाही आयोग ने खानों के राष्ट्रीयकरण की सिफारिश की लेकिन सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया।

महान् मन्दों का काल

1929 की मन्दो आने के कुछ ही वर्षों पहले तब से ही कोयला उद्योग को घटती हुई माँग तथा बेकारी की समस्या का सामना करना पड़ रहा था। कोयला

खान के मालिकों ने यह तर्क दिया कि कोयले की माँग के स्तर को बनाये रखने के लिए कोयले के मूल्यों में कमी करना आवश्यक था तथा कोयले के मूल्यों में कमी तभी सम्भव थी जबकि मजदूरी में कमी की जाती। मालिकों के इस मुद्दाव का श्रमिकों ने स्वाभाविक रूप से विरोध किया और 1925 में एक आम हड़ताल तभी होने से बच सकी जब सरकार ने मजदूरी के तत्कालीन स्तर को बनाय रखने के उद्देश्य से अनुदान देने की घोषणा की। लॉर्ड सेम्पुअल की अध्यक्षता में नियुक्त एवं अन्य शाही आयोग ने मजदूरी के स्तर को अपरिवर्तित रखने के उद्देश्य से सरकार द्वारा दिये जाने वाले इस अनुदान की कटु आलोचना की तथा इसे बन्द करने की भी सिफारिश की किन्तु साथ ही आयोग ने कोयला खानों में काम करने वाले मजदूरों की दशा सुधारने के लिए भी कई उपाय सुझाए। इस आयोग ने यह भी सिफारिश की कि कोयला खानें निजी स्वामित्व एवं प्रबन्ध के अन्तर्गत ही रहनी चाहिए। जब अप्रैल 1926 में अनुदान बन्द कर दिया गया तो कोयला खान के मालिकों ने मजदूरी में कटौती करने की घोषणा कर दी और उसका परिणाम यह हुआ कि मजदूरों ने काम बन्द कर दिया। किन्तु कुछ सप्ताह बेकार घूमने के बाद श्रमिकों को मजदूरन काम पर लौटकर आना पड़ा क्योंकि उनके पास विलकुल पैसा नहीं बचा था। 1926 में पारित कोयला खान विधेयक (Coal Mines Act, 1926) ने तो खानों के अन्दर काम में एक घण्टा प्रतिदिन की वृद्धि भी कर दी। किन्तु बेकारे कोयला खान मजदूरों के पास कोई विकल्प नहीं था क्योंकि मन्दी पूर ज़ोरों पर थी और उनके सामने बेकारी की समस्या विकट थी। वे तो निजी स्वामित्व के अन्त होने की आशा कर रहे थे। वे मजदूरी की कटौती स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। किन्तु दोनों ही जगह उन्हें हार माननी पड़ी।

दो विश्व-युद्धों के बीच कोयला उद्योग

प्रथम विश्व-युद्ध छिड़त ही कोयला उद्योग को सरकारी नियन्त्रण में रख दिया गया। श्रम के अभाव के कारण भी उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ा। जहाजों के न मिल पाने के कारण कोयलों के निर्यात में भी कमी आयी। कोयला उद्योग ने अपने 287 मिलियन टन के उत्पादन का रिकॉर्ड 1913 में कायम किया।

कोयला उत्पादन में प्रगति

(मिलियन टन में)

वर्ष	उत्पादन	वर्ष	उत्पादन
1800	10	1918	287
1860	80	1924	267
1900	225	1930	244
1913	287	1933	208

प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर कोयला उद्योग की स्थिति में थोड़ा सुधार अवश्य आया किन्तु थोड़े ही समय में उद्योग को पुनः सबूट का गामना करना पड़ा।

किन्तु 1927 तक उद्योग ने निर्यात माँग में हुई अस्थायी वृद्धि के कारण बढ़ती हुई परिस्थितियों का पूरा प्रभाव अनुभव नहीं किया। दो विश्व-युद्धों के बीच के बाल में कोयले का उत्पादन विश्व-स्तर पर भी काफी बढ़ चुका था। हॉलैण्ड, भारत, स्पेन तथा जापान जैसे देश कोयले का भारी माना में उत्पादन करने लग गये थे और उनमें से कुछ न केवल घरेलू बाजार को सुरक्षा (protection) प्रदान कर रहे थे बल्कि वे उनके कोयले के निर्यात को बढ़ावा देने की दृष्टि से अनुदान भी दे रहे थे। प्रतिस्पर्द्धियों की इस नई लहर से ब्रिटिश कोयला उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ना अवश्यम्भावी था।

मन्दी समाप्त हो जाने के बाद भी कोयला उद्योग की धीमी गति से प्रगति के लिए ब्रिटिश कोयला उद्योग के सगठनात्मक दोष भी उत्तरदायी थे। देश के कई भागों में बिलरे हुए कोयला भण्डारों के कारण उनके प्रबन्ध में किसी प्रकार की एकरूपता स्थापित नहीं की जा सकती थी। कोयला उद्योग में अनेक छोटी छोटी इकाइयाँ थीं जिन पर आसानी से नियन्त्रण नहीं स्थापित किया जा सकता था। 1924 में लगभग 2400 कम्पनियाँ कोयला उद्योग में कार्यरत थीं। इसके अलावा ब्रिटिश कोयला उद्योग मूलतः पुराने उत्पादन के तरीकों से चल रहा था। 1913 तक भी ब्रिटिश कोयला खानों में मशीनों से कोयले की कटाई का कुल उत्पादन में प्रतिशत 8 था तथा कई आगामी वर्षों में भी उसमें कोई वृद्धि नहीं हुई जबकि इन्हीं वर्षों में जर्मनी में मशीनों से कोयले की खुदाई 2 प्रतिशत से बढ़कर 1928 में 85 प्रतिशत हो चुकी थी। इसके अलावा ब्रिटिश कोयला उद्योग इस्पात, विद्युत तथा रसायन से सम्बन्धित मेल-जोल वाली क्रियाओं से भी ताल-मेल स्थापित करके नहीं चल रहा था। निर्यात माँग पर अत्यधिक निर्भरता ने भी कोयला उद्योग की स्थिति और भी खराब कर दी।

कोयला उद्योग को फिर से पटरी पर लाने के उद्देश्य से 1930 में कोयला खान अधिनियम (Coal Mines Act, 1930) पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा कोयले के उत्पादन तथा उसकी बिजली को नियमित करने तथा उद्योग में विलय (amalgamations) को प्रोत्साहन देकर पुनर्गठित करने का प्रयास किया गया। किन्तु 1930 का अधिनियम अनेक वानूनी वारिकियों में उलझकर रह गया। इसलिए 1937 में सरकार द्वारा एक और कोयला विधेयक (Coal Bill) लाया गया जिसने छोटी इकाइयों के विलय को अनिवार्य बना दिया। कोयला उद्योग की स्थिति में सुधार लाने के लिए किये गये इन समस्त प्रयासों के बावजूद वह काफी दबा-दबा-भा रहा तथा यह स्थिति द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने तक बनी रही। कोयला उद्योग कम मजदूरी, भीषण बेकारी तथा बिगड़ते हुए औद्योगिक सम्बन्धों की बीमारियों से ग्रस्त रहा।

जब द्वितीय विश्व-युद्ध छिड़ गया तो सरकार ने एक योजना बनायी जिसके अनुसार कोयले का वार्षिक उत्पादन 270 मिलियन टन के लगभग बनाये रखना था। कोयले के उत्पादन तथा वितरण के अनेक स्तरों पर नियन्त्रण रखा जाता था। जब दूसरा विश्व-युद्ध समाप्त चलता चला गया तो कोयले के लिए माँग काफी बढ़ गयी और

उसकी माँग तथा पूर्ति के बीच अन्तर भी काफी चौड़ा हो गया। कोयले की कमी, उसके ऊँचे मूल्य तथा वितरण सम्बन्धी कठिनाइयों से निबटने के लिए एक अलग ईंधन व शक्ति मन्त्रालय की स्थापना की गयी। कोयले के उत्पादन में कमी आने का मुख्य कारण श्रमिकों का अभाव तथा कोयला निकालने की मशीनों का उपलब्ध न होना था। उद्योग में लगे हुए श्रमिकों की संख्या 1939 में 7 66 लाख से घटकर 1943 में 7 08 लाख रह गयी। खानों में अनुपस्थिति (absenteeism) भी बढ़ गयी तथा अनुपस्थित रहने वाले श्रमिकों की संख्या का देश की कोयला खानों में प्रतिशत 1939 के 6 9 से बढ़कर 1945 में 16 3 हो गया। अनुपस्थिति दर में यह वृद्धि आवश्यक सेवा अधिनियम (essential work order) लागू किये जाने के बावजूद हुई जिसमें श्रमिकों के उद्योग छोड़ने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था।

द्वितीय विश्व-युद्ध के दौरान कोयले का उत्पादन व उपभोग

(मिलियन टन में)

वर्ष	कुल उत्पादन	कुल उपभोग
1939	231	233
1940	224	222
1941	206	206
1942	205	205
1943	199	198
1944	193	193
1945	183	185

युद्ध के दौरान कोयला उद्योग बराबर गड़बड़ी का केन्द्र बना रहा। उसके संचालन में कठिनाइयाँ आती रही तथा उसकी समस्याएँ युद्ध समाप्त हो चुकने के बाद भी बनी रही। इस उद्योग की लागत बहुत ऊँची थी। कोयला उद्योग को यन्त्रोपकरण के लिए पूँजी प्राप्त करने में भी कठिनाई हो रही थी। खानों के भीतर काम आने वाली मशीनों का भी अभाव था। पुरानी खानें गहरी से गहरी होती जा रही थीं और उन्हें चलाना अत्यधिक खर्चीला काम साबित हो रहा था। मजदूरों को खानों पर काम करने के लिए ठहराने मात्र के लिए ऊँची मजदूरी देनी पड़ रही थी। इस तरह यह कहा जा सकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर कोयला उद्योग बड़ी बुरी हालत में था और उसे जड़ता की स्थिति से बचाने के लिए नान्तिकारी उपायों की जरूरत थी।

आधुनिक समय में कोयला उद्योग

समय बीतने के साथ कोयला खानों में काम की दशा में सुधार हुआ मगर खनिक फिर भी असन्तुष्ट ही रहे। यह स्पष्ट हो चुका था कि श्रमिक लोग तब तक सन्तुष्ट नहीं होंगे जब तक कि खाने निजी स्वामित्व के अन्तर्गत बनी रहेंगे। 1946 में, जब लेबर दल की सरकार बनी, कोयला खान राष्ट्रीयकरण विधेयक पारित किया

गया। कोयला खानों का अधिग्रहण करने के लिए एक राष्ट्रीय कोयला बोर्ड बनाया गया। यह बोर्ड कोयला खानों में होने वाले काम के लिए उत्तरदायी था और साथ ही औद्योगिक व उपभोक्ता मांग के लिए कोयला उपलब्ध कराना भी इसी का काम था। राष्ट्रीयकरण विधेयक 1 जनवरी 1947 को लागू किया गया तथा श्रमिकों ने इस दिन को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। मई 1947 में उद्योग में पाँच दिन का सप्ताह आरम्भ किया गया।

किन्तु कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण भी मजदूरों को सन्तुष्ट करने में असफल रहा है। काम की दशाओं में काफी सुधार हुआ है, मजदूरी में भी भारी वृद्धि हुई है, कोयला वाटने की मशीनें भी खानों में स्थापित की गई हैं। इसके बावजूद हड़तालें कम नहीं हुई हैं तथा श्रम विवादों को आसानी से हल नहीं किया जा सका है। युद्धोत्तर काल में हो रहा कोयले का उत्पादन बड़ी मुश्किल से ही घरेलू जरूरतों को पूरा कर पाता है। कोयले के निर्यात का तो अब प्रश्न ही नहीं रह गया है। 1958 में कोयले का कुल उत्पादन 202 मिलियन टन था और 1970 में यह लगभग 250 मिलियन टन था। यह उत्पादन स्तर 1913 के रिकार्ड उत्पादन से काफी नीचा ही था।

कोयला उद्योग पर विशेष ध्यान न दिये जाने का एक कारण यह भी है कि 1960 के बाद ईंधन की पूर्ति के अनेक वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग किया जाने लगा है। विद्युत शक्ति तैयार करने के लिए आणविक शक्ति का उपयोग किया जा रहा है। बीच में तो यही लगने लगा था कि शायद ऊर्जा के स्रोत के रूप में कोयले का उपयोग धीरे-धीरे समाप्त ही हो जायेगा। लेकिन 1973 व दिसम्बर 1978 की तेल मूल्य वृद्धियों (जिनसे तेल की कीमत चार गुने से भी अधिक हो चुकी है) के बाद कोयला उद्योग के लिए आशा की एक नई किरण जगी है। ईंधन के स्रोत के रूप में कोयले को पुनः प्रतिष्ठित किया जा रहा है।

4 आधुनिक जहाज निर्माण उद्योग

वणिकवादी विचारक (Mercantilists) देश के लिए एक मजबूत नौ-सेना के पक्ष में थे। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही उन्होंने इंग्लैंड में अनेक नौ-परिवहन विधेयक (Navigational Acts) पारित करवाये थे। सबसे पहला नौ-परिवहन विधेयक 1381 में पारित किया गया जिसमें यह व्यवस्था की गई कि सारे आयात व निर्यात इंग्लैंड के ही जहाजों के माध्यम से किये जायें। आगे के विधेयक 1532 तथा 1540 में पारित किये गये। 1650 में पारित किये गये नौ-परिवहन विधेयक ने इंग्लैंड के बागानों के साथ विदेशी जहाजों के व्यापार पर प्रतिबन्ध लगा दिया। 1660 के नौ-परिवहन विधेयक ने, जो अधिक व्यापक एवं स्पष्ट था, कुछ ऐसे सिद्धान्त बनाये जिन पर ब्रिटिश जहाजरानी का विकास अगली दो शताब्दियों तक नियमित होता रहा। इन नौ-परिवहन कानूनों का उद्देश्य, जैसा कि 1660 के विधेयक की भूमिका में लिखा गया, यह था कि 'जहाजों की सत्ता में वृद्धि तथा इंग्लैंड के नौ-परिवहन को प्रोत्साहन देना' जिसमें कि इंग्लैंड की सुरक्षा, सम्पत्ति

तथा शक्ति इतनी अधिक अन्तर्निहित थी।' ये नौ-परिवहन सम्बन्धी प्रतिबन्धात्मक कानून उन्नीसवीं सदी में अपनी उपयोगिता खो चुके थे जब कि मुक्त व्यापार की नीति को बढ़ावा दिया जाने लगा था। किन्तु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि अपने परित्याग के पहले इन कानूनों ने ब्रिटिश जहाजरानी उद्योग के विकास में भारी योगदान दिया था।

उन्नीसवीं शताब्दी में इंग्लैंड के जहाजरानी उद्योग में अनेकों महत्वपूर्ण तकनीकी परिवर्तन हुए। पहला भाप से चलने वाला जहाज पहले भाप से चलने वाले रेल इंजिन से काफी पहले बना लिया गया था। पहला वाष्प चालित जहाज विलियम सिमिंगटन (William Symington) द्वारा 1802 में निर्मित किया गया। 1819 में अन्ध महासागर को पार करने वाला प्रथम वाष्प चालित जहाज सवानाह (Savannah) था। 1824 में जनरल स्टीम नेविगेशन कम्पनी का निर्माण किया गया।

1869 में स्वेज नहर के यातायात के लिए खुल जाने से जहाजरानी उद्योग को भारी प्रोत्साहन मिला। आरम्भ में वाष्प चालित जहाज लकड़ी व लोहे दोनों को मिलाकर बनाये जाते थे तथा इनका उपयोग भी 19वीं सदी के उत्तरार्द्ध में ही आरम्भ हुआ। जहाज निर्माण में सुधार का क्रम जारी रहा। 1854 में एक चार सिलेंडर वाला जहाज बनाया गया जिसमें भाप भी ज्यादा पैदा होती थी और जो ईंधन भी कम खाता था। सर चार्ल्स पार्सन्स (Sir Charles Parsons) ने एक टर्बाइन (Turbine) का आविष्कार किया जिसने जहाजों की गति तथा विद्यमानता को काफी बढ़ा दिया। आज तक भी अधिकांश जहाज मोटर चालित ही हैं तथा वे ईंधन के रूप में तेल अथवा कोयले का उपयोग करते हैं।

जहाज निर्माण में होने वाले इन उत्तरोत्तर सुधारों के कारण इंग्लैंड न केवल विश्व में सबसे बड़ा जहाजी बेड़े वाला देश बन गया बल्कि वह सबसे आधुनिक बेड़े वाला देश भी बन गया। विदेशों में पजीकृत अनेकों जहाज ब्रिटेन में ही निर्मित होते थे। ब्रिटिश व्यापारिक जहाजी बेड़े में ऐसे जहाज थे जिनमें नवीनतम सुधार बिधे जा चुके थे और इसके कारण वे काम के उद्देश्य से मितव्ययितापूर्ण एवं लाभदायक थे।

1854 में नौ-परिवहन विधेयको (Navigational Acts) के निरस्त कर दिये जाने के बाद ब्रिटिश जहाजरानी उद्योग सरकारी हस्तक्षेप से लगभग पूरी तरह मुक्त हो चुका है। एक जहाजी कम्पनी के लिए रेल कम्पनी की तरह ससद की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक नहीं था क्योंकि रेलों की तरह जहाजों को लाइन बिछाने के लिए जमीन की आवश्यकता तो पड़ती ही नहीं थी। समुद्र ही उनके लिए मार्ग था और वह सबके लिए मुक्त था। इसका परिणाम यह भी हुआ कि इंग्लैंड के अनेक जहाज 'छड़े जहाज' (Tramp Ships) बन गये जो अपने लिए माल किसी भी बन्दरगाह से किसी भी अन्य बन्दरगाह के ढोते और जो भी किराया मिलता ले लेते। ऐसे जहाज वर्षों तक इंग्लैंड से बाहर रहते और उनकी गतिविधियों पर कोई नियन्त्रण लगाना भी सम्भव नहीं था उन्हें उनकी समुद्र में रह सकने की योग्यता (Seaworthiness)

के लिए जर्जा भी नहीं जा सकता था इसका परिणाम कई बार यह निकलता था कि नाविकों की जान के खतरे को अनदेखा करके पुराने जहाजों में उनकी क्षमता से भी अधिक माल भर दिया जाता। मालिक लोग तो अपने जहाजों का भारी बोमा करवा लेते और सिर्फ लाभ कमाने के फिक्र में रहते।

सरकारी नियमन (Governmental Regulations)

एक सासद सेम्युअल प्लिमसोल (Samuel Plimsol) पहला व्यक्ति था जिसने अनियन्त्रित जहाजी कंपनियों की हठधर्मी की आलोचना की तथा उनके खिलाफ आवाज उठाई। उसने इस बात पर बल दिया कि जहाजों को सलामती प्रमाण-पत्र (Fitness Certificate) तब तक नहीं जारी किया जाना चाहिए जब तक उनकी पूरी तरह जांच न कर ली जाए। यह अधिकार 1873 में व्यापार-बोर्ड को दिया भी गया किन्तु उससे भी काम नहीं चला। 1875 तथा 1876 के व्यापारिक जहाज अधिनियमों में उन जहाज मालिकों पर भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया जो अपने जहाजों को खराब मौसम में भी समुद्र में भेज देते थे। 1912 में टाइटेनिक (Titanic) नामक विशाल यात्री जहाज के समुद्र में डूब जाने के बाद यात्रियों व जहाज कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए बने हुए कानूनों का अधिक कड़ाई से पालन किया जाने लगा।

ब्रिटिश रेलों ही की तरह ब्रिटिश जहाजरानी का भी उन्नीसवीं शताब्दी में विकास निजी उद्यम के आधार पर ही हुआ। यह उस जमाने में ब्रिटिश उद्योग में हो रहे विकास का स्वाभाविक परिणाम था तथा सरकार ने इस उद्योग के विकास के लिए कोई प्रत्यक्ष योगदान नहीं किया। ब्रिटिश तैयार माल (manufactured goods) की मांग सप्ताह भर के देशों में थी। इसने अलावा ब्रिटेन अपना कच्चा माल भी दुनिया भर से प्राप्त करता था। जहाजों की जरूरत इन दोनों ही बानों के लिए पड़ती थी।

इंग्लैंड में जहाज दो मुख्य कारणों से निर्मित किये जाते थे (1) प्रथमतः, इस बात की पूरी आशा रहती थी कि जहाज निर्माण में लगने वाली पूँजी पर अच्छा प्रतिफल प्राप्त हो सकेगा। (2) दूसरा कारण यह था कि जहाज निर्माण की जो सुविधाएँ ब्रिटेन में उपलब्ध थी उनसे प्रतिस्पर्द्धी देशों का तो सिर्फ इसीलिए सफाया हो जाता था कि ब्रिटिश जहाज निर्माण की लागत सबसे कम थी। इसका परिणाम यह हुआ कि उन्नीसवीं शताब्दी में ब्रिटिश जहाज निर्माण उद्योग में खूब समृद्धि आई। उस समय ब्रिटेन ने विश्व के लगभग 80 प्रतिशत जहाजों का निर्माण किया और 1890 के पहले तब विश्व के कुल जहाजों में 60 प्रतिशत जहाज ब्रिटेन के थे। उद्योग में अत्यधिक विशिष्टीकरण (specialisation) की स्थिति आ गई। तट के करीब ही कोयले व लोहे के प्रचुर भाना में भण्डार उपलब्ध होने से भी ब्रिटिश जहाज निर्माण उद्योग को काफी लाभ रहा।

उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम चरण में ब्रिटिश व्यापारिक जहाजी बेड़े को जर्मनी से प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना पड़ा। उद्योग को मदी का भी सामना करना पड़ा। प्रतिस्पर्द्धा का मुकाबला करने के लिए ब्रिटिश जहाजी कंपनियों ने मेल-जोल

(conferences) की व्यवस्था कायम कर ली। उन व्यापारियों को विशेष रियायत दी जाने लगी जो अपना माल हमेशा एक ही कम्पनी के द्वारा भेजते थे। किन्तु इन व्यवस्थाओं की इसलिए आलोचना हुई कि ये एकाधिकारिक प्रवृत्तियों को बढ़ावा देती थी। इन सब परिस्थितियों की जाच करने के उद्देश्य से 1906 में एक शाही आयोग नियुक्त किया गया। आयोग ने इस व्यवस्था की आलोचना इस बात के लिए तो की कि इससे भाड़े की दरें बढ़ती हैं किन्तु साथ ही उसने मेल-जोल पद्धति (Conference System) को उचित ठहराया। मेल-जोल पद्धति का जहाजी कम्पनियों को फायदा यह था कि वे अपने जहाजों को नियत तारीख पर पर यात्रा के लिए रवाना कर सकती थी तथा अपने भाड़ों में एकरूपता भी स्थापित कर सकती थी।

विश्व युद्धों का प्रभाव

प्रथम विश्व-युद्ध में ब्रिटिश जहाजरानी को जर्मन नाकेबंदी (Blockade) के कारण भारी हानि उठानी पड़ी। यह नाकेबंदी ब्रिटिश जहाजरानी को बिल्कुल समाप्त ही कर देती यदि ब्रिटिश नौ सेना उसे तोड़ने में सफल न होती। प्रथम महायुद्ध के अंत में ब्रिटिश जहाजों का टन भार घट गया था किन्तु तेजी के साथ नये जहाजों का निर्माण होने से क्षति-पूर्ति थोड़े ही समय में हो गई। युद्ध के बाद निर्मित ब्रिटिश जहाज (व्यापारिक) अधिक तेज गति से चलने वाले, सभी उपकरणों में सुसज्जित, नवीनतम तथा खनिज तेल से चलने वाले थे। प्रथम महायुद्ध के अंत के बाद भी ब्रिटिश व्यापारिक जहाजी ब्रेडा विश्व में सबसे बड़ा था यद्यपि उसमें विश्व के जहाजों का एक-तिहाई भाग ही रह गया जो कि 1914 में आधे के लगभग था।¹

प्रथम विश्व-युद्ध के बाद होने वाला जहाज निर्माण आवश्यकता को देखते हुए अधिक था। 1930 की मंदी ने भी जहाजरानी उद्योग पर विपरीत प्रभाव डाला। व्यापार के परिमाण में घमी आ जाने के कारण कम जहाजों की आवश्यकता रह गई। मंदी की भीषणता के कारण जहाज निर्माण उद्योग को भी सरकारी सहायता की आवश्यकता पड़ने लगी। लगभग प्रत्येक देश की सरकार वहाँ की जहाजी कम्पनियों को अनुदान दे रही थी। ब्रिटिश सरकार ने भी 1939 तक उद्योग को अनुदान एवं ऋण प्रदान किये।

दूसरे महायुद्ध के बाद ब्रिटिश जहाजरानी उद्योग को गम्भीर सकट का सामना करना पड़ा। पुनर्निर्माण का काम अत्यधिक भीषण था। किन्तु विजेता देश होने के कारण इंग्लैंड को कई जर्मन जहाज मिले। जहाज निर्माण के काम में भी तेजी लाई गई तथा 1946 में यह अनुमान लगाया गया था कि ब्रिटेन विश्व में बन रहे जहाजों में से आधे जहाज बना रहा था। पिछले कुछ वर्षों से जापान, जर्मनी तथा स्वीडन प्रमुख जहाज निर्माता देश बन चुके हैं। 1957 के बाद से तो जापानी जहाज निर्माण स्थलों (shipyards) से बनकर निकलने वाले जहाजों का टन भार ब्रिटेन से अधिक हो चुका है। 1957 में विश्व में बनने वाले कुल जहाजों में ब्रिटेन का भाग गिर कर

¹ Ibid, 268

20 प्रतिशत से भी नीचे आ गया था ।

ब्रिटिश जहाजरानी तथा उसके व्यापारिक वेड़े की सर्वोच्चता तो द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद से ही इतिहास का एक अध्याय बन चुकी है । अमरीका, जापान तथा सोवियत संघ ने विशाल जहाजी वेड़े बना लिये हैं । किन्तु इतना अवश्य कहना होगा कि आज दिन तक भी ब्रिटेन जहाजी वेड़ा रखने वाले अग्रणी देशों की पक्ति में ही आता है । जापानी प्रतिस्पर्द्धा की पृष्ठभूमि में ब्रिटिश जहाज-निर्माण उद्योग न केवल अपना अस्तित्व बनाये रखने में सफल हुआ है बल्कि उसने अपनी कार्यविधि में सुधार भी किया है तथा पिछले कुछ वर्षों में लागत में भी कमी की है । आज भी यह पूरे सम्मान के साथ अपना अस्तित्व बनाये हुए है ।

यातायात एवं व्यापार में क्रान्ति

(REVOLUTION IN TRANSPORT AND COMMERCE)

यातायात में क्रान्ति औद्योगिक क्रान्ति का एक स्वाभाविक परिणाम थी। ऑग एव शार्प¹ ने अपनी पुस्तक में यातायात क्रान्ति के क्षेत्र में हुई उपलब्धियों को चार प्रमुख अवस्थाओं में बाँटा है जो बहुत महत्व की हैं— (i) सड़कों की स्थिति में सुधार, (ii) नहरों का निर्माण, (iii) रेलों के निर्माण का आरम्भ, तथा (iv) वाष्प शक्ति का नदियों तथा समुद्र में नौ-परिवहन के लिए उपयोग। इस सूची में बीसवीं शताब्दी में हुए वायु यातायात के विकास को और जोड़ा जा सकता है।

यातायात के क्षेत्र में हुई इन उत्तरोत्तर प्रगतियों से न केवल भौगोलिक दूरियों को घटाने में सहायता मिली बल्कि वे बाजार की सीमाओं का विस्तार करने के लिए भी उत्तरदायी थी। यातायात के क्षेत्र में हुए इन सुधारों से समस्त विश्व में लोगों की गतिशीलता में भी व्यापक रूप से वृद्धि हुई। श्रीमती नॉर्वेल्स ने यातायात के क्षेत्र में आई इस क्रान्ति को यह कहकर बड़े सही रूप में चित्रित किया है कि 'रेलो व वाष्प चालित जहाजों के आगमन का अर्थ था—राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के स्थान पर अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का प्रतिस्थापन, जिसके सामान्य परिणाम अन्तर्राष्ट्रीय निर्भरता और विश्व प्रतिस्पर्धा के रूप में सामने आये। यन्त्रचालित यातायात के साधनों ने विभिन्न राष्ट्रों के व्यापारिक एवं औद्योगिक महत्व के क्षेत्र में एक नयी क्रान्ति ला दी। इससे वस्तुओं और मनुष्यों के लिए नयी गतिशीलता की स्थिति उत्पन्न हुई। साथ ही, इससे राष्ट्रीय नीतियाँ भी प्रभावित हुई।

वास्तव में देखा जाये तो यातायात में हुई क्रान्ति ने न केवल औद्योगिक क्रान्ति की गति को अत्यधिक बढ़ा दिया बल्कि उसने तो व्यापार के स्वभाव को ही बदल डाला। देश के सामाजिक एवं राजनीतिक अंचल में भी अनेक दूरगामी परिवर्तन आये। यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह यातायात के क्षेत्र में आये क्रान्ति ही थी कि जिसने ब्रिटेन को लहरो पर राज करने के योग्य बनाया और वह न्यूहा-सा द्वीप लगभग 400 वर्ष तक विश्व के एक विशाल और समृद्ध भूभाग पर शासन करता रहा।

1. सड़क यातायात

उत्तीसवीं शताब्दी के मध्य तक ब्रिटेन में सड़कों की स्थिति सतोषजनक नहीं जाने योग्य नहीं थी। मैकॉले ने अपने इंग्लैंड के इतिहास (History of England)

मे चार्ल्स द्वितीय के समय में सड़कों की शोचनीय स्थिति का विवेचन किया है। अठारहवीं शताब्दी में सड़कों की स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं किया गया था। जिन्हें सड़कें कहा जाता था वे अक्सर छोटी सकरी पगडंडियाँ (tracks) हुआ करती थीं तथा उन पर अक्सर डाकू-लुटेरों का आतंक बना रहता था। कई बार उन पर गुजरना भी असम्भव हो जाता था। लन्दन से मैनचेस्टर तक की यात्रा में पाँच दिन लग जाते थे। देश के ही सूबे (counties) एक-दूसरे से इतने दूर लगते थे जितना कि आजकल एक देश से दूसरा देश। सड़क मार्ग से व्यापार काफी असुविधाजनक था तथा कोयले जैसी भारी चीजों को दूर की जगहों तथा केन्द्रों तक ले जाना असम्भव-सा था।

सरकार ने सड़कों की स्थिति सुधारने पर तब तक कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जब तक कि 1555 में सड़कों की मरम्मत का दायित्व तय करने सम्बन्धी एक कानून पारित न कर दिया गया। किन्तु उस कानून को कभी लागू नहीं किया गया। तीन ऐसे प्रमुख कारण थे जिनके फलस्वरूप अठारहवीं शताब्दी से पहले तक देश में अच्छी सड़कों का निर्माण असम्भव बना रहा। पहला, सड़कों के निर्माण के लिए आवश्यक तकनीक उपलब्ध नहीं थी, दूसरा, जनसंख्या बहुत कम थी, और तीसरा, देश-भर में सड़कें बनाने के लिए आर्थिक समाधानों की कोई व्यवस्था नहीं थी।

किन्तु अठारहवीं शताब्दी में सड़कों में सुधार का काम एक बड़े विचित्र रूप में शुरू हुआ। यह कम से कम सरकारी हस्तक्षेप का युग था। लोगों का विश्वास था कि निजी उद्यम सड़कों की अच्छी तरह देख-भाल कर सकता है। कोई भी धनी आदमी, जो अपना धन-सड़क निर्माण पर व्यय करता, उसे सड़क के उतने ही टुकड़े पर नियन्त्रण का अधिकार प्राप्त हो जाता। इस तरह सड़क के प्रत्येक भाग के स्वत्व होने पर दरवाजे होते और वहाँ से गुजरने वाले हर व्यक्ति, हर जानवर और वाहन को उस सड़क के मालिक को कर (toll) चुकाना पड़ता। इससे तात्पर्य यह था कि सड़क के रख-रखाव का खर्च साधारण जनता में न लेकर केवल सड़क का उपयोग करने वालों से लिया जाए।

टर्नपाइक या मुख्य सड़कों के निर्माण का काल

सड़क निर्माण की दृष्टि से पहला टर्नपाइक कानून (Turnpike Act) ब्रिटिश संसद द्वारा 1663 में पारित किया गया जिसका उद्देश्य उन टर्नपाइक न्यासों (Turnpike Trusts) को गठित करना था जो सड़कों का निर्माण करके तथा उन पर नियन्त्रण रखकर लाभ कमाते थे। किन्तु नयी सड़कें बनाने की क्रिया ने अठारहवीं शताब्दी में ही अधिक जोर दिया। यह बात इसी से सिद्ध हो जाती है कि 1760 से 1774 के बीच इस तरह के 450 कानून पारित किये गये।

इन टर्नपाइक न्यासों के माध्यम से सड़क-निर्माण की व्यवस्था द्वारा देश में कुछ अच्छी मुख्य सड़कों का निर्माण हुआ। इस व्यवस्था के अनेक आलोचक भी थे जो यह मानते थे कि टर्नपाइक सड़कों की देख-रेख अच्छी नहीं होती थी। मोटे तौर पर यह आलोचना उन सहायक सड़कों तथा गाँवों को जोड़ने वाली सड़कों पर लागू होती थी जो छोटे-छोटे गाँवों को जोड़ती थी। ऐसा इसलिए होता था कि इन सड़कों पर याता-यात बहुत कम रहता था और टर्नपाइक ट्रस्ट लाभ में अधिक रुचि रखते थे। इसके

अतिरिक्त अठारहवीं शताब्दी के अन्त तक मुख्य सड़कें काफी अच्छी स्थिति में आ चुकी थीं तथा बड़े शहरों को बराबर चलने वाली कोच (coach) सेवा द्वारा जोड़ा जा चुका था।

सड़कों का मेकेडेमीकरण (Macadamisation of Roads)

अठारहवीं शताब्दी के अन्त तक सड़क-निर्माण की तकनीक में भी कुछ प्रगति की जा चुकी थी। सैन्डो मील लम्बी सड़कें तथा अनेक पुलों का निर्माण जॉन मेडकॉफ तथा टॉमस टेलफोर्ड जैसे व्यक्तियों द्वारा करवाया जा चुका था। किन्तु सड़क-निर्माण की कला में क्रांति लाने का श्रेय जॉन मेकएडम (Johan MacAdam) को जाता है। उसने पहले पत्थरों की तह पर मिट्टी (Concrete) की परत जमा कर उस पर भारी रोलर घुमाकर सड़क निर्माण की पद्धति का विकास किया। ऐसी सड़कें न केवल अधिक टिकाऊ होती थीं, बल्कि बड़ी सतह वाली होने के कारण वाहनों के आवागमन के लिए काफी उपयुक्त रहती थीं। यह सड़क-निर्माण की पद्धति इतनी सफल रही कि आज तक भी कई छोटी सड़कों को सिर्फ मेकेडेमीकृत (Macadamised) करके ही छोड़ दिया जाता है। इस तरह सड़कों के निर्माण की इस तकनीक के विकसित होने के साथ ही सड़कों ने एक नया युग में प्रवेश कर लिया था।

न्यासों का विलय (Amalgamation of Trusts)

उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध की विशेषता यह रही कि इसमें टर्नपाइक न्यासों (Turnpike Trusts) के विलय का आन्दोलन चल निकला। अनेक छोटे टर्नपाइक ट्रस्टों के स्थान पर कुछ विशाल टर्नपाइक ट्रस्टों का उद्भव हुआ। इन बड़ी कम्पनियों के पास अधिक धन था व प्रशिक्षक सर्वेक्षकों (Surveyors) तक इनकी पहुँच थी तथा ये अधिक कुशल भी थीं। किन्तु रेलों के आगमन के साथ ही इन बड़े और छोटे सभी टर्नपाइक ट्रस्टों का विघटन हो गया। सड़क यायायान में कमी आयी और उससे प्राप्त आगम भी घट गया और इस तरह एक-एक करके ये टर्नपाइक ट्रस्ट विलुप्त हो गये। सड़कों के रख-रखाव का उत्तरदायित्व स्थानीय मार्गजनिक संस्थाओं पर आ पड़ा।

मोटर यातायात का युग (Era of Motor Traffic)

बीसवीं सदी के आरम्भ में ही मोटर यातायात के द्रुत विकास ने सड़कों को पुनः अत्यधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। गति एवं भार में अप्रत्याशित वृद्धि हो जाने के कारण सड़क निर्माण की पुरानी तकनीकों को एकदम आधुनिक तकनीकों से प्रतिस्थापित कर दिया गया है। सड़क-निर्माण की नयी तकनीकों ने अधिक टिकाऊ धरातल वाली सड़कों का निर्माण सम्भव बना दिया है।

मोटर यातायात में वृद्धि होने के साथ ही एक और बात यह हुई कि जनसाधारण ने सड़कों की स्थिति में सुधार करने की माँग शुरू कर दी। किन्तु सड़कों को चौड़ा करने, सीधा बनाने, उनके धरातल को फिर से तैयार करने (resurfacing) व नयी सड़कें बनाने में भारी खर्च की आवश्यकता पड़ती है। इस लागत के लिए कोई

न कोई स्तोन ढूँढना आवश्यक था इसलिये 1909 से 1937 तक एक विशेष कोष बनाया गया जिसमें मोटर-कर से प्राप्त सारी राशि जमा की जाती रही। मोटर-करो से प्राप्त समस्त धनराशि सड़क कोष को स्थानान्तरित करने की प्रथा 1937 में ही समाप्त की गयी। अब सड़क कोष (Road Fund) को उतनी ही राशि प्राप्त होती है जितनी कि ससद द्वारा उसके लिए पारित की जाती है। 1929 के स्थानीय सरकार अधिनियम (Local Government Act, 1929) में सड़को को वर्गीकृत भी कर दिया गया है। ये वर्गीकृत सड़कें अब काउन्टी परिषदों (County Councils) का दायित्व मान ली गयी हैं। नयी सड़कें बनाने पर आने वाले वित्तीय खर्च का आंशिक दायित्व तो यातायात मंत्रालय पर है जो कुछ खर्च स्थानीय सत्थाएँ भी देती हैं।

1939 में इंग्लैंड में 1.80 लाख मील लम्बी सड़कें मौजूद थीं और लगभग 30 लाख वाहनों को सड़क उपयोग करने का लाइसेंस प्राप्त था। जब दूसरा महायुद्ध छिड़ा तो सरकार ने एक आपत्कालीन सड़क परिवहन संगठन (Emergency Road Transport Organisation) गठित किया। यह संगठन वाहनों को सरकारी काम के लिए ले सकता था तथा ईंधन का राशन भी तय करता था। जब युद्ध समाप्त हुआ तो सड़को को मरम्मत की आवश्यकता थी। मरम्मत का यह काम 1953 तक चला जबकि फिर एक बार नयी सड़को के निर्माण का काम शुरू किया गया। 1958 तक लाइसेंस धुदा वाहनों की संख्या 80 लाख तक पहुँच गयी। आजकल देश के प्रत्येक तीन व्यक्तियों के बीच एक मोटरवाहन का औसत आता है।

1947 में पारित सड़क यातायात विधेयक (Road Transport Act, 1947) ने सड़क यातायात द्वारा ढोए जाने वाले माल का राष्ट्रीयकरण कर दिया। एक सशोधन द्वारा 1953 में आंशिक रूप से उसे पुनः अराष्ट्रीयकृत कर दिया गया। ग्रेटर लन्दन के लिए लन्दन यातायात सेवा बोर्ड द्वारा एक अलग यातायात व्यवस्था संचालित की जाती है। सड़को के निर्माण का काम तो बहुत पहले ही पूरा हो चुका है। एक छोटा-सा द्वीपीय राष्ट्र होने के कारण उसकी सड़क आवश्यकताएँ भी सीमित हैं और वे पूरी हो चुकी हैं। सड़को का रख-रखाव बड़े सुन्दर तरीके से किया जाता है तथा वाहन यातायात बराबर बढ़ रहा है। 1970-80 के दशक में आये स्फीति व जड़ता (Stagflation) के मिश्रित वातावरण के बावजूद सड़क यातायात पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा है।

2 नहरें व अन्तर्देशीय जल परिवहन

यद्यपि अठारहवीं शताब्दी के दौरान सड़क यातायात के क्षेत्र में अनेक सुधार हो चुके थे। किन्तु फिर भी वे औद्योगिक गतिविधि में हुई वृद्धि के कारण भारी चीजों (जैसे कोयला) की बड़ी हुई माँग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। इस आवश्यकता को नहरों के निर्माण द्वारा पूरा किया गया। एअरे (Aire) तथा कैल्डर (Calder) को जोड़ने वाली आरम्भिक नहर सत्रहवीं सदी में पूरी की गयी।

ब्रिजवाटर नहर (Bridgewater Canal) का निर्माण ब्रिटिश अन्तर्देशीय जल परिवहन के इतिहास में एक महान् घटना थी। इस नहर ने मेनचैस्टर को वमने (Worsley) स्थित कोयले की खानों से जोड़कर इस औद्योगिक राष्ट्र के लिए कोयले

के आवागमन में भारी सुविधा कर दी। एक अन्य नहर मैनचेस्टर को लिवरपूल से जोड़ने के लिए बनायी गयी। इन दोनों नहरों का निर्माण बिन्दले (Bindley) की इंजीनियरिंग दक्षता का परिणाम था।

नहरोन्माद (Canal Mania) का काल • 1760-1800

महान् शहरी को जोड़ने में बिन्दले को प्राप्त हुई सफलता में प्रोत्साहित होकर देश-भर में नहरों का निर्माण शुरू किया गया। 1760 से 1800 के बीच अनेक नये जल-मार्गों (Waterways) का निर्माण किया गया। 1791 से 1797 के बीच की छह वर्षों की अवधि में तो देश में इतनी अधिक नहरों की खुदाई की गयी थी कि इस अवधि को नहरोन्माद (Canal mania) का युग कहा गया। इस सबका परिणाम यह रहा कि अठारहवीं सदी के समाप्त होने से पूर्व ही देश में नहरों का जाल फैल गया।

यहाँ यह बात महत्वपूर्ण है कि नहरों के निर्माण में भी सरकार ने धन नहीं दिया। निजी उद्यमियों ने ही सारा का सारा धन जुटाया। इससे निर्माण कार्य में एकरूपता भी नहीं रही और दूर तक के यातायात (through traffic) में कठिनाइयाँ भी आयी। किन्तु यह सब सरकारी अहस्तक्षेप की नीति के कारण ही हुआ। ये नहर कम्पनियाँ भी टर्नपाइक ट्रस्टों की तरह ही उपयोग करने वालों से कर (toll tax) वसूल करती थी। ये स्वयं वस्तुएँ लाने से जाने का काम नहीं करती थी।

अनेक दोषों के बावजूद उस जमाने में ये नहरें ही चीजों के आवागमन के लिए सर्वोत्कृष्ट माध्यम थी। औद्योगिक विकास नहरों के अभाव में शायद ही सम्भव हो पाता। उनके द्वारा खाद्य पदार्थ और कच्चे माल लाये लेजाये जाते। निर्मित वस्तुएँ भी उन्हीं के द्वारा भेजी जाती। कोयले को ले जाने की समस्या भी हल हो गयी।

नहरी व्यवस्था की अवनति

कई वर्षों तक नहरी व्यवस्था को समृद्धि प्राप्त होती रही। किन्तु रेलों के आगमन के साथ ही उनकी अवनति प्रारम्भ हो गयी। उनका बहुत सारा माल पहले तो रेलों और बाद में तटीय स्टीमरों द्वारा ढोया जाने लगा। इन नहरी कम्पनियों का विलय (amalgamation) भी इन्हे गला-काट प्रतिस्पर्द्धा से नहीं बचा पाया। कुछ नहरी कम्पनियाँ तो प्रतिस्पर्द्धा समाप्त कर डालने के उद्देश्य से रेल कम्पनियों द्वारा खरीद ली गयी। जब किसी एक नहरी भाग (canal section) को खरीद लिया जाता तो दूसरे नहरी भाग की स्थिति अपने आप ही कमजोर पड़ जाती। रेल कम्पनियों ने लगभग एक-तिहाई नहरों को खरीद लिया था।

रेलों की नहरों के साथ अनुचित प्रतिस्पर्द्धा के लिए आलोचना की गयी तथा 1888 में रेलों द्वारा और अधिक नहरों के खरीदने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम वर्षों में लीवरपूल को मैनचेस्टर से जोड़ने के लिए जहाजों के आ-जा सकने योग्य नहर का निर्माण किया गया। यह भी अपने आपमें एक इंजीनियरिंग चमत्कार था। इसे मैनचेस्टर शिप केनाल (Manchester Ship Canal) का नाम दिया गया और यह एकदम सफल हो गयी। 1955 में इस नहर

तथा ब्रिजवाटर नहर ने मिनकर 19 मिलियन टन वजन का आवागमन सम्भव बनाया था ।

नहरों की उपयोगिता अभी भी इंग्लैण्ड में पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है । 1909 में अपनी एक रिपोर्ट में नहरी शाही आयोग ने यह सिफारिश की थी कि एक जलमार्ग बोर्ड (Waterways Board) गठित किया जाना चाहिए । किन्तु इस सुझाव को व्यवहार में नहीं लाया जा सका । 1947 में पारित यातायात विधेयक ने नहरों पर नियन्त्रण गोदी व अन्तर्देशीय जलमार्ग निदेशक (Docks & Inland Waterways Executive) को सौंप दिया था । इस सस्था को भी 1953 में समाप्त कर दिया गया तथा नहरों के नियन्त्रण का काम प्रबन्धक बोर्ड (Board of Management) को सौंप दिया गया है ।

3 ब्रिटिश रेलें

रेल युग का आरम्भ लगभग 1830 में हुआ । उसी वर्ष में जार्ज स्टीफेंसन ने वाष्प-चालित इंजिन की व्यावहारिकता सिद्ध कर दी व उसके द्वारा निर्मित प्रथम रेल इंजिन 'रॉकेट' ने सफलतापूर्वक 13 टन वजन 29 मील प्रति घण्टा की रफ्तार से खींचकर दिखाया । जार्ज स्टीफेंसन की इस सफलता ने यातायात के इस नये तरीके के विकास द्वारा अनेक बाधाएँ दूर कर दी तथा इंग्लैण्ड में एक राष्ट्रीय रेल-व्यवस्था स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया । इंग्लैण्ड में रेलों के निर्माण में अनेक नवीन बातें सामने आयीं

(1) निजी पहल—देश में रेल व्यवस्था कायम करने का काम पूरा का पूरा निजी कम्पनियों पर छोड़ दिया गया । सरकार को सामान्य नियन्त्रण व अधिकार था तथा रेल परियोजनाओं को ससदीय अनुमति प्राप्त करनी होती थी ।

(2) ऊँची लागत—ग्रेट ब्रिटेन में रेलों के निर्माण की लागत काफी ऊँची आती थी । इंग्लैण्ड में 1849 में प्रति एक मील रेल लाइन बिछाने पर औसत लागत 56,915 पौण्ड आती थी जबकि यही लागत प्रशा (Prussia) व ऑस्ट्रिया (Austria) में क्रमशः 10,000 पौण्ड तथा 11,300 पौण्ड थी । ब्रिटेन में रेल लाइन बिछाने की इतनी ऊँची लागत इसलिए आती थी कि वहाँ रेल लाइने बिछाने के लिए आवश्यक भूमि पर बहुत ऊँची दर पर मुआवजा देना पड़ता था । सरकार द्वारा नक़्शे आदि भी नहीं बनवाये हुए थे और उसका खर्चा भी निजी कम्पनियों को ही वहन करना होता था । यह सारी प्रक्रिया काफी खर्चीली थी ।

(3) प्रयोगों की लागत—भाप से चलने वाले रेल इंजिनों का आविष्कार सबसे पहले इंग्लैण्ड ही में हुआ था । उनमें सुधार करने के लिए अनेक प्रयोग किये गये । इसमें सफलता अनेक बार की कोशिशों से ही मिली । इन प्रयोगों पर भी खर्च हुआ ।

(4) इंजीनियरिंग की समस्याएँ—इंजीनियरिंग की कठिन समस्याओं को हल करने के लिए भी भारी खर्च की आवश्यकता थी । लम्बे समतल भूखण्ड उपलब्ध नहीं थे इसलिए काफी खुदाई करनी पड़ती थी । जगह-जगह पहाड़ों की धार-नार

खोदना पड़ा था।

(5) निर्माण कार्य की मजदूती—निर्माण कार्य की मजदूती पर काफी बल दिया जाता था। रेल लाइने बिछाने में काफी सुरक्षा व्यवस्था की जाती थी जिससे खर्च काफी बढ़ जाता था।

यह एक विचारणीय प्रश्न है कि जब आरम्भिक निर्माण लागत इतनी ऊँची थी तो ब्रिटेन में रेलों का जन्म और विकास केवल निजी उपक्रमियों के बल पर किस तरह हुआ? यह इसलिए सम्भव हुआ कि बड़े पैमाने पर उत्पादन का युग आरम्भ हो चुका था और अनेक लोगो ने बड़ी मात्रा में सम्पत्ति अर्जित कर ली थी। ऐसे लोग अपना धन यातायात के इस नये तरीके में लगाकर लाभ कमाना चाहते थे। ब्रिटिश रेलों का विकास वहाँ के व्यवसाय की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए किया गया था और उसमें विनियोग करने वालों को अपने लगाये हुए धन पर तुरन्त लाभ पाने की आशा थी।

अपने निर्माण की प्रारम्भिक अवस्थाओं में रेल कम्पनियों का नहर कम्पनियों, कोच के मालिकों तथा टर्नपाइक ट्रस्टों के साथ सीधा संपर्क आरम्भ हुआ। सड़कों में काफी सुधार हो चुका था तथा अठारहवीं शताब्दी में देश-भर की नहरों का भी जाल फैल चुका था। उन्नीसवीं सदी में एकाधिकार को बढ़ावा नहीं दिया जाता था इसलिए सरकार ने रेलों की रेलों के साथ प्रतिस्पर्द्धा तथा रेलों की नहरों के साथ प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा दिया। न केवल रेलों तथा नहरों के बीच प्रतिस्पर्द्धा को बनाये रखा जाता था बल्कि विभिन्न रेल कम्पनियों के बीच भी इतनी तीव्र प्रतिस्पर्द्धा थी कि किमी भी बड़े शहर में एक से कहीं अधिक रेल कम्पनियाँ सेवाएँ देती थी। अन्य यूरोपीय देशों में, जहाँ नहरें होती थी, उन्हें प्रतिद्वन्द्वी के रूप में नहीं बल्कि रेलों के लिए माल की आपूर्ति बढ़ाने की दृष्टि से (feeders) काम में लिया जाता था।

रेल कम्पनियों के प्रारम्भिक उपक्रमियों ने ग्रेट ब्रिटेन में किसी राष्ट्रीय रेल व्यवस्था स्थापित करने की दृष्टि से कभी नहीं सोचा। उन्होंने विभिन्न गेज (gauge) वाली छोटी-छोटी लाइनों का निर्माण किया। कुछ समय बीत जाने के बाद ही इस बात का अनुभव किया गया कि इन लाइनों को जोड़ने की आवश्यकता है। अन्य देशों ने तो ब्रिटेन की इस कठिनाई से सवक सीखा और अपने वहाँ रेल लाइनों को जोड़ने में बिल्कुल भी समय नहीं खोया। रेल उद्योग के अग्रवाजों (pioneers) ने माल लाने से जाने से ही अधिक लाभ कमाने की आशा की थी इसलिए उन्होंने यात्रियों के आवागमन को, सुविधाजनक बनाने पर कोई ध्यान नहीं दिया, किन्तु यह एक श्रुति थी। प्रारम्भिक वर्षों में रेलों को प्राप्त होने वाले आगम में 75 प्रतिशत भाग यात्रियों से प्राप्त भाड़े का होता था। ब्रिटिश रेलों की एक और विशेषता यह थी कि रेल कम्पनियाँ सिर्फ रेल लाइनों की मालिक होती थी जबकि उन पर चलने वाले डिब्बे आदि और ही लोगो द्वारा चलाये जाते थे। ऐसा इसलिए था कि डिब्बों आदि की खरीद पर और भी अधिक पूँजी लगानी पड़ती। ये रेल कम्पनियाँ डिब्बों पर फीस वसूल करती थी किन्तु इस व्यवस्था में अनेक कठिनाइयाँ थी।

ब्रिटिश रेलों के विकास को कुछ मुरग कालों में विभक्त किया जा सकता है।

1 आरम्भिक प्रयोगों का काल 1821-1850

ब्रिटिश रेल व्यवस्था को उन्नीसवीं शताब्दी के दूसरे चतुर्थांश में एक निश्चित स्वरूप प्राप्त हो चुका था। रेलें तो 1825 से पहले भी मौजूद थीं किन्तु वे भाप की शक्ति का उपयोग नहीं करती थीं। 1850 तक रेलों के निर्माण के बारे में काफी प्रगति हो चुकी थी। वास्तव में रेल व्यवस्था की स्थापना ही इसी अवधि में हुई। 1821 में स्टॉकटन एण्ड डार्लिंगटन रेलवे (Stockton & Darlington Railways) की स्थापना की गयी। यह रेल कम्पनी घोड़े के स्थान पर भाप से चलने वाले इंजन का उपयोग करना चाहती थी। जार्ज स्टीफेंसन द्वारा तैयार किये गये प्रथम भाप के इंजन द्वारा एक रेलगाड़ी 1825 में पहली बार चलाई गयी। यह प्रयोग सफल रहा तथा 1830 में लीवरपूल व मैनचेस्टर के बीच रेल-व्यवस्था पूर्ण की गयी। अन्य रेल लाइनों के निर्माण का भी काम हाथ में लिया गया तथा 1838 में लन्दन को भी मैनचेस्टर से रेल लाइन द्वारा जोड़ दिया गया।

इस समय तक अनेक रेल लाइनें, जो एक दूसरे से सम्बन्धित नहीं थीं, देश-भर में बिछाई जा रही थीं। 1843 से 1847 के बीच 'रेल सम्राट' (Railway King) जॉर्ज हडसन द्वारा दिये गये प्रोत्साहन से देश में रेल उन्माद (Railway Mania)¹ की स्थिति पैदा हो गयी। किन्तु इतनी जल्दी-जल्दी में किये गये रेल-निर्माण से अनेक मूर्खतापूर्ण परियोजनाएँ भी तैयार कर ली गयीं जिनमें विनियोजकों को बहुत से धन से हाथ धोना पड़ा। किन्तु सारी योजनाएँ ऐसी नहीं थीं और 1850 तक इंग्लैंड में रेलों का जाल विद्यमान था। 1844 में इंग्लैंड में सक्रिय रेल लाइनों की सम्वाई 2100 मील तक पहुँच चुकी थी।

2 पुनर्गठन व ससदीय नियन्त्रण का काल 1850-1893

प्रारम्भिक रेल लाइनें तो छोटी निजी कम्पनियों द्वारा ही बनायीं गयीं किन्तु बाद में विलय (amalgamations) हुए उनके द्वारा 1850 तक तो लन्दन एण्ड नॉर्थ वेस्टर्न (London & North Western) तथा मिडलैंड (Midland) व ग्रेट नॉर्थर्न (Great Northern) जैसी विशालकाय रेल कम्पनियाँ स्थापित हो चुकी थीं। ससद ने भी पहले तो इस प्रकार के विलयों को प्रोत्साहन दिया किन्तु जब दो बड़ी रेल कम्पनियों—द लन्दन एण्ड नॉर्थ वेस्टर्न तथा द मिडलैंड—ने एक होने के लिए अनुमति चाही तो उन्हें ससद ने इस आधार पर मना कर दिया कि इससे एकाधिकार को बढ़ावा मिलता है। सरकार स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के पक्ष में थी। किन्तु इसके अनिर्दिष्ट कई कम्पनियों के बीच अनौपचारिक मेल-जाम (combinations) चलता रहा जिससे प्रतिस्पर्धा में कमी हो आयी।

रेलों द्वारा इसी अवधि में जिस एक अन्य समस्या का सामना करना पड़ा वह गेज के समानीकरण (standardisation of gauge) की थी। ससद ने इस सम्बन्ध में 1846 तक कोई कदम नहीं उठाया था। 1846 ही में ससद ने एक विधेयक पारित किया जिसके अनुसार भविष्य में सभी रेल लाइनों के बीच की दूरी के लिए

¹ G W Southgate, *op cit*, 200

मानक गेज (standard gauge) चार फीट साठ इंच तय कर दिया गया। बाकी रेल लाइनों के रूपांतरण का काम भी 1892 तक पूरा हो गया। परिस्थितियों ने रेल कम्पनियों को यात्री व माल ढोने के लिए भी बाध्य कर दिया। हालाँकि मूल रूप से उनका इरादा केवल लाइनों का उपयोग करने वालों से टैक्स वसूलना ही था।

धीरे-धीरे यह महसूस किया जाने लगा कि यद्यपि रेलों का विकास निजी उपक्रम के प्रयासों का ही परिणाम था किन्तु उनकी सार्वजनिक महत्ता भी कम नहीं थी। उन पर कुछ सीमा तक राज्य का नियन्त्रण आवश्यक था। आरम्भ में संसद किसी भी प्रकार के नियन्त्रण के विरुद्ध थी लेकिन आखिर 1873 में उसने एक रेल व नहर आयोग (Railway & Canal Commission) गठित कर ही दिया। रेलों का नियन्त्रित करने का यह पहला कदम था।

इससे पहले 1840 में यह कानून बना ही दिया गया था कि नयी लाइनों का निर्माण बोर्ड ऑफ ट्रेड की स्वीकृति मिलने के बाद ही किया जा सकता था। 1845 में संसद ने मान भाड़े (freight rates) की अधिकतम दरें भी तय कर दी थी। 1854 में एक कार्डवेल विधेयक (Cardwell Act) भी पारित किया गया जिसने रेल कम्पनियों को इस बात के निर्देश जारी किये कि वे वस्तुओं के आवागमन में यथासम्भव सुविधाएँ प्रदान करें तथा अनुचित प्राथमिकताएँ न दें। किन्तु कार्डवेल विधेयक कई वर्षों तक अप्रभावी बना रहा तथा रेल कम्पनियों ने अनेक वर्षों तक विभिन्न ग्राहकों से मानक दरें वसूल नहीं कीं। 1873 के विधेयक में कम्पनियों के लिए हर स्टेशन पर मान भाड़ की दरों की पुस्तक (rate book) रखना भी अनिवार्य कर दिया गया था। 1873 में स्थापित रेल तथा नहर आयोग को निम्न मुख्य काम सौंपे गये

- (1) प्राथमिकताएँ (preferences) देने पर सख्त पाबन्दी को लागू करवाना।
- (2) विनय के प्रस्तावों की जाँच पड़ताल करना।
- (3) लम्बी दूरी के लिए भाड़े की उचित दरें निर्धारित करना।
- (4) कम्पनियों के बीच हुए विवादों को पचनिर्णय के लिए सौंपना, तथा
- (5) नहरों को खरीदने से सम्बन्धित प्रस्तावों की स्वीकृति देना।

आरम्भ में तो आयोग को जन विश्वास भी नहीं मिला और कम्पनियों ने भी उसकी अनदेखी की। किन्तु आयोग को कम्पनियों द्वारा दी जाने वाली प्राथमिकताओं को घटाने में सफलता मिली। 1888 में रेल व नहर यातायात विधेयक (Railway and Canal Traffic Act 1888) के पारित कर दिये जाने के बाद रेल कम्पनियों पर सार्वजनिक नियन्त्रण कड़ा हो गया। काफी समय से रेल-भाड़ की दरों का सवाल व्यापारियों तथा कम्पनियों के बीच झगड़ों की जड़ बना हुआ था। विधेयक में इन दरों के निर्धारण तथा प्रकाशन के लिए प्रावधान किया गया। रेल कम्पनियों ने विभिन्न वस्तुओं की श्रेणियाँ बनायीं तथा प्रत्येक श्रेणी के लिए अधिकतम दर को प्रस्तावित व प्रकाशित किया गया। वस्तुओं का यह श्रेणीकरण वस्तुओं के मूल्य पर आधारित था न कि उनके वजन या आकार पर।

रेल कम्पनियों द्वारा तय की गयी इन भाड़ों की दरों पर कई आपत्तियाँ उठायी

गयी। नयी सूचियाँ तैयार की गयी। इन नयी दरों को ससद ने भी स्वीकृति दे दी तथा उन्हें 1 जनवरी 1893 से लागू करने का प्रस्ताव दिया गया। किन्तु इन नयी दरों से भी सिर्फ वे ही व्यापारी सन्तुष्ट हुए जिन्हें उनके अन्तर्गत की गयी कटौतियों से कोई लाभ होता था। दूसरे व्यापारी शिकायतें करते रहे। कुछ महीनों बाद कम्पनियों ने फिर वही पुरानी दरें वसूल करनी शुरू कर दी। सरकार ने इस आशय की घोषणा की कि 1892 में प्रचलित दरों में कोई भी वृद्धि अनुचित मानी जाएगी।

3. राज्य नियन्त्रण व विलय 1893-1913

ब्रिटिश ससद ने 1896 में एक लाइट रेलवे आयोग (Light Railway Commission) नियुक्त किया। आयोग को ऐसी योजनाएँ बनाकर प्रस्तुत करने का काम सौंपा गया जिनसे ग्रामीण क्षेत्रों को हल्की रेल लाइनें (Light Railways) बनाकर जोड़ा जा सके। किन्तु आयोग की नियुक्ति के प्रभाव के रूप में कोई विशेष निर्माण कार्य नहीं हुआ।

1890 से 1913 तक की अवधि में अधिकांश रेल कम्पनियाँ अतिरिक्त माल ढोने के लिए गहरी प्रतिद्वन्द्विता करती रही। यानियों या ढोये जाने वाले माल में वृद्धि होने से रेलों को चलाने की लागत नहीं बढ़ती थी इसलिए इन वृद्धियों से रेल कम्पनियों को अत्यधिक लाभ था। कम्पनियों ने अधिक माल व यात्री आकर्षित करने की दृष्टि से अपनी दरों में कटौती भी की।

उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में विलयोंकरण (amalgamations) का जो दौर चला था वह भी जारी रहा। 1899 में लन्दन-चेटहैम (London-Chatham) तथा दक्षिण-पूर्वी रेलवे (South-Eastern Railway) ने मिलकर एक कामचलाऊ संधि बना लिया। बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों में ऐसे और भी अनेक संधि बनाये गये। तीन मुख्य कम्पनियों ने 1908-09 में कामचलाऊ समझौते किये। 1909 में ससद द्वारा अनुमति न दिये जाने के बावजूद तीन और कम्पनियों—द ग्रेट गार्थर्न (the Great Northern), ग्रेट ईस्टर्न (Great Eastern), तथा ग्रेट सेंट्रल रेलवे (Great Central Railway) ने ससद की सहमति के बिना ही एक कामचलाऊ समझौता कर लिया ताकि अनावश्यक प्रतिस्पर्धा समाप्त की जा सकती। 1912 में लन्दन टिलबरी रेलवे (London Tilbury Railway) मिडलैंड रेलवे (Midland Railway) में मिल गयी।

बीसवीं शताब्दी लगने के बाद तो रेलों ने क्षेत्र में अनेक सुधार हुए हैं। राशन-यान, यात्रियों के बैठने के लिए अच्छे डिब्बे, तेज गति से चलने वाली गाड़ियाँ यादि उनमें से कुछ हैं। कम्पनियों ने इन सुविधाओं के लिए अपने भाड़े भी अधिक नहीं बढ़ाये। तृतीय श्रेणी के डिब्बों की हावत काफी सुधारी गयी। 1938 में लन्दन ट्रांसपोर्ट (London Transport) द्वारा सेवारत क्षेत्र में तो वर्गहीन (classless) यात्रा आरम्भ कर दी गयी और प्रथम श्रेणी को हटा दिया गया।

किन्तु प्रथम विश्व-युद्ध से पहले के ये कुछ वर्ष रेलों के लिए समृद्धि के वर्ष नहीं थे। कार्यकारी व्यय बढ़ रहा था। सुविधाओं में वृद्धि का अर्थ था—कम्पनियों के

लिए ऊँची लागत। यहाँ तक कि कोयले की लागत और करो की दरें भी ऊँची हो गयी थी। धम-सघो का विकास हो जाने के कारण बढ़ी हुई मजदूरी के लिए माँगें भी बढ़ गयी। कम्पनियों को ग्रामीण इलाकों में बनी हुई उन शाखाओं को भी बन्द नहीं करने दिया गया जिनसे कोई लाभ नहीं होता था। किन्तु 1913 में एक विधेयक पारित किया गया जिसने कम्पनियों को यात्री-भाड़ा व मात्त-भाड़ा बढ़ाने की अनुमति इस आधार पर क्षतिपूर्ति के रूप में दी कि उन्होंने इस दौरान अनेक सुधार करके अपनी लागत काफी ऊँची कर ली थी।

4 प्रथम विश्व-युद्ध और सरकारी नियन्त्रण

1914 में जब प्रथम विश्व-युद्ध छिड़ा तो रेलों का नियन्त्रण सरकार ने अपने हाथों में ले लिया। रेलों का प्रबन्ध तो कम्पनियों के पास ही रहने दिया गया किन्तु रेलें सरकार के उपयोग के लिए निश्चित कर दी गयीं ताकि सैनिकों व सैनिक सामान को इधर-उधर आसानी से ले जाया जा सके। रेलों की स्थिति युद्ध के वर्षों में इतनी दयनीय हो चुकी थी कि जब युद्ध समाप्त हुआ तो सरकार ने उन्हें क्षतिपूर्ति के लिए 60 मिलियन पाउण्ड की रकम प्रदान की।

सरकार ने सम्पूर्ण रेल व्यवस्था के पुनर्गठन का भी निर्णय लिया। 1921 के एक विधेयक द्वारा देश की 121 रेल कम्पनियों को चार बड़ी कम्पनियों में समूहीकृत कर दिया गया

(i) द लन्दन एण्ड नॉर्थ ईस्टर्न (the London and North Eastern),

(ii) द लन्दन मिडलैण्ड एण्ड स्कॉटिश (the London Midland and Scottish),

(iii) द ग्रेट वेस्टर्न (the Great Western), तथा

(iv) द सादर्न (the Southern)।

इन विलयों से यह अपेक्षा की गयी थी कि व्यय की प्रतिद्वन्द्विता समाप्त हो जाएगी तथा उद्योग अधिक समृद्ध बनेगा। एक रेल दर ट्रिब्युनल (Railway Rates Tribunal) गठित किया गया जिसे ऐसी दरें व भाड़े तय करने को कहा गया कि जिनमें कम्पनियों को निश्चित आगम प्राप्त हो सके। 1892 में वस्तुओं का जो श्रेणीकरण किया गया था उसे समाप्त कर दिया गया। उसके स्थान पर 21 श्रेणियों वाला एक नया वर्गीकरण किया गया जिसके आधार पर दूरों का निर्धारण होता था। दूरों का निर्धारण युद्ध-पूर्व के स्तर से 60 प्रतिशत ऊँचे स्तर पर किया गया। इन दूरों को प्रदर्शित करने वाले चार्ट छापे गये और उन्हें आम जनता को बेचा गया। कम्पनियों को सूची में अंकित दर से कम या अधिक दर वसूल करने से रोक दिया गया।

रेल कर्मचारियों की काम की दशाओं तथा उनके लिए वेतन-निर्धारण पर भी लोगों का ध्यान गया। पर्येक कम्पनी के लिए एक मजदूरी परिषद् (wage council) का गठन अनिवार्य कर दिया गया और उसके अमल होने पर मामला केन्द्रीय मजदूरी बोर्ड को भेजने की व्यवस्था की गयी। अपील का प्रावधान रखा गया जो

राष्ट्रीय मजदूरी बोर्ड को की जा सकती थी। किन्तु यह व्यवस्था सन्तोषप्रद नहीं रही और इसे 1935 में समाप्त करना पड़ा। नयी व्यवस्था के अन्तर्गत एक रेलवे कर्मचारी राष्ट्रीय परिषद् बनायी गयी जिसका कार्यक्षेत्र भी व्यापक था। असफलता की स्थिति में मामला ट्रिब्यूनल (Tribunal) में ले जाया जा सकता था जिसमें तीन सदस्य होते थे। एक कम्पनियों का प्रतिनिधित्व करता था, एक यूनियनों का तथा एक सभापति होता था जिसे श्रम-मन्त्री नियुक्त करता था।

किन्तु ये सारी व्यवस्थाएँ जो 1921 के विधेयक के अन्तर्गत की गयी थी न तो प्रतिद्वन्द्विता समाप्त कर पायी और न ही विलयीकरण को बढ़ावा देकर वे उद्योग को समृद्धि के मार्ग पर ले जा सकी। रेलों की प्राप्तियाँ (revenue) घट गयी तथा श्रम असन्तोष बढ़ गया। इन कठिनाइयों के अतिरिक्त रेलों के सामने अब सबसे गम्भीर समस्या मोटर यातायात में वृद्धि हो जाने के कारण उसके साथ होने वाली प्रतिद्वन्द्विता थी। यह यातायात का साधन अधिक लोकप्रिय होता जा रहा था क्योंकि यह सस्ता एवं सुविधाजनक था। सारा का सारा अच्छा माल अब मोटर परिवहन द्वारा ही ढोया जाने लगा। कम मुनाफे वाला माल ही अब रेलों के लिए शेष रह गया।

रेल व मोटर यातायात के बीच प्रतिद्वन्द्विता की गुत्थी सुलझाने के उद्देश्य से ब्रिटिश संसद ने 1933 में रेल व सड़क यातायात विधेयक (The Road and Rail Traffic Act, 1933) पारित किया। यह विधेयक दोनों ही यातायात के साधनों को बड़े ग्राहकों को कुछ रियायतें देने की अनुमति देता था। 1937 में यात्री भाड़े व माल भाड़े में भी 5 प्रतिशत की वृद्धि की गयी किन्तु उससे रेलों को कोई लाभ मिलने की सम्भावना नहीं थी क्योंकि सारा माल मोटर परिवहन को स्थानान्तरित हो जाने का अन्देश था।

विभिन्न समयों में ब्रिटिश रेलों की लम्बाई

वर्ष	मील
1840	1,857
1860	10,433
1900	21,666
1904	24,755
1912	31,553
1920	23,734
1923	20,314
1930	20,402
1947	19,414
1958	19,025

नोट 1912 के बाद रेलों की लम्बाई में कमी कुछ बिना मुनाफे वाली रेल लाइनों के बन्द कर दिये जाने से हुई।

5. द्वितीय विश्व-युद्ध का काल : 1939-1945

जिन दिनों रेल कम्पनियाँ सरकार से कुछ रियायतें प्राप्त कर मोटर यातायात

के साथ प्रतिद्वन्द्विता कर पाने के लिए तैयार कर रही थी जल्दी दिनों सितम्बर 1939 में दूसरा विश्व-युद्ध छिड़ गया। युद्ध के वर्षों में रेलों का कार्य-संचालन आर्थिक नहीं बल्कि सैनिक आधार पर किया गया। एक बार पुनः वे सरकारी नियन्त्रण में चली गयी। 1940 में एक योजना स्वीकार की गयी जिसके अनुसार रेलों को प्रतिवर्ष 40 मिलियन पौण्ड की न्यूनतम प्राप्तियों (minimum receipts) की गारण्टी प्रदान की गयी। यदि कोई नुकसान होता तो उसे सरकार द्वारा वहन करने का प्रस्ताव किया गया। इस राशि को बढ़ाकर 43 मिलियन पौण्ड कर दिया गया।

किन्तु वास्तव में कुछ ऐसा हुआ कि इस योजना के अन्तर्गत सरकार ने भारी लाभ कमाया। 1941-45 की अवधि में रेलों को हुई कुल प्राप्तियों में से कम्पनियों को भुगतान कर देने के बाद भी 200 मिलियन पौण्ड का अतिरिक्त शेष रह गया। इसके अलावा सरकार को सैनिकों व उनके साज-सामान का आवागमन बिना कोई भुगतान किये कर सकने की सुविधा भी मिल गयी।

लाभ बढ़ा किन्तु युद्ध के दौरान रेलों की स्थिति खराब होती चली गयी। रेल इंजिनो से उनकी क्षमता से अधिक काम लिया गया, लाइनों की अच्छी तरह देखभाल नहीं हो पायी तथा कर्मचारियों की संख्या घटा दी गयी। इस तरह युद्ध के बाद रेलों का पुनर्निर्माण एक भारी काम बन गया।

6 ब्रिटिश रेलों की आधुनिक स्थिति

1945 में लेबर दल की सरकार ने यह अनुभव किया कि रेलों के पुनर्निर्माण का काम उनके राष्ट्रीयकरण के बाद ही सम्भव था। अब उद्योग में सिर्फ चार ही मुरार रेल कम्पनियाँ बच रही थीं। 1947 के विधेयक के अन्तर्गत एक यातायात आयोग (Transport Commission) स्थापित किया गया जिसे न केवल रेलों बल्कि नहरों व सड़क यातायात कम्पनियों को भी अधिग्रहित (acquire) करने का काम सौंपा गया। सरकार ने यह श्रद्धा देश में एक एकीकृत यातायात व्यवस्था कायम करने के उद्देश्य से उठाया।

नयी रेल व्यवस्था को छह क्षेत्रों में विभक्त किया गया। पुरानी संस्थाओं को समाप्त कर दिया गया तथा उनके स्थान पर एक नया यातायात ट्रिब्यूनल गठित किया गया जिसका काम किराये व भाडों की नयी सूची को स्वीकृति देना था। आरम्भ में राष्ट्रीयकरण के कदम से कठिनाइयाँ ही बढ़ीं। कई नयी परेशानियाँ भी पैदा हुईं। लागते काफी चढ़ चुकी थी और पुनर्निर्माण का काम काफी सजीला बन गया। पेट्रोल पर राशनिंग हटा लिये जाने के बाद रेलों को फिर एक बार सड़क यातायात की प्रतिद्वन्द्विता का सामना करना था। 1956 में रेलों को 120 मिलियन पौण्ड का घाटा हुआ।

एक नवीनीकरण योजना जो 1971 तक चतनी थी, घोषित की गयी। इस योजना की लागत बहुत ऊँची थी और उसके लिए 1240 मिलियन पौण्ड का अनुमान लगाया गया था। इस योजना में भाग से चलने वाले इंजिनो के स्थान पर डीजल तथा बिजली से चलने वाले इंजिनो को लगाने का प्रस्ताव था। 1947 के

अवनति के कारण

(1) 'विश्व का कारखाना' बन जाने के बाद अब धीरे-धीरे ब्रिटेन की औद्योगिक शक्ति का ह्रास होता चला गया है। इसके परिणामस्वरूप विदेशों के साथ ब्रिटिश व्यापार में कमी आयी है जिससे जहाजों की माँग भी घटी है।

(2) जापान, स्वीडन तथा संयुक्त राज्य अमरीका अब ब्रिटेन के शक्तिशाली प्रतिद्वन्द्वी बन चुके हैं।

(3) द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद उपनिवेशों के हाथ में निकल जाने तथा युद्ध के दौरान अनेक जहाज नष्ट हो जाने के कारण भी ब्रिटिश जहाजों यातायात को भारी धक्का लगा है।

(4) वायु यातायात का विकास हो जाने के कारण यात्री जहाज तो बिल्कुल बेकार हो गये हैं।

यह बात अब लगभग निश्चित-नी हो चुकी है कि ब्रिटिश जहाजों यातायात की प्रमुखता की स्थिति समाप्त हो गयी है। इसका यह अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि ब्रिटेन का जहाजों टन भार निरक्षेप रूप से कम हो गया है। चूँकि विश्व भर में जहाजों टन भार में वृद्धि की दर अत्यधिक तीव्र रही है (विशेष रूप से जापान व अमरीकी जहाजों टन भार अत्यधिक तेजी से बढ़ गया है) इसीलिए ब्रिटिश जहाजों का टन भार प्रतिशत रूप से गिरता चला गया है।

5. हवाई यातायात

(The Air Transport)

भाप के इंजिन की तरह ही ब्रिटिश आविष्कारों को 'उड़ने वाली मशीन' (Flying Machine) बनाने का श्रेय नहीं मिला। यह काम अमरीका के राइट बन्धुओं (Wright Brothers) ने ही किया। ब्रिटेन में पहली हवाई यातायात कम्पनी इंपीरियल एयरवेज लिमिटेड (Imperial Airways Limited) 1926 में गठित की गयी। उसके बाद से लेकर आज तक हवाई यातायात ने एक से एक नये कीर्तिमान स्थापित किये हैं। नवीनतम कॉन्कोर्डे (Concorde) वायुयान, जो 2000 किलोमीटर प्रति घण्टा की रफ्तार से उड़ने वाला विश्व का सर्वाधिक तेज गति वाला वायुयान है, एक ब्रिटिश फर्म द्वारा ही तैयार किया गया है। एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में बी० ओ० ए० सी० (B O A C) ने अन्तर्राष्ट्रीय हवाई यातायात के क्षेत्र में अच्छी रयाति अर्जित की है तथा विश्व हवाई यातायात में उसका भाग भी काफी अच्छा है।

व्यावसायिक क्रान्ति

(The Commercial Revolution)

यातायात के क्षेत्र में हुई एक सम्पूर्ण क्रान्ति औद्योगिक क्रान्ति के साथ मिल कर व्यवसाय में भी क्रान्ति उत्पन्न करने के अतिरिक्त कर ही क्या सकती थी। जहाज-रानी तथा रेलों के विकास ने ब्रिटिश साम्राज्य के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई

□ ब्रिटेन का आर्थिक विद्वान/5

थी। ब्रिटेन की व्यावसायिक क्रान्ति की ऐसी अनेक विशेषताएँ रही जिनका उल्लेख किया जा सकता है

(1) भारी वस्तुओं के व्यापार का प्रसार—यातायात एवं दूर संचार के साधनों के क्षेत्र में हुए क्रान्तिकारी सुधारों से न केवल दुनिया बहुत सिमट चुकी है। बल्कि उनके कारण व्यापार की संरचना में भी अनेक दूरगामी परिवर्तन हुए हैं। ब्रिटिश वस्तुएँ अधिक समानोद्भूत (standardised) हुई हैं। संगठन एवं बिक्री के तरीकों में भारी परिवर्तन हुए हैं। व्यावसायिक क्रान्ति के बाद बड़े व्यापारिक सौदे करते समय वस्तुओं की भौतिक रूप में उपस्थिति की अनिवार्यता समाप्त हो चुकी है। भारी वस्तुएँ जैसे कोयला, लोहा, गेहूँ तथा अन्य वच्चे माल अब बहुत दूर तक आसानी से ले जाये जा सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप विश्व-भर में मूल्य एकरूपता स्थापित हुई है।

(2) व्यावसायिक संगठन में क्रान्ति—संयुक्त पूंजी कम्पनियों का प्रादुर्भाव एवं विकास, स्टॉक एक्सचेंज, आधुनिक वस्तु विनिमयालय (produce exchanges), अत्यधिक विकसित कृषि एवं औद्योगिक बाजार तथा अनेक मध्यस्थ इकाइयों (intermediaries) का उद्भव एवं प्रगति व्यावसायिक क्रान्ति का ही परिणाम हैं। बड़े-बड़े विभागीय स्टोरो (departmental stores) के रूप में खुदरा व्यापार का विकास तथा बहुधन्यो फर्मों का आगमन भी व्यावसायिक क्रान्ति के कारण ही हुआ है। इन विभागीय दुकानों में एक ही छत के नीचे सभी तरह की चीजें उपलब्ध होने लगीं। बहुशाखा फर्मों (multiple firms) दुकानों की शृंखला के रूप में विकसित हुईं जो शाखाओं के रूप में सभी भागों में फैल गयीं।

(3) उद्योग तथा व्यवसाय का पृथक्करण—व्यावसायिक क्रान्ति ने विशिष्टीकरण के युग की भी शुरुआत की। पहली बार उद्योग को व्यवसाय से अलग करके देखा जाने लगा। स्वयं उद्योगकर्ता द्वारा अपनी वस्तुएँ बाजार में बेचने के लिए ले जाना, उनके लिए मोल भाव करना आदि बिल्कुल वन्द हो गया। विपणन (marketing) एक अलग ही शाखा के रूप में विकसित हुआ तथा उसे व्यवसाय की एक विशिष्ट शाखा माना जाने लगा।

व्यावसायिक संगठन स्पष्ट रूप से दो भागों में विभक्त हो गया। थोक शाखा व खुदरा शाखा। इसके अलावा वस्तुगत विशिष्टीकरण की प्रथा भी आरम्भ हो गयी जिससे गेहूँ तथा कपास विनिमयालय (Wheat and Cotton Exchanges) की स्थापना हुई। त्रय एवं चतुर्भुज भी दो अलग अलग त्रियाएँ बन गयीं। व्यवसाय में आये इन परिवर्तनों ने व्यावसायिक अभिकर्ताओं (business agents) के एक ऐसे वर्ग का जन्म दिया जो अपनी फर्मों के लिए खरीद और बिक्री का ही काम देखते थे।

इन दिनों वापस ऐसी प्रवृत्ति देखने में आ रही है जिसमें निर्माता लोग स्वयं ही अपने लिए खरीद कर रहे हैं। इस प्रवृत्ति को 'व्यवसाय एवं उद्योग के पुनर्संगठन' की संज्ञा दी गयी है। यह प्रथा मुख्य रूप से तम्बाकू, कपड़ा तथा घरेलू मशीनें तैयार करने वाले उद्योगों में देखी जा रही है।

(4) एकीकरण की प्रवृत्ति—रेलो तथा वाष्प-चालित जहाजों के उन्नीसवीं

तथा बीसवी शताब्दी में व्यापक उपयोग से तथा औद्योगीकरण की गति अत्यधिक तीव्र हो जाने से समूहों तथा विलयीकरणों (combinations and amalgamations) के नये-नये रूप सामने आये हैं। खड़े (vertical) तथा आड़े (horizontal) समूह बन गये हैं। खड़े समूहों के अन्तर्गत कोयला खानों को चनाने, वच्चे लोहे की आपूर्ति करने, इस्पात तैयार करने के लिए भट्टियाँ चलाने जैसी क्रियाएँ एक ही प्रबन्ध के अन्तर्गत की जा रही हैं। आड़े समूहों के अन्तर्गत एक ही प्रकार का व्यवसाय करने वाली अनेक फर्में इकट्ठा हो गयी हैं जिससे कि आपसी प्रतिद्वन्द्विता को घटाया जा सके व मुनाफा बढ़ सके। विभागीय दुकानों (departmental stores) का विकास भी खुदरा व थोक व्यवसाय का सामूहिकीकरण ही है।

(5) नयी वित्तीय क्रियाओं का युग—यातायात एवं सदेशवाहन के नये तरीकों ने पूँजी की गतिशीलता को भी काफी बढ़ा दिया है। पूँजी का आवागमन अन्तर्राष्ट्रीय बन चुका है। सार्वजनिक वित्त के क्षेत्र का भी विकास हुआ है क्योंकि रेलों के निर्माण के लिए अनेक बार राष्ट्रीय ऋण लिये गये थे। रेलों और सड़क परिवहन के साधनों तथा जहाजों के निर्माण से विनियोग के नये-नये अवसर पैदा हुए हैं। अन्य देशों में रेल-निर्माण करने का काम भी ब्रिटिश विनियोगकर्ताओं के लिए लाभदायक रहा क्योंकि उनके पाम अपने छोटे से देश में लगाने से वही अधिक धन उपस्थित था।

सरकारों तथा विभिन्न देशों के बीच विनियोग के समझौते भी सामान्य बात बन गये। वस्तुओं व सेवाओं के आवागमन में वृद्धि हो जाने से समाशोधन गृहों (clearing houses) तथा सट्टें बाजारों का भी विकास हुआ। व्यावसायिक बैंकों द्वारा की जाने वाली साख निर्माण की प्रक्रिया में भी अनेक परिवर्तन आये।

(6) विदेशी व्यापार का विकास—यातायात एवं दूरसंचार के साधनों में हुई क्रान्ति के साथ-साथ व्यावसायिक नीति में आये परिवर्तनों ने मिलकर ब्रिटेन के विदेश व्यापार को काफी बढ़ा दिया। यह वृद्धि पिछली दो शताब्दियों में मुख्यतः हुई है। विदेश व्यापार का परिणाम सबसे अधिक 1800 से 1925 की अवधि के बीच बढ़ा। उसके निर्यातों में हमेशा निमित्त माल की प्रधानता तथा आयातों में कच्चे माल का आधिक्य रहा। इनके अतिरिक्त ब्रिटेन ने अनेक अद्भुत मदों जैसे जहाजी भाड़ों व विदेशों में अपने विनियोग पर प्राप्त प्रतिकूलों से भी काफी भावना में धन कमाया।

(7) व्यावसायिक क्रान्ति के सामाजिक प्रभाव—व्यावसायिक क्रान्ति ने नये नगरों को जन्म दिया। लोगो तथा पूँजी की गतिशीलता में भारी वृद्धि हुई। इसके परिणामस्वरूप जनसंख्या का आव्रजन, निष्क्रमण तथा स्थानान्तरण हुआ। दक्षिणी अफ्रीका, आस्ट्रेलिया तथा कनाडा का उपनिवेशन (colonisation) इंग्लैण्ड तथा यूरोप में यातायात एवं व्यापार के क्षेत्र में हुई क्रान्ति का प्रत्यक्ष परिणाम था। रेलों के विकास ने तो डाइवरो, गार्डों, आग बुझाने वालों (firemen) तथा स्टेशन मास्टरों का एक पूरा वर्ग ही तैयार कर दिया।

व्यावसायिक नीति : मुक्त व्यापार बनाम संरक्षण (THE COMMERCIAL POLICY FREE TRADE vs PROTECTIONISM)

ब्रिटिश व्यावसायिक नीति में पिछली चार-पाँच शताब्दियों के दौरान हुए परिवर्तनों को मोटे तौर पर तीन स्पष्ट वर्गों में रखा जा सकता है

(1) बणिक्वाद (mercantilism) की नीति जिसका कि उद्देश्य ब्रिटेन को सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्र बनाना था। यह नीति लगभग 250 वर्षों तक बड़े जोर-शोर से चलती रही जो सोलहवीं शताब्दी से प्रारम्भ होकर अठारहवीं शताब्दी के मध्य तक चली। बणिक्वादियों (mercantilists) का यह विश्वास था कि व्यवसाय और उद्योग पर राज्य का नियमन एवं नियन्त्रण रहना चाहिए।

(2) 1776 में एडम स्मिथ की पुस्तक 'वेल्थ ऑफ नेशन्स' के प्रकाशन के बाद मुक्त व्यापार (laissez faire) का एक नया युग प्रारम्भ हुआ जो सम्पूर्ण उन्नीसवीं शताब्दी तथा बीसवीं शताब्दी के भी प्रारम्भिक वर्षों तक चलता रहा।

(3) ब्रिटिश व्यावसायिक नीति का तीसरा चरण उन्नीसवीं सदी के आखिरी वर्षों में शुरू हो चुका था लेकिन संरक्षणवाद (protectionism) की नीति वाला यह चरण 1930 के बाद ही पूरी तरह स्थापित हो पाया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की आधुनिक व्यावसायिक नीति पर द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय समझौतों के रूप में विकसित हुई अन्तर्राष्ट्रीय पद्धतियों (bilateral and multilateral agreements) का व्यापक प्रभाव पड़ा है।

ब्रिटिश व्यावसायिक नीति के ये तीनों चरण, जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है, काफी लम्बी अवधि तक चलते रहे। प्रत्येक चरण समय एवं परिस्थितियों के आदेशों का पालन करता हुआ चला और जब समय व परिस्थितियाँ बदल गयीं तो वह समाप्त हो गया तथा उसके स्थान पर एकदम भिन्न प्रणाली का प्रादुर्भाव होता चला गया।

1 बणिक्वाद और राजकीय नियन्त्रण

पन्द्रहवीं शताब्दी से पहले इंग्लैंड में आर्थिक गतिविधियों की परिधि स्थानीय थी और सम्पत्ति का संचय ईसाई धर्म की मान्यताओं के विरुद्ध माना जाता था।

सामाजिक वर्गों का विभाजन आड़ी किस्म (horizontal) का था तथा लोग अपने आपको सूरमाँ (knights), पादरी (priests), व्यापारी या कृषिदाम (serfs) के रूप में मानते थे। वे अंग्रेज, फ्रेंच या स्पेनवासी बाद में थे। यह प्रवृत्ति पन्द्रहवीं शताब्दी आते ही एकदम बदल गयी तथा नव-जागरण (renaissance) के आन्दोलन ने इंग्लैण्ड में प्राचीन काल से चली आ रही सामन्तवादी प्रथा को समाप्त कर दिया व धर्म के क्षेत्र में भी सुधारवादी (reformation) आन्दोलन सक्रिय हो गया।

पन्द्रहवीं शताब्दी के समाप्त होते होते राष्ट्रवाद की भावना का विकास काफी स्पष्ट हो चुका था। यूरोप का प्रत्येक देश अपने आपको एक अलग राजनीतिक, धार्मिक एवं आर्थिक इकाई मानने लगा था। इस तरह जब विभिन्न देश अपने-अपने हितों के प्रति जागरूक हो गये तो उन्होंने अन्य देशों को अपने प्रतिद्वन्द्वी के रूप में देखना शुरू कर दिया। प्रत्येक देश का उद्देश्य अपनी आजादी की रक्षा करना था। इस उद्देश्य के लिए लोगों की गतिविधियों पर नियन्त्रण लगाना जरूरी था जिनकी मध्य युग में स्वतन्त्र छोड़ दिया गया था। यह अधिकार राज्य द्वारा प्रयुक्त होना था और इसीलिए सोलहवीं से अठारहवीं शताब्दी के बीच राज्य (state) इंग्लैण्ड व अन्य यूरोपीय देशों में काफी शक्तिशाली बन गया।

लोगों के क्रिया कलापो पर राजकीय नियन्त्रण के समर्थकों को वणिकवादियों (mercantilists) का नाम दिया गया। वणिकवाद (mercantilism) का अर्थ इस प्रकार के आर्थिक व राजनीतिक नियन्त्रण लगाना था कि जिनसे इंग्लैण्ड एक शक्तिशाली देश बन सके। वणिकवाद, जो सोलहवीं सदी से अठारहवीं सदी के बीच फला फूला, इस बात में विश्वास करता था कि राज्य के हितों को प्राथमिकता देने के लिए व्यक्ति के हितों पर नियन्त्रण लगाया जाना चाहिए।

वणिकवाद के उद्देश्य

(1) राष्ट्रीय शक्ति का विकास—यह इसका प्रथम उद्देश्य था जिसके लिए विशाल एवं स्वस्थ जनसंख्या को आवश्यक माना गया। चिकित्सा विज्ञान का अभी तक विकास नहीं हुआ था और सरकार का यह विश्वास था कि ग्रामीण जीवन अधिक स्वास्थ्यवर्द्धक होता है इसलिए वह नाहरों के विकास को हतोत्साहित करती थी। किसानों को जमीन से सम्बद्ध रखना सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझा जाता था।

(2) खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता—वणिकवादी खेती को चरागाह से अधिक महत्व देते थे। उनका मानना था कि यदि कोई देश खाद्यान्नों के लिए दूसरों पर निर्भर करता है तो उसे भूखी मरना पड़ सकता है।

(3) सुदृढ़ नौसेना—इंग्लैण्ड की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए वणिकवादी यह अनुभव करते थे कि ब्रिटेन के लिए सुदृढ़ नौसेना आवश्यक थी। जहाज निर्माण को राजकीय संरक्षण प्रदान किया जाना था।

(4) उद्योगों का नियंत्रण—यह स्थानीय स्तर पर किया जाता था किन्तु वणिकवादियों का विश्वास था कि उद्योगों पर राजकीय नियन्त्रण होना चाहिए।

(5) विदेशी व्यापार पर नियन्त्रण—वणिकवादी विदेशी व्यापार पर भी

राजकीय नियन्त्रण के पक्ष में थे। यह नियन्त्रण विदेशी व्यापार को कुछ विशेष रूप से बनायी कम्पनियों के हाथों सौंपकर किया जाना था। ईस्ट इण्डिया कम्पनी ऐसी ही एकाधिकारिक कम्पनी थी।

(6) सोना व चाँदी के पर्याप्त भण्डार—राज्य की सुरक्षा के लिए स्वर्ण व रजत के विशाल भण्डारों को अनिवार्य माना गया। ये युद्ध कार्य का संचालन करने के लिए आवश्यक थे क्योंकि इनसे हर चीज खरीदी जा सकती थी। वणिकवादी इंग्लैंड के लिए सोना व चाँदी के भण्डार जमा करना इसलिए भी जरूरी समझते थे क्योंकि ये दोनों धातु इंग्लैंड की खानों में नहीं निकलते थे। उनका विश्वास था कि इंग्लैंड के विदेश व्यापार का नियमन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि जिससे अधिक से अधिक बहुमूल्य धातुएँ प्राप्त हो सकें। वे सिर्फ ऐसे विदेशी व्यापार के हामी थे जो ब्रिटेन के पक्ष में हों ताकि अधिक से अधिक सोना देश में आ सके। ऐसा करते समय उन्होंने यह नहीं सोचा कि बहुमूल्य धातुओं की मात्रा बढ़ जाने से उनकी कीमत घट जायेगी तथा यह भी कि किसी भी देश के लिए हेर समय निर्यात अतिरेक बनाये रखना सम्भव नहीं होता।

वणिकवादियों के अधिकांश बड़े विचार, जो इंग्लैंड को सर्वाधिक नृत्तिशाली बनाने के लिए थे, आलोचना के शिकार हुए। किन्तु वह एक ऐसा समय था जब आत्मनिर्भरता अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से तथा सुरक्षा बहुलता से अधिक महत्त्वपूर्ण मानी जाती थी।

वणिकवाद के प्रभाव

(1) ब्रिटिश कृषि को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक कानून पारित किये गये। खाद्यान्नों के आयात को सीमित करने के लिए अन्न कानून (corn laws) पारित किये गये। ब्रिटिश संसद ने, जिसमें कि भूस्वामियों का दबदबा अधिक था, 1773 में यह तय किया कि इंग्लैंड में तब तक अनाज का आयात नहीं किया जायगा जब तक कि उसके मूल्य 48 शिलिंग की सीमा को न छू ले। किन्तु जब 1815 में अनाज (corn) के मूल्य 60 शिलिंग तक बढ़ गये तो सीमा को बढ़ाकर 80 शिलिंग कर दिया गया। इस तरह अनाज के आयात की अनुमति नहीं दी गयी। किन्तु यह सब श्रमिकों तथा सामान्य उपभोक्ताओं के हित में नहीं था। डेविड रिकॉर्डें ने, जोकि भू-स्वामियों का कट्टर विरोधी था, तर्क दिया कि अन्न कानून (corn laws) श्रमिकों के हितों के विरुद्ध थे तथा उनका कल्याण कम करते थे। इससे एक बटु सघर्ष आरम्भ हुआ तथा 1846 में अन्न कानूनों को रद्द कर दिया गया।

(2) सूती वस्त्र एवं ऊन उद्योग को वणिकवादी नीतियों से भारी लाभ मिला। उनसे विदेशी व्यापार को भी प्रोत्साहन मिला। अनेक महत्त्वपूर्ण औद्योगिक कानून पारित किये गये। उत्पादन का समानीकरण (standardisation) किया गया तथा अनेक बड़ी एकाधिकारी फर्में बनीं। वणिकवादी तैयार माल के आयात के विरुद्ध थे तथा वे बच्चे माल के आयात का स्वागत करते थे। 1463 में रेनम तथा अन्य अनेक वस्तुओं के आयात पर लगायी गयी रोक वणिकवाद का प्रत्यक्ष प्रभाव थी।

कच्चे माल के निर्यात का भी विरोध किया गया। ऊन उद्योग को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से कच्ची ऊन का निर्यात रोक दिया गया। 1721 में बेलिको कानून (Calico Act) पारित किया गया जिसने भारतीय बढिया वस्त्र के उपयोग पर रोक लगा दी। उनकी कला को रहस्य बनाये रखने के उद्देश्य से ब्रिटिश कारीगरों के देश छोड़कर जाने पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया गया। इसके विपरीत विदेशी कारीगरों को इंग्लैंड में आने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

माप व तोल को सुनिश्चित बनाया गया। श्रमिकों की काम की दशाओं को नियमित किया गया। 1563 में पारित एक विधेयक में न्यूनतम मजदूरी तथा सबको रोजगार देने का प्रावधान किया गया।

(3) वणिक्वादी नीतियों के प्रभाव में इंग्लैंड की सरकार ने अनेक व्यावसायिक सन्धियाँ (commercial treaties) की जिनका उद्देश्य देश के लिए नये बाजार तथा कुछ स्वतन्त्राधिकार प्राप्त करना था। निर्यात व आयात के आँबडों का बराबर अध्ययन किया जाता। फ्रांस के साथ व्यापार को हतोत्साहित किया गया क्योंकि उसमें अक्सर इंग्लैंड को घाटा रहता था।

(4) ब्रिटिश व्यापारिक जहाजों का विकास करने के उद्देश्य से नौ-परिवहन कानून (navigation laws) बनाये गये। 1381 में पारित एक विधेयक ने ब्रिटिश व्यापारियों द्वारा विदेशी जहाजों के उपयोग पर रोक लगा दी। 1660 में पारित विधेयक ने उपनिवेशों के बीच वस्तु व्यापार को ब्रिटिश जहाजों के लिए सुरक्षित कर दिया तथा साथ ही औद्योगिक वस्तुओं के व्यापार को भी ब्रिटिश व्यापारिक जहाजों वेड़े का एकाधिकार घोषित कर दिया।

(5) वणिक्वादियों ने उपनिवेशों के अधिकाधिक शोषण की ब्रिटिश साम्राज्य की नीति को भी प्रोत्साहित किया। उनका मानना था कि उपनिवेशों का तो अस्तित्व ही इंग्लैंड के लाभ के लिए था। उनका यह भी विश्वास था कि उपनिवेश कच्चा माल पैदा करने के लिए थे और उनका दूसरा उपयोग ब्रिटिश निर्मित माल के लिए सुरक्षित बाजारों के रूप में था। उपनिवेशों में नियुक्त ब्रिटिश गवर्नरों को यह निर्देश दिये गये कि वे उपनिवेशों में ऐसे उद्योग विकसित न होने दें जो ब्रिटिश उद्योगों के साथ प्रतिद्वन्द्विता कर सकते हों। 1699 में पारित विधेयक ने उपनिवेशों से ब्रिटेन में कपड़े के आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिया जिससे कि लकाशायर के वस्त्र उद्योग को फलने फूलने में आसानी होती।

(6) 'स्वर्णमन्त्र', 'वर्णित', 'वर्णितवादी', 'उपायो' व इंग्लैंड के, भारत, फ्रांस के स्वर्ण भण्डार बढ़ाने में सहायता मिली। सरकार के प्रत्यक्ष हस्तक्षेप द्वारा स्वर्ण के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। पन्द्रहवीं शताब्दी में स्वर्ण मुद्राओं के निर्यात को एक गम्भीर अपराध माना जाता था। विदेशियों को एक लिखित प्रमाण पत्र देना पड़ता था कि वे अपनी कमाई सोने या चाँदी के रूप में नहीं भेजेंगे। वणिक्वादियों ने सन्तुलित व्यापार नीति का प्रतिपादन किया जिसे स्वर्ण के आयात व निर्यात के नियमन में काम में लिया गया।

किन्तु वणिक्वादियों के इस स्वर्ण-उन्माद (gold mania) की कई लोगों

द्वारा आलोचना की गयी। किन्तु यही सम्पूर्ण वणिक्वाद नहीं था और न ही वणिक्वादी केवल स्वर्ण उन्मादी (gold maniacs) थे। वे ब्रिटिश कृषि, उद्योग, जहाजरानी तथा विदेशी व्यापार में संरक्षणवादी नीतियों के समर्थक थे। वे देश की आर्थिक स्वतन्त्रता के लिए अत्यधिक चिंतित थे तथा ब्रिटेन की आर्थिक सर्वोच्चता कायम करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने तीन स्तम्भ बनाये। ये स्तम्भ थे अन्न कानून (corn laws), वे विधेयक जिनमें उद्योगों को संरक्षण प्रदान किया गया तथा नौ-परिवहन कानून (navigation laws)। इस प्रकार से ब्रिटेन की कानूनी सीमाबन्दी (legal insulation) उस समय की ऐतिहासिक आवश्यकता थी तथा उसने देश को औद्योगिक क्रान्ति में अग्रणी बना दिया। इसके बावजूद वणिक्वादियों की अनेक बातों को लेकर आलोचना हुई जिसकी चर्चा की जा सकती है।

वणिक्वाद की आलोचना

(1) आत्मनिर्भरता का संकुचन दृष्टिकोण—वणिक्वादी विचारकों ने आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने पर आवश्यकता से अधिक बल दिया। उन्होंने यह नहीं समझा कि विशिष्टीकरण से लागतों में कमी आती है तथा सस्ती लागत पर उत्पादित वस्तुओं के परस्पर विनिमय से सभी को लाभ होता है।

(2) स्वर्ण उन्माद (Gold Mania)—एडम स्मिथ तथा जे० एस० मिल ने लिखा कि वणिक्वादी विचारक केवल सोने व चांदी को ही धन का एकमात्र स्वरूप मानते थे। इन लेखकों ने वणिक्वादियों पर यह भी आरोप लगाया कि उनका यह विश्वास था कि 'मुद्रा ही धन थी' (Money alone constituted Wealth)। किन्तु कुछ लोग इस बात से सहमत नहीं हैं। जैम लिप्सन (Lipson) ने लिखा है कि 'खजाने को भरने जाना वणिक्वाद का कोई आधारभूत सिद्धान्त नहीं था।' किन्तु इतना अवश्य कहना होगा कि वणिक्वादी विचारक यह तथ्य नहीं समझ पाए कि सोने का संग्रह करने के लिए राष्ट्र को निर्यातों के रूप में कीमत चुकानी पड़ती है। उन्होंने स्वर्ण तथा रजत का भारी मात्रा में संग्रह करने से उनकी मांग व पूर्ति की स्थितियों में आने वाले परिवर्तनों को भी अनदेखा कर दिया।

(3) उपनिवेशों के लिए हानिकारक—वणिक्वादी नीतियाँ अनुदार तथा अज्ञानतापूर्ण थीं जिनसे उपनिवेशों के साथ घोर अन्याय हुआ।

(4) देशों के बीच प्रतिद्वंद्विता की भावना में वृद्धि—अत्यधिक स्वार्थी दृष्टिकोण की बहुत अधिक वकालत करते वणिक्वादियों (mercantilists) ने यूरोप के विभिन्न राष्ट्रों के बीच ईर्ष्या तथा प्रतिद्वंद्विता की भावनाओं को उभारा और इस तरह अनेक युद्धों के बीज बो दिये।

(5) परस्पर विरोधी नीतियाँ—नौ परिवहन कानून (Navigational Acts), जिन्हें ब्रिटिश व्यापारिक जहाजों के विकास के लिए बनाया गया था, उद्योग तथा व्यापार के रास्ते में रोड़ा बन गए।

(6) ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करने में नगण्य योगदान—आलोचकों ने ब्रिटेन को महाशक्ति बनाने में वणिक्वादी नीतियों को अविश्वस्य नहीं दिया है। इन

आलोचको का मानना है कि 17वीं तथा 18वीं शताब्दी में आयी ब्रिटिश समृद्धि ब्रिटिश साहसिकताओं के प्रयासों तथा यूरोप के देशों के बीच हो रहे युद्धों से उसका कोई वास्ता न होने के कारण आयी।

इन विचारों के साथ-साथ उस समय की परिस्थितियों को नहीं भुलाया जाना चाहिये। उस समय देश एक-दूसरे से निरंतर शत्रुता की स्थिति में जीते थे तथा अपने पड़ोसियों पर भी उनका भरोसा नहीं था। ये देश सुरक्षा को समृद्धि या बहुलता से अधिक पसंद करते थे। इन बिन्दुओं को यदि ध्यान में रखा जाये तो लगता है कि उस काल में वणिकवाद (mercantilism) ही एकमात्र व्यावहारिक नीति थी।

2. मुक्त व्यापार नीति

सोलहवीं शताब्दी के बाद कम से कम 250 वर्षों तक ब्रिटिश अर्थव्यवस्था पर राज्य द्वारा अनेक नियंत्रण व नियमन आरोपित किये जाते रहे। इस तरह अर्थव्यवस्था पर राज्य की निगरानी वणिकवादी सिद्धान्तों पर आधारित थी। यह सब अठारहवीं शताब्दी तक चलता रहा किन्तु तब तक व्यापार व व्यवसाय पर राजकीय नियमन की नीतियों में लोगों की आस्था इस सीमा तक गिर चुकी थी कि उसका मुक्त व्यापार (Free Trade) के पक्ष में परित्याग करना पड़ा। एडमस्मिथ की शिक्षाओं के प्रभाव में 'बहुतायत की नीति' (policy of plenty) 'शक्ति की नीति' (policy of power) के स्थान पर प्रतिस्थापित होती चली गई। इसकी अन्तिम परिणति मुक्त व्यापार की एक शताब्दी के रूप में हुई जिसे अहस्तक्षेप का युग (Laissez Faire) भी कहा जाता है।

अहस्तक्षेप की नीति की मान्यताएँ

(1) व्यक्ति द्वारा अधिकतम लाभ अर्जित किया जा सकता है यदि प्रतिस्पर्द्धा मुक्त एवं प्रतिबन्ध रहित हो। अगर लोगों को प्रतिबन्धों तथा नियमनों से मुक्त रखा जाता है तो वे ऐसी गतिविधियों या क्रिया कलापों को चुनेंगे कि जिनसे उनको अधिकतम लाभ मिलेगा।

(2) इसके अतिरिक्त यह कि जब सब लोग अपने-अपने अधिकतम लाभ के लिए काम करेंगे तो स्वाभाविक रूप से उसकी अन्तिम परिणति के रूप में सारे देश को अधिकतम लाभ प्राप्त होगा।

(3) आर्थिक गतिविधियों पर राज्य द्वारा नियमन की प्रथा को जारी रखना देश के लिए हानिकर माना गया। राज्य का कर्तव्य यह निर्धारित किया गया कि वह निर्विकार भाव से एक ओर खड़ा रहे तथा आर्थिक हितों के टकराव में किसी प्रकार भाग न ले। राज्य से यही अपेक्षा की गई थी कि वह अपनी गतिविधियों को बाह्य आक्रमण से देश की रक्षा करने व आंतरिक कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने तक सीमित रखे।

मुक्त व्यापार की नीति स्वीकार करने के लिए उत्तरदायी तत्त्व

(1) औद्योगिक क्रान्ति का उद्भव—अठारहवीं सदी के मध्य तक ब्रिटिश उद्योगपति प्रतिस्पर्धा से डरते थे। उत्पादन कार्य छोटे पैमाने पर किया जाता था।¹ किन्तु यह सारा चित्र औद्योगिक क्रान्ति द्वारा बदल दिया गया। औद्योगिक क्रान्ति ने इंग्लैंड को दुनिया का सबसे अधिक औद्योगिक देश बना दिया था। उसके उद्योगपतियों को अपना माल बेचने के लिए अधिक से अधिक नये बाजारों की आवश्यकता थी। इस आवश्यकता ने ब्रिटिश उद्योगपतियों को संरक्षणवादी कानूनों को एक के बाद एक हटाने की माँग करने के लिए प्रेरित किया। वैसे भी ये प्रतिबन्ध प्रभावहीन हो चुके थे क्योंकि दुनिया के किसी भी देश में ब्रिटिश सर्वोच्चता को चुनौती दे सकने की क्षमता नहीं रह गई थी।

(2) विदेशों में बदले की कार्यवाही—अनाज से लेकर ऊन तथा जहाजों पर जो प्रतिबन्ध वणिक्वादी नीतियों के प्रभाव में लगाये गये थे उन पर यूरोप के देशों में भारी रोप उत्पन्न हो गया था। उन्होंने भी बदले के तौर पर कई प्रतिबन्ध ब्रिटिश वस्तुओं पर लगा दिये थे जो विकासशील ब्रिटिश उद्योगों के लिए हानिकारक थे।

(3) श्रमिक वर्ग द्वारा विरोध—1760 में औद्योगिक क्रान्ति के आरम्भ होने के साथ ही औद्योगिक श्रमिकों की संख्या में निरन्तर वृद्धि होती जा रही थी। वे लोग अनाज के आयात पर लगे हुए प्रतिबन्धों का घोर विरोध करते थे क्योंकि इससे खाद्य वस्तुओं के मूल्य बढ़ते थे और उन्हें उनके अधिक मूल्य देने के लिए बाध्य होना पड़ता था।

(4) स्वर्णमान की व्यवस्था अपना लिया जाना—नैपोलियन के साथ हुए युद्धों में ब्रिटेन की विजय के बाद से ही ब्रिटिश निर्यात आकाश को छूने लगे थे तथा देश ने स्वर्णमान की व्यवस्था को स्वीकार कर लिया था। स्वर्णमान अपनाने के लिए यह आवश्यक था कि वे सभी प्रतिबन्ध हटा दिये जाते जिन्हें वणिक्वादी नीतियों के प्रभाव में आकर पहले लगाया गया था। आयात को जाने वाली वस्तुओं पर लगे हुए प्रतिबन्धात्मक कर (duties) हटाने पड़े क्योंकि ब्रिटिश उद्योगों को भारी मात्रा में तथा निरन्तर कच्चे माल की आवश्यकता थी। ब्रिटेन ने अपने निर्यातों के बदले आयात करने वाले देश से भुगतान के रूप में कच्चा माल भी स्वीकार करना आरम्भ कर दिया क्योंकि वह प्रत्येक खरीददार देश को स्वर्ण में ही भुगतान के लिए बाध्य नहीं कर सकता था।

(5) निजी उपक्रम (Private Enterprise) में आस्था—जब औद्योगिक क्रान्ति के परिणामस्वरूप फैक्ट्री प्रणाली का उद्भव हुआ तो उसने अनेक बुराईयों को जन्म दिया। इससे श्रमिकों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेकिन सरकार को इस विषय पर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने से इस आधार पर रोका गया कि श्रमिकों को अधिक मजदूरी देने या उनके काम के घटे घटाने का अर्थ होगा ब्रिटिश निर्माताओं को उनके प्रतिद्वन्द्वियों की तुलना में प्रतिकूल स्थिति में रख दिया

इन्ही सिद्धान्तों को औद्योगिक आवास की व्यवस्था करने तथा गातायात के नये साधन अपनाने के मार्ग में अड़चने डालने के काम में लिया गया । टर्नपाइक सड़कों की देख-भाल के लिए निजी स्वामित्व वाले टर्नपाइक ट्रस्ट बनाये गये तथा नहरों का निर्माण कार्य भी निजी कम्पनियों द्वारा ही किया गया, सरकार ने इन्हें न तो कोई सहायता दी और न ही किसी प्रकार की शर्तें लगाईं । रेलों का निर्माण कार्य भी निजी कम्पनियों द्वारा, बिना किसी सरकारी सहायता के, सफलतापूर्वक किया जा चुका था । इन कार्यों के निजी कम्पनियों द्वारा सही तरीके से पूरा कर लेने से लोगो तथा सरकार के मस्तिष्क में निजी उपक्रम की क्षमता के बारे में आस्था उत्पन्न हो गई नियंत्रण तभी लगाये गये जब उनके बिना काम चल ही नहीं सकता था ।

(6) एडमस्मिथ द्वारा स्वतन्त्र व्यापार की वकालत—प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने सरकार द्वारा आरोपित सरक्षणवादी उपायों का घोर विरोध किया । उनका सबसे महान् प्रवक्ता एडमस्मिथ था जिसकी पुस्तक 'राष्ट्रों की सम्पदा' (Wealth of Nations) ने आर्थिक विचारों में क्रांति ला दी । उसने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि सभी व्यक्ति इसलिए कार्य करते हैं क्योंकि वे अपने स्व-हित (self-interest) से अनुप्राणित होते हैं तथा यह भी कि व्यक्ति व राज्य के हित हमेशा एक-दूसरे से मेल खाते हैं अर्थात् एक-दूसरे के पूरक होते हैं इस प्रकार का तालमेल या समन्वय स्थापित करने वाली एक अदृश्य शक्ति (invisible hand) होती है ऐसी स्थिति में सरकारी हस्तक्षेप की कही भी आवश्यकता नहीं पड़नी ।

इन सभी सत्त्वों के परिणामस्वरूप 19वीं शताब्दी में इंग्लैण्ड में स्वतन्त्र व्यापार की नीति की मजबूती से स्थापना हुई । इस आर्थिक दर्शन के फलस्वरूप अनेकों नये आर्थिक नियमों की भी स्थापना हुई । एडमस्मिथ ने अपना स्व-हित का नियम (the law of self-interest) प्रतिपादित किया जिसके अन्तर्गत उसने लिखा कि हमें अपना दोनों समय का खाना बसाई या बेकरी वाले की दया के कारण नहीं मिलता बल्कि वह हमें इसलिए मिलता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने 'स्व' (self) से संचालित होता है तथा धन प्राप्त करना चाहता है । इस नीति का स्वाभाविक परिणाम राष्ट्रीय समृद्धि के रूप में सामने आया । प्रतिस्पर्धा की भावना (spirit of competition) को नई ऊँचाइयों पर पहुँचाया गया । जे० एस० मिल ने तो यहाँ तक लिखा कि 'प्रतिस्पर्धा पर लगाया गया प्रत्येक नियन्त्रण बुराई है, उममें होने वाला प्रत्येक प्रसार अन्तिम अच्छाई है ।' भुक्त, व्यापार के समर्थक, मॉग व पूर्ति की, रक्षादो के साथ किसी भी प्रकार की छेड़-छाड़ के विरुद्ध थे । जे० बी० से (J B Say) ने तो कहा था कि 'पूर्ति अपनी माँग स्वयं पैदा करती है ।'

सरकार से यह भी अपेक्षा की जाती थी कि वह मजदूरों के निर्धारण में भी किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करे । स्वतन्त्र व्यापार के समर्थकों, जैसे कोबडन (Cobden) ने लिखा कि 'मजदूरी बड़ी है जब-जब दो मालिक एक ही आदमी के पीछे भागते हैं, और वह गिरी है जब-जब दो मजदूर एक ही मालिक के पीछे भागते हैं ।' इसका अर्थ यह हुआ कि माँग व पूर्ति का नियम श्रमिकों के सन्दर्भ में भी उतना ही लागू ।

होता था जितना वस्तुओं के सन्दर्भ में तथा यदि उनकी जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि नहीं होती तो उन्हें उनकी सीमान्त उत्पादकता के बराबर मजदूरी प्राप्त हो सकने की पूरी-पूरी सम्भावना बनती थी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धान्त में भी भारी क्रान्ति हुई जब रिकार्डों ने अपना यह मत व्यक्त किया कि विनिमय की प्रक्रिया में दोनों ही पक्षों को लाभ होता है ।

मुक्त व्यापार नीतियों का निर्माण व क्रियान्वयन

नैपोलियन के साथ हुए युद्धों के समाप्त होने के समय नौ परिवहन तथा औद्योगिक क्षेत्र में जो सर्वोच्चता ब्रिटेन प्राप्त कर चुका था उसे तब अनेक आर्थिक एवं सामाजिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जबकि व्यापार स्वातंत्र्य की माँगों ने जोर पकड़ा । 1815 में ब्रिटेन पर 860 मिलियन पौण्ड का कर्ज चढ़ा हुआ था तथा उसका वार्षिक करारोपण 72 मिलियन पौण्ड तक जा पहुँचा था जोकि कुछ ही वर्षों पहले तक केवल 17 मिलियन पौण्ड ही था । लगभग प्रत्येक वस्तु पर इतनी ऊँची दर से तटकर लगा दिये गये थे कि उनसे व्यापार बन्द होने का खतरा पैदा हो गया था । व्यवसाय को बेडियाँ डाल दी गई थी । कृषि मन्दी ग्रस्त हो चुकी थी । मजदूरी नीची थी और खाने की चीजें महँगी । कुल मिलाकर लोगों को यह अच्छी तरह पता चल चुका था कि देश की आर्थिक स्थिति शोचनीय थी ।¹

लोगों पर कर-भार कम करने के बजाय 1815 में जो कदम उठाए गए उनसे तो भू-स्वामियों को ही सबसे अधिक लाभ होता था । 1815 में एक ओर जहाँ आय पर कर को समाप्त कर दिया गया वहाँ दूसरी ओर अनाज के मूल्य तथा लगानों को ऊँचा रखा गया । जब 1815 में शान्ति की घोषणा की गई तथा ब्रिटेन में मुक्त रूप से अनाज के आयात की सम्भावना बनी, जिससे कि अनाज का मूल्य काफी गिर सकता था, तो वहाँ के भू-स्वामी काफी परेशान हो गये । उन्होंने संसद के समक्ष संरक्षण की अपील की । संसद, जोकि उस समय भू-स्वामियों द्वारा ही नियन्त्रित होती थी, ने 1815 में 'अनाज कानून' (corn law) के नाम से एक ऐतिहासिक कानून पारित कर दिया ।

1815 के विधेयक ने अनाज के आयात पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया केवल उस परिस्थिति के जबकि उसके मूल्य 80 शिलिंग से अधिक बढ़ जायें । इस मूल्य सीमा को जान बूझ कर ऊँचा रखा गया ताकि भू-स्वामियों के हितों को अधिकाधिक सुरक्षित किया जा सके । जिस समय यह अनाज कानून (corn law) पारित किया गया उस समय अनाज का वास्तविक मूल्य 61 शिलिंग था । यह एक ऐसा कदम था जिससे लोगों को काफी आघात लगा । 1793 के बाद से ही इंग्लैंड में खाद्यान्नों के अतिरिक्त की स्थिति समाप्त हो चुकी थी तथा बढ़ती हुई जनसंख्या ने अनाज को और भी महँगा बना दिया था क्योंकि उसके आयात की अनुमति नहीं थी । फसलें खराब हो जाने से (लगभग दो वर्ष तक) अनाज के मूल्य 1817 में 96 शिलिंग तक पहुँच गये । उनके अतिरिक्त अनाज के आयात करने की दिशा में कोई प्रयास नहीं किये गये ।

आरम्भ से ही अधिकांश लोगो द्वारा अनाज कानून (Corn law) को दुष्टता-पूर्ण माना गया था औद्योगिक जनसंख्या विशेष रूप से इसके मतव्यो के बारे में आशंकित थी। किन्तु जब गेहूँ के दाम चढ़ते चले गये तो अनाज कानून रद्द करने की माँग जोर पकड़ती चली गई। 1820 में लन्दन के व्यापारियों के एक समूह ने संसद के समक्ष एक माँग-पत्र (petition) प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने एडमस्मिथ की पुस्तक 'वैश्य ऑफ नेशनस' को उद्धृत किया तथा स्वतंत्र व्यापार की दिशा में तटकर प्रणाली में सामान्य सुधार के लिए प्रार्थना की। 1821 में नियुक्त एक लॉर्ड्स जांच समिति ने भी यही पाया कि अनाज कानून तथा पूरी की पूरी संरक्षणवादी व्यवस्था की उपयोगिता समाप्त हो चुकी थी।

शुरू में इंग्लैंड द्वारा अपनायी गयी स्वतंत्र व्यापार की नीति तीन मुख्य दिशाओं की तरफ चली

(1) अनाज कानूनों का अंत (Collapse of Corn Laws)—अनाज कानूनों को रद्द करने की माँग बलवती होती चली गई। अनाज कानून विरोधी आंदोलन संसद के भीतर और बाहर चलता रहा। 1832 तक इस आंदोलन को प्रमुख अर्थशास्त्रियों का भी समर्थन प्राप्त हो चुका था। संसद ने यह संकेत दिया कि यद्यपि वह अनाज कानूनों को समाप्त करने में पहल नहीं करेगी किन्तु वह आम राय का अनुसरण करेगी। 1839 में एक अन्न कानून विरोधी सघ (Anti-corn Law League) मैनचेस्टर में गठित किया गया व देश के विभिन्न अनाज कानून विरोधी सघ उससे सम्बद्ध हो गये। रिचर्ड कोबडन (Richard Cobden) व जॉन ब्राइट (John Bright) तथा अनेक कपास उत्पादक लोग इस आंदोलन के प्रबल समर्थकों में थे। इन लोगो ने मिलकर एक समाचार पत्र 'अनाज कानून विरोधी परिपत्र' भी निकाला व लाखों परचे 1843 में अन्न कानून के विरोध में बाटे।

कोबडन के हाउस ऑफ कॉमंस के लिए चुन लिये जाने के बाद तो अनाज कानून विरोधी आंदोलन को और भी बल मिला। इतिहास ने एक नई करवट ली। क्योंकि इन अनाज कानूनों को अनुदार दल की सरकार ने रद्द किया जिसमें कि भूस्वामियों का बहुमत था तथा जो संरक्षणवादी नीतियों को जारी रखना चाहती थी। 1842 में सर रॉबर्ट पील (Sir Robert Peel) की सरकार ने अनाज कानूनों में थोड़ी ढील दी। किन्तु अनाज कानूनों को रद्द करने की प्रक्रिया को पूरा करने का काम 1845 व 1846 की खराब फसलो ने किया। 15 मार्च 1849 को हाउस ऑफ कॉमंस ने एक विधेयक पारित किया जिसमें अनाज कानूनों को रद्द कर दिया।

40 वर्षों के ऐतिहासिक संघर्ष के बाद अनाज कानून रद्द करवाने में मिली सफलता ने उन संरक्षणवादी नीतियों के भाग्य के दरवाजे बन्द कर दिये जिन्हें वणिक-वादियों (Mercantilists) ने बड़ी मेहनत से तैयार किया था। मुक्त व्यापार के समर्थकों के लिए यह एक महान् विजय थी तथा उन्होंने अन्य संरक्षणवादी उपायों का उन्मूलन करवाने का अपना सघ जारी रखा।

(2) नौ परिवहन कानूनों का निरस्तीकरण (Repeal of Navigation Laws)—इंग्लैंड के नौ-परिवहन कानूनों को रद्द किये जाने के लिए तीन प्रमुख तत्त्व

उत्तरदायी थे . (i) संयुक्त राज्य अमरीका की स्वतन्त्रता, (ii) नेपोलियन युग के युद्ध, तथा (iii) वणिक्वादी विचारों के स्थान पर अहस्तक्षेपवादी विचारधारा का प्रतिस्थापन ।

कुछ समय तक टालमटोल करने के बाद ब्रिटिश सरकार ने आखिरकार 1824 में नौ-परिवहन अधिकारों के सम्बन्ध में विदेशी राष्ट्रों के साथ पूर्ण समानता एवं परस्पर स्वीकृति के आधार पर समझौता किया । 1830 तक ब्रिटेन ने लगभग सभी प्रमुख व्यापारिक राष्ट्रों के साथ नौ परिवहन संधियाँ कर ली थी । विदेशी जहाजों को तटीय व्यापार से अब भी अलग रखा गया था किन्तु उपनिवेशों के साथ व्यापार का अधिकार सभी राष्ट्रों को प्रदान कर दिया गया जिससे दूसरे देशों के उपनिवेशों के साथ व्यापार कर सकने का अधिकार ब्रिटेन को भी स्वतः ही मिल गया । किन्तु बाकी वचे विभेदकारी प्रावधानों को भी 1854 में तिलाजली दे दी गई । विलियम हस्किसन (William Huskisson), जो बोर्ड ऑफ ट्रेड का अध्यक्ष था, ने ब्रिटिश नौ-परिवहन कानूनों को निरस्त करवाने में प्रमुख भूमिका निभाई । इस नई नीति के आलोचकों की उपेक्षाओं के विपरीत ब्रिटिश व्यापारिक जहाजों की तीव्र प्रगति हुई । व्यापारिक जहाजों का टन भार 1800 से 1850 के पचास वर्षों में 16 मिलियन टन से बढ़ कर 35 मिलियन टन हो गया ।

(3) सामान्य तटकर में संशोधन (Revision of General Tariff)—हस्किसन (Huskisson) ने लौटती हुई समृद्धि का लाभ उठाकर न केवल पुराने व दिनातीत हो चुके नौ-परिवहन कानूनों को रद्द करवाने में सफलता प्राप्त की बल्कि उसने पूरे सामान्य तटकर ढांचे का स्वरूप ही बदल डाला । सीमा शुल्कों को पूरी तरह बदल डाला गया । हालांकि हस्किसन स्वयं कोई मुक्त व्यापार का कट्टर समर्थक नहीं था मगर उसने यह महसूस कर लिया कि व्यापार की कोई भी प्रथा हमेशा के लिए सतोपजनक नहीं बनी रह सकती । उसने तथा उसके समर्थकों ने पाया कि इंग्लैंड का व्यापार 1500 अलग अलग तरह के कानूनों की गिरफ्त में जकड़ा हुआ था जिनमें अनेक प्रतिबन्ध व अवरोध सम्मिलित थे । वे ब्रिटिश व्यापार को इन सभी बन्धनों से मुक्त करना चाहते थे और इस दिशा में वे वालपोल (Walpole) से भी काफी आगे निकल गये । उन्होंने चार उपलब्धियाँ प्राप्त की

(i) सीमा शुल्क सम्बन्धी कानून आसान बनाये गये ।

(ii) कच्चे माल पर लगने वाले कर (जैसे कोयला, ऊन, रेशम आदि जिन्हें ब्रिटिश निर्माता आयात करते थे) घटाये गये ।

(iii) 1825 के अधिनियम ने नौ आयात किये जाने वाले निर्मित माल पर भी सीमा शुल्कों में 30 प्रतिशत की कमी कर दी । पहले प्रतिबन्धित चीजें जैसे रेशम भी अब इस 30 प्रतिशत में घटाये गये तटकरों पर आयात किये जा सकते थे ।

(iv) निर्यातों पर लगे हुए सभी प्रतिबन्ध—चाहे वे कच्चे माल, थम या निर्मित माल पर हों—हटा लिये गये । यहाँ तक कि मशीनों के आयात की भी अनुमति दे दी गई जिन पर पहले इस ढर से प्रतिबन्ध लगा हुआ था कि कहीं इंग्लैंड के

प्रतिद्वन्द्वी न तैयार हो जाएँ।¹

यह पहले से चली आ रही नीतियों से काफी अलग था तथा संरक्षणवादी व्यवस्था लगभग पूरी तरह टूट चुकी थी। आठ वर्ष बाद 1833 में परिणित चीजों पर सारे सीमा शुल्क समाप्त कर दिये गये तथा सीमा शुल्क की दरें अन्य 700 वस्तुओं पर कम कर दी गयीं। इन परिवर्तनों के परिणाम आशा से कहीं अधिक अच्छे निकले। आयात व निर्यात, दोनों ही में खूब बढ़ोतरी हुई तथा देश समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ने लगा।

हसकिंसन द्वारा आरम्भ किये गये काम को पूरा करने की जिम्मेदारी ग्लेडस्टन (Gladstone) पर पड़ी जिसने, जब वह 1853 में वित्तमन्त्री बना, 120 वस्तुओं पर सीमा शुल्क हटा दिया तथा अन्य 140 वस्तुओं पर सीमा शुल्क कम कर दिया। 1860 में उसने फ्रांस के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किये तथा सीमा शुल्क वाले आयातों की कुल संख्या मात्र 48 कर दी। इस तरह अब रेशम, ऊनी वस्त्रों तथा निर्मित वस्तुओं पर लगे हुए अंतिम सीमा शुल्क भी हट गये। इन सभी उपायों ने इंग्लैंड को एक स्वतन्त्र व्यापार वाला राष्ट्र बना दिया। 1875 तक इमारती लकड़ी, अनाज तथा चीनी पर लगे हुए तटकर भी उठा लिये गये। खाद्यान्नों को पूरी तरह से मुक्त कर दिया गया। अंतिम रूप से शुल्क वाली चीजों की संख्या घटकर 20 रह गई तथा 1914 तक यही स्थिति बनी रही।

(4) औद्योगिक कानूनों की समाप्ति—अनेक वर्षों तक श्रमिक वर्ग को देश की सामान्य समृद्धि में कोई हिस्सा नहीं मिला। इससे अनेक विचारकों के मस्तिष्क में चिन्ता की स्थिति पैदा हुई। इन विचारकों ने अनुभव किया कि इस असंतोषजनक स्थिति की जिम्मेदारी अहस्तक्षेप की नीति के अधूरे त्रिव्यन्वयन पर थी। उस बात को ध्यान में रखते हुए निम्न महत्वपूर्ण औद्योगिक कानूनों को रद्द किया गया—

(अ) संयोजन कानून (Combination Laws) को 1824-25 में निरस्त किया गया। इसने श्रमिकों को अपनी मजदूरी के लिए सौदेबाजी करने की छूट मिल गई। इन कानूनों के रद्द हो जाने से श्रमिकों को अपने संघ (Unions) बनाने का भी अधिकार मिल गया। 1875 में पारित श्रम संघ अधिनियम ने श्रमिकों को अपने व्यवसाय संघ (Trade Unions) बनाने की स्वतन्त्रता प्रदान कर दी।

(ब) एंतिजावेध के काल के औद्योगिक विधेयक 1756 में ही रद्द किये जा चुके थे।

(स) प्रवास (emigration) पर लगी हुई रोक को भी 1825 में हटा लिया गया। उसी वर्ष मशीनों के आयात पर लगी हुई रोक को भी उठा लिया गया।

(द) भत्ता व्यवस्था (allowance system) को भी 1834 में समाप्त कर दिया गया।

(5) न्यूनतम हस्तक्षेप की उपनिवेश नीति—अमरीका में 13 उपनिवेशों में हुए विशाल ने इंग्लैंड को अपनी औपनिवेशिक नीति पर पुनर्विचार करने के लिए बाध्य कर दिया। श्रमिकवादी विचारक इन उपनिवेशों को बहुत ही निम्न स्तर देते थे तथा

उनका अधिकतम शोषण करना चाहते थे। इन उपनिवेशों की रक्षा करना भी काफी खर्चीला काम था। 1807 में गुलामों का व्यापार समाप्त कर दिये जाने से भी इस व्यवसाय में लगे हुए ब्रिटिश व्यापारियों को बड़ा धक्का लगा। उपनिवेश दायित्व (liabilities) बन गये तथा 1783 से लेकर 1870 तक की अवधि में वेतन लोगो द्वारा बसी हुई औपनिवेशिक बस्तियों के मामलों में कम से कम हस्तक्षेप का काल मानी जा सकती है।

स्वतन्त्र व्यापार के लिए सघर्ष काफी कड़ा व लम्बा था। सब कुछ सोचने विचारने के बाद यही बात उभरती है कि ब्रिटेन द्वारा स्वतन्त्र व्यापार की नीति अंगीकार कर लिया जाना आधुनिक आर्थिक व राजनीतिक इतिहास का एक आधार-भूत सर्वप्रमुख तथ्य है।¹ ब्रिटिश लोगो ने स्वतन्त्र व्यापार की नीति किसी प्रकार के प्रभाव में आ कर स्वीकार नहीं की थी। उन्होंने तो इसके पीछे छिपे हुए आर्थिक तर्कों का अनुभव कर लिया था। उन्होंने यह खोज लिया कि मजदूरी में उच्चावचन अनाज के मूल्यों के कारण नहीं आते जैसा कि बणिक्वादियों का विश्वास था। उन्होंने यह भी पाया कि खाने की चीजों पर सीमा शुल्क घटाने से बाजार में उनका अबार नहीं लगता और न ही उससे कृषि का कोई नुकसान होता है।

ब्रिटेन ने यह भी अनुभव कर लिया कि उसके निर्मित माल उत्पादों (manufactures) को किसी प्रकार के संरक्षण की आवश्यकता नहीं रह गई थी तथा उनकी कृषि भी अन्य देशों के साथ स्पर्धा कर सकती थी। अनेक विपरीत परिस्थितियों के दवावों के बावजूद देश ने यह भी अनुभव कर लिया कि वह एक उद्योग प्रधान राष्ट्र बन चुका है तथा इसके अतिरिक्त वह और कुछ भी नहीं बन सकता था। इस स्थिति से जो निष्कर्ष निकला वह यह था कि श्रमिकों का ऐसी स्थिति में लाया जाना चाहिये जहाँ वे खाने पीने की चीजें सस्ते दामों पर खरीद सकें। अनाज कानूनों के रद्द कर दिये जाने के बाद औद्योगिक संरक्षण को बनाये रखना भी संभव नहीं रह गया था। अन्तिम बात यह रही कि देश ने यह अनुभव कर लिया कि संरक्षण को समाप्त कर देने से आय में जो कमी हुई थी उसकी क्षति-पूर्ति मुक्त व्यापार के कारण हुए लाभ से हो चुकी थी।

उन्नीसवीं सदी का तृतीय चतुर्थांश ब्रिटिश कृषि, उद्योग तथा व्यवसाय के लिए स्वर्ण युग था। कैलिफोर्निया तथा आस्ट्रेलिया में सोने की खोज ने ऐसी आर्थिक तेजी की परिस्थितियाँ पैदा कर दी थी कि जिनमें व्यापार व उद्योग को प्रोत्साहन मिल रहा था। उद्योग की कुछ शाखाओं में तो लगभग ब्रिटेन का एकाधिकार था। जर्मनी का एकीकरण हो रहा था। फ्रांस नैपोलियन तृतीय के शासन में सैनिक सैन्या रियों में लगा हुआ था। रूस ने अपने कृषि दासों (Serfs) को मुक्त कर दिया था। तथा लिंकन के राष्ट्रपतित्व में अमरीका ने भी दासों को स्वतन्त्र कर दिया था। अमरीका में दासों को स्वतन्त्र कर देने से गृह युद्ध छिड़ गया था। ग्रेट ब्रिटेन इन सभी परिस्थितियों से लाभ उठा सकता था जिन्होंने उसके प्रतिद्वन्द्वियों का ध्यान बँटा रखा था उसने अपने उद्योग और व्यापार का सुदृढ़ निर्माण किया तथा दुनिया के हर हिस्से

में सम्बन्ध स्थापित किए। 1850-75 में आयी आर्थिक समृद्धि ने पहले से ही स्थापित इस विचारधारा की ओर पुष्टि कर दी कि सतत समृद्धि का रहस्य अहस्तक्षेप (laissez faire) के सिद्धान्तों के क्रियान्वयन में ही ढूँढा जा सकता था।

मुक्त व्यापार के विरोध में प्रतिक्रिया

कहावत है कि सफलता की तरह और कोई सफल नहीं होता। जब मुक्त व्यापार प्रचलित था तथा देश समृद्धि की ओर बढ़ रहा था तब सब कुछ ठीक था। किन्तु इस नीति ने अपना चरम बिन्दु उन्नीसवीं सदी के तृतीय चतुर्थांश में पा लिया था। लॉर्ड एशले (Lord Ashley) के नेतृत्व में कुछ मानवतावादी (humanitarians) साथ-साथ कुछ राजकीय हस्तक्षेप की मांग कर रहे थे। अनाज कानून (corn laws) रद्द किये जाने के 30 साल बाद तक मुक्तव्यापार नीतियाँ लोकप्रिय बनी रही। 1780 के बाद उनकी यह लोकप्रियता समाप्त हो गई तथा 1929 में अन्तिम रूप से उनका परित्याग कर दिये जाने से पहले अनेक वर्षों तक उनका बचाव तथा आलोचना की जाती रही। संरक्षणवाद के पुनरागमन के पीछे कई कारण थे

(1) मंदियों की श्रृंखला (Series of Depressions)—उन्नीसवीं सदी के तृतीय चतुर्थांश की समृद्धि के तुरन्त बाद मंदियों की एक लहर-सी आ गई। सबसे खराब प्रभाव 1873-86 की अवधि में अनुभव किये गये। यह पहली मंदी थी। ये मंदियाँ थोड़े थोड़े समय से फिर-फिर आती रही। ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को एक के बाद एक 1894, 1903 तथा 1929 में मंदी का सामना करना पड़ा। इस स्थिति ने लोगों का मुक्त व्यापार व राज्य के अहस्तक्षेप में विश्वास हिला दिया। कृषि तथा उद्योग दोनों ही को इन मंदियों का शिकार होना पड़ा था। 1869 में स्वेज नहर खुल जाने के बाद ब्रिटिश जहाजरानी को भी मंदी का शिकार होना पड़ा। भाड़े इस कदर गिर गये कि जहाज मामूली लाभ कमाने की हालत में भी नहीं रहे तथा कई पुराने जहाजों को कबाड़ियों के हाथों बेचना पड़ा। यूरोप तथा अमरीका से निरंतर बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा भी इन मंदियों के प्रमुख कारणों में से एक थी।

(2) अन्य देशों द्वारा संरक्षणवाद स्वीकार किया जाना—1879 में जर्मनी ने उच्च संरक्षणवादी नीति अपना ली तथा उसका अनुकरण कई और देशों ने भी कर लिया। अमरीका फ्रांस तथा अन्य यूरोपीय देशों ने भी कई संरक्षणवादी उपाय अपना लिये। यहाँ तक कि स्वशासित ब्रिटिश उपनिवेश (Self-governing British Colonies) भी अपने शिशु उद्योगों (infant industries) को संरक्षण प्रदान कर रहे थे। ये सभी उपाय ब्रिटिश व्यापार के लिए हानिकारक सिद्ध हो रहे थे।

(3) तकनीकी परिवर्तनों की भारी लागत—ब्रिटेन अब लोहे के उत्पादन में पहले की तरह एकाधिकारिक स्थिति में नहीं था। जब इस्पात बनाने के लिए बेसेमर प्रक्रिया (Bessemer process) खोज निकाला गया तो ब्रिटेन को भारी मात्रा में पुरानी मशीनों में लगी पूँजी को बेकार करना पड़ा। उसके प्रतिद्वन्द्वियों के सामने यह स्थिति नहीं आई क्योंकि उन्होंने पहले पूँजी लगा ही नहीं रखी थी। प्रत्येक

परिवर्तन के बाद ब्रिटेन अपने उद्योगों का पुनर्गठन भारी लागत लगा कर ही कर सकता था।

(4) अन्य देशों में राजकीय हस्तक्षेप व सरकारी सहायता—अनेक देशों में आर्थिक गतिविधियों को राजकीय सहायता दी जा रही थी और जो उनके लिए अच्छा था वह ब्रिटेन के लिए बुरा कैसे हो सकता था ? यह विचारधारा बलवती होती जा रही थी कि ब्रिटिश सरकार को अपने उद्योगों के लिए बही करना चाहिये जो जर्मन सरकार अपने उद्योगों के लिए कर रही थी।

(5) व्यापार असन्तुलन—1885-90 के दौरान यह अनुभव किया गया कि देश के आयात उसके निर्यातों के मुकाबले अधिक तेजी से बढ़ रहे थे। कई लोगों ने ऐसी तटकर नीति की आलोचना की कि जिससे आयातों को प्रोत्साहन मिल रहा था।

(6) कृषि मूल्यों में गिरावट—उत्तीसवीं शताब्दी के अन्तिम दो चतुर्थांशों में कृषि मूल्यों में गिरावट आई तथा कृषकों के मुनाफे भी घट गये। इसके निदान के लिए जो उपाय सुझाया गया वह यही था कि विदेशों से आयात किये जाने वाले कृषि पदार्थों पर प्रतिबन्धात्मक तटकर लगाये जाएँ।

(7) औद्योगिक तथा व्यावसायिक मुनाफों में कमी—1880 के बाद औद्योगिक तथा व्यावसायिक मुनाफे भी गिरने लगे। जिन लोगों को इसकी वजह से घाटा उठाना पड़ा उन्होंने यही सोचा कि संरक्षणवाद से कम से कम घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन तो मिल सकेगा।

(8) अधिक सरकारी हस्तक्षेप के लिए लोगों की मांग—फैक्ट्रियों के नियमन, अनिवार्य शिक्षा तथा नियोक्ताओं के दायित्व सम्बन्धी विधेयकों ने आम जनता को सामाजिक व आर्थिक नियमन का अभ्यस्त बना दिया था। इनके लाभ देखकर और अधिक राजकीय हस्तक्षेप की मांग की जाने लगी।

(9) मुक्त व्यापार वाला एकमात्र देश—सारे संसार में मुक्त व्यापार के प्रसार का युग कभी नहीं आया। फ्रांस तथा जर्मनी कुछ समय तक मुक्त व्यापार के प्रति झुके भी किन्तु उन्होंने भी इसे छोड़ दिया। अमरीका ने भी अपने तटकर (tariffs) बढ़ा दिये। ब्रिटेन अकेला छूट गया। व्यापार व तटकर पारस्परिक (reciprocal) बन गये जहाँ तटकरों का प्रयोग बढ़ने की कार्यवाही के लिए हथियारों के रूप में किया जाने लगा।

मुक्त व्यापार की अवनति

अन्य देशों में उद्योग तथा व्यापार का प्रसार वहाँ की सरकारों की मदद से हो रहा था। इस बात की जोरदार मांग की जाने लगी कि ब्रिटिश सरकार भी अपने व्यापारियों व निर्माताओं की सहायता के लिए आगे आये। इस मुक्त व्यापार की, धीरे-धीरे ही सही, अवनति होने लगी।

उपनिवेश सचिव जोसफ चेबरलेन ने 1903 में संपूर्ण गैर-ब्रिटिश विश्व के विरुद्ध वे तटकरों की दीवार (Tariff Wall) खड़ी करने तथा अधिमान्य व्यवस्था

(preferential system) कायम करने की जोरदार बकालत की। खानदान पर सीमा शुल्क लगाया गया तथा ब्रिटिश उद्योगों को विदेशी उद्योगों की अनुचित प्रतिस्पर्धा से बचाने के उद्देश्य से सीमा शुल्क आरोपित करने का प्रस्ताव किया गया। चेम्बरलेन के विचारों से लोग बहुत प्रभावित हुए। एक तटकर मुधार सघ गठित किया गया। सघ ने एक तटकर मुधार आयोग (Tariff Reform Commission) बनाया जिसमें चेम्बरलेन के प्रस्तावों को उचित ठहराया। किन्तु 1905 में अनुदार दल की सरकार की पराजय से लेकर 1914 तक उदारवादी सरकार ने सरक्षण के लिए कोई उपाय नहीं किये।

मुक्त व्यापार का परित्याग सर्वाधिक स्पष्ट रूप से ब्रिटन के उसके साम्राज्य के प्रति दृष्टिकोण में देखा जा सकता था। पुरानी औपनिवेशिक प्रणाली पर अमरीकी उपनिवेश खो देने का कलक लग चुका था। जब 1895 में जोसफ चेम्बरलेन (Joseph Chamberlain) उपनिवेश सचिव बना तो उसने लोगों का सलाह दी कि 'साम्राज्यवादी तरीके से सोचें' (think imperially)। उस समय ब्रिटिश साम्राज्य में दो प्रकार के देश सम्मिलित थे

(अ) मैत्री पर आधारित साम्राज्य (Empire in Alliance) जिसमें कि स्वशासी स्वतन्त्र उपनिवेश (Self governing Dominions) सम्मिलित थे तथा जहाँ स्वतः लोगों का निवास था। इनमें कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि देश शामिल थे जहाँ 1875 से पहले ही जिम्मेदार सरकारों का गठन किया जा चुका था। इन देशों के साथ निश्चित आर्थिक व राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित करने के उद्देश्य से कई बैठकें (conferences) की गईं। ये बैठक 1887 से आरम्भ हुईं तथा इनमें पाया गया कि यद्यपि इन स्वशासी स्वतन्त्र उपनिवेशों के साथ राजनीतिक एकीकरण सम्भव नहीं है किन्तु इनके साथ निकट के आर्थिक सम्बन्ध स्थापित किये जा सकते हैं। एक ही तरह के डाक टिकट जारी करके तथा साम्राज्यीय प्रसारण सेवा (imperial broadcasting) स्थापित करके सदेशवाहन के साधनों में सुधार किया गया। 1908 में इन स्वतन्त्र उपनिवेशों (dominions) में शाही व्यापार आयुक्त (Imperial Trade Commissioners) नियुक्त किये गए। अन्तर-साम्राज्यीय व्यापार में अधिमान्य तटकर (Preferential Tariffs) शुरू करने के प्रयास भी किये गये। 1897 में कनाडा द्वारा ब्रिटन को कुछ अधिमान स्वीकृत किये गये।

1914-18 के दौरान हुए प्रथम महायुद्ध में ब्रिटन ने अपनी कड़ी स्वतन्त्र व्यापार नीति त्याग दी। सीमा शुल्क, जिन्हें मैकेना (McKenna) शुल्क कहा गया, अनेक आयात की जाने वाली वस्तुओं पर लगाये गये। अगर ये चीजें उपनिवेशों से आती तो उन पर छूट देने की व्यवस्था की गई। 1931 में ब्रिटन ने पुनः सरक्षण की नीति अंगीकार कर ली। 1932 में ओटावा (Ottawa) में हुई शाही आर्थिक बैठक (imperial economic conference) में उपनिवेशों की वस्तुओं पर अधिमान का पैमाना तय किया गया।

(ब) न्यासपरक साम्राज्य (Empire in Trust) में उष्ण कटिबंधीय राष्ट्र सम्मिलित थे जो ब्रिटन को खाद्य पदार्थ व कच्चा माल भेजते थे तथा उससे निर्मित

माल मगवाते थे। इन देशों के साथ भी मुक्त व्यापार की नीति का परित्याग कर दिया गया क्योंकि इनके विकास में काफी सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता थी। स्वास्थ्य की दशाओं में तथा कृषि में सुधार किया गया। रेलों के लिए वित्तीय साधन जुटाए गये।

मुक्त व्यापार की अवनति के वर्षों में राज्य के हस्तक्षेप के कई स्वरूप रहे :

(1) श्रमिकों की स्थिति में सुधार के लिए राज्य द्वारा हस्तक्षेप—पैक्टरी में कानूनों का कार्यक्षेत्र बढ़ाया गया तथा उन्हें सिलसिलेवार (codified) बनाया गया। दुकानों के घण्टे तथा जल्दी काम बंद करने सम्बन्धी कानून पारित किये गये। 1909 में श्रमिकों के शोषण की प्रथा का उन्मूलन करने के लिए न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण करने हेतु व्यापार सचो (Trade Boards) की स्थापना की गई। 1918 में इस व्यवस्था को और आगे बढ़ाया गया। 1896 में औद्योगिक दुर्घटनाओं का शिकार हो जाने वाले श्रमिकों की क्षतिपूर्ति से सम्बन्धित कानून पारित किया जा चुका था। 1900 में वृद्धावस्था पेंशन चालू की गई तथा राष्ट्रीय बीमा योजना (National Insurance Scheme) 1911 में स्वीकार की गई।

औद्योगिक विवादों का निपटारा करने के लिए अनेक प्रावधान किये गये। मध्यस्थता विधेयक 1896 में पारित हुआ तथा पंच फैसला कचहरीयाँ (arbitration courts) 1908 में स्थापित की गईं। युद्ध के वर्षों में अनिवार्य पंच फैसले (compulsory arbitration) की व्यवस्था लागू की गई। 1916 में व्हित्ले समितियाँ (Whitley Councils) बनाई गईं तथा 1919 के अधिनियम द्वारा औद्योगिक अदालतों का गठन किया गया। श्रमिकों की शिक्षा को राज्य का दायित्व करार दिया गया। ये सभी प्रावधान नहीं किये जा सकते थे यदि देश में सरकारी हस्तक्षेप न करने देने की नीति को पूर्ववत् जारी रखा जाता।

(2) कृषि को राजकीय सहायता—वस्तु निशानदेही विधेयक, 1887 (Merchandise Marks Act, 1887) ने मूल उत्पादक देश के लिए उसकी अपनी वस्तुओं पर किसी तरह का निशान या मार्क लगाना आवश्यक कर दिया था ताकि उसकी चीजों को विदेशी वस्तुओं बताने में न बेचा जा सके। ट्रेड मार्क की नकल करने पर रोक लगा दी गई। पेटेंट कानून, 1907 (Patent Act 1907) में पारित किया गया ताकि ब्रिटिश पेटेंट को आड में उन्हीं चीजों का विदेशों में उत्पादन रोका जा सकता। व्यापार बोर्ड (Board of Trade) ने एक पत्रिका का प्रकाशन आरम्भ कर दिया। विदेशी व्यापार के लिए एक अलग विभाग कायम किया गया।

1930 की महान मदी ने औद्योगिक तथा व्यावसायिक गतिविधियों में राजकीय हस्तक्षेप को और भी अनिवार्य बना दिया। मुक्त व्यापार का पूरी तरह परित्याग कर दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ता राजकीय नियन्त्रण लगभग आधिक गति-विधियों के प्रत्येक पहलू पर लगा हुआ था।

3. महायुद्ध के बाद संरक्षणवाद

प्रथम विश्व युद्ध ने पहले से चली आ रही मुक्त व्यापार नीति में एक निश्चित

परिवर्तन किया था। 1915 में मैकेना शुल्क (McKenna Duties) के अन्तर्गत कारो, फिल्मों तथा घड़ियों के आयात पर सीमा शुल्क लगाया जाना मुक्त व्यापार से पहला प्रस्थान था। 1921 के औद्योगिक सुरक्षा अधिनियम ने इस सरक्षण को आधारभूत उद्योगों तक और बढ़ा दिया। इस विधेयक के अन्तर्गत 6000 वस्तुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाये गये तथा विदेशी वस्तुओं के राशिपातन (dumping) पर रोक लगा दी गई। यंगसन (Youngson) का कहना है कि '1920 के आस पास सरक्षण का कुल आकार तो छोटा था किन्तु तटकर व्यवस्था अधिकाधिक सरक्षणवादी बनती जा रही थी।' 1920-30 की अवधि में सरक्षणवाद को चुनावी मुद्दा बनाया गया। अनुदार दल की पराजय हुई तथा 1931 में एक अत्यधिक सरक्षणवादी सरकार सत्ता में आई। इस घटना के तुरन्त बाद अनेक सरक्षणवादी कानून पारित किये गये। 1931 व 1932 के सीमा शुल्क कानूनों (Customs Duties Acts) ने कुछ वस्तुओं के आयात पर 100 प्रतिशत आयात कर लगा दिये। 1932 के आयात कर कानून ने सभी विदेशी वस्तुओं पर 10 प्रतिशत कर समान रूप से लगा दिया। इस बीच 1932 में ओटावा में राष्ट्र-कुल के देशों की एक बैठक हुई जिसमें ब्रिटेन ने इन देशों में तटकर रहित वस्तुएँ आने देने की बात स्वीकार की। बदले में राष्ट्र-कुल के देशों (Commonwealth Countries) ने सूती वस्त्र तथा रसायनों जैसी ब्रिटिश वस्तुओं को विशेष अधिमान देने की बात स्वीकार की।

महान् मदी के बाद स्वर्णमान का परित्याग कर दिया गया जिसने ब्रिटेन को अधिक मुक्त बनाया। 1938 में अमरीका के साथ द्विपक्षीय समझौते किये गये। किन्तु फ्रांस अभी भी ब्रिटिश वस्तुओं के साथ भेद-भाव की नीति अपना रहा था इसलिए बदले की कार्यवाही के तौर पर कुछ फ्रांसीसी वस्तुओं पर 20 प्रतिशत सीमा शुल्क लगाया गया।

द्वितीय विश्व-युद्ध ने व्यापक एवं कड़े नियंत्रणों को अनिवार्य बना दिया। हमने अलावा ब्रिटिश व्यापार मित्र तथा तटस्थ राष्ट्रों तक सीमित था। युद्ध के बाद देश को घाटों का सामना करना पड़ा। उसके विनियोग घट गये तथा उसका व्यापार समुलन विपरीत हो गया।

'तटकर एवं व्यापार पर सामान्य सहमति' (GATT) का निर्माण अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी। इसका उद्देश्य बहुपक्षीय व्यापार समझौते को बढ़ावा देना तथा तटकरों में कमी लाना था। 'गाट' (GATT) में ब्रिटेन की सदस्यता होने में उसे अपने सीमा शुल्क कुछ घटाने पड़े किन्तु उसे राष्ट्रकुल अधिमान (Commonwealth preferences) बनाये रखने की अनुमति दे दी गई।

द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद की एक अन्य महत्वपूर्ण घटना अनेक व्यवस्थाओं द्वारा यूरोप में स्वतन्त्र व्यापार की स्थापना के प्रयास रहे हैं। यूरोपीय सहयोग सघ (O E C D) की 1948 में स्थापना तथा 1952 में कोयला व इस्पात समुदाय (E C S C) की स्थापना इसी दिशा में कुछ कदम थे। इंग्लैंड ने यूरोप में एक स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र की स्थापना का भी समर्थन किया। 1959 में 6 देशों (बेल्जियम, फ्रान्स, प० जर्मनी, इटली, लक्जमबर्ग व नीदरलैंड्स) ने मिलकर यूरोपीय साझा

बाजार (E C M) की स्थापना की। ब्रिटेन फ्रांस के विरोध तथा देश में ही कुछ लोगों के विरोध के कारण काफी वर्षों तक इस समस्या का मदस्य नहीं बन पाया। किन्तु 1970 के दशक में एक जनमत संग्रह द्वारा ब्रिटेन के लोगों ने अपने देश को यूरोपीय साझा बाजार का सदस्य बना दिया।

दूसरे महायुद्ध के बाद ब्रिटेन ने अपने तटकरो में अनेक कठौतियाँ की हैं। यूरोप के साथ स्वतन्त्र व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1957 व 1958 में दो महत्वपूर्ण विधेयक पारित किये गये 1968, 1971, 1972 व 1978 में सीमा शुल्कों में और कमियाँ की गईं। यूरोपीय साझा बाजार का सदस्य बन जाने के बाद तटकर में भारी कठौतियाँ की गई हैं। एक बार फिर ब्रिटेन कम प्रतिबन्ध वाले व्यापार की दिशा में अग्रसर हो रहा है।

माराश में, विटिंग व्यावसायिक नीति तीन सुस्पष्ट चरणों से गुजरी है।

- (i) वणिक्वादियों का राजकीय नियन्त्रण वाला चरण, (ii) उन्नीसवीं सदी व बीसवीं सदी के आरम्भिक वर्षों का अहस्तक्षेप की नीति (*laissez faire*) वाला काल, तथा (iii) युद्ध के बाद बहुपक्षीय व्यावसायिक समझौतों व तटकरो में कठौतियों का काल। इस तरह पहिया पूरा चक्र घूम चुका है।

या समूह (combinations) आदि बनाए जाने के विरुद्ध था। इन समूहों को जनता के खिलाफ पड़्यन्त्र माना जाता था तथा इन पर फौजदारी कार्यवाही की जाती थी। व्यक्तिगत रूप से श्रमिक अधिक मजदूरी की मांग कर सकते थे या काम करने से इनकार भी कर सकते थे लेकिन यदि वे इन उद्देश्यों के लिए संगठित होकर काम करते तो उन पर जुर्माना किया जा सकता था या उन्हें जेल भेजा जा सकता था। इंगलिश कॉमन लॉ (English Common Law) के अतिरिक्त, जिसमें श्रमिकों के समूह (worker's combinations) गैर कानूनी करार दिये गये थे, कई ऐसे कानून और भी थे जिन्हें श्रमिकों के खिलाफ, उनके द्वारा सघ बनाने की चेष्टा करने पर प्रयुक्त किया जा सकता था। ये कानून श्रमिकों द्वारा राजनीतिक संगठन बनाने या कोई आन्दोलन करने के विरुद्ध बने हुए थे। कुल मिलाकर लगभग 35 ऐसे समदीय कानून थे जिनका उद्देश्य श्रमिकों को संगठित होने से रोकना था। अठारहवीं शताब्दी के अन्तिम वर्षों में इन कानूनों में कुछ सख्त कानून और जोड़े गये।

किन्तु इन कड़े कानूनों की प्रतिक्रिया स्वल्प ही कुछ गुप्त श्रम संगठन प्रस्फुटित हो गए जिनमें ससद को काफी भय लगने लगा। 1799 में ससद ने श्रमिकों द्वारा गैरकानूनी रूप से संगठित होने को रोकने के लिए एक कानून (An Act to prevent Unlawful Combinations of Workmen) बनाया। 1801 में कुछ अतिरिक्त प्रावधान जोड़कर इस कानून को और भी कड़ा बना दिया गया। मजदूरी में वृद्धि की मांग करने के लिए संगठित होने वाले श्रमिकों को सपरिश्रम कारावास की सजा दी जा सकती थी।

उत्तीसवीं शताब्दी के पहले दो दशकों में निम्न चार बातें श्रमिकों के लिए दण्डनीय अपराध थीं

(i) एक निश्चित मजदूरी पर ही काम के लिए तैयार होना या कुछ निश्चित घंटों या समयों पर ही काम के लिए राजी होना।

(ii) मजदूरी बढ़ाने काम के घंटों में फेरबदल करवाने या काम की मात्रा घटाने के उद्देश्य से कोई भी संगठन बनाना।

(iii) किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट निर्माता के यहाँ काम करने के लिए राजी करना या उसके यहाँ से नौकरी छुड़वाना।

(iv) मजदूरी, काम के घंटे आदि के बारे में अनुबन्ध करने की दृष्टि से आयोजित की जाने वाली किसी भी सभा में भाग लेना या उसे अपना समर्थन देना।

1349 व 1562 के जो श्रम कानून (labour statutes) अभी तक कायम थे उनमें न केवल श्रमिकों को किसी भी प्रकार का संगठन बनाने से रोका गया था बल्कि उन्हें स्थानीय न्यायाधीशों (local justices) द्वारा निर्धारित की गई मजदूरी से अधिक मजदूरी स्वीकार करने की भी मनाही की गई थी और ये स्थानीय न्यायाधीश आमतौर पर मालिक लोग ही होते थे जो श्रमिकों को काम देते थे।

अन्धकार भरा युग 1800-1824

1799 में लेकर 1824 तक संगठित श्रम सघवाद (organised trade

unionism) गैर कानूनी था। इस रोक के पीछे मुख्य कारण राजनीतिक था। इतना ही नहीं, श्रम सघ स्वयं श्रमिकों के लिए हानिप्रद समझे जाते थे। यह माना जाता था कि मजदूरी कोष (wages fund) तो बँधा-बँधाया (fixed) होता है और उसी निश्चित रकम में से मजदूरी दी जाती है। इसलिए यदि एक समूह अपने लिए अधिक मजदूरी पाने में सफल हो जाना है तो अन्य मजदूरों को मिलने वाली मजदूरी घट जाती है।

इस अवधि में श्रमिकों ने समूह कानून (combination laws) को रद्द कराने के लिए विशेष आन्दोलन भी नहीं किये। इसके पीछे कई कारण थे (i) श्रमिक इतने अशिक्षित और अज्ञानी थे कि वे संगठित होने से मिलने वाले लाभों को अनुभव नहीं कर सकते थे। (ii) उनकी मजदूरी इतनी कम थी कि वे चढ़ा दे पाने की स्थिति में नहीं थे। और (iii) श्रमिक इतने अनजान थे कि उन्हें यह भी मालूम नहीं था कि उन्हीं के जैसे लोग अन्य औद्योगिक शहरों में जिल्लत की जिन्दगी जी रहे हैं।

श्रम समूहों (Labour Combinations) के लिए विधेयक 1824-25

ये सारे श्रम विरोधी कानून, जिनका उल्लेख ऊपर हुआ है, 1831 तक सक्रिय रहे। इनमें से कुछ 1867 तक भी चलते रहे और इनमें से सभी कानूनों को तो 1875 तक ही रद्द किया जा सका। किन्तु इन श्रम सघ विरोधी कानूनों (anti-labour combination laws) को 1824 में काफी नरम बना दिया गया। नैपोलियन के साथ हुए युद्धों की समाप्ति के बाद देश में काफी औद्योगिक अशान्ति फैल गई थी तथा श्रम सघ विरोधी कानूनों को रद्द करवाने के लिए कुछ प्रदर्शन आदि भी किये गये। अनेक गुप्त संगठन भी गठित किये गये।

1824 में नियुक्त की गई एक ससदीय समिति ने पाया कि (i) देश में श्रमिकों के अनेक समूह (combinations) विद्यमान थे तथा इस बावत बने हुए कानून प्रभावहीन सिद्ध हुए थे, (ii) हड़तालें काफी संख्या में हो रही थी जो मालिकों व मजदूरों के लिए समान रूप से मँहगी थी, (iii) मालिकों ने भी मजदूरी घटाने के उद्देश्य से गैर कानूनी संगठन बना रखे थे, (iv) जहाँ कानूनों की अवज्ञा करने पर श्रमिकों को दण्ड मिलता था वहाँ मालिक लोग बिना दण्ड के ही छूट रहे थे।

इस ससदीय समिति ने सिफारिश की कि (i) उन सभी कानूनों को, जो मालिकों तथा मजदूरों को मजदूरी की सौदेबाजी तथा शान्तिपूर्ण तरीके से सभाएँ करने पर रोक लगाते हैं, रद्द कर दिया जाना चाहिए, (ii) औद्योगिक विवादों का निपटारा पंच फॉर्मले (arbitration) द्वारा होना चाहिए, (iii) मालिक या मजदूर लोग, पारस्परिक समझौता करने की पूर्ण स्वतन्त्रता के उपरान्त यदि हिंसा या धमकियों का आश्रय लें तो उन्हें कानून द्वारा दण्डित किया जाना चाहिये।

इन सिफारिशों की रोशनी में जून 1824 में ब्रिटिश संसद ने श्रमिकों के संगठन के खिलाफ तथा उनसे सम्बन्धित बने हुए अनेक अन्य कानूनों को रद्द कर दिया। पिछले 500 वर्षों के दौरान बने 34 कानूनों को निरस्त (repeal) कर दिया गया। श्रमिकों द्वारा अपनी मजदूरी बढ़वाने काम के घंटे कम करवाने या काम की

मात्रा में कमी करवाने के उद्देश्य से शान्तिपूर्ण तरीके से व स्वेच्छापूर्वक बनाये गये समूहों (combinations) को वैधानिक करार दे दिया गया। इस कानून में मालिकों को अत्यधिक भय लगा तथा उन्होंने इस नये कानून को रद्द करने के लिए आवाज उठायी। 1825 में बनायी गयी एक हाउस ऑफ कॉमन्स की समिति ने 1824 में बनाये गये इस कानून को रद्द करने तथा इसके स्थान पर कम क्रान्तिकारी (radical) उपाय करने की सिफारिश की। इस तरह 1825 में पारित सशोधित कानून में इंग्लिश कॉमन लॉ (English Common Law) में मौजूद श्रम सघ विरोधी प्रावधानों (anti-labour combination provisions) को बरकरार रखते हुए श्रमिकों द्वारा शान्तिपूर्ण तरीके से सभाएँ करने व संगठित होने की अनुमति प्रदान की गई।

अनिश्चितता का काल 1825-45

1825 के विधेयक के पारित हो जाने के साथ ही ब्रिटिश श्रम सघ के इतिहास का निर्माणात्मक काल (formative period) समाप्त हो गया। 1825 के विधेयक के प्रावधान 1875 तक सकार्यशील रहे। इस सम्पूर्ण अवधि में श्रम सघ गैर कानूनी बने रहे यद्यपि उन्हें अपराधी संगठन नहीं माना गया। शान्तिपूर्वक मिलते रहने के श्रमिकों के अधिकार की तो गारण्टी दी गई किन्तु कॉमन ला में अभी भी श्रम सघों को पड़्यन्वकारी माना जाता रहा। श्रमिकों को सामान्यतः सजाएँ दी जाती रहीं।

किन्तु साथ ही 1825 के श्रम अधिनियम ने श्रमिक आन्दोलन को भारी गति प्रदान की। निम्नलिखित प्रमुख घटनाएँ घटित हुईं

- (i) श्रम सघों की संख्या में काफी वृद्धि हो गई।
- (ii) संगठन की स्वतन्त्रता से हड़तालों की लहर आ गई।
- (iii) एक राष्ट्रीय स्तर के श्रम संगठन का विचार जन्म लेने लगा।

श्रम सघों के सघ (federations) बनाये जाने लगे। 1829 में एक नेशनल यूनियन ऑफ कॉटन स्पिनर्स गठित की गई। 1830 में श्रमिकों की सुरक्षा के लिए एक राष्ट्रीय सघ (National Association for the Protection of Labour) बनाया गया जिसमें 150 यूनियनों शामिल हुईं। अन्त में, 1834 में एक जनरल ट्रेड्स यूनियन का निर्माण किया गया जिसे बाद में महान् पुनर्गठित राष्ट्रीय श्रम सघ (Grand Consolidated National Trades Union) का नाम दिया गया। यह कोई शुल्क नहीं लेती थी तथा इसकी सदस्य संख्या 5 लाख के लगभग थी। इस संगठन ने आठ घण्टों के कार्य दिवस के प्रश्न पर एक दशवर्षीय हड़ताल वा आहि्यान किया किन्तु वह असफल रही तथा अनेक श्रमिकों को दण्डित किया गया। इस असफलता ने श्रमिकों का ध्यान उस समय चल रहे अन्य सामाजिक एवं राजनीतिक आन्दोलनों जैसे चार्टिज्म (Chartism) तथा ओवेन (Owen) के सहकारवाद की तरफ मोड़ा।

ब्रिटिश श्रम सघवाद का प्रसार 1845-75

इस अवधि में श्रम सघों की संख्या व सदस्यता की दृष्टि से काफी विकास हुआ। विविध व्यवसायों में श्रम सघों के राष्ट्रीय स्तर पर सघ बनाने की प्रवृत्ति

अधिक सामान्य बनती चली गई। श्रमिक लोग अधिक व्यावहारिकतावादी बन गए। आदर्शवादी चार्टिस्ट आन्दोलन विघटित हो गया तथा पुनः एक बार श्रम सघवाद का अभूतपूर्व विकास होने लगा। अनेको नये सगठन बने तथा श्रमिकों व यूनियनों द्वारा सघ बनाने की स्वतन्त्रता को प्रतिबन्धित करने वाले सभी कानूनों को रद्द करवाने में सफलता मिली।

ताल्लुका (county), मभागीय (sectional) तथा राष्ट्रीय स्तर पर अलग-अलग निकायो (bodies) के निर्माण हो जाने से यूनियनों के सगठनात्मक ढाँचे में भी व्यापक सुधार हुआ। इस अवधि के प्रमुख संघों (federations) में 1841 का खनिक सघ (Miners' Association, 1841), अमलगमेटेड सोमायटी ऑफ इंजीनियर्स (Amalgamated Society of Engineers), 1850 व नेशनल यूनियन ऑफ बूट एण्ड शू ऑपरेटिवज (National Union of Boot and Shoe Operatives), 1874 प्रमुख थे। तत्कालीन संघों के अधिकारों का अतिक्रमण न करते हुए 1845 में लन्दन में एक श्रमिकों के हित रक्षार्थ समुक्त व्यवसायों के राष्ट्रीय सघ (National Association of United Trades for the Protection of Labour) की भी स्थापना की गई जो पन्द्रह वर्ष चला।

इस अवधि के श्रम सघवाद के सगठनात्मक ढाँचे का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी रहा कि इस काल में श्रम समितियाँ (Trade Councils) भी गठित की गयीं। ये समितियाँ एक ही शहर में एक विशिष्ट यूनियन की ममस्त शाखाओं का प्रतिनिधित्व करती थीं। इन समितियों ने श्रमिकों के हित सबद्धन की दिशा में अच्छा कार्य किया तथा संसद में उदार श्रम कानूनों के पारित किये जाने के लिए पृष्ठभूमि तैयार की। पहली राष्ट्रीय श्रम संघ कांग्रेस (National Trade Union Congress) 1864 में आयोजित हुई। यह प्रथा इतनी सफल रही कि इसे वार्षिक घटना बना दिया गया तथा इसे श्रमिकों की ब्रिटिश संसद के नाम से जाना जाने लगा।

उदार श्रम सघ कानून - 1871-76

ब्रिटिश श्रम सघवाद के दूसरे चरण में बाकी बचे हुए श्रम सघ विरोधी कानूनों को समाप्त कर दिया गया। यह सब 1866-76 के दौरान किये गये लम्बे व उग्र प्रदर्शनों तथा हड़तालों के बाद हुआ। 1867 में एक संसदीय आयोग गठित किया गया। आयोग ही अध्ययन व सुझावों के लिए यूनियनों को ही दोषी नहीं ठहराया यद्यपि उसका प्रतिवेदन यूनियनों के पक्ष में नहीं था। इस आयोग ने यूनियनों के पञ्जीकरण की सिफारिश की ताकि उनके पास जमा विशाल राशि को सुरक्षित बनाया जा सके।

संसदीय आयोग की इस रिपोर्ट को आधार बना कर तीन प्रमुख कानून पारित किये गए (i) 1871 का श्रम सघ कानून (Trade Union Act of 1871), (ii) पड़यंत्र एवं सम्पत्ति सुरक्षा कानून 1875 (Conspiracy and Protection of Property Act of 1875), तथा (iii) 1876 का श्रम सघ कानून। इस व्यापक श्रम सघ विधान ने अग्रकित मुख्य परिवर्तनों की आधारशिला रखी :

(1) श्रम संध की परिभाषा की गई—श्रम की परिभाषा करते हुये उसे 'ऐसी कोई भी सस्था या समूह (combination), चाहे वह स्थायी हो या अस्थायी, माना गया जो मालिकों एवं मजदूरों के बीच सम्बन्धों का नियमन करता हो।'

(2) पंजीकरण के लिए नियम—कोई भी सात या उससे अधिक लोग मिल कर श्रम संध पंजीकृत करवा सकते थे तथा कानून द्वारा प्रत्याभूत विशेषाधिकार प्राप्त कर सकते थे।

(3) गैर-कानूनी नहीं—श्रम संधों के उद्देश्यों को अब गैर कानूनी नहीं माना गया तथा उन पर फौजदारी मुकदमे नहीं चलाये जा सकते थे।

(4) सम्पत्ति रखने का अधिकार—यूनियनों को चढ़ा इक्ठ्ठा करने व सम्पत्ति रखने का पूरा अधिकार प्रदान किया गया।

(5) अनुबन्ध तोड़ने पर सजा या जुर्माना—दुर्भावना से प्रेरित हो कर श्रम अनुबन्ध तोड़ने पर 20 पौंड जुर्माना या 3 माह की कैद का प्रावधान किया गया।

असाधारण प्रगति का काल 1876-1905

1871 के बाद यूनियनों की संख्या व सदस्यता में असाधारण रूप से वृद्धि हुई। प्रतिबन्धों में डील तथा सामान्य समृद्धि ने इस विकास में अपना योगदान दिया। 1874 में इंग्लैंड में श्रम संधों की कुल सदस्यता 11 लाख थी। 1875-80 में मंदी छा जाने तथा कुछ हड़तालों के असफल हो जाने से देश में यूनियनों की सदस्य संख्या में कुछ गिरावट आयी। श्रम संधवाद में पुन प्रगति 1890 से 1900 के बीच हुई।

बीसवीं शताब्दी के आरम्भ से ही श्रमसंधवाद का विकास हुआ। 1899 में यूनियनों का एक संध बनाया जा चुका था। श्रम संधों की सदस्यता बढ़ कर 23 लाख हो चुकी थी। इस अवधि में दिये गये दो न्यायिक फैसले यूनियनों के लिए प्रतिकूल रहे। पहला मामला टेफ वैल (Taff-Vale Case) का था जिसमें रेल कर्मचारी संध (Railway Servants Society) पर हाऊस ऑफ लाड्स द्वारा क्षतिपूर्ति के रूप में 23,000 पौंड का जुर्माना किया गया। श्रम संधों के लिए एक गहरा धक्का था क्योंकि वे तो कानूनी निरापदता (immunity) के भरोसे बँठी हुई थी। श्रमिकों द्वारा इस फैसले की घोर निन्दा की गई।

हड़तालों की एक लहर सी आ गयी तथा सरकार को एक शाही आयोग नियुक्त करना पड़ा। लेकिन आयोग ने टेफ वैल निर्णय (Taff Vale Decision) में बनाये गये नियमों में डील देने का कोई प्रस्ताव नहीं किया। 1905 में उदार दल (Liberal Party) की सरकार बनने के बाद पुन एक बार यूनियनों के दायित्व को क्षति-पूर्ति देने के सम्बन्ध में सीमित करने के प्रयास किये गये, विशेष रूप से उन मामलों में जहाँ कोई भी काम यूनियन की कार्यकारिणी द्वारा अधिकृत किया जा चुका हो। 1906 में पारित किये गये श्रम संध तथा श्रम विवाद विधेयक (Trade Unions and Trade Disputes Act, 1906) ने अदालतों को श्रम संधों के विरुद्ध हानि या अन्याय (torts) के मामलों पर विचार करने से रोक दिया।

1906 के इस कानून ने शांतिपूर्ण तरीके से धरना देना (picketing) भी वैध माना ।

श्रम सघ कानून (Trade Union Act) 1913

श्रम सघवाद पर दूसरी चोट उसकी राजनीतिक गतिविधियों के कारण लगी । श्रम सघों द्वारा ऐसे ससद सदस्यों को वेतन या भत्ता देने की प्रथा बन गयी थी जो ससद में लेबर दल के कार्यक्रमों का समर्थन करते थे । इस काम के लिए श्रम सघ अपने सदस्यों से चन्दा लेते थे । श्रम सघों के इस अधिकार को चुनौती दी एक कुली (porter) वाल्टर ओसबोर्न (Walter Osborne) ने जो अमलगमेटेड मोसाइटी ऑफ रेलवे सर्वेन्ट्स का सदस्य था । उसकी बात को अदालतों ने स्वीकार लिया । ओसबोर्न निर्णय (Osborne Judgement) के पीछे जो तर्क दिया गया वह यह था कि श्रम सघों को इस बात का कोई अधिकार नहीं है कि वे अपने सदस्यों से इसलिए चन्दा उठाए कि वे ससद सदस्यों को भत्ता देते हैं । अदालत ने श्रम सघ के कोषों का इस कार्य के लिए उपयोग करने पर भी रोक लगा दी ।

न्यायालय के इस निर्णय पर प्रहार किये गये तथा इसको रद्द करने के लिए (reversal) आन्दोलन भड़क उठे । इस स्थिति में कुछ परिवर्तन तब आया जब एक उपाय करके हाउस ऑफ कॉमन्स के सभी गैर सरकारी सदस्यों (non-official members) को 400 पौण्ड वार्षिक का वेतन देने की स्वीकृति दे दी गयी (पहले श्रम सघ उसके समर्थक ससद सदस्यों को इसीलिए वेतन आदि देते थे क्योंकि कोई तनख्वाह या भत्ता नहीं मिलता था और न ही वे इतने सम्पन्न थे) ।

किन्तु ओसबोर्न निर्णय के विरुद्ध आन्दोलन फिर भी जारी रहे । 1913 में एक नया विधेयक लाया गया । 1913 के इन श्रम सघ अधिनियम में दो नई बातें थी (i) इसने श्रम सघ की पुनः परिभाषा की तथा उसे ऐमा समूह (combination) माना जिसका उद्देश्य व्यवसाय का नियमन करना तथा अपने सदस्यों के लाभ का प्रावधान करना था । (ii) यूनियन के कोषों का उपयोग करने के बारे में नये नियम बनाये गये । ओसबोर्न निर्णय (Osborne judgement) ने यूनियनों द्वारा अपने कोषों का राजनीतिक व अन्य अनेक उद्देश्यों के लिए उपयोग करने पर रोक लगा ही दी थी ।

1913 के अधिनियम ने श्रम सघों को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति दे दी यदि बहुमत चाहे तो इस कार्य के लिए कोष भी एकत्रित किया जा सकता था । कोई भी व्यक्ति उस राजनीतिक कोष में चन्दा देने से इनकार कर सकता था जिसकी रकम अलग ही रखी जाती थी । किन्तु मजदूरों ने इसे अपनी आंशिक विजय ही माना तथा अपने सघों को जारी रखा । इस बीच 1914 तक श्रम सघों की सदस्य संख्या बढ़कर 36 लाख हो चुकी थी तथा ब्रिटिश श्रम सघों को दुनिया-भर में न केवल सबसे पुरानी बल्कि सबसे मुट्ठे यूनियन होने का गौरव भी प्राप्त हो चुका था ।

प्रथम विश्व-युद्ध और श्रम सघ

1914 में पाँच व्यवसायों में श्रम सघ सर्वाधिक मजबूत थे । (i) खाने,

(ii) धातु इजीनियरिंग व जहाज निर्माण, (iii) सूती वस्त्र उत्पादन, (iv) भवन निर्माण, तथा (v) रेल, गोदी व अन्य यातायात व्यवसाय। प्रथम महायुद्ध की पूर्व सन्ध्या पर श्रम सघों की कुल सदस्यता 42 लाख हो चुकी थी। लड़ाई छिड़ जाने पर एक औद्योगिक सन्धि (industrial truce) की गयी तथा श्रमिकों ने नियोक्ताओं के साथ सहयोग करने का आश्वासन दिया। श्रम सघों ने सरकार का भी साथ देने का फैसला किया तथा अपने कई नियमों को ढीला कर दिया।

युद्ध के कारण श्रमिकों की भारी कमी हो गयी क्योंकि अधिकांश मजदूर या तो युद्ध सामग्री के उत्पादन में लगा दिये गये या फिर उन्हें फौज में दाखिल कर लिया गया। समय की मांग यही थी कि सारे राष्ट्र की शक्ति को बटोर कर मुकाबला किया जाय। यौद्धिक मामलों विधेयक (Ammunitions of War Acts) 1915 में पारित किये गये जिनमें सरकार को उद्योगों पर नियन्त्रण करने का अधिकार मिला गया। हड़तालें तथा तालाबन्धियाँ गैर कानूनी घोषित कर दी गयीं। काम से अनुपस्थिति (absenteeism) को दण्डनीय बना दिया गया। औद्योगिक विवादों का निपटारा पंच फैमले द्वारा करना अनिवार्य हो गया। महिला श्रमिकों को प्रोत्साहित किया गया तथा उनका राष्ट्रीय सघ बनाया गया।

सरकार द्वारा घोषित इन कड़े उपायों के उपरान्त तथा श्रम सघों की गतिविधियों पर रोक लगा दिये जाने के उपरान्त 1916-17 में गम्भीर श्रम असन्तोष की स्थिति पैदा हुई। 1917 में औद्योगिक हड़तालों के कारण लगभग 55 लाख मानव दिवसों की हानि हुई। सरकार ने व्हीटले आयोग (Whitley Commission) भी नियुक्त किया किन्तु वह भी श्रमिकों को सन्तुष्ट कर पाने में असफल रहा।

इस दौरान श्रम सघों की सदस्यता में बराबर वृद्धि हो रही थी। 1919 में वह 85 लाख हो गयी। श्रम असन्तोष जारी रहा। एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गयी जिसमें सभी यूनियनों ने भाग लिया। यह बैठक इस निष्पत्ति पर पहुँची कि कार्य दिवस 8 घण्टे का होना चाहिए न्यूनतम मजदूरी कानून द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए तथा श्रम सघों को पूरी तरह मान्यता दी जानी चाहिए। किन्तु इस दिशा में कुछ विशेष प्रगति नहीं हो पाई जिससे श्रमिकों को शान्त नहीं किया जा सका। 1922 में लेबर दल (Labour Party) अधिकृत रूप में विरोधी दल बनी तथा 1924 में उसने सरकार बना ली।

युद्धों के बीच का काल तथा महान् मन्दी

प्रथम महायुद्ध समाप्त होने के बाद माँग में आने वाली गिरावट ने मन्दी आयी तथा उसके कारण भारी सरपा में लोग बेरोजगार हो गये। मालिक लोग मजदूरी घटाना चाहते थे किन्तु मजदूरी में इन कटौतियों का श्रमिकों ने विरोध किया जिसके फलस्वरूप हड़तालें व तालाबन्धियाँ हुईं। 1926 की राष्ट्र-व्यापी आम हड़ताल के बाद 1927 में एक श्रम सघ कानून (Trade Unions Act) पारित किया गया जिसमें उल्लेख किया गया कि (i) हड़तालें गैर-कानूनी मानी जायेंगी यदि

वे सरकार पर दबाव डालने के उद्देश्य से की जाती हैं। (ii) एक बार यदि हड़ताल को गैर जानूनी घोषित कर दिया जाता है तो श्रम सघ के कोषों को प्रदान की जाने वाली सुरक्षा समाप्त मानी जायेगी। (iii) नागरिक सेवा अधिकारी (civil servants) अन्य श्रम सघ संगठनों के साथ सम्बद्ध नहीं हो सकेंगे। तथा (iv) महाधिवक्ता की प्रार्थना पर न्यायालय श्रम सघों द्वारा उनके कोषों का उपयोग करने पर प्रतिबन्ध लगा सकेंगे। इस अन्तिम प्रावधान ने श्रम सघों को न्यायाधीशों की कृपा पर आश्रित कर दिया।

प्रथम महायुद्ध के बाद के ब्रिटिश श्रम सघवाद ने 1917 की रूसी क्रान्ति से भी प्रेरणा ली। अनेकों ब्रिटिश शहरों में हिंसात्मक श्रमिक आन्दोलन हुए तथा उन्हें दबाने के लिए सेना तैनात करनी पड़ी। युद्ध के वर्षों में सरकार ने रेलों तथा खानों को अपने नियन्त्रण में ले लिया था। श्रमिकों को युद्ध के वर्षों में अपना जीवन स्तर बनाये रखने के लिए कोनस (cost of living bonus) दिया गया था क्योंकि कीमतेँ बहुत चढ़ गयी थी। 1919 में रेल कर्मचारियों ने रहन सहन की जागत में अत्यधिक बढ़ोत्तरी हो जाने से राष्ट्रव्यापी हड़ताल कर दी। हड़ताल पूरे देश में रही। सरकार को कुछ माँगे माननी भी पड़ी किन्तु वह हड़ताल से अप्रसन्न ही रही।

युद्ध के दौरान रेलों, खानों तथा कुछ अन्य उद्योगों पर राजकीय नियन्त्रण लगा देने के बाद जब युद्ध समाप्त हुआ तो उनके राष्ट्रीयकरण की माँग की गयी। सरकार ने 1919 में एक शाही आयोग नियुक्त किया जिसने सिफारिश की कि खनिकों के काम के घण्टे कम किये जाएँ मजदूरी में 2 शिलिंग प्रतिदिन के हिसाब से वृद्धि की जाए तथा कोयला उद्योग का पूरा राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। सरकार द्वारा यह रिपोर्ट पूरी तरह नहीं मानी गयी जिसका परिणाम यह रहा कि ट्रेड यूनियन कांग्रेस (T U C) ने 1919 में एक बान्दोतन छेड़ दिया। उन्होंने खानों के राष्ट्रीयकरण की माँग की किन्तु यह आन्दोलन असफल रहा क्योंकि श्रमिक स्वयं आपस में विभाजित थे।

1922 में इजीप्टियों द्वारा की गयी एक हड़ताल भी असफल रही। 1926 की सारे देश में की गयी आम हड़ताल भी सफल नहीं रही तथा सरकार ने 1927 में एक श्रम सघ अधिनियम पारित कर दिया जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। 1926 की आम हड़ताल की असफलता, वेवारी में दिनोंदिन वृद्धि तथा मन्दी ने मिलकर श्रमिकों का मोड़ल गिरा दिया। 1936 में यूनियनों की सदस्य संख्या घटकर 50 लाख रह गयी। लेबर दल की सरकार जो 1929-31 की अवधि में सत्ता में आयी, 1927 के श्रम सघ कानून को रद्द करना चाहती थी किन्तु वैसा करने के लिए वह पर्याप्त समर्थन नहीं जुटा पायी।

द्वितीय विश्व-युद्ध के दौरान श्रम सघ 1939-45

सर बिस्टन चर्चिल के नेतृत्व में युद्ध के दौरान लिबरल, कंजरवेटिव व लेबर दल की एक मिली जुली सरकार बनायी गयी थी। उद्योग तथा श्रम को राष्ट्र के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया तथा उन्हें कड़े सरकारी नियन्त्रण में रखा गया।

श्रम सघो ने राष्ट्रीय रक्षा कार्यक्रमों में अपना पूरा सहयोग दिया। श्रम सघो ने इस अवधि में अपनी स्थिति को काफी सुगठित कर लिया। उनकी सदस्य संख्या 1939 में 62 लाख थी जो 1946 में बढ़कर 88 लाख हो गयी। इसी अवधि में अनेक यूनियनों ने आपस में विलय से यूनियनों की कुल संख्या 1019 से घटकर 757 रह गयी।

युद्ध के दौरान एक अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि यह रही कि सरकार ने श्रम सघो के महत्व को स्वीकार कर लिया। ब्रिटिश प्रधानमन्त्री द्वारा श्रमिकों से सम्बन्ध रखने वाले प्रत्येक मामले पर ट्रेड यूनियन कांग्रेस (T U C) से मलाह ली गयी। यूनियनों को सामाजिक व राजनीतिक मान्यता भी प्राप्त हो गयी। 1945 में जब लेबर दल की सरकार बनी तो उसने 1946 में समर्थन प्राप्त कर 1927 के श्रम सघ कानून को (जो श्रमिकों के विरुद्ध था) रद्द करा दिया।

आधुनिक युग

आधुनिक श्रम सघवाद के निम्न स्वरूप काफी महत्वपूर्ण है

(1) महिला श्रमिकों में कम सक्रिय—ऐसा इस कारण है कि अधिकांश महिलाओं के लिए औद्योगिक अथवा व्यावसायिक रोजगार उनके जीवन का मुख्य धन्य नहीं है। इसके अतिरिक्त उनके लिए काम की दशाओं का पेंकट्री कानून द्वारा बराबर नियमन होता रहा है व उनके लिए यूनियनों के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं के बराबर है।

(2) गैर-शारीरिक (Non-manual) कार्य का प्रसार—सफेदपोश लोगों जैसे डॉक्टर कलाकार शिक्षक, सरकारी कर्मचारी आदि ने भी श्रम सघों के ही ढाँचे के आधार पर अपने अपने अलग सघ बना लिए हैं।

(3) सघों (Federations) का निर्माण—यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि बीसवीं शताब्दी के दौरान श्रम सघों द्वारा अनेक महासघों व मंत्री संस्थाओं का निर्माण किया गया है। अनेकों विलय (amalgamations) भी बीसवीं सदी में हुए हैं। 1889 में ग्रेट ब्रिटेन के खनिकों का सघ (Miners' Association) बना था। 1920 में एमलगेमेटेड इजीनियरिंग यूनियन का गठन किया गया। नेशनल यूनियन आफ माइन वर्कर्स 1945 में अस्तित्व में आयी।

श्रम सघों की सदस्यता में एक ओर जहाँ निरन्तर वृद्धि हुई है वहीं उनकी संख्या में कमी आती जा रही है। 1939 में श्रम सघों की संख्या 1019 थी जो 1957 में घटकर 653 1964 में 591 तथा 1979 में 350 के लगभग हो गयी है।

(5) श्रम सघ कांग्रेस (Trade Union Congress)—ब्रिटिश श्रम सघों की यही शीर्ष संस्था है तथा इसकी सदस्यता 1 करोड़ (10 मिलियन) के आस-पास रहती है। देश की अधिकांश यूनियनें इसी से सम्बद्ध हैं। इसकी (T U C) स्थापना 1868 में हुई थी। ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रमुख कार्य हैं श्रम सघों के

आपसी झगड़ों का निपटारा करवाना, ऐसी किसी भी यूनियन की गतिविधियों की जाँच पड़ताल करना जो सारे श्रम समुदाय के हितों को नुकसान पहुँचाती हो, प्रस्तावित श्रम कानूनों पर नज़र रखना तथा उचित कार्यवाही करना तथा श्रम सघों के बीच मिले-जुले कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देना।

कई बार ऐसा भी हुआ है जब कई उद्योगों में श्रमिकों ने ऐसे श्रमिकों के साथ काम करने से इनकार कर दिया है जो यूनियन के सदस्य नहीं हैं। कुछ समय से स्थानीय मण्डलियाँ इस बात पर जोर दे रही हैं कि सभी कर्मचारियों को किसी न किसी व्यावसायिक सघ का सदस्य होना चाहिए। ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से 'बन्द दुकान' (closed shop) की इस प्रथा का अनुमोदन नहीं किया है किन्तु उमने बिना जोर जबर्दस्ती के मौ प्रतिष्ठत यूनियन सदस्यता के लक्ष्य को प्राप्त करने का आदर्श भी सामने रखा हुआ है। वर्तमान में लगभग 320 यूनियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस से सम्बद्ध हैं तथा वह करीब 90 लाख श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करती हैं।

ट्रेड यूनियन कांग्रेस (T U C) से सम्बद्ध यूनियनों को 18 श्रेणियों में रखा जाता है। ये श्रेणियाँ व्यवसाय के अनुसार होती हैं तथा इनमें रेल, इजीनियरिंग उद्योग, निर्माण व रसायन उद्योग आदि सम्मिलित हैं। सरकार ने ट्रेड यूनियन कांग्रेस (T U C) को मान्यता प्रदान की हुई है तथा वह इसे औद्योगिक श्रमिकों की प्रतिनिधि सस्था मानती है। यह स्वयं एक गैर-राजनीतिक सस्था है लेकिन इससे सम्बद्ध यूनियनों राजनीतिक कौष संग्रह करने के लिए स्वतन्त्र है।

लगभग प्रत्येक उद्योग में आजकल कोई न कोई यूनियन बन गयी है। कम लोगों को रोजगार देने वाले उद्योग अधिक संगठित हैं। कृषि श्रमिक भी राष्ट्रीय कृषि मजदूर सघ के झण्डे तले संगठित हैं तथा उसकी सदस्यता 2 लाख के लगभग है। श्रम सघ सार्वजनिक सेवाओं (public utilities) तथा राष्ट्रीयकृत उद्योगों में भी विद्यमान है।

आज की आरामदेह स्थिति में पहुँचने तक ब्रिटिश श्रम सघ आन्दोलन को लगभग एक सताब्दी से भी अधिक का समय लगा है। अब वे इस स्थिति में हैं कि वे चाहें तो सारी अर्थव्यवस्था का काम ठप्प कर सकते हैं। श्रम सघों ने 1974, 1976, 1977 व 1978 में अनेक राष्ट्रव्यापी हड़तालें कराई हैं। लेबर दल का तो जन्म ही श्रमिकों द्वारा किये गये एक लम्बे व बड़े सघर्ष का परिणाम है। लेबर दल की अधिकांश शक्ति का स्रोत संगठित श्रमिक आन्दोलन ही रहा है।

आज के युग में ट्रेड यूनियन कांग्रेस सम्पर्क का कड़ा का काम कर रहा है। साथ ही, अपने समाजवादी देशों की साथी यूनियनों की तरह ब्रिटिश यूनियन न तो आग उगलने वाली हैं न ही श्रान्तिकारो। उन्होंने इतनी परिपक्वता प्राप्त कर ली है कि विश्व के श्रम आन्दोलन में उनका स्थान अनुपम है। 1973 के बाद से लेकर 1979 तक स्फीतिपरक प्रवृत्तियों (Inflationary trends) द्वारा पैदा की गयी कठिनाइयों ने इस जिम्मेदारी को अनुभव करने वाले ब्रिटिश श्रम सघवाद को पुनः एक बार परीक्षा की स्थिति में लाकर रख दिया है।

1930 की महान् मंदी : आर्थिक स्थिरीकरण की नीतियाँ (THE GREAT DEPRESSION OF 1930 · POLICIES OF STABILISATION)

वॉल स्ट्रीट संकट (Wall Street Crisis) जो 1929 में अमरीका में शुरू हुआ विश्वव्यापी मंदी में बदल गया तथा उसने लगभग सारे यूरोपीय देशों पर चोट की। इंग्लैंड इस आर्थिक मंदी का सबसे भयंकर शिकार हुआ। 1930 की इस महान् मंदी ने न केवल ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को अस्त-व्यस्त कर दिया बल्कि उसने ब्रिटिश उपनिवेशों की अर्थव्यवस्थाओं पर भी अपना दुष्प्रभाव डाल कर इंग्लैंड की स्थिति को और भी दयनीय बना दिया।

महान् मंदी के बारे में प्रसिद्ध लेखक आर्थर नुईस ने लिखा है कि '1929 में जो अवसाद प्रारम्भ हुआ वह कोई साधारण मंदी नहीं थी बल्कि आधुनिक इतिहास में अपनी दीर्घकालीनता और कठोरता दोनों ही दृष्टियों से सबसे बड़ी मंदी थी और सबसे खराब स्थिति तो 1932 में आयी जबकि बेरोजगारों की संख्या बढ़ते-बढ़ते 3 करोड़ तक हो चुकी थी।' आर्थर बिर्नी ने निष्कर्ष निकाला कि '1930 का संकट इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था के धीरे धीरे हो रहे पतन की शायद एक अपरिहार्य अवस्था थी। उसने अपना औद्योगिक नेतृत्व (Industrial leadership) खो दिया था और साथ ही निर्यात बाजार भी। वह कम अनुकूलनशील (adaptable) कम प्रगतिशील, कम गत्यात्मक तथा कम कुशल बन गई थी।'

मंदी का आरम्भ

1914-20 की प्रथम महायुद्ध की अवधि में इंग्लैंड तथा अन्य यूरोपीय देशों में मूल्यों में भारी वृद्धि हुई थी। युद्ध के दौरान भारी मात्रा में पत्र-मुद्रा छापे जाने के कारण इंग्लैंड में मुद्रा की कुल मात्रा में भारी प्रसार हो गया था। कुछ समय तक तो यह पत्र-मुद्रा स्वर्ण में परिवर्तनशील (convertible) बनाये रखी गयी किन्तु उसके बाद वह अपरिवर्तनीय और भार स्वरूप बन गयी। सेना द्वारा उपयोग में ली जाने वाली वस्तुओं को छोड़कर अन्य चीजों के कम उत्पादन से उनका अभाव हो गया। इंग्लैंड को पहुँचने वाली व्यापारों की पूर्ति में भी युद्ध की अवधि के दौरान काफी कटौती कर दी गई थी जिससे उनके मूल्यों में भी अत्यधिक वृद्धि हो

चुकी थी।

प्रथम महायुद्ध के दौरान मूल्यो में हुई वृद्धि को कई लोगो द्वारा काफी गंभीर माना गया। बोर्ड ऑफ ट्रेड द्वारा जारी किये गये मूल्य निर्देशाको के अनुसार सामान्य मूल्य स्तर जुलाई 1914 से लेकर जुलाई 1920 तक की 6 वर्षों की अवधि में तिगुना हो चुका था। 1900 को आधार वर्ष मानने पर बोर्ड ऑफ ट्रेड का 1914 के लिए मूल्य निर्देशांक 117 था जबकि 1920 में वह 358 तक पहुँच गया। इन बढ़ते हुए मूल्यों का श्रमिकों पर जो प्रभाव पड़ा उसकी गणना करना कठिन है। इन लोगो ने युद्ध के वर्षों में मृत्यु, बीमारी, अपगता तथा मानसिक सन्तुलन खो बैठने के रूप में जो घोर कष्ट उठाये उनका कोई हिसाब नहीं था। ये सभी कष्ट ज्यादा महत्वपूर्ण थे तथा मूल्य वृद्धि में इनका कोई सम्बन्ध नहीं था। यह बात अवश्य रही कि इन वर्षों में कोई बेरोजगार नहीं था। कई उद्योगों में तो मजदूरों की इतनी कमी थी कि उनमें पुरुषों के स्थान पर महिलाओं को काम पर लगाने की स्थिति आ पहुँची थी। मजदूरी में भी काफी वृद्धि हुई यद्यपि विभिन्न उद्योगों में यह वृद्धि अलग अलग रही। यह अनुमान लगाया गया है कि 1914 से 1920 तक की अवधि में श्रमिकों को मूल्य वृद्धि से जो कष्ट हुए वे नौकरी पेशा लोगों, क्लर्कों आदि के मुकाबले अपेक्षाकृत कम थे क्योंकि इन लोगो की आमदनी में शारीरिक काम करने वालों की आमदनी के अनुपात में वृद्धि नहीं हो पायी।

स्फीति की इस विकट स्थिति की पहली प्रतिक्रिया यही रही कि विस्फीतिकारी (deflationary) नीति अपनायी जाये। विस्फीति की नीति 1921 में ब्रिटेन में जाँच के तौर पर चलाई भी गयी। किन्तु विस्फीति व उससे उत्पन्न मंदी से जो मूल्य गिरे तथा बेरोजगारी बढ़ी उसने तो समाज पर जो छोट की वह स्फीति के कारण पैदा हुई अस्त-व्यस्तता से वही अधिक तिलमिलाने वाली थी।¹ इसके बाद विस्फीति माग के स्थान पर स्थिरीकरण (stabilisation) की माग की गई। लॉर्ड कीम तथा केम्ब्रिज विचारधारा के अर्थशास्त्रियों ने 'संचालित मुद्रा' (Managed Currency) का विचार लोगों के सामने रखा। उन्होंने यह तर्क दिया कि मूल्यों में स्थायित्व संभव है यदि प्रचलन में रहने वाली मुद्रा की पूर्ति को उसकी माग के अनुपात में घटाया बढ़ाया जाता रहे। किन्तु इन विचारों को स्वीकार नहीं किया गया तथा ब्रिटिश सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए पुनः स्वर्णमान (gold standard) अपनाने का निश्चय किया जिसे कि युद्ध छिड़ने के समय त्याग दिया गया था। स्वर्ण मान को फिर से अपनाने वाला यह महत्वपूर्ण निर्णय 1925 में लिया गया। कागजों नोटों को फिर से स्वर्ण में परिवर्तनीय घोषित किया गया यद्यपि उन्हें स्वर्ण मुद्राओं में नहीं बल्कि सोने-चाँदी (bullion) में ही बदलवाया जा सकता था। इस प्रावधान का उद्देश्य ऋण चुनाने तथा आयातों का भुगतान करने के लिए अधिक स्वर्ण प्राप्त करना था। आंतरिक सेन-देन में स्वर्ण का प्रयोग नहीं किया जाना था जिन्हें कि कुशलतापूर्वक यन्त्रनतम लागत पर पत्र मुद्रा में ही निपटाया जा सकता था। इस व्यवस्था में स्वर्ण के उपयोग में काफी मितव्ययिता सम्भव हुई। इंग्लैंड द्वारा स्वर्ण

¹ A Birnie, *op cit*, 83

मान की पुनर्प्रतिष्ठा ने कई अन्य यूरोपीय देशों को भी स्वर्णमान की व्यवस्था की ओर लौटने के लिए प्रवृत्त किया यद्यपि यह सब थोड़े ही समय तक चलने वाला था ।

मूल्यों में गिरावट

1920 के बाद से ही मूल्यों में गिरावट शुरू हो चुकी थी । मूल्य निर्देशक जो 1920 में 300 से भी ऊपर थे, अगले ही वर्ष 200 से भी नीचे आ गए । 1921 के बाद मूल्यों में यह कमी थोड़ी धीमी पड़ गई तथा 1924 में तो उनमें अस्थायी तौर पर कुछ वृद्धि भी हुई । किन्तु कुल मिला कर गिरावट चलती रही तथा 1932 में बोफ ऑव ट्रेड द्वारा प्रसारित थोक मूल्य निर्देशक घटते-घटते 1924 के स्तर का 61 प्रतिशत तथा 'स्टैटिस्ट' (statist) निर्देशक केवल 58 प्रतिशत रह गया । युद्धोत्तरकालीन¹ वर्षों में मूल्यों में आने वाली इस गिरावट का प्रमुख कारण मुद्रा तथा उत्पादन के बीच रहने वाले आनुपातिक सम्बन्ध का गड़बड़ा जाना था । सामान्य मूल्य स्तर इसी आनुपातिक सम्बन्ध पर आश्रित होता है । दूसरा तत्त्व, जिसने मूल्यों में गिरावट पैदा की, वे विस्फीतिकारी (deflationary) नीतियाँ थी जो युद्धोत्तरकाल में मूल्यों में और वृद्धि न होने देने के उद्देश्य से अपनायी गयी थी । तीसरा कारण, युद्ध समाप्त हो जाने के बाद उत्पादन की अनेक शाखाओं में उत्पादन में जो अत्यधिक वृद्धि हुई उसमें भी बाजार में चीजों का अबार (glut in the market) लग गया । यह इसलिए हुआ क्योंकि प्रभावी माग कम रही ।

1920 से 1924 के बीच ब्रिटेन में प्रचलित कुल मुद्रा में से 70 मिलियन पाँड के करेसी नोटों को कम कर दिया गया था । नोटों की यह रकम प्रचलन से निकाल ली गई तथा उसे मण्ट कर दिया गया । इसके साथ-साथ कई उद्योगों में चली आ रही दशाओं का पुनर्मूल्यांकन किया गया । नई मशीनें स्थापित की गयीं, गौण-उत्पादनों (by products) का नये तरीके से उपयोग किया गया तथा थम व अन्य ऊपरी लागतों में कटौतियाँ की गयीं । इस तरह एक ओर तो उत्पादन में वृद्धि होती चली गई तथा दूसरी ओर प्रचलन में नोटों की मात्रा कम कर देने से मूल्यों में गिरावट की स्थिति उत्पन्न हुई जिससे मदी का संकट बढ़ता चला गया ।

स्वर्णमान की व्यवस्था को पुन अपमाने का अनेक देशों का कदम भी अपरिपक्व सिद्ध हुआ । यह व्यवस्था अब युद्ध-पूर्व के दिनों की तरह सहज रूप से चलने की स्थिति में नहीं रह गयी थी क्योंकि स्वर्ण के भंडारों के वितरण में कुसमायोजन हो गया था । उस समय के अर्थशास्त्रियों का यह विश्वास गलत सिद्ध हुआ कि कोई भी देश उसकी मुद्रा व्यवस्था के लिए वांछित स्वर्ण से अधिक सोना अपने पास नहीं रखेगा । 1931 तक फ्रांस तथा समुक्त राज्य अमरीका के पास समार का 3/5 सोना जमा हो चुका था । उनके पास सोना इसलिए जमा होता चला गया कि उन्होंने ऋणदाता (creditor) देश होने के उपरांत स्वर्णमान के नियमों के अनुसार अपने अतिरिक्त को देनदार (debtor) देशों में विनियोग नहीं किया । देनदार देश, दूसरी

और, अपने ऋण केवल स्वर्ण में ही चुका सकते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि जब 1931 में वित्तीय संकट फट पड़ा तो ससार की मौद्रिक व्यवस्था बिखर गई। परिस्थितियों ने इंग्लैंड को पुनः 1931 में स्वर्णमान का परित्याग करने के लिए विवश कर दिया।

ब्रिटेन द्वारा स्वर्णमान के परित्याग के उदाहरण का अन्य देशों ने भी अनुकरण किया। 1930 के वर्षों में विश्व मौद्रिक व्यवस्था अनियंत्रित व अराजकतापूर्ण हो गयी। संपूर्ण विश्व मोटे तौर पर तीन स्पष्ट गुटों में बँट गया जिनमें प्रत्येक गुट भिन्न मौद्रिक नीति अपना रहा था—डॉलर समूह जिसका नेता अमरीका था, व जिसका लक्ष्य स्फीति पैदा करना था, स्वर्ण गुट (gold block) जिसका नेतृत्व फ्रांस कर रहा था व जिसका उद्देश्य अपस्फीति (deflation) पैदा करना था, तथा स्टर्लिंग समूह (Sterling group) जिसका नेता ब्रिटेन था व जिसका उद्देश्य स्थिरीकरण (stabilisation) करना था। जब 1936 में फ्रांस ने भी स्वर्णमान का परित्याग कर दिया तो हालत में कुछ सुधार हुआ किन्तु विश्व व्यापार के विकास एवं प्रसार में मौद्रिक अव्यवस्था 1939 तक भी एक भारी अड़चन बनी रही।

प्रथम विश्व युद्ध के बाद परिस्थितियों में आये क्रांतिकारी परिवर्तन के अतिरिक्त कुछ प्रमुख तत्त्व और भी थे जिन्होंने ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को महान् मंदी का शिकार बनाया। महान् मंदी के ये कारण निम्न थे—

(1) विश्व मांग में भारी गिरावट—विश्व युद्ध ने ब्रिटिश उद्योगों द्वारा उत्पादित लगभग प्रत्येक वस्तु की मांग में अस्थायी रूप से भारी वृद्धि कर दी थी। जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ यह मांग गिरने लगी तथा उससे मंदी आयी।

(2) नये औद्योगिक देश—बीसवीं सदी के प्रारम्भिक वर्षों में फ्रांस, जर्मनी तथा अमरीका ने भारी प्रगति कर ली थी। उनके पास विशाल मात्रा में प्राकृतिक ससाधन उपलब्ध थे तथा वे विश्व बाजार में निमित्त माल के क्षेत्र में शक्तिशाली प्रतिद्वन्द्वी बन गये। इस क्षेत्र में बनी हुई ब्रिटिश सर्वोच्चता समाप्त हो गई।

(3) संरक्षणवाद की लहर—संरक्षणवाद की एक नई लहर ने पहले चली आ रही मुक्त व्यापार नीति का स्थान ले लिया था। जर्मनी, अमरीका तथा अनेक यूरोपीय देशों ने सड़करो की एक अभेद्य दीवार (impregnable tariff wall) खड़ी कर ली थी तथा वे अपने देश के उद्योगों को आगे लाने के लिए सभी प्रकार की राजकीय सहायता दे रहे थे। इन सभी बातों से ब्रिटिश उद्योगों को, जोकि मुक्त व्यापार के वातावरण में पले थे, गंभीर धक्का लगा।

(4) विनियोग के अवसरों का अभाव—ब्रिटिश विनियोगकर्ताओं के समक्ष विनियोग को लेकर सतृप्ति (saturation) की स्थिति उपस्थित हो गयी थी। देश के भीतर विनियोग की अब कोई संभावना नहीं थी। बाहर विनियोग करने में अब काफी सावधानी की जरूरत थी क्योंकि अधिकांश उपनिवेशों में आजादी के लिए संघर्ष काफी शक्तिशाली बन चुके थे। ब्रिटिश साम्राज्य एक तरह से पतन की स्थिति की ओर बढ़ रहा था।

(5) बेलोचदार निर्मात उद्योग—मुख्य ब्रिटिश निर्मात उद्योग जैसे कोयला,

लोहा व इस्पात तथा सूती वस्त्र उद्योग समय के साथ अपने आप को बदल नहीं पाये। उत्पादन की पद्धतियों को बदलना तथा उसमें विविधता लाना आवश्यक बन चुका था। किन्तु ये ब्रिटिश उद्योग समय की माग के अनुसार अपने आप को बदलने में आलस्य करते रहे और परिणाम यह रहा कि वे दौड़ में पिछड़ गए। इजीनिरियरिंग तथा रासायनिक वस्तुओं की विश्व बाजार में भारी माग थी किन्तु ब्रिटिश उद्योग अपने परम्परागत उत्पादनो में ही लगे रहे।

मदी के प्रभाव

(1) व्यापक बेकारी—1930 की मदी से लोग भारी सख्या में बेरोजगार हो गए तथा बेरोजगारों की यह सरया इतनी अधिक थी कि वह दूसरे महायुद्ध के प्रारम्भ होने तक लुप्त नहीं हुई। चार प्रमुख ब्रिटिश उद्योगों में लगे हुए लोगों की सख्या में निरन्तर कमी आयी। 1907 में इन चार प्रमुख उद्योगों में लगे हुए श्रमिकों का भाग कुल श्रम-शक्ति का 44 प्रतिशत था। 1930 में यह घट कर 25 प्रतिशत रह गया। एक अनुमान के अनुसार 1930 की मदी को सबसे खराब समय में देश की कुल श्रम शक्ति का लगभग एक-चौथाई भाग बेरोजगार हो चुका था।

इस स्थिति में और बिगाड़ तब हुआ जब उद्योगों का विवेकीकरण (rationalisation) करने के कुछ प्रयास भी इसी समय छेड़े गये। कीमतों में भारी गिरावट ने निर्माताओं को अपनी उत्पादन लागतें घटाने के लिए मजबूर कर दिया था। उन्होंने ऐसा करने के लिए अपने उत्पादन ढांचे को पुनर्गठित किया जिसमें ऊपरी लागतों (overhead costs) में कटौती, मजदूरी में कटौती, श्रम की बचत करने वाली नई मशीनें लगाना आदि उपाय सम्मिलित थे। इससे बेकारी में और वृद्धि हुई।

(2) औद्योगिक अशांति—उद्योगपति युद्ध के दौरान कृत्रिम रूप से बढ़ायी गयी मजदूरियों (inflated wages) को घटाने की माग कर रहे थे। इन मजदूरों की कटौतियों तथा मजदूरों की छटनी (retrenchment) ने मिल कर देश में औद्योगिक अशांति के वातावरण को जन्म दिया।

(3) वृद्धिगत ऋण भार—मूल्यों में गिरावट का एक और प्रभाव यह हुआ कि राष्ट्रीय ऋण (National debt) का वास्तविक भार (real burden) और बढ़ गया। हजारों मिलियन पाँड तब उधार लिये गए थे जब उनकी क्रय-शक्ति 1930 में गिरे हुए मूल्य स्तर की अपेक्षा काफी कम थी। वस्तुओं के मूल्यों में यह भारी गिरावट सरकारी प्रतिभूतियाँ (state securities) रखने वाले लोगों के लिए काफी लाभप्रद सिद्ध हुई।

(4) निर्यातों में कमी—महान् मदी से पहले ही ब्रिटिश निर्यातों में वृद्धि होना रुक चुका था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रवाद की भावना अत्यधिक बलवती हो उठने के कारण भी निर्यातों में यह गिरावट आने लगी थी। वस्तुओं का, विशेषकर निर्मित माल (manufacturing) का उत्पादन प्रत्येक देश का स्थानीय मामला बन गया। युद्ध में ध्वस्त हो चुके राष्ट्रों के पास ब्रिटेन से माल मगवाने के लिए क्रय-शक्ति

विल्कुल नहीं बच रही थी। ब्रिटिश उपनिवेश, जो मूलतः कृषि प्रधान थे, भी मदी के गहरे शिकार हुए थे क्योंकि उनके प्रमुख निर्यात कच्चे माल आदि के थे जिनके मूल्यों में भी भारी कमी आ चुकी थी। इस तत्त्व ने निमित्त माल का आयात कर सकने की उनकी क्षमता में कमी कर दी थी।

ये कुछ प्रमुख कारण थे जिनके कारण से ब्रिटिश निर्यात प्रधान उद्योगों को मदी के वर्षों में भारी हानि उठानी पड़ी। 1913 की तुलना में 1929 में ब्रिटिश उद्योगों के निर्यात 12 से लेकर 37 प्रतिशत तक गिर चुके थे।

ब्रिटिश भुगतान सन्तुलन

(मिलियन पाउंड में)

1913	+181
1926	- 7
1928	+137
1929	+ 88
1930	+ 33
1931	-145

(5) औद्योगिक अवनति—कुल मिलाकर 1930 की महान् मदी ब्रिटिश उद्योगों के विकास के लिए काफी घातक मिट्टि हुई। अस्थिर व गलत मौद्रिक नीतियों, ऊँची लागतों, पुराने पड़ चुके संगठन तथा श्रमिक असंतोष की परिस्थितियों ने मिल कर एक ऐसी हालत पैदा कर दी जिसमें औद्योगिक उत्पादन में आयी गिरावट और भी अधिक स्पष्ट झलकने लगी। स्वर्णमान की पुनर्संस्थापना तथा कुछ वर्षों तक चलायी गयी विस्फीतिकारी (deflationary) नीतियों ने भी ब्रिटिश उद्योगों को हानि पहुँचाई। मदी के वर्षों में श्रमिकों द्वारा किये गये आन्दोलनों से सबट और भी विकट हो गया। 1919 से 1926 की अवधि में श्रम असंतोष के कारण कुल मिला कर लगभग 357 मानव दिवसों की क्षति हुई। श्रमिक किसी भी प्रकार की मजदूरी में कटौती के लिए राजी नहीं थे जबकि स्थिति यह थी कि जहाँ थोक मूल्यों में 40 प्रतिशत की गिरावट आ चुकी थी वहाँ मजदूरी में केवल 2 प्रतिशत की कमी आयी थी।

निम्नलिखित निर्देशांकों से महान् मदी के चित्र को देखा जा सकता है—

मदी के दौरान आर्थिक सूचक (1923=100)

	1929	1930	1931
औद्योगिक उत्पादन	106	98	89
रोजगार	102	98	94
विशुद्ध निर्यात मूल्य	103	89	74
थोक मूल्य	97	85	74

(6) बजट में घाटा—1929 में ग्रेट ब्रिटेन के चालू खाते में 100 मिलियन पौंड का अतिरेक था। 1931 तक यह अतिरेक न केवल लुप्त हो चुका था बल्कि उसके स्थान पर 100 मिलियन पौंड का घाटा और हो गया था। इसके अतिरिक्त आगामी वर्षों में भी बजटों में विशाल घाटे के अनुमान लगाये गये थे तथा देश की वित्तीय स्थिति की जाँच पड़ताल करने वाली एक समिति ने पाया कि देश दिवालियेपन की ओर अग्रसर हो रहा था।

1930 की मदी ने औद्योगिक देशों को घोर निराशा की स्थिति में ढकेल दिया था। सबसे अधिक प्रभावित होने वाला देश तो अमरीका ही था। ब्रिटेन पर भी मदी का आघात काफी जबरदस्त लगा किन्तु उसकी सुनियोजित सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था इस मौके पर काफी उपयोगी व कारगर साबित हुई। बेकारी बीमा आयोग (Unemployment Insurance Commission) की एक रिपोर्ट के अनुसार 1930 में बीमायुद्धा प्रत्येक 8 श्रमिकों में से एक श्रमिक बेरोजगार था। सामाजिक सेवाओं पर किया जाने वाला खर्च आकाश को छूने लग गया था।

निदान के उपाय

सामाजिक सेवाओं पर किये जा रहे खर्च में कटौती के मामले पर उठ खड़े विवाद को ले कर सितम्बर 1931 में लेबर दल की सरकार ने त्यागपत्र दे दिया तथा देश को आर्थिक दिवालियेपन के भय से बचाने के लिए अनुदार दल (Conservative Party) के बहुमत वाली एक राष्ट्रीय सरकार (National Government) का गठन किया गया। मदी का मुकाबला करने के लिए निम्न प्रमुख उपाय किये गये—

(1) संरक्षणवादी नीतियाँ—ब्रिटिश संसद ने प्रथम महायुद्ध प्रारम्भ होने से पहले तथा उसके बाद भी कुछ आयात शुल्क लगाये थे किन्तु कुल मिला कर ब्रिटेन एक मुक्त व्यापार वाला देश ही बना रहा था। ब्रिटेन द्वारा समझाने-बुझाने पर 1927 में अमरीका, हालैंड, जापान तथा कुछ अन्य देशों ने भी व्यापार पर लगे हुए प्रतिबन्धों को हटाना स्वीकार कर लिया था। किन्तु वास्तव में इन देशों ने वंसा नहीं किया। 1929 तक अर्थात् दो ही वर्षों बाद, जर्मनी ने अपने तटकरों में 129 प्रतिशत की वृद्धि कर दी और हालैंड ने अपने तटकर तो इससे भी अधिक अर्थात् 167 प्रतिशत से बढ़ा दिये। स्पष्ट है कि इंग्लैंड के पास कोई विकल्प नहीं रह गया था।

अब ब्रिटेन को भी यह बात समझ आ गयी कि मुक्त व्यापार के दिन लड़ चुके थे। ब्रिटिश संसद ने अनेक आपतकालीन विधेयक पारित कर अपने देश के उद्योगों को संरक्षण प्रदान किया। इंग्लैंड ने अपने प्रतिद्वन्द्वियों के साथ अनेक उदार व्यावसायिक समझौते भी किये। 1932 में ओटावा (कनाडा) में हुई साम्राज्यीय आर्थिक बैठक (Imperial Economic Conference) में साम्राज्य अधिमान की नीति (Policy of Imperial Preference) स्वीकार की गई। इसके अनुसार प्रथम प्राथमिकता या अधिमान (preference) घरेलू उद्योगों को दिया जाना था व दूसरा

अधिमान साम्राज्य के देशों को व अन्तिम अधिमान विदेशी प्रतिद्वन्द्वियों को देना था जो ब्रिटिश बाजारों में प्रवेश पाना चाहते थे ।

ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अपनायी गयी इस नई सरक्षणवादी नीति के प्रमुख लक्ष्य थे . भुगतान सतुलन में हो रहे घाटे को ठीक करना, सरकारी आय में वृद्धि करना तथा देश के अन्दर हो रहे उत्पादन व वितरण को अधिक कुशल बनाना । 1932 में मूल्य पर आधारित (ad valorem) 10 प्रतिशत का आयात शुल्क प्रत्येक वस्तु पर, केवल साद्य पदार्थों व कच्चे माल को छोड़कर, लगा दिया गया । निर्मित माल के आयातों पर शुल्क की यह दर 10 प्रतिशत रखी गई व उपनिवेशों में आने वाले माल को अधिमान प्रदान किया गया । यह समझौता परस्पर किया गया था किन्तु इसका लाभ ब्रिटिश तैयार माल बनाने वाले उद्योगों को ही मिला जो पहले से ही मजबूत स्थिति में थे ।

सरक्षणवादी नीतियों का ध्येय ब्रिटिश उद्योगों के लिए अधिक अवसर उपलब्ध कराना था । विश्व-व्यापार में ब्रिटेन का प्रतिशत भाग 1924 के 12.9 प्रतिशत से घट कर 1929 में 10.8 प्रतिशत रह गया था । किन्तु इन उपायों से विशेष लाभ इसलिए नहीं हो पाया कि अन्य देशों द्वारा अपनाये गये सरक्षणवादी उपायों व तटकर वृद्धियों के परिणामस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का कुल परिमाण ही घट गया था ।

(2) मौद्रिक नीति में परिवर्तन—1931 में दूसरी बार स्वर्णमान का परित्याग करने के बाद सस्ती मुद्रा-नीति (cheap money policy) को अपनाया गया । पौड-स्टर्लिंग का मूल्य गिरने दिया गया जिससे कि ब्रिटिश निर्यात विदेशी बाजारों में सस्ते बिक पाते । इसके पीछे विचार यह था कि निर्यातों में वृद्धि करके उत्पादन व रोजगार दोनों में वृद्धि की जा सकती थी । किन्तु यह लक्ष्य भी इसलिए प्राप्त नहीं हो पाया क्योंकि 1936 तक अन्य सभी देशों ने भी स्वर्णमान का परित्याग कर दिया था तथा इसी प्रकार की नीतियाँ अपना ली थी ।

यह भय लगने लगा था कि पौड-स्टर्लिंग के मूल्य में भारी उच्चावचन (fluctuations) हो सकते हैं । इस संभावना को रोकने के उद्देश्य से 1932 में एक विनिमय समानीकरण कोष (Exchange Equalisation Fund) स्थापित किया गया जिसका लक्ष्य विनिमय दरों पर अकुशल बनाये रखना था । 1930 के बाद ब्रिटिश करेंसी (British Currency) के संचालन तथा अनेक विनिमय नियन्त्रणों के लगा दिय जाने से देश के भुगतान सतुलन में हो रहे घाटे को ठीक करने में बड़ी सहायता मिली ।

सस्ती मुद्रा नीति (cheap money policy) लागू करने के इरादे से 1932 में यह निर्णय किया गया कि युद्ध के समय के लिए गये सभी ऋणों (जोकि कुल राष्ट्रीय ऋणों का एक-तिहाई थे) पर व्याज की दर 5 प्रतिशत से घटा कर साढ़े-तीन प्रतिशत कर दी जायेगी । इस उपाय से ऋणों की सेवा (debt servicing) पर हो रहा व्यय घट गया तथा सरकार को कम करने की स्थिति में पहुँच गयी । स्वर्णमान को विदा कर देने से सरकार को अधिक मौद्रिक स्वतन्त्रता प्राप्त हुई तथा व्यावसायिक गतिविधियों को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से नई मुद्रा छपी गई ।

लेकिन अभी भी कीस द्वारा प्रचारित राजकीय व्यय में वृद्धि करने का प्रस्ताव व्यवहार रूप में लागू नहीं किया गया था तथा सार्वजनिक व्यय के प्रयोग में सकोच बना रहा।

(3) कृषि में सुधार—अनाज का स्वतन्त्र रूप से आयात होने से ब्रिटिश कृषि की स्थिति काफी खराब हो गई थी। इन आयातों पर पूरी तरह से रोक लगाना भी सम्भव नहीं था क्योंकि बैसा करने से खाद्य पदार्थ काफी महँगे हो जाते। इस परिस्थिति में सरकार ने अनुदान (subsidies) देने व नई विपणन योजनाएँ लाने की नीति अपनायी। 1931 व 1932 में उत्तरोत्तर दो कृषि विपणन विधेयक (Agricultural Marketing Acts) पारित किये गये। इन विधेयकों का उद्देश्य एक विपणन बोर्ड (Marketing Board) की स्थापना करना था जो उन कृषिगत पदार्थों के आयातों पर प्रतिव्रध लगा सके जिन्हें कृषि विपणन स्कीमों (agricultural marketing schemes) के अन्तर्गत ले आया गया था। गेहूँ के लिए 45 शिलिंग प्रति क्वार्टर (quarter) की गारंटी दी गई। चुकंदर की खेती को भी प्रोत्साहन दिया गया।

इस तरह 1931 में बनायी गयी कृषि नीति का ध्येय इंग्लैंड को खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर बनाना था।

(4) आवास पर विनियोग (Investment in Housing)—1930 के बाद के वर्षों में भवन निर्माण के काम में जो तेजी आयी (Building boom) वह ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने वाले तत्वों में सर्वप्रमुख कही जा सकती है। कम ब्याज की दर होने के अलावा मकान बनाने की क्रिया ने इसलिए भी जोर पकड़ा क्योंकि उस समय मकान बनाना सस्ता पड़ता था। निर्माण कार्य के बढ़ने से रोजगार के अवसर बढ़े। रोजगार बढ़ने से लोगों के हाथों में क्रय-शक्ति बढ़ी तथा अधिक क्रय शक्ति लोगों के हाथों तक पहुँचने से निर्मित वस्तुओं की माग में भी वृद्धि हुई।

(5) बेकारी बीमा (Unemployment Insurance)—1932 में रजिस्टर्ड बेरोजगारों की संख्या बढ़ कर 27 लाख के लगभग पहुँच चुकी थी जैसे-जैसे बेरोजगारी की समस्या में वृद्धि हुई वैसे-वैसे बेरोजगारी बीमा योजना अधिक खर्चीली होती चली गई। किस्मों की दर को बदलना पड़ा। 1934 में स्थिति में कुछ सुधार आया जब कोय पर्याप्त हो गये तथा सामान्य लाभ पुनर्स्थापित हो गये। 1936 में दरों को संशोधित किया गया तथा पुरुषों के लिए वे 16 शिलिंग तथा महिला के लिए 15 शिलिंग तय की गयी।

बेरोजगारी में क्षेत्रीय असमानताएँ भी थी। देश में कुछ ऐसे भी क्षेत्र या प्रदेश थे जहाँ बेरोजगारी की समस्या अधिक गंभीर थी क्योंकि वहाँ के उद्योगों का स्थायी रूप से पतन हो गया था। उन्हें 'विपदग्रस्त क्षेत्र' (distressed areas) घोषित किया गया। इन विपदग्रस्त क्षेत्रों की समस्या सुलझाने के लिए या तो वहाँ के बेरोजगारों को उन क्षेत्रों में स्थानान्तरित करने की आवश्यकता थी जहाँ रोजगार उपलब्ध था या फिर विपदग्रस्त क्षेत्रों में ही नये उद्योग मोलने की आवश्यकता थी ताकि वहाँ के लोगों को वही काम मिल सके। लेकिन कोई ठोस काम इस बारे में

नहीं हो पाया जब तक कि 1934 में विशिष्ट क्षेत्र विधेयक (Special Areas Act) नहीं पारित कर दिया गया जिसके अन्तर्गत इन क्षेत्रों की देखभाल के लिए आयुक्त नियुक्त किये गये। इस विधेयक में 2 मिलियन पौंड का एक कोष भी बनाया गया।

(6) निर्यातों को अनुदान (Subsidies to Exports)—अन्य देशों में चलाई जा रही स्कीमों की भांति इंग्लैंड में भी निर्यातों को अनुदान देने की स्कीम हाथ में ली गई। कुछ निर्यातोन्मुख उद्योगों के लाभ को ऊँचा रखने के उद्देश्य से उनके लिए एकाधिकारिक व्यवस्थाएँ की गईं।

1932 से 1937 की अवधि में सुधार धीमी गति से किन्तु नियमित रूप से हुआ। इन पाँच वर्षों में औद्योगिक उत्पादन में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा मुनाफे 10 प्रतिशत से बढ़े। बेरोजगारी में भी काफी कमी आयी यद्यपि वह पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई। नये उद्योगों जैसे यातायात, रसायन, बिजली का साज-सामान व इंजीनियरिंग सामान बनाने वाले उद्योगों की भारी प्रगति हुई। इस अवधि में अन्य महत्वपूर्ण औद्योगिक देश जैसे अमरीका, जापान तथा जर्मनी भी काफी सफल चुके थे।

1929 के सूचकांकों की 1936 के सूचकांकों के साथ तुलना से ब्रिटिश अर्थव्यवस्था में हुए तत्कालीन असाधारण सुधार का अनुमान किया जा सकता है।

अर्थव्यवस्था में समुत्थान (Recovery) के सूचकांक

(आधार वर्ष 1928=100)

	1929	1936
औद्योगिक उत्पादन	88	121
रोजगार	94	108
शुद्ध निर्यात	50	61
घोष मूल्य	72	80
औद्योगिक लाभ	65	99

इन आंकड़ों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि ब्रिटिश अर्थव्यवस्था में सुधार या उसका समुत्थान (recovery) आशिक ही था। उस समय ऐसे कई लोग थे जो यह मोचने थे कि दूसरी मंदी भी अब दूर नहीं है। किन्तु तभी दूसरा महायुद्ध छिड़ गया। सामान्य मूल्य स्तर युद्ध की अवधि (1939-45) में पुनः खूब चढ़ गया। जीवन-स्तर लागत निर्देशांक (Cost of living index) जो मितम्बर 1939 में युद्ध प्रारम्भ होने के समय 155 पर था (1914=100), 1941 में बढ़कर 196 व 1942 में 200 हो गया। युद्ध के अन्त में यह 202 तक पहुँच गया था।

विदेशी व्यापार (FOREIGN TRADE)

अठारहवीं सदी के अन्त में एक प्रसिद्ध ब्रिटिश राजनीतिज्ञ ने वेजामिन फ्रैंकलिन (अमरीकी राजनेता) से यह इच्छा व्यक्त की थी कि वह इंग्लैंड को एक स्वतन्त्र बन्दरगाह (Free Port) के रूप में देखना चाहता है। जिसके लिए, उस ब्रिटिश राजनेता ने कहा कि 'इंग्लैंड स्वभाव से, पूँजी की दृष्टि से, साहस के प्रति प्रेम की दृष्टि से, नौमैनिक दृष्टि से तथा नई व पुरानी दुनिया के बीच स्थित होने की अपनी भौगोलिक स्थिति की दृष्टि से तथा यूरोप के उत्तर व दक्षिण में होने से सर्वाधिक उपयुक्त देश है।' आगे उस ब्रिटिश राजनेता ने यह भी कहा कि 'जो लोग व्यापार व्यवसाय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं वे लोग व्यापार को मुक्त रखकर लाभ ही उठा सकते हैं।' इस तरह ब्रिटेन में स्वतन्त्र व्यापार (Free Trade) के युग का आरम्भ हुआ और उसके साथ ही ब्रिटिश समृद्धि का युग भी। ब्रिटेन का आयात व निर्यात व्यापार जर्मनी, फ्रांस व अमरीका के व्यापार में अत्यधिक प्रसार हो चुकने के उपरान्त भी, विश्व व्यापार का अनुमानित पाँचवाँ हिस्सा (1/5) था।

उन्नीसवीं सदी में ब्रिटिश विदेशी व्यापार की असाधारण प्रगति के लिए अनेक कारण उत्तरदायी थे। प्रथमतः बाहरी दुनिया के सन्दर्भ में इंग्लैंड की अति विशिष्ट भौगोलिक स्थिति ही इसके लिए उत्तरदायी थी। दूसरा कारण इंग्लैंड का नौमैनिक दृष्टि से ताकतवर होने का था जिसकी वजह से वह न केवल युद्धों के समय अपने व्यापारिक जहाजों की रक्षा कर सकता था बल्कि जहाजों, गोदियों (docks) तथा नाविकों की सुविधा व्यापार के लिए वहाँ हर समय मौजूद रहती थी। तीसरा महत्वपूर्ण तत्त्व ब्रिटेन का उपनिवेशों पर अधिकार की दृष्टि से सबसे प्रमुख राष्ट्र होना था। चौथा तत्त्व इंग्लैंड में तुलनात्मक दृष्टि से बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सकने वाले उद्योगों का जल्दी विकास हो जाना था जिससे कि निर्यात के लिए भारी मात्रा में अतिरिक्त प्राप्त किया जा सकता था। फ्रांस व जर्मनी 1870 तक जाकर ही उतना औद्योगिक उत्पादन कर सकने की स्थिति में पहुँच सके थे कि जिससे वे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारी अतिरिक्त पैदा कर सकते। पाँचवीं बात यह थी कि ब्रिटिश निर्माता ऐसी चीजों का उत्पादन कर रहे थे जिनकी विश्व में भारी माँग थी। अन्तिम बात यह रही कि ब्रिटेन ऐसा पहला देश था जिसने अपने व्यापार को बन्धनों से मुक्त किया तथा अपने नौ-परिवहन कानूनों को उदार बनाया।

उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में ब्रिटिश विदेशी व्यापार के प्रसार की तीव्रता

का अनुमान निम्नलिखित तालिका से लगाया जा सकता है :

उत्तीसवी सदी में ब्रिटिश विदेश व्यापार

(मिलियन पौंड में)

वर्ष	औसत आयात	औसत निर्यात
1855-1859	146	116
1860-1864	193	138
1865-1869	237	181
1870-1874	291	235
1875-1879	320	202
1880-1884	344	234
1885-1889	318	226
1890-1894	357	234
1895-1899	393	238
1900	460	283

1890-99 के दशक में ब्रिटिश विदेश व्यापार की प्रगति धीमी रही। किन्तु 1900 के बाद असाधारण गति से प्रसार आरम्भ हो गया तथा 1914 तक ब्रिटिश निर्यात दुगुने हो गये। 1913 में निर्यातों का मूल्य बटकर 525 मिलियन पौण्ड तथा आयातों का कुल मूल्य 768 मिलियन पौण्ड हो चुका था। इस सम्पूर्ण अवधि में ब्रिटेन ने तैयार माल के निर्माण में अधिकाधिक विशिष्टीकरण किया। देश के निर्यात अविकाश रूप में निर्मित मात्र जैसे सूनी वस्त्र, मशीनों, चमड़े की बनी चीजों, रसायनों तथा चीनी मिट्टी के बर्तनों जैसी चीजों के रहे। आयातों में मुख्य रूप से खाद्य सामग्री, कच्चा सोहा, कपास चमड़ा तथा कागज प्रमुख थे।

प्रथम विश्व युद्ध के पहले तक विश्व विदेशी व्यापार में ब्रिटेन का भाग सबसे बड़ा था। यह निम्न तालिका से स्पष्ट है

विदेश व्यापार में ब्रिटेन का भाग

(प्रथम विश्व-युद्ध से पूर्व)

(प्रतिशत में)

देश	निर्यात		आयात	
	1894	1907	1894	1907
ग्रेट ब्रिटेन	20.8	15.5	14.2	11.2
जर्मनी	13.2	10.5	13.6	9.3
अमेरिका	8.9	9.5	12.4	15.1
हॉलैंड	8.0	6.6	—	—
मोवियन संघ	6.4	6.4	12.7	12.7

ब्रिटिश अर्थव्यवस्था में विदेशी व्यापार ने हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अठारहवीं सदी के अन्त में ब्रिटिश आयातों व निर्यातों का वहाँ की राष्ट्रीय आय में भाग 34 प्रतिशत था। 1870 में निर्यात कुल राष्ट्रीय आय का करीब 22 प्रतिशत थे जबकि आयात उसका लगभग 36 प्रतिशत थे। इस तरह दोनों मिलाकर राष्ट्रीय आय का 58 प्रतिशत हो जाते थे। 1950-55 के वर्षों में भी इन दोनों का राष्ट्रीय आय में भाग विशेष घटा नहीं था, वह 47 प्रतिशत के लगभग था।

इंग्लैंड के निवासियों की साहसिक यात्राएँ करने की आकांक्षा ने ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को विदेश व्यापार प्रधान अर्थव्यवस्था बनाया। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के जमाने में सोलहवीं सदी में ही अनेक व्यापारिक कम्पनियाँ गठित हो चुकी थी। बारबरी कम्पनी (Barbary Company) ने उत्तरी अफ्रीका के साथ व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित किये थे जबकि लेवेंट कम्पनी (Levant Company) ने मेडिटरेनियन देशों (Mediterranean Countries) देशों के साथ सामा व्यापार कायम कर लिया था। इन व्यापारिक कम्पनियों में सबसे प्रसिद्ध ईस्ट इण्डिया कम्पनी (East India Company) थी। हडसन बे कम्पनी (Hudson's Bay Company) 1670 में हडसन की खाड़ी वाले क्षेत्र में व्यापार के लिए स्थापित की गयी। दक्षिण अमरीका के साथ व्यापार करने के लिए 1711 में साउथ सी कम्पनी (South Sea Company) की गठित किया गया। ये कम्पनियाँ 17वीं सदी में अपनी मालिक आप थी किन्तु 18वीं सदी में इनका पतन हो गया।

ब्रिटिश साहसिकता (adventurism) का प्रसिद्ध लेखक जी० डब्लू० साउथगेट ने बहुत अच्छा चित्रण किया है¹ वे लोग जिनके कि पुरखे घरों में रहकर जानवर चराने का काम करते थे और जो यह सोचते थे कि उनका द्वीप सभ्यता के केन्द्र से बहुत दूर है, इस तथ्य के प्रति जागरूक बने कि दुनिया के बारे में जितना पता चला है दुनिया उससे कहीं अधिक बड़ी है, और यह भी कि इसमें बहुत से अजीबगरीब देश मौजूद हैं और बहुत-सी आश्चर्यजनक चीजें विद्यमान हैं जो खोजे जाने की प्रतीक्षा में हैं तथा वे लोग खोज का यह कार्य करने के लिए उत्तम स्थिति में हैं। इस तरह अंग्रेजों के मस्तिष्क में जोखिम उठाने की एक ऐसी भावना भर गयी जो उसने वाद कभी नहीं मरी। इंग्लैंड के जहाजों ने साहसिक यात्राएँ की, और ट्यूडर (Tudor) युग समाप्त होने से पहले ही अंग्रेज सारी धरती की परिक्रमा कर चुके थे।

उन्नीसवीं तथा बीसवीं सदी में ब्रिटिश विदेश व्यापार में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। उसके परिमाण में अत्यधिक वृद्धि हुई है। विश्व व्यापार में उसका सापेक्ष भाग 1876-80 के 38% से घटकर 1913 में 27% के करीब आ गया था। किन्तु निरपेक्ष रूप में ब्रिटिश विदेश व्यापार ने 1913 में अपना चरमबिन्दु छू लिया था जब वह 1295 मिलियन पाउंड पहुँच गया। ब्रिटिश विदेश व्यापार में आयात निर्यातों के मुकाबले हमेशा अधिक रहे हैं क्योंकि जनसंख्या में वृद्धि होते चले जाने के साथ खाद्यपदार्थों के आयातों की आवश्यकता बढ़ती चली गयी है। अपने दृश्य

निर्यातों पर दृश्य आयातों के आधिक्य (excess of visible imports over exports) के कारण इंग्लैंड भुगतान के लिए अपनी अदृश्य आय (invisible earnings), जो उसे जहाजी भाडों, बीमा कंपनियों व वैविध सेवाओं से मिलती रही है, का उपयोग करता रहा है।

ब्रिटिश विदेश व्यापार की सरचना में भी काफी परिवर्तन आया है। 1820 से 1920 की सौ सालों की अवधि में कच्चे माल के आयात में 15 गुना वृद्धि हुई। उसके निर्यात तो प्रारम्भ से ही मुख्यतः निर्मित माल के रहे। 1815 में भी ब्रिटेन के निर्यातों में तीन-चौथाई भाग तैयार माल का था। 1914 में वे धीरे-धीरे घटकर 50 प्रतिशत तक आ गये क्योंकि इस बीच इजीनियरिंग तथा रासायनिक चीजों का भाग बढ़ चुका था।

दो विश्व-युद्धों में विदेश व्यापार

ब्रिटिश विदेश व्यापार को पहला गहरा धक्का प्रथम विश्व-युद्ध से लगा। प्रथम विश्व-युद्ध के बाद दो शक्तिशाली प्रतिद्वन्द्वियों—अमरीका व जापान—के मैदान में आ जाने से विश्व व्यापार में ब्रिटेन का भाग काफी घट गया। इन दो देशों के अतिरिक्त कनाडा तथा आस्ट्रेलिया भी आगे आ रहे थे। इसके अलावा प्रथम युद्ध के समाप्त होने के तुरन्त बाद अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के कुल परिमाण में कमी भी आ रही थी। यह स्थिति तब और भी शोचनीय हो गयी जब 1930 की महान् मन्दी ने दुनिया को, जैसे बदला लेने की भावना से, झकझोर दिया।

मन्दी के वर्षों में ब्रिटिश निर्यातों में भारी कमी आयी। यह गिरावट इतनी अधिक थी कि भौतिक अर्थों (physical terms) में तो 1914 में प्राप्त निर्यात स्तर वापस 1950 में जाकर ही प्राप्त किया जा सका। 1930 के बाद के वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में ब्रिटेन का भाग भी घटकर 10 प्रतिशत से भी कम रह गया था। द्वितीय विश्व युद्ध भी ब्रिटिश विदेशी व्यापार के लिए गहरा धक्का ही साबित हुआ। जब द्वितीय महायुद्ध समाप्त हुआ तो अमरीका का विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली देश के रूप में उदय हो चुका था।

ब्रिटेन ने 1945 के बाद निर्यात बढ़ाने के लिए आवश्यक कच्चे माल के आयातों को अधिमान (preference) देने की नीति अपना ली थी। ऐसा करने से अगले 7 वर्षों की अवधि में ब्रिटिश निर्यातों में लगभग 60 प्रतिशत की वृद्धि हुई। युद्धोत्तरकाल के वर्षों में जहाँ एक ओर परम्परागत वस्तुओं के निर्यात में कमी की प्रवृत्ति जारी रही, इजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यात में भारी वृद्धि होती चली गयी। इसका परिणाम यह हुआ कि जहाँ सूती वस्त्र तथा जहाजों के निर्यात में कमी आई है, वहीं बिजली के उपकरणों, मोटर कारों, हवाई जहाजों तथा रसायनों के निर्यात बढ़ गये हैं।

विश्व निर्यात बाजार में नवीनतम प्रवृत्ति यह देखने में आयी है कि औद्योगिक राष्ट्र भी भारी मात्रा में मशीनों तथा इजीनियरिंग सामानों का आयात करने लगे हैं। यहाँ तक कि अमरीका भी ऐसी चीजें निरन्तर खरीद रहा है। अपने आपको

अच्छी स्थिति में रखने के उद्देश्य से अब ब्रिटेन ने भी यूरोपीय साक्षा वाजार की सदस्यता स्वीकार कर ली है। इसी का नतीजा है कि अब ब्रिटेन में बनी चीजें पश्चिमी जर्मनी द्वारा भी खरीदी जा रही हैं।

अधिकांश ब्रिटिश विदेशी व्यापार निजी फर्मों द्वारा चलाया जाता है जिनका संचालन निर्यातक व्यापारी (export merchants) करते हैं। ये निजी फर्म अपनी चीजें अपने प्रतिनिधियों की भाँत में सम्बन्धित देशों में भेजती हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तो देश का सम्पूर्ण विदेश व्यापार एक बार तो सरकार ने अपने हाथों में ही ले लिया था। किन्तु पुनः एक बार उसे निजी फर्मों के हाथों में सौंप दिया गया। अनेकों तटकरो तथा प्रतिबन्धित व्यावसायिक गतिविधियों, जिन पर युद्ध के दौरान प्रतिबन्ध लगा दिया गया था, को युद्ध समाप्त होने के बाद वापस हटा दिया गया या उनमें ढील दे दी गयी। कुछ अधिक महत्वपूर्ण विनिमय नियन्त्रण के उपायों (Exchange Control Measures) को जिन्हें कि युद्ध के दौरान लागू किया गया था, 1947 के विनिमय नियन्त्रण कानून (Exchange Control Act) में स्थायी रूप से सम्मिलित कर लिया गया।

विदेश व्यापार बढ़ाने के उपाय

(1) ब्रिटिश सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा 'गाट' (General Agreement on Trade and Tariff) की सदस्यता स्वीकार करने के बाद कुछ आयातों पर लगे हुए प्रतिबन्धों को हटाने के लिए कदम उठाये थे। इन वस्तुओं का आयात करने के लिए निश्चित मात्राएँ (Quota) तय कर दी गयी थी। लेकिन स्टॉलिंग क्षेत्र के बाहर के देशों को किये जाने वाले अनेक निर्यातों तथा कुछ अन्य देशों से किये जाने वाले आयातों पर प्रतिबन्ध अभी तक लगे हुए हैं।

(2) बोर्ड ऑफ ट्रेड (Board of Trade), जिसे आयातों व निर्यातों को प्रतिबन्धित करने व नियमित करने का अधिकार प्राप्त है, भी निर्यात सबर्द्धन में सहायता करता है। अधिकांश राष्ट्रकुल देशों (Commonwealth Countries) में व्यापार आयुक्त (Trade Commissioners) नियुक्त किये गये हैं जो बोर्ड ऑफ ट्रेड के प्रति उत्तरदायी हैं। उनका काम इन राष्ट्रकुल के देशों में ब्रिटिश निर्यातकों की सहायता करना है।

(3) एक अन्य महत्वपूर्ण संस्था जिसे विदेशी विपणन निगम (Overseas Marketing Corporation) के नाम से जाना जाता है, 1967 में स्थापित की गयी थी जो ब्रिटिश निर्यातकों की नये बाजारों की खोज करने में सहायता करती है।

(4) निर्यात सबर्द्धन के लिए अन्य महत्वपूर्ण संस्थाओं में निर्यात साक्ष गारण्टी विभाग (Export Credits Guarantee Department), पश्चिमी गोलार्द्ध निर्यात समिति (Western Hemisphere Exports Council), तथा यूरोपीय देशों के लिए निर्यात परिषद् (Exports Council for Europe) सम्मिलित हैं। राष्ट्रकुल के देशों में ब्रिटिश वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने के उद्देश्य से 1964 में

एक राष्ट्रमण्डल निर्यात परिषद् (Commonwealth Export Council) भी गठित की गयी थी ।

यह ब्रिटेन जैसे लघुकाय राष्ट्र के लिए बड़े गर्व की बात है कि विश्व जनसंख्या में उसकी आबादी 2 प्रतिशत के लगभग होने पर भी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में उसका भाग 1979 में भी 10 प्रतिशत के लगभग है । ब्रिटिश अर्थव्यवस्था में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का कितना महत्वपूर्ण स्थान है यह तो इसी से स्पष्ट हो जाता है कि 1977 के राष्ट्रीय उत्पाद में निर्यातित वस्तुओं का भाग 30% था ।¹ विश्व व्यापार में आज भी ब्रिटेन का स्थान (1979 में) पाँचवाँ है । 1977 में ब्रिटेन ने विश्व भर में खरीदे गये कच्चे माल का लगभग 9 प्रतिशत खरीदा व लगभग इतना ही निर्मित माल दुनिया के विभिन्न देशों को निर्यात किया ।

¹ Britain 1977, *An Official Handbook*, 190

था। हवाई-अड्डों को भी राष्ट्रीयकृत कर दिया गया। नागरिक उड्डयन मंत्री (Civil Aviation Minister) को यात्री भाड़ों, यात्रा सुविधाओं, सुरक्षा आदि मामलों में सलाह देने के उद्देश्य से एक वायु यातायात सलाहकार परिषद् गठित की गई।

(6) लोहा व इस्पात का राष्ट्रीयकरण—अनुदार दल ने इस कदम का डट कर विरोध किया। सरकार ने भी पहले तो कुछ हिचकिचाहट प्रदर्शित की किन्तु बाद में इसे भी राष्ट्रीयकृत करने का निर्णय ले लिया गया।

(7) दूर संचार साधनों पर राज्य का स्वामित्व—लेबर दल की सरकार का मत था कि दूर संचार (Telecommunications) के साधनों पर सरकार का ही स्वामित्व होना चाहिये। यह अब तक केवल एण्ड वायरलेस लिमिटेड के हाथ में थे। सरकार ने अनाधारियों को क्षतिपूर्ति की रकम देकर कम्पनी की शेयर पूंजी पर अपना वर्चस्व स्थापित करने का निर्णय किया। इन सारे सगठन को पोस्ट-मास्टर जनरल के नियन्त्रण में रख दिया गया।

समाज सुधार की योजनाएँ (Social Amelioration Schemes)

लेबर दल की सरकार ने अपने आप को मुख्य उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने तक ही सीमित नहीं रखा। निम्न मुख्य विधेयक पारित किये गए—

(1) परिवार भत्ता विधेयक, 1945—इस विधेयक द्वारा स्कूत जाने वाले बच्चों के परिवार में मा को साप्ताहिक भत्ता देने का प्रावधान किया गया।

(2) राष्ट्रीय बीमा योजना, 1946—इस विधेयक में घायल हो जाने वाले श्रमिकों के लिए अधिक मुआवजे की व्यवस्था तथा उनकी मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रितों को अधिक मुआवजा देने का प्रावधान किया गया।

(3) अन्य समाज सुधार विधेयक—राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा विधेयक 1946 में पारित किया गया। उसी वर्ष एक और राष्ट्रीय बीमा विधेयक (National Insurance Act) भी पारित किया गया। 1948 में राष्ट्रीय सहायता विधेयक (National Assistance Act) भी पारित किया गया।

दोसवीं शताब्दी के दौरान इंग्लैंड में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह रही कि इस अवधि में आर्थिक गतिविधियों में राज्य का नियन्त्रण निरन्तर बढ़ता चला गया है। यह समझ में न आने वाली बात थी कि युद्ध के दौरान राष्ट्रीय आर्थिक जीवन के प्रत्येक पहलू पर राज्य का नियन्त्रण होना चाहिए था और किसी ने इसका विरोध भी नहीं किया। किन्तु 1945-51 के वर्षों के दौरान लेबर दल की सरकार द्वारा कुछ मुख्य उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने के लिए उठाये गए कदमों का कजरवेटिव दल ने जोरशार विरोध किया।

किन्तु राजकीय नियन्त्रण में उत्तरोत्तर वृद्धि की प्रवृत्ति इतनी मजबूत बन चुकी थी कि 1951 में जब पुनः एक बार कजरवेटिव दल की सरकार सत्ता में लौटी तो सर विंस्टन चर्चिल के नेतृत्व वाली इस सरकार ने भी अपनी पहले वाली सरकार की नीतियों को उलट देने का काम नहीं किया। इसने कुछ परिवर्तन अवश्य किये जैसे

लोहा व इस्पात उद्योग के राष्ट्रीयकरण को रद्द कर दिया गया तथा इस उद्योग को आयरन एण्ड स्टील बोर्ड के सामान्य निरीक्षण में रख दिया। इसी तरह सड़क परिवहन भी निजी क्षेत्र को लौटा दिया गया। पाँच यातायात कार्यकारियों (Five Transport Executives) को समाप्त कर दिया गया तथा उनका काम यातायात आयोग को स्थानान्तरित कर दिया गया। किन्तु कजरवेटिव दल की सरकार ने लेबर दल की सरकार द्वारा उठाये गये सामाजिक उपायों को उलट-पुलट नहीं किया। ये उपाय दलीय हितों से ऊपर माने गये। युद्ध के ही वर्षों में ब्रिटिश प्रधानमन्त्री ने लॉर्ड बेवेरिज को सामाजिक सुरक्षा का एक व्यापक कार्यक्रम तैयार करने के लिए आमन्त्रित किया था तथा उनकी वह योजना 1948 से अस्तित्व में आ चुकी थी।

युद्धोत्तरकालीन नियन्त्रण (Post-war Controls)

(1) लगान—प्रथम विश्व युद्ध के समय से ही लगान व भाडों पर नियन्त्रण लगे हुए थे। किन्तु यह एक पेचीदा व्यवस्था थी। 1957 में तत्कालीन कजरवेटिव दल की सरकार ने इनको आंशिक रूप से नियन्त्रण से बाहर कर दिया।

(2) भवनों पर नियन्त्रण—युद्ध में हुई तबाही के कारण लाखों लोग बेघर हो गये थे। उधर भवन बनाने के लिए आवश्यक सामग्री की कमी थी। यह माना गया कि मकानों का निर्माण अन्य भवनों के पुनर्निर्माण से अधिक जरूरी है। 1956 के बाद यह स्थिति काफी सुधर चुकी थी तथा अन्य भवनों के निर्माण की अनुमति भी दी जाने लगी थी।

(3) अनाज राशनिंग की समाप्ति—युद्ध के प्रारम्भिक वर्षों में खाद्य पदार्थों की कमी हो जाने से उनका राशनिंग करना अनिवार्य हो गया था। खाद्य मन्त्रालय ने अनेक खाद्य पदार्थों के मूल्य निश्चित कर दिये थे तथा उन्हें सन्ना रखने के लिए अनुदान भी दिये थे। किसानों को उत्पादन बढ़ाने के लिए भी अनुदान देने की व्यवस्था की गयी। खाद्य पदार्थों पर से राशनिंग व्यवस्था 1954 में हटा ली गयी। 1954 में खाद्य मन्त्रालय भी समाप्त कर दिया गया तथा उसके काम कृषि मन्त्रालय को हस्तांतरित कर दिये गए।

(4) पेट्रोल व विदेश यात्रा पर से प्रतिबन्धों का हटाया जाना—लोगों द्वारा उपयोग किये जाने वाले पेट्रोल पर युद्ध के वर्षों में प्रतिबन्ध लगाये गये थे इन्हें 1950 में हटा लिया गया। विदेश यात्रा के लिए दिया जाने वाला भत्ता भी 1954 के बाद काफी बढ़ा दिया गया।

(5) औद्योगिक व व्यावसायिक गतिविधियों पर छूट—शेयर पूंजी के निर्गमन पर युद्ध के दौरान प्रतिबन्ध लगा दिये गये थे। नई तथा पहले से विद्यमान कम्पनियाँ पहले सरकारी अनुमति प्राप्त करने के बाद ही शेयर जारी कर सकती थीं। कई कम्पनियों के लिए कच्चे माल का आयात बरने के लिए सरकारी अनुमति प्राप्त करना भी कठिन बन गया था। 1953 में इन प्रतिबन्धों में कुछ ढील दी गई तथा वर्ष भर में कुल मिलाकर 50 000 पौंड में अधिक के शेयर जारी करने पर ही सरकारी अनुमति लेना आवश्यक रखा गया। एक के बाद एक, कच्चे माल के आयात

पर लगे हुए प्रतिबन्धों को भी, जैसे-जैसे स्थिति में सुधार हुआ, हटा लिया गया। अखबारी कागज की राशनिंग के रूप में लगा हुआ अन्तिम प्रतिबन्ध भी 1957 में हटा लिया गया।

एकाधिकारिक प्रवृत्तियों का विकास अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक माना गया। 1948 में एक एकाधिकारी एवं प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रथाएँ विधेयक (Monopolies and Restrictive Trade Practices Act) पारित किया गया जिसके अन्तर्गत एक एकाधिकार आयोग (Monopolies Commission) की स्थापना की गयी। इस आयोग को उद्योग तथा व्यापार के क्षेत्र में एकाधिकार स्थापित करने की शिकायतों पर विचार करने का अधिकार प्रदान किया गया। यदि यह पाया जाता कि कोई एक फर्म किसी उद्योग विशेष में हो रहे उत्पादन के एक-तिहाई से अधिक भाग पर नियन्त्रण करती है, तो आयोग उस मामले को बोर्ड ऑफ ट्रेड के सामने रखने के लिए बाध्य था। इस प्रकार के एकाधिकार को रोकने के लिए नियम बनाये जा सकते थे।

औद्योगिक कुशलता को बढ़ाने की दृष्टि से 1947 के औद्योगिक विकास एवं संगठन अधिनियम के अन्तर्गत विकास परिषदें (Development Councils) गठित करने का निषेध किया गया। इन परिषदों के सदस्यों में मालिकों, मजदूरों व आम जनता के प्रतिनिधि होते थे। शोषित श्रमिकों (Sweated labour) की प्रथा को जाँच पड़ताल करने तथा वेतन वृद्धि की उचित मांगों पर विचार करने के उद्देश्य से मजदूरी परिषदें (Wage Councils) भी गठित की गयी। इन मजदूरी परिषदों द्वारा इनसे पहले 1909 व 1918 में स्थापित ट्रेड बोर्डों (Trade Boards) का स्थान लिया जाना था।

व्यापार सन्तुलन (Balance of Trade)

युद्ध से पहले इंग्लैंड के दृश्य आयात (visible imports) हमेशा ही उसके दृश्य निर्यातों (visible exports) से अधिक होते थे। ऐसी स्थिति में सन्तुलन की स्थापना उसके अदृश्य निर्यातों (invisible exports) में प्राप्त होने वाली राशि, जिसमें विदेशों में किये हुए ब्रिटिश पूँजी विनियोग पर मिलने वाला ब्याज व लाभांश (interest and dividend), ब्रिटिश जहाजी कंपनियों की आय, ब्रिटिश बीमा कंपनियों द्वारा अर्जित लाभ तथा ब्रिटिश बैंकों द्वारा ससार भर में अपनी सेवाएँ देने के स्थान पर मिलने वाली कटौती-रकम (discount) सम्मिलित थी, से किये जाते थे। युद्ध के बाद युद्ध के कारण पड़े वित्तीय भार तथा ब्रिटिश जहाजों व बड़े म आर्थी कमी ने मिलकर ब्रिटेन के इन अदृश्य निर्यातों (invisible exports) से प्राप्त होने वाली आय को काफी कम कर दिया। अब यह स्पष्ट हो चला था कि दृश्य आयातों व निर्यातों (visible imports and exports) के बीच का अन्तर केवल दृश्य निर्यातों में वृद्धि करके ही कम किया जा सकता है। निर्यातों को बढ़ाने की दृष्टि से अर्थव्यवस्था पर कई नियन्त्रण आरोपित किये गये। इस काम में इसलिए दोहरी कठिनाई हो रही थी कि युद्ध के परिणामस्वरूप अन्य अनेक देशों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा था

तथा वे ब्रिटिश वस्तुएँ खरीद पाने की स्थिति में नहीं रह गये थे। इसके अतिरिक्त आयातों पर लगे हुए प्रतिबन्धों तथा कोटा प्रणालियों (quota systems) के कारण भी निर्यात वृद्धि के मार्ग में रुकावट आती थी।

इस बीच दो ऐसी महत्वपूर्ण बातें हुईं जिन्होंने ब्रिटिश निर्यातों तथा उसकी भुगतान सतुलन की स्थिति की सहायता की। पहली घटना कनाडा व आस्ट्रेलिया जैसे राष्ट्र कुल के देशों से उसे उदार भेट व अनुदान के रूप में अनेक वस्तुएँ व रकम प्राप्त होना रही। दूसरी घटना जिसने ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में सहायता की, वह उसे अमरीका द्वारा मार्शल योजना (Marshall Plan) के अन्तर्गत दी गई भारी सहायता थी। इस तरह द्वितीय महायुद्ध के बाद के वर्षों में ब्रिटिश निर्यात व्यापार की नमृद्धि का युग 1957 के बाद आरम्भ हुआ।

किन्तु 1960 व 1970 के दशकों में ब्रिटेन के सामने अनेक वित्तीय व अन्य प्रकार के संकट आते रहे हैं। ऐसी सबसे पहली कठिनाई पाउंड स्टर्लिंग (Pound Sterling) के मूल्य में गिरावट के रूप में उपस्थित हुई। इसे निपटाने के लिए कई बार अवमूल्यन किये गये। दूसरी कठिनाई 1973 में तब उपस्थित हुई जब तेल उत्पादक एवं निर्यातक राष्ट्रों (O P E C) ने एक होकर तेल मूल्यों को तिगुना-चौगुना बढ़ा दिया। इन कठिनाइयों तथा और भी अनेक कठिनाइयों के बावजूद ब्रिटिश अर्थव्यवस्था का कार्य बुरा नहीं रहा है। अब वह एक कल्याणकारी राज्य (Welfare State) बन चुका है जो कभी उसके समाजवादी चिंतकों का स्वप्न रहा था अधिकांश आम लोग समृद्धि का जीवन जी रहे हैं तथा गरीबी को काफी सीमा तक घटा दिया गया है। ब्रिटिश शिक्षा व्यवस्था भी काफी फैल चुकी है। 1973 के बाद के पिछले चार-पाच वर्षों को अगर छोड़ दिया जाए तो ब्रिटिश अर्थव्यवस्था में बेकारी लगभग नहीं के बराबर रही है। ब्रिटिश अर्थव्यवस्था आज भी निर्यात-मुखी (export oriented) बनी हुई है। आज की दुनिया में मौजूद अनेकों बहुराष्ट्रीय निगम ब्रिटिश मूल के हैं।

ब्रिटिश उद्योगों ने वायुयान-निर्माण के क्षेत्र में भारी प्रगति की है (नवीनतम मॉडल कॉनकोर्ड का है) जिनमें अनेक प्रकार के विमान शामिल हैं। कारें बनाने व उनका निर्यात करने, विजली का साज-सामान बनाने, मोटर साइकिलें तैयार करने व युद्ध पोतों तथा व्यापारिक जहाजों का निर्माण करने में भी ब्रिटिश उद्योगों ने भारी उन्नति की है। औद्योगिक कार्यों के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग करने वाले विश्व के देशों में भी ब्रिटेन अग्रणी रहा है।

ब्रिटेन का यूरोपीय साक्षा बाजार (E C M) में प्रवेश

युद्धोत्तरकालीन वर्षों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण आर्थिक घटना ब्रिटेन द्वारा यूरोपीय साक्षा मण्डी (European Common Market) में प्रवेश की रही है। जबसे 1958 में यूरोपीय साक्षा मण्डी का गठन हुआ है तभी से आर्थिक प्रेक्षक इस मत के रहे कि ब्रिटेन का इस मण्डी में प्रवेश उसकी आर्थिक विरासत दर को तीव्र कर सकता है तथा उसके सामने मुँह बाएँ सड़े आर्थिक जड़ता के दुष्चक्र (vicious circle

of stagnation) को तोड़ने में भी सहायक हो सकता है। साझा बाजार गठित करने के उद्देश्य थे सदस्य देशों के बीच मौजूद व्यापार बाधाओं (Trade barriers) को हटाना, सामान्य कृषि एवं यातायात सम्बन्धी नीतियाँ तैयार करना, गैर सदस्य राष्ट्रों के साथ व्यापार करने के लिए एक ही नीतियाँ बनाना तथा साझा बाजार के सदस्य देशों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। साझा बाजार की स्थापना युद्ध के बाद अमरीकी अर्थव्यवस्था के भीमकाय हो जाने के कारण उत्पन्न हुई चुनौती का सामना करने की दृष्टि से भी अनिवार्य बन गई थी।

आरम्भ में ब्रिटेन ने यूरोपीय साझा बाजार में सम्मिलित होने का प्रस्ताव ठुकरा दिया क्योंकि वंसा करने पर शायद उसे राष्ट्रकुल (Commonwealth) छोड़ना पड़ता। इसके अतिरिक्त वह एक राष्ट्र के रूप में अपना स्वतन्त्र अस्तित्व भी बनाए रखना चाहता था। इसलिए साझा बाजार का सदस्य बनने की जगह सात देशों ने मिलकर एक प्रतिद्वंद्वी संगठन यूरोपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र (European Free Trade Area) का गठन किया। किन्तु जब यूरोपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र (E F T A) के तीन सदस्यों ने 1961-62 में यूरोपीय साझा बाजार की सदस्यता स्वीकार कर ली तो ब्रिटेन के सम्मुख पुनः साझा बाजार का सदस्य बनने न बनने की उलझन उठ खड़ी हुई। पश्चिमी जर्मनी की बढ़ती जा रही आर्थिक शक्ति का मुकाबला करने तथा अमरीका की आर्थिक सुदृढ़ता के मामले में ठहर पाने की दलीलों को लेकर कुछ प्रमुख अर्थशास्त्रियों द्वारा ब्रिटेन के साझा बाजार का सदस्य बन जाने का समयन किया। उनका मानना था कि अगर ब्रिटेन यूरोपीय साझा बाजार का सदस्य बन जाता है तो ब्रिटिश उद्योगों को काफी विशाल बाजार उपलब्ध हो जाएगा। इसके पक्ष में और भी कई आर्थिक तर्क प्रस्तुत किये गये। 'यूरोपीय साझा बाजार की सदस्यता इस तरह ब्रिटिश उद्योगों पर दो प्रभाव डालेगी। वह हमें अपने प्रयास उन चीजों पर केन्द्रित करने के लिए बाध्य कर देगी जिन्हें हम सबसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं और वह उन चीजों को हमारे द्वारा और भी अधिक कुशलतापूर्वक किये जाने को बढ़ावा देगी और इसलिए वह हमारे लिए अधिक लाभ का सौदा भी रहेगा। अन्त में जाकर हम आर्थिक दृष्टि से लाभ में रहेगे या हानि में, यह दो बातों पर निर्भर करेगा वह दर जिसके हिसाब से सम्पूर्ण यूरोपीय साझा बाजार में वस्तुओं के लिए मांग बढ़ेगी तथा अन्य यूरोपीय प्रतिद्वंद्वियों (Continental Rivals) की तुलना में हमारे अपने उद्योगों की कार्य-क्षमता किन्तु यूरोपीय साझा बाजार की सदस्यता स्वीकार कर लेने से हम कुछ हानि और कुछ लाभ होंगे लेकिन उससे अलग बैठे रहने से तो केवल हानि ही हानि होनी है।'।

किन्तु जो लोग ब्रिटेन द्वारा यूरोपीय साझा बाजार में प्रवेश का विरोध करने थे उनके द्वारा यह दलील दी गयी कि ऐसा करने से साच पदार्थ मँहगे हो जायेंगे क्योंकि फिर ब्रिटेन उन्हें यूरोपीय आर्थिक समुदाय (European Economic Community) से ही मँगवाने के लिए बाध्य हो जायेगा जबकि वे उसे अब तक राष्ट्रकुल के देशों से सस्ते मिलते रहे हैं और साच पदार्थ ब्रिटेन द्वारा आयातित वस्तुओं में काफी महत्वपूर्ण मद हैं। इसके अलावा ब्रिटिश नीतियों में राजकीय

नियमन (State Regulation) की आवश्यकता साझा बाजार के अन्य सदस्य देशों द्वारा अपनायी जाने वाली नीतियों के मुकाबले अधिक किया जाता है। अर्थशास्त्री आर० एफ० हेरोड (R. F Harrod) ने तर्क दिया कि यदि ब्रिटेन साझा बाजार को सदस्यता स्वीकार कर लेता है तो उससे राष्ट्रकुल के अर्द्ध-विकसित सदस्य देशों को हानि होगी।

साझा बाजार में प्रवेश

लेकिन इन साझा बाजार प्रवेश विरोधी तर्कों को अनदेखा करने हुए तथा अपने प्रवेश को लेकर फ्रांस द्वारा किये जा रहे प्रतिरोध को शान्त करते हुए अन्ततः 1 जनवरी 1973 को ब्रिटेन ने यूरोपीय साझा बाजार में प्रवेश कर लिया। ब्रिटेन द्वारा साझा बाजार की सदस्यता स्वीकार करने के बाद उसकी सदस्य सस्या नौ की हो चुकी है। अब सुविम्बृत यूरोपीय आर्थिक समुदाय की कुल जनसंख्या अमरीका तथा रूस, दोनों ही महाशक्तियों की आबादी से अधिक है। समुदाय अब विश्व की दूसरी बड़ी आर्थिक व औद्योगिक शक्ति बन गया है। पहला स्थान अभी भी संयुक्त राज्य अमरीका का है। विश्व व्यापार में यूरोपीय आर्थिक समुदाय का भाग, ब्रिटेन द्वारा उसकी सदस्यता स्वीकार कर लिये जाने के बाद, अब बढ़कर 40 प्रतिशत तक जा पहुँचा है।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय के ये नौ सदस्य देश अब अत्रिक नजदीकी राजनीतिक सम्बन्ध भी कायम करने की दिशा में प्रयत्नशील हैं। इन देशों के राज्याध्यक्ष समय-समय पर मिलते रहकर आपसी समस्याओं का निपटारा भी करते रहते हैं तथा भावी नीति की रूपरेखा भी तैयार करते हैं। संयुक्त यूरोप (United Europe) का विचार अब कोई असम्भव बात नहीं रह गयी है। ब्रिटेन का भाग्य भी अब समुदाय के भाग्य के साथ जुड़ गया है।

ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के सामने मुख्य समस्याएँ

(1) मुद्रा स्फीति—भजदूरी, मूल्य तथा आय पर नियन्त्रण रखने के अपने समस्त प्रयासों के बावजूद ब्रिटिश अर्थव्यवस्था में, विशेष रूप से 1973 की तेल मूल्य वृद्धि के बाद, स्फीति की गति अनियन्त्रित-सी हो गयी है। इंग्लैण्ड के समुद्र तट पर खनिज तेल की नई खोज, जिनसे कि 1980 तक देश के आत्मनिर्भर हो सकने की सम्भावनाएँ व्यक्त की जा रही हैं, से कुछ आशा बनती है।

(2) विकास की दर में तेजी लाना—इस काम के लिए उत्पादकता में भारी सुधार तथा औद्योगिक कार्य कुशलता में भारी वृद्धि की आवश्यकता है। यह एक आम शिकायत है कि ब्रिटिश उद्योग अपने आपसे सन्तुष्ट हैं तथा वह अपनी प्रगति की धीमी दर के बारे में विशेष चिन्तित नहीं हैं। शायद 1950 के बाद के अनेक वर्षों तक जड़ता की स्थिति में रहने (ब्रिटिश अर्थव्यवस्था) के पीछे यही कारण रहा था।

(3) प्रतिकूल भुगतान सन्तुलन—ब्रिटिश निर्यातों में तीन प्रतिशत वार्षिक

से भी कम की दर से वृद्धि हो रही है जबकि उसके आयात 4 प्रतिशत से भी अधिक बढ़ रहे हैं। इस प्रकार आयात व निर्यात के बीच इस अन्तर ने व्यापार घाटे को काफी गम्भीर बना दिया है। इस स्थिति को स्थायी रूप से ठीक करने के लिए ब्रिटिश निर्यातों की प्रतिस्पर्धात्मकता (competitiveness) को काफी हद तक बढ़ाना जरूरी हो गया है।

(4) बेकारी व श्रम असन्तोष—1970 के दशक के आरम्भ से ही ब्रिटिश अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की एक नई लहर आने लगी थी। एक समय तो यह बेकारी कुल रोजगार का 8 प्रतिशत से भी अधिक हो गयी थी। इस समस्या के साथ एक और समस्या भी जुड़ गयी और वह थी मजदूरी बढ़ाने की मांगों को लेकर की जाने वाली हड़तालों के कारण पैदा हो रहे श्रम असन्तोष की समस्या। 1976 के बाद मजदूरी का जमा देने (Wage Freeze) के प्रयास किये गये। 20 जुलाई 1977 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री जेम्स कैनेहन (James Callaghan) ने हाऊस ऑफ कॉमर्स को सूचित किया कि औद्योगिक अस्थानि की एक नई स्थिति उत्पन्न हो गयी है। ऐसा शायद इसलिए हुआ है कि '1978 के बाद देश में कहीं भी किमी वेतन-वृद्धि को लागू नहीं किया जाएगा' यह कि इस प्रकार सरपट दौड़ते हुए वेतन-वृद्धि निर्णयों से देश में मूल्य वृद्धि के एक नये दौर की शुरुआत हो जायेगी। 1975 में 30 प्रतिशत से भी अधिक की बेहूदा (absurd) वेतन वृद्धियों की याद अभी भी हमारे मस्तिष्क में ताजा है जिन्हें हमने स्वीकार किया था किन्तु जो उन लोगों के जीवन-स्तर को सुधारने में असफल रही जिन्होंने उन्हें पा लिया था।'

प्रधानमंत्री कैनेहन ने आगे कहा कि '1973 के तेल संकट तथा उसके परिणामस्वरूप हुई अभूतपूर्व मूल्य वृद्धियां ने इस देश की परिस्थितियों में अन्य देशों की ही भांति आधारभूत परिवर्तन किये हैं हम अपना जीवन स्तर अपने स्वयं के प्रयासों द्वारा ही सुधारने की सम्भावनाओं पर ध्यान देना चाहिए।' साथ ही, 'मावजनिक श्रम की किसी भी शाखा में अत्यधिक मजदूरी का' अर्थव्यवस्था के शेष भाग पर प्रभाव पड़े बिना नहीं रहेगा उनके परिणामस्वरूप मूल्यों में वृद्धि होगी—जो स्फोटिक विरुद्ध किये जा रहे संघर्ष पर एक प्रत्यक्ष चोट होगी। मैं मौजूदा मुश्किलों को कम बताने की चेष्टा नहीं कर रहा हूँ, 1974 में प्रसारित लेबर दल के चुनाव घोषणा पत्र में बतायी गयी मुश्किलों से बिल्कुल भी कम नहीं, जबकि देश के सामने पिछले जनेब वर्षों की तुलना में सबसे गम्भीर संकट उपस्थित हो गया था।'

'हमारा समाज एक ऐसा समाज होगा जिसमें जिनके पास साधन हैं वे उनका त्याग करेंगे ताकि उन्हें उन लोगों को उपलब्ध कराया जा सके जिनके पास कुछ भी नहीं है। मेरा विश्वास है कि हमारा समाज ब्रिटेन के औद्योगिक भविष्य के लिए एक आधार प्रदान करने में सक्षम होगा तथा हमें संपुक्त प्रयासों द्वारा हमारे अपने ही राष्ट्र व निर्माण के काम को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए योग्य बनायेगा।'

आर्थिक आयोजन की ओर

द्वितीय महायुद्ध के बाद ब्रिटेन धीरे-धीरे अपनी अर्थ-व्यवस्था के नियोजित

विक्रम की ओर अग्रसर होता रहा है। देश के आर्थिक मामलों की नियोजित रूप से प्रगति को प्रोत्साहित करने के लिए अनेकों विभाग तथा संस्थाएँ स्थापित की गयी हैं। 1961 में राष्ट्रीय आर्थिक विकास परिषद् (National Economic Development Council) की स्थापना की गयी ताकि वह निजी व सरकारी क्षेत्र में चल रही प्रवृत्तियों की जांच पड़ताल करे। राष्ट्रीय आर्थिक विकास परिषद् को उन फलदायी उपायों का सुझाव देने की जिम्मेदारी भी सौंपी गयी जिनसे विदेश के संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग किया जा सकता था। 1964 में परिषद् का स्वरूप पूरी तरह से बदल दिया गया तथा उसे उद्योगों के सर्वांगीण विकास के लिए एक योजना बनाने तथा उसे लागू करने का काम सौंपा गया। अपनी स्थापना के बाद से ही अर्थव्यवस्था की कार्यशीलता पर अनेक आर्थिक प्रतिवेदनों का प्रकाशन कर परिषद् ने अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

दूसरी महत्वपूर्ण आयोजन संस्था आर्थिक मामलों का विभाग (Department of Economic Affairs) है जिसे 1964 में स्थापित किया गया था। इसके कार्य आयोजन से सम्बन्धित गतिविधियों का समन्वय करना तथा उनकी निगरानी (supervision) करना है। उद्योगों, आमदनियों तथा मूल्यों के बारे में नीतियों का निर्धारण करते समय यह विभाग नियोजकों व कर्मचारियों, दोनों ही के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर मुद्दे तय करता है। इस विभाग के पाँच उपखण्ड हैं

- (i) आर्थिक आयोजन खण्ड
- (ii) आर्थिक समन्वय खण्ड (घरेलू),
- (iii) आर्थिक समन्वय खण्ड (वैदेशिक),
- (iv) क्षेत्रीय नीति खण्ड,
- (v) औद्योगिक नीति खण्ड।

पिछले कुछ वर्षों से क्षेत्रीय नियोजन (regional planning) पर काफी ज़ोर दिया जा रहा है। इस कार्य के लिए क्षेत्रीय आर्थिक आयोजन बोर्ड (Regional Economic Planning Boards) गठित किये गये हैं। चिन्तु यहाँ यह समझ लेना महत्वपूर्ण है कि आयोजन को बजट उपायों (budgetary measures) तक ही सीमित रखा गया है तथा ब्रिटिश अर्थव्यवस्था मूल रूप से अभी तक भी मुक्त अर्थव्यवस्था (free economy) बनी हुई है।

दसवाँ अध्याय

आधुनिक अर्थव्यवस्था (THE MODERN ECONOMY)

ब्रिटिश अर्थव्यवस्था¹ को उसके राष्ट्रीय उत्पाद में निर्मित माल उद्योग (manufacturing) तथा सेवाओं² (services) से जाना जा सकता है जिनका कि कुल घरेलू आय में भाग क्रमशः 30 से लेकर 45 प्रतिशत तक आना है तथा उसे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण होने से भी जाना जाता है। वस्तुओं व सेवाओं का निर्यात कुल घरेलू उत्पादन (Gross Domestic Product) का 30 प्रतिशत के लगभग है। ब्रिटेन विश्व व्यापार में पाचवें स्थान पर है (अमरीका, पश्चिमी जर्मनी, जापान तथा फ्रांस के बाद) तथा बाजार अर्थव्यवस्थाओं (market economies) के बीच हो रहे कुल व्यापार में उसका हिस्सा 6 प्रतिशत के लगभग आता है। इंग्लैंड दुनिया भर में निर्यात होने वाली प्राथमिक वस्तुओं (primary products) में से लगभग 9 प्रतिशत भाग खरीदता है तथा निर्मित माल के प्रमुख निर्यातक देशों द्वारा तैयार माल के निर्यातों में भी उगता योगदान 9 प्रतिशत के लगभग है।

1976 में उत्तरी समुद्री तट पर तेल व प्राकृतिक गैस की खोज का देश की अर्थव्यवस्था पर आधारभूत प्रभाव पड़ रहा है। यह खोज वास्तव में इतनी दूरगामी है कि 1980 के बाद यह ब्रिटेन को विश्व का प्रमुख खनिज तेल उत्पादक देश बना सकती है।

कृषि उत्पादकता

कृषि में विद्यमान उत्पादकता के अत्यधिक उच्च स्तर के कारण ब्रिटेन अपनी साध्य आवश्यकता का आधे से कुछ अधिक अपनी भूमि से ही पूरा कर लेता है जबकि उसकी कुल वार्षिक जनसंख्या का केवल 2.7% भाग खेती के काम में लगा हुआ है। कृषि में जनसंख्या का यह अनुपात विश्व के किसी भी अन्य औद्योगिक देश की तुलना में कम है। शेष कृषि पदार्थों का आयात किया जाता है और ब्रिटेन गेहूँ, मांस, मक्खन, पशुओं का चारा, फल, चाय, तम्बाकू तथा ऊन जैसी चीजों के विश्व के सबसे बड़े आयातकों में से है। उसके अन्य आयातों में कच्चा माल (जैसे कच्ची धातुएँ, कूड

¹ Britain 1977, *An Official Handbook*, 190-202

² इन सर्वभ में सेवाओं में यातायात, सव्येणवाहन, विनरणात्मक व्यापार, बीमा, बैंकिंग, वित्तीय एवं व्यावसायिक सेवाएँ, जनस्वास्थ्य, शिक्षा व अन्य सेवाएँ (लोक प्रजामन रक्षा तथा मजानों के स्वामित्व के अलावा) सम्मिलित की गई हैं।

ऑयल तथा इमारती लकड़ी) अर्द्ध निर्मित वस्तुएँ (जैसे रसायन, सूती धागे) व कुछ निर्मित वस्तुएँ भी सम्मिलित हैं।

ब्रिटेन अपनी विदेशी मुद्रा निर्मित माल के निर्यात तथा अदृश्य लेन-देन (invisible transactions) जैसे विदेशी विनियोग से प्राप्त आय, यात्रा, नागरिक उड्डयन, ब्रिटिश अधिकार वाले जहाजों, वित्तीय, बैंकिंग, बीमा कम्पनियाँ व अन्य सेवाओं से प्राप्त आय से अर्जित करता है। ब्रिटेन सप्ताह के विमानों, मोटर कारों, बिजली के साज-सामानों, तैयार सूती वस्त्रों तथा अनेक प्रकार की मशीनों का निर्यात करने वाले सबसे बड़े देशों में से एक है। ब्रिटेन में प्रति व्यक्ति कुल घरेलू उत्पाद में 1965 से 1975 की दस वर्षों की अवधि में 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

ब्रिटिश भुगतान मतुलन में अदृश्य निर्यातों (invisible exports) के द्वारा किये जाने वाले भारी योगदान से यही सिद्ध होता है कि ब्रिटेन अभी भी विश्व का प्रमुख वित्तीय केन्द्र बना हुआ है। उसके बैंक, बीमा लेखाकार (insurance underwriters), दलाल व अन्य अनेक वित्तीय संस्थाएँ अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं। लन्दन शहर में शायद दुनिया की सबसे आधुनिक व विशाल मण्डी उपलब्ध है।

अर्थव्यवस्था की पिछली विकास उपलब्धियाँ

अठारहवीं व उन्नीसवीं सदी में हुई औद्योगिक क्रांति के परिणामस्वरूप ब्रिटेन विश्व के पहले औद्योगिक राष्ट्र के रूप में तथा यातायात के नये साधनों, सदेशवाहन व तकनीकी के क्षेत्र में अगुवा राष्ट्र के रूप में उभरा। विश्व भर में निर्माता, व्यापारी, बैंकर तथा विनियोजक के रूप में उसने नेतृत्व की स्थिति प्राप्त की तथा अपनी तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या की अर्थव्यवस्था का विकास तीव्र गति से कर सहारा दिया। 1870 से 1890 तक ब्रिटिश उद्योग स्पष्ट रूप से विश्व के किसी भी अन्य देश की तुलना में आगे रहे। 1890 से लेकर 1914 तक यूरोप के देशों व अमरीका के साथ प्रतिस्पर्धा अत्यधिक बढ़ चुकी थी किन्तु इस प्रतिस्पर्धा का ब्रिटेन पर कोई विशेष प्रभाव इसलिए नहीं पड़ा कि इस अवधि में विश्व व्यापार के परिणाम में अत्यधिक वृद्धि हो गई थी तथा इसके अतिरिक्त ब्रिटेन को उसके विदेशी विनियोगों पर भारी माना में प्रतिफल प्राप्त हो रहे थे।

प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त हो जाने पर ब्रिटेन के पुराने उद्योगों को अत्यधिक बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। उदाहरण के लिए, कोयला व लोहा उद्योग में यूरोप के साथ तथा सूती वस्त्र के उत्पादन में पूर्वी देशों के साथ उसका मुकाबला कड़ा रहा जहाँ थम सस्ती दरों पर उपलब्ध था। 1929 में आयी वार्षिक महान् मन्दी ने स्थिति को और भी कठिन बनाया इसके साथ ही सम्बन्धित देशों द्वारा आयात घटाने के प्रयासों से ब्रिटेन की कठिनाइयाँ और भी बढ़ गयीं। ब्रिटेन में इसका प्रभाव, जैसा कि उसके अन्य साथी देशों पर भी रहा, यह पड़ा कि वहाँ बेरोजगारी भयंकर रूप से बढ़ गयी।

1932 के बाद फिर एक बार उत्पादन व रोजगार के स्तर बढ़ने लगे। इसके

बाद वाले दशक में बाहनों, बिजली, रसायन व विमान निर्माण उद्योगों का तेजी के साथ विकास हुआ तथा देश में इन्हीं दिनों बने 30 लाख मकानों के कारण भवन निर्माण एवं सहायक उद्योगों में काफी तेजी आयी।

द्वितीय महायुद्ध व उसके बाद

द्वितीय विश्व-युद्ध के दौरान (1939-45) युद्ध प्रयासों को दृष्टिगत रखते हुए सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था में तीव्र एवं दूरगामी परिवर्तन किये गये तथा इसके लिए केन्द्रीय आयोजन का सहारा लिया गया। इस तरह अर्थव्यवस्था के विभिन्न त्रिधा-कलापों में जो राजकीय हस्तक्षेप अनिवार्य बन गया वह, कुछ सशोषकों के साथ, ब्रिटिश आर्थिक प्रणाली का स्थायी स्वरूप बन चुका है।

अमरीका व कनाडा द्वारा दी गई उदार सहायता के उपरान्त, जहाजों के तहम नहम हो जाने, बमबारी होने, औद्योगिक रख-रखाव तथा पुरानी या ध्वस्त हो चुकी मशीनों को बदलने की आवश्यकता के कारण ब्रिटेन की निजी घरेलू पूंजी में करीब 3,000 मिलियन पौण्ड की कमी आ गई थी। लगभग 1,000 मिलियन पौण्ड की लागत वाले विदेशी प्रतिष्ठानों को बेच दिया गया जिनमें से आधे उत्तरी अमरीका में थे। लगभग 3,000 मिलियन पौण्ड मूल्य के नये अन्तर्राष्ट्रीय ऋण लिये गये। इस बीच निर्यात काफी घट गये थे।

युद्ध समाप्त हो जाने के बाद जैसे-जैसे नागरिक उपभोग्य वस्तुओं का उत्पादन बढ़ा तथा व्यापार का पुनरुद्धार होने लगा बैसे-बैसे राशनिंग व अन्य नियन्त्रणों को ढीला किया गया। अधिकांश आयातों पर लगे हुए मात्रात्मक नियन्त्रणों (quantitative controls) को हटा लिया गया, स्टलिंग क्षेत्र तथा शेष विश्व के बीच व्यापार पर लगे हुए अधिकांश विनिमय नियन्त्रणों को भी हटा लिया गया तथा गैर ब्रिटिश नागरिकों के लिए भी चानू खाते में स्टलिंग को परिवर्तनशील (convertible) घोषित कर दिया गया।

आर्थिक प्रबन्ध (Economic Management)

अर्थव्यवस्था का संचालन करने के पीछे सरकार के निम्न उद्देश्य रहे हैं—

- (अ) सुस्थिर एवं निर्वाह योग्य (sustainable) विकास दर प्राप्त करना।
- (ब) निर्यातों व आय को बढ़ाना।
- (स) मजदूत भुगतान सन्तुलन की स्थिति बनाना।
- (द) ऊँचे स्तर का रोजगार-आधार बनाना।
- (य) धन का अधिक समान वितरण करना।

इन नीतियों को कार्यरूप में परिणित करने के काम का उत्तरदायित्व राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक उत्तरदायित्व वाले मुख्य सरकारी विभागों का है— राजकोष (Treasury), व्यापार विभाग, उद्योग विभाग, रोजगार विभाग, ऊर्जा, मूल्य, उपभोक्ता, सुरक्षा, पर्यावरण, यातायात विभाग व कृषि, मत्स्य तथा खाद्य मन्त्रालय।

सामान्य आर्थिक नीति निर्धारण के लिए एक प्रमुख सलाहकार संस्था राष्ट्रीय

आर्थिक विकास परिषद् (National Economic Development Council) है जिसमें सरकार, प्रवन्धकों तथा श्रम संघों के प्रतिनिधि प्रधानमन्त्री की अध्यक्षता में एकत्रित होते हैं। इस परिषद् का एक स्वतन्त्र यद्यपि सरकारी खर्च पर चलाया जा रहा सचिवालय है तथा इसने भिन्न-भिन्न उद्योगों से सम्बन्ध रखने वाली अनेक आर्थिक समितियाँ भी नियुक्त की हैं। ये समितियाँ सेवाओं तथा एक ही उद्योग के भिन्न भिन्न पहलुओं को भी देखती हैं। नीति निर्धारण के विशिष्ट पहलुओं पर सलाह देने के लिए बनायी गयी अन्य संस्थाओं में एकाधिकारिक शक्ति के दुरुपयोग पर रोक लगाने हेतु एकाधिकार एवं विलय आयोग (Monopolies and Mergers Commission) तथा जन-शक्ति अर्थशास्त्र कार्यालय (Office of Manpower Economics) सम्मिलित हैं।

मोटे तौर पर आर्थिक नीति का निर्धारण करने तथा मुद्रा स्फीति जैसी समस्या का मुकाबला करने के लिए सरकार अपने उद्देश्यों व उपायों को पहले से सार्वजनिक रूप से घोषित कर देती है। महत्वपूर्ण सार्वजनिक नीति सम्बन्धी विषयों पर सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था में चलने वाले घटनाक्रमों से अपने आपको अवगत बनाने के लिए सरकार मुराद औद्योगिक वित्तीय तथा श्रम हितों के साथ अनौपचारिक रूप से ही सही लेकिन बराबर सम्पर्क बनाये रखती है। किन्तु आर्थिक नीति को सुनिश्चित स्वरूप प्रदान करने का मुख्य उत्तरदायित्व अन्तिम रूप से मन्त्री परिषद् का ही रहता है।

क्षेत्रीय आर्थिक आयोजन मशीनरी

पर्यावरण के लिए राज्य मन्त्री (Secretary of State for Environment) पर इंग्लैण्ड के क्षेत्रीय आयोजन (regional planning) का भी दायित्व है। यह कार्य क्षेत्रीय आर्थिक आयोजन परिषदों तथा आर्थिक आयोजन बोर्डों की सहायता से किया जाता है। देश के आठ आर्थिक आयोजन क्षेत्रों में ऐसी एक परिषद् व एक बोर्ड बने हुए हैं। परिषदों में, जिनका काम सलाह देने का ही होता है, उस क्षेत्र के अनुभवों व्यक्तियों को सदस्य बनाया जाता है। वे मोटे तौर पर आर्थिक व भू-उपयोग सम्बन्धी नीतियाँ बनाने में सहायता करते हैं ताकि बाद में उस क्षेत्र की रूपरेखा (regional framework) को आधार मानते हुए राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्तर पर विनियोग सम्बन्धी निर्णय लिये जा सकें। बोर्डों में वरिष्ठ क्षेत्रीय सरकारी अधिकारी सदस्य होते हैं जिनका क्षेत्रीय आयोजन के विभिन्न पहलुओं से सम्बन्ध होता है। वे विभिन्न विभागों के क्षेत्रीय कार्यों का समन्वय भी करते हैं तथा परिषदों को सूचना एवं सलाह भी देते हैं।

स्कॉटलैण्ड में भी अलग से एक आर्थिक परिषद् (Economic Council) तथा आर्थिक आयोजन बोर्ड (Economic Planning Board) है। एक वेल्श परिषद् (Welsh Council) तथा वेल्श आयोजन बोर्ड भी बना हुआ है। उत्तरी आयरलैण्ड के लिए एक आर्थिक परिषद गठित की हुई है।

अर्थव्यवस्था का निर्देशन (Guidance)

इंग्लैण्ड में 1945 के बाद के वर्ष बढ़ते हुए उत्पादन के वर्ष थे तथा 1970 तक बेरोजगारी को स्तर भी बहुत नीचा (2.5 प्रतिशत या उससे भी कम) था। किन्तु आर्थिक विकास की दर जिसका कि औसत 1971 तक 2 से 3 प्रतिशत वार्षिक का रहा, अधिकांश पश्चिमी यूरोप के देशों की तुलना में नीची रही। इसके अतिरिक्त कुछ समस्याएँ निरन्तर बनी ही रही। उदाहरण के लिए, भुगतान सन्तुलन को लेकर मध्य-समय पर पैदा होने वाली कठिनाइयाँ, जो विशेष रूप से माँग वृद्धि के दबाव वाले वर्षों में तो बड़ी विकट हो गयी। अदृश्य निर्यातों द्वारा किये जाने वाले भारी योगदान के बावजूद चालू खाते में अनेक वर्षों तक काफी घाटा होता रहा।

1960 के दशक में तथा उसके बाद आने वाली सरकारों ने इन समस्याओं को अनेक तरीकों से हल करने की चेष्टा की। वही उन्होंने घरेलू माँग में होने वाली वृद्धि पर रोक लगायी तो कभी आय व मूल्य में होने वाली वृद्धियों को नियन्त्रित बनाने के लिए बनायी गयी नीतियों को क्रियान्वित किया। 1967 में स्टर्लिंग के अवमूल्यन के बाद, जब पाण्ड का मूल्य 2.80 डॉलर से घटाकर 2.40 डॉलर कर दिया गया था निर्यातों का कुछ उद्धार हुआ। इससे दृश्य निर्यातों से भी भारी अतिरिक्त मिलने लगा तथा 1971 में चालू खाते में रिकॉर्ड अतिरिक्त दिखाई दिया।

1973 में अर्थव्यवस्था ने 5 प्रतिशत की विकास दर प्राप्त कर ली। आर्थिक विकास की दर को बढ़ाने व बेकारी की दर घटाने के लिए 1971 के बाद अपनायी गयी सरकारी नीतियों का इसमें काफी योगदान रहा। लेकिन 1973 के अन्त में, जब विश्व में ऊर्जा संकट उत्पन्न हो गया, इंग्लैण्ड की आर्थिक विकास दर फिर घीमी हो गयी। 1974 में विश्व अर्थव्यवस्था ने अवसाद (recession) के चरण में प्रवेश किया जिसके मुख्य कारण सरपट दौड़ने वाली स्फीति व तेल मूल्यों में अप्रत्याशित वृद्धि रहे। ब्रिटिश अर्थव्यवस्था पर इन तत्वों का मुख्य प्रभाव 1975 के आरम्भ में दिखाई दिया, यह अन्य देशों की तुलना में कुछ देरी से था। 1975 के तीसरे चतुर्थांश तक कुल घरेलू उत्पाद (G D P) परिमाण की दृष्टि से 1974 के तीसरे चतुर्थांश की तुलना में 4.5 प्रतिशत घट गया था। निर्मित माल बनाने वाले उद्योगों में यह गिरावट अधिक तीव्र रही तथा बेरोजगारी भी बढ़ने लगी।

अप्रैल 1975 में रखे गये अपने बजट में सरकार ने निर्यातों के लिए समाधान उपलब्ध कराने हेतु कुछ उपाय किये। इसके अतिरिक्त ब्रिटेन के औद्योगिक आधार को अधिक मुहँड बनाने तथा कुल राष्ट्रीय उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र की ऋण आवश्यकताओं को घटाने के लिए भी उपाय अपनाये गये। मोटे तौर पर, मध्यकालीन लक्ष्य के रूप में इन उपायों का उद्देश्य रोजगार की व्यवस्था करना तथा विश्व अर्थव्यवस्था के उद्धार के साथ साथ ब्रिटिश अर्थव्यवस्था में भी अपेक्षित उद्धार की भूमिका बनाना था। 1975 के अन्तिम दिनों में कुछ सुधार के लक्षण दिखाई पड़ने लगे। खुदरा मूल्यों में वृद्धि की दर में कुछ गिरावट आयी तथा 1975 के चालू

याते में भुगतान अगन्तुन के कारण होने वाला घाटा 1974 के घाटे की अपेक्षा आधे से भी कम रहा। निर्यातों के परिमाण में भी तीव्र वृद्धि के आसार दिखायी दिये जो आशिक रूप से विश्व व्यापार में वृद्धि को प्रतिबिम्बित करते थे। किन्तु बेकारी में वृद्धि बराबर होती रही तथा इस वृद्धि दर को घटाने के लिए कुछ चुने हुए उपाय 1975 के अन्त व 1976 के प्रारम्भ में किये गये।

तेजी के साथ पूर्ण रोजगार, विदेशी व्यापार में सन्तुलन तथा ब्रिटिश उद्योगों को नये सिरे में मजबूत करने के ध्येय को सामने रखते हुए अप्रैल 1976 के बजट में मुद्रा स्फीति को घटाने के उपाय किये गये। स्फीति को घटाने की नीति का ही एक अंग मानते हुए आयकर में कुछ सशर्त परिवर्तन प्रस्तावित किये गये। शर्त यह थी कि ट्रेड यूनियन कांग्रेस नई वेतन सीमा को स्वीकार करे।

सरकार के द्वारा किये जाने वाले सार्वजनिक व्यय के बारे में तथा आर्थिक विकास के सम्बन्ध में जो सामान्य लक्ष्य रखे गये थे उन्हें 1976 में प्रकाशित एक परिपत्र '1979-80 में सार्वजनिक व्यय' में स्पष्ट किया गया। जुलाई 1976 में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए ऋण जरूरतों को घटाने के लिए और उपाय किये गये। इनमें 1977-78 में सार्वजनिक व्यय में कटौती के प्रस्ताव सम्मिलित थे जिनसे 1,000 मिलियन पाउण्ड की वृत्त बचत होने तथा नियोजकों द्वारा राष्ट्रीय धीमे में दिये जाने वाले योगदान में (दर बढ़ा दिये जाने के कारण) 900 मिलियन पाउण्ड की वृद्धि के अनुमान लगाये गये। इन उपायों के परिणामस्वरूप ऋण जरूरतें, जो 1976-77 में राष्ट्रीय उत्पाद (G D P) का 9 प्रतिशत थी, 1977-78 में 6 प्रतिशत रह गयी।

स्फीति पर नियन्त्रण

स्फीति, जिसका कि प्रकोप 1950 व 1960 वाले दशक से ही बढ़ता जा रहा था, ब्रिटेन में अन्य औद्योगिक राष्ट्रों की ही भांति 1970 वाले दशक में भी निरन्तर बढ़ती रही है। 1970 से 1975 तक ब्रिटेन में स्फीति के दौर में अपेक्षाकृत अधिक तीव्रता विश्व में खाद्यान्नों के मूल्यों में तीव्र वृद्धि होने तथा कच्चा माल (जिसमें खनिज तेल प्रमुख है) जिसे ब्रिटेन को भारी मात्रा में मँगाना पड़ता है, के मूल्यों में भारी वृद्धि के कारण आयी है। दूसरा कारण 1974 के बाद वेतन वृद्धियाँ रहा है जिन्होंने औद्योगिक लागतों को बहुत लेकिन 1975 के बाद स्फीति की दर में पुनः एक बार गिरावट आ रही है। पिछले 30 वर्षों में विविध सरकारों ने स्फीति पर नियन्त्रण लगाने के उद्देश्य से अनेक नीतियाँ अपनायी हैं जिनमें मूल्य व मजदूरी पर कानूनी रोक (Statutory Control) तक शामिल है। जबसे 1974 के आरम्भ में लेबर दल की सरकार ब्रिटेन में सत्ता में आयी तब से स्फीति विरोधी नीतियों के तीन चरण (Phases) रहे हैं तथा प्रत्येक चरण लेबर दल व ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बीच हुए 'सामाजिक अनुबन्ध' से सम्बन्धित रहा है। इस अनुबन्ध के अनुसार लेबर दल ने मूल रूप में बिना सरकारी नियन्त्रण वाली मजदूरी निर्धारण के लिए स्वतन्त्र संयुक्त सौदेबाजी (Free Collective Bargaining) को बनाये

रखने, मूल्यों पर नियन्त्रण लगाने, पेंशन पाने वाले लोगो व कम आय वाले लोगो की सहायता करने तथा पूर्ण रोजगार की स्थिति लाने का वायदा किया। बदले में ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने यह माना कि वैधानिक आय नीति (statutory incomes policy) के अभाव में श्रम सघो की निष्ठा न केवल उनके अपने सदस्यों के प्रति वरन् समाज के अन्य सदस्यों के प्रति भी है इसलिए उन्हें वेतन वृद्धियों को जीवन-निर्वाह की लागत में होने वाली वृद्धियों के बराबर रखना चाहिए।

जून 1974 में ट्रेड यूनियन कांग्रेस (T U C) ने 'सामूहिक सौदेबाजी व सामाजिक अनुबन्ध' नाम से एक नीति विषयक बयान जारी किया जिसमें स्थिति का मूल्यांकन करने के अलावा श्रम सघो व अन्य मध्यस्थों के लिए आने वाले वर्षों में सामूहिक सौदेबाजी के बारे में कुछ सिफारिशें व निर्देश दिये गये। यह बयान सरकार के उस वायदे के उत्तर में था जिसमें सरकार ने सामाजिक एवं आर्थिक कार्यक्रमों के लिए अपनी प्रतिबद्धता (commitment) व्यक्त की थी तथा बुद्धि स्राव पदार्थों पर अनुदान की व्यवस्था करने, मकान भाडों पर नियन्त्रण लगाने, ऊँची पेशों देने व अन्य सामाजिक लाभ प्रदान करने की इच्छा प्रकट की थी।

वैसे तो 1974-75 के दौरान मजदूरी के बारे में जो भी विचार विमर्श हुए उनमें ट्रेड यूनियन कांग्रेस के निर्देशों को ध्यान में रखा गया किन्तु सामाजिक अनुबन्ध का यह प्रस्ताव वेतन वृद्धियों पर नियन्त्रण नहीं लगा पाया। परिणाम यह रहा कि 1975 के पहले 6 महीनों में मजदूरी की दरें पिछले वर्ष की तुलना में 33 प्रतिशत बढ़ गयी तथा खुदरा मूल्य भी इसी अवधि में 25 प्रतिशत बढ़ गये। मध्य 1975 में सरकार व ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बीच अत्यन्त महत्वपूर्ण विचार विमर्श हुआ। ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने एक-एक नया बयान जारी किया। 'सामाजिक अनुबन्ध का विकास' नाम के इस बयान में वेतन वृद्धियों पर 6 पौण्ड प्रति सप्ताह से अधिक न होने देने के लिए स्वेच्छा से सीमा तथा वार्षिक वेतन प्राप्त करने वालों के लिए एक बिन्दु के बाद विलम्बित वेतन वृद्धि की माँग न करने की बात कही गयी। यह सीमा 1 अगस्त 1975 से आगामी एक वर्ष के लिए थी। जुलाई 1975 में प्रकाशित एक सरकारी बयान 'स्पीति पर आक्रमण' में सरकार ने 6 पौण्ड प्रति सप्ताह की वृद्धि सीमा तथा 8000 पौण्ड वार्षिक की आय को अन्तिम बिन्दु (cut off point) मान लिया। सरकार ने अपने लिए यह कार्य तय किया कि वह मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए कार्य करती रहेगी (इसमें मूल्य नियन्त्रणों की मौजूदा व्यवस्था को बनाये रखना तथा पहले से प्रस्तावित खाद्य पदार्थ व आवासीय अनुदानों पर अधिक खर्च शामिल थे) तथा लाभान्वीतों में वृद्धि को 10 प्रतिशत पर सीमित करेगी। महत्त्वपूर्ण भुगतान व अनुदान विधेयक 1975 (Remuneration, Charges and Grants Act) लाया गया तथा नियोक्ताओं को 6 पौण्ड से अधिक की वेतन वृद्धियाँ न करने के लिए अनुबन्ध के उत्तरदायित्व से मुक्त किया गया। स्पीति से लड़ने के एक अन्य उपाय के रूप में सरकार ने यह घोषणा की कि वह 'नक्द सीमा' का व्यापक प्रयोग करते हुए 1976-77 में सार्वजनिक व्यय पर कड़े नियन्त्रण लगायेगी।

6 पौण्ड की सीमा सारे देश में मानी गयी तथा वह बड़ी सफल रही।

जुलाई 1976 तक औसत आय में हुई वृद्धियाँ इससे पिछले वर्ष के मुकाबले आधी हो रही। इसी के परिणामस्वरूप खुदरा मूल्यों की स्फीतिक दर भी नाटकीय ढंग से घट गयी और यह भी पिछले वर्ष की तुलना में आधी रह गयी।

किन्तु इस सबके बावजूद ब्रिटेन में मुद्रा स्फीति की दर उसके अन्य विदेशी प्रतिद्वन्द्वियों की तुलना में काफी ऊँची बनी रही। 1976 में इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए कुछ और विचार विमर्श किया गया तथा सरकार ने मालिकों व मजदूरों को स्वेच्छा से मजदूरी नियन्त्रण पर वार्ता के दूसरे दौर के लिए बुलाया। इसमें 1 अगस्त 1976 से आगामी एक वर्ष तक मजदूरी पर स्वेच्छापूर्वक रोक लगाने की बात कही गयी ताकि 1977 तक ब्रिटेन में भी स्फीति की दर को उसके प्रतिद्वन्द्वी देशों की स्फीति दर के बराबर किया जा सके। फिर एक बार नई वेतन सीमा का विस्तृत ब्यौरा ट्रेड यूनियन कांग्रेस द्वारा प्रकाशित मई 1976 की एक रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया। नई सीमा, जो 1 अगस्त 1976 से अगले 12 महीनों के लिए थी, 5 प्रतिशत वृद्धि की रखी गयी जिसमें न्यूनतम वृद्धि 2.5 पौण्ड तथा अधिकतम वृद्धि 4 पौण्ड प्रति सप्ताह तक की जानी थी। ट्रेड यूनियन कांग्रेस द्वारा इस प्रकार वेतन वृद्धि पर सीमा लगाने की बात मान लिए जाने के बाद सरकार ने भी करो में राहत देने सम्बन्धी उन अनेक उपायों की घोषणा कर दी जो पहले सशर्त प्रस्तावित किये गये थे। जून 1976 में सरकार ने इस प्रस्तावित वेतन वृद्धि सीमा का अनुमोदन कर दिया। ट्रेड यूनियन कांग्रेस तथा लेबर पार्टी की सहयोग ममिति द्वारा जुलाई 1976 में इस बात को पुन दोहराया गया कि आगामी तीन वर्षों तक आर्थिक नीति व प्राथमिकताओं के कार्यक्रम पर सहयोग बनाये रखा जायेगा।

मूल्य नियन्त्रण

1973 से ही स्फीति विरोधी अधिनियम, 1973 के तहत स्थापित एक स्वतन्त्र वैधानिक संस्था मूल्य आयोग (Price Commission) मूल्य नियन्त्रण के एक बड़े कार्यक्रम को क्रियान्वित कर रहा था। ये नियन्त्रण एक मूल्य आचार संहिता (Price Code) में दिग्दर्शित किये जाते हैं जिन्हे सरकार तैयार करती है तथा जिनमें समय समय पर उचित संशोधन किया जाता रहता है। मोटे तौर पर यह माना जा सकता है कि मूल्य आचार संहिता यह इतिमान करने के लिए है कि मूल्य वृद्धियाँ अपरिहार्य हैं तथा लागत में वृद्धि हो जाने के कारण न्यायोचित हैं।

मुद्रा पूर्ति

मुद्रा पूर्ति पर नियन्त्रण लगाने से पहले सरकार यह ध्यान रखने का प्रयास कर रही है कि अन्य माँगों से पहले उद्योग की वित्तीय आवश्यकताएँ पूरी होती रह सक। इसके साथ ही मौद्रिक अतिरेक से स्फीतिक दबाव न बनने देने की भी चेष्टा की गयी है।

सावजनिक क्षेत्र की ऋण जरूरतों में वृद्धि के उपरान्त 1972 व 1973 में अनुभव किया गया मुद्रा प्रसार 1974 व 1975 में काफी धीमा हो चला है तथा

1976 में उसकी गति बहुत साधारण ही रही है। 1975 के आरम्भिक महीनों में व्याज की दरें यथायक चढ़ जाने के बाद 1976 के आरम्भ में वे पुन गिरी हैं। मई 1976 में न्यूनतम उधार दर (Minimum Lending rate) में वृद्धि हो जाने के बाद व्याज दरें पुन एक बार स्थिर हो गयी हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका

ब्रिटेन की मिश्रित अर्थव्यवस्था में उद्योग तथा व्यापार में जब कभी प्रत्यक्ष राजकीय हस्तक्षेप किया जाना होता है तो वह विधान द्वारा स्वीकृत विशेष सार्वजनिक निगमों की स्थापना करके क्रियान्वित किया जाता है। ये निगम जैसे सरकारी विभाग की तरह तो काम नहीं करते लेकिन इन पर विविध सीमाओं में सार्वजनिक नियन्त्रण रहता है। इन निगमों में सबसे महत्वपूर्ण वे हैं जो लोकहित में प्रमुख राष्ट्रीयकृत उद्योगों का संचालन करते हैं जिनमें कोयला, विद्युत, गैस, इस्पात, रेलें, हवाई अड्डे व हवाई यातायात, व्यावसायिक सड़क यातायात तथा डाक सेवा सम्मिलित हैं। कुल मिलाकर लगभग 8 प्रतिशत कर्मचारी इन संस्थाओं में काम करते हैं। सम्पूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र में कुल कार्यशील जनसंख्या का लगभग एक-चौथाई हिस्सा कार्यरत है।

नवीनतम घटनाक्रम में ब्रिटिश राष्ट्रीय तेल निगम की स्थापना रही है जिसके द्वारा सरकार ब्रिटेन के समुद्र तट पर हो रही तेल की खोज में अपने भागीदारी अधिकार बनाये हुए है। इसके अलावा जहाज निर्माण व वायुयान निर्माण के कारखानों तथा निजी लोगों के स्वामित्व वाले व्यावसायिक वन्दरगाहों व उनके द्वारा माल ढोने की गतिविधियों को भी राष्ट्रीयकृत करके सार्वजनिक स्वामित्व व नियन्त्रण के अन्तर्गत लाने के प्रस्ताव हैं।

इन राष्ट्रीयकृत उद्योगों का संचालन करने वाले बोर्ड तथा कर्मचारी आमतौर पर प्रशासनिक सेवा के लोग ही नहीं हैं। संसद में अपने उद्योगों के प्रति उत्तरदायी ये बोर्ड हैं न कि सरकार। इन राष्ट्रीयकृत उद्योगों में कुछ तो आत्मनिर्भर हैं, अन्य निगमों को उनका काम-बाज चलााने के लिए सरकारी सहायता दी जाती रहती है।

इन सभी निगमों में दो विशेषताएँ लगभग सामान्य हैं। प्रथमतः, बोर्ड के चेयरमैन व सदस्यों की नियुक्ति (व वर्खास्तगी) मन्त्री द्वारा की जाती है, तथा द्वितीयतः, मन्त्री को यह अधिकार होता है कि वह इस बारे में अपने सामान्य मुद्दाव दे सकता है कि उद्योग को किस तरह चलाया जाय यद्यपि वह दैनिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता। बोर्ड के लिए यह भी अनिवार्य है कि वह मन्त्री द्वारा चाही गयी कोई भी जानकारी आँकड़ा या वित्तीय हिसाब-किताब माँगे जाने पर उसके सम्मुख प्रस्तुत करे। व्यवहार रूप में क्योंकि सम्बन्धित मन्त्री को सारी जानकारी समय-समय पर दी जाती रहती है तथा बड़े निर्णय भी उसी की सहमति से लिए जाते हैं इसलिए ऐसा मौका कभी नहीं आता जब मन्त्री को इन कामों के लिए कोई औपचारिक आदेश जारी करना पड़ता हो।

मन्त्री को वित्तीय अधिकार व और जिम्मेदारियाँ भी हैं। साधारणतया

वैधानिक आवश्यकता यह है कि बोर्ड को अपना कार्य इस तरह चलाना होता है कि जिससे एक निश्चित अवधि में प्राप्तियाँ खर्च के बराबर हो जाएँ। किन्तु सरकार व विभिन्न उद्योगों के बीच वित्तीय लक्ष्यों को लेकर स्वीकृति हो चुकी है जिसमें पूँजी पर 15 प्रतिशत के प्रतिफल प्राप्त करने से लेकर 'न लाभ न हानि' तक के समझौते सम्मिलित हैं। इसमें घिसावट व व्याज के लिए अलग से प्रावधान होता है। इसके अलावा नये उद्योगों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने नये विनियोगों के लिए 10 प्रतिशत की रिबायन (Test discount) को पाने के लिए आवेदन करें। सम्बन्धित मन्त्री इस बात को तय करता है कि यदि प्राप्तियों में कोई अतिरिक्त पैदा होता है तो उसका क्या किया जाये। जहाँ तक पूँजीगत खर्च (Capital expenditure) का प्रश्न है अभी की व्यवस्था इस प्रकार है कि यदि आन्तरिक साधनों में उसकी व्यवस्था नहीं की जा सक्ती तो सरकार में उसके लिए व्याज वाले ऋण प्राप्त किये जा सकते हैं और कुछ मामलों में तो विदेशों में ऋण भी लिए जा सकते हैं।

सम्बन्धित मन्त्री का यह वैधानिक उत्तरदायित्व है कि वह इस बात को देखे कि उद्योग के ग्राहकों के हितों की अच्छी प्रकार सुरक्षा हो रही है। यह साधारणतया उपभोक्ता परिषदें स्थापित करके किया जाता है जो शिकायतों व मुद्दामों पर विचार करती हैं तथा बोर्ड या मन्त्री को उनके बारे में अपनी सलाह देती हैं।

राष्ट्रीयकृत उद्योगों के बारे में सरकारी नीति के लिए संसद के अनुमोदन की आवश्यकता पड़ती है। इन राष्ट्रीयकृत उद्योगों के वार्षिक प्रतिवेदनों पर संसद में बहस होती है। हाऊस ऑफ कॉमन्स की एव चयनित समिति (Select Committee) राष्ट्रीयकृत उद्योगों के प्रतिवेदनों व हिसाबों की जाँच करती है। उद्योगों में राज्य की भागीदारी के और भी कई स्वरूप हैं जैसे कुछ कम्पनियों के अधिसूच्य शेयर राष्ट्रीय उपक्रम बोर्ड (National Enterprise Board) द्वारा खरीदे या रत लिए जाते हैं।

वैदेशिक स्थिति

(1) विदेश व्यापार तथा भुगतान—1967 में पौंड के अवमूल्यन के बाद वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात में वास्तविक अर्थों में तेजी के साथ वृद्धि हुई। 1971 में 1,000 मिलियन पौंड के रिकॉर्ड अतिरिक्त (Record Surplus) तथा भारी मात्रा में पूँजी के देश में आगमन की सहमति में मई 1972 में विदेशी मुद्रा कोष 2,740 मिलियन पौंड के उच्च स्तर तक पहुँच चुके थे और यह ऊँचाई सरकारी अल्पकालिक एवं मध्य कालिक ऋणों का भुगतान कर देने के बाद प्राप्त की गयी थी।

लेकिन 1972 के बाद व्यापार सन्तुलन में ह्रास होने लगा। घरेलू माग में वृद्धि हो जाने के कारण आयातों में वृद्धि हाँ गयी और निर्यातों पर अनेक तत्त्वों का विपरीत प्रभाव पड़ा जिनमें से एक तत्त्व विश्व व्यापार का धीमी गति से विकास होना भी था। इस ह्रास के माध्य स्फीति का भय और जुड़ गया था और इनके परिणामस्वरूप जून 1972 में अल्पकालिक मट्टा पूँजी (Short term Speculative Capital) का बहिर्गमन आरम्भ हो गया। सरकार ने पौंड स्टर्लिंग की विनिमय दर को तैरने (float) के लिए मुक्त छोड़ दिया स्टर्लिंग क्षेत्र में आने वाले दशा के साथ

लेन-देन पर भी विनिमय नियन्त्रण लागू कर दिये। स्टर्लिंग की नीची विनिमय दर ने ब्रिटेन के निर्यातों को काफी प्रतिस्पर्धात्मक बना दिया और निर्यातों का परिमाण जो 1971 से 1972 में अपरिवर्तित ही रहा था वह 1973 में 14 प्रतिशत तथा 1974 में 7 प्रतिशत से बढ़ गया।

यह सब होने के उपरान्त, मुख्य रूप से आयातों के मूल्य बढ़ जाने से, जिनमें खनिज तेल शामिल था, चालू खाते में 1973 व 1974 में भारी घाटा दिखाई दिया। किन्तु 1975 में स्थिति में काफी सुधार आया जिसका मुख्य कारण आयातों के परिमाण में कमी तथा व्यापार की शर्तों (Terms of Trade) का अधिक अनुकूल बन जाना रहा। भावी वर्षों में उत्तरी सागर तट से इंग्लैंड को प्राप्त होने वाले खनिज तेल की पूर्ति बढ़ जाने के उसके भुगतान सन्तुलन की स्थिति में पर्याप्त सुधार की आशा की जा सकती है।

(1) विनिमय दरें—दिसम्बर 1971 में, काफी समय तक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में अनिश्चिन्ता भरा वातावरण रहने के बाद, जिसमें डॉलर विशेष रूप से प्रभावित हुआ, वाशिंगटन स्थित स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट में एक सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें सभी मुद्राओं को डॉलर के सन्दर्भ में पुनर्मूल्यित (revalue) कर दिया गया। इन नये सम्बन्धों के एक भाग के रूप में डॉलर के सन्दर्भ में स्टर्लिंग की दर 8.5% से ऊपर चली गई तथा अब नई विनिमय दर 2.60 डॉलर हो गई जबकि पुरानी दर 2.40 डॉलर प्रति पाउंड थी। अगस्त 1976 के अंत तक स्टर्लिंग पाउंड वास्तव में इस विनिमय दर के मुकाबले 39 प्रतिशत गिर चुका था।

(3) अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक समझौते—बीस राष्ट्रों की समिति (the Committee of Twenty) जिसमें मुख्य औद्योगिक एवं विकसित देशों के प्रतिनिधि थे, तथा जो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ढाँचे के भीतर स्थापित की गयी थी, ने अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली में सुधार करने के अपने कार्य को जून 1974 में पूरा कर लिया। समिति ने विशेष आहरण अधिकार (S D R), जिनका कि अन्तर्राष्ट्रीय रक्षित परिसंपत्त के रूप में इस्तेमाल होता है, के अहंता अनुमान (Valuation) के लिए एक तरीके पर सहमति व्यक्त की जो अन्तरिम समय (interim period) के लिए थी। समिति ने तैरती हुई दरों (floating rates) के संचालन के निर्देश भी मुद्राएं तथा भुगतान असन्तुलन वाले देशों की स्थिति ठीक करने के लिए कुछ उपाय भी सुझाये।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में आरम्भ के वर्षों में ही ब्रिटेन की नेतृत्व वाली स्थिति के कारण स्टर्लिंग घरेलू मुद्रा होने के साथ-साथ एक प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा बन गया था। ऐसा विशेष रूप से स्टर्लिंग क्षेत्र (Sterling area) के देशों के सन्दर्भ में हुआ जिन्होंने अपनी मुद्रायें स्टर्लिंग के साथ बाँध दीं। इस स्टर्लिंग क्षेत्र में सारे राष्ट्र कुल के देश व उन पर आश्रित क्षेत्र, कनाडा व रोडोसिया के अलावा, आ जाते थे।

जैसे-जैसे आधुनिक वर्षों में व्यापार तथा भुगतान के तोर-तरीकों में विविधता आयी है वैसे-वैसे स्टर्लिंग मुद्रा का अन्तर्राष्ट्रीय उपयोग घटता चला गया है। अब

केवल कुछ ही देशों ने स्टर्लिंग के साथ अपना नाता जोड़ा हुआ है। यद्यपि स्टर्लिंग क्षेत्र के बाहर वाले अन्य अनेक देशों के पास अभी भी रक्षित कोपो के रूप में भारी मात्रा में स्टर्लिंग विद्यमान है।

राष्ट्रीय आय तथा व्यय

(1) उत्पादन—1975 में ब्रिटेन का कुल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP) माधन मूल्यों पर (at factor cost) 99,095 मिलियन पाउंड होने का अनुमान था। मूल्यों में हुए परिवर्तनों का समायोजन करने के बाद 1965 के बाद के 10 वर्षों में यह वृद्धि लगभग 22.5 प्रतिशत रही।

कुल उत्पादन का लगभग एक तिहाई निर्मित माल रहा है तथा निर्मित माल वाले उद्योगों का यह अनुपात पिछले कई वर्षों से लगभग स्थिर रहा है। पिछले कुछ सालों से जिन क्षेत्रों में अधिक प्रसार हुआ है उनमें अधिकांश सेवायें, विशेष रूप से बैंकिंग, बीमा, वित्त, सार्वजनिक या लोक प्रशासन, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, प्रमुख रही हैं। कृषि, वन एवं मछली उद्योगों का भाग अपेक्षाकृत कम एवं गिरता हुआ रहा है और खनिज उत्पादन का भाग भी कम तथा गिरता हुआ ही आता है। वितरणात्मक व्यापार (distributional trade) का सापेक्ष भाग भी गिरा है। (तालिका 1 परिशिष्ट)

(2) ससाधनों का उपयोग—तालिका सरया 2 (परिशिष्ट) से स्पष्ट है कि वस्तुओं व सेवाओं की कुल आपूर्ति का वितरण 1965, 1970 तथा 1975 में, 1970 के बाजार मूल्यों के आधार पर, व्यक्तिगत उपभोग, सार्वजनिक व्यय तथा विनियोग एवं निर्यात कार्य के लिए किस प्रकार विभाजित हुआ है।

1965 के बाद से मुख्य प्रवृत्ति यही देखने में आ रही है कि कुल उत्पादन में से वह आनुपातिक भाग जो व्यक्तिगत उपभोग के काम में लिया जाता है बराबर घट रहा है तथा उसके साथ ही निर्यात में काम लिये जाने वाले उत्पादन का कुल उत्पादन में आनुपातिक भाग निरन्तर बढ़ता जा रहा है। यह अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छा संकेत माना जा सकता है।

(3) व्यक्तिगत आय तथा उपभोक्ता व्यय—वर लगने से पहले की व्यक्तिगत आय, वर्तमान मूल्यों पर, तेजी से बढ़ी है तथा उसकी यह वृद्धि निरन्तर हुई है। 1965 में यह 30,000 मिलियन पाउंड से कुछ अधिक थी जो 1975 में 97,500 मिलियन पाउंड हो चुकी थी। उपभोक्ता व्यय 1975 में वर लगने से पहले की आय में 66 प्रतिशत के लगभग था जबकि यही व्यय 1965 में 76 प्रतिशत था। यह अन्तर प्रत्यक्ष करों के अधिक भार, राष्ट्रीय बीमा योजना में अधिक चर्चे देने तथा व्यक्तिगत व्ययों में कुछ वृद्धि हो जाने से आया है।

(अ) आय के स्रोत—रोजगार से होने वाली आय 1975 में 68,200 मिलियन पाउंड थी जो कुल व्यक्तिगत आय का लगभग 71 प्रतिशत होनी थी। व्यक्तिगत आय के तीन अन्य स्रोत स्व-रोजगार (9 प्रतिशत), लाभान व व्याज (9 प्रतिशत) तथा लोक अधिकरणों (Public authorities) द्वारा स्वीकृत अनुदान (11%) रहे।

करारोपण हस्तान्तरण भुगतान (Transfer payments) तथा वस्तुओं के

रूप में लाभ का मिला-जुता उद्देश्य आय का अधिक समानता के आधार पर वितरण करना है। केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (Central Statistical Office) द्वारा किये गये एक अध्ययन के अनुसार 1974 में सबसे निर्धन जनसंख्या के लगभग 20 प्रतिशत को सभी परिवारों की मध्यका आय (Median income) के निकटतम लाना था। शाही आयोग के एक प्रतिवेदन के अनुसार भी, जो धन के वितरण का अध्ययन करने के लिए नियुक्त किया गया था, सर्वोच्च 5 प्रतिशत जनसंख्या की आय (कुल आय की) 1949 के 17.7 प्रतिशत से घट कर 1972-73 में 14.2 प्रतिशत पर आ चुकी है और उसमें यह गिरावट जारी है। कम्पनियों की आय पर एक दूसरी रिपोर्ट में यह स्पष्ट हुआ है कि एक-तिहाई से भी अधिक लाभदायक व्यावसायिक पेंशन स्कीम के लगभग 11 मिलियन सदस्यों में बँटता है। इसके अलावा यह 2.25 मिलियन करदाता व्यावसायिक पेंशनरों व 14 मिलियन ऐसे लोगों में बँटता है जो जीवन बीमा निगम के माध्यम से अपनी बचत करते हैं। इन सभी वर्गों में कम आय अर्जित करने वाले लोग ही आते हैं।

(ब) उपभोक्ताओं द्वारा व्यय—उपभोक्ताओं द्वारा किये जा रहे व्यय के परिमाण में वृद्धि, ब्रिटेन में ठीक उसी तरह ज़िम तरह कि अन्य विकसित देशों में हो रहा है, उसके स्वरूप में परिवर्तन के साथ जुड़ गयी है। खाद्य पदार्थ, कपड़ा तथा तम्बाकू पर होने वाला उपभोक्ता खर्च बराबर गिरता जा रहा है जब कि भूकान, शराब तथा मोटर कार चलाने पर होने वाले खर्च का अनुपात निरन्तर बढ़ता जा रहा है। (तालिका 3 . परिशिष्ट)

सार्वजनिक व्यय

वस्तुओं एवं सेवाओं पर केन्द्र सरकार एवं स्थानीय संस्थाओं द्वारा किया जाने वाला व्यय 1965 व 1975 के बीच 29 प्रतिशत से बढ़ चुका है। व्यय में इस वृद्धि का मुख्य कारण सामाजिक सेवाओं, विशेष रूप से शिक्षा, में होने वाला प्रसार रहा है। रक्षा व्यय का कुल सार्वजनिक व्यय में भाग प्रतिशत रूप में पिछले कुछ वर्षों से गिरता जा रहा है। 1953 में यह 48 प्रतिशत था जो 1965 में घट कर 34 प्रतिशत व 1975 में 22 प्रतिशत पर आ गया था।

वस्तुओं एवं सेवाओं पर व्यय करने के अतिरिक्त सार्वजनिक प्राधिकरण भारी मात्रा में रकम अन्य क्षेत्रों को हस्तांतरित करते हैं, विशेष रूप से व्यक्तिगत क्षेत्र को जिसे कि राष्ट्रीय बीमा योजना व अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभों, अनुदानों, व्याज आदि के माध्यम से रकम प्राप्त होती रहती है। सरकार स्थानीय प्राधिकरणों (Local authorities) को भी उनका व्यय चलाने के लिए उनके चालू व्यय का 55 प्रतिशत के लगभग वित्तीय सहायता के रूप में देती है।

विनियोग

कुल घरेलू स्थिर पूँजी निर्माण (Gross Domestic Fixed Capital) साधन

मूल्य पर कुल घरेलू उत्पाद (G D P at factor cost) का 22 प्रतिशत है। स्थिर परिपक्व (Fixed assets) का मूल्य इंग्लैण्ड में 1965 से 1975 के बीच 47 प्रतिशत बढ़ जाने का अनुमान है। उनका शुद्ध मूल्य, घिसावट को घटा देने के बाद 1975 में लगभग 3,22,100 मिलियन पाउंड था जिनमें से दो-तिहाई मूल्य भवनो का तथा बाकी एक-तिहाई मूल्य कारखानों, मशीनों और वाहनो आदि का था।

1975 के कुल घरेलू स्थिर पूंजी निर्माण में निजी क्षेत्र का विनियोग कुल घरेलू उत्पाद (G D P) का 12.2 प्रतिशत तथा सार्वजनिक क्षेत्र का विनियोग 8.9 प्रतिशत था। 1975 के कुल स्थिर विनियोग में विभिन्न उद्योग समूहों के अंश इस प्रकार थे (कोष्ठक में 1970 के आंकड़े दिये गये हैं) निर्मित माल उद्योग, 17% (23 प्रतिशत), गैस, बिजली व पानी, 6% (13 प्रतिशत), सामाजिक एवं अन्य सार्वजनिक सेवाएँ, 14% (15 प्रतिशत), अन्य उद्योग, 24% (16 प्रतिशत)। निर्मित माल वाले उद्योगों में विनिर्माण का एक चक्रीय स्वरूप रहा है। 1967 में वह काफी कम था, 1973 व 1974 में वह बढ़ा तथा 1975 में पुनः घट गया। पिछले कुछ वर्षों की विनियोग प्रवृत्ति का अध्ययन करने पर पता चलता है कि कृषि, उत्खनन (कोयला खानों के अलावा), उत्तरी समुद्र तेल उत्खनन उपकरण जहाज निर्माण व खुदरा वितरण जैसे क्षेत्रों में विनियोग में वृद्धि हुई है।

कम्पनी क्षेत्र की वित्तीय स्थिति में 1975 में काफी स्पष्ट रूप से सुधार दिखाई दिया था। किन्तु सार्वजनिक क्षेत्र का वित्तीय घाटा 1975 में अत्यधिक बढ़ गया तथा वह 8,280 मिलियन पाउंड तक पहुँच गया जो 1974 के घाटे के मुकाबले 56 प्रतिशत अधिक था। इसी तरह विदेश व्यापार में होने वाला अतिरेक भी 1975 में 1974 की अपेक्षा बहुत कम रहा। व्यक्तिगत क्षेत्र (personal sector) में अतिरेक 1975 के दौरान भी बढ़ता रहा, जो मुख्य रूप से उच्च व्यक्तिगत बचत अनुपात प्रदर्शित करता है।

कर्मचारियों में असन्तोष ब्रिटिश अर्थव्यवस्था का नवीनतम मर दण्ड बन गया है। 1979 के जनवरी के महीने में ट्रंक ड्राइवरो की हड़ताल के बाद वैमानिकों, रेलों तथा अन्य अनेक सार्वजनिक सेवाओं के कर्मचारियों की हड़ताल वहाँ की अर्थव्यवस्था की गिरती हुई स्थिति का ही परिचायक है। ये सभी हड़ताले मजदूरी बढ़ाने की माँग को लेकर की गयी है जो इस बात का प्रमाण है कि स्फीति की दर व भूतल्य वृद्धि पर नियन्त्रण के उपाय कारगर सिद्ध नहीं हुए हैं।

परिशिष्ट

तालिका 1 उद्योगवार कुल घरेलू उत्पाद (G D P. by Industry)

(चालू मूल्यो पर)

	1965		1975	
	मिलियन पीड	प्रतिशत	मिलियन पीड	प्रतिशत
कृषि, वन व मछली पालन	1,527	3.3	2,527	2.7
धार्मिक	708	2.3	1,645	1.8
निर्मित माल	10,624	34.0	26,726	28.7
निर्माण	2,153	6.9	6,411	6.9
गैस, बिजली, पानी	1,006	3.2	2,866	3.1
यातायात	1,984	6.3	5,753	6.2
संदेशवाहन	646	2.1	2,809	3.0
वितरणपरमक व्यापार	3,605	11.5	9,159	9.8
बीमा, बैंकिंग वित्त	2,092	6.7	7,727	8.3
मकानों की सम्पत्ति	1,395	4.5	5,535	5.9
लोक प्रशासन व रक्षा	1,805	5.8	7,107	7.6
जन स्वास्थ्य, शिक्षा	1,430	4.6	7,154	7.7
अन्य सेवाएँ	3,651	11.7	10,430	11.2
वित्तीय सेवाओं के लिए समायोजन	-905	-2.9	-3,623	-3.9
शेष बूटि	—	—	920	1.0
कुल घरेलू उत्पादक, साधन मूल्यो पर	31,221	100.00	93,146	100.00
विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय	435	—	949	—
कुल राष्ट्रीय उत्पाद	31,656	—	94,095	—

Source: National Income and Expenditure, 1965-75

तालिका 2
वस्तुओं व सेवाओं की कुल आपूर्ति का वितरण

	1 65	1975
उपभोक्ता व्यय	53.2	50.7
सरकारी चालू वर्ष	15.5	15.5
कुल घरेलू पूंजी निर्माण	15.8	13.3
वस्तुओं-सेवाओं का निर्यात	15.5	20.5
	100.00	100.00

तालिका 3
उपभोक्ता व्यय के स्वरूप में परिवर्तन
(Changes in Pattern of Consumers' Spending)

(आनु मूल्य पर)

	1965		1975	
	मिलियन पौंड	प्रतिशत	मिलियन पौंड	प्रतिशत
खाद्य पदार्थ	5,059	22.1	12,092	19.1
घराब आदि	1,499	6.6	4,902	7.7
तम्बाकू	1,428	6.3	2,741	4.3
आवास (भाड़े, दर)	2,592	11.4	9,201	14.5
ईंधन व रोगनी	1,087	4.8	2,927	4.6
कपड़ा, जूते	2,099	9.2	5,320	8.4
कारें, मोटर साइकिलें	707	3.1	1,932	3.1
अन्य टिकाउ चीजें	1,078	4.7	2,926	4.6
मोटरवाहना के चलाने पर खर्च	940	4.1	3,940	6.2
अन्य यात्रा व्यय	741	3.2	1,989	3.1
होटल सेवा	1,196	5.2	2,832	4.5
अन्य वस्तुएं	2,132	9.3	6,290	9.9
अन्य सेवाएं	2,096	9.2	6,432	10.2
अन्य मदें (उपभोक्ताओं द्वारा विदेशों में खर्च विदेशियों द्वारा देश में खर्च में से घटाने पर)	191	0.8	-151	-0.2
	22,845	100.00	63,373	100.00

अमरीका का आर्थिक विकास

पहला अध्याय

अमरीकी क्रान्ति

(THE AMERICAN REVOLUTION)

क्रान्ति से पूर्व की अमरीका की स्थिति पर टिप्पणी करते हुए थॉमस पेन ने कहा है कि 'ऐसे छोटे द्वीप जो स्वयं अपनी रक्षा करने में भी असमर्थ हो बड़े साम्राज्यों द्वारा देखभाल किये जाने योग्य होते हैं, किन्तु किसी महाद्वीप के स्थायी रूप से किसी लघुकाम द्वीप के अधीन रहने की बात में एक अजीब-सा बेतुकापन लगता है।'¹

अक्टूबर 1492 में क्रिस्टोफर कोलम्बस द्वारा अमरीकी उपमहाद्वीप की खोज करने के कोई सौ वर्षों के भीतर स्पेन के साहसी खोजकर्त्ताओं ने कैरेबियन द्वीपसमूहों (Caribbean islands) पर अपने उपनिवेश स्थापित कर लिये थे। इन द्वीपों पर उपनिवेशों की स्थापना के बाद ही उन्होंने आज के उत्तरी अमरीका कहे जाने वाले उपमहाद्वीप की मुख्य भूमि की खोज आरम्भ की। 1504 तक स्पेनवासियों ने मध्य अमरीका तथा दक्षिणी अमरीका के एक विशाल भू-भाग पर विजय पा ली थी और वर्तमान अमरीका के दक्षिणी भाग का खोज कार्य पूरा कर लिया था।

स्पेन अमरीकी उपमहाद्वीप में उपनिवेशों की स्थापना करना चाहता था लेकिन उसके पास इस कार्य के लिए सुदृढ़ आधार नहीं था। वह एक निर्धन राष्ट्र था तथा उसके पास बहुत कम ससाधन थे। स्पेन के साहसियों तथा उसके शासकों का मुख्य उद्देश्य खजाना प्राप्त करना था। पूरी की पूरी सोलहवीं शताब्दी में इन स्पेनिश साहसियों ने अमरीकी खानों तथा वहाँ के अन्य उत्पादों को अपने देश में भेजा। इस तरह अमरीकी उपमहाद्वीप में स्पेन की उपस्थिति एक महाशक्ति के रूप में बनी रही किन्तु वहाँ का भविष्य डच लोगों, फ्रांसवासियों तथा अन्तिम रूप से अंग्रेजों के लिए नियत था।

जब स्पेन का पतन हुआ तो हॉलैण्ड ने अमरीका में सर्वोच्चता प्राप्त कर ली। लेकिन शीघ्र ही दो अन्य देश, जिनके पास अधिक ससाधन व साज-सामान था, अमरीकी उपमहाद्वीप पर अधिकार करने की इस दौड़ में हॉलैण्ड से आगे निकल गये। ये दो देश फ्रांस और इंग्लैण्ड ही थे। फ्रांसियों ने अमरीकी उपमहाद्वीप के पश्चिमी भाग की सक्रिय रूप से खोज 1608 से आरम्भ कर दी थी तथा वे उसके दक्षिणी भाग तक 17वीं शताब्दी के अन्त तक पहुँच गये थे। फ्रांस ने 1664 में फ्रेंच ईस्ट इण्डिया कम्पनी स्थापित की तथा कुछ समय तक ब्रिटिश लोगों के साथ सफलतापूर्वक

¹ R M Robertson, *History of the American Economy*, Harcourt, Brace and World, Inc., 1964, 69

प्रतिस्पर्द्धा भी की। लेकिन अन्तिम विजय अग्रेजों की ही हुई। फ्रांसीसियों को तो अग्रेजों ने केवल अपनी सख्या से ही पछाड़ दिया। 1756 में कनाडा में फ्रांसीसी आप्रवासियों की सख्या केवल 60,000 थी जबकि ब्रिटिश उपनिवेशों में अग्रेज आप्रवासियों की सख्या तब तक 20 लाख हो चुकी थी।¹

अन्य यूरोपीय देशों के विपरीत ब्रिटिश लोगों ने प्रारम्भ से ही यह देख लिया था कि ये उपनिवेश उनके निर्मित माल के लिए प्रमुख बाजार बन जाएँगे। सोलहवीं शताब्दी के अन्त तक ब्रिटेन के लिए यही बात सबसे महत्वपूर्ण बन गई थी।

आवासों (Settlements) का आरम्भ

1607 में दो, एक दूसरे से बहुत दूर उपनिवेश, सागाडहॉक (Sagadahoc) जो अब मेन (Maine) कहलाता है तथा वर्जीनिया में स्थापित किये गये। जो लोग सोने की खोज में यहाँ आये थे उनको तो निराशा ही हाथ लगी किन्तु वर्जीनिया की जलवायु तम्बाकू की खेती के लिए उत्तम थी। इंग्लैण्ड में तम्बाकू के लिए विशाल बाजार उपलब्ध था। 1618 में ही तम्बाकू का ब्रिटेन को किया गया निर्यात 1 लाख पौण्ड मूल्य का था। 1625 में वर्जीनिया को क्राउन उपनिवेश (crown colony) घोषित कर दिया गया। वर्जीनिया का ही एक सहयोगी उपनिवेश मेरिलैण्ड में स्थापित किया गया। इसके बाद ब्रिटिश उपनिवेश मैसाचुसेट्स तथा कनेक्टिकट (Massachusetts and Connecticut) तक और भी फैल गये। उपनिवेशवाद की अन्तिम लहर की दो प्रमुख दिशाएँ रही—मध्य क्षेत्रीय उपनिवेश (the middle colonies) तथा वर्जीनिया के नीचे के क्षेत्र वाले दक्षिणी उपनिवेश।

उपनिवेशों में आर्थिक जीवन की दशाएँ

ब्रिटिश उपनिवेशों के अस्तित्व की सम्पूर्ण अवधि में अधिकांश लोग अपनी जीविका भूमि से ही कमाते थे। न्यू हैम्पशायर से लेकर जॉर्जिया तक लोगों का मुख्य व्यवसाय ही कृषि था। इस अवधि के अधिकांश उद्योग भी बनो या समुद्र से प्राप्त सामग्री पर आधारित थे। जहाँ भूमि कम उपजाऊ होती थी तथा जहाँ की जलवायु अनुकूल नहीं होती थी वहाँ मछली मारने या जहाज बनाने का काम किया जाता था। कृषि के पीछे इस तरह के पागलपन का परिणाम यह हुआ कि उपनिवेशों में कारीगरी व प्रशिक्षित लोगों की भारी कमी हो गई। यूरोप से अनुबन्धित (indentured) श्रमिकों को बुलाया गया किन्तु वे भी सभी अनुकूल या अप्रशिक्षित ही थे। केवल अपराधी लोग या कैदी ही, जिनके पास कोई विकल्प नहीं रहता, अमरीका आते व अपने साथ अपनी दक्षता या कारीगरी भी लाते। 1619 के बाद नीग्रो लोगों के आयात से श्रमिकों के अभाव की समस्या से निपटने का प्रयास किया गया। दक्षिणी भागों के उपनिवेशों में तो 1700 तक नीग्रो गुलामों को खरीदने व काम पर लगाने की प्रथा मजबूती से स्थापित हो गयी। यह तथ्य भी महत्वपूर्ण था कि तम्बाकू, चावल तथा नील जैसी चीजों की खेती अदक्ष नीग्रो गुलामों के लिए अत्यधिक उपयुक्त थी।

लेकिन उत्तरी राज्यों में श्रमिकों के लिए माँग पूरी अठारहवीं सदी में ज्यों की त्यों बनी रही। वह अन्तिम रूप से तभी समाप्त हुई जब 19वीं सदी में स्वतन्त्र श्रमिकों का अमरीका में आकर बस जाना (immigration) शुरू हो गया।

अधिवास (settlement) की प्रथम शताब्दी में पूँजीगत वस्तुओं का विशेष रूप से अभाव रहा। उपलब्ध प्राकृतिक ससाधनों से बनी हुई चीजों की प्रचुरता थी। किन्तु धातु से बनी चीजों का अभाव था। उपनिवेशों को अधिक पूँजी उपलब्ध कराई जा सकती थी किन्तु अंग्रेज अपने यहाँ की फर्मों में धन लगाना अधिक सुरक्षित समझते थे।

वणिक्वाद (Mercantilism) तथा ब्रिटिश उपनिवेश

15वीं से लेकर 18वीं सदी तक यूरोप के देश एक ऐसे विचारों के समूह से प्रभावित हुए थे जिसे वणिक्वाद कहा जाता था। ये वणिक्वादी लोग राज्य के लिए अधिक से अधिक शक्ति व सम्पदा अर्जित करने के पक्षपाती थे। वे आत्मनिर्भरता तथा अनुकूल भुगतान सन्तुलन के भी भ्रमर्यक थे। इन लोगों के अनुसार उपनिवेशों का नियमन मुख्य देश के हितों के लिए किया जाना था। इंग्लैंड ने उपनिवेशों से लाये व ले जाने वाले माल के विदेशी जहाजों में आवागमन पर अधिकाधिक प्रतिबन्ध लगा दिये। 1630 में तो विदेशियों को अमरीकी व्यापार के क्षेत्र से कानूनी रूप से प्रतिबन्धित कर दिया गया। 1651 में ब्रिटिश संसद ने पहले नौ-परिवहन कानून (Navigation Laws) पारित किये जिन्होंने डच जहाजों द्वारा अमरीकी चीजों के लाने ले जाने पर रोक लगा दी। इससे उपनिवेशों में बहुत क्षोभ व आक्रोश का वातावरण बना जिसकी अन्तिम परिणति क्रान्ति के रूप में हुई।

ब्रिटिश उपनिवेशकर्त्ताओं को अमरीका में अपने पाँव मजबूती से जमाने में करीब 50 वर्ष लगे। 1660 तक वर्जीनिया, मेरिलैण्ड तथा मेसाच्युसेट्स राष्ट्रमण्डल (Commonwealths) के रूप में स्थापित हो गये। लेकिन अमरीकी मुख्य भूमि पर 1660 तक केवल 80,000 अंग्रेज ही पहुँचे थे। 1690 में उनकी संख्या 2 लाख, 1790 तक 10 लाख तथा अमरीकी क्रान्ति की पूर्व सन्ध्या पर 22.5 लाख तक पहुँच चुकी थी।

कृषि की प्रधानता—18वीं सदी के अन्त तक लगभग 90% जनसंख्या अपने जीविकोपार्जन के लिए कृषि पर आश्रित थी। उसमें भी देश के दक्षिणी भागों की कृषि सम्पूर्ण उपनिवेश काल में उत्पादन के मूल्य की दृष्टि से अधिक प्रबल रही। दक्षिणी प्रदेशों के लोगों के पास उपजाऊ भूमि अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध थी। दक्षिणी भागों के अधिवासी (settlers) तम्बाकू, चावल तथा नील की खेती करते थे। ब्रिटिश व्यापारियों द्वारा इस निर्यात योग्य कृषि अतिरिक्त का उपयोग करने के प्रयास किये गये। ऊपर वर्णित कृषि उत्पादों के अलावा दक्षिणी भागों में स्थित उपनिवेशों में गेहूँ, अन्य अनाजों तथा चारे का भी भारी मात्रा में उत्पादन किया जाता था।

खाद्य पदार्थों के उत्पादन के लिए देश के मध्य भाग में स्थित उपनिवेश

(middle colonies) जो पोटमैक (Potamac) तथा हडसन नदियों के बीच में थे, सर्वाधिक उपयुक्त थे। क्रान्ति से पहले के वर्षों में पेंसिलवेनिया एक महान् गेहूँ उपनिवेश (wheat colony) बन चुका था। इन उपनिवेशों से भारी मात्रा में फल, सब्जियाँ व पशु सम्पदा भी प्राप्त होती थी। खाद्य पदार्थों के निर्यात से ये उपनिवेश निर्मित वस्तुओं का आयात किया करते थे।

न्यू इंग्लैण्ड (New England) में कृषि पिछड़ी हुई अवस्था में थी। धुरु से ही वहाँ के निवासियों ने खेती के साथ और घन्घे भी अपनाये हुए थे ताकि उनका जीवन स्तर ऊँचा रह सकता। न्यू इंग्लैण्ड में कृषि सगठन भी कुछ विशिष्ट प्रकार का था। शहर वहाँ की राजनीतिक इकाई ही नहीं बल्कि कृषि इकाई भी था। ग्रामीणों की जमीन शहरों के नजदीक ही थी। हर ग्रामवासी के पास एक छोटा-सा बगीचा या फलों का बाग तथा 50 से लेकर 100 एकड़ तक के जमीन के बिखरे-बिखरे टुकड़े होते थे। एक सबके काम आने वाला चरागाह, कुछ सामान्य खेत तथा बेकार जमीन भी होनी थी। 18वीं शताब्दी में इन बिखरे हुए टुकड़ों को एक आन्दोलन के तहत पुनर्गठित किया गया। उन पुराने और बेकार हो चुके खेती करने के तरीकों को आधुनिक अमरीकी कृषि पर कोई निशान भी शेष नहीं रह गया है लेकिन इतना अवश्य कहा जा सकता है कि शहरों का मुख्यवस्थित रूप से विकास सबसे पहले न्यू इंग्लैण्ड से ही शुरू हुआ था।

कृषि पर आधारित उद्योग—हालांकि अधिकांश उपनिवेश अपनी आय कृषि से ही अर्जित करते थे, उनमें से कुछ अपनी आय अप्रत्यक्ष रूप से भूमि से प्राप्त करते थे। ऐसा वे फर, चमड़े तथा वनों से प्राप्त इमारती लकड़ी या ह्वेल के शिकार पर आधारित उद्योगों (extractive industries) से करते थे। इस प्रकार के सत्व निखालने वाले उद्योग उपनिवेश काल में काफी महत्वपूर्ण थे।

फर व्यापार (Fur Trade) के भी दो प्रमुख केन्द्र थे उत्तर में फिलाडेल्फिया तथा दक्षिण में चार्ल्टन। अंग्रेज तथा फ्रांसीसी लोग फर तथा अन्य जानवरों की खालों की तलाश में उत्तर व दक्षिणी भागों में भीतर तक घुसते चले गये। 1808 के बाद से फर का सारा व्यापार अमरीकी फर कम्पनी के हाथों में केन्द्रित हो गया। वनों का भी आर्थिक शोषण किया जाने लगा। मेन तथा न्यू हेम्पशायर में तरबो, पट्टियों आदि को व्यावसायिक स्तर पर निर्मित किया जाने लगा। कुछ मिल जहाज निर्माण के काम में आने वाली सामग्री का भी निर्माण करने लग। यह उद्योग उत्तरी बेरोलिना में केन्द्रित था। समुद्र तट से नजदीक होने के कारण न्यू इंग्लैण्ड में मछली पकड़ने का व्यवसाय जोरो पर था। उपनिवेश काल में ह्वेल मछली के तेल की अत्यधिक माँग थी तथा ह्वेल पकड़ने वाले लोग न्यू इंग्लैण्ड के तट पर ही अधिक सक्रिय थे। 1775 में 300 से भी अधिक जहाज ह्वेल मछलियाँ पकड़ने के काम में लग थे।

धातु एवं निर्मित उद्योग—लोहा ही एकमात्र ऐसी धातु थी जो बहुतायत में उपलब्ध थी। कुछ ताँबा व थोड़ा बहुत कोयला भी स्थानों से निखाला जाता था। लोहा गलाने का काम काफी आदिम तरीके से किया जाता था, हालांकि अमरीकी क्रान्ति

के समय तक उसमें कुछ सुधार हो गया था। इस्पात का तो उत्पादन शुरू ही नहीं हुआ था। क्रान्ति के समय उपनिवेशों का कुल लोहा उत्पादन लगभग 30,000 टन था। उपनिवेश भारी मात्रा में लोहे की निमित्त वस्तुओं का आयात करते थे।

उपनिवेशों में घरों में लोग खाद्य पदार्थों तथा कपड़ों का उत्पादन करते थे। ये गृह उद्योग कीलों से लेकर रसोई में काम आने वाले बर्तनों तथा अच्छी किस्म का फर्नीचर तक तैयार करते थे। उपनिवेशों के निवासी अपने घर भी अपने हाथों से बनाते थे। कुछ ऐसे छोटे कारखाने (craftshops) भी होते थे जो गृह उद्योगों से अधिक विशिष्टीकृत थे। ये विविध हस्त शिल्प-निर्माण उद्योग न केवल उपनिवेशों के उत्पादन में भारी योगदान देते थे बल्कि उनसे भावी औद्योगिक विकास की नींव भी रखी गई थी।

उपनिवेशों में लगे हुए मिल बहुत ही आदिम किस्म के थे। वे चीजों को पीसने की विधि मात्र थे जिन्हें पशुओं, हवा या पानी की शक्ति से चलाया जाता था। सम्पूर्ण उपनिवेश काल में बहुत ही आदिम यन्त्रों का उपयोग होता था। अमरीकी क्रान्ति के कुछ ही वर्षों पूर्व मिलों द्वारा चीजें तैयार करने की प्रक्रिया में शक्ति के उपयोग को लेकर कुछ सुधार हुए थे। मिलों की प्रक्रिया (Milling process) अनेक उद्योगों द्वारा अपनायी गयी थी। पूरे दक्षिण तथा उत्तर में चमड़ा साफ करने वाले कारखाने (tanneries) थे जो छाल मिलों (bark mills) का उपयोग करते थे। पेन्सिलवेनिया तथा न्यू इंग्लैण्ड में अनेक कागज तैयार करने वाले प्रतिष्ठान थे। मेसाचुसेट्स तथा न्यूयॉर्क में अनेक वस्त्र मिल कार्यशील थे। न्यू इंग्लैण्ड में स्थित शराब बनाने वाले कारखाने (distillaries) निर्यात करने के लिए भारी मात्रा में शराब बनाते थे।

जहाज-निर्माण भी उपनिवेश काल का एक प्रमुख उद्योग था। अमरीकी जहाज-निर्माण कारखानों (shipyards) का उत्पादन अठारहवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में अपने सर्वोच्च बिन्दु तक पहुँच गया था। इन जहाजों में से अनेक का निर्यात किया गया। यह अनुमान है कि 1775 में ब्रिटिश व्यापारिक जहाजों-बेड़े के एक-तिहाई जहाजों का निर्माण अमरीकी जहाज-निर्माण कारखानों में हुआ था। प्रत्येक क्षेत्र में विशिष्टता की वर्तमान अवस्था के स्थान पर उपनिवेशों का उत्पादन बिखरा हुआ व अत्यधिक सामान्यीकृत था। किन्तु भावी विशाल उद्योगों के चिह्न उभरने लग गये थे। उदाहरण के लिए, कुछ स्थानों पर उद्योगों के सकेन्द्रण की शुरुआत को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। इसके अतिरिक्त यूरोप के देशों में स्थित समूक्त पूँजी कम्पनियों की ही भाँति एक नये व्यावसायिक संगठन के अभ्युदय की सम्भावना भी स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होने लगी थी। 1751 में तो एक 'उद्योगों को प्रोत्साहित करने वाली तथा गरीबों को रोजगार दिलाने वाली' समिति भी बनायी गयी थी। साहसी व्यापारी घरों व हस्तशिल्प के कारखानों के उत्पादन को एक ही छत के नीचे इकट्ठा करने लग गये थे। इस तरह एक व्यवसायी-नियोक्ता प्रणाली का भी विकास हो रहा था। फँकट्री उत्पादन अभी शुरू नहीं हुआ था। उसे अभी तक बाजारों के विकास की प्रतीक्षा करनी थी।

अमरीकी उपनिवेशों में ब्रिटिश नीति

दो शताब्दियों से भी अधिक समय तक अमरीकी उपनिवेश निर्मित वस्तुओं के आयात के लिए ब्रिटेन, जोकि उनका मातृ-देश (mother country) था, पर निर्भर थे। किन्तु जैसे-जैसे वस्तुओं का उत्पादन बढ़ा, वैसे-वैसे उपनिवेशों के व्यावसायिकों की स्थिति अधिक मजबूत बनती गई। इस स्थिति ने अंग्रेज व्यापारियों को असन्तुष्ट कर दिया जिसका अन्तिम परिणाम क्रान्ति के रूप में सामने आया।

(1) उपनिवेशों में मुद्रा की पूर्ति—उपनिवेशों के आरम्भिक वर्षों में सिक्कों का अभाव था तथा वस्तु-मुद्रा (commodity money) का ही अधिकतर प्रचलन था। सभी प्रमुख यूरोपीय देशों की स्वर्ण तथा रजत की मुद्राएँ निर्वाह रूप से स्वीकार की जाती थी। लेकिन इन मुद्राओं की हमेशा कमी रहती थी। इसीलिये औपनिवेशिक व्यापारियों ने ब्रिटिश अधिकारियों को अलग औपनिवेशिक टंकसाल (colonial mints) स्थापित करने के लिए कहा। मेसाच्युसेट्स राज्य में 1656 में एक टंकसाल लगाई भी गई। किन्तु यह प्रयोग असफल रहा क्योंकि उसने अपने सिक्कों में कम चाँदी का प्रयोग किया। 1690 के बाद पत्र-मुद्रा भी लोकप्रिय हो गई। यह बहुत आश्चर्य की बात है कि उपनिवेशों में मुद्रा में एकरूपता स्थापित करने की दृष्टि से ब्रिटिश संसद ने कोई गम्भीर प्रयास नहीं किया। अच्छी मुद्रा (sound money) तथा सस्ती मुद्रा (cheap money) के पक्षधरों के बीच विवाद था। किन्तु सम्पूर्ण उपनिवेश काल में एकरूप एवं कुशल मुद्रा व्यवस्था की स्थापना एक जटिल समस्या बनी रही।

(2) यातायात एवं संचार—17वीं शताब्दी में अमरीकी उपनिवेशों में यातायात एवं संचार मुख्यतः समुद्री मार्ग से था। जहाँ पहले अधिवास (settlements) स्थापित हुए वहाँ काफी अच्छे बन्दरगाह मौजूद थे। 1700 से पहले तक सड़कों का तो अस्तित्व ही नहीं था। सामुद्रिक यातायात को अधिक अच्छा समझा जाता था क्योंकि भूमि-यातायात की लागत काफी अधिक आती थी तथा लायी-ले जायी जाने वाली चीजें अक्सर भारी होती थी। अठारहवीं शताब्दी में एक सड़क प्रणाली विकसित होने लगी। किन्तु मुख्य राजमार्गों की स्थिति फिर भी शोचनीय ही बनी रही। सड़कवाहन भी धीमा तथा खर्चीला था। 1710 में एक अमरीकी डाक-व्यवस्था स्थापित की गई किन्तु उसका भी दरें बहुत ऊँची थीं।

(3) घरेलू व्यापार—दूरस्थ गाँवों में बसने वाले लोग अपने कृषि उत्पादन के बदले नमक, दवायें, गोला-बारूद, चाय, कॉफी या ऐसी ही अन्य चीजों का विनिमय करते थे। औपनिवेशिक काल में उपनिवेशों के घरेलू व्यापार में दो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। एक परिवर्तन तो शहरों व गाँवों के बीच वस्तुओं व सेवाओं के प्रवाह में प्रसार का था। दूसरा परिवर्तन तुलनात्मक दृष्टि से तटवर्ती व्यवसाय का तेजी से विकास हो जाना था।

(4) विदेशी व्यापार—औपनिवेशिक विदेशी व्यापार में दक्षिण के प्रदेश तम्बाकू, चावल तथा नील के प्रमुख उत्पादक होने के कारण सुदृढ़ स्थिति में थे। इन दक्षिणी राज्यों का इंग्लैण्ड के साथ मोघा व्यापार था। इसी कारण से ही दक्षिणी

उपनिवेशों के प्रति वणिक्वादी अधिक पक्षपातपूर्ण रवैया रखते थे। लेकिन उत्तरी राज्यो का विदेश व्यापार कोई आसान द्विपक्षीय मामला नहीं था। ये उत्तरी राज्य अर्द्ध-निर्मित वस्तुओं का भी निर्यात करते थे तथा मध्यवर्ती वस्तुओं का आयात भी करते थे। ग्रेट ब्रिटेन ही स्वाभाविक रूप से सबसे बड़ा खरीदार था तथा वही उपनिवेशों की पूर्ति का भी सबसे विशाल स्रोत था। 1769 में अर्थात् क्रान्ति से एक दशक पूर्व, उपनिवेशों ने अपने निर्यातों का 50% इंग्लैंड को भेजा था। औपनिवेशिक विदेशी व्यापार ने बड़े व्यापारियों के वर्ग को भी जन्म दिया। ये भ्रमणकर्त्ता व्यवसायी (itinerant merchants) आयात व निर्यात व्यापार करने में भारी जोखिम उठाते थे क्योंकि उनका व्यापार साधारणतः पिछड़े हुए सदेशवाहनो, खतरे भरे यातायात के साधनो तथा अनिश्चित मुद्रा पूर्ति पर निर्भर करता था। इन व्यापारियों का प्रभाव निरन्तर बढ़ता चला गया। इन भ्रमणकारी व्यापारियों की कुल संख्या 1770 में 300 से अधिक नहीं थी। किन्तु यह व्यापारी अभिजात्य वर्ग शहरो के राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक जीवन पर छा गया।

(5) पुरानी तथा नई उपनिवेश नीति—जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, वणिक्वादी लोग नौपरिवहन कानूनों पर अधिक बल देते थे। 1651, 1660 तथा 1663 के व्यापार व नौपरिवहन कानून इंग्लैंड तथा उपनिवेशों के बीच नये सम्बन्ध स्थापित करने के लिये ही बनाये गये थे। आरम्भ में उपनिवेशों का व्यापार इन कानूनों से अधिक प्रभावित नहीं हुआ किन्तु धीरे-धीरे इससे व्यापार का प्रवाह अस्त-व्यस्त हो गया। ब्रिटिश लोगो ने अफ्रीकी उपनिवेशों को अपना प्रारम्भित बाजार माना। समुद्र ने इन उपनिवेशों में कुछ प्रकार की निर्मित वस्तुओं के उत्पादन पर रोक लगाने के उद्देश्य से कानून बनाये ताकि प्रतिस्पर्धा का उन्मूलन किया जा सके। एक ऐसा कानून 1699 में पारित किया गया। 1750 में एक अन्य कानून बनाया गया जिसमें ब्रिटेन में शुल्क-मुक्त लौह-पिंड भेजने की अनुमति तो दे दी गई। किन्तु उसमें निर्मित लौह-वस्तुओं के प्रवेश पर पूर्णरूप से रोक लगा दी गई। इस पुरानी उपनिवेश नीति के बारे में एकमात्र अच्छी बात यही थी कि इसमें वर्णित आर्थिक नियन्त्रण बहुत बड़े नहीं थे तथा उनमें से कुछ की बिना किसी कठिनाई के अनदेखी की जा सकती थी।

क्रान्ति के कारण

(1) वणिक्वादी नीति (Mercantilist Policy)—मूल रूप से डेढ़ सौ वर्षों से स्वशासन के अभ्यस्त लोगो पर लादी गई वणिक्वादी नीति ने अपने अन्तिम परिणाम में ऐसे माविधानिक संघर्ष को जन्म दिया जिसे रणभूमि में ही हल किया जा सकता था। यह सही है कि अमरीकी क्रान्ति का सकट मूलतः एक राजनीतिक सकट था किन्तु वे दबाव और तनाव, जिन्होंने ब्रिटिश लोगो के प्रति अमरीकियों के मन में भय व घृणा भर दी थी, आर्थिक कारको से सम्बन्धित थे।

उधर नई उपनिवेशवादी नीति ने सकट को गहरा कर दिया। हालाँकि नई उपनिवेशवादी नीति पुरानी नीति का ही प्रसार थी किन्तु ब्रिटिश अधिकारी उसे

अक्षरशः लागू करना चाहते थे। उच्च ब्रिटिश अधिकारियों ने चूक करने वालों (defaulters) के विरुद्ध दण्डनीय कार्यवाही करके (वह भी गलत समय पर) आग में घी झोकने का ही काम किया। नाजुक स्थिति की शुरुआत 1763 में ब्रिटिश लोगों की फ्रांसीसियों पर विजय के बाद हुई। इस सातवर्षीय युद्ध में उपनिवेशों के निवासियों ने अंग्रेजों की किसी भी प्रकार से सहायता नहीं की थी, साथ ही साथ उन्होंने फ्रांसीसियों के साथ व्यापार भी जारी रखा था। ब्रिटिश लोगों ने इसे उनकी अकृतज्ञता माना। इसके अतिरिक्त युद्ध ने ब्रिटिश खजाने पर भारी दबाव डाला था तथा ब्रिटिश लोग अपनी क्षतिपूर्ति उपनिवेशों से करना चाहते थे।

(2) फौजी व्यय—ब्रिटेन ने अमरीकी उपनिवेशों में 10,000 ब्रिटिश सैनिक रखने का निर्णय लिया जिनके रख-रखाव पर 3,50,000 पौण्ड की आवश्यकता थी। इस उद्देश्य के लिए ब्रिटिश ससद द्वारा दो नये कर लगाये गये। 1764 में पारित चीनी कानून (Sugar Act, 1764) एक ऐसा ही कानून था जिससे अमरीकी चीनी उद्योग समाप्त होने का खतरा पैदा हो गया था जबकि वह ब्रिटिश उद्देश्यों को खूब अच्छी तरह पूरा करता था। किन्तु इससे भी अधिक रोप उपनिवेशों में 1765 के स्टाम्प कानून (Stamp Act, 1765) ने पैदा किया। इसी कानून ने वास्तव में क्रान्ति का सकट पैदा किया।

चीनी कानून ने वेस्टइण्डीज की बनी गैर ब्रिटिश वस्तुओं के आयात पर कर लगा दिये। इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश वस्तुओं को सरक्षण प्रदान करना था। किन्तु स्टाम्प कानून का उद्देश्य तो केवल सरकार की आय बढ़ाना था। उससे कोई भी अन्य वणिक्वादी उद्देश्य पूरा नहीं होता था। इस कानून के अन्तर्गत विभिन्न कानूनी दस्तावेजों पर अलग-अलग लागत के स्टाम्प चिपकाने की आवश्यकता थी। यह एक आन्तरिक कर था तथा उपनिवेशों के लोग इस प्रकार के करों से अनभिज्ञ थे। उपनिवेशों के लोग इस बात को लेकर भी नाराज थे कि जिस ससद ने उन पर यह कर लगाया था उसमें उनका एक भी प्रतिनिधि नहीं बैठता था। उन्होंने इन दोनों करों से प्राप्त राशि के ब्रिटेन भेजे जाने की बात पर और भी आपत्ति की। जैसे ही यह स्पष्ट होने लगा कि ब्रिटिश अधिकारी इन करों को सख्ती से लागू करना चाहते हैं वैसे-वैसे इनके विरुद्ध प्रतिरोध बढ़ता चला गया। उपनिवेशों में वकीलों तथा प्रकाशकों द्वारा स्टाम्प शुल्क विरोधी प्रदर्शन आयोजित किये गये। 1765 में ही एक स्टाम्प एक्ट कांफ्रेंस गठित की गई जिसने ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का कार्यक्रम बनाया। इस सारी स्थिति ने ब्रिटिश व्यापारियों पर इतना विपरीत प्रभाव डाला कि स्वयं उन्होंने स्टाम्प शुल्क रद्द करने की माँग की। इस तरह स्टाम्प शुल्क 1766 में रद्द कर दिया गया तथा चीनी पर लगाये गये शुल्क में भी कटौती की गई।

(3) कर लगाने का अधिकार—स्टाम्प शुल्क आदि रद्द कर देने का यह अर्थ नहीं था कि ब्रिटिश लोगों ने उपनिवेशों पर कर लगा सकने का अपना अधिकार छोड़ दिया था। उन्होंने इस अधिकार को मजबूती से बनाये रखा। एक घोषणा विधेयक (declaratory act) पारित किया गया जिसने ब्रिटिश ससद को औपनिवेशिक मामलों पर कानून बनाने का अधिकार दे दिया। जब 1765 में चार्ल्स टाउनशैंड

ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना तो उस समय ब्रिटेन के भूस्वामी करो के भार से छूट के लिए काफी आवाज उठा रहे थे। ऐसी स्थिति में फिर एक बार टाउनशैंड ने अमरीकी उपनिवेशों से आगम प्राप्त करने की चेष्टा की। आन्तरिक करो द्वारा आय प्राप्त करने के स्थान पर, जिनका कि उपनिवेशों के लोग विरोध करते थे, उसने चाय, काच, कागज आदि पर कर लगाये। इन करो को लागू करने के लिए एक कड़ी तथा सजग प्रशासनिक मशीनरी भी साथ ही साथ कायम कर दी गई। इस कार्यवाही ने पुनः उपनिवेशवासियों को क्रुद्ध कर दिया। फिर एक बार बहिष्कार आयोजित किये गये। 1769 में अमरीकी आयात उनके सामान्य स्तर का 33% रह गये। ब्रिटिश व्यापारियों ने वहाँ की ससद पर इन करो को रद्द करने के लिए दबाव डाला तथा ससद ने चाय पर लगे हुए समस्त टाउनशैंड शुल्को को उठा लिया।

इन कदमों ने कुछ समय के लिए उपनिवेशों के निवासियों को शान्त कर दिया किन्तु 1773 के चाय अधिनियम (Tea Act, 1773) ने पुनः शान्ति भंग कर दी। इस अधिनियम के पारित किये जाने से पहले अमरीका में चाय ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से कई मध्यस्थों (intermediaries) के माध्यम से भेजी जाती थी। इस अधिनियम ने अब चाय प्रत्यक्षतः ईस्ट इण्डिया कम्पनी को ही अमरीका ले जाने की अनुमति दे दी। चाय पर लगे हुए शुल्क को भी उठा लिया गया। ऐसा करने से चाय तो सस्ती हो गई किन्तु मध्यस्थों को इससे आघात पहुँचा। उनकी आवश्यकता समाप्त हो गई। इससे अमरीकी आयातक कार्यक्षेत्र के बाहर हो गये जिससे अमरीकी व्यापारी भयभीत होने लगे। उनका भय यह था कि अगर चाय की ही तरह ब्रिटेन ने अन्य एकाधिकारी कम्पनियों को भी इस तरह एकमात्र व्यापार का अधिकार दे दिया तो अन्य शोक व्यवसाय भी उनके हाथ से छिन जाएँगे।

(4) बोस्टन 'चाय पार्टी' (Boston Tea Party)—ईस्ट इण्डिया कम्पनी को चाय के व्यापार पर एकाधिकार प्रदान कर दिये जाने की घटना ने अमरीकी व्यापारियों को काफी नाराज कर दिया। बोस्टन शहर के समृद्ध व्यापारियों और यहाँ तक कि छोटे-छोटे दुकानदारों ने भी नीति सम्बन्धी इस परिवर्तन के प्रति अपनी हिंसक प्रतिक्रियाएँ व्यक्त की। चाय को या तो वापस इंग्लैंड लौटा दिया गया या उसे बन्दरगाहों पर ही नष्ट कर दिया गया।

उपनिवेश के निवासियों की इस कार्यवाही से अंग्रेज बहुत नाराज हुए तथा एक दण्डित करने वाला विधेयक 'इन्टॉलरेबल एक्ट' (Intolerable Act, 1774) में पारित किया गया। इस विधेयक में निम्न बातें सम्मिलित थी—(i) बोस्टन बन्दरगाह को तब तक के लिए बन्द कर दिया गया जब तक ईस्ट इण्डिया को उसकी समुद्र में फेंकी गई चाय का भुगतान नहीं किया जाता। (ii) बोस्टन नगर में सेना रखने की व्यवस्था की गई। दोनों ही प्रावधानों को बोस्टनवासियों ने काफी अयमानजनक माना। राजनीतिक विरोध व हिंसा नई ऊँचाइयों तक पहुँच गये। पहली महाद्वीपीय कांग्रेस (First continental congress) ने सभी ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का आह्वान किया। अमरीकी उपनिवेशवासियों ने मौलिक स्वतन्त्रता को पुनः प्रतिष्ठा की माँग की, किन्तु अंग्रेज अड़े रहे। अप्रैल 1775 में गोलीयाँ

चली और मेसाचुसेट्स राज्य में आपत्काल की घोषणा कर दी गई।

(5) ब्रिटिश भूमि नीति—जो घटनाएँ अन्तिम परिणाम में क्रान्ति का कारण बनी, वे इंग्लैंड द्वारा अपनाई गई वणिक्वादी नीति के विरोध तथा उत्तरी प्रदेशों के औपनिवेशिक व्यापारियों द्वारा अपनी गतिविधियों के प्रसार के इन दो मुद्दों के इर्द-गिर्द केन्द्रित थी। ब्रिटिश भूमि-नीति ने औपनिवेशिक कृषि को उसी तरह अवरोध कर दिया था जिस तरह वणिक्वादी नीति ने वहाँ के व्यापार-को सीमित किया था। 1763 से पहले ब्रिटिश नीति पश्चिमी प्रदेश के विकास की थी। लेकिन जब अमरीकी उपमहाद्वीप से विदेशी ताकतें लुप्त हो गईं तो ब्रिटिश लोगों ने तटवर्ती क्षेत्रों के आस-पास ही केन्द्रित रहना ठीक समझा। सारी पश्चिमी प्रदेश की भूमि को सम्राट के प्रत्यक्ष नियन्त्रण में रख दिया गया।

1774 में एक शाही घोषणा की गई जिसमें भूमि का निजी व्यक्तियों को स्थानान्तरण कठिन बना दिया गया। भूमि को अब नीलामियों में बेचा जाना था तथा न्यूनतम मूल्य भी तय कर दिये गये। इससे पहले जमीनें नि:शुल्क दे दी जाती थी, इस परिवर्तन से तम्बाकू की खेती करने वालों तथा सीमाओं पर रहने वाले कृषकों को आघात लगा। पश्चिमी प्रदेशों की भूमि को नि:शुल्क लेकर आबाद कर सकने की उनकी आशाएँ समाप्त हो गईं। इसलिये इन लोगों ने भी ब्रिटिश विरोधी रुख अपनाया क्योंकि उनका विश्वास था कि कोई भी अन्य सरकार भूमि आवंटित करने में अधिक उदार नीति अपनायेगी। इंग्लैंड के साथ व्यापार का बार-बार बहिष्कार (boycotts) तथा पत्र-मुद्रा के गिरते हुए मूल्य ने भी किसानों को अंग्रेजों के खिलाफ कर दिया। इन सभी तत्त्वों ने मिलकर क्रान्ति से पूर्व आर्थिक अस्थिरता का वातावरण बना दिया। मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियों ने आय में घी डालने का काम किया।

(6) स्वशासन की भावना का अभ्युदय—एक इतिहासकार ने लिखा है कि 'क्रान्ति का मुख्य प्रश्न स्वशासन (home rule) ही नहीं था बल्कि उसका प्रश्न यह भी था कि अपने ही प्रदेश पर शासन कौन करे?' महान् अतलातिक गमुद्र ने अमरीका व इंग्लैंड को 3,000 मील अलग कर रखा था। इन लोगों से ब्रिटिश सम्राट के प्रति स्वामीभक्ति की अपेक्षा करना मही नहीं था। इतना ही नहीं, अमरीका की एक चौथाई जनसंख्या अन्य यूरोपीय देशों से आई हुई थी और वे देश इंग्लैंड के घोर शत्रु थे। इस तरह घोर धीरे स्वशासन की भावना की जड़ें जमने लगीं। सत्य तो यह है कि अमरीका की क्रान्ति स्वतन्त्रता के युद्ध से काफी पहले प्रारम्भ हो चुकी थी।

यद्यपि सरकारी तौर पर अमरीकी क्रान्ति अप्रैल 1775 में शुरू हो गई थी किन्तु वह 6 वर्षों तक घिसटती रही। अमरीकी मामलों में गैर-बानूनी ब्रिटिश हस्तक्षेप से पूर्ण मुक्ति को एक पवित्र उद्देश्य बना लिया गया। अमरीकी क्रान्ति का एक महान् विरोधाभास यह रहा कि उसे कभी भी बहुमत का समर्थन प्राप्त नहीं था। लगभग एक तिहाई उपनिवेशों की जनसंख्या ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार थी। इसके अलावा दूसरी एक-तिहाई जनसंख्या न युद्ध व वर्षों में भारी मूल्यों पर

चीजें बेचकर लाभ कमाया। क्रान्ति में अन्तिम विजय नौ सैनिक शक्ति के कारण हुई जब 17 अक्तूबर 1781 को यॉर्कटाउन में कॉर्नवालिस को पराजित किया गया।

अमरीकी नेताओं के सामने तात्कालिक समस्या यह थी कि किस प्रकार की सरकार वे अन्तिम रूप से चुनें। चूँकि विशाल उपमहाद्वीप की समस्याएँ भी अत्यधिक थी इसलिए वे एक मजबूत संघ चाहते थे। नये गणराज्य को गम्भीर वित्तीय संकट का भी सामना करना पड़ रहा था। क्योंकि स्वतन्त्रता संग्राम के लिए धन की व्यवस्था पत्र-मुद्रा द्वारा की गई थी। एक ऐसा नया संविधान आवश्यक था जिसमें मुद्रा संघ तथा सामाजिक पूँजी-निर्माण पर भारी मात्रा में राशि के विनियोग का प्रावधान हो। 1787 में फिलाडेल्फिया में हुई बैठक (convention) में इन परिस्थितियों को दृष्टिगत रखा गया।

अमरीकी क्रान्ति के प्रभाव

(1) जनसंख्या के पश्चिम की ओर प्रस्थान (Westward movement) की गति क्रान्ति के बाद अत्यधिक तीव्र हो गई जो एक प्रतिवन्धात्मक शाही घोषणा से धोमी पड़ चुकी थी।

(2) स्वतन्त्रता संग्राम ने ब्रिटिशकालीन सामन्त-व्यवस्था को चूर-चूर कर दिया। स्थानीय लोगो ने उस भूमि पर अधिकार कर लिया जो पहले सम्राट की थी। बड़ी भूमि जोतों को विभाजित किया गया तथा भूमि को पुनर्वितरित किया गया है।

(3) क्रान्ति ने धार्मिक स्वतन्त्रता की मजबूत आधारशिला रखी। चर्च तथा राज्य के बापों को स्पष्ट रूप से पृथक् कर दिया गया।

(4) क्रान्ति ने समाज में स्त्रियों का स्थान काफी उन्नत कर दिया। उमने एक उदार और सार्वभौमिक शिक्षा को बढ़ावा दिया।

(5) बाहरी दुनिया के साथ सम्पर्क स्थापित हो जाने से उपनिवेशों की व्यावसायिक गतिविधियाँ अत्यधिक बढ़ गयीं। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का युग (era of boycotts) अब समाप्त हो गया तथा नये राष्ट्र ने भारी मात्रा में वस्तुओं का स्वतन्त्र रूप से आयात व निर्यात आरम्भ कर दिया।

(6) उद्योगों को क्रान्ति में भारी लाभ प्राप्त हुआ। विशाल अस्त्र-शस्त्र निर्माण उद्योग तथा जहाज-निर्माण उद्योग स्थापित किये गये। औद्योगिक मजदूरी में भी वृद्धि हुई।

(7) नये राष्ट्र में पूँजीवाद की दृढ़ता के साथ स्थापना होना क्रान्ति की एक महत्वपूर्ण घटना रही। एक निस्सीम आर्थिक विकास की क्षमता अमरीकी उप-महाद्वीप में सदैव विद्यमान थी तथा क्रान्ति ने उसे एक नई स्फूर्ति व शक्ति प्रदान की।

1789 में जॉर्ज वाशिंगटन की अध्यक्षता में नये संविधान का निर्माण किया गया। उस संविधान को 4 मार्च 1789 के दिन औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया और जॉर्ज वाशिंगटन को अमरीका का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया।

दूसरा अध्याय

जनसंख्या का पश्चिम की ओर प्रस्थान

(THE WESTWARD MOVEMENT OF POPULATION)

टर्नर के अनुसार, 'अमरीकी इतिहास मोटे तौर पर महान् पश्चिमी प्रदेशों के उपनिवेशन का इतिहास रहा है। विशाल माना में स्वतन्त्र भू खण्ड की विद्यमानता, उसका निरन्तर घटते चले जाना तथा पश्चिमी प्रदेशों की ओर अमरीकी अधिवास (American settlement) का अग्रसर होना अमरीका के विकास को अभिव्यक्त करते हैं।'

यूरोप के लोग, जो समुक्त राज्य अमरीका में आकर प्रवास कर रहे थे, वहाँ आकर भूमि के विशाल टुकड़ों पर अपना अधिकार करने के इच्छुक थे। उपनिवेशन आरम्भ होने के कोई 150 वर्षों तक यह भूमि पूर्वी समुद्री तट के समीप अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध थी। किन्तु कुछ समय के बाद इन उपनिवेशों में लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। नये आने वाले लोगों के पास सीमान्त प्रदेशों में जाने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था, जहाँ एक विशाल खाली क्षेत्र पड़ा हुआ था। अनेक ऐसे प्रवासी कृषक भी थे जो नई भूमि की तलाश में तथा अपना भाग्य आजमाने के उद्देश्य से पश्चिमी प्रदेशों में जाने लगे थे। इस तरह निरन्तर चलने वाले इस पश्चिम की ओर प्रस्थान के आन्दोलन ने एक नये वर्ग को जन्म दिया जो सीमान्त व्यक्ति (frontiersmen) कहलाये। ये लोग बहुत साहसी तथा हिम्मत की भावना से आगे बढ़ने वाले थे। 1862 के गृह-युद्ध के पहले यही सीमान्त व्यक्ति प्रगति के वास्तविक वीर पुरुष (heroes) बने हुए थे। इन लोगों द्वारा भारी जोखिम उठाने की प्रवृत्ति ने ही अमरीका के विशाल प्राकृतिक ससाधनों के तीव्रगति से विदोहन को सम्भव बनाया।

पश्चिम की ओर प्रस्थान के लिए उत्तरदायी कारक

आरम्भ में जनसंख्या के शक्ति की ओर प्रस्थान करने की शक्ति अत्यन्त धीमी व अस्त व्यस्त बनी रही। ऐसा इसलिए हुआ कि 1763 की शाही अधि-घोषणा ने लोगों के पश्चिम में आप्रवास पर स्पष्ट रूप से रोक लगा दी थी। इसके अलावा पश्चिमी प्रदेशों की ओर जाने वालों के मन में जंगली जानवरों तथा वहाँ के मूल निवासी रेड इण्डियनों का भय समाया हुआ था। यातायात के साधन तो लगभग थे ही नहीं। किन्तु इन सभी कठिनाइयों पर सीमान्त व्यक्तियों (frontiersmen) ने धीरे-धीरे विजय पायी तथा अमरीकी स्वतन्त्रता की घोषणा के बाद पश्चिम की ओर

प्रस्थान का एक नया अध्याय लिखा गया। तीव्रगति से लोगो के पश्चिम की ओर प्रस्थान के निम्न तत्त्व मुख्य रूप से उत्तरदायी थे—

(1) व्यावसायिक एवं औद्योगिक परिवर्तन—एक बहुत ही लम्बे समय तक (1807-15) पूर्वी तट पर स्थित व्यावसायिक नगर ब्रिटन के साथ युद्ध छिड़ जाने के कारण किसी भी प्रकार का विदेशी व्यापार नहीं कर पाय। आयातों की अनुपस्थिति में नये देश को अपने स्वयं के साधनों से काम चलाना पड़ा। इससे देश के भीतर ही अनेक उद्योगों का अभ्युदय हुआ। 1815 के बाद इन उद्योगों ने इतनी क्षमता व भजबूती प्राप्त कर ली थी कि वे अपने ब्रिटिश सहयोगी उद्योगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने लग गये थे। अधिकांश पूर्वोक्त के उद्योगों के पास भारी अतिरिक्त था तथा शहरों में भीड़ बढ़ती जा रही थी। इन परिस्थितियों ने नवामतुको को पश्चिम की ओर प्रस्थान के लिए प्रोत्साहित किया। वहाँ वे अधिक लाभकारी अवसरों की तलाश कर सकते थे। 1812 के बाद श्रम तथा पूँजी काफ़ी मात्रा में पश्चिमी प्रदेशों की ओर जाने लग गये। इस प्रस्थान को अधिक सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से तथा उसे अधिक तीव्रता प्रदान करने हेतु नौ परिवहन की सुविधाओं का प्रसार किया गया। उपजाऊ भूमि के विशाल भू भागों, इमारती लकड़ी से भरपूर जंगलों तथा ज्ञात एवं अज्ञात अनेक प्राकृतिक ससाधनों के भण्डार वाला यह पश्चिमी प्रदेश उतनी ही बड़ी चुनौती बन गया जितना वह रहस्यपूर्ण था।

(2) जनसंख्या की वृद्धि—यूरोप के राष्ट्रों से निरन्तर लोगों के आते चले जाने के कारण उपमहाद्वीप के पूर्वी तट वाले प्रदेशों की जनसंख्या अत्यधिक तेजी से बढ़ रही थी। 1790 में देश की जनसंख्या केवल 39 मिलियन थी। किन्तु केवल 85 वर्षों में अमरीका की जनसंख्या बढ़कर 31.5 मिलियन हो गई जो आठ गुनी वृद्धि इंगित करती है। गृह-युद्ध के समय तक अमरीका में जनसंख्या वृद्धि की दर 3% वार्षिक के आस पास रही। इस दर ने भी उसकी जनसंख्या को लगभग हर 20 वर्ष में दुगुना कर दिया।

जनसंख्या के आकार में वृद्धि होने से उसका घनत्व भी बढ़ता चला गया। 1790 में घनत्व 5 व्यक्ति प्रति वर्ग मील से भी कम था जो 1860 तक बढ़कर 10.6 व्यक्ति प्रति मील हो गया। जनसंख्या में हो रही इस वृद्धि ने भी पश्चिम की ओर प्रस्थान के आन्दोलन (Westward movement) को गति प्रदान की। पश्चिमी प्रदेश की ओर जाना एक सनक या उत्पाद बन गया। राष्ट्र का भौगोलिक आकार जो 1789 में 3.9 लाख वर्ग मील था, 85 वर्षों के बाद बढ़कर 30 लाख वर्ग मील हो गया। भूमि के भूखे लोग (land hungry people) पश्चिम में गहरे से गहरे पैठते चले गये तथा अछूती भूमि (virgin lands) व प्राकृतिक व अन्य बहुमूल्य खनिज पदार्थों की खोज उन्हें आगे से आगे ले जाती रही।

(3) सहायक सरकारी नीतियाँ—ब्रिटिश लोगों द्वारा अपनायी गयी। नीति के ठीक विपरीत अमरीकी कांग्रेस ने जनसंख्या के पश्चिम की ओर प्रस्थान के आन्दोलन को अपना पूर्ण समर्थन प्रदान किया। यह आन्दोलन दो प्रकार से लाभकारी था पहला, इससे दूरस्थ क्षेत्रों में अधिवास (settlement) को बढ़ावा मिला था,

दूसरे, सरकार को जमीनों की बिक्री से भारी रकम मिलती थी।

भूमि का अधिग्रहण तथा विक्रय—नया राष्ट्र, जो अपने आपको संयुक्त राज्य अमरीका कहता था, एक ऐसे विशाल भू-भाग से बना था जो अटलांटिक तट से मिसिसिपी नदी तक तथा ग्रेट लेक्स से फ्लोरिडा तक फैला हुआ था। मूल 13 राज्यों में से 7 राज्यों ने तो विलय के समय ही एप्पेलेशियन पर्वतमाला (appalachian mountains) के पश्चिम की ओर पड़ने वाले भू-भाग पर अपना दावा छोड़ दिया था तथा उस पर संघीय सरकार का अधिकार मान लिया था। अन्तिम राज्य जार्जिया ने भी अपना यह दावा 1802 में छोड़ दिया। 1898 में हवाई द्वीप के औपचारिक रूप से संयुक्त राज्य अमरीका में मिला लिये जाने के बाद उसने अपना वर्तमान भौगोलिक स्वरूप प्राप्त कर लिया था। संयुक्त राज्य अमरीका का वर्तमान भौगोलिक स्वरूप आठ समामेलनों (annexations) का परिणाम था। ये समामेलन इस प्रकार थे¹—

(1) लुइसीयाना का प्रदेश (Territory of Louisiana) जिसे 1803 में फ्रांस से ख़रीद कर अधिग्रहित किया गया।

(2) फ्लोरिडा जिसे 1819 में स्पेन से ख़रीदकर अवाप्त (acquire) किया गया।

(3) टेक्सास गणराज्य (Republic of Texas) जिसका एक राज्य के रूप में 1845 में समामेलन हुआ। अमरीकी अधिवासियों की मैक्सिको पर विजय के आठ वर्षों बाद यह गणराज्य स्थापित किया गया था।

(4) ओरेगन कंट्री (Oregon Country) 1846 में ब्रिटेन के साथ एक संधि से अधिग्रहित हुआ।

(5) मेक्सिकन सेशन (Mexican Cession) 1848 में मेक्सिको पर विजय प्राप्त कर अवाप्त किया गया।

(6) गेड्सडेन पचेंज (Gadsden Purchase) 1853 में मेक्सिको से अधिग्रहित किया गया।

(7) अलास्का पचेंज (Alaskan Purchase) रूस से 1867 में की गई।

(8) हवाई समामेलन (Hawaii Annexation) 1898 में औपचारिक रूप से स्वीकृत हुआ।

इस तरह लगभग आधी शताब्दी में संयुक्त राज्य अमरीका ने 30 लाख वर्ग मील भूमि अवाप्त कर ली थी। 1862 में इस विशाल भूभाग का 66% सरकार के पास था। भूमि की बिक्री के तरीके बहुत पहले ही स्वीकृत किये जा चुके थे।

1785 व 1787 के भूमि विधेयक (Land Acts)—स्वतन्त्रता संग्राम में विजयी हो जाने के बाद अमरीकी कांग्रेस को सरकार के अधीन भूमि की बिक्री या आवंटन के लिए तीन प्रमुख निर्णय लेने पड़े² (1) क्या न्यू इंग्लैण्ड की भूमि-प्रणाली

¹ Ibid., 100-101

² Ibid., 101

को चलता रहने दिया जाये ? (2) क्या सरकार भूमि के लिए ऊँचा मूल्य वसूल करे या प्रत्येक व्यक्ति को सस्ती भूमि उपलब्ध कराई जाये ? (3) नये अधिवासित क्षेत्रों (newly settled areas) का मूल उपनिवेशों के साथ राजनीतिक सम्बन्ध क्या हो ?

उपनिवेश काल में दो प्रमुख भू-प्रणालियाँ (land systems) विकसित हुई थी। पहली प्रणाली न्यू इंग्लैंड प्रणाली थी जिसे 'कस्बाई आयोजन' (township planning) भी कहा जाता था। इस प्रणाली में कस्बों को बसाना, कस्बों को सर्वेक्षण किये हुए भूमि के टुकड़ों में उपविभाजित करना तथा इन उपविभाजित टुकड़ों को अधिवासियों को नीलामी द्वारा बेचना सम्मिलित थे। अठारहवीं शताब्दी में इस प्रकार की कस्बाई बस्ती (townships) 6 वर्ग मील की होती और कोई भी व्यक्ति ऐसी भूमि का स्वामी नहीं बन सकता था जिसकी पहले से पैमाइश न कर ली गई हो। इसके विपरीत दक्षिणी प्रणाली (southern system) में इस प्रकार के आयताकार सर्वेक्षणों की कोई आवश्यकता नहीं थी। दक्षिण में तो अधिवासी लोग अपनी पसन्द की जमीन चुन लेते और उस पर ताल्लुके के सर्वेक्षक (country surveyor) से निगान लगवा लेते।

1784 में थॉमस जेकरसन की अध्यक्षता में नियुक्त की गई एक कांग्रेसीय समिति ने आयताकार सर्वेक्षण प्रणाली (rectangular survey system) प्रस्तावित किया। इस प्रकार न्यू इंग्लैंड प्रणाली के महत्त्व को स्वीकार कर लिया गया था। यही प्रस्ताव 1785 के भूमि अधिनियम (Land Ordinance of 1785) के रूप में पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार, 'सरकारी सर्वेक्षकों को खाली पड़ी भूमि (unsettled land) पर आड़ी रेखाएँ जिन्हें आधार रेखाएँ (base lines) कहा गया तथा खड़ी रेखाएँ जिन्हें मुख्य याम्योत्तर रेखाएँ (principal meridians) कहा गया, स्थापित करनी थी। 'पहली याम्योत्तर रेखा ओहियो राज्य में स्थापित की गई। जैसे-जैसे भूमि का सर्वेक्षण पश्चिमी प्रदेशों की ओर बढ़ा अन्य मुख्य याम्योत्तर रेखाएँ भी स्थापित की गईं। आधार रेखाएँ इन याम्योत्तर रेखाओं के लम्ब (perpendicular) के आधार पर खींची गईं। इस प्रकार के विभाजन से कस्बों की कतारें (tiers of townships), जिन्हें मालाएँ (ranges) कहा गया, पूर्व से लेकर पश्चिम के प्रदेशों तक फैल गईं। ये मालाएँ या पंक्तियाँ (ranges) एक विशेष सख्या तथा याम्योत्तर रेखा (meridian) से दिशा द्वारा जानी जाती थी। प्रत्येक कस्बा, जो 6×6 मील का होता था, 36 वर्ग मील क्षेत्रफल का था। कस्बों का उपखण्डों में उपविभाजन संयुक्त राज्य अमरीका में निम्न प्रकार से किया जाता था—

1785 में पारित भूमि अध्यादेश में प्रत्येक एक वर्ग मील के टुकड़े को 'उपखण्ड' या 'अनुभाग' कहा गया। इस अध्यादेश से यह भावना भी स्पष्ट रूप से झलकती थी कि सार्वजनिक भूमि सरकारी आय का एक बड़ा स्रोत होनी चाहिए। टुकड़ों के न्यूनतम आकार, मूल्य तथा खरीद की शर्तों के बारे में कड़े प्रावधान किये गये। जमीन को सार्वजनिक नीलामियों में 1 डॉलर प्रति एकड़ के न्यूनतम मूल्य पर बेचा जाना था तथा रकम पूरी की पूरी नकद के रूप में लेनी थी। छोटे से छोटा अनुभाग (section or lot) खरीदने के लिए 640 डॉलर

6	5	4	3	2	1
7	8	9	10	11	12
18	17	16	15	14	13
19	20	21	22	23	24
30	29	28	27	26	25
31	32	33	34	35	36

का विनियोग आवश्यक था। किन्तु यह राशि भी अगुवाओं या छोटे किसानों, जो पश्चिम की तरफ प्रस्थान कर रहे थे, के बूते के बाहर थी। सिर्फ धनी व्यक्ति या भूमि कम्पनियाँ ही इस पहले कानून के अन्तर्गत भूमि खरीद सकती थी।

1787 के कानून में यह प्रावधान किया गया कि उत्तर-पश्चिमी प्रदेश (north-west territory) को जिलों में गठित किया जाना चाहिए। प्रत्येक जिले में एक गवर्नर तथा कुछ न्यायाधीश काग्रेस द्वारा नियुक्त किये जाने थे। अध्यादेश में कुछ नागरिक व घासक स्वतन्त्रताएँ भी सम्मिलित थी। इस अध्यादेश में उत्तर-पश्चिम में दासता पर प्रतिबन्ध लगा दिया। इस अध्यादेश में इन नये क्षेत्रों के लिए भी अन्त में समानता का दर्जा देने का प्रस्ताव था। अध्यादेश ने नये फैलाये गये क्षेत्रों को भी मातृ-देश (mother country) के उपनिवेश मात्र मानने की प्रथा भी समाप्त कर दी। नये आबाद हुए क्षेत्रों को भी समान राजनीतिक एवं आर्थिक अधिकार प्रदान किये गये।

भूमि अध्यादेश (1796-1862)—1785 के अध्यादेश के बाद पश्चिमी प्रदेश में भूमि की अवाप्ति (acquisition) में दो तत्त्वों के कारण बाधा पड़ी। पहला तत्त्व वहाँ के मूल निवासियों का घैर भाव था तथा दूसरा तत्त्व सरकारी भूमि का ऊँचा मूल्य था। रेड इण्डियनों का प्रतिरोध अन्तिम रूप से 1794 में दबा दिया गया तथा 1795 में इण्डियन सरदारों (Indian braves) के साथ एक सन्धि कर ली गई। 1796 का भूमि अध्यादेश परम्परावादियों के लिए एक और विजय थी। इस अध्यादेश ने न केवल पहले किये गये आयताकार सर्वेक्षणों को स्थाई बना दिया बल्कि इसने न्यूनतम भूमि मूल्य भी बढ़ाकर 2 डॉलर प्रति एकड़ कर दिया। न्यूनतम भूमि खरीद भी 640 एकड़ (अर्थात् एक वर्ग मील) की ही स्वीकृत की गई। इस विधेयक के अन्तर्गत बहुत कम भू-भाग देखा जा सका। 1800 में न्यूनतम भूमि-त्रय की सीमा को घटाकर 320 एकड़ कर दिया गया तथा खरीदारों को कुल रकम का केवल आधा हिस्सा ही पहले नकद देना पड़ता था तथा शेष रकम वे दो किस्तों में चुका सकते थे। 1804 में न्यूनतम भूमि त्रय-सीमा घटाकर 160 एकड़ कर दी गई।

1820 में इसे और भी कम करके 80 एक्ड़ पर ले आया गया। प्रति एक्ड़ भूमि मूल्य भी घटा कर 1 25 डॉलर कर दिया गया। इस व्यवस्था से अगुआ लोग (pioneer) अपना खेत सिर्फ 50 डॉलर के विनियोग से स्थापित कर सकते थे।

किन्तु शुरु से ही अधिवासियों (settlers) की प्रवृत्ति पैमाइश किये जा चुके क्षेत्रों से भी परे जाने की रही। जैसे-जैसे पश्चिम में भी 'भीड़' बढ़ती गई और समय गुजरता गया वैसे-वैसे यह प्रवृत्ति और भी बढ़ी। ये लोग 'आबादकार' (squatters) कहलाये। किन्तु यह आबादकारी (squattung) अवैधानिक थी हालांकि इसे रोका नहीं जा सकता था। इन आबादकारों ने अपने सघ बना लिये तथा उनकी जमीन खरीदने वाले को रोकने के उद्देश्य से ये उन्हें धमकियाँ देने लगे। यहां तक कि कांग्रेस को भी मजबूर होकर इन आबादकारों को छूट देनी पड़ी। 1841 में कांग्रेस ने एक कानून पारित किया जिसमें इन आबादकारों को 160 एक्ड़ भूमि न्यूनतम मूल्य पर खरीदने की अनुमति प्रदान कर दी गई। इस प्रकार देश की भूमि-नीति को यथासम्भव उदार रखा गया तथा इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी आमदनी बढ़ाना था।

जनसंख्या का पश्चिम की ओर प्रस्थान

अगुआ या पय-प्रदर्शक लोग (pioneers) पश्चिम की ओर अठारहवीं शताब्दी के मध्य से ही जाने लग गये थे किन्तु 1790 तक भी 2 5 लाख से अधिक लोग विशाल पश्चिम में नहीं पहुँचे थे। जनसंख्या का प्रवास (migration) धीरे धीरे तेज होता चला गया। 1800 के बाद की जनगणनाओं के आँकड़े जनसंख्या के लगातार पश्चिम-प्रवाह की सूचना देते हैं। सीमान्त प्रदेश (frontier) अपने प्राकृतिक आकर्षणों के साथ साहसियों के लिये चुम्बक की तरह था।

संयुक्त राज्य अमरीका के धुर दक्षिणी प्रदेशों में स्थित पुराने कपास के खेतों की उर्वरा शक्ति घटने के कारण भी लोगों का पश्चिम की ओर प्रस्थान 1812 से लेकर अमरीकी गृह-युद्ध होने तक तीव्रतर होता चला गया। 1840 तक तो पहले के कपास उत्पादक राज्य काफी पीछे छूट गये थे। 1860 में मिसिसिपी व अलाबामा के नये क्षेत्र काफी आगे निकल चुके थे। सीमान्त प्रदेश के टेक्सास क्षेत्र में प्रसार से कपास के उत्पादन को एक नया आयाम मिला। 'दक्षिण की इस भूमि में खिंचाव (pull) व धक्का (push) दोनों ही थे।' धक्का (push) औपनिवेशिक काल में ही लगने लग गया था जब जमीनों की प्राकृतिक उर्वरकता घटने लगी थी। छोटे किसानों को और आगे बढ़ने के लिए बाध्य होना पड़ा। अगुआ लोग इसके बाद नये समृद्ध कपास प्रदेश में खिंचे (pulled) चले आये। इन लोगों ने सार्वजनिक नीलामियों में भूमि के विशाल टुकड़े खरीदे।

उत्तरी भाग में पश्चिम की ओर प्रस्थान का आन्दोलन ओहियो (Ohio) से प्रारम्भ हुआ। 1825 तक तो न्यू इंग्लैण्ड तथा अन्य पूर्वी राज्यों से लोग ओहियो, इण्डियाना तथा दक्षिणी मिसिसिपी प्रदेशों में भारी संख्या में आने लग गये थे। 1850 तक उत्तरी इलिनोई (northern Illinois) तथा दक्षिणी विसकोसिन की सारी अच्छी

भूमि आबाद हो चुकी थी। गृह-युद्ध की पूर्व सन्ध्या पर तो लोग मध्य मिनेसोटा प्रदेश की तरफ बढ़ रहे थे। शुरू के इस सारे काल में विदेशों से भी जमीन के भूखे लोग देश में बराबर पहुँच रहे थे। 1789 से लेकर 1812 तक लगभग 2,50,000 लोग यूरोप से अमरीका में आ चुके थे। नेपोलियन की पराजय के बाद यह आवक और अधिक तेजी पकड़ती चली गई। यह सन्ध्या 1830 के दशक की 5,00,000 से बढ़कर 1840 के दशक में 15,00,000 तथा 1850 के दशक में 25,00,000 तक पहुँच गई। ये लोग इंग्लैंड, जर्मनी तथा अन्य उत्तरी यूरोपीय देशों से आ रहे थे। इन आप्रवासियों ने उत्तर-पश्चिमी राज्यों के प्रवास तथा आर्थिक जन-जीवन पर भारी प्रभाव डाला।

उत्तीसवीं सदी के आरम्भिक वर्षों में पश्चिमी प्रदेशों में जीवन बड़ा कठिन था। सबसे पहले आने वालों के लिये तो वहाँ गुजारा भर कर सकना सम्भव था। जमीन को साफ करना, मकान बनाना आदि ऐसे काम थे जिनमें पूरी की पूरी एक पीढ़ी व्यप गई। सूअर पालन तथा अनाज उगाने का काम शुरू किया गया तथा 1830 तक पश्चिम में मांस के केन्द्र कायम होने लग गये। पश्चिम में गेहूँ का उत्पादन भी शुरू किया गया तथा 1860 तक वहाँ देश का आधा गेहूँ पैदा किया जाने लगा था। 1820 के दशक में एरी नहर (Eric Canal) के खुल जाने तथा 1840 के दशक में रेल-यातायात के विकास होने से यह तय हो गया कि सम्पन्न पश्चिमी प्रदेशों के उत्पाद बढ़ती हुई मात्रा में पूर्वी प्रदेशों तक पहुँचाये जा सकेंगे।

दासता का अर्थशास्त्र—1800 तक सभी मूल राज्यों ने अपने यहाँ से दासों की विदेशों से खरीद की प्रथा का उन्मूलन कर दिया था। किन्तु दक्षिणी प्रदेशों में दासों की तस्करी जारी रही तथा 1800 से लेकर 1862 तक दासों की जनसंख्या में लगभग 25 लाख दास और जुड़ गये। 1819 में देश में 11 दास-मुक्त तथा अन्य 11 दास-प्रथा प्रचलन वाले राज्य थे। 1860 में लिकन के राष्ट्रपति चुन लिये जाने के बाद दक्षिणी राज्यों के समक्ष या तो आत्मसमर्पण या फिर पृथक् हो जाने का ही विकल्प रह गया। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना जिससे देश में एक 'मूखेंतापूर्ण' और अनावश्यक युद्ध शुरू हो गया।

अमरीका में दासता का आरम्भ औपनिवेशिक काल में हुआ था जब वहाँ श्रमिकों की कमी थी। दास लोग तम्बाकू, चावल तथा गन्ने की खेती के लिए बहुत लाभदायक थे। दक्षिणी प्रदेशों में कपास की खेती में तेजी से वृद्धि होने के कारण भी दास लोग अनिवार्य बन गये। दक्षिणी राज्यों के नर्म जलवायु ने भी दास-प्रथा की निरन्तरता को बनाये रखने में सहायता की। संयुक्त राज्य अमरीका में वागानो (plantation) ने दास-प्रणाली को आर्थिक आधार प्रदान किया। यू० बी० फिलिप्स के अनुसार, वागान एक ऐसी इकाई थी जिसमें कम से कम 20 दास काम करते थे व एक ओवरसियर उनकी देख-भाल करता था। लुईसियाना के गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में इन इकाइयों का आकार बहुत बड़ा था जिनमें 20 से लेकर 40 हजार एकड़ तक भूमि होती थी तथा जो 500 या उससे भी अधिक दासों का उपयोग करती थी। बॉनरॉड तथा मेयर ने गणना की है कि इन दासों से प्राप्त प्रतिफल 22 से लेकर

13% तक होते थे ।

1860 में दक्षिणी राज्यों में लगभग 4 मिलियन नीग्रो तथा 8 मिलियन श्वेत लोग थे । किन्तु 5 मिलियन से अधिक श्वेत लोग भी अत्यधिक निर्धन थे तथा दक्षिणी प्रदेश की अर्थव्यवस्था इतनी अनाकर्षक थी कि वह आप्रवासियों को अपनी ओर खींचने में असफल रही । 1860 में दक्षिणी प्रदेशों की जनसंख्या में से केवल 3 4% विदेशों में पैदा हुए लोग थे जबकि न्यू इंग्लैण्ड में यह प्रतिशत 15 था । इतना ही नहीं, दक्षिणी प्रदेश भूमि, थम, पूँजी तथा साहसियों की गतिविधियों की दृष्टि से भी भारी अभावों से ग्रस्त था । जब तक दक्षिण के लोग इन अभावों की क्षति-पूर्ति दासों के शोषण द्वारा कर सकने की स्थिति में थे तब तक तो वे सन्तुष्ट रहे किन्तु दासों को मुक्त किया जाना (वह भी स्वतन्त्र किये गये दासों को बिना भूमि या 'वैकल्पिक रोजगार प्रदान किये व भूतपूर्व मालिकों को बिना मुआवजा दिये) अमरीकी गृह-युद्ध का कारण बनी । यही कारण दक्षिणी प्रदेशों के सामान्य पिछड़ेपन के लिए भी उत्तरदायी थे ।

पश्चिम की ओर प्रस्थान के प्रभाव (Effects of Westward Movement)

अमरीकी जनसंख्या के पश्चिमी प्रदेशों की ओर प्रस्थान करने से 20 नये राज्यों का जन्म हुआ जिन्होंने सघ की सदस्यता स्वीकार की । जनसंख्या में भी तीव्र वृद्धि हुई जैसा कि निम्नांकित तालिका से स्पष्ट है—

वर्ष	अमरीकी जनसंख्या (मिलियन में)
1775	2 5
1800	5 3
1825	11 3
1853	23 3
1860	31 5

हर कुछ वर्षों के बाद जनसंख्या का दुगुना होते चले जाना एक तो अत्यधिक ऊँची जन्म दर के कारण था जो 3% वार्षिक थी । इसके अतिरिक्त यह वृद्धि आप्रवासियों के कारण भी हुई जिसका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं । मध्य अठारहवीं तथा उन्नीसवीं शताब्दियों में अमरीकी जनसंख्या के पश्चिम की ओर प्रस्थान को लेकर प्रो० जेकसन टर्नर ने एक सिद्धान्त प्रतिपादित किया है । उनके अनुसार, 'राजनीतिक एवं सामाजिक अशान्ति के प्रतिकूल पश्चिम (West) एक प्रकार का 'सेफटी वाल्व' (safety-valve) था । उसने पूर्वी प्रदेशों के दबे हुए मजदूरों को एक शरणस्थान प्रदान किया तथा तकनीकी बेकारी के विरुद्ध वह एक प्रकार का धोमा था ।' किन्तु प्रो० टर्नर के इस सिद्धान्त का प्रो० क्रुस (Krooss) ने प्रतिवाद किया है । उनका कहना है कि पश्चिम में बसने वाले प्रारम्भिक अधिवासी बोर्ड बेकार फँकट्टी मजदूर नहीं थे बल्कि वे तो कृषक थे । ये कृषक समृद्ध बनने के इच्छुक थे तथा पश्चिम की ओर जाने के लिए उनके पास काफी पैसा था ।

पश्चिम की ओर हम प्रस्थान में कुछ शीघ्र और कुछ जगली-सौन्दर्य भरा था। 'प्रकृति की शक्तियों के विरुद्ध कभी समाप्त न होने वाला सघर्ष, प्रतिद्वन्द्वी इण्डियनो तथा जंगली जानवरों के साथ सघर्ष ने मिलकर एक ऐसे आक्रामक व आत्मनिर्भर व्यक्तियों की किस्म को जन्म दिया जो नियन्त्रणों से घृणा करती थी तथा अपनी आजादी को सीमित करने के किसी भी प्रयास के विरुद्ध थी।' एडमण्ड बर्क ने इसी को 'स्वतन्त्रता की अदम्य भावना' (a fierce spirit of liberty) की सन्ना दी। पश्चिम की ओर प्रस्थान के आन्दोलन के प्रभावों को हम तीन स्पष्ट वर्गों में रख सकते हैं—

(1) आर्थिक प्रभाव—चूंकि कृषि उस युग का प्रमुख व्यवसाय था अतः पश्चिम की ओर प्रस्थान का कृषि पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। विशाल आकार अछूने भू-भागों की क्षमता का पूर्ण विदोहन तभी सम्भव बना जब पश्चिम की ओर प्रस्थान का आन्दोलन अपने पूरे वेग पर था। भू-भाग तो प्रचुर मात्रा में था किन्तु आवश्यकता तो धर्मिकों की थी। जैसा कि जेफरसन ने लिखा था, 'यूरोप में उद्देश्य यही रहता है कि वे अपनी भूमि से ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे लें क्योंकि धर्म वहाँ पर काफी है, यहाँ हमें धर्म का अधिक से अधिक लाभ लेना है क्योंकि भूमि तो प्रचुर मात्रा में है।'।

पश्चिम की ओर प्रस्थान की अवधि में सरकारी भूमि सबसे प्रमुख सट्टा गति-विधियों का केन्द्र बन गई इस युग के अगुआ लोगो ने भूमि के मूल्यों की घटा-बढ़ी में पैदा होने वाले सट्टे में भूमि को वास्तव में जोतने में भी अधिक रुचि दिखाई। पूर्वी प्रदेशों के किमान पश्चिमी प्रदेशों की अछूती मिट्टी (virgin soil) से इतने अधिक आकृष्ट हुए कि जैसे ही उनकी भूमि खरीदने वाला कोई ग्राहक मिला वे उसे बेचकर पश्चिम की ओर चल पड़े। किन्तु भूमि के लिए इस उन्माद (land craze) के कुछ नुकसान भी थे। इससे काफी अपव्यय तथा अनुचित सट्टेबाजी को बढ़ावा मिला। पश्चिम की ओर प्रस्थान के आन्दोलन से युग के तथाकथित किसान खरीदो हुई भूमि के विकास में कम तथा उसे ऊँचे मूल्यों पर बेचकर उससे लाभ अर्जित करने के अधिक इच्छुक थे।

पश्चिमी प्रदेशों में विशाल मात्रा में भू-भाग अधिग्रहित करने की प्रवृत्ति ने पूर्व तथा पश्चिम के किसानों के बीच तीव्र प्रतिद्वन्द्विता को जन्म दिया। इसका परिणाम यह निकला कि पूर्वी प्रदेश के किसानों को खेती छोड़कर डेयरी फार्मिंग, फलों को उगाने का काम आदि शुरू करने पड़े क्योंकि उनकी भूमि कम उपजाऊ थी। इसी अवधि में कपास का उत्पादन तम्बाकू तथा नील के उत्पादन से आगे बढ़ गया था। यह मुख्य रूप से दक्षिणी प्रदेशों में दामो का धर्म काम में लिये जाने तथा नील व तम्बाकू के खेतों की उर्वरा शक्ति कम हो जाने से कपास की खेती के पक्ष में किसानों के अधिक सख्या में आ जाने से हुआ। कपास सभी कृषि उत्पादों का राजा बन गया। उसका उत्पादन 1790 की 4,000 गांठों (500 पौण्ड की प्रत्येक गांठ) से बढ़कर 1860 तक 3 84 मिलियन गांठों हो चुका था। चावल व गन्ने का उत्पादन भी पश्चिम की ओर प्रस्थान के आरम्भिक वर्षों में काफी तेज गति से बढ़ा हालांकि

वे उत्पादन की दृष्टि से कपास के साथ प्रतिस्पर्द्धा नहीं कर सके ।

पश्चिम की ओर प्रस्थान के आन्दोलन के तीव्र होने के साथ ही नये अधिवासियों ने भारी भाना में अनाज का उत्पादन भी प्रारम्भ कर दिया । पशुओं की संख्या में वृद्धि भी एक महत्वपूर्ण व्यवसाय बन गया, क्योंकि इस अवधि में मांस के लिए मांग अत्यधिक बढ़ चुकी थी । पश्चिमी प्रदेशों के कृषकों ने पाया कि बेकार पड़ी जमीन मक्का या मोटे अनाज के उत्पादन के लिए उपयुक्त है जिसे वे पशुओं के आहार के लिए काम लेते थे । पश्चिम की ओर प्रस्थान के आन्दोलन ने वैज्ञानिक खेती के विकास पर भी दल दिया । जेफरयाल तथा लिविंगस्टन जैसे लोगों ने खेती के नवीनतम तरीकों को लोकप्रिय बनाया । इंग्लैंड तथा यूरोप के अन्य देशों से पशुओं का आयात कर उनकी नस्ल सुधारने का काम पूरा किया गया ।

उद्योगों का विकास भी जनसंख्या के पश्चिम की ओर प्रस्थान से स्पष्ट रूप से प्रभावित हुआ । कार्यशील जनसंख्या के अधिकाधिक संख्या में पश्चिमी प्रदेशों में चले जाने के कारण पूर्वी राज्यों में श्रमिकों का अभाव हो गया । इसका परिणाम यह हुआ कि जो श्रमिक पूर्वी प्रदेशों में ही रह गये उन्हें ऊँची मजदूरी दी जाने लगी । लेकिन यह एक सक्रमणकालीन चरण था । सांख्यिकी से पता चलता है कि उस जमाने में भी पूर्वी राज्यों में भारी संख्या में लोग बेकार थे । यहाँ तब की मजदूरी की दरें भी 1850 के दशक तक कोई खास ऊँची नहीं थी । इसके ठीक विपरीत पश्चिमी प्रदेशों में कृषि मजदूरों का भारी अभाव था जहाँ पर अधिकाधिक भू-भाग कृषि कार्यों के लिए अधिग्रहित किया जा रहा था ।

उद्योग के क्षेत्र में वास्तविक महत्व की चीज यह थी कि पश्चिम की ओर प्रस्थान के आन्दोलन ने पूर्वी प्रदेशों के लिए बाजार को काफी व्यापक बना दिया । आने वाले वर्षों में पूर्वी प्रदेशों ने निर्मल माल तैयार करने में विशिष्टता प्राप्त कर ली जबकि खाद्य पदार्थों तथा कच्चे मालों का उत्पादन पश्चिमी प्रदेशों का मुख्य कार्य बन गया । जैसे-जैसे यातायात के साधन विकसित हुए पूर्व तथा पश्चिम के बीच निर्मित माल तथा खाद्य पदार्थों का यह आदान-प्रदान भी वैसे-वैसे बढ़ता चला गया । इसका एक परिणाम यह हुआ कि पूर्वी प्रदेशों में स्थित उद्योगों को बड़े पैमाने के उत्पादन के लाभ प्राप्त होने लग गए ।

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि जनसंख्या के पश्चिमी प्रदेशों की ओर प्रस्थान से अनेक आर्थिक लाभ हुए । इससे न केवल पूर्वी प्रदेशों का औद्योगिक उत्पादन प्रोत्साहित हुआ बल्कि पश्चिम में कृषि उत्पादन को इसके कारण बाकी गति मिली । सच पूछा जाए तो अमरीकी अर्थव्यवस्था की भावी समृद्धि की नींव इस पश्चिम की ओर प्रस्थान के आन्दोलन के युग में ही पड़ी ।

(2) राजनीतिक एवं सामाजिक प्रभाव—जैसे-जैसे पश्चिमी प्रदेश अधिक प्रभावशाली बने वैसे-वैसे देश में एक नई राजनीतिक स्थिति पैदा हुई । जब 1862 में उत्तरी तथा दक्षिणी राज्य आपस में भिड़ गये तब शक्ति मन्तुलन की कुन्जी पश्चिम के हाथ में ही रही । समुक्त राज्य अमरीका के राजनीतिक इतिहास में 1860 तक 20 नये राज्यों का सप में और प्रवेश कर जाना एक महत्वपूर्ण घटना थी ।

हालाकि अत्यल्प आबादी वाले ये पश्चिमी राज्य प्रतिनिधि सभा (House of Representatives) में अधिक प्रभावशाली नहीं बन पाये किन्तु सीनेट (Senate) में वे काफी शक्तिशाली सिद्ध हुए। दक्षिणी राज्य अमरीकी संघ में दास-मुक्त एवं दास-प्रथा वाले राज्यों की संख्या में सन्तुलन बनाये रखने की बात पर अड़े हुए थे। उत्तर व दक्षिण के राज्यों के बीच इस झगड़े ने पश्चिमी राज्यों को अधिक प्रभावशाली बनाया। वे राजनीतिक दृष्टि से अधिक सुदृढ़ बन गये। 1928 में राष्ट्रपति पद पर एण्ड्रयू जेक्सन (Andrew Jackson) का चुनाव, जो कि पश्चिमी प्रदेश के थे, इस बात का प्रमाण था कि राष्ट्रीय राजनीति में पश्चिम का प्रभाव निरन्तर बढ़ता जा रहा था। विश्व-प्रसिद्ध अमरीकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन भी एक पश्चिमी राज्य इलिनोय (Illinois) से ही चुनकर आये थे। पश्चिमी प्रदेशों के लोग अधिक से अधिक स्वतन्त्रता के समर्थक थे तथा वे कम से कम सरकारी हस्तक्षेप चाहते थे। इस प्रकार पश्चिमी प्रदेशों के लोग राजनीतिक क्षितिज पर उभरने लगे तथा इसमें वयस्क मताधिकार के तत्कालीन आन्दोलनों से काफी सहायता मिली। उन्होंने अधिक लोकप्रिय सरकार के गठन में योगदान दिया तथा ऐसे कानून पारित करवाये जिनसे कि औद्योगिक लोकतन्त्र की स्थापना होने में सहायता मिली।

सामाजिक दृष्टिकोण से देखने पर, जो कि पश्चिम की ओर प्रस्थान के आन्दोलन का तीमरा महत्वपूर्ण पहलू है, यह स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि इस आन्दोलन ने आप्रवासी लोगों को अधिक चुस्न एवं व्यक्तिवादी बनाया तथा उनमें स्वतन्त्रता के प्रति गहरा लगाव कूट-कूट कर भर दिया। विभिन्न जातियों और राष्ट्रीयताओं के लोग पश्चिम में आत्मसात हो गये तथा उनसे मिलकर एक 'मिश्रित अमरीकी नागरिक' (a composite type of American) का विकास हुआ। कुछ विचारकों ने यह भी लिखा है कि पश्चिम की ओर प्रस्थान के आन्दोलन ने लोगों में कानून के प्रति सम्मान को घटाया क्योंकि वहाँ के लोग स्वच्छता से रहने में विश्वास करते थे। उन्हें कोई पूछने वाला नहीं था। उन्होंने 'सांस्कृतिक मूल्यों में इस ह्रास तथा सामाजिक अनुशासन में इस गिरावट को अप्रतिबन्धित व्यक्तिवाद, भौतिक मान-दण्ड तथा हिंसा में वृद्धि व कानून के प्रति असम्मान का परिणाम बताया।' बन्दूकें दागते हुए नौजवान पश्चिमी प्रवासी (cowboys) पश्चिम का प्रतीक बन गये।

तीसरा अध्याय

कृषि का विकास

(DEVELOPMENT OF AGRICULTURE)

1862-1920 के दौरान भूमि नीति

1862 से 1920 तक की अवधि को पश्चिम की ओर प्रस्थान का दूसरा चरण भी माना जाता है। यह चरण 1862 में वासभूमि विधेयक (Homestead Act, 1862)¹ पारित होने के साथ ही आरम्भ हुआ। इस अधिनियम ने वास-भूमिपतियों (Homesteaders) को 160 एकड़ भूमि तक रख सकने की अनुमति दी किन्तु पूर्वतीय क्षेत्र में यह मात्रा काफी कम थी। इस सीमा में ढील देने के लिए अमरीकी कांग्रेस ने चार अलग अलग भूमि विधेयक बनाये जिनका उद्देश्य अछूती तथा बेकार पड़ी हुई भूमि का विकास करना तथा पश्चिमी प्रदेशों में उसे कृषि कार्य के अन्तर्गत लाना था। ये चार विधेयक निम्न थे—

(i) इमारती लकड़ी विधेयक, 1873 के अन्तर्गत ऐसे किसी भी व्यक्ति को 160 एकड़ भूमि नि शुल्क आवंटित की गई जो उसमें से 40 एकड़ पर पेड़ लगाने का वायदा करता।

(ii) मरुभूमि विधेयक, 1877 ने ऐसे किसी भी व्यक्ति को 640 एकड़ भूमि 1.25 डॉलर प्रति एकड़ के भाव से खरीदने की अनुमति दे दी जो तीन वर्ष के भीतर उस भूमि पर सिंचाई की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी लेता।

(iii) इमारती लकड़ी व प्रस्तर कानून, 1878 में महुँगी इमारती लकड़ी व प्रस्तर भूमि को 2.50 डॉलर प्रति एकड़ की दर से बेचने की व्यवस्था की।

(iv) इमारती लकड़ी कटाई कानून, 1878 ने कुछ क्षेत्रों के नागरिकों को सरकारी भूमि से बिना भुगतान किये लकड़ी काटने का अधिकार दिया यदि उस लकड़ी का उपयोग मकान बनाने या कृषि कार्यों के लिए किया जाना था। और भी अनेक तरीकों से सरकारी भूमि निजी व्यक्तियों को हस्तान्तरित की गई।

¹ वासभूमि विधेयक 1862 के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति को जो अपने परिवार का मुखिया है या जो 21 वर्ष की आयु पार कर चुका है तथा संयुक्त राज्य अमरीका का नागरिक है या जिसने अमरीकी नागरिकता प्राप्त करने की अपनी इच्छा के लिए घोषणा-पत्र भर दिया है तथा जिसने संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार के विरुद्ध कभी हथियार नहीं उठाये हैं और न ही उसके शत्रुओं को किसी प्रकार की सहायता पहुँचाई है। 1 जनवरी 1863 के बाद से अविनियुक्त ताबजनिक्त भूमि (unappropriated public lands) का एक-चौथाई अनुभाग (one-quarter section) या उससे कम भूमि प्राप्त करने का अधिकार होगा।

सार्वजनिक नीलामियाँ भी 1891 तक चलती रही। पश्चिमी राज्यों तथा रेल मार्ग कम्पनियों को भी सधीय सरकार ने विशाल भू-भाग अनुदान के रूप में स्वीकृत किये। डाएस विधेयक, 1887 (Dawes Act, 1887) ने लगभग 100 मिलियन एकड़ में फैले हुए इण्डियन क्षेत्र (Indian territories) को विक्रय के लिए खोल दिया। वासभूमि विधेयक (Homestead Act) को भी 1904 में संशोधित किया गया ताकि बसने वाले लोग 640 एकड़ का एक पूरा अनुभाग (section) खरीद सकते।

भूमि का वितरण—इन वर्षों में भूमि का जिस प्रकार वितरण हुआ वह बड़ा रोचक था। सार्वजनिक स्वामित्व की कुल भूमि¹ अमरीका में 1789 से 1904 के बीच 1,441 मिलियन एकड़ रही। इसमें से 278 मिलियन एकड़ भूमि निजी व्यक्तियों द्वारा नकद रकम देकर अधिग्रहित की गई तथा 273 मिलियन एकड़ भूमि राज्यों तथा रेल-मार्ग कम्पनियों को निशुल्क दे दी गई। विभिन्न विधेयकों के अन्तर्गत निजी व्यक्तियों द्वारा निशुल्क अधिग्रहित भूमि 147 मिलियन एकड़ रही। शेष भूमि सरकार द्वारा प्रारक्षित (reserved) कर ली गई। 1904 के बाद विवेक सगत बनाने के उद्देश्य से भूमि नीति में अनेक परिवर्तन किये गये। किन्तु तब तक लगभग सारी अच्छी कृषि-योग्य भूमि बेची या बाँटी जा चुकी थी। 1920 में खाली भू-भाग जिसका निपटारा किया जाना था, 200 मिलियन एकड़ के लगभग था।

भूमि की अत्यधिक उपलब्धि—इस अवधि की अमरीकी भूमि नीति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू वह गति थी जिससे कृषि योग्य, खनिज तथा इमारती लकड़ी वाले भू-भाग को निजी व्यक्तियों को हस्तान्तरित किया गया। इस तीव्र गति ने बाद में कुछ समस्याएँ भी पैदा की जब अयोग्य व्यक्तियों ने अपनी भूमि गवा दी तथा वे आसामी बनने के लिए वाध्य हो गये। किन्तु पश्चिमी प्रदेशों का कृषिगत उत्पादन इतना बढ़ गया था कि उसके बाजार मूल्य लागतों से भी नीचे गिरने लगे थे। अन्त में, भूमि की अत्यधिक उपलब्धि ने अपव्ययी कृषि पद्धतियों को बढ़ावा दिया।

पश्चिमी प्रदेशों पर अन्तिम चढ़ाई खनिकों व पशुपालकों (cattlemen) ने की। 1850 के बाद कैलिफोर्निया में स्वर्ण की खोज के बाद पश्चिमी प्रदेशों में खनिज सम्पदा के सर्वेक्षणों को प्रोत्साहन मिला। इन आवागमनों ने अन्तिम सीमाओं तक अधिवामों को प्रोत्साहित किया। खनिकों के पीछे पीछे व्यवसायी, कारीगर तथा अन्य पेशेवर लोग भी इधर आये। गृह-युद्ध (1861-1865) के बाद पश्चिमी राज्यों के महान् मैदानों (great plains) में पशुपालन उद्योग (range-cattle industry) जोर पकड़ गया। यह उद्योग 1885 तक अपने चरम बिन्दु पर पहुँचा किन्तु बाद में उसकी अवनति आरम्भ हो गई। एब स्थान से दूसरे दूर के स्थान तक पशुओं को ले जाने में बाधाएँ उपस्थित हो गयीं जब किसानों ने अपने खेतों के इर्द-गिर्द काँटेदार तारों की बाड़ लगा दी। रेल मार्ग यातायात विकास के बाद पशुपालन क्रियाएँ अधिक विकेन्द्रित हो गयीं।

प्रमुख फसलों का उत्पादन—इस अवधि में प्रमुख फसलों के कुछ नये क्षेत्र भी स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आये। गेहूँ व मक्का के उत्पादक क्षेत्र मिनेसोटा,

डाकोटाज, इण्डियाना तथा इलिनोय में विकसित हुए। अनाज (corn) उत्पादन¹ 1870 के 800 मिलियन बुशल से बढ़कर 1915 तक 3,000 मिलियन बुशल तक जा पहुँचा। इसी अवधि में गेहूँ का उत्पादन भी 173 मिलियन बुशल से बढ़कर 1,000 मिलियन बुशल हो गया।

1860-1914 की अवधि में कपास का उत्पादन चौगुना हो गया। यह 1914 में 16 मिलियन गाँठों के बराबर हो चुका था। उधर कपास का उत्पादन-क्षेत्र पश्चिमी प्रदेशों में फैलता रहा, तब तक तम्बाकू दक्षिणी प्रदेशों की दूसरे नम्बर की फसल बन गई। जब न्यू इंग्लैण्ड तथा न्यूयार्क के डेयरी फार्मिंग के विशेषज्ञ किसान पश्चिमी प्रदेशों की आर बढ़े तो वहाँ डेयरी उद्योग भी विकसित होने लगा।

अमरीकी कृषि का 1862 से 1920 तक का विकास

(i) **कृषि का यन्त्रीकरण**—कृषि में मशीनों का उपयोग वहाँ आवश्यक हो जाता है जहाँ जनसंख्या कम हो तथा श्रमिकों का अभाव हो। खेतों पर मशीनों के प्रयोग का अर्थ होना है पूँजी का प्रयोग ताकि भूमि की उत्पादकता को बढ़ाया जा सके। अमरीकी कृषि के यन्त्रीकरण का पहला काल 1830 से 1880 तक चला जब आधारभूत आविष्कारों का प्रयोग कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए किया गया। दूसरी अवधि 1910 तक चली जिसमें पशु शक्ति पर आधारित मशीनों का व्यापक रूप से उपयोग किया गया। शक्ति-चालित मशीनों का तीसरा काल 1910 के बाद से शुरू हुआ तथा वह आज तक जारी है।

1830 तक अनाज की फसल हाथ के औजारों में काटी जाती थी। गृह-युद्ध से पहले का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृषि आविष्कार पंजीकृत कटाई मशीन (mechanical reaper) का रहा। 1857 तक इस्पात के चूने हल भी लोकप्रिय हो गये। इस्पात के खुदाई यन्त्र, जुताई मशीनें तथा गाहने की मशीनें भी 1860 तक खूब काम में लिये जा रहे थे। किन्तु इन मशीनों से बहुत कम श्रम की बचत होती थी। 1880 के बाद संयुक्त फसल कटाई व गाहक यन्त्र (combined harvester-thresher) काम में लिये जाने लगे। 1900 में तो ऐसे अनेक कृषि यन्त्र काम में लिये जा रहे थे जिन्हें पशु शक्ति से चलाया जाता था। 1900 में उपलब्ध पशु शक्ति 18.5 मिलियन अश्व शक्ति क्षमता (horse power) की थी।

1905 में पेट्रोल-में चलने वाला ट्रैक्टर बना। प्रथम विश्व-युद्ध तक यह स्पष्ट हो गया कि ये ट्रैक्टर पशु शक्ति को प्रतिस्थापित कर देंगे। 1920 में ही देश में 2.5 लाख ट्रैक्टर हो चुके थे तथा उनकी संख्या तेजी से बढ़ रही थी। पशुओं की नस्ल, मिट्टी की किस्म तथा पौधों की क्षमता सुधारने में विज्ञान का उपयोग भी 1920 के बाद लोकप्रिय हो गया। कृषि में आधुनिक विज्ञान के 'चमत्कार' तो अभी देखे जाने शेष थे किन्तु उनकी नींव रखी जा चुकी थी।

(ii) **गृह युद्ध तथा कृषि के लिए खराब समय (1864-1896)**—गृह-युद्ध के निकट का समय कृषि के लिए खराब रहा। कृषि पदार्थों की पूर्ति उनकी माँग

की तुलना में काफी तेजी से बढ़ रही थी इसलिए उनके मूल्य इतने घट गये थे कि उनसे लागत भी पूरी नहीं मिल पा रही थी। इसलिए इस अवधि में कृषि आय काफी गिरी हालांकि खेतों की संख्या तिगुनी हो गई तथा कृषि पदार्थों के उत्पादन का वक्र भी काफी ऊपर चढ़ा।

खेतों की संख्या में वृद्धि

वर्ष	खेतों की संख्या (मिलियन में)
1860	2 04
1870	2 66
1880	4 00
1890	4 57
1900	5 74
1910	6 41
1920	6 52

Source Historical Statistics of the United States, 278

हालांकि जनसंख्या में वृद्धि जारी थी किन्तु कृषि पदार्थों की खरीद पर प्रतिशत प्रति व्यक्ति व्यय घट रहा था। 1870 में लोग अपनी चालू आय का 33% कृषिगत पदार्थों पर खर्च करते थे। 1890 में यह गिरकर 20% रह गया। इस तरह जहाँ जनसाधारण की आय बढ़ी, वहीं उन आमदनीयों का कृषि क्षेत्र को जाने वाला अनुपात घटता गया।

इस बीच कृषि निर्यात 1870 के 297 मिलियन डॉलर के स्तर से बढ़कर 1900 तक 840 मिलियन डॉलर तक पहुँच गये। इस निर्यात माँग ने कृषि क्षेत्र की सहायता की किन्तु प्रभावी घरेलू माँग के अभाव में वह अधिक कुछ प्राप्त नहीं कर पाया। इसके अतिरिक्त 1865 से 1896 तक अमरीका में औद्योगिक उत्पादन की विकास दर इतनी तीव्र नहीं थी कि वह कृषि उत्पादन में होनी वाली वृद्धि को काम में ले सकती। गृह युद्ध के बाद उद्योगों में इतनी तेजी से वृद्धि नहीं हुई कि वे लाभकारी मूल्यों पर कच्चा माल तथा खाद्य पदार्थ कृषि क्षेत्र से खरीद पाते।

(iii) स्वर्णकाल (1896-1915)—इस काल में अमरीकी किसान की आर्थिक स्थिति में महान् सुधार हुए। हालांकि कृषि उत्पादन में धीमापन आया फिर भी उसके मूल्य काफी बढ़े तथा कृषि आय में काफी वृद्धि हुई। कृषि पर आश्रित जनसंख्या 32 मिलियन के स्तर पर आकर स्थिर हो गई चूँकि कृषक समुदाय के लोग शहरों में जाकर पेशेवर बनने लग गये थे। इस तरह 1911 से 1915 तक कृषि आय का प्रति व्यक्ति स्तर 370 डॉलर था जबकि औद्योगिक आय 595 डॉलर थी। फिर भी यह एक अच्छा अनुपात था। कई कृषक अब भी निर्धन थे किन्तु बड़े भूस्वामियों की आर्थिक स्थिति में भारी सुधार हुआ।

औद्योगिक व कृषि उत्पादन सूचक (1895=100)

वर्ष	औद्योगिक उत्पादन	कृषि उत्पादन
1895	100	100
1900	120	119
1905	174	130
1910	198	132
1915	256	150

Source T W Schultz, *Agriculture in an Unstable Economy*, 1945, 115

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट हो जाता है कि 1895-1915 की अवधि में जहाँ कृषि उत्पादन में 50% की वृद्धि हुई वहीं औद्योगिक उत्पादन 156% बढ़ गया। उद्योगों के प्रसार की इस तीव्र गति का एक लाभ यह रहा कि वे कृषि-क्षेत्र के अतिरिक्त का उपयोग करने में समर्थ हो गये जिससे कृषि आमदनियाँ भी बढ़ी।

(iv) कृषि पर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव—प्रथम विश्व-युद्ध अमरीकी कृषि के लिए महान् समृद्धि लेकर आया। युद्ध में सम्मिलित राष्ट्र अपने यहाँ के कृषि-क्षेत्र से लोगों को निकलने के लिए विवश हो गये जिससे उनका कृषि-उत्पादन काफी घट गया। ऐसी परिस्थिति में ये देश अमरीका से अत्यधिक ऊँचे मूल्यों पर भी खाद्यान्नों का आयात करने के लिए बाध्य हो गये। अमरीकी भूमिपतियों ने इन देशों की मजबूरी का भरपूर लाभ उठाया।

लेकिन रॉबर्टसन का कहना है कि अनेक लेखकों ने अमरीकी कृषि पर प्रथम विश्व-युद्ध के प्रभावों को बढ़ा-चढ़ा कर बताया है। गेहूँ की 1 अरब बुशल की रिकॉर्ड फसल 1915 में प्राप्त की गई। हालांकि यह उत्पादन बाद के वर्षों में कम हो गया किन्तु युद्ध के वर्षों में भी गेहूँ के उत्पादन में ही सर्वाधिक वृद्धि हुई। इसके अन्तर्गत कृषित-क्षेत्र भी अन्य फसलों की कीमत पर बढ़ा। इसी का परिणाम था कि प्रथम विश्व-युद्ध के समय गेहूँ का उत्पादन 1909-13 के औसत उत्पादन से भी 38% अधिक रहा।

यदि सभी खाद्य फसलों को लिया जाये तो 1914-19 के दौरान उनके अन्तर्गत कुल कृषित क्षेत्र 203 मिलियन एकड़ से बढ़कर 227 मिलियन एकड़ हो

कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

वर्ष	औद्योगिक उत्पादन	कृषि उत्पादन
1915	100	100
1916	119	96
1917	118	99
1918	117	105
1919	102	106
1920	111	107

Source Schultz, *op cit*, 121

गया। समस्त खाद्यान्नों का उत्पादन प्रथम विश्व-युद्ध के दौरान 5% बढ़ा जबकि उनके अन्तर्गत आने वाले कृषित क्षेत्र में 12% की वृद्धि हुई। पशुओं की संख्या में 16% की वृद्धि हुई। युद्ध-पूर्व के अपने स्तर की तुलना में तम्बाकू के अन्तर्गत कृषित क्षेत्रफल में 1920 तक 60% की वृद्धि हुई।

(1) कृषि आन्दोलन व प्रदर्शन—उत्तीसवीं शताब्दी में अमरीकी किसान बड़ी दृष्टनीय अवस्था में थे। पश्चिम की ओर प्रस्थान तथा गृह-युद्ध से उनके और भी कठिनाइयाँ उठानी पड़ी क्योंकि कृषि पदार्थों के मूल्य घटने लगे। किसान लोग विशेष रूप से बैकरो, रेल सटक कम्पनियों तथा बड़े भूस्वामियों से विशेष रूप से नाराज थे जिन्हें वे अपना शोषण मानते थे। इस अवधि में चार महत्त्वपूर्ण कृषक आन्दोलन सघ सगठित हुए।

(अ) ग्रेंजर्स (The Grangers) पहला कृषक सगठन था जो 1867 में गठित किया गया था। 1874 तक इसकी सदस्य संख्या 15 मिलियन हो गई थी। लेकिन 1880 के बाद इसकी अवनति आरम्भ हो गई। हालांकि यह एक गैर-राजनीतिक सगठन था किन्तु इसने सुधारों के लिए दबाव डाला। यह पश्चिमी प्रदेशों में कृषकों के लिए कई रियायतों व छूटें प्राप्त कर पाने में सफल भी हुआ। इस सघ ने एक बहुत अच्छा सहकारी सगठन भी गठित किया जो ग्रेंज सदस्यों को उचित मूल्य पर सामान्य आवश्यकताओं की वस्तुओं तथा कृषि-औजार उपलब्ध कराता था।

(आ) ग्रीनबैक आन्दोलन (Greenback Movement) ग्रेंज के ही असन्तुष्ट सदस्यों द्वारा आरम्भ किया गया। किन्तु यह समूह बुरी तरह असफल रहा हालांकि इसने एक ग्रीनबैक लेबर नामक एक राजनीतिक दल भी बनाया जिसने 1878 के चुनावों में कुछ सीटें भी जीती थी। किसानों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने का यह पहला प्रयास था।

(इ) मेत्री सघ (Alliances) स्वतन्त्र कृषक क्लब थे जो दक्षिणी व पश्चिमी राज्यों में गठित किए गये थे। इन स्वतन्त्र क्लबों ने मिलकर नॉर्थ वेस्टर्न अलायंस तथा सदर्न अलायंस (North Western Alliance and Southern Alliance) बनाये। इन अलायंस ने मौद्रिक सुधारों की वकालत की तथा ये राजकीय नियमन पक्ष में थे। किन्तु इन्हें इनके आन्तिकारी विचारों के लिये अधिक समर्थन प्राप्त नहीं हुआ।

(ई) पापुलिस्ट्स (The Populists) ने अपने आपको जनरल वीवर (General Weaver) के नेतृत्व में 1891 में गठित किया। ये लोग एकाधिकार व धोर विरोधी थे। इन्होंने बैंकों, रेलवे कम्पनियों तथा सन्देशवाहकों के साधनों पर सरकारी स्वामित्व की मांग की। किन्तु उनके इस अति आन्तिकारी रव ने उन्हें अन्य परम्परावादी किसानों से विलग कर दिया।

इस प्रकार इस अवधि में आयोजित ये कृषि आन्दोलन कृषक समुदाय की सहायता करने में अधिक सफल नहीं हो पाये। किन्तु उन्होंने भारी वैधानिक सुधारों के लिए मार्ग अवश्य प्रशस्त कर दिया।

(2) सरकारी सहायता—पश्चिमी प्रदेशों में जाने वाले अगुवाओं का उत्तीसवीं सदी के विभिन्न भूमि विधेयकों का सामना मिला था। किन्तु इन विधेयकों

ने कृषि विकास का कोई कार्यक्रम तैयार नहीं किया था। हानाकि कृषि विभाग की स्थापना तो 1839 में ही कर दी गई थी किन्तु उसे मन्त्री स्तर का दर्जा 1889 में जाकर प्रदान किया गया। 1920 तक विभाग के अधीन तीन कार्य थे। (अ) शोध एवं प्रयोग, (आ) कृषि जानकारी का प्रसार, तथा (इ) उत्पादों की किस्म का नियमन।

1860 तक अनेक राज्यों में कृषि कॉलेज खोले जा चुके थे। 1887 में पारित हेच विधेयक (Hatch Act, 1887) में कृषि संस्थानों को सघीय वित्त सहायता देने का प्रावधान किया गया। 1917 के स्मिथ ह्यूग्स-विधेयक (Smith-Hughes Act) में कृषि में व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कूल स्तर पर देने के लिए प्रावधान किया गया। 1917 में पारित दो अन्य अधिनियम भी महत्वपूर्ण थे।—महले विधेयक ने कृषि विभाग को यह अधिकार प्रदान किया कि वह खेतों पर खाद्य पदार्थों के उत्पादन व अनुसंधान को प्रोत्साहन दे। दूसरे विधेयक ने सरकार को खाद्य पदार्थ पशु आहार तथा ईंधन जिसमें खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस भी सम्मिलित थे, तथा खाद व रासायनिक खादों के अवयव, औजार, बर्तन, उपकरण, मशीनें तथा खाद्य पदार्थों, आहारों व ईंधन के वास्तविक उत्पादन के लिए वांछित यन्त्रादि पर नियन्त्रण रखने का अधिकार प्रदान किया। देश में खाद्य समस्या का सही हल खोज निकालने के लिए हर्बर्ट ह्वर की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय खाद्य प्रशासन भी स्थापित किया गया।

अमरीकी कृषि का प्रसार • 1920—1962

(1) कृषि समृद्धि—1921 में कृषि मूल्यों में मामूली सी गिरावट आयी किन्तु 1925 तक वह पुन ठीक हो गयी। फिर भी किसान समुदाय अप्रसन्न ही रहा तथा वह मुधारवादी विधेयकों के लिए मांग करता रहा। भूमि के मूल्यों में अप्रत्याशित वृद्धि हो चुकी थी तथा 1920 में तो कुछ राज्यों में एक एकड़ जमीन 500 डॉलरों तक बिकने लगी थी। 1920 के बाद वाले दशक में किसानों ने भारी मात्रा में जमीन खरीदी तथा उनका ऋण दायित्व काफी ऊँचा हो गया। 1923 में ये ऋण दायित्व 11 अरब डॉलर के थे।

किन्तु ये सब कठिनाइयाँ महान् मन्दी से उत्पन्न वप्टों को देखते हुए कुछ भी नहीं थी। कृषि वस्तुओं का मूल्य निर्देशक जनवरी 1930 के 147 के स्तर से घट कर फरवरी 1933 तक केवल 57 (1909-14=100) रह गया। कृषि व गैर-कृषि आय के बीच खाई और चौड़ी हो गई। समग्र कृषि आय जो 1929 में 14 अरब डॉलर थी। घटकर 1932 में 6.5 अरब डॉलर रह गई। कृषक लोग अपनी ऋण की स्थाई जिम्मेदारी निभाने में भी असमर्थ हो गये।

कृषि मूल्यों में पुन वृद्धि का क्रम अप्रैल 1933 से शुरू हुआ तथा वे 1937 में पुन 131 के स्तर तक पहुँच गये। कुल कृषि आय भी, जो 1932 में 6.5 अरब डॉलर रह गई थी, 1940 तक बढ़कर 11 अरब डॉलर की हो गई। द्वितीय महायुद्ध से भी मन्दीग्रस्त कृषि को काफी राहत मिली। यह अनुमान लगाया

गया है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान औद्योगिक उत्पादन में 30% की वार्षिक वृद्धि हुई, कृषि उत्पादन भी 5% की दर से बढ़ा। 1946 में मूल्य नियन्त्रण हटा लिए जाने से भी कृषि मूल्य काफी बढ़ गये। 1954 तक आते-आते कृषि उत्पादन युद्ध-पूर्व के स्तर से 40% अधिक हो चुका था।

उच्च उत्पादन स्तर तथा अनुकूल कृषि मूल्यों ने मिलकर 1940 तथा 1950 के दशकों में अमरीकी कृषकों को समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1950 में कृषकों की डॉलर आय 1940 की तुलना में तीन गुना थी। मूल्यों का समायोजन करने पर भी उनकी वास्तविक आय में 50% की वृद्धि हो चुकी थी। कुल कृषि आय 1947 में 17 अरब डॉलर मूल्य की थी। 1962 में यह 40 अरब डॉलर के स्तर पर पहुँच गई। किन्तु ये महत्वपूर्ण वृद्धियाँ भी कृषक समुदाय को सन्तुष्ट नहीं कर सकी क्योंकि इस दौरान गैर कृषि क्षेत्र की आय में इससे भी अधिक तेजी से वृद्धि हुई थी।

(2) कृषि कानून—1920 से पहले सघीय सरकार द्वारा पारित कानूनों का कृषि पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ा। 1933 से 1941 के बीच पारित कानूनों का उद्देश्य अमरीकी कृषि का मन्दी से पुनरुद्धार करना था। द्वितीय महायुद्ध के दौरान पारित कृषि कानूनों का उद्देश्य कृषि उत्पादन को प्रोत्साहन देना था। युद्धोत्तरकालीन वर्षों में इन कानूनों का उद्देश्य कृषि व गैर-कृषि आय के बीच वैषम्य घटाना रहा है।

फ्रेकलिन रूजवेल्ट के राष्ट्रपति चुन लिये जाने के बाद अमरीकी कृषि नीति में आधारभूत परिवर्तन हुए। अमरीकी कृषि पदार्थों का अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में राशिपानन (dumping) करने के समर्थकों की विजय हुई जब 1933-34 में डॉलर का अवमूल्यन किया गया। कृषि समायोजन विधेयक (Agricultural Adjustment Act) 1933 में पारित किया गया। इस विधेयक के अन्तर्गत एक कृषि समायोजन प्रशासन (Agricultural Adjustment Administration or A A A) स्थापित किया गया। इन प्रशासन को कृषिगत पदार्थों की पूर्ति सीमित रखकर उनका मूल्य चढ़ाने का दायित्व सौंपा गया। कृषि समायोजन प्रशासन (A A A) अगली मौसम में फसलों की बुवाई के क्षेत्रफल का निर्धारण करता था। उन किसानों को समायोजन भुगतान (Adjustment Allowance) या मुआवजा दिया जाता था जो प्रशासन के निर्देशानुसार अपने कृषि क्षेत्र को सीमित करते थे।

लेकिन कृषि समायोजन प्रशासन (A A A) की मूल योजना को सर्वोच्च न्यायालय ने 1936 में असाविधानिक करार दे दिया। 1938 में एक संशोधित विधेयक पारित किया गया। मुख्य अनाजों के मूल्यों को समर्थन देने के उद्देश्य से वस्तु साख निगम (Commodity Credit Corporation, CCC) भी 1933 से कार्य कर रहा था। 1938 के संशोधित कृषि समायोजन विधेयक (A A A) ने वस्तुओं के प्रतिकूल ऋण देने के वस्तु साख निगम (CCC) के अधिकारों को और भी बढ़ा दिया। 1939 से 1941 के बीच निगम (CCC) ने गेहूँ, कपास, तम्बाकू तथा अनाज के विशाल भण्डार एकत्रित कर लिये। सरकार इन भण्डारों को

द्वितीय विश्व-युद्ध के दौरान भारी लाभ पर बेचने में सफल हुई।

द्वितीय विश्व-युद्ध ने अमरीकी कृषि के सम्मुख उपस्थित समस्याओं के स्वरूप को बदल दिया। कृषि उत्पादन में वृद्धि करना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन गई। 1941 में कांग्रेस ने इस सम्बन्ध में अनेक विधेयक पारित किये। वस्तु साख निगम (CCC) को मुख्य फसलों को उनके मूल्य के 85% तक समर्थन प्रदान करने के निर्देश दिये गये। तिलहों व मांस के उत्पादन में बढ़ोत्तरी करने पर अधिक बल दिया गया। किन्तु युद्ध के वर्षों में मूल्य समर्थन की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। 1944 से 1946 तक निगम (CCC) ने बहुत कम ऋण स्वीकृत किये। फसलों उगाने पर लगे हुए अधिकांश प्रतिबन्धों को भी द्वितीय महायुद्ध के दौरान हटा लिया गया।

लेकिन द्वितीय महायुद्ध का यह समृद्धि का काल बहुत कम समय का महमान रहा। 1948 के बाद पुन एक बार कृषि मूल्यों में गिरावट शुरू हो गई। वस्तु साख निगम को फिर एक बार ऋण देने की आवश्यकता पड़ गई। 1949 में एक कृषि विधेयक लाया गया। इस विधेयक ने कृषि पदार्थों को आधारभूत, गैर-आधार-भूत तथा शेष वस्तुएँ, इन तीन श्रेणियों में वर्गीकृत कर दिया। आधारभूत वस्तुओं को भरपूर समर्थन प्रदान किया गया। 1954 तक निगम ने 7 अरब डॉलर के ऋण दे दिये थे। गेहूँ, मक्का तथा अन्य आधारभूत अनाजों के भारी अतिरेक ने चिन्ता खड़ी कर दी। कनेडी प्रशासन ने 1961 में एक विधेयक पारित किया जिसमें गेहूँ तथा मक्का के अन्तर्गत कृषित क्षेत्र में भारी कमी का प्रस्ताव था। कुल कृषित क्षेत्र के 23% से घटकर यह 1962 में 18% के स्तर तक आ गया।

(3) माग व पूर्ति के बीच असन्तुलन—1920 के बाद के दशकों में अमरीकी कृषि को हमेशा ही अधिक पूर्ति व कम माग से ग्रस्त होना पड़ा है। इनके परिणामस्वरूप कृषि मूल्य केवल लागत के बराबर रह पाये हैं। अत्यधिक पूर्ति के लिए निम्न तत्त्व उत्तरदायी रहे हैं

(अ) 1920 के बाद से अब तक अनाज के उत्पादन में लगा हुआ 350 मिलियन एकड़ का कृषित क्षेत्र लगभग स्थिर बना रहा है।

(आ) तकनीकी प्रगति तथा यन्त्रीकरण ने उत्पादकता में निरन्तर वृद्धि की है। सिर्फ ट्रैक्टरों की संख्या ही 1960 में 4 75 मिलियन हो चुकी थी जो 1920 में केवल 2 5 लाख थी।

(इ) मौसम में अनुभूति उतार-चढ़ाव आये हैं जैसे गेहूँ का उत्पादन 1933 से 1936 तक औसत उत्पादन स्तर से भी 25% नीचा रहा जबकि वही उत्पादन 1942 में औसत से 44% अधिक था।

(ई) कृषि उत्पादन की मूल्यों के प्रति प्रतिसादनशीलता (responsiveness) अत्यधिक धीमी रही है। इसमें समय का अन्तराल बना रहता है।

कृषि पदार्थों के लिए अपेक्षाकृत मन्द मांग के लिए उत्तरदायी कारणों को भी इस प्रकार निचोड़ कर रखा जा सकता है।

(अ) संयुक्त राज्य अमरीका में जनसंख्या वृद्धि की दर में कमी आ चुकी

हे। यह कमी 1910 के बाद से आई है। 1880 में जनसंख्या वृद्धि की वार्षिक दर 2.6% थी जो 1940 में घटकर 0.72% रह गई थी। 1960 में यह बढ़कर 1.8% पहुँच गई किन्तु 1979 में यह पुनः 1 प्रतिशत से कम पर आ चुकी है।

(आ) कृषि पदार्थों के लिए माँग की आय व मूल्य लोच-शीलता का नीचा होना भी कृषि पदार्थों के लिए होनी वाली वास्तविक माँग को प्रभावित करता रहा है। अनुभवजन्य अध्ययनों से यही स्पष्ट हुआ है कि कृषि पदार्थों के लिए माँग की आय लोच कई दशकों से काफी नीची रही है तथा आय में वृद्धि के साथ इसमें और भी कमी आने की सम्भावना बनी हुई है। कृषि उत्पादन में भविष्य केवल उन्हीं वस्तुओं के साथ है जिन्हें 'खाने में अच्छी' माना जाता है।

(इ) उपभोक्ताओं की रुचि में परिवर्तन, पोषक आहार की आवश्यकताओं के प्रति जानकारी बढ़ने आदि ने भी खाद्य पदार्थों की माँग को अनाजों से अन्य वस्तुओं की ओर मोड़ दिया है।

(ई) कृषि पदार्थों से प्रतिद्वन्द्विता करने वाले अन्य औद्योगिक पदार्थों के विकास ने भी कृषि पदार्थों की माँग में कमी की है। उदाहरण के लिए कृत्रिम धागों ने कपास व ऊन की माँग को काफी गिराया है।

(उ) औद्योगिक उत्पादन में उतार चढ़ावों ने भी कृषि पर विपरीत प्रभाव डाला है। 1896 से 1915 तक के कृषि के स्वर्ण युग में उद्योगों का प्रसार भी तीव्र गति से हुआ था जिसके कारण कृषि पदार्थों का अतिरेक उसमें खप गया था।

1941 से 1948 तक की अवधि में कृषि का विकास स्वाभाविक था क्योंकि इस बीच घरेलू अर्थव्यवस्था में भी तेजी का चक्र चला तथा कृषि निर्यातों में भी तेजी से वृद्धि हुई। 1940 से 1953 के बीच औद्योगिक एवं कृषि पदार्थों का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में बढ़ा।

औद्योगिक एवं कृषि उत्पादन सूचकांक 1940-1953 (1940=100)

वर्ष	औद्योगिक उत्पादन	कृषि उत्पादन
1940	100	100
1941	130	104
1942	158	116
1943	190	114
1944	187	118
1945	160	117
1946	134	121
1947	149	116
1950	167	124
1951	179	126
1953	200	131

इसके बाद वाले दशक में कृषि उत्पादन फिर एक बार लड़खड़ाया क्योंकि इस अवधि में औद्योगिक उत्पादन भी घिसटता रहा। 1953 से 1962 की अवधि में औद्योगिक उत्पादन कृषि उत्पादन को पीछे छोड़ देने में विशेष सफलता प्राप्त नहीं कर पाया।

औद्योगिक एवं कृषि उत्पादन सूचकांक (1953-1962) (1953=100)

वर्ष	औद्योगिक उत्पादन	कृषि उत्पादन
1953	100	100
1955	106	103
1957	110	102
1959	116	111
1961	120	115
1962	130	116

(4) निर्यातों में कमी—दोनों महायुद्धों को छोड़कर 1910 के बाद से ही अमरीकी खाद्य पदार्थों तथा पशुओं पर आधारित उत्पादों के लिए निर्यात बाजार में बराबर कमजोरी बनी रही है। 1930 के बाद तथा 1940 के अन्त तक कृषि निर्यातों में मामूली वृद्धि हुई। 1940 में तो वे केवल 500 मिलियन डॉलर थे जो पिछले 50 सालों में न्यूनतम थे। द्वितीय महायुद्ध के बाद अमरीकी सरकार ने कृषि अतिरेक को विदेशी बाजारों में राशिपातन (dumping) हेतु उपयोग में लेने की नीति अंगीकार की। युद्धोत्तरकालीन वर्षों में भारी मात्रा में किये गये कृषि निर्यात ऋण एवं भेंट दिये जाने के कारण ही सम्भव हुए। 1948-49 के मध्य किये गये कुल कृषि निर्यातों में लगभग 60% के लिए वित्त का प्रवन्ध अमरीकी विदेश सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत किया गया था। 1954 से जी० एल० 480 के अन्तर्गत अमरीका ने अतिरेक वाले अनाजों के निर्यात के लिए भारी अनुदान की व्यवस्था की। व्यापारिक फसलों का निर्यात, जो 1953 में 2500 मिलियन डॉलर के लगभग था, 1962 में बढ़कर 3,500 मिलियन डॉलर तक पहुँच गया। किन्तु इनमें से भी 40% निर्यात विस्तृत रूप से सहायता के रूप में थे।

(5) न्यू डील (New Deal) नीति के अन्तर्गत व उसके बाद अमरीकी कृषि—1933 में स्वीकार की गई न्यू डील नीति (New Deal Policy) ने मन्दी के आघात से मुक्त हो चुकी कृषि को पुनरुज्जीवित करने के उद्देश्य से निम्न महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम सम्मिलित किये गये थे (अ) कृषि साख सुविधाएँ, (आ) मिट्टी-संरक्षण कार्यक्रम, (इ) कृषि समायोजन कार्यक्रम (Agricultural Adjustment Programme)।

न्यू डील कार्यक्रम ने अमरीका के दूरस्थ भागों में मिट्टी के संरक्षण, बाढ़ नियन्त्रण तथा वैज्ञानिक सेती जैसे कार्यक्रमों को प्रोत्साहन दिया। कृषक आबादी के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ भी तैयार की गयीं। किन्तु न्यू डील नीति ने यह

अनुभव कर लिया कि मन्दी का मुख्य कारण अति-उत्पादन ही था। जैसा कि पहले भी लिखा जा चुका है, 1933 में एक कृषि समायोजन कार्यक्रम शुरू किया गया जिसका उद्देश्य सतत आधारभूत अनाजों का उत्पादन घटाना था। इसके अन्तर्गत गेहूँ व कपास के अन्तर्गत आने वाले कृषि क्षेत्रों के एकड़ों को कम किया गया तथा किसानों को मुआवजे के रूप में 'लाभ-भुगतान' (benefit-payments) किये गये। किन्तु पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि करने तथा उसके फलस्वरूप कृषि-क्षेत्र में समृद्धि लाने के लिए कृत्रिम अभाव उत्पन्न करने वाली इस नीति की सफलता के बारे में शुरू से ही सन्देह रहा। अच्छे बीजों तथा सुघरे हुए रामायनिक सादों के प्रयोग के कारण कृषि के अन्तर्गत लिये एकड़ कम कर देने के वाद भी किसानों ने पहले से अधिक फसलों पैदा की। इस तरह न्यू डील नीति भी अमरीकी कृषि की मूल समस्याओं का समाधान खोजने में सफल नहीं हुई। ये मूल समस्याएँ थी (अ) अपर्याप्त मांग, तथा (आ) उत्पादन की ऊँची लागत। केवल द्वितीय महायुद्ध ही इन समस्याओं को हल कर पाया किन्तु वह भी अस्थायी तौर से।

(6) द्वितीय महायुद्धोत्तर कालीन परिवर्तन—युद्धोत्तर कालीन अमरीकी कृषि के युग में दो प्रकार के फार्म प्रमुख रहे हैं : व्यावसायिक फार्म तथा गैर व्यावसायिक फार्म। व्यावसायिक फार्म अक्सर बड़े व यन्त्रीकृत होते हैं। जबकि गैर व्यावसायिक फार्म 'पिछवाड़े के गाँव रखने व बगीचा लगाने वाले' फार्म होते हैं। व्यावसायिक फार्म अपने व्यवसाय के परिमाण को इन सीमा तक बढ़ाने में सफल हो चुके हैं कि जिससे कृषक परिवार को सन्तोषप्रद आय प्राप्त हो सकने के आसार काफी अच्छे हैं।

कृषि उत्पादन भी द्वितीय महायुद्ध के बाद से निरन्तर बढ़ता जा रहा है। अनाज का उत्पादन तो 1959 में ही 200 मिलियन टन की सीमा पार कर चुका था। 1930 की तुलना में पौल्ट्री तथा मांस का उत्पादन भी 1960 तक दुगुना हो चुका था। कृषि पदार्थों के उत्पादन में यह वृद्धि भूमि व श्रम की बढ़ी हुई उत्पादकता का परिणाम रही है। कार्यकुशलता में यह सुधार उत्पादन के साधनों को विभक्त करने व उनका समन्वयन करने में अधिक सुस्पष्टता होने, उन्नत किस्म की फसलों व सक्कर पशुओं का उपयोग करने, पशु व पौध संरक्षण कार्यक्रमों द्वारा इन सम्बन्ध में होने वाले नुकसानों को घटाने—तथा सबसे अधिक महत्वपूर्ण—खेतों की देखभाल करने वालों की प्रवृत्ति कुशलता में वृद्धि का मिला-जुला परिणाम रहा है।

द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद की कृषि का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू अमरीकी पूँजी द्वारा निरन्तर प्रतिस्थापन रहा है। 1958 में मशीनी शक्ति का उपयोग स्तर युद्ध पूर्व, की तुलना में ढाई-गुना था। उत्पादकता में वृद्धि तथा श्रम के स्थान पर बढते हुए पूँजी के प्रयोग ने मिलकर कृषि से काफी जनशक्ति को मुक्त कर दिया है। 1965 में कुल श्रम शक्ति का केवल 8.5% भाग कृषि कार्यों में लगा हुआ था। यह घटकर 1979 में 5% से भी नीचे आ गया है। हालाँकि खेतों की कुल सख्या में कमी आई है किन्तु उनका औसत आकार काफी बड़ गया है।

युद्धोत्तरकालीन वर्षों में पशुपालन पर भी काफी ध्यान दिया गया है।

लगभग एक अरब एकड़ भूमि चरागाहों के रूप में प्रयुक्त हो रही है। युद्धोत्तर काल के किसान अब व्यापार के साथ करीबी रिश्ता कायम कर चुके हैं। वे उन उद्योगों के साथ सीधे अनुबन्ध करने लगे हैं जो उनसे कच्चा माल खरीदने के इच्छुक होते हैं।

अमरीकी कृषि की समस्याएँ

(1) विशाल फार्मों का कृषि उत्पादन में बहुत बड़ा भाग है। 1959 में 56% बड़े फार्मों का 95% कृषि पदार्थों की बिक्री पर अधिकार बना हुआ था। छोटे खेतों पर लगे हुए लोगों की मर्यादा घटाने जैसे कई सुधारवादी उपाय करने के बाद भी लगभग 40% छोटे कृषकों के लिए गरीबी की समस्या अभी भी बनी हुई है।

(2) आसामी कृषकों (tenant farmers) की समस्या भी 1960 के दशक तक बनी रही। 1880 में 25% अमरीकी किसान आसामी थे। यह संख्या 1920 में बढ़कर 40% हो गई थी। यहाँ तक कि 1960-में भी यह अनुमान था कि अनाज व गेहूँ के क्षेत्रों में 40% के लगभग कृषि कार्य आसामियों द्वारा ही किया जा रहा था।

(3) कृषि क्षेत्र में भी गरीबी दक्षिणी प्रदेशों में अधिक स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। इस क्षेत्र की कृषि को पहला आघात तब लगा जब 1862 में दासों को मुक्त कर दिया गया। गृह-युद्ध के 75 वर्षों के बाद भी दक्षिणी प्रदेशों की औद्योगिक विकास की गति धीमी बनी रही तथा जनसंख्या के समक्ष जीवन निर्वाह खेती से मुक्ति पाने के कोई विशेष अवसर नहीं रहे। दूसरे महायुद्ध तक भी दक्षिणी प्रदेशों की कृषि गैर-दक्षिणी प्रदेशों की कृषि से घटिया थी। 1962 तक भी प्रति फार्म उपलब्ध भूमि का औसत दक्षिणी प्रान्तों में गैर दक्षिणी प्रान्तों के मुकाबले आधा था तथा वहाँ हर सात फार्मों के बीच एक ट्रैक्टर का औसत आता था जबकि गैर-दक्षिणी प्रान्तों में यही औसत 2 फार्मों के बीच एक ट्रैक्टर का था।

(4) पश्चिम की ओर प्रस्थान के आन्दोलन के समय से ही कृषि पदार्थों के अतिरेक की समस्या ने अमरीकी कृषि को हेरान कर रखा है। यहाँ तक कि 1961 की एक राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में भी यह कहा गया कि 'समस्या का परिमाण अतिरेक के आकार द्वारा प्रदर्शित होता है - पिछले साल का अतिरिक्त अनाज इतना है कि वह अगले 6 महीनों तक देश के सारे पशुओं के लिए पर्याप्त है' कपास का अतिरिक्त स्टॉक इतना है कि वह अगले 6 महीनों तक मिलों को चलाने के लिए पर्याप्त है। स्पष्ट है कि स्थिति में सुधार के लिए उत्पादन का प्रभावी माँग के साथ समायोजन बाध्यनीय है। जब तक यह समायोजन नहीं हो जाता तब तक अतिरेक की समस्या—चाहे वह प्रसुप्त ही क्यों न हो—लोगों की चिन्ता का एक प्रमुख विषय बनी रहेगी।'

कृषि सुधार कार्यक्रम

कृषि में तकनीकी सुधार का आशय रहा है देश की तथा सारे ससार की अधिक खाद्यान्न, पशुओं की अधिक आहार तथा लोगों की अधिक वस्त्र। लेकिन गृह

युद्ध के बाद से ही अमरीकी कृषि को अनेक मन्दियों से गुजरना पड़ा है। केवल 1895-1920 तथा 1941-52 की दो अवधियों को छोड़कर केवल बहुत अधिक कार्यक्रमाल कृषक ही कृषि को वास्तव में लाभकारी बनाने में सफल रहे हैं।

हमने उन अनेक कार्यक्रमों को प्रस्तुत किया है जो सघीय सरकार ने न्यू डील के दौरान व उसके बाद भी कृषि विकास के लिए लागू किये हैं। लेकिन इनमें से अधिकांश कार्यक्रमों ने केवल बड़े उत्पादकों को ही लाभ पहुँचाया है। सबसे अधिक अनुदान सबसे बड़े भूस्वामियों को मिले। जब न्यू डील के अन्तर्गत कृषि पर एकड़ों पर सीमा लगवाई गई तब भी इन्हीं बड़े भूस्वामियों को सबसे अधिक मुआवजे की राशि मिली क्योंकि एकड़ों में सर्वाधिक कमी भी यही लोग कर सकते थे। छोटे किसानों की स्थिति में पिछले कुछ वर्षों में सुधार आया है किन्तु वैसा कार्यशील जनसंख्या के अन्य क्षेत्रों में चले जाने से हुआ है। अमरीका में यही बात सही रही है। 1790 में 90% कार्यशील जनसंख्या कृषि में लगी हुई थी। 1960 में यह 10 प्रतिशत से भी कम हो गयी थी। अपने चरम बिन्दु पर 1916 में कृषि पर आश्रित जनसंख्या 32.5 मिलियन थी जो 1961 में 15 मिलियन से भी कम रह गई थी। इस बात पर विश्वास नहीं होता कि इतनी कम कार्यशील जनसंख्या इतना अधिक अन्न उत्पादन करती है कि वह न केवल अमरीका के लिए पर्याप्त है बल्कि शेष विश्व भी उसका लाभ उठा रहा है।

अन्य क्षेत्रों में अधिक लाभकारी अवसरों ने भी कृषि क्षेत्र से जनसंख्या का निष्क्रमण तीव्र बनाया है। अकेले 1961 में कृषि जनसंख्या में 6 लाख की कमी आई थी। अधिकांश कृषि संगठन उन उपायों से सन्तुष्ट थे जो कृषि में सुधार की दृष्टि से 1960 के बाद किये गये। यहाँ तक कि अहस्तक्षेप की नीति के उत्साही प्रवक्ता भी अब यह मानने लगे हैं कि आर्थिक उतार-चढ़ावों से किसानों की रक्षा करने के लिए किसी न किसी प्रकार का सघीय कृषि कार्यक्रम आवश्यक होता है। कृषि ने मन्दी का मुकाबला हमेशा उत्पादन के स्तर को बनाये रखकर व मूल्यों को गिरने देकर किया है जबकि उद्योगों की प्रतिक्रिया इसकी बिल्कुल विपरीत रही है। यह उपभोक्ताओं की दृष्टि से अच्छी बात हो सकती है किन्तु कृषकों के लिए यह बड़ी कठिनाई उत्पन्न कर देती है। 1960 के बाद से तो अर्थशास्त्री इस बात पर एक मत हैं कि बार-बार आने वाली मन्दियों की चुराई से बचाने के लिए एक कृषि कार्यक्रम बनाया जाना आवश्यक है। इस प्रकार के कार्यक्रम से स्वतन्त्रता की अवधारणा में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित नहीं होती।

किन्तु यह एक दुःख का विषय है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद पारित किये गये अधिकांश विधेयक कृषि के क्षेत्र में वांछित परिणाम प्राप्त कर पाने में असफल रहे हैं। 1958 में आर्थिक विकास के लिए नियुक्त समिति ने ठीक ही लिखा था कि, 'पिछले 25 वर्षों की सरकारी नीति तथा अबाध रूप से किये गये विनियोगों के उपरान्त इन तीन कृषि कठिनाइयों—अति उत्पादन, कृषि आय की अस्थिरता तथा कुछ किसानों की घोर दरिद्रता की स्थिति—में से एक भी आसान नहीं हुई है।'

1979 में अमरीकी कृषि ✓

(i) कृषि कार्य में लगाये गये एक घण्टे की उत्पादकता अब 1935 की तुलना में 4 गुना हो चुकी है। 1935 में एक कृषक 10 लोगों का पेट भर सकता था।

(ii) अमरीकी उपभोक्ता, जिसके सामने अत्यन्त आकर्षक साध्य पदार्थ चयन के लिए उपलब्ध हैं, अपने घर से जा सकने योग्य आय का लगभग केवल 17% खाने पीने के सामानों पर खर्च करता है जबकि पिछले दो दशकों में इन चीजों के दाम अत्यधिक बढ़ चुके हैं।

(iii) हालांकि कृषि जनसंख्या 1935 के 30 मिलियन से भी अधिक के स्तर से घटकर 9.5 मिलियन पर आ चुकी है, जो मुख्य रूप से अमरीकी समाज के शहरीकरण से हुआ है, कृषि-उद्योग का निरन्तर प्रसार होता जा रहा है। सैद्धांतिक अर्थों में कृषि आज भी अमरीका का अकेला सबसे बड़ा उद्योग है जिसके परिसंपत्ति 3,00,000 मिलियन डॉलर से भी अधिक मूल्य के हैं।

(iv) पिछले अनेक वर्षों में अमरीका में खेत कम व बड़े होते जा रहे हैं। खेतों की 2.8 मिलियन की वर्तमान संख्या 1935 की आधी से कम है। हालांकि हर साल करीब 1,00,000 खेत लुप्त हो जाते हैं किन्तु वे खो नहीं जाते बल्कि वे अधिक कुशल उत्पादन हेतु पड़ोस के किसी खेत में विलीन हो जाते हैं।

(v) अधिकांश खेत अभी भी 'पारिवारिक खेत' बने हुए हैं यद्यपि उनका औसत आकार अब 150 हेक्टेयर के लगभग हो चुका है जो 1935 में 62 हेक्टेयर ही था। बड़े आकार के खेत, जिन पर अधिकांश कार्य भाड़े के मजदूरों व मशीनों से किया जाता है, देश के कृषि उत्पादन का आधे से भी कम उत्पादन करते हैं। इस तरह पारिवारिक खेत (family farms) अभी भी अमरीकी कृषि की विशिष्टता बने हुए हैं।

फसले क्षेत्र, उत्पादकता, उत्पादन (1974-76)

फसल	बीया गया क्षेत्र ('000 एकड़)		प्रति एकड़ उपज		उत्पादन	
	1974	1976	1974	1976	1974	1976
अनाज का उत्पादन (कुल)	65357	67222	71 (बुधन)	87	46 63,631	62,16 000
गेहूँ	65613	70824	27 (बुधन)	30	17,96,187	21,47,401
चावल	2536	2501	4432 (Cwt)	4567	1,12,394	1 17,011
सम्ब्राकू	962	1043	2067 (पोन्ड)	2044	19 89 728	21,34,114
गन्ना	734	759	33 (टन)	37	24,812	25,790

Source : Agricultural Statistics, 1977

की दृष्टि से हम 1815 में घरेलू स्तर पर चल रहे निर्मित माल उद्योग तथा 1815 से 1860 तक औद्योगिक विकास की प्रवृत्तियों की समीक्षा कर सकते हैं। इसके बाद हम फैक्ट्री प्रणाली के अभ्युदय (Rise of the Factory System) की भी जाँच कर सकते हैं।

(i) घरेलू निर्मित माल उद्योग (Household Manufacturing)—घरेलू स्तर पर चलाया जा रहा निर्मित माल उद्योग 1805 से 1815 तक अपने चरम बिन्दु पर था। 1820 में अमरीका के कुल सूती वस्त्र का $\frac{2}{3}$ भाग अमरीकी परिवारों द्वारा तैयार किया गया था। लेकिन घरेलू स्तर पर चल रहे इन निर्मित माल के उद्योगों की 1830 के बाद अवनति प्रारम्भ हो गई। वे सूत्री वस्त्र तथा खाद्य पदार्थों को संसाधित (processing) करने की शाखाओं को छोड़ अन्य सभी उत्पादन की विधाओं से लुप्त होने लग गये। यह अवनति आधुनिक यातायात के साधनों तथा औद्योगिक संगठन के विकास के कारण आयी। फिर भी 1850 तक कुशल कारीगर (craftsmen) ही अधिकांश निर्मित माल के उत्पादन के लिए उत्तरदायी थे। 1815 से 1860 की अवधि में छोटे-छोटे मिल भी क्रियाशील थे। 1860 की एक गणना के अनुसार उम्र वर्ष देश में लगभग 20,000 लकड़ी चीरने का काम करने वाले मिल (sawmills) तथा 14,000 आटे के मिल (flour mills) थे। छोटे पैमाने पर चलाये जा रहे चर्म शोधक कारखाने, शराब के कारखाने तथा लोहे की भट्टियाँ स्थानीय बाजारों के लिए माल की पूर्ति करते थे।

(ii) कारखाना प्रणाली (The Factory System)—1845 तक ऊपर वर्णित उत्पादन पद्धतियाँ पुरानी व ममयातीत (outdated) हो चुकी थी। प्रो० ए० पी० अशर (A. P. Usher) ने कारखाना प्रणाली के आगमन से पहले के वर्षों तथा उसके आगमन के बाद के वर्षों के बीच अन्तर बड़े सुन्दर ढंग से अभिव्यक्त किया है 'सर्वाधिक प्रमुख विशेषता जो औद्योगिक क्रांति' के बाद की अवधि को उसके पूर्वगामी वर्षों से भिन्न बनाती है वह शारीरिक श्रम (Manual Labour) के स्थान पर मशीनों के प्रतिस्थापन की व्यापकता रही है।'

इस काल के दो सबसे महत्वपूर्ण घटना-क्रम इस प्रकार रहे (1) भाप की शक्ति का सफल रूप में उपयोग, तथा (2) वस्त्र उद्योग के आधारभूत संसाधनों (basic processes) में शक्ति का प्रयोग। सूती वस्तुएँ निर्मित करने के क्षेत्र में अत्यधिक तीव्र परिवर्तन हुए। 1860 तक अमरीकी सूती वस्त्र उद्योग लगभग पूरी तरह से यन्त्रीकृत हो चुका था। 1815 से 1860 के बीच पिछली अवधि में हुए आविष्कारों में सुधार भी किया गया। इस काल में ब्रिटिश नवप्रवर्तनों (innovations) को भी अमरीका में शुरू किया गया।

कारखानों का विकास सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग में हुआ। 1805 से 1815 के बीच केवल न्यू इंग्लैंड में 94 नई सूती मिलें निर्मित की जा चुकी थी। 1860 तक न्यू इंग्लैंड के मिलों में तबूओं की संख्या चार गुनी हो चुकी थी तथा वहाँ के मिल देश के कुल सूती वस्त्र उत्पादन का तीन-चौथाई भाग निर्मित कर रहे थे। सूती वस्त्र के उत्पादन में कारखानों ने अपनी श्रेष्ठता प्रदर्शित कर दी थी।

1830 के बाद ऊन उद्योग भी इसी आधार पर समर्थित होने लगा। 1860 तक तो वह इस अवस्था में पहुँच चुका था कि अमरीका की सर्वाधिक विशाल कपड़ा मिलें ऊनी फैक्ट्रियाँ ही थी।

अधिकांश अन्य उद्योगों में 1830 से 1860 तक अवधि प्रसार एवं नई उत्पादन पद्धतियों के साक्ष प्रयोगों की रही। 1845 तक लोहा उद्योग के क्षेत्र में अनेकों नए प्रतिष्ठान स्थापित हो चुके थे। गृह युद्ध से पहले ब्रेडीज बेंड आयरन कम्पनी (Brady's Bend Iron Company) अमरीका की सबसे विशाल लोहा उत्पादक कम्पनियों में से थी। 1850 तक तो अमरीकी फैक्ट्रियाँ हथियारों, दीवार घड़ियों व कलाई घड़ियों तथा मिलाई मशीनों जैसी चीजों का भारी मात्रा में उत्पादन करने लग गई थी। सवारी गाड़ियाँ, बैगन तथा खेती के काम आने वाले औजारों का भी भारी मात्रा में उत्पादन आरम्भ हो चुका था। ऐसे कारखानों में भारी स्थिर विनियोग किया गया जिनके बाजार स्थानीय ही न होकर अधिक विशाल थे।

अमरीकी निर्मित वस्तुएँ (U S Manufactures) 1860

वस्तु	वस्तु का कुल मूल्य (मिलियन डॉलरों में)
सूती वस्तुएँ	107
इमारती लकड़ी	104
जूते व बूट	92
आटा	248
वस्त्र (मिले मिलाये)	80
लोहा	73
मशीनें	52
ऊनी वस्तुएँ	61
सवारी गाड़ियाँ, बैगन	36
चमड़ा	67

Source Eighth Census of the U S Manufactures.

रॉबर्टसन¹ ने अनुमान लगाया है कि 1810 से 1860 तक की अवधि में निर्मित वस्तुओं की कुल अर्हता (value) 200 मिलियन डॉलर से बढ़कर 2,000 मिलियन डॉलर अर्थात् दस गुना हो गई। यह स्पष्ट दिखाई देता है कि निर्मित माल उद्योग ने गृह-युद्ध के पहले के 15 वर्षों में असाधारण प्रगति की। किन्तु कृषि अब भी पहले स्थान पर थी तथा उद्योगों में कुल पूँजी विनियोग कृषि भूमि तथा भवनो में लगी हुई पूँजी का केवल छठा भाग था। इतना होने के बाद भी निर्मित माल उत्पादन के क्षेत्र में अमरीका का विश्व में स्थान ग्रेट ब्रिटेन के बाद ही अर्थात् दूसरा था तथा वह विश्व का औद्योगिक नेतृत्व करने की दिशा में निरन्तर आगे बढ़ता जा रहा था।

2. उद्योग में आधारभूत परिवर्तनों (Key Changes)

का काल : 1860-1920

1880 के दशक तक कृषि ही अमरीका में आय सृजन करने वाला सबसे प्रमुख स्रोत थी। लेकिन 1900 तक निर्मित माल का वार्षिक मूल्य कृषि उत्पादन का दुगुना हो चुका था। 1910 तक अमरीकी फैक्ट्रियाँ अपने सबसे निकट के प्रतिद्वन्द्वी जर्मनी के मुकाबले दुगुना उत्पादन कर रही थी। 1913 में अमरीका का औद्योगिक उत्पादन विश्व के कुल औद्योगिक उत्पादन का एक-तिहाई था।¹

लेकिन यहाँ यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि अमरीकी औद्योगिक विकास यूरोपीय देशों के औद्योगिक विकास से दो अर्थों में भिन्न रहा (1) अमरीका के औद्योगिक उत्पाद 1900 तक प्रमुख रूप से घरेलू बाजार में ही बेचे जाते रहे। साहसियों को ऊँचे तटकरों द्वारा सुरक्षित एवं निरन्तर फैलते हुए बाजार देश की सीमाओं के भीतर ही उपलब्ध थे। (2) इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात आत्म-निर्भरता की थी। यूरोप के देश कच्चे माल का बाहर के देशों से आयात करने के लिए मजबूर थे। इसके विपरीत जैसा कि बी० एस० क्लार्क ने लिखा है, 'अमरीका की औद्योगिक प्रगति श्रमिकों को कच्चे माल के पास ले जाने का परिणाम थी।'

(1) तकनीकी परिवर्तन तथा उद्योगों का बढता हुआ आकार—जैसा कि पहले ही निष्ठा जा चुका है गृह-युद्ध से पहले सूती वस्त्र उद्योग के उत्पादन में शक्ति चालित मशीनों का प्रयोग काफी सफल रहा था। किन्तु सूती वस्त्र उत्पादन के क्षेत्र में सबसे प्रमुख घटना 1895 में नॉर्थरप (Northrup) द्वारा विकसित स्वचालित करधे की रही। 1900 के बाद स्वचालन के क्षेत्र में और आगे प्रगति हुई। प्रथम विश्व युद्ध के पहले तक दोनों प्राकृतिक धागे, सूत व ऊन, के सम्मुख कोई गम्भीर प्रतिद्वन्द्वी नहीं था। यद्यपि कृत्रिम धागे (Rayon) के लिए पहला स्वत्वाधिकार (Patent) 1884 में फ्रांस में प्राप्त कर लिया गया था किन्तु कृत्रिम रेशों ने प्राकृतिक धागों के सामने 1920 के पहले तक भी कोई गम्भीर सकट नहीं उपस्थित किया था।

सिलाई मशीनों के अधिक व्यापक उपयोग के साथ ही सिले-मिलाये वस्त्रों के उद्योगों ने भी काफी तीव्र गति से प्रगति की। 1895 तक सिलाई मशीनें भी शक्ति-चालित बन चुकी थी तथा प्रथम विश्व युद्ध आरम्भ होने से पहले ही प्रेसिंग मशीनें हाथ से इसी करने की पद्धति के स्थान पर प्रतिस्थापित की जाने लगी थी। एक ही नाप की ड्रेसें (standard size dresses) थोक स्तर पर तैयार की जाने लगी थी। जूता बनाने वाले उद्योग की तकनीक में भी भारी परिवर्तन हुआ। 1875 में गुड-ईयर वेल्ड प्रक्रिया (Goodyear Welt Process) को शुरू किया गया जिससे जूते के तलों (soles) को उनके ऊपरी भाग से बिना कीलों के उपयोग के जोड़ा जा सकता था। 1914 तक जूते निर्मित करने का अधिकांश कार्य मशीनों द्वारा किया जाने लगा था। खाद्य पदार्थों को डिब्बा बन्द (food canning) करने का उद्योग भी 1920 के बाद से दिखाई देने लगा था।

(ii) पूँजीगत वस्तुओं के उत्पादन का यन्त्रीकरण—भारी मात्रा में इस्पात तैयार कर सकने की प्रथम सफल विधि का एक अंग्रेज हेनरी टॉमस बेसेमर तथा एक अमरीकी विलियम कैली (William Kelly) ने मिलकर तैयार की थी। संयुक्त राज्य में यह विधि 1880 के आसपास स्वीकार की गई। विद्युत चालित भट्टी भी 1910 के लगभग काम में लेना प्रारम्भ किया गया। 1920 से पूर्व लौहा व इस्पात उद्योग के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण घटना विभिन्न प्रक्रियाओं के एक दूसरे से जोड़ देने (integration of processes) की रही जिससे ताप की भारी मात्रा में बचत सम्भव हो गई। इससे उत्पादन में अत्यधिक मितव्ययिता आयी।

प्रथम महायुद्ध से पहले इस्पात उत्पादन के क्षेत्र में हुए दो प्रमुख परिवर्तनों का उल्लेख खास तौर से किया जा सकता है। पहला परिवर्तन आधारभूत खुली भट्टी (basic open hearth) प्रणाली की श्रेष्ठता व उसका तीव्र गति से उपयोग रहा। यह प्रणाली बेसेमर तथा कैली द्वारा विकसित प्रणाली से काफी सुधरी हुई प्रणाली थी। इस प्रणाली की लागत बेसेमर प्रक्रिया (Bessemer process) की लागत से काफी नीची रही। दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन मिश्रित इस्पात (alloy steel) का बढ़ता हुआ उपयोग था। प्रथम विश्व युद्ध छिड़ने तक तो अमरीका मिश्रित इस्पात का विश्व में एक अग्रणी उत्पादक राष्ट्र बन चुका था। 1910 में 5 लाख टन से भी अधिक मिश्रित इस्पात का वार्षिक उत्पादन किया जाने लगा था। औद्योगिक उथल-पुथल के इस काल में अलौह धातुओं (nonferrous metals) का उत्पादन भी निरन्तर बढ़ती हुई मात्राओं में किया जाने लगा था।

गृह-युद्ध के बाद भाप से चलने वाले इंजिनो व बॉयलरो में भी कई सुधार हुए। अधिक सुरक्षा के साथ उच्च दबाव प्राप्त किये गये। मशीनी औजारों के क्षेत्र में एकरूपता, परिशुद्धता तथा डिजाइनों की सादगी की तरफ प्रगति हुई। 1910 के बाद सारे अमरीका में ओहियो सहर मशीनी औजारों के उत्पादन का प्रमुख केन्द्र बन गया। 1890 के बाद दो महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगतियाँ की जा चुकी थी : (अ) मशीनी औजारों की अर्द्ध-स्वचालित या स्वचालित बना दिया गया, तथा (आ) सम्पीडित वायु (compressed air) तथा विद्युत शक्ति का तेजी से धातु-कटाई करने वाले औजारों तथा प्रेसों (presses) को चलाने के लिये उपयोग शुरू हो गया।

(iii) शक्ति के नये स्रोत—1860 से 1920 की अवधि में वायु, जल तथा पशु व मानव शक्ति के उपयोग से शक्ति के अन्य साधनों के उपयोग की दिशा में भारी परिवर्तन हो चुका था। 1870 के बाद के दशक में भाप की शक्ति ने पानी की शक्ति से बाजी मार ली थी। 1882 में न्यूयॉर्क सहर में एडिसन (Edison) द्वारा निर्मित केन्द्रीय पावर प्लान्ट अमरीका में विद्युत शक्ति के विकास के इतिहास की एक महान् घटना थी। 1920 तक तो विद्युत शक्ति प्रजनन 40 अरब किलोवाट घण्टे हो चुका था। इस तरह 1920 में उद्योगों में काम बाने वाली कुल शक्ति का एक-तिहाई भाग विद्युत् प्रजनन से प्राप्त हो रहा था। यह अनुपात विश्व में सबसे ऊँचा था। 1920 में कोयला फिर भी शक्ति का सबसे मुख्य स्रोत बना हुआ था। लेकिन पेट्रोलियम ऊर्जा के महान् स्रोत के रूप में उभरने लगा था तथा जल विद्युत् (Hydro power)

भी दौड़ में सम्मिलित हो चुकी थी। अगले 25 वर्षों में यही दोनों शक्ति के प्रधान स्रोत बनने वाले थे।

(iv) पुजोत्पादन (Mass Production) की शुरुआत—1860 से लेकर 1920 तक चलने वाली अमरीकी औद्योगिक क्रान्ति के युग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति पुजोत्पादन तथा वैज्ञानिक प्रबन्ध का एक-दूसरे से सम्बन्धित विकास होना रही। पुजोत्पादन (mass production) की इस अभिव्यक्ति में आधुनिक अमरीकी उद्योग की लगभग सारी की सारी विशेषताएँ आ जाती हैं। इसमें उच्च स्तर का यन्त्रोपकरण सम्मिलित है। 1920 से पहले ही अधिकांश उद्योगों द्वारा मोटर चालित कनवेयरस् (conveyors) प्रयोग में लिये जाने लगे थे। प्रशिक्षित प्रबन्धकों को अप्रशिक्षित प्रबन्धकों की जगह लगाया जा रहा था तथा वैज्ञानिक प्रबन्ध (scientific management) की अवधारणा जोर पकड़ती जा रही थी।

(v) उद्योग का सकेन्द्रण (Concentration)—तकनीकी परिवर्तनों का एक स्वभाविक परिणाम यही हुआ कि फर्मों का आकार काफी बड़ा हो गया। गृह युद्ध के बाद से ही फर्मों के विशाल होने की प्रवृत्ति स्पष्ट होने लग गई थी। 1880 के लगभग एक 'समूह आन्दोलन' (combination movement) या न्यामो का अभ्युदय (rise of trusts) आरम्भ हुआ। 1880 से 1905 के बीच विशालता प्राप्त करने की प्रक्रिया और भी तीव्र हो गई क्योंकि अनेकों छोटी फर्मों ने विलयीकरण (amalgamation) के प्रयास शुरू कर दिये थे।

उद्योग में सकेन्द्रण की तीन मुख्य प्रवृत्तियाँ देखने में आ रही थी (अ) विभिन्न फर्मों का प्रबन्ध मिला-जुला बनाया गया जिससे वे बाजार को बाँट सकें, (आ) फर्मों के वित्तीय ढाँचे का जोड़ना, तथा (इ) एक ही विशाल नई फर्म बनाने के इरादे से छोटी फर्मों के प्रबन्ध, वित्तीय ढाँचे तथा भौतिक सम्पदाओं को साथ में मिलाना। प्रथम प्रकार के समूहीकरण (combination) के प्रयास कोयला, इस्पात, नमक तथा माँस उत्पादक उद्योगों द्वारा 1890 के दशक में किये गये। किन्तु इन एकीकरण के समझौतों (pooling agreements) से कोई विशेष अर्थ हल नहीं हुआ। इसमें कई कानूनी कमजोरियाँ थी। दूसरी प्रकार के समूह भी चीनी, मिट्टी का तेल, वनस्पति तेल आदि के उत्पादन का नियन्त्रण करने की दृष्टि से न्यामो के रूप में 1900 तथा उसके बाद के वर्षों में सामने आये। किन्तु इन न्यामो का धीरे-धीरे विरोध हुआ तथा इन्हें कानूनन अवैध भी घोषित कर दिया गया। अनेक महत्वाकांक्षी माहसकर्त्ताओं ने तीसरी प्रकार के समूहों को पसन्द किया जिनमें फर्मों का पूरी तरह से विलय किया जाना था। समूह का रास्ता चाहे कोई भी क्यों न रहा हो, 1904 तक एक विशाल फर्म की उपस्थिति अमरीकी निमित्त माल उद्योग का प्रतीक बन गई।

यह संयोजन आन्दोलन (combination movement) दो चरणों में चला—प्रथम चरण जिसे आड्डा संयोजन (horizontal combination) कहा गया, 1879 से 1893 के बीच पुरानी खाद्य पदार्थ तैयार करने वाली फर्मों के संयोजन से आरम्भ हुआ; द्वितीय चरण जिसे खड़े संयोजन (vertical combination) का नाम दिया गया था 1898-1904 के बीच लगभग सभी पूँजीगत वस्तुएँ बनाने वाले उद्योगों व

कुछ उपभोक्ता वस्तु उद्योगों में भी हुआ।

1870 तक अमरीका के प्रमुख उद्योग उसकी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था की सेवा करते रहे थे। केवल कुछ उन कम्पनियों को छोड़कर जो धातु के बने पुर्जे या रेल की पटरियाँ बनाती थीं, शेष सारी कम्पनियाँ कृषि से प्राप्त वस्तुओं को समाहित करने के काम में लगी हुई थी। किन्तु 1880 के बाद रेल-सड़क परिवहन के विकास ने देश को एकीकृत कर दिया तथा एक राष्ट्रीय बाजार को जन्म दिया। माँग में वृद्धि हुई जिसके परिणामस्वरूप छोटी फर्मों का प्रसार हुआ। अपने आप को दिवालियेपन से बचाने के उद्देश्य से चमड़ा, चीनी, नमक, मिट्टी के तेल आदि की उत्पादक अनेक छोटी फर्मों आड़े सयोजन (horizontal combination) के अन्तर्गत बड़ी इकाइयों में विलयीकृत हो गई। इस प्रकार जो बड़ी फर्में बनी उनके उदाहरण के रूप में स्टेण्डर्ड ऑयल कम्पनी, ओहियो, द डिस्टिलर्स एण्ड केटल फीडर्स ट्रस्ट आदि को लिया जा सकता है। इनमें सबसे शानदार कम्पनी स्टेण्डर्ड ऑयल कम्पनी रही। इस कम्पनी का गठन ओहियो की एक रॉकफेलर फर्म द्वारा 1869 में किया गया था। 1878 तक तो स्टेण्डर्ड ऑयल कम्पनी के पास देश की कुल तेल शोधन क्षमता का 90% स्वामित्व हाथ में आ चुका था।

इस्पात के क्षेत्र में कार्नेगी कम्पनी ने 1890 तक अपनी सम्पत्ति का दृढीकरण कर लिया था तथा विशान लोहा व कोयला भण्डारों पर अपना स्वामित्व कायम कर लिया था। एवं अन्य सयोजन से जो मॉर्गन के साथ हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कॉर्पोरेशन का 1901 में जन्म हुआ जिसकी पूँजी स्थापना के समय ही 1 अरब डॉलर थी। सयोजन आन्दोलन का निष्कर्ष निकालने में हम इस सन्दर्भ में लाइवमोर के अमरीकी उद्योगों के सम्बन्ध में दिये गये अनुमानों को ले सकते हैं। लाइवमोर (Livemore) के अनुसार, 1888 से 1905 के बीच कुल मिलाकर 328 सयोजन हुए। इनमें से 156 सयोजन इतने बड़े थे कि उनसे उनके क्षेत्रों पर उनका एकाधिकारिक नियन्त्रण हो गया था। इनमें से अनेक सयोजन असफल रहे किन्तु कुछ अब तक भीमकाय संगठन बन चुके हैं। 1904 तक निर्मित माल उद्योग में लगी हुई 40% पूँजी पर इन्हीं सयोजनों का नियन्त्रण था।

इसके बाद वाले 1905-1920 के काल में सकेन्द्रण की यह प्रवृत्ति कुछ धीमी पड़ गई। कुछ बड़ी फर्में तो दिवालिया हो चुकी थी तथा कुछ फर्मों को न्यास-विरोधी कानूनों (Anti-trust laws) दण्डित भी किया गया था। स्टेण्डर्ड ऑयल कम्पनी ऑफ न्यूजर्सी तथा अमरीकन टोबैको कम्पनी को शर्मन एक्ट (Sherman Act) के अन्तर्गत विसर्जित (dissolve) कर दिया गया। केवल वाहन उद्योग (Automobile Industry) की फर्में शेष बच रही। 1905 से 1920 की अवधि में सयोजन आन्दोलन आंशिक रूप से तो इसलिये धीमा पड़ गया कि थोड़े ही समय में काफी अच्छी सीमा तक उत्पादन कार्यकुशलता में वृद्धि हो चुकी थी तथा आंशिक रूप से उसमें यह धीमापन इसलिए भी आया कि आधारभूत उद्योगों में काफी सीमा तक एकाधिकारिक नियन्त्रण की स्थिति प्राप्त की जा चुकी थी।

(vi) अमरीकी औद्योगिक क्रान्ति के प्रमुख कारण—जैसा कि हम इन पिछले

पृष्ठो पर देख चुके हैं, अमरीकी गृह-युद्ध के बाद से लेकर प्रथम विश्व-युद्ध तक का समय वास्तव में अमरीकी उद्योगों के इतिहास में क्रान्ति का काल रहा। इस क्रान्ति को जन्म देने के लिए कई कारण उत्तरदायी रहे—

(अ) आयातों को प्रतिबन्धित करके स्वयं गृह-युद्ध ने निर्मित माल के लिए भारी माँग उत्पन्न कर दी थी।

(आ) देश में भूमि, जल तथा खनिजों के रूप में प्राकृतिक साधनों के विशाल भण्डार विद्यमान थे जो बाद में उद्योग का आधार बन गये।

(इ) बढ़ती हुई जनसंख्या से श्रम की पूर्ति में वृद्धि होती रही। आप्रवास ने भी देश में श्रम की आपूर्ति को बढ़ा दिया। बढ़ती हुई जनसंख्या से उद्योगों को न केवल सस्ता श्रम उपलब्ध हुआ बल्कि उनको विशाल बाजार भी प्राप्त हो गया।

(ई) गृह-युद्ध के बाद लगाये गये ऊँचे तटकरों ने भी उद्योगों को अत्यधिक सुरक्षण प्रदान कर उनकी सहायता की।

(उ) सरकार ने आन्तरिक बाजार में अहस्तक्षेप की नीति का अनुसरण किया। इस नीति ने विदेशी प्रतिस्पर्धा से उद्योगों की सुरक्षा के साथ मिलकर उद्योगों के विकास में बड़ी सहायता की।

(ऊ) सस्ते जल परिवहन तथा रेलों के जाल विद्यमान होने से भी उद्योगों के विकास में सहायता मिली। शक्ति चालित वाहन (automobiles) के आविष्कार व राजमार्गों के निर्माण से भी महत्वपूर्ण योगदान मिला।

(ए) अभियान्त्रिकी (Engineering) के क्षेत्र में नये आविष्कारों ने अनेक नये उद्योगों के विकास को बढ़ावा दिया। विजली का सामान, रेडियो, साइकिलें, वाहन तथा बाद में हवाई जहाजों का निर्माण करने वाले ऐसे ही कुछ उद्योग थे।

(ऐ) नये उद्योगों ने विज्ञान का प्रयोग प्रबन्ध व श्रम दोनों ही क्षेत्रों में किया। टेलर (Taylor) व उसके अनुयायियों ने इस आन्दोलन का नेतृत्व किया। टेलर का यह निश्चित मत था कि 'कार्य की प्रणालियाँ व उसमें लगने वाले समय का सही व ध्यानपूर्वक अध्ययन करने से किसी भी काम को कम से कम समय तथा अधिकतम कार्यकुशलता पूर्वक तरीके से करने की विधियाँ खोजी जा सकती हैं। अकुशल श्रमिकों को निकाल बाहर करने तथा श्रेष्ठ श्रमिकों को उत्तेजित करने हेतु मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उपयुक्त मजदूरी प्रणाली का प्रयोग कर अधिक उत्पादन भी प्राप्त किया जा सकता है व मजदूरी की मात्रा भी बढ़ सकती है।'।

(ओ) यह संयुक्त राज्य अमरीका का सौभाग्य था कि गृह युद्ध के बाद वहाँ ऐसे अनेक साहसी उद्यमकर्ता पैदा हुए जिन्होंने औद्योगीकरण की मशाल को जलाये रखा। बीसवीं शताब्दी के लगने के बाद तो कई महान् साहसकर्ता जैसे एण्ड्रयू कार्नेगी (Andrew Carnegie) इस्पात उद्योग में, फिलिप आर्मर (Philip Armour) मांस डिब्बा-बन्दो उद्योग में, जे० पी० मॉर्गन (J P Morgan) वित्तीय क्षेत्र में तथा जॉन डी० रॉकफेलर (John D Rockefeller) तेल शोधन उद्योग में अमरीकी औद्योगिक विकास को नई ऊँचाइयाँ प्रदान करने में लगे थे। इन औद्योगिक दंत्यों के अतिरिक्त ऐसे सैकड़ों छोटे निर्माता और भी थे 'जो अधिकतर इंजीनियर, आविष्कारक

या वैज्ञानिक तथा व्यापारी का मिला-जुला रूप होते थे तथा जो अमरीकी निर्मित मान उद्योग के मूल निर्माता थे ।'

(औ) विकास के आरम्भिक चरण में ही पूँजी निर्माण व वित्तीय संस्थाओं का समुचित विकास भी औद्योगिक प्रगति में एक सहायक तत्त्व रहा । विदेशी विनिर्माण-कर्ताओं ने भी अमरीका में अपनी पूँजी का विनियोग करने में भारी रुचि प्रदर्शित की । देश में लगी हुई कुल विदेशी पूँजी जो 1860 में 400 मिलियन डॉलर थी 1914 तक बढ़कर 1,400 मिलियन डॉलर हो गई । स्वयं अमरीका भी प्रथम विश्व युद्ध छिड़ने तक पूँजी की उपलब्धि में आत्मनिर्भर हो चुका था ।

3 औद्योगिक परिपक्वता का युग 1920 से आज तक

हर्मन कून के अनुसार, 'नये उद्योग बराबर खुलते रहे व पुराने उद्योग क्षीयमान्वा में वनस्क बने ताकि बोमबों सदी का निर्मित मान उद्योग उन्नीसवीं सदी के निर्मित मान उद्योग से महत्वपूर्ण तरीके से भिन्न बन गया ।'

(i) दो महायुद्धों के बीच का काल (1920-1939)—उद्योगों के क्षेत्र में दो महायुद्धों के बीच के काल में तीन स्पष्ट प्रवृत्तियाँ देखने में आयीं । 1920 से 1921 तक एक हल्की मी मन्दी आई तथा अमरीकी राष्ट्रीय उत्पाद 40 अरब डॉलर से घटकर 37.6 अरब डॉलर पर आ गया । किन्तु इसके तुरन्त बाद एक चस्पाईं तेजी का दौर भी आया । 1929 तक राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य बढ़कर 87 अरब डॉलर तक पहुँच गया । 1923-29 की अवधि में औद्योगिक उत्पादन 25% से बढ़ा । वाहन उद्योग (Automobile Industry) में सर्वाधिक तेजी से प्रसार हुआ । 1923-29 के दौरान ट्रकों व कारों का उत्पादन तो दुगुना हो गया । इसी तरह विद्युत् उत्पादन का स्तर भी 1920 के 43 अरब किलोवाट घण्ट की क्षमता से बढ़कर 1929 तक 97 अरब किलोवाट घण्ट हो गया । रिहायशी मकानों तथा व्यावसायिक इमारतों के निर्माण कार्य में भी भारी तेजी देखने में आई ।

किन्तु औद्योगिक गतिविधियों में यह प्रसार एकदम धम गया जब अमरीकी अर्थव्यवस्था 1929 के बाद मन्दी की गिरफ्त में आ गई । अर्थव्यवस्था अति-उत्पादन की अवस्था में पहुँच चुकी थी । सेयर बाजार अक्तूबर 1929 में समाप्त हो गया तथा व्यावसायिक गतिविधियाँ एकदम धीमी पड़ गयीं । मूल्य गिरे तथा बेकारी बढ़ी । 1933 में फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने राष्ट्रपति पद सम्भाला तथा एक नया कार्यक्रम शुरू किया जिसे न्यू डील (New Deal) नाम दिया गया ।

(ii) संयोजन आन्दोलन (Combination Movement) का पुनरागमन—खनिज उद्योग तथा निर्मित माल उद्योग में 1920 के बाद उद्योगों के संयोजन के आन्दोलन का पुनरागमन दिखाई दिया । 1920 से लेकर 1930 के बीच खनिज उद्योग व निर्मित माल उद्योग के क्षेत्र में 1268 नए संयोजन गठित हुए जिनमें 4,135 कम्पनियों का विलय हुआ । लगभग 5,591 कम्पनियों का अस्तित्व ही समाप्त हो गया । यह कहा गया कि 'दो कम्पनियाँ देश के इस्पात उत्पादन के

50% पर अधिकार रखे हुए हैं, तीन कम्पनियाँ वाहन (automobile) उद्योग पर छाई हुई हैं, एक फर्म का एल्यूमिनियम उत्पादन पर एकाधिकार है तथा चार विद्युत्, रोशनी व शक्ति प्रणालियाँ राष्ट्र के अधिकांश विद्युत् शक्ति प्रजनन पर कब्जा जमाए हुए हैं। 1920 से 1930 के बीच संयोजन आन्दोलनों को कई तत्त्वों ने प्रोत्साहित किया। प्रथमतः, 1923-29 की औद्योगिक समृद्धि ने संयोजनों को प्रोत्साहित किया। द्वितीयतः, अमरीकी उद्योग एक ऐसी स्थिति में पहुँच गए थे जहाँ पुनर्गठन या संयोजन के बिना आगे बढ़ सकना सम्भव ही नहीं था। तृतीयतः, लोग अब इन संयोजनों को लाभप्रद समझने लगे थे। औसत अमरीकी के जीवन स्तर में निरन्तर सुधार हो रहा था। चतुर्थतः, सरकार ने भी संयोजन विरोधी हथकड़ी काफी कम कर दिया था। सरकार ने तो अपव्यय बचाने के उद्देश्य से व्यापार संघों के निर्माण को प्रोत्साहन देना शुरू कर दिया था।

संघीय सरकार ने नए विधेयक पारित किये जो संयोजनों (combinations) के प्रति अधिक सहनशील थे। सरकार भी गला-काट प्रतियोगिता को न्यूनतम करने की इच्छुक थी। 1936 में पारित रोबिन्सन-पेटमैन विधेयक (Robinson-Patman Act, 1936) ने उन प्रतिस्पर्धियों को कुछ नरम बनाया जो 1914 के क्लैटन विधेयक द्वारा लगाये गए थे। 1937 में मिल्लर-टाइडिंग्स कानून (Miller-Tydings Act, 1937) पारित किया गया जिसने शर्मन न्याम-विरोधी कानून (Sherman anti-Trust Act) को संशोधित किया तथा निर्माताओं व वितरकों के बीच मूल्य समझौतों की अनुमति प्रदान कर दी।

(iii) द्वितीय विश्व-युद्ध के दौरान अमरीकी उद्योग—द्वितीय महायुद्ध छिड़ने के आरम्भिक वर्षों में अमरीकी उद्योग को इतना अधिक लाभ हुआ कि सितम्बर 1939 (युद्ध छिड़ने का समय) तथा दिसम्बर 1941 (पर्व हार्बर पर जापानी आक्रमण का समय) के बीच उसका औद्योगिक उत्पादन दुगुना हो गया। अमरीकी वस्तुओं के लिए यूरोप के देशों की माँग अचानक बढ़ गई। अमरीकी सरकार ने मित्र राष्ट्रों की सहायता करने का निष्पत्ति लिया क्योंकि उसके विचार में वे लोकतन्त्र की रक्षा के न्यायोचित उद्देश्य के लिए लड़ रहे थे। इसी उद्देश्य से अमरीका ने अपना रक्षा कार्यक्रम काफी तेज कर दिया। देश के भीतर भी 1939-41 के वर्षों में उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन काफी तेजी से बढ़ चुका था। सैनिक व नागरिक वस्तुओं के उत्पादन को साथ साथ बढ़ाने के प्रयास किये गये। देश के पास पूँजी या धन का अभाव नहीं था जिसकी आवश्यकता उत्पादन का प्रसार करने के लिए थी। समस्या उत्पादन को संगठित करने की थी जिसमें निम्न कठिनाइयाँ आ रही थी (अ) सभी प्रकार की वस्तुओं, कच्चे मालों तथा खाद्य पदार्थों का उत्पादन एक साथ करने की आवश्यकता, (आ) नागरिक उपयोग की वस्तुएँ तैयार करने वाले निर्मित माल उद्योग का सैनिक साज-सामान उत्पादन के लिए रूपान्तरण, (इ) नयी फैक्ट्रियों का निर्माण तथा हथियार व गोला-बारूद के उत्पादन का नये तरीके से संगठन, और (ई) युद्ध की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकताओं, आवंटनों व राशनिंग व्यवस्थाओं की स्थापना।

पूरे द्वितीय महायुद्ध काल में युद्ध-सामग्री तैयार करने पर अमरीका द्वारा कुल मिलाकर 186 अरब डॉलर व्यय किये जाने के अनुमान लगाये गये हैं। इसका परिणाम यह निकला कि उसके टैंकों की संख्या 1941 के मात्र 1,150 से बढ़कर 1945 तक 86,000 हो गयी तथा उसके लड़ाकू हवाई जहाजों का इस अवधि में कुल उत्पादन 2,97,000 तक पहुँच गया। 1941-45 की अवधि में अमरीका द्वारा मित्र-राष्ट्रों को भेजी गई कुल सैनिक सामग्री का मूल्य लगभग 50 अरब डॉलर रहा। युद्ध के दौरान मुख्य कमी अल्युमिनियम, जहाजों, रबर, पेट्रोल तथा ऐसी ही कुछ अन्य चीजों की रही।

(iv) द्वितीय महायुद्ध के बाद का काल—जैसे ही दूसरा महायुद्ध समाप्त हुआ कुछ समय के लिए तो ऐसा लगा कि जैसे देश औद्योगिक क्षेत्र में पुनः मन्दी की तरफ अग्रसर हो रहा है। किन्तु वास्तव में हल्का सा अवसाद (mild recession) ही आकर रह गया। वास्तव में हुआ यह कि टिकाऊ वस्तुओं का उत्पादन युद्ध के बाद निरन्तर बढ़ता चला गया। महान् मन्दी वापस कभी नहीं आई।

द्वितीय महायुद्ध के बाद दो प्रकार के उद्योग प्रमुख रूप से देखने में आए हैं। प्रथम प्रकार के उद्योगों को 'धीमी प्रगति वाले उद्योग' (slow growth industries) कहा जा सकता है। इस प्रकार के उद्योगों में वे उद्योग सम्मिलित थे जिनकी विकास दर कुल राष्ट्रीय उत्पाद (G N P) में वृद्धि की दर से नीची थी। 1950 के बाद तोहा व इस्पात तथा वाहन उद्योग (automobiles) ऐसे ही उद्योगों में गिने गये। जहाँ तक उत्पादन के कुल मूल्य का प्रश्न है लोहा व इस्पात आज भी सर्वप्रमुख आधारभूत उद्योग बना हुआ है। एक ऐसा भी समय था जब इस्पात उद्योग की विकास दर राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि की दर से ऊँची थी। यह कहा जाता था कि 'इस्पात उद्योग का व्यवहार एक परिपक्व अल्प क्रेताधिकारी (mature oligopoly) की विशेषताओं को प्रदर्शित करता है।'।

द्वितीय महायुद्ध के बाद के वर्षों में वाहन उद्योग को भी परिपक्व अल्प-क्रेताधिकारी उद्योग की सजा दी गई। इस उद्योग में फर्म का आकार शुरू से ही काफी विशाल रहा है। इसके अतिरिक्त डिजाइनों हर साल बदलती रहती हैं। 1955 के बाद उद्योग के सामने बड़ा कठिन समय आया जब वारों की विदेशी माँग घट गई। यहाँ तक कि स्वयं अमरीका में ही उद्योग को जापानी कारों की भीषण प्रतिद्वन्द्विता का सामना करना पड़ा।

द्वितीय महायुद्ध के बाद वाले वर्षों में दूसरे वर्ग के उद्योगों को विकास उद्योग' कहा गया। रसायन उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स ईंधन व शक्ति से सम्बन्धित उद्योग इन 'विकास उद्योगों' (Growth industries) की श्रेणी में लिखे गये। रसायन उद्योग ने युद्धोत्तरकालीन वर्षों में असाधारण प्रगति की है। उसने पुराने चले आ रहे उत्पादों के प्रतिस्थापन में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। प्राकृतिक रेशों का स्थान अब कृत्रिम रेशों ने लिया है तथा प्राकृतिक रबर के स्थान पर भी अब रसायनिक रबर का प्रयोग हो रहा है। जैसे-जैसे उसकी निर्यात माँग बढ़ी है वैसे-वैसे उद्योग में प्रगति की है। रसायनों का रक्षा सामग्री के उत्पादन में उपयोग तथा

रासायनिक, प्लास्टिक आदि उद्योगों में भी उसके प्रयोग में निरन्तर वृद्धि हुई है जिसने देश के रसायन-उद्योग को और भी आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

इलेक्ट्रॉनिक्स का विकास तो पूरी तरह से युद्धोत्तरकालीन घटना कही जा सकती है। 1939 में 49वें स्थान से आगे बढ़ते-बढ़ते 1956 में ही यह उद्योग पाँचवें स्थान पर आ गया था। अब विद्युत् ही ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है जिसे कोयले, पानी खनिज तेल या आणविक शक्ति द्वारा पैदा किया जाता है।

युद्धोत्तरकालीन वर्षों में एकाधिकार एवं संयोजन की समस्या ने एक नया ही रूप ले लिया है। द्वितीय महायुद्ध समाप्त होने के तुरन्त बाद सघीय न्याय विभाग (Justice Department) के न्यास-विरोधी खण्ड (Anti-trust Division) ने बड़ी कम्पनियों में से 122 की जाँच की। सरकार ने काफी कड़ा एकाधिकार विरोधी हथ्थ अपनाया। उसने स्वयं अपने युद्ध के समय निर्मित अल्युमिनियम प्लाट स्वतन्त्र निजी कम्पनियों को सौंप दिये।

संयोजनों (combinations) को प्रतिबन्धित करने के द्वाड़े से महायुद्ध के बाद के पहले दशक में तीन महत्वपूर्ण कानून बनाये गये। इनमें से प्रथम विधेयक सेलर-केफोव्हर विलय विरोधी कानून (Cellar-Kefauver Anti-Trust Act) था। इस विधेयक को अन्य निगमों के सभी परिसंपत्तियों द्वारा अवाप्त कर लेने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए पारित किया गया। इसका एक उद्देश्य संयोजनों के बीच आपसी प्रतिद्वन्द्विता को भी घटाना था। दूसरा कानून, जिसे मैकग्यूइर विधेयक (McGuire Act, 1952) कहा गया, 1952 में पारित हुआ। इसका उद्देश्य न्यूनतम पुनर्विक्री मूल्य तय करने हेतु उचित-व्यापार अनुबन्धों को क्रियान्वित करवाना था। 1955 में एक तीसरा परिवर्तन और किया गया जिसके अनुसार एंटी ट्रस्ट शर्मान एक्ट की अवज्ञा करने के अपराधी पर जुर्माने की रकम 5,000 डॉलर से बढ़ाकर 50,000 डॉलर कर दी गई। इस तरह युद्धोत्तरकालीन वर्षों में सरकारी कानूनों का उद्देश्य न केवल बड़ी फर्मों की कार्य-कुशलता वृद्धि के ध्येय से प्रोत्साहित करने का रहा बल्कि उनका लक्ष्य यह भी था कि छोटी फर्मों को बड़े संयोजनों द्वारा निगल लिये जाने से बचाया जाए। किन्तु इनमें से कई कानूनों को संयोजनों ने बड़ी चतुराई से क्रियान्वित होने से रोका है।

(v) *निर्मित माल उद्योग की प्रभावशालीता*—फिर एक बार हम औद्योगिक परिवर्तनों वाले भाग की तरफ लौट सकते हैं। किसी भी माप से देखा जाए, आज की अमरीकी अर्थव्यवस्था में निर्मित माल उद्योग का स्थान सर्वोपरि है। निर्मित माल वाले उद्योगों का वर्तमान में लाभ में जितना भाग है वह किसी भी अन्य वर्ग के उद्योग से अधिक है। यही हाल उपकरणों का है। निर्मित माल उद्योग में काम पर लगे हुए लोगों का कुल श्रम शक्ति (गैर-कृषि) में प्रतिशत 1947 के 35 से घटकर 1962 में 30% तथा 1977 में 32.7% पर आ जाने के उपरान्त इसमें रोजगार पाने वालों की संख्या अभी भी किसी भी अन्य उद्योग के मुकाबले अधिक है। महान् मन्दी के वर्षों को छोड़कर हमेशा ही $\frac{1}{4}$ राष्ट्रीय आय निर्मित माल उद्योग

से प्राप्त होनी रही है। अब राष्ट्रीय आय में इनका यह प्रतिशत भाग 30% हो चुका है।

उद्योग मूल से राष्ट्रीय आय : 1929-1977

(नियत ढाँच में)

	1929	1940	1945	1960	1977
कृषि, वन	8,278	6,247	14,889	17,286	44,600
खानें	2,048	1,868	2,717	5,207	1,00,400
निर्मित माल उद्योग	21,888	22,336	52,008	1,21,937	4,03,900
निर्माण	3,808	2,569	4,250	21,884	—
शेक, खुदरा व्यापार	13,358	14,337	27,997	67,953	2,37,000
वित्त, बीमा	12,693	8,208	12,830	42,537	1,77,900
यातायात	6,636	5,040	10,536	17,939	58,400
संचार	2,864	3,056	4,244	16,734	
सेवाएँ	10,338	8,854	14,614	49,150	2,13,100
सरकारी प्रतिष्ठान	5,093	8,762	36,764	52,506	2,32,700
शेष विरह	810	357	369	2,287	17,300
सभी उद्योग योग	87,814	81,634	1,81,248	4,15,480	15,54,800

Source Statistical Abstract of the U S and the Survey of Current Business

संक्षेप में, आय सृजन की दृष्टि से निर्मित माल उद्योग (manufacturing) की आज वही सापेक्ष स्थिति है जो 100 वर्ष पहले कृषि की थी।

‘जर्मनी में 1870 के बाद से उत्पादन की प्रवृत्तियाँ’ पर किया गया प्रो० आर्थर बर्न्स (Arthur Burns) का एक अध्ययन इस सन्दर्भ में उपयुक्त लगता है। प्रो० बर्न्स ने दो बातों का उल्लेख किया है—(अ) पहली बात वह है जिसे हम सब जानते हैं—कि किसी दिये हुए समय बिन्दु पर उद्योग चटते-गिरते हैं तथा जहाँ अधिकांश उद्योगों का विकास होता है वही कुछ की अवनति भी होती है, तथा (आ) दूसरा और अधिक महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि जैसे-जैसे दशक बीतते हैं वैसे-वैसे व्यक्तिगत उद्योगों की प्रगति की दर अवरुद्ध होती जाती है।

इस तरह प्रो० बर्न्स निम्न निष्कर्षों पर पहुँचे हैं ¹ (अ) कुछ विशिष्ट उद्योगों की विकास दर में गिरावट कुल उत्पादन में तीव्र वृद्धि का परिणाम होनी है। नई वस्तुओं व सेवाओं के निरन्तर उत्पादन का यही अर्थ होगा कि पुरानी वस्तुओं की माँग सीमित होनी चली जाए और नई वस्तुओं की उत्पादन गति जितनी तीव्र होगी पुरानी वस्तुओं के लिए प्रतिस्पर्धात्मक प्रभाव उनमें ही अधिक होंगे। उदाहरण के लिए, जमी हुई खाने की चीजों (frozen foods) के लिए अधिक माँग ने डिब्बा बन्द खाने की चीजों (canned foods) की माँग पर विपरीत प्रभाव डाला है।

¹ Ibid, 539-68

टेलीविजन ने चलचित्रों पर गहरी चोट की है, रेडियो के उत्पादन को एकदम बदल दिया है और यहां तक कि पुस्तकों की विक्री पर भी विपरीत प्रभाव डाला है।

(आ) नये व पुराने उद्योगों में उत्पादन के साधनों के लिए तथा उपभोक्ताओं की पसन्दगी के लिए निरन्तर प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। तकनीकी प्रगति से साधनों की सीमितता के रूप में लगे हुए प्रतिबन्ध हटते या घटते हैं किन्तु तकनीकी प्रगति से जिस एक उद्योग को अधिक लाभ मिलता है उसके प्रतिद्वन्द्वियों की विकास दर उस सीमा तक तो अवरुद्ध हो ही जाती है।

‘युद्धोत्तरकालीन औद्योगिक विकास’ के उपशीर्षक के अन्तर्गत इस बात का उल्लेख पहले ही किया जा चुका है कि ‘धीमी विकास गति वाले उद्योग’ तथा ‘विकास उद्योग’ के रूप में उद्योगों का दो प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। यह वर्गीकरण प्रो० लुइस परेडिसो (Louis Paradiso) द्वारा अमरीकी वाणिज्य विभाग द्वारा संग्रहित आँकड़ों को आधार मानकर किया गया है। उन्होंने 1941-51 की अवधि के लिए 160 से भी अधिक उद्योगों के आँकड़ों को तीन वर्गों में विभक्त किया तेजी से विकास करने वाले, साधारण गति से विकास करने वाले तथा अवनति करने वाले उद्योग। चूँकि इस अवधि में कुल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP) 5% की औसत वार्षिक दर से बढ़ी इसलिए ऐसे उद्योग तेजी से विकसित करने वाले उद्योग माने गये जिनकी विकास दर 7.5% या उससे अधिक रही। ऐसे उद्योग जिनकी विकास दर शून्य से अधिक किन्तु 7.5% से कम रही उन्हें धीमी विकास गति वाले उद्योग माना गया। कुछ उद्योग अवनति (decline) के लक्षण भी दिखा रहे थे।

60 से भी अधिक उत्पाद तीव्र गति से विकास करने वाले उद्योगों की श्रेणी में आये। एन्टीबायोटिक्स की वार्षिक विकास दर 118% की रही जो असाधारण कही जा सकती है। टेलीविजन सैटों का उत्पादन भी उतना ही तीव्र रहा। धीमी गति से विकास करने वाले उद्योगों में अधिकांश पुराने उद्योग थे जिनमें मोटे मोटे खाद्य पदार्थ बनाने वाले, रेडियो, बिजली के पंखे, सिगारे तथा चीनी का उत्पादन करने वाले उद्योग सम्मिलित थे। परेडिसो ने पाया कि 17 उद्योग तो ऐसे थे जिनमें गिरावट की प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से झलक रही थी। इनमें पवन चक्की के लिए पम्प बनाने वाले, साबुन, भाप के रेल इंजिन आदि का उत्पादन करने वाले उद्योग सम्मिलित थे।

अमरीका के वाणिज्य विभाग द्वारा 1948-60 की अवधि के लिए किये गये एक अन्य अध्ययन में निम्नलिखित मान उद्योग के क्षेत्र में और भी कई परिवर्तन सामने आये। तेजी से विकास करने वाले 70 उत्पादों के समूह में भी 10 उत्पाद (products) ऐसे थे जिनमें निर्वाध रूप से 15% की वार्षिक वृद्धि की दर बनी हुई थी। ऐसे उद्योगों में सबसे प्रमुख उदाहरण पोलिथीन व ट्रांजिस्टर उद्योग थे। कुछ वस्तुएँ जैसे सिगरेटें तथा कुछ सेवाएँ जैसे टेलीफोन सेवा पर व्यावसायिक उत्तार-चढ़ावों का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। दूसरे उद्योग, जैसे टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु उद्योग, आय बढ़ने के साथ एकदम तेजी से बढ़े।

(vi) द्वितीय औद्योगिक क्रान्ति (1960 के बाद विकास)—गृह-युद्ध तथा

प्रथम महायुद्ध के बीच का काल उद्योग में यन्त्रीकरण के आगमन का काल रहा। वाट (Watt) के पहले भाप से चलने वाले इंजिन से लेकर प्रथम महायुद्ध तक बड़े व अधिक क्षमता वाले औद्योगिक यन्त्र लगाये जाते रहे व उनमें सुधार होता रहा। यह प्रवृत्ति द्वितीय महायुद्ध तक अविराम रूप से चलती रही, जिसमें सक्तिचालित प्रविधिर्पां गुरु की जाती रहीं।

किन्तु यन्त्रीकरण के अतिरिक्त दो अन्य शक्तियों ने भी अमरीकी औद्योगिक क्षेत्र में हाल ही के वर्षों में अनेक परिवर्तन किये हैं। ये हैं (1) आजकल की वैज्ञानिक खोजों का औद्योगिक प्रक्रमों में उपयोग, तथा (2) स्वचालित नियन्त्रण की एकीकृत प्रणाली का विकास। ये दोनों ही परिवर्तन इतने महत्वपूर्ण रहे हैं कि कई लोगों ने इन्हें 'दूसरी औद्योगिक क्रान्ति' (second industrial revolution) की संज्ञा दी है। रसायनशास्त्री व धातु विगेषज्ञ (chemist and metallurgists) अब मनपसन्द नई चीजें बनाने की स्थिति में हैं तथा पुरानी चीजों को बदल सकते हैं। विद्युत् अभियन्ताओं ने बटन दबाकर किसी भी चीज का नियन्त्रण (push-button control) सम्भव बना दिया है।

1960 से 1979 तक अमरीकी उद्योग में घटित नवप्रवर्तन तथा पुरानी पद्धतियों के सुधार की सूची बनाई जाये तो कई पुस्तकें बन सकती हैं और उनके पूरा होने से पहले ही उनको नवीनीकृत (updated) करने की आवश्यकता पड़ सकती है। और लगभग हर मामले में यह बात स्पष्ट हो जायेगी कि प्रत्येक उद्योग के विकास में एक से अधिक उद्योगों के निवेश (inputs) की आवश्यकता पड़ी है तथा अन्तिम उत्पाद (final product) का एक से अधिक कार्यों के लिए उपयोग करने की सम्भावनाएँ रहती हैं। जैसा कि एक पर्यवेक्षक ने लिखा है, 'हम अजायब धरो को पहन स बही अधिक तेजी से भर रहे हैं क्योंकि कल की नई चीजें आज के साधारण उपकरण तथा आने वाले कल की तकनीक बनते जा रहे हैं।'

अमरीकी उद्योग का आकार औद्योगिक इतिहास की अभूतपूर्व घटना के रूप में बढ़ता चला गया है। उसमें प्रबन्ध तथा प्रशासनिक पहलू उतने ही महत्वपूर्ण बन गये हैं जितना कि उमका तकनीकी पहलू। तकनीकी दृष्टि से अब अमरीकी उद्योग के लिए वे सारी या ऐसी कोई चीज बनाना सम्भव है जो तर्क की दुनिया में सोची जा सकती है। लोह इस्पात का सामान बनाने में कोई समस्या नहीं रह गई है। विज्ञान औद्योगिक इकाइयों की सफलता की कुंजी प्रबन्धकीय एवं प्रशासनिक कुशलता का औद्योगिक एवं अभियन्त्रीक ज्ञानवपरी के सफेदरूप में है।

और किसी भी अन्य कार्यक्रम में अच्छा प्रबन्ध व सहविविवाह (synergism) इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि वह अमरीकी मानव युक्त अन्तरिक्ष उड़ान कार्यक्रम (American manned space flight programme) में रहा है। आज दिन तक इतिहास की सबसे ऊँची उपलब्धि के रूप में यह विज्ञान व प्रौद्योगिकी का संयुक्त कार्यक्रम प्रबन्ध एवं प्रशासन के क्षेत्र की भी उतनी ही महान् उपलब्धि रहा है।

जिन वैज्ञानिकों व इंजीनियरों ने रॉकेटों व अन्तरिक्ष यानों का निर्माण किया उन्होंने यह बात अनुभव की कि वर्तमान ज्ञान इन चीजों के निर्माण के लिए पर्याप्त नहीं

है। अनेक चीजें जिन्हें वे बनाना चाहते थे पहले कभी नहीं बनाई गई थी। नई व अत्यधिक विशिष्टीकृत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नई अवधारणाओं की आवश्यकता थी। विशाल पैमाने पर जनशक्ति व भौतिक साधनों के संगठन, अभिज्ञान व शिक्षण की भी आवश्यकता थी। भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञों को काम पर लगाने तथा उनमें आपस में सहयोग स्थापित करने की भी आवश्यकता थी। यह सब करके अमरीकी मानव युक्त अन्तरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के अगुवाओं ने देश ही नहीं बरन् विश्व के औद्योगिक इतिहास में एक नया अध्याय लिख डाला है।

अमरीका में औद्योगिक विकास की नवीनतम शाखा स्वाभाविक रूप से अन्तरिक्ष कार्यक्रम में सम्बन्धित है जिसे 'सश्लिष्ट भागीदारी' (complex partnership) की सज्ञा दी गई है। इस कार्य को पूरा करने के लिए एक सुविशाल सरकार-उद्योग-अकादमिक मंत्री कार्यक्रम बनाया गया है। 1970 के दशक में अन्तरिक्ष कार्यक्रम के सर्वाधिक व्यस्त वर्षों में 4,00,000 के लगभग प्रशिक्षित स्त्री-पुरुष अन्तरिक्ष परियोजना से सलम थे। अन्त में 50 अमरीकी राज्यों में फँसी हुई 20,000 से भी अधिक फर्मों ने इस कार्यक्रम में अपना योगदान दिया। उन्होंने 'नासा' (National Aeronautics and Space Administration, N A S A) के साथ अनुबन्धों के आधार पर एंटेना (Antennae) जैसी छोटी चीजों से लेकर अन्तरिक्ष यानों तथा रॉकेटों का निर्माण किया। ये अनुबन्ध सैकड़ों मिलियन डॉलर मूल्य के रहे।

सामान्य रूप से उद्योगों ने ही अन्तरिक्ष कार्यक्रम के लिए अधिकांश जानकारी तथा अन्य प्रकार की सेवा सुविधाएँ जुटाईं। विश्वविद्यालयों ने 'सोचने की शक्ति' (think power) तथा मुख्य अवधारणाओं को पैदा करने व उन्हें निश्चित स्वरूप प्रदान करने का कार्य किया। सरकार ने भी नासा के माध्यम से निर्देश प्रदान किये।

इसी प्रकार विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली रॉकेट सेटर्न-5 जिसने कि अन्तरिक्ष यात्रियों को चन्द्रमा तक पहुँचाया इसी 'सश्लिष्ट भागीदारी' का उत्पाद था। इस रॉकेट का निर्माण व डिजाइनिंग अमरीकी सरकार के अलाबामा स्थित मार्शल स्पेस फ्लाइट सेंटर पर किया गया। रॉकेट का पहला खण्ड लुइसियाना में बनाया गया। दूसरा व तीसरा खण्ड केलिफोर्निया में तैयार किया गया। सभी खण्डों या चरणों (stages) की परीक्षा मार्शल सेंटर या फिर मिसिसिपी स्थित नासा जॉन केन्द्र पर की गई। रॉकेट तथा स्वयं अन्तरिक्षयान (rocket and spacecraft) दोनों के कल-पुर्जों का निर्माण सैकड़ों अमरीकी उद्योगों द्वारा मिलकर किया गया। नासा का दायित्व यह देखने का था जब बड़े कल-पुर्जों केप केनेडी, फ्लोरिडा के मानव युक्त यान अन्तरिक्ष में भेजने के स्थल पर पहली बार आएँ तो वे आपस में एक दूसरे के साथ ठीक प्रकार से सम्बद्ध हो सकें। इन सभी भागों को इसी केन्द्र पर जोड़ा गया। इस बारे में कोई मामूली सी भूल चूक भी सारे कार्यक्रम को समय से पूरा होने से रोक सकती थी।

बित्त एवं किस्म नियन्त्रण (quality control) की समस्या से निपटने के लिए नासा ने एक नई प्रबन्ध व्यवस्था तैयार की जिसे 'फ़ेम्' (Forecasts and

Appraisals for Management Evaluation) के नाम से जाना गया। यह व्यवस्था कार्यक्रम के प्रभारी मैनेजरों को कार्यक्रम की नवीनतम स्थिति के बारे में निरन्तर अवगत कराती रही।

एक वाहन (automobile) में 3,000 से भी कम कार्यशील कल-पुर्जे होते हैं। अपोलो कमाण्ड मोड्यूल (Apollo Command Module) में 20 लाख से भी अधिक कल-पुर्जे लगे हुए थे। अमरीकी उद्योग तब अपने चरम बिन्दु पर पहुँच गया जब उसने धरती पर बनी अब तक कि इस सर्वाधिक परिष्कृत मशीन का निर्माण कर लिया। अमरीकी मानव युक्त अन्तरिक्ष उड़ान कार्यक्रमों में अपनाई गई किस्म नियन्त्रण प्रविधियों की विश्वसनीयता 99.999% तक पहुँच गई थी। यह काम अत्यधिक परिष्कृत औद्योगिक प्रबन्ध की सहायता से ही सफलतापूर्वक किया जा सका था। इस प्रकार 1960 के बाद अमरीकी उद्योगों के क्षेत्र में हुई दूसरी औद्योगिक क्रान्ति ने विविधता तथा परिष्कृतता के सन्दर्भ में प्रथम औद्योगिक क्रान्ति को बहुत पीछे छोड़ दिया है। अन्तरिक्ष कार्यक्रम तो उसका केवल एक उदाहरण है।

वर्तमान अमरीकी उद्योग का जितना अधिक अध्ययन किया जाये उतना ही यह पता लगाना कठिन होता जाता है कि कौनसा उद्योग कहाँ शुरू होता और कौनसा कहाँ समाप्त होता है। एक उद्योग का विकास दूसरे उद्योग में आवश्यकता पैदा करता है और जब वह आवश्यकता पूरी की जाती है तो नये प्रक्रम (new processes) तैयार हो जाते हैं जिनसे और नये उत्पाद तैयार किये जा सकते हैं। यह सारी प्रक्रिया एक प्रकार का शाश्वत औद्योगिक प्रवाह (perpetual industrial motion) है जो दिन-प्रतिदिन अधिक सश्लिष्ट या जटिल होता जा रहा है।

(vii) अमरीकी उद्योग की आधुनिक प्रवृत्तियाँ—आजकल अमरीकी उद्योग नये उत्पाद तैयार करने व पहले से प्राप्त उत्पादों की किस्म सुधारने के लिए आधारभूत एवं व्यावहारिक विज्ञान, दोनों ही क्षेत्रों में होने वाले अनुसन्धानों पर निर्भर है। पिछले दो दशकों में अमरीकी उद्योग में कुल शोध व विकास पर किया जाने वाला व्यय बढ़कर चौगुना हो चुका है तथा 1973 में यह 21,000 मिलियन डॉलर तक पहुँच चुका है। उसमें वृद्धि जारी है।

औद्योगिक अनुसन्धान एवं विकास के लिए कोष

(मिलियन डॉलर)

1953	4,000
1957	5,000
1961	11,000
1965	15,000
1969	18,500
1971	19,000
1973	21,000

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक : 1950-1973

(1967=100)

मद	1950	1973
मुख्य धातुएँ	80	130
मशीनें	N A	110
यातायात उपकरण	45	135
औजार	25	120
वस्त्र उत्पाद	60	130
चर्म उत्पाद	90	85
पेट्रोलियम उत्पाद	50	130

1950 से 1973 तक की अवधि के लिए औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि अधिकांश औद्योगिक वस्तुओं का उत्पादन दुगुने से भी अधिक हो चुका है। उत्पादन में वृद्धि की सर्वाधिक ऊँची दर सबसे नई वस्तुओं के सम्बन्ध में रही है।

निजी उद्योगों में प्रति मानव-घण्टा (Man-hour) उत्पादन का सूचकांक

(1967=100)

1950	67
1960	75
1967	100
1970	110
1973	127

1960 के बाद के ज्यामितिक दर से हो रहे औद्योगिक प्रसार के काल में प्रति मानव-घण्टा उत्पादन में भी वृद्धि हो रही है। यह भी 1950 के बाद लगभग दुगुना हो चुका है।

(viii) क्षेत्रीय विविधताएँ—विभिन्न प्रदेशों में उद्योगों के विकास की दर में 1950 के बाद भारी अन्तर उभरा है। उत्तरी प्रदेश, जिसमें न्यू इंग्लैण्ड, मेसाचुसेट्स तथा अन्य कुछ राज्य सम्मिलित हैं, अन्य प्रदेशों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल पाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। 1950 के बाद से ही वस्त्र उद्योग ने, जो इस प्रदेश का प्रमुख उद्योग रहा है, कई उतार-चढ़ाव देखे हैं। उत्तरी क्षेत्र के अन्य परम्परागत उद्योगों ने भी, जैसे चमड़ा व गैर-टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु उद्योग, नये उत्पादों के निकलने के साथ गिरावट की ही प्रवृत्ति देखी है। किन्तु पिछले कुछ वर्षों से क्षतिपूर्क शक्तियाँ भी सक्रिय हो रही हैं। उदाहरण के लिए, न्यू इंग्लैण्ड 1950 के बाद से ही टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन का प्रमुख केन्द्र बन गया है। इन वस्तुओं में इलेक्ट्रॉनिक साज-सामान, मशीनरी, रक्षा सामग्री आदि सम्मिलित हैं। इन उद्योगों के विकास के परिणामस्वरूप रोजगार में भी वृद्धि हुई है।

दक्षिणी-पश्चिमी प्रदेशों जिसमें टेक्सास (Texas) राज्य सम्मिलित है 1950 के बाद नाटकीय ढंग से आगे निकल गया है जबकि इससे पहले वह हमेशा ही पिछड़ा रहा था। रसायन उद्योग, हवाई जहाज निर्माण उद्योग तथा मशीनों के उत्पादन ने इस प्रदेश को अत्यधिक लाभ पहुँचाया है जहाँ इससे पहले परम्परागत कृषि तथा कृषि पदार्थों पर आधारित उद्योग की ही प्रधानता थी। दक्षिण पूर्वी प्रदेश में भी कई नये उद्योगों ने अपनी जड़े जमा ली हैं जिनमें वाहन उद्योग, खाद्य पदार्थ उत्पादक उद्योग, छापे खाने की मशीनें तथा यातायात सामग्री बनाने वाले उद्योग प्रमुख हैं। जहाज निर्माण उद्योग ने भी इस क्षेत्र में प्रगति की है।

ग्रेट लेक्स क्षेत्र (Great Lakes Region) ने निर्मित माल उत्पादन बेल्ट के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। वाहनों (automobiles) के उत्पादन का विकेन्द्रीकरण हो जाने से 1950 के दशक के कुछ वर्षों तक इण्डियाना व मिशिगन राज्यों को भारी आघात लगा था। यहाँ तक कि डेट्रॉइट (Detroit), जोकि महान् इस्पात नगर है, को भी बेकारी का सामना करना पड़ा था। किन्तु इस क्षेत्र ने भी रसायन उद्योग तथा धातु-वस्तु निर्माण उद्योग की स्थापना हो जाने से अपनी स्थिति काफी मजबूत कर ली है।

कैलिफोर्निया राज्य वाले धुर-पश्चिमी प्रदेश को भी द्वितीय महायुद्ध के बाद रक्षा सामग्री उद्योगों की स्थापना हो जाने से काफी लाभ मिला है। इसने कृषि के क्षेत्र में भी अपनी नेतृत्व की स्थिति को बनाए रखा है। इस तरह कुल मिलाकर विभिन्न क्षेत्रों में द्वितीय महायुद्ध के बाद उद्योगों का विकास काफी एक समान रूप से होता रहा है।

(ix) छोटे-पैमाने के उद्योग—संयुक्त राज्य अमरीका में लघु-उद्योग क्षेत्र पृष्ठभूमि में ही छूट गया है। इसे 'अलाभकारी समूह' (disadvantaged group) के रूप में जाना जाने लगा है। इसकी प्रमुख समस्याएँ दो रही हैं : प्रथमतः, नीची कार्यकुशलता, तथा द्वितीयतः, बाजारों पर अधिकार कर सकने या पूँजी एवं साख प्राप्त करने की क्षमता का अभाव। 1952 में सरकार ने इस सम्बन्ध में एक कानून पारित किया था जिसे मैकग्वीरे विधेयक (McGuire Act) के नाम से जाना जाता है। इस विधेयक का उद्देश्य छोटे उपक्रमों के हितों की रक्षा करना था। 1953 व 1958 में भी संघीय सरकार ने लघु व्यवसाय विधेयक (Small Business Acts) पारित किये थे। 1953 में एक नई व्यवस्था, जिसे लघु व्यवसाय प्रशासन कहा गया, भी कायम की गई जिसका उद्देश्य लघु उपक्रमों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करना था।

किन्तु ऐसा लगता है कि अमरीकी 'जलवायु' छोटे व्यवसायों के लिए अनुकूल नहीं है। इस तरह जागान से तुलना करने पर यह स्थिति एकदम विपरीत लगती है। अमरीकी लघु व्यवसाय 'ऊँची मृत्यु दर, छोटे जीवन काल, नीचे व अस्थिर लाभ, न्यून चालू अनुपातों तथा कमजोर तरलता' जैसी बीमारियों से ग्रस्त है।

इन कमजोरियों के बावजूद ऐसे अनेक कथन समय-समय पर सुनाई पड़ते हैं जिनमें लघु उद्योग के महत्त्व पर प्रकाश डाला जाता है तथा ऐसा स्वतन्त्र उपक्रम को

बँडावा देने के नाम से किया जाता है। यह कहा गया है कि 'निजी उद्यम वाली अमरीकी आर्थिक प्रणाली का निचोड़ ही स्वतन्त्र उपक्रम है। केवल स्वतन्त्र प्रतिस्पर्द्धा द्वारा ही बाजारो की स्वतन्त्रता, व्यवसाय में प्रवेश की स्वतन्त्रता, निजी पहल के लिए अवसरों की अभिव्यक्ति एवं उनका विकास तथा व्यक्तिगत निर्णयों में आस्था को बनाये रखा जा सकता है। इस प्रतिस्पर्द्धा की भावना को सुरक्षित रखना तथा उसका निर्वाह करते जाना न केवल आर्थिक कल्याण की दृष्टि से अपितु इस राष्ट्र की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है। यह सुरक्षा एवं आर्थिक कल्याण प्राप्त कर पाना तब तक सम्भव नहीं है जब तक कि लघु व्यवसाय को प्रोत्साहित एवं विकसित न किया जाए।'

किन्तु वास्तविकता यही है कि विशालकाय उद्योगों के इस युग में छोटे औद्योगिक उपक्रम अमरीका में हर दिन पुरावशेष (anachronistic) बनते जा रहे हैं।

यातायात सेवाओं का विकास (GROWTH OF TRANSPORTATION NETWORKS)

देश ने 1789 में एक नया संविधान स्वीकार किया था जिसने 13 राज्यों को एक राष्ट्र के रूप में एकीकृत कर दिया था। राज्यों को अब तटकर बाधाएँ (tariff barriers) खड़ी करने पर रोक लगा दी गई। आन्तरिक व्यापार के क्षेत्र में एक नये युग का आरम्भ हो रहा था। 1789 में विभिन्न उपनिवेशों के बीच का आपसी व्यापार उनके पश्चिमी यूरोप के साथ व्यापार से भी कम था। नए राष्ट्र के आर्थिक एकीकरण के लिए यातायात सेवाओं के क्षेत्र में एक क्रान्ति अनिवार्य बन गयी थी। यह समय पगडण्डियों, शुल्क फाटकों तथा कच्ची सड़कों (trails, turnpikes and towpaths) का युग था। जल परिवहन वस्तुएँ लाने-ले-जाने के लिए सबसे सुविधाजनक साधन था किन्तु कठिनाई यह थी कि नाव द्वारा हर स्थान तक नहीं पहुँचा जा सकता था। उपनिवेशों के विकास ने सबसे भारवाही घोड़ों (pack horses) के रूप में यातायात सेवा को बढ़ावा दिया। ग्रामीण सड़कें ही प्रारम्भिक यातायात सेवाओं का आधार थी। लम्बी सड़कें पूर्वी प्रदेश के विभिन्न शहरों को आपस में तथा उन्हें पश्चिमी प्रदेशों में फैलते हुए अधिवासों (settlements of the west) से जोड़ती थी। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण सड़क विल्डरनेस रोड (Wilderness Road) थी जिसके निर्माण में डेनियल बुन (Daniel Boone) ने पथ-प्रदर्शक का कार्य किया।

पक्के राज मार्गों (surfaced highways) में सबसे महत्वपूर्ण राजमार्ग कवरलेड रोड थी जिसे 1811 में सघीय सरकार ने 13,000 डालर प्रति मील की लागत से, जो उस समय में बहुत ऊँची लागत मानी गई, बनवाया था। किन्तु इस काल में सरकार ने अधिक सड़क निर्माण कार्य में हाथ नहीं डाला। ये सड़कें मुख्यतः निजी शुल्क फाटक कम्पनियों (private turnpike companies) द्वारा ही बनाई गईं जिनसे वे टोल-टैक्स वसूल किया करती थी।

प्रारम्भिक वर्षों में निर्मित सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहर, हालाँकि वही एक मात्र लाभकारी नहर नहीं थी, एरी नहर (Erie canal) थी जिसका निर्माण कार्य 1825 में पूरा हुआ था। इस नहर के निर्माण ने देश में नहरों के निर्माण कार्य का मार्ग प्रशस्त किया। किन्तु नहरों के निर्माण कार्य में यह तजी अधिक दिन नहीं चली। नहरों की अन्तिम रूप से अमफलता का प्रमुख कारण रेल-सड़क यातायात का विकास रहा।

रेलमार्ग व्यवस्था (Railroad System)

प्रारम्भिक वर्ष : 1830-1860

बाल्टीमोर तथा ओहियो रेल मार्ग क० ने मई 1830 में 13 मील लम्बे रेलमार्ग को चालू किया था। 1836 में जब चार्लस्टन व हेम्बर्ग रेलमार्ग का काम पूरा हुआ तो उसकी कुल लम्बाई 136 मील थी जो इस समय विश्व की सर्वाधिक लम्बी रेल लाइन थी। 1840 तक अमरीका में रेलमार्गों की कुल लम्बाई 2,818 मील हो गई। 1850 तक 9,000 मील लम्बा रेलमार्ग तैयार किया जा चुका था। किन्तु 1850 से 1860 के बीच देश में 20,000 मील लम्बी रेल लाइनें और बिछा दी गईं। इस तरह 1860 तक रेलमार्गों की कुल लम्बाई 30,000 मील पहुँच गई तथा उनके व्यापार का परिमाण नहरों के बराबर हो गया। गृह-युद्ध के छिड़ जाने से देश में रेलमार्गों के निर्माण के काम में काफी कटौती करनी पड़ी। देश के उत्तरी व दक्षिणी दोनों ही भागों में पहले बिछाई गई कई रेल लाइनें भी नष्ट कर दी गईं।

रेलमार्ग की पूर्णावृत्ति . 1861-1913

उन्नीसवीं सदी के तीसरे चतुर्थांश तक यह बात स्पष्ट हो चुकी थी कि आर्थिक विकास की सन्तोषजनक दर एक विश्वसनीय यातायात सेवा व्यवस्था पर ही निर्भर करेगी। 6 दशकों तक (1860-1920) तीव्रगामी व कुशल परिवहन के साधन के रूप में रेलमार्गों का एकाधिकार देश में बना रहा। रेलों ने इस अवधि में बड़ी मात्रा में लाभ कमाया। इसके बावजूद इस सम्पूर्ण अवधि में रेलमार्ग कम्पनियाँ वित्तीय कठिनाइयों से ग्रस्त रही तथा प्रथम विश्व-युद्ध की समाप्ति तक तो उनके राष्ट्रीयकरण करने पर भी गम्भीरता से विचार किया जाने लगा।

हालांकि रेलमार्गों के प्रसार के काम में गृह-युद्ध (1861-65) से भारी बाधा पड़ी थी किन्तु इन वर्षों में हुए तकनीकी सुधारों ने रेलों की कार्य-कुशलता में अत्यधिक वृद्धि कर दी। इस तरह गृह-युद्ध समाप्त हो गया तथा पश्चिमी प्रदेशों की भूमि अवाप्त करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य बनाया गया तो नये पश्चिमी प्रदेश के साथ एक सुरक्षित रेलमार्ग की बड़ी स्थापित कगना भी अत्यावश्यक बन गया। अन्तर-उपमहाद्वीपीय रेलमार्ग (Intercontinental Railway) के निर्माण का स्वप्न उतना ही पुराना था जितना रेलमार्गों का आविष्कार। 1862 में पारित पेसेफिक रेल विधेयक द्वारा कांग्रेस ने यूनिन पेसेफिक रेलमार्ग को नेवैदा (Nevada) राज्य की पश्चिमी सीमा तक रेलमार्ग का निर्माण करने की अनुमति दे दी। एक अन्य कम्पनी सेंट्रल पेसेफिक को इसी अवधि में रेलमार्ग के पश्चिमी भाग का निर्माण कार्य आरम्भ करने की अनुमति दे दी गई।

लेकिन उपमहाद्वीपीय रेल सेवा का निर्माण कोई आसान काम नहीं था। दोनों तरफ निर्माण कर रही कम्पनियों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यूनिन पेसेफिक कम्पनी के सामने मजदूरों की भर्ती की समस्या आयी।

सेन्ट्रल पेसेफिक कम्पनी को इस्पात प्राप्त करने में कठिनाई हो रही थी क्योंकि यह पूर्वी प्रदेशों के औद्योगिक नगरों तथा समुद्री बन्दरगाहों से काफी दूर कार्य कर रही थी। दोनों दिशाओं से रेलमार्ग का निर्माण करने वाली कम्पनियों (यूनियन पेसेफिक तथा सेन्ट्रल पेसेफिक) द्वारा निर्मित रेल लाइनों को मिलाने का कार्य 10 मई, 1869 के दिन पूरा हुआ।¹ अमरीकी रेलमार्ग निर्माण के इतिहास में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिन था। 1876 में दक्षिणी कैलिफोर्निया भी उपमहाद्वीपीय रेलमार्ग के साथ जुड़ गया।

इस प्रकार गृह-युद्ध के बाद के दो दशकों में देश में राष्ट्रीय रेलमार्ग (great trunk lines) का निर्माण कार्य पूरा किया गया। 1864 से लेकर 1900 तक रेलमार्गों का सर्वाधिक प्रतिशत महान् मैदानी राज्यों (great plains states) में बिछाया गया जो कुल रेलमार्ग का 50% था। दक्षिण-पूर्वी तथा दक्षिण पश्चिमी राज्य रेलमार्ग निर्माण की दृष्टि से तथा विभिन्न रेलमार्गों के एक प्रणाली के रूप में संयोजन की दृष्टि से काफी पिछड़े हुए रहे।

देश के रेलमार्गों के निर्माण पर विनियोग 'ऊँची-ऊँची लहरों' (towering waves) के रूप में हुआ। रेलमार्गों के निर्माण पर किया गया वार्षिक व्यय 1873, 1882, 1891 तथा 1911 में नई ऊँचाइयों तक पहुँचा। यह 1876, 1886, 1897 तथा 1920 वर्षों में नीचे गिरा। इस प्रकार रेलमार्गों के निर्माण पर हुए असमान विनियोग से कई बार आर्थिक अस्थिरता की स्थिति भी पैदा हुई। किन्तु इस विनियोग ने देश के आर्थिक विकास के लिए उत्तेजक का भी काम किया क्योंकि यह विनियोग 1870 में राष्ट्रीय आय का 20% तथा यहाँ तक 1920 में उसका 75% था।

रेलमार्गों के लिए वित्त व्यवस्था ने कई स्वरूप लिये। प्रारम्भिक वर्षों में राज्यों तथा नगरपालिकाओं ने भी छोटे छोटे रेलमार्गों के निर्माण में सहायता की। किन्तु उनका योगदान 1880 में बन्द हो गया। सघीय सरकार की सहायता इस अवधि में काफी बढ़ी। सघीय अनुदान का भी सबसे महत्वपूर्ण प्रकार भूमि प्रदान (grant of lands) करने के रूप में था। इन अनुदानों को निर्माण कम्पनियों को आकर्षित करने के लिए अभिप्रेरक (incentive) के रूप में रखा गया। प्रारम्भिक वर्षों में रेल कम्पनियों के अधिकांश असाधारण (Shareholders) लोग विदेशी थे। 1914 तक भी अमरीकी रेलमार्ग प्रतिभूतियों के 20% भाग पर ब्रिटिश नागरिकों का स्वामित्व था।

रेलमार्ग व्यापार (Railroad traffic) का नियमन करने के बारे में भी पहल उन्नीसवीं सदी में शुरू हो गई। 1870 से पहले एक रेलमार्ग कम्पनी का अपने क्षेत्र में एकाधिकार होता था। नियमन सम्बन्धी रेलमार्ग कानून (Regulatory Railroad Laws) अनेक राज्यों में 1871 व 1874 के बीच पारित किये गए। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रेजर कानून (Granger Laws) थे। 1890 तक 30 राज्यों ने इस प्रकार के नियमन कानून पारित कर दिये थे। व्यवसाय को नियमित करने

वाला संधीय कानून 1887 में पारित किया गया जिसने सभी अनुचित प्रथाओं (evil practices) पर प्रतिबन्ध लगा दिया। 1930 में पारित एल्किंस विधेयक (Elkins Act, 1903) में केवल विभेदकारी दरे वसूलने पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रावधान था। 1906 में पारित हेपबर्न विधेयक (Hepburn Act, 1906) ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार आयोग (Interstate Commerce Commission), जो कि 1878 में ही रेलमार्ग कम्पनियों के व्यापार पर निगरानी रखने के लिए गठित कर दिया गया था, को और अधिकार प्रदान किये। आयोग (I C C) को किसी भी रेलमार्ग कम्पनी के हिसाब-किताब की किसी भी समय जाँच करने का अधिकार दिया गया। रेलमार्ग व्यापार को नियमित करने वाला अन्तिम महत्वपूर्ण कानून मैन-एल्किंस विधेयक, 1910 (Mann-Elkins Act, 1910) था। इनमें से अधिकांश विधेयकों का उद्देश्य रेलमार्गों पर नियन्त्रण स्थापित करना था। किन्तु धीरे-धीरे यह अनुभव किया जाने लगा कि ये कानून पेशीदा व समझ में न आने जैसे बन गये थे।

1914 में अमरीका में रेलमार्गों की कुल लम्बाई सम्पूर्ण यूरोप में स्थित रेल लाइनों की लम्बाई से अधिक थी। वह विश्व रेलमार्गों का एक-तिहाई थी। 1860 के 30,000 मील लम्बे रेलमार्ग बढ़कर 2,52,000 मील हो चुके थे। जिस अवधि की हम चर्चा कर रहे हैं उसमें रेलों की लम्बाई में इतनी तीव्र वृद्धि के लिए अनेक तत्त्व उत्तरदायी रहे। ये तत्त्व थे—(अ) नये प्रदेशों की ओर प्रस्थान, (आ) प्राकृतिक ससाधनों का तीव्र गति से विकास, (इ) व्यापार व व्यवसाय में तेजी से वृद्धि, (ई) देश का अधिकांश भू-भाग समतल होना, (उ) लोहा व इस्पात उद्योग का तेजी से विकास, तथा (ऊ) बढ़ते हुए लाभ के कारण रेलों में भारी विनियोग।

प्रथम महायुद्ध के समय रेलों की स्थिति

1910 से 1913 के बीच रेलमार्गों का निर्माण बड़ी तेजी से हुआ। उसकी औसत गति 3,000 मील वार्षिक रही। किन्तु युद्ध ने ससाधनों को अन्य दिशाओं में मोड़ दिया। इसके फलस्वरूप नई रेल लाइनों का निर्माण घटा। स्वयं रेलमार्ग कम्पनियों ने मिलकर अप्रैल 1917 में अपनी समस्याओं का निपटारा करने के लिए एक रेलमार्ग वार बोर्ड गठित किया था किन्तु वे अपने प्रयासों में असफल रहे। दिसम्बर 1917 में एक अध्यादेश जारी कर रेलमार्गों को सरकारी नियन्त्रण में ले लिया जो 26 माह तक चला। रेलमार्ग कम्पनियाँ घाटे में चलने लगी थी। इस अवधि में सरकार को भी 12 अरब डॉलर का घाटा उठाना पड़ा।

1920 के बाद अमरीकी रेलें

1920 के बाद अमरीकी रेलों के सामने अलग ही तरह की समस्याएँ आयी। 1920 के बाद पारित संधीय विधेयकों ने आम जनता को विभेदकारी दरो (discriminatory rates) से बचाने पर अधिक बल दिया। किन्तु 1920 के बाद ट्रकों व अन्य मोटर-चालित वाहनों (automobiles) की प्रतिद्वन्द्विता ने रेलमार्गों

पर सरकारी नियन्त्रण के उद्देश्यो को ही बदल दिया। अब रेलमार्ग कम्पनियो को, न कि जनता को, बचाने की आवश्यकता आ पड़ी थी।

1920 में जबकि सरकार ने रेलमार्गों को पुनः उनके मालिकों के हाथ सौंप दिया तो अनेक नई समस्याएँ उभर कर सामने आ चुकी थी। सरकार को इन रेल कम्पनियो को उन सुधारों के लिए रकम चुकानी थी जो सरकार ने अपने नियन्त्रण काल में किये थे। विल्वर चुने कर्मचारियों व उपकरणों को पुनः एक स्थान पर जमा करने के लिए भी काफी धनराशि की आवश्यकता थी। 1920 के यातायात सेवा विधेयक (Transportation Act, 1920) ने रेलों के सम्मुख उपस्थित अल्पकालिक व दीर्घकालिक दोनों ही प्रकार की समस्याओं को हल करने का प्रयास किया। विधेयक ने रेलमार्ग कम्पनियो को 'स्वाभाविक एकाधिकारी' (Natural Monopolies) माना तथा अनुभव किया कि यदि उन पर प्रतिस्पर्धा थापी गई तो उससे अनुचित प्रथाएँ ही शुरू होने की सम्भावनाएँ थी। विधेयक ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार आयोग (I C C) के अधिकारों में भी अनेक परिवर्तन किये। आयोग को ऐसी दरें निर्धारित करने के निर्देश दिये गये कि जिनसे, 'ईमानदारी, कार्यकुशलता तथा मितव्ययितापूर्ण प्रबन्ध के अन्तर्गत रेलमार्ग कम्पनियाँ अपनी कुल रेल सम्पत्ति के मूल्य पर उचित प्रतिफल प्राप्त कर सकें।' आयोग को रेलमार्ग कम्पनियो को व्यवस्थाओं (Systems) में पुनर्गठित करने का भी अधिकार प्रदान किया गया तथा विनियोग की दर भी वह नियन्त्रित कर सकता था। इसके अतिरिक्त आयोग रेलमार्ग कम्पनियो को नये रेलमार्गों का निर्माण करने के लिए बाध्य कर सकता था जहाँ व्यापार का परिमाण काफी बढ़ चुका हो।

उधर 1920 के बाद यात्री आवागमन में गिरावट प्रारम्भ हो गई। 1929 के बाद महान् मन्दी आ जाने से कम्पनियो की वित्तीय स्थिति और भी खराब हो गई। 1931 में रेलमार्ग कम्पनियो के प्रबन्ध ने ऐसे अवसर पर भाड़ा बढ़ाने की माँग की जब उसकी प्रतिद्वन्द्वी यातायात सस्थाएँ उससे व्यवसाय छीनती जा रही थी। इस स्थिति में आयोग कोई राहत नहीं दे सकता था। 1932 में हुए घाटों के कारण आपातकालीन यातायात विधेयक, 1933 (Emergency Transportation Act, 1933) पारित किया गया। नये विधेयक का उद्देश्य रेलमार्ग कम्पनियो का 'अपव्ययपूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक प्रथाओं से मुक्ति दिलाकर' उन्हें तात्कालिक वित्तीय दबावों से बचाना था। इस विधेयक ने रेल व्यवस्था के हद्दीकरण (consolidation) का भी विचार पहली बार सामने रखा। 1936 में रेलों की आय उन पर लगी हुई पूँजी का सिर्फ 1% थी। ट्रकों तथा अन्य वाहनो की प्रतिस्पर्धा का भी अत्यधिक हानिकारक प्रभाव पड़ा था। कोयला, जोकि रेलमार्गों द्वारा ढोई जाने वाली सबसे प्रमुख वस्तु था, ऊर्जा के अन्य साधनों के सामने अपनी स्थिति खोता जा रहा था। इसके बावजूद रेलमार्ग कम्पनियो में तथा विनियोग पूरी तरह बन्द नहीं हुआ था। 1921-40 की अवधि में रेलमार्ग कम्पनियो ने उपकरणों व ढाँचों (equipments and structures) पर 11 अरब डॉलर व्यय किये थे।

द्वितीय महायुद्ध व उसके बाद

द्वितीय महायुद्ध ने अमरीकी रेलों को प्रोत्साहन दिया। व्यापार का आवागमन काफी अच्छा रहा। व्यापार का परिमाण प्रथम महायुद्ध की तुलना में दुगुना हो गया। देश के भीतर सैनिकों के लाने ले जाने के काम का 98% तथा सैनिक सामग्री के आवागमन का 91% कार्य रेलों द्वारा किया गया। युद्ध के इन वर्षों में यात्री एवं माल आवागमन के परिमाण में हुई भारी वृद्धि को अच्छी तरह निपट पाने में कई तत्त्वों ने सहायता की। मालवाही डिब्बों की क्षमता काफी बढ़ चुकी थी तथा रेल इंजिन भी अधिक शक्तिशाली बन गये थे। यातायात के अन्य साधनों के साथ भी एक अच्छा समन्वय स्थापित किया गया।

युद्ध के तुरन्त बाद रेलमार्ग कम्पनियों ने विभिन्न सुधार करने के उद्देश्य से 15 अरब डॉलर की राशि का विनियोग किया। बड़ी सख्या में डीजल-विद्युत् खण्ड जोड़े गये। यहाँ तक कि आणविक ऊर्जा से चल सकने वाले रेल इंजिनो की सम्भावना की भी खोज की गई। रेलमार्ग अब सरकार के नियन्त्रण व प्रबन्ध में हैं।

किन्तु युद्ध की समाप्ति के कुछ ही वर्षों बाद रेलमार्ग पुन मुसीबत में फँस गये। कोरिया के युद्ध (1950) ने यानियों व माल के आवागमन में वृद्धि करके कुछ समय तक अमरीकी रेलों की सहायता की। किन्तु इन दोनों ही के लाने ले जाने में 1960 के बाद से ही गिरावट की प्रवृत्ति जारी है। माल ढोने में रेलों का भाग $\frac{2}{3}$ से घटकर 1961 तक $\frac{1}{3}$ रह गया था। इस बीच यात्री यातायात कुल के 20% से घटकर केवल 3% रह गया। 1961 में रेल उद्योग ने अपने 27 अरब डॉलर के विशाल विनियोग पर मात्र 19% की दर से प्रतिफल प्राप्त किया। युद्ध के बाद रेल उद्योग की प्रमुख समस्या उसकी क्षमता का अतिरेक रहो है। रेल उद्योग के लिए, जोकि कुछ सुधार करके अभी के मुकाबले 75% अधिक व्यापार बढ़ा सकता है, अधिक व्यवसाय की आवश्यकता है। 1958 के यातायात विधेयक ने माल व यात्री भाड़े की दरों में परिवर्तन करके खोए हुए व्यवसाय को पुन प्राप्त करने की चेष्टा की।

अमरीकी रेलों के सम्मुख समस्याएँ

(1) सड़क, वायु तथा जल परिवहन के साथ बड़ती हुई प्रतिस्पर्धा के कारण रेलों के लिए व्यापार में काफी कमी आई है। ट्रकों ऊँची दर वाले माल व्यापार पर पूरी तरह कब्जा कर चुकी है जो माल व्यापार का विशेष भाग होता है तथा सड़कों के जाल के माध्यम से वे उसे तेजी के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचा रही हैं। अधिकांश यात्री यातायात अब हवाई जहाजों ने खींच लिया है।

(2) विभेदकारी करारोपण को भी एक कारण बताया गया है। 1940 में व्यावसायिक यातायात के समस्त साधनों पर एक कर लगाया था किन्तु ट्रकों को उससे मुक्त रखा गया।

(3) सघीय व राज्यीय नियमतों की संख्या अत्यधिक होने से भी स्थिति भ्रामक बन गई है।

(4) सरकार रेल कम्पनियों के प्रतिद्वन्द्वियों को सब प्रकार की सहायता उदार रूप से प्रदान करती रही है। राजमार्गों, हवाई अड्डों तथा जलमार्गों का निर्माण करने के लिए उदार अनुदान दिये गए हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रेल मात्तायात की प्रगति को अवरुद्ध करने में यह तत्त्व भी सहायक रहा है।

किन्तु इन सब कठिनाइयों से यह अर्थ नहीं निकाल लिया जाना चाहिये कि अब अमरीकी रेलों का भविष्य अन्धकारपूर्ण है। रेलें 17 लाख लोगों को रोजगार दे रही हैं। वे देश की कुल सम्पदा का 10% भाग हैं। रेलमार्गों की कुल लम्बाई अब बढ़कर 3,75,000 हो चुकी है जो विश्व में सर्वाधिक लम्बी रेल लाइनें हैं। अमरीकी रेलों के पास 30,000 से अधिक इन्जिन, 27,000 यात्री डिब्बे, तथा 17 लाख मालवाही डिब्बे हैं।

जल परिवहन (Water Transport)

नावों को यान्त्रिक शक्ति से चला सकने के आरम्भिक प्रयास असफल रहे थे। 1807 में रॉबर्ट फुल्टन (Robert Fulton) ने क्लेरमोंट (Clermont) नामक एक भाप से चलने वाली नाव (Steamboat) तैयार की। इसके बाद स्टीम बोटों के निर्माण को व्यावसायिक सफलता मिल गयी। नदियों द्वारा परिवहन का एक नया युग प्रारम्भ हो गया। 1820 के बाद स्टीम बोटों द्वारा माल लाने से जाने का तेजी से विकास हुआ। 1850 तक लगभग 750 स्टीम बोट पश्चिमी नदियों पर तैरने लगे थे।

व्यापारिक जहाजी बंडा (Merchant Shipping)

अमरीकी नौसेनिकों ने अमरीकी क्रांति के दौरान इंग्लैंड के साथ एक समुद्री लड़ाई में विजय प्राप्त की थी। 1820 से लेकर गृहयुद्ध छिड़ने तक अमरीकी एक प्रमुख जहाज निर्माता देश था। क्रांति के एक दशक बाद ही जहाज निर्माण उद्योग यूरोप में हो रहे नेपोलियन के साथ युद्धों के कारण भी उत्तेजित हुआ। विदेश व्यापार में दो प्रकार के जहाज प्रयुक्त हो रहे थे। 'छडे' जहाज (tramp ships) पहली प्रकार के जहाज थे जो जहाँ कहीं से माल मिलता ले लेते और किसी भी बन्दरगाह पर चले जाते। वे कई महीनों, यहाँ तक कि वर्षों में भी देश नहीं लौटते। न्यूयॉर्क की ब्लैक बाल लाइन (Black Ball Line) द्वारा 1818 में एक नियमित जहाजी सेवा आरम्भ की गई। 1820 से 1860 के बीच जहाजों के डिजाइन में भी भारी परिवर्तन हुए। जहाजों का औसत आकार 1820 के 300 टन से बढ़कर 1860 में 1,000 टन हो गया। 1850 के बाद से तो भाप से चलने वाले जहाजों की संख्या व उनका टन भार दिन दूनी व रात चौगुनी गति से बढ़े। 1820 के दशक में तो अमरीकी जहाज वहाँ के विदेशी व्यापार का 90% ला-लेजा रहे थे। यह प्रतिष्ठ

1850 में घटकर 70 पर आ गया।

गृह-युद्ध के दौरान अमरीकी व्यापारिक जहाजी बेड़े की अवनति हुई। किन्तु फिर भी तत्पर्वी जहाजी सेवा अप्रभावित ही रही क्योंकि वह एक पुराने कानून के अन्तर्गत सुरक्षित थी। उसके टन भार में भी 1860 से 1914 के बीच काफी वृद्धि हुई। प्रारम्भ में अमरीकी जहाजी बेड़े की अवनति का कारण ब्रिटिश जहाज-निर्माण की तकनीकी श्रेष्ठता रहा। कारण जो भी रहे हो, वह गिरावट असाधारण ही रही। विदेश व्यापार के लिए पंजीकृत जहाजी बेड़े का टन भार 1860 से 1910 के बीच 25 लाख टन से घटकर 7 लाख टन रह गया। 1860 में अमरीकी जहाज देश के कुल विदेशी व्यापार का दो-तिहाई माल स्वयं ला-लेजा रहे थे जो 1900 तक घटकर दसवाँ भाग रह गया। किन्तु 1910 से 1915 के बीच अमरीकी जहाजी बेड़े के टन भार में पुनः एक बार तेजी से वृद्धि हुई क्योंकि युद्ध में फँसे यूरोप के देशों को माल भेजने का काम अमरीका के जिम्मे ही था।

प्रथम विश्व-युद्ध के दौरान अमरीकी व्यापारिक जहाजी बेड़े का टन भार 3 मिलियन टन के लगभग रहा होगा।¹ किन्तु यह काफी कम था। 1916 में एक जहाजी आयोग (Shipping Board) गठित किया गया जिसे जहाज खरीदने के लिए 50 मिलियन डॉलर दिये गये। संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा युद्ध की घोषणा कर दिये जाने के बाद आयोग ने एक आपातकालीन जहाजी बेड़ा निगम (Emergency Fleet Corporation) की स्थापना की। इस निगम को नये जहाजों का निर्माण करवाने पर 4 अरब डॉलर व्यय करने हेतु प्रदान किये गये। 1918 तक व्यापारिक जहाजी बेड़े में 2 मिलियन टन की वृद्धि की गई। 1921 तक विदेश व्यापार के लिये पंजीकृत जहाजी बेड़े का टन भार 11 मिलियन टन के बिन्दु को पार कर चुका था।

1920 में पारित जहाजी विधेयक (Marine Act) ने सरकार को विदेशी व्यापार हेतु जहाजी बेड़े के उद्योग से बाहर निकाल लिया। सरकार ने स्वामित्व वाले जहाजों को निजी जहाजी कम्पनियों को नीचे मूल्यों पर बेचने की व्यवस्था की गई। इन मुविधाओं के बावजूद 1920 के बाद व्यापारिक जहाजी सेवा में गिरावट आती रही। 1928 में पारित एक विधेयक ने अनुदान की व्यवस्था कर व्यापारिक जहाजों का टन भार बढ़ाने की चेष्टा की किन्तु उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। टन भार 11 मिलियन टन से घट कर 1929 में 7 मिलियन टन ही रह गया। 1935 तक अमरीकी आयात-निर्यात व्यापार का केवल एक-तिहाई भाग अमरीकी जहाजों द्वारा लाया-ले-जाया जाने लगा था। हालांकि इन वर्षों में अमरीकी जहाजी बेड़ा टन भार के हिसाब में इंग्लैंड के बाद दूसरे स्थान पर था किन्तु वह घीमा व पुराना हो चुका था।

व्यापारिक जहाजों की इस मन्द प्रगति से चिन्ता होने लग गई। 1936 में कांग्रेस ने प्रत्यक्ष अनुदान नहीं देने की पुरानी नीति को बदल दिया। एक नई संस्था, जिसे अमरीकी मेरिटाइम कमिशन (U S Maritime Commission) का नाम दिया गया, 1936 के मर्चेंट मेराइन एक्ट द्वारा स्थापित किया गया। इस आयोग

को अनुदान प्रदान करने का अधिकार दिया गया इस विधेयक का उद्देश्य अमरीकी जहाज निर्माताओं, चालक कम्पनियों व मालिकों को उनके कम लागत पर कार्यरत विदेशी प्रतिद्वन्द्वियों के समकक्ष लाने का प्रयास किया गया। जहाज की वास्तविक लागत तथा उसकी अनुमानित विदेशी लागत के बीच का अन्तर अनुदान द्वारा पूरा किया गया। अगर वह जहाज प्रतिरक्षा के लिए उपयोगी होता तो उसकी पूरी लागत सरकार वहन करती। सकार्यशील अनुदान (operational subsidy) भी इसी प्रकार के सिद्धान्त पर आधारित था। आयोग अमरीकी स्वामित्व के अन्तर्गत चलाये जा रहे जहाजों की सकार्यशील लागत तथा विदेशी झण्डे वाले जहाज की सकार्यशील लागत (जो नीची होती थी) के बीच अन्तर का अनुदान देता था।

द्वितीय महायुद्ध

किन्तु 1936 से 1941 के बीच दिया गया अनुदान भी व्यापारिक बेड़े के आकार को पर्याप्त विशाल नहीं बना पाया। वह द्वितीय महायुद्ध में अनेक स्थानों पर, जहाँ लड़ाई चल रही थी, माल पहुँचाने के लिए पर्याप्त नहीं था। सरकारी व्यय पर युद्ध के दौरान लिबर्टी जहाज व विक्टरी जहाज (Liberty Ships and Victory Ships) बनाये गये। पर्ल हार्बर पर जापानी आक्रमण के बाद तो अनेक पोत निर्माण स्थलों की भरमभट्ट की गई तथा कई नये स्थल (shipyards) बनाये गये। जहाज निर्माण के कार्य को दो भागों में बाँटा गया। जहाज के कल पुर्जो देश के भीतरी भाग में बनाये जाते व उनको जोड़ने का काम सटवर्ती स्थानों पर किया जाता।

आधुनिक युग

युद्ध के बाद व्यापारिक जहाजी बेड़े को अनेक अप्रत्यक्ष मौद्रिक लाभ प्रदान किये गये। 1946 का व्यावसायिक पोत बिक्री अधिनियम (Merchant Ship Sales Act) अमरीकी जहाज चालकों के लिए बहुत लाभप्रद रहा। इस विधेयक में कई अच्छे जहाजों को बहुत आसान शर्तों पर बेचने की बात सम्मिलित थी। कई जहाजों को तो उनकी युद्ध पूर्व की कीमत के भी एक-तिहाई मूल्य पर बेच दिया गया। अमरीकी जहाजी प्रशासन (U S Maritime Administration) के अन्तर्गत, जोकि व्यापार विभाग (Department of Commerce) की एक एजेंसी है, प्रत्यक्ष अनुदान कार्यक्रम (direct subsidy programme) शुरू किया गया। फेडरल मेरिटाइम बोर्ड, जिसका कि अध्यक्ष मेरिटाइम एडमिनिस्ट्रेशन का भी अध्यक्ष होता है, एक विनियामक सस्था (Regulatory Agency) के रूप में कार्य करता है। यही बोर्ड दरें, सेवाएँ आदि तय करता है तथा जहाजी कम्पनियों के साथ अनुदान अनुबन्ध निधानित करता है।

सड़क यातायात (Road Transport)

1

1920 के बाद यातायात के क्षेत्र में जो सबसे असाधारण घटना हुई वह

रेलो से सड़को की तरफ उसके झुकाव में निरन्तर वृद्धि की थी। ट्रको व बसों ने रेलों से ऊँचे-स्तर का अधिकांश व्यापार (high grade traffic) छीन लिया है। किन्तु यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण बाहनों के निर्माण से काफी समय तक पिछड़ा रहा। इसका परिणाम यह रहा कि कारों व ट्रको का उपयोग शुरू के वर्षों में केवल शहरी क्षेत्र में ही किया जाता रहा। शहरों के बीच बस यात्राएँ तथा मोटर-ट्रक यातायात 1920 तक महत्वपूर्ण नहीं बने थे।

मोटर-कार के आगमन से पहले तक सड़को के रख-रखाव व निर्माण का दायित्व स्थानीय निकायों या राज्य सरकारों पर था। किन्तु 1920 के दशक में बहुत कम राज्य सरकारें अपने यहाँ सड़को का जाल बिछा सकने की स्थिति में थी। इसके अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय सड़को के निर्माण की समस्या भी थी। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण हेतु किसी सघीय कार्यक्रम का बनाया जाना आवश्यक था।

अनेक वर्गों ने देश में एक अच्छी सड़क व्यवस्था की माँग की। मोटर-कार क्लब ऐसा ही एक वर्ग था। 1900 में पहली मोटर-कार प्रदर्शनी आयोजित की गई। न्यूयार्क स्थित अमरीकी ऑटोमोबाइल क्लब तथा केलिफोर्निया का ऑटोमोबाइल क्लब भी इसी वर्षों में बने। अमरीकी सड़क निर्माण सघ ने भी इन क्लबों के साथ मिलकर अच्छी सड़क व्यवस्था की माँग की। किसानों तथा दूरस्थ क्षेत्रों के विधायकों ने भी कुशल सड़क व्यवस्था पर बल दिया।

राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य सड़कों के निर्माण का कार्य सुव्यवस्थित रूप से 1916 में पारित सघीय सड़क सहायता अधिनियम के बाद ही पहली बार आरम्भ हुआ। सरकार ने घोषणा की कि वह ग्रामीण सड़को के निर्माण कार्य पर 75 मिलियन डॉलर व्यय करेगी। अच्छी शुरुआत के बावजूद सड़क निर्माण कार्य योजनाबद्ध तरीके से नहीं चला व घिसटता रहा। कृपि प्रधान प्रदेशों में तो मुख्य सड़को की स्थिति 1930 तक भी खराब बनी रही। इन परिस्थितियों में अच्छे मौसम के अतिरिक्त कुछ मील तक की भी सड़क यात्रा सम्भव नहीं थी।

किन्तु 1930 की महान् मन्दी सड़क निर्माण के क्षेत्र में एक अच्छी घटना सिद्ध हुई। अर्थव्यवस्था को निरन्तर गिरते हुए विनियोग स्तर से बचाने के लिए किये गये अधिकांश सार्वजनिक विनियोग सड़क निर्माण पर हुए। 1932 से पहले सड़क निर्माण पर सघीय व्यय 10% से अधिक नहीं था। किन्तु 1932 में वह बढ़कर सघीय कोषों का 30% हो गया तथा द्वितीय महायुद्ध के छिड़ने तक बढ़ता ही रहा। 1933 के बाद तो सघीय राशि से सहायक सड़को का भी निर्माण किया गया।

द्वितीय विश्व-युद्ध

महायुद्ध के दौरान राष्ट्रीय सड़को की अच्छी प्रकार देखभाल नहीं हो पाई। कुछ प्रमुख मार्गों की हालत तो काफी खराब हो गई। कांग्रेस ने एक पुनर्निर्माण कार्यक्रम बनाया। युद्ध समाप्त होने के बाद के तीन वित्तीय वर्षों में सघीय सड़क सहायता अधिनियम, 1944 (Federal-Aid Highway Act, 1944) के अन्तर्गत

सड़को के विकास हेतु 1,500 मिलियन डॉलर खर्च करने का प्रस्ताव किया गया।

1956 में कांग्रेस ने अन्तर्राष्ट्रीय तथा प्रतिरक्षा सड़क प्रणाली (interstate and defence highway system) स्थापित करने के लिए अधिकृत कर दिया। इसके अन्तर्गत अमरीका के प्रमुख केन्द्रों को जोड़ने के लिए कुल मिलाकर 41,000 मील लम्बी सड़को बनाने का प्रस्ताव किया गया। यह कार्यक्रम 13 वर्षों में सम्पूर्ण किया जाना था तथा इस पर 27 अरब डॉलर की लागत आनी थी। किन्तु कुछ समय बाद लागत का संशोधित अनुमान 41 अरब डॉलर हो गया। एक सड़क मार्ग कोष (highway fund) स्थापित किया गया जिसमें पेट्रोलियम पदार्थों, ट्रकों तथा टायरों से प्राप्त होने वाले करों को एकत्रित करने का प्रावधान किया गया। किन्तु इस प्रावधान की कई लोगो ने आलोचना की और कहा कि यह तो 'जाओ उसके पहले पैसा दो' जैसी बात थी।

मोटर-कारों तथा अन्य वाहनों की संख्या द्वितीय महायुद्ध के बाद तेज्यामितिक दर से बढ़ रही है। 1895 में देश में केवल 4 मोटर कारें रजिस्टर्ड कराई गई थी। 1963 में रजिस्टर्ड मोटर गाड़ियों की संख्या 75 मिलियन से भी ऊपर थी। 1968 में प्रति 10,000 अमरीकियों के पीछे 4,110 मोटर वाहन थे। स्थानीय सड़को की कुल लम्बाई 1963 में 4 मिलियन मील के लगभग थी। राष्ट्रीय व संघीय सड़को की लम्बाई क्रमशः 1963 में 9 व 7 लाख मील थी। 1979 में अमरीका में मोटर कारों की संख्या 150 मिलियन से ऊपर है।

हवाई यातायात (Airlines)

वैसे तो अमरीका में हवाई यातायात प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आरम्भ हो चुका था किन्तु 1930 तक भी लोग-ब्राग नित नये हवाई स्तर कीतिमानों की स्थापना से रोमांचित होते रहे। बहु-इंजिन युक्त हवाई जहाजों के निर्माण के बाद तो हवाई यात्रा आर्थिक दृष्टि से मितव्ययितापूर्ण व सुरक्षित बन गयी। 1935 के लगभग बढ़ते हुए हवाई यातायात का विनियमन करने के उद्देश्य से तीन विनियामक एजेंसियाँ स्थापित की गईं। व्यावसायिक हवाई सेवा का प्रथम विनियमन नागरिक उड्डयन अधिनियम, 1938 (Civil Aeronautics Act, 1938) द्वारा किया गया। एक नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (Civil Aeronautics Authority) बनाया गया। इस नवीन प्राधिकरण के अन्तर्गत एक नागरिक उड्डयन प्रशासन (Civil Aeronautics Administration) तथा एक नागरिक उड्डयन बोर्ड (Civil Aeronautics Board) गठित किया गया। नागरिक उड्डयन प्रशासन (C A A) हवाई यातायात को बढ़ावा देने व सुरक्षा नियमों को लागू करने के लिए उत्तरदायी था। नागरिक उड्डयन बोर्ड (C A B) समस्त सुरक्षा नियम जारी करने तथा हवाई यातायात का आर्थिक विनियमन करने के लिए उत्तरदायी था।

द्वितीय विश्व-युद्ध के दौरान व उसके बाद व्यावसायिक हवाई यातायात की

प्रगति की दर आश्चर्यजनक रही है। 1939 में अमरीकी हवाई कम्पनियों ने 683 मिलियन यात्री मील (million passenger miles) के बराबर उड़ानें भरी थी। 1957 में यह आंकड़ा 29,000 मिलियन यात्री मील पहुँच गया। 1979 तक इस हवाई यातायात में कम से कम 10 गुना वृद्धि हो चुकी है।

1958 के सघीय उड्डयन विधेयक ने हवाई यातायात की बढ़ती हुई कठिनाइयों पर ध्यान दिया। उसने नागरिक उड्डयन बोर्ड (C A B) की पुरानी व्यवस्था को समाप्त कर दिया तथा उसके स्थान पर एक सघीय उड्डयन एजेंसी (federal aviation agency) की स्थापना की। इस एजेंसी का काम नागरिक उड्डयन की भौतिक सुख-सुविधाओं पर नियन्त्रण रखना था। एक प्रशासक (administrator), जोकि इस एजेंसी का प्रधान होता है, प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट देता है। वह राष्ट्रीय सुरक्षा तथा व्यावसायिक उड्डयन की आवश्यकताओं के बीच समन्वय भी रखता है। भविष्य हवाई यातायात के साथ है। वह सभी कीर्तिमान तोड़ने के लिए सन्नद्ध है। दिन के हरेक घण्टे में अमरीकी वायुमन में औसतन 28 हजार गैर सैनिक हवाई जहाज उड़ते हुए रहते हैं। हवाई यातायात ने परिवहन के अन्य सभी साधनों को पीछे धकेल दिया है। यात्री आवागमन पर तो हवाई यातायात ने एक तरह से एकाधिकार-सा कर लिया लगता है।

अमरीका में यातायात व संचार 1976-77

	1976	1977
1. हवाई यातायात बिलियन डॉलर		
कुल यात्री मील (प्राप्तिर्था)	179	195
घरेलू उड़ानें (यात्री मील) प्राप्तिर्था (revenue)	145	158
अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें (यात्री मील) प्राप्तिर्था	34	37
2. शहरी यातायात व्यवस्था मिलियन डॉलर		
ले जाए गये यात्री (प्राप्तिर्था)	5 690	5 979
3. मोटर वाहन मिलियन डॉलर		
वाहनों की संख्या	100	100
सेवा से प्राप्तिर्था कुल	11 420	13 853
4. प्रथम श्रेणी रेल सेवा मिलियन डॉलर		
सेवा से प्राप्तिर्था, कुल	18 574	20 116
माल भाड़ा	17 433	18 916
यात्री किराया	330	337

महान् मंदी और न्यू डील (GREAT DEPRESSION AND NEW DEAL)

1929 की गर्मी तक तो अमरीकी शायद यह सोच रहे थे कि उन्होंने शास्त्रतः समृद्धि का रास्ता ढूँढ़ लिया है। एक दशक में उनका औद्योगिक उत्पादन ड्योढ़ा हो चुका था। व्यापारी अपने लाभों से तथा मजदूर अपनी मजदूरी से सन्तुष्ट थे। केवल किसान कृषि पदार्थों के मूल्यों को लेकर भुनभुना रहे थे किन्तु उनके साथ तो ऐसा पहले से ही था। हर आदमी यही सोचना था कि इस समृद्धि व उत्पादन में वृद्धि होगी। यहाँ तक कि पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्थाएँ भी लगभग स्थिर हो चुकी थी। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में स्वतन्त्र व्यापार की पुनर्स्थापना की आशाएँ बलवती हो चली थी। किन्तु अक्टूबर 1929 में ये सारे सपने चूर-चूर हो गये जब शेयर बेचने की भगदड़ ने शेयर बाजार को हिला कर रख दिया। गिरते हुए शेयर मूल्यों का मनोवैज्ञानिक प्रभाव अत्यधिक भीषण था। अवसाद, फिर मंदी, तथा अन्त में तो अर्थव्यवस्था का पूरी तरह ठप्प हो जाना ही वास्तविक घटनाक्रम बन गया।¹

महान् मंदी (Great Depression)

महान् मंदी ने न केवल अमरीका के पूंजीवाद को निम्नीकृत किया बल्कि उमने अन्य अनेक देशों की पूंजीवादी प्रणाली को भी एक प्रकार से छिन्न-भिन्न कर दिया। महान् मंदी, यह सही ही कहा गया है, 'लाखों सामान्य-जनो के लिए निराशा व भ्रम पैदा की तथा उनके दिलों में अन्धों कुटन भर दी। इसके कारण कुल मिलाकर 200 अरब मानव-घण्टों का नुकसान हुआ। उमने कुछ ऐसा किया जो किसी विदेशी आक्रामक, राष्ट्रीय सकट या पुराने तरीकें की भगदड़ ने कभी नहीं किया था, उसके कारण कई वर्षों तक अमरीकी अर्थव्यवस्था को जैसे लकवा मार गया।'

1929-33 के चार सालों में तो अमरीकी अर्थव्यवस्था जैसे रसातल में हो चली गई। चालू मूल्यों पर राष्ट्रीय उत्पाद 46% घट गया, वह 104 अरब डॉलर से घटकर 56 अरब डॉलर पर आ गया। स्थिर मूल्यों पर देखा जाये तब भी राष्ट्रीय उत्पाद में 31% की गिरावट आ चुकी थी। औद्योगिक उत्पादन घटकर आधा रह गया, योज मूल्य एक्-विहाई से भी अधिक कम हो गये तथा उपभोक्ता मूल्यों में एक्-

चौथाई गिरावट आ गई।¹ किन्तु सबसे भयंकर आँकड़े तो रोजगार व बेरोजगारी के बारे में थे। नागरिक रोजगार में करीब 20% की गिरावट आयी तथा बेकारों की संख्या 15 लाख से बढ़कर 1 करोड़ 30 लाख हो गई। अत्यधिक अनुदार अनुमानों के अनुसार भी कम से कम 25% नागरिक कार्यों में लगी हुई श्रम शक्ति बेकार हो गई। यदि हम इन आँकड़ों में अर्द्ध-बेकारों को और मिला लें तो बेरोजगारी की वास्तविक दर महान् मन्दी के चरम बिन्दु पर 33% तक पहुँच जाती है।

अनुमानित बेकारी 1929-33

वर्ष	बेकारों की औसत वार्षिक संख्या (000)	नागरिक श्रम शक्ति का प्रतिशत
1929	1,550	3.2
1930	4,340	8.7
1931	8,020	15.9
1932	12,060	23.6
1933	12,830	24.9

महान् मन्दी के वर्षों में मजदूरों की दरों में तो साधारण गिरावट आयी किन्तु मजदूरों की कुल आय अत्यधिक घट गई क्योंकि काम के घण्टे काफी कम हो गये थे।

उत्पादक श्रमिकों की वास्तविक साप्ताहिक औसत मजदूरी

(1926=100)

वर्ष	निर्देशांक
1929	101.5
1930	94.3
1931	84.7
1932	69.2
1933	67.9
1934	74.6

Source Bureau of Labour Statistics

औसत साप्ताहिक आय के स्तर को देखने में भी यही स्पष्ट होता है कि सबसे अधिक नुकसान मजदूरों को ही रहा। उसके बाद व्यापार में लगे लोग रहे। सबसे कम नुकसान वेतन भोगी कर्मचारियों को रहा।

औसत साप्ताहिक आय

(डॉलर में)

वर्ष	मजदूर	वेतनभोगी कर्मचारी	व्यापारी
1929	27	35	28
1933	19	29	22
1937	25	33	25

Source Business Statistics, 1961

¹ Ibid, 628-29

सबसे अधिक आघात टिकाऊ वस्तुओं को लगा। 1920 के बाद उनके उत्पादन का चित्र उनमें आई गिरावट को स्पष्ट कर देता है। उत्पादन निर्देशांक के आधार पर (1957=100) 1929 में 40 के चरम बिन्दु से टिकाऊ वस्तुओं का उत्पादन घटकर 1932 में केवल 9 रह गया। मार्च 1933 में टिकाऊ वस्तुओं के उत्पादन का निम्नतम निर्देशांक 8 रह गया था। टिकाऊ वस्तुओं का उत्पादन 80% गिर गया था। गैर-टिकाऊ वस्तुओं का उत्पादन कुछ कम तेजी से गिरा था। वह निर्देशांक के रूप में 40 से घटकर 28 पर आ गया था (1957=100)।

रॉबर्टसन ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि 'मन्दी की तीव्रता अत्यधिक पीड़ादायक थी किन्तु उसके कभी समाप्त न होने जैसी स्थिति ने तो कुण्ठा व निराशा को जन्म दिया। 1880 के दशक में आयी मन्दी को 40 वर्ष गुजर चुके थे। 1920-21 के दौरान आयी मन्दी आकस्मिक व धिनीनी थी तथा उसमें टिकाऊ वस्तुओं का उत्पादन 43 प्रतिशत कम हो गया था। किन्तु यह सब होने के उपरान्त उसका व्यवहार मन्दी जैसा ही था—अर्थात् वह आई और जल्दी ही चली गई तथा निर्मित माल का उत्पादन अगले दो वर्षों में पुन पुराने स्तर तक पहुँच गया। इसके ठीक विपरीत महान् मन्दी के दौरान निर्मित माल का उत्पादन (manufacturing output) 1929 के स्तर को पुन 1936 के अन्त तक ही प्राप्त कर पाया, वह कोई साल भर तक 1929 के स्तर से ऊपर रहा, फिर वापस गिरा तथा महान् मन्दी से पूर्व की स्थिति में पुन अगस्त 1939 तक ही जाकर पहुँच पाया। टिकाऊ वस्तुओं के उत्पादन में तो युद्ध पूर्व का स्तर अगस्त 1940 तक अर्थात् महान् मन्दी की शुरुआत के 11 वर्षों के बाद ही पहुँच पाया था।'

महान् मन्दी के कारण

पिछले 50 वर्षों से अर्थशास्त्रियों से बार-बार यही प्रश्न पूछा जाता रहा है कि उस महान् मन्दी के कारण क्या थे जिसने समूची विश्व अर्थव्यवस्था को झकझोर कर रख दिया था। हम उन ताकतों के बीच अन्तर कर सकते हैं जिन्होंने आर्थिक गतिविधियों में गिरावट को जन्म दिया तथा जिन्होंने एक व्यापारिक अवसाद (business recession) को सबसे खराब विपत्ति में बदल दिया।

(1) वचत विनियोग व उत्पादन की गति—प्रसिद्ध अमरीकी अर्थशास्त्री हेंसन (Hansen) ने तर्क दिया है कि 'महान् मन्दी अनेक विशाल विनियोग उछालों (investment booms) के एक साथ अपने अन्तिम छोर तक पहुँचने का परिणाम थी। और यह भी कि अर्थव्यवस्था की 'परिपक्वता' (maturity) के परिणामस्वरूप वचत अत्यधिक होने लगी थी जबकि विनियोग के अवसर काफी गिर गये थे।' लन्दन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स के प्रो० रॉबिन्स ने लिखा है कि 'वास्तविक वचत बहुत कम थी जबकि विनियोग में अत्यधिक तेजी में प्रसार हुआ और फिर वह अचानक ध्वस्त हो गया क्योंकि उसके लिए वित्त अस्थिर बैंक साख से प्राप्त हुआ था न कि स्थिर वचत आदतों से।'

हार्वर्ड स्कूल के समर स्लिचर (Summer Slichter) ने, जोकि महान् मन्दी

के कारणों की जाँच के लिए नियुक्त समिति का अध्यक्ष भी था, अपने अध्ययन के निष्कर्ष में कहा कि 'उस समय की स्ट्रटेजी के पागलपन ने व्यापारियों के मन में शेयर बाजार के ढह जाने तथा व्यावसायिक अवसाद पैदा हो जाने का डर घुसा दिया और इसी के परिणामस्वरूप माल तालिकाओं (inventories) तथा पूँजी विनियोगों में कटौती होनी चली गई।' शुम्पीटर (Schumpeter) को लगा कि महान् मन्दी के बीच बीसवीं शताब्दी के प्रथम दो दशकों की औद्योगिक गतिविधियों द्वारा बोये गये थे। इन गतिविधियों में सबसे महत्वपूर्ण टिकाऊ वस्तुओं का पुंजोत्पादन (mass production) होने लग जाना था। 'बढ़ते हुए उत्पादन के साथ कदम से कदम मिला कर चल पाने के लिए यह आवश्यक था कि अमरीकी उपभोक्ताओं के हाथों में वर्तमान क्रय शक्ति में भी साथ ही साथ वृद्धि होती। उपभोक्ता माध्य (consumer credit) प्रदान करने की नई प्रथा ने निश्चय ही निर्माताओं को अपनी टिकाऊ वस्तुएँ जैसे, मोटर कारें, रेडियो, रेफ्रिजरेटर आदि कहीं अधिक मात्रा में बेच पाने में सहायता की।' किन्तु इससे भी कोई विशेष सहायता नहीं मिल पायी क्योंकि इस अवधि में लोगों की आय उत्पादकता वृद्धि के अनुपात में नहीं बढ़ सकी। शुम्पीटर ने अनुमान लगाया है कि 1923 से 1929 के बीच उत्पादकता में सम्भावित वृद्धि वास्तविक मजदूरी में होने वाली वृद्धि के मुकाबले तीन गुना रही। स्पष्ट है कि 1930 में आन्तरिक बाजारों में इतनी तीव्र गति से बढ़ता हुआ औद्योगिक उत्पादन खप नहीं पाया।

(2) भवन-निर्माण कार्य में गिरावट—1925 के बाद से ही रिहायशी व व्यावसायिक दोनों ही प्रकार की इमारतों के निर्माण कार्य में बड़ी तेजी से गिरावट आयी। 1918 में भवन-निर्माण कार्य में जो अचानक तेजी आयी थी उसने देश को 1920-21 के दौरान आयी एक साधारण सी मन्दी से उबारने में बड़ी सहायता की थी। किन्तु जब यह गतिविधि भी गिरने लगी तो अर्थव्यवस्था पर उमका अत्यधिक निराशाजनक प्रभाव (depressing influence) पड़ा। 1928 तक आते-आते तो देश में निर्माण कार्य में साफ दिक्काई पड़ने वाली गिरावट आ चुकी थी।

(3) गिरते हुए कृषि मूल्य—1920 के बाद विश्व भर में कृषि पदार्थों के मूल्य में गिरावट की प्रवृत्ति जारी थी। व्यापारियों की भी यह आम शिकायत हो चुकी थी कि किसानों को उनके द्वारा बेची जाने वाली वस्तुओं की मात्रा बराबर अच्छी जा रही थी। जैसा कि शुम्पीटर ने लिखा था, 'अनेक क्षेत्रों में हुए नव-प्रवर्तनों (innovations) से जो यातायात एवं कृषि कान्तिर्या पैदा हुई थी वे अखिर अनिश्चित काल तक तो चल नहीं सकती थी और उनकी अन्तिम परिणति मन्दी के रूप में ही होनी थी।'।

(4) शहर-बाजार में भारी उतार-चढ़ाव—आम तौर पर शेयर बाजार (stock market) में आने वाले उतार चढ़ाव व्यावसायिक उच्चावचनों (business fluctuations) का कारण नहीं माने जाते। किन्तु 1929 में जो स्थिति बनी वह इस सामान्य नियम का अपवाद ही रही। न्यूयार्क टाइम्स का 24 औद्योगिक इकाइयों का शेयर सूचकांक (stock index) जो 1924 में 110 के लगभग था,

जनवरी 1929 तक चढ़कर 338 तथा सितम्बर 1929 तक तो 452 हो चुका था। इतनी अप्रत्याशित तेजी से विनियोक्ताओं को भारी मौद्रिक लाभ हुए। यही आशावाद लोगों की इस आम धारणा का कारण बना कि अब देश में स्थाई समृद्धि आ चुकी थी। किन्तु अगले ही महीने अर्थात् अक्टूबर 1929 में जब इसकी एकदम विपरीत स्थिति (reversal) पैदा हुई तो उसके कारण अमरीकी अर्थव्यवस्था को जो धक्का लगा उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। एक सप्ताह में ही औद्योगिक क्षेत्रों का सूचकांक घटकर 275 पर आ गया। नवम्बर 1929 में तो वे 225 पर जा पहुँचे। इस बात को कोई भी निश्चय के साथ नहीं कह सकता कि यह गिरावट मनोवैज्ञानिक सदमे के कारण आयी या फिर ऐसा विनियोग के लिए उपलब्ध कोषों में अचानक भारी गिरावट आ जाने के कारण हुआ। किन्तु इन उतार-चढ़ावों ने गणना न कर सकने योग्य हानि पहुँचाई तथा औद्योगिक उत्पादन में 25% वार्षिक की गिरावट आने लगी।

1929 में शेयर बाजार के ढह जाने से प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला को जन्म मिला। उसके परिणामस्वरूप बैंकों के दिवालिया हो जाने की एक के बाद एक तीन लहरें आयीं। पहली लहर 1930 के अन्त में, दूसरी लहर 1931 के अन्तिम महीनों में तथा तीसरी व सर्वाधिक विनाशकारी लहर जो मध्य 1932 में प्रारम्भ हुई थी, 1933 की सर्दी तक चली। इन बैंकों के दिवालियेपन की लहरों ने जमाओं को नष्ट कर दिया तथा साख व्यवस्था को छिन्न-भिन्न कर डाला। बैंकों के डम तरह दिवालिया हो जाने का प्रमुख उत्तरदायित्व व्यक्तिगत सघीय बैंकों (individual federal reserve banks) द्वारा अपने कर्त्तव्य का ठीक से निर्वाह न कर पाने पर रहा।

(5) सस्ती मुद्रा नीति—एक अन्य तत्त्व जो महान् मन्दी के आगमन के लिए उत्तरदायी माना गया वह सघीय रिजर्व प्रणाली (federal reserve system) द्वारा 1924 व 1927 में सस्ती मुद्रा नीति की घटनाओं की पुनरावृत्ति किया जाना था। इन सस्ती मुद्रा नीति घटनाओं (easy money episodes) ने बड़े पैमाने पर सट्टेबाजी को जन्म दिया जिससे अन्तिम परिणाम के रूप में शेयर बाजार का सर्वनाश हुआ।

(6) निर्यातों में तेजी से गिरावट—कुछ लेखकों ने निर्यात में तेजी से आयी गिरावट को भी महान् मन्दी का एक प्रमुख कारण बतलाया है। लेकिन गहराई से देखने पर ऐसा लगता है कि निर्यातों में यह गिरावट महान् मन्दी का परिणाम अधिक थी। 1930 में आयात व निर्यात में लगभग समान रूप से गिरावट आयी तथा विदेश व्यापार से 1 अरब डॉलर की विगुद्ध वृद्धि रही। 1931 में यह विदेश व्यापार अतिरिक्त घटकर 500 मिलियन डॉलर रह गया। इससे भी अर्थव्यवस्था पर निराशाजनक प्रभाव पड़ा किन्तु विदेश व्यापार में गिरावट का परिमाण बहुत अधिक नहीं था।

महान् मन्दी के काल के दौरान उनके उपचार हेतु कई निदान प्रस्तुत किये गये किन्तु उनमें सार्वजनिक वित्त की चली आ रही नीतियों में क्रान्तिकारी परिवर्तन

सुझाए गये थे तथा सघीय सरकार को भी एकदम नवीन व अपरम्परागत भूमिका निभानी थी। राष्ट्रपति हूवर का प्रशासन यह सब कर सकने में सक्षम नहीं था। संकट की इस घड़ी में भी एक मूर्खतापूर्ण मौद्रिक नीति अपनाई जाती रही। हालांकि पुनर्निर्माण वित्त निगम (Reconstruction Finance Corporation) तथा सघीय कृषि बोर्ड (Federal Farm Board) जैसी संस्थाओं का निर्माण किया जा चुका था किन्तु उन्हें पूरी तरह क्रियाशील नहीं बनाया जा सका।¹ सरकार व ध्वससाय में नेतृत्व प्राप्त किये हुए लोगों के प्रमाण-पत्रों के आधार पर जन विश्वास बनाए रखने की बात पर आवश्यकता में ज्यादा जोर दिया गया और आय में वृद्धि करने तथा मुद्रा संकुचन को ठीक करने के उपायों पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया।

1932 के चुनावों में रिपब्लिकन दल की हार हुई तथा राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने मार्च 1933 में बागडोर सम्भाली। इस बीच 14 फरवरी 1933 को डेट्रॉइट के सभी प्रमुख बैंकों पर ताला पड़ चुका था। 'औद्योगिक उत्पादन अब कुल क्षमता का मात्र 40 प्रतिशत रह गया था, देश के एक चौथाई पारिवारिक मुखियाओं के पास कोई काम नहीं था और अज्ञात सख्या में लोग अक्षरशः भूखो मर रहे थे।'²

नया आर्थिक कार्यक्रम (New Deal Policy)

फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के अनुसार, 'वास्तव में हम जो चाहते हैं वह है हमारी आर्थिक प्रणाली में सन्तुलन उद्योग व कृषि के बीच सन्तुलन, मजदूर, नियोक्ता तथा उपभोक्ता के बीच सन्तुलन। हम यह भी चाहते हैं कि हमारे घरेलू बाजार व्यापक एवं समृद्ध बने रहें तथा अन्य देशों के साथ हमारा व्यापार बही-खाते के दोनों तरफ बढ़ता रहे।'

4 मार्च 1933 को शपथ ग्रहण करने के बाद दिये गये अपने प्रथम उद्घाटन भाषण में राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने घोषणा की कि, 'एकमात्र चीज जिससे हमें डरना चाहिए वह डर स्वयं है।' राष्ट्रपति रूजवेल्ट के प्रशासन ने मन्दी में निपटने के लिए जो उपाय किये उन्हें दो श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है (1) राहत व पुनरुद्धार सम्बन्धी उपाय, तथा (2) सुधार एवं पुनर्निर्माण सम्बन्धी उपाय। महान् मन्दी को निकाल बाहर करने का यह दुतरफा प्रयाण हो नवीन आर्थिक कार्यक्रम या 'न्यू डील' के नाम से विख्यात हुआ। कुछ अन्य लेखकों ने प्रथम न्यू डील तथा द्वितीय न्यू डील कार्यक्रम के बीच और अन्तर तक भी भेद किया है। प्रथम न्यू डील कार्यक्रम के अन्तर्गत 1933-35 तथा द्वितीय न्यू डील के अन्तर्गत रूजवेल्ट की 1935 के बाद की नीतियों को सम्मिलित किया गया है।

महान् मन्दी के घोर निराशा से भरे वातावरण में प्रशासन में परिवर्तन आवश्यक बन गया था। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट का आत्मविश्वास व शक्ति काफी धीरज बचाने वाले थे। किन्तु देश को मात्र मनोवैज्ञानिक उत्थान की ही आवश्यकता नहीं थी। आवश्यकता इस बात की थी कि बेसहारा हो चुके परिवारों को राहत प्रदान की जाये। एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य गिरते हुए मूल्यों की प्रवृत्ति को उलटने का था।

एक और आवश्यक कार्य किसानों व श्रमिकों की आय में वृद्धि करने का था।

(1) बेकारी राहत तथा 'सस्ते' डॉलर—अनेक संस्थाओं के माध्यम से एक बेरोजगारी राहत का सघीय कार्यक्रम तुरन्त शुरू किया गया। डॉलर का अवमूल्यन तब प्रारम्भ हो गया जब उसके पीछे स्वर्ण की माना घटा दी गई। सस्ती मुद्रा की इस सघीय नीति (Federal Policy of Easy Money) का उद्देश्य मूल्य स्तर को ऊँचा उठाना था। कृषि आय का आधारभूत पुनर्समायोजन करने तथा औद्योगिक मजदूरी-मूल्य ढाँचे को नया स्वरूप प्रदान करने का कार्य न्यू डील कार्यक्रम के अन्तर्गत जिन दो संस्थाओं द्वारा पूरा करना था, वे थी—कृषि समायोजन प्रशासन (A A A) तथा राष्ट्रीय पुनरुद्धार प्रशासन (National Recovery Administration)।

(2) कृषि के लिए नवीन आर्थिक कार्यक्रम—हम कृषि समायोजन कार्यक्रम (A A A) कृषि विकास के अन्तर्गत पहले ही देख चुके हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कपास उगाने वाले कृषि क्षेत्र में कम से कम 30% की कमी करना था ताकि उसकी पूर्ति को घटाया जा सके। अस्थायी रूप से इस प्रकार अपने कृषि क्षेत्र में कमी करने के लिए किसानों को क्षति पूर्ति के रूप में लाभ-भुगतान (benefit payments) करने का भी प्रावधान था। इसके बाद इसी तरह कृषित क्षेत्र में कमी का कार्यक्रम अन्य कई प्रकार की फसलों का उत्पादन घटाने की दृष्टि से भी लागू किया गया।

लेकिन कृषि समायोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत फसलों के कृषित क्षेत्र को घटाकर कृषि उत्पादन में कटौती करने की नीति की तीखी आलोचनाएँ की गयी। आलोचकों का तर्क था कि इस तरह कृषि पदार्थों का उत्पादन घटाना एक विरोधाभास-पूर्ण नीति थी विशेष रूप से तब जबकि लाखों लोग भूख व कुपोषण से पीड़ित थे। इस बीच तकनीकी सुधार हो जाने के कारण कृषित क्षेत्र में कमी द्वारा कृषि पदार्थों के उत्पादन में कमी करने के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था वह भी पूरा नहीं हो पाया। इतना ही नहीं, 1936 में अमरीका के सर्वोच्च न्यायालय ने कृषि समायोजन विधेयक (A A A) को ही असावधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया क्योंकि वह राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण करता था तथा सघीय सरकार द्वारा कर लगाने के अधिकार का दुरुपयोग करता था।

1936 ही में एक नया कृषि समायोजन विधेयक (Agricultural Adjustment Act) पारित किया गया। इसका उद्देश्य कुछ कृषि पदार्थों के लिए 'समता मूल्यों' (Parity Prices) की स्थापना करना था। ये समता मूल्य 1909-14 की अवधि में किसानों द्वारा खरीदी गई वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर रहे जाने थे। किसानों को और भी अधिक राहत प्रदान करने के उद्देश्य से 1933 में एक कृषि साख विधेयक (Farm Credit Act, 1933) लाया गया। इस विधेयक ने भूमि बैंकों की स्थापना की तथा उत्पादन साख, मध्यवर्ती साख व सहकारी साख के लिए भी प्रावधान किये।

तीन अन्य विधेयक, जो किसानों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से पारित किये गए, इस प्रकार थे—

(i) कृषि-रहन व पुनर्वित्त अधिनियम, 1934 (Farm Mortgage and Refinancing Act, 1934)—इस विधेयक ने एक मधीय कृषि-रहन निगम स्थापित किया जो कृषि ऋणों के लिए पुनर्वित्त की सुविधा देने में सहायता करता था।

(ii) कृषि-रहन मोचन-निषेध विधेयक, 1934 (Farm Mortgage Foreclosure Act, 1934)—इस विधेयक ने भूमि बैंक आयुक्तों को इस बात का अधिकार दिया कि वे किसानों को मोचन-निषेध पूर्व उनके स्वामित्व वाली भूमि का पुनर्नय करने के लिए ऋण प्रदान करने की सुविधा दे सकते हैं।

(iii) फ्रेज़ियर-लेम्के दिवालिया कानून, 1934 (Frazier-Lemke Bankruptcy Act, 1934)—इस विधेयक में यह प्रावधान किया गया कि कोई भी किसान अपने दिवालिया होने की वजह से बेचे गये भेत को 6 वर्षों के भीतर पुनर्नय कर सकेगा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस विधेयक को निरस्त घोषित कर दिये जाने के बाद इस अवधि को घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया।

(3) उद्योगों के लिए 'न्यू डील'—राष्ट्रीय औद्योगिक पुनरुद्धार विधेयक (National Industrial Recovery Act) 1933 में पारित किया गया। इसका उद्देश्य मूल्य एवं मजदूरी के स्तर को बढ़ाना व काम को फैलाना था जिसके लिये काम के घण्टों में कमी तथा प्रतिद्विन्द्वियों द्वारा मूल्यों में कटौती को रोकने जैसे उपाय किये गये। जनरल ह्यू जॉन्सन (General Hugh Johnson) की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय पुनरुद्धार प्रशासन (National Recovery Administration, N.R.A.) गठित किया गया। इस प्रशासन ने प्रत्येक उद्योग के लिए 'उचित व्यवहार आचार संहिता' (code of fair-practice) तैयार की। 1935 तक ऐसी 557 आचार संहिताएँ स्वीकार की जा चुकी थी। अनेक व्यक्तियों ने राष्ट्रीय पुनरुद्धार प्रशासन द्वारा किये गये उपायों को शका भरी नज़रों से देखा किन्तु राष्ट्रीय उत्पाद (G.N.P.) 1933 के 56 अरब डॉलर से बढ़कर 1935 में 72.5 अरब डॉलर तक पहुँच गया। वस्तुओं के थोक मूल्यों में 33% की वृद्धि हुई तथा वे 1930 के अन्तिम महीनों वाले स्तर तक जा पहुँची।

अर्थव्यवस्था में ढेर सारी नयी मुद्रा प्रवाहित करने (pump priming) के बारे में काफी चर्चा चली थी जिसे सार्वजनिक व राहत कार्यों पर व्यय करने के सुझाव थे। पहले पहल तो इसे अपव्यय माना गया किन्तु 1936 के बजट में 4,500 मिलियन डॉलर का घाटा दिखाया गया। यह घाटा अपने आप में एक रिकॉर्ड था। 1935 के बाद हर चीज में चढ़ने की प्रवृत्ति आयी तथा वह चल निकली। 1937 के आरम्भ में निर्मित वस्तुओं का कुल उत्पादन 1929 के स्तर से आगे निकल गया। मूल्य तथा मजदूरी में भी तेजी से वृद्धि हुई। बेकारी की समस्या में भी काफी कमी आई।

1937 में ऐसा सोचा गया कि मन्दो अन्तिम रूप से समाप्त हो चुकी है। इसके परिणामस्वरूप बजट में घाटे का प्रावधान समाप्त कर दिया गया तथा अनेक राहत कार्यों पर खर्च में कटौती कर दी गई। किन्तु मार्च 1938 में मन्दो एक बार पुन खीट कर आ गई। लोगों में न्यू डील कार्यक्रम के प्रति अविश्वास पैदा हो गया। 1939

अनुमानित बेकारी : 1934-43

वर्ष	बेकारी (मिलियन में)	नागरिक श्रम-शक्ति का %
1934	11.3	21.7
1935	10.6	20.1
1936	9.0	16.9
1937	7.7	14.3
1938	10.4	19.0
1939	9.5	17.2
1940	8.1	14.6
1941	5.6	9.9
1942	2.7	4.7
1943	1.1	1.9

के अन्त तक ही औद्योगिक उत्पादन का स्तर पुन 1937 के चरम उत्पादन तक पहुँच सका। टिकाऊ वस्तुओं के उत्पादन में तो पुनरुद्धार 1940 तक ही सम्भव हुआ। पूर्ण पुनरुद्धार के प्रथम चिह्न भी 1940 ही में दिखाई पड़ने लगे थे।

(4) बैंकिंग में 'न्यू डील'—स्वर्णमान का 1933 में परित्याग कर दिया गया। 1933 में एक ग्लास-स्टेगाल विधेयक (Glass-steagall Act) बैंकिंग गति विधियों के विनियमन हेतु पारित किया गया। इस विधेयक ने सघीय रिजर्व बैंक को व्यावसायिक बैंकों द्वारा सट्टेबाजी के कार्यों के लिए साख्त-सृजन पर रोक लगाने का अधिकार प्रदान किया। एक सघीय निक्षेप बीमा योजना (Federal Deposit Insurance Scheme) भी प्रारम्भ की गई तथा प्रत्येक बैंक को इससे सम्बद्ध होने के लिए बाध्य किया गया।

(5) टेनेसी घाटी क्षेत्र (Tennessee Valley Region) के लिए 'न्यू डील'—टेनेसी घाटी क्षेत्र का विकास न्यू डील कार्यक्रम की वह सर्वोत्कृष्ट घटना थी जो कृषि विकास के लिए घटी। इस कार्यक्रम में 7 राज्य सम्मिलित थे तथा लगभग 20 लाख लोगों पर इसका प्रभाव पड़ा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बाघ व बिजली घरों का निर्माण करना था। साथ ही साथ इसके द्वारा बाढ़ नियन्त्रण कार्यक्रम, भूमि या मिट्टी के कटाव को रोकना तथा बन लगाने के काम में तेजी लाने के उद्देश्य भी पूरे किये जाने थे। 'एक दशक के भीतर-भीतर (1933 में टेनेसी वैली एक्ट के पारित किये जाने के बाद) टेनेसी घाटी योजना ने इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया था। 1937 में कांग्रेस के नाम अपने एक विशेष सन्देश में ऐसी 6 और क्षेत्रीय आयोजन परियोजनाओं को प्रारम्भ करने की वकालत की थी जिनसे पूरा राष्ट्र लाभ उठा सकता था। किन्तु उसे एक की भी अनुमति नहीं मिली।'।

(6) श्रमिकों के लिए 'न्यू डील'—औद्योगिक श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए चार महत्वपूर्ण विधेयक पारित किये गये :

(1) राष्ट्रीय औद्योगिक पुनरुद्धार विधेयक 1933 ने मजदूरों के संगठित होने व सामूहिक सौदेबाजी कर सकने के अधिकार को गारन्टी प्रदान की।

(ii) राष्ट्रीय रोजगार सेवा विधेयक, 1933 (National Employment Service Act) ने सघीय सरकार तथा स्थानीय रोजगार कार्यालयों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए प्रावधान किये।

(iii) वाल्श-हीले विधेयक, 1936 (Walsh-Healey Act) में फेक्ट्रियो में काम की दशाओं के विनियमन हेतु प्रावधान किये गये।

(iv) उचित श्रम प्रतिमान विधेयक, 1938 (Fair Labour Standards Act) में श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी तथा काम के अधिकतम घण्टों के लिए प्रावधान किया गया।

नवीन आर्थिक कार्यक्रम (New Deal Policy) का मूल्यांकन

नवीन आर्थिक कार्यक्रम के समर्थकों का मानना था कि उसने देश को महा-विनाश से बचा लिया। इसके आलोचकों का मानना था कि यह कार्यक्रम अनेक नीतियों की खिचड़ी था तथा वह अमरीकी अर्थव्यवस्था की आधारभूत समस्याओं को हल करने में असफल ही रहा।

आलोचकों ने यह भी तर्क दिया कि नवीन आर्थिक कार्यक्रम रोजगार व उत्पादन को पुनर्जीवित करने में असफल ही रहा। 1937 में भी 70 लाख से अधिक औद्योगिक श्रमिक बेकार थे तथा कुल राष्ट्रीय उत्पाद (Gross National Product) भी 71 अरब डॉलर तक ही पहुँच पाया था जबकि वह 1929 में 82 अरब डॉलर के स्तर तक तो एक बार पहले ही पहुँच चुका था। आलोचकों ने नवीन आर्थिक कार्यक्रम पर यह भी आरोप लगाया कि उसने राष्ट्रीय ऋणों को दुगुना कर दिया था। विनियोग की धीमी दर भी गत सरकारी नीतियों के कारण बनी रही थी। यह भी तर्क दिया गया कि 'निजी उपक्रमों पर प्रहार करके, नौकरशाही विनियमन थोप करके, राष्ट्रीय ऋण भार बढ़ाकर तथा श्रमिकों को अनेक प्रकार के विशेषाधिकार प्रदान कर उसने एक अनिश्चितता की स्थिति पैदा कर दी थी जिसमें व्यापार का प्रसार असम्भव बन गया था।' अन्य आलोचकों का मानना था कि नवीन आर्थिक कार्यक्रम मुख्य रूप से इसलिए असफल रहा कि वह बहुत अधिक आगे तक नहीं जा पाया। उनके अनुसार 'सार्वजनिक विनियोग अब से एक स्थायी नीति होनी चाहिए थी और अगर धनराशि इस प्रकार व्यय की जाये कि जिसमें राष्ट्रीय सम्पदा में अभिवृद्धि हो जैसे कम लागत के रिहायशी मकानों का निर्माण, स्कूलों, अस्पतालों तथा अन्य सार्वजनिक उपयोग वाले भवनों का निर्माण—तो वज्रद में घाटे तथा राष्ट्रीय ऋण भार में निरन्तर वृद्धि से चिन्तित होने की आवश्यकता नहीं है।'।

इन अनेक आलोचनाओं के उपरान्त यह बात निःसन्देह रूप से कही जा सकती है कि सयुक्त राज्य अमरीका के आर्थिक इतिहास में यह नवीन आर्थिक कार्यक्रम पथ-प्रदर्शक (pace-setter) के रूप में जाना जायेगा। इसे पहले से ही एक ऐसे सर्वाधिक सन्निधाली एवं प्रभावशाली मुद्रा सकुचन विरोधी कार्यक्रम के रूप में ख्याति प्राप्त हो चुकी है जो अब तक के इस प्रकार के कार्यक्रमों में सबसे विशाल पैमाने पर चलाया गया। नवीन आर्थिक कार्यक्रम ने अमरीकी अर्थव्यवस्था में कुछ ऐसी विशिष्ट

प्रवृत्तियों को जन्म दिना जो उन कार्यक्रम के समाप्त हो जाने के बाद भी कई वर्षों तक सक्रिय रही। इन नवीन प्रवृत्तियों को इस प्रकार रखा जा सकता है—

(1) अमरीकी अर्थव्यवस्था ने, अपने जीवन काल में पहली बार, आयोजन व केन्द्रीय नियन्त्रण के महत्त्व को पहचाना। गम्भीर आर्थिक संकट का सामना करने में सरकार की भूमिका भी काफी स्पष्ट हो गई।

(2) नवीन आर्थिक कार्यक्रम को एक नये आर्थिक दर्शन की प्रारम्भ करने का भी श्रेय दिया जाता है। कीन्स द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त नवीन आर्थिक कार्यक्रम के तौर-तरीकों के समरूप ही थे।

(3) इस एक नये सिद्धान्त की भी स्थापना हुई कि आर्थिक समृद्धि की पुनर्स्थापना एकाधिकार की स्थापना द्वारा की जा सकती है तथा यह भी कि इस प्रकार के एकाधिकार के लिए सरकारी समर्थन आवश्यक होता है। सरकार द्वारा लाया गया कृषि समायोजन विधेयक (Agricultural Adjustment Act) कृषि एकाधिकार (Farm Monopoly) स्थापित करने का ही एक प्रयास था। राष्ट्रीय औद्योगिक पुनरुद्धार विधेयक (National Industrial Recovery Act) द्वारा इसी प्रकार औद्योगिक एकाधिकार स्थापित करने के भी प्रयास किये गये थे। उत्पादन पर अनेक प्रकार की सीमाएँ लगाकर उसे प्रतिबन्धित कर दिया गया था तथा बिक्री मूल्य भी तय कर दिये गये थे। ये एकाधिकारिक प्रयास अपने अन्तिम परिणाम में उद्योग व कृषि दोनों ही क्षेत्रों में माँग व पूर्ति के बीच समानता स्थापित कर पाने में सफल रहे थे।

(4) नवीन आर्थिक कार्यक्रम ने बैंकिंग सेवाओं तथा मुद्रा के निर्गमन में भी कुछ नयी बातें सिखाईं तथा परियोजनाओं के लिए मजबूत स्रोतों से वित्तीय साधन प्राप्त करने का तरीका भी बताया। मौद्रिक व राजकोषीय उपायों का नवीन आर्थिक कार्यक्रम के सम्पूर्ण कार्यकाल में अत्यन्त प्रभावशाली ढंग से उपयोग किया जाता रहा।

(5) नवीन आर्थिक कार्यक्रम ने प्रशासन को भविष्य में मन्दी से पैदा होने वाली किसी भी चुनौती का मुकाबला कर सकने की क्षमता व योग्यता प्रदान की।

(6) नवीन आर्थिक कार्यक्रम ने सघीय सरकार को और भी शक्तिशाली बनाया। वह प्रवृत्ति तब से ही चलती चली आ रही है तथा नवीन आर्थिक कार्यक्रम के बाद के वर्षों में बनी सघीय सरकारें पिछली सरकारों के मुकाबले अधिक शक्तिशाली बनकर सामने आयी हैं।

(7) अनेक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों (Social Security Programmes) की शुरुआत कर नवीन आर्थिक कार्यक्रम ने अमरीकी नागरिकों को पहली बार उनके सामाजिक दायित्वों से अवगत कराया। उसने सम्पूर्ण संयुक्त राज्य अमरीका में मानवतावादी कार्यक्रमों तथा सामाजिक सुधारों की एक लहर पैदा कर दी।

इस सन्दर्भ में नवीन आर्थिक कार्यक्रम प्रो० जे० के० गेल्ब्रेथ (J K Galbraith) की इस नई अवधारणा का अनुसमर्थन ही करती लगती है कि 'यदि अर्थव्यवस्था में एक मजबूत निजी बाजार की शक्ति दी हुई हो तो प्रतिभार वाली शक्ति (countervailing power) अर्थव्यवस्था की स्वतन्त्र रूप से स्व विनियमन

(autonomous self-regulation) कर सकने की क्षमता को दृढ़ ही बनाती है और इस तरह सरकारी नियन्त्रण या आयोजन के कुल परिमाण को वाछित या आवश्यक, अन्त में घटाती ही है ।¹

प्रो० फॉर्कनर ने लिखा है कि 'नवीन आर्थिक कार्यक्रम में एक नवीन तत्त्व अहस्तक्षेप की नीति की अवलति को अधिक तेज कर देने का था ।'¹

¹ 'The New element in the New Deal was the acceleration of the decline of the laissez faire'—Faulkner, *American Economic History*

सातवाँ अध्याय

श्रम संघवाद

(TRADE UNIONISM AND LABOUR MOVEMENT)

आरम्भिक श्रम आन्दोलन

अर्थशास्त्री सामान्यतया यह कहते हैं कि आधुनिक श्रम समस्याएँ 'श्रमिक के उसके औजारों से पृथक् हो जाने के कारण' उत्पन्न हुई हैं। जब संयुक्त राज्य अमरीका ने 1776 में एक स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में अपने अस्तित्व की शुरुआत की तब वह एक बहुत आदिम प्रकार का पूँजीवादी समाज था। अधिकांश जनसंख्या गाँवों में रहती थी तथा 1810 में 80% श्रम-शक्ति कृषि-कार्यों में लगी हुई थी।

1790 के दशक में फिलाडेल्फिया, न्यूयार्क तथा बोस्टन के कुछ शिल्पियों (craftsmen) ने आधुनिक श्रम-संघों के आदि स्वरूप (prototype) कुछ संघ बनाये थे। किन्तु ये अधिकांश संघ अस्थायी व सक्रमणकालीन थे। उनकी सदस्य-संख्या समृद्धि के समयों में तेजी से बढ़ जाती तथा मंदी के समयों में उतनी ही तेजी के साथ घट जाती। 1819-20 की मंदी ने ऐसे अधिकांश संघों को निर्मूल कर दिया था। लेकिन 1824 से 1837 के बीच शिल्प समितियाँ (craft societies) धीरे-धीरे वापस पुनर्जीवित हुईं। इस अवधि के श्रम संघवाद की दो मुख्य प्रवृत्तियों को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है—(1) सामूहिक सौदेबाजी की तकनीक सीख ली गई थी तथा लड़ने वाले श्रम संघों ने हड़तालों व बहिष्कारों (strikes and boycotts) का चतुराई व साहस से उपयोग आरम्भ कर दिया था, (2) तीव्र गति से बढ़ती हुई व्यक्तिगत समितियाँ धीरे-धीरे एक दूसरे में प्रवेश करने लगी तथा स्थानीय व बाद में राष्ट्रीय संघ बनने लगे।¹

गृह युद्ध के छिड़ जाने से श्रम आन्दोलन अस्त-व्यस्त हो गया तथा श्रम संघों को उसका आघात सहना पड़ा। किन्तु शिल्प-संघ (craft unions) अब तक काफी लोकप्रिय हो चुके थे। 1864 में लगभग 300 स्थानीय श्रम संघ बन चुके थे जिनकी सदस्य संख्या 2,00,000 के लगभग थी। ये श्रम संघ मुख्यतः न्यूयार्क, पेंसिलवेनिया तथा मेसाचुसेट्स जैसे औद्योगिक राज्यों में केन्द्रित थे। 1865 तक कम से कम 11 राष्ट्रीय यूनियनों भी बनाई जा चुकी थी। 1873 तक देश में 41 राष्ट्रीय शिल्प संघ थे जिनकी सदस्य-संख्या 3 से 4 लाख के बीच थी।

नाइट्स ऑफ लेबर (Knights of Labour)

अब तक एक विशाल यूनियन बनाने का विचार जोर पकड़ता जा रहा था। वैसे तो 1864 में ही सहरो में स्थित यूनियनों के एक राष्ट्रीय महासंघ बनाने का प्रयास हो चुका था किन्तु वह प्रयास सफल नहीं हो पाया। इस प्रथम प्रयास की परिणति एक राष्ट्रीय श्रमिक यूनियन (National Labour Union) के रूप में हुई। हालांकि वह असफल रही किन्तु उससे श्रमिक वर्ग की व्यापारिक वर्ग के विरुद्ध एक मजबूत मोर्चा बनाने की इच्छा अभिव्यक्त हो गई।

इन बीच फिलाडेल्फिया में 1869 में एक बहुत ही रोमानी श्रम संगठन अस्तित्व में आ चुका था। यह फिलाडेल्फिया के निर्धन दर्जियों का एक संगठन था जिसे बहुत ही लम्बा नाम—'द नोबल एण्ड होली ऑर्डर ऑफ द नाइट्स ऑफ लेबर'—दिया गया था। इस संघ ने श्रमिकों के नाम एक नई अपील जारी की तथा उनकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व लिया। नाइट्स (Knights of Labour) की प्राथमिक इकाइयाँ स्थानीय सभाएँ थीं। चार से पाँच स्थानीय सभाओं (Local Assemblies) से मिलकर एक जिला सभा (District Assembly) तथा जिला सभाओं से मिलकर एक सामान्य सभा (General Assembly) बनती थी। यह सामान्य सभा ही संगठन की प्रशासनिक संस्था (Governing Body) थी।

जैसे-जैसे उसकी सदस्य संख्या बढ़ी, नाइट्स में 'एक विशाल यूनियन' (One Big Union) बनने की अभिलाषा जागृत हुई। गुरु में तो इसकी प्रगति धीमी रही किन्तु 1881 के बाद इसकी वास्तविक प्रगति आरम्भ हुई। उस वर्ष में इसकी सदस्य संख्या 20,000 थी। अगले पाँच वर्षों में अर्थात् 1885 तक वह बढ़ कर 7,50,000 के अभूतपूर्व स्तर तक पहुँच गई। 1877 के श्रमिक प्रदर्शनों ने इसकी लोकप्रियता को बढ़ा दिया था। नाइट्स ने 1884 व 1885 में रेलमार्ग कंपनियों के विरुद्ध कई हड़तालों व काम-बन्दियाँ (work stoppages) कराये।

1886 में द नाइट्स ऑफ लेबर द्वारा एक रेलमार्ग कंपनी के विरुद्ध की गई हड़ताल असफल रही। उस असफलता के बाद से उसकी सदस्य संख्या घटने लगी। वह 1890 में घटकर 1,00,000 पर आ गई और 1900 तक तो द नाइट्स एक तुच्छ संगठन बन गया। द नाइट्स की असफलता के कई कारण रहे—(1) इसकी पंचमेल (heterogeneous) सदस्यता ने कई नीति सम्बन्धी विरोधों व विवादों को जन्म दिया। (2) सारी शक्ति कुछ शीर्षस्थ नेताओं के हाथों में सकेन्द्रित हो गई। (3) उसने अपने वित्तीय साधन हड़तालों पर बरबाद कर दिये जो सफल रहने पर भी महँगी सिद्ध हुई। (4) उसके सहकारी उपक्रम भी असफल रहे।

अमरीकी श्रमिक महासंघ

(The American Federation of Labour, A F L)

1881 में 6 दृढ़ व्यवसाय यूनियनों के नेताओं ने मिलकर श्रमिकों का एक अन्य महासंघ स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। 1886 में द नाइट्स से सम्बन्धित कुछ अन्य यूनियनों भी इस नये महासंघ में सम्मिलित हो गईं जिसे अमरीकी श्रमिक

महासघ (A F L) का नाम दिया गया। आरम्भ के वर्षों में इसकी सदस्यता वृद्धि की दर काफी धीमी रही। 1898 में वह 2,50,000 तक पहुँची थी, लेकिन इसके बाद सदस्यता में तेजी से वृद्धि हुई तथा 1904 में वह 16.7 लाख हो गई। 1914 तक इसकी सदस्यता 20 लाख की सीमा पार कर चुकी थी। इसके बाद अमरीकी श्रमिक महासघ (A F L) की सदस्यता में वृद्धि का दूसरा काल आया। प्रथम महायुद्ध की समाप्ति तक इस महासघ (A F L) की सदस्यता 40 लाख तक पहुँच गई। यह संख्या सभी यूनियन सदस्यों की संख्या का 80% थी।

अमरीकी श्रमिक महासघ की सदस्यता में इतनी तीव्र गति से हुई वृद्धि के लिए अनेक तत्त्व उत्तरदायी थे। 1898 से 1920 के बीच आर्थिक गतिविधियाँ काफी तेज रही। औद्योगिक उत्पादन अत्यधिक तीव्र गति से बढ़ रहा था। इसके अतिरिक्त अमरीकी श्रमिक महासघ (A F L) को स्ट्रासर व गोपर्स (Strasser and Gompers) जैसे अनुभवी लोगो के नेतृत्व का भी लाभ प्राप्त था। ये लोग ठोस उपलब्धियों में विश्वास करते थे तथा इन्होंने बिना राजनीति में पड़े श्रमिकों के लिए कुछ वैधानिक सुधार करवाये। इसके अलावा उन्होंने 'श्रमिकों के शत्रुओं को हराने तथा उनके मित्रों को पुरस्कृत करने की नीति' का अनुसरण किया। अमरीकी श्रमिक महासघ की सफलता इसलिए भी मिली कि (1) उनमें अपने ढाँचे में यथोचित सुधार कर सकने की क्षमता थी, तथा (2) उसने नियोक्ताओं के साथ सम्बन्ध स्थिर बनाने के लिए सामूहिक सौदेबाजी को बढ़ावा दिया।

अमरीकी श्रम संघों की 1920 के बाद प्रगति

श्रम संघों की सदस्यता जो 1920 के आस-पास 50 लाख तक पहुँच गयी थी 1923 में घटकर 35 लाख पर आ गई। 1929 तक वह लगभग इसी स्तर पर बनी रही। महान् मन्दो के समय उसमें और भी गिरावट आयी। 1933 में श्रम संघ की कुल सदस्यसंख्या 30 लाख के लगभग थी। अमरीकी श्रमिक महासघ (A F L) की सदस्यता इस दौरान 40 लाख से घटकर 22 लाख पर आ चुकी थी।

1920 के बाद श्रम संघों की सदस्यता में यह गिरावट कई कारणों से आई। मुख्य कारण इस प्रकार थे—(1) 1921 की मन्दो, (2) युद्ध के बाद के वर्षों में असफल हड़तालें, (3) नियोक्ता विरोध की एक नई लहर, (4) एक स्थिर मूल्य स्तर बना रहना जिसमें श्रमिक सुरक्षित अनुभव कर रहे थे, तथा (5) प्रगतिशील पुंजोत्पादन उद्योगों में श्रमिकों की संगठित करने के प्रति विशेष रुचि प्रदर्शित न करना। श्रम संघों का नेतृत्व भी कमजोर व अदूरदर्शी लोगों के हाथों में आ गया था।

1935 के आस-पास श्रमिकों में आपस में ही श्रम संघों के ढाँचे को लेकर पैदा हुआ विवाद काफी तीव्र हो गया। नये पुंजोत्पादन उद्योगों (new mass production industries) जैसे इस्पात, मोटर कार, रबड़ तथा बिजली उपकरण को संगठित करने के प्रस्ताव का अमरीकी श्रमिक महासघ से सम्बद्ध पुरानी यूनियनों ने विरोध किया। इसका परिणाम यह हुआ कि 1936 में आठ औद्योगिक श्रम संघों

ने एक नई राष्ट्रीय संस्था 'कमेटी फॉर इण्डस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन' स्थापित की। तीन वर्ष बाद इसे कांग्रेस ऑफ इण्डस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन' (C I O) के नाम से जाना गया। इस महासंघ ने अमरीकी श्रमिक महासंघ (A F L) के साथ अपने सभी सम्बन्ध तोड़ लिये।

अमरीकी श्रमिक महासंघ (A F L) तथा कांग्रेस ऑफ इण्डस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन (C I O) के बीच संघर्ष व विवाद चलता रहा। दोनों ही ओर से दल-यदल होता रहा। सी० आई० ओ० के नेता ए० एफ० एल० के दीलेपन तथा राजनीति में जोर शोर से हिस्सा न लेने की बात नापसन्द करते थे। उधर ए० एफ० एल० के नेता सी० आई० ओ० द्वारा परम्परावादी श्रम संघवाद से छिटक कर अलग हो जाने से रुष्ट थे। किन्तु लोकमत के दबाव तथा अत्यधिक कड़े श्रम कानूनों में बाध्य होकर 1955 में दोनों ही महासंघ पुनः एकीकृत हो गये। उनका मिला-जुला संघ ए० एफ० एल०-सी० आई० ओ० (A F L-C I O) कहलाया।

श्रम संघों की सदस्यता के आकड़े

वर्ष	(मिलियन में)	
	संख्या	
1920	50	
1925	35	
1930	34	
1935	36	
1940	87	
1945	143	
1950	143	
1955	168	
1960	170	
1975	180	

1920 के बाद के श्रम संघ सदस्यता अनुमानों से स्पष्ट होता है कि उसमें नवीन आर्थिक कार्यक्रम तथा द्वितीय महायुद्ध के काल में तेजी से वृद्धि हुई। किन्तु यह भी महत्वपूर्ण है कि किसी भी समय में श्रम संघों की सदस्यता कुल नागरिक श्रम शक्ति का 30% से अधिक कभी भी नहीं रही है।

1933 से 1953 के बीच श्रम संघों की सदस्यता में तीव्र गति से वृद्धि होने के लिए कई कारण उत्तरदायी थे। ये कारण इस प्रकार थे (1) कुल नागरिक श्रम शक्ति में 15 मिलियन की वृद्धि हो जाना, (2) श्रम शक्ति की एकस्यता (homogeneity) में वृद्धि (3) श्रम संघों की सदस्यता को सामाजिक मान्यता प्राप्त हो जाना, तथा (4) इस सम्पूर्ण अवधि में सरकार का श्रमिकों के प्रति अनुकूल रुख बने रहना।

महत्वपूर्ण श्रम विधेयक (Important Labour Acts)

नॉरिस-ला गार्डिया विधेयक, 1932 (Norris-La Guardia Act)

स्वतन्त्र रूप से संगठित होने के मार्ग में बाधाएँ हटाने की दिशा में पहला कदम था। किन्तु विधेयक में सामूहिक सौदेबाजी के लाभों को सकारात्मक रूप से प्रत्याभूत नहीं किया गया। सामूहिक सौदेबाजी (collective bargaining) का अधिकार पहली बार वेगनर विधेयक (Wagner Act), जिसे राष्ट्रीय श्रम सम्बन्ध विधेयक भी कहा गया, द्वारा बलपूर्वक कहा गया। श्रमिकों ने वेगनर विधेयक की प्रशंसा करते हुए उसे अपना मुक्ति दस्तावेज (magna charta) माना। किन्तु वेगनर विधेयक भी अधिक विवाद नहीं था। उसमें तो सामूहिक सौदेबाजी की परिभाषा भी नहीं की गई थी।

1946 में रिपब्लिकन दल की सरकार ने वेगनर विधेयक में अनेक संशोधन किये। नये कानून को श्रम-प्रबन्ध सम्बन्ध विधेयक (Labour Management Relation Act) का नाम दिया गया। इसका अधिक परिचित नाम टाफ्ट-हार्टले विधेयक (Taft-Hartley Act) था। इस विधेयक में कहा गया कि सार्वजनिक नीति के अन्तर्गत न केवल श्रमिक द्वारा यूनियन का सदस्य बनने के अधिकार की रक्षा की जानी चाहिए बल्कि उसके सदस्य बनने से इनकार करने के अधिकार की भी रक्षा की जानी चाहिए। बन्द-दुकान समझौते (closed-shop agreement), जिनके अन्तर्गत नियुक्ता केवल श्रम सघों के सदस्य की ही काम पर लगा सकते थे, गैर-कानूनी घोषित कर दिये गये। यूनियन शॉप समझौते (union shop agreement) जिनमें गैर-यूनियन सदस्य काम पर रखा जा सकता था किन्तु जिसे एक निश्चित अवधि में यूनियन की सदस्यता स्वीकार करनी होती थी, सही मान लिये गये। टाफ्ट-हार्टले विधेयक में इस बात पर भी बल दिया गया कि यूनियन तथा यूनियन के व्यक्तिगत सदस्यों के हित एक रूप नहीं होते। विधेयक का उद्देश्य श्रम सघों का 'सार्वजनिक हित' में विनियमन करना था। हड़ताल का अधिकार भी एक 'ठण्डे होने की अवधि' (cooling-off period) द्वारा संशोधित कर दिया गया।

12 वर्ष की खुली छूट के बाद श्रमिकों को यह विधेयक काफी प्रतिबन्धात्मक प्रतीत हुआ। श्रम सघों के नेतृत्व ने विधेयक को कटु आलोचना की। उसे 'गुलाम श्रम कानून' (slave labour law) की सजा दी गई। 1959 में पारित श्रम-प्रबन्ध विधेयक (Labour Management Act, 1959), जिसे लैंड्रम-ग्रिफिन विधेयक (Landrum-Griffin Act) के नाम से भी जाना जाता है, में यह मुद्दा बल दिया गया कि श्रम सघों के नेताओं व पदाधिकारियों द्वारा अपनाये जाने वाले भ्रष्ट तरीकों के विरुद्ध यूनियन के व्यक्तिगत सदस्यों के हितों की रक्षा का भी अधिकार होना चाहिए। 1960 के बाद से तथा 1979 तक के श्रम कानूनों में धीरे-धीरे करके टाफ्ट-हार्टले विधेयक में कुछ छूटें दी जाती रही हैं।

श्रम सघ आन्दोलन का मूल्यांकन

श्रम सघ सदस्यता का वर्तमान 18 मिलियन का स्तर काफी ऊँचा लग सकता है किन्तु यह अभी भी अमरीका की कुल श्रम-शक्ति का एक-चौथाई मात्र ही है। श्रम सघ की सदस्यता घानों, निर्मित माल उद्योगों, निर्माण कार्य तथा यातायात

सेवाओं आदि जैसे विभिन्न उद्योगों में तो काफी ऊँची है किन्तु वह सरकारी कार्यालयों तथा कृषि क्षेत्र में काफी नीची है। क्षेत्रीय दृष्टि से देखने पर श्रम सघों की सदस्यता पूर्वी, मध्य पश्चिमी तथा पश्चिमी तट के औद्योगिक क्षेत्रों में अधिक घनी है।

यूनियनों की सदस्यता में काफी अममानता भी है। कुछ यूनियनों की सदस्य-संख्या 100 से भी कम है तो दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टील वर्कर्स तथा यूनाइटेड ऑटोमोबाइल वर्कर्स जैसी यूनियनों में 10 लाख से भी अधिक सदस्य हैं। अमरीकी लोभ मूलक व्यक्तिवादी है तथा यह प्रवृत्ति यूनियन के सदस्यों में भी झलकती है। एक अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (I L O) के दल ने, जिसने अमरीका का दौरा किया था, लिखा कि 'सामान्यतः अमरीकियों की व्यक्तिवादी प्रवृत्ति तथा जिसमें अनेक यूनियन सदस्य भी सम्मिलित हैं कई बार श्रम सघों के प्रति शका व अविश्वास पैदा कर देती है क्योंकि श्रम सघ तो स्वभाव से ही एक मिली जुली गतिविधि है " वास्तव में यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि श्रम सघों को पूर्ण जन-मान्यता केवल राष्ट्रीय संकट के समयों में ही प्राप्त करने में सफलता मिली है जिनमें दोनों महायुद्ध तथा महान् सन्दी सम्मिलित किये जा सकते हैं। ऐसा लगता है कि अमरीका में श्रम सघ एक ऐसे सामाजिक ढाँचे में कार्यरत हैं जिसे वे तो स्वीकार करते हैं किन्तु वह ढाँचा उन्हें पूरी तरह स्वीकार नहीं करता।' अमरीका में श्रम सघों की धीमी रफ्तार से प्रगति का शायद यही सबसे उपयुक्त उत्तर है।

अमरीका में श्रम शक्ति का विकास

अमरीकी श्रम शक्ति में 1974 तक 80% से भी अधिक बयस्क लोग गैर-प्रबन्धकीय क्षेत्र में मजदूरी या वेतनभोगी कर्मचारी थे जो श्रम बाजार में अपनी श्रम-शक्ति बेचने के लिए तत्पर थे।

अमरीकी श्रम शक्ति का सर्वहाराकरण

वर्ष	मजदूरी व वेतन भोगी कर्मचारियों का प्रतिशत	श्रम बाजार क्षेत्रों का प्रतिशत	वेतन भोगी प्रबन्धकीय प्रशासकों का प्रतिशत	कुल
1780	20.0	80.0	—	100
1880	62.0	36.9	1.1	100
1890	65.0	33.9	1.2	100
1900	67.9	30.8	1.3	100
1910	71.9	26.3	1.8	100
1920	72.9	23.5	2.6	100
1930	76.8	20.3	2.9	100
1940	78.2	18.8	3.0	100
1950	77.7	17.9	4.4	100
1960	80.6	14.1	5.3	100
1969	83.6	9.2	7.2	100
1974	83.0	8.2	8.8	100

Source: Edwards Reich and Weisskopf, *The Capitalist System*, 1978, Prentice Hall, 180

आधुनिक निगम क्षेत्र (corporate sector) तथा नौकराही को बढ़ती हुई पेचीदगियों के साथ प्रबन्धकों (managers) की सहाय में भी निरन्तर वृद्धि हो रही है। 1970 में 6.5 मिलियन लोगों को प्रबन्धकों, प्रशासकों या मालिकों की श्रेणी में लिया गया था। अमरीकी श्रम शक्ति का बदलता हुआ व्यावसायिक ढाँचा निम्न तालिका से स्पष्ट है। तालिका में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सरचनात्मक परिवर्तन कृषि में लगे हुई श्रम शक्ति के सम्बन्ध में दिखाई पड़ता है। 1910 में कृषि कार्यों में रत 30.8% श्रम शक्ति के स्थान पर 1985 में उनका भाग घटकर 1.6% रह जायेगा। विकास का यह एक अद्वितीय उदाहरण है। तालिका इस प्रकार है—

अमरीकी श्रम शक्ति का बदलता हुआ व्यावसायिक ढाँचा

		(प्रतिशत में)				
	व्यावसायिक समूह	1910	1940	1960	1972	1985*
1	प्रबंधक, प्रशासक इ.यादि	6.6	7.3	8.5	9.8	10.3
2	सर्वेदपोष कर्मचारी	14.7	23.8	33.8	38.0	42.6
3	नीली कमीज वाले कर्मचारी	38.2	39.8	39.5	35.0	32.3
4	सेवा कर्मचारी	9.6	11.8	11.7	13.4	13.2
5	इ.वि.	30.9	17.4	6.3	3.8	1.6
	कुल	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

* अनुमानित।

Source Ibid, 182

तटकर नीति एवं विदेश व्यापार का विकास (GROWTH OF FOREIGN TRADE AND TARIFF POLICY)

1860 से 1920 के बीच अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पूरी तरह से आधुनिक बन चुका था। इस अवधि में दो मुख्य शक्तियाँ कार्यरत थीं। पहली शक्ति यातायात एवं संचार साधनों के तरीकों में हुए भारी सुधार के रूप में सामने आयी—पहला एटलांटिक महासागरीय तार केबल (Cable) 1866 में काम करने लगा तथा पहली अन्तर-उपमहाद्वीपीय रेल (Transcontinental Railway) 1869 में पूरी हुई। स्वेज नहर भी 1869 में ही यातायात के लिए खुल गई। दूसरा तत्त्व, जिसने विदेश व्यापार को बढ़ावा दिया, औद्योगीकरण की तीव्रगति थी।

चूँकि 1873-96 का काल गिरते हुए मूल्यों का काल रहा इसलिए इस बीच हुए विदेश व्यापार की भौतिक मात्रा (physical volume) तो काफी बढ़ी किन्तु डॉलर के रूप में आंकड़े थोड़ी गति से बढ़े। 1896-1914 की अवधि में मूल्य स्तर में तीव्रगति से वृद्धि हुई। उसके बाद प्रथम महायुद्ध के दौरान विदेश व्यापार में असाधारण वृद्धियाँ हुईं। 1915-20 की अवधि में अर्द्ध-निर्मित वस्तुओं व तैयार निर्मित वस्तुओं का कुल निर्यात व्यापार में आधा भाग हो चुका था।

विदेश व्यापार—निर्यात व आयात का मूल्य . 1860-1920

(मिलियन डॉलर में)

वर्ष	निर्यात	आयात	सन्तुलन
1860	334	354	- 20
1870	393	436	- 43
1892	836	663	+ 169
1890	858	789	+ 69
1900	1,394	850	+ 545
1910	1,745	1,557	+ 188
1914	2,365	1,894	+ 471
1918	6,149	3,031	+ 3,118
1920	8,228	5,278	+ 2,950

Source Historical Statistics of the US

इस अवधि की तटकर नीतियाँ (tariff policies) संरक्षणवादी (protectionist) स्वभाव की थीं। 1861 में अधिकतम अमरीकी तटकर 24% में ज्यादा नहीं

थे तथा उनका औसत 20% के लगभग आता था। 1864 तक यह औसत बढ़कर 47% हो गया था। गृह-युद्ध ने तटकरों की दरों में अत्यधिक वृद्धि कर दी थी। 1890 के मैकिनले तटकर (McKinley Tariff) ने इस स्तर को बढ़ाकर 50% कर दिया। 1897 में पारित डिंगले विधेयक (Dingley Act) द्वारा ये शुल्क बढ़कर 60% हो गये। 1897-1914 के सामान्य समृद्धि के काल में तटकरों की इस ऊँची दर को उचित ठहराया गया। किन्तु 1913 में प्रस्तुत अण्डरवुड-सिम्म्स विधेयक (Underwood Simmons Bill) ने इन तटकरों को सशोधित किया। इसके परिणामस्वरूप तटकरों का ढाँचा अधिक आसान बन गया। 1920 में तटकरों की औसत दर को घटाकर 25% पर ले आया गया।

1920 के बाद अमरीकी विदेश व्यापार व तटकर

प्रथम महायुद्धोत्तर काल के 8 अरब डॉलर के स्तर से घटकर 1930 की महान् मन्दी के दौरान निर्यात 2 अरब डॉलर पर आ पहुँचे थे। निर्यात माल के निर्यात जो 1920 में 4 अरब डॉलर के लगभग रहे थे, महान् मन्दी के वर्षों में शून्य हो चुके थे।

1920 से लेकर 1933 तक भुगतान सन्तुलन अमरीका के पक्ष में रहा। अमरीका के खाते में लगभग 16 अरब डॉलर का अतिरिक्त जमा था। किन्तु महान् मन्दी के वर्षों में निर्यात काफी घट गये और उसके कारण भुगतान सन्तुलन पर भी कुछ विपरीत प्रभाव पड़ा। उधर 1941-45 की द्वितीय महायुद्ध की अवधि में विशाल जमा राशि का भण्डार 40 अरब डॉलर के यूरोपीय देशों को किये गये एक-पक्षीय हस्तांतरणों (unilateral transfers) के कारण समाप्त हो गया। 1946 से 1949 के बीच जबकि पश्चिमी यूरोप के पुनर्निर्माण के लिए औद्योगिक वस्तुओं की आपूर्ति करने वाला अमरीका एकमात्र राष्ट्र था, उसका भुगतान सन्तुलन अतिरिक्त 2 अरब डॉलर वार्षिक का रहा। फिर 1950 से 1955 के बीच विशाल पैमाने पर प्रदान की गई सहायता के कारण अमरीका को इन वर्षों में औसतन 1,500 मिलियन डॉलर वार्षिक का घाटा रहा। समय निकलने के साथ यह घाटा और भी बढ़ता चला गया। 1962 व 1963 में तो घाटा इतना बढ़ चुका था कि वह चिन्ता का विषय बन गया।

अमरीका की भुगतान सन्तुलन स्थिति . 1946-1961

(मिलियन डॉलर में)

वर्ष	वित्तुद्ध भुगतान स्थिति
1946	+1,926
1950	-3,602
1954	-1,516
1956	-986
1958	-3,477
1960	-3,800
1961	-2,454

निष्कर्ष रूप में 1949-61 की अवधि में अमरीका का कुल भुगतान सन्तुलन का घाटा 23 अरब डॉलर रहा। किन्तु इससे विशेष चिन्ता इसलिये नहीं हुई क्योंकि अमरीका के पास स्वर्ण का विपुल भण्डार था तथा अल्पकालिक डॉलर परिसम्पत (short-term dollar assets) भी काफी थे। स्वर्ण परिसम्पत का मूल्य 16 अरब डॉलर था जबकि अल्पकालिक डॉलर परिसम्पत भी 1963 में 15 अरब डॉलर के थे। इस तरह 1963 में भी अमरीका के पास स्वतन्त्र विश्व (Free World) के कुल मौद्रिक स्वर्ण का 40% भण्डार था। इसके अतिरिक्त उसकी अन्तर्राष्ट्रीय लेनदारियाँ भी 27 अरब डॉलर के लगभग थी।

तटकर (Tariffs)

प्रथम विश्व-युद्ध के बाद 'शिशु उद्योगों' (infant industries) के एक समूह ने पुनः एक बार तटकर शुल्क बढ़ाने की माग की। पोंड्रेने मकम्बर तटकर विधेयक (Fordney-McCumber Tariff) जो 1922 में लाया गया, ने तटकरों को बढ़ाकर उनका औसत स्तर 33% कर दिया। 1929 में यह अनुभव किया गया कि तटकरों को ऊँचा रखकर गम्भीर मन्दी से बचा जा सकता है। कांग्रेस ने हॉले-स्मूट तटकर विधेयक (Hawley-Smoot Tariff) 1930 में पारित किया जिसमें तटकरों का औसत स्तर बढ़ाकर 40% कर दिया गया। बाद में कई लोगों ने यही मत व्यक्त किया कि महान् मन्दी के दौरान तटकरों में की गई इस वृद्धि ने सकट को और गहरा कर दिया था।

1934 में एक परस्पर व्यापार समझौता विधेयक (Reciprocal Trade Agreements Act) पारित किया गया जिसमें राष्ट्रपति को तीन वर्ष के लिए यह अधिकार प्रदान किया कि वे अन्य देशों के साथ ऐसे व्यापारिक समझौते कर सकते थे जिनमें 'तटकर रियायतें परस्पर स्वीकृत' करने की व्यवस्थाएँ होती। विधेयक का नवीनीकरण किया जाता रहा तथा 1934 से 1945 के मध्य 29 देशों के साथ इस प्रकार के पारस्परिक समझौते किये गये। 1945 में जब 1934 के विधेयक को नवीनीकरण के लिए लाया गया तो राष्ट्रपति के तटकर में रियायत दे सकने के अधिकारों में और वृद्धि कर दी गई। रैंडल आयोग (Randall Commission) ने 1954 में सूचित किया कि 1945 का घरेलू व्यापार को उदार बनाने की प्रक्रिया के इतिहास में, जोकि 1934 में आरम्भ की गयी थी, एक महत्वपूर्ण बिन्दु कहा जा सकता है। उसके बाद जो भी संशोधन हुए उनसे राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि के स्थान पर प्रतिबन्ध ही अधिक लगे हैं।'

बहुपक्षीय अनुबन्धों (Multilateral negotiations) की बढ़ती हुई आवश्यकता को देखते हुए अमरीका ने एक बहुपक्षीय व्यापार सन्धा गठित करने का प्रस्ताव किया। 1947 में व्यापार व तटकर पर एक सामान्य समझौता (G.A.T.T.) किया गया जिसका उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना था। अमरीका ने अपने तटकरों में 1960 में इस नई व्यवस्था के अन्तर्गत लगभग 12% की कटौती की।

अमरीकी विदेश व्यापार की वर्तमान स्थिति

द्वितीय महायुद्ध के बाद के वर्षों में तो अमरीकी विदेश व्यापार की वृद्धि असाधारण रूप से तीव्र रही है। वह विश्व में पहले स्थान पर पहुँच चुका है तथा उसके निकटतम प्रतिद्वन्दी उससे बहुत पीछे छूट चुके हैं। पूँजीवादी गुट में उसे नेतृत्व प्राप्त हो चुका है। ओलिवर कोक्स के अनुसार, 'पूँजीवादी व्यवस्था में नेतृत्व का अर्थ है विश्व के विदेश व्यापार में प्रभुत्व की स्थापना।'¹ जो नेतृत्व ग्रहण करता है वह अपनी घरेलू आवश्यकताएँ, तथा अन्य लोगों की आवश्यकताएँ दोनों ही पूरी करता है। वह विश्व के अन्य अर्थव्यवस्थाओं को अपने तैयार माल व सेवाओं पर आश्रित करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। इसके कारण नेतृत्व वाले देश के लिए कुछ आवश्यक आयात (critical imports) भी करने जरूरी हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में, जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था परिपक्व होती है उसकी अधिकाधिक निर्मित वस्तुएँ निर्यात के लिए उपयोग में आने लगती हैं और इसीलिए आयात भी सापेक्ष रूप से बढ़ जाते हैं। 'हालांकि ऐसा लगता है कि संयुक्त राज्य अमरीका अपने विदेश व्यापार पर कम आश्रित है क्योंकि उसके कुल राष्ट्रीय उत्पाद का आकार बहुत बड़ा है किन्तु इसके उपरान्त वह विश्व का सबसे बड़ा विदेश व्यापार वाला राष्ट्र है।'

अमरीका का विदेश व्यापार : 1976-77

(मिलियन डॉलर में)

	1976	1977
निर्यातों का मूल्य	1,14,992	1,21,242
आयातों का मूल्य	1 20 678	1 47,671

क्षेत्रवार अमरीकी विदेश व्यापार

(मिलियन डॉलर में)

देश	निर्यात		आयात	
	1976	1977	1976	1977
अफ्रीका	5,206	5,546	12,644	17,024
एशिया	29,728	31,429	39,367	49,422
ऑस्ट्रेलिया व ओपेनिया	2,690	2,877	1,671	1,720
उत्तरी उत्तर अमरीका	24,111	25,752	26,247	29,375
दक्षिणी उत्तर अमरीका	8,368	8,661	9,349	11,591
दक्षिणी अमरीका	8 595	9,275	7,761	9,343

वस्तुवार (Commodity-wise) आयात-निर्यात

(मिलियन डॉलर में)

	निर्यात		आयात	
	1976	1977	1976	1977
कुल, सैनिक अनुदान निकाल देने के बाद	1,13,128	1,17,900	1,20,678	1,47,671
कृषि पदार्थ, कुल	22,997	23,671	11,179	13,538
गैर-कृषि पदार्थ, कुल	90,321	94,222	1,09,510	1,33,278

Source Survey of Current Business

नवा अध्याय

वर्तमान अमरीकी अर्थव्यवस्था, 1985 के लिए अनुमान

(AMERICAN ECONOMY TODAY, OUTLOOK TO 1985)

1978 में अपनी 210 मिलियन की जनसंख्या के साथ अमरीका में विश्व जनसंख्या का केवल 5.5% भाग बसता है तथा विश्व की भूमिका 6% क्षेत्रफल उसके पास है किन्तु विश्व उत्पादन का 25% अमरीका में उत्पादित होता है। देश का कुल राष्ट्रीय उत्पाद (G N P) 1.3 मिलियन-मिलियन डॉलर (\$ 1.3 million-million) के बराबर है। यह महान् स्थिति दो शताब्दियों के अन्तराल में प्राप्त की गयी है।¹

स्वतन्त्र उद्यम अर्थव्यवस्था (Free Enterprise Economy)

अमरीकी अर्थव्यवस्था स्वतन्त्र उद्यम प्रणाली पर आधारित है जिसमें व्यक्ति व निगम बाजारों तथा लाभों के लिए खुले रूप में प्रतिस्पर्धा करते हैं। निजी क्षेत्र का राष्ट्रीय उत्पाद (G N P) 75% भाग है तथा शेष 25% भाग सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा पूरा किया जाता है। इसके अलावा आर्थिक नीति निर्धारण में सरकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वह आर्थिक लक्ष्यों को तय करने तथा आधार क्षेत्रों का विनियमन करने में सहायता करती है। 1930 के बाद से ही उसकी यह भूमिका और अधिक व्यापक बन गई जबकि महान् मन्दी के दुरुचक को तोड़ने के लिए सरकारी हस्तक्षेप अनिवार्य बन चुका था। इतना ही नहीं, 1890 में शर्मन न्यास-विरोधी कानून (Sherman Anti-Trust Act) गठबन्धनों को न पनपने देने के उद्देश्य से पारित कर सरकार ने आर्थिक नीति निर्धारण के क्षेत्र में अपना पहला बड़ा कदम रखा था।

राष्ट्रीय सकट के समय में जैसे युद्ध या भारी उतार-चढ़ावों (severe fluctuations), जो आर्थिक-चक्रों के परिणामस्वरूप उत्पन्न होते हैं, के समय में सघीय सरकार को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से नियन्त्रण कर सकने व जब तक आर्थिक सन्तुलन पुनः स्थापित न हो जाए जब तक बाजार शक्तियों पर प्रतिबन्ध लगाने का अधिकार है। द्वितीय महायुद्ध के दौरान, उदाहरण के लिए, सरकार ने

¹ Facts About America, USIS

मजदूरी व मूल्यों के उतार-चढ़ावों पर व्यापक नियन्त्रण लगाए थे। ऐसा मुद्रा स्थिति का दृढ़ता से मुकाबला करने के उद्देश्य से किया गया था। सरकारी शस्त्रागार के अन्य हथियारों में सरकार द्वारा किये जाने वाले खर्च व लगाए जाने वाले करो से पड़ने वाला भारी प्रभाव, देश में भुगतान सन्तुलन का स्थिति में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से अमरीकी पूँजी के विदेशों में ले जाने पर रोक, व्यापार सन्तुलन को प्रभावित करने के ध्येय से तटकर व गैर-तटकर बाधाएँ लगाना तथा मुद्रा की पूँति को सीमित करने के उद्देश्य से मौद्रिक व साख सम्बन्धी नियन्त्रण लगाना प्रमुख है।

आय का वितरण

इस तथ्य की प्रशंसा की जानी चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की शक्तियों ने भी अमरीका में राष्ट्रीय आय का असाधारण रूप से समान वितरण (egalitarian distribution) करने में सफलता प्राप्त की है। राष्ट्र की 85% आय स्वामित्व आय (proprietor's income), मजदूरी, वेतन तथा सामाजिक लाभों जैसे सामाजिक सुरक्षा भुगतानों, पेन्शनों तथा अन्य कल्याणकारी भुगतानों के रूप में है। शेष 15% राष्ट्रीय आय लगानों, मुनाफों तथा ब्याज के रूप में है। यह 15% का आंकड़ा भी धोखा देने वाला है क्योंकि बड़े-से-बड़े अमरीकी निगम जैसे जनरल मोटर्स तथा अमेरिकन टेलीफोन एण्ड टेलीग्राफ कम्पनी की भी शेयर पूँजी अधिकांश साधारण आय वाले मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों की ही है।

विशालकाय निगमों के विकास के साथ, जिनके कि हाथों में विशाल आर्थिक सत्ता केन्द्रित है, विशाल धन ग्रुपिंगों का भी विकास होता चला गया है जिनकी मदद से सन्ध्या लाखों करोड़ों में है। देश की 90 मिलियन की कुल धन शक्ति का पाँचवाँ हिस्सा (अर्थात् 18 मिलियन) इन धन ग्रुपों का सदस्य है। किन्तु विशालकाय व्यावसायिक निगमों व धन ग्रुपों दोनों ही की शक्ति पर सघीय सरकार की उपस्थिति से उस सीमा तक प्रतिबन्ध लगा रहता है जिस सीमा तक सघीय सरकार अपने विनियमन सम्बन्धी अधिकारों का प्रयोग करती है। पिछले कुछ वर्षों से इन तीनों ही शक्ति केन्द्रों ने एक चौथे शक्ति समूह का प्रभाव अनुभव किया है—वह समूह है उपभोक्ता—जो अब भी ढीले मगठना में बंधे हैं किन्तु तेजी के साथ इस तरह संप्रतिष्ठित होते जा रहे हैं कि जिससे वे आर्थिक निगमों की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकें।

अपनी विशाल समृद्धि तकनीकी विकास की उच्च अवस्था तथा विशाल उत्पादन क्षमता के उपरान्त समुक्त राज्य अमरीका के सामने आज दैर्घी कुछ समस्याएँ उपस्थित हैं जैसी कि अन्य देशों के सम्मुख होती हैं। गरीबी के छोटे-छोटे द्वीप अभी भी समृद्धि के महासमुद्र में कायम है। 1971 के बाद बेकारी बराबर बढ़ रही है तथा वह 6 से 8% के मध्य रही है। पर्याप्त कोषों के अभाव में शहरी समस्याएँ विकट बननी जा रही हैं। इससे यही संकेत मिलता है कि अमरीकी अर्थव्यवस्था के सामने अभी कुछ मजिदों और भी है।

ससाधन

अमरीकी अर्थव्यवस्था की मुहट नीव उसकी विशाल उपजाऊ कृषि भूमि, उसके व्यापक खनिज भण्डार, उसके विपुल जल साधनो, उसके वनो तथा उसके मुहावने शीतोष्ण (temperate) जलवायु पर टिकी हुई है।

हालांकि हर चार अमरीकियों में से तीन शहरों में रह रहे हैं किन्तु फिर भी खुली जगह की कमी नहीं है। 200 मिलियन हेक्टेयर में भी अधिक क्षेत्रफल वाले व्यावसायिक वन जो देश में हैं उनमें से तीन-चौथाई देश के पूर्वी भाग में स्थित हैं। इसके उपरान्त भी अमरीका वन-उत्पादो की दृष्टि से आत्म-निर्भर नहीं है। वह भारी मात्रा में कागज बनाने की लुग्दी (pulp wood) कनाडा से तथा कुछ विशेष प्रकार की लकड़ियों की सीमित मात्रा अन्य देशों से आयात करता है। देश के अनेक भागों में वन लगाने के विशाल कार्यक्रम प्रगति पर हैं। किन्तु तथाकथित धनाभाव की इस स्थिति के उपरान्त अमरीका में 155 सरकारी संरक्षण वाले विशाल राष्ट्रीय वन हैं जो 75 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर फैले हुए हैं।

समुक्त राज्य अमरीका सभी खनिज ससाधनों में आत्मनिर्भर तो नहीं है किन्तु कुछ जरूरी साधनों में देश प्रारम्भ से ही आत्मनिर्भर रहा है। उसके पास लोहे का विपुल भण्डार है तथा 1974 के एक अनुमान के अनुसार उसके पास विश्व के कुल कोयला भण्डारों का एक-चौथाई भाग मौजूद था। ये दोनों खनिज पदार्थ मिलकर देश के आधारभूत उद्योग 'इस्पात' की गेट की हड्डी बने हुए हैं और यही उद्योग अमरीकी समृद्धि की कुजी रहा है। अन्य खनिज साधन जो बहुतायत में उपलब्ध हैं उनमें तँबा, जस्ता, मोसा, मोना व चांदी प्रमुख हैं। नवीनतम आँकड़ों के अनुसार थोड़े ही समय पहले तक अमरीका सम्पूर्ण विश्व के खनिज तेल का 50% उत्पादन कर रहा था। वहाँ 3,000 मिलियन बैरल (Barrel) प्राकृतिक तेल व 600 मिलियन बैरल प्राकृतिक गैस प्रति वर्ष निकाले जा रहे हैं।

किन्तु ऊर्जा के लिए बटती हुई औद्योगिक माग ने अमरीका को ईंधन के लिए अन्य देशों पर आश्रित बना दिया है। हालांकि अमरीका की लोहा खानों से प्रति वर्ष 90 मिलियन टन कच्चा लोहा हर वर्ष निकाला जाता है फिर भी अमरीका प्रति वर्ष वेनेजुएला व कनाडा से 40 मिलियन टन कच्चे लोहे का आयात करता है। इसी तरह पेट्रोलियम के लिए बटती हुई माग के कारण 1980 तक अमरीका को अपने कुल उपयोग का 35% तेल आयात करना पड़ सकता है।

आधुनिक कृषि

अमरीकी खेत हर वर्ष 90,000 मिलियन डॉलर मूल्य से भी अधिक के कृषि पदार्थों का उत्पादन करते हैं। अमरीका विश्व का आधे से भी अधिक सोयाबीन व मक्का का उत्पादन करता है। वह अण्डो, मुंगियों के विश्व उत्पादन का एक-तिहाई, चनो व क्पास का 1/5, तम्बाकू का 1/6, तथा गेहूँ के विश्व उत्पादन का 12% अपने यहाँ पैदा करता है।

अमरीका का अधिनाश कृषि उत्पादन निर्यात किया जाता है। अमरीका में उगाई जाने वाली एक-चौथाई फसलें निर्यात के लिए होती हैं। देश की सूखे मटर की 60% फसल, चावल व मोयावीन का 50% व लगभग यही प्रतिशत गेहूँ व वपास का भी निर्यात कर दिये जाते हैं। इसके बावजूद अमरीका को कई कृषि पदार्थों का आयात करना पड़ता है। गेट ब्रिटेन व पश्चिमी जर्मनी के बाद अमरीका विश्व का तीसरे नम्बर का सबसे बड़ा कृषि पदार्थों का आयातक देश है। उसके आयातों में प्रमुख पदार्थ चीनी, मास, वनस्पति तेल, कॉफी, रबड़, कोकोआ, केले तथा चाय हैं।

संयुक्त राज्य अमरीका की कुल भूमि का आधा भाग वहाँ के खेत घेरे हुए है। लगभग 130 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर फसल बोई जाती है। स्थायी चरागाहों तथा वनों द्वारा 560 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र घिरा है। आज देश की कृषि जनसंख्या कुल जनसंख्या का 5% से भी कम है जबकि 1935 में वह 25.5% थी। किन्तु जहाँ पहले एक किसान 10 व्यक्तियों का पेट भरने जैसा अनाज उगा पाता था, आज एक किसान 45 व्यक्तियों के लिए पर्याप्त अनाज उगा रहा है।

उत्पादकता में यह विशाल वृद्धि अमरीका में हुई कृषि-क्रांति का परिणाम है। पिछले सौ सालों में कृषि क्षेत्र में रासायनिक खादों, बीजों, कीटाणुनाशक दवाओं, मशीनों तथा फसलों व पशुओं के बारे में जानकारी की दिशा में निरन्तर प्रगति होती रही है। 10 लाख से अधिक हारवेस्टर कम्बाइन (Harvester Combines) तथा 50 लाख से भी अधिक ट्रैक्टर काम में आ रहे हैं। 16 मिलियन हेक्टेयर भूमि सिंचित है। इसके अलावा अमरीका अपनी कृषि सम्बन्धी जानकारी में अन्य देशों को सहभागी बनाये हुए है। उसने मेक्सिको, भारत फिलिपाइन्स तथा अफ्रीका जैसे देशों में गेहूँ, चावल व मक्का अनुसन्धान केन्द्र स्थापित किये हैं। रॉकफेलर फाउण्डेशन में कार्यरत कृषि वैज्ञानिक डॉ॰ नॉर्मन बॉरलॉग (Norman Borlaug) को मेक्सिको में उनके 'चमत्कारी गेहूँ-बीजों' पर किये गये अनुसंधान के लिए नोबेल शान्ति पुरस्कार दिया गया था।

अमरीका विश्व के मछली पकड़ने वाले देशों में पाँचवें स्थान पर है तथा उसका वार्षिक मछली उत्पादन 2 से 3 मिलियन टन का है। यह अनुमान है कि 1,35,000 अमरीकी मछली पकड़ने के काम में लगे हुए हैं। तथा वे 90,000 मछली पकड़ने वाली बोटों (Boats) का उपयोग करके प्रति वर्ष 2,000 मिलियन डॉलर मूल्य की मछलियाँ पकड़ते हैं।

अमरीकी निर्मित माल उद्योग (U S Manufacturing)

अमरीका निर्मित माल उद्योग में विश्व में अग्रणी राष्ट्र है। अमरीका की कुल राष्ट्रीय आय में एक चौथाई से भी अधिक भाग निर्मित माल उद्योग का है। निर्मित माल उद्योग में सर्वाधिक रोजगार भी मिला हुआ है। इसमें 20 मिलियन लोग लगे हुए हैं। निर्मित माल उद्योग द्वारा प्रति वर्ष 3,50,000 मिलियन डॉलर मूल्य की वृद्धि (value addition) की जाती है।

अकेली सबसे बड़ी निर्मित माल उद्योग शाखा यातायात उपकरण बनाने की है। परम्परागत रूप से अमरीका मोटर वाहनो का सबसे बड़ा उत्पादक देश रहा है। हालांकि अब जापान तथा पश्चिमी जर्मनी से उसे चुनौती दी जा रही है। अन्य प्रमुख उद्योगो में खाद्य-पदार्थ, रसायन, वस्त्र-निर्माण, प्रमुख धातुएँ, मशीनें तथा विद्युत साज-सामान वाले उद्योग सम्मिलित हैं।

औद्योगिक गतिविधियों का प्रकार बराबर बदल रहा है। अमरीकी उद्योग प्रति वर्ष अनुसंधान पर 12,000 मिलियन डॉलर में भी अधिक खर्च करते हैं ताकि नये उत्पादों व तकनीकों का विकास हो। अमरीका में 11,000 से भी अधिक अनुसंधान फर्म हैं जिनमें 3,60,000 वैज्ञानिक व इंजीनियर कार्यरत हैं। उनके इस कार्य में विश्वविद्यालय, सरकारी विभाग तथा निजी न्याम (Private Foundations) सहायता करते हैं। 1960 के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में आई तेजी के कारण हजारों नये प्लांट तथा उत्पादन शाखाएँ खुल चुकी हैं।

अमरीकी विदेश व्यापार व भुगतान सन्तुलन

1971 तक अमरीका में परम्परागत रूप से दोष विद्व के सन्दर्भ में अनुकूल व्यापार की स्थिति बनी रही। अमरीका में बनी हुई पूँजीगत वस्तुओं ने ही द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद ध्वस्त योरोपीय देशों की अर्थव्यवस्थाओं को पुनः सही दिशा दी तथा जापान के चकाचौंध करने वाले विकास में सहायता प्रदान की। किन्तु 1960 के दशक के अन्तिम वर्षों में यह व्यापार सन्तुलन सिकुड़ने लगा तथा अमरीकी आयातों में उसके निर्यातों की तुलना में अधिक तीव्र गति से वृद्धि होती हुई दिसाई पड़ने लगी। 1971 में अमरीका को इस सन्तुलन में पहली बार व्यापार सन्तुलन में घाटा उठाना पड़ा जो 2,700 मिलियन डॉलर रहा। 1972 में यह व्यापार घाटा बढ़कर 6,900 मिलियन डॉलर हो गया। 1973 में पुनः एक बार व्यापार सन्तुलन में 1,300 मिलियन डॉलर की वृद्धि रही। मगर 1974 में फिर एक बार व्यापार में 3,000 मिलियन डॉलर का घाटा रहा। यह मुख्य रूप से अमरीका द्वारा आयातित पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में तीव्र वृद्धि हो जाने के कारण हुआ। पेट्रोलियम पदार्थों के आयात पर व्यय की गई राशि 24,000 मिलियन डॉलर हो चुकी थी। 1974 में कुल मिलाकर भुगतान सन्तुलन का घाटा 8,000 मिलियन डॉलर का रहा जिसमें एक-तिहाई भाग व्यापारिक घाटे (Trade deficit) का था। अन्य घाटे की मदों में प्रतिरक्षा व विदेशी सहायता पर व्यय, पर्यटकों द्वारा खर्च तथा पूँजी का प्रवाह रहे।

निर्यात व्यापार में प्रमुख अमरीकी वस्तुएँ मशीनें (कम्प्यूटर जिनमें सम्मिलित हैं), कृषि पदार्थ, स्वचालित उत्पाद (automotive products), हवाई-जहाज तथा रसायन वस्तुएँ आदि हैं। पिछले कुछ समय में प्रमुख अमरीकी आयात पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पादों, स्वचालित वस्तुओं, खाद्य पदार्थों व पेय पदार्थों (कॉफी), मशीनों व लोहे व इस्पात की बनी चीजों के रहे। पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती हुई लागत की काफी मात्रा में क्षति पूर्ति अमरीकी कृषि पदार्थों के निर्यात मूल्य भी साथ

के साथ बढ़ जाने से हो गई है। यहाँ तक कि इस उद्देश्य के लिए अतिरिक्त कृषि भूमि पर खेती का कार्य शुरू कर दिया गया है।

लेकिन नाजुक भुगतान-सन्तुलन स्थिति, जो विश्व-मौद्रिक असन्तुलन के कारण और भी खराब हो गई थी, ने अगस्त 1971 में तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को डॉलर की स्वर्ण व परिवर्तनशीलता समाप्त घोषित करने के लिए बाध्य कर दिया। राष्ट्रपति निक्सन ने अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली में आमूल-चूल सुधार लाने के उद्देश्य से व्यापारिक सुधार व व्यापार को उदार बनाने की दिशा में प्रमुख उपाय करने का भी आह्वान किया। घरेलू स्तर पर भी बेकारी व मुद्रा-स्फीति की समस्या का मुकाबला करने के उद्देश्य से अस्थायी मूल्य व मजदूरी नियन्त्रण लागू किये गये।

बाद में किये गये कुछ समझौता द्वारा विश्व की प्रमुख मुद्राओं के बीच दिसम्बर 1971 में कुछ नये समीकरण स्थापित किये गये। डॉलर को दुबारा 1973 में अवमूल्यित किया गया (पहला अवमूल्यन 1971 में किया जा चुका था)। बाद में मुख्य औद्योगिक राष्ट्रों ने अपनी-अपनी मुद्राओं की विनिमय दर को बाजार शक्तियों पर छोड़ दिया ताकि वे तैरती हुई (Floating) रह सकें।

1971 के बाद अमरीका के सम्मुख आई इन गम्भीर समस्याओं के बावजूद यही प्रत्याशा है कि अमरीका अपने परम्परागत विकास-स्वरूप को प्राप्त कर लेगा। उसकी अर्थव्यवस्था में पुनर्जीवन व सक्रियता के चिह्न 1978-79 में देखे जा सकते हैं। अमरीका के लिए अपने आपको तेल-संकट के बाद भी इतनी जल्दी सभाल पाना इसलिए सम्भव हो पाया कि उसके पास अत्यधिक उच्च विस्म की तकनीक होने के अलावा खनिज तेल के विशाल भण्डार हैं। अन्य यूरोपीय औद्योगिक राष्ट्रों के मुकाबले आयातित तेल पर उनकी निर्भरता काफी कम है। इसके अलावा वह बढ़ती हुई विश्व खाद्य मांग से लाभ उठाने के लिए अपने खाद्य उत्पादन को विशाल मात्रा तक बढ़ा सकता है। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि डॉलर के दो बार अवमूल्यनों तथा जर्मन मार्क व जापानी येन के इस बीच हुए पुनर्मूल्यनों (Revaluations) ने भी अमरीकी निर्यातों को विश्व-बाजार में अपेक्षाकृत मजबूत बना दिया है।

इसके बावजूद अमरीकी अधिकारी यह महसूस करते हैं कि डॉलर का अवमूल्यन तथा तैरती हुई विनिमय दरें (Floating Exchange Rates) की वर्तमान व्यवस्था कोई स्थायी निदान नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा मौद्रिक-प्रणाली के लिए नये नियम बनाने होंगे ताकि विश्व-अर्थव्यवस्था को पुनः एक बार अधिक स्थायित्व एवं सन्तुलन प्रदान किया जा सके।

जनसंख्या एवं औसत वार्षिक वृद्धि दरें - 1965-74

	जनसंख्या (मिलियन में)	जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत में
अमरीका	211.9	1.7
चीन	809.2	2.3
रूस	252.1	1.0
जापान	109.7	1.2
भारत	595.5	2.3

कुल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय व विकास दरें 1974

	कुल राष्ट्रीय आय (G N P) मिलियन डॉलर में	प्रति व्यक्ति आय डॉलर में	विकास दरें % में
अमरीका	14,13 530	6 670	2.4
सोवियत रूस	5,98 640	2 380	3.4
इंग्लैण्ड	2 00 830	3 590	2.2
जापान	4 46 026	4 070	8.5

Source World Bank Atlas, 1976

1985 के लिए उत्पादकता सम्भावनाएँ

1947-66 में वार्षिक उत्पादकता वृद्धि दर का औसत 3.3% था जो 1966-73 की अवधि में घट कर 2.1% पर आ गया था। अब 1973-85 की अवधि में उत्पादकता वृद्धि दर का वार्षिक औसत 2.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। श्रम-सांख्यिकी ब्यूरो के अनुमानों के अनुसार निजी अर्थव्यवस्था में श्रम-उत्पादकता में 1973-80 के बीच 2.4% की वार्षिक वृद्धि होगी तथा 1980-85 के बीच यह वृद्धि दर 2.7% रहेगी।

उत्पादकता, जिसे सम्पूर्ण निजी क्षेत्र में लगे हुए लोगों के प्रति घण्टा उत्पादन से मापा जाता है, 1947 से 1973 तक 3% की दर से बढ़ी। मगर इस अवधि में भी पहले 19 वर्षों में बाद के 7 वर्षों की तुलना में उत्पादकता में अधिक तेजी से वृद्धि हुई। 1947 से 1966 तक उत्पादकता वृद्धि दर 3.2% थी किन्तु 1967 से 1973 के बीच यह 1.7% हो रही जो काफी गिरावट इंगित करती है। 1966 से 1976 के बीच उत्पादकता में वृद्धि 1.6% वार्षिक से हुई।

उत्पादकता में यह गिरावट अर्थव्यवस्था की औद्योगिक संरचना में आये परिवर्तनों के कारण आई है। भारी मात्रा में विनियोग प्रदूषण की रोकथाम (Pollution abatement) के कार्यक्रमों की तरफ मोड़ने पड़े हैं। पूँजी-श्रम अनुपात में धीमी वृद्धि हुई है तथा अनेक उद्योग परिपक्व (mature) हो चुके हैं व उनमें तकनीकी सुधारों की गुंजायश बहुत कम है।

जैसा कि पहले लिखा जा चुका है श्रम सांख्यिकी ब्यूरो ने 1973-80 व 1980-85 की इन दो अवधियों में श्रम-उत्पादकता वृद्धि के अनुमान क्रमशः 2.4% व 2.7% वार्षिक के लगाये हैं। ये दरें 1947-66 के बीच रही उत्पादकता वृद्धि दर से नीची हैं। 1980-85 के दौरान श्रम शक्ति की बदलती हुई संरचना से भी श्रम-उत्पादकता में सकारात्मक वृद्धि की प्रत्याशा है।

सोवियत संघ का आर्थिक विकास

पहला अध्याय

लाल क्रान्ति से पूर्व (PRIOR TO THE REVOLUTION)

रूस में आधुनिक आर्थिक विकास का युग 1861 में प्रारम्भ हुआ माना जा सकता है। रूस के जार (रूसी शासक की पदवी) अलेक्जेंडर द्वितीय ने अपने देश में कृषि दास-प्रथा (serfdom) को उसी वर्ष समाप्त किया था। इसी वर्ष एटलांटिक समुद्र के उस पार अमरीका दासता का उन्मूलन कर दिये जाने के प्रश्न पर गृह-युद्ध में फैला हुआ था। उस समय भी रूस एक बहुत फैला हुआ विद्याल देश था लेकिन राजनीतिक दृष्टि से वह पश्चिमी यूरोप से अलग-थलग बना हुआ था। वह एक सामन्तवादी राष्ट्र था जहाँ कि अधिकांश जनसंख्या घोर दरिद्रता की स्थिति में जी रही थी। केवल कुछ धनी लोग ही उच्च शिक्षा प्राप्त किये हुए थे जबकि सामान्य-जन साधारणतया निरक्षर थे। देश का तकनीकी-स्तर बहुत ही नीचा था। इसके बावजूद रूस तत्कालीन जापान से कुछ कम ही पिछड़ा हुआ देश था क्योंकि वहाँ एक बड़े आकार वाला सूती वस्त्र उद्योग विद्यमान था तथा वह उस समय के जापान की तरह एकाकीपन में जी रहे द्वितीय देश की भाँति भी नहीं था।

अठारहवीं सदी के आरम्भिक वर्षों में पीटर महान् (Peter the Great) ने रूस के आधुनिकीकरण के लिए कुछ प्रयास किये। इस कार्य के लिए अनेक विदेशी विशेषज्ञ रूस में राजकीय उद्योग चलाने के लिए बुलवाये गये। पूँजी की व्यवस्था की गई तथा लोगों की रुचियाँ पश्चिमी देशों की रुचियों के आधार पर बदली गई। लेकिन ये प्रयास कुशल साहमियों तथा पर्याप्त पृष्ठभूमि (infrastructure) के अभाव में अधिक फलदायी नहीं हो पाये। रूस में आर्थिक विकास की दर इंग्लैंड व फ्रांस की तुलना में नीची बनी रही। यहाँ तक कि रूस में खाद्यान्नों का उत्पादन भी 1860 में, उससे पाम मौजूद विद्याल भूखण्ड के उपरान्त उसकी बढ़ती हुई जनसंख्या की अपेक्षा कम दर से बढ़ रहा था। 1856 के क्रीमीयाई युद्ध (Crimean War) में रूस की पराजय ने वहाँ के शासकों को गहरा धक्का पहुँचाया तथा वे कुछ सुधारवादी उपाय करने के लिए बाध्य हो गये। किन्तु इन सुधारवादी प्रयत्नों ने पीछे वह प्रतिबद्धता (commitment) नहीं थी जिसने इसी अवधि में मेजी जापान (Meiji Japan) को प्रेरणा प्रदान की थी।

रूसी कृषि

कृषि करने की तकनीक रूस में पिछले कई सौ वर्षों में बिल्कुल नहीं बदली

थी। 80 प्रतिशत से भी अधिक जनसंख्या खेती पर आश्रित थी लेकिन कुल कृषि क्षेत्र देश के कुल भू-भाग का 25 प्रतिशत से भी कम था। अधिकांश किसान कृषि-दास (serfs) थे जो अपने मालिकों के लिए काम करते थे तथा जिन्हें भूमि के साथ ही खरीदा और बेचा जा सकता था। कृषि में पूंजी का प्रयोग बहुत ही थोड़ा था तथा कृषि उत्पादकता बहुत नीची थी।

1861 के सुधारों का उद्देश्य देश से कृषि-दास प्रथा (serfdom) का उन्मूलन करना था। किसानों को अब भूस्वामियों की निजी सम्पत्ति की तरह नहीं माना जाता था। इन लोगों को स्वतन्त्र भूखण्ड आवंटित किये जिनका मूल्य उन्हें 49 वर्ष तक फैली हुई किस्तों में चुकाना था। किन्तु इन सुधारों ने भी किसानों का कोई विशेष भला नहीं किया। जमीन के लिए निर्धारित मूल्य बाजार मूल्य से काफी ऊँचे थे। आवंटित भूखण्ड बहुत ही छोटे आकार का था। भूस्वामियों के पास अभी भी जमीन के बहुत बड़े-बड़े टुकड़े मौजूद थे। किसान लोग तो इतने निर्धन थे कि वे खेती के काम के लिए एक घोड़ा रखने या छोटी-बड़ी कृषि मशीनों व औजारों का किराया चुकाने में भी असमर्थ थे।

ये भूमि सुधार जाली अधिक और वास्तविक कम थे क्योंकि इनके द्वारा भूस्वामियों को यह चुनने की स्वतन्त्रता दी गई थी कि वे कितनी जमीन अपने पास रखना चाहते हैं। इसका नतीजा यह हुआ कि भूस्वामियों ने अपनी अधिकांश घटिया जमीन दे दी ताकि उन्हें उसके बदले में अच्छा मौद्रिक मुआवजा मिल सकता। अधिकांश उपजाऊ जमीन को उन्होंने अपने पास ही रख लिया जिस पर वे भाड़े के मजदूरों से खेती करवा सकते थे। समुदाय का कम्यून (commune) को प्रशासन, कर वसूली तथा नागरिक सुरक्षा के लिए एक इकाई माना गया। किसान लोग इन कम्यूनो से आसानी से अलग नहीं हो सकते थे। इस तरह कृषि-दास प्रथा (serfdom) को समाप्त कर देने से किसानों को जो सशकित स्वतन्त्रता दे दी गई थी वे उसका लाभ नहीं ले सकते थे और उनकी गतिशीलता प्रतिबन्धित ही बनी रही।

इन सुधारों के परिणामस्वरूप कृषक समुदाय पर भार और भी बढ़ गया। उन पर अपना बाजार अतिरेक (marketed surplus) बढ़ाने के लिए दबाव बढ़ गया। उनमें से अधिकांश के पास भूखण्ड इतने छोटे थे कि उनका गुजारा भी नहीं चलता था। जेतने विखरी हुई भी थी। मोर (Mir) या ग्राम कम्यून में फसलों के हेर-फेर (crop rotation) वाली उस मध्ययुगीन प्रथा को अपनाया जाता था जिसमें एक-तिहाई जमीन को हर बार परती (fallow) छोड़ दिया जाता। मोर में कुछ वर्षों बाद भूमि का पुन आवंटन करने की प्रथा भूमि में स्थायी सुधार करने के मार्ग में बाधक थी। इन सभी तत्वों ने मिलकर कृषि की कुशलता को काफी कम कर दिया था।

लेनिन ने 1861 के भूमि सुधारों का मूल्यांकन करते हुए यह सिद्ध किया कि उनसे उत्पादकता बढ़ाने में बाधा पहुँचती थी क्योंकि उनमें सामन्तवादी तत्व रहने दिया गया था। लेनिन ने माना कि रूसी अर्थव्यवस्था के आर्थिक विवास में सबसे बड़ी संस्थागत बाधा (institutional barrier) सामन्तवादी

प्रेषा ही थी। 1882 में स्थापित किसान बैंक (peasant bank) ने भी केवल सम्पन्न किसानों व भूस्वामियों की ही सहायता की जिससे उन्होंने बहुत सारी अतिरिक्त भूमि को अपनी निजी सम्पत्ति बना लिया। इसमें देश में भू-असमानता की स्थिति और भी विषम हो गई।

इस प्रकार इन भूमि-मुधारों से कृषक-वर्ग बहुत ही असन्तुष्ट रहा। 1905 में किये गये एक असफल विद्रोह के पीछे यही कारण रहा जिसके परिणामस्वरूप जापान के साथ युद्ध में रूस को बहुत ही अपमानजनक पराजय हुई। किसानों को शान्त करने के उद्देश्य से 1906 में जार के प्रधानमंत्री स्टोलिपिन (Stolypin) ने कुछ और कृषि मुधारों की घोषणा की। मीर (Mir) के महत्त्व को बहुत कम कर दिया गया। भू-लगानों का भुगतान सामूहिक जिम्मेदारी न रखकर व्यक्तिगत उत्तरदायित्व बना दिया गया। कम्प्यूनों (Communes) में रह रहे किसानों को उनकी जमीनों का मालिक घोषित कर दिया गया। निधन किसानों को उनकी जमीन बेचने की अनुमति दी गई और वे भाड़े के मजदूर बन गये। कम्प्यून द्वारा अपने सदस्यों के आवागमन को प्रतिबन्धित करने का अधिकार समाप्त कर दिया गया।

स्टोलिपिन (Stolypin) मुधारों की आरम्भिक प्रतिक्रिया बड़ी उत्साहवर्द्धक रही। 1907 से 1916 के बीच लगभग 25 लाख किसान अपने कम्प्यून छोड़ गये तथा उन्होंने 19 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर स्वामित्व प्राप्त किया। किसान बैंक (peasant bank) को भी अधिक सक्रिय बनाया गया तथा 1906 से 1915 के बीच उसने विभिन्न प्रकार के विक्रेताओं के लिए 7 मिलियन हेक्टेयर भूमि का बेचान किया। किन्तु इन मुधारों से भी समृद्ध कृषक अधिक लाभान्वित हुए जिन्होंने अपने खेतों का आकार बहुत बड़ा लिया। 1917 की लान क्रान्ति की पूर्व संध्या पर अभी भी लगभग 50 प्रतिशत कृषकों के पास मीर-प्रणाली (Mir system) के अन्तर्गत भूमि के छोटे और बिखरे हुए टुकड़े ही थे।

1913 तक की रूसी कृषि की उत्पादकता बहुत नीची थी। रेमण्ड गोल्डस्मिथ (Raymond Goldsmith) ने अनुमान लगाया है कि 1860 से 1913 के बीच रूस में फसलों के उत्पादन में वृद्धि की वार्षिक दर 2 प्रतिशत से भी कम रही। भूमि मुधार न केवल अपने मुख्य उद्देश्य—भूमिहीन लोगों में भूमि के पुनर्वितरण—में असफल सिद्ध हुए बल्कि उल्टे उन्होंने किसानों पर वित्तीय बोझ भी बढ़ा दिया। ये किसान अधिक बड़े निर्यात अतिरेक का उत्पादन करने के लिए बाध्य हो गये तथा उन्हें सरकार और भूस्वामी दोनों ही को अधिक राशि चुकानी पड़ी। इस तरह जार शासन वाले रूस में प्रतिव्यक्ति कृषि उत्पादन का स्तर कई अन्य देशों को तुलना में काफी नीचा रहा।

कृषक लोग दो बातें चाहते थे जिसे जार की सरकार (Tsarist government) दे पाने में असमर्थ थी। ये थी (1) भूमि का अधिक समान वितरण, तथा (2) भूस्वामियों का उन्मूलन। जैसा कि बैकोव (Baykov) ने लिखा है : 'प्रत्येक राजनीतिक दल, जिसे कि किसानों का समर्थन चाहिए था, को क्रान्ति पूर्व के रूस के अधिसंख्य किसानों को इस शाश्वत एवं आदिम अभिलाषा को पूर्ण करना था।' किन्तु

जब किसानों की इन दो आकांक्षाओं को पूरा नहीं किया जा सका तो सालोसाल किसानों के असन्तोष का गुब्बार बढ़ता चला गया। कृषकों की इस दयनीय दरिद्रता की स्थिति के माझीदार बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों में असह्य काम की दशाओं में काम करने वाले औद्योगिक श्रमिक भी थे। पोल (Poles) लोगों की राष्ट्रवादी भावों को कुचल जाने तथा यहूदियों को हैरान करने की प्रवृत्ति को बड़ावा मिलने से हालत और सराब हो गई। सरकार द्वारा चलाये जा रहे पुलिस राज से लोगों की इतनी घृणा हो चुकी थी कि बुद्धिजीवियों द्वारा उसके विरोध ने क्रान्तिकारी एवं आतंकवादी स्वरूप ले लिया।

उद्योगों की हालत

रूस में उद्योगों का विकास पीटर महान् (Peter the Great) की पश्चिमी प्रभाव वाली नीतियों के अन्तर्गत आरम्भ हुआ था किन्तु बाद के वर्षों की विकास दर बहुत धीमी रही। लेकिन इस कार्यक्रम की दो बातें महत्वपूर्ण रही। पहली, राज्य ने नये कारखाने खोलने व खानों चलायाने में पहल की, दूसरी, भारी उद्योग की स्थापना बहुत पहले कर ली गई। यूराल की खानों से लौह-भण्डार का शोषण पीटर महान् के शासन-काल में ही आरम्भ हो गया था। अठारहवीं सदी के मध्य तक तो रूस ब्रिटेन से भी अधिक लोहे का उत्पादन करने लगा था। विश्व के सबसे विशाल लोहा एवं ताँबा उत्पादक देश के रूप में उसे जाना जाने लगा। पीटर महान् की मृत्यु ने औद्योगिक विकास की इस गति को धीमा कर दिया। औद्योगिक गतिविधियों में उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में एक बार फिर से तेजी आयी। रुई कातने (cotton spinning) के क्षेत्र में ब्रिटिश तकनीक को अपनाया गया। देश में रेल लाइनें बिछाने के काम में तेजी लायी गयी। 1903 तक देश में 40 हजार मील लम्बी रेल लाइनें बिछा दी गई थी। इससे कोयला व लोहा उद्योग का द्रुत गति से विकास होने में सहायता मिली।

वर्ष	कोयला (मिलियन टन)	लौह-पिंड (मिलियन टन)
1867	27	17
1877	110	25
1887	277	37
1897	684	115
1902	1,005	159

जार के शासन-काल में रूस में हुए औद्योगिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि उसमें विनियोग भी विदेशियों द्वारा किया गया तथा उन्हें चलाया भी विदेशियों द्वारा गया। यह अनुमान है कि 1900 में रूस की समस्त पूँजी कम्पनियों में लगी हुई कुल पूँजी में आधी पूँजी विदेशियों की थी। ज्ञान में तो विदेशियों की पूँजी का यह अनुमान और भी ऊँचा था। रूस में रेलों का निर्माण भी मुख्यतः फ्रान्स, ग्रेट ब्रिटेन व बेल्जियम द्वारा ही करवाया गया था।

19वीं शताब्दी में रूस में लगाये गए अधिवास उद्योग डोनबास-डेनियर

(Donbas-Dnieper) क्षेत्र में हो केन्द्रित थे। कोयले का अधिकांश उत्खनन इसी क्षेत्र में होता था तथा देश का अधिकांश लोहा भी इसी क्षेत्र में गलाकर (smelting) तैयार किया जाता था। उन्नीसवीं शताब्दी में रूस में औद्योगिक संगठन के नाम पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण व आमानीय संस्था कुस्तर (Kustar) या गृह उद्योग (household industry) थे। इस उद्योग पर अधिकांशतः पूँजीपति या व्यापारी हावी थे। लगभग 85 प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में रहती थी तथा 10 प्रतिशत से भी कम (कुल कार्यशील जनसंख्या में से) लोग उद्योगों में काम पर लगे हुए थे। कुस्तर या गृह उद्योगों में लगे हुए लोगों की संख्या बड़े पैमाने पर चलाये जाने वाले लोगों की संख्या की तुलना में दुगुनी थी। जैसा कि मॉरिस डॉब (Maurice Dobb) ने लिखा है, 'रूस में पूँजीवाद का स्वरूप अब भी अत्यधिक आदिम क्रिसम का था' काम घरों पर काम करने वाले कारीगरों को या छोटे ठेकेदारों, जिनके पास बर्कें बाँप होते थे, को दिया जाता था और यह काम देने वाले पूँजीपति व्यापारी एवं निर्माता दोनों ही होते थे।'।

अपने अनुमानों में रेमण्ड गोल्डस्मिथ ने 1860 से लेकर 1913 तक की अवधि में रूस में औद्योगिक उत्पादन में विकास की दर 6 प्रतिशत वार्षिक के लगभग मानी है। लेकिन यहाँ यह बात महत्वपूर्ण है कि देश में औद्योगिक आधार काफी संकीर्ण (narrow industrial base) होने के कारण निरपेक्ष रूप में औद्योगिक विकास की यह दर काफी कम थी। यूरोप के विकसित देशों की तुलना में रूस बहुत पीछे था। उन्नीसवीं सदी के मध्य में विश्व के सबसे बड़े लोहा उत्पादक राष्ट्र होने की अपनी स्थिति से गिरकर वह आठवें स्थान पर आ चुका था। निरपेक्ष रूप में रूस का लौह-पिण्डों (pig iron) का उत्पादन इंग्लैंड के उत्पादन का दसवाँ भाग था।

कृषि-दास प्रथा (serfdom) का उन्मूलन निर्माताओं के लिए अत्यधिक लाभकारी रहा। 1870 में स्वतन्त्र किये जा चुके 40 लाख कृषि दासों के पास अपने हाथों को मजदूरी के बदले बेचने के बजाया कुछ भी नहीं था। निर्माताओं ने इन लोगों को अपने यहाँ मजदूरी के बदले रख लिया। भू-स्वामियों को भी जो मुआवजा मिला उसे उन्होंने संयुक्त पूँजी कंपनियों में लगा दिया। इस तरह संयुक्त पूँजी कंपनियों की संख्या, जो 1861 में केवल 78 थी, 1871 तक बढ़कर 357 हो गयी।

उन्नीसवीं सदी के अन्तिम वर्षों में रूस का औद्योगीकरण करने में रूस की जारसाही सरकार ने सक्रिय भूमिका निभाई। रेल लाइनों के निर्माण को प्रोत्साहित करने के इरादे से सरकार ने निजी निर्माताओं को अभिप्रेरणा (incentive) प्रदान करने, विदेशी पूँजी का गतिशील करने तथा कुछ स्थानों पर रेल लाइनों का स्वयं निर्माण करने जैसे कार्य किये। इन प्रयासों से रेल लाइनों की लम्बाई 1860 के 1,600 किलोमीटर से बढ़कर 1913 तक 78,000 किलोमीटर हो चुकी थी। ऐसा हो जाने से कोयला, लोहा व पैट्रोलिएम जैसे प्राकृतिक ससाधनों के विशेषज्ञ में काफी सहायता मिली। किन्तु औद्योगीकरण के इस सारे कार्यक्रम एक आलोचनात्मक पक्ष यह था कि इससे लिए वित्तीय साधन जुटाने का मारा बाण कृषकों पर

अप्रत्यक्ष करो का भार निरन्तर बढ़ाकर किया गया। सरकार ने तटकरो को बढ़ाकर सरक्षणवादी नीति भी अपनायी। यह नीति 1891 में अपनी चरम अवस्था तक पहुँच गई। 1904 में स्थिति यह थी कि निमित्त माल पर रूस में 131 प्रतिशत का आयात शुल्क लगा हुआ था जबकि जर्मनी में यह शुल्क 25 प्रतिशत, इटली में 27 प्रतिशत तथा अमरीका में 73 प्रतिशत था।

देश में अधिकाधिक विदेशी विनियोगकर्त्ताओं को आकर्षित करने के उद्देश्य से 1897 में स्वर्णमान अपनाया गया। 1890 के बाद देश में निजी विदेशी पूँजी की आवक (inflow) भी काफी रही। बीसवीं सदी के पहले दशक तक देश के कुल पूँजी-निर्माण में चौथाई भाग विदेशों से आने वाली पूँजी का हो चुका था। 1913 में रूस के विभिन्न उद्योगों में विदेशियों द्वारा किया गया कुल विनियोग 2 अरब रूबल मूल्य का था। इसके अतिरिक्त रूसी जारशाही सरकार ने विदेशी ऋण-दाताओं की गारण्टी पर 58 अरब रूबल के और ऋण भी विदेशों से ले रखे थे। इस तरह कुल मिलाकर प्रथम विश्व-युद्ध की पूर्व संध्या पर रूस पर 8 अरब रूबल का विदेशी ऋण-भार चढ़ा हुआ था।

रैमण्ड गोल्डस्मिथ ने अनुमान लगाया है कि 1870 से 1913 के बीच रूस का कुल राष्ट्रीय उत्पाद (G N P) लगभग 25 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ रहा था। प्रतिव्यक्ति आय में 1 प्रतिशत से कुछ कम की वृद्धि हो रही थी। ये आँकड़े इस बात को सिद्ध करते हैं कि हालाँकि 1917 की सात क्रान्ति से पहले रूस एक पिछड़ा हुआ देश था किन्तु उसकी अर्थव्यवस्था जड़ता (stagnation) की स्थिति में नहीं थी। उन वर्षों में रूस में जो पिछड़ापन रहा उसका यह अर्थ नहीं था कि वहाँ के उद्योग या कृषि में कोई परिवर्तन नहीं हो रहे थे। 1913 में रूस में खाद्यान्नों का उत्पादन 80 मिलियन टन के लगभग था। 1913 में भी रूस आर्थिक विकास के मार्ग पर पूँजीवादी तरीके से अग्रसर हो रहा था। कुछ लोग तो यह भी मानते हैं कि यदि 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रान्ति (Bolshevik Revolution) न हुई होती तो शायद रूस भी पूँजीवादी तरीके से विकास करते हुए आज तक पश्चिमी यूरोप के देशों की तरह हो गया होता। ऐसी स्थिति में रूस में औद्योगीकरण की शुरुआत करने का श्रेय बोल्शेविक क्रान्ति को देना सही नहीं होगा। क्रान्ति ने तो औद्योगीकरण की दिशा ही बदल दी और भूमि तथा सम्पत्ति के स्वामित्व में आक्रोश-पूर्ण परिवर्तन ला दिया।

1917 की क्रान्ति और यौद्धिक साम्यवाद

(THE 1917 REVOLUTION AND WAR COMMUNISM)

1913 से पहले आर्थिक विकास की जो धीमी गति रूसी अर्थव्यवस्था में चल रही थी उस पर प्रथम विश्व युद्ध ने यथायक रोक लगा दी। इस युद्ध ने रूस की अर्थव्यवस्था को इतनी हानि पहुँचायी कि उसके पुनरुद्धार में बाद में एक दशक का समय लग गया। युद्ध में एक के बाद एक पराजय ने रूसी अर्थव्यवस्था के खोलखोल को पोल खोलकर रख दी और रूसी सेना अपने आपको अच्छी सुरक्षा सेना नहीं सिद्ध कर पायी। सैनिक साज-सामान तथा अन्य प्रकार की युद्ध-सामग्री के अभाव को आक्रमणकारियों के सम्मुख अप्रशिक्षित 15 मिलियन लोगो को लड़ने के लिए झोंक-कर पूरा करने की चेष्टा की गई। ऐसा करने से कृषि तथा उद्योग में जन-शक्ति का अभाव हो गया। रूस पिछले कुछ वर्षों से जर्मनी पर अत्यधिक आश्रित हो गया था तथा उसके अविकास रासायनिक खादों की आपूर्ति, मशीनें तथा अन्य आवश्यक सामान जर्मनी से ही आयात होते थे। यह सब युद्ध होने से पहले तक चलता रहा था। अब प्रथम महायुद्ध ने रूस को उसी शक्तिशाली देश जर्मनी से लड़ने पर बाध्य कर दिया था। इस घटनाक्रम ने रूसी अर्थव्यवस्था पर अत्यधिक भार डाला।

प्रथम महायुद्ध के पहले कुछ वर्षों में रूसी सेना को काफी पराजयों का मुँह देखना पड़ा तथा उसने अपने कई पोलिश प्रान्त (Polish provinces) खो दिये जिनमें उसके अधिकांश उद्योग लगे हुए थे। पूरी यातायात व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गई। औद्योगिक उत्पादन में भारी गिरावट आयी तथा 1917 में वह 1913 की तुलना में काफी घट चुका था। कृषि उत्पादन में भी कमी आयी खाद्य पदार्थों व अन्य कृषि पदार्थों की भी बाजार में पूर्ति काफी घट गयी। ऐसा इसलिए भी हुआ कि युद्ध के वर्षों में पत्र-मुद्रा अपनी क्रय-शक्ति खो चुकी थी तथा किसान लोग अपनी चीजें ऐसी मुद्रा के बदले में बेचने के लिए तैयार नहीं थे जिसका मूल्य हर दिन घटता जा रहा था। इसका परिणाम यह रहा कि सहरी क्षेत्रों में खाने-पीने की चीजों का भारी अभाव हो गया।

युद्ध के दौरान व्यय की गयी अपार धनराशि ने देश में मुद्रा-स्फीति की अभूतपूर्व स्थिति उत्पन्न कर दी। 1915 में सरकारी व्यय बढ़कर 11 अरब रूबल हो चुका था जबकि उस वर्ष सरकार को होने वाली प्राप्तियाँ 3 अरब रूबल थीं। आय एवं व्यय के बीच इस भारी अन्तर को काफी मात्रा में नये नोट छापकर ही पूरा किया जा सकता था। 1917 में पत्र-मुद्रा की कुल पूर्ति बढ़कर 16 अरब रूबल

हो गई थी जो 1914 की पत्र-मुद्रा पूर्ति की तुलना में 10 गुना अधिक थी। उधर किसानों को जब ऐसा लगने लगा कि उन्हें उनकी चीजों के बदले निर्मित माल बराबर मिलती हुई विनिमय दर पर मिल रहा है तो उन्होंने शहरी बाजारों में अपना कृषिगत उत्पादन कम से कम लाना आरम्भ कर दिया। किसानों को तो अपने गावों में शहरी निर्मित चीजों की जगह अन्य प्रतिस्थापक वस्तुएँ उपलब्ध हो जाती थीं किन्तु शहरी जनसंख्या को तो खाद्य पदार्थ ही मिलने बन्द हो गये थे। नई फैक्ट्रियों को बन्द कर देना पड़ा क्योंकि न तो श्रमिक उपलब्ध थे और न ही चीजों की माँग। इस सबका एक स्वाभाविक परिणाम घनघोर बेकारी के रूप में सामने आया और यह बेकारी विशेषकर शहरों में फैली। हड़तालें और खाद्य सामग्री पाने के लिए दंगे (food riots) सामान्य बात हो गयीं। किसी भी क्रान्ति के लिए इससे अच्छा अवसर और क्या हो सकता था ?

और रूस के क्रान्तिकारी तत्त्वों ने निराश भी नहीं किया। वास्तव में 1917 में रूस के लोगों ने एक नहीं दो श्रान्तियाँ देखीं। पहली और कम प्रसिद्ध क्रान्ति, जिसका की पतन हो गया, उदारवादी मध्यवर्गीय (Bourgeois) लोगों के नेतृत्व में मार्च 1917 में हुई। जब जार ने अपनी गद्दी त्यागी तो उसके स्थान पर केरेन्स्की (Kerensky) के नेतृत्व वाली एक अस्थायी (provisional) सरकार गठित की गई। नई सरकार ने बिगड़ती जा रही स्थिति को हाथ से न निकलने देने की गरज से अनाज के व्यापार को राजकीय एकाधिकार (state monopoly) घोषित कर दिया तथा किसानों को इस बात के निर्देश दिये गये कि वे अपना सारा अतिरिक्त अनाज राज्य द्वारा स्थापित नये केन्द्रों पर ही बेचें। लेकिन यह उपाय बुरी तरह असफल हुआ क्योंकि केरेन्स्की की कमजोर सरकार उसे लागू नहीं कर पायी। यह सही ही कहा गया है कि केरेन्स्की की सरकार, जिसका वामपन्थी झुकाव भी था, शुरू से ही अन्त की ओर अग्रसर होने लग गयी थी। अराजकता के इन महीनों में एक नई शक्ति का अस्तित्व दिखाई पड़ने लगा था जो श्रमिक प्रतिनिधियों के बने हुए सोवियत (Soviets of Workers' Representatives) थे और जिनके प्रतिनिधि फैक्ट्रियों या अन्य पेशेवर लोगों में से चुने जाते थे। यही सोवियत (soviets) वास्तविक सरकार बन गये। जैसा कि मॉरिस डॉब ने लिखा है, 'उस गर्मी व सर्दी में किसान और मजदूर भूस्वामियों की जागीरों या फैक्ट्री के प्रबन्धकों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की याचिका लेकर यदि किसी के पास जाते थे तो वे वे स्थानीय सोवियतों (local soviets) ही थे।' यह एक प्रकार का द्वैध शासन था जो अधिक समय तक नहीं चल सकता था।

युद्ध से किसानों और मजदूरों को बराबर कठिनाइयाँ उठानी पड़ी थी। देश भुलमरी व छिन्न विच्छिन्न होने के कगार पर था। दृष्टक वर्ग भूस्वामियों से बुरी तरह तन आ चुका था और गामीण क्षेत्रों में किसान लोग उनके विरुद्ध बगावत में उठ खड़े हुए। उधर शहरों में औद्योगिक मजदूरों ने सामान्य जनजीवन पहले ही ठप्प कर रखा था। सेना यह सब असहाय होकर देख रही थी क्योंकि उस पर अप्रभावी नियन्त्रण था।

अराजकता की इस स्थिति के परिणामस्वरूप केरेस्की सरकार का तरता पलट दिया गया तथा लेनिन के नेतृत्व में 7 नवम्बर 1917 को बोल्शेविकों ने सत्ता अपने हाथों में ले ली। साम्यवादी दल (Communist Party)¹ एक छोटा किन्तु अनुशासित दल था तथा इसके अधिकांश सदस्य बुद्धिजीवी या औद्योगिक मजदूर थे। क्रान्ति होने के पहले अनेक मार्क्सवादी लेखकों को यह सन्देह था कि रूस जैसे पिछड़े हुए देश में समाजवादी क्रान्ति शायद कभी नहीं हो पायेगी। उन लोगों का मत था कि पहला चरण मध्यवर्गीय क्रान्ति से गुजरने का होता अनिवार्य था। इस बीच उन्हें प्रत्याशा थी कि समाजवादी क्रान्ति अपेक्षाकृत अधिक विकसित देशों में होगी जिन्हें वे ऐसी क्रान्ति के लिए अधिक परिपक्व मानते थे। लेकिन वास्तविक घटनाएँ इस तरह नहीं हुईं। बोल्शेविकों द्वारा सत्ता पर कब्जा करने में अर्थव्यवस्था एवं प्रशासन के छिन्न-भिन्न हो जाने, केरेस्की सरकार द्वारा स्थूलता से वाम लेने व भूमि-मुधार के मामले का निपटारा न कर पाने तथा अन्यायपूर्ण सन्धि करने जैसे कारणों ने सहायता की। लेनिन ने शान्ति और भूमि मुधार को बोल्शेविक क्रान्ति की मुख्य नीति घोषित करते हुए इस अवसर को हाथ से न निकलने दिया तथा उसने असन्तुष्ट किसानों, सैनिकों व मजदूरों का समर्थन प्राप्त कर लिया।

रूस में साम्यवादी क्रान्ति को सफल बनाकर लेनिन ने यह एक बात सिद्ध कर दी कि श्रमिकों व किसानों के नाम पर सत्ता पर अधिकार कर लेना सम्भव है चाहे उस देश में पूँजीवाद कितनी ही पिछड़ी हुई अवस्था में क्यों न हो। क्रान्ति सफलतापूर्वक सम्पन्न हो जाने के बाद लेनिन ने क्रान्तिकारों सरकार की स्थिति मजबूत करने के उद्देश्य से एक तीन सूत्री कार्यक्रम लागू करने की योजना बनायी। ये तीन चरण थे—(1) जर्मनी के साथ शान्ति स्थापित करना, (2) किसानों के साथ मंत्री का निर्वाह करना, तथा (3) सम्पूर्ण समाजवादी कार्यक्रम को धीरे-धीरे (एक साथ नहीं) लागू करना।

शान्ति स्थापित करने के प्रश्न पर साम्यवादी दल के भीतर ही मतभेद थे। पार्टियों के कई सदस्य सम्मानजनक शान्ति चाहते थे तथा वे साम्राज्यवादी जर्मनी के साथ किसी भी प्रकार की सन्धि के विरोधी थे। किन्तु लेनिन ने सारी स्थिति पर अधिक व्यावहारिक दृष्टि में विचार किया। उसने तर्क दिया कि सैनिक युद्ध से थक चुके थे तथा उन्होंने अपने 'पावों' से शान्ति के लिए मत दिया था, अर्थात् वे युद्ध-क्षेत्रों में भाग खड़े हुए थे। लेनिन का मत मान लिया गया तथा जर्मनी के साथ एक सन्धि पर हस्ताक्षर किये गये जिससे नई क्रान्तिकारी सरकार को एक नए सार्थक लेने का अवसर मिल गया।

कृषकों को राहत पहुँचाने की दृष्टि से नई सरकार ने एक आदेश (decree) जारी करके भूस्वामियों, चर्च और अन्य लोगों की जमीनों में भी जन्म भर ली और उसके लिए किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया गया। यह सारी जमीन तथा उसके साथ जुड़ी हुई सारी कृषि सम्पत्ति जिला भूमि समितियों के हाथों में सीधे सौंप दी जानी थी। सरकार की इस जमीन को हाथों-हाथ व्यक्तिगत किसानों या भूमिहीनों में वितरित

¹ A. Maddison, *Economic Growth in Japan and USSR*, 93.

कर देने की इच्छा नहीं थी किन्तु वास्तव में हुआ ऐसा ही। क्रान्ति का उफान ही कुछ ऐसा था कि जगह-जगह पर स्थानीय किसानों ने बड़े-बड़े खेतों पर जबरन अधिकार कर लिया तथा उसे आपस में बाँट लिया। यह काफी आदिम तरीका था। इससे भूमि का काफी उपविभाजन व अपखण्डन भी हुआ। जैसा कि बेकोव (Baykov) ने लिखा है, इन बड़ी-बड़ी जागीरों पर कब्जा जमाने में किसानों की जमींदारों के विरुद्ध सामाजिक शिकायतों ने उनके आर्थिक हितों से भी अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई क्योंकि किसानों ने कई जगह घरों को जला डाला या उन्हें तहस-नहस कर दिया। अधिकांश मामलों में इन परिसमाप्त (liquidated) जागीरों को सोवियतों (Soviets) के अधिकार-क्षेत्रों में हस्तान्तरित करने के स्थान पर बड़े ही अमानवीय तरीके से उन पर कब्जा जमाने के बाद व्यक्तिगत रूपको ने उसे आपस में बाँट लिया। लोगों द्वारा अपने मन से ही की गई इस जबनी (Confiscation) से काफी सम्पत्ति बरबाद कर दी गयी तथा जानवरों को मार डाला गया। राजनीतिक कारणों से, केन्द्रीय सोवियत सरकार इस सारी आदिम प्रक्रिया (primitive process) को मूक दर्शक बनकर देखती रही।'

प्रगामनिक तथा राजनीतिक कारणों से केन्द्रीय सोवियत सरकार ने इस बारे में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। उसके पास हस्तक्षेप करने के लिए पूरा ढाँचा ही नहीं था।

जहाँ तक उद्योगों पर नियन्त्रण का प्रश्न था, क्रान्ति के आरम्भिक महीनों में इस सम्बन्ध में सकट को बुलावा देने की चेष्टा नहीं की गई। किन्तु स्पष्ट रूप से सोवियत सत्ता का उद्देश्य उद्योग पर नियन्त्रण प्राप्त करना था। यह नियन्त्रण ऊपर तथा नीचे दोनों ही ओर से (from above and from below) प्राप्त किया जाना था। हालांकि उद्योगों को मई 1918 से पहले राष्ट्रीयकृत नहीं किया गया किन्तु कुछ व्यक्तिगत औद्योगिक इकाइयों को सोवियत प्रशासन ने अपने अधिकार में कर लिया। 14 नवम्बर 1917 के आदेश से श्रमिक समितियों को कारखानों का निरीक्षण एवं प्रबन्ध करने के अधिकार प्रदान कर दिये गये। दिसम्बर 1917 में 'वसेन्खा' (Vesenkha) का गठन किया गया जिसे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की सर्वोच्च परिषद् (Supreme Council of the National Economy) के नाम से जाना गया। इस अवधि में एक प्रकार से दोहरे शासन की भी नीवत आ गयी क्योंकि सोवियत सत्ता ने श्रमिकों को कारखानों का पूरा नियन्त्रण नहीं सौंपा था। उन कारखानों के मालिकों को भी कारखानों पर नियन्त्रण रखने तथा आदेश देने का अधिकार था। श्रमिकों की समितियों (Workers' Committees) को सारे उपक्रम पर नियन्त्रण कर लेने या उसे निर्देश देने के अधिकार नहीं दिये गये थे।

परिणाम यह हुआ कि पहले-पहल कुछ सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण उद्योगों का ही राष्ट्रीयकरण किया गया। अनाज के व्यापार पर राज्य का एकाधिकार जारी रखा गया। सरकार ने विदेश व्यापार पर भी अपना अधिकार बनाये रखा। जैसा कि बेकोव ने लिखा है, विदेश व्यापार पर सरकारी एकाधिकार बनाये रखने का उद्देश्य पुनः राजनीतिक था—इसका ध्येय था विदेशों से हो सकने वाले वित्तीय

हस्तक्षेप को रोकना ।

किन्तु यहाँ भी काफी भ्रामक स्थिति चलती रही । सोवियत सत्ता द्वारा स्पष्ट रूप से जारी किये गये निर्देशों के उपरान्त कई श्रमिक समितियों ने निजी कारखानों को एक तरह से जब्त कर लिया । श्रमिक नियन्त्रण आदेश (Decree of workers' control) द्वारा निर्धारित की गई उनकी सीमा से कई श्रमिक समितियाँ बाहर चली गयी । इसी तरह कई मालिकों ने इन आदेशों का विरोध किया और अपनी फैक्ट्रियाँ बन्द कर दी । इस प्रकार की गतिविधियों से मजदूर और भी क्रुद्ध हो गये तथा उन्होंने ऐसे उपक्रमों पर जबरन अधिकार जमा लिया । मॉरिस डॉब ने इस बारे में लिखा है कि 'यह क्रान्ति का प्रारम्भिक काल था जब अधिकांश बाले असमन्वित स्थानीय पहल द्वारा की गई " इस प्रकार की आरम्भिक प्रवृत्तियाँ वैसे देखा जाये तो नई सत्ता की शक्ति थी - लेकिन इन आरम्भिक प्रवृत्तियों का तात्कालिक प्रभाव गड़बड़ी लाने वाला था ।' ऐसा इसलिए हुआ कि फैक्ट्री समितियों को कारखाने चलाने का बिलकुल भी अनुभव नहीं था । इसके परिणामस्वरूप सारे उत्पादन के संगठन में अस्त-व्यस्तता आ गई । इसके अतिरिक्त श्रमिक समितियों को एक प्रकार से यह गलनफहमी भी हो गई थी कि उन्होंने जो फैक्ट्रियाँ जब्त की हैं उनको केवल उनके स्वयं के हित में ही चलाया जाना है । ऐसा होने से विभिन्न उद्योगों के बीच की अन्तर्निर्भरता छिन्न-भिन्न हो गई । मॉरिस डॉब ने एक उदाहरण का उल्लेख किया है, 'डोनेट्ज (Donetz) क्षेत्र में धातु कारखानों व कोयला खानों ने एक दूसरे को उधार पर कोयला व लोहा देने से मना कर दिया और राज्य की आवश्यकताओं का ख्याल किये बिना लोहा किसानों को बेचना शुरू कर दिया ।' 300 से भी अधिक निजी फर्मों पर श्रमिकों की समितियों ने जून 1918 के केन्द्रीय निर्देशों के बिना ही अपना अधिकार कायम कर लिया था । 14 फरवरी 1918 के बैसेला द्वारा जारी निर्देश, जिसमें कि उसकी अनुमति के बिना किसी भी राष्ट्रीयकरण की मनाही कर दी गई थी, बार-बार अनदेखी व अवज्ञा की गयी ।

मध्य मार्ग की खोज में लेनिन ने ऐसे व्यक्तिगत प्रबन्ध का सुझाव दिया जिसमें कारखानों का प्रबन्ध ऐसे प्रबन्धकों को सौंपा जाना था जो प्रत्यक्ष रूप से राज्य के प्रति उत्तरदायी थे । उसने परिणामों के आधार पर भुगतान (payment by results) पर भी बल दिया । वह किसानों के साथ दौलत सम्बन्ध भी चाहता था तथा उसने घोषणा की कि नये सम्बन्धों की ओर यथासम्भव धीरे-धीरे बढ़ा जाएगा । लेनिन के कुछ पार्टी सहयोगियों ने ही उसकी इन नीतियों को शकालु दृष्टि से देखा । मध्यवर्गीय (Bourgeois) इन्जीनियरों व अर्थशास्त्रियों को काम पर लेने के उसके विचार को 'बुर्जुआओं के साथ गठजोड़' कहा गया । इस पृष्ठभूमि में लेनिन ने अपने राजकीय पूँजीवाद (state capitalism) के उस विचार को रखा था जो सत्रमण काल के लिए था तथा जिसमें पूँजीवाद व समाजवाद दोनों ही के तत्त्व विद्यमान थे । यह सब इस रूप में होना आवश्यक था क्योंकि आरम्भिक महीनों में सरकार इस स्थिति में नहीं थी कि वह तकनीकी दृष्टि से प्रशिक्षित लोगों की सेवाओं के बिना काम चला सकती या कुशल प्रबन्धकों के बिना कारखानों का संचालन कर पाती

हालांकि वे लोग उसके श्रांतिकारी विचारों का समर्थन नहीं करते थे।

लेकिन सोवियत सत्ता के इन प्रारम्भिक प्रयोगों का आठ महीनों के भीतर अन्त हो गया जबकि जून 1918 में देश में गृह-युद्ध भड़क उठा था। कई विदेशी सेनाएँ रूस की भूमि पर घुस आयीं। देश में मौजूद पूँजीवाद के समर्थक तत्वों को सोवियत सरकार के पतन की प्रत्याशा थी। उन्होंने नयी सरकार के साथ सहयोग करना बन्द कर दिया। सरकार के पास अब कोई विकल्प नहीं रह गया था। उसे अपनी सैनिक आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना पड़ा। मह-यौद्धिक साम्यवाद के युग का आरम्भ था।

यौद्धिक साम्यवाद (War Communism)

1917 की श्रान्ति के तुरन्त बाद देश में गृह-युद्ध छिड़ गया था। इस स्थिति में तब और भी पिगाड़ आया जब उन विदेशी शक्तियों ने हस्तक्षेप आरम्भ कर दिया जो रूस में साम्यवाद की स्थापना होने देने के विरुद्ध थीं। जो लोग सोवियत श्रान्ति के विरुद्ध थे आरम्भ में उनको कुछ सफलताएँ भी मिलीं। लूट-खसोट सामान्य बात हो गई। 1918 के प्रारम्भ में सोवियत सरकार कोयला खानों में से इतनी अधिक खाने विद्रोहियों के हाथों खो चुकी थी कि उसके पास पिछले समय की कोयले की पूर्ति की तुलना में सिर्फ 10 प्रतिशत कोयले की पूर्ति शेष बच रही थी। इसी तरह सोवियत सत्ता अपने हाथों से अपनी 75 प्रतिशत लोहा गलाने की फाउण्ड्रियाँ (foundries), अनाज उत्पादन का 50 प्रतिशत क्षेत्र तथा चुकन्दर की पूर्ति के स्रोत भी खो चुकी थी।

ऐसी स्थिति में अब सोवियत सत्ता के सम्मुख उपस्थित सबसे ज्वलन्त प्रश्न श्रान्ति को बचाने का था। सैनिक कामों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। प्रशासन को कड़ा एवं केन्द्रीकृत रूप दिया गया।

गृह-युद्ध के प्रभाव

(i) ईंधन अभाव तथा यातायात की कठिनाइयाँ—श्वेत सेनाओं (White Armies) द्वारा कोयला खानों पर अधिकार कर लेने तथा बाकू व ग्रोंजी (Baku and Gronzy) के तेल क्षेत्रों से तेल की पूर्ति बन्द हो जाने से श्रान्ति के कुछ ही महीनों बाद उद्योगों तथा यातायात के साधनों को जैसे लकड़ा मार गया। रेलगाडियाँ लकड़ी के कोयले से चलाई गईं। इस तरह रेल-ज्वयस्था लगभग समाप्त-ही हो गई। एक बड़ी सीमा तक, जैसा कि डॉन में लिखा है, 'गृह-युद्ध एक रेल-युद्ध (Railway War) था क्योंकि वह मुख्य लाइनों के आस-पास ही चला और ऐसा इसलिए हुआ कि सैनिकों, गोला-बारूद तथा अन्य पदार्थों को ले जाने का साधन रेलें ही थीं। 1916 की तुलना में ईंधन की खपत 1919 में घटकर 40 प्रतिशत रह गई थी। औद्योगिक रोगज़ार 50 प्रतिशत गिर गया। उत्पादकता में 30 प्रतिशत की कमी आयी। कुल औद्योगिक उत्पादन 14.5 प्रतिशत घट गया।

(ii) घुड़दौड़ स्फीति व विमुद्रीकरण (Gallopning inflation and demo-

nationalisation) — स्फीति ने लाल क्रांति का साथे की तरह पीछा किया था। गृह युद्ध ने उसे और भी तेज कर दिया क्योंकि उसके लिए वित्त की व्यवस्था नयी पत्र-मुद्रा जारी करके ही की जा सकती थी। 1920 में रुबल की त्रय शक्ति 1917 के रुबल का सौवाँ हिस्सा अर्थात् 1 प्रतिशत रह गयी थी। सोवियत सरकार ने मजदूरी तो बढ़ा दी लेकिन कृषक वर्ग तथा अपेक्षाकृत समृद्ध लोगों को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ा।

(iii) खाद्य-पदार्थों का अभाव — जब रुबल की त्रय शक्ति घट गयी तो किसानों ने अपना उत्पाद बाजार में लाना बन्द कर दिया। सरकार को मजबूर होकर बड़ा रख अपनाना पड़ा। पूर्ति विभाग (the Commissariat of Supplies) या नरकामप्रोद (Narcomprod) ने खाद्य पदार्थों का अधिग्रहण (requisition) शुरू कर दिया तथा उसे सेना व उद्योग के बीच आवंटित किया। लेकिन अनिवार्य अधिग्रहण का भारी पैमाने पर अपवचन (evasion) हुआ। विशुद्ध कृषित क्षेत्र घट गया। 1920 में हुई कुल फसल युद्ध पूर्व के वर्षों की फसल से भी कम रही। इनके अतिरिक्त किसानों को भी उनके उत्पादन का प्रतिफल बहुत कम मिला। डॉब ने एक स्थान पर लिखा है कि 'ऐसा लगता है कि जहाँ शहरो को राज्य द्वारा किये गये अधिग्रहण से युद्ध-पूर्व के स्तर की 33 प्रतिशत खाद्य व कृषि पदार्थों की आपूर्ति प्राप्त हुई वहाँ गाँवों को उनके युद्ध-पूर्व के निमित्त माल-प्राप्ति के स्तर का 12 से 15 प्रतिशत ही प्राप्त हो पाया।' इस प्रकार उद्योग तथा कृषि के बीच यह विनिमय, 'औद्योगिक वस्तुओं का गरीब किसानों की सेवाओं के साथ विनिमय था जिसमें उनके खेतों से अनाज जबरन ले लिया गया था।'

विदेशी सहायता से गठित श्वेत सेवाओं (White Armies)¹ से तथा देश में गृह-युद्ध छिड़ जाने से रूस में पूरी तरह से अराजकता फैल गयी। अपनी सत्ता को बचाये रखने के लिए हो रहे इस संघर्ष में नयी क्रान्तिकारी सरकार ने जो निर्भीक या निराशा से प्रेरित होकर प्रयास किये उन्हे ही यौद्धिक साम्यवाद (War Communism) के नाम से जाना गया। पार्टी की विचारधारा का आशिक रूप से निर्वाह करते हुए तथा आशिक रूप से आपातकालीन नीतियों को लागू करते हुए जो संयुक्त नीति बनी वह नान्ति के इतिहास की एक विशिष्ट अवधि बन गयी। यौद्धिक व्यवस्था के पूरी तरह दम तोड़ देने के कारण सरकार को वस्तुओं के रूप में भुगतान की नीति अपनानी पड़ी। कई सेवाएँ जैसे यातायात व सार्वजनिक सेवाएँ मुफ्त में दी गयीं। मुद्रा या वारारोपण की पूर्ण समाप्ति की किसी को भी प्रत्याशा नहीं थी। लोगों ने यौद्धिक साम्यवाद की इस नीति को सच्चे साम्यवादी समाज की स्थापना की दिशा में एक कदम माना। किन्तु लेनिन स्वयं यह कहने के लिए बाध्य हो गया था कि यौद्धिक साम्यवाद एक नीति के रूप में सरकार पर 'युद्ध और बरबादी की वजह से एक अस्थायी उपाय के रूप में' थोपा गया था।

शहरो और गाँवों में यौद्धिक साम्यवाद की नीति पर मिश्रित प्रतिक्रिया हुई। किसानों ने इसे अधिक समर्थन नहीं दिया क्योंकि इसमें हिंसा सम्मिलित थी। उन्होने

¹ A. G. Mazour, *Soviet Economic Development, 1921-65*, 17

अपना उत्पादन बाजार में लाने से स्पष्ट इनकार कर दिया व शहरो में खाने-पीने की चीजों का अभाव पैदा कर दिया। कालाबाजारी का बोलबाला बढ़ गया तथा भूखे शहरी लोग थोड़े से अनाज के बदले अपनी कीमती चीजें किसानों को देने के लिए मजबूर हो गये। यहाँ तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्यान्नों के अधिग्रहण के लिए भेजी गयी फौजी टुकड़ियों से भी कोई विरोध काम नहीं बना। किसान लोग नगरों से की जा रही 'क्रान्ति के भाग्य को बचाने' की अपील के प्रति उदासीन बने रहे। किसानों के लिए क्रान्ति का अर्थ भूस्वामियों को जमीन से निकाल देने तक ही सीमित था।

स्थिति की बिड़बुड़ना कुछ इस तरह सामने आयी कि क्रान्ति का पुराना नारा—भूमि किसान की—स्वयं क्रान्ति के विरुद्ध ही एक अस्त्र बन गया। इस स्थिति से क्रान्ति के नेता बड़े नाराज हुए। उन्होंने नगरों को असहयोग करने वाले किसानों पर निर्भरता से उबारने का निश्चय किया। जुलाई 1918 में सोवियत कांग्रेस (Congress of Soviets) द्वारा एक प्रस्ताव स्वीकार किया गया जिसका उद्देश्य राजनीय फार्मों तथा कृषि नम्पूनों का पुनर्गठन करना था। बड़े पैमाने पर समाजवादी खेती को बढ़ावा देकर नगरों व गाँवों के बीच सहयोग बढ़ाना भी इसका उद्देश्य रखा गया। अगस्त 1918 में एक आदेश जारी किया गया जो कृषि के समाजीकरण (Socialisation of agriculture) की सोवियत कृषि-नीति का आधार बना। समाजवादी ढंग से खेती करने को आसान बनाने के लिए नियम पारित किये गये। सरकार का विश्वास था कि नये कानूनों से देश में वैज्ञानिक खेती के नये प्रतिमान स्थापित होंगे। सरकार ने यह भी आशा की थी कि नये कानूनों से किसानों व औद्योगिक मजदूरों के बीच सम्बन्धों में भी सुधार होगा।

इन राजकीय फार्मों का संचालन राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की सर्वोच्च परिपक्वता द्वारा होना था। किन्तु यह परियोजना, जिसका उद्देश्य खाद्य समस्या हल करना था, कागजों पर ही रही। यह असफलता आंशिक रूप से सरकार के युद्ध में अत्यधिक व्यस्त रहने के कारण भी हुई। आंशिक रूप से यह असफलता किसानों द्वारा किसी भी प्रकार के समाजीकरण का विरोध करने से भी हुई। विदेशी शक्तियों के हस्तक्षेप ने स्थिति को और भी दयनीय बना दिया।

उद्योग का राष्ट्रीयकरण

जब 1917 में बोल्शेविकों ने सत्ता पर अधिकार कर लिया था तब राष्ट्रीय उत्पादन तेजी से गिर रहा था तथा बाजार में आवश्यक वस्तुओं की भारी कमी थी। नियन्त्रण में न आने वाली मुद्रा-स्फीति ख़ुब की क्रय-शक्ति को प्रतिदिन कम कर रही थी। यातायात व्यवस्था एकदम ठप्प होने की स्थिति में पहुँच रही थी। रेलमार्ग परिवहन को भारी घाटा हो रहा था। अनेकों आधारभूत उद्योगों को, कुशल श्रमिकों की कमी के अतिरिक्त, कच्चे माल की कमी के संकट का सामना करना पड़ रहा था।

इन मानसिक सन्तुलन को छिन्न-विच्छिन्न कर देने वाली परिस्थितियों में नयी-

नयी बनी सोवियत सरकार ने उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के कार्यक्रम की शुरुआत की। यौद्धिक साम्यवाद का यह सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग था। इस कदम ने सरकार को आर्थिक असमानताएँ समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध कर दिया। नवम्बर 1917 के अपने प्रथम आदेश में कौंसिल ऑफ पीपल्स कमिसार्स (Sovnarkom) ने सभी श्रमिकों के लिए सामाजिक बीमे की घोषणा की। इसके कुछ ही समय बाद एक अन्य आदेश द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। फरवरी 1918 में सर्वोच्च परिषद् ने औद्योगिक इकाइयों की जवनी के बारे में नियम जारी किये। उसी महीने में सोवियत ऑफ पीपल्स कमिसार्स (the Soviet of People's Commissars) ने सारे विदेश व्यापार का राष्ट्रीयकरण कर दिया।

इन राष्ट्रीयकरणों के कर दिये जाने मात्र से आर्थिक असमानताओं का उन्मूलन करने में कोई विशेष सहायता नहीं मिली। उत्पादन ही इतना थोड़ा था कि उसे अच्छी तरह वितरित किया ही नहीं जा सकता था। लेनिन इन बिगड़ी हुई स्थिति को जान रहा था लेकिन उसे यह भी पता था कि इन परिस्थितियों में पूँजीवाद को दी गयी कोई भी रियायत क्रांति की हार समझ ली जाएगी। इससे पहले कि लेनिन राष्ट्र को क्रांति के लक्ष्यों से कुछ पीछे हटने के लिए तैयार कर पाता तीन वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। तात्कालिक परिस्थितियों में इसीलिए कड़ाई से राष्ट्रीयकरण की नीति का परिपालन किया गया।

अप्रैल 1918 के आदेश से 10,000 हबल से अधिक सम्पत्ति पर उत्तराधिकार समाप्त कर दिया गया। सरकार ने फैक्ट्री समितियों से सभी कारखानों का नियन्त्रण भी अपने हाथ में ले लिया। किन्तु प्रशासनिक व प्रबन्ध सम्बन्धी अनुभव व अभाव का परिणाम यह निकला कि औद्योगिक उत्पादन में जोर भी कम आ गयी। जून 1918 तक सरकार ने लगभग 1,100 समुक्त पूँजी कम्पनियों पर 'उनकी सारी पूँजी व सम्पत्ति सहित' अधिकार कर लिया था। इन कम्पनियों में सभी प्रमुख खाने फैक्ट्रियाँ, मिल तथा अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान सम्मिलित थे। इन्हें राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की सर्वोच्च परिषद् के अधिकार-क्षेत्र में रख दिया गया। इन प्रतिष्ठानों में काम करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों को एक आदेश द्वारा अपने-अपने पदों पर बने रहने की आज्ञा दी गयी। मारी निजी पूँजी को जमा दिया (frozen) गया।

श्रम संधों की एक समुक्त घोषणा द्वारा हड़तालें गैर-कानूनी घोषित कर दी गयीं तथा आर्थिक सकट समाप्त करने के लिए केन्द्रीकृत प्रयास करने की अपील की गयी। किन्ती भी प्रकार की काम रोकने की घटना को (work stoppage) गैर-कानूनी माना गया तथा उसके लिए उत्तरदायी लोगों को विशेष अदालतों द्वारा भारी दण्ड दिलाने की व्यवस्था की गयी। अगस्त 1918 के एक आदेश से वास्तविक परिसम्पत्त (real estate) पर भी स्वामित्व समाप्त कर दिया गया। नगरों में मकान, जमीन आदि पर स्वामित्व समाप्त कर दिया गया तथा 10,000 हबल से अधिक के सभी रहन (mortgages) भी रद्द कर दिये गये। 10,000 हबल से कम के रहन राजनीय ऋण माने गये।

उत्पादन व वितरण के लिए सरकार का उत्तरदायित्व

नई सरकार ने उत्पादन तथा वितरण दोनों ही का नियमन करने का उत्तरदायित्व लिया। जुलाई 1918 में स्वीकृत संविधान में 'व्यक्ति का व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला सभी प्रकार का शोषण तथा समाज का वर्ग विभाजन समाप्त करने' की घोषणा की गयी। इसने भूमि का समानिकरण कर दिया तथा श्रमिकों के नियन्त्रण और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की सर्वोच्च परिपद की स्थापना का स्थायीकरण कर दिया। इस परिपद को राष्ट्रीयकृत उद्योगों के नियन्त्रण व संचालन का काम सौंपा गया। परिपद उत्पादन व वितरण के समन्वय के लिए भी उत्तरदायी बनायी गयी। परिपद की सहायता के लिए अनेक स्वतन्त्र कमिसरियेटे (Commissariats) या विभाग उद्योग, व्यापार, कृषि, वित्त आदि गतिविधियों के लिए बनाये गये। इनके कार्य एक दूसरे का अतिक्रमण करते थे।

श्रम अनुशासन को और भी बड़ा बनाया गया तथा अक्टूबर 1918 के एक आदेश में सभी नागरिकों को 'अनिवार्य श्रम' के लिए बाध्य कर दिया गया। उत्पादन के साधनों के राष्ट्रीयकरण के बाद सरकार द्वारा नियन्त्रित वितरण व्यवस्था कायम की गयी। यह काम दो संस्थाओं द्वारा किया जाना था खाद्य विभाग एवं कृषि विभाग (the Commissariat of Food and the Commissariat of Agriculture)। वितरण व्यवस्था की सबसे बड़ी कठिनाई खाद्य पदार्थों व अन्य वस्तुओं के केवल गाँवों में ही उपलब्ध होने की थी। 'क्रान्तिवारी निश्चय' भी इस काम में कोई सहायता नहीं कर पाया। राशनिंग व अधिग्रहण (requisition) बड़े पैमाने पर लागू किये गये। रसद विभाग (The Commissariat of Supplies) ने देश की जनसंख्या को चार भागों में विभाजित किया

- (i) सतरे भरे कामों में लगे हुए मजदूर,
- (ii) औद्योगिक मजदूर,
- (iii) सरकारी कर्मचारी,
- (iv) गैर-श्रमिक लोग।

इनमें से प्रत्येक वर्ग के लोगों को उत्तरोत्तर घटती हुई दर से खाद्यान्नों का दैनिक राशन आवंटित किया जाता। चौथी श्रेणी में लोगों को तो लगभग भूखे मरने के लिए छोड़ दिया गया।

बौद्धिक साम्यवाद का परिस्थान

तीन वर्ष तक चलने वाले गृह युद्ध के प्रभाव रूस तथा उसकी नयी क्रांतिकारी सरकार के लिए काफी घातक सिद्ध हुए। राजनीतिक सत्ता छीनने के लिए तीव्र संघर्ष हुआ। गृह-युद्ध के अतिरिक्त बाहरी शक्तियों द्वारा देश की घेराबन्दी ने रूस की अर्थव्यवस्था को दमनीय बना देने में पूरा योगदान दिया। 1921 में औद्योगिक उत्पादन गिरने-गिरते 1914 के पहले के वर्षों का 13 प्रतिशत रह गया। कृषि तो पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गयी। 1914 के बाद युद्ध और क्रांति के सात वर्षों ने

रान के लोगों को एक ऐसे स्थान पर ले जाकर सड़ा कर दिया था जहाँ उनके लिए जीवित रह लेने भर तक का प्रश्न शेष रह गया था ।

1920 के अन्त में यौद्धिक साम्यवाद का परित्याग कर दिये जाने के पीछे दो अत्यन्त महत्वपूर्ण कारण रहे । पहला कारण किसानों द्वारा कृषि के समाजीकरण का कटा विरोध रहा । ये कृषक लोग क्रान्ति के महान् मुद्दों को नहीं समझ पाये । दूसरा कारण था सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था का पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो जाना । सोवियत सत्ता का नींव को ही खतरा पैदा हो गया था । ऐसी स्थिति में यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यौद्धिक साम्यवाद की नीतियाँ आर्थिक पुनरुद्धार की प्रक्रिया प्रारम्भ करने में असफल रही, किन्तु उन्होंने एक आपातकालीन उपाय के रूप में नगरों में रहने वाले लोगों तथा फौज के लिए खाद्य पदार्थ जुटाने में बड़ा उपयोगी कार्य किया । आर्थिक संस्थाओं की एक लड़ी बनाकर यह एक अस्थायी राष्ट्रीय आर्थिक ढाँचा तैयार करने में भी सफल रही । यौद्धिक साम्यवाद के अन्तर्गत किये गये उपायों को कई लोग 'साम्यवादी समाज की हड्डियाँ व मांस' की संज्ञा देते हैं । मुद्रा के स्थान पर वस्तु-विनिमय को भी साम्यवाद की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना गया । इस सम्पूर्ण व्यवस्था के बारे में डॉब ने लिखा है कि 'आर्थिक अभाव, सैनिक आवश्यकताओं तथा गृह-युद्ध की थका देने वाली स्थितियों में यह एक अल्पकालिक उपाय के रूप में उभरी थी ।' नयी आर्थिक नीति के अन्तर्गत स्वीकार की गयी नीतियाँ यौद्धिक साम्यवाद के उपायों को नरम बनाने का प्रयास थीं ताकि अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण किया जा सकता व असन्तुष्ट किसानों को भी शान्त किया जा सकता ।

नवीन आर्थिक नीति

(THE NEW ECONOMIC POLICY)

1921-1928

गृह-युद्ध तो 1921 में समाप्त हो गया किन्तु उसके कारण अर्थव्यवस्था पर जो भार पड़ा वह इतना अधिक था क्रांसटेडट (Kronstadt Garrison) स्थान पर दंगा हो गया। एक बार जब किसान इस बात के बारे में आश्वस्त हो गये कि अब भू-स्वामी हमेशा के लिए खत्म हो चुके हैं तो वे सोवियत सरकार को भी अनाज आदि देने में आनाकानी करने लगे। उद्योग तक कृषि की उत्पादकता में निरन्तर ह्रास होता रहा। इसके परिणामस्वरूप आम जनता के उत्पीड़न, कष्ट तथा असन्तोष बढ़ते रहे। अन्य पूँजीवादी देशों में सोवियत रूस की तरह की ही क्रान्ति निकट भविष्य में ही होने की आशा विलुप्त हो गई। अब यह स्पष्ट रूप से अनुभव किया जाने लगा कि बौद्धिक साम्यवाद के दौरान स्थापित किया गया आर्थिक ढाँचा राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के कार्य को पूरा करने में सक्षम नहीं है तथा उसमें कुछ परिवर्तनों की आवश्यकता है। लेनिन ने दसवीं साम्यवादी कांग्रेस, जो मार्च 1921 में बुलाई गई, में इसी विचारों को प्रतिष्ठापित किया, जब उसने यह बयान जारी किया 'हम गरीबी और बर्बादी की ऐसी स्थिति में जा रहे हैं तथा हमारे धर्मिकों व किसानों की मुख्य उत्पादक शक्तियों पर इतना अधिक व थका देने वाला भार पड़ चुका है कि कुछ समय के लिए हर चीज को इसी मुख्य मुद्दे की दृष्टिगत रखते हुए देखा जाना चाहिए—प्रत्येक मूल्य पर वस्तुओं की मात्रा बढ़ायी जानी चाहिए।'

इसी वातावरण में नई आर्थिक नीति (New Economic Policy) का शीर्षणेश किया गया था। नवीन आर्थिक नीति की विषय सामग्री के बारे में अनेक मतभेद हैं। कई लेखकों ने नई आर्थिक नीति को सोवियत रूस में समाजवाद की स्थापना की असफलता का प्रमाण बताया तो कुछ ने उसे मार्क्सवाद की असफलता, समाजवादी सिद्धान्तों का पूँजीवाद के सम्मुख आत्म-समर्पण या समाजवाद से पीछे हटकर राजकीय पूँजीवाद की ओर जाने की सज्ञा दी। दूसरी ओर कुछ अन्य लेखकों ने नई आर्थिक नीति को शुद्ध साम्यवाद की स्थापना से पहले का कुछ विधाम, मार्क्सवाद से अस्थायी तौर पर पीछे हटने व समाजवादी राज्य (Socialist State) की स्थापना में विभिन्न महत्त्वपूर्ण शक्तियों का सामरिक पुनर्संग्रह (regrouping) किये जाने की सज्ञा दी। साम्यवादी दल के सदस्यों तक में भी यही विचार पैदा हो रहे थे। इन परस्पर विरोधी विचारधाराओं की जड़ वास्तव में देखा जाये तो स्वयं

नवीन आर्थिक नीति में ही विद्यमान थी जो एक ऐसी दोहरे किस्म की व्यवस्था थी जिसमें समाजवाद के तत्त्वों को प्रतियोगात्मक पूँजीवादी संस्थाओं के साथ सम्बद्ध कर दिया गया था।

नवीन आर्थिक नीति के तीन मध्यवर्ती (intermediate) लक्ष्य थे -

(i) प्रत्येक मूल्य पर वस्तुओं की मात्रा बढ़ाना।

(ii) राजनीतिक संकट का समाधान करना अर्थात् आर्थिक संकट बढ़ने के कारण श्रमिकों व कृषकों में केन्द्र सरकार के प्रति मनोमालिन्य की भावना को शान्त करना तथा गाँवों एवं शहरों के बीच बढ़ते जा रहे अलगाव की खाई को पाटना।

(iii) समस्त 'आर्थिक ऊँचाइयों' (Economic Commanding Heights) को सरकार के हाथों में रखना तथा उन्हें उत्पादकता के पुनरुद्धार की दिशा में इस प्रकार प्रयुक्त करना कि जिसमें 'सर्वहारा वर्ग की सम्प्रभुता' की अन्तिम विजय हो सके।

शुरू-शुरू में यह आशा थी कि स्वतन्त्र बाजार का कार्य-क्षेत्र स्थानीय लेन-देनों तक सीमित कर पाना सम्भव होगा तथा शहरों गाँवों के बीच राष्ट्रीय स्तर पर वस्तु-विनिमय (barter) की व्यवस्था स्थापित की जा सकेगी। लेकिन, लेनिन ही के शब्दों में, 'निजी व्यापार हमसे भी मजबूत सिद्ध हुआ, तथा वस्तु-विनिमय की जगह साधारण खरीद और बिक्री ही चलती रही।'।

साम्यवादी दल के वामपन्थी तत्त्वों के द्वारा किये जा रहे विरोध को देखते हुए यह कोई आसान निर्णय नहीं था। इस तरह पीछे हट जाना इन वामपन्थी तत्त्वों को विल्कुल रास नहीं आया। लेकिन पुनः एक बार वह लेनिन ही था जिसने स्थिति का व्यावहारिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन किया। लेनिन ने कहा 'यदि कुछ साम्यवादी सदस्य इसे सम्भव समझने की दिशा में सोचते हैं कि तीन वर्षों में सम्पूर्ण आर्थिक ढाँचे को रूपान्तरित किया जा सकता है तथा कृषि की जड़ों को ही पूरी तरह से बदला जा सकता है तो वे निश्चय ही स्वप्नदृष्टा (dreamers) हैं, और हमें यह स्वीकार करना होगा कि हम में कुछ ऐसे स्वप्नदृष्टा भी हैं।' लेकिन ने पार्टी को यह चेतावनी भी दी कि किसानों के साथ समझौता करके ही क्रान्ति को बचाया जा सकता है क्योंकि रूस में किसानों का वहाँ की जनसंख्या में भारी बहुमत है। उसने यह अनुभव कर लिया था कि रूस के किसानों की बुर्जुआ अर्थात् मध्यवर्गीय मनोवृत्ति को समाजवादी मनोवृत्ति में रूपान्तरित करने में अभी कई वर्षों का समय लग जायेगा। लेकिन रूस का समाजवादी देश के रूप में पुनर्निर्माण करने के लिए उसके औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करने की भी अत्यधिक आवश्यकता थी। इन परिस्थितियों में लेनिन ने बड़े पैमाने के उद्योग स्थापित करने पर ध्यान दिया।

व्यापार का विकास करना भी महत्वपूर्ण माना गया। लेनिन ने पार्टी के कार्यकर्त्ताओं को एक नया नारा दिया व्यापार करना सीखो। व्यापार में वृद्धि से यह आशा की गई थी कि शहरी आबादी के लिए खाद्य सामग्री जुटाई जा सकेगी तथा उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त किया जा सकेगा। इससे पूँजी-संचय भी सम्भव बन सकेगा।

नई आर्थिक नीति के यही उद्देश्य थे और उसके सामने यही कार्य रहे गये थे जब बौद्धिक साम्यवाद के युग से अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के नये युग की ओर अग्रसर होने का कार्यक्रम बनाया गया था। लेकिन जिन तरीकों से या साधनों से इन उद्देश्यों या कार्यों को नये आर्थिक ढाँचे के भीतर ढाल कर एक निश्चित स्वरूप प्रदान किया जाना था वह सब नई आर्थिक नीति के आरम्भ में स्पष्ट नहीं था। गलती करने व सोखने (methods of trial and error) का तरीका अपनाया गया जो संक्रमण काल में राज्य एवं निजी स्वामित्व वाली अर्थव्यवस्था के बीच समझौते के लिए चूकाया गया अपरिहार्य मूल्य था।¹

उपर्युक्त विश्लेषण से एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि नवीन आर्थिक नीति को मुक्त चुनाव से तो स्वीकार नहीं किया गया था। इस नीति को केवल इसलिए अपनाया गया था कि उस समय अर्थव्यवस्था के आर्थिक पुनरुद्धार की अत्यन्त आवश्यकता थी। सोवियत नेताओं ने अपने आपको यह समझा कर सान्त्वना दी कि वही भी महत्वपूर्ण उद्योगों का नियन्त्रण उनके हाँ हाथों में था तथा यह कि जैसे ही स्थिति में थोड़ा सुधार आजा पार्टी पुनः समाजवाद की ओर लौट जाएगी।

नई आर्थिक नीति के अन्तर्गत कृषि

नई आर्थिक नीति का सामान्य सक्षय राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की सभी शाखाओं में उत्पादन का पुनरुद्धार करना था। कृषि उत्पादन में यह पुनरुद्धार किसानों के सहयोग एवं व्यक्तिगत पहल (personal initiative) द्वारा ही सम्भव बनाया जा सकता था। इसीलिए नई आर्थिक नीति ने राष्ट्रीयकरण को बनाय रखने हुए, हालांकि जमीन साखों करोड़ों किसानों के हाथों में ही बनी रही, वास्तविक रूप से भूमि पर मालिक बने हुए लोगों का स्वामित्व स्वीकार किया। हालांकि जमीन बेचने पर पाबन्दी लगा दी गई क्योंकि उसे राज्य की सम्पत्ति माना गया लेकिन जमीन को लीज (lease) पर उठाने, मशीनें किराये पर लेने और यहाँ तक कि जानवर और श्रमिकों को भी भाड़े पर ले सकने की अनुमति दे दी गई। किसानों को अपने उत्पादन का संगठन करने तथा उसे बेचने की पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान की गई। इस स्वतन्त्रता ने समृद्ध किसानों के एक वर्ग को बड़ावा दिया जिन्हें कुलक (Kulak) के नाम से जाना गया। नई आर्थिक नीति की अवधि के दौरान सरकार ने छोटे किसानों की सहायता के लिए अनेक उपाय किये तथा कुलकों (Kulaks) के बढ़ने पर प्रतिबन्ध भी लगाये जिन्हें वर्ग-शत्रु माना गया।

सरकार किसानों को खुश रखना चाहती थी ताकि शहरो और गाँवों के बीच आवश्यक चीजों के आदान-प्रदान को फिर से सामान्य बनाया जा सकता। अतिरिक्त अनाज के अधिग्रहण की नीति समाप्त कर दी गई। उसके स्थान पर एक नया अनाज-कर (Food Tax) लगाया गया, जिसे 1923 के बाद मुद्रा में चुकाया जा सकता था। एक सत्कारी घोषणा में कहा गया कि 'अब से अधिग्रहण की नीति समाप्त घोषित की जाती है तथा उसके स्थान पर वस्तुओं के रूप में एक कृषि-कर

लगाया जा रहा है। अब हर किसान को यह समझ लेना चाहिए कि वह जितनी ज्यादा जमीन जोतेगा उतना ही अधिक अतिरिक्त अनाज उसकी व्यक्तिगत सम्पत्ति बन सकेगा।¹ वह इस अतिरिक्त अनाज को स्वतन्त्र बाजार में बेच सकता था।

अतिरिक्त अनाज का निर्धारण प्रति व्यक्ति न्यूनतम जीवन-निर्वाह के लिए आवश्यक अनाज को अलग रखकर ही किया जाना था तथा कर केवल अतिरिक्त अनाज पर ही लगाया गया था। यह इस बात का प्रमाण था कि स्वतन्त्र व्यापार व लाभ की प्रवृत्ति को मान लिया गया था। इसके लिए सुस्थिर मुद्रा की भी आवश्यकता थी। इन परिवर्तनों ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि लाख पदार्थों के केन्द्रीकृत वितरण की पुरानी व्यवस्था असफल सिद्ध हो चुकी थी।

इस तरह 1925-26 तक अनाज के उत्पादन का पुनरुद्धार हुआ तथा धनी किसानों पर प्रतिबन्ध लगाने की दृष्टि से कृषि-कर को अधिक प्रगतिशील बनाया गया। दूसरी ओर निर्धन किसानों को न केवल करो में रिपायत का लाभ मिला बल्कि उन्हें फसलें खराब हो जाने की स्थिति में सहायता भी दी गई।

नई आर्थिक नीति के कार्यकाल की समाप्ति तक देश में कृषक-फार्मों (peasant farms) की संख्या बढ़कर 10 मिलियन हो चुकी थी। कुछ निर्धन कृषक मध्यम वर्ग के किसान बन गये तो कुछ अन्य औद्योगिक मजदूर बन गये। धनी किसानों की जोतों में कमी आई। स्वाभाविक रूप से अनाज के उत्पादन में नई आर्थिक नीति के कार्यकाल में पुनरुद्धार धीरे-धीरे ही हो पाया क्योंकि वह जोतों के आकार पर भी निर्भर था। नई आर्थिक नीति के कार्यकाल के अन्त तक भी अनाज का उत्पादन क्रान्ति पूर्व के स्तर तक नहीं पहुँच पाया था। बाजार अतिरेक में भी गिरावट आई थी।

कृषि उत्पादन में इस धीमी गति से पुनरुद्धार में धरेलू बाजार में कठिनाइयाँ पैदा हो गयीं। 1927 में कुछ आपातकालीन उपाय किये गये। धनी किसानों के अनाज को, जिसे उन्होंने सरकार को निश्चित मूल्य पर देने से मना कर दिया था, जब्त कर लिया गया। अनाज का संग्रह करने वालों को जेल भेज दिया गया। भ्रष्ट किसानों ने इस स्थिति के प्रति अपनी प्रतिक्रिया अपने कृषित क्षेत्र को घटाकर व्यक्त की।

1927 में एक ऐसी सामान्य नीति बनाई गई जिसमें उपायों की एक लम्बी श्रृंखला थी। निर्धन किसानों को अधिक साख-सुविधाएँ तथा उत्पादन के अन्य साधन उपलब्ध कराये गये। बड़े पैमाने पर अन्य उत्पादन करने के उद्देश्य से नये राजकीय फार्म गठित किये गये। कृषक घरानों के सामूहिकीकरण (collectivisation) के लिए उपायों को तेज कर दिया गया।

नई आर्थिक नीति के अन्तर्गत उद्योग

उद्योग के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। उत्पादन में और गिरावट न होने देने के लिए उद्योग के पुनर्गठन को आवश्यक बताया गया। इस अवधि में औद्योगिक उत्पादन के संगठन में अग्रलिखित महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये² :

(i) बड़े एवं महत्त्वपूर्ण उद्योग राज्य के स्वामित्व में बने रहे ।

(ii) कुछ उद्योगों में अस्थायी रूप से उत्पादन रोक देना पड़ा । अधिकांश छोटे प्रतिष्ठानों को या तो सहकारियों को लीज (lease) पर दे दिया गया या फिर उन्हें वापस उनके पुराने मालिकों को लौटा दिया ।

(iii) कुछ मौजूदा प्रतिष्ठानों को विदेशियों को भी लीज (lease) पर दे दिया गया तथा नये उत्पादनों के लिए कुछ रियायतें भी दी गयीं ।

(iv) राजकीय तथा निजी पूंजी को मिला-जुलाकर भी कुछ नये प्रतिष्ठान प्रारम्भ किये गये ।

इन सभी उपायों के परिणामों का अनुमान 1923 की एक औद्योगिक सगणना में लगाया गया था । इस सगणना में शामिल किये गये 1,65,781 प्रतिष्ठानों में से 88.5 प्रतिशत निजी स्वामित्व में, 8.5 प्रतिशत सरकारी स्वामित्व में तथा 3 प्रतिशत सहकारी उपक्रम थे । लेकिन सरकारी अधिक होने के बावजूद ये निजी उपक्रम इतने छोटे थे कि इनमें कुल श्रम-शक्ति का केवल 12.4 प्रतिशत भाग कार्यरत था जबकि सरकारी प्रतिष्ठानों में काम में लगे हुए कुल श्रमिकों में से 84 प्रतिशत को रोजगार मिला हुआ था ।

इस तरह विकेंद्रीकरण की नीति अपनाकर सरकार ने स्वयं को अनेक छोटे-छोटे उपक्रमों को सम्भालने की जिम्मेदारी से मुक्त कर लिया और फिर भी औद्योगिक उत्पादन में 'निर्णायक ऊँचाइयाँ' उसके हाथों में बनी रही । इन राजकीय उपक्रमों को छोटी इकाइयों को अपने में मिलाने के लिए ट्रस्ट या समूह (combines) के रूप में बदला जा सकता था । प्रतिष्ठानों के समूहीकरण (combines of enterprises) का यह क्रम ट्रस्ट बनाने के रूप में उत्पादन को केन्द्रीभूत (centralise) करने के उद्देश्य से सम्पूर्ण नवीन आर्थिक नीति के कार्यकाल में चलता रहा ।

किन्तु ये सोवियत ट्रस्ट, साधारणतया ट्रस्ट से जो अर्थ लिया जाता है, उससे हटकर थे । वे तो ऐसे सरकारी औद्योगिक प्रतिष्ठान थे जिन्हें लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से अपने क्रियाकलाप चलाने के लिए राज्य द्वारा पूरी स्वतन्त्रता प्राप्त थी । इसलिए केवल राजकीय औद्योगिक प्रतिष्ठानों की ही न्यायो या ट्रस्टों के रूप में बदला जा सकता था । इन ट्रस्टों को उस पूंजी पर स्वामित्व नहीं था जो उनमें लगी हुई थी । सरकार उनकी पूंजी को स्थानान्तरित या परिसमाप्त कर सकती थी । इस तरह नवीन आर्थिक नीति के कार्यकाल में बने हुए ये सोवियत ट्रस्ट राजकीय उद्योगों की उत्पादक गतिविधियों को केन्द्रीभूत करने का ही एक स्वरूप थे ।

व्यापारिक गतिविधियों को सिण्डिकेटों (Syndicates) में केन्द्रीभूत कर दिया गया । नई आर्थिक नीति के कार्यकाल के आरम्भिक वर्षों में केवल ट्रस्ट ही वैधानिक व्यक्तित्व (legal personality) वाली इकाइयाँ माने जाते थे । फैक्ट्रियों, खानों आदि को 'प्रतिष्ठान' (establishments) का दर्जा दिया हुआ था तथा उन्हें ट्रस्टों का अंगमात्र माना जाता था । ट्रस्ट उत्पादन तथा बाजार के बीच कड़ी के रूप में काम करते थे ।

नई आर्थिक नीति को घोषित करते समय लेनिन ने कहा था कि 'बड़े

पैमाने के उद्योग, उनकी सफलता तथा उनका विकास, साम्यवाद का निर्माण करने के लिए सर्वाधिक प्रमुख आवश्यक शर्त हैं*** भारी उद्योग को राजकीय अनुदान की आवश्यकता पड़ती है। यदि हम उसकी व्यवस्था नहीं कर सकते तो एक सभ्य राष्ट्र के रूप में, एक समाजवादी राष्ट्र के रूप में तो बात का कहना ही क्या, हमारा अन्त मुनिश्चित है।' यही वाक्य सोवियत सरकार का मूल मन्त्र बन गया।

1924-25 के बाद से राजकीय कोषों का उद्योग के लिए वित्तीय व्यवस्था करने पर विनियोग उद्योगों से प्राप्त आगम से बराबर बढ़ता रहा। नई आर्थिक नीति के कार्यकाल के अन्तिम वर्षों में उद्योगों की आधारभूत पूँजी का प्रसार एवं नवीनीकरण बहुत तेज गति से हुआ। राजकीय बजट से अनुदान, बैंकों से उद्योग के लिए साख, विदेशी प्रतिस्पर्धा का उन्मूलन, निजी उपक्रम के विरुद्ध प्रतिबन्धात्मक उपाय—ये सभी तत्त्व राजकीय उद्योगों के पुनरुद्धार में सहयोगी तत्त्व रहे।

1926 में बड़े उद्योगों ने अपना 1914 पूर्व का उत्पादन स्तर पुन प्राप्त कर लिया था। लेकिन इस बीच जनसंख्या 1913 के 139 मिलियन से 1926 में बढ़कर 147 मिलियन हो जाने के कारण प्रति व्यक्ति औद्योगिक उत्पादन में गिरावट आ गयी। इसके अतिरिक्त उत्पादन की किस्म में भी कुछ गिरावट आयी। एक अन्य कठिनाई जो बराबर बनी रही वह निर्मित वस्तुओं की उत्पादन लागत के अत्यधिक ऊँचा बने रहने की थी। एक असन्तुष्ट बाजार (consaturated market) तथा लगभग सौ प्रतिशत राजकीय एकाधिकार, जिसमें की चीजों की ऊँची कीमत पर भी बेचने की गारण्टी थी, लागतों में कमी करने के लिए कोई अभिप्रेरणा (incentive) नहीं देने थे।

नई मुद्रा (New Currency)

बशर्त नवीन आर्थिक नीति¹ में मौद्रिक अर्थव्यवस्था का बने रहना जरूरी था इसलिए मुद्रा को सुस्थिर बनाना अनिवार्य हो गया तथा साथ ही एक ऐसी बैंकिंग व साख व्यवस्था भी स्थापित करना आवश्यक हो गया जिसे देश के भीतर तथा बाहर दोनों ही जगह मान्यता प्राप्त हो। 1921 में स्टेट बैंक को पुन खोल दिया गया। सरकार ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि वह व्यापार, उद्योग, कृषि आदि की पुनर्प्रतिष्ठा करेगी तथा एक 'स्थिर मौद्रिक प्रचलन' (sound monetary circulation) कायम करेगी। पुरानी व बेकार हो चुकी पत्र-मुद्रा को प्रचलन में निकाल लिया गया तथा उसके स्थान पर एक नई पत्र-मुद्रा जारी की गई। 1923 में स्टेट बैंक ने एक नई सुस्थिर मुद्रा निर्गमित की इस नई पत्र-मुद्रा, जिसे चेरवोनेट्स (chervonets) कहा गया, के पीछे विदेशी मुद्राओं व स्वर्ण की 25 प्रतिशत मूल्य तक की गारण्टी रखी गयी। 1924 में लगभग 2500 बचन बैंक भी खोले गये जिन्हें स्टेट बैंक से सम्बद्ध किया गया।

आन्तरिक एवं विदेश व्यापार

दल के भीतर नई आर्थिक नीति को लेकर सबसे अधिक विरोधी बातें मूल्यों

¹ A G Mazour, *op cit*, 25

लिया, जैसे ठेले और फुटपाथ वाले विक्रेता रह गये। 1923 में देश में 5 04 लाख व्यापारिक संस्थान थे जिनमें से 91 प्रतिशत निजी थे जबकि इन व्यापारिक संस्थानों की संख्या 1927 में 6 43 लाख थी जिनमें से 78 प्रतिशत निजी थे। लेकिन जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है ये निजी संस्थान इतने छोटे थे कि नई आर्थिक नीति के कार्यकाल में ही व्यापार का सारा काम सरकारी इकाइयों के हाथों में आ चुका था।

जब नई आर्थिक नीति आरम्भ की गई थी तो विदेश व्यापार को राजकीय एकाधिकार रहने दिया गया था। लेनिन ने तर्क दिया कि 'तटकर को कोई भी नीति साम्राज्यवाद के इन युग में वास्तव में सफल नहीं हो सकती, एक ऐसे युग में जिसमें कि गरीब व अमीर देशों के बीच भारी भेदभाव किया जा रहा है। किसी भी औद्योगिक देश के पास हमारे घरेलू उद्योगों को परास्त करने के लिए पर्याप्त से भी अधिक धन है।' क्रेसिन (Krasin), जो कि विदेश व्यापार नीति का निर्माता था, ने भी कहा कि 'बिना विदेश व्यापार को राजनीतिक एकाधिकार में रखे सोवियत सरकार राजकीय नियोजन व्यवस्था को आगे नहीं बढ़ा सकती।' इस प्रकार के एकाधिकार के कई लाभ थे। इससे विदेशी प्रतिस्पर्धा के विरुद्ध पूरी तरह सुरक्षा मिल जाता था। विदेश व्यापार पर राजकीय एकाधिकार होने से आयातों को कड़ाई के साथ योजना की आवश्यकताओं के अनुरूप नियमित किया जा सकता था। निर्यात भी नियोजित लक्ष्यों के हिसाब में किये जा सकते थे। राजकीय एकाधिकार होने से विदेश व्यापार का न केवल आर्थिक उद्देश्यों के लिए नियमन सम्भव था बल्कि राजनीतिक उद्देश्यों के लिए भी उसका नियमन किया जा सकता था। इसके अलावा राजकीय एकाधिकार में होने से देश की मुद्रा को विदेशी मुद्रा के साथ सम्बन्धित रखने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती थी।

विदेश व्यापार पर राज्य के एकाधिकार के जो ये विभिन्न लाभ थे वे ही सोवियत सरकार द्वारा इस सिद्धान्त से कभी विचलित न होने के कारण भी बने।¹ कुछ समय बाद, जबकि व्यावसायिक नाकेबन्दी हटा ली गई थी, कुछ देशों के साथ अस्थायी व्यापार समझौते भी किये गये। नई आर्थिक नीति के सारे कार्यक्रमों में विदेश व्यापार पूरी तरह से सोवियत सहकारियों तथा राज्य व्यापार निगमों द्वारा विदेश व्यापार की लोक कमिमारयत की देखरेख में चलाया गया। सोवियत रुम के विदेश व्यापार का सामान्य उद्देश्य किसी तरह का लाभ बमाना नहीं था बल्कि उसके द्वारा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास में सहयोग प्राप्त करना था। कुछ आयातों की बहुत अधिक आवश्यकता थी किन्तु उनके माँगवाने में अवसर बाधाएँ आती थी क्योंकि भुगतान सम्बन्धी कठिनाइयाँ बनी रहती थी। संक्षेप में निष्कर्ष यही है कि सोवियत रूस का विदेश व्यापार नवीन आर्थिक नीति के कार्यकाल में धीरे-धीरे आगे बढ़ा और वह उसके आखिर तक भी क्रान्ति-पूर्व के स्तर को प्राप्त नहीं कर पाया।

नई आर्थिक नीति के अन्तर्गत श्रम

नई आर्थिक नीति के कार्यकाल में श्रम सम्बन्धों में एक आधारभूत परिवर्तन

¹ Baykov, op cit, 73.

आया। यौद्धिक साम्यवाद की अनिवार्य श्रम तथा वस्तुओं के रूप में सबको समान वेतन देने की प्रथा का परित्याग कर दिया गया। श्रम-सघो तथा प्रबन्धको के बीच सम्बन्धों को फिर से स्थापित करने की आवश्यकता अनुभव हुई। वयस्को के लिए आठ घण्टे के कार्य-दिवस को वैधानिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई। श्रमिकों को नियुक्त करने व बर्खास्त करने के विषय में नियम बना दिये गये। ट्रेड यूनियनों को प्रबन्धको के लिए बनाये गये नियमों का उनके द्वारा कड़ाई से अनुपालन कराने की दृष्टि से निरीक्षण के अधिकार दिये गये। नई आर्थिक नीति प्रारम्भ करने से सामाजिक बीमों की व्यवस्था एक वास्तविकता बन गई। ट्रेड यूनियनों को श्रमिकों को उद्योग के नियन्त्रण में हिस्सा लेने के लिए आकर्षित करने, एक नये श्रम अनुशासन का विकास करने तथा श्रम-उत्पादकता बढ़ाने का कार्य सौंपा गया। श्रम-सघो को सभी राजकीय आयोजन सम्वन्धों में भी भाग लेने के लिए कहा गया।

श्रम सघो के कर्तव्यों में दोहरापन (dualism) एक ओर तो श्रमिकों के हितों के रक्षक के रूप में उनके कर्तव्य तथा दूसरी ओर उत्पादन के सगठन में भागीदार होने का कर्तव्य, कई भ्रामक स्थितियों का जन्मदाता बना। मजदूरी की वैधानिक निर्धारण (statutory fixation) की व्यवस्था के स्थान पर स्वतन्त्र सामूहिक सौदेबाजी की प्रणाली लागू की गई। वस्तुओं के रूप में मजदूरी देने की प्रथा के स्थान पर विगुद्ध मौद्रिक मजदूरी आरम्भ की गई। दश व अदश श्रमिकों के लिए एक समान वेतन की पुरानी व्यवस्था के स्थान पर मजदूरी में अन्तर (differential wages) वाली प्रणाली फिर से लायी गयी। एक अत्यधिक कुशल श्रमिक को एक अकुशल श्रमिक की तुलना में साढ़े तीन गुना अधिक मजदूरी दी जाती थी। नई आर्थिक नीति के कार्यकाल में मजदूरी को मुख्य अभिप्रेरक (main incentive) के रूप में काम में लिया गया।

श्रम अनुशासन व औद्योगिक उत्पादन का सगठन दोनों ही, जो यौद्धिक साम्यवाद की अवधि में अस्त-व्यस्त हो चुके थे, नई आर्थिक नीति के कार्यकाल में पुनः जमने लगे अर्थात् उनका पुनरुद्धार हुआ। नई आर्थिक नीति के कार्यकाल में श्रमिकों की औसत वार्षिक मजदूरी में तेजी से वृद्धि हुई। 1926-27 तक मजदूरी पुनः युद्ध-पूर्व के स्तर पर पहुँच गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना की पूर्व संध्या पर औद्योगिक मजदूरी 1913 की तुलना में 123 प्रतिशत थी इजीनियरों तथा तकनीशियनों को मजदूरी के अतिरिक्त बोनस भी दिया जाने लगा।

लेकिन यहाँ यह बात कहनी होगी कि नई आर्थिक नीति के कार्यकाल में औद्योगिक श्रमिकों को अन्य किसी भी समुदाय की तुलना में अधिक भौतिक लाभ मिले। सामाजिक दृष्टि से भी औद्योगिक श्रमिकों को प्रथम श्रेणी का तथा अन्य लोगों को द्वितीय श्रेणी का नागरिक समझा गया।

नई आर्थिक नीति के अन्तर्गत निजी पूंजीपति

जैसा कि हम देख चुके हैं कि निजी पूंजीपति जिसे नेपमेन (Nepmen) भी कहा गया, का खुदरा व्यापार पर नियन्त्रण काफी बढ़ गया। ऐसा इसलिए हुआ

कि अपने कार्यकाल के आरम्भिक वर्षों में नई आर्थिक नीति का उद्देश्य राजकीय उद्योगों का विकेन्द्रीकरण करना था। सहकारी इकाइयाँ आन्तरिक व्यापार के लिए पर्याप्त जाल नहीं बिछा पायी थी और राजकीय उद्योगों को अपनी चीजें बाजार तक पहुँचाने के लिए निजी व्यापारियों के माध्यम का सहारा लेना पड़ा। नेपमेन (निजी व्यवसायी) शहर व गाँव के बीच होने वाले लेन-देन की एक महत्वपूर्ण कड़ी भी थे। किन्तु 1923 के बाद जैसे-जैसे सहकारी व राजकीय व्यापार इकाइयों का आकार व संख्या बढ़ती चली गई वैसे-वैसे नेपमेन का योगदान घटता चला गया। नई आर्थिक नीति का कार्यकाल समाप्त होने के पहले ही नेपमेन अपना स्थान खो चुके थे।

नई आर्थिक नीति की समाप्ति

साम्यवादी पार्टी नई आर्थिक नीति के कार्यक्रम के बारे में आरम्भ से ही शकाओं से घिरी हुई रही थी। नई आर्थिक नीति के सैद्धान्तिक विरोध के कारण सरकार को उस पर पुनर्विचार करने के लिए बाध्य होना पड़ा। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी 1929 की मन्दी, नाजीवाद का उदय तथा चीन पर जापान द्वारा आक्रमण करने जैसी जो महत्वपूर्ण घटनाएँ इस बीच हुई थी उन्होंने भी परिवर्तन को अनिवार्य बना दिया था। नई आर्थिक नीति के पार्टी के भीतर के आलोचकों का कहना था कि विदेशी सहयोग के अभाव व देश में ही किसानों द्वारा किये जा रहे असहयोग के बावजूद देश को पूरी गति के साथ औद्योगीकरण का कार्यक्रम छेड़ देना चाहिए। इन आलोचकों का यह मानना था कि इस प्रकार के विशाल औद्योगीकरण का कार्यक्रम स्वतन्त्र उपग्रह की सामर्थ्य से बाहर की बात थी।

नई आर्थिक नीति के आलोचकों द्वारा सोचे गये औद्योगीकरण के इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का भार सभी वर्गों पर पड़ा किन्तु यह भार कृषक वर्ग पर सर्वाधिक पड़ा। सरकार के सम्मुख यह बहुत बड़ी समस्या थी क्योंकि उसे औद्योगीकरण के लिए वांछित पूँजी ग्रामीण क्षेत्रों से ही जुटानी थी। किन्तु कृषक वर्ग तो अभी भी उदासीन दिखाई दे रहा था। दूसरी ओर युवा तुर्क (radicals) समाजवादी नियोजन के कार्यक्रम को शीघ्रानिशीघ्र लागू करने पर बल दे रहे थे। युवा तुर्कों का ऐसा मत था कि इस बारे में की जाने वाली कोई भी देरी सोवियत सत्ता के अस्तित्व को ही खतरे में डाल देगी।

सरकार भी अपने उद्योगों के प्रसार कार्यक्रम के बारे में अब अधिक आश्वस्त अनुभव कर रही थी क्योंकि औद्योगिक इकाइयों पर पहले से ही उसका पूर्ण नियन्त्रण हो चुका था। प्रश्न केवल इस कार्यक्रम को गति प्रदान करने का ही था। राज्य योजना आयोग या जिसे गोसप्लान (Gosplan) का नाम दिया गया था, को अधिकतम आर्थिक स्वतन्त्रता का लक्ष्य रखते हुए एक व्यापक कार्यक्रम तैयार करने का कार्य सौंपा गया। पश्चिमी देशों द्वारा इस के प्रति अपनाये गये आक्रामक रुख से इस प्रकार का निर्णय शीघ्रता से लेने के लिए प्रेरणा ही मिली।

लेकिन यह बात कृषि के लिए सही नहीं थी जहाँ सरकार को अपने आप पर

इतना भरोसा नहीं था। 1922 में एक भूमि आचार संहिता (Land Code of 1922) बनाई गई थी जिसमें किसानों को यह याद दिलाया गया कि सारी भूमि सरकार की सम्पत्ति थी हालांकि उसे जोतने वाले किसान उसका पूरा शोषण करने के लिए स्वतन्त्र थे। नये आर्थिक कार्यक्रम में पिछड़ी पड़ो कम्प्यून प्रणाली के स्थान पर कृषि सहकारियों को प्रोत्साहित करने की व्यवस्था को बढ़ावा दिया गया था तथा इन सहकारियों में 6 मिलियन किसान सदस्य भी बन गये थे। इन कृषि सहकारियों के गठन के पीछे उद्देश्य यही था कि निर्धन किसानों की सहायता हो सके तथा एक कुलक वर्ग को पतन से रोका जा सके।

किन्तु सम्पूर्ण नई आर्थिक नीति के कार्यक्रमाल में पूँजीवादी अर्थव्यवस्था अग्रसर होती रही। कम्प्युनिस्टों ने भी इस बात को तो माना कि नई आर्थिक नीति में देश के पुनरुद्धार में सहायता मिली थी किन्तु उनका यह भी खयाल था कि यह सैद्धान्तिक धरातल पर एक तरह का अपसरण या पीछे हटना (ideological retreat) था इस 'सामरिक पश्चगमन' (strategic retreat) के साहसिक कदम तथा उद्योगों की 'निर्णायक ऊँचाइयों' (Commending Heights) पर स्थिर रहने की नीति ने जितनी समस्याएँ हल की उससे अधिक उत्पन्न कर दी। इससे सैद्धान्तिक मतभेद बढ़ गये। बोल्शेविक क्रान्ति जो पूर्ण साम्यवाद के माथ आरम्भ हुई थी अब पूँजीवाद को रियायतें देकर समाप्त हो रही थी। इस बारे में कुछ भी तय नहीं था कि कब यह सक्रमणकारीन नीतियों का दौर समाप्त होगा तथा कब विशुद्ध समाजवाद आ पायेगा।¹

नई आर्थिक नीति का योगदान

सोवियत अर्थव्यवस्था पर अपनी प्रतिनिध्या व्यक्त करने वाले अधिकांश लेखकों का यह मत रहा है कि नई आर्थिक नीति ने आर्थिक स्थायित्व की पुनर्स्थापना की दिशा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। नई आर्थिक नीति कोई ऐसा कदम नहीं थी जिसे सोवियत जनता पर थोपा गया हो। जैसा कि डॉब ने लिखा है, 'नई आर्थिक नीति कोई अनोखी चीज नहीं थी जिसे रातों-रात ऐसे मन्त्रियों पर थोप दिया गया हो जो उसके निये अजनबी थे और जो पुरानी सत्ता पर प्रत्यक्ष आक्रमण के प्रयास में असफल होने पर लाई गई हो।' जैसा कि स्वयं लेनिन ने 1918 में कहा था कि वर्तमान में देश में नीचे बुर्जुआ किस्म का पूँजीवाद प्रचलित है किन्तु यह वही एकमात्र सड़क है जो बड़े पैमाने पर किये जाने वाले राजकीय पूँजीवाद तथा समाजवाद की ओर जाती है और इसके जाने के रास्ते में वही एक जैसा मध्यवर्ती स्टेशन 'राष्ट्रीय लेखा (National accounting) तथा उत्पादन एवं वितरण के साधनों पर नियन्त्रण' पड़ता है।¹

नई आर्थिक नीति के काल में हुए इस पुनरुद्धार के अलावा इस अवधि में रोजगार बढ़ा, मजदूरी में वृद्धि हुई तथा काम की दशाओं में सुधार हुआ। व्यापार का न केवल पुनरुद्धार हुआ बल्कि उसमें थोड़ी बहुत समृद्धि भी आई। इन घटनाओं ने देश और विदेश के लोगों को आश्चर्य में डाल दिया।

तुलनात्मक उत्पादन, 1913-1928

उत्पादन	1913	1928
लोह पिंड (मिलियन टन)	42	33
इस्पात "	42	43
कोयला "	291	355
सीमेट "	15	18
अनाज "	820	730
सूती वस्त्र (मिलियन मीटर)	2270	27420

किन्तु नई आर्थिक नीति के प्रति मूल उदासीनता वैचारिक घरातल पर थी। क्रान्ति का सम्पूर्ण उद्देश्य ही समाप्त हो चुका होता यदि देश का फिर उन्ही निजी व्यावसायिकों (nepmen) द्वारा चलाया जाने के लिए छोड़ दिया जाता। कई लोगो को भय था कि निजी व्यवसायी क्रान्ति से प्राप्त लाभो को नष्ट कर देंगे। लोग लाभ पाने तथा जल्दी से जल्दी धनी बन जाने के लोभ का सवरण नहीं कर पा रहे थे। इसमें भी अधिक शोचनीय बात ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही थी जहाँ सरकार को साम्यवादी विचारधारा की बलि देकर किसानों को गिरावले देनी पड़ रही थी। मजदूरी के बढ़ने लोगो को काम पर रखने तथा व्यक्तिगत कृषको को लगान के बढ़ने अधिक भूमि दे सकने की व्यवस्थाओं का भी पार्टी के कट्टर सदस्यों में विरोध किया। इस बारे में एक रोचक बात यह रही कि इस सारे मतभेद के वातावरण में स्टालिन ने पहले तो मध्य मार्ग अपनाया किन्तु बाद में सब को स्तब्ध कर दिया।

किसान करो की धोरी करने लाग गये थे। पाँच वर्ष में करो की बकाया धनराशि कुल राशि का 45 प्रतिशत हो चुकी थी। इससे सरकार को बड़ी कठिनाई हुई। अनाज के बाजार में सट्टेबाजी की प्रवृत्ति के फैल जाने से सरकार और क्रुद्ध हो गई। बड़े हुए मूल्यों का लाभ उठाने के लिए समृद्ध किसान सरकारी आदेशों की अवहेलना करने लगे। छोटे किसानों से अतिरिक्त अनाज का ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर अधिग्रहण करना कठिन बनता जा रहा था। समाजीकृत कृषि (socialised agriculture) से कम स्तर का कोई भी उपाय इन समस्याओं का हल नहीं कर सकता था। इस तरह नई आर्थिक नीति जो वास्तविक अर्थों में सफल हो गई थी, वैचारिक घरातल पर परास्त हो गई। साम्यवादी सरकार भविष्यतः इस को कम से कम सम्भव समय में विश्व की अग्रणी औद्योगिक शक्ति के रूप में देखना चाहती थी और मर्यादित नई आर्थिक नीति इसका कोई उत्तर नहीं बन सकती थी।

चौथा अध्याय

कैंची संकट

(THE SCISSORS CRISIS)

नई आर्थिक नीति का एक प्रमुख उद्देश्य 'स्मिचका' (Smychka) की स्थापना करना था अर्थात् किसानों तथा औद्योगिक श्रमिकों के बीच एक प्रकार की एकता या सघ का निर्माण। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसानों को कई रियायतें भी दी गयीं। किन्तु 1923 के अन्त में स्थिति काफी जटिल बन गई जब प्रसिद्ध कैंची संकट (scissors crisis) तथा उसके ठीक बाद 'समापन संकट' (liquidation crisis) के कारण सोवियत अर्थव्यवस्था के सम्मुख अभूतपूर्व परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गयीं। इन परिस्थितियों ने साम्यवादी दल के भीतर ही परस्पर विरोधी पक्षों को उभारा। प्रश्न यह था कि औद्योगिक एवं कृषि मूल्यों के सम्बन्ध में क्या दृष्टिकोण अपनाया जाये? स्मिचका (Smychka) या मजदूर-किसान एकता का भविष्य इस प्रश्न के सही समाधान पर निर्भर करता था। इतना ही नहीं, यह कैंची संकट तब उत्पन्न हुआ था जब देश ने नई आर्थिक नीति के अन्तर्गत अपने पुनरुद्धार के लिए एक आर्थिक कार्यक्रम आरम्भ किया ही था।

मॉरिस डॉव ने कैंची संकट का बड़े विस्तार में विश्लेषण किया है। रूसी अर्थव्यवस्था पर लिखने वाले कई अन्य लेखकों ने भी इस विचित्र आर्थिक घटना पर अपना ध्यान केन्द्रित किया है। वैसे देखा जाये तो कैंची (scissors) की घटना तथा उससे पैदा होने वाला संकट अपने आप में काफी सीधी-सादी चीज थे लेकिन इसके कारणों तथा परिणामों ने उसे काफी जटिल बना दिया था। 1922 के मध्य के बाद, जबकि औद्योगिक व कृषि पदार्थों के मूल्य लगभग 1913 से पूर्व के आनुपातिक स्तर पर मिल गये थे, दो परस्पर विरोधी प्रवृत्तियाँ विकसित होने लगी। जहाँ एक ओर कृषि पदार्थों के मूल्य गिरे वहीं दूसरी ओर निर्मित वस्तुओं (manufactured goods) के मूल्य चढ़ते चले गये। और इन दोनों मूल्य स्तरों ने बीच अन्तर बढ़ता बढ़ता गया—अर्थात् कैंची के दोनों फलक (the two blades of the scissors) अधिक से अधिक खुलते रहे। जब कैंची के ये दोनों फलक एक दूसरे से सबसे अधिक दूरी पर थे तब केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय का थोक मूल्य निर्देशक कृषिगत पदार्थों के लिए 89 तथा औद्योगिक वस्तुओं के लिए 276 था (1913=100)। यद्यपि में स्थिति कृषि पदार्थों के लिए और अधिक प्रतिकूल थी। थोक व खुदरा कृषि मूल्यों के बीच भी भारी अन्तर था तथा खुदरा औद्योगिक वस्तुओं के मूल्य और भी ऊँचे थे।

औद्योगिक एवं कृषि पदार्थों के लिए मूल्य निर्देशांक (1913=100)

वर्ष	कृषि पदार्थ	औद्योगिक वस्तुएँ
जनवरी 1922	104	92
अप्रैल 1922	109	82
अगस्त 1922	100.5	99
सितम्बर 1922	94	112
फरवरी 1923	88.8	276

कँची सकट ने 1923 में ही एक अन्य सकट को जन्म दिया जिसे 'विक्री सकट' के नाम से जाना गया। किसानों को एक बार पुनः यह महसूस होने लगा कि उन्हें उनकी चीजों का सही मूल्य नहीं मिल रहा है। उन्होंने इस स्थिति का डटकर मुकाबला किया। उन्होंने निर्मित माल अर्थात् औद्योगिक वस्तुओं की खरीद ही बन्द कर दी। ये औद्योगिक वस्तुएँ किसानों के लिए आवश्यक भी नहीं थी इसलिए उनके लिए इनकी माँग काफी लोचदार थी। किमान इन चीजों के स्थानीय कारीगरों या कुटीर उद्योगों पर निर्भर कर सकते थे। वे अपनी कृषिगत वस्तुओं को औद्योगिक वस्तुओं के बदले बेचने के लिए तभी राजी थे जब उन्हें उनकी वस्तुओं का सही मूल्य दिया जाता। इस सन्दर्भ में शहरी जनसंख्या की, ओकि ये सारी निर्मित चीजें तैयार करती थी, स्थिति अपेक्षाकृत अधिक खराब थी। ऐसा इसलिए था कि जब तक किसान, अपनी वस्तुओं के बदले निर्मित माल नहीं खरीदते तब तक शहरी लोगों के लिए खाद्य पदार्थ कहाँ से आते? इसलिए स्थिति और भी जटिल बन गई।

औद्योगिक वस्तुओं के मूल्य चढ़ने के कारण

(i) ऊपर के खर्च ऊँचे होना (Higher overhead expenses)—नई आर्थिक नीति के प्रारम्भिक कार्यकाल में उद्योगों ने अपना उत्पादन बढ़ाना आरम्भ किया ही था और वे अपनी उत्पादन क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर पाये थे। इससे स्वामाविक रूप से उनकी चीजों पर ऊपरी लागत काफी ऊँची पड़ती थी।

(ii) ढीला संगठन—उत्पादन का संगठन बड़े ढीले तरीके से किया जाता था तथा प्रशासन अकुशल एवं खर्चीला दोनों ही था। इसमें औद्योगिक वस्तुओं की उत्पादन लागत और भी बढ़ गई थी।

(iii) ट्रस्टों द्वारा मुनाफाखोरी—औद्योगिक ट्रस्ट (जो नई आर्थिक नीति के अन्तर्गत बनाये गये थे) अपनी कार्यशील पूँजी बढ़ाने की जल्दी में लाभ बढ़ाकर उसे पाने की चेष्टा करने लगे थे।

(iv) ट्रस्टों का एकाधिकार—विदेशी प्रतिस्पर्द्धा के समाप्त कर दिये जाने से सोवियत औद्योगिक ट्रस्टों को एकाधिकारिक स्थिति प्राप्त हो गयी जिसके परिणाम-स्वरूप वे मूल्यों को मनमाने ढंग में ऊँचा रख रहे थे।

(v) सग्रह—राज्य द्वारा दी जा रही साख मुविषा ने इन ट्रस्टों को अपनी

चीजों का भण्डार रखने की स्थिति में ला दिया। वे अपनी चीजें फसल कटने के समय बेचते जब किसानों की सौदेबाजी की शक्ति सबसे कम होती। उधर खुदरा व्यापार में लाभ की दर अभी भी काफी ऊँची थी क्योंकि वह मुख्य रूप से निजी व्यवसायियों (Nepmen) के हाथों में था।

कृषि पदार्थों के मूल्य में गिरावट के कारण

(i) तेजी से पुनरुद्धार—कृषि उत्पादन का औद्योगिक उत्पादन की तुलना में बहुत तेजी से पुनरुद्धार हो गया था क्योंकि गृह-युद्ध के दौरान व उससे पहले भी कृषि की बहुत कम आधारभूत पूँजी ही नष्ट हुई थी।

(ii) अपरिवर्तित सगठन—भूमि का राष्ट्रीयकरण कर दिये जाने के बाद भी कृषि में कोई परिवर्तन नहीं आया। कृषि उत्पादन का सगठन भी अप्रभावित ही रहा।

(iii) वस्तुओं के रूप में कर—वस्तुओं के रूप में किसानों से वसूल किये जाने वाले कृषि-कर से शहरी जनसंख्या को खाली-भूति का एक आधार (cushion) तो मिल ही जाता था और किमान उनके पास शेष रहने वाले अतिरिक्त पर अपनी इच्छानुसार मूल्य नहीं ले पाते थे।

(iv) व्यक्तिगत बिच्री—किसान तो अपना उत्पादन व्यक्तिगत रूप से ही बेचते थे जबकि उसे खरीदने वाली संस्थाएँ, जैसे सहकारियाँ, बड़ी संस्थाएँ होती थी।

(v) सतृप्त (Saturated) बाजार—कृषि पदार्थों का निर्यात बहुत धीरे बढ़ा तथा इन वस्तुओं के लिए आन्तरिक बाजार पहले ही बहुत सतृप्त हो चुका था।

(vi) मुद्रा की आवश्यकता—सेतो पर काम आने वाले औजार इतने पुराने पड़ चुके थे कि उन्हें बदलने की आवश्यकता थी। इसका परिणाम यह हुआ कि इन निर्मित उपकरणों को खरीदने के लिए किसानों की नकद रूप में मुद्रा की बहुत तीव्र आवश्यकता पड़ने लगी।

(vii) कम अवसर—अभावग्रस्त निर्मित वस्तुओं को खरीद पाने के किसानों के पास कम अवसर थे। सहकारियों आदि का जाल भी शहरो में ही अधिक केन्द्रित था।

इस तरह यही ऊँची औद्योगिक कीमतों तथा नीची कृषि कीमतों के मिले-जुले कारण 'कैची सकट' के मूक में थे। इस सकट ने औद्योगिक व कृषि उत्पादन के आगे बढ़ने में बाधा उपस्थित की। राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो इसने 'स्मिचका' (Smychka) अर्थात् किसान-मजदूर एकता को ही खतरे में डाल दिया। कैची के इन फलकों को बन्द करना जरूरी था किन्तु प्रश्न यह था कि उन्हें बन्द किस तरह किया जाए? अगर कृषिगत पदार्थों के मूल्य बढ़ाने का निर्णय लिया जाता तो उसका परिणाम यह होता कि औद्योगिक थमिकों की वास्तविक मजदूरी घट जाती। या, दूसरे अर्थ में निर्मित वस्तुओं की निर्माण-लागत और बढ़ जाती क्योंकि उसमें औद्योगिक मजदूरों को दिये जाने वाले वृद्धिगत वेतन भुगतानों को और जोड़ देना पड़ता। इससे पूँजी मचय की दर में भी कमी आ जाने का खतरा था जोकि उद्योग

के पुनर्निर्माण के लिए अत्यावश्यक थी। इसके अतिरिक्त इससे कृषिगत पदार्थों के निर्यात की सम्भावनाएँ कम हो सकती थीं जिससे अत्यावश्यक मशीनरी के आयात को घटाना पड़ता। कृषि मूल्यों को बढ़ाने की बात में एक राजनीतिक मुद्दा भी अटका पड़ा था क्योंकि इस प्रकार की मूल्य-वृद्धि का लाभ सम्पन्न किसानों (Kulaks) को ही होने की सम्भावना थी क्योंकि बाजार में लाने योग्य अतिरिक्त अनाज केवल उन्हीं के पास था। दूसरी ओर औद्योगिक वस्तुओं के मूल्यों में कमी से पूँजी संचय की दर घटने की सम्भावना थी जिससे उद्योगों का पुनरुद्धार होने में बाधा आ सकती थी।

खुदरा व्यापार में निजी व्यावसायियों की उपस्थिति एक अन्य समस्या थी। औद्योगिक वस्तुओं के मूल्य में की जाने वाली कोई भी कटौती इन खुदरा निजी व्यापारियों के माध्यम से ही हो सकती थी। इस प्रकार औद्योगिक वस्तुओं के थोक मूल्य में कटौती करना, और वह भी बिना इस बात की गारण्टी के कि वह कभी खुदरा मूल्यों को भी कम कर सकेगी। निजी व्यापारियों की लाभशीलता को ही बढ़ाने का काम होता जो कि सरकार की नीतियों के विरुद्ध होता। इसके अतिरिक्त तत्कालीन परिस्थितियों में एकदम से निजी व्यापारियों की जगह सहकारियों या राजकीय निगमों का जाल बिछा देना भी सम्भव नहीं था। इन सभी बातों को देखते हुए पार्टी उद्योग व कृषि के सम्बन्धों, कुलकों (Kulaks) के भाग्य, निजी पूँजी के मामले, उद्योग का विकास करने की सम्भावना, तथा समाजवाद की स्थापना को लेकर आपस में ही बँटी हुई थी। यह सारा कार्य बिना बाह्य सहायता के किया जाना था।

तेरहवीं पार्टी कांग्रेस, जो 1924 में हुई, ने इस बारे में निम्न मत व्यक्त किया—

(i) निजी व्यापार के विकास पर सहकारी व राजकीय व्यापार को और अधिक मजबूत बनाकर नियन्त्रण लगाया जाना चाहिए।

(ii) कैंची के फलकों को औद्योगिक वस्तुओं का मूल्य कम कर बन्द किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त थोक व खुदरा मूल्यों के बीच के भारी अन्तर को कम करने, मूल्यों पर अधिक बड़ा नियमन करके, तथा कृषि पदार्थों के सरकारी मूल्य बढ़ाकर भी इस कैंची सकट को दूर किया जाना चाहिए।

(iii) व्यापार के सामान्य नियोजन के वर्तमान तत्त्वों को सिंडिकेटों (industrial syndicates) व सहकारियों के बीच अनुबन्धों के द्वारा सुदृढ़ बनाया चाहिए। कृषि पदार्थों के वितरण का कार्य और भी अधिक सहकारियों व राजकीय संस्थाओं के हाथों में केन्द्रित किया जाना चाहिए तथा निजी व्यापारियों को कृषिगत वस्तुओं का व्यवसाय करने से निकाल बाहर कर देना चाहिए। बाद में निमित्त वस्तुओं के व्यापार से भी निजी व्यापारियों को बाहर निकाल दिया जाना चाहिए।

कैंची सकट व बिजनी सरट (scissors and sales crisis) को हल करने के उद्देश्य में सरकार ने औद्योगिक वस्तुओं के मूल्य कम करने हेतु तीन उपाय किये—

(i) उद्योगों को दी जाने वाली बैंक साव में काफी कटौती कर दी गई। इस

उपाय ने औद्योगिक ट्रस्टों व व्यावसायिक सिंडिकेटों को उनकी जमा वस्तुओं को बेचने के लिए बाध्य कर दिया।

(ii) आन्तरिक व्यापार समिति गठित की गई जिसका उद्देश्य अधिकतम बिक्री मूल्य तय करना था।

(iii) कुछ मामलों में वस्तु हस्तक्षेप (goods intervention) की नीति अपनायी गई। इस नीति के अन्तर्गत कुछ कम मूल्य वाली वस्तुओं का विदेशों से आयात किया गया ताकि औद्योगिक सिंडिकेटों पर दबाव डाला जा सके।

निर्मित माल की उत्पादन लागत घटाने के भी उपाय किये गये। कई महत्वपूर्ण कारखानों में उनकी स्थापित क्षमता से काफी कम काम हो रहा था। उन कारखानों का उत्पादन बढ़ाया गया तथा उत्पादन अधिक कार्य-कुशल कारखानों में केन्द्रित किया गया। इन उपायों से काफी सफलता मिली और 1924 तक औद्योगिक लागतों में 20 प्रतिशत की गिरावट आयी। कैंची के फलक बन्द होने लगे। औद्योगिक एवं कृषि मूल्यों के बीच अनुपात जोकि सितम्बर 1923 में 3 : 1 तक पहुँच चुका था, अक्टूबर 1924 तक गिरकर 1 : 5 : 1 पर आ गया। औद्योगिक वस्तुओं के मूल्यों में गिरावट के साथ औद्योगिक उत्पादन में भी वृद्धि हुई।

पाँचवाँ अध्याय

सामूहिक खेती व कृषि का विकास

(COLLECTIVE FARMING AND THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE)

जारशाही रूस ने सोवियत रूस के लिए कृषि की बड़ी कठिन विरासत छोड़ी। एक ऐसे देश में जहाँ की 80 प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में रहती थी और कृषि कार्यों में लगी हुई थी भूमि का स्वामित्व भूस्वामियों, धार्मिक मठों, जार व उसके परिवार के सदस्यों तथा कुलक (Kulaks) लोगों के हाथों में था। भूस्वामियों के एक छोटे से समुदाय का देश की कुल भूमि के 63 प्रतिशत क्षेत्र पर अधिकार था। निम्नांकित तालिका में 19वीं शताब्दी के अन्त में रूस में भूमि के वितरण की स्थिति को दर्शाया गया है—

रूस में भू-सम्पत्ति का वितरण

भू-स्वामी	मिलियन हेक्टेयर	परिवारों की संख्या, (कुल का प्रतिशत)
जमींदार, मठ तथा जार का परिवार	152	—
कुलक	80	15
गरीब व मध्यम किसान	135	85

रूस के¹ कृषक वर्ग (peasantry) में कुलक लोगों का कुल परिवारों में प्रतिशत 15 था, मध्यम श्रेणी के किसानों का 20 प्रतिशत तथा गरीब श्रेणी के किसान 65 प्रतिशत थे। कृषि अत्यधिक पिछड़ी हुई अवस्था में थी, कमर तोड़ देने वाला शारीरिक काम प्रचलित था तथा खेती करने के तरीके भी आदिम व पुरातन-पथी थे। कृषि-दास प्रथा (serfdom) अभी भी विद्यमान थी और निर्धनता का अखंड साम्राज्य था। अक्टूबर 1917 की लाल क्रांति होने तक ऐसी ही स्थिति थी।

सोवियत सरकार का पहला कदम, जैसा कि हम देख चुके हैं भूमि पर एक आदेश (decree) जारी करना था जिससे समस्त भूमि का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इस आदेश में घोषणा की गई कि 'आज के बाद भूमि बेचने, खरीदने, लीज (lease) पर उठाने, रहन रहने या उसका किसी भी तरह से अलगाव (alienation) करने की मनाही होगी।' भूस्वामियों को किसी प्रकार का मुजावजा नहीं दिया गया।

¹ G. M. Papov, *The Soviet Planned Economy* (Compiled), 1974 50-75

भूमि सरकारी सम्पत्ति बन गई तथा उसे उपयोग के लिए मुफ्त में किसानों को सौंप दिया गया। इस तरह किसानों को लगभग 150 मिलियन हैक्टेयर भूमि कृषि कार्यों के लिए प्राप्त हुई। किसानों पर जो 1500 मिलियन रूबल के ऋण थे उन्हें भी समाप्त घोषित कर दिया। लेनिन ने लिखा, 'सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद के अन्तर्गत पहली बार किसान स्वयं अपने लिए काम कर रहा है तथा अपना निर्वाह शहरों में रहने वालों से भी ज्यादा अच्छी तरह कर रहा है। किसान ने पहली बार वास्तविक स्वतन्त्रता के दर्शन किये हैं—उसकी अपनी रोटी खा सकने की स्वतन्त्रता, भूख से स्वतन्त्रता।'।

लेनिन की सहकारिता योजना

लेकिन इन भूमि-सुधारों से कृषि की कम उत्पादकता तथा बाजार के लिए बहुत छोटे पैमाने पर उत्पादन जैसी समस्याओं के कारण दूर नहीं हो गये थे। ऐसा इसलिए हुआ कि कृषि-क्षेत्र अभी भी बिखरा हुआ था तथा उसका स्वामित्व व उस पर कार्य करने का अधिकार निजी व्यक्तियों के हाथ में ही था। निम्न-प्रकार के क्षेत्र उस समय की कृषि में विद्यमान थे—(1) छोटे पैमाने के वस्तु एवं जीवन-निर्वाह कृषक फार्म, (2) मध्यवर्गीय कृषक फार्म तथा बड़े कुलक फार्म जिनमें बाजार के लिए काफी मात्रा में उत्पादन होता था, तथा (3) राजकीय फार्म व कम्यून (communes) जिन्हें बड़ी भू-जागीरों में से पुनर्गठित किया गया था।

मुख्य समस्या करोड़ों किसानों को जो बहुत ही छोटे कृषक थे, शोषण से बचाने की थी। इसके साथ ही उत्पादन में भी वृद्धि करनी थी। लेनिन का विश्वास था कि किसानों को सहकारी सगठनों में सम्मिलित करके, पहले विपणन सहकारियों व बाद में उत्पादन सहकारियों में, किसानों को छोटे पैमाने की व्यक्तिगत खेती से बड़े पैमाने की सामूहिक खेती की दिशा में जाने के लिए अधिक आसानी से तैयार किया जा सकता है। इससे किसानों व मजदूरों में भेद और एकता भी मजबूत हो सकेगी।

लेनिन ने पूँजीवादी तरीके के अन्तर्गत अपनायी जा रही सहकारिता तथा सोवियत व्यवस्था के अन्तर्गत अपनायी जाने वाली सहकारिता में महत्वपूर्ण अन्तर बताया। उमने लिखा 'सर्वहारा वर्ग की राज्य सत्ता पर विजय के बाद सहकारियों (cooperatives) की स्थिति में एक आधारभूत परिवर्तन आ जाता है। यहाँ पर सत्ता के स्थान पर गुणात्मक पहलू पर अधिक जोर दिया जाता है। सहकारी सत्ता जो पूँजीवादी समाज में एक लघुकाय द्वीप है, छोटी-सी दुकान की तरह होती है। वहीं सहकारी सत्ता, जब वह सारे समाज को अपनी बाहों में ले लेती है, जिसमें भूमि का समाजीकरण तथा कारखानों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है, समाजवाद कहलाती है।'।

सामूहिकीकरण (Collectivisation)

नई आर्थिक नीति के कार्यकाल में किसानों को दी गई वित्तीय एवं सगठनात्मक सहायता से 1928 तक उनकी भौतिक दशाओं में सुधार होने की दृष्टि से काफी

अच्छे परिणाम निकले थे। निर्धन कहे जाने वाले किसानों की सरया घटकर 35 प्रतिशत रह गई थी जबकि मध्यम वर्ग के किसान परिवार बढ़कर 60 प्रतिशत हो गये थे। कृषि में सहकारिता का भी विकास माथ ही साथ हो रहा था। यह आंशिक रूप से स्वेच्छापूर्वक था तथा आंशिक रूप से पार्टी के दबाव से हुआ था। सामूहिक खेत (collective farms) तथा राजकीय खेत (state farms) कृषि उत्पादन की आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना प्रारम्भ कर चुके थे। माथ ही ट्रैक्टर तथा अन्य कृषि उपकरणों का उत्पादन करने वाले आधुनिक उद्योग भी बड़ी तेजी से निर्मित किये जा रहे थे। राज्य मशीन एवं ट्रैक्टर स्टेशन (Machine Tractor Stations) जिन्हें 1928 में गठित किया गया था, सामूहिक फार्म व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में सहायक हो रहे थे। एक लम्बे समय तक उन्होंने सामूहिक फार्मों को उत्पादन सम्बन्धी व अन्य तकनीकी सेवाएँ प्रदान कीं। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में नये औद्योगिक तरीकों को ले जाने में भी सहायता की।

कृषि क्षेत्र में हुए इन स्वस्थ परम्पराओं के विकास के बावजूद सोवियत सरकार ने सर्दी के मौसम की 1928 की बुवाई तथा 1929 की वसन्त ऋतु की बुवाई के समय यह देखा कि सम्पन्न किसान कृषि उत्पादन में कटौती करने की अपनी नीति को जारी रख रहे हैं। यह स्पष्ट हो गया कि बिना कुछ आपतकालीन कदम उठाये कृषि के वांछित उत्पादन भण्डार प्राप्त कर पाना सम्भव नहीं होगा। इस दृष्टि से, 1929 की गर्मी में, बड़े पैमाने की सामूहिक खेती (large-scale collective farming) शुरू करके कुलक लोगों के प्रतिरोध को समाप्त करने का निश्चय किया गया। यह तय किया गया कि अब 'कुलक लोगों की शोषण परस्त गतिविधियों पर नियन्त्रण लगाने की नीतियों के स्थान पर कुलक वर्ग का खारजा कर देने की नीति अपनाने की आवश्यकता है।' इस नीति सम्बन्धी परिवर्तन को, जिसमें समृद्ध कृषकों (Kulaks) को समाप्त किया जाना था, कृषि के क्षेत्र में दूसरी महान कृषि-क्रान्ति कहा गया। 1918 में जमीन का निजी स्वामित्व समाप्त किया ही जा चुका था हालाँकि कृषि व्यक्तिगत खेती के मिद्वान्त के आधार पर ही चलती रही थी। अब धनी-मानी कृषकों को सफ़ट करने का निर्णय कर लिया।

इस प्रकार 1929-30 तक राष्ट्रव्यापी सामूहिकीकरण करने के लिए आवश्यक सभी राजनीतिक एवं आर्थिक पूर्व-शर्तें पूरी हो जा चुकी थी। 1929 से 1935 के बीच सम्पूर्ण कृषक समुदाय को सामूहिक खेतों में अन्तर्गत ले जाया गया। लाखों-करोड़ों छोटे-छोटे व्यक्तिगत कृषक परिवारों के खेतों के स्थान पर सोवियत यूनियन में 2,43,500 सामूहिक फार्म बना दिये गये। राजकीय फार्मों की संख्या भी 4,000 तक पहुँच गई।

इस तरह धीरे-धीरे जो सामूहिकीकरण हुआ उसमें एक ओर तो सरकारी उपायों का दबाव रहा तथा दूसरी तरफ कृषक समुदाय द्वारा कुछ स्वेच्छापूर्वक किये गये प्रयास भी इस दिशा में सामने आये। सरकार ने समृद्ध कृषकों या कुलक लोगों के खारजे के लिए निम्न उपाय किये—

(1) पार्टी संगठन को सामूहिकीकरण आन्दोलन में भाग लेकर सामूहिक

खेत (Kolkhoz) निर्धन के निर्माण में सहायता करने के निर्देश दिये गये। गरीब किसानों को संगठित करने को विशेष महत्त्व दिया गया।

(2) ट्रेड यूनियनों को भी कोलखोज आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने को कहा गया।

(3) एक ऑल यूनियन सेंटर ऑफ मशीन ट्रेक्टर स्टेशन गठित किया गया तथा इन मशीन ट्रेक्टर स्टेशनों (M T S) को हर जिले में सामूहिकीकरण की स्थापना में अग्रणी रहने की भूमिका सौंपी गई।

(4) ट्रेक्टर व अन्य कृषि मशीनें तैयार करने वाले उद्योगों का तेजी से विकास करने का कार्यक्रम बनाया गया।

(5) एक कृषि कमिसारियत (Commissariat of Agriculture) स्थापित की गई जिसका काम बड़े राजकीय फार्मों, सामूहिक फार्मों तथा मशीन ट्रेक्टर स्टेशनों के बीच समन्वय स्थापित करना था।

(6) यह आदेश जारी किया गया कि सामूहिक फार्मों का मूल स्वरूप कृषि आर्टेल (Artel) का होगा जिसमें हर चीज का सभाजीकरण किया जायेगा।

सरकार द्वारा घोषित इन उपायों के बावजूद सामूहिकीकरण (collectivisation) ने किसानों के ही बीच भारी झगड़ों व संघर्षों की स्थिति पैदा कर दी। कुलको तथा निर्धन किसानों दोनों ही के द्वारा हत्याएँ, लूट-पाट व आगजनी की घटनाएँ की गयीं। इस तरह सामूहिकीकरण के इस तूफानी दौर ने, जिसमें स्थानीय अधिकारीगणों तथा अति उत्साही किसानों द्वारा कई ज्यादतियाँ भी की गईं राष्ट्र-व्यापी सामूहिकीकरण के प्रथम चरण में कृषि उत्पादन के विकास पर विपरीत प्रभाव डाला। सबसे महत्त्वपूर्ण हुए दुःप्रभाव पशुओं की सरया घट जाने तथा अनाज के उत्पादन में कमी हो जाने के रूप में परिलक्षित हुए जो 1933 तक चलते रहे।

पुनः एक बार सरकार ने अनेक ऐसे उपाय किये कि जिनसे उस समय सामूहिक फार्मों के सामने आ रही कठिनाइयों को दूर किया जा सकता। खेती के मौसम में काम की गति तथा उसके गुणात्मक पहलू पर कड़ा निरीक्षण लागू कर दिया गया। जटिल कृषि मशीनों को सामूहिक फार्मों से हटा दिया गया तथा उन्हें मशीन ट्रेक्टर स्टेशनों पर रख दिया गया। भू-धारण अधिकारों को स्थायित्व प्रदान करने तथा बहुत विशाल सामूहिक फार्मों को छोटी इकाइयों में विभक्त करने सम्बन्धी उपाय भी किये गये। सामूहिक कृषकों (collective farmers) के कुछ विशिष्ट समूहों पर कुछ विशिष्ट काम पूरा करने का उत्तरदायित्व सौंप दिया गया।

धीरे-धीरे पारिथमिक देने में किसानों के काम व दक्षता को भी मान्यता दी गई। राज्य बसूलों का तरीका भी 1933 में बदला गया। सामूहिक फार्मों पर राज्य को प्रति हेक्टेयर एक पूर्व विशिष्ट मात्रा में अनाज देने की व्यवस्था लागू की गयी। 1933 में ही सामूहिक फार्मों को व्यापार करने की भी कानूनी स्वीकृति दे दी गई। इसके अलावा सामूहिक फार्मों, उनके सदस्यों तथा व्यक्तिगत कृषकों द्वारा व्यापार 'बाजार में प्रचलित मूल्यों' पर किया जा सकता था। इस उपाय से यह प्रत्यागा की गई थी कि कोलखोज (collective farm) पर कार्यरत किसानों को आर्थिक पहल करने में

प्रेरणा मिल सकेगी तथा 'शहरी आबादी के लिए कृषि पदार्थों की आपूर्ति का एक अतिरिक्त स्रोत' खुल जायेगा। फरवरी 1933 में स्टालिन ने एक नये का उद्घोष किया—'सभी सामूहिक खेतीहरो को समृद्ध बनाओ।'

प्रत्येक सामूहिक कृषक¹ (collective farmer) तथा बाद में कृषि मजदूरों को दिये गये इस अधिकार ने, कि वे अपने छोटे से टुकड़े पर अलग से खेती कर सकते थे, कृषक परिवारों की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने की समस्या हल कर दी। इस रियायत का कई सामूहिक कृषकों द्वारा दुरुपयोग किया गया व उन्होंने सामूहिक खेत पर काम करने की अपेक्षा अपने टुकड़ों पर अधिक समय देने की चेष्टा की। उन्होंने कोलखोज पर होने वाले उत्पादन में भी अधिक से अधिक हिस्सा मार लेने का भी चेष्टा की। कोलखोज की फसल की चोरी तथा उसकी सम्पत्ति की भी चोर्गियां सामान्य बात हो गई थी।

सामूहिक खेतों की कार्य प्रणाली में 1933-35 के बीच भारी परिवर्तन किये गये। सामूहिक खेतों के नेतृत्व व नियन्त्रण को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से विशेष राजनीतिक टुकड़ियां भेजी गयीं। कोलखोज की सम्पत्ति की सुरक्षा के कड़े प्रवन्ध किये गये। कृषि कार्य में बाधा डालने पर कड़ी सजा की व्यवस्था की गई तथा सामूहिक खेत के काम की चोरी पर भी दण्ड की व्यवस्था की गई। फसलों की समय पर बुवाई व कटाई कराने के लिए भी कड़े उपाय किये गये।

इन सभी उपायों से कृषि उत्पादन में काफी वृद्धि हो गई। सक्षेप में, सामूहिक खेतों पर ईमानदारी से काम के आधार पर कृषि उत्पादन के विकास की दशाएं पैदा की गयीं। 1933 के बाद कृषि उत्पादन लगातार बढ़ता रहा। इस वृद्धि के परिणाम-स्वरूप 1935 में कृषि पदार्थों पर लगी हुई राशनिंग व्यवस्था हटा ली गई।

सामूहिक खेतों से लाभ

(1) सामूहिकीकरण ने कृषि उत्पादन को आधुनिक वैज्ञानिक एवं तकनीकी आधार पर सम्भव बनाया तथा कई अन्य ग्रामीण समस्याओं के सफलतापूर्वक समाधान में सहायता की।

(2) राजनीतिक दृष्टि से देखा जाये तो सामूहिक फार्म प्रणाली ने सोवियत राज्य को शक्तिशाली बनाया। उन्होंने मजदूरों व किसानों के बीच मैत्री व एकता को भी मजबूत किया तथा किसानों द्वारा अपने मामले स्वयं निपटाने के लिए परिस्थितियां पैदा की।

(3) आर्थिक दृष्टि से सामूहिक खेती व्यवस्था ने बड़े पैमाने के उत्पादन के लाभ को सोवियत कृषि की पहुँच के भीतर ला दिया।

(4) सामाजिक दृष्टि से सामूहिक फार्म व्यवस्था ने किसानों को निर्धनता व शोषण से मुक्त करवाने में सहायता की। इसने ग्रामीण अंचलों में एक नये वर्गहीन समाज की स्थापना करने में भी सहायता की। इसी का एक परिणाम यह भी हुआ कि गाँवों में शिक्षकों, शस्त्र वैज्ञानिकों (agronomists), पशु चिकित्सकों व इंजीनियरों जैसे

बुद्धिजीवियों का एक वर्ग तैयार हो गया। 1940 में ऐसे लोगों की संख्या सामूहिक व राजकीय फार्मों पर कुल मिला कर 15 लाख हो चुकी थी।

सामूहिक खेतों का पुनर्गठन

1938 में कुछ नये कानून लाये गये जो सामूहिक फार्मों का संविधान बने तथा जिनसे सामूहिक फार्मों के आन्तरिक संगठन के नियमन का तथा सामूहिक कृषकों का उनके सामूहिक फार्मों का सदस्य होने की हैसियत से व उनकी अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था के स्वामियों की हैसियत से प्राप्त अधिकारों के नियमन का उद्देश्य पूरा किया गया। निम्न कानून (statutes) सर्वाधिक महत्व के रहे—

(1) कोलखोज भू-धारण (kolkhoz tenure) को अन्तिम रूप से तय कर दिया गया। इस सम्बन्ध में लाये गये विधेयक में कहा गया 'आर्टेल (artel) के अधिकार-क्षेत्र वाली भूमि जनता व राज्य की सम्पत्ति है। उसे स्थायी उपयोग के लिए आर्टेल को दे दिया गया है अर्थात् हमेशा के लिए और इसे न खरीदा जा सकता है न बेचा जा सकता है और न ही आर्टेल द्वारा लीज (lease) पर उठाया जा सकता है।

(2) व्यक्तिगत भू-आवंटों पर सीमा लगा दी गई। व्यक्तिगत सामूहिक कृषक के निजी स्वामित्व व उपयोग वाली भूमि $\frac{1}{2}$ से $\frac{1}{2}$ हेक्टेयर व कुछ जगहों पर 1 हेक्टेयर तक रखी गई।

(3) सामूहिक कृषि किसानों द्वारा निजी तौर पर पशुओं के रखने पर भी सीमा लगा दी गई। यह संख्या 1 गाय 10 भेड़ों व दकरीयों तथा कुछ घोड़ों या ऊंटों पर जगई गई। इन जानवरों को रखने के लिए काम में ली जाने वाली जगहों का समाजीकरण नहीं किया गया।

(4) पिछले कानूनों के विपरीत अब सामूहिक फार्मों पर, कुलक लोगों के बच्चों व अन्य लोग जिनका मतलबिदार छीन लिया गया था, आने की अनुमति दे दी गई।

(5) सामूहिक फार्मों के प्रबन्धकों द्वारा फार्म के सदस्यों को मनमाने तरीके से निकाल देने पर प्रतिबन्ध लगाये गये।

(6) नये कानून में कोलखोज के प्रबन्धकों के अधिकारों व कर्तव्यों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया। उसका कार्यकाल भी 1 वर्ष से बढ़ाकर 2 वर्ष कर दिया गया।

(7) अन्त में, कानूनों में इस बात पर बल दिया गया कि 'आर्टेल इस बात का उत्तरदायित्व लेता है कि वह सामूहिक खेती को सरकार द्वारा स्थापित योजना एवं आर्टेल के राज्य के प्रति दायित्वों के अनुसार चलायेगा।'

कुल मिला कर किसी न किसी रूप में सामूहिक फार्मों के उत्पादन में अनाज उत्पादन के बाजारों अतिरिक्त का 90 प्रतिशत भाग राज्य के हाथों में पहुँचता था। इससे राज्य अविवाश अनारों के मूल्य पर नियन्त्रण रख सकता था। ऐसे जिले जहाँ पर सामूहिक कृषकों को जाबटिल करने के लिए भूमि उपलब्ध नहीं थी वहाँ से उन्हें

सामूहिक खेत के उत्पादन का वितरण (1938)

कुल उत्पादन के प्रतिशत के रूप में

निश्चित मूल्य पर अनिवार्य राजकीय वसूली	15
राज्य को मशीन ट्रैक्टर स्टेशनों के काम के लिए भुगतान	16
राजकीय वसूली एजेंसियों की बिजली	5.1
बीज की राजकीय सप्लाई को वापसी	2
बीज कोष को आवंटन	18.6
पशु आहार कोष को आवंटन	13.6
सामूहिक कृषकों को शुल्क	26.9
अन्य आवंटन	2.8

ऐसे जिलों में स्थानान्तरित करने का सुझाव दिया गया जहाँ भूमि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थी। सामूहिकीकरण के प्रारम्भिक वर्षों में कोलकोता उत्पादन के प्रयासों का मुख्य जोर अनाज के उत्पादन में वृद्धि करने पर था। पशु-पालन आदि कार्यक्रम 1934 के बाद में प्रारम्भ किये गये थे।

सामूहिक खेती प्रणाली ने सोवियत कृषि के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह प्रयोग समय की कसौटी पर भी सरा उतरा। द्वितीय विश्व-युद्ध के दौरान जर्मन आक्रामक सेनाओं ने इसी कृषि को काफी हानि पहुँचाई थी। उन्होंने 70,000 गाँवों को नष्ट कर दिया था। वे लोग या तो 1,37,000 ट्रैक्टर ले गये या उन्हें नष्ट कर डाला। यही स्थिति 49,000 फसल कटाई यन्त्रों (harvesters) की भी की गई। इस तरह सामूहिक खेतों को द्वितीय विश्व-युद्ध में कुल मिलाकर 1,81,000 मिलियन रूबल की हानि उठानी पड़ी।

युद्ध समाप्त होने के बाद, उनको हुई भारी क्षति के बावजूद, सामूहिक व राजकीय फार्म बहुत जल्दी ही पुरानी स्थिति में पहुँच गये। आज सोवियत रूस में लगभग 30,000 सामूहिक खेत हैं जिनमें 14 मिलियन कृषक परिवार लगे हुए हैं।

आधुनिक सामूहिक फार्म

अपने अस्तित्व के इन 50 वर्षों में सामूहिक खेतों को अनेक परिवर्तन देखने पड़े हैं। उनकी वर्तमान स्थिति निम्नांकित तालिका से स्पष्ट होती है—

सामूहिक फार्मों के मुरय आर्थिक सूचक

	नाम की इकाई	1965	1973
1. सामूहिक खेतों की संख्या	हज़ारों में	36.9	31.5*
2. यंत्रों (मशीनों) की औसत संख्या	मिलियन में	18.6	13.9
3. अवितरणीय परिमण्यत	हज़ार मि. रूबल	42.3	74.3
4. कुल वाषिक आय	"	17.9	24.0

* संख्या में यह कमी वित्तबीकरण एवं पुनर्गठन के कारण आई है।

सामूहिक खेत कृषि पदार्थों के मुख्य उत्पादक एवं आपूर्तिकर्ता (Suppliers) बन गये हैं। सोवियत सरकार को इन सामूहिक फार्मों से अपनी कुल वसूली का 51 प्रतिशत अनाज, 76 प्रतिशत कपास, 92 प्रतिशत चुकन्दर, 38 प्रतिशत सब्जियाँ, 50 प्रतिशत भास तथा 42 प्रतिशत ऊन प्राप्त हो रही है।

इन आधुनिक सामूहिक फार्मों के पास भारी सख्या में मशीनें हैं जिनमें उनके 10 लाख ट्रैक्टर, 3 लाख से अधिक हार्वेस्टर तथा 5 लाख ट्रक शामिल हैं। राज्य भी सामूहिक फार्मों को भारी मात्रा में अनुदान आदि देता है। उदाहरण के लिए, 1974 में सामूहिक फार्मों को दीर्घकालीन राजकीय ऋणों के रूप में 3,200 मिलियन रूबल स्वीकृत किये गये थे।

1966 से 1970 के मध्य सामूहिक कृषकों की वास्तविक आय में 42 प्रतिशत की वृद्धि होने का दावा किया गया था। चेपयेव सामूहिक फार्म (Chapayev collective farm)¹, जो दक्षिणी रूम के रोस्टोव क्षेत्र का एक विशिष्ट फार्म है, का उत्पादन 1970 के 3,760 रूबल के प्रति व्यक्ति स्तर से बढ़कर 6,220 रूबल हो चुका है।

1969 में सामूहिक फार्मों के लिए नये आदर्श नियम स्वीकार किये गये। इन नियमों ने सामूहिक फार्मों के भीतर लोकतन्त्र, आर्थिक स्वतन्त्रता व पहल की भावना को काफी प्रोत्साहित किया है। इन नियमों द्वारा फलों व सब्जियों के उत्पादन हेतु सहायक सामूहिक फार्मों की स्थापना करने को भी प्रोत्साहन दिया गया है। इन्हीं नियमों के अन्तर्गत 1970 में एक नई सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना भी लागू की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत 12 मिलियन सामूहिक कृषकों को वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है। ये सामूहिक कृषक 60 वर्ष की आयु में सेवा निवृत्त होते हैं।

सामूहिक फार्मों के मुख्य सिद्धान्तों व सगठनात्मक स्वरूपों को फिर से बनाया गया है। एक सामूहिक फार्म अब एक ऐसे सहकारी सगठन के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें कृषक उत्पादन के साधनों के सामाजिक स्वामित्व के सिद्धान्त के आधार पर स्वेच्छा से बड़े पैमाने की समाजवादी खेती के लिए एक होकर काम करते हैं। ऐसे नागरिक जिनकी आयु 16 वर्ष हो चुकी हो इसके सदस्य बनते हैं। एक सामूहिक फार्म की सर्वोच्च प्रशासनिक सभा सामान्य सदस्यता सभा (general membership meeting) होती है। ये सभाएँ साल में चार बार बुलाई जाती हैं। इन सामान्य सभाओं में चैयरमैन तथा बोर्ड के सदस्यों का चुनाव किया जाता है जो सामूहिक फार्म के निम्न कार्यों का सम्पन्न कर रहे हैं।

यहाँ यह भी उल्लेख करना आवश्यक होगा कि बढ़ती हुई सख्या में ये सामूहिक फार्म अपने स्वयं के प्रक्रम प्रतिष्ठान (processing enterprises) लगा रहे हैं। ऐसे प्रतिष्ठानों की सख्या 1973 में 5,400 थी। एक सामूहिक फार्म सामान्य सदस्यगण सभा द्वारा स्वीकृत योजना के अनुसार चलाया जाता है। इस योजना-अनुबन्ध (plan contract) में राज्य द्वारा सामूहिक फार्म के उत्पादन को एकसूत्र मूल्य (uniform price) पर खरीदने की गारण्टी होती है। कभी कभी अनाज व

कुछ महत्वपूर्ण औद्योगिक फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ऊँचे मूल्य भी निश्चित किये जाते हैं।

सामूहिक फार्मों में आय के वितरण के तरीकों को भी धीरे-धीरे बदला गया है तथा उसके कार्यशील सदस्यों को अधिक अभिप्रेरणाएँ देने की बातें शामिल की गई हैं। सबसे पहले फार्म के कुल उत्पादन का उपयोग प्रदाओं (inputs) के भुगतान के लिए होता है। उसके बाद एक धार्मिक पारिश्रमिक कोष बनाया जाता है। कोष भाग का उपयोग करो का भुगतान करने (12 प्रतिशत तक) तथा फार्म के परिसम्पत्त बढ़ाने में किया जाता है। अब यह महसूस किया जा रहा है कि मौद्रिक अभिप्रेरणाएँ (money incentive) सामूहिक फार्मों का उत्पादन बढ़ाने के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। पिछले कुछ वर्षों से सामूहिक फार्म इकाई-दर (piece-rate), काम के हिसाब से भुगतान (payment-by-the-job), समय-दर (time-rate) तथा समय-दर + बोनस (time-rate plus bonus system) प्रणाली के आधार पर भुगतान करने लगे हैं। अधिकांश सामूहिक फार्मों ने गारण्टीयुद्ध मासिक मौद्रिक मजदूरी देना शुरू कर दिया है। उत्पादन को प्रोत्साहित देने के कारण से सामूहिक फार्मों ने अब अतिरिक्त भुगतान करना व अन्य प्रकार के भौतिक अभिप्रेरक (material incentives) देना भी आरम्भ कर दिया है।

सामूहिक कृषकों को उनके अपने उपभोग तथा उनके पशुओं के आहार के लिए अनाज आदि उपलब्ध कराने हेतु फार्मों पर एक वस्तुओं के रूप में कोष भी बनाया गया है जो उन कृषकों को आंशिक भुगतान वस्तुओं के रूप में करता है। सामूहिक फार्म अपने उत्पादन का अधिकांश भाग राज्य को योजना-अनुबन्ध व्यवस्था के आधार पर ही बेचते हैं तथा उसमें से कुछ भाग सामूहिक फार्म बाजार व शहरों में भी बेचा जाता है। सामूहिक फार्म अपने सदस्यों को मुफ्त उपयोग के लिए (स्वामित्व के लिए नहीं) भूमि के 0.2 से लेकर 0.5 हेक्टेयर के टुकड़े भी आवंटित करते हैं। इन आवंटित व्यक्तिगत भूखण्डों (private plots) पर सामूहिक कृषक अपनी निजी सम्पत्ति जैसे मकान, जानवरों का बाड़ा व पशु आदि रख सकते हैं।

राजकीय फार्म (State Farms)

सोवियत कृषि उत्पादन में राजकीय फार्म महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सोवियत रूस में लगभग 17,700 राजकीय फार्म (Sovkhoz) हैं। उनमें लगभग 8 मिलियन लोग लगे हुए हैं तथा उनके अन्तर्गत 106 मिलियन हेक्टेयर के लगभग शुद्ध कृषित क्षेत्र आता है। राजकीय फार्म तथा सामूहिक फार्म दोनों ही काफी बड़े होते हैं किन्तु सामूहिक फार्मों से राजकीय फार्मों की भिन्नता यही है कि राजकीय फार्म की सारी सम्पत्ति सरकार की होती है। सामूहिक फार्मों में उनका स्वामित्व सदस्यों का होता है। राजकीय फार्मों पर काम करने वाले श्रमिकों तथा कार्यालय कर्मचारियों को, उद्योग की ही भाँति, राज्य में बड़ी-बड़ी मजदूरी या वेतन मिलता है। सामूहिक कृषकों की आय में फार्म से प्राप्त हिस्सा तथा निजी भू-खण्ड से प्राप्त आय सम्मिलित होते हैं।

औसतन एक राजकीय फार्म के पास 19,000 हैक्टेयर कृषि योग्य भूमि, लगभग 2,000 पशु, हजारों की संख्या में ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ट्रैक्टर आदि होते हैं। वे विद्युत-शक्ति का भी व्यापक उपयोग करते हैं। राजकीय फार्म सामूहिक फार्मों से अधिक विशिष्टीकृत (specialised) भी होते हैं। उनके उत्पादन में निरन्तर वृद्धि हो रही है। 1973 में राजकीय फार्मों ने कुल अनाज उत्पादन का 49%, सब्जियों का 56%, मांस का 43%, अण्डों का 71% तथा ऊन का 46% उत्पादन किया था।

1954 से 1956 की अवधि में पूर्वी सोवियत रुम में नई भूमि (virgin land) को खेती योग्य बनाने का अभियान छेड़ा गया था। उस क्षेत्र में करीब 4,000 नए राजकीय फार्म स्थापित किये गये। करीब 42 मिलियन हैक्टेयर भूमि को कृषि योग्य बनाया गया। यह दावा किया जा रहा है कि केवल इन फार्मों से अब देश में सरकार द्वारा वसूल किये जा रहे अनाज का 25 प्रतिशत प्राप्त होता है।

राज्य ही इन राजकीय फार्मों का उत्पादन के साधन प्रदान करता है तथा अपने बजट में इनको पुनर्भुगतान न करने वाले कोष आवंटित किये जाते हैं। इन फार्मों का मुनाफा राजकीय बजट में जाड़ा जाता है। 1960 के दशक के प्रारम्भिक वर्षों में ऐसा महसूस किया गया था कि राजकीय फार्मों का मान-ब्राज ठीक में नहीं चल रहा है तथा उनकी उत्पादकता गिर रही है। ऐसा श्रमिकों का पर्याप्त अभिप्रेरणण (incentives) न देने के कारण हो रहा था। 1965 में राजकीय फार्मों की कार्य-शैली पर पुनर्विचार किया गया। उन्हें अपना उत्पादन नियोजित करने व उसे बेचने, लाभ का उपयोग करने तथा अपने श्रमिकों को अधिक आर्थिक अभिप्रेरणण दे सकने के अधिकार दिये गए।

इन राजकीय फार्मों में अब विशिष्टीकरण (specialisation) की प्रवृत्ति व्यापक बनती जा रही है। वे अब एक में लेकर तीन फसलों तक का उत्पादन करते हैं। राजकीय फार्मों का प्रबन्ध एक निदेशक द्वारा किया जाता है जिसे उच्च आर्थिक सत्ता नियुक्त करती है। इसे एक-व्यक्ति संचालन (one man management) के सिद्धान्त पर चलाया जाता है। हालांकि साथ ही यह भी दावा किया जाना है कि इसका माय संचालन में अभी श्रमिकों की व्यापक भागीदारी होती है। इन राजकीय फार्मों के चलाने में पार्टी तथा ट्रेड यूनियनों भी काफी हस्तक्षेप करती हैं।

राजकीय फार्मों की उत्पादकता में वृद्धि करने के उद्देश्य में अब श्रमिकों को अधिकतर काम की तुलना में भुगतान व बोनस मिलाकर (payment by-the-job plus bonus system) मजदूरी दी जाती है। इस प्रणाली में उत्पादन परिणाम, उसकी मात्रा व किस्म का लेखा-जोखा रखा जाता है। पिछले कुछ समय से, सामूहिक कृषकों की ही भाँति, अनेकों राजकीय फार्मों श्रमिकों व कर्मचारियों को थोड़ी-सी व्यक्तिगत खेती करने की अनुमति दी गई है। राजकीय फार्मों पर काम करने वाले श्रमिकों की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था आवश्यक थी।

राजकीय फार्मों को पंचवर्षीय एवं वार्षिक योजनाओं के अनुसार लक्ष्य सौंप दिये जाते हैं जिन्हें पहले तो राजकीय फार्मों पर ही बनाया जाता है तथा बाद में

उच्च कृषि अधिकारियों से स्वीकृत करवाया जाता है। जिस मूल्य पर राजकीय फार्म अपना उत्पादन सरकार को बेचते हैं उन्हें सोवियत सरकार ही स्वीकृत करती है।

सामूहिक फार्म व राजकीय फार्म एक-दूसरे से निकट सम्बन्ध रखते हैं। वे उत्पादन के मगठन में अपने अनुभवों का आदान-प्रदान करते हैं तथा एक-दूसरे को वैज्ञानिक तरीके से प्रबन्ध करने में सहायता भी देते हैं। पिछले 20 वर्षों में कृषि में सोवियत यूनियन के अनुभवों का पूर्वी यूरोप के अनेक समाजवादी देशों द्वारा अनुकरण किया गया है।

सोवियत कृषि का विकास

एक उच्चस्तरीय कृषि-व्यवस्था का निर्माण करना सोवियत सरकार द्वारा प्रमुख लक्ष्य माना गया था। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कृषि-उत्पादन का औद्योगीकरण करना सोवियत सरकार की कृषि-नीति का मुख्य लक्ष्य रहा है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सरकार ने सामूहिक फार्मों के साथ मिलकर कृषि में नवी पंचवर्षीय योजना के दौरान (1971-75) 1,31,000 मिलियन रूबल की राशि का विनियोग किया है। 1975 के बजट में अकेले एक वर्ष के लिए कृषि हेतु 31,000 मिलियन रूबल आवंटित किये गये जो, यह दावा किया गया था, कि रक्षा पर व्यय की राशि के दुगुने थे।

सोवियत रूस में कृषि का सर्वांगीण यन्त्रीकरण चल रहा है। 1975 में प्रति कृषक विद्युत उपलब्धि 1970 की तुलना में 50 प्रतिशत अधिक थी। शारीरिक श्रम के स्थान पर मशीनों का उपयोग बराबर बढ़ रहा है। आठवीं व नवी योजना में मिलावर ट्रैक्टरों व हार्वेस्टरों की सम्मिलित क्षमता में 80 प्रतिशत वृद्धि का दावा किया गया है। 1920 के दशक के अन्तिम वर्षों में, जब सामूहिकीकरण शुरू किया गया था देश में कुल 27,000 ट्रैक्टर तथा 700 ट्रकों व 2 हार्वेस्टर थे। आज सामूहिक फार्मों के पास 23 लाख ट्रैक्टर, 13 लाख ट्रकों तथा 6 लाख हार्वेस्टर (grain harvester) हैं।

गहन यन्त्रीकरण एवं स्वचालन द्वारा कृषि-उत्पादन प्राप्त किये जाने के कारण प्रति इकाई उत्पादन में श्रम-प्रदा (labour input) काफी घट गई है। यह उत्पादन क्षमता में वृद्धि का सूचक है। इसीलिए 1971-74 की अवधि में वार्षिक उत्पादन में 15% की औसत वृद्धि होने का दावा किया गया है। रासायनिक खादों का उपयोग भी बढ़ रहा है। 1973 में सोवियत रूस दुनिया का सबसे अधिक रासायनिक खाद उत्पादन करने वाला देश बन गया था। देश में प्रति हेक्टेयर लगभग 65 किलोग्राम रासायनिक खाद का प्रयोग किया जा रहा है। निन्तु इस मात्रा को भी अपर्याप्त माना जा रहा है तथा इसमें वृद्धि करने के प्रयास जारी हैं।

भूमि में सुधार करने का कार्यक्रम देश के अधिकाधिक प्रदेशों में फैलाया जा रहा है। वोल्गा घाटी के मूखे प्रदेश में एक शक्तिशाली मिर्चाई व्यवस्था काममें की जा रही है। सोवियत रूस में कुल कृषित क्षेत्रफल में मिचित क्षेत्रफल 8 प्रतिशत है तथा उसमें कुल उत्पादन का लगभग 25 प्रतिशत भाग प्राप्त किया जाता है।

कृषि के क्षेत्र में विज्ञान का प्रयोग बराबर बढ़ाया जा रहा है। कुछ दशकों के अन्तराल में सरकार ने 900 कृषि अनुसंधान केन्द्र खोले हैं। अनाज के उत्पादन को सोवियत कृषि का मरुदण्ड माना जाता है किन्तु 1960 के बाद फसल खराब हो जाने की कई घटनाएँ हुई हैं। अनाज का उत्पादन कुल मिलाकर 127 मिलियन हेक्टेयर भूमि में होता है। यह कहा जाता है कि अनाज उगाने के लिए सोवियत रुम की जलवायु सम्बन्धी दशाएँ पश्चिमी यूरोप के देशों की तुलना में अधिक खराब हैं। फसलों में स्थायित्व लाने के प्रयास किये जा रहे हैं किन्तु पिछले दो दशकों में (1960-80) सोवियत यूनियन को कई बार अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से गेहूँ आदि की खरीद के लिए बाध्य होना पड़ा है।

कृषि में लगी हुई स्थिर उत्पादक पूंजी 1974 में 1,41,000 मिलियन रूबल तक पहुँच चुकी है तथा कुल शक्ति-प्रजनन क्षमता अब 430 मिलियन अश्व-शक्ति (Horse power) के बराबर है। 1971-74 की अवधि में कुल वार्षिक कृषि-उत्पादन का औसत मूल्य 91,000 मिलियन रूबल रहा जबकि आठवीं पंचवर्षीय योजना में यह औसत 80,500 मिलियन रूबल वार्षिक का रहा था। 1971-74 की अवधि में अनाज उत्पादन का वार्षिक औसत भी 192 मिलियन टन रहा था जबकि यही वार्षिक औसत आठवीं पंचवर्षीय योजना में 168 मिलियन टन व सातवीं पंचवर्षीय योजना में 130 मिलियन टन रहा था। 1975 में फसल खराब हो गई थी तथा कुल अन्न उत्पादन केवल 140 मिलियन टन ही रहा। इन आँकड़ों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि सोवियत कृषि-उत्पादन में अनिश्चितता का तत्त्व अभी तक विद्यमान है।

सोवियत कृषि की ठोस उपलब्धियाँ

इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सोवियत सत्ता के पिछले 63 वर्षों में कृषि में क्रांतिकारी मात्रात्मक परिवर्तन हुए हैं। 1971 तक कृषि-उत्पादन 1913 की तुलना में बढ़कर तीन गुना हो चुका था। धर्म-उत्पादकता में, कृषि-क्षेत्र में, 5.4 गुनी वृद्धि हुई। सामूहिकीकरण से पहले सरकार किसानों में 10 मिलियन टन अनाज की वसूली कर पाती थी जबकि 1940 में उसने किसानों से 36 मिलियन टन अनाज तथा 1970 में तो 66 मिलियन टन अनाज खरीदा था।

कुल कृषि-उत्पादन का वार्षिक औसत सम्पूर्ण आठवीं योजना की अवधि में मूल्य की दृष्टि से 80,500 मिलियन रूबल का रहा था जबकि 1973 में यह राशि 96,000 मिलियन रूबल तक पहुँच गई थी जो 19% की वृद्धि इंगित करती है। ऐसा अनुमान है कि 1918 से 1971 की अवधि में कृषि विकास पर 1,67,100 मिलियन रूबल की राशि का विनियोग किया गया। चीजों व मुद्रा के रूप में कृषकों की आमदनी 1913 की तुलना में 8 गुनी होने का दावा किया गया है। सोवियत रूस सप्ताह-भर में ऐसा एकमात्र देश होने का भी दावा करता है जहाँ राजकीय फार्मों व सामूहिक फार्मों पर काम करने वाले कृषि मजदूरों की वृद्धावस्था पेंशन, अयोग्यता

□ सोवियत संघ का आर्थिक विकास/3

(भारीक) पेशन, बीमारी में भत्ता व सर्वतनिक अवकाश दिया जाता है ।

सोवियत कृषि का विकास : 1971-75

(प्रतिजन में)

	औसत वार्षिक उत्पादन, 1971-75	उत्पादन में औसत वार्षिक वृद्धि 1971-75
कुल कृषि उत्पादन ('000 मिलियन रुबल में)	98	17.7
अनाज (मिलियन टनो में)	195	27.5
कपास "	6.75	0.65
मांस "	14.3	2.7
दूध "	42.3	11.8
अंडे ('000 मिलियन)	46.7	10.9
ऊन ('000 टनो में)	464.0	67.0

सोवियत कृषि की समस्याएँ

सोवियत कृषि के सम्मुख अब एक भारी और जटिल चुनौती है । उत्पादन को अत्यधिक तीव्र बनाना सबसे महत्वपूर्ण है । इसके लिए धन-उत्पादकता में एक नये स्तर तक की वृद्धि आवश्यक है । इसके अलावा भूमि का अधिक अच्छा उपयोग, उसकी उपजाऊ शक्ति में सुधार, उत्पादन का विशिष्टीकरण एवं उसका केन्द्रीकरण, धन का वैज्ञानिक आधार पर संग्रह व तकनीकी प्रगति का और अधिक उपयोग भी उतने ही आवश्यक हैं । भूमि में सुधार, व्यापक यन्त्रीकरण तथा विद्युतीकरण भी कृषि-क्षेत्र की कार्य-कुशलता बढ़ाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण तत्व हैं ।

विशेष ध्यान सिंचित क्षेत्रों में वृद्धि करने पर दिया जाना होगा जो किमी भी मौसम में फसल पैदा करने की गारण्टी दे सकें । यही एकमात्र उपाय है जो सोवियत कृषि को बार-बार पैदा होने वाली अनिश्चित उत्पादन की स्थिति से बचा सकता है । सरकार ने फसलों को सुस्थिर बनाने के लिए अनेक उपाय किये हैं, विशेष रूप से मुश्किल जलवायु की दशाओं में अनेक प्रदेशों में ऐसे उपाय किये जा रहे हैं ।

यह विश्वास किया जाता है कि भावी हमी कृषि अत्यधिक तकनीकी आधार वाली होगी । इसका अर्थ यही होगा कि कृषि-उत्पादन बढ़ाने के लिए औद्योगिक उपायों का प्रयोग किया जायेगा । इस प्रकार के कृषिगत-औद्योगिक ढाँचे (agrarian-industrial complexes) के विकास हेतु कृषि श्रमिकों को विविध प्रकार के औद्योगिक श्रमिकों में रूपान्तरित करने की आवश्यकता पड़ेगी । ग्रामीण जनता के भौतिक एवं सांस्कृतिक प्रतिष्ठानों में भी सुधार करना होगा तथा हर प्रकार की औद्योगिक व कृषिगत वस्तुओं की प्रचुर मात्रा में पूर्ति उपलब्ध करानी होगी ।

गोभाम्य से सोवियत यूनियन में इन सभी समस्याओं का मुकाबला करने के लिए आवश्यक दशार्थ विद्यमान है । उसमें फास विद्यालय भू-खण्ड, सामूहिक व

राजकीय फार्मों के रूप में विशाल समाजवादी कृषि प्रतिष्ठान, एक शक्तिशाली उद्योग, एक प्रगतिशील विज्ञान, एक दक्ष श्रम-शक्ति तथा कृषि-कार्य में प्रशिक्षित लाखों-करोड़ों श्रमिक है। कृषि-श्रमिकों को दी जा रही अभिप्रेरणाओं के वर्तमान ढाँचे में साधारण-सा परिवर्तन लाकर तथा एक अधिक विश्वमनीय सिंचाई व्यवस्था की स्थापना करके सोवियत कृषि नई बुलन्दियों को छू सकती है।

वैसे तो सोवियत कृषि में काफी विविधता है तथा वहाँ सभी प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं किन्तु मुख्य सोवियत फसलों की उत्पादन की प्रवृत्ति का अनुमान इन तालिका में लगाया जा सकता है

मुख्य फसलों का उत्पादन

	(मिलियन टन में)					
वर्ष	1913	1928	1940	1950	1960	1973
अनाज	86	73	96	81	125	223
कपास	74	79	2 24	3 54	4 29	7 66
खुबंदर	11	10	18	21	57	87
सूरजमुखी बीज	75	2 13	2 64	1 80	3 97	7 34
आलू	32	46	76	89	84	108
सर्पिणियाँ	6	11	14	9	17	25

1917 की तुलना में 1976 में सोवियत रूस में अपने कृषि उत्पादन में 340% की वृद्धि कर ली थी। कृषि में पूँजी विनियोगों में भी उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। सातवीं पंचवर्षीय योजना ने कृषि पर 48,200 मिलियन रूबल की राशि का विनियोग किया था। दसवीं पंचवर्षीय योजना (1976-1980) में यह राशि 1,70,000 मिलियन रूबल रखी गई है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना : 1928-1933

(THE FIRST FIVE YEAR PLAN : 1928-1933)

नई आर्थिक नीति ने देश की उत्पादन क्षमता को पुनर्स्थापित कर तथा समाजवादी क्षेत्र की प्रधानता को सुदृढ़ कर अपने उद्देश्य को पूरा कर लिया था। लेकिन नई आर्थिक नीति के कार्यकाल की समाप्ति के समय इस बात को लेकर विवाद छिड़ गया कि सम्पूर्ण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण का भावी स्वरूप क्या हो? पार्टी के एक घटक का आग्रह था कि कृषि को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जबकि दूसरे घटक का विचार था कि सर्वाधिक प्राथमिकता उद्योग को ही मिलनी चाहिए। यहाँ तक कि उद्योग को प्राथमिकता देने के पक्षधर भी आपस में विभक्त थे। उनका मतभेद औद्योगीकरण की गति को लेकर था, कुछ उसकी तीव्रतम गति के पक्षपाती थे जबकि अन्य लोग धीमी गति की सलाह दे रहे थे।

ऊँचे दर्जे का केन्द्रीकृत प्रबन्ध¹, नियोजित अर्थव्यवस्था की निर्दयी परिपालना, सामूहिकीकरण की और भी दहला देने वाली परिपालना (enforcement) इन सभी ने मिलकर नई प्रचारित नीति के कुछ कटु भागों को स्पष्ट किया था। जिन अर्थशास्त्रियों ने स्टालिन की बात मानने से इनकार किया वे जैसे पृष्ठभूमि से विलुप्त हो गये। अन्य अर्थ-विशेषज्ञों ने किसी-न-किसी रूप में इस नियोजित अर्थव्यवस्था को लागू करने में सहायता देने के लिए अपनी सहमति दे दी और अपना काम स्वीकार कर लिया। बिल्कुल इसी तरह की नई आर्थिक नीति ने पंचवर्षीय योजनाओं के लिए मार्ग प्रशस्त किया जिन्होंने वास्तव में सोवियत अर्थव्यवस्था की पूर्णतया कार्यापलट करने की शुरुआत की।

प्रथम पंचवर्षीय योजना की मान्यताएँ

अन्तिम रूप से स्वीकृत योजना का प्रारूप 960 पृष्ठों का था। अन्तिम रूप रेखा में माना गया कि—

(i) पाँच वर्षों के दौरान फसल खराब हो जाने की किसी भी सम्भावना पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

(ii) योजना के पहले कुछ वर्षों में ही निर्यातों के अत्यधिक प्रसार हो जाने

कमी का लक्ष्य था।

(4) पूँजी-प्रधान उद्योगों का निर्माण विज्ञात पैमाने पर करने का लक्ष्य रखा गया। इसमें से अधिकांश विनियोग की आवृत्ति विशाल विद्युत-रसायन-धातु निर्माण संयोगों (electrochemicals-metallurgical combinats) के रूप में अर्थात् अन्तर्निर्भर उपक्रमों के समूह (groups of interdependent enterprises) के रूप में सामने आनी थी। आधारभूत उद्योगों पर विनियोग की जाने वाली कुल 13.5 अरब रुबल की राशि में से अकेले पूँजीगत वस्तुओं के उत्पादन हेतु 9.8 अरब रुबल आवंटित किये गये थे। केवल 2.9 अरब रुबल की रकम उपभोक्ता वस्तुओं के लिए रखी गई थी। क्योंकि प्रथम पंचवर्षीय योजना का आवश्यक लक्ष्य भारी औद्योगिक प्रतिष्ठानों का निर्माण करना था इसलिए उपभोक्ता वस्तुएँ बनाने वाले उद्योगों के लिए प्रस्तावित योजना राशि में और भी बढ़ती कर दी गई। यही योजना के निर्माण को एक खतरा पैदा होने की सम्भावना हो गई थी।

(5) विशेष कामों को करने के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने का काम जो प्रथम योजना में लिया गया, उसका एक प्रमुख उत्तरदायित्व था। उदाहरण के लिए, सिर्फ उद्योग के लिए योजनावधि में 25,000 इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता थी। इतना ही नहीं, बड़े पैमाने के उद्योगों के निर्माण कार्यों के लिए विदेशी विशेषज्ञों को आमन्त्रित किया जाना था।

(6) अन्त में, इस बात पर बल दिया गया कि हालांकि पहली योजना का उद्देश्य उद्योग का विकास करना था, वह राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के सर्वांगीण विकास का ही एक भाग बनने थे।

प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल मिलाकर देश की अर्थव्यवस्था में 64.5 अरब रुबल का विनियोग किया जाना था। इसमें से 16.4 अरब रुबल बड़े पैमाने के उद्योगों के लिए सुरक्षित थे। 23% राशि कृषि के लिए, 4% विद्युतीकरण के लिए, 2% घरेलू व्यापार के लिए, 2% म्युनिसिपल सेवाओं के लिए तथा 6% राशि शहरी क्षेत्र में मकान बनाने के लिए निर्धारित की गई।

प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप योजना आयोग (gosplan) द्वारा तैयार किया गया तथा 1929 में उसे सरकार ने स्वीकृति दे दी। स्वीकृत योजना में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को ले लिया गया था। किन्तु विस्तार में व्याख्या केवल मुख्य बिन्दुओं की ही की गई। मोटे तौर पर योजना का उद्देश्य, 'एक ऐसे उद्योग का निर्माण करना था जो न केवल स्वयं उद्योग को ही नये उपकरण प्रदान करे व सम्पूर्ण उद्योग को पुनर्गठित करे बल्कि यातायात व कृषि को भी विकसित करे तथा समाजवाद के लिए आधार तैयार करे।' योजना बनाने समय गॉसप्लान को न केवल सरकारी निर्देशों का बराबर ध्यान रखना पड़ा बल्कि स्थानीय दबावों के लिए भी उसे प्रावधान करना पड़ा। इसका परिणाम यह रहा कि कई अत्यावहारिक अपरियोजनाएँ भी प्रथम पंचवर्षीय योजना में शामिल कर ली गयीं।

कई लेखकों ने वर्ष 1928 का सभी जानकारी सड़क पर महत्त्वपूर्ण मील का पत्थर माना है। 1927 की फेब्रुवरी पार्टी कांफ्रेंस द्वारा सरकार के लिए स्वीकृत

महत्वाकांक्षी कार्यक्रम स्टालिन की अपने प्रतिद्वन्द्वियों पर पूर्ण विजय थी। यह 'एक राष्ट्र में समाजवाद' (socialism in a single country) के विचार की ट्रॉट्स्की के अन्तर्राष्ट्रीय समाजवाद के विचार पर भी विजय थी। गोसप्लान ने सोवियत यूनियन जैसे विशाल राष्ट्र के औद्योगिक एवं कृषिगत पुनर्गठन की एक महान् परिवर्तन की थी। योजनाकारों का उद्देश्य उद्योगों को वहाँ स्थापित करना भी था। जहाँ प्राकृतिक ससाधन उपलब्ध थे। इसका उद्देश्य न केवल उत्पादन लागत घटाना था बल्कि उद्योगों को सम्भावित युद्ध-क्षेत्रों (war zones) से हटाकर दूर ले जाना भी था।

नई आर्थिक नीति से आयोजन पद्धति पर आ जाने के पीछे कई कारण रहे। क्रान्ति को नई आर्थिक नीति के दौरान पैदा हो चुकी पूँजीवादी ताकतों से बचाने के अतिरिक्त आयोजन पद्धति अपनाने के पीछे पश्चिमी पूँजीवाद से अपने आपको पूरी तरह अलग कर लेने की भी अभिलाषा थी। सोवियत सरकार को दीर्घकालिक ऋणों की सख्त जरूरत थी जिसे पश्चिमी देश तब तक देने के लिए तैयार नहीं थे जब तक क्रान्ति-पूर्व के उनके ऋणों का फँसला नहीं कर दिया जाता। युद्ध एवं कलह के स्पष्ट आसार दिखाई दे रहे थे। ऐसे संकट के समय में सोवियत सत्ता के लिए सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद (dictatorship of the proletariat) को मुद्दब करना आवश्यक बन चुका था। उसे निजी व्यवसायी (Nepmen) को पुनः सक्रिय बनने से रोकना भी था तथा क्रुद्ध किसानों को शांत भी करना था। सरकार को बराबर विदेशी आक्रमण का भी भय था। वह सभी प्रकार की विदेशी वस्तुओं के बिना काम चलाने के लिए बाध्य हो चुकी थी। सरकार ने यह भी अच्छी तरह अनुभव कर लिया था कि देश का अस्तित्व तथा उसकी अन्तिम ताकत उसके अपने उद्योगों पर ही निर्भर करेगी। आयात कितना भी किया जाए वह अपर्याप्त ही रहेगा। यही तत्त्व योजनाकारों के मस्तिष्क में भी बराबर घूमते रहे थे। इसीलिए औद्योगिक, कृषिगत एवं मनोवैज्ञानिक क्रान्ति इस विशाल परिमाण व तीव्रगति से लाने की योजना तैयार की गई जिसकी आर्थिक विकास के इतिहास में पहले कोई मिसाल नहीं थी।

प्रथम पंचवर्षीय योजना का लागू किया जाना

जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, गोसप्लान (राज्य योजना आयोग) ही शीर्ष सस्था थी। उसे सहयोग प्रदान करने के लिए कई अन्य सस्थाएँ और भी थीं। मांग व पूर्ति की शक्तियों का स्वतन्त्र बाजार में मुक्त विचरण करने देने की नीति का परित्याग कर दिया गया। योजना में उन परियोजनाओं को शामिल नहीं किया गया जो सबसे अधिक लाभ वाली थीं। ऐसी परियोजनाओं को सम्मिलित किया गया जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए विशेष महत्त्व की थी। उत्पात, शक्ति, कोयला आदि को लाभ या हानि के बावजूद प्राथमिकता दी गई। यहाँ तक कि स्टेट बैंक को भी उन्हें उनकी ऋण-भुगतान क्षमता (means test) की जाँच के बिना ही साख्त प्रदान करने के निर्देश दिये गये। यह समाजवादी ढाँचे में ढल रही अर्थव्यवस्था का एक अनोखा

रूप था। अन्य मुख्य बातों में व्याज से मुक्ति तथा लागत या घिसावट की कोई-भी चिन्ता न होना प्रमुख थे।

प्रथम पंचवर्षीय योजना की असाधारण विशेषताओं में¹ उसकी समाजवादी पद्धति, उसकी तीव्रगति, उसके पूरे होने में विश्वास तथा सम्पूर्ण परियोजना के क्रियान्वयन में एक प्रकार की सूक्ष्मता (precision) की प्रमुख रूप से लिया जा सकता है। इस महान् प्रयास के कान्तिकारी पहलुओं को केवल आकड़ों के माध्यम से अभिव्यक्त करने का प्रयास व्यर्थ होगा। इसकी उपलब्धियों में अत्यधिक गौरव व इसकी असफलताओं में उतनी व्यथा थी। दक्ष श्रमिकों तथा प्रशिक्षित कर्मचारियों के भारी अभाव में कई महँगी त्रुटियाँ भी हुईं। उत्पादन लागत कई बार गैर-अनुपातिक रूप से ऊँची रही तो दूसरी ओर चीजों का अपव्यय सामान्य बात थी। मानवीय श्रम व उत्पीड़न के रूप में तो अनेकों ही त्याग व बलिदान किये गये। विदेशी पूँजी की अनुपलब्धि में लोगों को अपनी कमर पेटियाँ (belts) और अधिक कसने के लिए मजबूर कर दिया। लगभग 33% राष्ट्रीय आय का वित्तियोग कर दिया गया। आवश्यक आयातों के लिए भुगतान हेतु सरकार को निर्माण करने के लिए बाध्य होना पड़ा जिससे उपभोग में और भी कटौती करनी पड़ी।

औद्योगीकरण करने व सामूहिकीकरण करने की सोवियत अर्थव्यवस्था द्वारा अपनायी गई नीतियों के इस अवधि की आर्थिक नीतियों पर व्यापक प्रभाव पड़े। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था को प्रारम्भ करने में पहल ने सोवियत नागरिकों को सर्व की अनुभूति प्रदान की। उसने राष्ट्रवाद की भावनाओं को जन्म दिया। शारीरिक कष्ट औद्योगिक श्रमिकों व किसानों ने सर्वाधिक उठाए। सरकार ने भी जबरन मजदूरी (forced labour) का उपयोग नहरे, रेल व सड़कें, आँध आदि का निर्माण करवाने में किया।

औद्योगिक विकास

बड़े पैमाने के उद्योगों के उत्पादन में योजना के पहले वर्ष की 19% की प्रस्तावित वृद्धि के स्थान पर वास्तविक वृद्धि 24% की रही। औद्योगिक लागतों में 4% की कमी आयी। वैसे किस्म खराब हो जाने की शिकायतें आती रहीं। लेकिन यह स्वाभाविक ही था क्योंकि उद्योगों को मात्रा पर ध्यान केन्द्रित करने के निर्देश दिये गये थे। इसके अतिरिक्त आवश्यक योग्यता रखने वाले प्रबन्धकों व दक्ष श्रमिकों की कमी थी। जहाँ तक उत्पादन में मात्रात्मक प्रगति होने का प्रश्न था उसमें प्रथम वर्ष में सद्य से अधिक वृद्धि हुई।

बड़े पैमाने के उद्योगों का कुल उत्पादन योजना के दूसरे वर्ष भी 24% बढ़ा। लागतों में भी कमी आई यद्यपि चीजों की किस्म में गिरावट या क्रम जारी रहा। किन्तु उत्साह मात्रात्मक वृद्धियों में था। यह नारा कि 'प्रथम योजना चार वर्षों में पूरी होगी' तुलना में भी दिया गया। उत्पादन 1931 में 24% के लक्ष्य की तुलना में 42% बढ़ा। तीसरे वर्ष उसमें इन रूप में कुछ कमी आयी कि 24% के

¹ A. G. Mazour, *op cit*, 36

लक्ष्य के मुकाबले उसमें 20% वृद्धि ही हो पायी। इस वर्ष में उत्पादन लागत भी घटने के स्थान पर 6% बढ़ गयी। 1932 के वर्ष में भी औद्योगिक उत्पादन के परिणाम कम सन्तोषजनक रहे। कुछ अनुमानों के अनुसार तो बड़े उद्योगों का उत्पादन चौथे वर्ष में 8% ही बढ़ा।

औद्योगिक उत्पादन 1928-1932

(अरब खबली में)

	1928	1932	1932-33
सभी उद्योग	15.7	34.3	36.6
ग्रुप 'ए' (पूँजीगत उद्योग)	7	18	17.4
ग्रुप 'बी' (उपभोक्ता वस्तु उद्योग)	8.7	16.3	19.2

किस्म को लेकर चाहे कोई भी विवाद हो, यह एक निर्विवाद मस्य है कि मानात्मक दृष्टि से औद्योगिक उत्पादन में प्रथम पंचवर्षीय योजना काल की वृद्धियाँ काफी महत्वपूर्ण रही। लेकिन वे असमान अवस्थ थी। मशीनों आदि का उत्पादन तो 157% बढ़ा लेकिन उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन लक्ष्य का 74% ही बढ़ पाया। ऐसा इसलिये हुआ था क्योंकि कुल विनियोगों में से 86% विनियोग भारी उद्योगों में किये गये थे जबकि उपभोक्ता वस्तु उद्योगों में व्यय की गई राशि नियोजित राशि से भी कम थी।

योजना काल में उद्योगों के साथ और महत्वपूर्ण बात भी घटित हुई। उसका निम्न आधारों पर पूरी तरह से पुनर्गठन कर दिया गया—

(1) प्रतिष्ठान (enterprise) जिसे कि उत्पादन की आधारभूत इकाई माना गया।

(2) उद्योग संयुक्त (the combine) को योजना के उत्पादन का उत्तरदायित्व सौंपा गया। इसके अलावा पूँजी निर्देश करने, व प्रतिष्ठानों की देखभाल व निरीक्षण का काम भी 'कम्बाइन्स' के जिम्मे रखा गया।

(3) ट्रस्टों को प्रतिष्ठान तथा 'कम्बाइन्स' (combine) के बीच की कड़ी माना गया।

(4) सर्वोच्च आर्थिक परिषद् सम्पूर्ण उद्योग के लिए वित्तीय योजनाएँ बनाने तथा उत्पादन का निर्धारण करने के लिए उत्तरदायी थी। यह 'कम्बाइन्स' (combines) का नियन्त्रण व प्रबन्ध भी करती थी।

1932 में स्वयं सर्वोच्च आर्थिक परिषद् को भी पुनर्गठित करके तीन औद्योगिक कमिस्सारेयट विभाग (industrial commissariats) बनाई गईं।

जैसे ही स्टालिन ने अपनी स्थिति को अधिक सुरक्षित अनुभव किया वैसे वैसे उसने शहरों की किसानों पर निर्भरता को कम करने वाली नीतियाँ अपनायीं। प्रथम योजनावधि की औद्योगिक नीति का एक अन्य लक्ष्य देश की पश्चिमी राष्ट्रों पर

आर्थिक रूप से निर्भरता को समाप्त करना था क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाने की दृष्टि से देश का औद्योगीकरण सबसे महत्वपूर्ण माना गया। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कोई भी कीमत ऊँची नहीं समझी गयी। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु समस्त उपलब्ध दक्ष श्रमिकों का उपयोग करने व घरेलू तकनीक के पूरक के रूप में विदेशी विशेषज्ञों को बुलाने के अलावा सम्पूर्ण सोवियत संघ के भीतर मौजूद प्राकृतिक ससाधनों का विदोहन करने के लिए भारी सरया में परियोजनाएँ तैयार की गईं। शारीरिक दृष्टि में योग्य प्रत्येक व्यक्ति को काम पर बुलाया गया तथा समस्त उपलब्ध पूँजी को देश के औद्योगीकरण के लिए प्रयुक्त किया गया। उपभोक्ताओं के कल्याण की अनदेखी की गयी। औद्योगीकरण के दीर्घकालिक लक्ष्यों को तात्कालिक महत्त्व के साथ बनाया गया जिससे जनसाधारण को आवश्यक वस्तुएँ उपलब्ध नहीं हो पायीं।

विकास के प्रमुख निर्देशांक 1927-28 से 1932-33

(विलियन रूबल में 1926-27 के मूल्यों पर)

	1927-28	1932-33	% वृद्धि
घर के अंत में कुल आधारभूत पूँजी	69.8	126.9	82
सम्पूर्ण अव्ययवस्था में पूँजी विनियोग	8.2	27.7	238
राष्ट्रीय आय	24.4	49.7	103
घर के अंत में उद्योग की आधारभूत पूँजी	9.6	30.7	220
उद्योग में पूँजी विनियोग	1.9	7.4	290
सम्पूर्ण उद्योगों का कुल उत्पादन	18.3	43.3	136
जीवन निर्वाह लागत निर्देशांक (1913=100)	205	176	-24

Source Economic Handbook of the Soviet Union

श्रम कानून

औद्योगिक लक्ष्यों की प्राप्ति प्रमुख रूप से अनुशासित श्रम-शक्ति पर निर्भर करती थी। इस दिशा में स्टालिन की सरकार द्वारा कई कड़े एवं क्रूर कदम उठाये गये। ऐसे श्रमिक जो अनुशासनहीनता करते हुए पाये गये जबरन काम वाले कैम्पों (forced labour camps) में भेज दिये गये या उन्हें लम्बे समय तक के लिए जेल भेज दिया गया। अनुपस्थित रहने, काम छोड़कर एक जगह से दूसरी जगह चले जाने तथा यहाँ तक कि काम में ढील दिखाने पर भी बड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई। ट्रेड यूनियनों को औद्योगीकरण की योजना को क्रियान्वित करवाने के निर्देश दे दिये गये। इन यूनियनों को हड़ताल पर जाने का कोई अधिकार नहीं था। प्रशासन ने निडर व निराव होकर काम किया। श्रम-सचों को अपने सदस्यों की ओर से काम की दशाओं, मजदूरी, काम के घण्टों, छुट्टियों आदि जैसे विषयों को लेकर हस्तक्षेप करने या बकायत करने का भी अधिकार नहीं था। इन सभी का निर्धारण केवल सरकार द्वारा ही किया जाता था।

प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भिक वर्षों में कुशल श्रमिकों की भारी कमी

हो गई। जैसा कि डॉब ने लिखा है, 'उच्च प्रवर्णकीय स्तर के आधे से भी अधिक पदों पर ऐसे लोग आसीन थे जिन्होंने कोई भी विशेष तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया हुआ था।' वास्तव में कुशल श्रमिकों एवं इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने के लिए तीव्रतर उपाय किये गये। केवल प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान 4,50,000 कुशल श्रमिक प्रशिक्षित किये गये। इनके अतिरिक्त काम सीखने वाले जिन प्रशिक्षार्थियों (apprentices) को बड़े पैमाने के उद्योगों में लगाया जा रहा था उनकी संख्या 1927 के 27 मिलियन से बढ़कर 1932 में 52 मिलियन तक पहुँच गई। योजना में भारी मात्रा में विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करने के लिए भी प्रावधान किया गया। विश्वविद्यालयों एवं तकनीकी स्कूलों की संख्या में निरन्तर वृद्धि होती चली गयी जैसा कि निम्न तालिका से स्पष्ट है—

	1928-29	1932
विश्वविद्यालय (संख्या)	129	645
विद्यार्थी (000)	167	394
तकनीकी स्कूल (संख्या)	1,054	3,069
विद्यार्थी (000)	208	751

विदेशी लेखकों विशेषकर पाश्चात्य लेखकों ने इस अवधि के क्रान्तिकारी उत्साह को शका भरी दृष्टि से देखा किन्तु वास्तव में ऐसी बात नहीं थी। कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने सभी सदस्यों से कहा—'सभी सदस्य अपने प्रयत्नों को आर्थिक कठिनाइयों पर विजय पाने तथा श्रमिक वर्गों की समस्त उत्पादन शक्तियों को गतिशील बनाने के लिये केन्द्रित करें ताकि किसी भी कीमत पर औद्योगीकरण की तीव्र गति को बनाये रखा जा सके तथा प्रस्तावित आर्थिक योजना को आगे बढ़ाया जा सके।' संबन्धी कारखानों व हजारों मजदूरों ने इन अपीलों पर ध्यान दिया। जनवरी 1929 में एक अखिल-संघ समाजवादी प्रतियोगिता (All-Union Socialist Competition) प्रतिष्ठानों के बीच आयोजित किया गया। 1932 तक ऐसी प्रतियोगिताओं में देश के कुल श्रमिकों में से 70 प्रतिशत श्रमिक भाग ले रहे थे। अत्यधिक उत्साही व अनुकरणयोग्य श्रमिकों को कुछ आर्थिक सुविधाएँ भी दी जाती थी। ट्रेड यूनियनों ने पार्टी संगठनों के साथ मिलकर इस प्रकार की समाजवादी प्रतियोगिताएँ (Socialist competitions) आयोजित करने में प्रमुख एवं सक्रिय भूमिका निभाई। 1930 में आयोजित सोल्हबी पार्टी कांग्रेस ने श्रम संघों के लिए एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें उनके लिए 'श्रमिक समुदाय को गतिशील बनाने व संगठित करने का लक्ष्य रखा गया ताकि समाजवादी समाज की रचना का ध्येय पूरा हो सके। श्रम संघ राज्य के स्वामी एवं सबसे निकट के सहयोगी होने चाहिए।'।

योजना में कृषि

जब पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी तब सोवियत संघ मूलतः एक कृषि-प्रधान देश था। देश की ग्रामीण जनसंख्या में लगभग 25 मिलियन स्वतन्त्र

कृषक परिवार सम्मिलित थे। इस क्षेत्र में सोवियत सत्ता द्वारा एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कायापलट का काम हाथ में लिया गया। प्रमुख समस्या इन व्यक्तिगत पारिवारिक फार्मों (individual household farms) को विस्तृत सामूहिक फार्मों में बदलने का था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में ऐसे ही विशाल राजकीय व सामूहिक फार्म बनाये गये। इन राजकीय एवं सामूहिक खेतों का निर्माण सोवियत कृषि को समाजवादी कृषि के रूप में प्रतिस्थापित करने का ही एक भाग था।

1928 की ग्रीष्म ऋतु तक भी यह आशा की जा रही थी कि सरकार व्यक्तिगत एवं मध्यम आकार के खेतों को अनछुआ ही रहने देगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1929 में स्टालिन द्वारा ऐसे किसानों के विरुद्ध कड़ी कायबाही की घोषणा की गई जो सामूहिकीकरण का विरोध कर रहे थे जिसे कि समाजवादी क्रान्ति का एक महत्त्वपूर्ण अंग माना गया था।

सामूहिकीकरण (collectivisation) का मुख्य उद्देश्य सम्पन्न कृषकों (Kulaks) या कुलकों का निष्वासन करना था। इस वक़्त में किसानों के बीच भारी हिंसात्मक तनाव पैदा हो गया तथा अनाज की बमूली के लिए सेना की टुकड़ियाँ भेजी गयी। जब किसानों ने यह महसूस कर लिया कि खुली लड़ाई (open battle) में तो उनकी हार सुनिश्चित है तो उन्होंने उत्पादन में कटौती करने की नीति अपना ली। उनके ऐसा करने से सरकार का यह विश्वास और भी दृढ़ हो गया कि इस समस्या का एकमात्र हल सामूहिकीकरण ही रह गया था। सरकार की आशाओं के ठीक विपरीत सामूहिकीकरण का विरोध सम्पन्न कृषकों या कुलकों ने ही नहीं बल्कि छोटे-छोटे कृषकों ने भी किया। इन विरोधी शक्तियों को 1930 तक अन्तिम रूप से पराजित कर दिया गया तथा पुरानी व्यवस्था को नष्ट कर दिया गया। अब से सामूहिकीकरण ही सोवियत कृषि का मुख्य स्वरूप बन गया। इन सारी स्थिति का दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यही रहा कि सामूहिकीकरण को जबरन या हिंसा में तभी लागू करना पड़ा जब सरकार और भी अनेक भीषण समस्याओं से जूझ रही थी। पार्टी में कुछ ऐसे सदस्य भी थे जो सामूहिकीकरण को जबरन लागू किये जाने के पक्ष में नहीं थे किन्तु स्टालिन कुलकों को नष्ट (squeezing out the Kulaks) करने पर अड़ा रहा जिन्हें वह वर्ग-शत्रु (class enemy) मानता था।

अपने एक 1929 के भाषण में स्टालिन ने कहा "कुलक वर्ग को, एक वर्ग के रूप में, करारोपण के उपायों से नहीं निचोड़ा (squeeze out) जा सकता और न ही उसे अन्य उपायों में कुचला जा सकता है जब तक कि उत्पादन के साधन उस वर्ग के हाथों में रहने दिये जाते हैं तथा उस वर्ग को जमीन का आजादी के माध्यम उपयोग करने की अनुमति रहती है" "कुलक लोगों को एक वर्ग के रूप में निचोड़ देने के लिए हमें इस वर्ग के प्रतिरोध को खुली लड़ाई में ताड़ना होगा तथा उसे उसके अस्तित्व के प्रमुख स्रोत बने हुए साधनों से वंचित करना होगा" "इसके बिना सामूहिकीकरण सोचा भी नहीं जा सकता।"

सरकारी तौर पर सामूहिकीकरण कार्यक्रम 1930 में प्रारम्भ हुआ। सरकार ने लगभग 16 मिलियन हेक्टर पर जमीन से 1,00,000 सामूहिक फार्म बनाने की

योजना बनाई। केवल राज्य का ही इस बात का फ़ैसला करना था कि किसानों के लिए क्या अच्छा है। किन्तु प्रतिरोध और हिंसा कुछ इस तरह भड़क उठे कि अस्थायी तौर पर एक बार सरकार का पीछे हटना पड़ा। कृषक को उमका अपना छोटा-सा निजी खेत रख सकने का अधिकार लौटाया गया। 1932-33 में देश में एक गम्भीर अकाल भी पड़ा जिससे सामूहिकीकरण के आलोचकों को उस नीति का विरोध करने का एक अवसर मिला। किन्तु सामूहिकीकरण तो बन रहने के लिए आया था।

सरकार ने प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान ही राजकीय फार्म या सोवखोज (Sovkhoz) का विचार कार्यरूप में परिणत किया था। यह अनुमान लगाया गया था कि 1930 के अन्त तक राजकीय फार्मों को 5 मिलियन हैक्टेयर भूमि पर स्थापित कर दिया जायेगा। ये फार्म पूरी तरह से राजकीय अधिकार में रहने थे तथा राज्य द्वारा ही संचालित किए जाने थे लेकिन यह एक बड़ी खेदजनक टिप्पणी है कि ये राजकीय फार्म कभी भी पूरी तरह सफल नहीं रहे। आर्थिक रूप से ऐसा इसलिए है कि उनमें निजी पहल (private initiative) या रचि का अभाव रहता है तथा आर्थिक रूप से उनकी यह कमफलता इसलिए भी है कि राज्य उनके उत्पादन के लिए उन्हें कम कीमत चुकाता है।

माबिन्न कृषि में प्रथम योजना काल में किये गये इन सत्यागत परिवर्तनों का मिला जुला प्रभाव मिथित सा रहा। प्रति हैक्टेयर उत्पादकता में दिखाई पड़ने जैसी वृद्धि नहीं हुई। किन्तु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि इन सामूहिक व राजकीय फार्मों ने यन्त्रीकरण सम्भव बनाया। इन फार्मों ने कृषि पदार्थों के बाजार अनिरेक में भी काफी वृद्धि की जो तीव्र गति से चलाय जा रहे औद्योगीकरण के कार्यक्रम को समर्थन प्रदान करने के लिए अत्यावश्यक था। सामूहिक खेती ने ग्रामीण वचतो का औद्योगीकरण के कार्यों के लिए गतिशीलन (mobilisation) करने में भी सहायता की। जैसा कि रेगनर नर्कसे ने लिखा है 'सामूहिक फार्म केवल सामूहिक संगठन (collective organisation) का ही एक रूप नहीं है, इससे भी अधिक वह सचय का एक उपकरण है।' इन फार्मों से बाजार अनिरेक के लिए प्राप्त होने वाल कुल अनाज का 84% भाग प्राप्त होने लगा था।

आन्तरिक एवं विदेश व्यापार

कृषि पदार्थों में चल रहा वैधानिक निजी व्यापार पहली पंचवर्षीय योजना के पहले ही वर्ष में समाप्त कर दिया गया। 1929 में निजी व्यापार कुल खुदरा व्यापार का 13.5% रह गया था। 1930 में यह निजी खुदरा व्यापार घटकर 5.6% रह गया तथा 1931 तक बिल्कुल समाप्त हो गया। 1933 में ही पुन स्वतन्त्र बाजार को आर्थिक रूप से कोल्लोज व्यापार (सामूहिक फार्मों की व्यावसायिक गतिविधियाँ) के नाम से चन्ने की छूट दी गई। लेकिन यह बहुत सीमित था। इस अवधि में सरकार ने कुल कृषिगत बाजार अनिरेक का 95 प्रतिशत खुद बेचा था।

सभी वस्तुओं को दो मुख्य समूहों या वर्गों में बाँटा गया। ये वर्ग थे गैर-बाजार पूर्ति (non market supply) तथा बाजार पूर्ति (market supply)।

गैर-वाजार-पूर्ति वर्ग की वस्तुओं को औद्योगिक श्रमिकों, सेना तथा निर्यात के लिए सुरक्षित कर दिया गया। बाजार-पूर्ति वर्ग की वस्तुओं को पुनः 'नियोजित' (planned) तथा 'नियमित' (regulated) वर्गों में बाँटा गया जिनमें क्रमशः अभावग्रस्त तथा कम अभावग्रस्त उपभोक्ता वस्तुओं को रखा गया। अधिकांश 'वाजार पूर्ति' वर्ग में आने वाली वस्तुओं का राशननिग था। सबसे अधिक राशन विशेष समूह (श्रमिकों) को मिलता था, उसके बाद प्रथम समूह व वित्तीय समूह को राशन दिया जाता था।

प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान घरेलू व्यापार के निम्न मुख्य उद्देश्य थे—(1) एक विभेदकारी पूर्ति (a differentiated supply), (2) राजकीय व्यापार तथा लोगों के हाथों से ऋण-शक्ति मोखना, (3) मूल्य विभेद (pricedifferentiation) द्वारा 'लाभ' कमा कर उसे संचित करके राज्य बजट में सम्मिलित करवाने के लिए मोड़ देना, (4) आवश्यक वस्तुओं की काला बाजारी पर नियन्त्रण लगाना, तथा (5) राशननिग प्रणाली समाप्त करने के लिए रास्ता तैयार करना।

घरेलू या आन्तरिक व्यापार को इस रूप में संगठित करने के कई लाभ थे। अत्यधिक केन्द्रीकरण होने के कारण अत्यधिक कम पूर्ति वाली आवश्यक वस्तुएँ भी अनेक क्षेत्रों में पहुँचाई जा सकती थी। किन्तु इसकी कई हानियाँ भी थी। विभिन्न प्रदेशों में आवश्यक वस्तुएँ बहुत कम मात्रा में पहुँच पाती थी। राजकीय व सहकारी व्यापार में उपभोक्ताओं को अनदेखा किया जाता था। मूल्य अक्सर 'नियोजित मूल्यों' से भिन्न होते थे। विभिन्न श्रेणियों के लोगों के लिए वस्तु-विभेद होने के कारण ख़ुब की ऋण-शक्ति अलग-अलग होती थी। इस कारण ख़ुब की मार्बदेशिक अहंता इकाई (universal unit of value) के रूप में मान्यता समाप्त हो गयी। ये सभी कमियाँ सरकार द्वारा भी महसूस कर ली गई थी तथा 1933 के बाद से ही राशननिग व्यवस्था को समाप्त करने की तैयारी शुरू कर दी गयी।

विदेशी व्यापार के बारे में प्रथम पंचवर्षीय योजना की मान्यता गलत सिद्ध हुई। 1929 की मन्दी ने भी सोवियत संघ के लिए व्यापार की शर्तों को हानिकारक बना दिया गया। मॉरिस डॉब ने अनुमान लगाया है कि 1930-31 के वर्षों में मन्दी के कारण रूस के निर्यातों का मूल्य 30% तथा आयातों का मूल्य 20% गिर गया। आयातित माल के मूल्यों में गिरावट का देश को लाभ मिला क्योंकि सोवियत संघ इन वर्षों में मशीनों व उपकरणों का आयात कर रहा था। बाजारों के निर्यात 1931 के बाद बड़े।

कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की उपलब्धियाँ सन्तोषप्रद रही। एक मजबूत औद्योगिक आधार खड़ा हो रहा था। कुशल जनशक्ति की कमी निरन्तर घटती जा रही थी लेकिन उपभोक्ता लोग योजना के अन्त में भी अधिक भौतिक अभावों की स्थिति में जी रहे थे। आवश्यक वस्तुओं के अभाव के साथ जटिल राशननिग प्रणाली ने मिलकर उनके कष्टों को और भी बढ़ा दिया था। किन्तु इस मामले को लेकर सोवियत सत्ता अधिक चिन्तित नहीं थी क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य सोवियत रूस को एक औद्योगिक महाशक्ति (industrial super power) बनाने का था और वह वास्तव में प्राप्त होने के ही दौर में गुजर रहा था।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना : 1933-1938

(THE SECOND FIVE YEAR PLAN . 1933-1938)

प्रथम पंचवर्षीय योजना को 1932 में ही समाप्त घोषित कर दिया गया और उसमें पांच वर्षों के स्थान पर साढ़े-चार वर्ष का समय ही लगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1 जनवरी 1933 से प्रभाव में आयी। प्रथम पंचवर्षीय योजना को देश के औद्योगीकरण, सामूहिकीकरण तथा कृषि के यन्त्रीकरण की दिशा में एक कष्टदायी गुराजत माना जा सकता है। समय-समय पर इसमें तनावपूर्ण तथा हिंसात्मक घटनाएँ भी हुईं।

दूसरी पंचवर्षीय योजना को पहली योजना की अपेक्षा एक लाभ तो यह रहा कि वह उसके अनुभवों से लाभ उठा सकने की स्थिति में थी। सच्चाई यह है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित लक्ष्य पहली योजना के लक्ष्यों में से ही निकले थे। ऐसे चार प्रमुख लक्ष्य थे—(1) औद्योगिक प्रगति का दृढीकरण (consolidation), (2) उत्पादन की किस्म में सुधार तथा लागतों में कमी करना, (3) नये स्थापित किए गये कारखानों में उत्पादन को दुगुना करना, तथा (4) याता-यात सुविधाओं के निर्माण कार्य का प्रसार करना।¹

यदि प्रथम पंचवर्षीय योजना देश के पूर्ण औद्योगीकरण के लक्ष्य को लेकर चली थी तो दूसरी पंचवर्षीय योजना ने स्वयं के लिए अधिक सूक्ष्म लेकिन ऊँचा लक्ष्य 'मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण की समाप्ति' (eliminating exploitation of man by man) अपने सामने रखा। जबकि प्रथम पंचवर्षीय योजना ने अपना सारा ध्यान भारी उद्योगों के विकास पर केन्द्रित कर दिया था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन पर भी समुचित ध्यान देने के संकेत दिये गये। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हल्के उद्योगों को कुछ कम उपेक्षित रखा गया। योजना में जूते तथा खाद्य-सदार्थों का उत्पादन दुगुना करने का लक्ष्य था।

किन्तु इनमें से कोई भी रियायत बड़े पैमाने के उद्योगों के विकास की कीमत पर नहीं दी जानी थी। विनियोग में उनसे भाग को 75% रखकर उन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जा चुकी थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने अपने पहले दो वर्ष प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान अधूरे छूट गये निर्माण कार्यों को पूरा करने में लगाये। किन्तु इस्पात व लोह-पिंडो (pig-iron) का उत्पादन दुगुना करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए नयी लोहा गलाने की भट्टियाँ (New blast furnaces) की

भी आवश्यकता थी। यह भी अनुभव किया गया कि अलौह-धातु उद्योगों (non-ferrous metal industries) का विकास भी अत्यावश्यक है। निकल (nickel), ताँबा, एल्यूमिनियम आदि के उत्पादन हेतु उद्योग स्थापित किये गये। ये उद्योग साइबेरिया में लगाये गये। इन उद्योगों ने द्वितीय महायुद्ध के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभायी।

मशीनी औजारों (machine tools) के लिए विदेशी आयातों पर निर्भरता को कम करना भी अत्यावश्यक था। उनके उत्पादन में तिगुनी वृद्धि का लक्ष्य रखा गया। निकट भविष्य में ही युद्ध छिड़ जाने की सम्भावना को ध्यान में रखते हुए उद्योगों के स्थानों का चुनाव इस ढंग से किया गया कि जिससे हवाई आक्रमणों की स्थिति में वे सुरक्षित रह सकें।

नये ससाधनों की खोज

महत्वपूर्ण कोयला व लोहा उद्योग देश के दक्षिणी भाग में स्थित थे जहाँ उन पर विदेशी आक्रमण से अत्यधिक हानि पहुँचायी जा सकती थी। देश के अन्य भागों में लाहे व कोयले के भण्डारों की खोज करने के लिए व्यापक सर्वेक्षण करने के आदेश दिये गये। साइबेरिया के कोयला भण्डारों को यूराल के लौह भण्डारों से जोड़कर एक विशालकाय लोहा व इस्पात संयुक्त उद्योग (combine) स्थापित किया गया। कजाखिस्तान में भी नये कोयले के भण्डारों का विदोहन शुरू किया गया। मुद्गर आर्कटिक क्षेत्र (Arctic area) में भी खोज दल भेजे गये। एक 700 मील लम्बी रेल लाइन का भी निर्माण किया गया जिसने इन नये खोजे गये क्षेत्रों को धुर दक्षिणी क्षेत्रों से जोड़ दिया। यह कमरतोड मेहनत का काम जबरन मजदूरी कैंम्पो में रह रहे बन्दि्यों (forced labour camp prisoners) द्वारा किया गया। आर्कटिक क्षेत्र में एक तेल क्षेत्र भी खोजा गया। ब्लाइट सागर व बाल्टिक सागर को 1933 में एक नहर द्वारा जोड़ दिया गया। मॉस्को (Moscow) तथा वोल्गा (Volga) नदियों को भी 1937 में एक नहर से मिला दिया गया। इस प्रकार एक महत्वपूर्ण आन्तरिक जल परिवहन का जाल बिछ गया जो भारी सव्वा में यात्री व भारी मात्रा में माल ले जाने के काम में लिया जा रहा है।

औद्योगिक विकास

जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, पहली योजना द्वारा काफी निर्माण कार्य अधूरा छोड़ दिया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों के विकास हेतु 64.7 बिलियन रूबल (अरब रूबल) की राशि निर्धारित की गई। इस राशि का 60% तो नये उद्योगों के निर्माण पर व्यय करने का प्रस्ताव था तथा शेष 40% मौजूदा कारखानों की मरम्मत या उन्हें पूरा करने के काम में व्यय किया जाना था। दूसरी योजना में औद्योगिक उत्पादन 16.5% की वार्षिक वृद्धि करने का प्रस्ताव था लेकिन 1933 में उसमें 8.9% की ही वृद्धि हुई। साथ ही औद्योगिक वस्तुओं की विम्व घटिया बनी रही। 1934 में कुछ बड़े उपाय अपनाये गये तथा उस वर्ष

वस्तुओं की किस्म में कुछ सुधार भी दिखाई दिया। 1934 के लिए तैयार की गयी वार्षिक योजना में औद्योगिक उत्पादन में 19% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया।¹

1935 के बाद में बराबर औद्योगिक वस्तुओं की किस्म में सुधार लाने पर बल दिया जाता रहा। उस वर्ष के लिए उत्पादन वृद्धि लक्ष्य भी घटाकर 16% कर दिया गया। 1935 के लिए औद्योगिक उत्पादन वृद्धि योजना ठीक तरह चली तथा उसमें 20% की वृद्धि हुई। थम उत्पादकता बढ़ाने व उत्पादन लागत घटाने सम्बन्धी लक्ष्य भी पूरी तरह प्राप्त हुए। उद्योग में स्टाखनोव आन्दोलन (Stakhanov movement) लाने के निर्देश दिये गये जिसका उद्देश्य, 'उत्पादन में अधिकतम वृद्धि तथा लागत में यथासम्भव कमी करना था, यह मानते हुए कि उत्पादन कार्यक्रम एक अनिवार्य न्यूनतम लक्ष्य है।' 1936 के लिए नियोजित औद्योगिक उत्पादन वृद्धि लक्ष्य काफी ऊँचा अर्थात् 23% रखा गया। लेकिन फिर भी परिणाम सन्तोषप्रद रहे। सरकारी आँकड़ों के अनुसार औद्योगिक उत्पादन 30% से बढ़ा। 1937 के लिए भी औद्योगिक उत्पादन में 20% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था। वह लक्ष्य भी प्राप्त कर लिया गया।

अप्रैल 1937 में एक सरकारी वक्तव्य प्रकाशित किया गया कि 'राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की अधिकांश महत्वपूर्ण शाखाओं के सन्दर्भ में द्वितीय पंचवर्षीय समय से पूर्व ही अपना लक्ष्य प्राप्त कर चुकी है तथा सोवियत उद्योग में ये लक्ष्य 1 अप्रैल 1937 तक ही पूरे हो चुके हैं।' उस समय पश्चिमी देशों के अखबारों ने इस वक्तव्य पर विद्वान नहीं किया लेकिन बाद में प्रकाशित आँकड़ों ने इसे सिद्ध कर दिया।

औद्योगिक उत्पादन नियोजित एवं वास्तविक

(बिलियन रुबलों में 1926-27 के मूल्यों पर)

	1937 के लिए नियोजित उत्पादन	1937 में वास्तविक उपलब्धियाँ
पूँजीगत वस्तुओं का उत्पादन (ग्रुप ए)	46	56
उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन (ग्रुप बी)	47	40
कुल औद्योगिक उत्पादन	93	96

कुल मिलाकर 1937 में द्वितीय पंचवर्षीय योजना की उपलब्धियाँ उसके लिए निर्धारित लक्ष्यों से अधिक रही। लक्ष्यों से भी अधिक प्राप्तिदायक धातु-कार्य उद्योगों (Metal-working industry), जिनमें शस्त्र-निर्माण उद्योग भी सम्मिलित था, में रही। किन्तु सूती कपड़ों का उत्पादन लक्ष्य से कम रहा। पिछली दो पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान विशाल स्तर पर निर्मित उद्योगों के परिणामस्वरूप 1937 में हो रहे समग्र औद्योगिक उत्पादन का 80% भाग नये बनाये गये या जीर्णोद्धार किये हुए कारखानों द्वारा उत्पादित किया जा रहा था। दोनों योजनाओं में मिलाकर

¹ Baykov, *op cit*, 187-89

श्रम उत्पादकता में वृद्धि करने के 63% के लक्ष्य की तुलना में उसमें हुई वास्तविक वृद्धि 82% रही। इस प्रकार अनेक कठिनाइयों एवं चुटियों के बावजूद, जिनका कि उत्तेजक ऊपर किया जा चुका है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना को औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने में प्रथम पंचवर्षीय योजना की तुलना में अधिक सफलता मिली। इसके साथ-साथ औद्योगिक उत्पादन की विस्म में भी भारी सुधार हुआ।

महत्त्वपूर्ण उद्योगों का उत्पादन

	1913	1933	1938
इजीनियरिंग व धातु उद्योग (मिलियन रुबल)	1 446	10 882	33 613
मालबारी टर्क (000)	15	18	49
बोमना (मिलियन टन)	29	76	133
बच्चा लोहा (,)	9	14	27
इस्पात (,)	4	7	18
तांबा (000 टन)	—	45	103
चीनी ()	1,290	995	2 519

कृषि विकास

द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में सामूहिक खेतों (Kolkhoz) तथा राजकीय खेतों (Sovkhoz) को नियंत्रित व नियमित करने के लिए अनेक उपाय किये गये। अब तक सरकार का इस क्षेत्र में अच्छा अनुभव भी प्राप्त हो चुका था। किसान लोग भी अब यह समझ चुके थे कि वे अपनी आर्थिक स्थिति ईमानदारी और मेहनत से काम करके ही सुधार सकते हैं। किसानों से सामूहिक खेतों पर काम करवाने के लिए बल-प्रयोग भी किया गया। जिन किसानों ने राज्य की भूमि को उपयोग के लिए रख दिया था उन्हें भी बुवाई करने व राज्य को अपने उत्पादन का निश्चित भाग सोपाने जाकि स्थानीय सोवियत तम करती थी, के लिए बाध्य होना पड़ा। इन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन में 1933 के बाद निरन्तर वृद्धि होती चली गई जिसने 1935 में राज्य द्वारा राशनिय व्यवस्था उठा लेने की परिस्थितियाँ पैदा की।

कृषि के नियोजित विकास ने राज्य तथा सामूहिक फार्मों को बहुत अल्प समय में कृषि में पर्याप्त एवं महत्त्वपूर्ण परिवर्तन लाने की स्थिति में पहुँचाया। बड़े आकार के पहले कभी काम न लिये गये भूमि के टुकड़ों को कृषि योग्य बनाया गया। 1939 में राजकीय फार्म 60 मिलियन हैक्टेयर भूमि पर फैल चुके थे जिनमें से केवल 3 मिलियन हैक्टेयर भूमि ही पुराने राजकीय फार्मों की भूमि थी। शेष भूमि नई जोड़ी गई थी।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना तथा उसमें पहले प्रथम पंचवर्षीय योजना में हसी कृषि में किये गये इन प्रयोगों के परिणाम अन्य कृषि-प्रधान देशों के लिए भारी महत्त्व रखते हैं। जैसा कि बेकोव ने लिखा है—‘सामूहिक फार्म उत्पादन को,

कृषि का कायापलट

	1913	1933	1938
कुल कृषित क्षेत्र (मिलियन हेक्टेयर)	105	130	137
अनाज उत्पादन (मिलियन टन)	80	90	95
कपास (मिलियन क्विंटल)	6.8	13	27
सुन्दर (")	90	90	167
	1928-32	1933-37	1938
अनाज की औसत उत्पत्ति (क्विंटल प्रति हेक्टेयर)	7.5	9.1	9.3

जिमका अर्थ है बड़े पैमाने की पद्धति वाला उत्पादन, सामूहिक रूपको की छोटी व्यक्तिगत सहायक कृषि (small personal subsidiary farming) के साथ जोड़कर सोवियत रूम में कृषि उत्पादन की समस्या के आर्थिक व सामाजिक पहलुओं को हल करने की चेष्टा की गई है।'

राशनिंग की समाप्ति

रोटी (bread) व अन्य अनाज की बनी चीजों का राशनिंग 1 जनवरी 1935 के एक आदेश से हटा लिया गया। इस आदेश ने अनाजों के लिए एक एकीकृत मूल्य व्यवस्था भी स्थापित कर दी। इस समाप्ति का अर्थ यह था कि लोग अब किसी भी मात्रा में इन चीजों को खरीद सकते थे तथा उन्हें चुनने की भी स्वतन्त्रता थी। सरकार मूल्यों का नियमन पहले ही की तरह करती रही। 1932 के बाद सहकारियों के जाल का प्रसार कर दिया गया और 1939 तक ग्रामीण क्षेत्रों से अनाज की खरीद आदि का 85% काम इन सहकारियों के नियन्त्रण में आ चुका था। निजी स्तर पर चलाये जाने वाले खुदरा व्यापार को पहले ही परिमत्त (liquidate) कर दिया गया था। सामान्यतया सोवियत सरकार मुख्य वस्तुओं के मूल्य नियन्त्रित करने तथा जनसाधारण के काम आने वाली अन्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्य द्वितीय योजना काल में नियमित करने में सफल रही।

घरेलू मामलों में इस आरामदायक स्थिति से देश के लिए अनुकूल व्यापार सन्तुलन पैदा हुआ। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आयातों में काफी कटौती की गई। 1935 के बाद निरन्तर एक अनुकूल भुगतान सन्तुलन की स्थिति भी पैदा हो गई। साथ ही देश के आन्तरिक उपभोग में कटौती किये बिना निर्यातों का प्रसार कर पाना भी सम्भव हो गया। विदेश व्यापार के लिए आयोजन द्वितीय योजना काल में घरेलू व्यापार के आयोजन की अपेक्षा अधिक सफल रहा। निर्यात व आयात इस प्रकार रहे :

	1913	1932	1937
निर्यात (मिलियन रुबल)	1,520	575	395
आयात (")	1,374	704	306

श्रम (Labour)

4 मई 1935 को स्टालिन ने एक नारा दिया - 'कर्मचारीगण हर चीज तय करें' (Personnel decide everything)। यह कथन अनेको उत्पादन-गोष्ठियों में विचार-विमर्श का केन्द्र बना साथ ही उत्पादन के तकनीकी स्तर को सुधारने की मांगों पर वाद-विवाद छेड़ा गया। 30 अगस्त 1935 के दिन कोयला खान के एक मजदूर स्टेखनोव (Stakhanov) ने 6 घण्टों के भीतर 102 टन कोयला निकाल कर (hewing out) एक नया रिकॉर्ड कायम किया। इस कीतिमान की स्थापना ने श्रम-उत्पादकता एवं श्रम-विभाजन को एक नया आयाम (New dimension) प्रदान किया। उसके प्रयोग का अनेक क्षेत्रों में अनुकरण किया गया। स्टेखनोव जैसे श्रमिक अत्यन्त कुशल श्रमिक थे। जो प्रथम एवं द्वितीय योजनाकाल में प्रशिक्षित किये गये थे। स्टेखनोव आन्दोलन (Stakhanov movement) से औद्योगिक उत्पादन के प्रसार में काफी सहायता मिली तथा 1936 में इसकी वजह से उत्पादकता भी काफी बढ़ गई।

मजदूरी के भुगतान को लेकर श्रमिकों में कुछ असन्तोष बना हुआ था। वस्तु-दर (piece-rate) के अतिरिक्त वेतन-मजदूरी भुगतान की ओर भी अनेक व्यवस्थाएँ थीं। मजदूरी के निर्धारण की सबसे अपक्व त्रुटि (crudest mistake) बोन्स प्रणालियाँ की बहुतायत तथा उनके मनमानेपन (arbitrariness) की थी। इजी-नियरो व कुशल श्रमिकों को निरन्तर भुगतान करने का परिणाम यह रहा कि कुछ श्रमिक इजीनियरो से भी अधिक वेतन पाने लगे। द्वितीय महायुद्ध से पहले के वर्षों में इन मजदूरी दरों में संशोधन भी किया गया। इतना ही नहीं विधेयकों के लिए 'व्यक्तिगत वेतन' (personal pay) भी शुरू किया गया।

औद्योगिक रोजगार व मजदूरी

	श्रमिकों व कर्मचारियों की संख्या (मिलियन में)	औसत वार्षिक मजदूरी (रुबल में)
1928	12	703
1932	23	1,427
1937	27	3,038
1938	28	3,467
1942	32	4,100

नये श्रमिकों की प्रथम योजनाकाल में भर्ती भारी मात्रा में की गई थी किन्तु दूसरी पंचवर्षीय योजना में श्रमिकों को दिये गये रोजगार में वृद्धि की दर अधिक नियमित रही। जहाँ पहली योजना में रोजगार प्रदान किये गये श्रमिकों की संख्या निर्धारित लक्ष्य से कहीं अधिक रही थी, दूसरी योजना में रोजगार की यह समस्या निर्धारित लक्ष्य में कुछ कम ही रही। इसके अतिरिक्त प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्रत्येक वर्ष रोजगार उपलब्ध कराने की दर प्रति वर्ष श्रम-उत्पादकता में होने वाली वृद्धि-दर से हमेशा आगे बनी रहती थी वहाँ दूसरी योजना में इसकी बिल्कुल विपरीत

स्थिति रही। 1937 में भारी उद्योगों में प्रति व्यक्ति उत्पादनता 1932 की उत्पादनता का 209% थी जबकि राशियाँ उसे 163% करने का था। इस तरह दूसरी योजना में रोजगार की सराया बढ़ाने की जगह उत्पादनता बढ़ाने पर अधिक जोर दिया गया।

यातायात का विकास

1930 से पहले रूस में बहुत कम राजमार्ग (High ways) थे। जल-परिवहन भी बहुत खराब तरीके से संगठित था तथा रेलों के उपकरण भी बर्बादखानों में डाल देने जैसे हो गये थे। औद्योगीकरण एवं नगरीकरण की प्रवृत्तियों के तीव्रतर होते जाने के साथ ही अच्छी यातायात सुविधाओं के लिए भी माँग बढ़ने लगी। मौजूदा यातायात व्यवस्था के लिए भारी सराया में नये सिरे से स्थापित किये गये प्रतिष्ठानों को कच्चा माल पहुँचा सकना तथा पुनः तैयार माल को देश के दूरस्थ क्षेत्रों तक ले जा सकना सामर्थ्य के बाहर था।

अनेक नई रेलमार्ग परियोजनाओं के निर्माण का काम हाथ में लिया गया। इनमें सबसे महत्वपूर्ण लाइनें (lines) बैकल के उत्तर (North of Baikal) से कोमसोमोलस्क (Komsomolsk) तक तथा साइबेरिया-पार रेलमार्ग (Trans-Siberian Railroad) की एक शाखा थी जिसमें अनेक बड़े सोवियत शहर जुड़ गये। तुर्किस्तान-साइबेरिया रेलमार्ग (Turkestan-Siberian Railway) के निर्माण कार्य के पूरे हो जाने से, जो 1931 में सम्पूर्ण हुई, देश में एक महत्वपूर्ण रेल-कड़ी स्थापित हो गई। लेकिन ये रेलमार्ग देश की आवश्यकताओं को देखते हुए काफी कम थे। जहाँ 1937 में यात्री आवागमन 6 गुना बढ़ चुका था तथा माल की ढुलाई भी 1913 की तुलना में 5 गुनी हो चुकी थी वहाँ इस अवधि में निर्मित अतिरिक्त रेल-लाइनों की लम्बाई में केवल 44% की वृद्धि हुई थी। 1940 में जाकर ही रेल-लाइनों की लम्बाई बढ़ कर 1,00,000 किलोमीटर के योग तक पहुँच सकी थी। पहली पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इन रेलों का प्रबन्ध काफी अकुशल बना रहा तथा कई दिनाशकारी दुर्घटनाएँ हुईं। इन स्थितियों में दूसरी पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में सुधार हुआ।

समस्याएँ व भावी आसार

सबसे कम उपलब्धि वाला क्षेत्र दूसरी पंचवर्षीय योजना में यदि कोई रहा तो वह कृषि क्षेत्र था। यद्यपि सरकार कुलकों के वर्ग को समाप्त करने में सफल हो गई थी लेकिन कृषि के दृढीकरण (consolidation) की जबर्दस्त वायेंवाही बाकी थी। किन्तु कृषि-उत्पादन और विशेष रूप से अन्न उत्पादन बढ़ना शुरू हो गया था। दूसरे, यद्यपि उपभोक्ता वस्तुएँ अभी भी दूसरे स्थान पर थी, जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, उनमें भी सुधार दिखाई देने लगा था। रूसी जनसंख्या के औसत जीवन-स्तर में भी सुधार हो रहा था यद्यपि पश्चात्य जगत की तुलना में अभी भी वह काफी नीचा था।

पूरी होने से पहले द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कई परिवर्तन किये गये।

इनमें से अधिकांश परिवर्तन युद्ध के खतरे के कारण करने पड़े। उपभोक्ता सामग्री तैयार करने वाले हल्के उद्योगों के मूल 150% वृद्धि के उत्पादन लक्ष्य को घटाकर 100% किया गया। दूसरी ओर, भारी उद्योगों के लिए लक्ष्य को और भी बढ़ावा दिया गया। भारी उद्योग की अनेक शाखाओं में तो उत्पादन तिगुना कर दिया गया। दूसरी योजना की समाप्ति तक रूस रेल-इन्जिनो तथा मोटरचालित कृषि उपकरणों के उत्पादन में विश्व का अग्रणी देश बन चुका था। ए० जी० माजूर ने लिखा है कि 'एक जागा हुआ दानव उठ रहा था और वह अपनी सुविशाल आर्थिक क्षमता की शक्ति तथा अपनी विशाल भूमि के प्रति चेतन बन रहा था—मदियों से गहरे पैठ चुके निष्क्रियता के वातावरण से कृषकों को निकालना तथा औद्योगिक श्रमिकों की अल्प उत्पादकता को उच्च उत्पादकता से प्रतिस्थापित करना ही मुख्य उद्देश्य थे। तकनीकी दक्षता में निरन्तरता प्राप्त करना, आधुनिक बड़े पैमाने का उत्पादन करना, मायात्मक एवं गुणात्मक उत्पादन पक्षों को मजबूत करना, जीवन-स्तर में सुधार लाना लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा की कीमत पर नहीं—उस समय के मुख्य नारे बने रहे जब तीसरी पंचवर्षीय योजना को अपनाया जा रहा था।'

दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान कई समस्याओं का भी सामना करना पड़ा। विदेशी पूंजी उपलब्ध नहीं थी। सोवियत सरकार अपने स्वयं के ही न्यून ससाधनों से काम चलाने के लिए बाध्य थी। प्रत्येक उपलब्ध स्वतंत्रता को विनाश पर लगाया गया। बड़ी सराया में गाँवों से सहरो की ओर लोगों की आवक ने भीषण खाद्य एवं आवास की समस्याएँ पैदा कर दी थी। किन्तु चार वर्षों में स्थिति अधिकाधिक स्पष्ट होने लगी यद्यपि उसके लिए जो त्याग किये गये वे स्तम्भित कर देने वाले थे। सोवियत रुम का चेहरा बदल दिया गया। एक आश्चर्यजनक औद्योगिक एवं कृषिगत प्रगति के लिए नींव डाल दी गई थी। सामाजिक ढाँचे को भी पहचाने न जा सकने वाली सीमा तक बढ़ा दिया गया था। राष्ट्र अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा था।

जैसे जो कुछ दो योजनाओं में प्राप्त हो चुका था उससे सतुष्टि नहीं हुई थी इसलिए सोवियत संघ ने अपने सामने एक नया ही लक्ष्य रखा। लक्ष्य था, 'अमरीका को दोड़ में पकड़ना और उससे आगे निकल जाना।' (To catch-up and out-strip America) इस उद्देश्य को पाने के लिए कोई कसर नहीं उठा रखनी थी। इसी अवधि का दूसरा नारा था 'पंचवर्षीय योजना को चार वर्षों में पूरा करो।' सामरिक महत्त्व के उद्योगों में उत्पादन तेजी से बढ़ाया गया। युद्ध के पूर्व-संध्या पर 1941 में रूस का तनिज तेल व इस्पात का उत्पादन 1928 की तुलना में चार गुना तथा कोयले का उत्पादन 6 गुना हो चुका था। भारी संख्या में ट्रैक्टर व अन्य शक्तिचालित वाहनो का उत्पादन किया जा रहा था। 1937 में सोवियत रूस में 2,00,000 कारो का निर्माण हुआ। 1937 तक ट्रकों के उत्पादन में तो सोवियत रूस यूरोप का अग्रणी देश बन चुका था। 1940 तक सोवियत रूस का वित्त-प्रजनन 50 अरब किनोवाट-घण्टे हो चुका था।

इस तथ्य को स्वीकार किया जा चुका है कि 1928 से 1937 की अवधि में

सोवियत आर्थिक विकास पश्चिमी देशों की अपेक्षा अधिक तीव्र था। पश्चिमी देशों में इसी अवधि में आर्थिक विकास पर महान् मन्दी (1930) का बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। प्रो० मूरस्टीन तथा पॉवेल (Moorsteen and Powell) ने इस अवधि में हुए सोवियत संघ के विकास के लिए भिन्न 'भारों' (weights) का उपयोग किया है। उन्होंने अनुमान लगाया है कि 1937 के भारों का उपयोग करने पर 1928-37 की अवधि में सोवियत संघ की आर्थिक विकास की दर 6.2% वार्षिक आती है जबकि 1928 के भारों का उपयोग करने पर यह विकास-दर 11.9% थी। एक अन्य पश्चिमी लेखक बर्गसन (Bergson) ने अनुमान लगाया है कि 1928 से 1937 की अवधि में सोवियत संघ में विनियोग दर कुल राष्ट्रीय उत्पाद (G N P) के 12.5% से बढ़ाकर 26% कर दी गई थी तथा भारी उद्योगों के उत्पादन में उपभोक्ता उद्योगों के उत्पादन की तुलना में दुगुनी तेजी से वृद्धि हुई थी। बर्गसन का कहना है कि दुनिया के किसी भी अन्य देश ने इतनी कम अवधि में अपने वृद्ध प्रयासों को इतनी तीव्र गति से नहीं बढ़ाया है। इसके साथ ही रक्षा-व्यय भी कुल राष्ट्रीय उत्पाद के 1.3% से बढ़कर इसी अवधि में 7.9% हो चुका था। निजी उपभोग में भारी कटौती की गई।

सोवियत कुल राष्ट्रीय व्यय 1928-37

(प्रतिशत में)

	1928	1937
निजी उपभोग	79.5	52.5
सामुदायिक सेवाएँ	4.6	10.5
सरकारी प्रशासन	2.1	3.2
रक्षा	1.3	7.9
कुल स्विचर विनियोग	12.5	21.9
माल तालिकाएँ		3.9

Source A Bergson, *The Real National Income of Soviet Russia since 1928*, Harvard, 1961, 130-392

एक अन्य सरचनात्मक परिवर्तन प्रथम दो योजनाओं की अवधि में रोजगार के क्षेत्र में आया। 1928 से 1937 के बीच की अवधि में गैर कृषि श्रम शक्ति कुल श्रम-शक्ति की 29% से बढ़कर 46% हो गई। इसी अवधि में गैर कृषि उत्पादन भी कुल उत्पादन का 52% से बढ़कर 69% हो गया। यह वही काल था जिसमें सोवियत संघ से बेकारी का उन्मूलन कर दिया गया था जिससे कि शहरों की 20 लाख जनसंख्या प्रभावित हो रही थी।

कई विदेशी लेखकों ने सोवियत सरकार की इस बात को लेकर आलोचना की है कि उसने औद्योगीकरण में बड़ी उतावली व निर्दयता (hasty and merciless) से काम लिया था। यह सही है कि सोवियत योजनाओं में मानवीय भावनाओं के लिए कोई स्थान नहीं था किन्तु इसके लिए स्टालिन का उत्तर काफी रुखा था।

उमने उस वाक्य को उद्धृत किया जो लेनिन ने अक्टूबर क्रान्ति की पूर्व संध्या पर कहा था 'या तो नष्ट हो जाओ या फिर विकसित पूँजीवादी देशों से आगे निकल चलो।' (Either perish, or overtake and outstrip the advanced capitalist countries)

सोवियत शासन के लिए पंचवर्षीय योजनाएँ वे उत्तोलक (levers) थी जिनसे वह राष्ट्र को ताम्बे समय से चली आ रही सुस्ती की स्थिति से निकाल कर उसे अपनी छिपी हुई शक्ति व क्षमता का भान करा सकती था। औद्योगीकरण की अत्यधिक तीव्र गति के द्वारा ही सरकार बेकारी का उन्मूलन कर सकती थी तथा सोवियत संघ को विश्व के अग्रणी औद्योगिक राष्ट्रों की पंक्ति में खड़ा कर सकती थी। शायद इसी लक्ष्य को अपने मस्तिष्क में रखते हुए सोवियत सत्ता ने स्टालिन के नेतृत्व में कभी नरम व कभी आरामदेह विकल्प (soft options) नहीं चुने।

आठवाँ अध्याय

नियोजन और स्टालिन युग का अन्त

(UPTO END OF STALIN ERA)

तीसरी पंचवर्षीय योजना

तीसरी पंचवर्षीय योजना दूसरे महायुद्ध की विभीषिका के नीचे पूरी तरह छिप गई। उसका मुरझाये हुए राष्ट्र की रक्षा करना बन गया। रक्षा सामग्री के उत्पादन को बढ़ाने की दृष्टि से भारी विनियोगों को उनकी ओर मोड़ने की आवश्यकता पड़ी तथा मारिस् डॉब ने लिखा है कि 'विनियोग व रक्षा पर मिले-जुले व्यय ने रुम द्वारा युद्ध में कूद पड़ने से पहले के वर्ष की राष्ट्रीय आय का शायद आधा हिस्सा निगल लिया था।'

जनवरी 1934 में ही सत्रहवीं कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस ने विकास की गति को तीव्र करने के उद्देश्य से कुछ सशोधनों का (द्वितीय पंचवर्षीय योजना में) मुद्दाव दिया था। इन सशोधन में उद्योगों में मन्त्रीकरण (mechanisation) की गति को तीव्रतर करना, थम कुशलता में वृद्धि करना, अल्प लागतों पर अच्छी किस्म की औद्योगिक वस्तुओं का उत्पादन करना तथा घरेलू बाजार के लिए उपभोक्ता वस्तुओं की बढ़ी हुई मात्रा उपलब्ध कराना सम्मिलित थे।¹ लेकिन इन सशोधनों को आगामी योजना में सम्मिलित करना इसलिए सम्भव नहीं रह गया था कि इस बीच अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति बहुत विस्फोटक हो चली थी। जब 1938 में तीसरी पंचवर्षीय योजना की घोषणा की गई तो देश के सम्मुख सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उसकी अपनी रक्षा

तुलनात्मक उत्पादन व लक्ष्य

	1938	1942 के लिए तृतीय योजना के लक्ष्य
लोह पिंड (मिलियन टन)	15	22
इस्पात "	18	28
कोयला "	133	243
सनिज तेल "	32	54
बनाज "	95	133
मूनी कपड़ा (मिलियन मीटर)	3,491	4,900

Source * Maurice Dobb, *Soviet Economic Development since 1917*, 311.

¹ A. G. Mazour, *op cit*, 55.

का था। जैसा-जैसे युद्ध के बादल गहरे होते चले गए वैसे-वैसे उपभोक्ता उद्योगों की अनदेखी हुई। यह आशा, कि आखिरकार अब तीसरी योजना में तो लोगों को अधिक उपभोक्ता वस्तुएँ उपलब्ध हो सकेंगी, चूर चूर हो गई।

1942 के लिए निर्धारित इन लक्ष्यों में दूसरे महायुद्ध ने बाधा डाली। इसलिए तीसरी पंचवर्षीय योजना प्रायः अधूरी ही रही। 1941 तक सैनिक व्यय 1938 की तुलना में तिगुना हो चुका था। जब 1941 में नाज़ी जर्मनी ने सोवियत संघ पर आक्रमण कर दिया तो देश के सामने एकमात्र प्रश्न उसके अपने अस्तित्व की रक्षा का रह गया था।

योजना के मुख्य उद्देश्य

(1) यातायात के विकास पर अत्यधिक बत दिया गया जिसे युद्ध एवं शांति दोनों ही समयों में अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया।

(2) अलौह धातुओं (Non-ferrous metals) का उत्पादन तथा रसायन उद्योग के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। 'तीसरी योजना को रसायन योजना बनाओ'—नारा दिया गया।

(3) उद्योगों को देश के पूर्वी भाग में स्थानान्तरित करने के काम में तेज़ी लानी थी। कॉकेशियाई तेल क्षेत्र (Caucasian oil fields) काफी अमुरक्षित थे। युद्ध के समय तेल की पूर्ति से वंचित हो जाने के सम्भावित खतरे से बचने के लिए यूरेल के तेल क्षेत्रों में (जहाँ तेल उन्हीं वर्षों में मिला था) तेल की और खोज को तीव्र कर दिया गया।

(4) तीसरी पंचवर्षीय योजना का मूल बिन्दु भारी उद्योगों का विकास करना बना रहा। रक्षा आवश्यकताओं को देखते हुए यह लक्ष्य और भी महत्वपूर्ण बन गया।

(5) युद्ध को निकट ही भाँपते हुए तीसरी पंचवर्षीय योजना में शुरु से ही राष्ट्रीय प्रतिरक्षा उपायों को दृढ़ करने के उपायों पर बल दिया गया। इसी बात को ध्यान में रखते हुए तीसरी योजना में राष्ट्रीय यातायात व्यवस्था स्थापित करने, इस्पात मशीनी औज़ार तथा रासायनिक उद्योगों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया था। सैनिक दृष्टि में महत्वपूर्ण धातुओं को प्राथमिकता दी गई। योजना में कुछ रेलमार्गों का विद्युतीकरण करने तथा अन्य कुछ मार्गों पर दोहरी लाइनें बिछाने का भी लक्ष्य रखा गया।

युद्ध के लिए तैयारी से लोगों को 'परिश्रम और रक्त' ही मिलने का वायदा था। जैसा कि डॉब ने लिखा है, 'साधारण नागरिक के लिए तंगी के वर्षों में उसके द्वारा की गई मेहनत के फल जैसे ही पकने लगे थे वैसे ही उन्हें पहले तो शस्त्रीकरण के लिए किये जा रहे प्रयासों ने तथा बाद में निर्देयी व थका देने वाले युद्ध ने छीन लिया।'।

(6) तीसरी पंचवर्षीय योजना ने पहले की औद्योगिक प्रतिष्ठान बनाने की नीति का परित्याग करने का उद्देश्य भी रखा। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि बड़े प्रतिष्ठानों का संतर्भता काल (gestation period) अत्यधिक लम्बा होता था।

सामरिक दृष्टि से कुछ ही प्रतिष्ठानों पर अत्यधिक निर्भरता भी अबुद्धिमत्तापूर्ण समझी गई। इसके परिणामस्वरूप उद्योगों को विभिन्न प्रदेशों में फैलाकर स्थापित करने तथा छोटे कारखाने बनाने की नीति अपनाने का निर्णय लिया गया।

द्वितीय महायुद्ध के प्रभाव

प्रथम दो पंचवर्षीय योजनाओं में उपभोक्ताओं की अनदेखी की गई थी क्योंकि योजनाकार एक औद्योगिक आधार का जल्दी से निर्माण करना चाहते थे। एक नया तत्त्व जो उन्हें आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं से आगे भी ध्वस्त रखने वाला था वह शस्त्र निर्माण पर अत्यधिक व्यय की नयी रणनीति थी जोर साथ ही उद्योगों को युद्ध सामग्री का उत्पादन करने के लिए रूपान्तरित करने की प्रवृत्ति थी। कुल मिलाकर केवल 15% विनियोग उपभोक्ता वस्तुओं के लिए बच रहा था। औद्योगिक उत्पादन के लिए सर्वांगीण विकास दर तीसरी योजना के लिए 14% रखी गई थी। यह साधारण दर भी प्राप्त नहीं की जा सकी। आक्रमक देश जर्मनी निश्चय ही अधिक शक्तिशाली देश था। रूस जैसे देश के लिए, जिसके पीछे एक दशक के नियोजन का ही आधार था, ऐसे शक्तिशाली शत्रु का सामना करना काफी कठिन काम था। अन्तिम रूप से जो बात सोवियत रूस के पक्ष में रही और जिसने उसे युद्ध में विजय भी दिलाई वह उसकी आर्थिक शक्ति से कुछ अधिक ही रही।

द्वितीय महायुद्ध ने एक बात सिद्ध कर दी कि सोवियत संघ का नियोजित विकास एक सही दिशा में उठाया गया कदम था। उसी के बल पर देश अपने उद्योगों को बहुत ही अल्प सूचना पर युद्ध सामग्री के निर्माण के लिए रूपान्तरित कर सका था। लेकिन साथ ही युद्ध ने कुछ खनिजों तथा कुछ औद्योगिक उपकरणों जैसे मशीनी औजार की कमी की और भी खराब स्थिति में पहुँचा दिया।

युद्ध ने देश में भारी विनाश का दृश्य उपस्थित कर दिया। 1942 की सर्दी के मौसम में किया गया आकस्मिक आक्रमण सोवियत संघ के लिए बड़ा महंगा पड़ा। जर्मन फौज उसकी सीमाओं के 1,200 मील भीतर घुस आई तथा उसे उसके कई खनिज व औद्योगिक केन्द्रों से ध्वस्त कर दिया। कोयले, लोहे, इस्पात व खनिज तेल की आपूर्ति 60 से 70 प्रतिशत तक घट गई तथा कृषि पदार्थों का उत्पादन भी 35 प्रतिशत कम हो गया। जैसे-जैसे जर्मन फौज आगे बढ़ी रूसी लोग अपने उद्योगों को पूर्वी प्रदेशों की ओर ले जाते रहे। लेनिनग्राद उद्योगों का लगभग 70% साज-सामान 1941-42 के दौरान खाली किया गया था। 'बीरान' इलाकों में मनुष्यों को ले जाकर बसाने का भी काम किया गया। ऐसे युद्ध निर्वासित लोग, जिन्हें फिर से नए इलाकों में बसाया गया, 12 मिलियन के लगभग रहे।¹

यह अनुमान लगाया गया कि युद्ध ने सोवियत संघ की उत्पादन क्षमता में एक-चौथाई कमी कर दी थी। इतना ही नहीं, युद्ध ने लगभग ढाई करोड़ लोगों को बेघर कर दिया था।

पुनर्निर्माण कार्यक्रम

युद्ध के वर्षों में उद्योगों के पूर्वी भागों में स्थानान्तरित कर दिये जाने से देश में आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति बनी रही क्योंकि इन स्थानान्तरित उद्योगों ने 1943 में ही उत्पादन आरम्भ कर दिया था। लेकिन युद्ध ने जो सर्वाधिक विशालकाय और अत्यावश्यक समस्या छोड़ी थी वह ध्वस्त हो चुके विशाल क्षेत्रों को फिर से आबाद करने की थी। लाखों, करोड़ों लोगों को, जो निर्वासित या अपग हो गये थे, फिर से बसाने की समस्या सबसे अधिक दबाव डाल रही थी। सरकारी आँकड़ों के अनुसार, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण सोवियत संघ को 485 अरब अमरीकी डॉलरों के बराबर हानि उठानी पड़ी जो उसकी 6 वर्षों की कुल राष्ट्रीय आय के बराबर थी। सम्पत्ति का होने वाला नुकसान इस प्रकार रहा 1,710 शहर, 70,000 गाँव, 35,000 प्लांट व कारखाने, 40,000 अस्पताल, 60 लाख भवन, तथा कम से कम ढाई करोड़ बेघरदार लोग। सोवियत सरकार द्वारा प्रकाशित युद्ध के पन्द्रह वर्ष के बाद के आँकड़ों से स्पष्ट होता है कि उसका उत्पात उत्पादन 1942 में 60 प्रतिशत से गिर गया—अर्थात् 18 मिलियन टन से घट कर 8 मिलियन टन रह गया था। कोयले का उत्पादन 1940 के 166 मिलियन टन से घटकर 1942 में 75 मिलियन टन रह गया। अनाज के उत्पादन में भी भारी गिरावट आयी क्योंकि कृषि क्षेत्र में 60% की बर्बाद आ गई थी। एक ऐसी अर्थव्यवस्था, जिसको इतनी अधिक हानि सहनी पड़ी हो, का पुनर्निर्माण कोई आसान काम नहीं था। यह काम कम से कम तीसरी पंचवर्षीय योजना की तो सामर्थ्य के बाहर की बात थी। यह भीषण कार्य चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए छोड़ दिया गया।

चौथी पंचवर्षीय योजना

देश के सामने सबसे आवश्यक कार्य युद्ध-पूर्व के कृषि व औद्योगिक उत्पादन स्तरों को पुनः प्राप्त करना था। यही ब्रह्म एकमात्र उपाय था जो जीवन-स्तर को ऊँचा उठा सकता था तथा अर्थव्यवस्था की गाड़ी को पुनः पटरियों पर ला सकता था। इस अत्यावश्यक कार्य को प्रभावी रूप प्रदान करने के उद्देश्य से ही 18 मार्च 1946 को चतुर्थ पंचवर्षीय योजना स्वीकार की गई।

चौथी योजना से 1946-50 के दौरान सोवियत अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण एवं विकास काय को पूरा करने की अपेक्षा की गई। उद्योगों के विकास के लिए 205 अरब रूबल की एक बहुत बड़ी राशि आवंटित की गई। भारी उद्योग अब भी विकास कार्यक्रम का केन्द्र-बिन्दु बने रहे क्योंकि यह तर्क दिया गया कि विकास व पुनर्निर्माण के लिए सामग्री इनसे ही प्राप्त हो सकती है। इसके अतिरिक्त देश की सैनिक शक्तता को न केवल बनाये रखने की आवश्यकता थी बल्कि उसका विकास करने की भी आवश्यकता थी ताकि अमरीका की बराबरी की जा सके। यह सब देश के औद्योगीकरण से ही सम्भव था।

अतः चौथी योजना में लोहा व इस्पात, कोयला, मशीन-निर्माण तथा खाद्यान्न

के उत्पादन में बहुत ऊँची वृद्धि दर प्राप्त करने की बात कही गई। लोहा व इस्पात का उत्पादन युद्ध-पूर्व के उत्पादन स्तर से भी 35% ऊपर रखा गया, कोयले का उत्पादन 50% तथा विद्युत शक्ति का उत्पादन 70% ऊपर रखा गया। सबसे अमाधारण लक्ष्य इजीनियरिंग वस्तु उद्योग के लिए निर्धारित किये गये मशीनों का उत्पादन दुगुना करने का लक्ष्य रखा गया। ट्रैंक्टरों तथा मोटरो का उत्पादन लक्ष्य युद्ध-पूर्व के उत्पादन से साढ़े-तीन गुना रखा गया।

अक्टूबर 1948 में सोवियत सरकार ने अगले 15 वर्षों के लिए एक भूमि पुनर्ग्रहण कार्यक्रम (land reclamation programme) घोषित किया जिसमें 300 मिलियन एक्ड भूमि सम्मिलित की जानी थी। कार्यक्रम के बारे में की गई, सरकारी घोषणा में कहा गया कि यह कार्यक्रम, 'मूखा पड़ने के विरुद्ध आक्रमण था या जिसमें कृषि के सबसे पुराने मंत्र पर विजय सुनिश्चित थी।' इस योजना के कई पहलू थे जिनमें भूमि के कटाव को रोकना, मिचाई की मुविधाओं में वृद्धि करना, नए वन लगाना तथा मन्त्रीकृत खेती करना सम्मिलित थे। इस विज्ञात कृषि कार्यक्रम के लिए भारी मात्रा में विनियोग की आवश्यकता थी। सरकार ने फिर एक बार घरेलू वचन की दर को बढ़ाने की नीति अपनायी।

इसे विडम्बना ही कहा जाना चाहिए लेकिन चौथी योजना में भी उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन के बारे में कोई सुनिश्चित लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये। उन्हें अपने हाल पर ही छोड़ दिया गया। टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने के बारे में कुछ शब्द कहे गये। लेकिन उपभोक्ता उद्योगों के प्रसार की दर भारी उद्योगों के प्रसार की दर से काफी नीची बनी रही।

आधारभूत उद्योगों की वस्तुओं के उत्पादन में औसत वार्षिक निरपेक्ष वृद्धियाँ (पंचवर्षीय योजनाओं के परिणाम)

	पहली योजना 1928-32	दूसरी योजना 1933-37	तीसरी योजना 1938-40	चौथी योजना 1946-50
विद्युत (000 मिलियन कि०वा०)	2.1	4.5	4.0	9.6
तेल (मिलियन टन)	2.4	1.4	0.9	3.7
कोयला "	7.2	12.7	12.7	22.4
लोह पिंड "	७.7	1.7	७.1	2.1
इस्पात "	0.4	2.4	0.2	3.0

Source SSSR v tsifzakh v 1970, Moscow, 1971, 90

आधारभूत औद्योगिक वस्तुओं की औसत वार्षिक निरपेक्ष वृद्धियों के ये आँकड़े स्पष्ट करते हैं कि ये वार्षिक वृद्धियाँ अन्य तीन योजनाओं की तुलना में चतुर्थ योजना में काफी ऊँची रही। स्पष्टतः चतुर्थ योजना की इन दोषों में उल्लिखित काफी ठीक रहीं।

मुरय फसलो का उत्पादन

(मिलियन टन मे)

कृषि फसल	1928	1940	1950
अनाज	73	96	81
कपास	0.79	2.24	3.54
चूना	10	18	21
आलू	46	76	89
मक्कियाँ	11	14	9

Source SSSR, *op cit*, 108

आँकड़ों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि 1950 तक भी सोवियत संघ का अनाज का उत्पादन 1913 के 86 मिलियन टन के अनाज उत्पादन स्तर को प्राप्त नहीं कर पाया था। अन्य कृषि पदार्थों का उत्पादन स्तर भी बहुत अच्छा नहीं रहा।

चौथी पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों काफी कठिन रहे। देश में ऐसा सूखा पड़ा जो पिछले 50 वर्षों में कभी नहीं पड़ा था। उद्योग का पुनरुद्धार भी 1947 तक ही सम्भव हो पाया। मौद्रिक सुधार किये गये तथा पुराने रूबल की जगह नया रूबल चलाया गया। दिसम्बर 1947 तक खाद्य पदार्थों का राशनिंग भी समाप्त कर दिया गया। वास्तविक मजदूरी में काफी वृद्धि हुई। खुदरा मूल्य स्तर को नीचे लाया गया। 1954 में वह युद्ध पूर्व के स्तर से केवल 20% ही अधिक था जबकि मजदूरी का स्तर युद्ध पूर्व की अपेक्षा 65% ऊपर था। इस तरह चौथी योजना के लक्ष्य उसकी अवधि समाप्त होने से पहले ही पूरे हो चुके थे। औद्योगिक उत्पादन युद्ध-पूर्व के स्तर से 70% ऊपर पहुँच चुका था यद्यपि उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योगों की युद्ध पूर्व की विवाम दर पर 23% की वृद्धि ही हो पायी थी। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की एकमात्र कमजोरी यही रही कि उसके दौरान खाद्यान्नों के उत्पादन का पुनरुद्धार नहीं हो पाया।

1953 में आर्थिक स्थिति

1953 में स्टालिन की मृत्यु सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था के इतिहास में एक युग की समाप्ति का प्रतीक मानी जा सकती है। स्टालिन ही वह व्यक्ति था जिसने देश में आयोजन की पद्धति शुरू की थी तथा उसे निष्पन्नित किया था। क्योंकि वह भारी उद्योगों का पक्षधर था इसलिए उसके शासन काल में भारी उद्योग बराबर पनपते रहे। मनोवैज्ञानिक धरातल पर यदि हम सम्पूर्ण स्थिति का विश्लेषण किया जाये तो यही प्रतीत होता है कि भारी सत्यन्त या उद्योग स्टालिन को शक्ति व सुरक्षा की भावना का अनुभव कराते थे। वह भारी उद्योगों को पहली व सर्वोच्च प्राथमिकता देने की अपनी घोषित नीति से सभी विचलित नहीं हुआ। स्टालिन की मृत्यु के समय कृषि की स्थिति काफी शोचनीय थी जब स्टालिन की मृत्यु हुई। ऐसा इसलिए हुआ कि निजी पहल (private initiative) के अभाव में स्टाचिन युग में किये गये कृषि सुधार के प्रयास सफल नहीं रहे।

नियोजित अर्थव्यवस्था के पच्चीस वर्षों में अर्थात् चौथाई सदी में औद्योगीकरण के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए। कुशल श्रमिकों व कर्मचारियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई। तकनीकी विशेषज्ञों (Technocrats) तथा वैज्ञानिकों का वर्ग अधिकाधिक प्रभावशाली बनता जा रहा था। सोवियत संघ एक ऐसी स्थिति में पहुँच चुना था जहाँ वह कई यूरोपीय देशों से आगे निकल सकता था।

युद्धोत्तर काल में भी सोवियत संघ का पुनरुद्धार तेजी से हुआ। 1937 से 1953 तक की अवधि में सोवियत अर्थव्यवस्था की औसत वार्षिक विकास दर 3.5% के लगभग रही। यह विकास दर किसी भी पश्चिम यूरोप के देश से अधिक ऊँची थी। यह तो केवल कृषि का क्षेत्र ही ऐसा रहा जिसमें सोवियत संघ कोई महत्त्वपूर्ण उपलब्धि नहीं कर पाया। किन्तु कृषि के क्षेत्र में भी एक सरचनात्मक परिवर्तन आ चुका था जिसके कृषि पर दूरगामी प्रभाव पड़ने अवश्यम्भावी थे।

कृषि का कुल रोजगार व राष्ट्रीय उत्पाद (G N P.) में भाग (1926-65)

	1928	1937	1953	1965
रोजगार	71	54	40	30
कुल राष्ट्रीय उत्पाद (G N P)	48	31	19	15

किन्तु यह बात भी सर्वविदित हो गई थी कि सामूहिकीकरण के प्रयोगों के वांछित परिणाम सोवियत कृषि के क्षेत्र में परिलक्षित नहीं हुए हैं। स्टालिन की मृत्यु की पूर्व संध्या पर रूस जितना अनाज पैदा कर रहा था वह 1914 के स्तर की तुलना में मात्र 10% ही ऊपर था। प्रति व्यक्ति खेतीहारा आय भी सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए आय के औसत से आधी ही थी। निम्न सम्पत्तिहीन हो चुके थे तथा इन कृषकों को इस बात का भारी अपसोस भी था। स्टालिन के क्रूर तरीकों की भी भर्त्सना की गई। वह देश की 2% जनसंख्या (लगभग 40 लाख) के जबरन मजदूरी कैंम्पो में कारावास व यातना भोगने के लिए भी उत्तरदायी था। सोवियत कृषि का जहाँ तक प्रश्न है, स्टालिन ने उसकी जितनी समस्याएँ हल की थी उनसे अधिक उसने पैदा कर दी थी।

नवा अध्याय

स्टालिनेतर युग में नियोजन (PLANNING IN POST-STALIN ERA)

मार्च 1953 में स्टालिन की मृत्यु ने सोवियत राजनीति में एक रिसता ला दी। सोवियत संघ के नेतृत्व में शीघ्रता से परिवर्तन होते रहे। उसका प्रधानमन्त्री पद जल्दी-जल्दी व एक के बाद एक—मेलेंकोव (Malenkov), बुलगानिन (Bulganin) तथा ख्रुश्चेव (Khrushchev) को मिला। नेतृत्व में इतनी शीघ्रता से परिवर्तन स्टालिन के बाद के सभी नेताओं में परस्पर विरोधी विचारधाराएँ होने के कारण हुए। स्टालिन ने तो सर्वप्रथम उद्योगों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने में विश्वास किया था। उसने 1930 के बाद से ही कृषि के क्षेत्र में भी सामूहिकीकरण की नीति को बराबर जारी रखा था। इस सामूहिकीकरण की नीति की ही अग्र पुनर्परीक्षा की जा रही थी।

पाँचवी पंचवर्षीय योजना की सार्वजनिक रूप से घोषणा अप्रैल 1952 में उत्तरीय पार्टी कांग्रेस में कर दी गई थी।

पाँचवी पंचवर्षीय योजना

उद्देश्य व मुख्य उपाय

(1) उपभोक्ता वस्तुओं पर बल—पाँचवी पंचवर्षीय योजना पहली अन्य योजनाओं से कुछ इस रूप में भिन्न थी कि उसमें उपभोक्ता वस्तुओं तथा पूँजीगत वस्तुओं के उत्पादन को लगभग एक समान प्राथमिकता प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया था। पूँजीगत एवं उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन लक्ष्य क्रमशः 80% व 65% वृद्धि के रखे गये। प्रधानमन्त्री मेलेंकोव, जो स्टालिन का उत्तराधिकारी बना, का यह विश्वास था कि अब समय आ गया है कि जब हमेशा से अनुदेने किये जाते रहे सोवियत उपभोक्ता के वर्तमान पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। अप्रैल 1953 में इस आशय की एक सरकारी घोषणा की गई कि सरकार ने अनेक उपभोक्ता वस्तुओं तथा खाद्य पदार्थों के मूल्य घटाने का फैसला किया है। परिणामस्वरूप मांस के मूल्यों में 15%, औरतों के कपड़ों में 14%, सब्जियों में 50% तथा रोटी के मूल्यों में 10% की कटौती की गई। उपभोक्ताओं के हाथों में अधिक क्रय-शक्ति छोड़ने के उद्देश्य से सरकार ने राजकीय बाण्डों की अनिवार्य खरीद में भी 50% की कटौती कर दी।

इस अकेले उपाय ने सोवियत उपभोक्ताओं को इतनी राहत प्रदान की कि उनके पास अब उपभोक्ता वस्तुओं पर खर्च करने के लिए 15 अरब रूबल अधिक राशि थी। किन्तु उपभोक्ताओं के हाथों में त्रय शक्ति बढ़ा देने मात्र से समस्या का समाधान नहीं हो गया। अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता वस्तुओं की भारी कमी बनी हुई थी।

अगस्त 1953 में सर्वोच्च सोवियत (Supreme Soviet) के समक्ष प्रधानमंत्री मेलेंकोव ने दलील दी कि हालांकि बड़े उद्योगों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती रहती चाहिए किन्तु जब उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए भी अनुकूल दशाएँ विद्यमान हैं। उसने इस कदम की अत्यावश्यकता पर भी जोर दिया। इस उद्देश्य के लिए, उनने आगे कहा, अनेकों औद्योगिक प्रतिष्ठानों को बड़े पैमाने पर उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करने वाले कारखानों में रूपांतरित करना होगा। ऐसा कहकर मानो मेलेंकोव ने तो मधु-मक्खी या ततैय्यों के छत्ते को छेड़ दिया था। उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करने का प्रयत्न स्टालिन युग में केवल अकादमिक महत्त्व (academic interest) व हल्के-फुल्के मतलब का ही रहा था। मेलेंकोव के विरोधियों ने अब यह तर्क पेश किया कि इस प्रकार की नीति सोवियत राज्य की सुरक्षा के लिए हानिकारक होगी तथा वह उसकी औद्योगिक प्रगति पर भी विपरीत प्रभाव डालेगी। इस तरह मेलेंकोव के प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं हो पाया तथा उसे त्यागपत्र देकर अलग होना पड़ा। उसका विरोधी ए.इ.चेव था जो कुछ वर्षों बाद स्वयं भी इसी नीतियों पर लौटा था।

(2) अनाज का उत्पादन बढ़ाना—पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का दूसरा महत्त्वपूर्ण उद्देश्य अनाज के उत्पादन में 40 से 50 प्रतिशत तक की वृद्धि करना था। विद्यार्थी उपलब्धियों को देखते हुए यह काफी महत्वाकांक्षी लक्ष्य था। अन्य कृषिगत वस्तुओं के लिए भी उतने ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य रक्ते गये। यहाँ भी मेलेंकोव कुछ परिवर्तन करना चाहता था। उनकी इच्छा कृषि पदार्थों का मूल्य बढ़ाने की थी ताकि कृषकों को कुछ अधिक उत्पादन बढ़ाने सम्बन्धी अभिप्रेरणा मिल सके। उसने सामूहिक कृषक द्वारा उसके अपने निजी क्षेत्र की देखभाल में भी अधिक स्वतन्त्रता प्रदान करने की वकालत की। उसने यह भी तर्क दिया कि कृषकों को सज्जियों व अन्य टैररी उत्पादनों के लिए ऊँचे मूल्य दिये जाने चाहिए ताकि उन्हें उनका उत्पादन बढ़ाने के लिए अभिप्रेरणा (incentive) मिल सके।

लेकिन पार्टी ने इन रियायतों को दूसरी ही दृष्टि से देखा। यह भय व्यक्त किया गया कि इस तरह की रियायतें पार्टी के आदर्शों (ममाजबादी) के विरुद्ध होंगी। एक अधिक सावधानीपूर्ण कदम लेने की सिफारिश की गई। सिद्धान्त रूप में सामूहिक निमान द्वारा अपने निजी भूमि के टुकड़े (private plot) पर अधिक समय दे मजदूरी अनुमति देने की बात स्वीकार की गई लेकिन ऐसा सामूहिक क्षेत्र के काम की कीमत पर नहीं किया जाना था। 1954 में सरकार ने घोषणा की कि सामूहिक फार्म के प्रत्येक पुरुष सदस्य को वर्ष में 300 कार्य दिवस तथा स्त्री-सदस्य को 200 कार्य दिवस तक काम करना होगा।

□ सोवियत संघ का आर्थिक विनाश/5

पाँचवी योजना का मूल्यांकन

यह एक दुर्भाग्यपूर्ण बात रही कि मेलकोव द्वारा किसानों के लिए रियायतों तथा उपभोक्ताओं के लिए हितकारी बातें 1953 के खराब फसल वाले वर्ष में कही गईं। 1950 के दशक के आरम्भिक वर्षों में अनाज के उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई थी। पशुओं के चारे व आहार की भी भारी कमी थी जिससे दूध व मांस का उत्पादन भी घट गया था। पुनः एक बार कृषि उत्पादन को बढ़ाने के उपाय किये गये। मेलकोव का विरोध कर चुकने के बावजूद पार्टी ने अब आर्थिक अभिप्रेरणाओं पर प्रशासनिक उपायों से अधिक निर्भरता रखने की बात स्वीकार की। पाँचवी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में अनाज के उत्पादन में 1950 के स्तर पर 29% की वृद्धि हुई।

1950-55 की अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादन में 85% की वृद्धि हुई। पहली बार उपभोक्ता वस्तु उद्योगों के उत्पादन में 76% की वृद्धि रिकार्ड की गई। पूँजीगत वस्तुओं के उत्पादन की प्रमुखता फिर भी बनी रही तथा इसी अवधि में 80% के वृद्धि-लक्ष्य की तुलना में उनका उत्पादन 91% से बढ़ा। उद्योग के क्षेत्र में यह विकास दर वास्तव में असाधारण थी। इसकी प्रशंसा करते हुए डॉब ने लिखा कि 'यह अमरीका में 1899 से 1937 के बीच रही विकास दर की तीन गुना, पश्चिमी यूरोप के देशों में औद्योगिक उत्पादन में 1950 से 1955 के बीच की वृद्धि दर की भी तीन गुना तथा इस अवधि में अमरीकी विकास दर की दुगुनी थी।'

आधारभूत औद्योगिक वस्तुओं में औसत वार्षिक निरपेक्ष वृद्धि (पंचवर्षीय योजनाओं के परिणाम)

	पाँचवी योजना 1951-1955	छठी योजना 1956-1960	सातवी योजना 1961-1965	आठवी योजना 1966-1970
विद्युत, 000 मिलियन (कि॰वा॰)	16	24	43	47
तेल (मिलियन टन)	7	15	19	22
कोयला ()	26	24	14	9
लोह पिंड ()	3	3	4	4
इस्पात ()	4	4	5	5

छठी पंचवर्षीय योजना

1956 में जब ख़रुश्चेव (Khrushchev) ने प्रधानमन्त्री पद सम्भाला तो राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के प्रबन्ध एवं नियन्त्रण में अनेक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किये गये। औद्योगिक श्रमिकों के लिए अधिक स्वतन्त्रता स्वीकृत की गई जो उन्हें स्टालिन के समय में कभी नहीं मिली थी। मजदूरी तथा पेंशनों की नई दरें सुझाने के लिए एक राजकीय समिति नियुक्त की गई। जोखिम वाले कामों में लगे हुए श्रमिकों के लिए अधिक मजदूरी की सिफारिश की गई। श्रम-सघोषों को अधिक सक्रिय रूप से कार्य

करने की छूट दी गई तथा प्रबन्ध के मामलों और मजदूरी तथा तकनीकी सुधारों को लेकर उन्हें अधिक आलोचनात्मक व स्पष्ट सम्मति देने की अनुमति दे दी गई। इस प्रकार सोवियत संघ में एक परिवर्तन जन्म ले रहा था।

उद्देश्य

1956 में प्रारम्भ की गई छठी योजना में भारी उद्योगों के समर्थकों तथा उपभोक्ता वस्तुओं के प्रवक्ताओं के बीच एक प्रकार का समझौता कराने का प्रयास किया गया था।¹ योजना में राष्ट्रीय आय 60% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया। औद्योगिक उत्पादन में 65% वृद्धि तथा मजदूरी में 30% वृद्धि का आश्वासन भी इस योजना के उद्देश्यों में सम्मिलित किया गया।

उपभोक्ता वस्तु उद्योगों तथा पूँजीगत वस्तु उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि की दरें क्रमशः 60% व 70% निर्धारित की गयी। इन दोनों के बीच अन्तर घटाने का विचार व्यक्त किया गया। उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने की प्रवृत्ति पाँचवीं पंचवर्षीय योजना द्वारा धुरु की गई। इस बारे में महत्वपूर्ण बात यह थी कि दोनों क्षेत्रों—पूँजीगत व उपभोक्ता वस्तु—के बीच केवल अन्तर ही कम किया जाना था। इस तरह भारी उद्योगों को सर्वोच्च प्राथमिकता अन्य योजनाओं की तरह इस योजना में भी दी जाती रही।

योजनावधि में अनाज का उत्पादन 38% से बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। इस वृद्धि का अधिकांश भाग 'नई भूमि आन्दोलन' (virgin soil campaign) नाम के कार्यक्रम से प्राप्त किया जाता था। कृषि का तीव्र गति से यन्त्रीकरण करने का काम राख में लिया गया। 5 लाख में भी अधिक हार्वेस्टर तथा 15 लाख से भी अधिक ट्रैक्टर उपलब्ध कराने की योजना तैयार की गई। योजनावधि में मांस तथा दूध की पूर्ति को दुगुना करने का लक्ष्य रखा गया। भारी पैमाने पर आवासीय व्यवस्था के लिए मकानों के निर्माण की शुरुआत की गई।

वर्ष	मकानों का निर्माण (मिनिमम वन मीटर में)
1953	31
1954	33
1955	34
1956	41
1957	52
1958	71
1959	81
1960	83

श्रम उत्पादकता बढ़ाने पर अधिक जोर दिया गया। स्वचालित (automation) प्रणाली को बड़े पैमाने पर लागू करने का प्रस्ताव था। पिछली योजनाओं में श्रम-उत्पादकता में वृद्धि करने के लक्ष्य, दूसरी पंचवर्षीय योजना को छोड़कर शायद

¹ A G Mazour, *op cit*, 69

ही कभी पूरी तरह प्राप्त हो पाये थे। परिणाम यह रहा कि उद्योगों के उत्पादन में इस दौरान जितनी वृद्धियाँ हुईं वे अक्सर रोजगार में अधिक थमिकों को लेने के कारण रही। लेकिन छठी योजना में रोजगार में वृद्धि करने का लक्ष्य 15% का ही रखा गया जो पिछले लक्ष्यों को देखते हुए काफी नीचा हो था। किन्तु उत्पादकता में वृद्धि करने का लक्ष्य 50 प्रतिशत रखा गया था। वास्तविक मजदूरी में 30% की वृद्धि तथा किसानों की आय में 40 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव था।

लेकिन, कई कारणों से, इस सारी योजना को 1957 में संशोधित करना पड़ा।

आधारभूत परिवर्तन

छठी योजना में स्टुस्चेव ने अनेक क्षेत्रों में आधारभूत परिवर्तन किये। सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन औद्योगिक प्रबन्ध (Industrial Management) तथा प्रशासन में किये गये। इसने औद्योगिक प्रबन्ध की नवीनतम तकनीक न अपना पाने की अनेक असफलताओं को स्पष्ट किया। 1956 में अनेक ऐसी कठिनाइयाँ भी पैदा हो गई थी जिन्होंने योजना के क्रियान्वयन को बहुत दुष्कर बना दिया था। यह गणना की गई कि 1957 के लिए 7 अरब रूबल की अतिरिक्त राशि तथा योजना के शेष वर्षों के लिए 37 अरब रूबल की राशि निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त समाधनों के रूप में जुटाई जानी होगी। स्टुस्चेव ने सत्ता समालने के बाद यह भी बताया कि योजना को 'काफी अपभ्रष्टपूर्ण तरीके से, महुँगी लागतों पर तथा भारी नुकसान में' चलाया जा रहा था। स्टुस्चेव इस सारी स्थिति से अप्रसन्न था तथा उसने 1957 में पार्टी की केन्द्रीय समिति से कहा था कि प्रशासनिक ढाँचे में पूर्णरूप से परिवर्तन (overhauling the administration) की आवश्यकता है। उसने चली आ रही तापस्वार्थी, अपव्यय, विवेकीकरण के अभाव तथा इनसे भी ऊपर प्रशासन के व्यर्थ के केन्द्रीकरण पर तीव्र प्रहार किये जो कि विभिन्न योजनाओं में दिखाई देते थे।¹

मई 1957 में सर्वोच्च सोवियत (Supreme Soviet) ने केन्द्रीय समिति (Central Committee) की सिफारिशों का अनुमोदन कर दिया तथा योजना की प्रणाली को अधिक विवेकीकृत कर दिया गया। 25 मुख्य आर्थिक मन्त्रालयों को समाप्त कर दिया गया। उनकी सत्ता अब 105 क्षेत्रीय आर्थिक संगठनों (Regional Economic Organisations) के हाथों में सौंप दी गई जिन्हें राष्ट्रीय आर्थिक परिषद् (Council of the National Economy) के प्रत्यक्ष अधिकार-क्षेत्र में रखा गया। माम्को में अखिल सोवियत राज्य आयोजन समिति (All Soviet State Planning Committee) को राष्ट्रीय आयोजन व समन्वयन का प्रभारी (incharge) बताया गया।

इन सभी परिवर्तनों ने नियोजन को विवेकीकृत करने में तो काफी योगदान दिया लेकिन उनसे स्थानीय दबावों (local pressures) तथा आर्थिक प्रवेशवाद

(Economic provincialism) की सम्भावनाओं के बढ़ने का भी अन्देश उत्पन्न हो गया।

सम्पूर्ण आर्थिक नियोजन व्यवस्था के पूरी तरह ससोधित कर दिये जाने से भी वांछित परिणाम नहीं निकल सके क्योंकि इस बीच कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों की प्रगति की रफ्तार धीमी पड़ने लग गई थी। कृषि में भी तो प्रमुख परिवर्तन शुरू किये गये थे। मशीन ट्रैक्टर स्टेशनों (M T S) को साधारणतया समाप्त कर दिया गया था तथा पुरानी जटिल राजकीय खरीद की व्यवस्था के स्थान पर भी एकस्य क्रय-प्रणाली, जिसमें क्षेत्रीय विभेदकारी मूल्य पर खरीद की जानी थी (a uniform purchase system with regionally differentiated prices) लागू की गई।

मुख्य फसलों का उत्पादन

(मिलियन टनो में)

	1960	1970	1973
कुल फसल	126	187	223
कपास	4	7	8
सन्निपा	17	20	25

किन्तु 1957 के आते-आते तो यह स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लगा था कि छठी योजना की पूरी जाँच व सुधार (complete overhauling) की आवश्यकता है। सितम्बर 1957 में इस आशय की घोषणा की गई कि एक दीर्घकालिक योजना बनाने की प्रक्रिया में चल रही है। इस तरह छठी योजना के मूल रूप को उसके बनाने के दो ही वर्षों के भीतर समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार छठी योजना का समाप्त किया जाना शायद आवश्यक भी था क्योंकि उससे लिए निर्धारित किये गये सफ़ा का काफी ऊँचा समझा गया, विनोद रूप से उन साधनों के परिप्रेक्ष्य में जो कि उनके लिए उपलब्ध होने थे।

सप्तवर्षीय सातवीं योजना : 1959-65

सप्तवर्षीय सातवीं योजना की फरवरी 1959 से प्रभावी घोषित किया गया। साम्यवादी दल की 21वीं कांग्रेस (Twenty First Congress of the Communist Party) में रुड्हेव ने कहा कि सप्तवर्षीय योजना का मुख्य कार्य 1959-65 की अवधि में सोवियत संघ की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का इस प्रकार से विकास करना है कि भारी उद्योगों के तीव्र गति से प्रसार, तथा देश की आर्थिक क्षमताओं में अभूतपूर्व वृद्धि के आधार पर अर्थव्यवस्था की सभी शाखाओं का विकास हो सके जिसमें कि लोगों के जीवन-स्तर में निरन्तर सुधार को प्रत्याभूत (ensure) किया जा सके।

मुख्य उद्देश्य

(1) आर्थिक तथा तकनीकी आधार की रचना करना कि जिससे साम्यवादी रूस न्यूनतम सम्भव समय में विकसित पूँजीवादी देशों से भी प्रति व्यक्ति उत्पादन की दृष्टि से आगे निकल सके।

(2) भारी उद्योगों को ऐसी शाखाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देना जो सम्पूर्ण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास को और भी आगे बढ़ाने में सहायक हो।

(3) प्राकृतिक ससाधनों को तीव्र गति से विकसित करना, उत्पादक शक्तियों के वितरण में सुधार करना, तथा उद्योगों को कच्चे माल के क्षेत्रों के निकट ले जाना व ईंधन को उपभोक्ता क्षेत्रों के निकट लाना।

सप्तवर्षीय योजना में प्रस्तावित व्यय उसके पहले के सात वर्षों में किये गये कुल योजना विनियोग की तुलना में 80% अधिक था। इस कुल विनियोग में से 77% उद्योगों, यातायात तथा कृषि के विकास हेतु आवंटित किया गया। शेष बची हुई विनियोग राशि का उपयोग शहरी आवास व अन्य सार्वजनिक कल्याण के कार्यों, जैसे स्कूल व अस्पतालों का निर्माण करने के लिए किया जाना था। किन्तु सातवी योजना में आर्थिक विकास की दर छठी योजना की अपेक्षा नीची रखी गई।

नई सप्तवर्षीय सातवी योजना में 12 मिलियन लोगों को उद्योगों में रोजगार प्रदान करने तथा श्रम-उत्पादकता में 50 प्रतिशत की वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया। श्रमिकों को 1960 तक '41 घण्टों का सप्ताह' कर देने का आश्वासन दिया गया जिसे 1962 तक घटाकर 40 घण्टे का सप्ताह कर दिया जाना था। शहरी आवास को बढ़ावा देने की दृष्टि से मकानों के निर्माण-कार्य को 60 मिलियन वर्ग मीटर (रहने की जगह) से बढ़ाकर 1965 तक 90 मिलियन वर्ग मीटर करने का प्रावधान रखा गया। दोनों ही—न्यूनतम मजदूरी तथा पेशनों—को विभिन्न चरणों में बढ़ाकर 350 रूबल से 600 रूबल तक ले जाने का भी लक्ष्य रखा गया।

किन्तु सातवी योजना का भी लगभग वही परिणाम हुआ जो इससे पहले छठी योजना का हुआ था। उसे भी मार्च 1963 में, अर्थात् पूरा होने की तारीख से दो वर्ष पहले, त्याग दिया गया। अब 1965 के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पुन संशोधित करके उन्हें काफी नीचे ले आया गया।

संशोधित लक्ष्य : 1964-65

(मिलियन टन में)

	पुरानी योजना	संशोधित नयी योजना
कोयला	600	553
तेल	240	240
लोह पिंड	70	66
इस्पात	81	89

सातवी योजना को असमय ही समाप्त घोषित कर दिये जाने के पीछे कारण यह दिया गया कि 1958 के बाद से परिस्थितियों में भारी परिवर्तन आ चुका है। ऐसा लगता है कि तकनीकी परिवर्तनों तथा प्रशासनिक व प्रबन्धनीय स्तर पर किये गये सुधारों ने मिलकर सरकार को सातवी योजना को उसकी अवधि से पूर्व ही त्याग देने के लिए बाध्य कर दिया। इनमें 'नई भूमि योजना' (virgin soil campaign) तथा 'रासायनिक क्रान्ति' (Chemical Revolution) जैसी योजनाओं का उल्लेख किया जा सकता है जो काफी सीमा तक असफल रही। इन्हीं कार्यक्रमों पर सातवी योजना की बचाने का उत्तरदायित्व था।

‘अछूती भूमि कार्यक्रम’ (Virgin Land Programme)

उत्तरोत्तर प्रत्येक योजना में किये गये अनथक प्रयासों के उपरान्त सोवियत कृषि बराबर पिछड़ी हुई बनी रही थी। एरुश्चेव ने कृषि-उत्पादन को बढ़ाने के लिए, अधिक रासायनिक खादों का प्रयोग कर तथा मध्य एशिया में बेकार पड़ी विशाल भूमि को कृषि बायों के लिए उपयोगी बनाकर नये सिरे से प्रयास किये। यह कार्यक्रम काफी सीधा-सादा तथा उपयोगी लगता था। इसमें अनाज उत्पादन में 50 प्रतिशत वृद्धि करने का दावा किया गया था। इस कार्यक्रम की एकमात्र कमी यह थी कि जिन क्षेत्रों के लिए इसे बनाया गया था उनमें जनसंख्या काफी बिलखी बिखरी थी। लेकिन इस जनसंख्या की कमी को अधिक बुलडोजरों व ट्रैक्टरों का उपयोग करके तथा अन्य आधुनिक मशीनों का उपयोग करके पूरा किया जाना था।

दो वर्षों में भी कम समय में 87 मिलियन एकड़ भूमि को हलो के नीचे ला दिया गया। इसमें से अधिकांश भूमि का अधिग्रहण कज़ाखिस्तान प्रदेश में किया गया था। 1960 में इसमें से 70 मिलियन एकड़ भूमि अनाज के उत्पादन के लिए आवंटित की गई जिसे दुगुना करना था। 1958 में 50 मिलियन एकड़ भूमि पर गेहूँ का उत्पादन करते की तैयारी भी हो चुकी थी। करीब साढ़े तीन लाख युवाओं को मध्य एशिया में काम करने के लिए भेजा गया था। 1958 तक परिणाम भी अच्छे रहे। लेकिन फसलों में 1959 में 15 प्रतिशत की गिरावट आयी। 1963 तक फसलों में लक्ष्य की तुलना में 20 प्रतिशत की कमी आ चुकी थी तथा सोवियत संघ की अनाज का आयात करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। नई भूमि पर फसलों की यह असफलता वर्षों की कमी तथा रासायनिक खाद की कमी से हुई। 1964 से इस 'नई या अछूती भूमि कार्यक्रम' की असफलता को मान लिया गया, जिस वर्ष सोवियत सरकार ने विदेशों से 12 मिलियन टन गेहूँ का आयात किया था।

रासायनिक क्रान्ति (The Chemical Revolution)

अछूती भूमि के विशाल भागों को कृषि-योग्य बनाने की अपनी विशाल परियोजना में असफल हो जाने के बाद एरुश्चेव ने राष्ट्र को रासायनिक क्रान्ति करके समृद्धि की राह पर ले जाने की एक और चेष्टा की। उसने तर्क दिया कि सांश्लेषिकी (synthetics) के विकास से न केवल उपभोक्ताओं की छोटी-छोटी आवश्यकताओं

को पूरा किया जा सकेगा बल्कि उससे उद्योगों के निर्माण में भी सहायता मिलेगी जिससे 1970 तक राष्ट्रीय उत्पादन को तिगुना किया जा सकेगा। किन्तु एक जटिल रासायनिक उद्योग ढाँचे (Complex of Chemical Industries) की स्थापना के लिए 1963-70 की अवधि में 46 अरब रुपय के अतिरिक्त विनियोग की आवश्यकता थी। इसके लिए अमरीका, ब्रिटेन व फ्रांस से अनेक मशीनो-सबकनीकों का आयात भी आवश्यक था। लाल क्रान्ति के बाद पहली बार सोवियत सरकार ने पश्चिमी देशों को उसके यहाँ रासायनिक उद्योग में ढाँचा खड़ा करने के लिए आमन्त्रित किया। फ्रांस तथा ब्रिटेन ने इस सम्बन्ध में कुछ दीर्घकालिक सार्व भी स्वीकृत की। किन्तु इस बीच खरुबचेव को ही पद-त्याग करना पड़ा। आठवीं तथा नवीं योजनाओं को उद्योग तथा कृषि के अधिक समन्वित विकास के उद्देश्य से बनाया गया जिसमें आधुनिक उद्योगों की प्रगति की ओर झुकाव भी स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता था।

आधुनिक सोवियत उद्योग (MODERN SOVIET INDUSTRY)

एक औद्योगिक महाशक्ति के रूप में अब सोवियत संघ का स्थान अमरीका से दूसरा है। लेकिन सोवियत संघ अपनी अर्थव्यवस्था का संचालन बिना बाजार-संयंत्र की सहायता से करता है जो अन्य विकसित राष्ट्रों में सामान्य रूप से प्रचलित है। एक शताब्दी से भी कुछ पहले तक रूस में पिछड़ेपन के सारे तत्त्व और स्वामित्व के वे समस्त स्वरूप विद्यमान थे जिन्हें कार्ल मार्क्स ने गुलामी, सामन्तवाद तथा पूँजीवाद का नाम दिया था। 1917 के बाद सोवियत संघ द्वारा अपनाये गये उपाय किसी भी राज्य के लिए नये थे। यद्यपि व्यक्तियों पर लगे हुए आर्थिक प्रतिबन्ध—राशनिंग तथा जबरन मजदूरी—आपात स्थिति में ही लगाने का दावा किया गया है किन्तु यह फिर भी सत्य है कि प्रचलन के सौ स्वरूपों में से एक स्वरूप भी स्वतन्त्र रूप से मांग व पूर्ति पर आधारित लेन देन के काम में नहीं लिया जाता है। सोवियत अधिकारीगण मूल्यों और लाभों के स्थान पर अभी भी विकास लक्ष्यों (growth targets) को अभिप्रेरक व उपलब्धियों का सूचक बनाये हुए है।

लेकिन सोवियत रूस की अर्थव्यवस्था की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि उसकी औद्योगिक प्रगति है। नियोजित अर्थव्यवस्था ने सोवियत रूस तथा अन्य समाजवादी देशों को अपनी अर्थव्यवस्थाओं में तीव्र औद्योगिक प्रगति कर सकने की सामर्थ्य प्रदान की है। 1970 में परस्पर आर्थिक सहायता परिषद् (Council for Mutual Economic Assistance) के सदस्य समाजवादी देशों का औद्योगिक उत्पादन 1950 की तुलना में 68 गुना बढ़ चुका था जबकि इसी अवधि में विकसित पूँजीवादी देशों में यह वृद्धि केवल 28 गुना ही हुई थी।

1960 के बाद सोवियत संघ की आर्थिक प्रगति कितनी तीव्र गति से हुई है इसका प्रमाण तो इसी से मिलता है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना (1966-70) के चार वर्षों में उसकी राष्ट्रीय आय का कुल योग चकाचौंध कर देने वाली 11,66,000 मिलियन रूबल की राशि पर पहुँच गया था। 1971-75 की अवधि में, जो कि नवीं पंचवर्षीय योजना का काल था, राष्ट्रीय आय में 40% की और वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया था। सोवियत उद्योग ही इस राष्ट्रीय आय में होने वाली वृद्धि के लिए उत्तरदायी है जो कि देश के कुल राष्ट्रीय उत्पाद में दो-तिहाई योगदान प्रदान करते हैं।¹

विकास की वर्तमान अवस्था

आठवीं पंचवर्षीय योजना के सफलतापूर्वक पूरा हो जाने के कारण सोवियत संघ के औद्योगिक उत्पादन में 1966-70 की अवधि में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

मुख्य उद्योगों की विकास दर (निर्देशांक)

	1965	1970	1975 (नियोजित)
कुल	100	150	221
इजीनियरिंग व धातु निर्माण	100	174	299
मशीन टूल्स	100	218	447
रसायन व पेट्रोनियम	100	178	306
कृषिगत मशीन	100	141	247
भवन-निर्माण सामग्री	100	150	210
विद्युत् शक्ति	100	146	210

आधुनिक सोवियत उद्योग की एक प्रमुख विशेषता यह रही है कि उपभोक्ता वस्तुओं व पूंजीगत वस्तुओं के बीच उत्पादन का अन्तर घटता जा रहा है। यह अन्तर जो 1950-65 की अवधि में 1:49 था, 1966-70 में पूंजीगत व उपभोक्ता वस्तु-उत्पादन में क्रमशः 1:01:1 अर्थात् लगभग बराबर-सा हो गया। नवी योजना में यह बात कही गई थी कि उसके दौरान उपभोक्ता वस्तुओं का औद्योगिक उत्पादन पूंजीगत वस्तुओं के औद्योगिक उत्पादन की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ेगा।

नवी योजना (1971-75) में श्रम उत्पादकता में वृद्धि करने पर भी विशेष बल दिया गया है। श्रम उत्पादकता की यह वृद्धि औद्योगिक क्षेत्र में 39% रहेगी तथा औद्योगिक उत्पादन में योजना काल में होने वाली कुल वृद्धि का 90% इसी उत्पादकता वृद्धि के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। तकनीकी प्रगति सोवियत उद्योग की एक अन्य प्रमुख विशेषता है। मानव श्रम के स्थान पर मशीनों व उपकरणों को निरन्तर प्रतिस्थापित किया जा रहा है। यह प्रवृत्ति औद्योगिक लागतों में प्रतिबिम्बित हो रही है। मजदूरी का औद्योगिक लागतों में भाग 1965 के 18% से गिरकर 1971 में 15.5% पर आ गया है जबकि इसी अवधि में औद्योगिक लागतों में शक्ति का प्रतिशत 2:1 से बढ़कर 2:5 हो गया है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लोहा व इस्पात उद्योग में सर्वाधिक यन्त्रीकरण व स्वचालन किया गया है। यहाँ तक कि कोयला उद्योग जैसा श्रम प्रधान उद्योग भी अधिकाधिक यन्त्रीकृत होता जा रहा है। 1972 तक कोयलों को लादने का काम 92% तक यन्त्रचालित हो गया है।

प्रमुख औद्योगिक वस्तुओं का उत्पादन सोवियत संघ में अन्य किसी भी पूंजीवादी विकसित देश की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ा है।

उसका औद्योगिक उत्पादन (1917-1979) 225 गुना हो चुका है। औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन में निरपेक्ष वृद्धि की दरें इस प्रकार रही हैं—

(1000 मिलियन रुबल में)

सालची योजना	80
आठवीं योजना	119
नवीं योजना	154
दसवीं योजना	183

सोवियत संघ में औद्योगिक उत्पादन में विकास दर अन्य अग्रणी पूँजीवादी देशों की तुलना में 1976 में इस प्रकार रही (1950 के प्रतिशत के रूप में)—

अमरीका	190
फ्रांस	270
प० जर्मनी	380
इटली	460
सोवियत संघ	900

इन उपलब्धियों के साथ-साथ औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्र में कुछ कमियाँ भी रही हैं। अनेक औद्योगिक प्रतिष्ठान उनके लिए निर्धारित विकास दर को प्राप्त करने में असफल रहे हैं। कई औद्योगिक वस्तुओं जैसे गन्धक का तेजाब (sulphuric acid), कॉस्टिक सोडा, धातु काटने की मशीनें, रेडियो सेट, टेलोविजन सेट, रेफ्रिजरेटर, मोटर साइकिलें इत्यादि का उत्पादन लक्ष्य से कम हुआ है। इसी प्रकार मशीनों का निर्माण करने वाले कुछ कारखानों में भी उनकी स्थापित क्षमता के अनुरूप कार्य नहीं हो पाया है। शोध-कार्य के लिए बनाई गई योजनाएँ तथा राष्ट्रीय व्ययव्यवस्था में औद्योगिकी प्रचार-प्रसार करने के लिए तैयार कार्यक्रम भी अधूरे रहे हैं।

सोवियत संघ में औद्योगिक उत्पादन का कुल राष्ट्रीय उत्पाद (G.N.P.) में निरपेक्ष (absolute) रूप में भाग इस प्रकार है—

निरपेक्ष सात्राएँ

	(हजार मिलियन रुबलो में)			
	1960	1965	1970	1975
कुल राष्ट्रीय उत्पाद	304	420	644	859
औद्योगिक उत्पादन	157	229	374	511

दसवीं पंचवर्षीय योजना (THE TENTH FIVE YEAR PLAN)

दसवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य, जैसा कि सोवियत संघ के साम्यवादी दल (C P S U) की 25वीं कांग्रेस में निर्धारित किया गया था, एक अच्छे सन्तुलित सामाजिक उत्पादन (well-balanced social production) के विकास द्वारा लोगों के जीवन-स्तर में सुधार लाना तथा उनकी कार्यकुशलता में और वृद्धि करना, वैज्ञानिक व तकनीकी प्रगति को आगे बढ़ाना, श्रम-उत्पादकता को ऊँचा उठाना तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में गुणात्मक सुधार को बढ़ावा देना है।¹

मुख्य उद्देश्य

(1) दसवीं पंचवर्षीय योजना को एक 'गुणात्मक व कुशलता योजना' (a plan of quality and efficiency) कहा जायेगा। जब दसवीं पंचवर्षीय योजना को तैयार किया जा रहा था तो विशेष बल राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में तकनीकी एवं वैज्ञानिक विकास की गति बढ़ाने पर दिया गया। यह गणना की गई है कि नवी योजना के कार्यकाल में उद्योग ने प्रति वर्ष लगभग 600 नई उत्पादन तकनीकें तथा 3,500 नये प्रकार के उत्पादन तैयार किये थे।

(2) दसवीं पंचवर्षीय योजना का अगला काम शारीरिक कार्य करने वालों के रोजगार में कमी लाने तथा यन्त्रीकरण व स्वचलन की पद्धतियों को व्यापक पैमाने पर बढ़ावा देने का होगा। यह अनुमान है कि नवी पंचवर्षीय योजना में श्रम बढ़ाने वाली तकनीकों के उपयोग से लगभग 17 लाख श्रमिकों के श्रम जितनी बचत की जा सकती थी।

(3) 1976-80 के दौरान औद्योगिक उत्पादन 35 से लेकर 39 प्रतिशत बढ़ेगा। उपभोक्ता वस्तु उद्योगों में यह वृद्धि 40 प्रतिशत रहेगी। मशीन निर्माण उद्योग में आधुनिक उपकरणों का उत्पादन 50 प्रतिशत से बढ़ जाने की प्रत्याशा है। धातु-कार्य उद्योगों, रासायनिक तथा पेट्रोकेमिकल (Petro-chemical) उद्योगों में उत्पादन में 50 प्रतिशत से भी अधिक तक की वृद्धि होने की सम्भावना है।

(4) 1975 के शुरू में उत्पादन-एव-उत्पादन संधी (Research-and-

¹ B Mochalov, *Economic Development under Tenth Five Year Plan*, Moscow, 1976

production associations) की सहा 2,300 थी तथा वे औद्योगिक उत्पादन का 24 प्रतिशत भाग पैदा कर रहे थे। दसवी योजना में ऐसे उत्पादन सघों की स्थापना का काम पूर्ण कर लिया जायेगा।

(5) 'समाजवादी अनुकरण' (Socialist emulation)¹ अब सोवियत सघ में व्यापक रूप से चल रहा है। यह दावा किया गया है कि 1968 में इसमें 61 मिलियन श्रमिकों ने भाग लिया था तथा 1974 में उनकी सहा 81 मिलियन हो गई थी। 1976-80 की अवधि में देश के सभी श्रमिकों द्वारा इस आन्दोलन में भाग लेने की प्रत्याशा है।

(6) विगत 10-15 वर्षों से सोवियत सघ में दक्षता के निर्माण (skill formation) का काम बड़ी तेजी से चल रहा है। 1976-80 के दौरान चलाये जाने वाले व्यवसाय प्रशिक्षण कार्यक्रम से कुल श्रम-शक्ति में 11 मिलियन अतिरिक्त श्रमिक जुड़ने की सम्भावना है।

(7) दसवी पंचवर्षीय योजना में बड़ी हुई उत्पादकता का कुल औद्योगिक उत्पादन वृद्धि में योगदान 90%, कृषि-उत्पादन तथा निर्माण-कार्य में 100%, तथा रेलों में माल ढुनाई के कामों में 95% रहने की प्रत्याशा की गई है।

(8) अपने सङ्ख्यात्मक पहलू (quantitative aspect) के अतिरिक्त दसवी पंचवर्षीय योजना का एक महत्वपूर्ण गुणात्मक पहलू (qualitative aspect) भी है। योजना के दौरान उत्पादन की किस्म में भारी सुधार लाने की प्रत्याशा है तथा श्रमिकों की कार्यकुशलता व उपभोक्ता वर्ग के लाभ भी बढ़ने की सम्भावना है।

(9) दसवी पंचवर्षीय योजना में शक्ति-उद्योग (power industry) विशेष रूप से विद्युत-शक्ति, की अधिक तीव्र प्रगति का अनुमान लगाया गया है। उद्योग को तीन काम करने हैं। अप्रयुक्त ईंधन समाधानों की खोज करना व उन्हें काम में लेना, सबसे पहले देश के उम्र भाग में जो यूरोप में पड़ता है, (ii) साइबेरिया, मध्य एशिया तथा सुदूर-पूर्व में समृद्ध ईंधन भण्डारों की खोज व पुनर्ग्रहण (reclamation) का काम जारी रखना, तथा (iii) देश के पूर्वी भाग से ऊर्जा का पश्चिमी भाग में प्रेषण (transmission) करना।

13 से 15 मिलियन किलोवॉट क्षमता वाले कुछ आणविक ऊर्जा संचालित पावर-स्टेशन 1976-80 के दौरान देश के यूरोप में पड़ने वाले भाग में लगाये जायेंगे। साइबेरिया में विशालकाय जल शक्ति केन्द्र (Hydro Power Stations) प्रतिस्थापित किये जायेंगे। अनेक विशाल ताप बिजली घर (Thermal Power Stations) भी 1976-80 की अवधि में साइबेरिया में लगाये जायेंगे जो सस्ते बोलने या गैस से चलेंगे।

दसवी पंचवर्षीय योजना में ही मध्य एशिया में एक और विशाल शक्ति-केन्द्र (power centre) स्थापित किया जायेगा। शक्ति उद्योग की क्षमता में दसवी योजना में प्रस्तावित ये वृद्धियाँ अर्थव्यवस्था में अन्य उपयोगियों के लिए आगे आने का

¹ 'समाजवादी अनुकरण' एक आन्दोलन है जिसमें श्रमिक लोग सर्वाधिक मात्रात्मक एवं गुणात्मक सनेहों को प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं।

अच्छा मार्ग बनायेगी। कुल मिलाकर 1980 तक सोवियत सघ में 67 से 70 मिलियन किलोवाट की शक्ति-प्रजनन क्षमताएँ नये सिरे से स्थापित की जायेंगी। इस शक्ति-प्रजनन (power generation) के जुड़ जाने से सोवियत सघ में कुल शक्ति-उत्पादन बढ़कर 13,80,000 मिलियन किलोवाट हो जाने की प्रत्याशा है जो 1970 का दुगुना होगा।

एक राष्ट्रव्यापी शक्ति-जाली (power grid) तैयार करने के विचार से दसवी योजना के दौरान 1,70,000 किलोमीटर लम्बी नई प्रेषण लाइनें (Transmission lines) तैयार करने का भी प्रस्ताव है। इन लाइनों के माध्यम से सोवियत सघ के यूरोप वाले भाग में पावर-ग्रिड मध्य एशिया, उत्तरी कज़ाखिस्तान व साइबेरिया स्थित पावर-सिस्टम एक-दूसरे से जुड़ जायेंगे।

ईंधन उत्पादन व पूंजीगत वस्तुएँ

दसवी पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्पादक कार्यों के लिए गैस की खपत दुगुनी हो जाने की आशा है तथा तेल का विधायन (processing of oil) भी 25 से 30 प्रतिशत तक बढ़ जायेगा। अभी भी सोवियत सघ यह दावा करता है कि वह संसार में पहले नम्बर का तेल-उत्पादक राष्ट्र है। दसवी पंचवर्षीय योजना में तेल निकालने के क्षेत्र में 25 से 30 मिलियन टन तक की वार्षिक वृद्धियाँ प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। दसवी योजनावधि में ही साइबेरिया के तेल-क्षेत्र उनके लिए निर्धारित 120 मिलियन टन तेल-उत्पादन की वार्षिक क्षमता प्राप्त कर लेंगे। देश के विभिन्न भागों में अनेक नये पेट्रो-कैमिकल कारखाने स्थापित किये जायेंगे। तेल निकालने के क्षेत्र में स्वचालन का प्रयोग तेजी से किया जायेगा। एक राष्ट्रव्यापी गैस आपूर्ति जाल विछाया जा रहा है जिसमें कुल मिलाकर 1,00,000 किलोमीटर लम्बी पाइप लाइनें (मुरा) होगी।

दसवी पंचवर्षीय योजना में रासायनिक व पेट्रो-रासायनिक उद्योगों के उत्पादन में 60 से 65 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है। खनिज उर्वरकों का उत्पादन 143 मिलियन टन तक लाये जाने का प्रस्ताव है। रासायनिक रेशों व धागों का उत्पादन भी 15,00,000 टन तक पहुँच जाने की आशा है। यह लक्ष्य वर्तमान प्रतिष्ठानों की कार्यक्षमता को बढ़ाकर तथा अनेक नये औद्योगिक प्रतिष्ठान स्थापित कर प्राप्त किया जायेगा।

इसी प्रकार दसवी योजना में लौह व अलौह धातुओं के उत्पादन में भी तथा मशीनों बनाने के काम में भी और तीव्रता आने की सम्भावना है। अभी भी सोवियत सघ लौह पिण्डों व इस्पात का दुनिया के किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक उत्पादन कर रहा है। 1980 तक तैयार इस्पात का उत्पादन (finished rolled products) 115-120 मिलियन टन हो जायेगा। अलौह धातु उत्पादन के क्षेत्र में अल्युमीनियम, ताँबा तथा निकल (Nickel) का उत्पादन काफी मात्रा में बढ़ाने का लक्ष्य है।

आगामी 5 वर्षों में मशीन-निर्माण उद्योग के उत्पादन में 50-60 प्रतिशत

वृद्धि की आशा की जा रही है। किन्तु इस बार मशीनों, उपकरणों व पुर्जों की किस्म पर अधिक ध्यान दिये जाने के निर्देश भी साथ लगा दिये गये हैं। उन मशीनों का तकनीकी स्तर, उत्पादकता एवं विश्वसनीयता में भी सुधार लाने की बात कही जा रही है।

उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाना

स्टालिनेतर युग (Post-Stalin era) में नियोजन के क्षेत्र में उत्पन्न हुई नई प्रवृत्ति का अनुसरण करते हुए दसवी योजना ने उपभोक्ता वस्तुएँ बनाने वाले उद्योगों के पर्याप्त विद्वास का प्रस्ताव भी किया है। निमित्त उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में 30 से 32 प्रतिशत तक की वृद्धि होने की आशा है। पर्नोवर का उत्पादन 40-50 प्रतिशत में तथा घरेलू काम-काज की वस्तुओं का उत्पादन 60 प्रतिशत से बढ़ाया जायेगा।

उपभोक्ताओं की आवश्यकताएँ पूरी करने वाले उद्योगों की शाखाओं में हल्के उद्योग (Light industry) सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं जो समस्त उपभोक्ता वस्तुओं का 56 प्रतिशत तैयार करते हैं। इस क्षेत्र में भी अधिक स्वचलन स्थापित किया जायेगा तथा नई मशीनें भी लगाई जायेंगी। ऊँचे किस्म के सूती वस्त्र, बनी हुई चीजें, जूते, सिले-सिलाये कपड़े तथा अन्य सामान्य उपभोक्ता वस्तुओं की अच्छी किस्मों का उत्पादन बढ़ाने का प्रस्ताव है।

1970-75 की अवधि में सोवियत मोटर उद्योग (Soviet Motor Industry) ने लगभग 45 लाख कारें निमित्त की थी। 1976-80 की अवधि में कारों के उत्पादन में और वृद्धि की योजना है। ऐसी कारों के उत्पादन को प्राथमिकता दी जायेगी जो सामान्य उपभोक्ता के उपयोग में आ सकें। खाद्य-विधायन उद्योग के सामन मुख्य कार्य खाद्य-पदार्थों की किस्म, स्वाद तथा पोषक शक्ति में सुधार करने का है।

कृषि का विकास

कृषि के विकास को बढ़ावा देने की दिशा में दसवी पंचवर्षीय योजना को काफी करना कुछ है। उद्योगों की बच्चे माल की माँग तथा बढ़ती हुई जनसंख्या की खाद्य-पदार्थों की माँग को पूरा करने के लिए कृषि-उत्पादन में अधिक स्थायित्व तथा मीत्र विकास के उपाय करना अत्यन्त आवश्यक है।

कृषि-उत्पादन तथा पशु-धन में वृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से राजकीय व सामूहिक फार्मों में गहन उत्पादन करने के साथ-साथ उनका दृढीकरण (consolidation) करने का कार्य भी दसवी योजना के अन्तर्गत है। खाद्यान्नों के उत्पादन में औसत वार्षिक वृद्धि 20 वर्षों में इस प्रकार हुई है

(मिलियन टने में)

1956-1960	121.5
1961-1965	130.3
1966-1970	167.7
1971-1975	181.5

1976-80 को अवधि में अनाज का औसत वार्षिक उत्पादन 215-220 मिलियन टन लाने का प्रस्ताव है जो नवी पंचवर्षीय योजना के वार्षिक अनाज उत्पादन के औसत से 35-40 मिलियन टन अधिक है। दसवी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 9 मिलियन टन कपास, 95-98 मिलियन टन चुकन्दर, 15 मिलियन टन मास, 96 मिलियन टन दूध, 61 हजार मिलियन अण्डे 1980 तक उत्पादित करने का है। ये लक्ष्य अप्राप्य नहीं हैं। 1973 में, जब मौसम अनुकूल रहा, सोवियत संघ का अनाज उत्पादन 223 मिलियन टन रहा था।

फसलों की खराबी तथा मास, दूध व ऊन आदि के उत्पादन में कमी का मुख्य कारण समय-समय पर पड़ने वाले सूखे (droughts) रहे हैं। इसके कारण उपभोक्ता उद्योगों का विकास भी धीमी गति से हुआ है क्योंकि सोवियत संघ में उपभोक्ता वस्तुएँ बनाने वाले उद्योग अपना 75 प्रतिशत कच्चा माल कृषि से प्राप्त करते हैं।

सोवियत कृषि-विशेषज्ञ यह भी तर्क देते हैं कि अमरीका में कृषि अधिक उत्पादक (सोवियत रूस की कृषि की तुलना में) इसलिए है कि जलवायु व मिट्टी सम्बन्धी दशाएँ सोवियत संघ में कहीं अधिक खराब व प्रतिदूल हैं। इसलिए सोवियत संघ में कृषि-उत्पादन में अमरीका की तुलना में अधिक पूँजी तथा श्रम के विनियोग की आवश्यकता रहती है।

यही कारण है कि इन दिनों सोवियत योजनाकार कृषि-उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य को, तकनीक व विज्ञान को अधिक मात्रा में प्रयुक्त करने पर बल दे रहे हैं। 1971-76 के बीच सोवियत कृषि-क्षेत्र को 17 लाख ट्रेक्टर तथा 11 लाख ट्रैक्टर व भारी मात्रा में अन्य अनेक कृषि उपयोगी मशीनें उपलब्ध करायी गयीं। 1976-80 में यह संख्या बढ़ाकर 19 लाख ट्रेक्टर, 13.5 लाख ट्रैक्टर तथा 5 लाख से भी अधिक हारवेस्टर, करने का प्रस्ताव है।

अनाज का उत्पादन कृषि की सर्वाधिक महत्वपूर्ण शाखा बनी हुई है जिसके लिए सबसे अधिक ध्यान, प्रयास व भौतिक साधनों की आवश्यकता पड़ती है। इस बात की चेष्टा की जायेगी कि जहाँ भी सम्भव हो अनाज के उत्पादन का क्षेत्र बढ़ाया जाये। दसवी पंचवर्षीय योजना में कृषि-विकास कार्यक्रम इस प्रकार बनाया गया है कि कृषि को अत्यधिक प्रगतिशील उत्पादन शाखा के रूप में बदला जा सके।

कृषि विकास पर दसवी योजना में किया जाने वाला कुल विनियोग 172 अरब रूबल रहने की आशा है। यह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर कुल विनियोग की जा रही 600 अरब की राशि में से किया जायेगा। कृषि-उत्पादन में औसत वार्षिक वृद्धि 14-17 प्रतिशत रहने की सम्भावना है। अगले पाँच वर्षों में कृषि-क्षेत्र को 50% अधिक कृषि-उपकरण उपलब्ध कराये जायेंगे। प्रति श्रमिक विद्युत उपयोग में भी योजनाकाल के दौरान दुगुनी वृद्धि होने की आशा है जिससे कृषि कार्यों में लग रहे 15 लाख लोगो को वहाँ से हटाना सम्भव होगा। राजकीय तथा सामूहिक खेतों पर उत्पादनता में 3% वृद्धि की प्रत्याशा की जा रही है।

पूँजी-निर्माण

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में पूँजी-निवेश करने की दृष्टि से सोवियत संघ विश्व में सर्वोपरि होने का दावा करता है। दसवीं पंचवर्षीय योजना में पूँजी-निवेशों की मात्रा में 24-26% वृद्धि होने की आशा है। इनमें से लगभग दो-तिहाई पूँजी-विनियोग (capital investments) वर्तमान प्रतिष्ठानों के पुनर्निर्माण, उनके औजारों में सुधार तथा उनकी क्षमता का विस्तार करने जैसे कार्यों पर किये जायेंगे। इन विनियोगों से पुराने पूँजी-विनियोगों की प्रभावशीलता में वृद्धि होने की अपेक्षा की जा रही है जो 1976 में 117 बिलियन रूबल मूल्य के थे। किन्तु इस बात के संकेत अभी से मिलने आरम्भ हो गये हैं कि निर्माण-कार्य सब जगह पर्याप्त तेजी से नहीं चल रहा है। इससे काफी चिन्तन भी हुए हैं। अब एक अलग से प्रतिष्ठान स्थापित करने की अपेक्षा औद्योगिक संकलित (industrial complexes) बनाने का पक्ष लिया जाने लगा है। अनेक औद्योगिक प्रतिष्ठानों में, जिन्हें दसवीं योजनाकाल में पूरा किया जाना है, विनालकाय कॉमा ऑटो वर्क्स भी सम्मिलित हैं जो प्रत्येक वर्ष 1,50,000 हेवी ड्यूटी ट्रकों (Heavy Duty Trucks) तथा 2,50,000 डीजल इंजिनों का निर्माण करेगा।

दसवीं योजना में श्रम-कल्याण

1976-80 के दौरान औद्योगिक मजदूरों व कर्मचारीगणों को वेतन-मजदूरों 16-18% से बढ़ने की आशा है। साथ ही उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य इस अवधि में स्थिर रहेंगे। सामूहिक कृषकों की सामूहिक स्वामित्व वाले खेतों से प्राप्त आय 24-27% बढ़ने की प्रत्याशा है। भुगतान तथा लाभ सामाजिक उपभोग कोषों¹ (social consumption funds) से भी किये जायेंगे। इस प्रकार के भुगतानों के 1980 तक बढ़कर 116 अरब रूबल हो जाने की सम्भावना है। 1975 की तुलना में 1980 तक वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में 22% वृद्धि होने का अनुमान है।

एक नई बात यह है कि दसवीं योजना में मजदूरी की दरों का अभिप्रेरकों (incentives) के रूप में प्रयोग किया जायेगा। उनका उपयोग उत्पादकता बढ़ाने तथा उत्पादन की किस्म सुधारने के लिए किया जाना है। उत्तरी प्रदेशों व साइबेरिया जैसी जगहों के लिए मजदूरी बढ़ाने का भी प्रस्ताव है जहाँ प्राकृतिक व जलवायु सम्बन्धी दशाएँ काफी अमन्तोपजनक हैं। ऊँची न्यूनतम मजदूरी लागू करने का काम भी इसी अवधि में पूरा किया जायेगा। सुदूर-पूर्व के प्रदेशों में कार्यरत लोगों को दिया जाने वाला परिष्ठात बोनस फिर से आरम्भ किया जा रहा है। रात-पाली में काम करने वालों के लिए अधिक मजदूरी देने का प्रस्ताव है। महिला श्रमिकों के लिए काम की दशाओं में सुधार किया जायेगा।

आय में वृद्धि के साथ-साथ उपभोक्ता वस्तुओं की मात्रा तथा उनकी विविधता

¹ ये कोष राष्ट्रीय आय का एक भाग हैं जिसे मजदूरी कोष के अलावा श्रमिकों की कुछ आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अलग में रखा जाता है। ये सेवाएँ मुफ्त या कम कीमत पर दी जाती हैं।

को बढ़ाने का भी प्रस्ताव दसवी योजना के प्रारूप में है। मूल्य तो 1970 के बाद से लगभग स्थिर ही रहे हैं। खुदरा मूल्यों का मूल्य-निर्देशांक 1970 के आधार पर अभी 99.6% है।

दसवी योजना के दौरान औद्योगिक आवास (industrial housing) को भी उच्च प्राथमिकता दी जायेगी। यह दावा किया जाता है कि पूँजीवादी देशों से एकदम भिन्न, जहाँ कि मजदूरों की आय का 25 से 40% केवल मकान किराये पर खर्च हो जाता है, सोवियत संघ में किराया एक परिवार की आय का 3% से अधिक नहीं होता। 1970-75 के बीच लगभग 46 मिलियन प्लॉट बनाये गये थे। दसवी योजना के दौरान 13-14 मिलियन प्लॉट और बनाने का प्रस्ताव है।

इनके अतिरिक्त दसवी योजना में सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के लिए भी प्रावधान है। दवाएँ सोवियत संघ में दुनिया के किसी भी देश की तुलना में सस्ती होने का दावा किया जाता है। औसत आयु 70 वर्ष पहले ही पहुँच चुकी है।

विदेश व्यापार

दसवी योजनाकाल में विदेश व्यापार के परिमाण में 30-35% वृद्धि का प्रस्ताव है। 1975 में विदेश व्यापार का लेन-देन 51 अरब रूबल पहुँच गया था। पूँजीवादी तथा विकासोन्मुख राष्ट्रों के साथ आर्थिक सहयोग और भी बढ़ाया जा रहा है। फ्रांस, जर्मनी, इटली, अमरीका व जापान के साथ महत्वपूर्ण समझौते व अनुवन्ध किये गये हैं जिनसे देश में पोलिथाइलीन (Polythylene) व अन्य रासायनिक वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा मिल सकेगा।

अब ऐसा दिखाई पड़ने लगा है कि सोवियत संघ आर्थिक सहयोग बढ़ाने का इच्छुक है। जून 1976 में बर्लिन में यूरोपीय साम्यवादी दलों की गोष्ठी में बोतते हुए ब्रेज़नेव ने कहा था कि 'यह निर्विवाद रूप से महत्वपूर्ण है कि यूरोप में शान्तिपूर्ण सहयोग का ताना-बाना बुना जाये मैं परस्पर लाभकारी सहयोग के बारे में सोच रहा हूँ—व्यापार, उत्पादन में सहयोग तथा वैज्ञानिक व तकनीकी सम्बन्ध।'।

इस रूप में सोवियत संघ अपनी दसवी योजना को चला रहा है।

श्रम, मजदूरी तथा श्रम संघ (LABOUR, WAGES AND TRADE UNIONS)

सरकारी तौर पर श्रम को सोवियत संघ में एक वस्तु की तरह नहीं माना जाता। उसका शोषण भी नहीं होता क्योंकि वहाँ कोई निजी पूंजी नहीं है और वैसे देखा जाये तो राज्य भी कोई निर्योक्ता नहीं है। लेकिन इसके बावजूद सोवियत संघ को पूरी तरह से वर्ग-हीन राज्य (classless state) नहीं माना जाता। वहाँ दो भिन्न मंजी रखने वाले वर्ग हैं किसान और मजदूर। बुद्धिजीवियों का अस्तित्व तो केवल एक परत का सा है। ऐसी परिस्थितियों में कौन किसका शोषण कर सकता है? समाजवाद का आदर्श तो 'प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार' और 'प्रत्येक को उसके काम के अनुसार' है। राज्य ही विभिन्न व्यक्तियों एवं समूहों को अलग-अलग आय आवंटित करता है।

श्रम बाजार

श्रम की परिभाषा करते हुए तथा मजदूरी निर्धारण को स्पष्ट करते हुए एक सोवियत पाठ्य-पुस्तक में लिखा है 'समाजवाद के अन्तर्गत श्रम समाज द्वारा श्रम शक्ति का उपयोग किया जाना नहीं बल्कि श्रम के स्वामी द्वारा उसका प्रयोग करना है अर्थात् समाज के एक सदस्य की कुल श्रम में प्रत्यक्ष भागीदारी। अतः मजदूरी उसकी इस भागीदारी की सीमा का माप है, तथा उसका परिमाण कुल सामाजिक उत्पाद के प्रकार व व्यक्ति के कार्य के परिणाम दोनों ही पर निर्भर करता है। आय में अन्तर उनकी दक्षताओं या उनकी उपलब्धियों के अनुपात में हो सकता है लेकिन प्रमुख रूप से व्यक्तियों व समूहों की आय राज्य निर्धारित करता है। श्रम बाजार की इसमें कोई भूमिका नहीं दिखाई देती।

किन्तु इस सबका यह अर्थ नहीं है कि माँग व पूर्ति की शक्तियाँ सोवियत श्रम बाजार पर कोई प्रभाव नहीं डालती। ये शक्तियाँ विभिन्न प्रकार के श्रमिकों तथा उनकी सापेक्ष आय को दो प्रकार से प्रभावित करती हैं पहला, वे सरकार के निर्णयों को प्रभावित करती हैं दूसरा चूँकि सरकारी मजदूरी दरें शायद ही कभी सशोधित होती हैं तथा वे स्थानीय परिस्थितियों में ठीक भी नहीं बैठती, इसलिए प्रबन्धक (managers) सरकारी वेतनमानों का अपवचन (evasion) करने की कोशिश में रहते हैं।

मजदूरों में जो अन्तर (wage differentiation) बने हुए थे उन्हें कम

करने में कई वर्ष लगे। शुरू में श्रमिकों के लिए कोई 1900 भिन्न वेतनमान थे। 1960 तक की इनकी संख्या को घटाकर 10 कर दिया गया था। अब इसे घटाकर 3 तक ले जाने का इरादा है। वर्मचारियों के वेतनमान भी 700 से घटकर 150 रह गये हैं। अब भी भारी उद्योगों, निर्माण कार्यों व यातायात के लिए निर्धारित वेतनमान अन्य गैर-प्राथमिकता वाले उद्योगों व सेवाओं की तुलना में अधिक हैं।

चूँकि मजदूरी-निर्धारण सोवियत संघ में अत्यधिक संकेन्द्रित है इसलिए उसका अपवचन करने के तरीके खोजे जाते हैं। अपवचन (evasion) की सबसे आसान विधियाँ या तो वस्तु-दरों (piece-rates) को अधिक रखने या बोनस स्कीम लागू करने की या फिर श्रमिकों को नया दर्जा (regrading) प्रदान कर देने जैसी हैं। यही तरीके स्टालिन युग में भी काम लिये जाते थे। 1956 में 78% श्रमिक वस्तु या इकाई दर (piece-rate) पर काम कर रहे थे। चूँकि अर्द्ध श्रमिकों के वेतनमान बहुत नीचे थे इसलिये उन्हें अर्द्ध-कुशल श्रमिकों का दर्जा दे दिया जाता था। 1956 में मजदूरी दरों में अत्यधिक संशोधन किया गया तथा श्रमिकों की आय में मूल वेतन का भाग काफी बड़ गया। इसके परिणामस्वरूप वस्तु-इकाई दरों (piece-rate) पर काम करने वाले श्रमिकों का प्रतिशत 1965 में गिरकर 57 रह गया था।

इसमें यही सीखा जा सकता है कि आर्थिक शक्तियाँ सापेक्ष आय के निर्धारण में हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं, चाहे वह अप्रत्यक्ष तरीके से ही क्यों न हो। इस बात के प्रमाण हैं कि कोई भी व्यक्ति जिसे परिणाम के आधार पर भुगतान किया जाता है, उसकी मजदूरी सरकार तय नहीं कर सकती। सोवियत संघ में मजदूरी पर प्रभावकारी नियन्त्रण नियोजित मजदूरी कोष के माध्यम से रखा जाता है। दूसरे शब्दों में, केन्द्र सरकार किसी पंक्ती या ग्लान में मजदूरी के अन्तर को तय नहीं कर सकती। लेकिन वह उस न्यूनतम राशि का निर्धारण कर सकती है जो मजदूरी या वेतन के रूप में दी जायेगी, तथा बेकिंग व्यवस्था से उसे लागू भी कर सकती है। प्रबन्धक साधारणतया इस सीमा से आगे नहीं जा सकते। पिछले कुछ वर्षों से तो योजना में मजदूरी में प्रतिशत वृद्धि को सम्मिलित भी किया गया है।

नियन्त्रित श्रम बाजार के सोवियत अनुभव से अनेक निष्कर्ष निवाले जा सकते हैं। पहला, ऐसे किसी भी तर्कसंगत एवं सर्वसम्मत मानदण्ड को खोज पाना लगभग असम्भव है जिसके आधार पर सापेक्ष आय का निर्धारण किया जा सके, दूसरा, तरीका चाहे कोई भी रहे, माँग व पूर्ति की बाजार-शक्तियाँ सापेक्ष आय पर प्रभाव डालने का कोई तरीका खोज ही लेगी जिन्हें राज्य निर्धारित करता है, तीसरा, जाने-माने तरीकों से अपवचन शुरू हो जाता है, तथा मजदूरी पर एवमात्र प्रभावी 'पूर्ण विराम' नियोजित मजदूरी कोष पर लगायी गयी सीमा होती है। इस तरीके की अपनी कीमत चुकानी पड़ती है। मजदूरी कोष में वृद्धि के लिए अर्जियाँ देने में प्रबन्धक अपना समय नष्ट करके ही अतिरिक्त श्रमिक काम पर ले सकते हैं।¹

¹ Alec Nove, *The Soviet Economic System*, 1978, Allen and Unwin, 207.

आय अन्तर (Income Differentials) तथा न्यूनतम मजदूरी

इस क्षेत्र में कई परिवर्तन किये गये हैं। यह काफी जानी-मानी बात है कि 1931 में स्टालिन ने स्वयं हस्तक्षेप करके मजदूरी में अन्तर को 1 : 4 : 4 तक बढ़ाया था। इन्जीनियरों, तकनीशियनों आदि को भी लाभ हुआ था। प्राथमिक व गैर-प्राथमिक क्षेत्रों में भी वेतन में अन्तर थे। रिकॉर्डें तोड़ने वालों को भारी मजदूरी वृद्धियों से पुरस्कृत किया जाता था। कम मजदूरी पाने वाले लोगों (जैसे सलामी, डाकिये आदि) तथा उच्च श्रेणी वाले लोगों की आय में अन्तर बढ़कर 1 : 12 हो गये थे। स्टालिन ने आगिर इन मजदूरी के अन्तरों की वजालत इसलिये की कि प्रथम दो योजनाओं में कुशल श्रमिकों व तकनीशियनों की पूर्ति बढ़ाना अत्यावश्यक था। साथ ही साथ भारी सत्पा में गाँवा में आने वाले भूतपूर्व किसानों की, जो एकदम अकुशल थे, उत्पादकता बहुत कम थी। दूसरे शब्दों में माँग व पूर्ति की स्थिति ने मजदूरी में अन्तर बढ़ाने का पक्ष लिया था।

द्वितीय महायुद्ध के बाद के वर्षों में, जब आय नीति पर बहुत कम ध्यान दिया गया था, वस्तु-इकाई दरों (piece-rate) पर काम करने वाले श्रमिकों को, जैसा कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है, काफी लाभ हुआ। काफी विसंगतियाँ पँदा हुईं क्योंकि समय दरें (time rates) तथा वेतन अपरिवर्तित ही रहे। सफेद पोश श्रमिकों (white-collar workers) को सबसे अधिक हानि उठानी पड़ी। न्यूनतम मजदूरी स्थापित करने का प्रथम प्रयास 1956 में किया गया। 1957-65 की अवधि में सफेद पोश श्रमिकों जैसे डाक्टरों व शिक्षकों के वेतन भी बढ़ाये गये।

जब न्यूनतम मजदूरी 1956 के 30 रूबल से, कई चरणों में बढ़कर 1976 में 70 रूबल प्रति सप्ताह हो गई तो मजदूरी में अन्तर भी काफी घट गये। मजदूरी में ये अन्तर अब 1 : 1.86 (खानों में) से 1 : 1.58 (हल्की व खाद्य मान्यता बनाने वाले उद्योग) तक है। पिछले दो दशकों में विभिन्न श्रेणियों को सम्प्रेक्ष स्थिति में नाटकीय परिवर्तन आये हैं जैसा कि निम्नांकित तालिका से स्पष्ट है¹

उद्योगों में मजदूरी

	(रूबल में)		
	1940	1965	1973
श्रमिक	32	102	146
इन्जीनियर, तकनीशियन	70	148	185
कर्मचारी (क्लर्क आदि)	36	86	119

ये आंकड़े यही तथ्य स्पष्ट करते हैं कि श्रमिक वर्ग को अधिक लाभ हुआ है। 1956 के बाद दो बार वृद्धियाँ हो जाने के बावजूद डाक्टरों तथा शिक्षकों के वेतन मजदूरी की तुलना में अभी भी काफी कम हैं। मास्को के एक बस ड्राइवर को

200-220 रुबल प्रतिमाह मिलते हैं जो सफेद पोश कर्मचारी की आय से 70 से 80 प्रतिशत अधिक है। डॉक्टर और अध्यापक, जिन्हें कम वेतन मिलता है, अधिकांश महिलाएँ हैं। यहाँ तक कि कनिष्ठ इन्जीनियरों को कुछल श्रमिकों से कम वेतन मिलता है। वास्तव में समानता की प्रवृत्ति काफी दूर तक पहुँच गई लगती है। यह अनुमान लगाया गया है कि 1969-78 की अवधि में औसत मजदूरी में जहाँ 39% की वृद्धि होगी वहाँ न्यूनतम मजदूरी 17% ही बढ़ेगी।

1946 के आँकड़ों में मजदूरी में अन्तर काफी था। किन्तु उसके पास न्यूनतम मजदूरी में की गई बार-बार की वृद्धियों से 1956 तक यह अन्तर निरन्तर घटता रहा। यहाँ यह बात ध्यान रखने योग्य है कि हम सर्वोच्च पदों पर विद्यमान लोगों की नीचे से नीचे के पद वाले से तुलना नहीं कर रहे हैं बल्कि सबसे ऊँचे 10% लोगों से सबसे नीचे के 10% लोगों की तुलना कर रहे हैं। सर्वोच्च पदों वाले 1% लोगों से तुलना करने पर ये वेतन अन्तर अधिक आयेगे।

सोवियत रूस में मजदूरी अन्तर की वास्तविकता जानना बहुत जटिल काम है क्योंकि वहाँ कई अतिरिक्त सुविधाएँ व लाभ (perks) भी मजदूरी-वेतन के साथ लगे होते हैं। उदाहरण के लिए कार के उपयोग की सुविधा, अच्छा फ्लैट, अत्यधिक आरामदायक यात्रा-भत्ता तथा कभी-कभी अतिरिक्त 'मोटो भरे लिफाफे।' इनकी गणना करना बड़ा ही कठिन काम है।

1956 के बाद एक बार तो स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आयी है कि इन्जीनियरों, लेखा-अधिकारियों, शिक्षकों आदि का अभाव मूल्य (scarcity value) श्रमिकों की तुलना में काफी घट गया है। यह एक कारण है जिसके परिणामस्वरूप मजदूरी में अन्तर काफी घट गये हैं। एक प्रश्न यह उठता है कि क्या मजदूरी-अन्तर अधिक थे या है। कुछ लोगों का विश्वास है कि 1970 के दशक में कुछ मजदूरी-अन्तर—उदाहरण के लिए मजदूरों व इन्जीनियरों के बीच—काफी कम और कहीं-कहीं तो नकारात्मक बन गये हैं। 1946 के मजदूरी अन्तर तो इनके सामने अत्यधिक असमान लगते हैं। कई बार ध्यान उन बहुत थोड़े उच्च पदाधिकारियों, कुछ सफल लेखकों, संगीतज्ञों या उच्च विद्वानों की ओर आकर्षित किया जाता है जो काफी आराम व विलासिता से रहते हैं। किन्तु हम इस बारे में अधिक कुछ मालूम नहीं क्योंकि वहाँ हर चीज के बारे में गोपनीयता रहती है।

कृषि आय व ग्रामीण श्रमिक

1966 तक किसानों की आय पूर्णतया इस तथ्य पर निर्भर करती थी कि ज़िम क्षेत्र पर वे काम करते थे वहाँ कितनी राशि वितरण के लिए उपलब्ध थी। ट्रुदोदन (Trudoden) या कार्य-दिवस इकाई को दिये गये कार्य का माप माना जाता था। एक कार्य-दिवस-इकाई 1963-64 तक सिर्फ 0.30 रुबल तथा 1.5 किलो अनाज के बराबर थी। राजकीय फार्मों पर भी वेतन उद्योग का 58% ही था। राज्य कृषि उत्पादन के लिए काफी नीचे मूल्य देता था। 1966 तक, कुछ चरणी में, मूल्यों को उचित स्तर पर ले आया गया। उसी वर्ष यह भी निश्चित हुआ

कि कोलखोज पर काम करने वाले श्रमिकों को सोव खोज बेतनमानों पर वेतन दिया जाये। किन्तु कोलखोज वेतन अभी भी औद्योगिक मजदूरों की आय से कम है। किन्तु कोलखोज श्रमिकों को उनके निजी वेतन में भी आय प्राप्त होती है इसीलिए अन्तर अधिक नहीं है।

ग्रामीण श्रमिकों को अधिक नियमित रोजगार उपलब्ध है—पशु-पालन क्षेत्र में, जहाँ वर्ष भर काम रहता है। लेकिन ग्रामीण व्यवसायों से शहर का जीवन अधिक ऊँचा गिना जाता है। ग्रामीण श्रम काफी असमान रूप से भी बँटा हुआ है। वैसे सोवियत सरकार की घोषणाएँ बेरोजगारी से साफ इनकार करती हैं किन्तु इन क्षेत्रों में, 'कम काम करने वालों की नारी सस्या' मौजूद है।

महिला रोजगार

सोवियत संघ की श्रम-शक्ति में महिलाओं का अनुपात काफी ऊँचा है। 1973 में सोवियत संघ में काम पर लगे हुए कुल व्यक्तियों में 51% महिलाएँ थी (इनमें यातायात में 24% से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं व सामाजिक बीमा में लगी हुई 85% महिलाएँ सम्मिलित हैं)। 52% से भी अधिक नौकरी-शुदा स्नातक महिलाएँ थी। ये शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग सेवाओं, बीमा आदि में काफी अधिक हैं तथा राज्य के अनेक कार्यालयों व आर्थिक प्रशासन के कार्यों में नये लोगों में उनका प्रतिशत 60 है। उच्च शिक्षण संस्थाओं में कुल विद्यार्थियों में 50 प्रतिशत महिलाएँ हैं तथा विधि व अर्थशास्त्र में विशिष्ट उपाधि के लिए अध्ययन करने वालों में तो वे 61% हैं।¹

किन्तु इस सम्बन्ध में दो असंतोषप्रद बातें भी कही जा सकती हैं। एक तो यह कि अधिकांश महिलाएँ नीची श्रेणी के व्यवसायों में काम पर लगी हुई हैं। दूसरे, जिन व्यवसायों में महिलाएँ अधिक हैं उन्हीं में वेतन सबसे कम है। वैज्ञानिक कार्यकर्ताओं में महिलाएँ 40% ही हैं जबकि वे पाठशालाओं में पढ़ाने वालों में 80% हैं, सेकेंडरी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों में उनका प्रतिशत 27 है।

अन्त में, सभी महिला-प्रधान व्यवसाय-समूहों की आय औसत आय से कम है। इनमें डाक विभाग, शिक्षण, स्वास्थ्य, बैंकिंग व व्यापार सेवाएँ सम्मिलित हैं। उद्योग में क्लर्क या लेखपाल महिलाएँ हैं जिनको सबसे कम वेतन मिलता है। क्या इसका यह अर्थ लिया जाये कि सोवियत संघ में प्रत्यक्ष उत्पादक गतिविधि को ही अधिक मजदूरी देने का अधिकार है? शायद यह ऐसा हो है।

जन-शक्ति नियोजन

यह सही है कि सोवियत संघ में अनियोजित श्रम गतिशीलता विद्यमान है क्योंकि श्रमिक अपनी नौकरी छोड़ने व अन्य स्थान पर नौकरी करने के लिए स्वतंत्र हैं। यह नियोजन ऐसी स्थिति में निर्देशात्मक (directive) ही न होकर सूचक (indicative) भी हो सकता है। लेकिन सोवियत व्यवस्था को इस दृष्टि से एक लाभ है। विभिन्न क्षेत्रों के लिए योजनाएँ उपलब्ध संसाधनों की जानकारी के आधार

पर बनायी जाती है। रोजगार उपलब्ध कराना कर्तव्य है, कार्य के अधिकार को मान्यता प्राप्त है और इसी तरह काम करना भी कर्तव्य है। श्रम उत्पादकता योजनाओं में विभिन्न उद्योगों में सम्भावित श्रम बचत तथा श्रम के वैकल्पिक उपयोग (श्रमिकों का अन्य उद्योगों या सेवाओं में उपयोग) दोनों ही का हिसाब देखा जाता है।

इस सोवियत दावे पर विश्वास कर पाना असम्भव है कि वहाँ कोई बेकार है ही नहीं किन्तु यह कहना उचित होगा कि यहाँ की अपेक्षा बेकारी की समस्या पश्चिमी देशों में अधिक विकट है। यहाँ तक कि अमरीका में बेकारी की दर 6% के लगभग है। ब्रिटेन में तो यह 8% तक पहुँची है। सोवियत संघ में नौकरी की सुरक्षा ऊँचे दर्जे की है। वहाँ इधर-उधर आ जाने की भी स्वतन्त्रता है। विशेष रूप से नये औद्योगिक क्षेत्रों में आने-जाने की।

किन्तु रोजगार के क्षेत्र में भी कुछ समस्याएँ दृष्टिगत होती हैं। एक ऐसी कठिनाई उपलब्ध मजदूरी, आवास व अन्य सुविधाओं की देखते हुए लोगों की साइबेरिया जैसे क्षेत्रों में काम करने के प्रति अनिच्छा है। एक अन्य शिकायत प्रतिष्ठानों द्वारा अतिरिक्त श्रमिकों को हटाने को लेकर है। जब तक वैकल्पिक काम स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध न हो, मजदूरों को रस्ते रहने के लिए स्थानीय दबाव पड़ते हैं। यह शायद एक उत्तर भी है, उस स्थिति के लिए जहाँ एक ओर तो अनुपयोगी या अर्द्ध उपयोगी श्रमिक होते हैं तथा दूसरी ओर उनका अभाव रहता है। अधिक समस्या विभिन्न प्रकार के श्रमिकों की, विशेषकर के विशेषज्ञों की, माँग की व पूर्ति, में सन्तुलन स्थापित करने की रहती है। 'सोवियत व्यवस्था के आलोचकों का कहना है कि वहाँ 'प्रशिक्षित श्रमिकों की योग्यताओं (qualifications) तथा राष्ट्रीय उच्च स्तरीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के बीच विसंगतियाँ' विद्यमान हैं। एक अनुमान के अनुसार, सेक्रेण्डरी पास व्यक्तियों, जिन्होंने बाद में तीन से चार वर्षों तक तकनीकी कॉलेजों में शिक्षा पायी हो, कि उद्योग में आवश्यकता 1973 तक भी 40-42% तक ही पूरी की जा सकी थी। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को चला सकने वाले व्यक्तियों की तो विशेष कमी है। इसीलिए जब 17 विशाल नये प्रतिष्ठानों का, एक विशेष प्रदेश (republic) में, सर्वेक्षण किया गया तो पता चला कि उनमें से कोई भी उत्पादन की पूर्ण क्षमता प्राप्त नहीं कर पाया था, क्योंकि उन्हें योग्यता प्राप्त श्रमिक उनकी कुल आवश्यकताओं के 58% ही दिये गये थे। रासायनिक उद्योगों को शुरू करने में कुछ क्लिफ्ट भी 'कुछ सीमा तक योग्यता प्राप्त कर्मचारियों के अभाव' के कारण ही हुआ था। एक अधिक सामान्य प्रकार का असन्तुलन यह है कि 'अनुसंधान या बिना योग्यता वाले श्रमिक उनकी आवश्यकता में 15-33% अधिक हैं जबकि कुशल श्रमिक कुल मिलाकर कम हैं, हालांकि उनमें से कुछ की पूर्ति अधिक है।'।

इन कुसमायोजना के लिए अनेक कारण उत्तरदायी हैं। दत्त श्रमिकों की भावी आवश्यकता के लिए सूचनाओं का प्रवाह (flow of information) दोषपूर्ण है। उन लोगों के लिए वेतन व पद, जो तकनीकी योग्यता प्राप्त हैं, अपर्याप्त आकर्षण वाला है। अनेक तकनीकी प्रशिक्षण संस्थानों में पर्याप्त उपकरण ही नहीं हैं। उनके

परिसर अपर्याप्त है तथा प्रशिक्षक स्वयं अपूर्ण योग्यताओं वाले हैं।

इस स्थिति में सुधार हो रहा है। सोवियत संघ में इन दिनों 'काम के वैज्ञानिक संगठन' को लेकर काफी चर्चा है। तकनीकी प्रशिक्षण का गुणात्मक व मात्रात्मक पक्ष भी सुधर रहा है। एक अनुमान के अनुसार 1973 में 30% औद्योगिक श्रमिकों ने सेकेंडरी शिक्षा पूरी कर ली थी जबकि यही प्रतिशत 1952 में 24 था। इस में निम्न जन्म-दर में श्रमिकों की पूर्ति में वृद्धि की दर पहले ही गिर रही है। इसलिए नये श्रम की आवक के बारे में आयोजन अब और भी अनावश्यक हो गया है तथा आने वाले वर्षों में उनका अधिक कुशलता से प्रशिक्षण भी महत्वपूर्ण है।

काम की दशाएँ

सोवियत संघ में श्रमिकों के लिए काम के घण्टों में काफी कटौती कर दी गई है तथा सप्ताह में अब कार्यदिवस की संख्या अधिकांश स्थानों पर 5 ही हो गयी है।¹ यह बताया गया है कि 1973 में सप्ताह में काम के घण्टों का औसत घटकर 40.7 घण्टे रह गया था जो 1955 में 47.8 घण्टों का था। सरकारी तौर पर तो इसे मना किया जाता रहा है किन्तु वहाँ कुछ ओवर टाइम भी किया जाता है। इसे वहाँ तूफानी दौर (storming) या (shturmovshchina) या योजना को जल्दी से पूरा करने के लिए दौड़ का नाम दिया जाता है।

प्रचण्ड इन बातों को भी सरकारी तौर पर इनकार किया जाता रहा है किन्तु सोवियत संघ में श्रमिकों की अनुपस्थिति, काम चुराना, घराबखोरी, छोटी चोरियों की आदत, घूसखोरी और ऐसी ही छोटी नकारात्मक चीजें देखने में आती हैं। कुछ ऐसे अपराध भी पकड़े गये हैं जिनमें बड़े पैमाने पर डेर सारा कच्चा माल गतव्य स्थल से दूसरी ओर मोड़ दिया जाता है ताकि उपभोक्ता वस्तुओं का निर्माण किया जा सके। निजी बातचीत के दौरान यह भी पता चला है कि कई लोग कई अप्रचारित तरीकों से अतिरिक्त आय भी कमाते हैं।

सबेतेन अवकाश वर्ष भर में कम से कम 15 दिन का होता है। कई भारी उद्योगों के श्रमिकों को यह अवकाश 4 सप्ताह तक का मिलता है। इनके अतिरिक्त वैतनिक मातृत्व अवकाश, अपंग होने की स्थिति में लाभ, बीमारी में वेतन, वृद्धावस्था पेंशन आदि का भी जिक्र उल्लेख किया जाना चाहिए। बच्चों के लिए भत्ता भी मिलता है। अब ऐसे लोगों को पूरक राशि भी दी जा रही है जिनकी पारिवारिक आय 50 रूबल मासिक से कम है। 1956 में किये गये संशोधन के बाद पेंशनों 35 रूबल से लेकर 120 रूबल प्रति माह तक हो गई हैं। स्वास्थ्य सेवा निशुल्क तथा सेकेंडरी या उच्च शिक्षा के लिए कोई ट्यूशन फीस नहीं ली जाती। मकान किराया में भी सरकार अनुदान देती है। वास्तविक जीवन-स्तर का मूल्यांकन करते समय इन सभी तत्वों का उल्लेख करना आवश्यक है। वास्तव में श्रमिकों को मिलने वाले ये अतिरिक्त लाभ इतने अधिक हैं कि केवल उनकी सूची बनाने के लिए एक अलग पुस्तक की आवश्यकता पड़ेगी।

श्रम सघ (Soviet Trade Unions)

श्रम सघों का संगठन सोवियत रूस में उद्योग के आधार पर होता है तथा उसमें उच्च श्रेणी के लोग, मैनेजर भी, सम्मिलित होते हैं। इन श्रम सघों में चुनावों से पदाधिकारी नियुक्त होते हैं और इन्हें कुछ लोकतान्त्रिक अधिकार भी प्राप्त हैं। राष्ट्रीय गोप्टियो में अखिल सघ केन्द्रीय परिषद् (All Union Central Council, AUCCTU) का चुनाव किया जाता है। किन्तु सभी स्तरों पर साम्यवादी पार्टों का पूर्ण निधन्त्रण होता है। 1932 व 1954 के बीच अखिल-सघ केन्द्रीय परिषद् का चुनाव करने के लिए केवल एक बैठक हुई थी। केन्द्रीय सस्था को श्रमिकों की एक अर्द्ध शासकीय सस्था ही माना जाता है। यह सामाजिक धोमा योजना को क्रियान्वित करने तथा योजना के लक्ष्यों के अनुरूप उत्पादन बढ़ाने के श्रमिकों को प्रोत्साहित करने व अन्य सरकारी नीतियों को लागू करने में सहायता देती है। स्थानीय स्तर पर, श्रम सघों के पदाधिकारी श्रमिकों के हितों की रक्षा का कार्य अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने वाले प्रबन्ध के विरुद्ध भी करते हैं।

सोवियत स्थानीय श्रम सघों का मुख्य कार्य श्रम कल्याण व सुविधाएँ जुटाने का है तथा वे मजदूरी निर्धारण से सम्बन्धित नहीं होती। उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये श्रम सघ कई 'समाजवादी प्रतिस्पर्द्धाएँ' (Socialist competitions) व्यक्तिगत श्रमिकों, समूहों व कारखानों के बीच आयोजित करते रहते हैं। श्रम सघ पदाधिकारी नियोजित वस्तु-इकाई-दरों (price-rates) से भी सम्बन्धित होते हैं। इस प्रकार उनके सदस्यों की कुल आय का निर्धारण करने में उनका हाथ होता है। स्थानीय श्रम सघ प्रबन्धक तथा श्रमिकों के बीच घोरतम समझौते, गैर-वानुशी निष्कामन, पदावनति आदि के बारे में उठने वाले विवादों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे समान दर्जे पर, 'वाद-विवाद आयोग' (conflict commissions) में भी भाग लेते हैं जो कारखानों में होने वाले ऐसे झगड़ों को निपटाते हैं। यदि ये आयोग मामले को निपटा सकने में असफल हो जाते हैं तो फिर उसे अन्तिम निर्णय के लिए केन्द्रीय श्रम सघ को भेजा जाता है। यदि श्रमिक या प्रबन्धक फिर भी ऐसा समझे कि फैसला कानून के विरुद्ध हुआ है तो वे उनके विरुद्ध अदालतों में अपील दायर कर सकते हैं।

स्टालिन के युग में श्रम सघों का कार्य मुख्यतः उत्पादन लक्ष्य पूरे करवाने के लिए श्रमिकों का गतिशीलन करना ही रह गया था तथा श्रमिकों की रक्षा करने की उनकी भूमिका गंभीर हो गई थी। इसे इस आधार पर उचित ठहराया जाता था कि चूंकि राज्य ही नियोजता है इसलिए श्रमिकों की सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। 1940 के दो अत्यधिक बड़े आदेश, जिनमें बिना अनुमति के काम की जगह बदलने पर रोक लगा दी गई थी तथा अनुपस्थित रहने व देर से आने पर भारी जुर्मानों की व्यवस्था की गई थी, केन्द्रीय श्रम सघ की प्रार्थना पर ही जारी किये गये थे। श्रम सघों का एक काम यह भी था कि वे अपने सदस्यों को राज्य बॉण्ड खरीदने के लिए बाध्य करें। आतिरकार स्थिति इतनी गंभीर हो गयी कि वह स्वयं सरकार

के लिए भी असहनीय हो गई। अनेक स्तरों पर कई अपसलताएँ सामने आयी। स्थानीय श्रम सघ अपने सदस्यों को अधिकारों का दुरुपयोग करने वाले प्रबन्ध से नहीं बचा पाये। 'समाजवादी प्रतियोगिताएँ' कोरी कागजी कार्यवाहियाँ बनकर रह गयी। स्टालिन की मृत्यु के बाद ऐसे कई लेख प्रकाशित हुए जिनमें श्रम सघों के विषय में भारी असन्तोष व्यक्त किया गया। 1957 में श्रम सघों की केन्द्रीय समिति ने स्थानीय इकाइयों को सदस्यों के हितों की रक्षा की भूमिका अधिक अच्छी तरह निभाने के निर्देश दिये। उसने स्थानीय श्रम सघों के गतिशीलक (mobilisers) के रूप में भूमिका पर भी बल दिया तथा उन्हें स्थायी उत्पादन परिषदों (Permanent Production Councils) का सदस्य बनाया।

सोवियत श्रम सघों के बारे में पश्चिमी देशों में सामान्य धारणा यह है कि वे श्रम सघ है ही नहीं। यह सही है कि वे राज्य या दल से स्वतन्त्र होकर काम नहीं कर सकते। उनका मुख्य काम राज्य या पार्टी द्वारा अपनायी गई नीतियों का परिपालन कराने के लिए श्रमिकों का गतिशीलन करना है। इन परिस्थितियों में श्रमिकों के रक्षक के रूप में दायित्व का निर्वाह कर सकना उनके लिए काफी कठिन है। जहाँ तक उत्पादन लक्ष्यों को पूरा करने का प्रश्न है प्रबन्धन श्रम सघों के बीच कोई टकराव नहीं है। वे श्रम सघ श्रमिकों के रक्षक के रूप में अपने दायित्व का निर्वाह नहीं करते। यह तो प्रबन्धकों द्वारा जारी किये गये उन निष्कासन (dismissals) आदेशों को भारी सख्या में अदालतों द्वारा रद्द किये जाने से ही स्पष्ट है। यह कहा जाता है कि एक क्षेत्र में तो निष्कासन के विरुद्ध आघों से भी अधिक अपीलें को न्यायालयों में उचित माना।

तेरहवाँ अध्याय

आयोजन का संगठन व आर्थिक प्रबन्ध (ORGANISATION OF PLANNING AND ECONOMIC MANAGEMENT)

सोवियत संघ में आयोजन व प्रबन्ध का सामान्य उद्देश्य उसके विकास को संचालित करने वाले वस्तुनिष्ठ कानूनों का आदर्शतम उपयोग करना, उसके मानवीय, भौतिक एवं वित्तीय साधनों का संगठन करना तथा मौजूदा जानकारी के भण्डार का साम्यवाद के निर्माण में उपयोग करना है।¹ वहाँ सामाजिक स्वामित्व की प्रधानता है। आयोजन व प्रबन्ध के मुख्य सिद्धान्त सोवियत संघ में इस प्रकार हैं

(1) जनतान्त्रिक सकेन्द्रण (Democratic Centralism)—सोवियत संघ में आयोजन व प्रबन्ध को संचालित करने वाला यह प्रमुख सिद्धान्त बताया जाता है।

(2) एक व्यवस्था—विश्लेषण का तरीका (A system—analysis approach)—चूँकि अर्थव्यवस्था एक जटिल प्रणाली है जिसमें विविध अन्तर्सम्बन्ध तथा अनेक उपप्रणालियाँ (subsystems) जैसे पृथक् आर्थिक प्रदेश व क्षेत्र भी हैं इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि मुख्य आर्थिक प्रश्नों को अलग से नहीं बल्कि समग्र रूप से एक व्यवस्था के अन्तर्गत हल किया जाना चाहिए।

(3) आर्थिक विकास को बढ़ावा—श्रमिकों के उत्पादक प्रयासों को उत्तेजित करना तथा उनके काम के गुणात्मक पहलू में निरन्तर सुधार करना भी महत्वपूर्ण माने गये हैं।

(4) प्रशासनिक व आर्थिक उपायों का संयोग—आर्थिक नियोजन को वैज्ञानिक तरीके से सोचे गये प्रशासनिक व आर्थिक उपायों पर आधारित बताया गया है। इसका अर्थ यह है कि आयोजन एजेंसियों के पास प्रशासनिक अधिकार होने चाहिए। वे अपने इन अधिकारों का प्रयोग कुछ आर्थिक उत्तोलकों (economic levers) जिनमें मूल्य, मजदूरी, लागत हिसाब, लाभ कमाने के लिए अभिप्रेरणएँ तथा साख्त सम्मिलित हैं।

(5) कार्यकुशलता—इसे भी आयोजन व प्रबन्ध का आधारभूत सिद्धान्त माना जाता है। इससे यह बात प्रत्याभूत (ensured) की जाती है कि पूर्वं निर्धारित कार्यक्रमों को न्यूनतम सम्भव समय में पूरा किया जा सके तथा उनमें न्यूनतम जनशक्ति, साधन व वित्तीय प्रदाय (inputs) काम में आये।

संगठन

सोवियत सभ में आर्थिक नियोजन तथा प्रबन्ध को क्षेत्रवार संगठित किया जाता है। राज्य के स्वामित्व वाले औद्योगिक, कृषि, यातायात व निर्माण प्रतिष्ठानों व संगठनों की उत्पादक व अन्य गतिविधियाँ क्षेत्रीय मन्त्रालयों द्वारा संचालित होती हैं। लेकिन सोवियत सभ में 15 सम्प्रभु (sovereign) गणराज्य भी हैं। इन गणराज्यों की सरकारें अपने गोसप्लानों (gosplans) द्वारा (अर्थात् राज्य योजना आयोगों द्वारा) तथा आर्थिक मन्त्रालयों द्वारा उनके नियन्त्रण वाले प्रतिष्ठानों के कार्यों का निर्देश करती हैं। ये गणराज्य राष्ट्रीय महत्त्व के प्रतिष्ठानों के लिए भी रूपरेखा तैयार करने में योग देते हैं। इन गणराज्यों के अधीन इतने अधिक प्रतिष्ठान हैं कि वे देश राष्ट्रीय आय का दो तिहाई भाग पैदा करते हैं। इस तरह इन गणराज्यों के पास विशाल आर्थिक क्षमता है। गणराज्यीय योजना आयोग (Republican gosplans) अपनी अर्थव्यवस्थाओं के विकास के लिए व्यापक पंचवर्षीय योजनाएँ भी तैयार करते हैं।

देश में दो प्रकार के प्रतिष्ठान हैं स्थानीय व गणराज्यीय प्रतिष्ठान तथा पूर्ण-सघीय प्रतिष्ठान। पहली प्रकार के प्रतिष्ठान पूरी तरह स्थानीय एवं गणराज्यीय अधिकारियों के अधीन होते हैं जबकि दूसरी तरह के प्रतिष्ठान आर्थिक मन्त्रालयों (सघीय) के अधीन होते हैं। आयोजन का एक महत्त्वपूर्ण कार्य पूर्ण-सघीय हितों तथा स्थानीय व गणराज्यीय हितों के बीच अच्छा तालमेल स्थापित करना है। चूँकि सारी की सारी अर्थव्यवस्था नियोजित है इसलिए आर्थिक गतिविधियों को सभी स्तरों पर इस प्रकार संगठित करना सम्भव है कि स्थानीय हितों के साथ राष्ट्रीय हितों का टकराव न हो। इस कार्य के लिए सोवियत सरकार अनेक उपाय काम में लेती है जो मूल्यों में लेकर मजदूरी, भुगतानों व लागत-लेखा (cost-accounting) तक फैले हुए हैं। आर्थिक अभिप्रेरणाओं के अतिरिक्त सामाजिक व नैतिक उत्तेजकों (stimulus) का भी प्रयोग किया जाता है। दवाव व अन्य ऐसे ही तरीकों का उल्लेख न करना ही शायद अधिक शान्तितापूर्ण होगा।

योजना आयोगों (Gosplans) के कार्य

अब हम आर्थिक नियन्त्रणों की वर्तमान सोवियत प्रणाली में केन्द्रीय एवं गणराज्यीय याजना आयोगों के मुख्य कार्यों की विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। सोवियत नियोजन प्रणाली के अन्तर्गत वहाँ की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था आ जाती है। सारी आयोजन एजेंसियों का कार्य एक ही आर्थिक नीति तथा योजना बनाने के सामान्य सिद्धान्तों से समन्वित होता है। सोवियत सभ की इन आयोजन एजेंसियों को दो समूहों में विभक्त किया जा सकता है

- (i) सामान्य आयोजन एजेंसियाँ, व
- (ii) आर्थिक एजेंसियों के आयोजन उपविभाग।

पहले समूह में सोवियत सभ की मन्त्रि-परिषद् की आयोजन समिति (State

Planning Committee of the U S S R Council of Ministers), सघीय गणराज्यों के योजना आयोग (Republican gosplans), प्रादेशिक, शहरी तथा जिला योजना आयोग सम्मिलित है। वर्तमान में गणराज्यों के योजना आयोग सघीय योजना आयोग तथा सम्बन्धित गणराज्यों के मन्त्रालयों के दोहरे नियन्त्रण में हैं। इस प्रकार सोवियत सघ का योजना आयोग (U S S R gosplan) एक मिली-जुली सघ गणराज्य आयोजना इकाई है जिसकी आधीनता में क्षेत्रीय मन्त्रालय, जो अपने-अपने क्षेत्र के उद्योगों के लिए योजनाएँ तैयार करते हैं (जैसे उद्योग, कृषि, यातायात आदि), कार्य करते हैं। इस प्रकार के संगठनात्मक ढाँचे के कारण सोवियत योजना आयोग अव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों तथा विभिन्न गणराज्यों व स्थानीय इकाइयों द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समन्वित करने का कार्य करता है।

दूसरे समूह में सघीय एवं गणराज्यों के मन्त्रालयों के आयोजना विभाग, प्रमुख प्रतिष्ठानों, ट्रस्टों व उत्पादक सघों के योजना खण्ड आते हैं।

दोनों समूहों का एक-दूसरे से घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है।

सोवियत योजना आयोग के कार्य

(1) सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुसार यह आर्थिक विकास के सामान्य पैमाने तथा मुख्य प्रवृत्तियों, प्रमुख समष्टि अनुपातों (macro-economic proportions) तथा सोवियत सघ के परराष्ट्रीय आर्थिक सम्बन्धों का निर्धारण करता है।

(2) यह योजना बनाने के लिए मान्य तरीकों, समय सीमाओं तथा कार्य-प्रणालियों को स्पष्ट करता है।

(3) यह सघीय गणराज्यों तथा क्षेत्रीय मन्त्रालयों द्वारा तैयार किये गये राष्ट्रीय आर्थिक नियोजन के प्राप्ति की जाँच करता है तथा उनकी योजनाओं को समन्वित करके स्थानीय एवं क्षेत्रीय असफलताओं का समायोजन करते हुए उनके आधार पर सामान्य आर्थिक नियोजन का प्रारूप तैयार करता है।

(4) अन्य केन्द्रीय इकाइयों—वित्त मन्त्रालय, स्टेट बैंक तथा धन, मूल्य, मजदूरी विज्ञान एवं तकनीकी समितियाँ—के साथ मिलकर योजना के दौरान आर्थिक विकास पक्काभूत (ensure) करने की दृष्टि में यह आर्थिक उपाय (economic measures) तैयार करता है। इन उपायों में उत्पादन को उत्तेजित करने वाले मूल्यों की स्थापना करने बँकों की व्याज दर तथा साख सम्बन्धी नियमन करने, परिसम्पत्तु के लिए निश्चित भुगतान करन तथा आर्थिक एजेंसियाँ व राज्य बजट के बीच सम्बन्धों के लिए मानदण्ड निर्धारित करने जैसे उपाय सम्मिलित हैं। सोवियत योजना आयोग, सोवियत सघ की विज्ञान अकादमी के साथ मिलकर, दीर्घकालीन तकनीकी नीति व आधारभूत एवं व्यावहारिक विज्ञानों की मुख्य प्रवृत्तियों का भी निर्धारण करता है।

केन्द्रीय एजेंसियों को बजट द्वारा वित्त उपलब्ध कराने वाली विनियोग नीति (Budget financed investment policy), विनियोग के लिए कोषों की क्षेत्रवार तथा विभिन्न प्रदेशों में प्रवाह तथा उद्योगों के लिए स्थान का चुनाव करने का अधिकार है। केन्द्रीय एजेंसियाँ अग्रलिखित कामों के लिए भी उत्तरदायी हैं (अ) विदेशी

आर्थिक सम्बन्ध, (था) आयात निर्यात योजना तैयार करना, (इ) ऋण व साख के आकार का निर्धारण, (ई) विवासोन्मुख देशों को आर्थिक सहायता, (उ) मिले-जुले प्रतिष्ठानों की स्थापना, तथा (ऊ) प्राकृतिक समाधनों का समुक्त विदोहन ।

(5) अन्त में, सोवियत योजना आयोग राष्ट्रीय आर्थिक आयोजन के पूरे होने की दृष्टि से निगरानीयाँ रखता है । वह योजना से अवांछित विचलनों (undesirable deviations) को रोकने के उपाय करता है । इसका एक मुख्य कार्य सोवियत संघ की योजनाओं को परस्पर आर्थिक सहायता परिषद् (Council for Mutual Economic Assistance) के समाजवादी सदस्य देशों की योजनाओं के साथ समन्वित करने सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत करना भी है ।

राज्यीय योजना आयोगों (Republican Gosplans) के कार्य

गणराज्यों के योजना आयोग गणराज्य की अर्थव्यवस्था के लिए दीर्घकालीन व चालू योजनाएँ तैयार करते हैं । वे गणराज्य के मन्त्रालयों, स्थानीय व प्रादेशिक समितियों द्वारा तैयार की गई योजनाओं में संशोधन भी करते हैं । वे योजनाओं के पूरे होने के लिए निगरानी भी रखते हैं । वे सघीय-राज्यीय तथा पूर्ण सघीय मन्त्रालयों के योजना विभागों में पूरी तरह सम्पर्क भी बताये रखते हैं तथा राष्ट्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के लिए भी अपने प्रस्ताव बांटे भेजते हैं ।

प्रादेशिक, नगर एवं जिला स्तर पर कार्यरत स्थानीय योजना आयोगों द्वारा भी महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है । विशेष रूप से वे स्थानीय क्षेत्र के विकास में प्रतिष्ठानों की पूर्ण क्षमता के उपयोग की ओर ध्यान देते हैं । स्थानीय नियोजन राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा होता है ।

विभिन्न मन्त्रालय अपने-से सम्बन्धित क्षेत्रों में उत्पादन एवं अन्य आर्थिक गतिविधियों को निर्देशित करते हैं । ये मन्त्रालय अपने-अपने क्षेत्र में अर्थव्यवस्था में वांछित वस्तुओं की पूर्ति के लिए नी उत्तरदायी होते हैं । ये मन्त्रालय अपने क्षेत्र की तपनीय प्रगति की भी देख-भाल करते हैं । इनका काम यह देखना भी होता है कि सम्बन्धित क्षेत्र लाभ से चटना है या नहीं ।

पिछले कुछ वर्षों में उद्योग व प्रतिष्ठानों के प्रबन्ध को सुधारने के लिए कुछ परिवर्तन किये गये हैं । वेग व्यक्तिगत प्रतिष्ठान ही नहीं बरिक्त सम्पूर्ण उद्योग को लागत-लेखा (cost accounting) के अन्तर्गत रख दिया गया है । प्रत्येक गणराज्य में गणराज्यीय उद्योग संघ गठित किये गये हैं । देश में अनेक विद्यालय समुक्त उद्योग (combines) भी हैं जो संघों (associations) की तरह हैं । प्रबन्ध का यही स्वरूप कृषि, यातायात, निर्माण तथा व्यापार में भी है ।

योजना निर्माण (Plan Formulation)

योजना बनाने का काम शुरू करने से पहले गत वर्षों में हुए आर्थिक विकास एवं नई आवश्यकताओं का गहन एवं व्यापक विश्लेषण किया जाता है । उसके बाद उपर्युक्त सरकारी सत्ताएँ प्राप्ति निर्देशा (draft directives) के रूप में नई योजना

के उद्देश्यो व बाणों को परिभाषित करती है। इन निर्देशों में मुख्य आर्थिक, तकनीकी तथा सामाजिक समस्याओं, जिनके कि समाधान की आवश्यकता होती है, का उल्लेख किया जाता है। ये निर्देश योजना के सामने रखे गये मुख्य प्रश्न के समाधान की रूपरेखा भी प्रस्तुत करते हैं। राष्ट्रीय आय में नियोजित वृद्धियों को नये स्थिर व गतिशील परिसम्पत् का निर्माण करने में किस प्रकार प्रयुक्त किया जाए?

इसके बाद इन प्रारूप निर्देशों को वाद-विवाद के लिए प्रकाशित किया जाता है। इसके बाद सोवियत सरकार तथा साम्यवादी पार्टी के नेताओं द्वारा उनकी जाँच की जाती है। इन निर्देशों को आधार मानते हुए विभिन्न आर्थिक नियोजन एजेंसियाँ एक पूरी पाँच वर्षों की योजना तैयार करती है। योजना बनाने के इसी तरीके को 'जनतान्त्रिक सकेन्द्रण' (democratic centralism) की सज्ञा दी गई है।

योजनाएँ बनाने के समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि मुख्य निर्णय संगठन एवं प्रबन्ध के स्तर पर लिये जाएँ जिनके पास अधिकतम मात्रा में सूचनाएँ उपलब्ध होती हैं। लेकिन वास्तव में सोवियत योजना-निर्माण केन्द्रीय सरकार का ही विषय-क्षेत्र रहता है। केन्द्रीय संस्थाएँ वे कानून या नियम बना देती हैं जो स्थानीय व क्षेत्रीय एजेंसियों की गतिविधियों का नियमन करने के लिए मानदण्ड का काम करते हैं। इस प्रकार केन्द्रीय संस्थाओं के निर्णयों की नीचे की संस्थाओं द्वारा अनुपालना की जाती है।

समाजवादी गुट (Socialist Bloc) की संयुक्त योजनाएँ

1949 में यूरोप के समाजवादी देशों द्वारा परस्पर आर्थिक सहयोग परिषद् (Council for Mutual Economic Assistance) ने सदस्य देशों के बीच आर्थिक बहुपक्षीय सहयोग का नया क्रम शुरू कर दिया है। 1971 में सहयोग के लिए एक विशाल कार्यक्रम तथा परिषद् के सदस्य देशों के बीच समाजवादी एकीकरण का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। इस कार्यक्रम में विभिन्न राष्ट्रीय आर्थिक योजनाओं के ममन्वयन तथा वैज्ञानिक एवं तकनीकी समस्याओं पर मिला जुलकर काम करने का प्रस्ताव किया गया है। इसमें उत्पादन विशिष्टीकरण (production specialisation) तथा पूर्ति एवं विज्ञान का संगठन करने पर भी बल दिया गया है। विभिन्न समाजवादी देशों के आर्थिक स्तर में समानता स्थापित करना भी इसका एक उद्देश्य है।

इन समाजवादी देशों का यह संयुक्त आयोजन कार्यक्रम ऐच्छित आधार पर है। परस्पर अनिवार्यता तभी आती है जब द्विपक्षीय या बहुपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर कर दिये जाते हैं। व्यापक कार्यक्रम (the comprehensive programme) में परिषद् के सदस्य देशों से 1990 व 2000 तक उर्वरक, ईंधन व ऊर्जा आवश्यकताओं की भविष्यवाणी करने को भी कहा गया है।

पिछले कुछ वर्षों में परिषद् (CMEA) के सदस्यों ने समस्त क्षेत्रों के विकास के लिए संयुक्त योजनाएँ बनाना आरम्भ कर दिया है। वे न केवल सभी देशों की आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं का उत्पादन करने की मिली-जुली योजनाएँ

वना रहे हैं बल्कि मिले जुते अनुसन्धान एवं विकास (Research and Development) कार्यक्रम भी उनके द्वारा तैयार किये जा रहे हैं।

सोवियत संघ की साम्यवादी पार्टी की भूमिका

सोवियत आर्थिक विकास में संचालक की भूमिका वहाँ की साम्यवादी पार्टी (CPSU) की है। ब्रेज्नेव के शब्दों में, 'पार्टी सम्पूर्ण सामाजिक व्यवस्था का केन्द्र-बिन्दु है, वह सारी सोवियत जनता का सामूहिक मस्तिष्क (collective brain) है।' यह साम्यवादी पार्टी ही है जो राज्य तथा आयोजन संस्थाओं के कार्य निर्धारित करती है तथा इन संस्थाओं व स्वयं सरकार में अपने प्रतिनिधियों द्वारा उनकी कार्यान्विति (implementation) पर दृष्टि रखती है। पंचवर्षीय योजनाओं पर दल के निर्देशों को ज्यों का त्यों (in toto) स्वीकार कर लिया जाता है। साम्यवादी दल आर्थिक प्रबन्ध में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्राथमिक पार्टी संगठनों को प्रशासन के क्रियाकलापों पर निगरानी रखने का अधिकार है। यह भी सोवियत प्रणाली की अपनी ही विशेषता है। ये प्राथमिक संगठन (primary organisations) प्रशासन को उसकी कमियाँ या त्रुटियाँ बताकर उत्पादन के स्तर को ऊँचा उठाने का प्रयास करते हैं।

श्रम-संघों में साम्यवादी दल महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वर्तमान में श्रम-संघों के प्रत्येक 6 सदस्यों में से एक साम्यवादी दल का भी सदस्य है। जिस दल की अपनी सदस्य-संख्या अब 15 मिलियन है। आधे से भी अधिक साम्यवादी दल के सदस्य कारखानों, सामूहिक खेतों, राजकीय खेतों, खानों तथा अन्य प्रतिष्ठानों में काम करते हैं जहाँ वे अपना प्रभाव व नियन्त्रण बनाय रखते हैं।

चौदहवाँ अध्याय

सोवियत अर्थव्यवस्था में आधुनिक प्रवृत्तियाँ (RECENT TRENDS IN THE SOVIET ECONOMY)

1953 में स्टालिन की मृत्यु के बाद सोवियत अर्थव्यवस्था में काफी कुछ बदला है। सोवियत आर्थिक नीति में अधिक उदारता (liberalisation) आई है। जबरन काम कराने तथा अन्य दबावों का उपयोग करने में गिरावट आ रही है। जबरन मजदूरी (Forced Labour) अब अतीत की बात बनती जा रही है। राज-नीतिक विरोधियों को अब गोली नहीं मार दी जाती है तथा योजना से सम्बन्धित विषयों पर खुले रूप से वाद-विवाद सामान्य बात बनती जा रही है।

1 बढ़ती हुई विकास-दर

सोवियत रूस का कुल राष्ट्रीय उत्पाद (G N P) तेजी से बढ़ रहा है। 1953 से 1965 के बीच यह 61 प्रतिशत वार्षिक की दर से बढ़ा। कुल राष्ट्रीय उत्पाद के 1970 से 1980 के बीच दुगुना हो जाने का अनुमान है। 1953 से 1965 के बीच सोवियत संघ में काम के घण्टों में 15 प्रतिशत की बढ़ोती की गई तथा यह कटौती की प्रवृत्ति जारी है।

प्रति व्यक्ति-घण्टा उत्पादन (per man hour output) की दृष्टि से अब सोवियत रूस केवल जापान व जर्मनी से पीछे है।

प्रति व्यक्ति-घण्टा उत्पादन 1953-65

(वार्षिक औसत वृद्धि प्रमाण दर)

जापान	7.8
प० जर्मनी	5.4
सोवियत संघ	5.2
फ्रांस	4.6
इंग्लैंड	2.7
अमेरिका	2.2
कनाडा	1.9

2 उपभोक्ताओं के लाभ

पिछले कुछ वर्षों में उत्पादन में हुई वृद्धियों से सोवियत उपभोक्ता पूरी तरह लाभान्वित होता रहा है। 1950 से 1965 के प्रति व्यक्ति निजी उपभोग में

5.5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई है। 1970 के दशक में उसमें और भी तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। 1950 से 1965 के बीच शहरी में उपलब्ध आवासीय स्थान की प्रति व्यक्ति उपलब्धि 5.0 वर्ग मीटर से बढ़कर 6.4 वर्ग मीटर हो चुकी थी।

रुश्चेव के सत्ता में हट जाने के बाद पदासीन हुए रूसी नेतृत्व ने लोगों के कल्याण को अपना ध्येय बनाया है। लोगों को सामान्य आवश्यकताओं की वस्तुएँ उपलब्ध करवाने का काम सोवियत योजनाओं का प्रमुख लक्ष्य बन चुका है। 1966 के बाद बनी हुई पंचवर्षीय योजनाओं में उपभोक्ता उद्योगों के विवास की जो दर रखी गई है वह भारी उद्योगों की विकास-दर के बराबर-सी है।

3 'लाइबरमेनवाद' (Libermanism)

स्टालिन युग में सोवियत फैक्ट्रियाँ केन्द्रीय आयोजन एजेंसी से प्राप्त आदेशों के आधार पर चला करती थीं। जहाँ तक उपभोक्ताओं का प्रश्न था वे केन्द्रीय आयोजन एजेंसी के लिए महत्वपूर्ण नहीं थे। इस प्रणाली की असफलता तो उन सरकारी भण्डारों में खराब और घटिया किस्म की वस्तुओं के भण्डार बढ़ते चले जाने में स्पष्ट हो गई थी जिन्हें खरीदने वाला कोई भी नहीं था। 1964 में 257 फैक्ट्रियों का उत्पादन रोक देना पड़ा था क्योंकि उनकी वस्तुएँ कोई भी खरीदने के लिए तैयार नहीं था। रेडियो, टेलीविजन, धुलाई मशीनों आदि की घटिया किस्म के बारे में शिकायतों का डेर लग गया था। उपभोक्ता किस्म पर जोर देने लगे थे। इस सारी समस्या का निष्कर्ष यही था कि केन्द्रीय आयोजन एजेंसी केवल एक ही मापदण्ड स्वीकार करती थी और वह मापदण्ड था—लक्ष्यों की पूर्ति।

बोनस के भुगतानों को लेकर भी 1960 के बाद कठिनाइयाँ आयीं। ये बोनस वस्तुओं की उत्पादित मात्रा तथा सौंप देने के समय के आधार पर दिये जाते थे। लेकिन अब यह स्वीकार्य नहीं था क्योंकि उपभोक्ता गुणात्मक पहलू पर जोर दे रहे थे। ऐसी स्थिति में इस नीति में परिवर्तन किया गया। कई उद्योगों में ऐसी व्यवस्था कर दी गई जिससे वे अपने भावी उत्पादन लक्ष्यों का निर्धारण उनकी वस्तुओं की वास्तविक बिक्री से किया करेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि अब उपभोक्ताओं की रुचि, केन्द्रीय आयोजन एजेंसी से प्राप्त निर्देश नहीं, उत्पादन का निर्धारण करेगी। इसीलिए फैक्ट्रियों को उनके भण्डारों को प्राप्त होने वाले ऑर्डरों के आधार पर उत्पादन का आयोजन करने को कहा गया। इन फैक्ट्रियों की सफलता का पता इस आधार पर लगाया जायेगा कि उनकी वस्तुओं को उपभोक्ताओं की स्वीकृति कहाँ तक प्राप्त होती है। इस तरह निम्नी भी वस्तु की सफलता या असफलता श्रेता की स्वीकृति या अस्वीकृति पर निर्भर करेगी।

ये परिवर्तन प्रो० बाई० जी० लाइबरमेन द्वारा सुझाये गये लाभ-अभिप्रेरणा कार्यक्रम (profit-incentive system) का सारांश थे। उसने यह अनुभव लिया कि अब सोवियत अर्थव्यवस्था इतनी जटिल और न सफलने योग्य हो चुकी है कि उसका एक केन्द्रीय संस्था द्वारा चलाया जाना सम्भव नहीं रह गया है। उसने अपनी पुस्तक 'योजना, लाभ तथा बोनस' (Plan, Profit and Bonus) 1962 में प्रकाशित की

जिस पर राष्ट्रव्यापी चर्चा हुई। लाइबरमेन ने जोर देकर कहा कि औद्योगिक कार्य-कुशलता तथा किस्म (quality) में सुधार लाभ की भावना पर जोर देकर किया जा सकता है।¹ उसने सोवियत व्यवस्था की कमी को भाँप लिया। वस्तु की उत्पादित मात्रा तथा उसे सौंप जाने के समय को वस्तु की किस्म से अधिक महत्व दिया जाना, उपर्युक्त दोनों मिथ्यात्मक आधारों (fallacies) पर औद्योगिक प्रबन्धकों द्वारा अधिक से अधिक उत्पादन लक्ष्य (assignments) प्राप्त करने की चेष्टा करना।

इस स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से प्रो० लाइबरमेन ने सुझाव दिया कि लाभ को प्रधान तत्व बनाया जाना चाहिए। 'जितना अधिक लाभ उतनी ही अधिक अभिप्रेरणा', कार्यकुशलता व किस्म दोनों के लिए। उसने निम्न महत्वपूर्ण परिवर्तन सुझाये

(अ) प्रबन्धकों को कार्यभार (assignments) चुनने की पूरी स्वतन्त्रता दी जाये। वे कार्यभार की जाँच करें तथा उसी को स्वीकार करें जिसे वे अच्छी तरह व पूरी कार्यकुशलता से कर सकें।

(आ) केन्द्रीय आयोजन आदेशों को सरकार व प्रतिष्ठानों के बीच अनुवन्धों से प्रतिस्थापित कर दिया जाना चाहिए कि जिनमें सबसे नीची बोली लगाने वाले को कार्य सौंपा जाये तथा वही उसका मूल्य निर्धारित करे।

(इ) प्रत्येक प्रबन्धकों को अनुबन्धित वस्तु का उत्पादन करने के लिए सहायकों का चुनाव कर सकने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए।

(ई) अन्त में, वस्तु को सौंपने में की गई जल्दी के आधार पर प्रबन्धकों को दिये जाने वाले बोनसों (Bonuses) के स्थान पर भुगतान उत्पादन में लगी हुई कुल पूँजी पर अर्जित किये गये लाभ की दर पर आधारित किये जाने चाहिए। ऊँची लाभ की दर के लिए बोनस भुगतान की दर भी ऊँची रहनी चाहिए। यह एक स्वाभाविक बात है कि जब लाभ को मुख्य सिद्धान्त मान लिया जाये तो मूल्यों को माँग व पूर्ति की बाजार-शक्तियों के अनुरूप चलना पड़ेगा, बजाय इसके कि उनका निर्धारण किसी केन्द्रीय सत्ता द्वारा कर दिया जाये।

प्रो० लाइबरमेन ने अपने आलोचकों के इस तर्क का भी खण्डन किया कि उनकी योजना पूँजीवादी तरीके की है। उसने कहा कि लाभों को सोवियत संघ में कभी अमान्यता नहीं दी गई। 'समाजवाद तथा लाभ की मनाही तथा पूँजीवाद द्वारा लाभ को मान्यता समाजवाद को भिन्न बनाने वाली विशेषता कभी नहीं रही। अन्तर तो उस ढंग का है जिससे लाभ बनाया, इकट्ठा किया तथा काम में लिया जाता है।'² यह भी कहा गया है कि उत्पादन का एकमात्र उद्देश्य लाभ कमाना ही नहीं है। लाभ का प्रयोग तो उत्पादन बढ़ाने व उसकी किस्म सुधारने के लिए किया जाना है। इसीलिए लाइबरमेन के समर्थकों ने कहा कि 'लाइबरमेनवाद कोई साम्यवादी विरोधी रामबाण दवा नहीं था बल्कि यह साम्यवाद को अधिक कुशल बनाने के लिए एक निदान था।' लाभ के सिद्धान्त को प्रयोग के तौर पर कुछ सीमित क्षेत्र में लागू किया

¹ A G Mazour, *op cit*, 83

² Liberman, in *Time*, 12 February 1965.

गया है। मास्को व गोर्की फैक्ट्रियों में कपड़े के उत्पादन में ये प्रयोग काफी सफल रहे।

4 सरकारी नियन्त्रणों में ढील

1965 में केन्द्रीय समिति ने केन्द्रीय नियन्त्रणों में ढील देने के विषय पर काफी विचार किया। इसका अर्थ था सरकार के स्वामित्व वाले उद्योगों पर चले आ रहे नियन्त्रण को कमजोर करना। फैक्ट्री प्रबंधकों को अधिक पहल देने की छूट दी गई। मूल्य, लागतों तथा बाजार सम्बन्धों को अधिक ध्यान से जाँचा गया। ये सुधार सोवियत संघ के इतिहास में 1921 की नई आर्थिक नीति के बाद का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ थे। प्रारम्भ में सोवियत संघ के विभिन्न भागों में स्थित केवल 50 कारखानों को इस प्रयोग के लिए चुना गया। कुछ अधिक कारखानों को भी बाद में शामिल किया गया। इन कारखानों को अधिक जिम्मेदारी का बहन करना था तथा उनकी उपलब्धि का फँसला उनके द्वारा उपभोक्ताओं को बेची जाने वाली वस्तुओं से किया जाना था। केन्द्रीय सरकार की एजेंसियों की भूमिका सलाह देने तथा व्यापक लक्ष्य निर्धारित करने तक सीमित कर दी गई।

1965 के बाद विनियोगों के लिए वित्तीय व्यवस्था करने के लिए भी एक नई नीति अपनायी गई है। कारखानों की क्षमता का विस्तार करने के लिए वाढित भारी विनियोग या नये कारखानों की स्थापना पर विनियोग की राशि अब ब्याज वाले ऋणों से प्राप्त करने की व्यवस्था की गई। पहले यह राशि वजेट-अनुदानों से दी जाती थी। पहले मूल्य भी मनमाने ढंग से तय कर दिये जाते थे मगर अब उन्हें वास्तविक उत्पादन लागत पर आधारित किया गया।

5 सैनिक व्यय

सोवियत शासन के आरम्भ से ही सोवियत सैनिक कार्यक्रमों पर तुल्य राष्ट्रीय उत्पाद का बहुत बड़ा भाग खर्च किया जाता रहा है। 1953 में राष्ट्रीय उत्पाद का 14.5% सैनिक कार्यों पर व्यय हुआ। 1953 के बाद लेकिन इसमें कमी आई जब सेना की संख्या घटाकर आधी कर दी गई थी। 58 लाख से 30 लाख की कटौती की गई। अब सैनिक व्यय का भार कुल राष्ट्रीय उत्पाद का लगभग 12% है। यह व्यय भी अमरीका में सैनिक व्यय के भार की तुलना में 25% अधिक है तथा पश्चिमी यूरोप के देशों के व्यय की तुलना में तो तीन गुना अधिक है। यह विशाल सैनिक व्यय सोवियत संघ के आर्थिक विकास को कुछ हद तक सीमित करने वाला तत्त्व (constraint) रहा है। विशेष रूप से हल्के उद्योगों तथा उपभोक्ताओं को इसका नुकसान उठाना पड़ा है।

6 विदेश व्यापार

विदेश व्यापार के क्षेत्र में भी सोवियत अर्थव्यवस्था को अधिकाधिक उदार बनाया जा रहा है। इस नीति के बाद में निर्यातों में मूल्यों में 9% से भी अधिक तक की वार्षिक वृद्धि हो रही है। व्यापार अभी भी अन्य साम्यवादी देशों पर अधिक

केन्द्रित है। लेकिन सोवियत संघ बाहरी दुनिया के देशों के साथ भी अब अपना व्यापार काफी बढ़ा रहा है। पिछली अमरुक्षा की भावनाएँ अब समाप्त हो चुकी हैं। उमका विदेश व्यापार, कुल राष्ट्रीय उत्पाद के सापेक्ष में, अब उतना ही है जितना अमरीका का। सोवियत संघ के सामने पूँजीगत वस्तुओं के निर्यात तथा साद्य-पदार्थों एवं बच्चे मालों के आयातों की अच्छी सम्भावनाएँ हैं।

7. कृषि में परिवर्तन

सोवियत संघ में सर्वाधिक कुशल खेत वे निजी टुकड़े हैं जो सामूहिक व राजकीय कृषकों को व उनके परिवारों को दिये गये हैं। इन भू-खण्डों का आकार $\frac{1}{2}$ से $\frac{1}{4}$ हैक्टेयर है और ये कुल कृषित क्षेत्र का मात्र 3 प्रतिशत हैं। किन्तु ये 1965 में सोवियत संघ में 40 प्रतिशत मांस उत्पादन, 39 प्रतिशत दूध उत्पादन, 67 प्रतिशत अण्डों, 41 प्रतिशत सब्जियों तथा 63 प्रतिशत आलुओं (कुल उत्पादन के प्रतिशत के रूप में) के उत्पादन के लिए उत्तरदायी थे। किन्तु इन निजी भू-खण्डों की अच्छी कार्य-कुशलता से इनका आकार बढ़ने की कोई गुंजायश नहीं लगती। लेकिन कृषि-उत्पादन को बढ़ाने के लिए ऊँचे मूल्यों व मजदूरी-दरों का अभिप्रेरकों के रूप में व्यापक उपयोग किया जाने लगा है।

सोवियत अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन¹

यह सत्य है कि 1917 से पहले रूसी साम्राज्य बहुत कम विकसित था, वह एक कृषि प्रधान देश ही था और इसनिये एक ऐसे देश का शक्तिशाली औद्योगिक राष्ट्र के रूप में काया-पलट हो जाना स्वाभाविक रूप से आज के विकासोन्मुख देशों के लिए अध्ययन का एक रोचक विषय है। प्रो० अलेक नोव (Alec Nove) के शब्दों में, 'सोवियत रूस को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में देखा जाता है और वह सही भी है, जो अपने ही प्रयासों से जागे बढ़कर सामने आया है तथा अपना औद्योगीकरण भी जिसने अपने ही प्रयत्नों से किया है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पश्चिमी देशों की माख तथा मशीनों ने सहायता की किन्तु यह भी तथ्य झुठलाया नहीं जा सकता कि सोवियत विकास का मॉडल एक ऐसा मॉडल है जिसमें स्वामित्व मजबूती से राज्य के हाथों में रहा तथा विदेशी उपक्रमों या विनियोगों ने बहुत सीमित भूमिका निभायी। अकुशलताएँ, बर्तमान, सरकार की जोर जबरदस्तियाँ तथा सामूहिकीकरण की असफलता आदि के लिए काफी आलोचनाएँ की जा सकती हैं किन्तु ये सब भी सीखने की सागते ही थी। जहाँ तक सरकार द्वारा किये गये दमन का प्रश्न है, कौन से देश में औद्योगीकरण जनता की पूर्वानुमति लेकर किया गया है? क्या किसी ने ब्रिटिश अनसह्यता से पूछा था कि वह औद्योगिक क्रान्ति चाहती है अथवा नहीं?'

‘अन्त में सकेन्द्रित योजनाएँ बनाने के क्षेत्र में सोवियत अनुभव उन सभी के लिए काम की चीज है जो अपने यहाँ औद्योगिक विकास का आयोजन करना चाहते

हैं। भारत ने अपने यहाँ नियोजित विकास का कार्यक्रम शुरू करने में रूस से बहुत कुछ सीखा है। एक सोवियत विशेषज्ञ शेमलेव ने कहा था 'समाजवादी देशों का विकास कार्यक्रम एक वाँटो भरे रास्ते से गुजरा था तथा बड़े चीजे केवल व्यावहारिक अनुभव की प्रक्रिया में जाकर ही स्पष्ट हो पायीं। दूसरे शब्दों में, शेमलेव यही कहना चाहता था कि 'हमारी गलतियों से सीखो।'

दूसरे देशों ने सोवियत अनुभव से काफी कुछ सीखा है उनके यहाँ मूल्य सयन की सीमित भूमिका तथा उनके विनियोग मानदण्डों की जटिलता को अधिक अच्छी तरह समझने की आवश्यकता है।

वास्तव में, जैसा कि गुनार मिडल (Gunnar Myrdal) ने लिखा है 'आर्थिक प्रक्रिया का एक बहुत बड़ा भाग' लागतो, मूल्यों, लाभ की दरो बादि को, जो मूल्य व्यवस्था के भीतर सकार्यशील होते हैं, निर्देशित करने के लिए अनेक परिवर्तन करने होने हैं।' यहाँ तक कि एकदम अविवेकपूर्ण राजनीति से प्रेरित आर्थिक आन्दोलनों (पिछले कुछ वर्षों में इनमें सबसे महत्वपूर्ण निकिता ख्रुश्चेव द्वारा चलाया गया अछूती भूमि आन्दोलन था, जिसके लिए ब्रेजनेव ने 1978 में प्रकाशित अपनी जीवनी में उसकी आलोचना की है) ने भी लोगों के गतिशीलन में तथा उन्हें लक्ष्य तक ले जाने में अपनी भूमिका निभायी है। यह सही है कि कभी-कभी सोवियत योजनाएँ व्यावहारिक होती हैं, अधिकांश अवसरों पर उनके लक्ष्य अधूरे रह जाते हैं, किन्तु वे सकार्यशील (operational) हैं। उनके महान् विनियोग कार्यक्रम नियम से पूरे होते हैं चाहे वे निर्धारित तिथि से कुछ समय बाद क्यों न पूरे होने हों।

पश्चिमी देशों में भी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ससाधनों को युद्ध कार्यों के लिए सकेन्द्रित करने के उद्देश्य से केन्द्रीय नियोजन अपनाया गया था। ऐसा किये जाने से अर्थव्यवस्थाओं में बड़े दृष्टिमूलक विसंगतियाँ एवं विवेकहीनताएँ भी पैदा हो गयी थी किन्तु उस समय वहाँ भी किसी ने यह तर्क नहीं दिया कि युद्ध की सामग्री बाजार तन्त्र से चिपके रहकर ही जुटायी जानी चाहिए। सोवियत अर्थव्यवस्था को युद्ध अर्थव्यवस्था (war economy) के साथ समता काफी युक्ति-युक्त है। ऑस्कर लांगे (Oskar Lange) ने एक बार सोवियत अर्थव्यवस्था को शाश्वत युद्ध अर्थव्यवस्था (perpetual war economy) कहा था। बेगामिन हिगिंग, एक प्रसिद्ध विकास अर्थशास्त्री ने लिखा कि 'सम्पूर्ण युद्ध में, गरीब एवं जड़प्राय अर्थव्यवस्थाओं के लिए विकास हेतु किये जाने वाले आयोजन की तरह ही, कई सरचनान्मक एवं बिखरे बिखरे परिवर्तन करने होते हैं तथा साधन आवंटित किये जाते हैं किन्तु स्वतन्त्र बाजार से उनकी अनुमति नहीं सी जाती।' उसने आगे लिखा है, 'और न ही ये वाढ़ियाँ समायोजन सीमान्त होते हैं। इन देशों में तो स्वयं विवास का ही संचालन करना पड़ता है। इनके लिए क्षेत्रवार नियोजन आवश्यक है। विभिन्न दरे—जिनके आधार पर भारी उद्योग, हल्के उद्योग, कृषि में सुधार, यातायात एवं मवेशिवाहन का विवास, आवाग की व्यवस्था आदि आगे बढ़ाये जाने होते हैं, भी जागरूक नीतियों का भाग बन जाते हैं। इस प्रकार के आयोजन में गणनाएँ करनी होती हैं, जिनमें

लाभ-लागत तुलनाएँ सम्मिलित होती है, किन्तु ये गणनाएँ भी अब शुद्ध सीमान्त गणनाएँ नहीं रह गयी हैं।' हिंमंस द्वारा व्यक्त किये गये ये विचार सोवियत व्यवस्था के अध्ययन पर आधारित नहीं हैं किन्तु वे यह तथ्य उजागर कर देते हैं कि सोवियत रूस भी एक विकासोन्मुख देश रह चुका है तथा उसके भाग में भी वे सारी समस्याएँ आयी हैं जो ऐसे देशों के लिए सामान्य होती हैं।

यह सारा तर्क, नोव (Nove) ने लिखा है, कोई चिकनी-चुपड़ी माफी नहीं समझा जाना चाहिए। उसके अनुसार, 'सोवियत आर्थिक इतिहास भीषण अपव्ययी, ज्यादातियों, अपराधों (जैसे कि जबरन सामूहिकीकरण) से भरा पड़ा है तथा यह कहना एकदम अनैतिक होगा कि ये डेर सारी गलतियाँ या दबाव किसी न किसी रूप में आवश्यक थे और न ही उन्हें वाद की उपलब्धियों या विकास के आँकड़े दिखाकर न्यायोचित ठहराया जा सकता है। लेकिन इस तथ्य को समझना भी आवश्यक है कि सोवियत व्यवस्था एक ऐतिहासिक विकास सन्दर्भ में उभरी जिसमें जारशाही द्वारा शुरू औद्योगिकीकरण को आगे बढ़ाया गया। साथ ही यह अनुभव विवासोन्मुख राष्ट्रों के लिए न केवल विशेष रुचि का है बल्कि आर्थिक विकास की कथनी और करनी का यह लेखा-जोखा हमें सोवियत रूस की समस्याओं व उसके आर्थिक इतिहास को अधिक अच्छी तरह समझने का अवसर प्रदान करता है।'।

मुख्य कमजोरियाँ व उनके निदान

सोवियत आर्थिक प्रणाली की अधिकांश कमजोरियाँ उसके 'सकेन्द्रण के पैमाने की अमितव्ययिताओं' (diseconomies of centralised scale) से सम्बन्ध रखती हैं। एक ऐसे मॉडल में जहाँ राज्य, समाज की तरफ से, यह निश्चित करता हो कि किस चीज की आवश्यकता है, क्या उत्पादन किया जाना चाहिए तथा कैसे और किसके लिए किया जाना चाहिए, वहाँ निर्णय लेने तथा जानकारी की छटनी करने का काम इतना बड़ जाता है कि वह केन्द्र की क्षमता के बाहर हो जाता है। इस आधारभूत तथ्य को किसी भी सीमा तक पुनर्गठन करके बदला नहीं जा सकता। इनके दो परिणाम अवश्यम्भावी होते हैं जिन्हें सोवियत प्रणाली में भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है—केन्द्र स्वयं विभक्त हो जाता है (इसी विचार को अब 'सकेन्द्रित बहुलवाद' (Centralised Pluralism) का नाम दिया गया है), तथा बहुत बड़ी सहाय में निर्णय, प्रतिष्ठानों व अन्य स्थानों पर, मातहत (subordinate) कर्मचारियों के क्रियाकलापों पर अग्रिम हो जाते हैं। गुणस्तर (assessments in quality), नयी डिजाइने तैयार करना आदि स्थानीय एवं मध्यवर्ती प्रबन्ध पर निर्भर करते हैं। लेकिन उन्हें ऊपर से प्राप्त अधूरे और समय आवेशों के आधार पर काम करना पड़ता है। उत्तरदायी या प्रभारी व्यक्ति का भ्रम और भी बड़ जाता है जब पार्टी के संगठन भी हस्तक्षेप शुरू कर देते हैं तथा उनके व मन्त्रानुयों के बीच भी सम्पर्क एकरूप नहीं रह पाता। एक ऐसी मूल्य प्रणाली, जो उपलब्धियों के मूल्यांकन तथा व्यय पर नियन्त्रण को आसान बनाने के लिए तैयार की हुई है, योजना बनाने वालों को वांछित सूचनाएँ उपलब्ध नहीं करा सकती। यहाँ तक कि

अभिप्रेरक व्यवस्था (incentive system) भी कई बार बड़े विरोधी परिणाम प्रस्तुत करती है। प्रो० नोब ने लिखा है कि 'ऐसे सफलता सूचक तैयार कर पाना असम्भव हो चुका है जो उन कार्यों को उत्तेजित कर सके व पुरस्कृत करने के काम आ सकें जिन कार्यों को पार्टी या योजनाकार चाहते हैं किन्तु जिन्हें सकार्यशीलता की दृष्टि से (operationally) वे परिभाषित करने में सक्षम नहीं हैं।'।

मकेन्द्रण की समस्या एक अन्य समस्या के साथ जुड़ी हुई है, वह है सूचनाओं के प्रवाह पर सेंसर (censor)। स्टालिन युग में कई हानियाँ केवल भय से हुईं। ऊपर से आने वाले किसी प्रस्ताव के बारे में प्रश्न नहीं किया जा सकता था। अब ऐसा नहीं है। किन्तु अभी भी 'केन्द्रीय प्रतिबन्धों व सूचना प्रणाली में हेरा-फेरी करने' के उदाहरण हैं।

पार्टी के सदस्यों द्वारा अत्यधिक हस्तक्षेप एक अलग ही समस्या है। पार्टी के वरिष्ठ सदस्य अर्थव्यवस्था की इस तकनीकी क्रान्ति के युग में भरपूर कार्यकुशलता के साथ-साथ आर्थिक प्रबन्ध के प्रत्येक स्तर पर नियुक्तियों आदि पर अपना पूर्ण नियन्त्रण भी चाहते हैं। पार्टी के ये सदस्य सूचनाओं के प्रवाह (flow of information), प्रसारण माध्यमों तथा पुरस्कार वितरण व उसकी राशि पर भी अपना नियन्त्रण रखते हैं। व्यवस्था में सुधार करने के मार्ग में यह एक बड़ी बाधा है। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि बाजार मयन्त्रण (market mechanism) की कोई सीमाएँ हैं ही नहीं। दीर्घकालीन विनियोग निर्णयों के सम्बन्ध में मूल्यों की अपनी कमियाँ रहती हैं। बाजार शक्तियों के कुछ सकारात्मक तो कुछ नकारात्मक प्रभाव होते हैं। ये नकारात्मक प्रभाव बेरोजगारी, एक ही काम के दुहरेपन तथा आय की असमानताओं के रूप में परिलक्षित होते हैं।

ब्रुस (Brus) ने एक मध्य मार्ग सुझाया है। उसका कहना है कि 'नियोजित अर्थव्यवस्था का एक ऐसा मॉडल जो नियमित (regulated) बाजार मयन्त्रण का उपयोग करता हो' एक व्यावहारिक निदान है। उसमें 'आधारभूत समष्टि आर्थिक निर्णयों' तथा 'चालू सकार्य समस्याओं' के बीच भेद किया है। इस तरह चालू उत्पादन तथा उपयोग सम्बन्धी निर्णय बाजार मयन्त्रण पर आधारित होने चाहिए जिन पर केन्द्र कुछ नियम लागू करके नियन्त्रण कर सकता है।

अवधारणाओं की समस्या उत्पन्न हो जाती है जब सोवियत व्यवस्था का नकारात्मक या सकारात्मक पहलू से मूल्यांकन करने की चेष्टा की जाती है। हो सकता है, जैसा कि सोवियत संघ का दावा है, वहाँ कोई बेकारी न हो और न ही उससे पैदा होने वाले कष्ट हों। किन्तु वह तकतीफो, वितम्बों तथा कूड़ाओं से श्रुत है जब उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण का प्रश्न आता है। हर जगह लगने वाली लम्बी लाइनें (queue) इसका प्रमाण देते हैं। ये नकारात्मक व सकारात्मक पहलू सिर्फं संयोगवश ही सम्बद्ध हैं। तो फिर यदि पश्चिमी देशों में बेकारी है, किन्तु वितरण व्यवस्था अच्छी है तो इनमें से 'श्रेष्ठ' कौन-सी व्यवस्था हुई? इसका मापदण्ड क्या हो?

इसके बावजूद हम सोवियत प्रणाली को उसकी दुर्बलताओं व दृढ़ताओं के

आधार पर तोल सकते हैं। साथ ही हमें उनकी क्षमता को भी ध्यान में रखना होगा। यदि कमियों का निदान सम्भव है तो सुधार की गुंजाइश रहती है।

सकेन्द्रित योजनाओं में बड़े पैमाने पर विनियोग कम अनिश्चित होते हैं और यह एक सकारात्मक विन्दु है। किन्तु जो बात ध्यान देने योग्य है वह यह है कि भविष्य के बारे में जानकारी की कमी, न कि कीमतों व प्रतिफल दरों के बारे में गणनाएँ, सोवियत व्यवस्था में विशिष्ट अपव्ययों (conspicuous wastes) का स्रोत है। यह सही है कि विनियोग की मात्रा विनियोग वस्तुओं के उत्पादन कार्यक्रम के सन्दर्भ में समायोजित की जा सकती है, किन्तु ऐसा होता नहीं है। विनियोग आयोजन तथा पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन की योजनाओं में समन्वय दोषपूर्ण रहे है।

क्योंकि सोवियत संघ में प्राथमिकताओं का निर्धारण भी केन्द्रीय स्तर पर होता है इसलिए ससाधनों को एक ही उद्देश्य जैसे प्रतिरक्षा पर केन्द्रित किया जा सकता है। स्वाभाविक रूप से कार्य करने वाली वाज़ार शक्तियाँ वैसा कभी नहीं करेंगी। सापेक्ष आय पर नियन्त्रण लोगों को ऐसे क्षेत्रों में जाने से स्वयं ही रोक देता है जिन्हें कम महत्वपूर्ण समझा जाता है जैसे प्रचार का काम, स्टॉक मार्केट आदि। चूंकि मूल्यो तथा आमदनियों पर नियन्त्रण सोवियत संघ में पश्चिम के मुकाबले अधिक प्रभावकारी है इसलिए सामाजिक सघर्षों को अधिक सफलतापूर्वक हल किया जा सकता है या जैसा कुछ लोग कहते हैं, दबाया जा सकता है।

अब हम सोवियत आर्थिक प्रणाली की कुछ कमियों पर भी नज़र दौड़ा सकते हैं। इनमें से अधिकांश कमियाँ समष्टि आर्थिक स्तर पर देखने को मिलती हैं। मुख्य समस्या क्षेत्र उत्पादन की किस्म, नव-प्रवर्तन, पहल, दीर्घकालीन उत्तरदायित्व, भ्रामक मूल्य तथा चयन का अभाव से सम्बन्धित हैं। नोब द्वारा लिखित 'ये कमियाँ व्यवस्थागत (systemic) हैं जो केन्द्रीकृत निर्देशात्मक आयोजन प्रणाली के मूल विचार में गहरी घँसी हुई हैं।' इनके लिए कोई आसान या आसिक समाधान नहीं है। ये कमियाँ उत्पादकता पर विपरीत प्रभाव डालती हैं, अकुशलता को जन्म देती हैं, गतत आबटनों, विसंगतियों तथा अभिप्रेरणाओं से भ्रामक परिणामों की प्राप्ति का निमित्त बनती हैं। सोवियत संघ के उच्च नेता इन कमियों से अपरिचिन नहीं हैं किन्तु वे भी इस बारे में कुछ भी कर सकने में असहाय हैं। अधिक कार्यकुशलता तथा ऊँची किस्म के बारे में बात करने में कोई कठिनाई नहीं है किन्तु उन्हें उतनी आसानी से लागू नहीं किया जा सकता। नोब के अनुसार, 'व्यष्टि अर्थशास्त्र के सामान्य क्षेत्र में पश्चिम की श्रेष्ठता निर्विवाद लगती है। सकेन्द्रण से पैमाने की भारी अभितय्ययिताएँ उत्पन्न होती हैं।'।

इसके अतिरिक्त पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं व सोवियत अर्थव्यवस्था का अपनी गलतियों को सुधारने का तरीका भी अलग है। एक अमरीकी निगम के अधिकारी ने कहा था कि 'एक चीज़ जो योजनाओं के बारे में निश्चय से कही जा सकती है वह यह है कि गलतियाँ तो होगी ही।' सुधार या संशोधन का काम कितनी जल्दी होता है यह इस पर निर्भर करता है कि निर्णय लेने वाले के पास सूचना अब तक पहुँचती है। इस बारे में सोवियत अनुभव अलग ही तरीके का है। ऐसे विचार

जिनसे यह प्रकट होना हो कि राज्य या पार्टी या निर्णय त्रुटिपूर्ण था या तो हतोत्साहित लिये जाते हैं या फिर आगे नहीं पहुँचने दिये जाते। गलतियाँ या कुप्रबन्ध पश्चिम में भी कोई असामान्य बात नहीं है किन्तु स्वतन्त्र अर्थव्यवस्था में उनके लिये दण्ड की सम्भावनाएँ काफी हैं।

जब कोई आघात (shocks) लगता है तो दोनों अर्थव्यवस्थाओं की प्रतिक्रिया भिन्न रहती है। जब 1973 में तेल मूल्यों में अचानक वृद्धि हुई और वे चौगुने हो गये तो प्रभावित पश्चिमी देशों ने ईंधन बचाने के अभियान छेड़े तथा वैकल्पिक ईंधन पर विनियोग बढ़ा दिये। किन्तु सोवियत संघ में तेल मूल्य अपरिवर्तित ही रहे। जैसे कुछ हुआ ही न हो। किन्तु सोवियत आयोगों ने यह महसूस कर लिया कि पश्चिमी देशों को तेल बेच कर नकद मुद्रा कमा सकते हैं। इसीलिए दसवी योजना में ईंधन के लिए प्रयुक्त किये जाने वाले तेल में कटौती कर दी गई। जैसा कि पहले भी लिखा जा चुका है, सोवियत पद्धति वाली अर्थव्यवस्था ऐसे प्रश्नों पर अधिक ध्यान दे सकती है जो केन्द्र द्वारा निपटाये जाने हों। यही कारण है कि सोवियत संघ एक दीर्घकालीन ईंधन नीति बनाने में सफल रहा है।

व्यष्टि-आर्थिक मामलों में ही सोवियत कठिनाइयाँ जमा होती रहती हैं। उनके कानून बड़े अदूरदर्शी होते हैं क्योंकि उन्हें चालू योजना के लक्ष्यों को पूरा करना होता है। एक नियन्त्रित मूल्य व्यवस्था के कारण सही माँग की खबर हो ही नहीं पाती। किन्तु यह बात ध्यान में रखनी होगी कि इन कमियों से सोवियत प्रणाली घटिया नहीं बन जाती। वास्तव में उत्पादन तथा अपव्यय दोनों ही के लिए आज की तेजी से बदलती हुई दुनिया में बदल रही परिभाषाओं के सन्दर्भ में सोवियत प्रणाली की तुलनात्मक प्रभावशीलता या अभावशीलता को माप सकना असम्भव-सा है। यह निर्णय करना पाठक पर छोड़ दिया गया है।

तथ्य और आंकड़े*

सारणी 1

जनसंख्या का आकार, जन्म दर, मृत्यु दर तथा सोवियत संघ में
स्वाभाविक वृद्धि दर

वर्ष	कुल जनसंख्या (मिलियन में)	प्रति 1000 जनसंख्या पर		प्रति 1000 जनसंख्या पर		
		ग्रामीण	शहरी	जन्म	मृत्यु	स्वाभाविक वृद्धि
1897	124.5	106.2	18.4	50	32	18
1913	159.1	130.7	28.5	46	29	17
1926	147.0	120.7	26.3	44	20	24
1940	196.7	131.8	64.9	31	18	13
1950	181.6	108.6	73.0	27	10	17
1960	216.2	107.9	108.3	25	7	18
1970	241.7	105.7	136.0	17	8	9
1972	246.3	103.8	142.5	18	8	10

सारणी 2

रूस में जनसंख्या की सामाजिक संरचना

	(प्रतिशत में)			
	1913	1928	1939	1974
फैक्ट्री व आफिस कर्मचारी	17	17.6	50.2	81.3
सामूहिक फार्म कृषक	—	2.9	47.2	18.7
व्यक्तिगत कृषक व कारीगर	66.7	74.9	2.6	0.0
भूस्वामी, व्यवसायी आदि	16.3	4.6	—	—
कुल जनसंख्या	100	100	100	100

*The Soviet Planned Economy, Progress Publishers, Moscow, 1974,

सारणी 3

विनियोग तथा स्थायी परिसम्पत् की स्थापना, आर्थिक
विकास की प्रमुख अवस्थाओं में

('000 मिलियन रुबल में)

		कुल विनियोग	कुल स्थापित स्थायी परिसम्पत्
1918-28		4.4	3.9
प्रथम योजना	(1929-32)	8.8	9.4
द्वितीय योजना	(1953-37)	19.9	17.4
तीसरी योजना के साढ़े तीन वर्ष	(1938-41)	20.6	18.6
1 जुलाई, 1941 से 1 जनवरी 1946		20.8	19.1
चौथी योजना	(1946-50)	48.1	42.8
पाँचवी योजना	(1951-55)	91.1	81.1
छठी योजना	(1956-60)	170.5	158.0
सातवी योजना	(1961-65)	247.6	231.9
आठवी योजना	(1966-70)	353.8	324.4

सारणी 4

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत विदेश व्यापार का विकास

(मिलियन रुबल में, बालू मूल्यों पर)

	1946	1950	1960	1970	1973
कुल विदेश व्यापार					
जिनमें से	1,280	2,925	10,073	22,079	31,300
समाजवादी युट	698	2,373	7,371	14,403	18,300
विकासित पूँजीवादी देश	491	440	1,917	4,694	13,000
विकासोन्मुख देश	91	112	785	2,982	

सारणी 5

सोवियत रुस में विद्यार्थियों की संख्या

(मिलियन में)

1914-1915	10.6
1940-1941	47.6
1960-1961	52.7
1970-1971	79.6
1972-1973	80.7

सारणी 6

सोवियत स्वास्थ्य सेवा के प्रमुख सूचक

	1913	1940	1950	1960	1970
फिजीशियनों की					
संख्या ('000)	28	155	265	432	668
प्रति 10,000 जनसंख्या पर					
डॉक्टरों की संख्या	2	8	15	20	28
हॉस्पिटल बेड्स की					
संख्या ('000)	208	791	1,011	1,739	2,663
प्रति 10,000 जनसंख्या					
पर बेड्स की संख्या	13	40	56	80	109

सारणी 7

सोवियत राजकीय बजट

	('000 मिलियन रुबल)				
	1940	1950	1960	1970	1972
कुल प्राप्तियाँ	18 0	42 3	77 1	156 7	175 1
कुल व्यय	17 4	41 3	73 1	154 4	173 2

सारणी 8

सोवियत संघ में महिला जनसंख्या।

	(मिलियन में)	(जनसंख्या का %)
1913	80	50
1940	101	52
1959	115	55
1969	129	54
1974	135	54

सारणी 9

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में औसत मासिक मजदूरी

(रुपये में)

वर्ष	1940	1950	1960	1970	1973
औसत मासिक मजदूरी	33 1	61 2	80 6	122 0	135

जापान का आर्थिक विकास

पहला अध्याय

मेजी पुनर्संस्थापना की पृष्ठभूमि

(MEIJI RESTORATION : BACKGROUND)

जापानी अर्थव्यवस्था का पूर्णरूपेण कायाकल्प तथा उसका असाधारण विकास 1868 में हुई मेजी पुनर्संस्थापना (Meiji Restoration) के बाद प्रारम्भ हुआ। 1868 की यह घटना जापान के आर्थिक इतिहास में विशेष महत्त्व की है क्योंकि यही सदियों पुरानी सामन्तवादी व्यवस्था के उन्मूलन तथा 260 वर्षों से चले आ रहे तोकुगावा वंश (Tokugawa dynasty) के अधिनायकतावादी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए उत्तरदायी थी। जापान के इस कायापलट की गति, जिसके द्वारा वह अर्द्ध-सामन्ती अवस्था से एक आधुनिक पूँजीवादी राज्य बन गया, ने लगभग प्रत्येक आर्थिक इतिहास के पर्यवेक्षक को आश्चर्य में डाल दिया है। पिछले सौ वर्षों के अन्तराल में जापानी अर्थव्यवस्था का यह आधुनिकीकरण और भी विलक्षण प्रतीत होता है क्योंकि उसकी तुलना में पश्चिमी देशों में विकास की प्रक्रिया धीरे-धीरे जमी तथा उसके पीछे सदियों का परिश्रम व उत्पीड़न भी था।

यूरोप में पूँजीवादी तरीके का उत्पादन प्रक्रम मध्य-युग (Middle Ages) से ही आरम्भ हो चुका था। इंग्लैण्ड में तो पूँजीवादी तरीके से उत्पादन की शुरुआत 13वीं तथा 14वीं शताब्दी से ही देखी जा सकती है। सारी व्यवस्था में अत्यधिक समय लगा तथा वह विदेशी व्यापार में वृद्धि के साथ शुरू हुई थी जिसने व्यापारी नियोक्ताओं (Merchant employers) के एक वर्ग को जन्म दिया था। मध्य-युग की समाप्ति पर पश्चिमी यूरोप की प्रमुख विशेषता वहाँ की व्यावसायिक धीनियाँ (Merchant guilds) बन चुकी थी। धीरे-धीरे कुछ नये आर्थिक संगठन भी बने जिन्होंने बैंकिंग तथा व्यवसाय के क्षेत्र में क्रांति ला दी। अन्त में कारखाना प्रणाली (Factory system) आई। इन परिवर्तनों के सहायक परिवर्तन के रूप में बाजारों की व्यापकता, उपनिवेशों का प्रसार, जनसंख्या में वृद्धि और सहरो का विकास तथा स्थल-सेना व नौसेना की बढ़ती हुई आवश्यकताओं का भी उल्लेख करना अनिवार्य हो जाता है। यान्त्रिक आविष्कारों तथा लोहे व कोयले के उपयोग ने भी इस सम्बन्ध में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा तीन सौ से चार सौ वर्षों के अनथक प्रयास के बाद ही ग्रेट ब्रिटेन में कारखानों (factories) को मजदूती के साथ स्थापित किया जा सका था। सम्पूर्ण यूरोप में कारखाना प्रणाली के प्रचार-प्रसार में तो और भी अधिक समय लग गया।

इससे तुलना करने पर तो जापानी आर्थिक कायावरण की कहानी और भी रहस्यपूर्ण लगने लगती है। उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य तक भी जापानी अर्थव्यवस्था एक आदिम या पुरातन कृषि अवस्था में थी। उसके 28 से 30 मिलियन लोगो¹ में अधिकांश लोग या तो दास थे या फिर गरीबी से त्रस्त किसान थे। उनमें से अधिकांश आत्मनिर्भर गांवों में रहते थे। अर्थव्यवस्था का मूलधार तथा उसकी सम्पदा का प्रमुख स्रोत सदियों से अपरिवर्तित तरीकों से की जाने वाली चावल की खेती थी।

इन निराशाजनक परिस्थितियों में जापान का एक महाशक्ति के रूप में उदय² इसी बीच जर्मनी के पुनर्निर्माण की तरह ही 1914 से पिछले 50 वर्षों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन की घटना कही जा सकती है। अनेक पश्चिमी पर्य-वेक्षकों को जापान की आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्र की उपलब्धियाँ इतनी आश्चर्यजनक लगी कि उन्हें उसके पीछे कोई विवेक-सम्मत स्पष्टीकरण भी नहीं दिखाई दिया। इसका परिणाम यह रहा कि कुछ पश्चिमी विचारक तो उन जापानियों के साथ एकमत हो गये जो अपनी नई गौरवपूर्ण स्थिति की प्राप्ति को किसी दैवी शक्ति की कृपा का परिणाम बताते तो कुछ अन्य पश्चिमी लेखकों ने जापान की इस महान् प्रगति को भाग्यशाली घटना-क्रमों (lucky accidents) का परिणाम बताते हुए यह भी लिखा कि बहुत जल्द ही उसकी सामान्यता (mediocrity) का पता चल जायेगा। वैसे देखा जाए तो विशेष रूप से आर्थिक क्षेत्र में जापान के आधुनिक इतिहास की प्रत्येक अवस्था पर महाविनाश एवं पतन की भविष्यवाणियाँ इतनी ज्यादा व प्रभावित करने वाली रही कि उसकी आन्तरिक शक्ति का सही अनुमान (shrewder estimate) तब तक नहीं लग पाया जब तक कि उसने अपने आपको संयुक्त राज्य अमरीका तथा ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध महायुद्ध में नहीं झोक दिया।

तोकुगावा जापान एक अवरुद्ध समाज (Tokugawa Japan A Closed Society)

उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में तथा बीसवीं शताब्दी में जापान द्वारा की गई तीव्र प्रगति को अच्छी तरह समझने के लिए तोकुगावा शासन के अन्तर्गत जापान के इतिहास की जानकारी आवश्यक है। 1853 से पहले जापान एक अलग-थलग पड़े देश की तरह रहा था जिसका बाहरी दुनिया के साथ किसी प्रकार का सम्पर्क नहीं था। तोकुगावा शासकों के शासन-काल में, दो शताब्दियों में भी अधिक समय तक, जापान में विदेशियों के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबन्ध लगा हुआ था। सरकार विदेशों के साथ किसी भी प्रकार के व्यापार की अनुमति नहीं देती थी। इसी तरह तोकुगावा सरकार ने विदेश यात्रा व विदेशों में अध्ययन पर भी रोक लगा रखी थी। सरकार ईसाइयत के प्रसार की भी घोर विरोधी थी तथा तोकुगावा शासकों ने जिस एकमात्र पश्चिमी सम्पर्क को अनुमति दे रखी थी वह डच लोगों द्वारा जापान में स्थापित एक व्यापारिक चौकी थी। चीन जो कि जापान का निकटस्थ पड़ोसी था, के साथ भी

¹ W W Lockwood, *The Economic Development of Japan*, 1968, 3

² G C Allen, *A Short Economic History of Modern Japan*, 1950, 9

जापान के कोई सम्बन्ध नहीं थे। जापानी लोगों को दुनिया से अलग रखने के उद्देश्य से जापानी सरकार 75 टन से अधिक क्षमता वाले जहाजों के निर्माण की भी अनुमति नहीं देती थी।

तोकुगावा लोगों को सत्ता सोलहवीं शताब्दी में लम्बे समय तक चतने वाले गृह-युद्धों से प्राप्त हुई थी। सम्राट एकान्तवास में क्योटो (Kyoto) में रहने लग गया तथा तोकुगावा लोग ही देश के वास्तविक शासनाध्यक्ष बन गये। उन्होंने देश में एक प्रकार की सैनिक तानाशाही कायम कर दी। इस व्यवस्था को बाकुफू (Bakufu) कहा गया। शोगुन (Shogun) या धर्मनिरपेक्ष कहलाने वाले तोकुगावाओं का देश की एक-चौथाई कृषि-योग्य भूमि पर अधिकार था। उन्हें अपनी अधिकांश आय भूमि से ही प्राप्त होती थी। देश की शेष कृषि-योग्य भूमि पर भूस्वामियों या दायम्यो (Daimyo) का अधिकार था जो अपने क्षेत्र पर, जिसे हान (Han) कहा जाता, काफी स्वायत्तता से प्रशासन चलाते थे। दायम्यो तथा शोगुन के कारिंदे (retainers) समुराई (Samurai) के नाम से जाने जाते थे। इस वर्ग के लोग योद्धा (warriors) होते थे जो लड़ाई के समय अपने भूस्वामियों की सेवा में बुला लिये जाते थे। जहाँ समुराई वर्ग के कुछ सदस्यों को काफी अधिक भत्ते आदि मिलते तथा उनके पास प्रशासनिक अधिकार भी काफी मात्रा में होते, वही अधिकांश समुराई वर्ग (Samurai) के सदस्यों को मामूली सा चावल दिया जाता था तथा वे रक्षकों (guards) का काम करते थे। तोकुगावा शासन-काल में आम तौर पर शान्ति बनी रही इसलिये समुराई वर्ग के लोगों को योद्धाओं के रूप में कार्य करने की जरूरत बहुत कम ही पड़ी। धीरे-धीरे ये लोग निष्क्रिय तथा परोपजीवी (functionless and parasitic) के हो गये। उनके परिवारों की संख्या करीब 20 लाख थी तथा वे देश पर एक बहुत बड़ा भार बन गये।

किन्तु यह निष्कर्ष निबालना भी गलत होगा कि तोकुगावा जापान कोई आदिम समाज था। सरकार कार्यकुशल व प्रभावशाली थी। केन्द्रीय सत्ता मजबूत थी तथा कहीं भी महत्वपूर्ण आन्तरिक गड़बड़ियाँ नहीं थी। हालाँकि तोकुगावा जापान के पास इंग्लैंड की तुलना में भी कम उपजाऊ भूमि थी किन्तु वह 35 मिलियन लोगों का भरण-पोषण कर रहा था जोकि ब्रिटेन की तत्कालीन जनसंख्या के 5 गुना थे। वह एक अजीबोगरीब किन्तु परिष्कृत संस्कृति थी। पाश्चात्य जानकारों किसी तरह चिकित्सा एवं विज्ञान के क्षेत्र में पहुँच चुकी थी तथा यह अनुमान लगाया गया है कि उन्नीसवीं सदी के आरम्भ में जापान में पश्चिमी यूरोप की तुलना में अधिक साक्षरता थी।

कृषि पर आधारित तोकुगावा जापान का समाज लगभग 270 क्षेत्रीय स्वामियों (Daimyo) तथा एक पूरे के पूरे योद्धा वर्ग समुराई (Samurai) का भरण-पोषण करता था। दायम्यो लोगों को काफी लम्बे समय से सामन्ती अधिकार प्राप्त थे तथा वे क्योटो में रह रहे सम्राट की केवल नाममात्र की आधीनता स्वीकार करते थे। किन्तु 1603 से, जबसे तोकुगावाओं का सैनिक परिवार सत्ता में आया, वे दायम्यो लोग वास्तव में उसकी ही आधीनता में थे। दायम्यो सरदारों ने शोगुन (शैतूक

तोकुगावा तानाशाह) के साथ मिलकर प्रतिवर्ष किसानों के कुल उत्पादन का 40% कर के रूप में वसूलने की व्यवस्था की हुई थी। शेष बचने वाला खाद्य उत्पादन बाकी बची हुई आबादी का पेट भरने के लिए जैसे-तैसे पूरा पड़ता था। अकाल, महामारियाँ आदि आते रहते थे तथा बच्चों की हत्याएँ (infanticide) भी असामान्य नहीं थी।

दायम्यो तथा समुराई वर्ग के परोपजीवी लोगों के बाद जिस गैर-विशेषाधिकार वाले वर्ग का बहुमत था उसमें किसान लोग आते थे। ये किसान कुल आबादी का 75% थे। उन्हें कई प्रतिबन्धों के अन्तर्गत काम करना पड़ता था। उनकी स्थिति यूरोप के कृषि-दासों (Serfs) जैसी थी। उन्हें अपने खेत छोड़ने तथा शहरों में जाकर बगने की अनुमति नहीं थी। इन किसानों से वार्षिक भूमि-कर के रूप में वसूल किया जाने वाला भुगतान ही शोगुन (Shogun) तथा दायम्यो (Daimyo) की प्रमुख आय थी। यह चावल के रूप में दिया जाता था तथा धान के कुल उत्पादन का 40% से 50% होता था। इस भूमि-लगान के अलावा किसानों का शोषण और भी कई तरीकों से किया जाता था जिसमें उनसे वस्तुओं या सेवाओं के रूप में भुगतान जबरन ले लिये जाते थे। तोकुगावा काल में इन किसानों की सामान्य स्थिति इतनी दयनीय थी कि एक लेखक ई० होजो (E. Honjo) ने तो यहाँ तक लिखा है, 'ऐसा लगता था कि जैसे वे कर देने के उद्देश्य के लिए ही जी रहे हों।' मिचित खेतों में उगाई जाने वाली मुख्य फसल चावल थी। अन्य खाद्य फसलें जैसे गेहूँ, जौ, सोयाबीन, तथा औद्योगिक फसलें जैसे रेशम के कीड़ों के लिए शहतूत की पत्तियाँ, नील तथा कपास भी थोड़ी-थोड़ी मात्रा में उगाये जाते थे। तोकुगावा काल में रेशम के कीड़ों की खेती (Sericulture) में असाधारण प्रगति हुई। इसी तरह कृषि तकनीकों में भी तोकुगावा काल में काफी सुधार हुए जिनसे उत्पादकता में तीव्र गति से वृद्धि हुई।

तोकुगावा शासन के प्रारम्भिक वर्षों में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में एक 'स्वाभाविक या प्राकृतिक अर्थव्यवस्था' (Natural Economy) प्रचलित थी। गाँव आत्मनिर्भर थे। अपने मालिकों (Lords) को वस्तुओं व सेवाओं के रूप में कर चुकाने के बाद किसी तरह किसान लोग अपना गुजारा भी कर लेते थे। सिर्फ कुछ चीजें जैसे नमक, धातु का बना सामान व दवाएँ ही वे बाहर से खरीदते। तोकुगावा शासन के बाद के वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रा के प्रवेश ने ही पुराने सामाजिक व राजनीतिक ढाँचे को तोड़ने की प्रक्रिया आरम्भ की।

क्योटो, येदो तथा ओसाका (Kyoto, Yedo and Osaka) जैसे शहरों में कुछ विशेष प्रकार का निर्मित माल तैयार करने वाले उद्योग भी थे। ये उद्योग मुख्य रूप से विशेषाधिकार प्राप्त दायम्यो या समुराई वर्ग द्वारा की गई माँगों पर निर्भर करते थे। राजधानी एडो (Edo), आधुनिक टोक्यो, की जनसंख्या 1780 में ही 14 लाख पहुँच चुकी थी और उस समय वह शायद विश्व का सबसे घनी आबादी वाला शहर बन चुका था।¹ ओसाका तथा क्योटो भी बड़े शहर थे। मुख्य औद्योगिक वस्तुओं में सूती वस्त्र, ताँबे की बनी चीजें, कागज, छाते, मोमवस्त्रियाँ तथा परम्परागत दवाएँ

¹ H. Rosovsky, *Capital Formation in Japan : 1860-1970*, 66

आती थी। शिल्प व्यवसायों पर यूरोप की श्रेणियों (Guilds) जैसी सस्थाओं का ही नियन्त्रण था।

ये औद्योगिक श्रेणियाँ (Industrial guilds) मूल्यों, उत्पादन की मात्रा तथा वस्तुओं की बिक्री आदि का विनियमन करती थी। उनकी सदस्यता वशानुगत होती थी तथा वह काफी कम थी। ये औद्योगिक श्रेणियाँ तोकुगावा सरकार के एक आदेश द्वारा बहुत पहले ही अर्थात् 1721 में ही मान्यता प्राप्त कर चुकी थी। किन्तु इन श्रेणियों का कार्यक्षेत्र बहुत सीमित था तथा ये मूल रूप से सामन्ती समाज के अधीन कार्य करती थी। इसके अलावा तोकुगावा काल में औद्योगिक गतिविधियाँ इन श्रेणियों तक ही सीमित नहीं थी। किसान तथा गहरी मजदूर भी तैयार माल की विभिन्न वस्तुएँ बनाते थे। जिन्हें वे व्यापारियों को बेच देते और उन व्यापारियों के माध्यम से निर्मित वस्तुएँ उपभोक्ताओं के हाथों में पहुँचती थी। ये व्यापारी मजदूरों को कच्चा माल तथा औजार खरीदने के लिए अग्रिम या पेशगी रकम भी देते थे।

हालांकि कारखाने (factories) तोकुगावा शासन-काल में अज्ञात नहीं थे किन्तु वे बहुत छोटे थे तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका विशेष महत्वपूर्ण नहीं थी। तोकुगावाओं के शासन-काल में औद्योगिक उत्पादों में हस्तशिल्प की बनी हुई वस्तुओं की ही प्रधानता बनी रही। इतना ही नहीं, कारीगरों तथा मजदूरों को घटिया किस्म के लोग माना जाता था। फँट्रियाँ व वाम की जगहे, जहाँ सौ के लगभग मजदूर काम करते, आमतौर पर शोमुन या दायम्यो के ही स्वामित्व व संचालन में होती थी।

इस तथ्य के बावजूद कि तोकुगावा शासन-काल में जापानी अर्थव्यवस्था में आत्मनिर्भरता की प्रवृत्ति प्रधान थी, देश के विभिन्न भागों के बीच व्यापार की मात्रा का परिमाण अत्यधिक व्यापक था। विभिन्न प्रान्तों से राजधानी की ओर विशाल मात्रा में वस्तुओं का प्रवाह होता था। भूस्वामियों के क्षेत्रों में उत्पादित चावल व अन्य उत्पाद बिक्री हेतु एडो तथा ओसाका भेजे जाते। इस प्रक्रिया ने व्यापारियों के एक वर्ग को जन्म दिया जो विभिन्न वित्तीय एवं व्यावसायिक लेन-देन करते थे। यही कारण था कि तोकुगावा काल में भी जापान में एक ऐसी वित्तीय व्यवस्था कायम हो चुकी थी जो एशिया के अन्य देशों को देखते हुए काफी समुन्नत कही जा सकती थी। दोनों बड़े शहरों (Edo, Osaka) में विभिन्न प्रान्तों से बिक्री के लिए लाई जाने वाली वस्तुओं को रखने के लिए बड़े बड़े गोदाम बनाये गये। दायम्यो लोग अपनी भावी आय की जमानत पर भारी मात्रा में धनराशि पहले ही व्यापारियों से लेते रहते थे। इस प्रवृत्ति के परिणामस्वरूप साहूकारों (financiers) के एक वर्ग का जन्म हुआ जो उधार देने का काम करते थे। विनियम विल तथा प्रॉमिसरी नोट की प्रणालियाँ रकम उधार देने के समय वाम में ली जाती थी। तोकुगावा काल में खुदरा व्यापार भी काफी तेजी से विकसित हुआ। इसमें से कुछ किराने की दुकानें तो बड़े पैमाने पर गठित हो गईं। मिस्तुई घराना (House of Mitsui) अठारहवीं सदी के आखिर में अपनी दोक्यो स्थित खुदरा दुकान पर 1,000 आर्दामयों का रोजगार दे रहा था।

आन्तरिक कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से शोगुन ने सड़कों की स्थिति में काफी सुधार करवाया। येदो तथा ओसाका के बीच तटवर्ती व्यापार भी अत्यधिक सुगठित था हालांकि सरकार जापान को दुनिया से अलग-थलग रखने की नीति का अनुसरण करने के कारण बड़े जहाजों के निर्माण की अनुमति नहीं देती थी। यही कारण था कि जापानी तकनीक भी अलग-थलग रह गई। तोकुगावा प्रशासन के पुलिस राज जैसे वातावरण के कारण विदेशी व्यापार का भी विकास अवरुद्ध ही रहा। शोगुनते (Shogunate) अर्थात् तोकुगावा शासक द्वारा लगाये गये विनियमों से विदेशी व्यापार एकदम अपग बन गया। यहाँ तक कि देश के भीतर भी व्यापार एवं आवागमन पर प्रतिबन्ध लगे हुए थे। 1641 के बाद, पृथक्तावादी नीति का अनुसरण करने के कारण, जापान व बाहरी विश्व के बीच व्यापार इतना प्रतिबन्धित था कि केवल चीनी लोग नागासाकी में तथा डच लोग देशिमा (Deshima) में बहुत थोड़ी मात्रा में विदेशी व्यापार कर सकते थे। इस प्रकार के व्यापार की संरचना तथा मात्रा पर भी बड़े प्रतिबन्ध थे। कच्ची रेशम प्रमुख आयात था जिसके बदले में सोने का भुगतान किया जाता था। यह भी एक कारण था जिसकी वजह से सरकार विदेशी व्यापार को हतोत्साहित करती थी। विदेशी व्यापार का अर्थ था बहुमूल्य धातुओं के भण्डारों में कमी।

तोकुगावा शासकों द्वारा अपनाई गई पृथक्तावाद की नीति (Policy of Seclusion) का प्रमुख उद्देश्य उनकी राजनीतिक व्यवस्था को अक्षुण्ण बनाये रखना था। उन्होंने यूरोपीय पुस्तकों का जापानी में अनुवाद करने की भी अनुमति नहीं दी। कुछ दायम्यो लोगों द्वारा इस प्रकार के प्रतिबन्धों से बचने की चेष्टाएँ भी की गईं किन्तु कुल मिलाकर तोकुगावा शासन-काल में पृथक्तावादी नीति अच्छी तरह लागू रही। आर्थिक जीवन पर कठोर नियन्त्रण कई असह्य एवं दमनकारी कानूनों द्वारा और भी बुरे बना दिये गये। किसानों को अक्कर एक पूर्व-निर्धारित फसल बोने के लिए बाध्य किया जाता। लोगों के लिए अपनी सामाजिक स्थिति बदलना असम्भव था। सिर्फ सन्तान व्यक्ति ही समुराई वर्ग में शादी इत्यादि (अपने धन के बल पर) करके उसमें प्रवेश पा सकते थे। सरकार ने विभिन्न जातियों व वर्गों के पहनावे तक तय कर रखे थे। केवल समुराई लोगों को ही तलवार लेकर चलने का अधिकार था। ये लोग अपनी तलवारों का उपयोग उन लोगों या व्यापारियों को डराने-धमकाने में खूब करते थे जिनसे कि वे धन उधार लेते थे। हर्बर्ट नॉर्मन ने लिखा है कि 'यह बाद का सामन्तवाद समाज को एक श्रेणीबद्ध संघे में जमाये रखने का इतिहास में किया गया सर्वाधिक जागरूक प्रयास था।'

तोकुगावा शासन के ढहने के कारण

(1) भारी ऋणप्रस्तता—तोकुगावा काल के उत्तरार्द्ध में सामाजिक एवं आर्थिक प्रणाली बिखर जाने के कारण पर आ खड़ी हुई थी। शोगुन (तोकुगावा शासक) को हर थोड़े समय बाद वित्तीय कठिनाइयों का मुकाबला करना पड़ रहा था। दायम्यो (भूस्वामी) लोग व्यापारियों के भारी मात्रा में कर्जदार बन चुके थे

तथा वे अपने अंगरक्षकों का कार्य करने वाले समुराई लोगों को उनके लिए निर्धारित चावल का भुगतान करने की स्थिति में भी नहीं रह गये थे।

(2) समुराई वर्ग की अनिष्ठा (Disloyalty)—समुराई लोग इतने अधिबन्धित हो चुके थे कि वे लोग शहरो में जाकर बस गये तथा वही नौकरी करने लग गये। उनमें से कुछ डाकु बन गये या सड़कों पर लूटमार मचाने लग गये। शोगुन तथा कुछ अधिक शक्तिशाली दायम्यो सरदारों के बीच प्रतिद्वन्द्विता भी खुलकर सामने आने लगी।

(3) विदेशियों का हस्तक्षेप—इस बात से असहमत हुआ जा सकता है कि जापान के बन्दरगाहों का जबरन खुलवाया जाना ही तोकुगावा शासन के पतन का प्रमुख कारण रहा, किन्तु इस बारे में कोई सन्देह नहीं हो सकता कि उसका इस पतन में बड़ा योग रहा। 1853 में अंगरीकी नौसेना अपनी गनबोटों (Gunboats) की सहायता से जापानी बन्दरगाहों में बलात् प्रवेश कर गई। यह आक्रमण धीरे-धीरे और भी बड़ा बन गया। 1858 में तोकुगावा शासकों को एक व्यापारिक सन्धि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होना पड़ा जिसमें विदेशी नागरिकों, फ्रांसीसियों तथा अन्य राष्ट्रीयताओं वालों को जापान के साथ व्यापार करने के अधिकार प्राप्त हो गये। विदेशियों के लिए गैर बन्दरगाह खोल दिये गये। पश्चिमी देशों की नौसेना की शक्ति तब प्रदर्शित हुई जब 1863 व 1864 में उसने विदेशियों के प्रवेश का विरोध करने वाले दो शहरो पर गोले बरसाये। इस विदेशी आक्रमण ने तोकुगावा शासन की कमजोरी की पोल खोल दी तथा परिवर्तन की आवश्यकता को भी स्पष्ट कर दिया। मगर कुछ लेखकों का मत है कि इस विदेशी आक्रमण ने केवल तोकुगावा शासन के पतन को अधिक शीघ्रतापूर्वक करने का ही काम किया। डब्लू० ई० ग्रिफ़्स ने लिखा है कि 'विदेशी लोग तथा उनके विचार केवल एक अवसर ही थे कारण नहीं जिनसे दोहरे शासन का भेद खुला। उनकी उपस्थिति ने उस पतन को शीघ्रता प्रदान की जो अवश्यम्भावी था वास्तविक कारण देश के भीतर ही कही था, वह बाहर से नहीं आया था।'

(4) बुद्धिजीवियों द्वारा विरोध—चीन में मिंग वंश (Ming Dynasty) का पतन हो जाने के कारण कई चीनी विद्वान् जापान में शरण लेने आये तथा उन्होंने प्राचीन जापानी इतिहास व साहित्य की ओर जापानियों का ध्यान खींचा। इससे उन कालों को गौरवान्वित किया गया जब शोगुन नहीं बल्कि सम्राट (Emperor) देश का वास्तविक शासक था। जब शोगुन को विदेशियों के साथ समझौता करने के लिए बाध्य होना पड़ा तथा ऐसा करते समय उसने जापान व उसके सम्राट को असभ्य (barbarians) लोगों के सामने बलि पर चढ़ा दिया तो देशभक्ति की दुहाई देकर बुद्धिजीवियों ने सरकार बदलने की पुरजोर माँग की। अठारहवीं सदी में डच भाषा के माध्यम से जापानी बुद्धिजीवी पश्चिमी विज्ञानों (खगोल-शास्त्र, शरीर-विज्ञान, चिकित्सा व सैनिक विद्याशास्त्र आदि) के बारे में काफी कुछ सीख चुके थे। इस तरह पश्चिम द्वारा इन वर्षों में की गई भौतिक प्रगति के बारे में वे अब विस्मृत भी अनुभूति नहीं रह गये थे। उनके इस ज्ञान ने उन्हें पुराने तरीके से

चलाई जा रही तोकुगावा सरकार का और भी बटु आलोचक बना दिया। उन्होंने पश्चिमी राष्ट्रों की बढ़ती हुई शक्ति से जापान को पैदा हुए खतरो का भी अनुमान लगा लिया।

(5) आर्थिक कठिनाइयाँ—अनेक लेखकों ने लिखा है कि 'परिवर्तन में आर्थिक कारण गम्भीर, शायद सर्वाधिक अग्रणी, कारण थे।' 1867 से पहले भारी मात्रा में आर्थिक विमृश्वयता पैदा हो चुकी थी। तोकुगावा शासन वित्तीय कठिनाइयाँ बढ़ जाने तथा आर्थिक एवं सामाजिक स्तर पर अन्य अनेक परिवर्तन आ जाने के कारण पहले ही बुरी तरह हिल चुका था। प्रथम तोकुगावा शासक द्वारा विशाल मात्रा में जमा किया गया खजाना 17वीं सदी के उत्तरार्द्ध तक समाप्त हो चुका था। अगली शताब्दी में आर्थिक एवं वित्तीय स्थायित्व बनाय रखने के प्रयास सफल नहीं हुए थे। विदेशी व्यापार के पूर्ण अभाव के कारण तोकुगावा शासक अपनी आय किसानों द्वारा चावल के रूप में चुकाये जाने वाले कर तथा व्यापारियों पर लगाये गये कुछ अन्य करों में ही प्राप्त करते थे। किन्तु ये कर भी भ्रष्ट प्रशासन के कारण कभी भी पूरी तरह वसूल नहीं हो पाते थे। उधर भूमि पर करों की दर ऊँची होने के कारण किसान खेती का छोड़कर शहरों में जाकर बसने लगे थे।

वित्तीय विपत्ति ने, जो उत्तरोत्तर आने वाली सरकारों के सामने गम्भीर होती चली गई, जापानी मान्य मौद्रिक इकाई की न्य शक्ति इतनी घटा दी थी कि वह 19वीं शताब्दी के मध्य तक 1661 की तुलना में आठवाँ भाग रह गई। उधर विदेशी आक्रमणों ने सरकार को प्रतिरक्षा पर भी अत्यधिक धनराशि खर्च करने के लिए बाध्य कर दिया था। कागजी मुद्रा को और उदारता से जारी किया गया जिससे आर्थिक जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया। सामन्ती व्यवस्था दिखरने लगी थी तथा दायम्यो लोग समुराई लोगों के रूप में बेकार बैठने वाले सेवकों का रख-रखाव करने में असमर्थ हो गये थे। अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध से दायम्यो लोगो ने अपने चावल के रूप में किसानों से प्राप्त भुगतान को जमानत के तौर पर रखकर व्यापारियों से भारी रकम ऋण के रूप में लेनी प्रारम्भ कर दी। धीरे-धीरे ये दायम्यो इन व्यापारियों के प्रभाव-क्षेत्र में आ गये तथा वे व्यापारी वास्तविक शासक बन गये। इ० होजो (E Honjo) ने इसी स्थिति को चित्रित करते हुए लिखा था कि 'ओसाका के समृद्ध व्यापारियों के क्रोध में दायम्यो (Daimyo) का दिल दहला देने की शक्ति है।'

बढ़ते हुए मूल्यों पर नियन्त्रण नहीं रहा। अपनी व्यवृत्ति की माँगों को बराबर बढ़ते जाने को पूरा करने के लिए दायम्यो लोगो ने न केवल जाली मुद्रा व नोट निर्गमित किये बल्कि भारी मात्रा में कर्ज भी लिये। तोकुगावा शासकों ने मूल्य-वृद्धि पर नियन्त्रण लगाने के उद्देश्य से 1831 व 1843 के दो आदेशों द्वारा सभी प्रकार के व्यावसायिक संगठनों (guilds) को गैर वानूनी घोषित कर दिया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि सरकार का विश्वास था कि व्यापारियों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है तथा वे मनमाने मूल्य वसूल कर रहे हैं। किन्तु यह निदान रोग से भी खराब रहा क्योंकि श्रेणियों के उन्मूलन ने साख व्यवस्था को छिन्न-भिन्न कर दिया। इससे आर्थिक

जन-जीवन और भी अधिक अस्त-व्यस्त हो गया ।

बाहरी विश्व के सामने खुल जाने का प्रभाव 1859-67 के मूल्यों में आसानी से देखा जा सकता था । चावल, रेशम तथा चाय जैसी चीजों की कीमतें एकदम चढ़ गईं क्योंकि उनके लिए विदेशों में तीव्र माँग थी । दूसरी ओर सूती वस्त्र, धागे तथा अन्य मशीनों की बनौ वस्तुओं का आयात खुल जाने से उनके मूल्य तेजी से घट गये । विदेशी व्यापारी जापान में आकर बसने लगे तथा जापानी पूँजी देश के बाहर प्रवाहित होने लगी ।

जापान को बाहरी दुनिया के लिए खोल देने का निर्णय शोगुन ने पश्चिमी नौसेना से पराजित होने के बाद ही लिया था । इस कटु तथ्य ने न केवल शोगुन को उसके मनुष्यों की आँखों में एक शाही अधिकारी का अपहारी (Usurper) बना दिया बल्कि वह देश को दगा देने वाला भी बहा जाने लगा । इससे एक ऐसी स्थिति पैदा हुई जिसमें लोग शोगुन को जापान की वित्तीय कठिनाइयों तथा देश में व्याप्त मौजूद राजनीतिक बुराइयों, दोनों ही के लिए जिम्मेदार मानने लग गये । देश के शक्तिशाली वर्ग शोगुन के विरुद्ध हो गये । शोगुन देश को एक सांस्कृतिक तथा सक्रिय नेतृत्व प्रदान करने में असफल रहा जब देश को वैसे नेतृत्व की आवश्यकता थी । उसकी प्रतिष्ठा व विश्वसनीयता दोनों ही समाप्त हो गई । अन्य व्यक्ति व संस्थाएँ इस स्थिति से उबारने के लिए वाञ्छित बन गये ।

नये नेतृत्व के लिए खोज का कार्य उन सम्पन्न व्यापारियों ने नहीं किया जिन्होंने तोकुगावा शासन-काल में दोनों हाथों से धन बढ़ोरा था बल्कि यह कार्य निम्न श्रेणी के समुराई (Samurai) योद्धाओं ने किया जो तोकुगावा शासन में एकदम फटेहाल हो चुके थे । इस तरह निम्न श्रेणी के समुराई लोगों ने ही अन्तिम की शुरुआत की तथा नये जापान के आर्थिक व राजनीतिक ढाँचे को नवीन स्वरूप प्रदान करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई । अन्य लोगों की तरह पुरानी सामन-व्यवस्था हटने से उनको किसी तरह का नुकसान होने वाला नहीं था । वास्तव में उनका हित तो परिवर्तन में ही था ।

कुछ लेखक इस बात पर दृढ़ मत हैं कि मेजी काल में जापान की आर्थिक प्रगति की शुरुआत तोकुगावा शासन के अन्तिम वर्षों में ही हो चुकी थी । उन्होंने मेजी शासन-काल में हुई उपनवधियों की आलोचना तक भी की है । किन्तु यह सही नहीं है । यह स्वीकार किया जा सकता है कि तोकुगावा समाज पूरी तरह जड़ नहीं था । इस बारे में कोई सन्देह नहीं हो सकता कि उसकी संस्थाओं ने जापान के विकास को अवरोध दिया था तथा यह भी कि जापान को तीव्र आर्थिक प्रगति के मार्ग पर लाने का कार्य मेजी युग के सुधारों से ही प्रारम्भ हुआ ।

यहाँ तक कि 1853 तक भी तोकुगावा शासन अत्यधिक दृढ़ एवं दुर्मेघ दिखाई पड़ता था । किन्तु उसकी नीचे राजनीतिक, आर्थिक एवं बौद्धिक परिवर्तनों से कमजोर पड़ चुकी थी और उसके सारे भवन को धराशायी करने के लिए एक विदेशी आक्रमण मात्र पर्याप्त था । जी० सी० एलेन के अनुसार, 'जब बाहरी जातिवाँ समुराई वर्ग के नेतृत्व में सम्राट के नाम पर तथा शोगुनते के विरुद्ध आगे

दूसरा अध्याय

मेजी पुनर्संस्थापना

(MEIJI RESTORATION)

अन्तिम तोकुगावा शोगुन (शासक) को 1867 में पदच्युत कर दिया गया तथा विजयी समुराई जाति के समर्थन से नये युवक सम्राट मेजी को 1868 में गद्दी पर बिठाया गया। अपनी महान् प्रतिज्ञा में उसने वायदा किया कि 'साम्राज्य की नींव पुख्ता करने के उद्देश्य से ज्ञान व बुद्धि की तलाश सारे ससार में की जायेगी।' नये शासन ने तेजी के साथ कुछ संस्थागत सुधार (institutional reforms) किये तथा जापान को दृढ़ता से आर्थिक विकास के मार्ग पर ला खड़ा किया। एकदम आधुनिक पाश्चात्य किस्म की संस्थाएँ जापान में स्थापित की गईं। व्यवस्था में यह परिवर्तन 'सम्पूर्ण' था तथा इसके समानान्तर दो ऐतिहासिक घटनाएँ—पीटर महान् द्वारा रूस का पश्चिमीकरण व कमाल अतातुर्क द्वारा तुर्की का पाश्चात्पीकरण—काफी कम सफल रही।¹

पुनर्संस्थापना के पहले दशक में तेजी से किये गये सुधारों का प्रमुख उद्देश्य नई शासन व्यवस्था को मजबूत बनाना व उसका दृढीकरण करना था। शोगुनते (तोकुगावा शासक की पदवी व इलाका) तथा हान (Han) को समाप्त कर दिया गया। सम्राट को टोक्यो में एक एकीकृत राष्ट्राध्यक्ष के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया गया। देश को 46 उपखण्डों (Prefectures) में बाँटा गया। सभी वर्गों के बीच समानता स्थापित की गई तथा पुराने सभी विभेद—जैसे योद्धाओं की वेशभूषा व उनके अधिकार, किसानों, मजदूरों व व्यापारियों को घटिया स्थान—समाप्त घोषित किये गये। लोगों को व्यवसायों की स्वतन्त्रता प्रदान की गई तथा उन्हें किसी भी फसल या वस्तु का उत्पादन करने की छूट दे दी गई। पुराने ढाँचे के खण्डहुरों पर एक नई प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण किया गया। सम्पत्ती सम्पत्ति अधिकार छीन लिये गये तथा अपने लगानों को समर्पित कर देने के बदले में भूस्वामियों को पैसें निर्धारित कर दी गई। इनके अतिरिक्त सरकार ने दायम्यो द्वारा लिये गये ऋणों का भुगतान करने का दायित्व लिया। इससे नई शासन-व्यवस्था के लिए जमींदारों व व्यापारियों दोनों ही का प्रतिरोध कम हो गया।

(1) सामान्य आर्थिक परिवर्तन—आन्तरिक व्यापार पर लगे प्रतिबन्ध उठा लिये गये। मामन्ती सम्पत्ति सम्बन्ध समाप्त मान लिये गये तथा भूमि पर स्वामित्व अधिकार प्रदान किये गए ताकि नई जमीन स्वतन्त्र रूप से विक्रि सकती। वस्तुओं के रूप

मे लगे सामन्ती करो के स्थान पर मुद्रा में राजकीय वर लगाये गये। सारे देश में कर-भार में समानता स्थापित की गई। 1873 के भूमि-कर सुधार ने भूस्वामियों से कर वसूलने की एकीकृत प्रणाली स्थापित की जिसमें उनसे उनकी भूमि के नये सिरे से हुए मूल्यांकन के अनुपात में कर लेने की व्यवस्था की गई। वस्तुओं के आन्तरिक आवागमन पर लगे हुए कर तथा देश में ही लोगों के आने-जाने पर रोक के लिए बने हुए पासपोर्ट-केन्द्र हटा लिये गये। सामन्ती चावल वजीफा (Feudal Rice Stipend) तथा दायम्यो व समुराई के सम्पत्ति अधिकारों का लघुकरण (commutation) कर दिया गया। उनके बदले में सरकारी बॉण्ड तथा पेंशन दे दी गई।

मेजी शासन के आरम्भिक वर्षों में विदेशी विशेषज्ञों को देश में काम के लिए बुलाने की नीति को ओर आगे बढ़ाया गया। 1872 में सरकार द्वारा काम पर लगाये विदेशी विशेषज्ञों की संख्या 200 के लगभग थी। जापानियों को विदेश जाने व पश्चिमी तकनीकों सीखने के लिए प्रोत्साहित किया गया। लोगों को तकनीकी प्रशिक्षण देने के लिए योजनाएँ बनाई गईं। पाठ्यालय पाठ्यक्रम पर आधारित प्राथमिक शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य कर दी गई। भ्रमणकारी शिक्षक सारे देश में भेजे गये। सरकार ने नये स्कूल व कॉलेज खोले जिनमें खान, इंजीनियरिंग तथा कृषि से सम्बन्धित कॉलेज सम्मिलित थे। कृषि की पद्धति में सुधार लाने के उद्देश्य से कृषि प्रयोग केन्द्र खोले गये। मेजी राजनीतिज्ञों ने एक नई राजकीय नीति, बाष्प-चालित जहाज सेवा, डाक व तार सेवा तथा कारखानों की शुरुआत की।

नई सत्ता राष्ट्रीय शक्ति की ऐसी आधारशिला तैयार करना चाहती थी जो आन्तरिक विरोधों तथा बाहरी खतरों की पृष्ठभूमि में भी सुरक्षित रह सके। इस क्रान्ति के नेता भी निम्न समुराई वर्ग के ही थे लोग थे जो शोगुन के विरोधी प्रान्तों (Hans) में प्रशासकों के पदों पर कार्य कर रहे थे। उनको मित्सुई घराने तथा सुमीतोमो (House of Mitsui & Sumitomo) जैसे समृद्ध व्यापारियों का भी समर्थन मिल गया जो नये जापान में प्रमुख शक्तियाँ बन गये। क्रान्ति में सर्वाधिक हानि शोगुन ही को हुई। परिवर्तन का प्रतिरोध न करने के कारण दायम्यो को भी उदार मुआवजा मिल गया। इन तरल कोषों में ये लोग बैंकर, भूस्वामी तथा उद्योग-पति बन बैठे। 1884 में ये लोग नये सिरे से बनाये गये पदवीधारी लोग (pears) बन गये।

किन्तु समुराई वर्ग को पूरी उदारता से मुआवजा देने की सरकार की पूरी इच्छा के बावजूद वित्तीय कठिनाइयों के कारण उसके लिये पैसा करना सम्भव नहीं हो पाया। इसके परिणामस्वरूप समुराई लोगों को मिलने वाला मुआवजा उनकी पिछली आय से भी कम रहा। इसका अर्थ यह था कि अब समुराई लोग मिठले बैठकर खगानों आदि के बलबूते पर अपना काम नहीं चला सकते थे। वे नौकरियाँ करने के लिए बाध्य हो गये। बड़ी संख्या में समुराई लोगों को प्रान्तीय तथा नगर-पालिका के प्रशासन में नौकरियाँ दी गईं। पुलिस तथा सेना में भी भारी संख्या में समुराई लोग लिये गये। जैसा कि उस समय के बारे में इ० एच० नॉर्मन ने लिखा था कि 'पूरा राज्यतन्त्र समुराई प्रभाव में भीग चुका था।' ऐसा कुछ तो इसलिए

भी हुआ कि समुराई वर्ग को खपाने के लिए भी कुछ रास्ता निकालना था। इतना ही नहीं, सरकार ने समुराई लोगों को उद्योगों में भी रोजगार देने की कोशिश की तथा उन्हें कृषि में पुनः स्थापित करने के इरादे से होक्केइडो द्वीप के उत्तर में कुछ व्यवस्थाएँ भी कीं। किन्तु इन सारे प्रयासों के बावजूद सम्पूर्ण समुराई वर्ग को खपाया नहीं जा सका। उनमें से कई सरकार द्वारा उनकी अनदेखी किये जाने के कारण कटुता से भर गये तथा उन्होंने अन्तिम बार एक समन्वय विद्रोह का प्रयास भी किया—यह 1877 का सत्सुमा (Satsuma) विद्रोह था।

यहाँ तक कि किसान लोगों ने भी अनुभव किया कि सरकार ने उनकी आशाओं को पूरा नहीं किया। सरकार द्वारा निश्चित मौद्रिक वार बसूल करने की नीति अपनाने के कारण कई किसानों की अपनी जमीनें बेचनी पड़ी क्योंकि उतरते-चढ़ते भावों पर चावल बेचने से उन्हें पर्याप्त राशि नहीं मिलती थी। मालिकों से वे लोग आसामी बन गये। यह हम तथ्य में स्पष्ट है कि देश में आसामीयों के पास मौजूद भूमि का प्रतिशत जो मेजी काल के आरम्भ में 31 था, उसके आखिर में 46 हो चुका था। ये आसामी लोग अभी भी ऊँचे लगान देने के लिए बाध्य थे तथा गरीबी की कुगार पर जी रहे थे।

(2) पुनर्निर्माण (Reconstruction 1868-81)—‘तोकुगावा घराने’ को उखाड़ फेंकने तथा पुनर्संस्थापना के तुरन्त बाद कई छोटे बड़े सघर्षों व राजनीतिक झगड़ों का सामना करने के कारण केन्द्रीय सरकार के वित्तीय साधनों व उसकी प्रशासनिक क्षमता पर कड़ा जोर पड़ा। लेकिन इसके बावजूद नई सरकार की उपलब्धियाँ असाधारण रही। सामंतवादी संस्थाओं का उन्मूलन करने तथा पश्चिमीकरण की शुरुआत करने के बाद मेजी (Meiji) के नेतृत्व वाली इस नई सरकार ने अपना ध्यान पुनर्निर्माण के पहले 14 वर्षों में देश के विदेशी व्यापार की स्थिति सुधारने की तरफ लगाया। 1869 में कलात्मक वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए एक व्यावसायिक ब्यूरो स्थापित किया गया। आवश्यक वस्तुओं का आयात करने के लिए भी विदेशी मुद्रा प्राप्त करने में कठिनाई होती थी। कभी-कभी तो विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए सरकार स्वयं निर्यात का कार्य करती थी। वह धरेलू भण्डारों से चावल, चाय तथा रेशम खरीदती तथा उसे विदेशों में बेचती। ऐसा करने में जो आय प्राप्त होती उसका उपयोग अत्यावश्यक आयातों के लिए किया जाता।

पुनर्संस्थापना के बाद के दशक में विदेशी व्यापार में सतोपजनक वृद्धि हुई। 1868 में विदेशी व्यापार का कुल मूल्य, चाँदी के येनो में 26 मिलियन के बराबर था जो 1873 तक बढ़कर 50 मिलियन येन तथा 1881 तक तो बढ़कर 62 मिलियन येन हो गया। इसके बावजूद देश के मामले विपरीत भुगतान सतुनन की समस्या विद्यमान थी। केवल 1868 तथा 1876 के अपवादों को छोड़कर आयातों का मूल्य हमेशा ही निर्यातों से काफी अधिक रहा। 1868 से 1881 के बीच केवल दृश्य व्यापार में ही भुगतान में घाटा 79 मिलियन येन का रहा। कुल भुगतान सतुनन का घाटा तो इससे बड़ी अधिक था क्योंकि जापान का विदेशियों की सेवाओं के बदले

तथा जहाजी भाडों के रूप में भी भारी रकम विदेशों को भेजनी पड़ती थी।

1868 से 1881 के बीच विदेशी व्यापार की संरचना एक ऐसे विशिष्ट देश का आभास दिलाती थी जो अपना आधार तैयार करने की कोशिश कर रहा था। अधिकांश आयात विनिर्मित वस्तुओं (Manufactured goods)—विशेष रूप से वस्त्र, पूंजीगत पदार्थों जैसे मशीनें, जहाज, रेल, साज सामान, सैनिक सामग्री, तथा अन्य विनिर्मित धातु पदार्थों—के थे। इनमें से अधिकांश आयात इंग्लैंड से किये गये। निर्यात मुख्य रूप से कच्चे माल के होते थे जिनमें रेशम व चाय प्रमुख थे। लगभग इसी समय यूरोप में रेशम के कीड़ों में महामारी फैल जाना जापानी रेशम उद्योग के लिए बड़ी भाग्यशाली घटना रही। 1876 में जापान के आधे निर्यात कच्ची रेशम के थे। जापान के लिए अपने पश्चिमीकरण (Westernisation) के कार्यक्रम को चला सकना बहुत बठिन हो जाता यदि यूरोप में रेशम के कीड़ों की वह बीमारी न फैलती जिसकी वजह से जापान को विश्व में बड़ी हुई रेशम की मांग जिसका कि वह भारी मात्रा में उत्पादन कर सकने में समर्थ था, पूरा करने का अवसर मिल गया। निर्यात की दूसरी सबसे प्रमुख मद चाय थी जो प्रमुख रूप से अमरीका को भेजी जाती थी। चावल व तांबा भी निर्यात के पर्याप्त महत्वपूर्ण अंग थे। इनमें से अधिकांश मदे किसान परिवारों द्वारा चलाए जा रहे लघु उद्योगों से प्राप्त होती थी।

(3) वित्तीय कठिनाइयाँ—1868 में नई सरकार के सम्मुख बजट में भारी घाटा उपस्थित हो गया था। पुनर्संस्थापना के तुरन्त बाद देश में आंतरिक शांति कायम करना बहुत महंगा पड़ा था। सरकार के लिये नए कर लगा पाना भी सम्भव नहीं था क्योंकि देश पहले ही अराजकता व विघटन के कगार पर खड़ा हुआ था। 1868 में सरकार का खर्च 25 मिलियन येन रहा जबकि उस वर्ष सरकारी प्राप्तियाँ 37 मिलियन येन ही रही थीं। सरकार ने अनेक जापानी तथा विदेशी व्यापारियों में धन उधार लिया। किन्तु इन स्रोतों से प्राप्त धनराशि भी 54 मिलियन येन ही रही और इसके परिणामस्वरूप उस अकेले वर्ष में 16 मिलियन येन का घाटा फिर भी शेष रह गया। 1869 में भी लगभग 208 मिलियन येन के खर्च के मुकाबले सरकारी प्राप्तियाँ 105 मिलियन येन के बराबर ही रह पाईं। सरकार को मजबूर होकर नए नोट छापने पड़े तथा दो वर्षों में 48 मिलियन येन के नए नोट जारी किये गये। इन अपरिवर्तनीय कामज के नोटों के प्रति दायिम्यो ने अपना रोप प्रकट किया क्योंकि उन्हें इन सरकारी नोटों का उनकी अपनी पत्र-मुद्रा पर विपरीत प्रभाव पड़ने का भय था। इससे सरकारी नोटों का भारी मूल्य-ह्रास हो गया।

मेजी पुनर्संस्थापना के विरोधी तत्वों को 1869 तक अन्तिम रूप से कुचल दिया गया। सरकारी खर्च घटाया गया तथा लोगों का नई सरकार में विश्वास भी काफी बढ़ गया। 1871 में हान (Han) के उन्मूलन से सरकारी आय के स्रोत भी बढ़ गए। मुद्रा ढालने के कार्य में भी सुधार के लिए प्रयास किया गया। स्वर्ण येन की विचुद्ध मात्रा परिभाषित करने के लिए एक कानून लाया गया तथा उसे स्टैंडर्ड

सिक्का भी घोषित किया गया हालांकि चांदी के येन को भी विधि-सम्मत (Legal Tender) मुद्रा माना गया। सरकार द्वारा ओसाका में नई मशीनों से युक्त एक टंकसाल भी स्थापित की गई।

इतना ही नहीं कई और वित्तीय कठिनाइयों से भी पार पाना था। हालांकि सरकार ने हान को समाप्त घोषित कर दिया था, किन्तु लोगों से उन करो को वसूल करना आसान नहीं था जो पहले दायम्यों द्वारा वसूल किये जाते थे। समुराई लोगों को पेंशन देने की जिम्मेदारी लेने तथा दायम्यों लोगों के कर्ज का भार अपने पर ले लेने से भी सरकार पर काफी वित्तीय भार पड़ गया। दायदों से बजट की कठिनाइयाँ और भी बढ़ गई। 1872 में, उदाहरण के लिए, जबकि व्यय 58 मिलियन येन का था, प्राप्तियाँ 33 मिलियन येन ही रही। नई पत्र-मुद्रा छापना ज़रूरी हो गया। हान सरकारों द्वारा स्थानीय स्तर पर नोट छापने की जिम्मेदारी भी अपने पर ले लेने से राज्य पर जो अतिरिक्त भार पड़ा उससे भी मुद्रा की पूर्ति में 26 मिलियन येन की वृद्धि हो गई। इस तरह 1872 के अन्त तक पत्र-मुद्रा का कुल परिमाण 100 मिलियन येन हो चुका था। सरकार ने पत्र-मुद्रा के बदले ऐसे बॉण्ड प्रदान करने की योजना बनाई जिन पर 6 प्रतिशत की दर से व्याज देने की व्यवस्था थी। 1876 में नोट निर्गमन 94 मिलियन येन पर आ चुका था। इस स्थिति में तेज़ी से बढ़ते हुए रैदम निर्यातों द्वारा और सुधार आया। इस तरह ऐसा लगने लगा कि अब सरकार की मुद्रा कठिनाइयाँ काफी कुछ हल हो चुकी हैं।

इस बीच कर-प्रणाली में सुधार करने व उसे अधिक व्यवस्थित बनाने का प्रयास किया गया। तोकुगावा बाल के मनमाने करो के स्थान पर अधिक समानता स्थापित करने वाला कर प्रणाली लायी गयी। 3% की दर से पहले एक भूमि कर लगाया गया किन्तु 1876 में उसे घटाकर 2.5% कर दिया गया। 1875 में छोटे-मोटे करो की सम्पूर्ण व्यवस्था में इन प्रकार सुधार कर दिया गया कि करो की संख्या अब 1,600 से घटकर 74 रह गई। किन्तु भूमि-कर अभी भी आगम का प्रमुख स्रोत बना रहा तथा 1880 में उसमें कुल प्राप्तियों का 80% भाग प्राप्त हुआ।

लेकिन सरकार की वित्तीय कठिनाइयाँ अभी समाप्त नहीं हुई थी। 1877 में हुए सत्सुमा विद्रोह (Satsuma Rebellion) को दबाने में भारी खर्च हुआ। उसे पूरा करने के लिए 27 मिलियन येन के नए नोट और जारी करने पड़े तथा 15 मिलियन येन का बंक ऋण भी लेना पड़ा। विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों को स्वीकृत पेंसनों का लघुकरण (commutation) करके ब्याज-युक्त बॉण्ड जारी करने से भी सरकार पर 174 मिलियन येन का भार पड़ा। इस तरह राष्ट्रीय ऋण-भार 55 मिलियन येन से बढ़कर 240 मिलियन येन हो गया। हान के सुप्त हो जाने से कई व्यापारी बैंकरो (Merchant Bankers) का धन्य समाप्त हो गया और 1873 तक उनमें से कई दिवालिया हो गये। थोड़े समय के लिए सारा साख लेन-देन रुक गया और उनके परिणामस्वरूप मुद्रा की बढ़ी तंगी आ गई। इस तरह पुराने वित्तीय तंत्र के तहम-नहम हो जाने तथा राजनीतिक परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होने वाली नई वित्तीय समस्याओं के आ खड़े होने से नए सिरे से बैंकिंग संस्थाओं की आवश्यकता पढ़ने

लगी। राष्ट्रीय बैंको (National Banks) की अमरीकी प्रणाली को आदर्श के रूप में स्वीकार किया गया। 1874 तक चार नेशनल बैंक स्थापित किये गये किन्तु यह प्रयोग असफल रहा। इन बैंको के सामने अपनी परिवर्तनीय पत्र-मुद्रा को प्रचलन में रखने में कठिनाई आई। व्यापारियों ने नोट निर्गमित करने वाले बैंक के सामने बैंक नोट प्रस्तुत कर स्वर्ण प्राप्त करना भुनाफे का सौदा बना लिया क्योंकि उस स्वर्ण से वे वस्तुओं का विदेशों से आयात कर सकते थे। इस तरह नेशनल बैंको के रक्षित कोष खाली हो गये। ऐसी स्थिति में नेशनल बैंक विनियमन में संशोधन किये गये तथा 1876 के बाद उनके नोट भी अपरिवर्तनीय घोषित कर दिये गये जिन्हें सरकारी बाँण्डों की आद में जारी किया जा सकता था। 1876 से 1880 के बीच 148 नये नेशनल बैंक स्थापित किये गये। लेकिन बिना व्यावसायिक अनुभव वाले लोगों द्वारा गठित किये जाने के कारण वे खराब तरीके से संचालित हो रहे थे तथा अधिकांश वास्तविक बैंकिंग व्यवसाय विदेशी बैंको द्वारा किया जाने लगा। उधर बैंको द्वारा भारी मात्रा में नोट जारी करने से मुद्रास्फीति पैदा हो गई। जून 1877 में 95 मिलियन येन की मुद्रा की पूर्ति 1878 तक बढ़कर 150 मिलियन येन हो गई। चावल के मूल्य 1877 से 1880 के बीच दुगुने हो गये। व्याज की दरें चढ़ गईं तथा सरकारी बाँण्डों के मूल्य गिर गये। पत्र-मुद्रा की तुलना में रजत येन का मूल्य इतना चढ़ गया कि 1881 तक एक रजत येन पत्र-मुद्रा के 80 येन के बराबर हो गया।

सरकार डम मुद्रा-स्फीति से अवगत थी। जीवन-स्तर लागत निरन्तर बढ़ती जा रही थी तथा विदेशी व्यापारी जोर-शोर से शिकायतें करने लगे थे। 1880 में सरकार ने अपने पास जमा कुछ रजत कोषों को बेचकर करेंगी नोटों के घटते हुए मूल्य को नियन्त्रित करने की चेष्टा की। सरकार ने करो को बढ़ाकर अपना बजट का घाटा भी कम किया। 1881 तक वित्त मंत्री प्रिंस मत्सुकाता द्वारा वित्तीय स्थिति को अन्तिम रूप से नियन्त्रण में ले आया गया।

नई सरकार इन वित्तीय तथा राजनीतिक परेशानियों से इतनी शिंशोड़ी जा चुकी थी कि उससे भावी विनाम की कोई आशा नहीं बंधती थी। विदेशी लोग भी जापान के भविष्य के प्रति अंधविश्वास आशावादी नहीं थे। 'हम समृद्ध जन यह नहीं सोचते कि जापान कभी वनेगा प्रकृति द्वारा प्रदत्त लाभ, एक जलवायु के अपवाद को छोड़कर तथा लोगों की आमोद-प्रमाद व आलस्य में रूचि इस सम्भावना पर रोक लगा देते हैं। जापानी लोग एक खुशगवार किस्म के लोग हैं तथा थोड़े में ही सन्न कर लेने के कारण उनके द्वारा कुछ अधिक पैसा लेने की सम्भावनाएँ नहीं के बराबर हैं।' ¹ कम से कम पश्चिमी देशों ने यह प्रत्याशा तो कभी नहीं की थी कि एक दिन जापान उनका ही प्रतिद्वन्द्वी बन जाएगा। जब 1870 के दशक में उनका बैंकिंग प्रयोग असफल

¹ 'Wealthy we do not think Japan will ever become the advantages conferred by Nature with the exception of the climate, and the love of indolence and pleasure of the people themselves forbid it. The Japanese are a happy race, and being content with little are not likely to achieve much.'

हो गया तो विदेशियों को अपनी धारणा में और भी पक्का बिस्वास हो गया। 'जापान की नेशनल बैंकिंग व्यवस्था पाश्चात्य विकास को पूर्वी आवास (Oriental habitat) में हस्तांतरित करने की व्यर्थ चेष्टा का एक और उदाहरण है। दुनिया के इस भाग में सिद्धान्त, जो पश्चिम में मान्य एवं स्थापित होते हैं, अपने गुणों तथा शक्ति को खो देते हैं जो उनमें मूल रूप से विद्यमान होती है तथा बेखर-पतवार (weediness) तथा भ्रष्टाचार की तरफ सांघातिक रूप से मुड़ जाते हैं।'¹

मेजी काल के मुख्य आर्थिक परिवर्तन

मेजी युग के आरम्भ होने के बाद आधुनिकीकरण की एक तीव्र प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई।² जापान अब पाश्चात्य प्रभावों के आरोही-प्रवाह से पूरी तरह अनाकृत हो गया। 1868 के बाद के पहले ही दशक में विदेशी व्यापार दुगुने से भी अधिक हो गया। विशाल सङ्ग में युवा जापानी पवित्रमी विज्ञान एवं तकनीक, राजनीतिक संस्थाओं तथा आर्थिक संगठन का अध्ययन करने के उद्देश्य से विदेश जाने लगे। विदेशी व्यापारी तथा विदेशी विशेषज्ञ भी भारी संख्या में जापान आये। युवा समुदाय प्रशासनिक अधिकारियों ने अधिनायकतावादी राष्ट्रीय सुधारों का एक विचाल कार्यक्रम सम्राट के नये शासन के अन्तर्गत छेड़ दिया। ओकुबो, किदो तथा इवाकुरा जैसे लोगों का स्वप्न पहले नई सरकार की शक्ति व सत्ता की आन्तरिक विरोधों की पृष्ठ-भूमि में हवीवृत करना था तथा दूसरे, एक मजबूत राष्ट्रीय राज्य (Strong National State) बनाना था जो विश्व राजनीति के क्षेत्र में अपनी रक्षा कर सके तथा अपनी बात पर जोर दे सके। अगली चौथाई शताब्दी में यही महत्वाकांक्षाएँ राष्ट्रीय आर्थिक विकास के नये दौर का आधारभूत ढांचा बन गईं। यही महत्वाकांक्षाएँ उच्च सरकारी अधिकारियों व नवोदित वित्तदाताओं तथा उद्योगपतियों के बीच एक निकटस्थ बणिक्वादी गैरी (close mercantilist alliance) का भी स्वाभाविक आधार बन गईं।

दोना ही अर्थात् मेजी पुनर्संस्थापना व उसके तत्वाधान में किये गये सुधारों ने संकट की घड़ी में जापानियों की सुयोग्य नेताओं को आग ला सक्ने की असाधारण क्षमता का परिचय दिया। इस प्रकार के सुयोग्य नेतृत्व के साथ जापानियों में जुडो (Judo) जैसी कुर्सी भी थी जिससे वे अपने दाँव आने तक चुप पड़े रह सन्ते थे और मौका मिलते ही अपने शत्रुओं पर प्रहार कर देते। मेजी शासन के आरम्भिक वर्षों में सरकार ने ढहते हुए सामन्तवादी ढाँचे को पूरी तरह नष्ट करने तथा अपनी सत्ता को सारे देश में अनुभव करा देने के कार्य किये। 1877 में सत्सुमा के विद्रोह को सत्सुमा से दबा देना इसका एक उदाहरण था। 1881 के बाद सरकार की विनीय स्थिति तथा उसकी पञ्च-मुद्रा को भी जापान के सत्वालीन चतुर एवं कुशल वित्त मंत्री काउन्ट मत्सुकाता द्वारा सुदृढ़ आधार प्रदान कर दिया गया।

(1) विकास के लिए आवश्यक ढाँचे (Infrastructure) का निर्माण—नये

¹ *Ibid*, 112.

² *Ibid*, 12-13.

उद्योग स्थापित करने तथा यातायात एवं संचार सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा जोर-शोर से उपाय किये गये। 1870-72 में एक छोटे से ब्रिटिश ऋण की सहायता से टोक्यो व योकोहामा के बीच पहले रेल-मार्ग का निर्माण किया गया। उसके कुछ ही समय बाद योकोहामा व नागासाकी के बीच स्टीमर सेवा भी आरम्भ की गई। सरकारी अनुदानों द्वारा इसका नेजी में प्रसार कर दिया गया। 1893 तक जापान ने अपनी प्रथम 2,000 मील लम्बी रेल लाइन, प्रथम 1,00,000 टन भार से चलने वाले जहाजों तथा पहली 4,000 मील लम्बी टेलीग्राफ लाइन का निर्माण कर लिया था।

आयातित उपकरणों तथा पश्चिमी विशेषज्ञों की सहायता से देश में पोत-निर्माण स्थलों (shipyards), शस्त्रागारों, औजार कारखानों तथा तकनीकी स्कूलों की स्थापना की गई या उन्हें आधुनिक बनाया गया। पहला आधुनिक रेशम कताई मिल 1870 में खोला गया जिसकी देख-रेख एक फ़ामीसी विशेषज्ञ करता था। सूती धागे की कताई मिलें भी खोली गईं या उन्हें इंग्लैंड से आयातित नवीन उपकरणों से मज्जित किया गया। सीमेंट, चीनी, वियर, काच, रसायन व अन्य पाश्चात्य वस्तुओं का उत्पादन देश में आरम्भ करने के उद्देश्य से प्रायोगिक फैक्ट्रियाँ खोली गईं। कोयला, ताँबा व अन्य महत्वपूर्ण खनिजों की खोज व उत्खनन के नए कार्य हाथ में लिये गये। 1876 से 1896 के बीच खनिजों के उत्पादन में 7 गुनी वृद्धि हो गई।

इनमें से अधिकांश उपक्रमों के लिए आरम्भ में सरकार ने ही धनराशि जुटाई। यह बात यातायात, खान उद्योग इजीनियरिंग उद्योग तथा सैनिक सामग्री के बारे में विशेष रूप से सही थी। बाद में, जैसे जैसे निजी साहसिकता अधिक सक्रिय हुए तथा सरकारी कारखानों को बहुत मामूली-सा लाभ होने लगा, सरकार ने अपनी अधिकांश औद्योगिक सम्पत्ति बहुत मस्ते मूल्य पर निजी उद्योगपतियों के हाथों बेच दी। 1880 में जारी फैक्ट्रियों के हस्तान्तरण सम्बन्धी विनियमन में यह सरकारी तौर पर स्पष्ट किया गया कि 'उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए लगाई गई फैक्ट्रियाँ अब काफी सुसंगठित हो चुकी हैं तथा व्यापार भी काफी समृद्ध हो चुका है इसलिये सरकार अब इन फैक्ट्रियों का स्वामित्व त्याग देगी जोकि लोगों द्वारा ही चलाई जानी चाहिए।' फैक्ट्रियों के निजी हाथों में स्थानांतरित कर देने की इस प्रक्रिया ने बाद के वर्षों में देश में अनेक विशाल वित्तीय एवं औद्योगिक घरानों की स्थापना में सहायता की। सामरिक महत्व के उद्योगों, जैसे इस्पात व कोयला, को सरकारी नियन्त्रण में रखा गया।

(2) तीव्र औद्योगीकरण (Fever of Industrialisation)—1868 के बाद की चौथाई शताब्दी में जापान में हुई नाटकीय घटनाओं की परिणति वहाँ पर नई आवश्यकताओं व तकनीकों के सृजन तथा सरकारी सन्स्थाओं के एक नए ढाँचे के निर्माण के रूप में हुई। उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम वर्षों में तो जापानी व्यावसायिक व राजनीतिक नेताओं को औद्योगीकरण की दीवानगी सी चढ़ गई थी। इन जापानी नेताओं की ऊँची ऊँची औद्योगिक महत्वाकांक्षाओं से कई विदेशी प्रभावित हुए थे। यहाँ तक कि सेना के लोग भी इस औद्योगीकरण के बुखार से नहीं बचे थे। एक

अमरीकी अर्थशास्त्री रॉबर्ट पी० पोटर, जो उन दिनों जापान की यात्रा पर गये थे, ने लिखा कि 'सार्वजनिक वक्ताओं में केवल अधिकारीगण ही नहीं पाये जाते जिनका कि काम ही व्यवसाय या कृषि पर भाषण देना है बल्कि यहाँ तक कि एक नौसैनिक अधिकारी भी इसे अपने सम्मान के विरुद्ध नहीं समझता कि वह अपने देशवासियों से यह कहे कि राष्ट्र व्यापार के विकास से ही महान् बन सकता है तथा व्यापार उतना ही सम्मानजनक है जितने कि युद्ध के लिए उनके श्रेष्ठ प्रयास।'।

किन्तु यहाँ यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि मेजी पुनर्स्थापना के बाद के प्रारम्भिक वर्षों में राष्ट्रीय आय में जो वृद्धियाँ हुईं वे उद्योगों में हुए विकास का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं थी। पहले की जड़प्राय जापानी अर्थव्यवस्था में नई फैक्ट्रियों की स्थापना के लिए दिखाया गया आरम्भिक उत्साह अपने आप में एक प्रमुख आर्थिक परिवर्तन था। पुनर्स्थापना के आरम्भिक वर्षों में वास्तविक राष्ट्रीय आय में हुई बड़ी वृद्धियाँ मुख्य रूप से कृषि, हस्तशिल्प आदि में हुए सामान्य सुधारों तथा देश के एक मजबूत केंद्रीय सरकार के अधीन एकीकृत होने के कारण हुई थी।

औद्योगिक ताप, जिससे मारा देश एक प्रकार से घबकने लग गया था, के उस उत्साह भरे वातावरण के कारण 1880 तक जापान में विशाल पैमाने के उद्योगों की नींव डल चुकी थी। अगला दशक जापानी अर्थव्यवस्था के विकास में एक नया अध्याय था। पिछले वर्षों में डाली गई नींव पर अब एक नयी औद्योगिक व्यवस्था का उदय हो रहा था। नई तकनीक का अपना लिपि जाना, वैकों के माध्यम से पूंजी संचय होने लगना तथा अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य स्तर में सामान्य वृद्धि—सभी ने मिलकर औद्योगिक उत्पादन में तीव्र प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर दिया।

(3) युद्ध एवं आर्थिक प्रसार—एक दशक के अन्तराल में दो युद्धों में विजय प्राप्त करना भी मेजी युग की गौरवशाली घटनाएँ थीं चूँकि उनके कारण राज्य तथा नए उदीयमान पूँजीपतियों (जैवत्यु) के नेतृत्व में यातायात, बैंकिंग व आधारभूत उद्योगों के विकास की दिशा में भारी योगदान मिला। 1894-95 का चीन के साथ युद्ध तो लगभग जापानी प्रशासकों ने जान-बूझ कर ही खेड़ा था। जापान की अपना साम्राज्य स्थापित करने की महत्वाकांक्षा बलवती हो चली थी ताकि वह अपने लिए सुरक्षित बाजार व सुनिश्चित कच्चे माल की पूर्ति की व्यवस्था कर सकता।

जापान की यह सैनिक वपट-युक्ति (Military Manoeuvre) असाधारण रूप में सफल रही। चीनी-जापानी युद्ध से विजयी जापान को हरजान की एक मोटी रकम, करीब 200 मिलियन डॉलर, प्राप्त हुई जो उसके तत्कालीन राष्ट्रीय उत्पाद (G N P) का एक-तिहाई थी। यह हरजाने की रकम 1895-96 में विदेशी मुद्रा के रूप में भुगतान की गई तथा इसने 'मेन्ता व नौमेन्ता का प्रसार सम्भव बताया व रेल-मार्गों के प्रसार, तार व टेलीफोन की सेवाओं के विस्तार, यथाता मोहा मिल की स्थापना तथा स्वर्णमान स्वोकार करने में भी जापान की सहायता की।¹ आर्थिक दृष्टि से युद्ध ने अनेक महत्वपूर्ण गतिविधियों को उत्तेजित किया। युद्ध-मामलों का उत्पादन करने वाले नए उद्योगों में नया आ गे। इस युद्ध में विजय प्राप्त करने

¹ M. Shunohara, *Growth and Cycles in the Japanese Economy*, 1962, 53.

से जापान उन अपमानजनक सन्धियों को भी समाप्त करने में सफल हुआ जो 1858 में पश्चिमी शक्तियों द्वारा उस पर थोप दी गई थी।

राजनीतिक दृष्टि से देखा जाय तो इस युद्ध ने सम्राट की शक्ति व प्रतिष्ठा में काफी वृद्धि की। जापान के नेताओं ने अब सम्पूर्ण एशिया में अपने साम्राज्य के विस्तार का अभियान छेड़ दिया। चीन पर विजय प्राप्त करने के तुरन्त बाद उसने फारमोसा पर अधिकार कर लिया। उसने चीन में भी व्यापारिक, औद्योगिक तथा नौपरिवहन सम्बन्धी अधिकार प्राप्त कर लिये। बाद में जापान ने चीन में हुए बक्सर विद्रोह को दबाने में भी पश्चिमी देशों के साथ भाग लिया तथा 1901 में इसके पुरस्कार स्वरूप उसे 26 मिलियन डॉलर की हरजाने की रकम (indemnity) भी प्राप्त हुई।

ये सामरिक सफलताएँ व आवश्यक धनराशि प्राप्त करने के बाद जापान ने अपनी सैनिक गतिविधियाँ दुगुनी तेज कर दी। 1905 में उसने रूस जैसे विशाल देश को पराजित कर दिया, उसके कराफुतो द्वीप पर अधिकार जमा लिया तथा चीन में भी और छूटें जीत के पुरस्कार के रूप में प्राप्त कर ली। कोरिया को 1910 में अधिग्रहण कर लिया गया। चीन के साथ युद्ध में विजय से जो आर्थिक तेजी आई थी रूस पर विजय पा लेने में वह और भी सुदृढ़ व गतिमान हो गई। इसके परिणाम-स्वरूप पुन वित्तीय समस्याओं, नौपरिवहन तथा औद्योगिक तकनीक की विकास दर में वृद्धि हो गई। जापान ने अपनी घरेलू बचत के पूरव के रूप में भारी मात्रा में विदेशों से ऋण लिये। मूल रूप से फिर भी वह जापान की सम्पदा व औद्योगिक उत्पादकता में होने वाली निरन्तर वृद्धि ही थी जिसने उसे युद्धों में विजयी बनाया। इस प्रकार आर्थिक विकास जापान की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का वाहक बन गया।

प्रथम विश्व-युद्ध पूर्व के विश्वसनीय आँकड़े तो उपलब्ध नहीं हैं किन्तु फिर भी यह अनुमान लगाया गया है कि 1890-1914 के बीच जापान की वास्तविक राष्ट्रीय आय में 80 से 100 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। इतना ही नहीं यह विकास पर्याप्त मात्रा से अधिक ही था तथा इसमें सभी महत्वपूर्ण क्षेत्र आ गये थे। विनिर्माण, खनिज तथा यातायात उद्योग तो दिन-दूनी-रात-धीनुनी गति से बढ़ रहे थे। श्रम-शक्ति में होने वाली समस्त वृद्धियाँ उद्योग, व्यापार तथा अन्य सेवाओं में खप गई थी।

(4) बड़े पैमाने के उद्योगों का विकास—बढ़ती हुई सट्टा में जापानी लोग अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बिक्री के लिए अनिरेक का उत्पादन कर रहे थे। 1913 में पारिवारिक कार्य केंद्रों (workshops) में ही कोई 20 लाख लोग लगे थे। रोजगार के स्वरूप में परिवर्तन आ जाने के उपरान्त कृषि उत्पादन भी बराबर बढ़ रहा था तथा वह बढ़ती हुई घरेलू माँग के साथ ही चढ़ता आ रहा था। जापान के आयात व निर्यात दोनों ही 1889-93 में 1899-1903 की अवधि में दुगुने हो चुके थे। अगले दशक में वे पुन दुगुने हो गये। यह इसलिए सम्भव हुआ कि मेजी युग की समाप्ति तक जापानियों द्वारा स्थापित कारखाने व खानें जितना उत्पादन कर रही थी वह न केवल घरेलू माँग के लिए पर्याप्त था बल्कि विदेशों में बिक्री के लिए भी

उसे भेजा जा सकता था। निर्यातों में वृद्धि से जापान को अधिकाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई जिसका उसने अपनी औद्योगिक व सैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु मशीनों, उपकरणों व कच्चे माल का आयात करने में अविलम्ब उपयोग किया। मेजी युग के अन्तिम चतुर्दश में औद्योगिक गतिविधियाँ वित्तीय तीव्र हो चुकी थीं इसका पता तो केवल इस एक उदाहरण से चल सकता है कि कोयले का उपभोग, जो 1893 में 2 मिलियन टन बाँपा था, 1913 तक बढ़कर 15 मिलियन टन हो गया। रेल-मार्गों की लम्बाई तिगुनी हो गई तथा माल ढोने का परिमाण सात गुना बढ़ गया।

मेजी युग में बड़े पैमाने पर सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में सबसे सफल व्यापारिक जहाज-निर्माण कार्य रहा। मेजी प्रशासन ने जहाज-निर्माण को सरकारी समर्थन 1870 से ही प्रदान किया था। चीन जापान युद्ध ने इसे और तेज कर दिया। सरकार ने घरेलू स्तर पर जहाज निर्माण को बढ़ावा देने के लिए अनुदान की व्यवस्था भी की। इसके परिणामस्वरूप 1913 तक जापान के वाष्प-चालित व्यापारिक जहाज 15 मिलियन टन भार के हो चुके थे। यह 1896 की तुलना में तीन गुनी वृद्धि प्रदर्शित करता था।

धातु-निर्माण (Metallurgical) उद्योगों की स्थापना करने में अधिक रुचिनाइयाँ आईं। ताँबे व कोयले के अलावा और कोई भी खनिज देश में उपलब्ध नहीं थे। विदेशों से मँगवाई गई कच्ची व तैयार धातुओं के आयात 1913 में 100 मिलियन यें के रहे। इन आयातों में प्रमुख स्थान लोहे व इस्पात का था। 1913 तक लोह पिंडों का उत्पादन बढ़कर 2.4 लाख टन तथा इस्पात का उत्पादन 2.5 लाख टन हो चुका था। किन्तु यह घरेलू उपभोग वा केवल तीसरा हिस्सा ही था। शेष आपूर्ति आयातों से होनी थी।

जहाज निर्माण के अलावा इन्जीनियरिंग उद्योग की कुछ शाखाओं में भी साधारण भी सफलता मिली। 1906 में रेलों के राष्ट्रीयकरण के बाद सरकारी आदेशों के बढ़ने से रेल उपकरणों का उत्पादन भी बढ़ा। 1900 के बाद विजली का सामान तैयार करने वाले उद्योगों की भी प्रगति हुई क्योंकि देश में नये ताप व जल विद्युत गृहों का निर्माण किया जाने लगा था।

मेजी युग में कोयले का उत्खनन करने में भी काफी सफलता मिली। पुनर्संस्थापना के बाद कोयला निखालने की पाश्चात्य तकनीक शुरू की गई। पहले तो उत्पादन काफी कम रहा किन्तु 1894 के बाद वह तेजी से बढ़ गया। 1913 तक 100 खनिज कंपनियाँ घन चुकी थी जिनकी कुल प्रदत्त पूँजी 39 मिलियन यें थी तथा जिनमें 1.72 लाख मजदूर काम करते थे। 1913 तक जापान लगभग 3 मिलियन टन कोयले का निर्यात करने लगा था। अधिकांश कोयला कुछ बड़ी फर्मों द्वारा उत्पादित किया जाता था। इनमें भी अधिसह्य फर्म जैबत्सु (Zaibatsu) से सम्बद्ध थी। किन्तु कोयला उत्पादन के तरीके अधिक कार्यकुशलता वाले नहीं थे। 1913 में प्रति ध्रमिक कोयले का उत्पादन 123 टन ही था।

कोयना उत्पादन (वार्षिक औसत)

वर्ष	(मिलियन मैट्रिक टन)
1877—1884	0.8
1885—1894	2.6
1895—1904	8.0
1905—1914	16.8
1915	22.3

पुरानी नांवा खानों तथा तेल-शोधन कारखानों के पुनर्गठन से भी काफी लाभ प्राप्त हुए। 1914 तक जापान बिजली का दूसरा सबसे बड़ा तांत्रा निर्माता देश बन गया था। यह उद्योग भी कुछ बड़े औद्योगिक घरानों जैसे—कुहारा, मित्सुबिशी तथा फुजीत्सा के हाथों में सकेन्द्रित था। कुछ छोटे-छोटे खनिज उपक्रम भी थे किन्तु यह उद्योग सामान्य रूप से बड़े पैमाने पर ही चलाया जा रहा था।

तेल की ख़ुदाई एक ऐसा अन्य उद्योग था जिसका मेज़ी युग में तेज़ी से प्रसार हुआ। 1888 में जापान ऑयल कम्पनी की स्थापना के बाद इसका विकास काफी तीव्र हो गया। जापान में तेल ऑयल का उत्पादन 1887 के 33,000 बैरल (Barrel) की तुलना में 1893 में 1,00,000 बैरल हो गया तथा 1903 तक तो वह 12.5 लाख बैरल तक पहुँच गया।

रेल्वो, जहाज़ों, फैक्ट्रियों, बिजलीघरों तथा खानों के काम आने वाले उपकरणों का आयात किया जाना था क्योंकि जापान के इन्जीनियरिंग उद्योग की क्षमता सीमित थी। किन्तु इस काल में ही कुछ ऐसे इन्जीनियरिंग उद्योग स्थापित किये गये जो बाद के वर्षों में काफी महत्वपूर्ण बन गये। इनमें सबसे प्रमुख फर्म मित्रोवा इन्जीनियरिंग वर्क्स था जो 1887 में स्थापित किया गया। यह फर्म बिजली का मात्र-मापन तथा अन्य मशीनी उपकरण तैयार करती थी। एक अन्य फर्म टोक्यो इलेक्ट्रिक कम्पनी न बिजली के बल्ब बनाने में अग्रणी कार्य किया। फुजीकुटा इलेक्ट्रिक वायर कम्पनी माधारण तार व केबल बनाती थी तथा ओकी इलेक्ट्रिक कम्पनी टेम्पोफान व तार के उपकरण तैयार करती थी।

दशमवी सताब्दी के पहले दशक में विद्युत् शक्ति का प्रचार कार्यों के लिए उपयोग काफी बड़ गया। नये बिजलीघर बनाये गये तथा जापान ने अपनी जल शक्ति का उपयोग विद्युत्-उत्पादन के लिए करना आरम्भ कर दिया। 1907 में विद्युत्-उत्पादन 1.15 लाख किलोवाट था जो 1914 तक बढ़कर 7.16 लाख किलोवाट हो गया। बिजली का रोज़ानी कार्यों के लिये उपयोग बढ़ने से विद्युत् सामग्री तथा इन्जीनियरिंग उपकरणों की अन्य शायदाओं के विकास में भी तेज़ी आई। इन उद्योगों में विद्वानों पूँजी आकर्षित हुई। कई अमरीकी फर्मों ने उनके ही क्षेत्र में कार्यरत जापानी फर्मों के साथ सहयोग कर लिया। इन्जीनियरिंग उद्योग की प्रदत्त पूँजी (paid-up capital) 1893 के मात्र 2.6 मिलियन येन से बढ़कर 1903 में 14.6 मिलियन येन तथा 1913 में 61.1 मिलियन येन तक पहुँच गई। प्रथम महायुद्ध की पूर्व संध्या पर मशीनें, औज़ार, वाहन आदि के निर्माण में लगे हुए

उद्योगों में 60,000 से भी अधिक लोग कार्यरत थे। इस संख्या में वे लोग सम्मिलित नहीं थे जो जहाज-निर्माण के कार्य में लगे थे।

अन्य बड़े पैमाने पर उत्पादन करने वाले उद्योगों में, जिनकी जड़ें मेजी काल में ही जमी, सीमेंट, चीनी, काँच, बियर, कागज तथा रासायनिक उर्वरक जैसे उद्योगों का उल्लेख किया जा सकता है। इनमें से अधिसंख्य उद्योग जापान के महान् औद्योगिक घरानों द्वारा आरम्भ किये गये तथा राज्य ने भी उनकी सहायता की। पाश्चात्य तरीके के कागज का उत्पादन 1871 में ओजी कम्पनी के निर्माण से शुरू हो गया। कई अन्य फर्म भी स्थापित की गईं तथा 1913 तक कागज का उत्पादन 500 मिलियन पीण्ड के वार्षिक स्तर तक पहुँच गया।

नया बीयर उद्योग (Beer industry) शुरू से ही बहुत कम बड़ी फर्मों के हाथ में केन्द्रित था। सम्पूर्ण व्यवसाय पर जैबत्सु के नियन्त्रण वाली चार बड़ी फर्मों का नियन्त्रण था। चीनी उद्योग में विशाल पैमाने पर उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिये सरकार ने जैबत्सु को सहयोग दिया। मेजी काल के आरम्भिक वर्षों में सस्ती चीनी के आयात के कारण जापान का चीनी उद्योग प्रगति नहीं कर पाया था। हालाँकि फारमोसा पर अधिकार कर लेने से जापान को गन्ना उगाने के लिए उपयुक्त जमीन मिल गई थी किन्तु अभी भी जापानी चीनी उद्योग जावा की सस्ती चीनी से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहा था। घरेलू उद्योग को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार ने चीनी पर भारी आयात शुल्क लगा दिये व उसे अनुदान भी प्रदान किये। 1902 से 1913 के बीच चीनी का उत्पादन तिगुना हो गया। 1902 से घरेलू चीनी बाजार पर तब तक दाई निप्पन सैंतो कम्पनी का एकाधिकार सा रहा जब तक कि दो अन्य फर्म 1908 में प्रवेश नहीं कर गईं। किन्तु ये सभी विशाल फर्म सरकार की आर्थिक नीति के क्रियान्वयन हेतु अभिकर्ताओं का कार्य करती रहीं।

जापान सीमेंट उद्योग के विकास के लिए उपयुक्त था क्योंकि वहाँ चूने के पत्थर व कोयले के पर्याप्त भण्डार थे। 1871 में एक सरकारी सीमेंट मिल स्थापित की गई थी, किन्तु 1884 में उसे एक निजी उद्योगपति को बेच दिया गया। एक अन्य फर्म, ओनोदा सीमेंट कम्पनी भी 1880 के दशक में बनी। किन्तु सीमेंट उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि पश्चिमी पद्धतियों की शुरुआत के बाद ही सम्भव हो पायी। देश के औद्योगीकरण के साथ सीमेंट की माँग भी बढ़ी तथा इसका उत्पादन भी, जो 1896 में केवल 87,000 टन था, 1913 तक बढ़कर 6 45 लाख टन तक जा पहुँचा।

एक अन्य बड़े पैमाने का उद्योग, जो मेजी काल में जन्मा, काँच उद्योग था। यह उद्योग 1907 के बाद ही महत्वपूर्ण बना जब मित्रमुबिशी उद्योग घराने की पूंजी से आसाई ग्लास कम्पनी का पुनर्गठन किया गया। ग्लैस उद्योग की शुरुआत भी प्रथम महायुद्ध के पहले वाले दशक में ही हुई। चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने का उद्योग भी तेजी से विकसित हुआ। 1893 में इस उद्योग में लगभग 434 पॉटर (Potters) कार्यरत थे तथा लगभग 3,000 मजदूर इसमें लगे हुए थे। 1914 तक चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने वाले प्रतिष्ठानों की संख्या 5,540 हो गई तथा उसके एक-तिहाई

उत्पादन का निर्यात किया जाने लगा ।

मेजी काल के जापानी औद्योगिक विकास की सबसे असाधारण विशेषता यही थी कि जिन क्षेत्रों में सरकारी हस्तक्षेप न्यूनतम था उन क्षेत्रों में सर्वाधिक तेजी से प्रगति हुई । जापानी सूती वस्त्र उद्योग के विकास में इसलिये भी सहायता मिली कि देश में परम्परागत रूप से सस्ती दर पर सूती वस्त्र बनाने के लिए स्त्री श्रमिक उपलब्ध थे । जापानी अर्थव्यवस्था को बाहरी विश्व के लिए खोल दिये जाने का लाभ रेशम उद्योग को भी मिला जिसे यूरोप के देशों की तुलना में जापान में कुछ प्राकृतिक लाभ प्राप्त थे । रेशम लपेटने की कला तथा रेशम के कीड़ों की किस्म में भारी सुधार किये गये तथा सरकारी किस्म नियन्त्रण व्यवस्था ने रेशम को मेजी युग की सबसे बड़ी निर्यात मद बना दिया ।

मेजी काल के प्रारम्भिक वर्षों में जापान का परम्परागत सूती वस्त्र उद्योग इतनी बुरी स्थिति में था कि पुनर्संस्थापना के बाद के पहले दशक में किये गये कुल आयातों में 40% आयात तो सिर्फ सूती वस्त्र के रहे । यह स्थिति 1890 के बाद बदली तथा सूती तक़ुओं की संख्या 1887 के 77,000 से बढ़कर 1913 में 24 लाख तक जा पहुँची । न केवल सूती घागे तथा वस्त्र के आयात बन्द हो गये बल्कि जापान सूती वस्त्रों का एक प्रमुख निर्यातक देश बन गया । मेजी काल में ही जापान को ऊनी वस्त्रों का आयात भी प्रतिस्थापित करने में सफलता मिली ।

आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र के विकास के साथ-साथ मेजी युग में परम्परागत रूप से चलाये जाने वाले लघु उद्योगों का भी विकास हुआ । ये छोटे पैमाने पर चलाये जाने वाले उपक्रम जापानी उपभोक्ताओं की पसन्दगी तथा रहन सहन की आदतों का ख्याल रखते थे तथा आधुनिकीकरण की लहर भी उन्हें समाप्त नहीं कर सकी । मेजी युग के अन्त तक भी औद्योगिक मजदूरियाँ काफी नीची बनी रही । ऐसा इसलिए हुआ कि श्रम की पूर्ति उसकी माँग से काफी ज्यादा थी । उनकी रहने की दशाएँ भी अच्छी नहीं थी । एक बड़ी संख्या में महिला श्रमिक तथा अशकालिक वस्त्र मजदूर बड़ी दयनीय स्थिति में रहने के लिये बाध्य थे । इन औद्योगिक श्रमिकों को श्रम-संघ बनाने की अनुमति नहीं थी जो उनके अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ सके ।

(5) पाश्चात्य तकनीक व शिक्षा की शुरुआत—नव-स्थापित मेजी प्रशासन के सामने एक प्रमुख कार्य जापानी शिक्षा एवं तकनीक का पश्चिमीकरण (westernisation) करने की थी । पश्चिमी देशों की तकनीकों का प्रसार करने के लिए तथा जापानियों को प्रशिक्षित करने के लिए तकनीशियनों को विदेशों से बुलाया गया । रुढ़िवादी तोकुगावा शासन के अन्तर्गत जापान में न तो आधुनिक शिक्षा दी जाती थी और न ही वहाँ कोई विश्वविद्यालय था । आधुनिक दक्षताओं का निर्माण करने के उद्देश्य से सारी शिक्षा-प्रणाली का फिर से संगठन करना तथा उसे नये सिरे से तैयार करना आवश्यक था । यहाँ तक कि स्वर-व्यंजनों (alphabets) का भी सरलीकरण कर दिया गया ताकि साक्षरता तेजी से फैलाई जा सके । 1871 में शिक्षा के लिए अलग मन्त्रालय बनाया गया तथा 1872 में स्कूल प्रणाली कानून पारित

किया गया।

मेजी शासन के आरम्भ में पूरे जापान में शिक्षा व्यवस्था को समानोक्त किया गया। 1886 में चार वर्ष की स्कूली शिक्षा अनिवार्य कर दी गई तथा 1907 में इस अवधि को बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। 5 से 19 वर्ष की आयु के बच्चों की स्कूलों में भर्ती का औसत 1868 में केवल 10% था। मेजी युग के अन्त में इस आयु-वर्ग के 63% बच्चे स्कूली शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। जापान ने विशाल पैमाने पर शिक्षा का आयोजन पश्चिमी तरीके से नहीं किया क्योंकि उसमें बीच में पड़ाई छोड़ने वालों (drop outs) के कारण काफी अपव्यय होता था। जापान में जन-जन को जिज्ञासु करने का उद्देश्य यह था कि वे साक्षर होकर नई तकनीक फैलाने तथा राष्ट्रीय कृषि को सुधारने में महायत्न कर सकें। व्यावसायिक स्कूली शिक्षा पर अधिक बल दिया जाता था तथा आधुनिक विश्वविद्यालयों के साथ अनेक कृषि कॉलेज भी स्थापित किये गये। चिकित्सा, नौ परिवहन, सैन्य शास्त्र तथा मछली-पालन के क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए तकनीकी स्कूल खोले गये। प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करने हेतु टोक्यो में इम्पीरियल यूनिवर्सिटी खोली गई तथा अनेक नये शोध संस्थान भी खोले गये।

इन मेजी सुधारों के अनुवर्तन (follow-up) के रूप में सरकार ने अनेक युवा जापानियों को अध्ययन के लिए अनेक यूरोपीय देशों में भेजा। अनेक विदेशी विशेषज्ञों को भी मेना, नौ सेना, कानून प्रणाली, पुलिस तथा प्रशासन व उद्योग एवं कृषि तक को आधुनिक बनाने के लिए बुलाया गया। ये विदेशी विशेषज्ञ शिक्षा मन्त्रालय में सलाहकारों के रूप में रहते गये तथा इनका मुख्य कार्य नई शोध संस्थाएँ स्थापित करना था। महत्वपूर्ण विदेशी पुस्तकें तथा तकनीकी साहित्य का जापानी भाषा में अनुवाद करवाया गया। 1876 से 1895 के बीच लगभग 4,000 विदेशी विशेषज्ञ जापानी सरकार को अपनी सेवाएँ दे चुके थे। उन्हें उनके ही पदों पर कार्य करने वाले जापानियों से दस गुना वेतन दिया जाता था। इस अवधि में विदेशी विशेषज्ञों के रख-रखाव पर ही उद्योग मन्त्रालय के कुल बजट की 40 से 50 प्रतिशत रकम खर्च हो जानी थी। अनेक विदेशियों को व्यापारिक जहाजी बड़े पर भी अधिकारी बनाया गया। एक अनुमान के अनुसार, 1893 में वाप्यचालित जापानी जहाजों पर 722 विदेशी अधिकारी तैनात थे।

जापानी शिक्षा में भर्ती अनुपात (Enrolment Ratios) (1880-1963)

वर्ष	प्राथमिक व सेकेंडरी स्तर, आयु वर्ष की जनसंख्या का प्रतिशत (5-19 वर्ष)	उच्च सेकेंडरी वर्ग 15-19 वर्ष की आयु वर्ग के प्रतिशत के हिसाब में	हायर सेकेंडरी वर्ग 20-24 वर्ष की आयु की जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब में
1880	31	1	0.3
1915	63	21	1.3
1950	86	71	5.2
1963	94	92	10.2

Source : Research Section, Ministry of Education, Japan.

1868 से 1895 के बीच मेजी सरकार ने 600 विद्यार्थियों को पश्चिमी देशों में भेजा। विदेशी तौर-तरीके सीखने के लिए जापानी अधिकारी तथा व्यापारी लोग अक्सर विदेश-यात्राओं पर जात थे। 1868-95 के बीच लगभग 4,000 सरकारी अधिकारी विदेश गये। मेजी पुनर्स्थापना के प्रारम्भिक वर्षों में विदेशी तकनीशियनों को देश में बुलाने तथा जापानी नागरिकों को विदेश भेजने पर जो खर्च आता था वह केन्द्रीय बजट का 6 प्रतिशत था। इस सारी घेष्टा में महत्त्वपूर्ण तथ्य यह था कि अपनी अर्थव्यवस्था के तकनीकी उत्थान के लिए जापानी लोगो ने स्वयं भुगतान किया था और चूँकि वे इसके लिए धनराशि खर्च करते थे इसलिये वे यह भी देखते थे कि उनका यह व्यय बेकार न जाने पाये। इसके ठीक विपरीत आज के अधिकांश विकासोन्मुख देश, जिन्हें यह तकनीकी सहायता भेंट के रूप में मिलती है, उसका वे किस तरह अपव्यय करत हैं ?

(6) कृषि का काया पलट—जापान में बड़े पैमाने के उद्योगों की स्थापना उसके परम्परागत ढाँचे में एकदम स्पष्ट वैपश्य उपस्थित करती थी और इसीलिए उस तरफ बाहरी विश्व का ध्यान काफी आकृष्ट हुआ। किन्तु वह कृषि तथा छोटे पैमाने के उद्योगों का प्रसार ही था जिसने मेजी काल में राष्ट्रीय उत्पादकता एवं आय में अधिकांश वृद्धि की थी।

1873 के भूमि सुधारों ने भूस्वामियों तथा पुराने आसामियों को पट्टे दे दिये, भूमि की विक्री व उसका हस्तान्तरण मामन्ती प्रतिबन्धों से मुक्त कर दिया तथा भूमि के मूल्य का 3% करों के रूप में लेने की व्यवस्था की। 1878 में इस भूमि कर को घटाकर 2.5% कर दिया गया तथा उस पर लगने वाले सरचार्ज को भी 30% में घटाकर 20% कर दिया। यह कर फसल का लगभग एक-चौथाई पड़ता था। इस भारी भूमि-कर का उपयोग पुराने भूस्वामियों को मुआवजे देने तथा नये प्रशासन को चलाने में किया जाता था। 1868-80 की अवधि में भूमि-कर केन्द्रीय प्राप्तियों का 80% भाग प्रदान करता था। प्रथम महायुद्ध के समय भी भूमि-कर का कुल आगम में 33% भाग था। इस तरह जापान के आधुनिकीकरण का अधिकांश भार उसके कृषि-क्षेत्र ने ही वहन किया था।

नये भूमि-कर पुराने मामन्ती करों से कम भारी थे किन्तु उनका भुगतान नकद में करना पड़ना था तथा प्रत्येक वर्ष एक बँधी-बँधाई धनराशि देनी होती थी। ऊँचे करों के भार तथा कृषि के व्यवसायीकरण होते चले जाने से मेजी युग के प्रारम्भ में आसामियों की संख्या काफी बढ़ गई। 1910 तक खेती कर रहे 39% किसानों के पास बिल्कुल भी जमीन नहीं थी। आसामी प्रथा (tenancy) के अन्तर्गत भूमि का अनुपात 31% (1872) से बढ़कर 1914 में 46% हो गया था। मेजी युग की समाप्ति तक केवल 33% किसान ही उनकी भूमि के मालिक रह गये थे। कृषि जनसंख्या का आकार मेजी युग में लगभग स्थिर ही रहा तथा औसत सेत 1 हेक्टेयर से कुछ कम का था। भूमि के अभाव की जापानी परिस्थिति में अधिक बड़े खेत लाभकारी नहीं थे। फिर लगान की दरें भी काफी ऊँची थीं। अतः आधारभूत इकाई पारिवारिक फार्म ही रहे।

किन्तु एक सीमित भूखण्ड पर लोगो की भीड़ बढ़ जाने से कृषि में कम उत्पादकता की निरन्तरता बनी रही। कृषि मशीनें तो नहीं के बराबर थी। बाढ़ी से अधिक भूमि तो पशुओं तक के बिना जोती जाती थी। छोटे किसानों की दशा में सुधार साख के अभाव में भी अवर्द्ध हो जाते थे। ब्याज की दर 20% या उससे भी ऊँची थी। किसान लोग सर्वाधिक बर देते थे। एक अनुमान के अनुसार 1908 में जहाँ किसान लोग अपनी आय का 28% भाग करों के रूप में दे देते थे वहीं एक उद्योगपति या व्यापारी अपनी आय का 14% ही करों के रूप में देता था।

1894 से 1914 की अवधि में खाद्य उत्पादन में 40% की वृद्धि रिकॉर्ड की गई। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्त्व को देखते हुए यह वृद्धि पर्याप्त महत्त्वपूर्ण थी। आंशिक रूप से यह धीमी गति से कृषि क्षेत्र बढ़ने का परिणाम थी। खाद्य उत्पादन में यह वृद्धि आंशिक रूप से अधिक खाद अच्छी साख सुविधाओं तथा गहन खेती के कारण भी हुई। फसलों के प्रारूप में विशेष परिवर्तन नहीं आया। लगभग 55% कृषि-क्षेत्र पर अब भी चावल बोया जाता था जिसे किसान परिवार छोटे-छोटे खेतों पर हाथों के श्रम में ही पैदा करते थे। हालांकि चावल का उत्पादन ही किसानों की आय का प्रमुख स्रोत था किन्तु किसान लोग अपनी आय में उद्योगों व सहायक सेवाओं के जरिये भी वृद्धि करने लग गये थे।

मेजी युग के जापान में कृषि उत्पादन में होने वाली वृद्धि की दर को लेकर कुछ परस्पर विरोधी अनुमान लगाये गये हैं। यदि हम सरकारी अनुमानों को मान लें तो 1874 से 1913 के बीच कृषि उत्पादन में 2% की वार्षिक वृद्धि हुई। नाकामुरा द्वारा लगाये गये एक अन्य अनुमान के अनुसार यह वृद्धि दर 0.8% से लेकर 1.2% वार्षिक के बीच रही।

निजी सम्पत्ति के लिए एक निश्चित सम्मान भूमि बेचने के लिए नई स्वतन्त्रताएँ फसलों का स्वरूप बदलने तथा नौकरी बदलने की छूटों आदि ने मिलकर मेजी काल में कृषि उत्पादकता में सुधार करने में सहायता की। नये बरों की एक अच्छाई यह रही कि हालांकि वे भारी थे, किन्तु कम से कम निश्चित अवश्य थे। वे उत्पादन के साथ बढ़ते नहीं थे जैसा कि तोकुगावा काल में होता था।

नई जापानी सरकार ने तकनीकी परिवर्तनों का प्रचार-प्रसार करने में भी काफी रुचि ली। जापानी भूमि पर पश्चिमी कृषि तकनीक लागू करने के आरम्भिक प्रयास असफल रहे। तब थोड़े परम्परागत कृषि तकनीकों को फैलाने का काम प्रचार-प्रसार माध्यम से किया जाने लगा। 1885 में अनुभवों, किमानों तथा नये मॉडल गैज कृषि कल्लेजों के स्नातकों को गाँवों में विस्तार-सेवा कार्य के लिए भेजा गया। रात्रि बशाएँ चलाई गईं। 1893 में प्रत्येक प्रिफेक्चर (prefecture) में अनुसन्धान मस्थाएँ तथा प्रयोग केन्द्र खोले गये। इन प्रयोग केन्द्रों का एक दायित्व विस्तार सेवा कार्य-वर्त्तियों को सलाह देने का भी था। व्यापक साक्षरता के कारण विस्तार सेवा प्रकाशित पैम्फलेटों तथा निर्देशों द्वारा भी सम्भव बन गई। नई तकनीकें आसानी से लोकप्रिय बन गईं क्योंकि किसान लोग घनी वस्तियों में नजदोश-नजदीक रहते थे।

ब्रिटिश तथा अमरीकी विशेषज्ञों को जांचने के बाद जापानी दशाओं में उपयुक्त

रसायनों व खादों के बारे में सुझाव हेतु जर्मन विशेषज्ञ बुलाये गये। कृषक संगठनों तथा सभाओं को सरकार द्वारा तकनीक के आदान-प्रदान तथा बीजों की अदला-बदली की दृष्टि से प्रोत्साहित किया गया। 1900 के बाद सहकारी संस्थाओं की भी स्थापना की गई।

मेजी काल में कृषि उत्पादन में वृद्धि के कारणों में तीन कारण प्रमुख रहे। भूमि का अधिक विवेकपूर्ण उपयोग, बीजों में सुधार, तथा खादों का वृद्धिगत उपयोग। 1878 से 1913 के बीच फॉस्फेट खादों का उपयोग सात गुना बढ़ गया। 1880 से 1915 के बीच कृषित धेन में भी 30% की वृद्धि हुई। अनेक तकनीकी नव-प्रवर्तनों ने भी कृषि उत्पादन बढ़ाने में सहायता की। कृत्रिम सेने (artificial incubation) की प्रक्रिया ने रेशम के कीड़ों का शीत ऋतु तथा गर्मी दोनों ही मौसम में उत्पादन सम्भव बना दिया। सूखी धान खेती से एक ही वर्ष में दो फसलें उगाई जा सकती थी। छोटे जापानी खेतों के लिए एक नये किस्म का हल बनाया गया। घोड़ों, भेड़ों, सूअरों व अन्य कृषि कार्य के पशुओं की नस्ल सुधारने के लिए 1867 के बाद से सरकार ने विदेशी पशु जातियों (foreign strains) का आयात किया। सरकार ने पशु-पालन पर प्रचार सामग्री छपवाकर वितरित कराई। कुछ विवादास्पद बातों के होते हुए भी मेजी कृषि द्वारा प्राप्त की गई सफलताएँ प्रभावशाली रही। केवल 4% विनियोग के बावजूद कृषि से सरकारी आगम का एक प्रमुख भाग, अच्छी मात्रा में बचत तथा विदेशी मुद्रा प्राप्त होती थी। इसके अलावा जनसंख्या को खाद्य पदार्थ उपलब्ध होते थे।

(7) बृह प्रशासन का अभ्युदय—अर्थव्यवस्था को पुनरुज्जीवित करने के लिए एक मुख्य शर्त सुदृढ़ प्रशासन स्थापित करने की थी जो जापान को एक आधुनिक राज्य तथा सैनिक शक्ति बनाने पर कटिबद्ध हो। नई सरकार ने सादगी व कठिन परिश्रम की परम्परा को और मजबूत बनाया। निजी तथा सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को नई भूमिकाएँ प्रदान करने तथा नई तकनीक को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार ने लचीली एवं व्यावहारिक नीति अपनायी। प्रसन्नता की बात यह रही कि जापान में आर्थिक विकास की नीति का धार्मिक या वैचारिक धरातल पर कोई विरोध नहीं था। प्रारम्भ से ही सरकार आर्थिक विकास का एक गतिशील तत्त्व बन गई। अन्य देशों से तुलना करने पर जापान में सरकार द्वारा किया गया विकास खर्च तथा एकत्रित कर राशि सर्वाधिक थी।

जापानी सरकार अपने यहाँ की अर्थव्यवस्था के उद्धार में अन्य यूरोपीय देशों की सरकारों से अधिक सक्रिय भूमिका निभा रही थी। जैसा कि तालिका से स्पष्ट है, 1913 में, इटली को छोड़कर सरकार का चालू खर्च (current expenditure) जापान में सर्वाधिक था। 1880 में जापानी अर्थव्यवस्था में सरकारी खर्च कुल राष्ट्रीय उत्पाद (G N P) का दस प्रतिशत के लगभग पहुँच चुका था। अर्थव्यवस्था में हो रहे पूँजी-निर्माण में भी सरकार का भाग लगभग 40% था। यह भारी सरकारी खर्च अश्वत्थ तो सैनिक व्यय के कारण था जो कि चीन तथा रूस के साथ हुए युद्धों के बाद निरन्तर बढ़ता ही जा रहा था।

राष्ट्रीय उत्पाद (G N P.) के अनुपात के रूप में चालू सरकारी खर्च : 1870-1965

देश	1870	1913	1938	1965
कनाडा	46	81	109	138
जर्मनी	59	87	231	155
डेन्मार्क	—	—	93	154
इटली	81	97	157	147
जापान	68	91	250	193
नार्वे	38	63	99	170
स्वीडन	47	56	104	193
इंग्लैंड	49	70	130	167
अमरीका	37	42	101	174
सोवियत रूस	—	—	216	230

Source A Maddison, *Economic Growth in Japan and the U S S R*, 1969, 13

(8) वित्तीय स्थायित्व की ओर—मेजी शासन काल के पहले कुछ वर्षों में नई सरकार को गम्भीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। सरकार द्वारा किये गये बड़े-बड़े बायदों की तुलना में उसकी प्राप्तियाँ बहुत नीची रही। बजट में भारी घाटे चलते रहे तथा सरकार को बड़े-बड़े बर्ज लेने पड़े। पत्र-मुद्रा भारी मात्रा में जारी की गई व सरपट दौड़ती हुई स्फीति पैदा हुई। एक केन्द्रीय बैंक की स्थापना करने के स्थान पर 1872 में जापानी सरकार ने अमरीका में उस समय प्रचलित नेशनल बैंक व्यवस्था चालू की। 1876 तक इन नेशनल बैंकों के नोट जारी कर सकने के अधिकार बहुत बढ़ा दिये गये। 1876 से 1880 के बीच 148 नये नेशनल बैंक खोले गये जिनसे मुद्रा-स्फीति को और बढ़ावा मिला।

1881 से 1885 तक वित्तमन्त्री वाउन्ट मत्सुकाता ने सफलतापूर्वक स्फीति पर नियन्त्रण लगाने व लिए एक विस्फीतिकारी नीति अपनायी जिसके अन्तर्गत नये कर लगाये गये व सरकारी खर्च को कम किया गया। उसने जापानी निर्यातों को अधिक स्पर्धात्मक बनाने व भी प्रयास किये। मत्सुकाता न आर्थिक विधाम के आधार के रूप में सत्पायत ढाँचा भी अत्यधिक मुद्ब करने की योजना बनाई। मत्सुकाता के ही कार्यकाल में 1882 में बैंक ऑफ जापान की एक केन्द्रीय बैंक के रूप में स्थापना की। अपने दूसरे कार्यकाल में उसने 1897 में हाइपोथेक बैंक (Hypothec Bank) की भी स्थापना की जिसका कार्य कृषि विकास तथा उद्योग खोलने में सहायता करने वाले विभिन्न बैंकों को वित्त उपलब्ध कराना था।

उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम दो दशक जापान में वित्तीय स्थायित्व की स्थापना करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहे। मौद्रिक प्रणाली इतनी स्थायी बन चुकी थी कि वह चीन तथा रूस के साथ युद्धों से पैदा हुए दबावों को भी सहन कर सकी। जापान की इस नई वित्तीय स्थिरता को 1894-95 के चीन-जापान युद्ध में

परीक्षा के दौर से गुजरना पड़ा। युद्ध की पूर्व संध्या पर जापान का वार्षिक सरकारी खर्च लगभग 80 मिलियन येन था। किन्तु केवल युद्ध का ही खर्च 200 मिलियन येन आया जिसे 117 मिलियन येन भूतल्य के आन्तरिक बॉण्ड जारी करके पूरा किया गया। शेष व्यय को चीन से प्राप्त हरजाने की रकम (indemnity) से पूरा किया गया। इस सम्बन्ध में असाधारण बात यह रही कि न तो करो में वृद्धि करनी पड़ी और न ही राष्ट्रीय ऋण-भार में कोई विशेष वृद्धि हुई।

1905 में हुए रूस के साथ युद्ध में जापान को 1,500 मिलियन येन खर्च करने पड़े। यह व्यय प्रमुख रूप से विदेशी कर्जों द्वारा प्राप्त किया गया हालांकि करो में भी वृद्धि की गई व आन्तरिक बॉण्ड भी जारी किये गये। 1894 से 1907 के बीच राष्ट्रीय ऋण-भार बढ़कर सात गुना हो गया तथा वह 2,244 मिलियन येन के स्तर तक पहुँच गया।

साधारण आगम (Ordinary Revenue)

वर्ष	(000 मिलियन येन)
1893—1894	85 8
1903—1904	224 4
1906—1907	392 5

महायुद्ध के पहले के 20 वर्षों में जापानी लोकवित्त की तीन प्रमुख विशेषताएँ थी¹ पहली, वार्षिक खर्च में भारी वृद्धि, दूसरी, राष्ट्रीय ऋण-भार में वृद्धि, तथा तीसरी, विदेशी पूँजी का भारी आयात। जापान द्वारा अपने ससाधनों को अपनी राष्ट्रीय शक्ति के विकास हेतु तेजी से विनसित करने के ये स्वाभाविक परिणाम थे। वृद्धिगत व्यय तथा ऋण राशि का उपयोग मुख्य रूप से युद्धों में, अस्त्र-शस्त्रों के लिए तथा राष्ट्रीय महत्त्व के उद्योगों की स्थापना के लिए किया गया। लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की इस भाग दौड़ ने उनकी वित्तीय क्षमताओं पर गहरा दबाव डाला तथा 1914 तक जापान अपने लिये विदेशी साख पा सकने की अन्तिम सीमा तक पहुँच गया।

नोट निर्गमन

(मिलियन येन में)

वर्ष	सरकारी पत्र-मुद्रा	नेशनल बैंक नोट	बैंक ऑफ जापान के नोट
1881	119	34	—
1815	93	30	4
1890	40	26	103
1895	16	22	111
1900	5	2	180

¹ G C Allen *op cit*, 45

जब हम इस अवधि की जापान की पत्र-मुद्रा के इतिहास पर दृष्टि डालते हैं तो हम पाने हैं कि 1881 में मुख्य वित्तीय उद्देश्य अपरिवर्तनीय पत्र-मुद्रा से मुक्ति दिलाना तथा पर्याप्त निधि की सुरक्षा रखते हुए एक एकीकृत नोट-निर्गमन प्रणाली स्थापित करना थे। इन्हीं उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए मार्च 1882 में काउंट मत्सुकाता ने तुरन्त एक केन्द्रीय बैंक की स्थापना पर बल दिया था। उसने नेशनल बैंको की उनके बीच आपसी सहयोग के अभाव तथा पत्र-मुद्रा के अत्यधिक जारी करने व उसका असमान वितरण करने के दोषों के कारण आलोचना की। उसने घोषणा की कि राज्य की वित्तीय गतिविधियों का समन्वयन करने के लिए एक केन्द्रीय बैंक आवश्यक है। नेशनल बैंको को अपनी निधियाँ बैंक ऑफ जापान को सौंप देने के लिए कहा गया। 1899 तक सरकारी पत्र-मुद्रा का भी उद्धार (redeemed) कर दिया गया तथा 1904 तक अन्तिम नेशनल बैंक नोट का भी उद्धार हो गया।

इस बीच मत्सुकाता लगातार इस सिद्धान्त को व्यावहारिक रूप प्रदान करने पर बल दे रहा था कि एक स्वस्थ वित्तीय व्यवस्था में विशिष्ट कार्य करने के लिए अलग-अलग बैंको की स्थापना जरूरी है। उदाहरण के लिए कृषि एवं उद्योग को दीर्घकालिक ऋण प्रदान करने, गरीब लोगों की बचत का गतिशीलन करने, विदेशी लेन-देन करने तथा धरेलू व्यावसायिक कार्यकलापों के लिए अलग-अलग बैंक स्थापित किये जाने थे। इन विशिष्ट बैंको में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योकोहामा स्पीसी बैंक 1880 में स्थापित किया गया।

पत्र-मुद्रा के स्थिरोत्करण, केन्द्रीय बैंक की 1882 में स्थापना तथा एक विदेशी मुद्रा बैंक खोल चुकने के बाद काउंट मत्सुकाता का अगला कदम दीर्घकालिक ऋण प्रदान करने वाली वित्तीय संस्थाओं का निर्माण करना था। ऐसी एक संस्था का उल्लेख हम पहले ही कर चुके हैं जो फ्रांस के साख बैंक के सदस्य बनायी गयी तथा 10 मिलियन येन की पूंजी से शुरू की गई। इस संस्था का नाम हाइपोथेक बैंक ऑफ जापान था। प्रत्येक प्रिफेक्चर (Prefecture) में स्थापित 46 कृषि एवं औद्योगिक बैंक भी इसी प्रकार का कार्य करने के लिए बनाये गये। जापान का औद्योगिक बैंक 1900 में स्थापित किया गया। मेजी सरकार ने तो अपने उप-निवेशों, ताइवान व कोरिया, में भी बैंको की स्थापना की। 1899 में उपनिवेशन (colonisation) के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु होक्केइडो कोलोनिअल बैंक खोला गया।

इन विशिष्ट बैंको को सरकार व सम्राट द्वारा पूंजी उपलब्ध कराया जाता था तथा उन पर बड़ा सरकारी नियन्त्रण रहता था। ये न केवल सरकार के माध्यमिक वित्तीय सम्बन्ध रखते थे बल्कि जैबत्सु (Zaibatsu) की महान् वित्तीय संस्थाओं से भी उनका सम्पर्क था। मेजी काल की एक अन्य महत्वपूर्ण वित्तीय संस्था डिपॉजिट्स ब्यूरो थी जो 1877 में खोली गई थी। यह ब्यूरो छोटी बचतें जमा करता था। 1914 में इसमें 12 मिलियन जमाकर्ताओं ने अपनी 189 मिलियन येन की राशि जमा कराई हुई थी।

जापान में मेजी युग में हुई वित्तीय प्रान्ति वेवज सरकारी संस्थाओं तक ही

सीमित नहीं थी। कुछ पुरानी किस्म के साहूकारी घरानों (Money lending houses) ने भी पुनर्संस्थापना के बाद अपना पुनर्गठन कर लिया तथा वे आधुनिक व्यावसायिक बैंकों के रूप में फलने-फूलने लगे। अनेक नेशनल बैंकों को भी निजी व्यावसायिक बैंकों के रूप में पुनर्गठित किया गया। 1901 तक देश में 2,359 पृथक् बैंकिंग फर्मों थीं जिनकी कुल जमाएँ 516 मिलियन येन हो चुकी थी।

मेजी युग के दौरान जापान में जो एक विशिष्ट प्रकार की बैंकिंग प्रणाली विकसित हुई वह वहाँ की अर्थव्यवस्था के स्वभाव तथा राज्य की आर्थिक नीति का मिला-जुला परिणाम थी। विशेष बैंक तो सरकारी तन्त्र का ही भाग थे। बैंक ऑफ जापान का कार्य मुद्रा-प्रणाली में सुधार करने व उस पर नियन्त्रण रखने का था। दूसरे, जापान अपनी सैनिक क्षमता बढ़ा रहा था जिसके लिए उसे भारी मात्रा में साज-सामान का आयात करना था। योकोहामा स्पीसी बैंक का गठन मुख्य रूप से इसी कार्य के लिए किया गया। तीसरे, क्योंकि जापान में विनियोगकर्ताओं का कोई विशिष्ट वर्ग नहीं था इसलिए एक बैंको का समूह गठित किया गया जिसका कार्य राष्ट्रीय महत्व के बड़े पैमाने के उद्योगों को वित्त प्रदान करना था। अन्त में, डिपॉजिट्स ब्यूरो जैसी संस्थाएँ निर्धन लोगों की बचतें एकत्रित करने के लिए बनायी गयी थी।

किन्तु कार्यों के बारे में ये बारीक अन्तर तथा विशिष्टीकरण के सिद्धान्त व्यवहार रूप में नहीं चल पाये। व्यावसायिक बैंकिंग तथा औद्योगिक बैंकिंग के बीच कार्य विभाजन पूरी तरह प्राप्त नहीं हुआ। जापानी जनता अपनी जमाओं को साधारण बैंकों में सावधि बचत (Fixed Deposit) जमाओं के रूप में रखना पसंद करती थी और ये बैंक इस रुपये को औद्योगिक फर्मों में लगाते थे। इससे कुछ प्रमुख व्यावसायिक घरानों की वित्तीय शक्ति काफी बढ़ गयी, क्योंकि वे अपने नियन्त्रण वाले बैंकों से धनराशि प्राप्त कर सकते थे। सरकार इस खतरे को महसूस करती थी किन्तु वह कुछ भी करने की स्थिति में नहीं थी क्योंकि आपातकाल में वह स्वयं इन्हीं बड़े वित्तीय समूहों पर निर्भर करती थी। 1894-95 तथा 1904-05 के मध्य सरकार द्वारा जारी किये गए युद्ध बॉण्ड (War Bonds) केवल चार बड़े औद्योगिक घरानों की सिडीकेटों ने ही खरीदे थे। बैंक ऑफ जापान की साधारण बैंको को नियन्त्रित कर सकने की असमर्थता का परिणाम यह रहा कि देश के स्वर्ण भण्डार गिरते चले गये।

(9) विदेशी व्यापार में तीव्र वृद्धि—1890 के पहले जापान का विदेश व्यापार नगण्य सा था। लेकिन 1881 से 1914 के बीच उसमें दस गुनी वृद्धि हुई। 1881 से 1893 तक लगभग प्रत्येक वर्ष व्यापार सन्तुलन जापान के पक्ष में रहा किन्तु चीन-जापान युद्ध के बाद भारी मात्रा में आयात किये गये जिनसे दृश्य व्यापार सन्तुलन अत्यधिक विपरीत हो गया। सम्पूर्ण मेजी काल निर्यातों में सर्वाधिक भाग अर्द्ध विनिर्मित माल का रहा। इस अवधि में निर्यात व्यापार में प्रवेश करने वाली सर्वप्रमुख विनिर्मित मर्चें रेशम की बनी चीजें व दिवामलाइयाँ रही।

औद्योगीकरण ने परिणामस्वरूप सूती धागे का बड़े पैमाने पर बाजार निर्मित

हो गया तथा सूती चीजों का निर्यात भी छोटे स्तर पर आरम्भ हो गया । 1900 तक सूती व रेशमी वस्त्र कुल निर्यातों में 22% तक पहुँच चुके थे । कोयले तथा तंबाकू का महत्व अपरिवर्तित ही रहा जबकि चाय, चावल तथा अन्य कृषि पदार्थों के निर्यात में कमी आयी । निर्यातों में 1900 से 1913 के बीच तीव्र वृद्धि हुई । 1913 में सूती एवं रेशमी वस्त्रों के निर्यात से 30% आय प्राप्त हुई । खनिज एवं कृषि पदार्थों के निर्यात, जो उन्नीसवीं शताब्दी में इतने महत्वपूर्ण थे, इस अवधि में काफी घट गये ।

आयात व्यापार में भी परिवर्तन देखे जा सकते थे । 1880 में आर्थिक लक्ष्मण आयात विनिर्मित वस्तुओं के होते थे । 1913 तक तैयार विनिर्मित माल के आयात कुल व्यापार का 20% रह गये । 1913 में लगभग एक-तिहाई निर्यात कच्ची रूई व ऊन के थे । दूसरी ओर सूती धागे व सूत की बनी हुई वस्तुओं के आयात इस समय तक काफी कम हो चुके थे । इस परिवर्तन से यही संकेत मिलता था कि देश में सूती वस्त्र उद्योग काफी विकसित हो चुका था तथा देश विनिर्माण व्यवसाय (Manufacturing trade) स्थापित करने की दिशा में काफी आगे बढ़ चुका था । वास्तव में, मेजी युग की समाप्ति तक, जापान विदेश के अग्रणी विनिर्मित माल बनाने वाले तथा निर्यातक देशों की पंक्ति में आ चुका था ।

जापान के आयातों व निर्यातों के क्षेत्र में मेजी काल में हुए कायापलट से ही यह आभास होता है कि कितने नाटकीय एवं दृढ़ रूप से जापान में आधुनिक उद्योग का विकास हो चुका था ।

मुख्य निर्यात श्रेणियाँ

(प्रतिशत में)

वर्ष	खाद्य पदार्थ	कच्चे माल	विद्यार्थिन कच्चे माल	तैयार माल	सुदरा चीजें	कुल
1877	38.5	8.3	45.8	2.7	4.6	100
1887	26.3	10.9	45.4	13.5	3.9	100
1893	20.5	10.5	40.8	24.5	3.8	100
1897	12.9	10.3	50.8	23.0	2.9	100
1903	11.9	10.5	47.2	27.9	2.4	100
1911	11.6	9.0	47.6	30.7	1.1	100
1913	9.8	8.1	51.9	29.2	0.9	100
1921	6.4	6.3	43.9	41.8	1.5	100

मुख्य आयात श्रेणियाँ

(प्रतिशत में)

वर्ष	खाद्य पदार्थ	कच्चे माल	विधायित कच्चे माल	तैयार माल	सुदरा चीजें	कुल
1877	12.7	3.7	24.1	56.0	3.5	100
1887	17.8	5.2	30.1	44.4	2.6	100
1893	23.1	21.6	19.7	33.1	2.5	100
1897	24.4	24.4	16.6	33.4	1	100
1903	32.6	30.9	13.6	21.5	1.4	100
1911	10.0	45.0	19.5	24.6	0.7	100
1913	16.5	48.5	17.4	17.0	0.5	100
1921	12.9	46.9	25.1	19.2	0.8	100

Source Kamekichi Takahashi, *The Rise and Development of Japan's Modern Economy*, 1969, 354

उपर्युक्त आँकड़े विधायित कच्चे माल व तैयार माल के आयातों में वृद्धि तथा निर्यातों में कमी की प्रवृत्ति को स्पष्ट करते हैं। विशेष रूप से तैयार माल के आँकड़ों से विनिर्माण उद्योग की प्रगति का पता चलता है।

मेजी काल में समग्र आर्थिक विकास

पुनर्स्थापना के बाद का पहला दशक अशांत रहा इसलिए उसके बारे में कोई विश्वस्त आँकड़े उपलब्ध नहीं होते। 1879-1913 की अवधि के लिए प्रकाशित नवीनतम अनुमानों के अनुसार जापान की इस अवधि की औसत वार्षिक विकास दर 3.3% रही। ओहकावा व रोसोवस्की (Ohkava and Rosovsky) ने अनुमान लगाया है कि इस अवधि में कृषि उत्पादन 2% से बढ़ा जबकि औद्योगिक उत्पादन में 5.5% की वार्षिक वृद्धि हुई। किन्तु जापानी अर्थव्यवस्था के कुछ विदेशी पर्यवेक्षक इन अनुमानों को बढ़ा-चढ़ा कर बताये गये अनुमान मानते हैं। एंगस मैडिसन (Angus Maddison) ने समग्र आर्थिक विकास की जापानी दर 2.7% के आस-पास रहने का अनुमान लगाया है।

15 देशों के कुल राष्ट्रीय उत्पाद (G N P) की वृद्धि दरें, 1870-1913

(वार्षिक औसत चक्रवृद्धि विकास दरें)

1	अमरीका	4.3	9	सोवियत संघ	2.5
2	कनाडा	3.8	10	रिबटजरलैण्ड	2.4
3	ऑस्ट्रिया	3.3	11	नार्वे	2.2
4	डेनमार्क	3.2	12	इंग्लैण्ड	1.9
5	स्वीडन	3.0	13	नेदरलैण्ड	1.9
6	जर्मनी	2.8	14	फ्रांस	1.6
7	बेल्जियम	2.7	15	इटली	1.4
8	जापान	2.7		औसत	2.6

ऊपर लिखे गए आँकड़ों से तो यही स्पष्ट होता है कि मेजी जापान में आर्थिक विकास की दर अन्य अनेक पश्चिमी देशों की उसी अवधि की विकास दरों से अधिक नहीं थी। किन्तु जापान ने आधुनिक आर्थिक विकास की नींव डाल दी थी जिससे उसे आगे के वर्षों में नेतृत्व प्राप्त करने में सहायता मिली।

जब हम इन आँकड़ों की तुलना अन्य पड़ोसी एशियाई देशों से करते हैं तो मेजी जापान की उपलब्धियाँ अद्वितीय दिखाई देती हैं। जापान ने स्वयं को उपनिवेशों के लबादे से मुक्त रखा तथा बँकिंग, विदेश व्यापार और तटकर के क्षेत्र में भी सारे विदेशी हस्तक्षेप दूर कर दिये। अनेक पूँजी प्रदान करने वाली संस्थाओं का जाल बिछा दिया गया। जापान ने अपना केन्द्रीय बैंक 1882 में ही स्थापित कर लिया था जबकि अधिकांश पड़ोसी एशियाई देशों में यह कार्य उसके 50 वर्ष बाद ही किया जा सका था।

1913 तक जापानी अर्थव्यवस्था की इस असाधारण प्रगति के लिए दो मुख्य तत्त्व उत्तरदायी रहे (i) आर्थिक विकास को सरकार का सक्रिय समर्थन जिसमें संस्थागत सुधारों के रूप में किये गये महान् प्रयास, शिक्षा व तकनीक का विकास तथा क्रांतिकारी मौद्रिक एवं राजकोषीय परिवर्तन सम्मिलित हैं। (ii) एकदम बन्द अर्थव्यवस्था (closed economy) को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खोल दिया जाना जिसके तकनीकी लाभ तथा विशिष्टीकरण की मितव्ययताएँ जापानी अर्थ-व्यवस्था को प्राप्त होने शुरू हो गये। जापान की सबसे प्रभाव डालने वाली बात उसके द्वारा उपभोग पर लगाये गये प्रतिबन्ध रहे। मेजी युग में जापान में विनियोग की दर कई यूरोपीय देशों से ऊँची रही। कुल राष्ट्रीय उत्पाद के प्रतिशत के रूप में घरेलू पूँजी-निर्माण की दर 1887 से 1913 तक 9.1% रही तथा इस अवधि में सरकारी व्यय उसका 12.4 प्रतिशत के लगभग रहा।

मेजी जापान की एक असाधारण बात यह रही कि उसने एक ऐसी तकनीक तैयार करने में सफलता पायी जो उसकी घटिया भूमि तथा थम अतिरेक वाली अर्थ-व्यवस्था के लिए उपयुक्त थी। कई गलतियाँ भी हुईं तथा इस तकनीक की तलाश में धन का अपव्यय भी हुआ किन्तु अन्त में इस तकनीक का इलाज करने में मेजी शासन सफल रहा। कृषि में सुधार तोकुगावा शासन के कार्य को आगे बढ़ाने के ही रूप में रहे किन्तु एक सुदृढ औद्योगिक आधार के निर्माण का कार्य ऐसा था जो केवल मेजी काल में ही आरम्भ हुआ तथा जिसन दोनों महायुद्धों के बीच के काल में अनपेक्षित ऊँचाइयाँ प्राप्त कर ली।

तीसरा अध्याय

आर्थिक विकास की अवस्थाएँ

(STAGES OF ECONOMIC DEVELOPMENT)

अपनी भौगोलिक स्थिति व अपनी पृथक्तावादी नीति (Policy of Isolation) के कारण जापान पश्चिमी देशों के सम्पर्क में आने वाले 19वीं सदी के अफ्रेशियाई देशों में अन्तिम देश था। जब अन्तिम रूप से जापान पश्चिम के सम्पर्क में आया तो वह एक अत्यन्त निर्धन एवं कमजोर देश था। और उसके बाद, पिछले 110 वर्षों में वह विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली आर्थिक देशों की श्रेणी में आ चुका है। जापान का कुल राष्ट्रीय उत्पाद दुनिया में अब तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उत्पाद है तथा आज वह जहाज-निर्माण, इस्पात विनिर्माण, मोटरकार उत्पादन तथा कृषि-वस्त्र उत्पादन के क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व कर रहा है। आखिरकार इतने कम समय में जापान ने इतनी महान् प्रगति किस प्रकार की ?

आम बोलचाल में जापान के विकास को 'चमत्कारिक' कहा जाता है, किन्तु वास्तव में, ऐसा कोई चमत्कार नहीं हुआ है।¹ सच तो यह है कि यह विकास पिछले सौ से भी अधिक वर्षों में किये गये जापानियों के अथक् प्रयत्नों का परिणाम है। समय के साथ-साथ इन प्रयत्नों के फल प्राप्त होने लगे। जापान वास्तव में एक विनिर्माण राष्ट्र (manufacturing country) तो प्रथम महायुद्ध के छिड़ने के समय ही बन पाया था और इस उपलब्धि तक पहुँचने से पहले जापान को अपनी कमजोर कृषि-प्रधान अर्थव्यवस्था को एक विनिर्माण प्रधान अर्थव्यवस्था में बदलने हेतु एक अत्यन्त कठिन संक्रमण काल से गुजरना पड़ा था।

जापानी आर्थिक इतिहास के एक सुप्रसिद्ध लेखक कामेकिची ताकाहाशी ने मत व्यक्त किया है कि तोकुगावा के सामन्ती ढाँचे द्वारा लगाए गए प्रतिबन्धों को हटा लिये जाने से जापानी लोगों की बौद्धिक क्षमता यकायक पूरे प्रकाश में आ गयी। इस अकेली घटना ने ही जापान को पश्चिमी तकनीक को अपनाने व आत्मसात् कर लेने में सहायता की। जापान अन्य एशियाई देशों से एक माने में भिन्न भी था। पुनर्स्थापना के पहले 30 वर्षों में, जबकि विदेशी सहायता की आवश्यकता सर्वाधिक थी, तब जापान ने बाहरी सहायता पर निर्भर रहना अस्वीकार कर दिया (क्योंकि उस जमाने में इसका अर्थ था विदेशी आक्रमण का भय) तथा उसने अपनी अर्थव्यवस्था का निर्माण अपने ही साधनों से करने का निश्चय किया। इस अवधि में कई अन्वीक्षाएँ व

¹ T. Kamekichi, *The Rise and Development of Japan's Modern Economy*, 1969, Preface, V

श्रुतियाँ हुईं ।

1868 से 1895 के वर्षों में एक आधुनिक अर्थव्यवस्था के विकास की नीचे धीरे-धीरे भरी जाती रही । पर्याप्त आर्थिक मजबूती संचित कर ली गई ताकि बाद के वर्षों में वास्तविक स्वावलम्बी विकास की अवस्था (take-off stage) प्राप्त हो सके । मेजी पुनर्संस्थापना के बाद जापानी आर्थिक विकास की सम्पूर्ण प्रक्रिया का अवलोकन करने के लिए इस सारी अवधि को पाँच मुख्य अवस्थाओं में विभाजित किया जा सकता है—

प्रथम अवस्था (1868-1885)

इस अवस्था में दो प्रमुख बातें घटित हो रही थी—एक बात तो जापानी अर्थव्यवस्था का पश्चिमीकरण करने के लिए किये जा रहे पुरजोर प्रयास थे, दूसरी बात सामन्ती प्रथा को हटाने की थी जो कि आर्थिक विकास को अवरुद्ध किये हुए थी । ये सामन्ती सरदार लोग समुराई वर्ग के थे, किन्तु उन्होंने स्वयं ही मुधारो को लाने का साहस किया । यही वह अवस्था थी जब आधुनिक आर्थिक विकास की नीचे डाली गई ।

आत्मसात्करण (assimilation) की गति आरम्भ में तो काफी धीमी रही । देश में झगड़े-फसाद और अव्यवस्थाएँ फैल गईं जो पुराने सामन्ती ढाँचे को तोड़ देने से पैदा हुई थी । आसिक रूप से ऐसा इसलिए भी रहा कि लोगों को इस बात का भान भी नहीं था कि 'आधुनिक अर्थव्यवस्था' आखिर है क्या ? इसलिए आधुनिक अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बाह्यीन तत्त्व तैयार किये गये । इस तैयारी में पुनर्संस्थापना के बाद के 18 वर्ष निवृत्त गये ।

द्वितीय अवस्था (1886-1913)

इस अवस्था तक उन नीवों का उपयोग कर पाना सम्भव बन गया जो पहले डाल दी गई थी । मेजी पुनर्संस्थापना के इस दूसरे काल में ही अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण किया गया तथा विकास की दर तीव्र की गई । इस काल में जापान की स्थिति में शेष विश्व के प्रतिकूल तीन महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए जिन्होंने अर्थव्यवस्था को शक्ति प्रदान की—

(1) विदेशों के साथ सन्धियों को सशोधित किया गया । पूर्ववर्ती सन्धियाँ समानता एवं पारस्परिकता पर आधारित नहीं थी । इसीलिए वे आर्थिक विकास में बाधक बनी हुई थी । नई सन्धियों के अन्तर्गत विदेशियों को दिये गये सभी विशेषाधिकार वापस ले लिये गये । सुल्को पर जापान का नियन्त्रण पुन स्थापित हो गया ।

(2) विदेशी पूँजी के आगमन को अब अनुमति प्रदान कर दी गई । पश्चिमी देशों द्वारा उपनिवेश बना लिये जाने के भय से उन पर पहले प्रतिबन्ध लगा हुआ था ।

(3) अन्तिम रूप में, शक्ति सन्तुलन में भी परिवर्तन आ गया । चीन व रूस पर जापान की विजयों ने उसे विश्व मानचित्र पर प्रमुख राष्ट्र के रूप में उभार दिया । ये विजयें भी अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण के कारण ही सम्भव हुई थी ।

यह एक तीव्र विकास का युग था। इस अवस्था में हालांकि जापान को परिपक्व औद्योगिक राष्ट्रों की श्रेणी में तो सम्मिलित नहीं किया जा सकता था किन्तु वह उनकी पंक्ति में प्रवेश पाने के निकट पहुँच चुका था।

तीसरी अवस्था (1914-1928)

प्रथम महायुद्ध में जापान ने एक असाधारण आर्थिक शक्ति के रूप में प्रवेश किया। युद्ध में फँसे होने के कारण प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र अपने परम्परागत औपनिवेशिक या विदेशी बाजारों में वस्तुओं की पूर्ति की निरन्तरता बनाये रखने में असमर्थ थे। जापान को जैसे इसी अवसर की प्रतीक्षा थी। देखते ही देखते वह सूती वस्त्र तथा इजीनियरिंग क्षेत्रों में विश्व का एक प्रमुख विनिर्माण राष्ट्र बन गया। इससे पहले अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा समुद्री यातायात पर यूरोप का एकाधिकार-सा था। युद्ध ने स्थिति को अस्थायी रूप से बदल दिया तथा जापान के अलावा कोई भी अन्य एशियाई देश इस अवसर को पकड़ पाने की स्थिति में नहीं था। जापान ने मेजो काल में विनिर्माण गतिविधियाँ पहले ही आरम्भ कर दी थी। इसीलिए प्रथम महायुद्ध ने जापान को जैसे तीव्र आर्थिक विकास के लिए अवसर ही प्रदान किया। निम्न क्षेत्रों में प्रमुख विकास दृष्टिगोचर होने लगा—

(1) सूती धागे का निर्माण, जिसमें बाद में जापान ने इंग्लैंड को पहले स्थान से दूसरे स्थान पर ला दिया।

(2) भारी उद्योगों में, विशेष रूप से इस्पात, जहाज-निर्माण, मशीन टूल्स आदि क्षेत्रों में भारी प्रगति हुई। इन उद्योगों पर भी पहले इंग्लैंड तथा जर्मनी का प्रभुत्व स्थापित था।

(3) समुद्री जहाज सेवा तथा विदेशी व्यापार का विकास हुआ।

(4) विदेशी मुद्रा की स्थिति में सुधार आया।

ये सभी परिवर्तन प्रथम विश्व-युद्ध द्वारा पैदा की गई गरमागरम (Hot-house type) दशाओं के कारण आये जो विकास के लिए वरदान सिद्ध हुए। 1920 से 1928 तक जापान का आर्थिक विकास 1923 के भूकम्प तथा 1927 की आर्थिक विभीषिका (financial panic) के कारण धीमा रहा।

चौथी अवस्था (1929-1940)

महान् मन्दी ने जापानी अर्थव्यवस्था पर भी विपरीत प्रभाव डाला। किन्तु जापानी अर्थव्यवस्था का पुनरुद्धार भी तेजी से हुआ क्योंकि उसने येन को 1929 में पुनर्मूल्यित कर दिया तथा स्वर्ण के स्वतन्त्र आयात व निर्यात की अनुमति दे दी। जहाँ अधिकांश औद्योगिक राष्ट्र मन्दी के समय अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी चीजें मिट्टी के मोल बेच रहे थे वहीं जापान को कच्चा माल पहले की अपेक्षा कहीं अधिक सस्ते मूल्य पर मिलने लगा जिसकी उसे अत्यधिक आवश्यकता थी। इस तथ्य ने महान् मन्दी के समय निर्यात प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से जापान को लाभ की स्थिति में पहुँचा दिया। जापान ने विश्व-बाजार पर इतनी तेजी में अधिकार कर

लिया था कि अनेक स्थानों पर तो जापानी वस्तुओं का बायकॉट करने की माँगें होने लगीं। 1931 के बाद जापान ने संरक्षणवादी नीति स्वीकार कर ली जिसका उद्देश्य भारी व रसायन उद्योगों में आत्म-निर्भरता प्राप्त करना था जो सैनिक आवश्यकताओं को पूरा करती थी। संरक्षण के परिणामस्वरूप इन उद्योगों में तीव्र वृद्धि अकित की गई तथा इससे तीव्र तकनीकी विकास की प्रक्रिया भी प्रारम्भ हो गई।

पाँचवी अवस्था (द्वितीय महायुद्धोत्तर काल)

द्वितीय महायुद्ध में जापान की भोषण पराजय ने उसका सम्पूर्ण आर्थिक ढाँचा व उपकरण नष्ट कर दिये जो उसने युद्ध-पूर्व के वर्षों में कड़ी मेहनत से तैयार किये थे। युद्ध के बाद जो एकमात्र साधन जापान के पास बच रहा वह उसके कुशल धर्मिक व तकनीशियन लोग थे जो भेजी काल से ही प्रशिक्षित हो रहे थे और अब उस कुशल देने वाली पराजय के 34 वर्षों के भीतर जापान ने पुनः एक बार विनिर्माण के क्षेत्र में सभी पश्चिमी यूरोपीय देशों को पीछे छोड़ दिया है। यह असाधारण उपलब्धि कम से कम इन पाँच तत्वों का परिणाम रही है—

(1) सबसे आधारभूत कारण युद्धोत्तरकालीन वर्षों में हुई विश्वव्यापी तकनीकी क्रान्ति रही है। इसका सर्वाधिक लाभ कई कारणों से जापान को ही हुआ है।

(2) जापान के पाम मानवीय साधन तथा तकनीकी जानकारों का विशाल भण्डार था जो पुनर्संस्थापना के बाद से ही वहाँ प्रशिक्षित होते रहे थे। युद्ध के दौरान भारी एवं रसायन उद्योगों में आत्म-निर्भरता की नीति ने भी जापान की तकनीकी क्षमता को काफी बढ़ा दिया।

(3) इन सबसे अलग, युद्ध के बाद जापान के सामने तो अपने अस्तित्व को बनाये रखने का प्रश्न था। इस परिस्थिति ने उसे नवीनतम तकनीकों तथा वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग करने का साहम प्रदान किया। जब इस क्षेत्र में पहले नव-प्रवर्तकों को सफलता मिली तो अन्य लोगों ने उनका अनुसरण किया। इसका परिणाम यह है कि आज जापानी साज-सामान दुनिया के श्रेष्ठतम उपकरणों में गिना जाता है।

(4) द्वितीय महायुद्ध के बाद कच्चे माल की पूर्ति अधिकधिक होती चली गई है। नए व अधिक समृद्ध खनिज-सम्पदाएँ खोजे गये व उनका विदोहन किया गया। नव-व्यवस्था देश अपने बच्चे माल बेचने के लिए बहुत आतुर थे और जापान उनका स्थायी ग्राहक बन गया।

(5) अधिकांश कारखानों का समुद्र तट पर स्थापित होना भी लाभकारी रहा। इससे जहाजी सेवाओं की लागत में काफी बचत रही। अनेक श्रेष्ठ बन्दरगाहों से युक्त जापानी तटों के कारण देश को अपना विशाल बेड़ा तैयार करने में सहायता मिली।

ये आधारभूत आवश्यकताएँ, जो विकास के लिए इतनी अनिवार्य होती हैं, बहुत पहले ही पूरी कर ली गईं। इसीलिए जापान पश्चिमी यूरोप में भी कई क्षेत्रों में आगे निकल पाया। इसके अतिरिक्त द्वितीय महायुद्ध के बाद अमरीका द्वारा विशाल

मात्रा में दी गई सहायता तथा कोरियाई युद्ध (1950) द्वारा प्रदान किये गये अवसरों ने भी जापान को तीव्र गति से विकास करने योग्य बनाया ।

उपर्युक्त वर्णित ये पाँच अवस्थाएँ स्पष्ट रूप से यह प्रदर्शित करती हैं कि जापान का एक औद्योगिक महाशक्ति के रूप में विकास किस प्रकार हुआ । हालांकि प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएँ रही किन्तु दूसरी से लेकर पाँचवी अवस्था तक एक विशेषता सामान्य ही रही । इनमें से प्रत्येक अवस्था में अपने से पिछली अवस्थाओं द्वारा छोड़ी गई कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करना था तथा पिछली अवस्था से प्राप्त किये गये अनुभवों का आगे के लिए उपयोग करना था । यही वह सामान्य विशेषता थी ।

कामेकिची ने लिखा है, 'जापान के चमत्कारिक विकास के रहस्य को खोलने वाली कुंजी विकास की प्रथम अवस्था को समझने में छिपी है । वह यह जानने में निहित है कि किस प्रकार पूँजीवाद ने जापान को अपना ठिकाना बना लिया जब नींव डालने का काम काफी भीमा तक पूरा हो गया तो बाद का विकास तीव्र एवं तीव्रतर होता रहा ।' दो प्रमुख प्रक्रियाएँ—सामन्ती व्यवस्था का समाप्त किया जाना तथा यूरोपीय अर्थव्यवस्था जैसी आधुनिक अर्थव्यवस्था का अधिग्रहण—सक्रिय रही । इन दोनों आधारभूत तत्वों की अनदेखी करने पर मेजी काल के बाद हुए जापान के विकास का ऐतिहासिक अर्थ समझना कठिनाई होगा ।

चौथा अध्याय

प्रथम महायुद्ध व महायुद्धों के बीच का काल (FIRST WORLD WAR AND THE INTER-WAR YEARS)

मेजी काल के तीसरे व चौथे दशक में स्वयं-स्फूर्त विकास (Take-off stage) की अवस्था के अन्तरिम रूप में पूर्ण हो जाने का पता निम्न तत्त्वों या दशाओं से लगता है

(1) अगुवा फर्मों को मिली व्यावसायिक सफलताओं के कारण, जिन्होंने कि पश्चिमी तकनीक का आयात किया व उसको जापानी दशाओं में आत्ममात (assimilate) कर लिया, उद्योग व व्यवसाय के प्रति अन्य लोगों का उत्साह भी बढ़ा।

(2) पश्चिमी तकनीक को अलग-अलग चरणों में इस प्रकार स्वीकार किया गया कि प्रथम चरण में उनका स्वदेशीकरण (Indigenisation) कर दिया गया। दूसरे चरण में अधिकाधिक फोरमैन (Foremen) प्रशिक्षित किये गये जिन्होंने आधुनिक मशीनरी चलाने में सिद्धहस्तता पा ली। स्वयं-स्फूर्त विकास की अवस्था तीसरे चरण के साथ प्राप्त हो गई जब आधुनिक उपक्रमों के लिए प्रबन्धकीय वर्ग-चारी (Managerial staff) भी भारी संख्या में देश में ही प्रशिक्षित होकर निकलने लगे।

(3) आधुनिक बड़े पैमाने के उद्योगों के विकास के लिए आवश्यक सहायक उद्योगों (ancillary industries) का विकास भी दिखाई पड़ने लगा था। जिन तत्त्वों ने इन सहायक उद्योगों की स्थापना में अपना योगदान दिया वे थे (अ) परिष्कृत बैंकिंग व्यवस्था के कारण पूंजी की अधिक मात्रा में उपलब्धि। (आ) रेल-मार्गों के प्रसार तथा आधुनिक जहाजी सेवा के आरम्भ हो जाने से यातायात सुविधाओं का आधुनिकीकरण, (इ) ऊर्षि तथा उत्खनन में हुए सुधारों के कारण सामान्य आर्थिक स्थिति में सुधार, तथा (ई) मध्यम व निम्न श्रेणी की फर्मों का और आगे विकास जो कि उत्तरोत्तर पश्चिमी तकनीकों का प्रयोग कर बड़ी फर्में बनती जा रही थी।

(4) इन विभिन्न परिवर्तनों का परिणाम यह हुआ कि (अ) घरेलू क्रय-शक्ति में वृद्धि हो गई, (आ) पूंजी संचय बढ़ गया, (इ) विनिर्माण के लिए आवश्यक कच्चे माल व ऊर्जा स्रोतों में वृद्धि हुई, तथा (ई) व्यवसाय का विकास हुआ।

ये स्वयं-स्फूर्त विकास (Take-off conditions) की दशाएँ कुछ ऐसी थी कि उन्होंने जैसे भावी विनाश-प्रक्रिया के पथ लगा दिये। इसका परिणाम यह रहा कि

आने वाले वर्षों में जापानी अर्थव्यवस्था की विकास दर गत वर्षों की अपेक्षा काफी तीव्र रही।

रेल-मार्गों तथा व्यापारिक जहाजों का विकास

वर्ष	रेल-मार्ग (मीलों में)	वाष्पचालित जहाज टन भार (000 टनों में)
1890	1,698	94
1895	2,290	213
1900	3,855	543
1905	4,783	940
1910	5,354	1,234
1915	6,539	1,528
1920	8,475	3,047
1925	10,884	3,547

मेजी काल उस युग के साथ ही पड़ा जिसमें जापानी अर्थव्यवस्था अपने पाँच मजदूती से जमाने में सफल हो गई थी। नया सम्राट तैशो (Taisho) प्रथम महायुद्ध आरम्भ होने के दो ही वर्ष पहले सिंहासन पर बैठा। उसकी अवधि 1926 में समाप्त हुई जो वर्ष जापानी आर्थिक इतिहास में एक विभाजन रेखा के रूप में माना जाता है।

जापान के लिए प्रथम और द्वितीय महायुद्ध के बीच के वर्ष तीव्र विकास के वर्ष रहे। उसके उद्योग तथा कुल राष्ट्रीय उत्पाद (G N P) में भी मेजी काल की अपेक्षा अधिक तेजी से वृद्धि हुई। एक अनुमान के अनुसार 1913 से 1938 तक के बीच जापान का कुल राष्ट्रीय उत्पाद 4% वार्षिक की दर से बढ़ा। उसके कृषि उत्पादन में 1 2% तथा विनिर्मित वस्तुओं के उत्पादन में 7% की वार्षिक वृद्धि हुई। 1913-38 के बीच किसी भी देश द्वारा प्राप्त विकास दर से यह दर ऊँची रही।

प्रति व्यक्ति वास्तविक कुल उत्पाद (Growth of Real G N P Per Capita), 1913-38

(वार्षिक औसत वृद्धि विकास दरें)

जापान	2.6	इटली	1.0
नॉर्वे	2.1	म	0.8
सोवियत संघ	1.9	अमेरिका	0.8
स्वीडन	1.3	इंग्लैंड	0.7
जर्मनी	1.1	कनाडा	0.0

हालांकि प्रथम महायुद्ध के आरम्भ में जापान ने मित्र राष्ट्रों का पक्ष लिया किन्तु उसने युद्ध में भाग नहीं लिया। इस कारण उसे कोई हानि भी नहीं उठानी पड़ी। औद्योगिक उत्पादन काफी बढ़ गया तथा उसे एशिया में कई नये बाजार भी प्राप्त हुए। उसके बनाये वस्त्र अब चीन व भारत में विक्रय लगे। उसके व्यापारिक जहाजों की भारी माँग थी। विदेशी मुद्रा-कोष काफी बढ़ गये।

वास्तविक कुल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि, 1913-38

(वार्षिक औसत चक्रवृद्धि विकास दरें)

जापान	40	इटली	17
नाँवें	29	जर्मनी	16
सोवियत संघ	28	कनाडा	15
अमरीका	20	इंग्लैण्ड	11
स्वीडन	18	फ्रांस	09

प्रथम विश्व-युद्ध के प्रभाव

युद्ध का तात्कालिक प्रभाव तो यह रहा कि जापान की वित्तीय कठिनाइयाँ बढ़ गईं क्योंकि उसका विदेशी व्यापार तथा ऋण सम्बन्धी क्रिया-कलाप संदेह लन्दन में ही किये जाते थे। किन्तु जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि जापान बहुत समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। उसके निर्यातों में दिन-दूनी-रात-चौगुनी वृद्धि हुई। सूती वस्तुओं का निर्यात तो दुगुना हो गया। सूती वस्त्र का निर्यात 1913 के 412 मिलियन गज से बढ़कर 1918 में 1,174 मिलियन गज हो गया। पहली बार जापानी सूती वस्त्र भारत, ईस्ट इण्डोनेशिया तथा अन्य दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों में बिकने लगे।

युद्ध के कारण से आई यह तेजी 1920 तक चली। नये औद्योगिक प्रतिष्ठान स्थापित किये गये। फैक्ट्रियों में रोजगार 1914 के 9 48 लाख से बढ़कर 1919 में 16 1 लाख हो गया। निर्यात माँग में ऐसे समय पर तेजी आ जाने से, जबकि युद्ध के नियन्त्रणों की वजह से वह बराबरी पर आयात नहीं कर पा रहा था, उसके व्यापार में भारी अतिरेक उत्पन्न हो गया। 1911-14 के दौरान हुए 65 मिलियन येन के व्यापार घाटे की तुलना में 1915-18 की अवधि में निर्यातों के आयातों पर आधिक्य का वार्षिक औसत 352 मिलियन येन रहा। मूल्य की दृष्टि से 1918 के निर्यात 1913 की तुलना में तीन गुना थे। उसके अदृश्य निर्यातों में भी काफी तीव्र गति से वृद्धि हुई। भाड़ों से जापान को होने वाली आय, जो 1914 में 40 मिलियन येन थी, 1918 में बढ़कर 450 मिलियन येन हो गई।

निर्यातों में तुलनात्मक विकास, 1913-37

(वार्षिक औसत चक्रवृद्धि विकास दरें)

अमरीकी डॉलरों में

जापान	52	अमरीका	14
मलाया	42	विश्व औसत	14
कनाडा	37	इटली	05
आस्ट्रेलिया	22	इंग्लैण्ड	01
नेदरलैण्ड्स	18	सोवियत संघ	-12.4

जापान ने निर्यातों में प्राप्त अधिकांश अतिरेक का उपयोग अपने स्वर्ण कोषों

को बढ़ाने में किया। जापान ने बड़े पैमाने पर स्वर्ण का आयात किया तथा बैंक ऑफ जापान के स्वर्ण कोष काफी बड़ गये।

बैंक ऑफ जापान व जापानी सरकार के स्वर्ण कोष

(मिलियन येन में)

वर्ष	दत्त म मौजूद	विदेशी म रक्षित	कुल
दिसम्बर, 1914	129	213	342
दिसम्बर, 1920	1 116	1,062	2,178

जापानी वस्तुओं एवं सेवाओं की बढ़ती जा रही माँग का उनकी आन्तरिक अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ा। मौद्रिक आय बढ़ गई, पत्र मुद्रा तथा बैंक साख्त में प्रसार हुआ। उद्योग तथा व्यवसाय ने ऐसी समृद्धि प्राप्त की जैसी उन्हें पहले कभी देखने को भी नहीं मिली थी। लाभ की मात्रा काफी ऊँचाइयों तक पहुँच गयी। मट्टेवाजी की गतिविधियाँ जोर पकड़ गई तथा नई फर्मों की सख्या बढ़ती गई।

किन्तु इस समृद्धि में कहीं एक चोथापन भी था। 1914 से 1919 के बीच श्रोक मूल्य 150% बढ़ गये थे। आयात व निर्यात मूल्य के आधार पर तिगुने हो गये थे किन्तु भौतिक रूप में वे एक चौथाई से ही बड़े थे। औद्योगिक उत्पादन 1914 के 1,371 मिलियन येन में बढ़कर 1919 तक 6,738 मिलियन येन हो गया था तथा कृषि उत्पादन भी इस बीच 1700 मिलियन येन से बढ़कर 4,083 मिलियन येन हो गया था। जापानी वस्तुनियों की प्रदत्त पूँजी 2,676 मिलियन येन में बढ़ कर 7,615 मिलियन येन हो गई। इन सभी वृद्धियों में मुद्रा के मूल्य में ह्रास स्पष्ट रूप में झलकता हुआ दिखाई देता था।¹

येन के मूल्य में ह्रास तथा बढ़ती हुई मुद्रा-स्फीति का यह अर्थ नहीं था कि जापानी अर्थव्यवस्था को प्रथम महायुद्ध से कोई लाभ नहीं हुआ। कृषि तथा खनिज उत्पादनो में क्रमशः 16 व 29% की वृद्धि हुई। रेलों में माल की दुलाई व यात्री आवागमन दुगुने हो गये। विनिर्मित माल का परिमाण 78% बढ़ा। भवन-निर्माण कार्य में काफी तेजी से वृद्धि हुई तथा रसायनों व इन्जीनियरिंग के क्षेत्र में अनेक नई फर्में खोली गईं। यह सही है कि युद्ध के वर्षों के दौरान खोले गये कुछ कारखाने बाद में बन्द हो गये। किन्तु कुल मिलाकर युद्ध के वर्षों में जापान की उत्पादक क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई तथा उसकी विदेशी व्यापार की स्थिति एवं तकनीकी परिपक्वता में भी सुधार हुआ।

उत्पादन क्षमता में हुई इन वृद्धियों का जापानियों के जीवन स्तर पर कोई ब्रिजेय प्रभाव नहीं पड़न पाया। उपभोग लगभग अपरिवर्तित ही रहा। उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में शान वाली वृद्धि जनसख्या की वृद्धि द्वारा बराबर कर दी गई। एक अनुमान के अनुसार वास्तविक औद्योगिक मजदूरी सम्पूर्ण युद्ध-काल में

नगभग स्थिर रही। शहरी क्षेत्रों में रहने वालों पर बढ़ते हुए मूल्यों का भार बहन करना पड़ा, केवल सम्पन्न लोगों के एक बहुत ही छोटे वर्ग को बढ़ते हुए मूल्यों का लाभ मिला। यह तथ्य युद्ध के कारण आयी तेजी के वर्षों में बचत एवं विनियोग के ऊँचे स्तर का कारण एवं परिणाम दोनों ही बन गया।

अपसोस की बात यह रही कि जापान ने अपने अतिरेक का प्रयोग अपने ऋण चुकाने के लिए नहीं किया। जैसा कि पहले लिखा जा चुका है उनका प्रयोग स्वर्ण आयात करने के लिए किया गया। किन्तु 1917 के बाद अमरीका ने भी स्वर्ण के निर्यात पर प्रतिबन्ध (Embargo) लगा दिया। इसने जापान वित्तदाताओं के लिए कुछ समस्याएँ खड़ी कर दी। उधर सरकार घरेलू स्तर पर ऋण लेकर विदेशी ऋण चुकाने के पक्ष में नहीं थी। केवल अल्पकालिक ऋणों का भुगतान किया गया। अधिकांश विदेश व्यापार अतिरेक को विदेशों में ही जमा होत रहने दिया गया। इनमें से अधिकांश अतिरेक युद्धोत्तरकालीन वर्षों में उत्पन्न हुई विदेशी मुद्रा कठिनाइयों को दूर करने में खर्च हो गये।

दो महायुद्धों के बीच के वर्षों में आर्थिक विकास

1918 में प्रथम विश्व-युद्ध की समाप्ति ने जापान की युद्ध-तेजी (War boom) के अन्त का संकेत दे दिया। लगातार बनी रहने वाली स्फीति के प्रभाव में आर्थिक गतिविधियाँ इन वर्षों में काफी ऊँची बनी रही थी। युद्ध समाप्त होने के दो वर्षों बाद ही 1920 में यह तेजी ढह गई तथा जापानी अर्थव्यवस्था को मुद्रा संकुचन का सामना करना पड़ा। सबसे पहले थोक मूल्य निर्देशांक पर इसका प्रभाव पड़ा तथा मार्च 1920 के 322 के स्तर से गिरकर अप्रैल 1921 में वे 190 तक आ पहुँचे। मूल्यों में यह गिरावट कच्चे रेशम तथा चावल के सन्दर्भ में सर्वाधिक रही। जहाज-निर्माण व कोयला उद्योग को भारी धक्का लगा। निर्यातों में कमी आयी तथा अदृश्य मही में अनुभूत सतुलन की स्थिति में काफी कमी आ गयी।

थोक मूल्य निर्देशांक (1913=100)

समय	जापान	इंग्लैण्ड	अमरीका
मार्च, 1920	322	307	227
अप्रैल, 1921	190	199	142
दिसम्बर 1921	209	157	133
दिसम्बर 1922	183	152	144
अगस्त 1923	190	147	140

Source G C Allen *A Short Economic History of Japan*, 1950, 94

सामान्य स्थिति लौट आन पर शान्तिकालीन आर्थिक अवसरों को पैदा करन की आवश्यकता आ पड़ी क्योंकि जापान की जनसंख्या तो बराबर बढ़ती जा रही थी। जापानी सरकार की प्रशंसा में यह बात कही जा सकती है कि उसने द्वारा

अपनायी गयी उदार साख एवं अनुदान नीतियों के कारण जापान अवसाद (recession) की इस स्थिति से अन्य यूरोपीय देशों की तुलना में जल्दी उबर सका। जापान ने अपनी मुद्रा के मूल्य को तब भी बनाए रखा जब येन के अधिमूल्यित (over valued) होने के कारण उसका आयात बिल बढ़ रहा था। किन्तु 1923 के विनाशकारी भूकम्प ने गहरी चोट की। पुनर्निर्माण के लिए विशाल मात्रा में सामग्री आयात की गई। येन के मूल्य को तब तक गिरने दिया गया जब तक वह 1925 में 20% अवमूल्यित नहीं हो गया।

1923 के भूकम्प में 1 लाख से भी अधिक लोगों की जानें गईं। 5 अरब येन मूल्य की सम्पत्ति नष्ट हो गई। टोक्यो व योकोहामा जैसे विशाल नगरों को भारी नुकसान हुआ। पुनर्निर्माण पर भारी व्यय किया गया जिसके लिये वित्त व्यवस्था कर्ज द्वारा की गई। इस समस्त गतिविधि से देश में 'पुनर्निर्माण तेजी' आ गई। थोक मूल्य निर्देशांक बढ़कर 214 हो गये जो एक वर्ष पूर्व 190 ही थे। इससे वित्तीय अस्थिरता का खतरा पैदा हो गया। सरकार ने मितव्ययता के कुछ उपाय किये किन्तु उनकी परिणति भी 1927 के बैंकिंग संकट के रूप में हुई। यह संकट जापान के भावी आर्थिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। कमजोर और अध्यवस्थित बैंक, औद्योगिक तथा व्यावसायिक इकाइयाँ स्वयं ही नष्ट हो गई तथा कुछ अन्य एक-दूसरे में मिल गईं। सम्पूर्ण बैंकिंग उद्योग का नये सिरे से गठन हुआ तथा बैंकों की संख्या 1927-28 में 1,359 से घटकर 1,031 पर आ गयी।

इस बीच जापान लोकतान्त्रिक शासन पद्धति की ओर भी कदम बढ़ा रहा था। शिंसा, प्रेस तथा राजनीति में उदारता की नीति स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थी। यह उदारता की नीति लाने का श्रेय मध्यवर्गीय लोगों तथा शहरी सर्वहारा लोगों को था। युद्धों के बीच के इन वर्षों में ही जापान को साविधानिक लोकतन्त्र का पहली बार अनुभव हुआ।

जापान ने 1917 में स्वर्णमान का परित्याग कर दिया था किन्तु कुछ समय तक अनुकूल भुगतान सन्तुलन रहने से प्रोत्साहित होकर उसने 1930 में उसे पुनः अपनाया। स्वर्णमान की पुनर्स्थापना के लिये यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घड़ी थी। महान् मन्दी या जाने के कारण विश्व स्तर पर मूल्य घट रहे थे तथा येन के पुनर्स्थापित मूल्य का निर्वाह करना बहुत कठिन हो चुका था। जापान के थोक मूल्यों में भी लगभग 35% की कमी आयी।

थोक मूल्य निर्देशांकों का उतार-चढ़ाव (1913=100)

	जापान	अमरीका
अप्रैल, 1929	170	139
दिसम्बर, 1929	155	135
दिसम्बर, 1930	122	112
अक्टूबर, 1931	110	101

चीन में अपनी सैनिक गतिविधियाँ बढ़ाने के लिए वित्त की व्यवस्था करने हेतु जापान ने 1931 के बाद स्फीति का सहारा लिया। भारी घाटे के बजट सरकार द्वारा बनाये गये। साख को आसान बना दिया गया तथा येन के मूल्य का ह्रास होने दिया गया। कड़े विनियम नियन्त्रण उपाय किये गये तथा तटकरो में वृद्धि कर दी गई। आयात शुल्को को 1911 के 10-15% से बढ़ाकर कुछ वस्तुओं पर 100% कर दिया गया। इस अवधि में उसे ब्रिटिश साम्राज्य के बाजारों जैसे चीन व भारत के विभेदकारी तटकरो का सामना करना पड़ा क्योंकि 1931-33 में उन्होंने अपने तट-कर बढ़ा दिये थे। उसकी व्यापार शर्तों (Terms of trade) पर विपरीत प्रभाव पड़ा किन्तु उसके निर्यातों के परिमाण में फिर भी 1929 से 1937 के बीच 70% की वृद्धि हुई। यह उपलब्धि और भी अधिक गौरवपूर्ण थी क्योंकि इसी अवधि में फ्रान्स, जर्मनी, इंग्लैंड व अमरीका जैसे देशों को भी अपने निर्यातों में गिरावट का सामना करना पड़ा था।

1931 से 1937 के बीच जापानी निर्यात 52% वार्षिक की दर से बढ़े। 1937 में जापान अपने कुल राष्ट्रीय उत्पाद का 25% निर्यात कर रहा था। उसका व्यापारिक जहाजी बेड़ा दुनिया में तीसरा सबसे विशाल बेड़ा था। उसके निर्यातों की संरचना में भी भारी परिवर्तन आ चुका था। 1938 तक तो जापान के 58% निर्यात तैयार माल के थे जबकि यह 1913 में 29% ही था।

प्रथम विश्व-युद्ध के बाद जापान ने मंचूरिया, चीन, कोरिया व फारमोसा में प्रत्यक्ष विनियोग की नीति अपना ली थी। 1938 में ये विदेशी विनियोग बढ़ते-बढ़ते 125 अरब डॉलर के हो चुके थे। 1930 के बाद के वर्षों में घरेलू विनियोग की भी एक बहुत ऊँची दर प्राप्त कर ली गई थी। 1938 में जापानी लोग अपने कुल राष्ट्रीय उत्पाद का केवल 60% ही उपभोग कर रहे थे। 1938 में सरकारी व्यय कुल राष्ट्रीय उत्पाद का 25% हो चुका था जबकि 1913 में यह प्रतिशत मात्र 9 था। इस अवधि में सैनिक व्यय में भी भारी वृद्धि हो चुकी थी। वह राष्ट्रीय उत्पाद का 16% हो चुका था तथा उसमें औद्योगिक वस्तुओं के लिए भारी माँग उत्पन्न हो रही थी। वार्षिक स्थिर विनियोग (annual fixed investment) की दर भी राष्ट्रीय उत्पाद की 15% हो चुकी थी। 1920-38 की अवधि की यह दर मेज़ी काल की दर से काफी ऊँची थी।

निर्यातों में तीव्र वृद्धि के साथ भारी सैनिक खर्च तथा स्थिर विनियोग की अत्यधिक ऊँची दरों ने मिलकर जापान में जिस विकास दर को जन्म दिया वह मेज़ी काल की विकास दर से काफी ऊँची रही। इस अवधि में औद्योगिक ढाँचे में प्रमुख परिवर्तन भी हुए। धातु इंजीनियरिंग तथा रसायन उद्योगों के देश में ही विकसित हो जाने से जापान पूंजीगत माल सामान का आयात बिलकुल बन्द करने की स्थिति में पहुँच गया। 1930 के बाद रेशम उद्योग की अवनति से हुई क्षति की पूर्ति ऊन व रेशम क्षेत्र में हुई भारी प्रगति से हो गई।

जंबलु की गतिविधियाँ भी युद्धों के बीच के काल में काफी बढ़ गईं। अपनी वित्तीय गतिविधियों द्वारा उसने अनेक भारी उद्योगों तथा कुछ हल्के उद्योगों पर

चालू बाजार मूल्यों पर कुल राष्ट्रीय उत्पाद के अनुपात के रूप में स्थिर विनियोग (उल्लिखित वर्षों के लिए अनुपातों का औसत)

	1900-13	1920-38	1953-65
जापान	10.4	15.3	28.3
आस्ट्रेलिया	14.9	16.6	24.5
फ्रांस	14.3	15.7	18.9
इटली	13.4	16.1	21.1
स्वीडन	11.1	13.3	21.6
इंग्लैंड	7.1	8.6	15.7
अमरीका	18.7	15.6	17.9

Source A. Maddison, *Economic Growth in Japan and U S S R*,
1969, 39

अपना काफी प्रभाव स्थापित कर लिया था। 1927 के बैंकिंग संकट के बाद तो जैबत्सु का आर्थिक प्रभुत्व और भी मजबूत हो गया क्योंकि बैंको की संख्या उस संकट के समय घट गई थी। 1920 में जहाँ देश में बैंको की संख्या 2,000 से भी अधिक थी वहाँ 1937 तक वह घटकर 377 ही रह गई थी। इनमें भी जैबत्सु (जापानी पूँजीपति घराने) द्वारा नियन्त्रित 7 बैंको का कुल बैंकिंग व्यवसाय के दो-तिहाई भाग पर अधिकार था। जैबत्सु का न केवल बैंकिंग व्यवसाय पर दबदबा था बल्कि उसने न्यायो तथा बीमा कंपनियों पर भी अपना नियन्त्रण स्थापित कर रखा था। जैबत्सु ने सरकार के साथ भी निकट के सम्बन्ध स्थापित कर रखे थे। मगर जैसे-जैसे युद्ध की तैयारी में तेजी आने लगी वैसे-वैसे उद्योगों पर सरकार का प्रत्यक्ष नियन्त्रण भी बढ़ता गया। इन उद्योगों को वित्तीय साधन उपलब्ध कराने के लिए विशेष सरकारी बैंक स्थापित किये गये। किन्तु 1937 में बिजली व्यवस्था का राष्ट्रीयकरण करने के अतिरिक्त सरकार ने निजी औद्योगिक गतिविधियों में अधिक हस्तक्षेप नहीं किया।

जापानी अर्थव्यवस्था का दोहरापन (Dual character) भी युद्धों के बीच के वर्षों में ही स्पष्ट हुआ। भारी उद्योगों में बड़े पैमाने पर विनियोग आवश्यक था। इसीलिये उनका प्रबन्ध एवं नियन्त्रण जैबत्सु के हाथों में आ गया। जैबत्सु द्वारा नियन्त्रित इन भारी उद्योगों में इस बात का ध्यान रखा गया कि उत्पादन अपने सर्वोत्तम बिन्दु तक होता रहे। इतना ही नहीं, बड़े पैमाने का उत्पादन केवल उन्हीं उद्योगों में शुरू किया गया जहाँ उसकी तकनीकी आवश्यकता थी। छोटे थम प्रधान कारखानों की अनुबन्ध पर उठा देना सामान्य प्रथा बन गयी। यही वह तथाकथित दोहरी अर्थव्यवस्था थी जहाँ लघु इकाइयाँ विशाल इकाइयों की पूरक बन गईं।

छोटी व बड़ी इकाइयों के बीच उत्पादकता में भारी अन्तर विद्यमान थे। हालांकि बड़े पैमाने पर उत्पादन करने वाली फर्मों को भारी मात्रा में वित्तीय साधन उपलब्ध थे तथा वे आधुनिकतम तकनीक का भी उपयोग करती थीं। फिर भी मजदूरी में भारी अन्तर के कारण छोटी इकाइयाँ भी अपना अस्तित्व बनाये रखने में

सफा हुई। छोटी इकाइयों के लिए बहुत कम मजदूरी देना ही जरूरी था तथा बड़ी इकाइयों में भी शिक्षा, सेवा की अवधि व यहाँ तक कि पारिवारिक उत्तरदायित्व को लेकर भी मजदूरी में अन्तर बने हुए थे। विशाल औद्योगिक इकाइयों में मजदूर लोग जीवनपर्यन्त अनुबन्धित (Life-time contract) होते थे जबकि छोटी इकाइयों के श्रमिक साधारणतया अस्थायी या अर्ध-कालिक होते थे।

छोटे कारखानों में मजदूरी की दरें कम होने का एक कारण यह भी था कि उनमें अर्ध-कालिक श्रमिक या फिर महिलाएँ व बच्चे काम में लगे हुए थे। उनमें कृषि क्षेत्र से आने वाले अस्थायी श्रमिक भी काम करते थे। इनमें से अधिसंख्य छोटे कारखाने ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत थे। कई कृषि परिवारों के लिए यह आंशिक रोजगार भी उपलब्ध कराते थे। श्रम-संधों का अस्तित्व ही नहीं था। इस प्रकार का यह श्रम बाजार पश्चिमी देशों के श्रम बाजारों से बिल्कुल भिन्न प्रकार का था। इसकी एक विशेषता यह भी थी कि जापान अपने पूंजीगत साधनों का उपयोग भी पश्चिमी देशों की अपेक्षा अधिक समय तक कर सकता था। कई-कई शिफ्टों में काम करके जापानी लोग पश्चिमी देशों के मुकाबले अपनी मशीनों का भी अधिक गहन उपयोग करते थे।

युद्धों के बीच के इन वर्षों में एक सरचनात्मक परिवर्तन भी जापानी अर्थ-व्यवस्था में दृष्टिगोचर हो रहा था। कृषि पर आश्रित श्रम-शक्ति 1913 के 15.5 मिलियन से घटकर 1938 में 13.9 मिलियन रह गयी। कुल श्रम-शक्ति में भी उमका प्रतिशत इस बीच घटकर 61 से 46 प्रतिशत पर आ गया।

मुख्य उपलब्धियाँ

(1) युद्धों के बीच के इन वर्षों की एक प्रमुख उपलब्धि तो यह रही कि गेहूँ, रेशम के कीड़ों (cocoons), फलों, सब्जियों तथा खाद्य पदार्थों का उत्पादन काफी तेजी से बढ़ गया। 1914 में 1929 के बीच कुल खाद्य उत्पादन में 35% की वृद्धि हुई।

(2) प्रथम युद्ध के बाद आई अल्पकालिक मंदी के बाद आयात व निर्यात दोनों ही वापस बढ़े तथा 1925 में क्रमशः 2,573 मिलियन येन तथा 2,306 मिलियन येन की ऊँचाई तक पहुँच गये। 1929 में आयात व निर्यात दोनों ही के मूल्य 1913 के अंकड़ों की तुलना में तीन गुना हो चुके थे।

(3) सूती वस्त्र के क्षेत्र में भारी सुधार किये गये। प्रति व्यक्ति उत्पादन तेजी से बढ़ा। हालांकि कारखानों में रोजगार 2 मिलियन पर स्थिर ही रहा किन्तु विनिर्मित माल का उत्पादन 70% बढ़ गया। धातुओं के उत्पादन में 16% तथा कोयले के उत्पादन में 10% की वृद्धि हुई। 1929 में विभिन्न जापानी कम्पनियों की प्रदत्त पूंजी तथा अन्य कोषों की कुल राशि 16,410 मिलियन येन तक पहुँच गई। यह राशि जापान में विदेशी विनियोग की कुल मात्रा की 20 गुना थी।

(4) बोटिया, पारमोसा आदि स्थानों पर भारी मात्रा में विनियोग किये गये। 1929 तक 12 लाख से भी अधिक जापानी उमके समुद्र-पार उपनिवेशों में

रह रहे थे, जिनमें आधे से अधिक कोरिया में थे।

(5) 1930 के आस-पास के वर्षों की सबसे उल्लेखनीय विशेषता उसके द्वारा विश्व के सभी प्रमुख बाजारों में अपना माल भर देना रही। 1930 से 1936 के बीच जापानी निर्यातों का परिमाण (volume) दुगुना हो गया था। मौद्रिक दृष्टि से 1930 के 1,435 मिलियन येन के स्तर से जापानी निर्यात 2,641 मिलियन येन पर जा पहुँचे थे। 1936 तक जापान सूती वस्तुओं का दुनिया का सर्वप्रमुख निर्यातक देश बन चुका था।

(6) 1930 से 1936 तक जापान का विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (N N P), 1930 के मूल्यों पर, 10.2 बिलियन येन से बढ़कर 15.8 बिलियन येन हो चुका था। उपभोग में भी 20% की वृद्धि हुई। इन 6 वर्षों में जनसंख्या भी 64.5 मिलियन से बढ़कर 70.2 मिलियन हो गई। अतः प्रति व्यक्ति उपभोग में 10% की ही वृद्धि हुई।

आर्थिक क्षेत्र में तकनीक एवं व्यापार की नई शक्तियों के प्रभाव में युद्धों के बीच के इस काल में (Inter-war years) काफी महत्वपूर्ण रूपान्तरण (transformation) हुआ। परिवर्तन की इस प्रक्रिया को अब समझना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अब जापान ही के कदमों पर एशिया के कई विकासोन्मुख देश भी चलने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए वित्त, विदेशी व्यापार, उद्योग, कृषि, लघु-उद्योग क्षेत्र आदि में जापान में हुए आधारभूत परिवर्तनों का विस्तृत विवेचन आगे आने वाले अध्यायों में किया गया है।

कृषि का विकास

(DEVELOPMENT OF AGRICULTURE)

तोकुगावा शासन-काल में जनसंख्या में 80% कृषक लोग थे। 1872 में व्यवसाय में लगी हुई 19 मिलियन जन-शक्ति में से 77 प्रतिशत कृषि कार्यों में सलग्न थी। तोकुगावा शासन में कृषि-संरचना में लगभग 270 भूस्वामियों (Lords) को भारी मात्रा में लगान व सेवाएँ प्राप्त होती थी। किसानों के कुल उत्पादन का लगभग 40% प्रतिवर्ष इन भूस्वामियों, जिन्हें दायम्यो (Daimyo) कहा जाता था, द्वारा अधिग्रहित कर लिया जाता था। तोकुगावा शासन में कृषि में सुधार की दृष्टि से कोई भी विशेष प्रयास नहीं किये गये। दूसरी ओर कई कड़े प्रतिबन्ध लगाकर जापान के तोकुगावा शासकों ने यही चेष्टा की कि ऐसी शक्तियाँ जोर न पकड़ पायें जिनसे उनकी सामन्ती नीवें हिल जाएँ।

यहाँ तक कि 1893 तक भी जापान की लगभग 84 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती थी। हालांकि उनमें से सबसे सब कृषि-कार्यों में नहीं लगे हुए थे। अधिसंख्य लोग परम्परागत आर्थिक गतिविधियों में ही लगे थे। सिर्फ 16% जनसंख्या सहरो में रहती थी। इस तरह जनसंख्या में हुई इन वर्षों की वृद्धियाँ भी कृषि-क्षेत्र में ही खपती रही। 1893 से 1898 तक जापान की जनसंख्या, जिसमें 3.33 मिलियन की कुल वृद्धि हुई थी, में से 2 मिलियन लोग ग्रामीण केन्द्रों पर ही खप गये थे जहाँ मुख्य व्यवसाय कृषि ही था।

मेजी युग की कृषि (1868-1913)

मेजी काल में जापानी कृषि में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। चावल के अन्तर्गत कृषि क्षेत्र 1978 के 2.57 मिलियन चो (Cho) से बढ़कर मेजी काल के अन्त तक 2.92 मिलियन चो हो गया। अन्य अनाजों के अन्तर्गत आने वाले कृषि क्षेत्र में भी काफी वृद्धि हुई। हालांकि पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण जापान की कुल भूमि में से केवल 15% भूमि ही कृषि के अन्तर्गत लायी जा सकी थी। इसके बावजूद उसकी कृषि की जनसंख्या में होने वाली वृद्धियों एवं प्रतिव्यक्ति उपभोग स्तर में होने वाली वृद्धि से साधारणों की यही हुई माँग को पूरा करने में सफलता मिली। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि चावल आदि फसलों के उत्पादन में हुई इन वृद्धियों में कृषि-क्षेत्र में होने वाली बढ़ोतरी की भूमिका आशिक रही। मेजी युग में कृषि उत्पादन में हुई वृद्धि का प्रमुख स्रोत कृषि पद्धतियाँ व सुधार तथा अधिकाधिक गहन

सेती ही थे। मुख्य खाद्य फसलों के उत्पादन में हुई वृद्धियों को नीचे तालिका में दिखाया गया है :

अनाजों का वार्षिक औसत उत्पादन

('000 कोटि में)

	चावल	जौ	गेहूँ
1879-1883	30,874	5,516	2,219
1889-1893	35,549	6,945	3,102
1899-1903	42,268	8,330	3,700
1909-1913	50,242	9,677	4,901

मेजी सरकार ने किसानों को सामन्ती प्रतिबन्धों के शिकारों से मुक्त करने के बाद पहले दो दशकों में अपना ध्यान नई फसलों का उत्पादन शुरू करवाने तथा कृषि की सुधरी हुई पद्धतियों को प्रोत्साहित करने की ओर केन्द्रित किया। कृषि स्कूल व कॉलेज खोले गये। सरकार ने विस्तार-मेवको की नियुक्ति की जिन्होंने गाँव-गाँव घूमकर किसानों को सलाह व जानकारी दी। इनमें कुछ योजनाएँ, जैसे 1870 की भेड़-पालन परियोजना, असफल भी रहीं किन्तु यह भी खेल का एक भाग था। सिंचाई व खाद देने के कुछ नये तरीकों को सफलता मिली। कृषि के लिए साख की व्यवस्था में कई सुधार किये गये।

इन परिवर्तनों के बावजूद जौत का आकार अपरिवर्तित ही रहा। वह लगभग आधे चो (1 2 एकड़) के बराबर था। सेतो का यह छोटा आकार आंशिक रूप से तो इसलिए भी था कि चावल की सेती के लिए छोटे सेत ही अधिक उपयुक्त रहते थे जिनकी सिंचाई आसानी से की जा सकती थी। आंशिक रूप से ऐसा इसलिए था कि जापान एक पहाड़ी देश है और वहाँ चावल की सेती छोटे सीडियोनुमा सेतो पर ही सम्भव थी। ये दोनों ही दशाएँ मेजी काल में अपरिवर्तित ही रही। यहाँ तक कि 1910 में भी जापान के एक-तिहाई से अधिक सेतो का क्षेत्रफल आधे चो से भी कम था तथा शेष दो-तिहाई सेत भी एक चो या उससे कम क्षेत्र के थे।

भू-धारण प्रणाली (Land tenure system) में मेजी काल में काफी क्रान्तिकारी परिवर्तन किये गये। कृषक स्वामियों का प्रतिगत वर्षों के साथ बढ़ता गया। 1910 में एक-तिहाई से अधिक किसान आसामी थे, 2/5 कृषक-स्वामी (Peasant Proprietors) थे तथा शेष के पास भी थोड़ी बहुत जमीनें थी। लगानों का भुगतान चावल के रूप में किया जाता रहा तथा वे फसल का 25% से लेकर 80% तक रहे। किसान लोग अब केवल खाद्य फसलों का उत्पादन करने तक ही सीमित नहीं रहे, उन्होंने कृषि के साथ मछली पकड़ने का काम भी शुरू किया। उन्होंने व्यापारिक फसलों भी उगानी शुरू कर दी। इस क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। कपास पर लगे शुल्क को हटा लिये जाने के बाद उसका घरेलू उत्पादन एकदम बन्द हो गया।

सबसे महान् परिवर्तन कच्ची रेशम के उत्पादन में हुआ। मूल रूप से कच्चे रेशम का उत्पादन कृपक परिवारों में किया जाता था। देश के बाहरी दुनिया के साथ सम्पर्क स्थापित हो जाने से रेशम के लिए भारी विदेशी माँग पैदा हो गई। सरकार ने पश्चिमी मशीनों से युक्त शक्ति-चालित रेशम करखे लगाये। कच्ची रेशम का उत्पादन 1868 के 2 78 लाख क्वान से बढ़कर 1883 में 4 57 लाख क्वान हो गया।

रेशम का उत्पादन व निर्यात

('000 क्वान में)

वर्ष	उत्पादन	निर्यात
1883	457	365
1889-1893 (वार्षिक औसत)	1,110	662
1899-1903	1,924	1,110
1909-1913	3,375	2,563

कच्चा रेशम कृपकों की खेती की ही एक उपशाखा थी। 1914 में न केवल रेशम का उत्पादन वस्त्र रेशम सपटने के उद्योग का भी एक महत्वपूर्ण भाग किसानों या लघु उत्पादकों द्वारा चलाया जाता था। किन्तु इस काल में रेशम का अधिकांश निर्यात व्यापार विदेशी व्यापारियों द्वारा संचालित होता था।

इस बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य याद रखा जाना चाहिए कि मेजी युग की कृषि ने जापान के आधुनिक विनिर्माण उद्योगों के विकास में भारी योगदान दिया था। विनिर्माण उद्योग में हुई प्रगति एक बड़े अंश तक कृषि के विकास पर आश्रित रही। ऐसी स्थिति मेजी काल के चतुर्थ दशक तक रही। उसके बाद विनिर्माण (Manufacturing) उद्योग अपना विकास स्वयं करने की स्थिति में पहुँच गया। मेजी काल की कृषि ने विनिर्माण उद्योग के विकास में निम्न प्रकार से सहायता की थी—

(1) जापान को औद्योगिक राष्ट्र बनाने के लिए जिन भारी विनियोग की आवश्यकता थी उसे प्राप्त करने के लिए मेजी सरकार को प्रमुख रूप से कृषि-क्षेत्र द्वारा प्रदान किये जाने वाले प्रत्यक्ष भूमि करों से प्राप्त आय पर निर्भर रहना पड़ा। कुल कर-आय में भूमि-कर का अनुपात 1876 में 80% से अधिक, 1887 में लगभग 64% और 1892 में 57% रहा तथा वह 1910 में घटकर 20% के स्तर तक पहुँच गया।

(2) अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण करने के लिए भारी मात्रा में वस्तुओं के आयात की आवश्यकता थी। इन आयातों के लिए भुगतान कृषि पदार्थों के निर्यात से होने वाली आय में ही किया जाना रहा। जापानी निर्यातों में कृषि पदार्थों का भाग 1868-77 में 80% से अधिक, 1883-87 में 68% तथा 1888-92 के बीच 60% रहा। जापान द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था को आधुनिक बनाने पर सीधा

निर्यात किये जा रहे इन कृषि पदार्थों ने ही लगाई ।

(3) मेजी काल के तीसरे दशक के बाद तक भी कृषि जापान के पूँजी-निर्माण का प्रमुख स्रोत बनी रही ।

(4) 1897 तक जापानी विनिर्मित वस्तुओं के सबसे बड़े खरीदार किसान लोग ही थे । आरम्भ में ये किसान लोग बेंबल उपभोक्ता सामान ही खरीदते थे किन्तु बाद में रासायनिक खाद, उपकरण आदि जैसी उत्पादक वस्तुएँ भी इनके द्वारा भारी मात्रा में खरीदी जाने लगी ।

(5) आधुनिक अर्थव्यवस्था का निर्माण करने के लिए आवश्यक धन-शक्ति भी कृषि-प्रधान गाँवों द्वारा ही प्रदान की गई ।

उपर्युक्त विवेचन यही तथ्य उद्घाटित करता है कि जापान की आधुनिक अर्थव्यवस्था के निर्माण में वहाँ की कृषि का विकास कितनी आधारभूत महत्त्व की शक्ति थी । 1887 तक जापान की कृषि का विकास मुख्य रूप से कृषि कार्यों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में वृद्धि, सामन्ती प्रतिबन्धों के समाप्त घोषित कर दिये जाने, पृथक्तावादी नीति का परित्याग कर दिये जाने तथा देश के सभी भागों में नमी कृषि तकनीक का प्रचार-प्रसार हो जाने से हुआ ।

मेजी काल के तीसरे दशक के बाद जापानी कृषि क्षेत्र में आधुनिक उत्पादकता की असाधारण वृद्धि दिखाई देने लगी ।

बड़े-बड़े खेतों पर बड़े पैमाने की पाश्चात्य कृषि जापान के छोटे-छोटे और गीले चावल के खेतों के लिए उपयुक्त नहीं थी । किन्तु पश्चिमी कृषि तकनीक के आत्मसात्करण (assimilation) द्वारा बीजों व पौधों की क्रिम्म में सुधार की दिशा में शुद्ध्यत की गई । भूमि के स्वभाव व उचित उर्वरण (fertilisation) सम्बन्धी अध्ययन भी किये गये ।

एक 'तान' (Tan)* भूमि पर चावल व गेहूँ का उत्पादन

(इकाई कोकु=4.96 वुशल)

वर्ष	चावल	गेहूँ
1879	1 18	0 57
1884	1 23	0 68
1889	1 42	0 73
1894	1 42	0 81
1899	1 48	0 89
1904	1 53	0 74
1909	1 71	0 99
1917	1 80	1 06
1919	1 86	1 13

* 1 Tan=0.992 Hectares

Source T Kamekichi, *Changes in Agricultural Village Economy in Meiji and Taisho Eras*, 197-48

इस तरह कृत्रिम खादों के उपयोग से कृषि उत्पादकता में असाधारण रूप से वृद्धि हुई। जब देश में तीसरे मेजी दशक तक रेल-मार्गों के निर्माण का कार्य काफी अंश तक पूरा हो गया तो उससे कृषि उत्पादकता में और भी अधिक प्रगति हुई। जापानी कृषि को देश के विश्व के लिए खोल दिये जाने से भी अप्रत्यक्ष लाभ मिला। कम उत्पादकता वाली फसलें जैसे कपास, नील, गन्ना इत्यादि, जो जापान की भूमि के लिए उपयुक्त नहीं थी, अपने आप बाहर निकल गईं क्योंकि उनका सस्ती दरों पर आयात किया जा सकता था। उनके स्थान पर रेशम के कीड़ों, चावल, फलों आदि का उत्पादन किया जाने लगा जिनकी कि जापान में उत्पादकता काफी ऊँची थी।

कृषि उत्पादन की मात्रा (1874-76 मूल्य)

(इकाई 1 मिलियन येन)

वर्ष	चावल	गेहूँ	रेशम के कीड़ों की खेती	कुल (अन्य शामिल करते हुए)
1874	408	72	32	679
1879	455	71	43	773
1884	423	94	50	792
1889	429	94	51	839
1894	541	122	77	1,025
1899	413	119	106	1,044
1904	664	121	121	1,250
1909	677	135	152	1,337
1914	737	134	183	1,513

Source T Kamekichi, *op cit*, 1969, 293

मेजी काल की कृषि नीति का मूल्यांकन

सम्पूर्ण मेजी काल में औद्योगीकरण का विकास कृषि के विकास के साथ अविच्छिन्न रूप से जुड़ा रहा। यह स्वाभाविक ही था क्योंकि किसी भी देश में कृषि में तीव्र विकास किये बिना औद्योगिक विकास कर सकने में सफलता नहीं प्राप्त की थी। यदि किसी देश के उद्योगों को कच्चा माल प्राप्त करने में शुरू से ही विदेशों की ओर देखने के लिए बाध्य होना पड़े तथा उसके किसान उसके शहरों को खाद्य पदार्थ उपलब्ध करा पाने में समर्थ न हो तो वहाँ औद्योगिक प्रगति की गति धीमी ही रहती है।

इस दृष्टि से तो अपनी सीमित भूमि तथा घटिया मिट्टी के साथ जापान भी एक अपवाद ही रहना चाहिए था। किन्तु वह दो रूपों में भाग्यशाली था : पहला, वह एक द्वीपीय राष्ट्र था जिसकी जनसंख्या छोटी थी, और दूसरा, उसका औद्योगीकरण ऐसे युग में हुआ जब कच्चा माल आसान शर्तों पर उपलब्ध हो जाता था। इसके अतिरिक्त जापान ने अपने आयातों को लागत सस्ते जल-यातायात, खाद्य पदार्थों के उपनिवेशों से सस्ती दरों पर आयात करके तथा कई घटिया किस्म के कच्चे मालों (second grade raw materials) का उपयोग करने की विधि खोज कर

घटा ली। इसका यह अर्थ नहीं है कि इन आयातों का कोई वित्तीय भार नहीं पड़ता था। यदि मेजी काल के लगभग 5 दशकों में जापान का खाद्य वस्तुओं व कच्चे मालों का उत्पादन लगभग 200% से नहीं बढ़ता तो जापान उतना महान् विनिर्माण राष्ट्र नहीं बन पाता जितना कि वह बाद के वर्षों में बना।

मेजी कृषि का चित्र अधिक गुलाबी (Rosy) भी नहीं था। कृषि उत्पादकता में वृद्धि से कृषि वर्गों को लाभ मिला था किन्तु अनेक छोटे किसान, जो कि कम सफल रहे, मेजी पुनर्संस्थापना के पहले दो दशकों में ऋण-भार से ही मालिकों से आसामी बन गये। कई किसान वापस अपनी जमीन कभी प्राप्त नहीं कर पाये क्योंकि आने वाले वर्षों में जमीन की कीमत, लगान व रकम पर ब्याज बहुत चढ़ चुके थे। कृषि जनसंख्या में बढ़ता जा रहा अतिरिक्त भी कृषि-क्षेत्र के बाहर रोजगार ढूँढने के लिए बाध्य हो गया। ऊँचे लगानों, कृषि ऋणों पर ऊँची ब्याज दरों तथा सरकारी करों के कारण कृषि आय का अधिकांश भाग वित्तीय संस्थाओं, भू-स्वामियों तथा सरकार के पास जाता रहा। शायद जापान की राष्ट्रीय आय में अधिक तेजी से वृद्धि होती यदि मेजी सरकार ने कृषकों की दशा तेजी से सुधारने में कुछ अधिक रुचि ली होती। गरीबी तथा असुरक्षा के कारण ये किसान अपनी उत्पादकता को अधिक नहीं बढ़ा पाये। जैसा कि डब्लू० डब्लू० लॉकवुड ने लिखा है, 'मेजी नीतियों को इस प्रकार बनाया हुआ माना जा सकता है कि जिनसे राज्य का खर्च चलाने तथा शासक वर्ग की सैनिक व औद्योगिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए कृषि क्षेत्र से अधिकाधिक रकम ऐंठी जा सके।'

कुछ लोगों का मत है कि कम से कम जापानी नेतृत्व ने कृषि में सुधार करने के नाम पर उतनी पीडादायक विधियाँ तो नहीं अपनायी जितनी कि बाद में रूस में लेनिन व स्टालिन ने अपनायी थी। जो भी हो, इतना अवश्य कहा जा सकता है कि मेजी नीति का उद्देश्य कृषकों को औद्योगिक हितों के लिए कार्य करने हेतु बाध्य करना अवश्य रहा। इसके अतिरिक्त मेजी शासन को जापानी कृषि में एक सर्वांगीण पश्चिमी देशों जैसी कृषि क्रांति करन में भी सफलता नहीं मिली। ऐसा लगता है कि जापानी कृषि पर प्रकृति द्वारा लगाई गई सीमाओं तथा वहाँ के किसानों द्वारा कृषि से बहुत भारी लाभ अर्जित करने की असफलता ने ही दीर्घकाल में विनिर्माण के क्षेत्र में नये अवसरों को खोजने की गति को तीव्र बनाया।

1914 से 1938 के बीच कृषि विकास

1914 से 1930 के बीच जापान की जनसंख्या 51 मिलियन से बढ़कर 64 मिलियन हो चुकी थी। वास्तविक राष्ट्रीय आय लगभग दुगुनी हो गयी। औद्योगिक श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी में 60% की वृद्धि हुई। किसानों की वास्तविक आय में भी वृद्धि हुई किन्तु वे कुछ कम बढ़ी। कच्चे मालों का उत्पादन कोई 46% बढ़ा। 1914 से 1930 के बीच हुई यह वृद्धि मुख्य रूप से मत्स्य-पालन, रेशम के कीड़ों के उत्पादन तथा कृषिगत कच्चे मालों में हुई। खाद्यान्नों के उत्पादन में यह वृद्धि अपेक्षाकृत कम रही। कृषि परिवारों की संख्या 55 मिलियन

के स्तर पर ही स्थिर रही। उनकी जोतो का आकार व वितरण भी नहीं बदला। भू-धारण प्रणाली में भी परिवर्तन नहीं आया हालांकि आसामियों की सख्या में कुछ कमी हुई तथा ऐसे लोगों की सख्या बढ़ी जो अपनी भूमि का थोड़ा-सा भाग अपने पास रखकर शेष लगान पर उठा देते थे। आधे से भी अधिक कुपित क्षेत्र पर बोई जाने के साथ चावल की फसल सबसे प्रमुख रही। इसके बाद गेहूँ व जौ प्रमुख फसलें थी। इस बीच जो मुख्य तकनीकी परिवर्तन आया वह जापानी कृषि में कृत्रिम उर्वरकों का बढ़ता हुआ प्रयोग था। कृषि पद्धतियों में कुछ अन्य सुधार भी हुए।

किसानों में भी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कुछ समृद्धि आयी किन्तु उस तंजी के समाप्त होते ही चावल का मूल्य प्रति कोकु (Koku) जनवरी 1920 के 55 येन के स्तर से घटकर मार्च 1921 में 25 येन पर आ गया। चावल को समर्थन मूल्य प्रदान करने की दृष्टि से चावल अधिनियम लाया गया। इसके बाद कई वर्षों तक फसलें खराब होने से कृषि मूल्य 1927 में पुनः बढ़ गये। किन्तु 1930 में भरपूर फसल हुई। अगस्त 1930 से दिसम्बर 1930 के चार ही महीनों में चावल के मूल्य 31 येन प्रति कोकु से घटकर 18 येन प्रति कोकु पर आ गये। जापानी किसानों के लिए यह बड़ा आघात था विशेष रूप से तब जबकि महान् मदी उनकी आय के अन्य स्रोत, कच्ची रेशम, को भी नष्ट करने वाली थी।

जापान के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण कृषि उत्पाद कच्चे रेशम के उत्पादन में 1914 से 1929 के बीच तीन गुना वृद्धि हुई। 1929 तक लगभग 40% कृषक परिवार रेशम के उत्पादन में लगे थे। रेशम उद्योग के विकास में होने वाली कोई भी गड़बड़ी उन लोगों पर बहुत बुरा प्रभाव डाल सकती थी। युद्ध के दौरान तो कच्चे रेशम के मूल्य काफी चढ़ गये थे। फिर इसके मूल्य 1920 में गिरे किन्तु 1923 तक उनमें काफी सुधार आ गया। तभी अमरीका में जापानी रेशम का बाजार डूब गया तथा अक्टूबर 1930 तक उसकी कीमत आधी रह गयी। किसानों की नकद आय एकदम कम हो गई। यह ऐसे समय हुआ जब चावल की कीमतें भी गिर चुकी थी। लोगों ने और विशेषकर किसानों ने इस कुप्रवन्ध के लिए सरकार को दोषी ठहराया।

खाद्य-उत्पादन के क्षेत्र में मछली पकड़ने वाले उद्योग की अच्छी प्रगति हुई। इसका उत्पादन निर्देशांक 1914 में 43 की तुलना में 1929 में बढ़कर 127 तक पहुँच गया। मछली पकड़ने के क्षेत्र में कुछ तकनीकी सुधार भी हुए जिनके कारण लागत में कमी आयी।

किन्तु कुल मिलाकर 1929 की मदी ने जापानी कृषि पर गहरा प्रहार किया। उसके रेशम के निर्यात बहुत घट गये तथा उनका मूल्य भी बहुत कम मिला। 1932 में सरकार ने दो नये विधेयक पारित किये जिन्हें 'विशेष ऋण व क्षतिपूर्ति कानून' तथा 'अचल सम्पत्ति और रहन ऋण व क्षतिपूर्ति कानून' के नाम से जाना गया। इन कानूनों ने केन्द्रीय सहकारी बैंकों को तथा बंधक बैंकों को किसानों को अधिम प्रदान करने की अनुमति दे दी। हानि होने की स्थिति में सरकार ने ज़िम्मेदारी ली। किन्तु इन उपायों से किसान लोग सन्तुष्ट नहीं

हुए जो कोरिया व फारमोसा जैसे उपनिवेशों से किये जा रहे आयातों पर प्रतिबन्ध लगाने की माँग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे ताकि वे 'राष्ट्र के मेरुदण्ड के रूप में, उसकी सैनिक शक्ति के स्रोत के रूप में तथा विदेशी प्रभावों के विरुद्ध परम्परागत मूल्यों के रक्षक के रूप में जीवित रह सकें।'

चावल उत्पादन, 1915-1937

(वार्षिक औसत)

समय	उत्पादन (मिलियन कोकु)	उत्पत्ति, प्रति बो (कोकु)
1915-19	57	18.5
1920-24	56	18.6
1925-29	59	18.7
1930-34	62	19.0
1935-37	64	19.5

द्वितीय महायुद्ध में जापानी कृषि (1939-1945)

इसे भाग्य की विडम्बना ही कहा जाना चाहिए कि जापान के उन किसानों को महान् मदी का शिकार होना पड़ा जिन्होंने पहले औद्योगीकरण के उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपनी ओर से भरपूर योगदान दिया था। प्रथम महायुद्ध में जापानी कृषि के साथ जो हुआ उसके ठीक विपरीत द्वितीय महायुद्ध में जापानी कृषि को भारी नुकसान उठाना पड़ा। अधिकांश कृषि जनशक्ति को सेना में भर्ती कर लिया गया। कृषि भूमि का सैनिक कार्यों के लिए उपयोग किया गया तथा द्वितीय महायुद्ध के दौरान किसानों को रासायनिक उर्वरक नहीं के बराबर या बहुत अल्प-मात्रा में उपलब्ध कराये गये। खेतों पर श्रमिकों की कमी को मशीनों के उपयोग द्वारा भी पूरा कर पाना सम्भव नहीं था क्योंकि इस्पात का सैनिक कार्यों के लिए उपयोग होने के कारण खेती के पूरे औजार तक भी नहीं मिल पा रहे थे।

कृषि उत्पादन में 1942 के बाद निरावट शुरू हो गयी। 1935 को आधार वर्ष मानने पर 1942 में कृषि उत्पादन 78% था जबकि 1937 में वह 111 था। युद्ध के वर्षों में कृषि के अन्तर्गत कुल क्षेत्रफल में भी 3 प्रतिशत की कमी आयी। 1945 में जब मित्र-राष्ट्रों के हाथों जापान की घोर पराजय के बाद उसकी सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था ही ध्वस्त हो गई तो कृषि उत्पादन निर्देशांक भी घटकर 60 से नीचे जा पहुँचा।

अमरीकी अधिकार के काल में कृषि (1945-1952)

अमरीकी सेना द्वारा जापान पर अधिकार के काल में (American occupation) वहाँ की कृषि में कई दूरगामी प्रभाव वाले महान् सुधार किये गये। भूमि सुधारों पर विशेष बल दिया गया। मित्र-राष्ट्रों की सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर जनरल मैक आर्थर ने दिसम्बर 1945 में एक निर्देश जारी किया जिसमें कहा गया

कि 'जापान की शाही सरकार को यह निर्देश दिया जाता है कि वह देखे कि जो लोग जापान की भूमि को जोतते हैं उन्हें अपनी मेहनत का फल पाने में अधिक बराबरी के अवसर मिलें।'

अमरीकी अधिकार के दौरान शुरू किये गये भूमि सुधारों का उद्देश्य जापान के वास्तविक किसानों को उनके अनुपस्थित भू-स्वामियों के नियन्त्रण से मुक्त करना था। इस उद्देश्य को प्राप्त करने की दृष्टि से जापानी 'डायट' (संसद) ने 1945 में एक कृषि सुधार बिल पारित किया जिसमें सरकार को यह अधिकार दिया गया कि वह अनुपस्थित भूस्वामियों से न्यूनतम वैधानिक मूल्यों पर सारी अतिरिक्त भूमि खरीद ले। एक अन्य अधिनियम 'द ओनर-फार्मर एस्टेब्लिशमेंट लॉ, 1946' के द्वारा भू-स्वामियों को एक छोटे से भू-भाग के अतिरिक्त सारी भूमि से बेदखल कर दिया। इन भू-स्वामियों को मुआवजे के रूप में 24-वर्षीय बॉण्ड दिये गये जिन पर 3.66% का व्याज दिया जाना था। पत्र-मुद्रा के रूप में कुछ नकद मुआवजा भी दिया गया किन्तु पत्र-मुद्रा नोटों की क्रय-शक्ति घट जाने के कारण उन्हें उसका कोई विशेष लाभ नहीं मिल पाया। इस तरह सरकार ने जो भूमि अधिग्रहित की उसे उन लोगों को बेचा गया जो उसे जोतने के इच्छुक थे। इस भूमि के खरीदारों को इसका मूल्य 30 वर्ष तक किस्तों में चुकाना था।

इन भूमि सुधार के उपायों के परिणाम आश्चर्यजनक रहे। जब 1949 में कार्य पूरा हुआ तो 92% किसान अपनी भूमि के मालिक बन चुके थे जबकि 1941 में ऐसे लोगों का प्रतिशत मात्र 54 था। इस प्रकार के भूमि सुधारों का किसानों पर बड़ा अनुकरणीय प्रभाव पड़ा जिन्होंने कि अपने आपको भू-स्वामियों के प्रति दायित्वों से पूरी तरह मुक्त कर लिया। इन किसानों के साथ मेजी युग में भी न्याय नहीं हुआ था तथा उल्टे उस युग में भी उन्हें करो की अधिकांश मार सहनी पड़ी थी। जापान पर अमरीकी सेना का आधिपत्य कम से कम इन लाखों किसानों के लिए तो बरदान ही सिद्ध हुआ।

इन पेचीदा भूमि-सुधारों को क्रियान्वित करने का काम स्थानीय भूमि आयोगों द्वारा किया गया जो देश के सभी 11,000 गाँवों में नियुक्त किये गये थे। उनके सामने 40 मिलियन भूमि के टुकड़ों को विभिन्न लोगों में बाँटने का काम था। 5 आसामियों, तीन भू-स्वामियों तथा दो मालिक-कृषकों को सदस्य बनाकर गठित किये गये ये आयोग अपने काम को पूरा करने के लिए काफी उपयुक्त थे। स्थानीय लोगों से सुपरिचित होने के कारण ये आयोग दोनों ही पक्षों के लाभ में मामलों को निपटा सकते थे। ये आयोग स्थानीय नेतृत्व को आगे लाने के लिए भी उत्तरदायी थे जो द्वितीय महायुद्ध के बाद जापान के लोकतांत्रिक शासन का आधार बन गया। भूमि-सुधार के उपायों का लागू करने के लिए नियुक्त किये गये इन आयोगों की सबसे असाधारण बात यह थी कि उन्होंने वर्ग संघर्ष को जन्म नहीं लेने दिया। इन स्थानीय भूमि आयोगों के बारे में यह कहा गया कि 'उन्होंने एक वर्ग को विस्थापित कर उसका स्थान दूसरे वर्ग को नहीं दे दिया। किन्तु भूमि के स्वामित्व वाले किसानों की संख्या में वृद्धि हो जान से जापान के ग्रामीण समाज में अधिक स्थायित्व आया

तथा प्रतिष्ठा, अधिकार व विशेषाधिकारों को अधिक सामान्य रूप से विभक्त किया जा सका ।'

एक ऐसे युग में जब विश्व के अधिकांश विकासोन्मुख राष्ट्र अपने यहाँ कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से इन भूमि सुधारों को लागू करने के लिए तरह-तरह की चेष्टाएँ कर रहे हैं, उनके लिए जापान के भूमि-सुधार अनुकरणीय है। जैसा कि भूमि-सुधारों पर एव' विशेषज्ञ डब्लू० आई० लादेजेस्की ने लिखा है, 'जब कभी भूमि-सुधारों के बारे में कोरी बातचीत की अवस्था का स्थान कुछ ठोस कार्य करने की इच्छा ले लेगी तब जापान के भूमि सुधारों का अनुभव ध्यानपूर्वक देखने योग्य होगा, विशेषकर उन देशों के लिए जहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव भारी है तथा व्यवसाय के वैकल्पिक स्रोत भी उपलब्ध नहीं हैं ।'

द्वितीय महायुद्ध के बाद जापानी कृषि का पुनरुद्धार अधिक तेजी से होने के दो प्रमुख कारण रहे। प्रथम, उनका विनाश उतना नहीं हुआ था जितना कि उद्योगों का हुआ था, और द्वितीय, अमरीकी सैनिक सत्ता ने देश को अकात के खतरे से बचाने के लिए कृषि विवास के बारे में सहानुभूतिपूर्ण रुख अपनाया। इस दृष्टि से भूमि-सुधार के उपाय सबसे शक्तिशाली अभिप्रेरक (incentive) सिद्ध हुए। 1955 में कृषि उत्पादन निर्देशक, 1935 को आधार-वर्ष मानते हुए, 130 तक पहुँच गये। अमरीकी अधिकार की इस अवधि में कृषि जनसंख्या भी 14 मिलियन से बढ़कर 17 मिलियन हो गई क्योंकि युद्ध-क्षेत्रों से लौटकर आये लोग भी खेती के कार्यों में लग गये।

आधुनिक वर्षों में जापानी कृषि

अमरीकी आधिपत्य के काल में किये गये व्यापक कृषि-सुधारों (1945-52) ने जापानी कृषकों को स्थायी समृद्धि प्रदान की। सहायक रोजगारों से भी कृषकों की आय में वृद्धि हुई। 1950 में राष्ट्रीय आय में कृषि का भाग बढ़कर 40% तक पहुँच गया। किन्तु 1950 के बाद उद्योगों के शानदार विकास ने पुनः एक बार कृषि के राष्ट्रीय धाम में प्रतिशत भाग को 1955 में युद्ध-पूर्व के स्तर तक घटा दिया। अमरीकी आधिपत्य के बाद जापानी कृषि को आधुनिक बनाने की दृष्टि से किये गये सुधारों का निचोड़ इस प्रकार है—

(i) कृषि का यन्त्रीकरण—अमरीकी आधिपत्य में न केवल भूमि-सुधारों का कार्य पूरा हुआ बल्कि उस अवधि में खेतों पर मशीनों का उपयोग भी लोकप्रिय बन गया। यन्त्रीकरण ने कृषि उत्पादकता को बढ़ा दिया तथा किसानों की आर्थिक दशा में भी काफी सुधार किया।

(ii) कृषि जनसंख्या में कमी—औद्योगिक व विनिर्माण क्षेत्र में अधिक लाभकारी अवसर उपलब्ध होने के साथ ही कृषि में कार्यरत लोगों की संख्या घटने लगी। 1964 में कृषि में लगे लोगों का प्रतिशत घटकर 27 पर पहुँच गया जबकि 1955 में वह 39 था। 1979 में वह 10 प्रतिशत से भी नीचे आ चुका है। अत्यधिक गहन यन्त्रीकरण हो चुकने के उपरान्त पिछले कुछ वर्षों से जापानी कृषि को श्रम की

कमी का सामना करना पड़ रहा है।

(iii) गहन खेती—कृषि-योग्य भूमि की कमी ने जापानी कृषकों को कृषि की गहन पद्धतियाँ अपनाने के लिए बाध्य कर दिया। अब वे विश्व में सर्वाधिक रासायनिक खाद का उपयोग कर रहे हैं। रासायनिक खाद का वहाँ का प्रति एकड़ उपभोग भारत की तुलना में 25 से 30 गुना अधिक है।

(iv) राष्ट्रीय आय में घटता हुआ प्रतिशत भाग—हालांकि निरपेक्ष रूप में जापान का कृषि उत्पादन निरन्तर बढ़ रहा है किन्तु कुल राष्ट्रीय उत्पाद (G N P) में उसका प्रतिशत भाग अवनति पर है। राष्ट्रीय उत्पाद में कृषि का प्रतिशत भाग 17.8 से घटकर 1964 में 8.9 पर आ गया था। 1979 में यह 5-6% के बीच में है।

(v) जीवन स्तर में सुधार—किसानों के जीवन-स्तर में काफी सुधार हुआ है। हर गाँव में बिजली पहुँच चुकी है तथा 95% से अधिक लोग लिख-पढ़ सकते हैं। अधिकांश लोग टेलीविजन तथा अन्य विद्युत्-चालित आधुनिकतम उपकरणों का प्रयोग करते हैं।

(vi) कृषि का व्यवसायीकरण होना—कृषि का बाजार अतिरिक्त बराबर बढ़ता जा रहा है। 1952 के 62% से बढ़कर यह बाजार अतिरिक्त 1979 तक 75% के लगभग पहुँच चुका है।

(vii) सहकारी खेती—कृषि सहकारी साख समितियाँ बनायी गयी हैं। 1964 में 4,900 से अधिक सहकारी कृषि उपक्रम कार्यरत थे।

किन्तु जापान की कृषि आज भी सभी समस्याओं से मुक्त नहीं है जैसी कि कोई कल्पना कर सकता है। किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए कोपो का अभाव एक ऐसी ही समस्या है। जो निष्कर्ष प्रो० जी० सी० एसन ने 1950 में निकाला था वह आज भी सही है 'यदि कृषि कान्ति को सफलतापूर्वक पूरा करना है तो सरकार को किसी न किसी रूप में बाध्य होकर उसके लिए अधिक ऋण अनुपात में वांछित कोपो की व्यवस्था करनी होगी।'

कृषि की भूमिका पर लिखे गये इस अध्याय को समाप्त करने से पहले जापानी कृषि की प्रशंसा में यह बात बहनी पड़ेगी कि उसने पिछले 110 वर्षों में जापानी अर्थव्यवस्था के सर्वांगीण विकास में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एवं उपयोगी भूमिका निभाई है। उसने बढ़ती हुई जनसंख्या को पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने में सहायता की है, पश्चिमी देशों से मशीनरी व तकनीक का आयात करने के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा अर्जित की है, उद्योग का विकास करने के लिए पर्याप्त घरेलू पूँजी जुटाई है तथा एक श्रम भण्डार (Labour pool) के रूप में कार्य किया है जिससे उद्योगों ने अपनी आवश्यकतानुसार श्रमिक समय समय पर प्राप्त किये हैं। जापानी कृषि ने अपने देश के उद्योग व विनिर्माण के विकास के लिए जितने त्याग किये हैं उनकी गणना करना भी कठिन है।

उद्योगों का विकास (GROWTH OF INDUSTRIES)

मेजी पुनर्संस्थापना के बाद के पिछले 110 वर्षों में जापानी उद्योगों के विकास ने ससार को आश्चर्य-चकित कर दिया है। किन्तु जापान में हुए इस औद्योगिक विकास में रहस्य जैसी या पौराणिक चमत्कार जैसी कोई बात नहीं है। यह एक बिलकुल अलग बात है कि एक एशियाई देश होते हुए भी जापान ने पश्चिमी देशों के साथ होड़ की है। ऐसा करके जापान ने उन लोगों को एक हल्का सा धक्का भी पहुँचाया है जो यह सोचते रहे हैं कि पश्चिमी तौर-तरीके अप्रतिम (inimitable) हैं।

बड़े पैमाने के उपक्रमों के गठन की आवश्यकता जापान में मेजी पुनर्संस्थापना के पहले ही दशक में अनुभव कर ली गयी थी। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उन वर्षों में पूँजी-निर्माण पर सबसे अधिक बल दिया गया था। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जापानी अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण को सच्ची गति प्रदान करने की यही सबसे आधारभूत शर्त थी। मेजी काल के आरम्भिक वर्षों में एक प्रमुख प्रश्न यही था कि किस प्रकार ऐसे नये विशाल पैमाने के प्रतिष्ठान गठित किये जाएँ तथा यह सब कम से कम समय में किस तरह हो ? सारी प्रक्रिया एक विशाल स्तर पर पूँजी-निर्माण से शुरू हुई जो क्रांतिकारी तरीके से किया गया। चार सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्त्व, जिन्होंने विशाल मात्रा में पूँजी की खोज को प्रेरित किया, इस प्रकार थे :

(1) विदेशी व्यापार के विकास के कारण जापान को शेष विश्व के लिए खोल दिये जाने से अनेक आवश्यकताएँ उत्पन्न हुईं। तोकुगावा काल में कम पूँजी वाले जापानी व्यापारियों को विदेशी व्यापारियों के साथ लेन-देन करने में बड़ी हानि उठानी पड़ती थी। ये विदेशी व्यापारी जापानियों से उनकी वस्तुएँ सस्ते मूल्यों पर खरीदते तथा उनकी अपनी वस्तुएँ उन्हें महँगे मूल्यों पर बेचते। इसीलिए मेजी सरकार ने अपने आरम्भिक वर्षों में अर्द्ध-सरकारी व्यावसायिक एवं विदेशी विनिमय कम्पनियाँ गठित कीं। सीधे निर्यात व आयात के लिए भारी मात्रा में पूँजी की आवश्यकता थी। वास्तव में वे ही कम्पनियाँ लाभदायक रह सकती थीं जो विदेशी व्यापार के क्षेत्र में कार्य के लिए भारी मात्रा में पूँजी जुटा सकती थीं।

(2) आधुनिक यातायात व संचार के साधनों की स्थापना करने के लिए भी भारी मात्रा में पूँजी की आवश्यकता थी। विकास की गति पश्चिमी आधुनिक सुविधाओं जैसे वाष्प-चालित जहाज, रेल-मार्ग, विजली व तार सेवाएँ आदि की

स्थापना पर ही निर्भर करती थी। इस सभी के लिए विशाल पूँजी मचय की जरूरत थी। सरकारी विनियोग का उपयोग किया गया किन्तु चूँकि वह अकुशल व अपर्याप्त था इसलिए इन क्षेत्रों में निजी उद्यमियों को प्रवेश के लिए आमन्त्रित किया गया।

(3) एक अन्य तत्त्व, जिसने विशाल पूँजी विनियोगों को आवश्यक बनाया, खनिज उपक्रमों में बड़ी मात्रा में राशि लगाने की आवश्यकता रहा। तोकुगावा काल में खानों की गतिविधियाँ पुरातन-पथी दशाओं में संचालित हो रही थी। पश्चिम की बड़े पैमाने की उत्खनन तकनीकों से ही खनिज उपक्रमों को लाभदायक बनाया जा सकता था। किन्तु इसके लिए भी बड़ी मात्रा में पूँजी की आवश्यकता थी।

(4) अन्न में, पूँजी-प्रधान तकनीकों पर आधारित भारी विनिर्माण उद्योगों (Heavy Manufacturing Industries) की स्थापना का कार्य पूरा करने के लिए भी भारी विनियोग की आवश्यकता थी। जापानी अर्थव्यवस्था के भावी विकास को दिशा इसी बात पर निर्भर करती थी कि वहाँ आधुनिक भारी पूँजी प्रधान विनिर्माण उद्योगों को कितनी सफलता से स्थापित किया जा सकता था। किन्तु अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की तुलना में, मेजो काल के पूर्वार्द्ध में आधुनिक विनिर्माण उद्योगों की प्रतिस्थापना काफी धीमी रही।¹ वास्तविक तैजी 1887 के बाद ही आ पायी।

आरम्भिक बाधाएँ

हालाकि मेजी सरकार ने देश में आधुनिक विनिर्माण उद्योगों व उत्खनन के विकास की भरसक चेष्टा की किन्तु वास्तविक स्वयं स्फूर्त विकास (Take-off) इस क्षेत्र में 1884 में ओसाका स्पिनिंग कम्पनी की स्थापना के बाद ही प्रारम्भ हो पाया। इस विलम्ब के कई कारण थे। 6 प्रमुख समस्याएँ निम्नांकित रही।

(1) आधुनिक विनिर्माण के विकास एवं प्रगति के लिए आवश्यक तकनीक का अभाव—(अ) तकनीकी कर्मचारियों की सख्यात्मक व गुणात्मक कमी (आ) प्रबन्धकीय कर्मचारियों का अभाव। 1880 तक जापान के धीमी गति से हुए विनिर्माण उद्योगों के विकास के लिए यही सबसे आधारभूत कठिनाई रही। किन्तु इस तथ्य को भी अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए कि समय के साथ-साथ इन कमियों को शीघ्र ही दूर कर दिया गया।

(ii) पूँजी सचय की अपर्याप्तता तथा अब तक का अपूर्ण वित्तीय ढाँचा। परिणाम यह हुआ कि आधुनिक विनिर्माण कर्मों की स्थापना व उन्हें चलाने के लिए आवश्यक पूँजी की पूर्ति बहुत सीमित थी। साख मुद्रा में लेन-देन में अच्छी वित्तीय सस्थाएँ न होने के कारण बाधाएँ आती थी (उदाहरण के लिए बैंक ऑफ जापान खुल तो 1882 में गया किन्तु वह 1885 के बाद ही सक्रिय हो पाया)। साथ ही ब्याज-दरें बहुत ऊँची थी, वे 10% से 15% के बीच थी। इससे जापान में आधुनिक विनिर्माण उद्योगों का विकास व स्थापना काफी सीमित हो गये।

(iii) आधुनिक विनिर्माण कारखानों को उपकरणों से सुसज्जित करने तथा उन्हें चलाने में आने वाली भारी लागत (अ) यूरोप से जापान तक नगीनें आदि लाने

मे लगने वाला ऊँचा यातायात भाड़ा। (आ) इसके अतिरिक्त हर चीज का निर्माण करने व उसे चलाने के लिए विदेशी विशेषज्ञों की आवश्यकता पड़ती थी। (इ) मरम्मत की ऊँची लागत क्योंकि अभी तब जापान में कोई मशीन टूल (Machine Tool) उद्योग नहीं था। (ई) ऐसी मशीनों को जिन्हें मूल रूप से यूरोपीय देशों के लिए तैयार किया गया था जापानियों के लिए काम लेने में कई कठिनाइयाँ थी, उदाहरण के लिए, लम्बे बंद के यूरोपीय लोगों के लिए बनाई गई मशीनें जापानी लोग प्लेटफॉर्म पर धड़े रहकर ही काम में ले सकते थे। (उ) जापान की ऊँची ब्याज दरों में उसे विदेशियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में और भी कठिनाई होती थी।

(iv) इसके अलावा उसे नीचे तटकरो का भी मुकसान था जो असमान सन्धियों में विदेशियों ने उस पर थोप दिये थे। ये 2.5% से 4% के बीच थे। इनसे भी जापानी वस्तुओं की पश्चिमी वस्तुओं के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकने की क्षमता घट गई।

(v) भारी मात्रा में तथा अत्यधिक सस्ती थम शक्ति, जिसने एक तरह से सहायता भी की उद्योगों को यन्त्रीकृत करने व उन्हें आधुनिक बनाने में बाधक थी। वास्तव में, प्रारम्भ में तो जापानी विनिर्माण तथा खनिज उद्योगों ने आँख मूंद कर पश्चिमी विशेषज्ञों की योजनाओं को स्वीकार किया। इनमें से कई योजनाएँ ऊँची लागत के कारण असफल हो गईं। तब जहाँ वही श्रमिक काम कर सकते थे वहाँ उनको लगाया गया। इस तरह जब जापानियों ने स्वयं ही जापानी प्रकार के यन्त्रीकृत प्रतिष्ठान तैयार किये तभी मेजी युग के यन्त्रीकृत उपक्रमों में पहली बार सफलता दिखाई देने लगी।

(vi) इन बिन्दुओं के अलावा यह तथ्य भी नहीं भुलाया जाना चाहिए कि उस समय जापानी लोग आधुनिक औद्योगिक प्रतिष्ठानों के बारे में बहुत कम जानते थे। सच तो यह है कि मेजी काल के आरम्भिक वर्षों में आधुनिक उद्योग जापान में लगभग अज्ञान थे। जापानी लोग अक्सर हाथों के श्रम पर आधारित कारखाने पसन्द करते थे। बड़े उद्योगों को शुरू करने में पैदा होने वाले खतरो को दूर रखने के लिए जापानियों ने लघु एवं मध्यम दर्जे के उपक्रम प्रारम्भ किये।

मेजी काल में सरकार ने लोगों को वास्तविक प्रदर्शनों द्वारा औद्योगीकरण के बारे में सिखाया। सरकार ने कुछ आधुनिक विनिर्माण फर्मों अपनी देख रेख में देश में प्रतिस्थापित की। किन्तु उनमें से अधिकांश फर्मों को घाटा लगा। इसीलिए 1880 के निजी स्वामित्व को सरकारी कारखानों में हस्तान्तरित कर देने का सरकारी निर्णय एक तरह से सरकार की इस असमर्थता की स्थितिकोश्लेषी ही था। इस तरह वास्तविक प्रदर्शनों द्वारा लोगों को आधुनिक उद्योग स्थापित करने की ओर आकृष्ट कर पाने में सरकार को विशेष सफलता नहीं मिली। वैसे तो केवल विशाल पूँजी वाली व अनुभववी विदेशी फर्मों पर निर्भर रहकर ही जापान अपने यहाँ आधुनिक विनिर्माण फर्मों स्थापित कर सकता था। किन्तु देश में आधारभूत धारणा इन विदेशियों की गतिविधियों पर नियन्त्रण लगाने की थी। इस दृष्टि से जापानियों के मामले में जो एकमात्र रास्ता खुला था वह यही था कि वे अपन ही प्रयासों से देश में आधुनिक विनिर्माण उद्योग स्थापित करें।

आधुनिक पूँजी-प्रधान उद्योगों का सरकारी तत्त्वावधान में प्रत्यारोपण (Transplantation)

मेजी काल के प्रथम 15 वर्षों में देश में आधुनिक पूँजी-सज्जित (capital equipped) कारखानों का प्रत्यारोपण निजी उद्यमियों की सामर्थ्य की बात नहीं था। उधर सरकार जापान का उपनिवेशन न होने देने के लिए कटिबद्ध थी। स्वतन्त्र राष्ट्र के लिए फलने-फूलने का एकमात्र उपाय 'समृद्ध एवं सुदृढ़' बनने में था। इसीलिए सरकार ने आधुनिक पूँजी सज्जित पश्चिमी उद्योग देश में स्थापित करने की नीति अपनायी।

इन्हीं कारणों से 1882 तक जापान में आधुनिक उद्योग स्थापित करने का कार्य सरकार ही ने किया। इस प्रक्रिया के तीन स्वरूप रहे—

(1) प्रत्यक्ष सरकारी प्रबन्ध वाले उद्योग।

(2) लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा निर्मित एवं चलाये जाने वाले कारखाने।

(3) वे निजी उद्योग जिन्हें सरकारी संरक्षण, प्रोत्साहन तथा सहायता प्राप्त थी।

ये तीन प्रकार के उद्योग जापानी अर्थव्यवस्था में इन रूपों में प्रकट हुए—

(1) प्रत्यक्ष सरकारी प्रबन्ध वाले उद्योग : (अ) वे उद्योग जिन्हें बाद में निजी उद्यमियों को हस्तान्तरित कर दिया गया जैसे खनिज प्रतिष्ठान, नागासाकी शिपयार्ड्स, ह्योगो मैन्युफैक्चरिंग वर्क्स, फुकागावा सीमेन्ट वर्क्स, शिनागाना ग्लास वर्क्स व टाइप फाउण्ड्री। (आ) वे उद्योग जो सार्वजनिक प्रतिष्ठान बने रहे जैसे रेलमार्ग, तार, योकोसुका शिपयार्ड्स तथा ओसाका टकसाब।

(2) मॉडल कारखाने जो लोगों को प्रबोधित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा चलाये जाते थे व जिन्हें बाद में निजी उद्यमियों को बेच दिया गया। इनमें तोमिओका सिल्क रीलिंग, हिरोशिमा स्पिनिंग कम्पनी तथा आइची स्पिनिंग कम्पनी सम्मिलित थे।

(3) वे प्रकरण जिनमें सरकार ने निजी प्रतिष्ठानों को उपकरण आदि खरीदने के लिये राशि उधार दी जैसे (i) 2,000 त्कुओ वाले 20 कताई मिल खोलने के इच्छुक लोगों के लिए राशि का प्रावधान। ऐसे दस मिल देश के विभिन्न भागों में स्थापित किये गये। (ii) एक निजी व्यापारिक जहाज उद्योग शुरू करने के उद्देश्य से सरकार ने भाष से चलने वाले कुछ जहाज खरीदे तथा उन्हें मित्सुबिशी शिपिंग कम्पनी को उधार दे दिया।

इन समस्त उद्योगों में से खनिज उद्योग फर्मों, रेल मार्ग कम्पनियाँ, योकोसुका शिपयार्ड्स, ओसाका टकसाब व तोमीओका सिल्क रीलिंग उद्योग अपने-अपने क्षेत्रों में अगुवा बने। अन्य उद्योग अण्डों की तरह थे जिन्हें सेने से बाद के वर्षों में आधुनिक भारी उद्योगों का जन्म हुआ।²

मेजी काल के आरम्भ में सिर्फ सरकार ही के पास साधन थे। किन्तु इन

साधनों की भी सीमा थी और वह बहुत जल्द आ गई। इसके परिणामस्वरूप विनियोग के लिए आवश्यक कोषों को निजी विनियोजकों के अभ्युदय की प्रतीक्षा करनी पड़ी। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा चलाई जा रही फर्मों एकदम अकुशल व धाटे में चलने वाली फर्मों थी। यही तथ्य 1880 में इन फर्मों के निजी लोगों को हस्तान्तरित कर दिये जाने के लिए उत्तरदायी था।

मेजी काल के दौरान जापान में आधुनिक उद्योगों को शुरू करवाने में सरकार द्वारा संचालित इन उद्योगों का अपना योगदान अवश्य रहा। इस योगदान को इस तरह निचोड़ कर देखा जा सकता है—

(1) विभिन्न उद्योगों का सुसज्जित करके व उनका संचालन करके सरकार ने आधुनिक उद्योगों के बारे में एक पाठ पढ़ाया जो काफी उपयोगी मिट्टि हुआ।

(2) अत्यधिक कुशल विदेशी विशेषज्ञों को अपने यहाँ काम पर रखकर जापानी लोगों ने आधुनिक तकनीक का वास्तविक प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया। ऐसा होने से भावी तकनीकी प्रगति के भी बीज बो दिये गये। मेजी काल के तीसरे दशक के बाद जापान में जो भारी उद्योग खुले उनमें काम पर लगने वाले अधिकांश लोग सरकार द्वारा चलाये गये कारखानों में ही प्रशिक्षित हुए थे।

(3) अन्त में, सरकार ने आधुनिक उद्योगों के विकास को ध्यान में रखते हुए अपने पूँजीगत साज-सामानों को निजी व्यक्तियों के हाथों बहुत सस्ती दर पर बेचा।

बाधाओं का उन्मूलन

उपर्युक्त वर्णित भारी उद्योगों के विकास में आने वाली बाधाओं को निम्न-लिखित उपायों द्वारा दूर किया गया

(1) जैसे-जैसे आधुनिक शिक्षा के प्रसार के कारण प्रशिक्षित जन शक्ति तैयार हुई वैसे-वैसे आधुनिक उद्योग के बारे में जानकारी का प्रसार भी होने लगा। खान उद्योग व विनिर्माण में भारी विनियोग करने की आवश्यकता की बाधा भी तब कुछ कम हो गई जब जापानी तकनीशियनों ने विदेशी मशीनों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप ढाल लिया।

(2) दूसरे मेजी दशक तक बनी रहने वाली पूँजी के अभाव की बाधा पर भी विजय पा ली गई जब 1877 व 1885 के बीच आधुनिक वित्तीय संस्थाओं का निर्माण हुआ तथा घरेलू पूँजी-संचय में भी वृद्धि हुई।

(3) विशाल मात्रा में पूँजी-निर्माण में नये उद्यमियों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। संयुक्त पूँजी कम्पनियों के विकास व प्रसार ने बड़े पैमाने पर उत्पादन करने वाले उद्योगों की स्थापना को अधिक सुविधाजनक बना दिया। वित्तीय गुटों (जैबत्सु)¹ के अभ्युदय के साथ बड़े पैमाने के उद्योगों को प्रारम्भ करना आसान बन गया।

(4) आधुनिक यातायात सुविधाएँ तथा उनसे सम्बन्धित उद्योग धीरे-धीरे

¹ वित्तीय गुटों या जैबत्सु की चर्चा आठवें अध्याय में की गई है।

स्थापित किये गये। ये भी आधुनिक उद्योगों की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण थे। व्यापारिक जहाजी सेवा का विकास तथा रेल-मार्गों का निर्माण इस क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण योगदान थे।

इन बाधाओं पर प्राप्त की गई विजय के अतिरिक्त निम्न तत्त्व भी आधुनिक उद्योगों को आगे बढ़ाने में सहायक हुए

(1) कोयले के भण्डारों की खोज भी आधुनिक विनिर्माण उद्योग के विकास का प्रभावी आधार बन गई। ऊर्जा के अन्य स्रोत जैसे जल-विद्युत् 1910 के बाद से प्रभावशाली बन गये। द्वितीय राष्ट्र के श्रेष्ठ बन्दरगाह, उसकी शीतोष्ण जलवायु तथा पानी की प्रचुर उपलब्धि भी आधुनिक उद्योग के विकास में सहायक तत्त्व रहे।

(2) विश्व रजत मूल्यों में आई गिरावट भी सहायक रही। जापान ने रजत-मान अपनाया हुआ था तथा चांदी के मूल्यों में कमी घेन की विदेशी विनिमय दर में गिरावट के रूप में सामने आयी। यह स्थिति जापान के विदेशी व्यापार, उसके खान उद्योग तथा विनिर्माण के लिए बहुत लाभदायक रही। यह प्रभाव 1885 के बाद ही अनुभव किया गया।

उपर्युक्त वर्णित परिस्थितियों से स्पष्ट है कि आधुनिक उद्योगों के विकास के लिए अनिवार्य शर्तें धीरे धीरे हो पूरी की गईं। किन्तु असमान सन्धियों के अन्तर्गत आरोपित नीचे तटकरो (Low tariffs) की बाधा फिर भी बनी रही। उन्हें 1899 में सशोधित किया गया तथा तटकरो के विनियमन पर जापान का पूर्ण नियन्त्रण 1911 में ही स्थापित हो पाया। संक्षेप में, औद्योगिक विकास की प्रक्रिया इस अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक दबाव का विरोध करते हुए ही आगे बढ़ी।

आधुनिक बड़े पैमाने के उद्योगों का गठन तथा महान् उद्यमियों का उत्कर्ष

मेजी शासन के आरम्भ में बिल्कुल भी पूंजीगत ससाधन नहीं थे जिसके दो प्रमुख कारण रहे (1) लोगों की वृत्तें थोड़ी व बिखरी हुई थी, तथा (2) हालांकि कुछ धनी व्यापारी थे किन्तु उनमें से अधिकांश अपनी पूंजी पुनर्संस्थापना की क्रांति में खो चुके थे। इस तरह मेजी काल के आरम्भ के समय सरकार ही एकमात्र ऐसी संस्था थी जो आधुनिक बड़े पैमाने के उद्योग प्रारम्भ कर सकती थी। किन्तु सरकार के पास मौजूद सीमित धनराशि भी बहुत जल्द समाप्त हो गई। इस तरह विशाल पैमाने के उद्योगों के विकास को तब तक प्रतीक्षा करनी पड़ी जब तक पर्याप्त निजी पूंजी जमा हो पाती। निजी पूंजी को तीन स्रोतों से एकत्रित किया गया (i) व्यापार के लिए उत्साह रखने वाले निजी उद्योगपतियों द्वारा बड़े पैमाने पर पूंजी संचय की प्रक्रिया प्रारम्भ होना, (ii) संयुक्त पूंजी कम्पनियों का विकास, तथा (iii) आधुनिक वंकिंग व्यवस्था का विकास।

विचाराधीन अवधि के अन्तर्गत बड़े प्रतिष्ठान सरकार, निजी व्यक्तियों या फिर सार्वजनिक स्वामित्व वाली स्टॉक कम्पनियों द्वारा गठित किये गये जिनमें से प्रत्येक की अपनी विशेषताएँ थी—

(1) सरकार द्वारा गठित विशाल प्रतिष्ठानों पर ही चर्चा को पहले जा चुकी है।

(2) निजी व्यक्तियों द्वारा विशाल पैमाने के उद्योगों की स्थापना—
(अ) व्यापारिक फर्म—इनमें से अधिकांश निजी व्यक्तियों के प्रयासों से विकसित हुई।
(आ) व्यापारिक जहाजी सेवा—इसे सरकारी ऋणों से निजी उद्यमियों द्वारा प्रारम्भ किया गया। (इ) खान कम्पनियाँ—कुछ कम्पनियाँ शुरू से ही निजी व्यक्तियों के प्रयासों पर आधारित थी तथा कुछ निजी व्यक्तियों के हाथों में सरकार द्वारा अपनी खानें बेचने के बाद आयी। (ई) विनिर्माण—ये कम्पनियाँ सरकारी स्वामित्व वाली कम्पनियों को खरीदने के बाद बनी। इनमें नागासा की डॉकयार्ड्स, ह्योगो बक्स तथा सीमेट बक्स सम्मिलित थे।

(3) समुक्त पूंजी कम्पनी प्रबन्ध के अन्तर्गत विशाल स्तर पर पूंजी-निर्माण—
(अ) बैंक—एक तो ऐसे बैंक थे जो नेशनल बैंकों की तरह विशुद्ध समुक्त पूंजी कम्पनियों के दूसरे मित्रमुई बैंक की तरह निजी प्रबन्ध वाले थे। इसके अतिरिक्त बैंक ऑफ जापान जैसे सरकारी बैंक भी थे। (आ) रेल मार्ग कम्पनियाँ—सारे निजी प्रबन्ध वाले रेल-मार्ग कम्पनी प्रणाली के अन्तर्गत विकसित हुए जैसे हकाई एण्ड निप्पोन रेल रोड। (इ) व्यापारिक जहाजी सेवा—जब 1885 में निप्पोन युसेन कम्पनी स्थापित हुई तो सभी जहाजी उपक्रम कम्पनी प्रणाली के अन्तर्गत गठित हो गये। एक अन्य बड़ी जहाजी फर्म ओसाका सोसेन कम्पनी थी। (ई) सूत कटाई कम्पनियाँ—आधुनिक विशाल पैमाने पर विनिर्माण ओसाका स्पिनिंग कम्पनी की स्थापना के बाद शुरू हुआ।

संक्षेप में, 1888 के अन्त तक निजी व्यक्तियों ने विशाल पैमाने के प्रतिष्ठान या तो व्यावसायिक क्षेत्र में या फिर खानों के क्षेत्र में बनाये थे। रेल मार्गों, जहाजी सेवा, बैंकिंग आदि प्रमुख क्षेत्रों में सरकार ही नेतृत्व कर रही थी। निजी क्षेत्र में विशाल पैमाने पर उत्पादन करने वाली इकाइयों की स्थापना को पर्याप्त पूंजी वाले निजी उद्यमियों के आगमन की प्रतीक्षा करनी पड़ी। 1892 में एक जापानी विचारक फुकुजावा युकिची ने धनी व्यक्तियों की विकास में महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हुए लिखा 'एक स्थान में पूंजी का संग्रह करने व उसका एकीकृत रूप में उपयोग करने के लिए धनी व्यक्ति महत्वपूर्ण होते हैं। जब पूंजी एक स्थान पर पहले ही जमा हो जाती है तो वह उस समाधान के गुणों को खुली छूट दे देती है तथा उसके लिए किसी बाहरी निर्देश की आवश्यकता नहीं पड़ती। धनी व्यक्ति फिर देश को मजबूत बनाने में प्रत्यक्ष रूप से नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप में सहायता करते हैं।'

1868 में हुई पुनर्संस्थापना के बाद सरकार ने पूंजीपतियों को समर्थन प्रदान किया। सरकार ने प्रगतिशील उद्यमियों को अपना समर्थन देकर एक ऐसा अवसर प्रदान किया कि जिससे समृद्धि के द्वार उनके लिए खुल गये। एक असाधारण वातावरण बना जिसमें नव-धनाढ्य लोग पैदा होने लगे। इस स्थिति के लिए निम्न तत्त्व उत्तरदायी थे—(1) विदेशी व्यापार का खुल जाना, (2) घरेलू

स्तर पर सामन्तवाद के उन्मूलन से पुराने ढाँचे में एक क्रान्तिकारी परिवर्तन आ जाना, (3) भारी मूल्य उच्चावचन हो रहे थे जिन्होंने सटोमियो को दानदार अबसर प्रदान किये, तथा (4) अन्त में, पश्चिमी तकनीक अपनाने के परिणामस्वरूप कई समाधान, जिन्हे पहले बेकार समझा जाता था, बहुमूल्य बन गये।

मेजी काल के दूसरे दशक की समाप्ति तक निजी पूँजी सचय सर्वाधिक विदेशी व्यापार, सट्टेबाजी, खान क्षेत्र व वास्तविक परिमम्पत (Real Estate) के क्षेत्र में हुआ। राजनीति से सम्बद्ध व्यापारियों के वर्ग का उदय इस अवधि की एक अन्य महत्वपूर्ण घटना थी। पुनर्संस्थापना के बाद स्थापित सरकार का मुख्य राजनीतिक उद्देश्य आधुनिकीकरण करना था। सरकार ने सहज रूप से सोचा कि सुयोग्य निजी व्यवसायी लोग आगे आ सकेंगे तथा वे लोग देश के औद्योगिक विकास को नई गति प्रदान कर सकेंगे। पुनर्संस्थापना ने प्रारम्भ में इन धनी व्यक्तियों को भयभीत कर दिया था।

इन्हीं परिस्थितियों में सरकार ने स्वयं ही औद्योगिक प्रतिष्ठानों की स्थापना करने का प्रयास किया था मगर उसे सफलता नहीं मिली। जब सरकारी स्वामित्व वाले प्रतिष्ठान असफल हो गये तो यही आशा की गई अधिक आधुनिकीकरण का सक्षम निजी व्यक्तियों द्वारा अधिक तेजी से प्राप्त किया जा सकेगा। आवश्यकता इस प्रकार के निजी व्यवसायों की थी जिनमें (1) नये जमाने की प्रवृत्तियों को समझने की अन्तर्दृष्टि, (2) व्यवसाय का संचालन करने की योग्यता, तथा (3) आवश्यक पूँजी प्राप्त कर सकने की शक्ति का संयोग हो।

नई मेजी सरकार के पास अपने पहले 20 वर्षों में इन राजनीतिक व्यवसायियों की सहायता माँगने के अतिरिक्त कोई चारा न था। यह ऐसा समय था जब कम्पनी प्रणाली पूरी तरह विवक्षित नहीं हुई थी तथा अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण के लिए उपयुक्त निजी उद्यमकर्ताओं की आवश्यकता थी। सरकार ने इन लोगों को संरक्षण व सहायता का आश्वासन दिया। इस तरह योग्यता वाले निजी व्यवसायियों को चुनना आवश्यक बन गया। इनमें या तो वे धनी लोग आते थे जो मेजी सरकार के साथ सहयोग करना चाहते थे या भूतपूर्व समुराई (Samurai) लोग या फिर वे सामान्य लोग जिन्होंने अपने व्यवसाय मेजी पुनर्संस्थापना से तुरन्त पहले या बाद में शुरु किये थे। सरकारी संरक्षण में इन लोगों ने शीघ्र ही भारी सम्पत्ति अर्जित कर ली। अपनी इसी पूँजी के बल पर ये लोग मेजी युग में हुए औद्योगिक विकास के दाहक बन गये।

इन राजनीतिक व्यवसायियों के समूह द्वारा निजी व्यवसाय गठित करने का प्रयास सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा उसके प्रतिष्ठानों को बहुत ही कम मूल्य पर बेच दिये जाने से काफी मजबूत हुआ। किन्तु यहाँ एक बात याद रखनी होगी कि इस बात की कोई गारन्टी नहीं थी कि ये निजी व्यवसायी उन कारखानों से लाभ बँटा लेंगे जिनमें पहले सरकार घाटा खाकर बैठ रही थी। इन व्यवसायियों को धनी बनाने में दूसरे तरीके से सरकार ने सहायता की दृष्टि से उनसे भारी लाभ पर सैनिक सामान खरीदा।

मेजी युग के उत्तरार्द्ध के विश्लेषण से यही पता चलता है कि जिन शक्तिशाली उद्यमियों ने जापान के उद्योगों को विवसित किया वे ही लोग थे जिन्होंने सरकारी सहायता का लाभ उठाते हुए पूँजी संचय किया था जो आधुनिक उद्योगों के लिए आवश्यक था। इस तरह सरकार द्वारा व्यापारियों को प्रोत्साहित करने की नीति के साथ भ्रष्टाचार का भी खतरा जुड़ा था। किन्तु मुख्य औद्योगिक स्वावलम्बन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शक्तिशाली निजी व्यवसायियों को सरक्षण के अन्तर्गत आगे लाना भी आवश्यक था ताकि वे विदेशी पूँजी की प्रतिस्पर्धा का मुकाबला कर सकें। जहाँ तक भ्रष्टाचार या दुरुपयोग का प्रश्न है वह तो सारे ससार में आज तक भी कायम है। मेजी नीति के गुण-दोषों का मूल्यांकन इसी रोशनी में किया जाना चाहिए।

औद्योगिक विकास में जैबत्सु (Zaibatsu) का योगदान

वित्तीय गुट (Financial clique) जैसे संगठन के विकास ने, जिसे जैबत्सु कहा गया, जापान के उद्योगों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पीर-बवर्ची-मिश्टी-खर जैसे ये जैबत्सु मेजी काल के दूसरे दशक से ही बनने आरम्भ हो गये थे। मित्सुबि, मित्सुबिशी तथा सुमीतोमो तीन सबसे बड़े जैबत्सु थे। ये जैबत्सु तब तक चलते रहे जब तक द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद जापान पर अमरीकी आधिपत्य वाली सरकार ने इनको एक आदेश द्वारा समाप्त नहीं कर दिया।

संयुक्त पूँजी कम्पनी प्रणाली

तीसरे मेजी दशक के बाद संयुक्त पूँजी कम्पनी प्रणाली की शुरुआत व तीव्र विकास ने भी जापान में आधुनिक उद्योगों के विकास को गति प्रदान की। 1876-81 के बीच कई कम्पनियाँ दिवालिया हो गईं। इस प्रणाली को अचानक प्रत्यारोपित करना सरकार की गलती रही। जैसा कि एडम स्मिथ ने भी कहा था, संयुक्त पूँजी कम्पनी प्रणाली यूरोप में भी केवल स्थिर व्यवसायों जैसे बैंकिंग व रेल-मार्गों के लिए ही उपयुक्त थी।

अब, जापान में कम्पनियों के विकास को समग्रता से देखने पर कहा जा सकता है कि इनका प्रारम्भिक काल 1885 तक चला। प्रथम विकास की अवस्था रेल-मार्ग तथा कपास की कटाई के उद्योग में 1886 से 1893 तक चली। अन्तर्द्विक विफलता 1894 के बाद से शुरू हुआ तथा 'धन कमाने का युग' प्रथम महायुद्ध के समय आया।

कम्पनी प्रणाली की निम्न उपसब्धियाँ रही—

(1) नेशनल बैंकों की स्थापना संयुक्त पूँजी कम्पनी प्रणाली की शुरुआत के कारण ही सम्भव हुई।

(2) एक ही व्यक्ति आधुनिक उपकरणों से युक्त विशाल औद्योगिक उपक्रम के प्रबन्ध में आने वाले खतरों या कठिनाइयों का सामना नहीं कर सकता था। अग्रणी औद्योगिक प्रतिष्ठान जैसे निप्पोन रेलवे कम्पनी व ओसाका स्पिनग कम्पनी

संयुक्त पूंजी कम्पनी प्रणाली की शुरुआत के बाद ही स्थापित किये जा सके थे।

(3) कम्पनी प्रणाली में नये दल लोग आकर्षित होते थे। इनमें से अनेक लोग 1890 से 1925 तक आधुनिक अर्थव्यवस्था के विकास की अवधि में प्रमुख योगदान देने वाले व्यक्ति भी बने।

मेजी पुनर्संस्थापना के बाद जो निजी व्यवसाय सबसे पहले बड़े पैमाने पर किये जाने लगे उनमें बैंकिंग तथा जहाजी सेवा प्रमुख थे। रेल-मार्ग कम्पनियों व पूंजी प्रधान उत्खनन द्वारा इनका अनुमरण किया गया। किन्तु विनिर्माण के क्षेत्र में लम्बे डग भरे गये। वास्तव में तो उनमें ही जापानी अर्थव्यवस्था की चमत्कारिक प्रगति का आभास हुआ। हालांकि इसकी शुरुआत सरकार द्वारा की गई थी किन्तु इसका वास्तविक विकास निजी साहसियों द्वारा ही किया गया।

बड़े पैमाने पर विनिर्माण का विकास

निम्नांकित पाँच शीर्षक उन कारणों या स्रोतों को इंगित करते हैं जिनसे विनिर्माण उद्योगों की शुरुआत हुई—

(1) सरकार द्वारा शुरू की गई व प्रत्यारोपित औद्योगिक इकाइयाँ जो मुख्यतः सैनिक उद्देश्यों के लिए थी जैसा जहाज निर्माण एवं इस्पात।

(2) वे उद्योग जिनका प्रत्यारोपण सरकारी प्रबन्ध में हुआ या जिन्हें काफी सरकारी संरक्षण प्राप्त था जैसे व्यापारिक जहाजी सेवा, रेल मार्ग कम्पनियाँ, तार सेवा आदि।

(3) आयातों को घटाने के लिए शुरू या प्रत्यारोपित उद्योग जैसे कपास की कटाई (Cotton spinning)।

(4) निर्यातोंमुख उद्योग जैसे यन्त्रीकृत रेशम रीजिंग व चीनी मिट्टी के उद्योग।

(5) आधुनिक उद्योग जिनकी शुरुआत व प्रत्यारोपण विकास के लिए तब शुरू हुआ जब पूंजी उपलब्ध होने लगी थी। इनमें ताँबा परिशोधन एवं विधायन, लोहा व इस्पात उद्योग तथा कोयला प्रमुख थे।

उपर्युक्त उद्योग जापान में आधुनिक प्रतिष्ठानों की शुरुआत के प्रमुख कारण रहे। ये आधारभूत उद्योग आपस में एक-दूसरे पर निर्भर भी थे। कृषि में रेशम उद्योग चलता था। खनिज वच्चे मालों, जैसे ताँबा व कोयला, में सम्बन्धित उद्योग चलते थे। जहाजी सेवा तथा रेल-मार्ग कम्पनियों ने यानायात के लिए आवश्यक उपकरणों की माँग बढ़ाई। सैनिक उद्देश्यों के लिए कार्यरत उद्योगों का लाभ हुआ। औद्योगिक प्रसार की ये घटनाएँ मेजी शासन के प्रथम 20 वर्षों में घटी।

1885 के पहले सच्चे अर्थों में विनिर्माण उद्योग के उदाहरणों में सूत कटाई, सिल्क की यन्त्रीकृत रीजिंग तथा जहाज-निर्माण से सम्बन्धित क्रियाओं को लिया जा सकता है। किन्तु जापान के आधुनिक विनिर्माण के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान सूत कटाई (Cotton spinning) का रहा।

निर्माण, मृत कत्ताई व खान क्षेत्र में आया ।

(3) पूँजी के अत्यधिक प्रयोग में उत्पादकता भी बढ़ी ।

(4) जापानी अर्थव्यवस्था की पूँजी संचय की क्षमता भी काफी बढ़ गई ।

(5) रेल मार्गों, जहाजों तथा धानों के काम आने वाले पूँजीगत उपकरणों के लिए बड़ी हुई माँग के कारण अनेक उद्योगों को गृहला को जन्म मिला ।

(6) इससे मानवीय पूँजी-निर्माण में सहायता मिली ।

इस तरह आधुनिक बड़े पूँजी प्रधान उद्योग मेज़ी काल के दूसरे दशक तक स्वयं स्फूर्त विकास की अवस्था (Take off stage) में पहुँच गये । तीसरे दशक तक तो वे न केवल अपने आप प्रगति करने लगे बल्कि अन्य विनिर्माण उद्योगों के विकास में भी वे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने लगे । इसी सन्दर्भ में मेज़ी पुनर्संस्थापना के पहले दो दशकों के तबु उपक्रम, सरकारी व निजी, विशेष महत्त्व के रहे ।

औद्योगिक विकास 1888-1914

एक बार जब स्वयं स्फूर्त विकास (Take-off) के लिए अन्तरिम शर्तें पूरी हो गईं तो एच केन्द्र (Hub) सा बन गया जिसके चारों ओर अर्थव्यवस्था का विकास जारी रह सक्ता था । 1887 के आस पास ही रेल मार्ग व व्यापारिक जहाजों सेवा में इस सीमा तक मुधार हो चुके थे कि उनमें जापान की अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण में सहायता मिलने लग गई ।

उदाहरण के लिए रेल मार्गों की लम्बाई 1885 में 351 मील से बढ़कर 1915 तक 6,539 मील हो गई । जहाजों टन भार इसी अवधि में 60,000 टन से बढ़कर 15,30,000 टन हो गया । 1911 तक सभी मुख्य मार्गों पर काम पूरा हो चुका था ।

बैंकिंग व्यवस्था भी प्रभावशाली होने लगी थी । बैंक ऑफ जापान हालांकि 1882 में स्थापित हो चुका था किन्तु एक केन्द्रीय बैंक के रूप में उसने अपना कार्य 1887 के बाद ही पूरी तरह शुरू किया । बैंक ने उद्योगों द्वारा की जाने वाली अधिकाधिक पूँजी की माँगों को साख निर्गमन द्वारा पूरा किया । जापानियों को उनके छोटे हुए व्यावसायिक अधिकार भी पुन प्राप्त हो गये । विदेश व्यापार कम्पनियों का एकाधिकार नष्ट हो गया । 1874 में आयातों पर विदेशी व्यापारियों का अधिकार 99% तक था । 1899 तक वह 60% पर आ गया । बड़े पैमाने के उद्योगों के विकास के लिए मुहृद आधार की दृष्टि से कृषि को भी आधुनिक बनाने की चेष्टा की गई ।

खनन के क्षेत्र में भी क्रांति आयी । सीमाग्य से मेज़ी जापान में ताँबा, मोना, चाँदी, कोयला व अन्य कुछ खनिज पदार्थ मौजूद थे । तकनीक के अभाव में उनमें से अधिकांश अभी तक अप्रकट ही रहे थे । पुनर्संस्थापना के बाद खनन के विकास से सफलता व लाभ दोनों ही प्राप्त हुए । इन खनिजों के निर्यात में काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई ।

खनिजों के उत्पादन में वृद्धि

वर्ष	कोयला ('000 टन)	ताबा (टन)	सोना (कि० ग्राम०)	चादी (कि० ग्राम०)
1875	567	2,399	174	6,993
1890	2,608	18,115	727	52,844
1900	7,429	25,809	2,125	58,806
1910	15,681	49,324	4,368	1,41,613
1920	29,245	67,792	7,719	1,53,164
1925	31,459	66,487	8,463	1,26,195

Source . Bank of Japan's Statistical Section

कोयला उद्योग के विकास से रेल-मार्गों, जहाजों, कारखानों आदि के विकास में सहायता मिली। खानों का विकास करने के लिए काम में जाने वाली मशीनों का पहले तो आयात होता था किन्तु धीरे-धीरे उनका विनिर्माण भी आरम्भ हो गया। घातुओं को साफ करने के काम के पूरक विनिर्माण के रूप में बिजली के तार बनने लग गये। इस तरह आधुनिक विनिर्माण के विकास में खनन एक महत्त्वपूर्ण आधार बन गया।

औद्योगिक विकास में सरकारी नीतियों का योग

(1) 1894-95 के चीन-जापान युद्ध के बाद सरकार ने सैनिक सामग्री के क्षेत्र में आत्म-निर्भर बनने का निर्णय कर लिया। इससे जहाज-निर्माण व शस्त्र निर्माण सम्बन्धी क्रियाओं को तीव्र किया गया।

(2) 1896 में पारित जहाज निर्माण प्रोत्साहन विनियमन के अन्तर्गत अपनायी गयी नीति के अनुसार जापान में ही युद्धपोत बनाये जाने लगे।

(3) रुम के साथ युद्ध के बाद रेलों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया तथा निजी कारखानों द्वारा रेलों के डिब्बे आदि बना सकने के प्रयास किये गये।

(4) तार, टेलीफोन, बिजली आदि सेवाओं का प्रसार करने में जापानी सरकार ने देश में ही बने उपकरणों का अधिकाधिक प्रयोग करने की नीति अपनायी।

इस तरह सरकारी संरक्षण नीति के माध्यम से कई अन्य विनिर्माण उद्योगों का भी विकास हुआ। 1885 के बाद चाँदी के मूल्यों में गिरावट के कारण नुफा घेन के अनधिकृत अवमूल्यन के कारण भी जापान को लाभ रहा। फलस्वरूप जापानी निर्यात अधिक मस्ते पड़ने लगे।

(5) चीन-जापान युद्ध के बाद जापानियों का यह भय तो दूर हो गया कि अगर उन्होंने विदेशी सहायता ली तो उन्हें भी गुलाम बना लिया जाएगा। इससे विदेशी पूँजी के उपयोग में भारी वृद्धि हुई। विदेशी पूँजी आयात करने की सरकारी नीति 1897 में आरम्भ हुई। उसी वर्ष उसने 43 मिलियन येन मूल्य की विदेशी पूँजी का आयात किया। 1913 तक विदेशी पूँजी आयात 1,970 मिलियन

येन पहुँच चुका था। इस नीति ने न केवल अर्थव्यवस्था के तेजी के साथ निर्माण में सहायता की बल्कि उसने जापान के औद्योगिक विकास के लिए अनिवार्य पूँजी भी उपलब्ध करायी।

(6) प्रसुल्लभ नीति पर पुनः नियन्त्रण स्थापित हो जाने के कारण भी सरकार जापान का औद्योगिक उत्पादन बढ़ा सक्ने में सफल हुई। 1899 से पहले आयात शुल्को की दर लगभग 36 प्रतिशत थी। तट-कर सम्बन्धी स्वायत्तता पूरी तरह लौट आने के बाद जापानी सरकार ने 1913 में आयात शुल्क 20% कर दिये। इस वृद्धि से सूती धागे का आयात तो बन्द हो ही गया। इससे सरकार की आय में भी वृद्धि हुई।

कुल मिलाकर इन सबका परिणाम यह हुआ कि चीन के साथ युद्ध के बाद की जापानी अर्थव्यवस्था में निर्मित वस्तुओं के निर्यात चढ़ते चले गये। आयात प्रतिस्थापन उद्योग भी काफी विकसित हुए। जापान उस स्थिति में पहुँच गया जहाँ उसकी अर्थव्यवस्था आधुनिक अर्थव्यवस्था के जैसी हो गई। 1902 में विद्यमान 8,612 कम्पनियों में से 84% की स्थापना 1894-1902 में हुई थी। कारखानों के क्षेत्र में 55% कारखाने उपर्युक्त अवधि में प्रारम्भ किये गये। इसलिए यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि प्रथम विश्व-युद्ध के दौरान जापान का विश्व के एक महान् विनिर्माण राष्ट्र के रूप में विकास 1904-05 में रूस पर विजय के बाद ही आरम्भ हो गया था।

विभिन्न क्षेत्रों से राष्ट्रीय आय

(प्रतिशत में)

पञ्चवर्षीय औसत	प्राथमिक क्षेत्र	विनिर्माण उद्योग क्षेत्र	सेवा क्षेत्र
1878-1882	64.6	10.6	24.8
1893-1897	51.4	18.7	29.9
1918-1922	34.2	25.8	40.0
1928-1932	21.8	27.7	50.5
1938-1942	17.7	40.3	42.0

इस प्रकार जापान कृषि अवस्था से विनिर्माण अवस्था में तेजी पुनर्स्थापना के 30 वर्षों बाद पहुँच गया। जापान की राष्ट्रीय आय में कृषि का भाग 1898 में 50% से कम पर आ चुका था। इसी अवधि में निर्यातों में कृषि पदार्थों का अनुपात भी घट गया।

कृषि पदार्थों का निर्यातों में आनुपातिक भाग

(प्रतिशत में)

पञ्चवर्षीय औसत	कृषि पदार्थों का आनुपातिक भाग	विनिर्माण का प्रतिशत भाग
1873-1877	80.4	19.6
1898-1902	44.0	56.0
1912-1916	44.8	55.2
1918-1922	38.8	61.2

मेजी बाल के उत्तरार्द्ध में विनिर्माण क्षेत्र में हुई प्रगति का एक प्रभावशाली माप उत्पादन प्रक्रियाओं में हुआ यंत्रीकरण रहा। रेशम लपेटने के क्षेत्र में हुई यांत्रिक प्रगति एक ऐसा ही उदाहरण है।

रेशम लपेटने (Reeling) में यांत्रिक प्रगति

(रेशम उत्पादन का प्रतिशत)

वर्ष	मशीन द्वारा लपेटना	हाथों से लपेटना
1893	41	59
1903	58	42
1914	77	23
1921	84	16
1925	87	13

अधिकाधिक कारखाने मोटर शक्ति का उपयोग करने लग गये। तृतीय मेजी दशक में लगभग 30% कारखाने मोटर शक्ति का उपयोग कर रहे थे। 1914 में यह प्रतिशत 60 हो गया। 1925 में यह 78% तक पहुँच गया। विनिर्माण में लगी हुई कंपनियों की प्रदत्त पूँजी, जो 1896 में मात्र 400 मिलियन येन थी, 1913 में बढ़कर 2,000 मिलियन येन तथा 1924 में 10,849 मिलियन येन हो गई।

अगर हम गौण उद्योगों को खनन व विनिर्माण उद्योगों में उपविभाजित करें तथा 1887 के आय स्तरों की 1912 के आय स्तरों के साथ तुलना करें तो ज्ञात होता है कि विनिर्माण में आय में आठ गुना वृद्धि हुई। विनिर्माण में भी प्रमुख उद्योग बतार्ई-बुनार्ई का था जिसमें 1912 में कुल धूम-शक्ति का 65% लगा हुआ था। सूती कपड़े के निर्यात, जो 1890 में मात्र 1,70,000 येन के थे, 1913 तक बढ़कर 33.6 मिलियन येन हो गये। निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है कि किस प्रकार प्रथम महायुद्ध से पहले के 25 वर्षों में तकुओं की संख्या व सूत का उत्पादन बढ़ा

वर्ष	तकुओं की संख्या (हजारों में)	सूत का उत्पादन (मिलियन पौंड में)
1887	77	—
1893	382	88
1897	971	220
1903	1,381	317
1913	2,415	607

औद्योगिक विकास 1914-1938

उन विनिर्माण उद्योगों जो 1914 से पहले ही महत्वपूर्ण बन चुके थे जैसे सूती वस्त्र व रेशम, की क्षमता काफी बढ़ गई। कई अन्य उद्योग जैसे रसायन, ऊनी वस्त्र, इलीक्ट्रिक तथा लोहा व इस्पात, जिन्हें पश्चिम से प्रत्यारोपित किया गया था, भी काफी फैल गये।

विभिन्न उद्योगों का उत्पादन . 1914-1929

वर्ष	सूती धागा (मिलियन पौंड)	कच्चा रेशम ('000 क्वान)	कोयला (मि० टन)	इस्पात ('000 टन)	सीमेंट ('000 टन)	विद्युत शक्ति ('000 कि०वाट)
1913	607	3,741	21	255	645	504
1920	727	5,834	29	533	1,353	1,214
1925	975	8,284	32	1,043	2,508	2,768
1929	1,117	11,292	34	2,034	4,349	4,194

पूर्ति पक्ष की दृष्टि से, इस काल के उद्योगों की उत्पादन के उन्नत तरीकों तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान का लाभ मिला। रेशमी कपड़े का बुनाई उद्योग काफी फैला। सूती वस्त्र उद्योग में प्रगति जारी रही। इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि यह रही कि शक्ति-चालित कारखों में युक्त कई विशाल शेड (shed) स्थापित हो गये। 1928-29 में यही शेड 2/5 सूती वस्त्र निर्माता के लिए उत्तरदायी थे। 1926 के बाद कताई व बुनाई दोनों ही क्षेत्रों में कार्यकुशलता में असाधारण सुधार हुआ। युद्ध से पहले ऊनी वस्त्र उद्योग बहुत छोटा था। किन्तु प्रथम विश्व-युद्ध ने इस उद्योग को भी भारी प्रोत्साहन दिया। गर्म कपड़े का उत्पादन 1914 में 16 मिलियन गज के स्तर से बढ़कर 1929 में 9 मिलियन गज तक जा पहुँचा।

धातु निर्माण उद्योग 1914 के बाद विकसित हुए किन्तु वे सूती वस्त्र की तुलना में दूसरे स्थान पर ही रहे जिनमें अभी भी एक-चौथाई श्रम शक्ति लगी हुई थी। इस्पात का उत्पादन 1914 के 2,55,000 टन से बढ़कर 1929 में 2 मिलियन टन हो गया किन्तु अपनी आवश्यकता का एक बहुत बड़ा भाग जापान अब भी आयात करता था। 90% कच्चा लोहा चीन व मलाया से आयात होता था। युद्ध से पहले अफ्रीका इस्पात सरकारी कारखानों, जो यवाता में स्थित थे, में तैयार होता था। युद्ध के दौरान कई निजी इस्पात मिल भी स्थापित किये गये किन्तु 1929 तक भी यवाता वक्त ही देश के अधिकांश इस्पात का उत्पादन कर रहा था।

कोयला खान उद्योग में भी युद्ध के बाद उत्पादन काफी तेजी से बढ़ा। 1913 से 1919 के बीच यह 21 मिलियन टन से बढ़कर 31 मिलियन टन हो गया। उसके बाद थोड़ा धक्का लगा तथा उत्पादन पुन 1929 में जाकर ही 34 मिलियन टन तक पहुँच पाया। जहाज-निर्माण में भी इस अवधि में प्रगति धीमी रही। भारी उद्योगों में कुल मिलाकर भी प्रगति धीमी रही तथा 1929 तक भी लोहा व इस्पात उद्योग ने जापान के विनिर्माण उद्योगों में उतना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं किया था जितना उसे यूरोप में प्राप्त था। कुछ विदेशियों ने इससे यह निष्कर्ष निकाल लिया कि जापानी लोग केवल हल्के उद्योग ही चला सकते हैं (खासतौर से सूती वस्त्र व अन्य वस्त्र-निर्माण उद्योग) तथा उसके द्वारा 'विनिर्माण राष्ट्र' के रूप में प्रमुख महत्व का स्थान प्राप्त करने की बहुत कम सम्भावना थी।

इजीनिरिंग उद्योग की प्रगति अधिक तीव्र थी। 1920 के बाद अनेक

इजीनियरिंग वस्तुओं के आयातों में भारी गिरावट आ जाने से जापान के अपने इजीनियरिंग उद्योगों का विकास हुआ। एकमात्र अन्य उद्योग, जिसे सम्मिलित किया जा सकता है, चीनी मिट्टी के बर्तन (Pottery) बनाने का था। यह छोटे पैमाने पर चलता रहा।

बड़ी मात्रा में वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन जापान में विशिष्ट रूप से होता रहा। पश्चिमी तकनीक पर आधारित उद्योगों के साथ-साथ छोटे पैमाने के व्यवसाय भी चलते रहे। उनमें से अनेक पश्चिमी देशों के साथ इस सम्पर्क के बावजूद अप्रभावित ही रहे। इनमें आवासीय मकान निर्माण व्यवसाय जापानी तरीके की बेशुभूषण व खाद्य-सामग्री तैयार करने वाले उद्योग तथा कई अन्य सम्मिलित थे। बड़े व नये उद्योगों के आगमन से ये पुराने व्यवसाय विलुप्त नहीं हुए। 1920 के लगभग जापान की अर्थव्यवस्था में एक ओर विशाल पैमाने के नए उद्योगों तथा दूसरी ओर पुराने छोटे पैमाने के उद्योगों के चलते रहने से कई लोगों का ध्यान आकृष्ट हुआ।

1929 से पहले के वर्षों में औद्योगिक विकास की प्रवृत्ति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया तथा निर्यात व्यापार मुख्य रूप से वस्त्रों तक ही केन्द्रित रहा। परन्तु इनमें 1929 से 1937 के बीच भारी परिवर्तन आये। यह वह समय था जब जापान युद्ध की तैयारी कर रहा था। इन वर्षों में उत्पादन में प्रमुख वृद्धि पूँजीगत वस्तुओं के क्षेत्र में लगे हुए उद्योगों में हुई। वस्त्रों के उत्पादन में कुछ सापेक्ष कमी आई जबकि धातुओं व रसायनों तथा इजीनियरिंग सामान का भाग बढ़ता चला गया, 1937 के अन्त तक कुल श्रम-शक्ति में उनका अनुपात बढ़कर 45% हो चुका था।

विभिन्न विनिर्माण उद्योगों में फैक्ट्री रोजगार के प्रतिशत · 1929-1937

वर्ष	वस्त्र	धातुएँ	मशीनें	रसायन	अन्य	कुल	कुल फैक्टरी रोजगार (हजारों में)
1929	50.4	6.2	13.8	6.4	23.2	100	1,825
1936	37.9	9.7	18.3	11.1	23.0	100	2,593
1937	35.2	10.6	20.5	11.0	22.7	100	2,937

लेकिन औद्योगिक प्रगति पूँजीगत वस्तुओं तक ही सीमित नहीं रही। सूती वस्त्र उद्योग आगे बढ़ता रहा व उसने अच्छी व ऊँची किस्म की वस्तुओं का उत्पादन शुरू कर दिया। सूत का उत्पादन दुगुना हो गया व निर्यात घट गये। रेयन उद्योग में सबसे तीव्र प्रगति हुई जो 1937 तक विश्व में पहले स्थान पर आ गया। इस उद्योग ने 1929 के 27 मिलियन पौण्ड रेयन के स्थान पर 1937 में 326 मिलियन पौण्ड रेयन का उत्पादन किया। 1929 से 1936 के बीच रेशम के उत्पादन में तो विशेष गिरावट नहीं आयी किन्तु उसके उत्पादन का मूल्य 857 मिलियन येन से घटकर 517 मिलियन येन पर आ गया। ऐसा रेशम के मूल्यों में कमी आ जाने से हुआ।

इस अवधि में वस्त्र-निर्माण के क्षेत्र में रोजगार में आने वाली सम्पूर्ण सापेक्ष कमी को मन्दी के कारण ही आयी हुई नहीं माना जा सकता। यह कमी उन तकनीकी सुधारों के कारण भी आयी जो इन वर्षों में धर्म की वचन के उद्देश्य से किये गये थे। 1927 से 1933 के बीच पुरानी मशीनें पूरी तरह बदल दी गई।

रसायन उद्योग में भी भारी परिवर्तन हुए। अपव्ययो को घटाकर लागतों को नीचे लाया गया। जैसे 1928 में प्रति 100 पौण्ड कागज का उत्पादन करने के लिए 94 पौण्ड कोयला ऊर्जा के रूप में बाम लिया जाता था। कोयले का यह उपयोग 1937 में गिरकर 57 पौण्ड रह गया। चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने के उद्योग में भी क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए। कन्वेयर बेल्टों (Conveyor Belts) के प्रयोग ने उत्पादन में तेजी ला दी। कोयले की जगह बिजली का इस्तेमाल किया जाने लगा।

लोहा व इस्पात उद्योग में भी तकनीकी सुधार हुए। 1929 से 1936 के बीच लोहा गलाने की मशीनों की औसत क्षमता बढ़कर दुगुनी हो गई। 1936 तक तो तैयार इस्पात के निर्यात उसके आयात से बढ़ गये थे। 1930 से 1936 के बीच धातु-निर्माण उद्योगों में प्रति मानव घण्टे उत्पादन में 25% की वृद्धि हुई। कोयला खानों में जमीन के नीचे काम करने वाले श्रमिकों का प्रतिव्यक्ति (प्रति शिफ्ट) उत्पादन 1928 के 0.7 टन से बढ़कर 1931 में 1.2 टन हो गया। यह और भी अधिक प्रशंसनीय था क्योंकि विनिर्माण में सुधार भी प्रमुख रूप से मन्दी के वर्षों में ही किये गये थे।

सरकारी नीतियों का प्रभाव

सरकार की वित्तीय एवं शस्त्रीकरण की नीतियों ने उद्योगों के विकास को अत्यधिक प्रभावित किया। सरकार ने उद्योगों के संगठन व उनकी कार्यकुशलता दोनों ही में सुधार करने की दृष्टि से कुछ उपाय किये। 1930-31 अर्थात् मन्दी के वर्षों में सरकार ने कई उद्योगों के बंद होने या दिवालिया हो जाने से बचाने हेतु भी कदम उठाये। सबसे महत्वपूर्ण कदम औद्योगिक विवेकीकरण ब्यूरो की स्थापना था जिसमें आपसी समन्वय द्वारा विभिन्न उद्योगों की कार्य-कुशलता बढ़ाने का प्रस्ताव था। ब्यूरो का एक कार्य प्रमुख उद्योग नियन्त्रण कानून के अन्तर्गत उत्पादन, विप्री व मूल्यों का विनियमन करना भी था। 1930-31 में सरकार पर मुख्य रूप से बड़े उद्योगपतियों का नियन्त्रण था इसलिए भी उद्योगों को मन्दी से बचाना सरकार की एक प्रमुख नीति बन गई। किन्तु 1935 तक, मन्दो के खतम हो जाने के बाद, राजनीतिक सत्ता सैनिक तत्वों के हाथों में आ चुकी थी जो राष्ट्र की सामरिक शक्ति में वृद्धि करने के लिए उद्योगों का विनियमन करना चाहते थे।

युद्ध के लिए की जा रही तैयारियों ने उद्योगों पर राष्ट्रीय नियन्त्रण आवश्यक बना दिया। जहाजी सेवा व जहाज-निर्माण के क्षेत्र में विशेष हस्तक्षेप किया गया। आयातित तेल पर शुल्क बढ़ा दिया गया ताकि जल विद्युत् प्रजनन को बढ़ावा मिल सकता। जैवतु की संस्था पर प्रहार किया गया क्योंकि वह राज्य के हितों

को सतरे में डालती थी। सेना में शक्तिशाली घटकों ने एक् अर्द्ध-यौद्धिक अर्थव्यवस्था (Quasi War Economy) के निर्माण पर बल दिया। ये लोग पूँजीपतियों के हितों को नष्ट कर समाधानों को युद्ध-कार्यों की तरफ मोड़ना चाहते थे। वे गुट जो आर्थिक कल्याण में नहीं बल्कि साम्राज्य के विस्तार में अधिक रुचि रखते थे, इस काल में शक्तिशाली हुए। यह निर्णय निश्चलना सही नहीं होगा कि इन वर्षों में जापानी साम्राज्यवाद को बढ़ावा देने वाले तत्वों की जड़ें अधिक बारको में थी।

चीन में पुनः आक्रमण के लिए भारी सैनिक व्यय की आवश्यकता थी। सरकार की घाटे की वित्त व्यवस्था, जो 1937 में 605 मिलियन येन की थी, 1939 तक बढ़कर 1298 मिलियन येन तथा 1941 तक 2,406 मिलियन येन हो गई। धरेलू उत्पादन पर नियन्त्रण लगा दिया गया तथा सैनिक साज-सामान तैयार करने वाले उद्योग पूरे वेग से चलने लगे। इससे शान्तिवालीन उद्योग एवं व्यवसाय अस्त-व्यस्त हो गए।

उद्योगवाद की ओर रूपान्तरण

द्वितीय विश्व-युद्ध के पहले का जापान विभिन्न प्रकार से पश्चिमी यूरोप व अमरीका से निम्नतर था। किन्तु वह लैटिन अमरीका, अफ्रीका व एशिया के देशों से बहुत आगे बड़ चुका था। 1937 में जापान का ऊर्जा उपभोग भारत से 20 गुना था। सबसे महत्वपूर्ण बात विनिर्माण गतिविधियों में वृद्धि की थी। उसका निर्देशांक 1905-09 के 69 से बढ़कर 1930-34 तक 377 पर जा पहुँचा था। स्पष्ट रूप से जापानी उद्योगों के विकास ने इस अवधि में उसके प्राथमिक उत्पादन को बहुत पीछे छोड़ दिया था। इस चौथाई शताब्दी में प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन तो दुगुना भी नहीं हो पाया। विदेश व्यापार व यातायात सेवाओं में भी दो से चार गुना वृद्धि हुई।

विनिर्माण, यातायात व व्यवसाय का विकास 1885-1938

(निर्देशांक 1910-1914=100)

वार्षिक औसत	विनिर्माण उत्पादन	रेल सेवा	आयातों का परिमाण	निर्यातों का परिमाण
1885-89	—	2	16	16
1895-99	37	24	46	31
1905-09	69	68	87	61
1910-14	100	100	100	100
1915-19	160	161	124	168
1920-24	217	218	190	142
1925-29	313	277	242	217
1930-34	377	256	277	327
1935-38	600	354	347	505

समग्र विनिर्माण में हुई वृद्धियों को अगली तालिका में प्रदर्शित किया गया है। यह निर्देशक जो नागोया कॉमर्शियल कॉलेज द्वारा तैयार किया गया था, कुछ बढ़ा-चढ़ाकर विनिर्माण की प्रगति का चित्र देता है किन्तु इतना सही है कि 1905 के बाद विनिर्माण के क्षेत्र में निरन्तर उच्च वृद्धि हुई। यदि यह वृद्धि निरन्तर 5% की भी रही हो तब भी वह प्रभावशाली थी।

जापान में विनिर्माण उद्योग के भौतिक उत्पादन में वृद्धि

(निर्देशक : 1910-1914=100)

वार्षिक औसत	वस्त्र	मशीनें	विजली	समस्त विनिर्माण
1895-99	41	25	—	37
1900-04	50	33	10	48
1905-09	70	61	27	69
1910-14	100	100	100	100
1915-19	152	162	198	160
1920-24	185	244	356	217
1925-29	270	355	653	313
1930-34	352	410	1,002	377
1935-38	416	920	1,517	600

अन्य देशों के साथ जापानी औद्योगिक विकास की तुलना करने से पता चलता है कि जापान को अपनी नेतृत्व की स्थिति दो अवधियों में प्राप्त हुई - प्रथम विश्व युद्ध के वर्ष तथा 1931-35 की महान् मन्दी जब उसकी अर्थव्यवस्था मुद्रा-प्रसार के प्रभाव से आगे बढ़ती गई। इसके विपरीत अधिकांश अग्रणी देशों के आर्थिक इतिहास में इन दोनों अवधियों ने विकास को अवरुद्ध किया।

विनिर्माण गतिविधि का जापान, विश्व व चुने हुए देशों में विकास 1876-1938

(निर्देशक 1913=100)

वार्षिक औसत	विश्व	जापान	अमरीका	इंग्लैंड	भारत
1876-1880	25	—	17	50	—
1881-1885	30	—	24	57	—
1896-1900	54	35	45	74	54
1901-1905	67	48	66	77	69
1906-1910	80	64	79	83	85
1911-1913	94	93	92	93	97
1921-1925	103	205	129	76	122
1926-1930	139	297	160	92	146
1931-1935	128	410	118	92	175
1936-1938	185	631	167	122	230

Source League of Nations, *Industrialisation and Foreign Trade*, 1945

खाली आँकड़ों से उन वास्तविक प्रक्रियाओं का अनुमान नहीं लग सकता जिनसे विनिर्माण उद्योगों में वास्तव में प्रगति हुई। प्रसार के इन वक्रों (curves)¹ के पीछे कई शक्तियों की बेची-दा प्रतिक्रियाएँ निहित हैं। शहरी औद्योगिक रोजगार में जन शक्ति की वृद्धि, बाजारों का विस्तार जिसमें घरेलू व विदेशी दोनों ही स्तरों पर विनिमय में वृद्धि, नये व विविध रूपों में जैसे कारखानों, माल सूचियों व उपकरणों के रूप में पूंजी का संचय, नई तकनीकी दक्षताओं तथा व्यावसायिक संगठन के स्वरूपों का विकास, आदि ऐसी ही प्रतिक्रियाएँ थी। इस विकास की रूपरेखाओं का सार संक्षेप में निम्नांकित तालिका में दिया गया है—

जापान में फैक्ट्री उद्योग का विकास 1909-38

वर्ष	फैक्ट्रियों की संख्या	श्रमिकों की संख्या (हजारों में)	उत्पादन का कुल मूल्य (मिलियन येन)
1909	32,390	1,012	781
1914	31,859	1,187	1,371
1919	44,087	2,025	6,738
1924	48,394	1,977	6,625
1929	60,275	2,384	7,994
1934	80,880	2,580	9,758
1938	113,205	3,718	20,101

जापानी उद्योग के यन्त्रीकरण को प्रमाणित करने वाले आँकड़ों से भी इन वर्षों में हो रहे परिवर्तन का अनुमान लगाया जा सकता है। 1914 से 1938 के बीच फैक्ट्रियों में स्थापित किया गया कुल शक्ति-चालित उपकरण 500% से बढ़ा। 1936 में मोटरो की अश्व शक्ति (Horse Power) क्षमता 5 मिलियन थी। प्रति श्रमिक शक्ति की उपलब्धि 1.69 अश्व शक्ति थी। 1914 के बाद यन्त्रीकरण की प्रगति निरन्तर रही। 1920 के बाद प्रारम्भ हुए विवेकीकरण (rationalisation) अभियान में शक्ति चालित मशीनों व उपकरणों में भारी वृद्धि हुई। विजनों की पूर्ति तो अविश्वसनीय रूप से बढ़ी। 1938 में दस में से नौ जापानी घरों में विजनी पहुँच चुकी थी। उद्योगों के विद्युतीकरण ने जापान को उसके प्राकृतिक ससाधनों का विकास करने तथा गाँवों व बस्वों में छोटे-छोटे कारखानों की स्थापना करने में सहायता की। 1914 से 1938 के बीच श्रम उत्पादकता में असाधारण वृद्धि के पीछे इन वर्षों में वहाँ शक्ति चालित मशीनों के उपयोग में हुई महान् वृद्धि ही थी। उद्योग के भीतर भी प्रबन्धकों व श्रमिकों दोनों ही के अनुभव व कार्यकुशलता में वृद्धि हुई।

जापान के आर्थिक विकास में वहाँ के सेवा क्षेत्र के रोजगार में भी भारी वृद्धि की। आँकड़ें 1880 से 1930 के बीच सेवा-रोजगार में तिगुनी वृद्धि इंगित करते हैं इस प्रसार की प्रक्रिया में अर्थशास्त्री कोलिन क्लार्क ने अपने इस तथ्य की पुष्टि पायी कि आर्थिक विकास ने अन्य स्थानों की तरह जापान में भी ससाधनों को उत्तरोत्तर प्राथमिक क्षेत्र से सेवा एवं विनिर्माण के क्षेत्र में स्थानान्तरित किया है। क्लार्क ने

यह भी पाया कि द्वितीय महायुद्ध के पहले जापान में सेवा उद्योगों द्वारा उत्पन्न रोजगार अन्य औद्योगिक देशों की तुलना में काफी ऊँचा था।

प्रमुख निष्कर्ष

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के प्रकाश में हम कुछ निष्कर्षों पर पहुँच सकते हैं। मेजी पुनर्स्थापना के बाद के 70 वर्षों में जापान की उत्पादक शक्ति में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई। इस रिकॉर्ड में और भी सुधार करने का श्रेय भी जापान की दूसरे महायुद्ध के बाद की औद्योगिक प्रगति को ही है। 1885 से 1935 के बीच समग्र वृद्धियाँ चार गुनी रही। वार्षिक दर के हिसाब से ये वृद्धियाँ 3.3% थी। यमुदा (Yamuda) के अनुमानों से 1885 से 1910 के बीच वास्तविक आय लगभग दुगुनी हो गई। इसके बाद प्रथम विश्व-युद्ध तक वह पुनः दुगुनी हो गई। प्रथम महायुद्ध के बाद के एक दशक में फिर दोहरी होने के बाद 1930 के दशक में उसमें 50% वृद्धि हुई।

यह जापान का सौभाग्य था कि प्रथम महायुद्ध के दौरान उसकी कोई बरबादी नहीं हुई। 1914 से 1938 तक हुए तीसरे जापानी औद्योगिक विकास के लिए एक यह तत्त्व भी उत्तरदायी था। किन्तु 1939 से 1945 का द्वितीय महायुद्ध काल एक अलग कहानी है। पहली बार जापान ने स्वयं को एक अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध में झोंक दिया जिसने उसके उद्योगों पर करारी चोट की तथा उसकी समृद्धि की नींव को ही उखाड़ फेंका।

द्वितीय महायुद्ध के दौरान व युद्धोत्तर-कालीन उद्योग

द्वितीय महायुद्ध के दौरान उद्योगों को सबसे अधिक हानि उठानी पड़ी। औद्योगिक उत्पादन छिन्न-विच्छिन्न हो गया। उद्योग के दौरान लगभग प्रत्येक उद्योग को युद्ध-सामग्री तैयार करने के लिए बाध्य होना पड़ा। इसका परिणाम शस्त्र-निर्माण व अन्य सैनिक सामग्री तैयार करने वाले उद्योगों के असन्तुलित विकास के रूप में सामने आया।

द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति तक लगभग सभी जापानी उद्योग बरबाद हो चुके थे। अधिकांश मशीनें, भवन तथा उपकरण नष्ट हो चुके थे। उसके महान् औद्योगिक शहर मलबे के ढेर बन चुके थे। कच्चे माल का कहीं अता-पता ही नहीं रह गया था। परिणाम यह हुआ कि उसका औद्योगिक उत्पादन युद्ध-पूर्व के स्तर की तुलना में एकदम नीचे गिर गया।

किन्तु जापानी उद्योगों का पुनरुद्धार उतना ही आश्चर्यजनक था जितना कि वह वेगवान था। 1950 से 1953 तक कोरियाई युद्ध ने जापानी उद्योगों के पुनरुद्धार में सहायता की। इसके अलावा 'जापान में बनी हुई' (Made in Japan) वस्तुओं की माँग द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद अत्यधिक तेजी से बढ़ी। युद्ध-पूर्व भारी उद्योगों पर दिया गया अधिक जोर भी उसके दीर्घ पुनरुद्धार में सहायक रहा। इनमें

से अधिकांश भारी उद्योगों ने युद्ध के बाद तीव्र गति से प्रगति की। 1955 तक जापान द्वितीय महायुद्ध की बरबादी से एकदम उबर चुका था। 1963 में तो उसका औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक (1960=100) 142 तक पहुँच चुका था जबकि 1935 में यह 29 था। वस्त्रों का उत्पादन 1955 से 1963 के बीच दुगुना हो गया। रसायनों का 1962 का उत्पादन युद्ध-पूर्व स्तर का चौगुना था। 1970 में जापान में 53 मिलियन कि० वा० बिजली का प्रजनन हो रहा था। 1974 व 1975 के अपवाद वर्षों के अलावा, जब तेल मूल्यों में आकस्मिक तिगुनी-चौगुनी वृद्धि से उसकी औद्योगिक विकास दर द्रुम्य हो चुकी थी, जापानी उद्योग 10% से अधिक ऊँची वार्षिक विकास दर से निरन्तर आगे बढ़ रहे हैं। 1979 में जापान का औद्योगिक उत्पादन विश्व में तीसरा सबसे विशाल राष्ट्रीय उत्पादन है। इस दृष्टि से जापान केवल अमरीका व सोवियत संघ से पीछे है।

महत्त्वपूर्ण भारी उद्योग (IMPOTANT HEAVY INDUSTRIES)

दूसरे मेजी दशक के बाद जापान में एक औद्योगिक प्रणाली का स्वरूप उभरने लगा था। मशीनी तकनीक का आत्मसात्करण (assimilation), बैंकिंग व औद्योगिक पूंजी संचय, विश्व समृद्धि व वृद्धिगत मूल्यों के प्रसारक (expansive) प्रभाव—सभी ने मिलकर तीव्र औद्योगिक उत्पादन सम्भव बनाया।¹

1 वस्त्र उद्योग (Textile Industries)

वस्त्र उद्योगों का विकास जापानी अर्थव्यवस्था में क्रांति लाने वाले तत्वों में अकेला सबसे महत्त्वपूर्ण तत्व था। इसके विकास को तीन प्रमुख कालों में विभाजित किया जा सकता है।

मेजी काल 1868-1913

मेजी काल में जापान में रेशम उद्योग का उत्थान एक परम्परागत उद्योग के अन्तर्राष्ट्रीय माँग की प्रतिक्रिया के रूप में आगे बढ़ जाने का उदाहरण था। प्रथम महायुद्ध के पहले तक विश्व में रेशम माँग बराबर बढ़ती रही। जापानी रेशम उद्योग ने बाजार में प्रभुत्व स्थापित कर लिया। कच्ची रेशम का उत्पादन, जो 1893 में 7.5 मिलियन पौंड था, 1913 तक बढ़कर 28 मिलियन पौंड हो गया। चीन व अन्य यूरोपीय प्रतिद्वन्द्वी काफी पिछड़ गये। 1898 के बाद अमरीका द्वारा रेशम पर आयात शुल्क बढ़ा दिये जाने से कुछ कठिनाई अवश्य हुई। किन्तु रेशम के निर्यात 1913 तक भी सूती वस्त्र निर्यात से आगे हो रहे।

रेशम के उत्पादन में वृद्धि तथा उसकी किस्म में सुधार तकनीकी प्रगतियों द्वारा प्राप्त किये गये। रेशम के कीड़े पालने व रेशम लपेटने, दोनों ही में आधुनिकीकरण हुआ। हाथ में धरखी पर लपेटने की जगह मशीनों का उपयोग शुरू हो गया। किन्तु उद्योग फिर भी प्रमुख रूप से छोटे पैमाने पर ही चलाया जाता रहा। रेशम के कीड़े पालने में लगभग 33% किसानों को पूरक आय प्राप्त होती थी। 1913 में शामोण क्षेत्रों में 4701 मशीन रीलिंग इकाइयाँ स्थापित हो जाने के उपरान्त रेशम हाथ से लपेटने वाली 2.84 लाख इकाइयाँ कार्यरत थी। रेशम बुनने का काम भी किसान लोग ही करते थे। रेशम उत्पादन में मुख्य लागत तत्त्व उसमें लगने वाला

श्रम ही था ।

इस अवधि में विकसित होने वाला दूसरे नम्बर का सबसे बड़ा उद्योग, जो बाद में सही रूप में बड़े पैमाने पर उत्पादन वाला उद्योग भी बना, सूती वस्त्र उद्योग था । सूती वस्त्र उद्योग की प्रगति में यह बात कहनी होगी कि वह सम्पूर्ण विश्व में औद्योगिक क्रान्ति करने में अगुवा रहा है । इस अवधि में जिन तत्त्वों ने सूती वस्त्र उद्योग के विकास में अपना योग दिया वे इस प्रकार थे—(1) एक विशाल तैयार उपभोक्ता बाजार, (2) हस्तशिल्प के साथ इसका तालमेल, (3) कताई व बुनाई के लिए अल्प मजदूरी पर श्रमिकों की उपलब्धि, (4) कपड़ा मिलों की पूँजी के लिए सीमित आवश्यकता (5) चीन व भारत से सस्ते कपास की प्राप्ति, तथा (6) पर्याप्त उष्ण जलवायु जो बुनाई के लिए उपयुक्त थी ।

मेजी शासन के अन्तिम दो दशकों में सूती वस्त्र के उत्पादन में फैक्ट्री प्रणाली मजदूती के साथ स्थापित हो गई थी । 1913 तक जापान के वस्त्र उद्योग का घरेलू बाजार पर पूर्ण वर्चस्व स्थापित हो चुका था । इसके अलावा वस्त्रों के निर्यात को बढ़ाने के प्रयास पूरी तेजी से किये जा रहे थे तथा वस्त्र उद्योग को विश्व में अगुवा बनाने के प्रयास जारी थे ।

सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति 1890 के बाद ही की जा सकी । 1899 तक वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में 1 17 मिलियन तकुओं से युक्त 83 मिल थे तथा सूत का उत्पादन 355 मिलियन पौण्ड हो चुका था । विशाल फर्मों द्वारा उद्योग को आधुनिक बनाने व शक्ति चालित करके स्थापित करने के उद्देश्य से एक जापान कॉटन स्पिनर्स एसोसिएशन भी गठित की जा चुकी थी । 1913 तक उद्योग की क्षमता दुगुनी हो चुकी थी । उद्योग में अब 2 4 मिलियन तकुवे (Spindles) थे तथा सूत उत्पादन 672 मिलियन पौण्ड हो चुका था । कारखानों का आकार व उनकी कताई क्षमता भी काफी बढ़ गई । विदेशी बाजारों में उनकी प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति बेहतर बाजार एवं साख अवस्था तथा उद्योग के एकीकरण से और भी बढ़ गई थी ।

जापान का सूत उत्पादन उनकी शिफ्ट प्रणाली (Shift System) के रात दिन काम करते रहने के कारण पश्चिमी यूरोप के देशों के मुकाबले 2 से 3 गुना था । शक्ति चालित करघों के उपयोग के बाद बुनाई में भी क्रान्ति आ गई । 1913 में इन शक्ति चालित करघों की संख्या 50,000 थी । किन्तु इस अवधि में बुनाई कुटीर उद्योग ही बनी रही । उसमें महिला श्रमिक ही मुख्य रहे । मजदूरी तो जापानी स्तर में भी नीची थी । किन्हीं प्रकार के फैक्ट्री कानून नहीं थे । कुछ अच्छी मिलों को छोड़कर शेष सभी में काम व जीवन की दशाएँ शोचनीय थी ।

किन्तु सूती वस्त्र उद्योग अन्तर्राष्ट्रीय जगत में अपना सिक्का जमा रहा था । 1913 तक जापानी सूत चौथाई विश्व को निर्यात होने लगा था । इसी तरह 1913 में जापान अपनी मिलों में विघ्रायित (processed) आधा कपास विदेशों को भेज रहा था । 1900 के साथ 1913 की तुलना से स्पष्ट है कि कताई मिलों का उत्पादन 150% बढ़ा जिसमें से आधे का निर्यात कर दिया गया । सूती वस्त्र बनाने

के लिए रुई का उपभोग करने वाले दुनिया के देशों में जापान अग्रणी हो गया। 1913 में जापान अपने रुई आयात का 60% भारत से तथा 25% अमरीका से मगवाता था। उसने ब्रिटेन व भारत को चीन के बाजारों से खदेड़ दिया था। किन्तु उसके निर्यात मोटे व भारी किस्म के कपड़ों के थे और वे दूर के बाजारों तक नहीं पहुँचे थे। अभी तक भी जापान विश्व बाजार में लकाशायर मिलों के लिए गम्भीर चुनौती नहीं बना था। 1910-13 में ब्रिटिश निर्यात जापानी निर्यातों का 30 गुना थे। स्वयं जापान में भी सूती वस्त्र उद्योग रेशम के बाद दूसरे स्थान पर था।

यह सही है कि इस अवधि में बड़े पैमाने के उत्पादन ने जापान की कुछ ही आर्थिक गतिविधियों को छुआ था। निम्न तालिका में तबूजों की सख्या व उत्पादन में प्रथम महायुद्ध के पहले के 25 वर्षों में हुई वृद्धियाँ दिखाई गई हैं—

वर्ष	तबूजों की सख्या (हजारों में)	सूत का उत्पादन (मिलियन पौंड में)	कताई कम्पनियों की सख्या
1887	77	—	—
1893	382	88	40
1897	971	220	74
1903	1,381	317	51
1907	1,540	393	42
1913	2,415	607	44

वस्त्र उत्पादन की एक अन्य महत्वपूर्ण शाखा जो पूरी तरह पश्चिमी देशों के सम्पर्क से ही विकसित हुई, ऊन उद्योग थी। सरकार ने 1877 में सैनिकों की बर्दा बनाने के लिए एक फैक्ट्री लगाई थी। इसके बाद 1890 में कुछ निजी फर्म भी लगीं जो सैनिकों के लिए कपड़ा, बम्बलें आदि बनाती थी। ऊनी कपड़ों का उत्पादन, जो 1903 में 82 लाख गज था, 1913 में बढ़कर 176 लाख गज हो गया। किन्तु ये मिल आयातित ऊनी धागे पर आश्रित थे। उद्योग पर कुछ बड़ी कम्पनियों का अधिकार था। 1913 में ऊनी उद्योग के कुल उत्पादन का मूल्य 24 मिलियन येन था।

मेजी युग के अन्त तक वस्त्र उद्योग जापान के विनिर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग बन चुका था। 1913 में विनिर्माण उद्योगों में सगे हुए कुल श्रमिकों में से 60% वस्त्र उत्पादन करने वाले कारखानों में लगे थे। वस्त्र उत्पादन के कुल मूल्य में 37% भाग रेशमी चीजों का तथा 53% भाग सूती वस्त्र का था।

मेजी युग का वस्त्र उद्योग एक ऐसी आर्थिक गतिविधि का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें उसकी परम्परागत कृषक अर्थव्यवस्था तथा एक नवीन पूँजीवादी अर्थव्यवस्था एक दूसरे से मिलते हैं। विनाल कताई मिल निरन्तर ही पूँजीवादी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे किन्तु वे भी अपने श्रमिकों की आपूर्ति हेतु किमान परिचारों पर निर्भर करते थे। इस तरह मूनी, ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन में लगी विनाल इकाइयों को भी पुराने समाज के साथ तालमेल स्थापित कर चलना पड़ रहा था।

विस्फोटक प्रगति 1914-1938

प्रथम महायुद्ध काल तथा उसके बाद के वर्षों में वस्त्र उत्पादन के क्षेत्र

में भारी तकनीकी परिवर्तन प्रारम्भ किये। सूती वस्त्र, ऊन व रेशम उद्योगों के बारे में उपलब्ध आँकड़ों से उनकी इसी तीव्र प्रगति का पता चलता है।

वर्ष	सूत उत्पादन (मिलियन पौंड)	कच्चा रेशम (हजार बबान)	ऊनी कपड़ा (मिलियन गज)
1913	607	3,741	81
1920	727	5,834	71
1925	975	8,284	161
1929	1,117	11,292	222

इन आँकड़ों से स्पष्ट है कि वस्त्र उद्योग ने 1914 के बाद भारी प्रगति की। रेशम उद्योग की भारी प्रगति भी माँग पक्ष की तरफ तो अमरीका में रेशम की भारी खपत से तथा पूर्ति पक्ष की तरफ उत्पादन की विधियों में हुए सुधार व अनुसन्धान से प्रभावित एवं लाभान्वित हुई। अमरीका में जापानी रेशम फैसनेबल कपड़ों के लिए लोकप्रिय बन गया था।

उधर सूती वस्त्र उद्योग में भी भारी प्रगति हुई। तकुओ की सख्या 1913 के 24 मिलियन से बढ़कर 1929 तक 665 मिलियन हो गई। मिल भी बहुत बड़े बन गये। वस्त्र उद्योग में एकीकरण की प्रवृत्ति भी जोर पकड़ गई थी तथा 1929 तक देश के 56% तकुओ केवल 7 इकाइयों के अधिकार में आ चुके थे। 1913 से 1929 के बीच कताई व बुनाई की गतिविधियाँ समुक्त रूप से भी की जाने लगी। कताई करने वालों (Spinners) के पास करघों की सख्या 1913 के 24,000 से बढ़कर 1929 तक 74,000 हो गई। उनका वस्त्र उत्पादन चौगुना हो गया। अब वस्त्र उद्योग ने अच्छे किस्म का कपड़ा भी बनाना आरम्भ कर दिया। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन विशालकाय शेड (Sheds) स्थापित होने का रहा जिनमें 50 से भी अधिक शक्तिचालित करघे लगे होते थे।

मोटे रूप में 1929 तक उद्योग के मुख्य अवयव निम्न थे। (1) कताई मिलें जो धागा बुनकरों व निर्यात के लिए तैयार कर रही थी, (2) बड़े कताई-बुनाई मिल जो अपने सूत का स्वयं उपयोग करते तथा निर्यात के लिए कपड़ा बना रहे थे, (3) मध्यम आकार के बुनाई शेड (Weaving Sheds) जो शक्तिचालित करघों का उपयोग करते तथा निर्यात के लिए कपड़ा बना रहे थे, (4) छोटे बुनाई शेड जिनमें 50 से कम करघे थे तथा जो घरेलू बाजार के लिए कपड़ा बुनते, तथा (5) अवनति की ओर अग्रसर घरेलू उद्योग जिनमें हथकरघे लगे थे।

1926 के बाद कताई व बुनाई दोनों ही क्षेत्रों में कार्यकुशलता में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई। ऊन उद्योग को प्रथम महायुद्ध से बहुत प्रोत्साहन मिला। सूत का उत्पादन 1921 के 21 मिलियन पौण्ड से बढ़कर 1929 तक 64 मिलियन पौण्ड हो गया। 1920 के बाद घरेलू स्तर पर ऊनी वस्त्रों की बढ़ी हुई माँग में भी प्रमुख भाग जापानी ऊन उद्योग को ही मिला।

इन आँकड़ों को देखते हुए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अग्रणी वस्त्र

उद्योगों का 1913 से 1929 के बीच काफी तीव्र विकास हुआ। उनके उत्पादक तरीकों तथा उनकी कार्य-कुशलता में भारी सुधार हुए। इतना ही नहीं, वस्त्र-निर्माण में लगे उद्योगों ने जापानी औद्योगिक प्रणाली में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाये रखा। 1930 में उनमें कुल श्रमिकों में से 25% श्रमिक लगे थे।

तकनीकी प्रगति सूती वस्त्र उद्योग में अधिक उल्लेखनीय रही। उत्पादन के पैमाने में भी भारी वृद्धि हुई। कार्यरत तकुजों की औसत संख्या 1929 के 5.8 मिलियन से बढ़कर 1935 में 8.2 मिलियन पर जा पहुँची।

सूत उत्पादन

	(मिलियन बॉड में)
1913	492
1923	796
1929	1,026
1934	1,158
1937	1,485

सूती चीजों के निर्यात भी इस अवधि में तेजी से बढ़े जिसका संवेत विम्ब तालिका से मिलता है

सूती वस्तुओं (Cotton goods) का निर्यात

	(मिलियन येन में)
वर्ष	रक्ति
1913	34
1918	238
1921	206
1925	433
1929	413
1931	199
1934	492
1936	484

सूती वस्त्र उद्योग में कुल करघों की संख्या

	(हजारों में)		
करघों का प्रकार	1922	1929	1936
हथ करघा	165	86	51
छोटे शक्ति चालित करघे	122	106	76
बड़े शक्ति चालित करघे	96	171	266

द्वितीय महायुद्ध व युद्धोत्तर काल

द्वितीय महायुद्ध ने वस्त्र उद्योगों को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया था। उधर रेशम उद्योग को कच्चा माल न मिलने से हानि हो रही थी। युद्ध के बाद रेशम उद्योग को उसके पुराने उत्पादन स्तर तक पहुँचाने के प्रयास किये गये। मजदूरी व लागतों में भारी वृद्धि हो जाने के कारण युद्ध के बाद रेशम उद्योग में कुछ संरचनात्मक परिवर्तनों की आवश्यकता थी। श्रम वृद्धि के उपाय शुरू किये गये। किन्तु इन सबसे कोई लाभ नहीं हुआ क्योंकि युद्ध के बाद तो रेशम उद्योग की माग ही घट जाने से उसकी अवनति हो रही थी। फिर मनुष्य-निर्मित कृत्रिम धागों से बने कपड़ों ने तो रेशम की माग को और भी घटा दिया। निर्यातों में उसका भाग इस स्तर तक गिरा कि 1936 में 85 मिलियन गज से घटकर वे 1963 में 62 मिलियन गज पर आ गये। 1979 तक रेशम का जापान के निर्यातों में प्रतिशत भाग नगण्य हो चुका है।

सूती वस्त्र उद्योग को भी द्वितीय महायुद्ध से उतनी ही हानि हुई। 1937 में कार्यरत 285 मिलों की जगह 1945 में सिर्फ 38 मिल सुरक्षित बच रहे थे। इसी अवधि में तकुओं की संख्या 12.5 मिलियन से घटकर 2 मिलियन पर तथा करघों की संख्या 1,16,000 से घटकर 23,000 पर आ गई। द्वितीय महायुद्ध में सूती वस्त्र उद्योग की इस विशाल स्तर पर हुई बरबादी ने उसके पुनर्निर्माण को एक गम्भीर समस्या बना दिया।

कच्ची रई के अभाव ने समस्या को और भी विकट व पेचीदा बना दिया। 1946 में अमरीकी आधिपत्य वाली सैनिक सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संधि वस्तु साख निगम से प्रार्थना की कि वह जापान को 2 लाख रई की गाँठें भिजवाए। आधिपत्य सरकार (Occupation Government) ने सूती वस्त्र उद्योग की क्षमता को 4 मिलियन तकुओं तक प्रतिबन्धित कर दिया। यह सीमा 1937 में जापान द्वारा प्राप्त की जा चुकी क्षमता का भी एक-तिहाई थी।

जब 1952 में अमरीकी आधिपत्य समाप्त हुआ तो सम्पूर्ण उद्योग को पुनर्गठित करने के प्रयास नये सिरे से प्रारम्भ किये गये। कई मिलों ने नवीनतम मशीनें प्राप्त कर ली तथा प्रति मानव घण्टा उत्पादकता एकदम बढ़ने लगी। साथ ही साथ कृत्रिम रेशों वाले उद्योग में भी विनियोग किया गया। अब सम्पूर्ण उद्योग पर 10 बड़ी फर्मों का नियन्त्रण है। उनके अलावा लगभग 8,200 स्वतन्त्र उत्पादक हैं। 10 विशाल कम्पनियों का लगभग 109 मिलों पर नियन्त्रण है। इनमें 14 लाख मजदूर लगे हैं। छोटे स्वतन्त्र निर्माताओं ने भी 1 लाख मजदूर रखे हुए हैं। जापान ने वस्त्र उत्पादन व निर्यात के क्षेत्र में विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है। हालांकि भारत, ब्रिटेन की सूती वस्तुएँ तथा अमरीकी कृत्रिम रेशों के कपड़े उसके बहुत निकट के प्रतिद्वन्द्वी हैं। 1969 में जापान का कृत्रिम रेशों का उत्पादन 13 मिलियन टन तथा सूती वस्त्र का उत्पादन 280 मिलियन गज था।

1979 में स्थिति के विस्लेषण से यही पता चलता है कि कृत्रिम रेशों वाले

उद्योगों ने सूती वस्त्रों से बाजी मार ली है। इजीनियरिंग व रासायनिक वस्तुओं के उत्पादन व निर्यात में वृद्धि हो जाने से जापान के निर्यातों में सूती वस्त्र के निर्यात का प्रतिशत भाग भी घटता जा रहा है। अब देश के निर्यातों में उसका प्रथम स्थान नहीं है जैसा कि 1930 के बाद के दशक में था।

2. लोहा व इस्पात उद्योग

तत्काल निर्माताओं के रूप में जापानी शिल्पियों को शताब्दियों तक प्रतिष्ठा मिलती रही। किन्तु हुआ कुछ इस तरह कि विभिन्न धातुओं जिनमें लोहा व इस्पात भी सम्मिलित है, के उत्पादन में पश्चिमी उत्पादन पद्धतियाँ अपनाने में जापान को सर्वाधिक कठिनाई हुई। इस कठिनाई के लिए कई कारण उत्तरदायी थे

(1) धातु व भारी इजीनियरिंग सामान के उत्पादन में अधिक खर्चीली पूंजीगत वस्तुएँ चाहिए थी।

(2) धातु विनिर्माण के वर्तमान तरीके परम्परागत तरीकों से अत्यधिक भिन्न थे। उनके लिए उच्च वैज्ञानिक जानकारी तथा प्रशिक्षित श्रमिकों की आवश्यकता थी।

(3) किसी भी देश के लिए धातुओं को सर्वोत्तम पैमाने पर विनिर्मित करना तभी सम्भव है जब वहाँ कई धातुओं का एक साथ विनिर्माण होता हो। उसके लिए विशाल बाजार भी आवश्यक था।

(4) कोयले व लोहे, दोनों ही के अभाव के कारण भी जापान को काफी कठिनाई थी। उद्योग को भारी मात्रा में सरकारी सुरक्षण की आवश्यकता थी। इसे सरकारी सहायता राजनीतिक कारणों से अधिक व आर्थिक लाभों से कम मिली।

प्रथम अवस्था 1881-1914

प्रारम्भिक मेजो वर्षों में लोहे का घरेलू उत्पादन उतना था जितना लोहा-युक्त रेत से प्राप्त हो पाता था। 1896 में लोहे का घरेलू उत्पादन मात्र 26,000 टन था। इस्पात का उत्पादन देश में शून्य था तथा 22 लाख टन की सम्पूर्ण आवश्यकता आयात द्वारा पूरी होती थी। सरकार ने 1901 में श्वेता आयरन

लोहा व इस्पात उद्योग

(हजार टनों में)

वर्ष	लोह पिंड	तैयार इस्पात
1896	26	1
1906	145	69
1913	243	255
1920	521	533
1925	685	1,043
1929	1,087	2,034
1931	917	1,663
1936	2,008	4,539

वर्षों के नाम से एक कारखाना लगाया। कुछ वर्षों बाद कई निजी कम्पनियों द्वारा भी बहुत से कारखाने लगाये गये। इसके परिणामस्वरूप 1913 तक लोह पिंडों का उत्पादन 2,43,000 टन तथा इस्पात का उत्पादन 2,55,000 टन तक पहुँच गया। इससे घरेलू आवश्यकताओं का क्रमशः 48% व 34% पूरा होता था। शेष आयात किया जाता था। तकनीकी कठिनाइयों तथा कच्चे लोहे व कुकिंग कोयले की कमी के कारण इस उद्योग को काफी कठिनाइयाँ उठानी पड़ी।

प्रसार का काल 1914-1938

हालांकि 1914 से 1929 के बीच धातु विनिर्माण उद्योगों का काफी प्रसार हुआ किन्तु अभी भी वे गौण महत्त्व की ही रही। 1929 में इस्पात उत्पादन 2 मिलियन टन से कुछ ऊपर था किन्तु फिर भी जापान को आयातों पर निर्भर रहना पड़ता था। आशाजनक तथ्य यही था कि आयातों पर उसकी यह निर्भरता निरन्तर घटती जा रही थी। प्रथम महायुद्ध से पहले तक अपने घरेलू उत्पादन से जापान को उसकी जरूरतों का 30% इस्पात मिल पाता था। 1929 में यह प्रतिशत 70 तक पहुँच गया। 1929 में लोह पिंड उत्पादन भी 1913 की तुलना में चार गुना हो चुका था। धातु गलाने की भट्टियों के लिए 90% कच्चा लोहा चीन व मलाया से आयात किया जाता था। अधिकांश लोह पिंडों का उत्पादन यवाता आयरन वर्क्स में होता था।

लोहा व इस्पात बनाने के तरीकों में भी सुधार हो रहा था। 1929 से 1936 के बीच भट्टियों की औसत क्षमता दुगुनी हो गई। बिजली से गलाए जाने वाले इस्पात का भी उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ने लगा। इसने जापान की उच्च किस्म का इस्पात बना सक्ने की क्षमता का सकेत दिया। विभिन्न प्रकार के इस्पात तैयार कर सक्ने की उसकी क्षमता भी काफी बढ़ गई।

द्वितीय महायुद्ध व उसके बाद

लोहा व इस्पात उन उद्योगों में से था जिन्होंने द्वितीय महायुद्ध के वर्षों में ही कीर्तिमान स्थापित किये। इसका परिणाम यह हुआ कि 1943 में जापान के के पास सम्पूर्ण क्षत्र का सबसे विशाल लोहा व इस्पात उद्योग था। इस्पात का उत्पादन 1944 में अपने सर्वोच्च बिन्दु पर था। युद्ध समाप्त होने के बाद भी इनमें से कारखाने सही सलामत बच गये किन्तु समस्या कच्चे माल के अभाव की थी। अमरीकी आधिपत्य वाली सरकार ने जापान के लोहा व इस्पात उद्योग को पुनर्स्थापित करने में अधिक रुचि नहीं ली।

किन्तु अमरीकी आधिपत्य के काल में इस उद्योग में कई परिवर्तन हुए। सरकारी स्वामित्व वाली निप्पोन सेंटैल्सु कम्पनी व जैवत्सु के स्वामित्व वाली अन्य कम्पनियों को पुराने यवाता वर्क्स तथा एक नई कम्पनी फुजी आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के अन्तर्गत पुनर्गठित किया गया। ये दोनों कम्पनियाँ तथा एक अन्य तीसरी कम्पनी निप्पोन कोकन कम्पनी मिलकर आधुनिक समय की तीन सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण

इस्पात उत्पादक फर्मों बन चुकी है।

लोह पिंड उत्पादन 1949 में 15 मिलियन टन तथा इस्पात उत्पादन 3 मिलियन टन था। 20 वर्षों के अन्तराल में वह कई गुना हो गया। 1969 में उसका इस्पात उत्पादन 82 मिलियन टन था। इस्पात के उत्पादन में अब दुनिया भर में जापान अमरीका व रूस के बाद तीसरे स्थान पर है। जापान ने इस्पात के उत्पादन में 100 मिलियन टन का लक्ष्य पार कर लिया है तथा 1980 के बाद किसी भी समय वह अमरीका व हम से भी आगे निकलने की महत्वाकांक्षा रखता है। 1978-79 के निर्यातों में इस्पात का स्थान काफी प्रमुख रहा है।

3 कोयला खनन उद्योग

पुनर्संस्थापना के बाद पहली आधुनिक कोयला खान क्युशु (Kyushu) में शुरू की गई। 1883 के बाद होक्वेइडो कोयला क्षेत्र का विदोहन शुरू किया गया। लोहा व इस्पात उद्योग के विकास के साथ और अधिक कोयले की खोज का काम तेज किया गया।

आरम्भिक वर्ष 1881-1914

शुरू में कोयले का उत्पादन काफी कम था किन्तु 1894 के बाद औद्योगीकरण की गति बढ़ने के साथ ही उसके उत्पादन में भी तेजी से वृद्धि होने लगी। 1913 तक जापान में 100 खनन कम्पनियाँ थी जिनकी प्रदत्त पूँजी 39 मिलियन येन थी। उनमें 17 लाख खनिक कार्यरत थे।

1890 के बाद जापान थोड़ी-थोड़ी मात्रा में कोयले का निर्यात करने लग गया तथा 1913 तक वह 3 मिलियन टन प्रति वर्ष तक पहुँच चुका था। देश में ही उसका सबसे विशाल खरीदार नमक उद्योग था। 1890 के बाद जब विनिर्माण उद्योगों में भाप की शक्ति का प्रयोग आरम्भ हो गया तो वे कोयले के सबसे बड़े उपभोक्ता बन गये। इस अवधि में अधिकांश कोयला उत्पादन कुछ ही फर्मों द्वारा किया जाता था जो जैबत्सु से सम्बन्धित थी। 1913 में प्रति कार्यरत व्यक्ति उत्पादन 123 टन ही था तथा प्रति व्यक्ति शिफ्ट (Per Man-Shift) उत्पादन 0.53 टन आता था।

तीव्र विकास 1914-1938

प्रथम महायुद्ध के दौरान जापान के कोयला उत्पादन में काफी तीव्र गति से वृद्धि हुई। युद्ध के वर्षों में कोयला उत्पादन में कुल मिलाकर 10 मिलियन टन की वृद्धि हुई। किन्तु उसके बाद 1929 तक कोयला उद्योग की प्रगति काफी धीमी रही।

1936 में कोयले के उत्पादन में 1931 के मुकाबले महत्त्वपूर्ण वृद्धि हो जाने के उपरान्त कोकिंग कोयले का आयात जारी रहा। यह आयात उसके इस्पात उत्पादन के लिए आवश्यक था।

कोयला उत्पादन

(मिलियन टनो मे)

1875	0.6	1921	26.2
1885	1.2	1925	31.5
1895	5.0	1929	34.3
1905	13.0	1931	28.0
1913	21.3	1936	41.8
1919	31.3		

द्वितीय महायुद्ध के बाद

द्वितीय महायुद्ध के दौरान हुई बरबादी ने कोयला खान उद्योग पर कुछ समय के लिए विपरीत प्रभाव डाला। किन्तु उद्योग ने 1947 तक अपना युद्ध-पूर्व का उत्पादन स्तर पुनः प्राप्त कर लिया था। 1948 से 1953 की अवधि कोयला उद्योग के लिये पुनरुद्धार का काल था।

एक अनुमान के अनुसार जापान के सम्पूर्ण कोयला भण्डार विश्व कोयला भण्डारों का मात्र 0.4% है। 1969 में भी कोकिंग कोयले (Coking Coal) के लिए 52 मिलियन टन की माँग रही जिसमें से आधे से अधिक आयात किया गया। 1979 तक जापान की कोयला माँग 100 मिलियन टन के करीब पहुँच चुकी है। किन्तु अपने कोयला भण्डारों की सीमितता का ख्याल करते हुए तथा कोयले की घटिया किस्म को देखते हुए सरकार अब जल-विद्युत क्षमता के विकास पर अधिक बल दे रही है। खनिज तेल की कीमतें 1979 तक चौगुनी हो जाने के बाद वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत का विकास जापानी विनिर्माण उद्योगों के लिए जीवन-मरण का प्रश्न बन गया है।

4 इन्जीनियरिंग व रसायन उद्योग

मेजी युग में इन्जीनियरिंग उद्योग कोई भी सम्मानजनक आकार प्राप्त करने में असफल रहा था हालांकि 1979 में वह जापान के विनिर्माण उद्योगों के क्षेत्र में सर्वप्रमुख स्थान पर है। मेजी शासन काल के अन्तिम वर्षों तक भी अपने व्यापारिक जहाजों में से अधिकांश जापान ने विदेशी पोत-निर्माण स्थलों से ही प्राप्त किये थे। कुछ सरकारी पोत-निर्माण स्थलों को निजी व्यावसायियों को सौंप दिया गया। कुछ नये निजी पोत-निर्माण स्थल (Shipyards) जैसे ओमावा आयरन वर्क्स तथा ओनो शिप बिल्डिंग कम्पनी भी स्थापित हुए।

जहाज-निर्माण के काम में तेजी 1896 के जहाज-निर्माण प्रोत्साहन अधिनियम के पारित होने के बाद आयी। 1913 तक देश में 6 ऐसे पोत-निर्माण स्थल थे जहाँ 1,000 टन से अधिक क्षमता वाले जहाज बन सकते थे। जहाज-निर्माण उद्योग में इस समय 26,000 श्रमिक लगे हुए थे।

1. मेजी काल में रेलों, जहाजों, फैक्ट्रियों आदि के निर्माण के लिए आवश्यक

अधिकांश औजारों व उपकरणों का आयात करना पड़ता था। किन्तु इस काल में स्थापित की गई कुछ इन्जीनियरिंग कम्पनियाँ जैसे शिबोरा इन्जीनियरिंग वर्क्स, 1887, टोक्यो इलेक्ट्रिक कम्पनी तथा काबासाकी कम्पनी बाद के वर्षों में काफी महत्वपूर्ण बन गयी।

इन्जीनियरिंग उद्योग की प्रदत्त पूँजी 1893 के 26 मिलियन येन से बढ़कर 1913 में 61 मिलियन येन हो गई। विद्युत सप्लाय कम्पनियों में विनियोग की गई पूँजी 1893 के 2 मिलियन येन से बढ़कर 1913 तक 200 मिलियन येन तक पहुँच चुकी थी। 1913 में इन उद्योगों में 60,000 से अधिक लोग कार्यरत थे।

हल्के इन्जीनियरिंग उद्योगों की कुछ शाखाएँ जैसे साइकिल निर्माण, जो बाद के वर्षों में काफी प्रमुख बन गई, इसी अवधि में शुरू की गई थी। इन उद्योगों में साइकिल निर्माण उद्योग प्रमुख व्यवसाय बना। हालाँकि साइकिलों का उत्पादन 1914 में काफी कम था तथा उसके अधिकांश हिस्से-पुर्जे भी आयात किये जाते थे किन्तु इस उद्योग का उल्लेख इसलिए जरूरी है कि वह नये उद्योगों की शुरुआत का एक प्रारम्भिक उदाहरण है। ऐसे ही उद्योग बाद में जापान के विनिर्माण में प्रमुख बन गये।

तीव्र प्रगति . 1914-1938

भारी इन्जीनियरिंग की एक प्रमुख शाखा के रूप में जहाज-निर्माण उद्योग प्रथम महायुद्ध के बाद एक प्रमुख उद्योग बन गया। 1919 में कुल व्यापारिक जहाजों का टन भार जिन्हें जापानी पोत-निर्माण स्थलों में तैयार किया गया था, 6,50,000 टन था।

जहाज निर्माण

वर्ष	वाष्पचालित जहाज (हजार टन में)
1919	646
1922	71
1929	165
1932	54
1936	295

इन्जीनियरिंग की कुछ अन्य शाखाओं में प्रगति अधिक तीव्र थी। घड़ियों, वाहनों तथा औजारों का आयात निरन्तर गिरता गया जो इस बात का द्योतक था कि इनका देश में ही उत्पादन बढ़ रहा था। यह गिरावट रेलों के रोलिंग स्टॉक, बिजली के उपकरण, वस्त्र मशीनरी तथा छपाई की मशीनों में अधिक स्पष्ट थी। पैडल चालित साइकिलों का उत्पादन भी काफी तेजी से बढ़ा तथा 1920 तक जापान साइकिलों में आत्मनिर्भर हो गया।

1929 के पहले लगभग सारे टरबाइन (Turbine) आयात किये जाते थे। 1937 तक उनमें से अधिकांश जापान में बनने लग गये। 1936 तक विशाल आकार की इस्पात डलाई का काम भी किया जाने लगा। कई विदेशी विरोधजों ने भी माना कि जापान की इन्जीनियरिंग वस्तुओं की विस्म में काफी सुधार हुआ था।

रसायन उद्योग का आरम्भ 1920 के बाद ही हुआ। 1920 में रासायनिक खाद का कुल उत्पादन 5,89,000 टन था। 1929 तक यह बढ़कर 11,81,000 टन हो गया। 1929 के बाद रसायन उद्योग में भी स्पष्ट सुधार हुए। रासायनिक खाद के कारखानों का पैमाना काफी बड़ा दिया गया।

द्वितीय महायुद्ध व उसके बाद

युद्ध ने इन्जीनियरिंग उद्योग को तीव्रता प्रदान की। 1944 में इन्जीनियरिंग वस्तुओं का उत्पादन 1937 की तुलना में तीन गुना था। युद्ध के तुरन्त बाद सत्ताह्वित हुई अमरीकी आधिपत्य वाली सरकार को यह पसन्द नहीं था कि जापान एक महत्त्वपूर्ण इन्जीनियरिंग राष्ट्र बने। इससे पुनः एक बार सैनिक खतरा पैदा हो सकता था। द्वितीय महायुद्ध के बाद के वर्षों में कच्चे माल तथा पूँजी का अभाव भी इन्जीनियरिंग उद्योग के विकास में प्रमुख बाधाएँ बने हुए थे। आधिपत्य सरकार ने जैबत्तु का सम्प्राप्तीकरण कर दिया था जिससे स्थिति और भी जटिल बन गई थी।

मगर 1950 का कोरियाई युद्ध जापान के इन्जीनियरिंग उद्योग के लिए जैसे भगवान का दिया हुआ कोई वरदान था। इस घटना ने आधिपत्य सरकार का दृष्टिकोण भी बदल दिया। जहाज निर्माण के क्षेत्र में सबसे शानदार प्रगति हुई। इस क्षेत्र में जापान 1956 तक दुनिया के सभी देशों से आगे निकल गया तथा विश्व का पहले नम्बर का जहाज निर्माता बन गया। 1978-79 में बने 50% से भी अधिक तेल-वाहक जहाज (Tankers) जापानी पोत निर्माण स्थलों पर तैयार किये गये। वर्तमान में जापान में 1000 से भी अधिक पोत-निर्माण स्थल हैं। 1967 में जापान ने कुल मिलाकर 17 मिलियन टन भार के व्यापारिक जहाज बनाये थे। 1969 में यह टन भार बढ़कर 93 मिलियन टन हो गया जिसमें से 28 मिलियन टन का तो निर्यात किया गया था। वर्तमान में जापान विश्व में बनने वाले कुल जहाजों में से 50% अकेले बनाता है।

द्वितीय महायुद्ध में पहले जापान कारों का आयात करता था तथा इस उद्योग की विशेष प्रगति नहीं हुई थी। मगर 1960 के बाद से यह उद्योग अत्यधिक महत्त्वपूर्ण बन गया है। अधिकांश यूरोपीय देशों व यहाँ तक कि अमरीका के मोटरकार बाजारों में जापानी कारों का अम्बार लग गया है। 1969 में जापान अमरीका के बाद विश्व का दूसरे नम्बर का सबसे बड़ा कार निर्माता राष्ट्र बन गया। 1969 में उसने 4.7 मिलियन से भी अधिक कारों का निर्माण किया था। 1960 से 1965 के बीच जापानी कारों के निर्यात 15 गुना हो गये। 1969 में लगभग 1 मिलियन कारों का निर्यात किया गया। जापानियों का इरादा 1979-80 तक विश्व बाजार में जापानी कारों का डेर लगा देने का है। ये कारें अमरीका व यूरोप के बाजारों में तो वहाँ की स्थानीय कारों से भी अधिक लोकप्रिय हैं। जापान का रासायनिक खादों का निर्यात भी बहुत ऊँचाई तक पहुँच चुका है। 1969 में वह 315 मिलियन येन मूल्य तक पहुँच गया था। रासायनिक खाद का घरेलू उपभोग भी जापान में विश्व में सर्वाधिक है।

आर्थिक विकास में जैवत्सु की भूमिका (THE ROLE OF THE ZAIBATSU)

मेजी युग¹ में बड़े पैमाने वाले उद्योगों के विकास की चर्चा करते समय पीर-ववर्ची-भिन्ती-खर (Jack of all trades) जैसे समूह जैवत्सु, जिसने वित्तीय गुट बनाकर प्रबन्ध के क्षेत्र में एक नई प्रवृत्ति को जन्म दिया, को अलग से देखना आवश्यक है। पुनर्स्थापना के बाद के प्रारम्भिक वर्षों में अधिकांश नये प्रतिष्ठान विशेषज्ञ व्यावसायिकों द्वारा शुरू किये गये। इन लोगों ने जापानी अर्थव्यवस्था में पहले भी अपना साधारण-सा स्थान बना रखा था। किन्तु एक तरह से सभी लोग इस दृष्टि से नौसीखिये ही थे। उस समय कुछ ऐसा भाहूल था कि अगर किसी के पास थोड़ी पूंजी की शक्ति व सक्षम प्रबन्धकीय कर्मचारी होते तो वह उद्योग के किसी भी क्षेत्र में तुलनात्मक दृष्टि से काफी लाभकारी स्थिति प्राप्त कर सकता था। इन परिस्थितियों में जाग्रदृक् साहसकर्ता, जिन्होंने थोड़ी-बहुत पूंजी एकत्रित कर ली थी, ऐसे व्यवसायों पर अधिकार जमाने व उन्हें सफलतापूर्वक चलाने में सफल हुए जिनसे मूल रूप में उनका कभी कोई सम्बन्ध नहीं रहा था। उदाहरण के लिए प्रमुख जैवत्सु घराना मितामुई जो व्यापार के क्षेत्र में प्रारम्भ होकर बैंकिंग, कोयला खनन व धातु खनन के क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण बन गया, मितामुई घराना जहाजी सेवा के क्षेत्र में प्रारम्भ हुआ मगर उसने जहाज निर्माण, कोयला तथा धातु-निर्माण के क्षेत्रों में भी प्रवेश कर लिया। अन्य लोग, जो समृद्ध बने, वे ही थे जिन्होंने अन्तर्सम्बन्धित विशाल उपक्रमों में भारी विनियोग किया था। इनमें मूल कताई के क्षेत्र में सूत के धोक व्यापारियों द्वारा विनियोग या रेल-मार्गों के निर्माण में क्युशु कोयला खान मालिकों द्वारा किये गये विनियोगों को उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है। इस तरह निजी व्यक्तियों द्वारा संचित की गई पूंजी को न केवल उन लोगों द्वारा अपने मूल व्यक्तिगत उपक्रमों की विशाल पैमाने के प्रतिष्ठानों के रूप में विकसित करने पर विनियोग किया गया बल्कि उसे अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में भी विशाल पैमाने की औद्योगिक इकाइयाँ गठित करने के उपयोग में लिया गया।

‘जैवत्सु’² वा शाब्दिक अर्थ ‘धनी गुटों’ (Money cliques) से है जिसे विभिन्न क्षेत्रों में अपनी गतिविधियाँ फैलाये हुए कुछ महान् जापानी औद्योगिक घरानों को इंगित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। सब कामों के थोड़े-थोड़े जानकार

¹ K. Takahashi, *op cit*, 254-55

² G C Allen, *op cit*, 125

इस 'जैवत्मु' का ढाँचा वैसे तो मेजी युग के दूसरे दशक में ही बनना आरम्भ हो गया था किन्तु उस युग में और विशेष रूप से विकास की उस अवस्था में जब उन लोगों से बड़ी आगाएँ की जाती थी जो अपने विशाल पूँजी भण्डारों के साथ व्यवसाय के प्रति उत्साह का अच्छा समागम कर सकते थे, इन बहुउद्देशीय या बहुमुखी व्यावसायिक संगठनों (Zaibatsu) के माध्यम से उद्यमियों को बहुत लाभ कमाने के अवसर मिल रहे थे। समय के साथ-साथ इस नई प्रवृत्त की प्रवृत्ति ने विनाश जैवत्मु फर्मों को जन्म दिया। मित्सुबि, मित्सुबि, मुनीतोमी तथा यामुदा चार सबसे बड़े जैवत्मु थे किन्तु अन्य अनेक छोटी व मध्यम इकाइयाँ भी इन्हीं चिह्नों पर विवर्णित हुईं जो जापान के आर्थिक विकास की एक विशिष्टता बनी। (अमरीकी आधिपत्य वाली सरकार (1945-52) ने इन सभी कम्पनियों का समाप्तीकरण कर दिया था।) यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मेजी युग में जापान के आधुनिक बड़े पैमाने के औद्योगिक प्रतिष्ठानों की स्थापना का बहुत कुछ श्रेय जैवत्मु द्वारा आरम्भ किये गये उपक्रमों को ही रहा।

इन प्रमुख और गौण जैवत्मु इकाइयों ने जापान के आर्थिक उत्थान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा दोनों महायुद्धों के बीच ये इकाइयाँ जापान की अर्थव्यवस्था में जैसा स्थान प्राप्त किये हुए थी वैसा विश्व के अन्य देशों में कोई उदाहरण नहीं था। जैवत्मु का महत्व केवल आर्थिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं था क्योंकि वे देश की राजनीति पर भी प्रभाव डालने की स्थिति में थे। वैसे प्रमुख रूप से जैवत्मु का अधिकार-क्षेत्र बैंकिंग व वित्त तक सीमित रहा किन्तु प्रथम महायुद्ध के बाद उनकी रुचि औद्योगिक प्रतिष्ठानों की ओर मुड़ गई।

ये महान् औद्योगिक घराने (जैवत्मु) प्रथम महायुद्ध व उसके बाद के वर्षों के दौरान आकार व शक्ति की दृष्टि से बराबर बढ़ते चले गये। 1880 के दशक में सरकार द्वारा उद्योगों से हाथ खींच लिये जाने के बाद तो आधुनिक उद्योग की सभी प्रमुख शाखाओं पर इनका पूर्ण प्रभुत्व स्थापित हो गया अब उन्होंने छोटे पैमाने के व्यवसायों पर भी अप्रत्यक्ष रूप से अपना प्रभाव स्थापित करना प्रारम्भ कर दिया। अन्तर्निगम (Inter-corporate), व्यक्तिगत तथा राजनीतिक गठबन्धनों के एक पेचीदा पिरामिड जैसे ढाँचे (Pyramid-like structure) द्वारा इन प्रमुख जैवत्मु इकाइयों ने विशाल उपक्रम स्थापित कर लिये जिनका नियन्त्रण जहाजी सेवा, व्यवसाय, बैंकिंग, बीमा, वास्तविक परिसंपत्ति, खनन, विनिर्माण तथा औपनिवेशिक कम्पनियों तक फैल चुका था। आर्थिक सत्ता का उनका यह सकेन्द्रण (concentration) उनकी सेना तथा सरकारी अधिकारियों के साथ साँठ-गाँठ से सम्भव बना था। इसके अलावा जापान में अमरीका या ब्रिटेन की तरह आर्थिक सकेन्द्रण पर प्रतिबन्ध लगाने वाले न्यास-विरोधी कानून (Anti-Trust Laws) भी बने हुए नहीं थे।

दोनों महायुद्धों के बीच के वर्षों में अधिकांश बैंक भी जैवत्मु के स्वामित्व या नियन्त्रण में थे। एक मण्डित पूँजी बाजार के अभाव में व्यावसायिक फर्मों के लिए ये बैंक ही निजी पूँजी प्राप्त कर सकने के प्रमुख स्रोत थे। इतना ही नहीं, ये जैवत्मु बैंक निरीक्षण या अन्य सरकारी विनियमनों से भी मुक्त थे। इससे उन्हें अपने

कमजोर प्रतिद्वन्द्वियों को अपने में विलय करने में कोई कठिनाई नहीं हुई तथा 1927 के वैकिंग सकट के समय उन्होंने ऐसा ही किया।

एक समूह के रूप में जैबत्सु व उनके अन्य छोटे उपग्रहों (Satellites) का जापानी अर्थव्यवस्था के आधुनिक क्षेत्र पर प्रभुत्व था। वे कृषि क्षेत्र में चल रहे अत्यन्त छोटे पैमाने के उत्पादन की तुलना में गम्भीर वैपम्य की स्थिति निर्दिशित करते थे। छोटे पैमाने का यह उत्पादन विनिर्माण के क्षेत्र में भी व व्यवसाय के क्षेत्र में भी था इसलिए यह वैपम्य और भी स्पष्ट झलकता था। यह अब सभी द्वारा स्वीकार किया जाता है कि जैबत्सु की संस्था¹ (institution of Zaibatsu) ने पूँजी संचय की दर को तीव्र बनाने व तकनीक का आधुनिकीकरण करने में महान् योगदान दिया जो जापान के औद्योगिक विकास के वाहक बने। उसने जापान को बड़े पैमाने के उत्पादन की मितव्ययिताओं का लाभ दिलाया, उसने अर्थव्यवस्था के विशाल क्षेत्रों का निर्देशन जैबत्सु फर्मों द्वारा वाम पर लगाये गये सुयोग्य तकनीशियनों व प्रबन्धकों के हाथों में सौंपा, उसने एक ऐसा तरीका विकसित किया कि जिसमें मालिकों को होने वाला भारी लाभ पुनर्विनियोग के काम में लेना (ploughing back) सम्भव बन गया।

हालांकि जापानी उद्योग के वित्त व नियन्त्रण पर सकेन्द्रण जैबत्सु के ही हाथों में हो जाना तकनीकी दृष्टि से लाभकारी रहा, तथापि इसके सामाजिक पहलू उतने प्रशंसनीय नहीं थे। उसने आय व अवसरों की असमानताओं को बनाये रखने में सहायता की जो लगभग सामन्ती युग जैसी ही बनी रही। उसने आधुनिक उद्योग में अधिनायकतावादी नियन्त्रण (authoritarian control) की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जो राजनीतिक व आर्थिक प्रजातन्त्र की स्थापना की दृष्टि से हानिकारक थी। उसने स्वतन्त्रता व निजी पहलू के विकास को अवरुद्ध किया तथा जापान में एक सशक्त थम सघ आन्दोलन के विकास में भी बाधा डाली। जैबत्सु ने जापान में 1930 के बाद ससर्दीय लोकतन्त्र की पराजय में भी सहायता की।

पूँजी-निर्माण के प्रोत्साहनकर्त्ता के रूप में . 1913-1938

उपर्युक्त वर्णित जैबत्सु की कुछ बुराइयों के बावजूद यह कहा जा सकता है कि किसी भी अन्य संस्था की तुलना में उसने जापानी अर्थव्यवस्था में पूँजी-निर्माण की दिशा में अधिक महत्त्वपूर्ण सहायता की। आधुनिक बैंकों, व्यावसायिक फर्मों तथा उद्योगों का स्वामित्व महान् जैबत्सु घरानों (जिनमें शाही घराना सम्मिलित था) में केन्द्रीभूत हो गया था। सम्पत्ति से प्राप्त आय का यह सकेन्द्रण उच्च पदों पर आसीन प्रबन्धकों को ऊँचे वेतन व बोनस का भुगतान करने से और भी मजबूत बना। इनके नीचे लघु व मध्यम आकार के कोई 4 मिलियन उद्यमी थे जिन्होंने भी जैबत्सु पिरामिड के निर्माण में अपना योग दिया।

विचारार्थ अवधि में जैबत्सु की सम्पत्ति के कुल परिमाण का पता लगा पाना काफी कठिन काम है। मगर ओल्ड डी रसेल² ने जापानी सूत्रों के माध्यम से मित्सुई

¹ W W Lockwood, *op cit*, 61

² *Ibid*, 278-79.

घराने की 1937 की कुल सम्पदा 1,635 मिलियन येन होने का अनुमान लगाया है। बहुत सम्भव है कि चारो विशाल जैवतु घरानो, जिनमे मित्सुबिशी, सुमीतोमो तथा यासुदा के व्यावसायिक साम्राज्य भी सम्मिलित है, की कुल सम्पदा उपर्युक्त राशि की कम से कम दुगुनी हो।

किन्तु इन पारिवारिक सम्पदा की अद्वितीयता व रोचकता उनके आकारो की ही नहीं थी। जापानी विशालकाय सगठनो पर नियुक्त एव अगरीकी मिशन के द्वारा मित्सुई घराने का विश्लेषण इस सम्बन्ध मे एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। प्रथमतः, मित्सुई की 11 पारिवारिक शाखाओ की कुल सम्पत्ति का 90% से भी अधिक नवम्बर 1945 तक संयुक्त रूप मे रखा जाता था। उस पर पारिवारिक परिषद् (family council) का संयुक्त नियन्त्रण था जिसकी अध्यक्षता सबसे बड़े लड़के के परिवार की होती थी। द्वितीयतः, इस सम्पदा में से 90% से भी अधिक पूंजी मित्सुई होशा नामक सबसे विशाल होल्डिंग कम्पनी में इक्विटी शेयरों के रूप में तथा अन्य बैंको व फर्मों में लगी हुई थी। उधर होशा कम्पनी ने अपनी कुल पूंजी का 75 से 90% भाग इस तरह विनियोग किया हुआ था कि वह सम्पूर्ण जापानी अर्थव्यवस्था में फैली हुई अनेक सहायक कम्पनियों पर नियन्त्रण किये हुए थी। इन स्थितियों में, जैसे-जैसे जापान में पूंजीवाद का विकास हुआ, उसमें बचत करने का प्रमुख दायित्व उच्च आय वर्ग वाले लोगो ने निभाया।

प्रमुख उद्योगो का अधिग्रहण

मेजी युग में उन राजनीतिज्ञो, जो कि विशिष्ट सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी थे, तथा उन व्यावसायिक घरानो, जो कि वित्तीय सहायता उपलब्ध करा सकते थे के बीच विशेष सम्बन्ध स्थापित हुए। सरकार को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के बदले में समय समय पर जैवतु बहुत मस्ते मूल्यों पर सरकारी कारखाने खरीदते रहे तथा मूल्यवान अनुबन्ध भी पाते रहे। सरकारी ऋणों के निम्नांकन (Underwriting) द्वारा भी उन्होंने भारी लाभ कमाये। 1890 में मित्सुबिशी ने टोक्यो में शाही महल के निवृत्त वेकार पड़ी जमीन का एक टुकड़ा कौडियो के मोल खरीदा जो दस वर्ष बाद वहाँ का सबसे प्रसिद्ध व्यापार-केन्द्र बन गया। अन्य जैवतु घरानो को भी ऐसे ही अनेक लाभ मिले। उन्होंने जापान द्वारा लड़े गये युद्धो में भी वित्त उपलब्ध कराया तथा उपनिवेशों के विकास में भी सहायता की। उन्होंने सामरिक महत्त्व के उद्योग स्थापित करने में भी सरकार को मदद दी। जब वित्तीय संकट के समय कुछ पुराने व्यापारिक घराने दिवालिया हो जाते तो उनकी सम्पत्ति कोई भी जैवतु घराना अधिग्रहण कर लेता। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने अपने औद्योगिक प्रतिष्ठानो का विस्तार किया तथा युद्धोत्तरवालीन दशक में उनके व्यावसायिक व वित्तीय हितों में भारी वढोत्तरी हुई।

1929 में जैवतु अपनी शक्ति व प्रभाव के चरमोत्कर्ष पर थे। अधिकांश प्रतिद्वन्द्वी चित हो चुके थे। जापानी ससद (Diet) की शक्ति वढ रही थी। अपने राजनीतिक सम्बन्धो द्वारा जैवतु नीति-निर्धारण को प्रभावित कर रहे थे। मेजी युग

मे तो ये जैवत्सु फर्म सरकार का एजेंट मान थी किन्तु 1929 मे तो वे सरकार पर अपनी इच्छाएँ थोप सकती थी। उनकी स्थिति विरोधाधिकारयुक्त हो गई क्योंकि उद्योग व व्यापार की प्रत्येक महत्वपूर्ण शाखा पर उनका नियन्त्रण था। 1920 के बाद तो वित्तीय सहायता व तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने के बहाने जैवत्सु ने लघु उत्पादन-क्षेत्र मे भी प्रवेश कर लिया था। वैसे तो सभी जैवत्सु घरानो मे आपसी प्रतिद्वन्द्विता थी किन्तु जब सैनिक गुट, जो उनके विकास के विरोधी थे, से उनका आमना-सामना होता तो वे एक हो जाते।

द्वितीय महायुद्ध के बाद जैवत्सु

इस बात मे कोई दो मत नहीं हो सकते कि दोनो महायुद्धो के बीच की अवधि मे व्यापार व उद्योग की तीव्र प्रगति के पीछे प्रेरणा का स्रोत जैवत्सु सस्था ही रही। प्रो० जी० सी० एलन ने बड़ी ही सटीक भाषा मे लिखा है कि 'जैवत्सु आर्थिक उत्थान के ज्वार पर ऊपर चढ़े जिसे उन्होंने स्वयं ही उठाया था।' किन्तु जैवत्सु का अत्यधिक प्रभुत्व भी जापान के लिये महंगा पड़ा क्योंकि इन विशाल फर्मों के कारण ही जापान दूसरे महायुद्ध मे हारने के लिए बाध्य हुआ। वे अपने व्यावसायिक हितो को बढ़ावा देने के लिए भ्रष्ट से भ्रष्ट तरीके का उपयोग करने से भी नहीं हिचकते थे। कुछ लोग तो यह भी आरोप लगाते है कि जैवत्सु के लिए व्यावसायिक हित राष्ट्रीय हितो से भी ऊपर थे। 1930 के बाद उन्होंने जापान की साम्राज्यवादी नीति का केवल इसीलिए समर्थन किया कि उससे उनके व्यावसायिक हितो को बढ़ावा मिलता था। इस तरह यदि दो महायुद्धो के बीच के काल मे हुए जापानी अर्थव्यवस्था मे उद्योगो का आधुनिकीकरण करने का कार्य जैवत्सु ने पूरा किया तो द्वितीय महायुद्ध मे आर्थिक महत्वाकांक्षाओ की पूर्ति हेतु जापान को धकेल-कर उन्होंने उन उद्योगो को बरबाद भी अपने ही हाथो से कर दिया।

सैनिक विजय के आकर्षण के अलावा द्वितीय महायुद्ध मे भाग लेने के पीछे जापान का आर्थिक कारण अपने लिए एकाधिकार बाजार प्राप्त करना रहा। जैवत्सु ने इस अभिलाषा को और भी तीव्र बनाया। यही एकमात्र कारण रहा कि द्वितीय महायुद्ध के बाद जापान मे स्थापित अन्तरिम अमरीकी आधिपत्य वाली सरकार ने वहाँ सबसे पहले जैवत्सु की सस्था को उखाड़ फेंकने का ही काम किया। इस नीति का उद्देश्य आर्थिक सत्ता के मुट्ठी-भर लोगों के हाथ मे सकेन्द्रण को रोकना व अधिक न्यायपूर्ण एवं लोकतांत्रिक सामाजिक व्यवस्था कायम करना था।

1945 मे प्रशासन सम्भालने के तुरन्त बाद अन्तरिम सरकार ने एक आदेश (decree) जारी करके महान् जैवत्सु फर्मों का द्रवीकरण (dissolved) कर दिया। इन फर्मों को छोटी इकाइयों मे विभाजित एवं उपविभाजित कर दिया। अधिकांश प्रभावशाली व्यक्तियों को, जो पहले जैवत्सु फर्मों पर नियन्त्रण किये हुए थे, अपने स्थानो से हटा दिया गया। 1947 मे न्यास विरोधी कानून (Anti-trust laws) पारित किये गये ताकि ये फर्म फिर कभी गिर उठाने की स्थिति मे न रहे।

1954 तक जैवत्सु की सम्पत्ति व अधिकार पूरी तरह नष्ट किये जा चुके

थे किन्तु यह सब पूंजीपतियों के पुराने ढाँचे को पूरी तरह नष्ट नहीं कर पाया। उल्टे अन्तरिम सरकार निजी एकाधिकार समाप्त कर सरकारी एकाधिकार को स्थापित करने में ही सफल हुई। इसके अतिरिक्त उन्मूलन की यह नीति भेदभावपूर्ण थी। इससे मित्सुबिशी की व्यावसायिक एकाधिकार की स्थिति समाप्त करने में तो सफलता मिली किन्तु मित्सुबिशी का बैंकिंग व वित्तीय एकाधिकार तथा यामुदा (Yasuda) के एकाधिकार फिर भी बने रहे। इस परिस्थिति में जापानी अर्थ-व्यवस्था को उदार बनाने व विकेन्द्रित करने का अन्तरिम सरकार का उद्देश्य आशंकित रूप से ही पूरा हो पाया।

इतना ही नहीं, जैवत्सु के समाप्त कर दिये जाने का द्वितीय महायुद्ध में नष्ट हो चुकी जापानी अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा। युद्ध में पहले नए उद्योग स्थापित करने में पहल करने का काम जैवत्सु का ही था। युद्ध के बाद जापान को पूरी तरह पगु बताने के उद्देश्य से अमरीकी आधिपत्य वाली सैनिक सरकार ने जैवत्सु को अपने अधिकांश परिसंपत्त भी बेचने के लिए विवश किया।

किन्तु जैवत्सु का यह भाग्य नहीं था कि वह इस तरह एकाएक ही मृत्यु का शिकार बन जाता। यदि दूसरे महायुद्ध ने उसे बरबाद किया था तो 1950 के कोरियाई युद्ध ने उसे पुनर्जीवित (resurrected) कर दिया। अमरीकी सरकार ने अरबो डॉलर की लागत से जापान में शस्त्र-निर्माण के कारखाने खोले ताकि कोरियाई युद्ध क्षेत्र तक हथियार शीघ्रातिशीघ्र पहुँचाए जा सकें, जहाँ अमरीका की प्रतिष्ठा दाव पर थी। न्यास-विरोधी कानूनों को संशोधित किया गया ताकि कारखानों की स्थापना के लिए महान् जैवत्सु फर्म अधिक पूंजी व साख जुटा सके। परिणाम यह रहा कि 1954 में अन्तरिम सरकार द्वारा जापान से जाने के लिए पहले ही जैवत्सु का पुनः एक आर्थिक शक्ति के रूप में उदय हो चुका था। मित्सुबिशी, मित्सुबिशी तथा सुमीतोमो का अनेक उद्योगों व वित्तीय संस्थाओं पर पुनः नियन्त्रण स्थापित हो गया। 1954 की मुद्रा-संक्रांति की स्थिति, जिसने कई कमजोर फर्मों का उन्मूलन कर दिया, ने भी जैवत्सु के पुनः विकास में सहायता की जो कि इस तरह के संकटों से निपटने में पर्याप्त शक्तिशाली थे। किन्तु जैवत्सु का पुनरागमन कभी भी सम्पूर्ण रूप में नहीं हो पाया।

1960 के बाद जैवत्सु के स्वरूप में आधारभूत परिवर्तन हुए। वे अब पहले की तरह राज्य की नीतियों को प्रभावित कर पाने की स्थिति में नहीं रह गये थे। उनका वित्तीय व प्रशासनिक नियन्त्रण भी ढीला पड़ चुका था। इन नई प्रवृत्तियों पर टीका करते हुए प्रो० जी० सी० एलन ने लिखा है कि 'विभिन्न जैवत्सु में ही केन्द्रापसारक (centrifugal) व केन्द्राभिमुखी (centripetal) शक्तियाँ सक्रिय हो चुकी हैं उनके अंगों (limbs) में स्वतन्त्र जीवन पैदा हो चुका है।' विभिन्न गुटों के बीच प्रतिद्वन्द्विता बढ रही है तथा प्रत्येक गुट नये उद्योग में अपना अधिक से अधिक भाग प्राप्त करने के लिए सचेष्ट है। जैवत्सु अब ढीले और बिना आकृति वाले (loose and shapeless) सगठन बन चुके हैं।

लघु उद्योगों की स्थिति (THE SMALL-SCALE INDUSTRIES)

आज दिन तक लघु उद्योगों की आर्थिक उपादेय इकाइयों के रूप में विशिष्टता व महत्त्व का बर्ना रहना जापानी अर्थव्यवस्था की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विशेषता कही जा सकती है। पचास से भी कम श्रमिकों वाली, यहाँ तक कि पाँच से भी कम श्रमिकों वाली इकाइयों का अस्तित्व विशाल पूँजी-प्रधान प्रतिष्ठानों की प्रतिस्पर्धा होते हुए भी आज तक बने रहना केवल जापान ही की विशिष्टता रही है।

कृषि क्षेत्र में एक ही परिवार का छोटा-सा खेत आज भी सगठन का सबसे प्रमुख स्वरूप बना हुआ है। महायुद्ध से पहले चावल व अन्य फसलों का उत्पादन हाथ के श्रम से ही देश के 5 मिलियन किसान परिवारों द्वारा किया जाता था। वे जिन खेतों को जोतते थे उनका औसत आकार 2.5 एकड़ के लगभग था। अधिक सेवा-व्यवसाय भी, बैंकिंग व यातायात को छोड़कर, स्वतन्त्र व्यक्तिगत इकाइयों द्वारा ही चलाए जाते थे। अधिक से अधिक पारिवारिक सदस्यों या कुछ भाड़े के मजदूरों की सहायता ली जाती थी। यही बात धोके व खुदरा व्यापार, भवन-निर्माण व स्थानीय यातायात, मनोरंजन के साधनों या पेशों के बारे में सही थी।

किन्तु इन लघु उत्पादन इकाइयों ने विनिर्माण, खनन तथा दूरी तक चलने वाले यातायात के साधनों के क्षेत्र में अपना स्थान खो दिया। यह स्पष्ट रूप से इस लिए हुआ कि उत्पादन का बड़ा पैमाना पूँजी संचय तथा तकनीकी अनुभव में वृद्धि के साथ अधिक व्यावहारिक बन चुका था। बाजारों के प्रसार व उत्पादों के समानो-करण के साथ बड़े पैमाने पर उत्पादन और अधिक कार्यकुशलता-पूर्ण बन गया। अनेक निर्यात-प्रधान उपभोक्ता उद्योगों में भी बड़े पैमाने का उत्पादन अधिक प्रमुख बन गया। घरेलू बाजार में जहाँ डिजाइनें व विविधताएँ अधिक महत्त्वपूर्ण थीं लघु उत्पादकों का काम अच्छी तरह चलता रहा।

यहाँ तक कि फँकट्री प्रणाली वाले उद्योगों में भी छोटे कारखाने एक तकनीकी इकाई के रूप में अपनी प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति का प्रदर्शन करने में सफल रहे। 100 से कम श्रमिकों वाले कारखाने 1934 में निजी फँकट्रियों द्वारा किये गये कुल उत्पादन में एक तिहाई भाग के हिस्सेदार थे। वे कुल श्रमिकों में से 50% को रोजगार प्रदान कर रहे थे तथा 1919 के बाद से अपना उत्पादन अगदान पूर्ववत् रखे हुए थे।

युद्ध के लिए तैयारियों के काल में 1934 के बाद औद्योगिक स्वरूप में कुछ

भारी परिवर्तन किये गये जिनका लाभ बड़े पमाने के उद्योगों को अधिक मिला। किन्तु यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि 1930 के बाद के वर्षों में भी लघु एवं मध्यम आकार के उद्योगों ने विशाल सस्ते-निर्माण कारखानों के सहायक के रूप में अपनी सापेक्ष स्थिति पर आच नहीं आने दी।

विनिर्माण के क्षेत्र में छोटे वर्कशॉप अपने सम्बन्ध में दिये गये आँकड़ों से भी अधिक महत्वपूर्ण रहे। इन वर्कशॉपों में 1934 में 1 मिलियन छोटे-छोटे परिवार कार्यरत थे। इनमें से आधे से अधिक तो एक आदमी वाले वर्कशॉप थे। पाँच व्यक्तियों से भी कम रोजगार वाले इन वर्कशॉपों का 1930 के बाद के वर्षों के औद्योगिक उत्पादन में लगभग 25% भाग बना रहा। 1930 में इन छोटे उद्योगों का विद्युत् उत्पादन 832 मिलियन घन मूल्य का आँका गया था।

रोजगार के बारे में भी आँकड़े महत्वपूर्ण हैं। 1930 के जनगणना आँकड़े बतलाते हैं कि पाँच या उनसे कम व्यक्तियों वाले उपक्रम 2.5 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार दे रहे थे। औद्योगिक कार्यस्थल जिन्हे फैक्ट्रियों की श्रेणी में भी नहीं रखा जा सकता (जिनमें पाँच या उससे अधिक श्रमिक कार्यरत थे) जापान के कुल विनिर्माण रोजगार का 50% प्रदान कर रहे थे। इसकी तुलना में ऐसी फैक्ट्रियाँ जिनमें 100 या उससे अधिक श्रमिक कार्यरत थे केवल 25% रोजगार प्रदान कर रही थी व औद्योगिक उत्पादन में उनका भाग 50% था।

ये लघु या कुटीर उद्योग, मुख्यतः खाद्य पदार्थों, चीनी मिट्टी के बर्तनों, साइकिलों, खर के जूतों, खिलौनों, बिजली के बल्बों तथा मशीनों के पुर्जों का उत्पादन करते थे। निम्नांकित प्रतिशत विभिन्न उद्योगों में 1932 में किये जा रहे पारिवारिक उत्पादन (household production) के महत्व को स्पष्ट करते हैं—

उद्योग	रोजगार, उन कारखानों में जहाँ		उत्पादन, उन कारखानों में जहाँ	
	पाँच से कम श्रमिक	पाँच या उससे अधिक श्रमिक	पाँच से कम श्रमिक	पाँच या उससे अधिक श्रमिक
सूती वस्त्र	48	52	31	69
रेशम	66	34	57	43
चीनी मिट्टी	57	43	62	38
लकड़ी के खिलौने	85	15	56	44

यदि 100 श्रमिकों से कम वाली समस्त इकाइयों को लिया जाये तो ज्ञात होता है कि 1934 में वे समग्र विनिर्माण उत्पादन के 45 से 50% भाग का उत्पादन कर रही थी। उनमें 65% लोग लगे हुए थे। इसकी तुलना अमरीकी स्थिति से की जा सकती है जहाँ 1935 में 100 श्रमिकों से कम रोजगार वाले कारखानों में केवल 29% मजदूर कार्यरत थे।

निर्यात के क्षेत्र में भी ये छोटी इकाइयाँ काफी सक्रिय थीं। कृत्रिम धागे, कच्चे रेशम, सूती धागे, व चीनी को छोड़कर शेष सभी विनिर्मित वस्तुएँ, जिनका

कि निर्यात किया जा रहा था, लघु एवं मध्यम क्षेत्र द्वारा उत्पादित की जा रही थी। 1931 से 1937 के बीच छोटे बुनकरों ने अपने बाजारों का अपने विशाल प्रतिस्पर्द्धियों की तुलना में अधिक तेजी से प्रसार किया था।

छोटे उद्यमी

जापानी लघु उद्योगों की चर्चा करते समय उत्पादन की तकनीकी इकाई अर्थात् फैक्ट्री तथा उपक्रम या व्यावसायिक इकाई में अन्तर किया जाना आवश्यक है। इन व्यावसायिक इकाइयों में निर्णय लेने का दायित्व होता है। 1930 में लाभकारी कार्यों में लगे हुए 30 मिलियन जापानियों में से 6 मिलियन लोग अपने आपको 'नियोक्ता' (employers) बताते थे। इनमें से अधिकांश लोग या तो कृषि में थे या फिर स्वतन्त्र रूप से अपना कोई छोटा सा वर्कशॉप चलाते थे।

जापानी व भारतीय औद्योगीकरण में अन्तर भी काफी प्रेरणा प्रदान करने वाला है। फैक्ट्री उपक्रम जापान में भारत की तुलना में अधिक तेजी से विकसित हुए किन्तु वहाँ उन्होंने लघु एवं कुटीर उद्योगों को नष्ट नहीं किया। जापानियों को लघु उद्योगों की उत्पादन तकनीक को आधुनिक बनाने में सफलता मिली।

जापान में छोटी या मध्यम औद्योगिक इकाई उसे माना जाता है जिसमें 300 से कम श्रमिक लगे हों। 1955 में ऐसी इकाइयाँ 73% रोजगार के लिए उत्तरदायी थीं। 1960 में भी यह 70% था।

आकार के आधार पर रोजगार व उत्पादन का प्रतिशत

वैमाना	रोजगार (1960)	उत्पादन (1960)
छोट उपक्रम (3 से कम श्रमिक)	6.9	1.9
लघु उपक्रम (29 से कम श्रमिक)	27.1	14.7
मध्यम उपक्रम (299 से कम श्रमिक)	35.6	32.6
बड़े पैमाने के उपक्रम (999 से कम श्रमिक)	13.6	20.5
विशालकाय उपक्रम (1000 से कम श्रमिक)	16.8	30.3

लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास की अवस्थाएँ

(1) मेजी युग—मेजी पुनर्संस्थापना से पहले जापान में 'टोन्ग्या प्रणाली' (Tonya system) काफी लोकप्रिय थी। 'टोन्ग्या' शब्द का प्रयोग एक छोटे उत्पादक या 'थोक विक्रेता' के लिए होता था। वह एक प्रकार का मध्यस्थ था जो उत्पादक एवं बाजार के बीच की कड़ी बना हुआ था। वह अपनी पूँजी का उपयोग एक स्थानीय कृषक उद्योग को गठित करने में करता था। 1868 के बाद इस व्यवस्था में काफी अन्तर आ गया किन्तु 1880 के बाद विशाल पैमाने पर उत्पादन का आरम्भ भी लघु स्तर पर किये जाने वाले उत्पादन की इस टोन्ग्या प्रणाली को नष्ट नहीं कर पाया।

मेजी शासन का सम्पूर्ण काल जापान की औद्योगिक क्रांति का सबसे बड़ा भाग रहा है। इसी अवधि में पश्चिमी उत्पादन पद्धतियाँ अपनायी गयी तथा बड़े

पैमाने का उत्पादन शुरू किया गया। किन्तु मेजी अर्थव्यवस्था की एक उल्लेखनीय विशेषता यह रही कि उसके आधुनिकीकरण पर दिये गये बल से जापान के छोटे पैमाने के उद्योगों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा। वे जीवित रहे क्योंकि किसानों की पूरक आय के वे ही एकमात्र स्रोत थे। उन्होंने उस युग में जापान के विनिर्माण क्षेत्र की सहायता की जब उसमें पूँजी का अभाव था।

आन्तरिक बाजार की आवश्यकताओं को पूरा कर सकने की दृष्टि से पुनर्संस्थापना के पहले वाली टोन्या प्रणाली लघु उपक्रमों में परिवर्तित हो गई। एक अन्य तत्त्व जिसने मेजी काल में लघु उद्योगों के विकास को अवरोध नहीं होने दिया, यह था कि आयातित पश्चिमी ढंग के विशाल पैमाने के उद्योगों तथा घरेलू किस्म के छोटे पैमाने के कुटीर उद्योगों में कहीं कोई प्रतिस्पर्धा पैदा नहीं हुई। ऐसा इसलिए हुआ कि बड़े उद्योग तो क्षत्रादि की आवश्यकता पूरी करने में लग गये जबकि छोटे उद्योग आन्तरिक बाजार की आवश्यकताओं को पूरा करने का काम करते रहे। इस तरह दोनों एक-दूसरे के प्रतिस्पर्द्धी बनने के स्थान पर पूरक बन गये। पश्चिम के प्रभाव से भी इस अवधि के कुटीर व लघु उद्योगों को लाभ हुआ।

(2) तैशो काल (Taisho Era)—छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास तैशो काल में असाधारण तेजी से हुआ इसे औद्योगिक विवेकीकरण का काल भी कहा जाता है। प्रथम विश्व-युद्ध के बाद घरेलू व विदेशी बाजार काफी व्यापक बन चुके थे। जनसंख्या भी काफी बढ़ चुकी थी। इन तत्त्वों ने लघु एवं कुटीर उद्योगों के लिए यान्त्रिक उत्पादन पद्धतियाँ अंगीकार करना अनिवार्य सा बना दिया।

प्रथम विश्व-युद्ध के बाद दुनिया-भर में जापानी वस्तुओं की बढ़ चुकी माँग को केवल बड़े पैमाने के उद्योगों द्वारा पूरा करना सम्भव नहीं था। इसके अलावा बड़े पैमाने के उद्योग अपनी स्थापित क्षमता के विस्तार में अधिक रुचि भी नहीं ले रहे थे क्योंकि माँग की इस वृद्धि को वे अस्थायी मानते थे। इन्होंने एक उप-अनुबन्ध (Sub-contracting) की प्रणाली को जन्म दिया। समय के साथ यह प्रणाली सामान्य हो गई। अब तक भी बड़े व छोटे पैमाने के उद्योगों के बीच समन्वयन में यह प्रणाली महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उप-अनुबन्ध के द्वारा दोनों क्षेत्र साथ मिलकर काम कर सकते हैं। छोटे निर्माता अपने उत्पादन को एक या कुछ बड़ी फर्मों को बेचते हैं। इस प्रणाली का दुर्ूपयोग भी हुआ है तथा सरकार ने उसे रोकने के उपाय भी किये हैं। उप-अनुबन्धकर्त्ताओं को किये जाने वाले भुगतानों के विलम्ब को रोकने के लिए एक कानून बनाया गया।

सरकार ने भी इस अवधि में छोटी फर्मों को औद्योगिक सहकारियों के रूप में संगठित हो जाने के लिए प्रोत्साहित किया। इसे 'नव टोन्या प्रणाली' (New Tonya System) की सजा दी गयी। इसके पीछे इरादा यह था कि पूँजी व कच्चा माल सही समय व निरन्तर उपलब्ध कराकर इन लघु इकाइयों की निर्यात क्षमता को विकसित किया जाये। 1925 में पारित एक कानून द्वारा उन सब लोगों को निकाल बाहर किया गया जो वास्तविक उत्पादन नहीं कर रहे थे। इस तरह पुरानी टोन्या प्रणाली समाप्त हो गई जिसमें टोन्या केवल मध्यस्थ बनकर वास्तविक

उत्पादन का शोषण करता था ।

नई टोन्पा प्रणाली के अन्तर्गत शक्ति-चालित मशीनों के प्रयोग पर बल दिया गया । छोटे प्लांट के कार्य-पैमाने को भी बढ़ाया गया । पुरानी टोन्पा प्रणाली में तो जो व्यक्ति टोन्पा के लिए काम करता था वह उसके नौकर की तरह था किन्तु नयी 'टोन्पा प्रणाली' के अन्तर्गत वह पूरी तरह लघु उद्यमकर्त्ता बन गया ।

1930 के दशक में यह पाया गया कि लघु स्तर पर उत्पादन करने वाले उद्योगों के सामुग्र्य कुछ प्रमुख समस्याएँ थी । उनके उपकरण पुराने व अनुपयुक्त थे । उनके पास पर्याप्त पूँजी भी नहीं थी । तकनीकी सुधार काफी धीमा था तथा विभिन्न फर्मों के बीच अन्यायपूर्ण प्रतिस्पर्धा थी । इसके निदान हेतु 1931 में 'इण्डस्ट्रीयल एसोसियेशन लॉ' पारित किया गया जिसके अन्तर्गत छोटे उपक्रमों को सघ बनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया । इन सघों का उद्देश्य कुछ नियन्त्रण स्थापित करना था ।

(3) द्वितीय महायुद्ध काल—1937 के बाद से तो सरकारी नीति सैनिक साज-सामान के उत्पादन को अधिकतम करने की बन गई थी । इसके परिणामस्वरूप घरेलू उपभोग के लिए उपलब्ध साधनों में कमी आयी । कच्चे मालों पर बड़े आर्थिक नियन्त्रण लगा दिये गये जिनसे लघु उद्योगों पर विपरीत प्रभाव पड़ा ।

द्वितीय महायुद्ध के दौरान भी छोटे पैमाने के उद्योगों की स्थिति और खराब होती चली गई क्योंकि हर जगह नियन्त्रण लगा दिये गये थे । केवल उन्हीं छोटी इकाइयों को कार्य करते रहने की अनुमति दी गई जो युद्ध सामग्री में कुछ योग दे सकती थी । 1942 तक अधिकांश छोटी फर्में लुप्त हो गईं । मिन-राष्ट्रों की बमबारी ने अधिवास ढाँचा (Infrastructure) नष्ट कर दिया था तथा युद्ध के अन्त में लघु उद्योगों की स्थिति शोचनीय हो चुकी थी ।

(4) युद्धोत्तर काल—युद्ध समाप्त होने के बाद लघु पैमाने के उद्योगों का पुनरुद्धार भी उतनी ही तीव्र गति से हुआ । ऐसा इसलिए था क्योंकि युद्ध के समय लगाये गये अधिवास नियन्त्रण (War controls) उठा लिये गये थे । चूँकि ये छोटी फर्में भाड़े के मजदूरों पर अधिक आश्रित नहीं थी इसलिए इन्हें अपना काम शुरू करने में देर भी नहीं लगी । युद्ध के बाद उपभोक्ता वस्तुओं के तीव्र अभाव ने छोटे पैमाने के उद्योगों को आगे आने के लिए स्वर्ण अवसर प्रदान किया । युद्ध समाप्त होने के तुरन्त बाद अमरीकी आधिपत्य वाली सरकार द्वारा जैवत्सु को समाप्त कर दिये जाने से भी छोटी फर्मों को आगे आने में अत्यधिक सहायता मिली ।

किन्तु 1947 में सरकार द्वारा स्वीकृत 'प्राथमिकता फार्मूला' छोटी इकाइयों के विपक्ष में था क्योंकि उसमें उन आधारभूत उद्योगों को अधिमान (preference) प्रदान करने की बात कही गई थी जिनसे देश के पुनर्निर्माण के कार्य में सहायता मिल सकती थी । कच्चा माल भी इन्हें पहले आवंटित किया गया । छोटी इकाइयों की आशाओं पर तब और भी पानी फिर गया जब युद्ध के समय सैनिक सामग्री तैयार करने वाली बड़ी फर्में शान्ति स्थापना के बाद उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में लग गयीं । 1949 में अपनायी गयी विस्फीतिकारी नीतियों ने भी लघु उद्योगों के विकास को आघात पहुँचाया ।

कोरियाई युद्ध ने इस निराशाजनक स्थिति में पुनः एक आशा की किरण जगा दी। बड़ी फर्मों को बड़े आर्डर मिले जिन्हें उन्होंने बाद में छोटी इकाइयों को ठेके पर दे दिया। इस तरह जापानी अर्थव्यवस्था की दोहरी स्थिति समाप्त नहीं हुई। 1950 के बाद मध्यम व छोटे आकार की फर्मों ने, जो बड़ी फर्मों के लिए उप-अनुबन्धकर्ता (sub-contractors) का काम करती थी, अपने उपकरणों को आधुनिक बना दिया ताकि उनकी उत्पादन लागत कुछ घट पाती। 1960 के बाद विकसित हुई कैरेत्सु (Keiretsu system) प्रणाली ने भी इस क्षेत्र में भारी परिवर्तन किये। यह प्रणाली अनेक आश्रित उप-अनुबन्धकर्ताओं को निर्देशन देने, गठित करने व आगे लाने का काम करती है।

1960 के बाद जापानी अर्थव्यवस्था में छोटे पैमाने के उद्योगों का स्थान पुनः महत्वपूर्ण हो गया है। 1963 के लघु व्यवसाय आधारभूत कानून के अनुसार लघु उपक्रम वह है जिसमें 50 मिलियन येन से कम का पूंजी विनियोग हो तथा जिसमें नियमित रूप से 300 से अधिक लोगो को रोजगार न दिया जाता हो। खनन के क्षेत्र में 50 मिलियन येन पूंजी व 1,000 श्रमिकों तक की इकाइयों को भी छोटी इकाई माना गया है। व्यवसाय एवं सेवाओं के क्षेत्र में 10 मिलियन येन तक की पूंजी व 50 श्रमिकों तक की इकाइयों को लघु इकाई करार दिया गया है।

उपर्युक्त वर्णित श्रेणियों के अनुसार 1960 में देश की कुल 3 22 मिलियन औद्योगिक इकाइयों में से 3 20 मिलियन इकाइयाँ छोटे पैमाने की इकाइयाँ थी। यह देश की कुल औद्योगिक इकाइयों का 99.4% था। 1962 में देश की श्रम-शक्ति का 78% छोटे व्यवसायों में लगा हुआ था। वे देश के कुल उत्पादन का 48% पैदा कर रहे थे। 1979 में भी इन लघु इकाइयों का उत्पादन व राजगार में प्रतिशत भाग लगभग अपरिवर्तित ही रहा है। उनके महत्त्व में किसी प्रकार की कमी नहीं आई है।

सरकार ने वाणिज्य एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मन्त्रालय के अन्तर्गत छोटे पैमाने के उद्योगों की देखभाल के लिए एक एजेंसी स्थापित की है। इन इकाइयों के आधुनिकीकरण के लिए व्याज-मुक्त ऋण भी दिये गये हैं। पिछले 35 वर्षों में सरकार ने छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास करने के उद्देश्य से भारी सहायता में बहुत कम व्याज पर भी ऋण दिये हैं। बड़े पैमाने पर उत्पादन करने वाली तथा छोटे पैमाने पर उत्पादन करने वाली इकाइयों के बीच सम्बन्धों का विनियमन करने के उद्देश्य से 1963 में एक महत्वपूर्ण विधेयक भी पारित किया गया था। छोटे पैमाने की इकाइयों को प्लाट, भवन तथा यहाँ तक कि वच्चे माल के लिए भी ऋण सुविधाएँ उपलब्ध हैं।

छोटे पैमाने के उद्योगों ने जापानी अर्थव्यवस्था के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्रम के आधिक्य से उसे शक्ति मिली है। उसने लोगों की विविध रुचियों को पूरा किया है। वह अपनी कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर रहा है। एक प्रमुख अर्थशास्त्री ने उनके बारे में एकदम ठीक ही लिखा है कि 'यदि आर्थिक प्रसार की गत्यात्मकता का अधिकांश सम्बन्ध मेजी सरकारी अधिकारियों व जैवतन्त्र प्रदन्धकों से रहा तो उसे वास्तविक सामग्री उपलब्ध कराने में छोटे किसान, व्यापारी व उद्योगपतियों ने भी अपनी क्षमता को देखते हुए कम योगदान नहीं किया।'।

आर्थिक विकास में सरकार का योगदान

(STATE AS PROMOTER OF ECONOMIC DEVELOPMENT)

औद्योगीकरण की दिशा में एशिया में किये गए प्रयासों का इतिहास एक बहुत कठोर पाठ पढ़ाता है। कोई भी देश विदेशों से औद्योगिक क्रांति को आयात नहीं कर सकता, उसे किसी मशीन की तरह अपने यहाँ उतार कर चालू नहीं कर सकता “विदेशी उदाहरण उत्तेजक हो सकते हैं” किन्तु परिवर्तन की सच्ची शक्ति देश के भीतर से ही आ सकती है। भूतपूर्व अमरीकी सचिव एचसन के शब्दों में बाहरी विश्व तो केवल ‘खो रहे अवयव या कड़ी’ (missing link) को ही उपलब्ध करा सकता है।¹

आर्थिक विकास की शुरुआत करने वाले लोगों के लिए सबसे नाजुक समस्या वही होती है कि वे पहल (initiative) तथा उत्तरदायित्व की निपाओ को किस प्रकार सगठित करें। दूसरे शब्दों में, एक उद्यमी के कार्यों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जा सकता है। यहाँ प्रमुख भूमिका राज्य को ही निभानी पड़ती है। राज्य के गतिशील नेतृत्व के अभाव में आर्थिक विकास की दर धीमी रहती है। इसका यह अर्थ नहीं है कि प्रत्येक समस्या के आसान हल के लिए सरकार की ओर एक सर्व-शक्तिमान सस्था के रूप में देखा जा सकता है। वह एक वास्तविक तरीका कहलाएगा। राज्य को आर्थिक गतिविधियों का संचालन इस रूप में करना चाहिए कि जिससे आर्थिक जीवन में अधिकाधिक व्यक्तियों को अवसर एवं अभिप्रेरणाएँ प्रदान कर वह आर्थिक विकास की प्रक्रिया को वास्तविक गति दे सके।

आधुनिकीकरण करने में पहले 50 वर्षों के जापान के अनुभवों के अध्ययन से इस बारे में काफी कुछ सीखा जा सकता है। क्योंकि, 110 वर्ष पहले जापान भी किमी भी अन्य एशियाई देश की तरह था। उसकी 30 मिलियन आबादी उतनी ही कृषि-प्रधान थी जितनी अन्य किमी स्थान पर थी। भूमि पर तीव्र दबाव था। तकनीक परम्परागत थी। कुपोषण, बीमारियाँ, शिशुओं की हत्या का कोई पार नहीं था। अन्य तत्व भी कोई विशेष आश्चर्यजनक नहीं थे। उसके औद्योगिक संसाधन अपर्याप्त थे तथा उसका राजनीतिक ढाँचा सामन्ती था। वहाँ के लोगों को लोकुगावा शासकों ने 250 वर्षों तक कृत्रिम रूप से दुनिया से अलग रखा था।

इन सबके बावजूद मेजी पुनर्संस्थापना के 75 वर्षों में बाद जापान में उत्पादक शक्तियों का जो विकास दिखाई दिया वह पश्चिमी राष्ट्रों के इतिहास में भी नहीं

मिलता। एक पृथक् एवं पिछड़े राष्ट्र से वह एक प्रमुख औद्योगिक एवं व्यावसायिक राष्ट्र बन गया। उसकी औद्योगिक क्षमता इतनी भीषण बन चुकी थी कि जब उसने 1941 में उसे युद्ध में झोंक दिया तो अमरीका जैसे देश को जापान को परास्त करने के लिए सैनिक कार्यों पर चार वर्षों तक अपार धनराशि खर्च करनी पड़ी।

किसी भी माप से यह एक असाधारण प्रगति थी। यह तकनीकी प्रगति का एक करिड्रमा था। जापान के आर्थिक विकास में राज्य की भूमिका जांचते समय इन तीन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए—

(1) यह चर्चा मुख्य रूप से उन कदमों तथा दृष्टिकोणों तक सीमित है जो सरकारों द्वारा समय-समय पर औपचारिक रूप से घोषित किये गये हैं। इसका अन्य मुद्दों से कोई सम्बन्ध नहीं है जैसे कि राज्य पर किसका नियन्त्रण था।

(2) यह विवेचन राष्ट्रीय सरकार की नीतियों से सम्बन्ध रखता है तथा इसमें स्थानीय निकायों का कहीं भी उल्लेख नहीं हुआ है।

(3) यह मुख्य रूप से उन राजकीय नीतियों से सम्बन्धित है जिन्होंने किसी न किसी रूप में जापान की वास्तविक प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय को प्रभावित किया। यह औद्योगीकरण के दौरान उठाये जाने वाले विवादों या मूल्यों (values) से सम्बन्धित नहीं है।

स्पेंगलर (Spengler) ने लिखा है कि 'आर्थिक विकास के गति-विज्ञान (dynamics) के क्षेत्र की विभिन्न परिकल्पनाओं (hypotheses) की जांच के लिए जापान एक आकर्षक प्रकरण प्रस्तुत करता है। आधुनिक समयों में व सांस्कृतिक विवाद एवं संवाद (synthesis) का सीमा क्षेत्र रहा है। जापान को अपनी अधिकांश प्रगति का श्रेय उन लोगों के नव-प्रवर्तनों (innovations) को रखा है जिन्हें अन्तिम टॉयनबी ने 'सृजनकर्त्ता अल्पसंख्यक' (creative minority) की संज्ञा दी है।' उसका विकास उसके अपने भौतिक परिवेश की चुनौती की प्रतिक्रिया भी रहा है— 'सीमित भूमि साधन किन्तु हर तरफ से समुद्र तक पहुँच'। उस पर युद्धों, मूल्यों के उत्तार-चढ़ावों तथा अन्य सांस्कृतिक एवं भौतिक तत्वों का महान् प्रभाव पड़ा है। औद्योगीकरण की समस्याओं में जापान का अनुभव एशियाई देशों के लिए पश्चिमी देशों के अनुभवों से कई रूपों में अधिक उपयोगी हो सकता है।

मेजी युग में राज्य द्वारा उद्योगों में अगुवाई

एक बार जब सम्राट की सत्ता अच्छी तरह स्थापित हो गई तो मेजी जापान के नेता महान् शक्ति एवं कुशलता के साथ उसके औद्योगिक विकास की नींव डालने में जुट गये। नौकरशाही (bureaucracy) तथा व्यापारी वर्ग ने एक प्रकार का संयुक्त मोर्चा बना लिया। मेजी सरकारी अधिकारी देश के उद्योगों व व्यापार के विकास का जोरदार समर्थन करते थे। यह सही है कि इसके पीछे उनका प्रमुख उद्देश्य

¹ *Ibid*, 503.

देश को सैनिक शक्ति बनाना था और इसीलिये वे पश्चिमी देशों के रहस्य जानने में उत्सुक थे। राज्य के शक्तिशाली बनाने में मेजी नेताओं व उनके उत्तराधिकारियों ने आर्थिक हितों की बलि देने में कभी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। किन्तु ये लोग शक्ति की उपासना तथा धन-सम्पदा की उपासना को एक दूसरे के सहयोगी उद्देश्य मानते थे। उनका नारा था 'फुकोकु क्यो हे'—अर्थात् एक समृद्ध देश एक सुदृढ़ सेना।

मेजी अधिकारियों ने यह अच्छी तरह समझ लिया कि औद्योगीकरण ही देश की सैनिक शक्ति का आधार बन सकता है। इसीलिये उन्होंने औद्योगीकरण को देश की नीति का प्रमुख ध्येय बना लिया। जन-कल्याण के स्थान पर शक्ति प्राप्त करने के प्रति यह पक्षपात बना रहा। किन्तु मेजी प्रशासकों ने आर्थिक समस्याओं को भी मोटे रूप में लिया। उन्होंने यह अनुभव कर लिया कि औद्योगीकरण के पीछे सहज मशीनों या तकनीकी विशेषज्ञों का आयात कर लेने से भी बहुत अधिक अपेक्षाएँ हैं। वे तोकुगावा शासन के कालातीत ढाँच को नष्ट करने में लग गये तथा उसके स्थान पर उन्होंने न्याय, प्रशासन एवं प्रतिरक्षा पर आधारित एक आधुनिक ढाँचे की स्थापना पर बल दिया। उन्होंने अनिवार्य शिक्षा का कार्यक्रम प्रारम्भ किया। इस तरह 1868 में हुई पुनर्संस्थापना के एक दशक के भीतर जापान एक मजबूत केन्द्रीय सरकार की स्थापना के साथ आर्थिक आधुनिकीकरण का मार्ग प्रशस्त करने की ओर बढ़ चला। मेजी युग की कुछ प्रमुख विशेषताएँ निम्नांकित रही—

(1) मेजी शासन पश्चिमी दबावों के उपरान्त जापान की स्वतन्त्रता बनाये रखने में सफल रहा। जब सरकार अशक्त थी तो उसने असमानतापूर्ण संधियों को भी मान लिया किन्तु 1899 में जब वह मजबूत हो गई तो उसने उन्हें रद्द कर दिया। देश के भीतर विदेशी व्यावसायिक उपक्रमों की स्थापना को हतोत्साहित किया गया। प्रारम्भ से ही आर्थिक नीति बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त रही। वह भावना से राष्ट्रीयतावादी थी।

(2) मेजी शासकों ने बहुत जल्द ही देश में गम्भीर प्रतिरोध को समाप्त कर दिया। सरकार अधिनायकवादी तथा नौकरशाही वाली बनी रही। ससद नाम-मात्र की सस्था थी। सरकार को राष्ट्रीय विकास के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ने की हर प्रकार से छूट थी।

(3) सरकार आर्थिक नीतियों के प्रति समर्पित थी। कई बार सकाएँ व जल्द-बाजी भी होती किन्तु सरकार आर्थिक क्षेत्र में सर्वशक्तिमान व हर जगह उपस्थित रही। उद्योग, बैंकिंग, रेलों के निर्माण आदि में उसके प्रयोगों में कई त्रुटियाँ दिखाई देती हैं। यद्यपि जापान के प्रशासकों व व्यावसायिकों की अधिनायकतावादी परम्पराएँ ही विरासत में मिली थी किन्तु वे जापान की आधुनिकता प्रदर्शित करने के लिए उतावले थे।

यह याद रखा जाना चाहिए कि राज्य ने ही जापान में औद्योगीकरण के लिए पहल की। 1868 के बाद वाले दशक में राज्य ने रेलमार्गों व तार की लाइनों का निर्माण किया। उसने नई कोयला खानें तथा अनुसंधान केन्द्र खोले। उसने लोहा गलाने की भट्टियाँ, पोत-निर्माण रयल तथा मशीन टूल कारखाने लगाये। उसने सूत

कताई व रेशम लपेटने के काम को मशीकृत करने के लिए विदेशी उपकरणों व विशेषज्ञों का आयात किया। सरकार ने ही सीमेंट, कागज तथा काँच का उत्पादन करने के लिए मॉडल फैक्ट्रियाँ लगाईं। इस तरह पश्चिमी तकनीक पर आधारित अधिकांश कारखाने सरकार द्वारा ही खोले गये। उसी ने प्रारम्भिक खतरे उठाये तथा अनेक निजी उद्यमों को सहायता दी।

किन्तु प्रत्यक्ष सरकारी उद्यम की यह अवधि जल्दी ही समाप्त हो गई। 1882 के बाद सरकार ने नेतृत्व प्रदान करना बन्द कर दिया। उसे अधिकांश प्रतिष्ठानों में हानि हुई। अब सरकार ने निजी उद्यमियों को प्रोत्साहन देने की नीति अपनायी। अधिकांश सरकारी प्रतिष्ठानों को कुछ निजी पूंजीपतियों के हाथों बेच दिया गया जो बाद में जैबत्सु के रूप में सामने आये। राजकीय पूंजीवाद की अवनति होने लगी हालांकि 1930 के बाद वह पुनर्जीवित हुआ। राजकीय स्वामित्व कुछ चुने हुए उद्योगों में रहा। उदाहरणस्वरूप सैनिक उद्देश्यों के लिए सरकार ने यवाता आयरन वर्क्स स्थापित किया। वह इस्पात उद्योग में अपना प्रभुत्व जमाये रहा। 1906 में सभी प्रमुख रेलमार्गों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। सरकार टेलीफोन, तार, टकसाल तथा कुछ सैनिक व नौसैनिक उपयोग के कारखानों को स्वयं चलाती रही। उसने जापानी बैंकिंग व्यवस्था पर अपना नियन्त्रण बनाये रखा।

एक अनुमान के अनुसार 1934 में सरकारी विनियोगों का कुल मूल्य 4,500 मिलियन येन के बराबर था। शाही रेलों में ही 3,682 मिलियन येन लगे हुए थे। 1930 में की गई राष्ट्रीय सम्पत्ति का सगणना के अनुसार जापान की राष्ट्रीय एवं स्थानीय सरकारों के पास 18 अरब येन मूल्य की सम्पत्ति होने का अनुमान लगाया गया था। यह वहाँ की कुल 110 अरब येन की राष्ट्रीय सम्पत्ति का छठा भाग थी। लगभग यही अनुपात तत्कालीन अमरीकी सम्पदा में अमरीकी सरकार का था। 1937 में चीन के साथ दुवारा लड़ाई छेड़ देने के बाद ही सरकार ने पुनः उद्योगों में भारी प्रत्यक्ष विनियोग करने तथा उन पर नियन्त्रण स्थापित करने की नीति अपनायी।

अप्रत्यक्ष सरकारी प्रयास

(1) शिक्षा—राष्ट्रीय एकता एवं प्रतिरक्षा के बाद मेजी सरकार ने सर्वाधिक ध्यान शिक्षा पर ही केन्द्रित किया। इसमें पहले शिक्षा केवल समुराई (Samurai) कोल्ले की अपेक्षा थी। सरकार ने कई प्रिन्सिपल व प्रिन्सिपल वरिन्सिपल विद्यालयों का अध्ययन करने हेतु विदेश भेजे। 1871 में एक शिक्षा विभाग बनाया गया। चिकित्सा, सैनिक विज्ञान, व्यवसाय, मत्स्य पालन तथा कृषि के क्षेत्र में स्कूल कॉलेज खोले गये। शिक्षा एवं अनुसंधान के क्षेत्र में प्रमुख केन्द्र के रूप में टोक्यो शाही विश्वविद्यालय को आगे लाया गया। जापान के प्रमुख शिक्षाशास्त्री अमरीकी विचारों से प्रभावित हुए।

अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में सारी प्रगति की गई। 1900 में देश के 27,000 स्कूलों में 5 मिलियन बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। कॉलेजों व विश्वविद्यालयों में 15,000 छात्र थे। 1903 तक 240 तकनीकी स्कूल गठित किये

जा चुके थे। जनसंख्या की दृष्टि से जापान में इजीनियरो का अनुपात कई पश्चिमी यूरोप के देशों से ऊँचा हो चुका था। शिक्षा के प्रसार ने आर्थिक अवसरों में वृद्धि की तथा असमानताओं को कम किया। राज्य के किसी भी अन्य उपक्रम ने इतना लाभान्वित नहीं प्रदान किया था जितना कि शिक्षा ने।

(2) मौद्रिक एवं राजकोषीय नीतियाँ—मेजी जापान में वचत का गतिशीलन एक महत्वपूर्ण समस्या थी। हालांकि कुल विनियोग में सरकार का भाग काफी कम था किन्तु उसने हर कदम पर देश के पूँजी-निर्माण को प्रभावित किया। जैसे-जैसे सरकार द्वारा नई तकनीकों को लोकप्रिय बनाया गया वैसे वैसे विनियोग की गति तीव्र हुई। आय व धन की भारी असमानताओं ने निजी पूँजी निर्माण की सहायता की। वचतों के उत्पादक उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिए एक नई वित्तीय प्रणाली की आवश्यकता थी। 1868 से 1881 तक अस्त-व्यस्त वित्तीय इतिहास यही स्पष्ट करता है कि ये प्रक्रियाएँ निर्माण की अवस्था में थी। केवल भारी मात्रा में पत्र-मुद्रा निर्गमित करके ही मेजी सरकार अपनी प्रारम्भिक आवश्यकताएँ पूरी कर सकती थी। एक अधिक व्यवस्थित समाधान बाद में खोजा गया।

1873 का भूमि-कर सुधार भूमि लगान को अधिक व्यवस्थित रूप में वसूल करने की दिशा में एक प्रमुख कदम था। अधिकारियों ने पूँजी की पूर्ति में वृद्धि करने के लिये सयुक्त पूँजी कम्पनियों को प्रोत्साहन दिया। पत्र मुद्रा तथा बैंकिंग के क्षेत्र में 1880 के बाद के दो दशकों तक लगातार वाउन्ट मत्सुकाता द्वारा दूरगामी सुधार किये गये। 1882 में स्थापित बैंक ऑफ जापान को केन्द्रीय बैंक के रूप में विकसित किया गया।

(3) बैंकिंग का विकास—मेजी काल में स्थापित किये गये अर्द्ध-सरकारी बैंकों ने बैंकिंग के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बैंक ऑफ जापान के अतिरिक्त उनमें योकोहामा स्पीशी बैंक, जापान का औद्योगिक बैंक तथा हाइपोथेक बैंक ऑफ जापान भी सम्मिलित थे। ये बैंक जैक्सु द्वारा संचालित निजी बैंकों के साथ सहयोग करके चलते थे। 1900 के बाद इन सरकारी बैंकों के पास कुल प्रदत्त पूँजी का पाँचवाँ भाग था। डाकखानों की वचत योजना को डिपॉजिट ब्यूरो के अन्तर्गत चुरू किया गया।

सरकारी बैंकों का प्रमुख उद्देश्य निजी वचतों का सरकारी वित्तीय आवश्यकताओं के लिए उपयोग करना था। बैंक ऑफ जापान अन्य बैंकों को नियन्त्रित करता था। योकोहामा स्पीशी बैंक ने देश को एक कुशल विदेशी विनिमय-प्रणाली प्रदान की। औद्योगिक बैंक ने उद्योगों के लिए देश के भीतर तथा विदेशों से ऋण जुटाये। हाइपोथेक बैंक ने कृषि क्षेत्र को साख सुविधाएँ प्रदान की।

प्रथम महायुद्ध से पहले तक जापान में मुद्रा एवं साख का प्रसार कुल मिलाकर एक अस्त-व्यस्त प्रक्रिया थी। उसमें बार-बार मन्दी व तेजी की स्थितियाँ आती रहती थी। किन्तु मन्दी की स्थितियाँ काफी कम समय तक रही तथा पत्र मुद्रा के प्रारम्भिक अनुभवों के बाद सरपट दोड़ती हुई स्थिति पर भी नियन्त्रण पा लिया गया। कुल मिलाकर जापान ने मुद्रा व साख की आधुनिक पेशीदण्डियों को सफलतापूर्वक निपटा

लिया जिनमे राज्य का उत्तरदायित्व सर्वाधिक था। उसने बहुत रूढ़िवादी नीति भी नहीं अपनायी। विकास की इस प्रक्रिया में कई नव-प्रवर्तन भी आवश्यक थे। इनमें नये विनियोगों की आवश्यकता थी। मुद्रा व साख के क्षेत्र में मौद्रिक-प्रसार द्वारा सार्वजनिक नीति ने इन आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता की।

(4) भेजी कर प्रणाली व उपक्रम—राजकीय नीति का एक सबसे प्रभावशाली हथियार करारोपण होता है। इसमें न केवल करो का पैमाना व भार (Scale and incidence) सम्मिलित होते हैं जिन्हें कि सरकार लगाती है बल्कि वे उद्देश्य भी शामिल होते हैं जिनके लिए उन करो का प्रयोग किया जाता है।

भेजी युग में किये कर-सुधारों ने एक निश्चितता का वातावरण पैदा किया। उनमें कुल मिलाकर कटौती भी की गई। मनमाना करारोपण समाप्त किया गया। 1873 के भूमि-कर सुधार कानून के बाद भूमि-कर सरकारी आय का प्रमुख स्रोत बन गया। 1882 में उसमें कुल करो का 82% प्राप्त हुआ। 1887 में पश्चिम से आयकर का विचार भी देश में लाया गया। 1896 में व्यावसायिक लेन-देन (Turnover) पर एक सामान्य कर भी लगाया गया। 1905 में एक साधारण सा उत्तराधिकार कर भी लगाया गया। किन्तु इन सभी करों से 1913 तक भी कुल आगम का केवल 15% भाग प्राप्त होता था। 1880 से 1913 तक अप्रत्यक्ष कर ही सरकारी आय का प्रमुख स्रोत थे। 1893 व 1913 में उनका भाग क्रमशः 79% तथा 63% था। इस बीच स्थानीय निकायों भी करो द्वारा आय प्राप्त कर रही थी। वे राष्ट्रीय करों का 40% थे।

दो महायुद्धों के बीच सरकारी नीति

जब प्रथम महायुद्ध समाप्त हो गया तो शस्त्रास्त्रों पर व्यय में कटौती कर दी गई। सरकार ने कृषि विकास के लिए व सामाजिक कल्याण के लिए अधिक कोष नियत किये। 1921 में चावल के मूल्य स्थिर करने के लिए भी सरकार ने भारी राशि खर्च की। उसने सार्वजनिक स्वास्थ्य, शहरी सफाई आदि के नये दायित्व स्वीकार किये। कर-प्रणाली में संशोधन किया गया। किन्तु जापानी संसद की इन सभी उपायों में अधिक रुचि नहीं थी। उसकी रुचि तो अधिकाधिक कोष बढ़े बँकों व बड़े पैमाने के उद्योगों के लिए जुटाने में थी तथा उसने कृषि पर बहुत कम ध्यान दिया। कर-प्रणाली में भी कोई आधारभूत परिवर्तन नहीं किये गये। आय की बड़ी मात्रा पर बहुत हल्के कर लगाये गये। दोनों महायुद्धों के बीच के वर्षों में कुल कर भार राष्ट्रीय आय के 10 से 15 प्रतिशत के बीच रहा।

युद्ध से पहले की जापानी सरकारों ने अपने कर लगाने के अधिकार का उपयोग आय में अधिक समानता स्थापित करने के लिए नहीं किया। सम्पत्ति से प्राप्त भारी आय पर बहुत कम कर लगाये गये। 1940 में किये गये कर सुधारों के बाद ही आयकर का एक प्रभावशाली अस्त्र के रूप में उपयोग आरम्भ हुआ। किन्तु, अन्य एशियाई देशों के विपरीत, जापान के समृद्ध व्यक्तियों की प्रशंसा में यह बात कही जा सकती है कि उन्होंने अपने धन का उपयोग मूँजी-निर्माण को बढ़ावा देने के

लिए किया।

युद्धों के बीच के काल में औद्योगिक विकास अन्य प्रकार के राजकीय हस्तक्षेपों से भी प्रभावित हुआ। कृषि, जहाज-निर्माण तथा रेलों के विकास के लिए भारी अनुदान दिये गये। किन्तु इन अनुदानों की भूमिका जापान के आर्थिक विकास में काफी सीमित ही रही। 1931 में इन अनुदानों की कुल वितरित राशि मात्र 61 मिलियन येन ही थी। इसी तरह तटकरों ने भी राष्ट्रीय विकास में कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं दिया। 1911 में निर्धारित तटकर नीति के पीछे यही सिद्धान्त अपनाया गया कि जो कच्चे माल जापान में उपलब्ध नहीं होते उन्हें शुल्क मुक्त प्रवेश दिया जाए। विलासिताओं पर भारी तटकर लगाये गये। इस तरह दोनों महायुद्धों के बीच के वर्षों में जापान अत्यन्त साधारण तटकरों वाला देश बना रहा।

विदेशी अर्थ-नीति

विदेशों में आर्थिक अवसरों की खोज एवं ऐसा क्षेत्र था जिसमें सरकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। इसमें वे सभी नीतियाँ सम्मिलित थी जो विदेशों से वस्तुएँ, विचार, पूँजी तथा व्यक्तियों के देश में आने से सम्बन्ध रखती थी। ये नीतियाँ राज्य के लिए विशेष ध्यान देने योग्य थी क्योंकि जापान की विदेशी वस्तुओं तथा तकनीक पर निर्भरता अत्यधिक थी। द्वीपीय राष्ट्र की राजनीतिक असुरक्षा के कारण भी इन आवागमनों पर नियन्त्रण आवश्यक था। राज्य ने इस सम्बन्ध में निम्न उत्तरदायित्व ग्रहण किये—

(1) उमने अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्पर्कों के लिए सस्वागत ढाँचा तैयार किया। राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित करने के अतिरिक्त इसमें जापानी वित्तीय प्रणाली को विदेशी मुद्रा बाजारों से जोड़ने की मशीनरी का निर्माण करना भी इसमें सम्मिलित था। 1897 में स्वर्णमान का अपनाया जाना तथा योकोहामा स्पीशी बैंक की स्थापना किया जाना (विदेशी विनियमों की देखभाल हेतु) इसी दिशा में उपाय थे।

(2) तकनीकी सहायता के प्रदान किये जाने के महत्व पर पहले ही प्रकाश डाला जा चुका है। इसमें भी पहले करने का काम सरकार ने ही किया था।

(3) श्रम व पूँजी के जापान से बाहर जाने के विनियमन का कार्य भी राज्य ने ही किया। इसका प्रमुख सम्बन्ध उपनिवेशों के साथ व्यापार से था तथा वह अर्थ-व्यवस्था के सर्वांगीण विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण था।

(4) सरकार ने भारी मात्रा में पश्चिमी देशों से कर्ज लिये। 1897 से 1913 तक राज्य सरकार की साख पर ही यूरोप के मुद्रा बाजारों से जापान ने 2 बिलियन येन मूल्य के कर्ज लिये। इससे जापान को अपने घरेलू साधनों का सम्बर्द्धन करने में सहायता मिली।

विदेश व्यापार का विकास—राज्य ने जापानी व्यवसायियों को विदेशों में व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करने में बहुत सहायता की। राज्य उन उद्योगों के विकास के बारे में अधिक चिन्तित था जो अपने आयातों के लिए अपने निर्यातों द्वारा भुगतान कर सकती थी। सरकार ने विदेश व्यापार तकनीकों के विकास में सक्रिय रुचि ली।

उत्तम जापानी वस्तुओं की विदेशों में प्रदर्शनियाँ लगाईं। उसने एक पूरे औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना की जिसमें जापानी व्यवसायी निर्बाध रूप से व्यापार कर सकते थे। अपने विदेश व्यापार में जापानी सरकार ने बहुपक्षीय व्यापार के मिडान्त को स्वीकार किया। उसने अपने लिए कच्चा माल सस्ते से सस्ते बाजारों में खरीदा तथा निर्मित माल को श्रेष्ठतम सम्भव मूल्यों पर जहाँ भी सम्भव हुआ बेचा। 1929-30 के दौरान जापान को अमरीका के साथ व्यापार में 75 मिलियन येन तथा चीन के साथ व्यापार में 143 मिलियन येन का लाभ रहा। जापान ने इस अतिरिक्त का उपयोग अपने यूरोप व एशिया के साथ हुए क्रमशः 233 मिलियन येन व 123 मिलियन येन के घाटों को पूरा करने में किया। इस बीच जापान के सैनिक तत्त्व सम्पूर्ण एशिया पर विजय पाने की अपनी याजना को आगे बढ़ा रहे थे। उनकी ये योजनाएँ ही उनके विनाश का कारण बनीं।

इस तरह आर्थिक साम्राज्यवाद¹ सैनिक प्रसारवाद को दासी बन गया। शक्ति, कूटनीति, विनियोग, व्यापार एवं प्रवास सभी का एक साथ सहारा लिया गया। इन सबने मिलकर कुछ समय के लिए सम्राट के अधिक गौरव (Greater glory of the Emperor) के लिए तथा साथ ही कुछ व्यावसायिक हितों की स्वायत्त-पूर्ण हेतु कार्य किया। करदाता धैर्य से इन सबके लिए धन उपलब्ध कराते रहे।

साम्राज्य के लिए तलाश 1930 के बाद आरम्भ हो चुकी थी। 1931 में मन्चूरिया पर विजय के बाद जापान के आर्थिक प्रतिष्ठानों के क्षेत्र में साम्राज्य स्थापना का लक्ष्य प्रमुख बन गया। 1938 के अन्त तक जापान का मन्चूरिया में विनियोग बढ़कर 3,600 मिलियन येन हो चुका था। एक अनुमान के अनुसार 1936 से 1939 तक जापान को कोरिया तथा फारमोसा से प्रति वर्ष 213 मिलियन येन का विशुद्ध प्रतिफल प्राप्त हो रहा था। सफेदपोश कर्मचारियों के लिए भी साम्राज्य नौकरियाँ पाने का अच्छा क्षेत्र बन गया था। 1933-37 के बीच कोरिया, फारमोसा व मन्चूरिया ने जापान के कुल निर्यातों में से 37% को खपाया था तथा खाद्य पदार्थ व कच्चे माल के रूप में उसके कुल आयातों में 29% का योग दिया था। किन्तु इन साम्राज्यवादी नीतियों का बड़ा बुरा अन्त हुआ तथा उनसे केवल हथियारों पर खर्च ही बढ़ा। जापान के आर्थिक इतिहास में यही एक बिन्दु था जहाँ युद्धोन्मत्त (war maniacs) लोगो ने देश को गलत दिशा दी जिसने उस पर द्वितीय महायुद्ध की बरबादी थोप दी।

सुरक्षणवाद एवं अनुदान

इस बारे में कोई सन्देह नहीं हो सकता कि जापान द्वारा घरेलू व उसके औपनिवेशिक बाजारों में अपनायी गई सुरक्षणवादी नीति ने वहाँ के विनिर्माण-उद्योग को भारी लाभ पहुँचाया। रेशम व सूती वस्त्र जैसे पुराने उद्योगों को तो विशेष सुरक्षण की आवश्यकता नहीं थी किन्तु इस तटवर सहायता का कई नये उद्योगों को लाभ हुआ।

जहाज-निर्माण एक ऐसा उद्योग रहा जिसे सरकारी सहायता व अनुदानों का भारी लाभ मिला। शुरु से ही उसे मेजी अधिकारियों ने काफी महत्वपूर्ण माना व उस पर ध्यान दिया था। इन नीतियों ने ही 1913 तक जापान को विश्व का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक जहाजी ब्रेडे वाला राष्ट्र बना दिया था। जहाज-निर्माण व सेवा के विकास में दी गई सरकारी सहायता संक्षेप में इस प्रकार रही—

(1) 1896 व 1909 के कानूनों के अन्तर्गत सरकारी अनुदान (operating subsidies) दिये गये। बड़ी कम्पनियों को उनकी जहाजी सेवाएँ बढ़ाने तथा उनके जहाजी ब्रेडे को आधुनिक बनाने के लिए सहायता दी गई। 1900 से 1914 तक जहाजी कम्पनियों को अपनी विशुद्ध आय का 77% इन अनुदानों से प्राप्त हुआ।

(2) प्रमुख जापानी बन्दरगाहों के बीच व्यापार करने से विदेशी जहाजों को 1894 के बाद से रोक दिया गया। 1911 में तो उन्हें तटवर्ती व्यापार से पूरी तरह बाहर कर दिया गया।

(3) एक न्यूनतम आकार के जहाजों का निर्माण करने पर 1896 से 1917 तक अनुदान दिया जाता रहा। बड़े और अधिक गति वाले जहाजों के लिए अनुदान अधिक दर पर दिया जाता था।

(4) 1931 में व्यापार के प्रसार के साथ ही जहाज-निर्माण को और आधुनिक बना दिया गया। 4,000 टन से अधिक क्षमता वाले तथा 13.5 समुद्री मील से अधिक गति वाले जहाजों के निर्माण व्यय का 20% जापान की सरकार अनुदान के रूप में देती थी। 1937 तक जापान के पास 4 मिलियन टन क्षमता का वाष्प-चालित जहाजी बेड़ा तैयार हो चुका था जिसकी गति 14 समुद्री मील प्रति घण्टा से अधिक थी।

सारांश रूप में राजकीय सहायता व प्रोत्साहनों ने प्रारम्भिक वर्षों में जापान के जहाज-निर्माण उद्योग को काफी सहायता प्रदान की। इसके बिना उसका व्यापारिक जहाजी बेड़ा 1880 से 1910 के बीच प्रत्येक दशक में दुगुना नहीं हो सकता था। 1941-44 के बीच जापान ने जो विशाल साम्राज्य जीता तथा अपने नियन्त्रण में रखा वह भी उसकी नौसैनिक शक्ति का ही परिणाम था जो द्वितीय महायुद्ध के दौरान नष्ट हो गई थी।

कृषि में सरकार का योग

यह कुछ आश्चर्यजनक प्रतीत हो सकता है कि जापान के एक सामन्ती देश से आधुनिक देश के रूप में रूपांतरण के लिए कृषि में पूर्ण क्रान्ति की आवश्यकता नहीं पड़ी। यही कारण था कि मेजी क्रान्ति ने औसत किसान के जीवन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं डाला। देश का 15% से भी कम क्षेत्रफल कृषि-योग्य था। इसमें से अधिकांश भाग पर किसान लोग 2 से 3 एकड़ के छोटे-छोटे टुकड़ों पर गहन खेती कर रहे थे। पुनर्स्थापना के बाद की जापानी सरकारों ने कृषि सुधार की दिशा में कुछ कदम उठाये भी जिनसे मेजी युग के अन्त तक कृषि उत्पादन दुगुना हो चुका था। सरकार ने जापानी कृषि को औद्योगीकरण की बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने की भी चेष्टा की। राष्ट्रीय सरकार ने कई तकनीकी सहायताएँ तथा ग्रामीण

सार्वजनिक कार्य शुरू किये। स्थानीय संस्थाओं ने भी भूमि के पुनर्ग्रहण, सड़कों के निर्माण व सिंचाई के विकास में सहायता की। कृषि सहकारियों व ग्रामीण मछली पकड़ने वाले सघों का गठन किया गया। 1890 के बाद सरकार ने कृषि अनुसन्धान क्षेत्रों का जाल बिछाया तथा भू-प्रबन्ध, कीटाणु नियन्त्रण, उन्नत बीज तथा रासायनिक खादों से सम्बन्धित तकनीकी समस्याओं के समाधान हेतु कई एजेंसियाँ भी स्थापित कीं। वन संरक्षण कार्यक्रम भी चलाया गया।

कृषि को दी गई इस तकनीकी सहायता जितना और कोई भी सार्वजनिक व्यय फलीभूत नहीं हुआ। इसने युद्ध-पूर्व कृषि की उत्पादकता 50 से 75% तक बढ़ा दी। किन्तु इन तकनीकी सहायताओं तथा कुछ पूँजीगत सहायता के अलावा कृषि का भाग्य मेजी काल में निजी व्यक्तियों तथा बाजार शक्तियों के हाथों में मौप दिया गया। भू-धारण प्रणाली तब तक दोषपूर्ण बनी रही जब तक द्वितीय महायुद्ध के बाद अमरीकी आधिपत्य वाली सरकार ने क्रांतिकारी भूमि-सुधार नहीं कर लिये। कृषि मामलों पर 1920 के बाद से ध्यान दिया जाने लगा। जन मांगों से बाध्य होकर सरकार को सक्रिय रूप से ग्रामीण सहायता करनी पड़ी। 1935 तक प्रत्येक 3 खेतों में से 2 सहकारी समितियों के सदस्य बन चुके थे। किन्तु लम्बे समय से चली आ रही कृषि समस्याओं पर भारी व प्रभावों प्रहार करने का कार्य अमरीकी आधिपत्य वाली सरकार ने ही अन्जाम दिया।

श्रमिक हितों का संरक्षण व सरकार

प्रथम महायुद्ध से पहले की जापानी सरकारों ने श्रमिकों की सुरक्षा के लिए बहुत कम कानून बनाये थे। काम के घटो, मजदूरी या बाल श्रम के बारे में भी कोई कानून नहीं था। श्रमिक हितों की सुरक्षा करने वाले कानूनों के लिए मांग मेजी काल के प्रारम्भिक वर्षों से की जाने लगी थी। पहला कानून 1905 का खान कानून था। 1919 में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (I.L.O.) की स्थापना के बाद पहली बार अन्तर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जापानी सरकार पर वहाँ के श्रमिकों के हितों की सुरक्षा हेतु कानून बनाने के लिए दबाव डाला गया। मजदूर सघों की सदस्यता बढ़ी थी गति से बढ़ी। 1926 में मजदूर सघों की सदस्यता 3 लाख के लगभग थी। 1932 में फैक्ट्री एक्ट का अधिकार-क्षेत्र बढ़ाया गया। 1921 से 1936 के बीच श्रम कानूनों के क्षेत्र में काफी प्रगति की जा चुकी थी किन्तु 1937 के बाद वे निरर्थक हो गये। सैनिक उद्देश्यों की पूर्ति ने इन श्रम कानूनों को बहा दिया। युद्ध के बाद इस क्षेत्र में सारा कार्य नये सिरे से करना पड़ा।

व्यापार पर नियन्त्रण

मेजी राजनीतिज्ञ आधुनिक उद्योग स्थापित करने की जल्दी में थे, विशेष रूप से उन्हें जितने सैनिक शिक्षा का विकास होता हो। इसीलिए अपनी औद्योगिक नीति में भी जापानियों ने, सैनिक संगठन के क्षेत्र की ही भाँति, जर्मन, डॉचे का अनुसरण किया। छोटे पैमाने के उद्योगों में जापानी सरकार ने अधिक हस्तक्षेप नहीं किया।

जब 1880 में जापानी सरकार ने उद्योगों के विकास का दायित्व छोड़ दिया तो निजी पूंजीपतियों ने अपनी जड़ें मजबूती से जमा लीं। प्रो० जी० सी० एलन के शब्दों में, जैबत्सु का विकास 'राष्ट्रीय नीति के अंग' के रूप में हुआ। सैनिक व नागरिक प्राधिकरणों ने हमेशा राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों के क्रियान्वयन में सहयोग किया। यह फिर भी कहना होगा कि 1880 के बाद छोटे व बड़े दोनों ही उद्योगों को काफी अंशों तक स्वतन्त्र रहने दिया गया था, यद्यपि इसके लिए 'अहस्तक्षेप' की नीति का शब्द काम में नहीं लाया जा सकता। सरकार ने बैंकिंग तथा वित्तीय नीतियों के द्वारा नियन्त्रण के कुछ उल्लेख (levers) अपने हाथों में रखे। फिर भी आर्थिक एवं औद्योगिक शक्ति के संकेन्द्रण के लिए असीमित अवसर दे दिये गये थे।

युद्ध, मदी तथा औद्योगिक नियन्त्रण

प्रथम महायुद्ध के बाद आर्थिक गतिविधियों में राजकीय हस्तक्षेप बढ़ गया। यह हस्तक्षेप श्रम कानूनों, तटकर अधिनियमों आदि के रूप में सामने आया। महान् मदी के समय तो बड़े उद्योगपतियों ने स्वयं सरकार से हस्तक्षेप करने के लिए कहा। बड़े उद्योगों की कार्यकुशलता बढ़ाने व लागते घटाने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया। 1930 में इसी उद्देश्य से सरकार द्वारा एक विवेकीकरण ब्यूरो स्थापित किया गया प्रमुख उद्योग नियन्त्रण कानून 1931 में पारित किया गया। सरकार ने छोटे विनिर्माताओं व व्यापारियों को विनिर्माण संघों तथा निर्यातक संघों के रूप में एकीकृत हो जाने के लिए प्रोत्साहित किया। 1937 के चीन-जापान युद्ध के बाद देश 'नये आर्थिक ढाँचे' की तरफ बढ़ने लगा जिसने विशाल उपक्रमों पर राज्य का नियन्त्रण के असीमित अधिकार प्रदान किये। युद्ध के समय यह नियन्त्रण और भी बढ़ गया। 1941 में देश में करीब 20,000 नियन्त्रण एजेंसियाँ थीं।

1945 में युद्ध समाप्त हो जाने के बाद देश के पुनर्निर्माण में जापानी सरकार ने सक्रिय भूमिका निभायी। एक दशक से भी कम समय में देश का पुनर्निर्माण कर पाना एक ऐसा आश्चर्य था जो केवल जर्मनी द्वारा दोहराया गया।

राज्य की भूमिका के बारे में थोड़ा हटकर रॉबर्ट पी० पोटर के इस कथन को देखा जा सकता है जो इस अमरीकी अन्वेषक ने इस शताब्दी के आरम्भ में प्रस्तुत किया था 'इस अवधि में जापानी लोग आर्थिक एवं व्यावसायिक प्रश्नों के साथ जितना जूझ रहे थे उतना दुनिया के इतिहास में शायद ही कभी कोई व्यक्तियाँ जालि जूझी होगी। सम्राट, प्रधानमंत्री, मन्त्रिमण्डल, जापानी ससद (Diet) के सदस्य, अन्य अधिकारी—सबके सब जापान की भावी प्रगति व महानता के रंग में रंगे हुए थे तथा उसे विश्व के उस भाग का सर्वाधिक प्रभुत्व वाला देश बनते देखना चाहते थे। सार्वजनिक भोजन पर, सभी प्रकार के सरकारी उत्सवों पर यही सुनाई पड़ता था कि जापान की भौतिक प्रगति को तीव्रतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? जापानी भाषा के पत्रों ने इसी प्रश्न को उठा रखा है तथा सभी प्रकार के उपक्रमों का विदोहन उतने ही हर्षोल्लास से किया जा रहा है जितना हमारे देश (अमरीका) के निर्माण के समय किया गया था।'

विदेश व्यापार

(THE JAPANESE FOREIGN TRADE)

आधुनिक जापान का कोई भी पहलू इतना नाटकीय नहीं है जितना कि 1868 के बाद उसके विदेश व्यापार में हुई क्रांतिकारी वृद्धि।¹ आर्थिक पृथक्ता की स्थिति में जीने वाला यह लघुकाय द्वीपीय राष्ट्र पिछले 110 वर्षों में विश्व के विशालतम व्यावसायिक साम्राज्यों में से एक बन गया है। 1850 में जापान के पास व्यापारिक जहाजी ब्रेडा नाम को भी नहीं था। यदि कोई जापानी देश से बाहर जाना चाहता और पकड़ा जाता तो उसे मृत्यु-दण्ड मिलता था। 50 टन से अधिक की क्षमता वाला कोई भी जहाज जापान में निर्मित नहीं किया जा सकता था।

इस पृष्ठभूमि में आधुनिक समयों में हुआ कायाकल्प आश्चर्य में डाल देने वाला है। द्वितीय महायुद्ध की बर्बादी से पहले जापान ने व्यापार का जाल विछा दिया था तथा वह दुनिया में पाँचवें स्थान पर आ चुका था। एशिया में उपभोग की जाने वाली कारखानों से उत्पादित वस्तुओं का प्रमुख भाग जापान उपलब्ध कराता था।

स्वयं जापान के लिए विदेश व्यापार आर्थिक समृद्धि का द्वार खोलने वाली कुंजी सिद्ध हुआ। एक नई तकनीक ने उसके सम्पूर्ण आर्थिक जीवन में क्रांति ला दी। विदेशी बाजारों पर जापान की निर्भरता उसकी अपनी व उपनिवेशों की सीमा पार कर गयी। इससे कुछ राजनीतिक असुरक्षा भी पैदा हो गयी। इस सम्भावना से बचने के लिए साम्राज्यवादी विचारधारा वाले कुछ सैनिक तत्त्वों ने एक हिंसक दौर में दूसरे महायुद्ध के दौरान सभी कुछ दाव पर लगाकर पूर्वी एशिया में एक नया साम्राज्य स्थापित करने की चेष्टा की। जो परिणाम निकला वह आज इतिहास बन चुका है। युद्ध ने जापान के औद्योगिक ढाँचे की व्यावसायिक नींवों को ही नष्ट कर दिया। युद्धोत्तरकालीन पीढ़ियों को वे नींवें फिर से बनानी पड़ी।

आन्तरिक एवं विदेशी व्यापार की पारस्परिक निर्भरता

यह विचार कि विदेशी बाजारों को प्राप्त करना ही जापानी औद्योगीकरण का मूलधार रहा, अर्द्ध-सत्य ही है। यह सही है कि प्रारम्भिक प्रोत्साहन (initial stimuli) तथा नई तकनीक प्रमुख रूप से विदेशों से ही आयी थी। इस रूप में जापान की औद्योगिक क्रांति विदेशी व्यापार का सृजन भी रही। किन्तु राष्ट्रीय प्रतिक्रिया भी सकारात्मक व सम्पूर्ण रही तथा सारी अर्थव्यवस्था में सक्रिय भी रही। इसके

परिणामस्वरूप उत्पादकता एवं सम्पदा में निरन्तर वृद्धि हुई जिससे आयात व निर्यात दोनों ही का बहुत विकास हुआ। जैसे-जैसे किसी देश की राष्ट्रीय आय बढ़ती है उसे विदेश व्यापार में भी लाभ होता है।

यदि जापान का विदेश व्यापार बढ़ा तो आन्तरिक व्यापार भी पीछे नहीं रहा। उल्टे आन्तरिक व्यापार का परिमाण हमेशा अधिक रहा। कोई भी देश एक कमजोर एवं अनिर्मित अर्थव्यवस्था के बल पर महान् विदेशी व्यापार की संरचना नहीं कर सकता। जापान में न केवल आन्तरिक एवं विदेशी व्यापार एक-दूसरे से निकट बने रहे बल्कि वे एक ही प्रक्रिया के दो पहलू भी बने रहे। जापानी अर्थ-व्यवस्था का विकास इन दोनों ही पहलुओं की पंचोदा अन्तर्प्रतिक्रिया (interaction) का ही परिणाम था।

दूसरा अतिवादी निर्णय जापान को राष्ट्रीय आर्थिक विकास का ही एक 'घत-प्रतिशत' मामला बताना होगा। कई अर्थों में उसका विकास अन्तर्राष्ट्रीय विकास का एक अनूठा उदाहरण था। विदेशी प्रभाव तथा विदेशी व्यापार ने उसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह जापान का सौभाग्य रहा कि उसने अपनी अर्थ-व्यवस्था के लिए आधुनिकीकरण का मार्ग ऐसे समय में चुना जब सम्पूर्ण विश्व अर्थ-व्यवस्था का प्रसार हो रहा था। स्वयं जापान ने पहले 70 वर्षों तक एक बहुत उदार व्यापार नीति अपनायी।

विदेश व्यापार का विकास . 1868-1938

1868 से 1938 के बीच जापान के विदेश व्यापार में तीव्र एवं भारी वृद्धि हुई।

विदेशों के साथ जापानी व्यापार का विकास 1885-1938

वार्षिक औसत	कुल मूल्य (मिलियन येन में)		
	आयात	निर्यात	संतुलन
1885-1889	47	55	+ 8
1895-1899	206	163	- 43
1905-1909	468	413	- 55
1915-1919	1,423	1,663	+240
1925-1929	2,849	2,449	-355
1930-1934	2,212	2,058	-154
1935-1938	3,868	3,772	- 96

इस विकास की अनेक विशेषताओं की तरफ ध्यान आकृष्ट हो जाता है। एक ऐसी प्रवृत्ति आयात व निर्यात दोनों ही में बराबर वृद्धि को रही है। वे हर दशक में दुगुने होते चले गये तथा उनकी वार्षिक विकास दर 7.5% से अधिक ही रही। यह विश्व आयातों में विकास की दर से दुगुनी थी। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया अपने पूरे जोर पर थी। विदेशों से भारी मात्रा में मशीनों तथा बच्चे माल का आयात कर जापान ने विश्व व्यापारिक नीतियों का भरपूर लाभ उठाया।

प्रथम विश्व-युद्ध ने जापानी निर्यातों की वृद्धि के लिए एक अनुग्रह सुअवसर प्रदान किया। वास्तव में 1932-37 के बीच की व्यापारिक तेजी एक सम्बन्धित समय से चली आ रही गतिविधियों के गहन हो जाने का ही परिणाम थी। यह दो रूपों में भिन्न थी - (1) जापानी व्यापार अब सम्पूर्ण विश्व में फैल चुका था, तथा (2) जापान के निर्यात महान् मन्दी के दौरान लगभग अप्रभावित ही रहे। व्यापार में प्रसार, जो मेजी काल से आरम्भ हो चुका था, आगे बढ़ता गया। चार सीमित युद्धों, मूल्यों में आने वाले उतार-चढ़ावों, भूकम्पों तथा कुछ अन्य सकटों ने व्यापार में इस दीर्घकालिक वृद्धि को अस्थायी रूप से छिन्न-विच्छिन्न किया। किन्तु पहला वास्तविक आघात तो तभी लगा जब इस ढाँचे को युद्ध की तैयारियों के चक्कर में उत्तरोत्तर बिगाड़ा गया तथा बाद में तो वास्तविक युद्ध ने इसे नष्ट ही कर दिया था।

व्यापार में इस प्रसार की दूसरी विशेषता के रूप में कोई यह अनुमान भी लगा सकता है कि शायद बढ़ते हुए निर्यात अधिकाधिक विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद सोखते जा रहे थे अथवा आयातों का राष्ट्रीय आय में भाग बढ़ता जा रहा था।

शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (N.N.P.) के प्रतिशत के रूप में जापान का विदेश व्यापार, 1885-1938

(यमुदा के अनुमान)

वार्षिक औसत	शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (मिलियन येन में)	राष्ट्रीय उत्पाद के प्रतिशत के रूप में	
		निर्यात	आयात
1885-1889	937	5.9	5.1
1895-1899	1,962	8.3	10.5
1905-1909	3,106	13.2	15.1
1915-1919	7,623	21.8	18.8
1925-1929	13,621	18.3	20.9
1930-1934	12,029	17.1	18.4
1935-1938	18,377	20.5	21.0

1860 के शून्य से घुट होकर आयात व निर्यात दोनों ही 1900 तक शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का 10% हो चुके थे। दोनों महायुद्धों के बीच के वर्षों में ये अनुपात 15 से 20% के बीच रहे। 1918 के बाद निर्यातों ने न केवल आयातों के लिए वित्त प्रदान करने में प्रमुख भूमिका निभाई बल्कि उन्होंने जापानी आर्थिक गतिविधि को बाहरी दुनिया से जोड़ दिया। 1912 से 1937 के बीच आयात राष्ट्रीय आय का 20% रहे। जापान ने आयात अधिक किया क्योंकि उसे कौशल तथा साधन दोनों की आवश्यकता थी। उसकी क्रय शक्ति भी बढ़ गई थी।

इस अवधि की तीसरी विशेषता आयातों व निर्यातों में समानान्तर वृद्धि की रही। यह भौतिक आकार व मूल्य दोनों ही के बारे में सही था। उतार-चढ़ाव भी आए जैसे प्रथम महायुद्ध में निर्यातों की तेजी ने भारी अतिरेक पैदा कर दिया था। 1910-14 से 1935-38 के बीच आयात ज्यामितिक दर से प्रति वर्ष 5.2% बढ़े। निर्यातों की वृद्धि दर 6.7% रही।

चौथी विशेषता से पता चलता है कि प्रथम महायुद्ध से पहले व उसके दौरान जापान का व्यापारिक इतिहास उसके विरुद्ध ही रहा। 1909 में 1918 के बीच आयात मूल्य निर्देशांक लगभग तिगुने हो गये जबकि उसके निर्यातों के मूल्य 85% ही बढ़े। दूसरे शब्दों में जापान निर्यातों के बढ़ने आयात प्रतिफल शर्तों पर प्राप्त कर रहा था। इसका अर्थ यह भी था कि जापान की बढ़ती हुई तकनीकी कुशलता व निम्न मजदूरी स्तर से एशिया, अमरीका आदि जापानी वस्तुओं के खरीदार लाभान्वित हो रहे थे।

जापान के विकास में विदेश व्यापार की भूमिका

विदेश व्यापार ने जापान की अर्थव्यवस्था को तीन रूपों में प्रभावित किया—

(1) उसने आधुनिक विज्ञान, मशीनी तकनीक तथा व्यावसायिक संगठन को प्रारम्भ करने में सहायता की। बढ़ते हुए आयातों ने पश्चिम के औद्योगिक राष्ट्रों के साथ एक स्थायी सम्पर्क कायम कर दिया। इसके अतिरिक्त जापान के बढ़ते हुए निर्यातों ने अनेक उत्पादक उपक्रमों में विनियोग को प्रोत्साहन दिया। उनमें नये कौशल का बड़े पैमाने के उत्पादन में उपयोग करने पर भी बल दिया। उससे नगरीकरण को भी बढ़ावा मिला। परिवर्तन तथा विकास को प्रोत्साहन देने में भी उसने काफी गतिशील भूमिका निभाई। विदेश व्यापार ने ही जापान की प्राकृतिक साधनों की निर्धनता को दायित्व के स्थान पर परिसम्पत्ति में बदल दिया।

(2) दूसरा योगदान भी पहले योगदान के साथ साथ चला। विश्व बाजार में पहुँच होने के कारण उसे वे वस्तुएँ प्राप्त करने में सुविधा रही जिनका उत्पादन वह स्वयं सस्ती दर पर नहीं कर सकता था। उनका भूगतान निर्यात द्वारा किया जाता था। उदाहरण के लिए, युद्धों के बीच के वर्षों में उपयोग में लाये गये लोहे व इस्पात का 20% से भी कम जापानी कच्चे लोहे से बना था। संक्षेप में विदेश अर्थव्यवस्था ने जापान को विशिष्टीकरण का लाभ निरन्तर बढ़ते हुए पैमाने पर लेने योग्य बनाया। विश्व के किसी भी अन्य देश का इस अवधि के बहुपक्षीय व्यापार से उतसा लाभ नहीं मिला जितना कि जापान को प्राप्त हुआ। बहुपक्षीय व्यापार ने जापान की नई औद्योगिक तकनीक की उत्पादकता को और बढ़ाने में योगदान दिया।

(3) विदेश व्यापार का तीसरा प्रभाव यह रहा कि जापान की अर्थव्यवस्था विश्व के उतार-चढ़ावों से जुड़ गई। यह स्थिर बनाने तथा अस्थिरता प्रदान करने का काम साथ-साथ करता रहा। उदाहरण के लिए, फसल खराब हो जाना कम गम्भीर बन गया क्योंकि चावल बाहर से मँगवाया जा सकता था। दूसरी ओर जब 1929-32 की मन्दी में उसका रेशम बाजार नष्ट हो गया तो जापान को कई अव्यवस्थाओं एवं कुसमायोजनों का सामना करना पड़ा।

व्यापार-शिक्षा के माध्यम के रूप में

मेजी शान्ति, जैसा कि सर जॉर्ज सेसम ने लिखा है, वास्तविक अर्थों में 'एक आन्तरिक विस्फोट' थी। किन्तु जिस तथ्य ने उसे तकनीकी एवं आर्थिक संगठन

के क्षेत्र में क्रान्तिकारी बनाया। वह यही था कि उसने पश्चिम के लिए अपने द्वार खोल दिये थे। पश्चिमी विनिर्माताओं को अब भारी सख्या में देश में आने दिया गया। जापानियों ने ब्रिटिश धातु-विज्ञान एवं वस्त्र-निर्माण, अमरीकी रेल प्रणाली, फ्रान्सीसी कानून, व जर्मन सैनिक विज्ञान का अध्ययन किया। वियना में लगे एक विश्व व्यापार मेले में एक जापानी एम्पोरियम 'साम्राज्य के स्थानीय कार्यों को प्रदर्शित' करने के उद्देश्य से लगाया गया। एक को छोड़कर वे सभी अवसर मेजी शासको द्वारा खूब अच्छी तरह काम में लिये गये। मेजी शासको ने प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग की अनुमति नहीं दी क्योंकि उन्होंने देख लिया कि उसकी एशियाई देशों में अन्तिम परिणति उपनिवेश बनने के रूप में हुई थी। विदेशी उपक्रमों के बारे में इस सशयपूर्ण रवैये में 1900 के बाद ही ढील दी गई। वास्तव में उन दिनों स्वर्णमान भी पश्चिमी पूंजी आकर्षित करने के उद्देश्य से ही अपनाया गया था। युद्धों के बीच के काल में जापानियों ने भारी कर्ज लिये। कुछ विदेशी फर्मों को जापानी फर्मों में स्वामित्व सम्बन्धी अधिकार प्राप्त करने की अनुमति दी गई। जैसे, 1905 में अमरीकी जनरल इलेक्ट्रिक कम्पनी ने जापानी टोक्यो इलेक्ट्रिक लाइट कम्पनी में अपना कुछ हिस्सा रखा। इस प्रकार की व्यवस्थाओं से तकनीकी क्रान्ति की शुरुआत हुई।

किन्तु इस प्रकार की विदेशी भागीदारी का पैमाना सीमित ही रहा। जापान में कुल प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग 1913 व 1933 में क्रमशः 70 व 200 मिलियन येन ही था। सख्यात्मक दृष्टि से यह नगण्य था। जापान तथा एशिया के अन्य देशों के बीच मूल अन्तर यही रहा कि 1868 के बाद जापान ने भारी मात्रा में आयात किये तथा विदेशों में उत्पादित तकनीकों व संस्थाओं को लेकर अपने यहाँ पनपाया। जापानियों ने सीखने की तत्परता दिखाई। युवक बादशाह मेजी ने 1868 में ही घोषित कर दिया था कि 'बुद्धि एवं ज्ञान सारे ससार में खोजा जाएगा ताकि साम्राज्य की नींव मजबूती से स्थापित की जा सके।'

कुछ बहुत कम कीमत वाले आयात बहुत आधारभूत सिद्ध हुए। लेथ मशीन (Lathe Machine) एक ऐसा ही उदाहरण रही। यही हाल छपाई की मशीनों, उन्नत बीजों, कीटाणुनाशक दवाओं, सूखे सेलों (dry cells) तथा गैस इंजिन का रहा। 1889-93 के दौरान मशीनों के आयात का वार्षिक औसत मात्र 6 मिलियन येन रहा। यही औसत 1909-13 में 30 मिलियन येन तथा 1929-33 में 120 मिलियन येन रहा था। किन्तु उन्होंने अर्थ-व्यवस्था का तो कायाकल्प ही कर दिया।

आरम्भिक वर्षों में तो कारखानों की बनी चीजों में घरेलू हस्तशिल्प के बने वस्त्रों आदि को अपनी जगह से पदच्युत कर दिया। किन्तु यह कुछ समय के लिए ही हुआ। जल्द ही हर तरह के विदेशी वस्तुओं की नकल करने के लिए कई छोटे छोटे कारखाने खुल गये। वे साबुन, माचिस, जूते, छाते आदि बनाने लगे। उस समय की एक सरकारी रिपोर्ट में लिखा गया कि 'विदेशी वस्तुओं के पीछे पागलपन हर कहीं दिखाई पड़ता था तथा हर चीज विदेशी वस्तुओं की नकल करके बनायी जाने लगी थी।'

यूरोप तथा अमरीका से आयातों ने, कुछ व्यवसायों के समाप्त हो जाने के बावजूद, देश में नई आवश्यकताओं व तकनीकों को जन्म दिया जो समय के साथ विशाल पैमाने के उद्योगों के रूप में सामने आयीं। इस तरह पुराने व्यवसायों की समाप्ति से हुई हानि की तुलना में इन उद्योगों से नये व्यवसाय स्थापित होने के रूप में होने वाले प्रसारवादी प्रभाव कहीं अधिक थे। यातायात के उपकरणों के तुरन्त आयात के साथ बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए मशीनें मँगवाना जापान के तीव्र विकास में सहायक रहा। 1868 के पहले पहियों पर चलने वाले वाहन जापान में कहीं दिखाई नहीं पड़ते थे। किन्तु दो ही दशकों में वहाँ रेलों का जाल बिछ गया जिनसे बाजार व्यापक बना, श्रम की गतिशीलता बढ़ी तथा नये नगरों का जन्म हुआ।

विदेश यात्रा तथा जापानियों द्वारा अध्ययन ने भी उनके वाद के वर्षों के विकास में सहायता की। पश्चिमी विशेषज्ञों को आधुनिक जापान का सृजनकर्ता कहना तो अतिशयोक्ति होगी परन्तु उस देश के विकास में उनका योगदान किसी भी तरह नगण्य नहीं था। हाल ही के वर्षों में कुछ देशों के उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है कि केवल मशीनों या उपकरणों का आयात कर लेना ही काफी नहीं है। बिना तकनीकी सलाह के, जिसे वि जापानियों ने तत्परता से प्राप्त किया उन मशीनों को जग ही लग सकता है। जापान का अनुपात इस प्रकार की सहायता अधिक न पा सकने की असफलता में नहीं बल्कि ऐसी सहायता के बिना काम चला सकने की गति में रहा है। जैसे, 1895 में जहाज निर्माण करने वाली एक जापानी कंपनी में 224 विदेशी विशेषज्ञ कार्यरत थे। 1920 तक विसी भी जापानी जहाज पर एक भी विदेशी काम पर लगा हुआ नहीं था। यह एक ऐसा युग था जब विकसित देश मशीनें व तकनीक निर्बाध रूप से उपलब्ध कराते थे। इसीलिए जापानी लोग, जहाँ कहीं भी जरूरत पड़ी, श्रेष्ठ पश्चिमी तकनीक प्राप्त करने में सफल हो पाये।

निर्यातों की प्रगति

अविव सकारात्मक रूप से, विदेश व्यापार तकनीकी परिवर्तनों को सक्रिय भी कर सकता है। क्योंकि बढ़ते हुए निर्यात नई आय व नये रोजगार का सृजन करते हैं। वे प्रभावित उद्योगों में आधुनिक विज्ञान, मशीनों तथा कौशल को प्रोत्साहित भी कर सकते हैं, और यही वास्तव में मेजो जापान में हुआ। चूँकि निर्यात उन आयातों के भुगतान के लिए आवश्यक थे, जिन्हें राष्ट्रीय प्रतिरक्षा एवं विकास के लिये किया जा रहा था, इसलिए उनकी वृद्धि राज्य नीति का एक अंग बन गयी तथा सरकार ने उन्हें भारी प्रोत्साहन दिया। विश्व की कुल माँग में इसी अवधि में आयी तीव्रता का भी जापान के औद्योगीकरण पर काफी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। 1858 में जापानी बन्दरगाहों को विदेश व्यापार के लिए खोल दिये जाने के बाद उसके नियति व्यापार में जो प्रसार आरम्भ हुआ वह आज तक कायम है। सम्पूर्ण मेजो काल के प्रत्येक दशक में (1868-1911) विदेशों से आने व वहाँ जाने वाले साज-सामान दुगुने होते चले गये। 1900 तक वे 200 मिलियन येन की सीमा पार कर चुके थे।

आरम्भिक वर्षों में ये निर्यात प्रमुख रूप से खाद्य पदार्थों व कच्चे मालों के थे। सबसे बड़ी मद कच्चा रेशम था जिसका निर्यात में प्रतिशत 40 के लगभग था। जापान के बन्दरगाह जब सबसे पहले विदेश व्यापार के लिए खोले गये तो चाय, ताबा या रेशम के साधारण से निर्यातों से भी देश में उनका अभाव हो जाता था। इसमें उनके मूल्य बढ़ जाते थे। पूर्ति काफी बेल्कोचदार थी। सर्वप्रथम बाजारों को व्यापक बनाने की आवश्यकता थी। इसका परिणाम यह हुआ कि उत्पादन में प्रसार एवं सुधार हुए। विदेशी व्यापार के खुल जाने के बाद कच्चा रेशम उद्योग एक परम्परागत उद्योग से बड़े पैमाने के उद्योग के रूप में रूपान्तरित हो जाने का एक ज्वलन्त उदाहरण है। 150 से भी अधिक वर्षों तक 65% से लेकर 80% कच्चा रेशम (कुल उत्पादन का) निर्यात किया जाता रहा था।

रेशम के विपरीत आरम्भिक वर्षों में जापान द्वारा उत्पादित पश्चिमी देशों की कारखाना प्रणाली पर आधारित वस्तुएँ केवल घरेलू बाजार के लिए थीं। इनमें जहाज, मशीनें, वागज, सूत, मीमेट आदि चीजे सम्मिलित थीं। 1900 से 1913 के बीच सूती वस्त्र के निर्यात तिगुने हो गये। इसके बाद सस्ती विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात शुरू हुआ जिसका परिमाण बढ़ता ही गया। वे विदेशों को भेजी जाने वाली वस्तुओं में बढ़ते-बढ़ते 60% हो गये। जहाँ तक विकास की दर का प्रश्न है दोनों महायुद्धों के बीच के काल में जापानी निर्यातों की वृद्धि दर तत्कालीन औद्योगिक पश्चिमी राष्ट्रों की तुलना में बहुत आगे रही। वास्तव में 1901-05 से 1931-35 की अवधि में विश्व निर्यातों के भौतिक परिमाण (physical volume) में केवल 20% की ही वृद्धि हुई थी। इसकी तुलना में जापान के निर्यात परिमाण में 600% बढ़े।

सामान्य धारणा के विपरीत, युद्ध से पहले का जापान विदेशी बाजारों पर उससे कहीं कम निर्भर रहा जितना कि उसके बारे में सोचा जाता है। 1910 तक उसकी यह निर्भरता 15% तक पहुँची थी। साधारणतया जापान के निर्यातों का उसकी राष्ट्रीय आय के साथ अनुपात 1 : 5 रहा। किन्तु यह अवश्य कहा जा सकता है कि यह अनुपात अमरीका व ब्रिटेन की तुलना में तीन गुना था। 1930, 1936 व 1938 में जापान को निर्यातों से प्राप्त हुई कुल प्राप्तियों की तुलना उसके विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (NNP) से की जा सकती है¹—

(मिलियन येन में)

	1930	1936	1938
शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद	10 224	15,779	20,682
शुद्ध निर्यात प्राप्तियाँ	1 371	2,427	3,043
शुद्ध निर्यात प्राप्तियाँ—राष्ट्रीय उत्पाद (प्रतिशत)	13.4	15.4	14.7

¹ Ibid, 344

1927-36 की अवधि में राष्ट्रीय उत्पाद का लगभग 15% भाग साधारण-तया विदेशी बाजारों को निर्यात किया जाता रहा। विदेशी बाजारों पर जापान की निर्भरता की सीमा तथा स्वरूप का स्पष्ट अनुमान वस्तु उत्पादन के साथ निर्यातों की तुलना द्वारा लगाया जा सकता है। प्राथमिक उद्योगों (primary industries) में घरेलू बाजार का प्रभुत्व बना रहा—

(i) कृषि—1928-36 की अवधि में जापान के कुल निर्यातों में खाद्य पदार्थों का भाग केवल 7% ही रहा। जापानी कृषि की दो सर्वप्रमुख निर्यात मदें रेशम व चाय थी। बाद में रेशम का निर्यात चाय के मुकाबले कहीं अधिक हो गया।

(ii) मछली उत्पाद—जापान विश्व के प्रमुख मछली उत्पादक राष्ट्रों में से है। द्वितीय महायुद्ध से पहले उसका मछली उत्पादन अमरीका के मुकाबले दुगुना था। वह विश्व के कुल मछली उत्पादन का पाँचवा भाग था। युद्ध से पहले 90% से अधिक मछली उत्पादन घरेलू उपभोग के काम आता था। प्रथम महायुद्ध के बाद डिब्बा-बंदी तथा अवशीतन (canning and refrigeration) ने मछली उत्पादनों को काफी बढ़ावा दिया। वह निर्यात भाग ही थी जिसके कारण मछली पकड़ने के लिए अलग जहाज (fishing vessels) तथा अवशीतन जहाज (refrigerator ships) बनाये गये। कुछ किस्म की मछलियों के उत्पादन का तो 90% निर्यात किया जाने लगा। किन्तु कुल मिलाकर 1930 के दशक में, जब मछली निर्यात अपने चरम बिन्दु पर था, उसमें कुल उत्पादन का 10% भाग काम आ रहा था।

(iii) खनन—खनन के जापान के आरम्भिक विकास में निर्यात प्रमुख महत्त्व के रहे। 1913 के बाद औद्योगिक खनिजों के लिए जापान की अपनी आवश्यकताएँ ही इतनी बढ़ चुकी थी कि उनके निर्यात अपने आप ही कम हो गये। कोयले के निर्यात तो महायुद्धों के बीच के वर्षों में बन्द ही हो गये। तंबाकू का अवश्य निर्यात-धातु के रूप में विकास हुआ। प्रथम महायुद्ध से पहले वह अपने तंबाकू-उत्पादन का 60% निर्यात करता था, किन्तु 1936 तक यह प्रतिशत घटकर 20 पर आ गया।

(iv) विनिर्मित माल का निर्यात—विनिर्मित माल के क्षेत्र में ही विश्व बाजार जापान के लिए सर्वाधिक महत्त्व का रहा है। कभी-कभी मेजी काल के बाद जापानी उद्योगों में हुए विकास का एकमात्र कारण उनकी वस्तुओं के लिए उत्तम विदेशी मांग को ही बताया जाता है। किन्तु यह धारणा सही नहीं है। 1928-37 के बीच जापान के कुल विनिर्मित माल उत्पादन का 25 से लेकर 35% भाग निर्यात किया गया। यह तम समय के किमी. भी अन्य औद्योगिक राष्ट्र, जैसे, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, सम्मिलित है, के मुकाबले अधिक ऊँचा प्रतिशत था। अन्तिम एवं प्रामाणिक रूप से इस स्थिति का पता लगाने के लिए विनिर्मित माल के उत्पादन निर्देशांक की निर्यात के लिए प्रयुक्त विनिर्मित माल के निर्देशांक के साथ (नामोया निर्देशांक) तुलना की जा सकती है—

आश्चर्य की बात है कि प्रथम महायुद्ध के पहले तक विनिर्मित माल की उत्पादन वृद्धि दर उनके निर्यातों की वृद्धि दर से ऊँची रही। स्पष्ट है कि विनिर्मित माल का अधिकांश भाग बढ़ती हुई घरेलू मांग को पूरा करने में खप गया। विदेश

व्यापार के लिए प्रयुक्त विनिर्मित माल और घरेलू माग के लिए प्रयुक्त विनिर्मित माल की वृद्धि दर एक सी रही।

	विनिर्मित माल उत्पादन	विनिर्मित माल का विदेशी को निर्यात
1905-1909	69	61
1910-1914	100	100
1915-1919	160	173
1920-1924	217	157
1925-1929	313	252
1930-1934	377	326

औद्योगिक तकनीक व निर्यात

निर्यातों का एक प्रत्यक्ष योगदान तो यही रहा कि उन्होंने मशीनों, खाद्यान्नों व कच्चे मालों के भुगतान के लिए राशि जुटाई। 1870 से 1930 के बीच किये गए कुल आयातों का एक-तिहाई भुगतान तो केवल रेशम के निर्यातों से हो गया। दूसरे, निर्यात व्यापार में ही जापानी व्यावसायियों को नए उपक्रम आरम्भ करने के अत्यधिक लाभकारी अवसर प्राप्त हुए। तीसरे, निर्यात व्यापार में लगे हुए विभिन्न उद्योगों की उत्पादन गतिविधियों में वृद्धि से विशाल पैमाने के विपणन, उत्पादन तथा वित्त की मितव्ययिताएँ भी प्राप्त होने लगी। अधिकांश निर्यात मर्दे ऐसे उद्योगों द्वारा निर्मित की जाती थी जिनके लिए भारी मात्रा में घरेलू माग भी थी। यह बात रेशम सूती वस्त्र, रेयन, चीनी व कागज जैसे उद्योगों के लिए सही थी। मुख्य जापानी निर्यातों में ऐसे पदार्थ भी थे। जिनमें कारखानों का सर्वोत्तम आकार (optimum size) मध्यम या लघु पैमाने का था।

निर्यात व्यापार के कुछ अन्य प्रभाव निम्न रहे—

(1) निर्यात व्यापार ने न केवल कुछ उद्योगों को बहुत बड़ा बनाया बल्कि उसने जापान के कुछ महान् शहरों में उत्पादन का क्षेत्रीय सकेन्द्रण भी कर दिया। 1938 तक तीन महान् औद्योगिक केन्द्र टोक्यो ओसाका व नागोया में जापान की कुल श्रम शक्ति का 30% लगा था तथा वे देश के कुल कारखाना उत्पादन का 33% भाग निमित्त कर रहे थे।

(2) निर्यातों के कारण विभिन्न वस्तुओं का समानीकरण भी हुआ। कई उद्योगों में विदेशी माग ने अधिक एकस्य एच स्टैंडर्ड डिजाइनों वाली चीजों के उत्पादन को बढ़ावा दिया। घरेलू बाजार के लिए उत्पादित वस्तुओं के उत्पादन में इतनी एकरूपता आवश्यक नहीं थी।

इस तरह जापान के आर्थिक विकास में वहाँ के निर्यात बाजार की भूमिका को निम्न रूपों में देखा जा सकता है—

(1) आवश्यक आयातों का भुगतान निर्यातों ने किया। (2) उन्होंने आय वृद्धि की गत्यात्मकता तथा पूँजी-निर्माण में योगदान दिया, तथा (3) उन्होंने तकनीकी प्रगति को (अ) नए सम्पर्क व अवसर प्रदान करके, व (आ) कुछ प्रमुख

उद्योगों में उत्पादन का पैमाना बढ़ाकर, प्रोत्साहित किया। किन्तु जैसा कि पहले भी लिखा जा चुका है, इस अन्तिम बिन्दु पर आवश्यकता से अधिक बल नहीं दिया जाना चाहिए।¹

यह आधुनिक युग की एक दुःखातिका ही है कि अत्यधिक आर्थिक निर्भरता राष्ट्रीय असुरक्षा को जन्म देती है। जापानियों का इस बारे में चिन्तित रहना स्वाभाविक ही था। अपने आर्थिक प्रसार के चरम बिन्दु पर पहुँचने के बाद भी वे पूर्वी एशिया में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए शायद एक तरह से बाध्य ही हुए। यह विडम्बना ही कही जानी चाहिये कि साम्राज्य स्थापना की इस चेष्टा का मूलधार आर्थिक कारण रहे। वास्तविकता यह थी कि 1930 के बाद आर्थिक राष्ट्रीयवाद को बढ़ावा मिलने के कारण जापान के आर्थिक प्रसार पर ब्रेक लग गये थे तथा उसका भविष्य थोड़ा अन्धकारमय होने लगा था।

विदेश व्यापार 1934-1962

	निर्यात			आयात		
	1934-36	1953	1962	1934-36	1953	1962
कुल मूल्य (मिलियन डॉलर में)	936	1,275	4,916	980	2,410	5,637
निर्भरता अनुपात (Dependency Ratio) राष्ट्रीय उत्पाद का %	20.0	6.7	9.2	20.5	12.7	8.8

द्वितीय महायुद्ध के बाद का विदेश व्यापार

उपर्युक्त तालिका यह स्पष्ट करती है कि विदेश व्यापार पर जापान की प्रतिशत निर्भरता द्वितीय महायुद्ध के बाद बराबर घटती जा रही है। युद्ध के तुरन्त बाद अर्थात् अमरीकी आधिपत्य के बाल में जापान का विदेश व्यापार युद्ध पूर्व के मुकाबले बहुत नीचे स्तर पर था। उसकी औद्योगिक क्षमता तथा उसका जहाजी बड़ा दोनों ही दूसरे महायुद्ध में नष्ट हो चुके थे। इन तत्त्वों ने जापान की निर्यात क्षमता को भी एकदम सीमित कर दिया था। किन्तु 1950 के कोरियाई युद्ध ने स्थिति को वापस बदल दिया। इस युद्ध के कारण जापान भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित करने की स्थिति में पहुँच गया। 1951 में जापान के निर्यात 1949 की तुलना में 165% अधिक थे। आयातों में भी वृद्धि हुई। विदेशी माँग के बढ़ जाने के कारण निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के घरेलू मूल्य भी काफी बढ़ गए। इस आन्तरिक स्थिति ने पुनः एक बार अस्थायी तौर पर उसके निर्यातों को सीमित कर दिया।

1953 के बाद निर्यात सबर्द्धन के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपायों की घोषणा की गई—(1) आन्तरिक मूल्य स्तर को विश्व मूल्य स्तर के समक्ष लाने के लिए

एक भुद्रा सकुचन की नीति तैयार की गई। (2) आयात ताडसेन्स केवल उन्ही फर्मों को जारी किये गये जो निर्यात के लिए विनिर्मित वस्तुएँ बनाती थी। ये दोनों उपाय सफल रहे तथा 1955 तक जापान के निर्यात असाधारण रूप में बढ़ गये। किन्तु अभी तक भी युद्ध-पूर्व का निर्यात स्तर प्राप्त नहीं किया जा सका था। इस बारे में बिलम्ब कई कारणों से हो रहा था। युद्ध के तुरन्त बाद जापान अपने अधिकांश समाधन देश के पुनर्निर्माण में लगाने के लिए बाध्य हो गया था। अमरीकी आधिपत्य वाली सैनिक सरकार द्वारा किये गये भारी खर्च से देश में स्थिति पंदा हो गई जिसने जापानी निर्यातों को अपेक्षाकृत महँगा बना दिया। जैबत्सु के उन्मूलन कर दिये जाने से भी जापान की व्यावसायिक क्षमता पर करारा आघात हुआ। रेसम के स्थान पर रेयन के उपयोग के बढ़ जाने से भी जापानी निर्यातों पर अत्यधिक विपरीत प्रभाव पड़ा।

किन्तु 1960 के बाद से निर्यातों में जो वृद्धि शुरू हुई है वह निरन्तर जारी है। 1960 तक जापान के पूँजीगत वस्तुओं के निर्यात में 70% की वृद्धि हुई थी। 1951 से 1961 के बीच जापान के निर्यात व आयात क्रमशः 147% तथा 131% की वार्षिक दर से बढ़े। इस बीच उसका राष्ट्रीय उत्पाद 97% की दर से बढ़ा।

जापानी आयातों व निर्यातों में वृद्धि : 1956-1969

(इकाई : मिलियन डॉलर)

वर्ष	निर्यात	आयात
1956	2,501	3,229
1958	2,877	3,033
1960	4,055	4,491
1962	4,916	5,637
1969	15,990	15,024

जापान के वर्तमान विदेश व्यापार में निर्यात एवं निर्यातों के रूप में सबसे पहला स्थान अमरीका का है। 1969 में जापान के कुल निर्यातों का 31% अकेले अमरीका को भेजा गया। पिछले कुछ वर्षों में जापान ने अनेक तटकर हटाकर अपने आयातों को भी अधिक उदार बनाया है।

1970 के बाद जापान के निर्यातों में वृद्धि विस्मयकारी रही है। 1970 से 1979 के बीच उनमें 12 से 15% की वार्षिक (औसत) वृद्धि होती रही है। केवल 1973 व 1974 के वर्ष इस बारे में अपवाद रहे हैं जब तेल मूल्यों की आकस्मिक वृद्धि ने जापानी आयात विल में भारी वृद्धि कर दी थी तथा उसके निर्यातों की लागत को भी काफी बढ़ा दिया था। जापान द्वारा अमरीका को किये जाने वाले निर्यातों तो 1970-79 के वर्षों में इस तेजी से बढ़े हैं कि 3 अक्टूबर 1978 को अमरीकी सरकार ने एक चेतावनी जारी की कि यदि जापान ने अमरीका से अपने निर्यातों के बराबर वस्तुओं का आयात नहीं किया तो अमरीका जापान से आने वाली वस्तुओं पर प्रतिबन्ध लगा देगा।

द्वितीय महायुद्ध के बाद असाधारण प्रगति (EXPLOSIVE GROWTH AFTER SECOND WORLD WAR)

जापान के आधुनिकीकरण की प्रथम शताब्दी, जिस तरह वह शुरू हुई थी, अब व्यावहारिक ऊर्जा के बिम्फोट के साथ समाप्त होती है। फिर एक बार, 1868 की ही तरह, जापानी नेता बाहरी विश्व की ओर टकटकी लगाये देख रहे हैं जहाँ उनके लिए भय भी है और भविष्य भी। पुनः एक बार देश में एक नवीन औद्योगिक क्रान्ति तीव्र हो रही है जिसमें निजी एवं सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्र सक्रिय हैं।¹

असाधारण विकास दर (High Pitched Growth)

अमरीकी आधिपत्य के वर्षों में जापान ने पराजय तथा बरबादी से निकलने के लिए पूरी चेष्टा की। जब 1952 में मित्र-राष्ट्रों ने जापान पर अपना सैनिक अधिकार त्यागा तो जापानी अर्थव्यवस्था अपने युद्ध-पूर्व के स्तर पर पहुँच चुकी थी। उसके बाद से वह जिस गति से आगे बढ़ी है उसकी समानता तो युद्ध-पूर्व के वर्षों में नहीं मिलती। 1951 से 1963 के बीच जापान का वास्तविक राष्ट्रीय उत्पाद तिगुना हो चुका था तथा उसमें 9% से अधिक वार्षिक वृद्धि हो रही थी। इस अवधि में प्रति व्यक्ति आय भी 8% प्रति वर्ष के हिसाब से बढ़ रही थी।

जापान के आर्थिक विकास के निर्देशांक (1934-36=100)

वर्ष	वास्तविक राष्ट्रीय आय	बिछले वर्ष पर % वृद्धि
1951	107	—
1952	118	9.8
1953	124	5.8
1954	129	2.8
1955	142	11.4
1956	156	9.7
1957	167	7.2
1958	176	5.0
1959	204	16.3
1960	236	15.6
1961	264	11.8
1962	286	8.5
1963	315	10.0

सर्वाधिक प्रगति विनिर्माण उद्योगों में हुई। उनके उत्पादन का परिमाण 1951 से 1963 के बीच चौगुना हो गया। सेवाओं का राष्ट्रीय आय में 50% योगदान रहा। केवल कृषि व वन-सम्पदा का प्रतिशत घटा। ये दोनों किसी जमाने में आधी राष्ट्रीय आय का स्रोत थे किन्तु अब वे घट कर 15% आय का स्रोत रह गये। 1951 से 1963 के बीच जापान ने असाधारण प्रगति की। अब जापान उन देशों की पंक्ति में आ गया है जहाँ आम आदमी के लिए गरीबी समाप्त हो चुकी है। इस रूप में अब उसकी औद्योगिक क्रान्ति वयस्क हो चली है।

जनसंख्या, समग्र राष्ट्रीय उत्पाद (G N P) और प्रति व्यक्ति उत्पाद : 1973-1975

	1973	1974	1975
जनसंख्या ('000)	7,95,920	8,09,251	8,22,800
राष्ट्रीय उत्पाद (G N P) (अमरीकी मिलियन डॉलर)	4,11,260	4,46,030	4,95,180
प्रति व्यक्ति उत्पाद (अमरीकी डॉलर में)	3,800	4,070	4,460

चुने हुए कुछ देशों की जनसंख्या व प्रति व्यक्ति आय में वार्षिक वृद्धि : 1965-1974

देश	जनसंख्या वृद्धि (%)	प्रति व्यक्ति आय (%)
साल चीन	17	—
भारत	23	32
जापान	12	85
सोवियत रूस	10	—
अमरीका	10	24
इंग्लैण्ड	04	22
फ्रांस	08	48
प० जर्मनी	06	39

उपर्युक्त आँकड़े अपनी बात स्वयं बोलने हैं। जापान की प्रति व्यक्ति आय उसके समग्र राष्ट्रीय उत्पाद के साथ निरन्तर बढ़ती जा रही है। उसकी 1.2% की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर काफी सन्तुलित एवं नियन्त्रित है। राष्ट्रीय उत्पाद में जापान की वृद्धि-दर समार में सर्वाधिक है। 1978 के एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जापानी वित्त-मन्त्री ने कहा था कि वे 6% की वार्षिक वृद्धि दर को जापान में बहुत नीची मानते हैं।

प्रमुख क्षेत्रों के प्रति व्यक्ति आय तथा
कुल राष्ट्रीय उत्पाद : 1974

प्रदेश या देश	प्रति व्यक्ति आय (अमरीकी डॉलर में)	कुल राष्ट्रीय उत्पाद (G N P) (अमरीकी '000 मिलियन डॉलर)
उत्तरी अमरीका	6,630	1,553
ओशेनिया (Oceania)	4,110	88
जापान	4,070	446
यूरोप	3,580	1,829
सोवियत रूस	2,380	599
मध्य पूर्व	1,480	116
मध्य अमरीका	960	98
दक्षिणी अमरीका	950	198
अफ्रीका	370	148
एशिया	230	461

वैषम्य पुन स्पष्ट रूप में देखा जा सकता है। अकेले जापान का समग्र राष्ट्रीय उत्पाद (G N P) सम्पूर्ण एशियाई देशों के राष्ट्रीय उत्पाद से भी अधिक है। इसी तरह उसकी प्रति व्यक्ति आय भी यूरोप के देशों से भी अधिक है।

चुने हुए देशों की प्रति व्यक्ति आय, : 1975

(अमरीकी डॉलर में)

साउ चीन	350
भारत	150
जापान	4 460
द्वाराइल	3,580
कुवैत	11,510
सोवियत रूस	2,620
य० अर्जेंटी	6,610
इस्रैल	3,840
फ्रांस	5,760
स्वीडन	7,880
अमरीका	7,060
कनाडा	6,650
श्रीलंका	1,010
ऑस्ट्रेलिया	5,640
दक्षिण अफ्रीका	180

उपभोग में क्रान्ति

स्वयं जापानी अब उपभोग क्रान्ति के बारे में बात करने लगे हैं। 1951 से 1963 के बीच जापान में उपभोग दुगुना हो चुका था। 1979 में जापान का उपभोग-स्तर 1951 के मुकाबले पाँच गुने से भी अधिक हो चुका है। उपभोग में इस वृद्धि में सभी वर्गों को लाभ मिला है। युद्ध के बाद श्रमिकों की आय में तेजी से वृद्धि हुई है। इससे श्रमिकों का उपभोग-स्तर काफी सुधर चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी उपभोग में काफी सुधार आया है। इन घटनाओं ने जापान की 'दुमजिली' (Double Decker) अर्थव्यवस्था में आर्थिक असमानताओं को कम कर दिया है। सफेदपोश कर्मचारियों की तुलना में किसानों व मजदूरों का प्रतिशत उपभोग अधिक तेजी से बढ़ा है।

उपभोग की इस तेजी (consumption boom) के साथ उत्पादन के ढाँचे व तकनीक में क्रान्तिकारी नवप्रवर्तन (innovations) भी हुए हैं। एक ओर 1955 के बाद से निरन्तर बढ़ती हुई उत्पादकता के कारण अनेक नयी वस्तुएँ तथा सेवाएँ प्राप्त हो रही हैं तो दूसरी ओर उपभोग में वृद्धि के कारण समग्र माँग में होने वाली वृद्धि ने विनियोग स्तर को आगे बढ़ाने में सहायता की है। टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में हुई वृद्धि विशेष ध्यान देने योग्य है। कुल औद्योगिक उत्पादन में हुई वृद्धि में उनका भाग एक-तिहाई है। कृषि में भी बाजार बढ़ने के साथ कृषक लोग बड़े पैमाने के तथा अधिकाधिक पूँजी-प्रधान उत्पादन तरीकों को अपना रहे हैं।

उपभोग में वृद्धि के कई सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी पड़े हैं। बढ़ती हुई आय तथा अधिक आर्थिक सुरक्षा के वातावरण से नई व्यावसायिक गतिशीलता एवं भविष्य के प्रति विश्वास जगें हैं। प्रत्येक चार में से तीन जापानी परिवार अब अपने आपको मध्यवर्गीय आय वाले परिवार मानते हैं।

औद्योगिक शक्ति

जापान अब एक समयें औद्योगिक महाशक्ति बन गया है। उसकी मजदूरी दरें तथा वास्तविक आमदनियाँ यूरोप के देशों से आगे निकल गई हैं। छोटे उत्पादकों पर यह दबाव बढ़ता जा रहा है कि या तो वे अपनी कार्यकुशलता बढ़ाएँ या फिर व्यवसाय से निकल जाएँ। आज उसके विनिर्माण उद्योग इटली, फ्रांस, इंग्लैंड या पश्चिमी जर्मनी विनिर्माण उद्योगों से अधिक उत्पादन कर रहे हैं। अब जापान के आगे केवल दो ही विशालकाय राष्ट्र—अमरीका व सोवियत संघ—रह गये हैं। अब जापान दुनिया की औद्योगिक महाशक्तियों में तीसरे स्थान पर है।

विस्फोटात्मक प्रगति के प्रमुख कारण

(1) राजनीतिक अवसर—प्रमुख कारण राजनीति से सम्बन्ध रखता है जो अर्थशास्त्रियों द्वारा आमतौर पर बनाये गये विकास मॉडलों में सम्मिलित नहीं होता। सर्वप्रथम, मित्र-राष्ट्रों के आधिपत्य (1945-52) के दौरान जापान में एक उदार

एवं एकीकृत राजनीतिक सत्ता की स्थापना को प्रोत्साहन दिया गया। दूसरे, अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों ने भी जापान के पुनरुद्धार में सहायता की। विजयी मित्र-राष्ट्रों द्वारा युद्ध के बाद भारी मात्रा में एव उदार आर्थिक सहायता ने जापान के पुनर्निर्माण में सहायता की। उसके बाद से ही आज तक जापान शान्ति-क्षेत्र बना रहा है तथा बिना शस्त्रार्थ पर व्यय किये वह अमरीकी सुरक्षा छाते के नीचे सुरक्षित है। इस पृष्ठभूमि में जापान उस औद्योगिक विकास में भागीदार बन पाया है जो द्वितीय महायुद्ध के बाद लगभग सभी औद्योगिक राष्ट्रों में देखने में आया है।

(2) उत्पादकता एवं मजदूरी में वृद्धि—1935 से 1950 तक जापान का सम्पर्क आधुनिकतम औद्योगिक तकनीकों से कटा रहा। परन्तु शान्ति एवं व्यापार की पुनर्स्थापना के बाद उसने अपनी अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए पुन पश्चिम से तकनीक का आयात किया। तकनीक उधार लेना जापानियों के लिए कोई नयी बात नहीं थी। विदेशी कम्पनियों को जापानी कम्पनियों में भागीदारी की अनुमति दी गयी जिसने जापानी उद्योगों की उत्पादक व प्रतिस्पर्द्धात्मक क्षमता में पर्याप्त वृद्धि कर दी।

देश के भीतर भी औद्योगिक अनुसन्धान को बढ़ावा दिया गया। 1955 के बाद अनुसन्धान पर किये जा रहे व्यावसायिक कम्पनियों के खर्च निरन्तर बढ़ते जा रहे हैं। प्रमुख प्रतिष्ठानों में तो ये खर्च अब अमरीकियों द्वारा किये जा रहे खर्च से कम नहीं हैं। इस तरह आर्थिक विकास की कुजी श्रम की उत्पादकता में होने वाली निरन्तर वृद्धि में ही निहित रही है। 1961 तक समाप्त हुए दशक में उत्पादकता 7.5% वार्षिक से बढ़ रही थी। कृषि में भी उत्पादकता वृद्धि के कारण लगभग आत्म-निर्भरता की स्थिति आ चुकी है। उत्पादकता में इस वृद्धि के साथ ही औद्योगिक मजदूरी में द्वितीय महायुद्ध के बाद बराबर वृद्धि हो रही है। 1979 में जापान के उद्योगों पर 'शोपित उद्योग' (sweated industries) होने का आरोप नहीं लगाया जा सकता। रोजगार के क्षेत्र में भी चहुँमुखी प्रगति हुई है। वास्तव में कुछ क्षेत्रों में तो श्रमिकों का अभाव देखने में आ रहा है।

(3) विनियोगों का ज्वार (Tied of Investment)—1951-55 के बीच कुल विनियोग राष्ट्रीय उत्पाद का 27.3% तथा 1956-60 में वे 31.8% पहुँच गये थे। व्यापार की उदार बनाने तथा सरकार द्वारा आय दुगुनी करने की योजना से प्रोत्साहित होकर 1961-63 की अवधि में तो विनियोग 40% के स्तर तक जा पहुँचे थे। 1953 से 1965 तक जापान में कुल विनियोग दर का औसत 32.1% रहा। यह विनियोग की दर सप्तर के किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक ऊँची तथा जापान की अर्थव्यवस्था की असाधारण प्रगति का एक प्रमुख कारण रही। इसके अलावा शान्तिकालीन अर्थव्यवस्था में विनियोग की इतनी ऊँची दर अद्वितीय ही कही जायेगी विशेष रूप से जहाँ अर्थव्यवस्था में किसी प्रकार के दबाव काम में न लिये जा रहे हों।

विनियोग की दर : 1953-65

कुल राष्ट्रीय उत्पाद का प्रतिशत

देश	कुल स्थिर विनियोग
बेल्जियम	18.3
कनाडा	23.4
फ्रान्स	18.9
यू.एस.ए.	23.3
इटली	21.1
जापान	28.3*
नेदरलैंड्स	23.4
स्वीडन	21.6
इंग्लैंड	15.7
अमरीका	17.9
सोवियत रूस	24.0

* इसमें माल तालिकाएँ (Inventories) सम्मिलित नहीं हैं।

जापानी विनियोग की एक अन्य प्रमुख विशेषता यह रही कि इसमें से बहुत कम भाग भवन-निर्माण पर लगाया गया। ऐसा प्रमुख रूप से जापानी मकानों के कम लागत पर निर्मित होने के कारण हुआ। इससे जापान को भारी बचत रही जब कि अन्य देश आवास पर इसी अवधि में भारी रकमें खर्च कर रहे थे। इसके अलावा सिर्फ विनियोग दर ऊँची होने मात्र से पूँजी-निर्माण के आर्थिक विकास में योगदान का पूरा अनुमान नहीं लगाया जा सकता। ऐसा इसलिए है कि इस प्रकार के विनियोग का एक भाग तो पुरानी मशीनों को बदलने में लग जाता है तथा उससे नई मशीनों आदि में कोई बढोत्तरी नहीं होती। पूँजी स्टॉक के अनुमान बड़े कठिन होते हैं। एक मोटे अनुमान से पता चलता है कि जापान में पूँजी स्टॉक की वृद्धि अन्य देशों की तुलना में बहुत अधिक तेज रही है। वह अमरीका से तीन गुना तथा सोवियत रूस से भी तीव्र रही है।

एक कारण¹ जिसकी वजह से जापान अपनी विनियोग दर को इतना बढ़ा देने के बावजूद घटते हुए प्रतिफल के प्रभावों से बचा रह सका है उसमें अन्य देशों की तुलना में रोजगार का अत्यधिक तेजी से बढ़ना है। ऐसा विशेष रूप से गैर-कृषि क्षेत्र में हुआ है। जब पूँजी स्टॉक को अतिरिक्त श्रमिकों को उपकरण आदि उपलब्ध कराने के लिए बढ़ाया जाता है तो उससे साधन अनुपात (factor proportions) नहीं बदलते। इसीलिये वहाँ घटते हुए प्रतिफल नहीं दिखाई दिये हैं।

(4) सार्वजनिक एवं निजी बचत का उच्च स्तर—यह भी आश्चर्यजनक ही कहलायेगा कि अधिकांश विनियोग सार्वजनिक बचत द्वारा किये गये हैं। मालोसाल करो की दर घटाने के बावजूद सरकार के खालू खाते में अतिरिक्त बढ़ता रहा है। 1950 से 1960 के बीच कर प्राप्ति में तिगुनी हो चुकी थी। केवल इसी स्रोत से देश को 21% बचत प्राप्त हुई। बहुत सम्भव है कि करो में इन वटीतियों ने ही

¹ A Maddison, *op cit*, 59

शायद वहाँ कर प्राप्तियों को बढ़ाया है।

सरकार की इस सक्रिय भूमिका के साथ-साथ नई पूँजी के स्रोत मुख्यतः निजी रहे हैं। यहाँ तक कि विदेशी पूँजी की आवक भी कम हो रही है। बड़े प्रतिष्ठानों के उपकरणों में केवल 10% विदेशों से प्राप्त किये गये हैं। अमरीकी आधिपत्य के समाप्त होने के बाद से ही जापान ने अपने विकास के लिए वित्त की व्यवस्था स्वयं ही की है। पिछले कुछ वर्षों में व्यक्तिगत बचतों से कुल राष्ट्रीय बचतों का 40% प्राप्ति होता रहा है। ये व्यक्तिगत बचतें 1956 में कुल निकृत्त आय का 14.6% थीं जो 1962 तक बढ़कर 21.4% हो चुकी थी। यह वृद्धि उपभोग में हुई भारी बढ़ोतरी के बावजूद हुई है। विनियोग व्यास कई स्थानों पर गठित किये जा चुके हैं। बड़ी संख्या में परिवारों के पास कम्पनियों के शेयर हैं। लोगों के पास इस तरह शेयरों के बढ़ने को कुछ टीकाकारों ने 'नये जन-पूँजीवाद' का नाम दिया है। व्यावसायिक बैंकों ने भी सफलतापूर्वक बचत व संचय का विनियोगों के लिए भारी मात्रा में गतिशीलता किया है।

(5) आय दोहरा करने (Doubling the income plan) की योजना—1960 में आर्थिक नियोजन एजेंसी ने एक दीर्घकालीन योजना बनायी जिसका उद्देश्य 1960-70 के दशक में 7.2% की विकास दर प्राप्त करना था। आय दुगुना करने की यह योजना न केवल सफल हुई बल्कि इस योजना की सफलता ने भावी आय-वृद्धियों का भी रास्ता आसान बना दिया। यदि अब 1985 तक जापान का कुल राष्ट्रीय उत्पाद (G N P) सोवियत रूस के मुकाबले अधिक हो जाये तो आश्चर्य नहीं होगा।

सतत आर्थिक विकास सार्वजनिक नीति के कई क्षेत्रों में किये गये उपायों पर निर्भर करता है। इनमें पहला स्थान विदेश व्यापार के अवसरों में वृद्धि का तथा दूसरा घरेलू औद्योगिक प्रतिष्ठानों की क्षमता बढ़ाने का है। ये दोनों एक दूसरे के साथ क्रिया-प्रतिक्रिया करते हैं तथा एक-दूसरे के तत्त्व पर निर्भर करते हैं और वह तत्त्व है राजनीतिक स्थायित्व।

(6) विदेश व्यापार—जापान की युद्धोत्तरकालीन प्रगति में अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में उसका पुनः प्रवेश, वह भी पूरी तरह बरबाद हो चुकने के दस वर्षों से भी कम समय में, प्रमुख तत्त्व रहा है। 1951 से 1963 तक जापान के निर्यात विश्व निर्यातों की तुलना में तीन गुना अधिक तेजी से बढ़े।

तुलनात्मक निर्यात उपलब्धियाँ

(वार्षिक चक्रवृद्धि प्रतिशत दरें)

जापान	17.1
इटली	13.9
व० जर्मनी	11.7
सोवियत रूस	8.9
इंग्लैंड	5.2
अमरीका	4.7

यह भी आश्चर्य की बात है कि जापान की विदेशी कच्चे माल पर निर्भरता में भारी कमी आ रही है जबकि उसके उद्योग वर्तमान में युद्ध-पूर्व की तुलना में कई गुना उत्पादन कर रहे हैं। पहले जो बहुत सारी चीजें आवश्यक थीं उन्हें औद्योगिक सिलिक्टो (synthetics) ने प्रतिस्थापित कर दिया है। औद्योगिक कच्चे माल में जापान का आयात अनुपात अभी भी अन्य यूरोप के देशों से ऊँचा है किन्तु इसकी क्षति-पूर्ति खाद्य पदार्थों, मशीनों तथा अन्य उपभोक्ता वस्तुओं के बम जापानी आयात अनुपात से हो जाती है। जहाँ तक राष्ट्रीय उत्पाद के सन्दर्भ में कुल आयातों का प्रश्न है वे 1936 में 24.3% तक पहुँच चुके थे। 1962 में वे 12.2% पर आ गये थे। 1979 में ये आयात 10% के इर्द-गिर्द हैं।

अब जबकि जापान अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (I M F) तथा ओ.ई.सी.डी. जैसे संगठनों का सदस्य है उसके लिए युद्ध-पूर्व के वर्षों की तरह व्यापार एवं विनिमय नियन्त्रणों को लागू करना सम्भव नहीं रह गया है। इन नई 'खुले दरवाजे' वाली नीति से बँसी ही कुछ समस्याएँ उत्पन्न हो गई हैं जैसी कुछ अन्य यूरोपीय देशों को हो रही है। किन्तु जापान की तीव्र विकास दर तथा अपेक्षाकृत स्थिर मूल्य अर्थव्यवस्था के कारण वह अपनी चाले ठीक से चल सकने की स्थिति में है।

जापान को कई बार भुगतान सन्तुलन में घाटों का सामना करना पड़ा है परन्तु हर बार मौद्रिक प्रतिबन्धों से उसने वापस सन्तुलन स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है। जापान को दीर्घकालिक घाटों या अतिरेकों की समस्या का कभी सामना नहीं करना पड़ा (1974-75 इसमें अपवाद वर्ष रहे हैं)। मुधारों की तीव्र गति तथा मूल्य मजदूरी ढाँचे द्वारा तेजी से समायोजन सम्भव बनाने से विशेष कठिनाइयाँ नहीं आयी हैं। जापान ने अपने भुगतान घाटों को पूरा करने के लिए समय-समय पर अमरीका तथा यूरोप से ऋण लिये हैं। उसने मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक से भी उधार लिया है। 1945 से 1964 के बीच जापान को अमरीका से 1 अरब डॉलर मूल्य की सहायता मिली। जापानी सरकार ने देश में प्रत्यक्ष विदेशी पूँजी विनियोग पर जानबूझ कर प्रतिबन्ध लगा रखे हैं। किन्तु उसने विदेशों में प्रत्यक्ष जापानी पूँजी विनियोग पुनः आरम्भ कर दिये हैं तथा जापानी सरकार विकासोन्मुख देशों को पूँजी उपलब्ध कराने में सक्रिय भूमिका निभा रही है।

(7) अनुसन्धान एवं विकास—जापान ने तकनीकी क्रान्ति के लिए महान् प्रयास किये हैं। 1964 में भी राष्ट्रीय उत्पाद का 1.4% भाग अनुसन्धान एवं विकास पर खर्च किया गया। 1979 में यह खर्च 2% के लगभग है। निरपेक्ष रूप में जापान के शोध प्रयास अमरीका व रूस के बाद तीसरे स्थान पर आते हैं। रेडियो, टेलीविजन, मिनी मोटर साइकिलें, कैमरे, जहाज-निर्माण आदि के क्षेत्र में जापानी अनुसन्धान का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

अधिकांश जापानी औद्योगिक प्रतिष्ठानों में बड़ी शोध इकाइयाँ हैं। कुछ तो उनमें से यूरोपीय देशों की शोध इकाइयों से काफी बड़ी हैं। बैंक ऑफ जापान तथा आर्थिक नियोजन एजेंसी दोनों ही में अर्थशास्त्रियों की भरमार है। इसका परिणाम यह है कि आर्थिक निर्णय, यूरोप के देशों की तुलना में, कहीं अधिक आँकड़ों व

निश्चित जानकारी पर आधारित होते हैं।

विज्ञान एवं तकनीक के लिए स्थापित जापानी मूचना केन्द्र प्रति वर्ष लाखों वैज्ञानिक शोध पत्रों का जापानी भाषा में अनुवाद करता है। जापानी अधिकारी व्यापारी बराबर विदेशों में आते-जाते रहते हैं ताकि वे नये विचार सीख सकें। तकनीक के आयात पर काफी धन खर्च किया जाता है। और यह प्रक्रिया सरकार के नियन्त्रण में है। तकनीक के आयात पर किये गये समझौतों की सरकार वारीकी से जाँच करती है।

(8) सरकारी नीति—सरकारी नीतियों से भी आर्थिक विकास की गति को बल मिला है। सरकार ने औद्योगिक प्रसार तथा निर्माण सब्सिडी के लिए सारे वित्तीय एवं सहायक ढाँचे को फिर से तैयार किया है। सरकार ने विनियोग के लिए विशाल संसाधन उपलब्ध कराये हैं तथा अनुसन्धान एवं विकास पर मोटी रकम खर्च की है। सरकार ने अपने आप को अनावश्यक हस्तक्षेप से भी दूर रखा है तथा उसने व्यवसाय व उद्योगों को काफी स्वतन्त्र ही रहने दिया है।

(9) स्वतन्त्र उपक्रम—नव-प्रवर्तन तथा विकास की कसौटी पर जापानी व्यावसायिक प्रणाली अब तक खरी उतरी है। हालांकि उससे पहला लाभ पूँजीपति को मिलता है किन्तु वह श्रमिकों व उपभोक्ताओं को भी लाभ पहुँचाती है।

जापान के नये पूँजीवाद का भविष्य वहाँ पर ससदीय लोकतन्त्र की प्रणाली के सफलतापूर्वक चलने पर निर्भर करता है। पूँजीवाद पर आधारित औद्योगीकरण तथा स्वतन्त्र उपक्रम एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं। आज जापान में मजबूत और परिपक्व ससदीय सरकार है। तथा स्वतन्त्र उपक्रम के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता ने न केवल जॉब्स को पुनर्जीवित कर दिया है वरन् उसने ऐसी कई विशाल स्वायत्त शासी इकाइयों को पनपाया है जो जापानी अर्थव्यवस्था के तीव्र विकास में योग दे रही हैं।

(10) असीमित धर्म पूर्ति—औद्योगिक विकास के लिये जापान के पास अक्षरशः असीमित मात्रा में धर्म उपलब्ध था। किन्तु फिर भी रोजगार में जनसंख्या के मुकाबले अधिक तेजी से वृद्धि हुई है। 1979 में जापान की जनसंख्या वृद्धि दर तो मात्र 1% के आस-पास आ चुकी है। भीड़ भरे कृषि क्षेत्र से श्रमिकों का भारी विवर्तन (shift) हुआ है। केवल 1953 से 1965 के बीच के 12 वर्षों में कृषि क्षेत्र में श्रमिकों की संख्या में 46 मिलियन की कमी आयी। यह धर्म की पूर्ति में एक अतिरिक्त यागदान था। इस तत्त्व ने ही गैर कृषि रोजगार को 38% की वार्षिक दर से बढ़ा पाना सम्भव बनाया, वह भी ऐसे देश में जहाँ जनसंख्या 1% वार्षिक से ही बढ़ रही हो। यह वृद्धि दर भी (रोजगार में) दुनिया के किसी भी औद्योगिक देश की तुलना में अधिक तीव्र रही है।

उद्योगों के भीतर भी कम उत्पादकता से अधिक उत्पादकता वाले क्षेत्रों में रोजगार का स्थानान्तरण हुआ है। 1950 के आरम्भ में करीब 25% धर्म शक्ति 1 से 9 श्रमिकों वाले ऐसे प्रतिष्ठानों में लगी थी जिनकी उत्पादकता बहुत नीची थी। 1963 तक यह प्रतिष्ठान घटकर 16 रह गया था। 1979 में यह लगभग समाप्त

हो चुका है, अर्थात् कम उत्पादकता वाले उद्योगों का उन्मूलन हो गया है।

श्रम की पूर्ति लोचदार होने की वजह से जापान के मजदूरी स्तर में हुई समग्र वृद्धि उसके वहाँ हुई उत्पादकता वृद्धि के मुकाबले कम रही। इससे लागतें कम रहीं, विशेष रूप से अवसाद के समयों में। यही कारण था कि 1653 से लेकर 1979 तक भी अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में जापानी वस्तुओं की प्रतिस्पर्धाशीलता ज्यों की त्यों बनी रही है। अन्य देशों की तुलना में उसके निर्यातों में अधिक तेजी से वृद्धि होने का एक कारण यह भी रहा है।

यह जापान का सौभाग्य है कि उसके पास प्रशिक्षित जनशक्ति का अपार भण्डार है। पेचीदा उद्योगों, विदेश व्यापार तथा जहाजी सेवाओं के क्षेत्र में उसके पास अनुभव का खजाना है। इतना ही नहीं, जापान का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास कई यूरोप के देशों की तुलना में अधिक विशाल रहा। युद्धोत्तर काल में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भारी प्रसार हुआ है। युद्ध-पूर्व की तुलना में जापान में इन्जीनियरों की संख्या 1979 तक कई गुना हो चुकी है।

(11) निम्न उपभोग स्तर—जापानी लोगों में उपभोग पर नियन्त्रण लगा सकने की एक असाधारण क्षमता है। यह पहले भी लिखा जा चुका है कि मेज़ी युग के बाद से ही सरकार द्वारा तथा विनियोग हेतु सोखे जाने वाले समाधनों का कुल राष्ट्रीय आय में भाग बढ़ता ही गया है तथा एक बार तो वह 40% की ऊँचाई तक पहुँचा है। युद्धोत्तर काल में जबकि सैनिक व्यय लगभग नहीं के बराबर हुआ है, सरकारी उपभोग अन्य देशों की तुलना में काफी नीचा रहा है। अधिकांश ऋण-भार मुद्रा स्फीति के कारण हल्का हो गया था तथा सरकार के अन्य हस्तान्तरण व्यय भी यूरोपीय देशों की तुलना में नीचे रहे। प्रति व्यक्ति जापानी खाद्य उपभोग व्यय इतना कम है कि 1965 में वह मात्र 68 डॉलर था जबकि उस समय अमरीका में यह व्यय 134 डॉलर था। संरक्षणवादी नीतियों तथा खाद्य पदार्थों के ऊँचे मूल्यों ने भी जापानी खाद्य उपभोग को न्यूनतम सम्भव स्तर पर रखा है।

इस तरह युद्धोत्तर काल में जापान के तीव्र आर्थिक विकास को प्रभावित करने में इन तत्वों का विशेष महत्त्व माना जा सकता है¹—

(i) पुनर्द्धार का तत्त्व।

(ii) बहुत विशाल साधन प्रथाएँ (factor inputs)। गैर-कृषि रोजगार में 3.8% तथा पूँजी स्टॉक में 12.1% की उच्च दर से वृद्धि हुई। जर्मनी, जो कि राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि के हिसाब से दूसरे स्थान पर रहा, में ये वृद्धि दरें क्रमशः 2.5 व 8.5 प्रतिशत रही।

(iii) कम उत्पादकता वाले उद्योगों से अधिक उत्पादकता वाले क्षेत्रों में साधनों के हस्तान्तरण करने की असाधारण क्षमता।

(iv) कौशल तथा प्रशिक्षित जनशक्ति की असाधारण पूर्ति।

(v) सैनिक व्यय के माध्यम से होने वाले आर्थिक अपव्यय का पूर्ण अभाव।

विकासोन्मुख देशों को जो तीव्र आर्थिक विकास चाहते हैं, वे अधिकांश बातें

सीखनी व करनी होगी जिन्हें जापान ने किया है। उन्हें उच्च पूंजी-निर्माण की दर पर जल्दी से जल्दी अपना ध्यान केन्द्रित करना होगा। उन्हें जनसंख्या पर नियन्त्रण लगाने के अधिक कड़े उपाय करने होंगे तथा विकसित देशों का अधिक सक्रिय सहयोग प्राप्त करना होगा।

जोसफ स्टालिन¹ ने भविष्यवाणी की थी कि द्वितीय महायुद्ध के बाद जापान के तीव्र विकास का विजयी पूंजीवादी प्रतिद्वन्दी देश सहन नहीं करेंगे। 1952 के बाद वा रिवॉर्ड इस भविष्यवाणी को नकारते हुए भविष्य के प्रति आशाएं उत्पन्न करता है। यह एक भूतपूर्व जापानी प्रधानमन्त्री के उस स्वप्न को साकार रूप प्रदान करता है जिसमें उन्होंने जापान को उत्तरी अमरीका व पश्चिमी यूरोप के साथ खड़ा करके 'स्यतन्त्र विश्व के तीन स्तम्भ' बनाने की कल्पना की थी।

¹ W. W. Lockwood, *op cit*, 668